

राष्ट्रीयता

और

समाजवाद

राष्ट्रीयता और समाजवाद

लेखक
आचार्य नरेन्द्रदेव

वाराणसी
ज्ञानमण्डल लिमिटेड

प्रथमावृत्ति : वसन्तपञ्चमी संवत् २००६
पुनर्मुद्रित : गणतन्त्रदिवस संवत् २०३०

मूल्य २५।

प्रकाशक : ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी-१

मुद्रक : ओम् प्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी-१ ७१६३-३०

समर्पण-पत्र

काशी-विद्यापीठके सभी सहयोगियों और विद्यार्थियों
को
सस्नेह अर्पित

नरेन्द्रदेव .



विषय-सूची

पृष्ठ

पहला अध्याय—राष्ट्रीय आन्दोलनका इतिहास

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनका इतिहास	१
जन-जागृतिका पुनर्जन्म	५१

दूसरा अध्याय—स्वतन्त्रता संघर्ष

अभिभाषण (युक्तप्रान्तीय राज० सम्मेलनमे)	६३
आस्तीन के ये साँप !	८२
कांग्रेसके सामने सवाल	८८
समझौता विरोधी सम्मेलन	९२
पाकिस्तानकी योजना देशके लिए आत्म घातक है	९८
रामगढ कांग्रेसकी नीतिमे परिवर्तन आत्मघातक है	१०३
सत्याग्रहपर पावन्दियाँ	१०५
व्यक्तिगत सत्याग्रह और आजादी की लड़ाई	१०८
भारतकी स्वाधीनताका प्रश्न	१११
भारतकी स्वाधीनताका सवाल	११६
अगस्त क्रान्तिका स्वरूप और उसका सन्देश	१२२
सफल क्रान्तिकी तैयारी कीजिये	१२४
मध्यकालीन सरकार	१२६
स्वाधीनता दिवस और हमारा कर्तव्य	१२९
कांग्रेस किधर	१३३
लोकतन्त्रकी स्थापनाका मार्ग	१३८
हिन्दुस्तान और राष्ट्रमण्डल (१)	१४३
हिन्दुस्तान और राष्ट्रमण्डल (२)	१४५
लखनऊमे ६ अगस्तको भाषण—कामनवेल्थ विरोधी	१४७

तीसरा अध्याय—समाजवादकी ओर

कांग्रेस समाजवादी कांफरेन्स	१५३
सयुक्त मोर्चा और भारतीय कम्युनिस्ट	१५६
युद्ध और जनता	१६७
समाजवादी क्रान्तिकी रूपरेखा	१८७
समाजवादी दल	१९५
किसानोका उद्धार कैसे हो ?	२०१

काग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी	२०४
जनतन्त्रकी रक्षाके लिए विरोधी दलकी आवश्यकता	२०६
हमने कांग्रेस क्यों छोड़ी ?	२०८
कुछ गम्भीर प्रश्न	२१२
सन् ४२ की क्रान्तिका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ	२१८
पटना अधिवेशन	२२१
सत्याग्रह और प्रजातन्त्र	२४३
कृपिसुधार समितिके सामने वयान	२४६
अनिवार्य गल्लावसूली योजना	२५०
गाँवोमे शोपितोका संयुक्त मोर्चा कायम हो	२५३
जनताका आशा दीप बुझ रहा है	२५५

चौथा अध्याय—समाजवाद

समाजवादका लक्ष्य	२६३
सामाजिक वर्गोंका अर्थ	२६६
मानव-समाजका विकास	२६६
वर्ग-संघर्षकी आवश्यकता	२७४
इतिहासकी भौतिक व्याख्या	२७७
द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद	२८२
समाजवादका मूलाधार—मानदता	२८७
वर्गसंघर्षकी अनिवार्यता	२९३
मार्क्सवाद और पूंजीवादी विज्ञान	२९८
मार्क्स और नियतिवाद	३०५

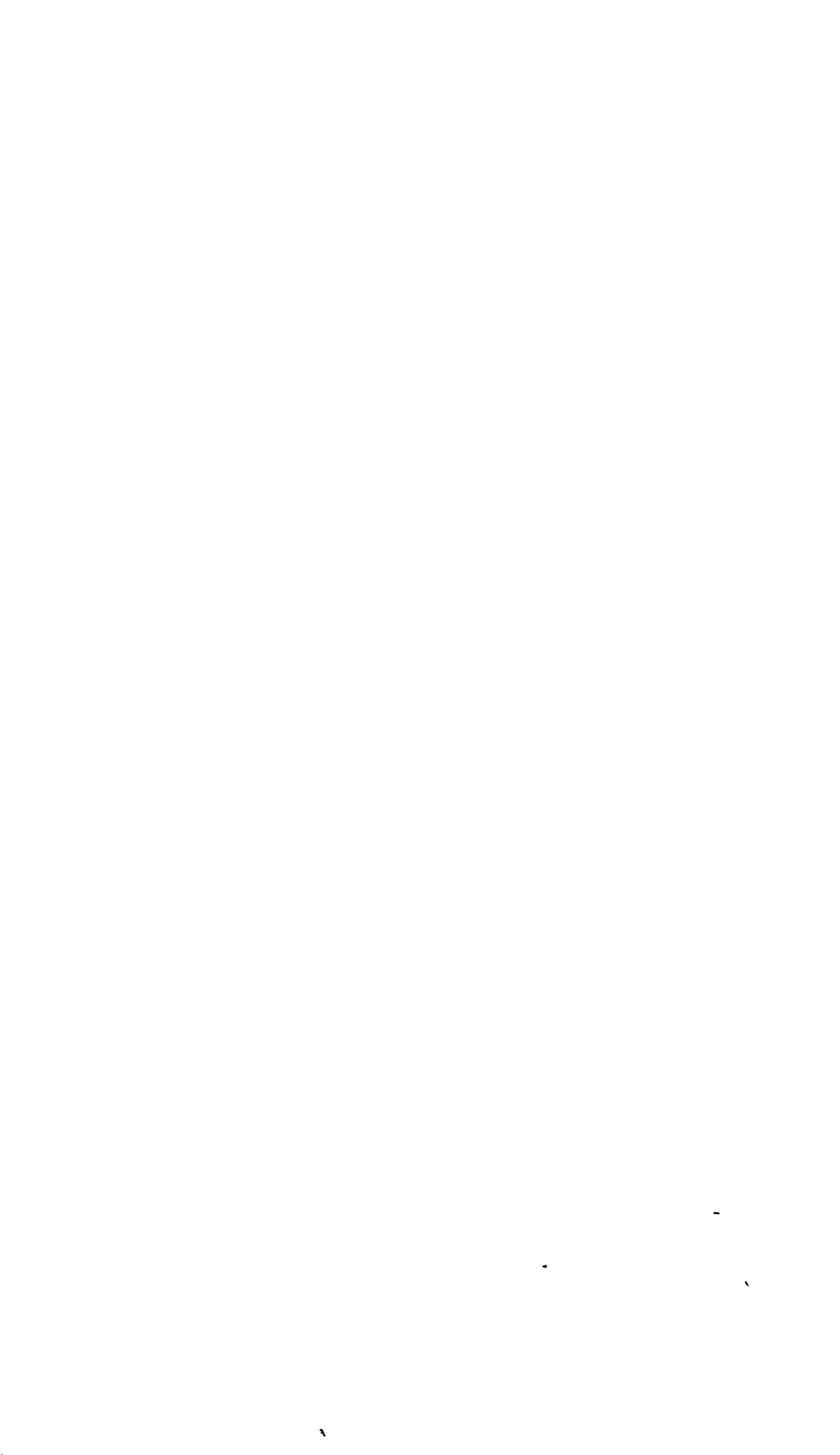
पाँचवाँ अध्याय—शिक्षा

युवकोंका समाजमे स्थान और भारत	३१३
विद्यार्थियोंका राजनीतिमे स्थान	३१६
योग्य शिक्षकोंकी कमी	३२१
क्या धार्मिक शिक्षा हमारी शिक्षा-संस्थाओंद्वारा दी जानी चाहिये	३२५
युवकोंको सन्देश	३३०
जन-शिक्षा	३३१
आगरा विश्वविद्यालय	३३६
अध्यापकोंका कर्त्तव्य	३४३
विश्वविद्यालय दे : नवयुगके नागरिक	३५३

छठा अध्याय—संस्कृति

हमारा आदर्श और उद्देश्य	३५९
-------------------------	-----

प्रगतिशील साहित्य	३६०
संस्कृतवाङ्मयका महत्त्व और उसकी शिक्षा	३६६
सातवाँ अध्याय--अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति	
सोवियत रूसकी एशिया-सम्बन्धी नीति	३७६
यूरोपकी स्थिति	३८६
एशियाके स्वतन्त्रता-आन्दोलनकी रूपरेखा	३९४
पेरिसका शान्ति-सम्मेलन	४००
जर्मन राजनीतिकी दिशा	४०७
आस्ट्रिया	४११
मिस्रकी राजनीतिक पार्टियाँ	४१३
फिलिस्तीन और भारत	४१६
ईराकके राजनीतिक दल और उनकी स्थिति	४१८
एशियाई सम्मेलन	४२०
हिन्दचीन और कम्युनिस्ट पार्टी	४२५
अमेरिकाका नया साम्राज्यवाद	४२७
आठवाँ अध्याय--स्फुट विचार	
मेरे सम्मरण	४३५
जनसाधारण और सरकारके आदर्श	४४७
पूँजीवादी समाज और प्रेस	४५०
विचारकोके सम्मुख एक नयी समस्या	४५५
फासिज्मका वास्तविक रूप	४५६
असली और नकली समाजवाद	४६४
महात्मागांधीको श्रद्धाञ्जलि	४६६
युक्तप्रान्तकी असेम्बलीमे दिया भाषण	४७२
गांधीजी	४७५



पहला अध्याय

राष्ट्रीय आन्दोलनका इतिहास

पहला अध्याय

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनका इतिहास

बहुत प्राचीनकालसे भारतवर्षसे विदेशोसे व्यापार हुआ करता था । यह व्यापार स्थल-मार्ग और जल-मार्ग दोनोंसे होता था । इन मार्गोंपर एकाधिकार प्राप्त करनेके लिए विविध राष्ट्रोंमें समय-समयपर संघर्ष हुआ करता था । जब इस्लामका उदय हुआ और अरब, फारस, मिस्र और मध्य एशियाके विविध देशोंमें इस्लामका प्रसार हुआ, तब धीरे-धीरे इन मार्गोंपर मुसलमानोंका अधिकार हो गया और भारतका व्यापार अरब-निवासियोंके हाथमें चला गया । अफ्रीकाके पूर्वी किनारेसे लेकर चीन-समुद्रतक समुद्र-तटपर अरब व्यापारियोंकी कोठियाँ स्थापित हो गयी । यूरोपमें भारतका जो माल जाता था वह इटलीके दो नगर—जिनोआ और वेनिससे जाता था । ये नगर भारतीय व्यापारसे मालामाल हो गये । वे भारतका माल कुस्तुन्तुनियाकी मण्डीमें खरीदते थे । इन नगरोंकी धन-समृद्धिको देखकर यूरोपके अन्य राष्ट्रोंको भारतीय व्यापारसे लाभ उठानेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई, पर व्यापारके मार्गोंपर मुसलमान राष्ट्रोंका अधिकार होनेके कारण वे अपनी इस इच्छाकी पूर्तिमें सफल न हो सके । बहुत प्राचीनकालसे यूरोपके लोगोंका अनुमान था कि अफ्रीका होकर भारतवर्षतक समुद्र-द्वारा पहुँचनेका कोई-न-कोई मार्ग अवश्य है । चौदहवीं शताब्दीमें यूरोपमें एक नये युगका प्रारम्भ हुआ । नये-नये भौगोलिक प्रदेशोंकी खोज आरम्भ हुई । कोलम्बसने सन् १४९२ ईसवीमें अमेरिकाका पता लगाया और यह प्रमाणित कर दिया कि अटलाण्टिकके उस पार भी भूमि है । पुर्तगालकी ओरसे बहुत दिनोंसे भारतवर्षके आनेके मार्गका पता लगाया जा रहा था । अन्तमें, अनेक वर्षोंके प्रयासके अनन्तर सन् १४९८ ई० में वास्को-डिगामा शुभाशा अन्तरीपको पार कर अफ्रीकाके पूर्वी किनारेपर आया; और वहाँसे एक गुजराती नियामकको लेकर मालावारमें कालीकट पहुँचा । पुर्तगालवासियोंने धीरे-धीरे पूर्वीय व्यापारको अरबके व्यापारियोंसे छीन लिया । इस व्यापारसे पुर्तगालकी बहुत श्री-वृद्धि हुई । देखा-देखी डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियोंने भी भारतसे व्यापार करना शुरू किया । इन विदेशी व्यापारियोंमें भारतके लिए आपसमें प्रतिद्वन्द्विता चलती थी और इनमेंसे हर एकका यह इरादा था कि दूसरोंको हटाकर अपना अक्षुण्ण अधिकार स्थापित करे । व्यापारकी रक्षा तथा वृद्धिके लिए इनको यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करे । यह संघर्ष बहुत दिनोंतक चलता रहा और अंग्रेजोंने अपने प्रतिद्वन्द्वियोंपर विजय प्राप्त की और सन् १७६३ के बादसे उनका कोई प्रबल प्रतिद्वन्द्वी नहीं रह गया । इस बीचमें अंग्रेजोंने कुछ प्रदेश भी हस्तगत कर लिये थे और बङ्गाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटकमें जो नवाब राज्य करते थे वे अंग्रेजोंके

हाथकी कठपुतली थे। उनपर यह बात अच्छी तरह जाहिर हो गयी थी कि अंग्रेजोंका विरोध करनेसे वे पदच्युत कर दिये जायेंगे।

यह विदेशी व्यापारी भारतसे मसाला, मोती, जवाहिरात, हाथीदाँतकी बनी चीजें, ढाकेकी मलमल और आवेरवाँ, मुँशिदावादका रेशम, लखनऊकी छोट, अहमदावादके दुपट्टे, नील आदि पदार्थ ले जाया करते थे और वहाँसे शीशेका सामान, मखमल, साटन और लोहेके औजार भारतवर्षमें बेचनेके लिए लाते थे। हमें इस ऐतिहासिक तथ्यको नहीं भूलना चाहिये कि भारतमें ब्रिटिशसत्ताका आरम्भ एक व्यापारिक कम्पनीकी स्थापनासे हुआ। अंग्रेजोंकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा तथा चेष्टा भी इसी व्यापारकी रक्षा और वृद्धिके लिए हुई थी। आज भारतवर्षमें अंग्रेजोंकी बहुत बड़ी पूँजी लगी हुई है। पिछले पचास-साठ वर्षोंमें इस पूँजीमें बहुत तेजीके साथ वृद्धि हुई है। ६३४ विदेशी कम्पनियाँ भारतमें इस समय कारोबार कर रही हैं। इनकी वसूल हुई पूँजी लगभग साढ़े सात खर्व रुपया है और ५१६४ कम्पनियाँ ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्री भारतमें हुई है और जिनकी पूँजी ३ खर्व रुपया है। इनमेंसे अधिकतर अंग्रेजी कम्पनियाँ हैं। इङ्ग्लैण्डसे जो माल विदेशोंको जाता है उसका दशमांश प्रतिवर्ष भारतवर्ष आता है। वस्त्र और लोहेके व्यवसाय ही इङ्ग्लैण्डके प्रधान व्यवसाय हैं और ब्रिटिश राजनीतिमें इनका प्रभाव सबसे अधिक है। भारतपर इङ्ग्लैण्डका अधिकार बनाये रखनेमें इन व्यवसायोंका सबसे बड़ा स्वार्थ है; क्योंकि जो माल ये बाहर रवाना करते हैं उसके लगभग पञ्चमांशकी खपत भारतवर्षमें होती है। भारतका जो माल विलायत जाता है उसकी कीमत भी कुछ कम नहीं है। इङ्ग्लैण्ड प्रतिवर्ष चाय, जूट, रुई, तेलहन, ऊन और चमड़ा भारतसे खरीदता है। यदि केवल चायका विचार किया जाय तो ३६ करोड़ रुपया होगा। इन बातोंपर विचार करनेसे यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों इङ्ग्लैण्डका भारतमें आर्थिक लाभ बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसका राजनीतिक स्वार्थ भी बढ़ता जाता है।

उन्नीसवीं शताब्दीके पहले इङ्ग्लैण्डका भारतपर बहुत कम अधिकार था और पश्चिमी सभ्यता तथा सस्थाओंका प्रभाव यहाँ नहींके बराबर था। सन् १७५० से पूर्व इङ्ग्लैण्डमें औद्योगिक क्रान्ति भी नहीं आरम्भ हुई थी। उसके पहले भारतवर्षकी तरह इङ्ग्लैण्ड भी एक कृषि-प्रधान देश था। उस समय इङ्ग्लैण्डको आजकी तरह अपने मालके लिए विदेशोंमें बाजारकी खोज नहीं करनी पड़ती थी। उस समय गमनागमनकी सुविधाएँ न होनेके कारण सिर्फ हल्की-हल्की चीजें ही बाहर भेजी जा सकती थी। भारतवर्षसे जो व्यापार उस समय विदेशोंसे होता था, उससे भारतको कोई आर्थिक क्षति भी नहीं थी। सन् १७६५में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनीको मुगल बादशाह शाहआलमसे बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी दीवानी प्राप्त हुई, तबसे वह इन प्रान्तोंमें जमीनका बन्दोबस्त और मालगुजारी वसूल करने लगी। इस प्रकार सबसे पहले अंग्रेजोंने यहाँकी मालगुजारीकी प्रथामे हेर-फेर किया। इसको छोड़कर किसी पुरानी संस्थामें किसी प्रकारका भी परिवर्तन नहीं किया गया। उस समय पत्रव्यवहारकी भाषा फारसी थी। कम्पनीके नौकर देशी राजाओंसे फारसीमें ही पत्र-व्यवहार करते थे। फौजदारी अदालतोंमें क्राजी और मौलवी

मुसलमानी कानूनके अनुसार अपना निर्णय देते थे । दीवानीकी, अदालतोंमें धर्म-शास्त्र और शरहके अनुसार पण्डितों और मौलवियोंकी सलाहसे अंग्रेज कलेक्टर मुकदमोंका फैसला करते थे । जब ईस्टइण्डिया कम्पनीने शिक्षापर कुछ व्यय करनेका निश्चय किया, तो उनका पहला निर्णय अरबी, फारसी और संस्कृत-शिक्षाके पक्षमें ही हुआ । बनारसमें संस्कृत कालेज और कलकत्तेमें कलकत्ता मदरसाकी स्थापना की गयी । पण्डितों और मौलवियोंको पुरस्कार देकर प्राचीन पुस्तकोंके मुद्रित कराने और नवीन पुस्तकोंके लिखानेका आयोजन किया गया । उस समय ईसाइयोंको कम्पनीके राजमें अपने धर्मके प्रचार करनेकी स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त थी । बिना कम्पनीसे लाइसेन्स प्राप्त किये कोई अंग्रेज न भारतवर्षमें आकर बस सकता था और न जायदाद खरीद सकता था । कम्पनीके अफसरोंका कहना था कि यदि यहाँ अंग्रेजोंको बसनेकी आम इजाजत दे दी जायगी तो उससे विद्रोहकी आशङ्का है, क्योंकि विदेशियोंके भारतीय धर्म और रस्म-रिवाजसे भलीभाँति परिचित न होनेके कारण इस बातका बहुत भय है कि वे भारतीयोंके भावोंका उचित आदर न करेंगे । देशकी पुरानी प्रथाके अनुसार कम्पनी अपने राज्यके हिन्दू और मुसलमान धर्म-स्थानोंका प्रबन्ध और निरीक्षण करती थी । मन्दिर, मस्जिद, इमामवाड़े और खानकाहके आय-व्ययका हिसाब रखना, इमारतोंकी मरम्मत कराना और पूजाका प्रबन्ध, यह सब कम्पनीके जिम्मे था । अठारहवीं शताब्दीके अन्तसे ही इङ्ग्लैण्डके पादरियोंने इस व्यवस्थाका विरोध करना शुरू किया । उनका कहना था कि ईसाई होनेके नाते कम्पनी विधर्मियोंके धर्म-स्थानोंका प्रबन्ध अपने हाथमें नहीं ले सकती । वे इस बातकी भी कोशिश कर रहे थे कि ईसाईधर्मके प्रचारमें कम्पनीकी ओरसे कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । उस समय देशी ईसाइयोंकी अवस्था बहुत शोचनीय थी । यदि कोई हिन्दू या मुसलमान ईसाई हो जाता था तो उसका अपनी जायदाद और वीवी एवम् वच्चोपर कोई हक नहीं रह जाता था । मद्रासके अहातेमें देणी ईसाइयोंको बड़ी-बड़ी नौकरियाँ नहीं मिल सकती थी । इनको भी हिन्दुओंके धार्मिक-कृत्योंके लिए टैक्स देना पड़ता था । जगन्नाथजीका रथ खींचनेके लिए रथ-यात्राके अवसरपर जो लोग बेगारमें पकड़े जाते थे उनमें कभी-कभी ईसाई भी होते थे । यदि वे इस बेगारसे इन्कार करते थे तो उनको बेत लगाये जाते थे । इङ्ग्लैण्डके पादरियोंका कहना था कि ईसाइयोंको उनके धार्मिक विश्वासके प्रतिकूल किसी कामके करनेके लिए विवश नहीं करना चाहिये और यदि उनके साथ कोई रियायत नहीं की जा सकती तो कमसे कम उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिये जो अन्य धर्मावलम्बियोंके साथ होता है । धीरे-धीरे इस दलका प्रभाव बढ़ने लगा और अन्तमें ईसाई पादरियोंकी माँगोंको बहुत कुछ अंशमें पूरा करना पड़ा । कानून बनाकर यह नियम कर दिया गया कि जो कोई धर्म-परिवर्तन करेगा उसको उसके फलस्वरूप अपनी जायदादसे हाथ नहीं धोना पड़ेगा । ईसाइयोंको धर्म-प्रचारकी भी स्वतन्त्रता मिल गयी । अब राज-दरबारकी भाषा अंग्रेजी हो गयी और अंग्रेजी शिक्षाको प्रोत्साहन देनेका निश्चय हुआ । धर्म-शास्त्र और शरहका अंग्रेजीमें अनुवाद किया-गया और एक 'ला कमीशन' नियुक्त कर एक नया दण्ड-विधान और अन्य नये कानून तैयार

व्यवसायोंके लिए जो पदार्थ विशेष रूपसे उपयोगी हैं उनकी पैदावार संसारके जिस किसी भू-भागमें प्रचुरतासे होती है उस भू-भागपर आधिपत्य प्राप्त करनेके लिए ये औद्योगिक राष्ट्र प्रयत्न करते हैं। यह बात प्रसिद्ध ही है कि कोयला, लोहा और तेलके कारण कितने ही गुट बने हैं और कितने ही युद्ध हुए हैं। उद्योग-व्यवसायकी वृद्धिका एक फल यह भी हुआ है कि प्रत्येक राष्ट्रकी पूँजी बहुत अधिक बढ़ गयी है। यह पूँजी यहाँतक बढ़ गयी है कि उसके एक भागको अपने ही देशमें बहुत मुनाफेके साथ नहीं लगाया जा सकता। जो पूँजी यदि फ्रांसमें नयी रेलोंके निर्माणमें लगायी जाय तो मुश्किलसे दो या तीन प्रतिशत मुनाफा मिलेगा, उसी पूँजीको यदि नये देशोंमें लगाया जाय तो १० से २० प्रतिशत तक मुनाफा मिल सकता है। यही कारण है कि औद्योगिक राष्ट्रोंकी बहुत बड़ी पूँजी विदेशोंमें लगी हुई है।

इन विविध आर्थिक कारणोंसे साम्राज्यवादका जन्म हुआ और उसी साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए भारत तथा एशियाके अन्य देशोंमें राष्ट्रीयताका जन्म हुआ। चूँकि भारतका अंग्रेजी शिक्षित समुदाय ही अंग्रेजी साहित्यके द्वारा यूरोपकी विचारधारा और इतिहाससे सबसे पहले परिचित हुआ था, इसलिए इसी वर्गने राष्ट्रीय आन्दोलनका सूत्रपात किया। जहाँ अंग्रेजी शिक्षाके आरम्भ होनेके पहले जमीन्दार और अच्छे और ऊँचे खानदानके लोग—जैसे नवाब और सरदार—समाजका नेतृत्व करते थे, वहाँ अंग्रेजी-शिक्षाके प्रतापसे धीरे-धीरे मध्यम श्रेणीके अंग्रेजी शिक्षित वर्गका प्रभाव बढ़ने लगा। यद्यपि कुछ अंग्रेज शासकोंने मध्यम श्रेणीके बढ़ते हुए प्रभावको रोकनेका प्रयत्न किया; तथापि वे प्रवाहके विरुद्ध जानेमें असफल हुए। पुराने खानदानोंका प्रभाव दिनोदिन घटता गया और धीरे-धीरे मध्यम श्रेणीके लोगोंने समाजका नेतृत्व ग्रहण करना शुरू किया।

जहाँ अंग्रेजी शिक्षाका अधिक प्रचार था वहाँ भारतीयोंकी समितियाँ कायम होने लगीं। इन समितियोंका उद्देश्य जनताकी शिकायतोंको दूर करानेके लिए समय-समयपर सरकारको प्रार्थना-पत्र देना था। लोकमतको शिक्षित करनेके लिए इनकी स्थापना नहीं हुई थी। सन् १८५१ में कलकत्तेमें 'ब्रिटिश-इण्डियन-एसोसियेशन' और सन् १८५३ में 'बम्बई-एसोसियेशन' और 'मद्रास-एसोसियेशन'की स्थापना हुई। सन् १८७० में पूना-सार्वजनिक सभा कायम हुई। सन् १८७६ में कलकत्तेमें श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और श्री आनन्दमोहन बोसके उद्योगसे 'इण्डियन एसोसियेशन' कायम हुआ। सन् १८८४ में 'मद्रास एसोसियेशन'का स्थान महाजन-सभाने लिया। 'बम्बई एसोसियेशन' कुछ वर्ष काम करके बन्द हो गया था; परन्तु सन् १८८५ में श्री वदरुद्दीन तैयबजी, श्री फिरोजशाह मेहता और श्री काशीनाथ त्र्यम्बक तैलङ्गके प्रयत्नसे 'बम्बई प्रेसीडेंसी एसोसियेशन'के नामसे उसका फिरसे उद्धार हुआ। 'इण्डियन एसोसियेशन' और 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन'के उद्देश्योंमें बड़ा अन्तर था। 'इण्डियन एसोसियेशन' लोकमतकी शिक्षापर बहुत जोर देता था। इसके संस्थापकोंने इङ्ग्लैण्डमें शिक्षा प्राप्त की थी और वहाँ रहकर उन्होंने राजनीतिक आन्दोलनके महत्त्वको भलीभाँति समझ लिया था। वे सरकारके पास आवेदन-पत्र भेजकर ही सन्तुष्ट नहीं रहते थे। वे भारतमें वैध उपायों द्वारा औप-

निवेशिक स्वराज्यकी स्थापना चाहते थे । वे अंग्रेजी शासनके अनेक लाभोको स्वीकार करते थे और पक्के राजभक्त थे । वे इस बातको मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते थे कि अभी भारतीयोंको स्वराज्यकी योग्यता प्राप्त नहीं हुई है, पर उनका कहना था कि सरकारका यह कर्तव्य है कि धीरे-धीरे शिक्षाका प्रचार कर भारतीयोंको अधिकार दे और उन्हें इस बातके योग्य बनाया जाय कि वे अपने देशका शासन स्वयं कर सकें । भारतीय सरकारकी नेकनीयतीपर भी आरम्भमें उनको कोई शक नहीं था । उनका यह भी खयाल था कि इङ्ग्लैण्डमें भी भारतके लिए आन्दोलन करना अत्यावश्यक है । बंगालके कई जिलोमें तथा उत्तरी भारतकी कई जगहोंमें 'इण्डियन एसोसियेशन' की शाखाएँ स्थापित की गयी । इङ्ग्लैण्डमें समय-समयपर डेपुटेशन भेजनेका भी प्रयत्न किया गया । श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जीपर मेजिनीके लेखोंका बहुत प्रभाव पड़ा था । इटलीकी स्वाधीनताका प्रश्न उनके समयमें एक जीता-जागता प्रश्न था । भारतीय एकताका विचार भी उन्होंने मेजिनीसे ही सीखा था । भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके बीच स्नेह-सम्बन्ध स्थापित करनेका उन्होंने उद्योग किया था । बम्बई, पूना और मद्रासकी संस्थाएँ प्रान्तीय थी, लेकिन 'इण्डियन एसोसियेशन' का कार्य केवल बङ्गालप्रान्तमें ही सीमित न था । 'इण्डियन एसोसियेशन' समस्त भारतके लिए एक राजनीतिक संस्थाकी स्थापना करना चाहता था । सन् १८८३ के दिसम्बर मासमें एसोसियेशनकी ओरसे कलकत्तेमें पहली राष्ट्रीय कान्फरेन्स की गयी थी जिसमें मद्रास, बम्बई और संयुक्तप्रान्तके प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे और यदि सन् १८८५ में ह्यूम और उनके मित्रोंने कांग्रेसकी स्थापनाका स्वतन्त्र निश्चय न किया होता तो भी सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके उद्योगसे अखिल भारतीय राजनीतिक संस्थाकी प्रतिष्ठा होना निश्चित था । बनर्जीने मेजिनीसे यह भी सीखा था कि बिना अपूर्व त्यागके कोई देश स्वाधीन नहीं हो सकता और देशके नवयुवकोसे ही अपूर्व त्यागकी आशा हो सकती है, क्योंकि उनका हृदय जीवनकी कठोरता और कर्कशतासे कलुषित नहीं हो जाता है और वे आदर्शके लिए अपना सर्वस्व त्याग करनेके लिए भी उद्यत किये जा सकते हैं । जिस प्रकार मेजिनीने 'यंग इटली' नामक संस्थाकी स्थापना की थी उसी प्रकार बनर्जी महाशयने कलकत्तेमें विद्यार्थियोंका एक सघ स्थापित किया । लोकमतको शिक्षित करनेके लिए उन्होंने अंग्रेजीमें 'वङ्गाली' नामक सामाचार-पत्र भी निकाला । 'इण्डियन एसोसियेशन' भारतीयोंके अधिकारोंकी रक्षाका निरन्तर प्रयत्न करता था । हमको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ये सब राजनीतिक संस्थाएँ अंग्रेजी शिक्षित मध्यम श्रेणीके लोगोंकी ही थी । इसलिए वे प्रायः ऐसे ही प्रश्नोंको लेकर आन्दोलन किया करती थी जिनका मध्यम श्रेणीके लोगोंके स्वार्थ और लाभसे सम्बन्ध था ।

जब लार्ड सेल्सवरीने सिविल सर्विसकी परीक्षाके लिए २१ वर्षसे घटाकर १९ वर्षकी उम्रका नियम कर दिया तब इस नियमका इन सब संस्थाओंने समान रूपसे विरोध किया । यह पहला ही अवसर था जब यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतमें एक ऐसे वर्गका प्रादुर्भाव हो गया है जिसकी आकांक्षाएँ, जिसकी भावनाएँ एवम् जिसके विचार एक ही प्रकारके हैं । लार्ड लिटनके शासन-कालमें जब सन् १८७८ में, 'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट' पास हुआ

था, तब उसका भी एक स्वरसे विरोध किया गया। 'इण्डियन एसोसियेशन' ने इस सम्बन्धमें पार्लमेण्टको एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसको ग्लैडस्टनने पार्लमेण्टमें पेश किया। पार्लमेण्टमें इस सम्बन्धमें वाद-विवाद हुआ, परन्तु ग्लैडस्टनका प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। अफगान युद्धके सम्बन्धमें लिटनकी नीतिकी इङ्ग्लैण्डमें बहुत टीका-टिप्पणी हुई। इस प्रकार इङ्ग्लैण्डनिवासियोंने भारतीय प्रश्नमें दिलचस्पी लेना शुरू किया। भारत-सम्बन्धी तरह-तरहके प्रश्नोंपर पार्लमेण्टमें वाद-विवाद होने लगा। ग्लैडस्टनने, जो कि लिबरल दलका नेता था, भारतीयोंका पक्ष लिया। लिबरल दल आयरलैण्डके साथ सहानुभूति रखता था और उसकी सहायतासे ही आयरलैण्डके कई कानून रद्द किये गये थे। इससे भारतीयोंको यह आशा हो चली थी कि लिबरल दल भारतीयोंकी सहायता करेगा और जब इङ्ग्लैण्डके शासनकी वाग-डोर उसके हाथमें आयगी तो भारतके साथ न्याय किया जायगा। सन् १८८० में जब लिबरल मंत्रिमण्डल शासनारूढ हुआ, तब भारतीयोंने सन्तोष प्रकट किया। आरम्भमें भारतीय नेता कंजर्वेंटिव और लिबरल दलमें कोई विवेक नहीं करते थे। वे इङ्ग्लैण्डके सब दलोंसे समान रूपसे सहायता प्राप्त करनेकी चेष्टा करते थे। लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि लिबरल दल कंजर्वेंटिव दलकी अपेक्षा अधिक उदार है और आयरलैण्डके साथ न्याय करना चाहता है तो उनको लिबरल दलसे सहानुभूति प्राप्त करनेकी अधिक आशा बँधी।

जिस प्रकार बंगालमें आनन्दमोहन बोस और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी प्रधान कार्यकर्ता थे उसी प्रकार बम्बई प्रान्तमें फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलङ्ग, बदरुद्दीन तैयबजी, चन्दावरकर और वाचा आदि सज्जन प्रमुख कार्यकर्ता थे। श्री दादाभाई नौरोजी इनके नेता थे। दादाभाई नौरोजीके उद्योगसे इङ्ग्लैण्डमें 'ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन' नामकी संस्था सन् १८६७ ईसवीमें कायम की गयी थी। उसी समय उन्होंने वहाँ 'लन्दन इण्डिया सोसाइटी' के नामसे एक संस्था खोली। विद्यार्थी-अवस्थामें फिरोज शाह मेहता इस संस्थामें सम्मिलित हुए थे। इस समय हिन्दुस्तानकी गरीबीका प्रश्न एक विकट रूप धारण कर रहा था। भारतवर्षमें इस समय बार-बार अकाल पड़ते थे। सन् १८६८-६९ में राजपूतानेमें, १८७३-७४ में बङ्गाल और बिहार प्रान्तमें, १८७६ से ७८ तक मद्रास और बम्बई प्रान्तमें अकाल पड़े। कई जगह किसानोंके बलबे भी हो गये। इसलिए देशके नेताओंका ध्यान भारतकी गरीबीके प्रश्नकी ओर आकृष्ट हुआ। दादाभाई नौरोजीने इस गरीबीके कारणोंका अध्ययन किया और ग्रन्थ एवम् लेख लिखकर शिक्षित जनताका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया।

हम ऊपर कह चुके हैं कि सन् १८८५ में ह्यूमके उद्योगसे काग्रेसकी स्थापना हुई थी। सन् १८८४ के दिसम्बर मासमें अडयार (मद्रास) में थियासोफिकल सोसाइटीका वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशनमें भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके प्रतिनिधि तथा थियासोफिकल सोसाइटीसे सहानुभूति रखनेवाले मित्त एकत्रित हुए थे। इनमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, काशीनाथ व्यम्बक तैलग और दादाभाई नौरोजीके नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं। इन लोगोंने देशके सुधारके लिए एक राजनीतिक संस्था स्थापित करनेका विचार निश्चित किया

और एक गश्ती चिट्ठी इस आशयकी घुमायी कि इण्डियन नेशनल यूनियनकी कान्फरेन्स सन् १८८५के दिसम्बरमे पूनेमे होगी तथा सब प्रान्तोके अंग्रेजी पढ़े राजनीतिज्ञ प्रतिनिधि-रूपसे इस कान्फरेन्समे सम्मिलित हो सकेंगे । यह कान्फरेन्स दो उद्देश्योको दृष्टिमे रखकर बुलायी गयी थी । पहला उद्देश्य भिन्न-भिन्न प्रान्तोके कार्यकर्ताओंमें परिचय करानेका था । दूसरा उद्देश्य यह था कि अगले वर्षका राजनीतिक कार्य-क्रम स्थिर किया जाय । ह्यूम साहब कांग्रेसके पिता कहे जाते हैं । ये पहले इण्डियन सिविल सर्विसके एक सदस्य थे । इन्होंने सिपाही-विद्रोहका जमाना देखा था । बार-बार अकाल पड़नेसे और अफगान-युद्धके कारण जनतामे अशान्ति बढ़ रही थी । उस समय रूस एशियामे इङ्गलैण्डका एक जवर्दस्त प्रतिपक्षी समझा जाता था । द्वितीय अफगान युद्धके छिड़नेपर बाजारोमे तरह-तरहकी अफवाहे फैलने लगी । लोग जावजा कहने लगे कि रूस भारतवर्षपर आक्रमण करेगा । वे रूसको इतना शक्तिशाली समझते थे कि यदि इङ्गलैण्ड और रूसके बीच कोई युद्ध छिड़ा तो उसमे रूस इङ्गलैण्डको हरा देगा । ह्यूम साहब साधुओंसे अक्सर मिला करते थे और उनको इस बातका पता चला कि लोगोकी अशान्ति बढ़ रही है और उनको इसकी आशंका हुई कि कहीं सिपाही-विद्रोहकी पुनरावृत्ति न हो जाय । इसलिए उन्होंने इस बातकी आवश्यकता समझी कि कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये जिससे सरकारको जनताके हृद्गत भावोका पता चलता रहे और जनताकी अशान्ति विद्रोहका रूप न धारण कर वैध आन्दोलनका रूप धारण करे । इस कार्यके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षित वर्गको उपयुक्त समझा ; क्योंकि वे समझते थे कि अंग्रेजी शिक्षितवर्ग ही एक ऐसी शृङ्खला है जो इङ्गलैण्ड और भारतके सम्बन्धको सुदृढ़ कर सकती है और वे यह भी जानते थे कि विदेशी शासक और अपठ जनताके बीच दुभापियेका काम भी यही वर्ग कर सकता है । सन् १८८८ मे इलाहाबादकी कांग्रेसके अवसरपर ह्यूम महाशयने एक वक्तृतामे यह कहा था कि कांग्रेसका एक उद्देश्य यह भी है कि लोगोकी मनोवृत्तिको इस प्रकार बदल दे जिसमे वह वाद-विवाद द्वारा पार्लमेण्टकी शैलीके अनुसार अपने देशका प्रबन्ध करना सीखे । इससे स्पष्ट है कि ह्यूम साहबने कांग्रेसकी स्थापनाको इङ्गलैण्डके स्वार्थके लिए ही आवश्यक समझा था । उनका यह खयाल बहुत ठीक था । अंग्रेजी-शिक्षाके प्रभावकी चर्चा करते हुए ट्रैविलियन अपनी पुस्तकमे लिखता है—‘संयुक्तप्रान्त और बंगालके ऊँची श्रेणीके लोगोके राजनीतिक विचारोमे मैंने एक बड़ा भारी अन्तर पाया है । संयुक्तप्रान्तमे, जहाँ अंग्रेजी-शिक्षाका अभी आरम्भ ही हुआ है, लोग केवल एक ही प्रकारसे अर्थात् अंग्रेजोंको निकालनेसे ही अपनी राजनीतिक अवस्थाका सुधार सम्भव समझते हैं । इसके विपरीत बंगालमे, जहाँ अंग्रेजी-शिक्षाका काफी प्रसार हो चुका है, लोग किसी-न-किसी रूपकी प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणालीको ही अपना आदर्श समझते हैं । इसमे सन्देह नहीं कि दोनो प्रकारसे अंग्रेजी राज्यका अन्त होना निश्चित है । लेकिन दोनो प्रकारोमे यह एक बड़ा अन्तर है कि जहाँ एक प्रकारमे हमारी सरकारका तत्काल ही अन्त करना अभीष्ट है वहाँ दूसरे प्रकारमे इस बातको स्वीकार कर लिया जाता है कि बहुत दिनोतक हमारे शासनकी आवश्यकता बनी रहेगी और ज्यों-ज्यों

जनता अपनेमें शासनकी योग्यता प्रतिपादित करती जायगी त्यों-त्यों अधिकाधिक अधिकार उसको प्राप्त होते जायँगे।' 'ह्यूम साहबने गवर्नर-जनरल लार्ड डफरिनसे भी इस सम्बन्धमें सलाह की और उनकी अनुमति प्राप्त की। इङ्ग्लैण्डमें पेशनयापता एंग्लो-इण्डियनोसे भी मणविरा किया गया और सबका आशीर्वाद लेकर इस कार्यका मूलपात हुआ। लार्ड डफरिनका खयाल था कि इस प्रकार बढ़ते हुए असन्तोषको रोककर कुछ वर्षोंके बाद इस संस्थाको वन्द कर देंगे।

हैजेके प्रकोपके कारण पहला अधिवेशन पूनेमें न होकर बम्बईमें श्री उमेशचन्द्र बनर्जीकी अध्यक्षतामें हुआ। संस्थाका नाम 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' रखा गया। इस अधिवेशनमें ७२ प्रतिनिधि उपस्थित थे। कई सरकारी अहल-कार भी सलाह-मणविरके लिए मौजूद थे, यद्यपि सरकारी नौकर होनेकी वजहसे वे प्रतिनिधिकी हैसियतमें काररवाईमें भाग नहीं ले सकते थे। उस समय सरकारी नौकरोके लिए दर्शकरूपसे ऐसे अधिवेशनोंमें सम्मिलित होनेकी मनाही न थी। सन् १८८६ में जो कांग्रेस कलकत्तेमें हुई थी उसके प्रतिनिधियोंको लार्ड डफरिनने दावत भी दी थी।

आरम्भमें कांग्रेसका उद्देश्य शुद्ध राजनीतिक न था। वह सब प्रकारके सुधारके लिए उद्योग करना चाहती थी। लेकिन सन् १८८६ की कांग्रेसमें दादाभाई नौरोजीने समापतिकी हैसियतसे इस बातकी घोषणा की कि कांग्रेस एक शुद्ध राजनीतिक संस्था है और उसको उन सामाजिक प्रश्नोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है जिनके बारेमें मतभेद पाया जाता है। ज्यों-ज्यों कांग्रेसका प्रभाव शिक्षित-समुदायमें बढ़ने लगा और प्रचार-कार्यका विस्तार होने लगा त्यों-त्यों सरकारका विरोध भी आरम्भ होने लगा। सन् १८८८ में जब कांग्रेसका अधिवेशन प्रयागमें हुआ था तब अधिकारीवर्गके विरोधके कारण स्थानके मिलनेमें प्रबन्धको-को बहुत दिक्कत उठानी पड़ी थी। मुसलमानोंको कांग्रेससे अलग रखनेकी कोशिश भी इसी समय शुरू हुई। मुसलमानोंके नेता सय्यद अहमद खाँ मुसलमानोंको राजनीतिसे अलग रखना चाहते थे। इसके कई कारण थे। पहले तो वे सरकारको अपने सम्प्रदायका विरोधी नहीं बनाना चाहते थे। सिपाही-विद्रोहके पश्चात् सरकार मुसलमानोंसे बहुत नाराज थी, क्योंकि उन्होंने इस विद्रोहमें अच्छा खासा हिस्सा लिया था। मुसलमानोंने अंग्रेजी-शिक्षासे लाभ नहीं उठाया, क्योंकि उनका खयाल था कि उनके लड़के यदि अंग्रेजी स्कूलोंमें पढ़ने जायँगे तो नास्तिक बन जायँगे। अंग्रेजी-शिक्षासे विमुख रहनेका दूसरा कारण यह था कि इन अंग्रेजी स्कूलोंमें धार्मिक शिक्षाका कोई प्रबन्ध न था और अध्यापक प्रायः हिन्दू या ईसाई होते थे। बाज लोगोका यह भी खयाल था कि शरहके अनुसार अंग्रेजी-शिक्षा प्राप्त करना मना है। उनकी यह भी धारणा थी कि अंग्रेजी-शिक्षासे कोई लाभ नहीं है और उससे उनका नैतिक अधःपतन ही होगा। अंग्रेजी न पढ़नेके कारण मुसलमानोंको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती थी। बहुतोंकी जमीन्दारियाँ जप्त कर ली गयी थी। मुगल सल्तनतके नष्ट हो जानेके कारण उनको फौजमें अब ऊँचे-ऊँचे

ओहदे भी नहीं मिलते थे । एक प्रकारसे मुसलमानोंकी आर्थिक अवस्था इस समय बहुत हीन हो गयी थी । हिन्दुओंने अंग्रेजी-शिक्षासे पूरा लाभ उठाया और इसलिए सरकारी नौकरियाँ विशेषकर उनको ही मिलती थी । सन् १८२३ मे वहाबियोंने सिक्खोंके खिलाफ जिहादकी घोषणा की थी । इससे अंग्रेजोंका यह खयाल हुआ कि मुसलमान-धर्म विधर्मियोंके विरुद्ध जिहाद करनेकी शिक्षा देता है । सय्यद अहमद खाँ सरकारी मुलाजिम रह चुके थे । इन्होंने कई पुस्तके लिखकर इस बातके दिखलानेकी कोशिश की कि सिपाही-विद्रोहमे मुसलमानोंने हिन्दुओंकी अपेक्षा अधिक हिस्सा नहीं लिया था और उस समय भी बहुतसे मुसलमानोंने सरकारकी सहायता की थी । उन्होंने यह भी दिखलाया कि इस्लाम विधर्मी राजाओंके प्रति भी राजभक्त रहनेकी शिक्षा देता है और जिहाद केवल ऐसे राजाके विरुद्ध ही घोषित किया जा सकता है जिसके राज्यमे मुसलमानोंको धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त न हो । उन्होंने मुसलमानोंको अंग्रेजी शिक्षाके लिए प्रोत्साहित किया । अंग्रेजोंकी भी इस समय यही धारणा हो रही थी कि मुसलमानोंके विरोधके परिहारका यदि कोई उपाय है तो यही है कि उनको अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए तैयार किया जाय । सैयदअहमद खाँने अलीगढमे 'मोहमडन एग्लो ओरिएण्टल कालेज'की स्थापना की जहाँ और विषयोंके साथ-साथ इस्लाम धर्मकी शिक्षाका भी प्रबन्ध किया गया था । लार्ड नार्थ ब्रुकने इस सस्थाको दस हजार रुपया दानमे दिया और लार्ड लिटनने सन् १८७७ मे शिलान्यास-संस्कार किया । सैयद अहमद खाँका कहना था कि मुसलमानोंको अपनी सारी शक्ति शिक्षाके कार्यमे लगा देनी चाहिये । उनका खयाल था कि जबतक मुसलमान शिक्षित नहीं हो जाते तबतक वे कांग्रेसके आन्दोलनके फलस्वरूप जो अधिकार उनके देशवासियोंको प्राप्त होंगे उनसे लाभ नहीं उठा सकेंगे । इसके अतिरिक्त कांग्रेसमें सम्मिलित होनेसे सरकार भी मुसलमानोंसे नाराज होगी । इन विविध कारणोंसे उन्होंने मुसलमानोंको कांग्रेसमे शरीक होनेसे रोका ।

उस समयके कांग्रेसके नेता ब्रिटिश सरकारकी नेकनीयतीपर विश्वास रखते थे और उनका यह खयाल था कि ज्यों-ज्यों भारतीय अपनेमे योग्यता प्रतिपादित करते जायेंगे त्यों-त्यों सरकार उनके न्यायोचित अधिकार उनको प्रदान करती जायगी । उनका विश्वास था कि भारतमे अंग्रेजोंका आगमन इतिहासकी एक आकस्मिक घटना नहीं है ; बल्कि भारतके कल्याणके लिए ही ईश्वरकी प्रेरणासे इस जातिका यहाँ आगमन हुआ है । ब्रिटिश शासन उनकी दृष्टिमे एक अच्छा शासन था । इसने देशमे शान्ति स्थापित की थी और उनको यह आशा थी कि अंग्रेजी शिक्षाके प्रचारसे देशका अन्धकार दूर होगा । वह अपने समाजकी दुर्बलताको अच्छी तरह पहचानते थे । वह देखते थे कि भारतीय अशिक्षित हैं और उनमे अनेक सामाजिक कुरीतियाँ पायी जाती हैं । उनका विचार था कि भारतवासी अभी इस योग्य नहीं हैं कि अपने देशका राज्य-प्रबन्ध स्वयं कर सकें । ह्यूम महाशयने अपनी इलाहावादकी वक्तृतामें कहा था कि हमसे यह कहा जाता है कि कांग्रेसके लोग शासनकी वागडोर अपने हाथमे लेना चाहते हैं, पर सच्ची बात यह है कि कांग्रेसवाले ही सबसे ज्यादा इस बातको पहचानते हैं कि भारतीय किसी प्रकार भी शासन

करनेकी योग्यता अभी नहीं रखते और इसीलिए वे भारत और इङ्गलैण्डके सम्बन्धको दृढ़ बनानेके लिए परम उत्सुक हैं। कांग्रेसके नेताओंको राजभक्त होनेका बड़ा गर्व था। लार्ड लिटनके समयमें जब 'बर्नार्डियुलर प्रेस ऐक्ट' पास हुआ था तब बर्नार्ड महागजने यह कहकर उसका विरोध किया था कि इससे भारतीयोंकी राजभक्तिपर धब्बा लगता है। उन्होंने रानी विक्टोरिया तथा इङ्गलैण्डके राजनीतिज्ञोंके सन्देश और वक्तृताओंसे उद्धरण देकर इस बातको प्रमाणित करनेकी चेष्टा की थी कि भारतीयोंकी राजभक्ति असन्दिग्ध है। ब्रिटिश शासकोंकी घोषणाओंपर उनका बड़ा विश्वास था और वे सदा अपने समर्थनमें इनको पेश किया करते थे। धीरे-धीरे उनकी मोह-निद्रा टूटने लगी और वे वास्तविक स्थितिको समझने लगे। लार्ड रिपनके शासनकालके ठीक बाद ही कांग्रेसका जन्म हुआ था। लार्ड रिपन एक लोकप्रिय शासक थे। भारतीयोंका पक्ष लेकर वह अंग्रेजोंमें बहुत बदनाम हो गये थे। स्थानीय स्वायत्त-शासनकी नींव उन्होंने डाली थी। कांग्रेसकी स्थापनामें लार्ड डफरिनकी भी सम्मति थी। एक अंग्रेज महागजने ही कांग्रेसको जन्म दिया था। जिस स्थितिमें कांग्रेसकी स्थापना हुई वह अंग्रेजोंके बहुत अनुकूल थी। सरकारकी सहानुभूतिको देखकर उनको सहज ही विश्वास होता था कि भारतीय सरकार शिक्षित समुदायके उद्देश्योंसे सहानुभूति रखती है। जब डलवर्ट विलका घोर विरोध एंग्लो-इण्डियन समुदायने किया तो भारतमें रहनेवाले अंग्रेज व्यापारी और सम्पादकोंसे उनको कोई आशा न रही। आगे चलकर जब सरकारने कांग्रेसका विरोध करना शुरू किया तब उनकी यह भी धारणा होने लगी कि भारतीय सरकारसे हमको न्यायकी आशा न रखनी चाहिये। कांग्रेस प्रतिवर्ष जिन प्रस्तावोंको पास करती थी उनका कोई भी प्रभाव भारतीय सरकारपर नहीं पड़ता था। उनकी एक साधारण माँग भी पूरी न की जाती थी। कांग्रेस चाहती थी कि फौजका खर्च घटा दिया जाय, भारतकी गरीबीके कारणोंका अनुसन्धान किया जाय, भारतमें भी सिविल सर्विसकी परीक्षाका प्रवन्ध हो, नमक-कर घटाया जाय, व्यवस्थापक सभाओंके सदस्योंकी सख्यामें वृद्धि की जाय, नाम-जदगीके साथ-साथ चुनावका क्रम भी चलाया जाय और इन सभाओंके सदस्योंको सरकारसे प्रश्न पूछने तथा बजटपर वाद-विवाद करनेका अधिकार दिया जाय। चूँकि वे एंग्लो-इण्डियनोंको भारतवासियोंका विरोधी समझते थे, इसलिए कांग्रेसने यह भी प्रस्ताव किया कि इण्डिया-कौंसिल तोड़ दी जाय, पर इन प्रस्तावोंमेंसे एक भी प्रस्ताव स्वीकृत न हुआ। सन् १८६२ के पहले शासन-सम्बन्धी सुधार भी नहीं हुए थे और सन् १८६२ में जो सुधार किये गये थे वह कांग्रेसकी माँगसे कहीं कम थे। भारतीय सरकारके रवैयोंको देखकर सन् १८८६ में कांग्रेसके नेताओंने यह निश्चय किया कि इङ्गलैण्डमें बड़े पैमानेपर आन्दोलन करना चाहिये। इङ्गलैण्ड-निवासियोंसे उनको न्यायकी आशा थी। सन् १८८६ में इङ्गलैण्डमें कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी कायम की गयी। बादको 'इण्डिया पार्लेमेण्टरी कमेटी' का संगठन किया गया और 'इण्डिया' नामक पत्र प्रकाशित किया गया। लेकिन धीरे-धीरे कुछ लोग इस विचारके होने लगे कि केवल वक्तृताओं और प्रस्तावोंसे कुछ होनेका नहीं है। धीरे-धीरे ब्रिटिश सरकारपरसे विश्वास उठने लगा और इस ध्रुव

सत्यका उदय होने लगा कि जो अपने पैरोंपर नहीं खड़ा होता उसकी ईश्वर भी सहायता नहीं करता । लार्ड कर्जनके शासनकालमें कई ऐसी घटनाएँ हुई जिनसे इस विचारके लोगोकी संख्यामें तेजीके साथ वृद्धि होने लगी । कर्जनके समयमें भारत महामारी तथा अकालसे कई बार पीड़ित हुआ था । जनताकी आर्थिक दशा भी शोचनीय थी । गल्लोर्के मँहगे हो जानेसे नौकरी पेशा लोग कष्टमें थे । जनताकी अशान्ति बढ़ती जाती थी । सरकारको विवश होकर आर्थिक अवस्थाकी जाँच करानी पड़ी और अकालके समय कई प्रकारसे सहायता पहुँचानेके सम्बन्धमें नियम भी बनाने पड़े । सन् १९०१ में कृषि-विभाग खोला गया और सन् १९०४ में सहयोग समितिका कानून पास हुआ, पर इन छोटे-छोटे सुधारोंसे कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा । यह सुधार मौलिक नहीं थे । कांग्रेसका इस सम्बन्धमें कुछ और ही मन्तव्य था । कांग्रेसका कहना था कि जबतक बन्दोबस्त हर जगह स्थायी नहीं हो जाता और इङ्गलैण्डको जो धन भारतसे जाता है उसका जाना बन्द नहीं होता तबतक भारतवर्षकी गरीबी दूर नहीं हो सकती । आज हम इस बातको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कांग्रेसने उस समय भारतकी गरीबी दूर करनेके जो उपाय उचित समझे थे उनसे उद्देश्यकी सफलता नहीं हो सकती थी । इन उपायोंको प्रयोगमें लानेसे अधिकतर जमीन्दार और मध्यम श्रेणीके लोगोको ही फायदा पहुँच सकता था । इससे उनकी मनोवृत्तिका पता अवश्य चलता है । सन् १९०१ से कांग्रेस औद्योगिक शिक्षापर भी जोर देने लगी । सन् १९०१ में प्रथम बार कांग्रेसके साथ-साथ एक प्रदर्शनी भी हुई थी ।

लार्ड कर्जन उच्च कोटिकी शिक्षापर सरकारी नियन्त्रण चाहते थे । उस समय विश्वविद्यालयोंके सिनेट और सिण्डिकेटमें भारतीयोंका अच्छा प्रभाव था । वह इन संस्थाओंका पुनः सगठन कर उनके प्रभावको घटाना चाहते थे । सन् १९०४में 'यूनिवर्सिटीज ऐक्ट' पासकर ऐसी व्यवस्था की गयी जिससे गरीबोंके लिए ऊँची शिक्षाका प्राप्त करना कठिन हो गया । सिण्डिकेटके अधिकार नियमित कर दिये गये । शिक्षा-संस्थाओंके कड़े निरीक्षणका प्रबन्ध किया गया । शिक्षा-विभागके डाइरेक्टर-जनरलकी नयी जगह कायम की गयी । भारतीयोंकी यही धारणा हुई कि सरकार इन उपायोंद्वारा विश्वविद्यालयोंकी स्वतन्त्रता छीनना चाहती है और उनको सरकारी विभागमें परिणत करना चाहती है । इस कानूनसे अंग्रेजी शिक्षितवर्गमें बड़ा असन्तोष फैला; क्योंकि उन्होंने इस विधानका यह अर्थ लगाया कि सरकार उनके बढ़ते हुए प्रभावको रोकना चाहती है । लार्ड लिटनकी तरह लार्ड कर्जन भी अंग्रेजी शिक्षित भारतीयोंको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते थे । कलकत्ता विश्वविद्यालयके पदवी-दान-समारम्भके अवसरपर लार्ड कर्जनने चान्सलरकी हैसियतसे जो वक्तृता दी थी उसमें उन्होंने भारतीय सभ्यतामें छिद्रान्वेषण किया था । उनका कथन था कि भारतीयोंको सत्यका वैसा आग्रह नहीं है जैसा यूरोपियनोंको होता है । एक प्रकारसे पूर्वी सभ्यतापर ही उन्होंने आक्रमण किया था । इससे हिन्दूस्तानियोंको बहुत चोट लगी और बहुत मानसिक क्लेश पहुँचा । सन् १९०५ में वग-विच्छेद कर कर्जनने मानो बढ़ती हुई अशान्तिकी आगमें पूर्णाहुति दी । सरकारका

कहना था कि शासनकी सुविधाकी दृष्टिसे ही बंगालके दो टुकड़े किये जाते हैं, पर बङ्गालियोंके विचारमें इसमें एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ था। उनका खयाल था कि इस प्रकार सरकार बङ्गालियोंकी शक्तिको क्षीण और कलकत्तेकी राजनीतिक प्रधानताको नष्ट करना चाहती है। पूर्वोक्त बंगाल और आसामका एक नया प्रान्त बनाकर बंगाली मुसलमानोंको सरकार यह दिखलाना चाहती थी कि उन्हींके लाभके लिए बंग-विच्छेद किया जा रहा है। बंगालियोंने इस निश्चयका घोर विरोध किया। पहले जगह-जगह सभा कर और आवेदनपत्र भेजकर सरकारको जनताके रोप और असन्तोषसे परिचित कराया। बंगालियोंने दृढ़-संकल्प कर लिया कि हम बंगालका विच्छेद न होने देंगे। जब प्रार्थना और वित्तसे काम न चला तो बंगाली नेताओंने स्वदेशी वस्तुओंके प्रचार और विलायती वस्तुओंके बहिष्कारका आन्दोलन आरम्भ किया। उन्होंने यह समझा कि अंग्रेजोंका मुख्य स्वार्थ व्यापार है और जबतक इस स्वार्थपर आघात न पहुँचाया जायगा तबतक सरकार जनताकी प्रार्थनाको न सुनेगी। बंगालमें एक अपूर्व-जागृतिके चिह्न दिखलायी पड़ने लगे। 'बन्देमातरम्' के पवित्र शब्द हर जगह सुनायी देने लगे। स्वदेशी और वायकाटकी धूम मच गयी। कांग्रेसने बंगालके नेताओंके इस निर्णयको स्वीकार किया और अन्य प्रान्तोंने भी बंगालके साथ सहानुभूति दिखलायी। इसी समय कांग्रेसमें एक नये दलकी प्रतिष्ठा हुई जिसे लोग गरम दलके नामसे पुकारने लगे। मिस्रमें भी राष्ट्रवादियोंमें 'इन्तिहा पसन्द' नामक एक दल था। अंग्रेज सम्पादकोंने शायद मिस्रकी देखा-देखी भारतीय दलोंका ऐसा नामकरण किया था। इस समय कांग्रेसमें नरम दलका आधिपत्य था। गरम दलके प्रमुख नेताओंमें लोकमान्य तिलक, श्री विपिनचन्द्र पाल, श्री अरविन्द घोष और लाला लाजपतराय थे। इस दलका प्रभाव बंगाल और महाराष्ट्रमें विशेष रूपसे था। धीरे-धीरे इस दलके अनुयायी बढ़ने लगे। यह दल आत्म-निर्भरतामें विश्वास करता था। इस दलका कहना था कि अपने ही प्रयत्न और परिश्रमसे, न कि दूसरोपर आश्रित होकर, दासताके बन्धनसे कोई जाति मुक्त हो सकती है। राजनीतिके क्षेत्रमें जहाँ नरम दलका ध्येय औपनिवेगिक स्वराज्य था वहाँ गरम दलका ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता था। नरम दल वैध उपायोंद्वारा ही अपने उद्देश्योंकी पूर्ति चाहता था। इसके विरुद्ध गरम दलका कहना था कि जो देश परतन्त्र है उसके पास कोई शासन-विधान नहीं है जो उसको मान्य हो सके। उनका यह कहना था कि प्रत्येक देशको इस बातका पूरा अधिकार है कि वह सब प्रकारके उपायोंद्वारा अपनी स्वतन्त्रता अर्जित करे। पर भारतकी वर्तमान स्थितिको देखते हुए हमारे लिए यह उपयुक्त न होगा कि हम सरकारके कानूनको तोड़ें, पर समय आनेपर यदि हम ऐसा करें और हमको सफलता मिले तो इतिहास हमारे कार्योंकी प्रशंसा ही करेगा और इस कार्यके लिए हम दोषी न ठहराये जावेगे। वह राष्ट्रीय आन्दोलनको एक आध्यात्मिक आन्दोलन समझते थे। उनको अपने देशवासियोंपर विश्वास था। वह समझते थे कि जातिकी सूत्रात्मा इस आन्दोलनद्वारा अपनेको परिपूर्ण करेगी। उनका विश्वास था कि दृढ़ संकल्प, आत्मत्याग और सङ्गठनद्वारा राष्ट्रका उत्थान अवश्यम्भावी है और किसी-न-किसी दिन इस अभागे देशमें भी स्वराज्यकी स्थापना होगी।

इस दलके कई नेता धार्मिक प्रवृत्तिके थे और वे अपने देशके उज्ज्वल भविष्यमें पूर्ण विश्वास रखते थे । उन्होंने 'रचनात्मक कार्य' आरम्भ कर दिया । देशी कारखाने जगह-जगह खुलने लगे । राष्ट्रीय पक्षके समाचार-पत्र प्रकाशित होने लगे और आन्दोलनने एक तीव्र रूप धारण किया । सन् १९०६ की कलकत्ता-कांग्रेसमें श्री दादाभाई नौरोजीने 'अपनिवेशक शासन' इन शब्दोंका प्रयोग न कर पहले-पहल स्वराज शब्दका प्रयोग किया था । धीरे-धीरे यह एक मन्त्र हो गया । लोकमान्यका कहना था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसको प्राप्त करेंगे । इस समय एक ऐसी घटना हुई जिससे सारा संसार विशेषकर एशियाके देश प्रभावित हुए । ८ फरवरी, १९०४ को रूस-जापानका युद्ध आरम्भ हुआ । इस युद्धमें जापानने रूस ऐसे बलशाली यूरोपीय राष्ट्रको पराजित किया । अबतक बार-बार विताडित होनेके कारण एशियावासियोंकी यह धारणा हो गयी थी कि वे यूरोपके राष्ट्रोंका मुकाबिला नहीं कर सकते । एशियाके करीब-करीब सब राष्ट्र यूरोपके साम्राज्यवादियोंके आतंकसे त्रस्त थे । जापान ऐसे छोटे देशने यूरोपके एक विशाल राष्ट्रपर विजय प्राप्त की — इस घटनाने भारत आदि देशोंको अत्यन्त प्रभावित किया । एशियावासी यूरोपकी शक्तिका रहस्य समझ गये । उन्हें मालूम हुआ कि यदि हम भी यूरोपका अनुकरण कर शक्तिका संचय करें तो उससे अवश्य टक्कर ले सकते हैं । उनको अपने ऊपर विश्वास हुआ और मायाका परदा हट गया । इसी समयसे एशियाके पददलित और दुर्बल देशोंमें राष्ट्रीयताकी एक नयी लहर प्रवाहित हुई और स्वाभिमानकी रेखा लक्षित होने लगी । चीनने अपने घरका सुधार करना शुरू किया । यूरोपीय पद्धतिके अनुसार सन् १९०५ में सेनाकी शिक्षा आरम्भ हुई । नवीन शिक्षाका आयोजन किया गया । शासन-प्रणालीमें आवश्यक परिवर्तन करनेके विचारसे अमेरिका, जापान और यूरोपके देशोंमें शासन-विधानोंका अध्ययन करनेके लिए एक कमीशन नियुक्त हुआ । सन् १९०८ में एक घोषणा की गयी कि ६ वर्षके उपरान्त प्रतिनिधि सत्तात्मक शासनकी स्थापना की जावेगी और इस बीचमें देशको इन सुधारोंके लिए तैयार किया जायगा । सन् १९०६ में फारसके शाहको शासन-विधान बदलना पड़ा जिसके अनुसार एक मजलिसकी स्थापना करनेकी घोषणा की गयी । इसको बहुतसे अधिकार दिये गये । फारसका राष्ट्रीय दल यूरोपीय शक्तियोंसे अपने देशकी रक्षा करना चाहता था और शासनमें सुधार करनेकी उसकी उत्कट अभिलाषा थी । सन् १९०५ में रूसमें क्रान्ति हुई और जारको शासनमें सुधार और ड्यूमाकी स्थापना करनी पड़ी । सन् १९०८ में तुर्क युवकोंने तुर्कीमें एक क्रान्ति की जिसका फल यह हुआ कि सुलतान अब्दुल हमीद पदच्युत किये गये । जापान उस समय एशियाके दुर्बल राष्ट्रोंका संरक्षक समझा जाता था । सब जगह शासन-सुधारकी चर्चा आरम्भ हो गयी । जहाँ स्वेच्छाचारी राजा थे वहाँ वैध शासनकी स्थापनाका उद्योग किया गया । यूरोपकी राष्ट्रीयताका सर्वत्र प्रचार होने लगा । विदेशियोंसे अपने देशको बचानेकी भावना काम करने लगी । भारत भी इन व्यापक प्रभावोंसे बच न सका । यहाँ भी इन नवीन विचारोंका उपक्रम हुआ । क्षेत्र तैयार हो चुका था । जापानकी विजयसे देशभक्तोंको

एक नवीन स्फूर्ति मिली। लोगोंके घूमे हुए दिल रोशन हो गये और ऊर्जा जारी और निराशाका साम्राज्य था वहाँ आशाकी धीण देखा दिया। पहले नवी। स्वदेशीय प्रचार बढ़ने लगा। कलकत्तेके विद्यार्थियोंने निदेशी माननीय दूकानोंपर धरना देना आरम्भ किया। हर साल दुर्गापूजाके अवसरपर कलकत्तेके भारतीयोंने अपने अपने विषय मेचेस्टरके एजेण्टोंमें नाचो रणयोग मोक्ष करने थे, परन्तु १९०५ में एक भी मोक्ष नहीं हुआ। विद्यार्थियोंको आन्दोलनके प्रथम स्तरके लिए कागजात सङ्गठित निकाला गया। इस सङ्गठनके अनुसार स्कूल और कॉलेजके विद्यार्थियोंको शिक्षा दिया गया कि यदि वे दूकानोंपर धरना देगे या राजनीतिक गथाओं या उद्योगोंमें शरीर होने या स्वदेशी मातृस्का धोप करेगे तो उनको दण्ड दिया जायगा। चन्देमातरम्का प्रयोग करना गुरुतर अपराध समझा जाता था कि उन्हींके लिए रंगपुर स्कूलके सब विद्यार्थियोंको प्रेरित किया गया था। जब विद्यार्थियोंने जमाना देनेमें इनकार दिया तब वे स्कूलमें विद्रोह दिये गये। फल यह हुआ कि उन घटनाके तत्पश्चात् एक नतीजा के भीतर ही रंगपुरमें एक राष्ट्रीय विद्यालयकी स्थापना हो गयी। कलकत्तेके सङ्गठनके प्रभावमें केनाथोंने शिक्षार्थी कार्यको अपने हाथमें लेनेका विचार किया। कलकत्तेमें एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया।

किसी-किसी जिलेमें स्वदेशी और वहिष्कारका विशेष रूपसे प्रचार था। इस समयमें वारीसालकी एक घटना उल्लेखनीय है। वारीसालमें भी अश्विनीकुमार दत्तका प्रभाव था। उनका प्रभाव जनतापर बहुततक था कि बिना उनकी अनुमतिके किसीको बाजारमें एक गज भी बिनायती कपड़ा नहीं मिल सकता था। एक बार कदाचि शक्ति अंग्रेज मैनेजरको कुछ विलायती कपड़ा खरीदनेकी जरूरत पड़ी। जब उनकी दूकानमें कपड़ा न मिला तो उन्होंने पुलिस सुपरिटेण्डेण्टकी सहायता ली। पुलिसका प्रयत्न भी निष्फल हुआ। इसकी शिकायत जिला मजिस्ट्रेटने की गयी। जिला मजिस्ट्रेटने पत्र लिखकर अश्विनी बाबूमें अनुमति देनेकी प्रार्थना की। अश्विनी बाबूने अनुमतिमें दूकानदारने उस अंग्रेजके हाथ कपड़ा बेचना स्वीकार किया। अश्विनी बाबूका यह प्रभाव सरकारको बहुत अद्भुत। उस समय पूर्वी बंगाल और आसाममें लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर साहब थे। यह राष्ट्रीय पक्षके लोगोंसे बहुत नाराज थे। एक बार जब यह शक्त गये थे तब वहाँके विद्यार्थियोंने उनके स्वागतका वहिष्कार किया था और यह गहने बाहर पिकनिकके लिए चले गये थे। जब उन्हें वारीसालकी स्थिति मालूम हुई तो वह फौरेन लार्ड कर्जनसे मिलनेके लिए आगरेके लिए रवाना हुए। वहाँ लार्ड कर्जनसे परामर्श कर भविष्यकी नीति निर्धारित की गयी। आसामकी सुरमा मिनिस्टरी पुलिसको वारीसाल जानेका तारद्वारा आदेश दिया गया। जब फुलर साहब वारीसाल गये तब उन्होंने अश्विनी बाबू तथा उनके सहकारियोंका चुले तौरसे अपमान किया। सरकारको यह दिखलाना था कि जिन अश्विनी बाबूपर लोग इतना निर्भर करने हैं और जिनको वे अपना नेता मानते हैं उनकी सरकारकी निगाहमें कोई कीमत नहीं है और सरकारकी शक्तिके सामने वह एक तिनकेके बराबर है। इसी समय वारीसालमें कान्फरेंस हुई थी जिसमें

वज्जालके वड़े-वड़े नेता सम्मिलित हुए थे । एक जुलूस निकाला गया था । जुलूसके लिए कोई आज्ञा नहीं ली गयी थी, पर राह चलतोंको कोई तकलीफ न हो इस खयालसे आधी सड़क खाली छोड़ दी गयी थी । पुलिसने जुलूसको तितर-वितर करनेके लिए जुलूसपर लाठी-प्रहार शुरू किया । किसीने वुजदिली नहीं दिखलायी । दृढ़ताके साथ लोग इस प्रहारको सहन करते रहे । इस प्रकार सरकार उनका अपकर्ष न कर सकी । पूर्वी वगालके कुछ जिलोमे अदालतोंका भी वहिष्कार किया गया था और पचायते कायम कर दी गयी थी । वगालके गरम दलके नेता 'वहिष्कार'का व्यापक अर्थ करते थे । वहिष्कारसे केवल विदेशी मालका वहिष्कार नहीं समझा जाता था । वहिष्कारका अर्थ था सरकारसे धीरे-धीरे अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर लेना । श्री विपिनचन्द्र पालने—जो उस समय राष्ट्रीयताके ऋषि समझे जाते थे—मद्रासके अपने एक व्याख्यानमे कहा था कि हम इस बातका प्रयत्न करेंगे कि लोग धीरे-धीरे सरकारसे सहयोग करना छोड़ दे । उन्होंने इसे स्वीकार किया कि यह सम्भव नहीं है कि सब लोग सरकारकी नौकरी छोड़ दे, पर वहिष्कारसे एक लाभ अवश्य होगा कि सरकारी नौकरोका आज जो असाधारण आदर और सम्मान है वह बहुत घट जायगा । उनका कहना था कि सरकारी नौकरोका सामाजिक वहिष्कार करके उनका प्रभुत्व नष्ट किया जा सकता है । पाल महाशय तो सरकारके मुकाबलेमे अपना स्वतन्त्र शासन-चक्र स्थापित करना चाहते थे । उनकी शिक्षा थी कि हमको गाँवों और जिलोंका संगठन करना चाहिये और अपने अन्दर शक्ति पैदा कर धीरे-धीरे उन सारी संस्थाओंको स्थापित करना चाहिये जो आज सरकारद्वारा संचालित हो रही हैं । सरकारकी ओरसे दमन जोरोंसे शुरू हो गया । आन्दोलनको दवानेके लिए कई नये कानून बनाये गये । १९०७ मे राजनीतिक सभाओंको रोकनेके लिए एक कानून बनाया गया । इसी वर्ष लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंहको १८१८ के रेगुलेशन ३ के अनुसार देश-निर्वासनका दण्ड दिया गया । इस दमनके कारण देशमे विप्लवकारियोंका एक दल भी पैदा हो गया । कई राजनीतिक हत्याएँ हुईं । इसलिए सरकारने कई और कानून बनाये । समितियोंको बन्द करनेके लिए और पड़्यन्त्रके मुकद्दमोंमे सरसरी फैसला करनेके लिए १९०८ मे 'क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट' पास हुआ । जुलाई १९०८ मे लोकमान्य तिलकको ६ वर्ष कारावासका दण्ड मिला और वगालके नौ प्रसिद्ध नेता दिसम्बर मासमे निर्वासित कर दिये गये । १९१० मे 'प्रेस एक्ट' पास करके प्रेसकी स्वतन्त्रता छीन ली गयी । इसके पहले ही १९०७ मे सूरतकी कांग्रेसके अवसरपर नरम और गरम दलके बीच झगडा हो गया था । गरम दल कांग्रेससे अलग हो गया । १९१६ तक नरम दलका कांग्रेसपर एकाधिकार रहा । लोकमान्य १९१४ मे जब माण्डले जेलसे छूटकर वापस आये तो उन्होंने दलका फिरसे संगठन किया और श्रीमती एनी बेसेण्टके उद्योगसे १९१६मे दोनों दलोंमे एकता हो गयी ।

लार्ड कर्जनके उत्तराधिकारी लार्ड मिण्टो इस बातको अच्छी तरह समझते थे कि भारतवासियोंको और अधिकार दिये बिना देशका असन्तोष दूर नहीं किया जा सकता । उन्होंने १९०६ मे ही इस बातपर बहुत जोर दिया था कि सरकारको अपनी इच्छासे स्वयं

सुधारोकी सिफारिश करनी चाहिये और लोगोको इस बातके कहनेका अवसर नही देना चाहिये कि भारतीय सरकार केवल ब्रिटिश सरकारके दबावसे अथवा आन्दोलनके प्रभावसे विवश होकर ही कुछ करनेको तैयार होती है। इसीलिए उन्होने १९०६मे सुधारोपर विचार करनेके लिए अपनी कौंसिलकी एक उपसमिति नियुक्त की थी। नया कानून १९०६मे बना। इसके अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाग्रोमे ही गैर सरकारी सदस्योका बहुमत रखा गया। केन्द्रीय व्यवस्थापक सभापर सरकार अपना अधुष्ण अधिकार रखना चाहती थी। इसलिए केन्द्रीय व्यवस्थापक सभामे सरकारी सदस्योका ही बहुमत रखा गया। सुधारके सम्बन्धमे भारत-सरकारकी ओरसे प्रान्तीय सरकारोके पास जो सरकुलर भेजा गया था उसमे यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि इस सुधार-योजनामे ब्रिटिश-अधिकार और प्रभुत्वके परित्याग करने या उसे कम करनेका कोई विचार नही है। इन व्यवस्थापक सभाओके सदस्योकी संख्यामे भी वृद्धि की गयी। सदस्योको बिल और प्रस्ताव उपस्थित करनेका अधिकार मिला। बजटपर वाद-विवाद करनेका उन्हें पूरा मौका दिया गया, लेकिन इन सभाओको कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त न थे। सरकार इनके स्वीकृत प्रस्तावोको भी रद्द कर सकती थी, इसलिए इन्हे एक प्रकारकी वाद-विवाद सभाएँ ही समझना चाहिये। यद्यपि इन सुधारोमे कुछ सार न था; तथापि नरम दलके नेताओने उस समय इन सुधारोकी बड़ी प्रशंसा की थी और उन्हे उदारतापूर्ण बतलाया था। इन सुधारोके द्वारा एक बात अवश्य हुई कि चार-पाँच भारतवासियोको भारत-सचिवकी इण्डिया-कौंसिल, गवर्नर-जनरल और प्रान्तकी कार्यकारिणी समितिकी सदस्यता मिली। यह स्पष्ट है कि इन सुधारोसे सामान्य जनताको कोई लाभ नही हुआ। कुछ सालके अनुभवके पश्चात् नरम दलके नेताओको भी ये सुधार अपर्याप्त प्रतीत हुए। इस नयी योजनाके बनाते समय सरकारने इस बातपर ध्यान रखा था कि अंग्रेजी शिक्षित हिन्दुओका प्रभाव घटाया जाय। भारतीय सरकारके जिस सर्कुलरका हमने ऊपर उल्लेख किया है उसमे यह कहा गया था कि सरकार ऐसे वर्गोको विरोधाधिकार देकर राजनीतिके क्षेत्रमे लाना चाहती है जो हर प्रकारके परिवर्तनसे घबराते हैं और जिनकी यह कोशिश रहती है कि वर्तमान परिस्थिति सदाके लिए अपरिवर्तित रूपसे कायम रहे। इस दृष्टिसे उसने यह आदेश दिया कि सुधारकी कोई योजना वर्तमान समयकी आवश्यकताओको पूरा नही कर सकती जबतक कि उसमें बड़े जमीन्दार, व्यापारी और व्यवसायियोके उचित प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था न की जाय। मुसलमान प्रायः कांग्रेससे अलग रहें और वे राजभक्त समझे जाते थे। इस समय मुसलमान अपनी जातिमे शिक्षाका प्रचार करनेमे संलग्न थे। १८८६मे 'मोहमडन एजुकेशनल कान्फरेन्स'का आरम्भ हुआ जिसका अधिवेशन वर्षमे एक बार हुआ करता था। उनकी कोई राजनीतिक संस्था न थी। लार्ड मिण्टो मुसलमानोको विशेष प्रतिनिधित्व देना चाहता था। लार्ड मिण्टोके संकेतपर ही १९०६ मे सर आगा खानके नेतृत्वमे मुसलमानोका एक डेपुटेशन मिण्टोसे मिला था। मौलाना मुहम्मदअलीने कोकोनाडा कांग्रेसके अवसरपर सभापतिकी हैसियतसे जो भाषण किया था उसमे इस रहस्यको खोला था। माले साहबने भी अपने सस्मरणोमें

इसका उल्लेख किया है। लार्ड मिण्टोने मुसलमानोंको आश्वासन दिलाया कि नये शासन-विधानमें मुसलमानोंके स्वत्वकी रक्षाका पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा और पृथक् निर्वाचनद्वारा अपनी सख्यासे अधिक प्रतिनिधि चुननेका अधिकार उनको दिया जायगा। १९०६ में ही लार्ड मिण्टोके प्रोत्साहनसे मुस्लिम लीगकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारतमें बसनेवाली अन्य जातियोंके साथ स्नेह-भाव रखते हुए अपनी जातिके स्वत्वकी रक्षा करना था। लीगके उद्देश्योंमें मुसलमानोंकी राजभक्तिकी घोषणा की गयी थी। इस प्रकार पृथक् निर्वाचनकी प्रथाका आरम्भ हुआ। इससे साम्प्रदायिक भावोंको उत्तेजना मिली और मुसलमानोंकी देखा-देखी १९०६ में पंजावमें प्रान्तीय हिन्दू-सभाकी स्थापना हुई और यह निश्चय हुआ कि अगले वर्ष अखिल भारतवर्षीय हिन्दू-सभाका आयोजन किया जाय। मुस्लिम लीगके अधिवेशनकी काररवाईको देखनेसे यह प्रत्यक्ष है कि मुसलमानों-में साम्प्रदायिक भावनाकी वृद्धि होती चली गयी और वे हिन्दुओंकी शक्ति और प्रभावको कम करनेके उपाय सोचने लगे। उदाहरणके लिए सन् १९१० में मुस्लिम लीगने यह प्रस्ताव किया कि अगली मनुष्य-गणनामें अछूतोंको हिन्दू न लिखा जाय। उनका तर्क यह था कि अछूतोंको हिन्दुओंमें सम्मिलित करनेसे अछूतोंका काफी नुकसान होता है। उनकी शिक्षाकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती और हिन्दू निर्वाचन-क्षेत्रमें वे अपने सच्चे प्रतिनिधियोंको भी नहीं चुनवा सकते। इसके अतिरिक्त मुसलमानोंका भी नुकसान होता है; क्योंकि इस प्रकार हिन्दुओंको अपनी संख्यासे अधिक प्रतिनिधिन्व मिल जाता है। उन्होंने इस आशयका एक प्रार्थना-पत्र भी सरकारकी सेवामें भेजा, पर हिन्दुओंके घोर विरोधके कारण उनका आशय पूरा न हो सका। आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाएँ उपस्थित हुईं जिनके कारण मुसलमानोंके भाव धीरे-धीरे सरकारके प्रतिकूल होने लगे। कांग्रेस इस समय निस्तेज हो गयी थी और दमनके कारण राष्ट्रीय आन्दोलनकी गति मन्द पड़ गयी थी। गरम दलके प्रमुख नेता और कार्यकर्त्ता या तो जेलमें बन्द कर दिये गये थे या समयको अनुकूल न समझकर विदेश चले गये थे। इसलिए सरकारको इस समय हिन्दुओंसे कोई भय न था; तथापि वज्जालके हिन्दुओंके असन्तोषको दूर करनेके लिए १९११ में वज्ज-भङ्ग रद्द कर दिया गया। इससे मुसलमानोंकी आँखें खुली। वे अब धीरे-धीरे समझने लगे कि केवल हिन्दुओंको दुर्बल करनेके अभिप्रायसे ही सरकारने मुसलमानोंसे मित्रता बढ़ायी थी। वज्ज-भङ्गके समय मुसलमानोंसे कहा गया था कि तुम्हारे लाभके लिए ही वगालके दो टुकड़े किये जाते हैं। पूर्वी वज्जाल और आसामके प्रान्तमें मुसलमानोंकी जन-संख्या हिन्दुओंसे अधिक थी। ढाका इसकी राजधानी थी। अंग्रेजोंकी हुकूमतके पहले वगालकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी और ढाका उसका एक प्रसिद्ध नगर था। उनकी पुरानी स्मृतियाँ जागृत हो गयी थी और उनको यह आशा बँध गयी थी कि अपने जातीय विकासके लिए उनको उचित क्षेत्र मिल गया है। पर वज्ज-भङ्गके रद्द होनेसे इस आशापर पानी फिर गया। इसलिए मुसलमान सरकारसे बहुत असन्तुष्ट थे। इधर यूरोपमें सन् १९१२-१३ में तुर्कीका ईसाई ताकतसे युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध बालकन-युद्धके नामसे इतिहासमें प्रसिद्ध है। यह युद्ध मुसलमान और

ईसाइयोका युद्ध था । इस युद्धमे ब्रिटिश सरकारने ईसाइयोका साथ दिया । हिन्दुस्तानके मुसलमानोंकी सहानुभूति रवभावत तुर्कीसे थी ; क्योंकि तुर्कीका मुस्तान संसारके मुसलमानोंका खलीफा था और तुर्की इस्तामकी तलवार नमझा जाता था । हिन्दुस्तानके मुसलमानोंने जखमी तुर्कीकी सेवाके लिए बहुत-सा धन एकत्र किया और एक मिशन भी कुस्तुन्तुनिया भेजा । यहाँ वे तुर्कीके राष्ट्रवादी युवकोंके सम्पर्कमे आये । सन् १९०८ मे तुर्कीमे क्रान्ति हुई थी । इस क्रान्तिके नेता वे राष्ट्रवादी युवक तुर्क थे जिन्होंने फ्रांस या इङ्ग्लैण्डमे शिक्षा पायी थी । हिन्दुस्तानी मिशनके सदस्योंने उनसे यह सबक सीखा कि ब्रिटिश परराष्ट्र-नीतिका एक उद्देश्य इस्लामकी ताकतको कमजोर करना है । उन्होंने यह बतलाया कि अंग्रेजोंके कारण मुसलमानोंकी अवस्था बहुत शोचनीय हो गयी है । मिस्र अंग्रेजोंके कब्जेमे है । फारसके सम्बन्धमे अंग्रेजोंने रूससे समझौता कर लिया है कि उत्तरी फारसमे रूसका और दक्षिणी फारसमे अंग्रेजोंका प्रभाव रहेगा । मरक्कोके सम्बन्धमे भी अंग्रेजोंने फ्रांससे तस्फिया कर लिया है । अबतक हिन्दुस्तानके मुसलमानोंका खयाल था कि इङ्ग्लैण्ड तुर्कीका मित्र है, क्योंकि सन् १८५४ और १८७७ मे इङ्ग्लैण्डने रूसके विरुद्ध उसकी सहायता की थी, लेकिन सन् १९१२-१३ मे जो व्यवहार इङ्ग्लैण्डने तुर्कीके साथ किया उससे उनकी यह धारणा दूर हो गयी । उस समय इस्लाम-जगत्मे एक जागृति हो रही थी और सब मुसलमानोंको एक सूत्रमे ग्रथित कर देनेकी चेष्टा की जा रही थी । इस आन्दोलनको 'पान इस्लामिज्म' कहते हैं । यूरोपके राष्ट्रोंके आक्रमणने इस्लामकी रक्षा करनेके लिए ही इस आन्दोलनका जन्म हुआ था । मय्यद जमालुद्दीन अफगानी इस आन्दोलनका जन्मदाता समझा जाता है । इसका जन्म सन् १८३८ में हुआ था । इसका बाल्यकाल अफगानिस्तानमें व्यतीत हुआ । बुखारामें इमने शिक्षा प्राप्त की । वह अपने समयमें इस्लाम-जगत्का एक प्रसिद्ध दार्शनिक और पण्डित समझा जाता था । उसने कुछ दिनोतक कैरोके अलअजहर नामक विश्वविद्यालयमे अध्यापकका काम किया था । मिस्रके नवयुवकोपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव था । उसने नवयुवकोंमे राष्ट्रीयताका प्रचार किया । उसके धार्मिक विचार बड़े उदार थे । वह शासन और धर्ममे सुधार करनेका पक्षपाती था । अरबीपाशा, जिसने सन् १८८२ मे विटेजियोके विरुद्ध मिस्रमे आन्दोलन किया था, जमालुद्दीनका भक्त था । अधिकारिवर्ग जमालुद्दीनपर शक करता था । इसलिए सन् १८७९ मे वह मिस्रसे निकाल दिया गया । वह कुछ समयतक भारतवर्षमे भी रहा । फारसके शाह नसीरुद्दीनके निमन्त्रणपर वह फारस गया । वहाँ भी उसने प्रभावशाली लोगोंमे नवीन विचार फैलाये । जमालुद्दीनकी सलाहसे तुर्कीके सुलतान अब्दुल हमीदने खिलाफतकी सस्थाका पुनरज्जीवन किया और इस प्रकार यूरोपीय शक्तियोंके विरुद्ध इस्लाम-जगत्की सहानुभूति प्राप्त की । खिलाफत का पुराना गौरव नष्ट हो गया था । अब्दुल हमीदने इसके गौरवको फिरसे प्रतिष्ठित कर अपनी शक्ति बढ़ायी । सुलतानके दूत जगह-जगह खिलाफतका प्रचार करते फिरते थे । धीरे-धीरे सुलतान खलीफा स्वीकार किये जाने लगे और मुसलमान तुर्कीको इस्लामकी तलवार समझने लगे । जमालुद्दीन सन् १८९२में कुस्तुन्तुनियामे बस गया और वही

सन् १८६७ में उसकी मृत्यु हुई । मित्र, फारस और तुर्की में जो जागृति हुई उसकी आधार शिखा रखनेवाला जमालुद्दीन ही समझा जाता है । सन् १६१२-१३ के बालकन युद्ध ने भारत में भी 'पान इस्लामिज्म' के भाव को प्रबल कर दिया । इस आन्दोलन का मुख्य अभिप्राय ही यूरोपीय जातियों का विरोध करना था । भारत के जो मुसलमान इस आन्दोलन से प्रभावित हुए, वे अंग्रेजों के भी विरोधी हो गये । इन लोगों ने मुसलिम लीग पर कब्जा कर लिया और उसकी नीति बदल दी । आरम्भ में लीग की स्थापना कांग्रेस का विरोध करने के लिए हुई थी । सरकार का उद्देश्य इस बात को दिखलाना था कि मुसलमान केवल कांग्रेस से अलग ही नहीं हैं, बल्कि गवर्नमेंट के साथ हैं । मुसलिम लीग ने अवतक राजनीतिक सुधारों के लिए कोई उद्योग नहीं किया था, पर सन् १६१३ में लीग का उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति हो गया । हिन्दू-मुसलमानों की मैत्री बढ़ने लगी । कांग्रेस और लीग के वार्षिक अधिवेशन एक ही स्थान पर होने लगे । मुसलमान भी समझने लगे कि यदि हिन्दू-मुसलमान एक साथ मिलकर कार्य करें तो देश की राजनीतिक उन्नति सुगमता से हो सकती है । सर आगा खाँ सभापतिके पद से अलग हो गये और लीग में उन्नत विचार के लोगों का प्रभुत्व हो गया । सन् १६१५ में गोखले और फीरोजशाह की मृत्यु से नरम दल की शक्ति क्षीण हो गयी । सन् १६१६ में नरम दल और गरम दल में मेल हो गया और लखनऊ में दोनों दलों का संयुक्त अधिवेशन हुआ । धीरे-धीरे कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव बढ़ने लगा । सन् १६१६ में लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनीबेसेण्ट ने अपने-अपने होमरूल लीग की स्थापना की । देश में एक व्यापक आन्दोलन आरम्भ हो गया । सन् १६१४ में यूरोपीय महासमर का आरम्भ हुआ था । इसके कारण देश में बहुत अशान्ति थी । विप्लववादियों के आन्दोलन की भी गति तीव्र हो गयी थी । जर्मनी की सहायता से विप्लववादी इङ्ग्लैण्ड के शासन को नष्ट करना चाहते थे । 'अमेरिका की गदर पार्टी' की ओर से भेजे हुए बहुत से सिख विप्लव करने के लिए भारत आये । बङ्गाल और पंजाब में जगह-जगह राजनीतिक डकैतियाँ और हत्याएँ होने लगी । क्रान्तिकारी दिन भी निश्चित हो गया । २१ फरवरी सन् १६१५ को एक ही समय कई स्थानों में विप्लव होना निश्चित हुआ था, पर सरकार को इसका पता चल जाने से यह योजना असफल रही । सन् १६१५ में सरकार ने विप्लव का दमन करने के लिए 'डिफेंस आफ इण्डिया ऐक्ट' पास किया और इसके अनुसार बहुत से विप्लवकारी नजरबन्द कर लिये गये । होमरूल का आन्दोलन देहातो में भी फैलने लगा । सन् १६१७ में श्रीमती एनीबेसेण्ट नजरबन्द कर ली गयी । लखनऊ कांग्रेस के पहले ही बड़ी व्यवस्थापक सभा के १६ सदस्यों ने सुधार की एक योजना प्रकाशित की थी । सन् १६१६ में कांग्रेस और मुसलिम लीग की ओर से एक संयुक्त माँग पेश की गयी । इसी अवसर पर हिन्दू-मुसलमानों ने प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में एक समझौता कर लिया था जिसके अनुसार हिन्दुओं ने कई प्रान्तों में मुसलमानों को उनकी संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया था । यह समझौता 'लखनऊ पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध है । अमेरिका को युद्ध में सम्मिलित करने के लिए और भारतीयों को आश्वासन देने के लिए भारत-सचिव माटेगू को २० अगस्त सन् १६१७ को पार्लमेंट में एक

वक्तव्य देना पड़ा। इस वक्तव्यमें उन्होंने यह घोषित किया कि भारतको ब्रिटिश साम्राज्य-के अन्तर्गत क्रमशः दायित्वपूर्ण शासन प्रदान करना ब्रिटिश नीतिका उद्देश्य है। इस यात्रामें कितने विश्रामस्थान होंगे, उसका निर्णय करनेका अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंटके अधीन रहेगा। अंग्रेजोंकी ओरसे यह कहा जाता था कि वे सत्य, न्याय और मनारकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार इस युद्धमें अमेरिकाको अपने पक्षमें करना चाहती थी। संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके प्रेसीडेंट उडरो विल्सन उदार विचारके एक व्यक्ति थे। वह छोटे राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करना चाहते थे और उनका यह विचार था कि ऐसे उपायोंको काममें लाना चाहिये जिसमें युद्ध नदीके लिए बन्द हो जायें और राष्ट्र अपने झगड़ोंका निपटारा तलवारमें न कर किसी ऐसी पंचायत द्वारा करावें जिसका निर्णय सबको मान्य हो। यदि अंग्रेज केवल इनकी मौखिक घोषणा करते रहते कि वह छोटे राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रहे हैं और अपने ही साम्राज्यके अधीन देशोंके नायब न्यायका व्यवहार न करते तो उनको कौन सच्चा मानता। उन्हें मनारको विश्वास दिलाना था कि वह इस नीतिको जहाँतक उनका सम्बन्ध है कार्यान्वित करनेके लिए तैयार हैं। सन् १९१८में मांटैगू साहब भारतवर्ष आये और सबसे परामर्श कर उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

इस रिपोर्टके आधारपर सन् १९१९में पार्लमेंटने एक कानून बनाया। इसके द्वारा भारतीय व्यवस्थापक समाके सदस्योंकी संख्यामें वृद्धि की गयी। सब व्यवस्थापक सभाओंमें गैर-सरकारी चुने हुए सदस्योंका बहुमत हो गया। पार्लमेंटका भारतीय ज्ञानपर जो नियंत्रण था वह कुछ ढीला कर दिया गया। भारतीयोंको कुछ और ऊँचे पद प्रदान किये गये। एक खास बात यह हुई कि प्रान्तीय शासन दो भागोंमें विभक्त कर दिया गया। कुछ विषय सरकारके अधीन रखे गये। इन्हें सुरक्षित विषय कहते हैं। कुछ विषयोंका कार्य-भार भारतीय मन्त्रियोंके मुपुद् किया गया। इन विषयोंको हस्तान्तरित-विषय कहते हैं। गैर-सरकारी निर्वाचित सदस्योंमेंसे ही मन्त्रियोंका तिया जाना निश्चित हुआ। ऐसे शासनको द्विक्रम शासन (डायरकी) की संज्ञा दी गयी है। केन्द्रीय शासनमें ऐसा कोई विभाग नहीं किया गया। इस नवीन योजनाकी कल्पनाके मूलमें यह विचार काम करता है कि जहाँतक प्रान्तके शासनका सम्बन्ध है भारतवासियोंको छोटा हिस्सेदार बनाना चाहिये। सुधारकी इस योजनाके साथ-साथ हमको सरकारकी इस समयकी औद्योगिक नीतिपर भी विचार करना चाहिये। आलोचना करनेपर हमको यह मालूम होगा कि राजनीति तथा उद्योगके क्षेत्रमें समान रूपमें एक ही विचार काम कर रहा था। जिस प्रकार बड़े-बड़े मारवाडी व्यापारियोंके मुनीम अपने मालिकके कारोबारमें कभी-कभी छोटे-मोटे हिस्सेदार भी हो जाते हैं वैसे ही यूरोपीय युद्धके आरम्भ होनेके बाद सरकारने यह निश्चय किया कि हिन्दुस्तानियोंको सरकारी कारोबारमें छोटा-मोटा हिस्सेदार बना देना चाहिये। सन् १९१६में होमरूलका जो आन्दोलन आरम्भ हुआ उसके पहले ही बिना किसी दवावके लार्ड हार्डिजने सन् १९१५में अपने एक खरीतेमें भारत-मन्त्रीको यह लिखा था कि यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती जाती है कि युद्धके

पश्चात् भारतके उद्योग-व्यवसायको उन्नत करनेके लिए किसी एक निश्चित नीतिका अनुसरण करना पड़ेगा । उस समय भारतवासी एक स्वरसे सरकारसे इस औद्योगिक उन्नतिके लिए पूरी सहायता चाहेंगे । वाइसरायकी इस सिफारिशपर ब्रिटिश सरकारने सन् १९१६ मे 'इण्डियन इण्डस्ट्रियल कमीशन' को नियुक्त किया और उसको आदेश दिया कि वह इस बातकी जाँच करे कि भारतके उद्योग-व्यवसायकी उन्नतिके लिए देशमे कौन-कौन साधन उपलब्ध है और किन-किन बातोंके करनेकी आवश्यकता है । इस कमीशनने सन् १९१८ मे अपनी रिपोर्ट पेश की और सरकारसे सिफारिश की कि सरकारका कर्तव्य है कि वह देशके उद्योग-व्यवसायकी उन्नतिके लिए पूरा उद्योग करे । उन्होंने यह भी सिफारिश की कि नये उपायोका प्रयोगकर कृषिकी उन्नति करनी चाहिये और प्राथमिक शिक्षा सर्वसाधारणके लिए अनिवार्य कर देनी चाहिये । हम ऊपर कह चुके हैं कि पहले सरकारकी नीति यह थी कि भारत कृषिप्रधान देश बना रहे, पर यूरोपीय युद्धके कारण इस नीतिमे परिवर्तन हुआ । इस नीति-परिवर्तनके अन्य भी कई कारण थे । ब्रिटिश सरकारने यह देखा कि युद्धकी अवस्थामे भारत साम्राज्यकी रक्षामे तभी विशेष रूपसे सहायक हो सकेगा जब उसके उद्योग-व्यवसायकी काफी उन्नति की जायेगी । इङ्गलैण्डके पूँजीपतियोंके लाभके लिए भी भारतके उद्योगोंकी वृद्धि करना आवश्यक था । व्यापार-व्यवसायके क्षेत्रमे इङ्गलैण्डका वह पुराना एकाधिकार अब नहीं रहा था । कई नये राष्ट्र उससे प्रतियोगिता करने लग गये थे । संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, जर्मनी और जापानकी प्रतिस्पर्द्धासे इङ्गलैण्डको भारी क्षति पहुँची और एशियाके देशोंके कई बाजार उसके हाथसे धीरे-धीरे निकलने लगे । यूरोपीय महासमरमे सलग्न रहनेके कारण इङ्गलैण्ड अपने व्यापारकी रक्षाके लिए कोई प्रवन्ध न कर सका । इस समय वह विदेश भेजनेके लिए माल तैयार न कर ज्यादातर युद्धकी सामग्री तैयार करनेमे लगा हुआ था । इङ्गलैण्डकी इस परिस्थितिसे संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और जापानने अच्छा लाभ उठाया । युद्धकी समाप्तिपर इङ्गलैण्डकी पूँजी घट गयी थी और औद्योगिक उन्नति इस दर्जेतक पहुँच गयी थी कि पूँजी अच्छे मुनाफेके साथ देशमे लगायी भी नहीं जा सकती थी । इसलिए उनको इस बातकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसे देशोमे अपनी पूँजी लगाये जहाँ कि मजदूरी सस्ती हो, कच्चा माल भी बहुतायतसे मिल सके और एक जगहसे दूसरी जगह माल लाने-ले जानेका खर्च भी बर्दाश्त न करना पड़े । इसलिए ब्रिटिश व्यवसायियोंको इसी प्रकार सहायता पहुँचायी जा सकती थी कि औद्योगिक नीतिका अवलम्बनकर ब्रिटिश पूँजी-पतियोंको भारतमे पूँजी लगानेके लिए प्रोत्साहित किया जाय । भारतमे सब प्रकारकी सुविधाएँ उपलब्ध थी और यह आशा की जाती थी कि इस प्रकार ब्रिटिश पूँजीपति अपने व्यापारकी फिरसे प्रतिष्ठाकर अपनी अवस्थाको उन्नत करनेमे समर्थ होंगे । भारतीय सरकारने यह भी निश्चय किया कि उसके विविध विभागोंके लिए जिस-जिस सामग्रीकी आवश्यकता हो वह जहाँतक सम्भव हो भारतमे ही खरीदी जाय । इस निश्चयसे भी ब्रिटिश पूँजीपति भारतमे नये-नये व्यवसाय खोलनेको प्रोत्साहित हुए । युद्धके समाप्त होनेके बाद ही कई लोहे और फैलादके कारखाने खुल गये । धीरे-धीरे भारतमे बहुत-सी

अंग्रेजी कम्पनियोंकी रजिस्ट्री हो गयी और वे अपना कारोबार करने लगीं । सन् १९२१में 'फिस्कल कमीशन'की नियुक्ति की गयी । इस कमीशनने यह सिफारिश की कि भारतीय सरकारको सरक्षणकी नीतिका प्रयोग करना चाहिये और एक स्थायी 'टैरिफ बोर्ड' इस अभिप्रायसे स्थापित करना चाहिये कि वह समय-समयपर इस बातका विचार करे कि भारतके किन विशेष व्यवसायोको सरक्षणकी आवश्यकता है । कमीशनने यह भी सिफारिश की कि विदेशी पूँजीके भारतके व्यवसायमे लगनेमे कोई बाधा न उत्पन्न की जाय और जो चुङ्गी हिन्दुस्तानके कपड़ेके व्यवसायपर लगती है वह हटा दी जाय । सन् १९२३मे भारतीय सरकारने सरक्षणकी नीतिको बहुत कुछ अग्रमे स्वीकार कर लिया । 'टैरिफ बोर्ड'की स्थापना की गयी और सन् १९२४मे लोहे और फीलादके व्यवसायको सरक्षण दिया गया । इस नीति-परिवर्तनका एक कारण यह भी था कि सरकारके लिए अब यह आवश्यक हो गया था कि वह भारतवर्षके पूँजीपति, बड़े व्यवसायी और मध्यम श्रेणीके लोगोका सहयोग प्राप्त करे । यूरोपीय युद्धसे सामान्य लोगोमे अपूर्व जागृति हो गयी थी । भारतकी जनता पहलेकी तरह अब निष्क्रिय और निश्चेष्ट नहीं रह गयी थी । उसका आर्थिक क्लेश बहुत बढ़ गया था । अशान्ति और विद्रोहके चिह्न स्पष्ट दिखलायी पड़ते थे । युद्धके पहले भारतीय सरकारके प्रधान विरोधी मध्यम श्रेणीके लोग ही थे । जमींदार, बड़े-बड़े व्यवसायी प्रायः राजभक्त थे और सामान्य जनताको अपने अधिकारोका ज्ञान न था । उस समय मध्यम श्रेणीके लोगोको दवाना कोई ऐसा कठिन कार्य न था, लेकिन युद्धके पश्चात् जब लोक-जागृति हुई तब सरकारको अपनी रक्षाके लिए मध्यम श्रेणीके लोगोको सन्तुष्ट करना आवश्यक हो गया । इसीलिए द्विचक्र-शासनकी नीति अपनायी गयी । इस नीतिसे सरकारका प्रत्यक्ष लाभ था । जहाँतक औद्योगिक क्षेत्रमे इस नीतिके अनुसार कार्य करनेका सम्बन्ध है इसका आरम्भ सरकारकी ओरसे स्वतः ही हुआ । इससे व्यवसायी और व्यापारियोका वर्ग सन्तुष्ट हो गया । मध्यम श्रेणीके लोग बहुत दिनोंसे इस बातकी कोशिश कर रहे थे कि भारत-सरकार देशी व्यवसाय और उद्योगकी उन्नतिके लिए संरक्षणका अवलम्बन करे । अब उनके मनकी बात पूरी हो गयी । शासन-क्षेत्रमे भी उनको हिस्सेदार बनाकर सरकारने नरम दलको कांग्रेससे अलग करके अपने साथ मिला लिया । कांग्रेसका गरम दल इन सुधारोसे सन्तुष्ट न था । वह इनको अपर्याप्त और निस्सार समझता था । नरम दलके लोग सुधारकी योजनाको काममे लानेके पक्षमे थे । कांग्रेसकी नीतिसे वे सहमत न थे । कांग्रेसपर इस समय गरम दलके लोगोका प्रभुत्व हो गया था । इसलिए नरम दलके लोगोने कांग्रेसका परित्याग किया । श्रीमती वेसेण्टका प्रभाव भी कम हो गया और वे भी कांग्रेससे अलग होकर नरम दलमे सम्मिलित हो गयी । नरम दलके लोगोने अपनी एक अलग सस्था कायम की जिसे 'लिवरल फेडरेशन' कहते हैं ।

जिस प्रकार शासनके क्षेत्रमे हिन्दुस्तानियोको कुछ हिस्सा दिया गया उसी प्रकार ब्रिटिश पूँजीपतियोकी भी यही इच्छा थी कि जो व्यवसाय वे भारतवर्षमे करें उसमे भारतीय पूँजीपतियोका भी सहयोग हो । इस साझेके कारोबारसे उनको कई लाभ थे । पहला

लाभ तो यह था कि ऐसा करनेसे कारोवारका वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होता । दूसरा लाभ यह था कि इस प्रकार भारतके पूँजीपतियोंमें एक ऐसा वर्ग पैदा हो जायगा जिसका स्वार्थ ब्रिटिश पूँजीपतियोंके स्वार्थसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखेगा । 'फिस्कल कमीशन'के सदस्योंने अपनी रिपोर्टमें एक सिफारिश यह भी की थी कि सरकार उन्हीं कम्पनियोंको विशेष रिआयते दे जिनकी रजिस्ट्री भारतमें हुई हो एवं जिसके प्रबन्धमें भारतीयोंका हाथ हो । भारतीय पूँजीपतियोंका सहयोग प्राप्त करके ही ब्रिटिश व्यवसायी इस सिफारिशसे फायदा उठा सकते थे । इङ्गलैण्डके प्रसिद्ध पत्र 'इकानोमिस्ट'ने सन १९२४में लिखा था कि एक नियन्त्रणमें भारतीय और ब्रिटिश पूँजीकी सहायतासे व्यवसायीकी प्रतिष्ठा करनेसे बहुत बड़े लाभ होंगे । भारतके औद्योगिक विकासमें 'डायरकी'की मजिल उतनी ही अनिवार्य है जितनी कि शासनके क्षेत्रमें । जूटकी मिलोंमें इस समय जो पूँजी लगी है उसका आधेसे ज्यादा हिस्सा हिन्दुस्तानियोंका है । तब भी अंग्रेजोंका पुराना नियन्त्रण ज्यो-का-ज्यो मौजूद है; क्योंकि हिन्दुस्तानी अपने मुनाफेसे सन्तुष्ट हैं । उनको प्रबन्धमें हिस्सा लेनेकी कोई इच्छा नहीं है ।' ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि साम्राज्यवादकी नवीन आवश्यकताओंके विचारसे ही भारत-सरकारकी नीतियोंमें परिवर्तन हुआ । इस नीतिको एक अंशमें सफलता भी प्राप्त हुई; क्योंकि हम देखते हैं कि असहयोग आन्दोलनके समय भारतके बड़े-बड़े व्यापारी, व्यवसायी और नरम दिलके लोग केवल आन्दोलनसे पृथक् ही नहीं रहे बल्कि आन्दोलनके दवानेमें सरकारकी सहायता करते रहे ।

हम ऊपर कह चुके हैं कि यूरोपीय युद्धके समय विप्लवको कुचलनेके लिए 'डिफेंस ऑफ इण्डिया ऐक्ट' पास हुआ था और इस कानूनकी सहायतासे बहुतसे नवयुवक नजरबन्द कर लिये गये थे । युद्धके समाप्त होनेपर इस कानूनकी अवधि भी समाप्त होनेवाली थी । तदनन्तर सरकारको इन नजरबन्दोंको छोड़ देना आवश्यक होता । सरकारका ख्याल था कि साधारण कानून विप्लवके दवानेके लिए काफी नहीं है, इसलिए सरकारने सन् १९१८में 'रैलेट कमीशन' नियुक्त किया । कमीशनने पड़यन्त्रोंकी जाँच की और विप्लवके दवानेके लिए नये कानूनके बनानेकी सिफारिश की । कमीशनकी रिपोर्टके आधारपर सरकारने सन् १९१९में बड़ी व्यवस्थापक सभामें दो बिल पेश किये, जो काले कानूनके नामसे प्रसिद्ध हुए । गैर-सरकारी सदस्योंने एकमत होकर और व्यवस्थापक सभाके बाहरके सब दल और विचारके लोगोंने इनका समान रूपसे विरोध किया, पर सरकारने इस विरोधकी परवाह न की और अन्तमें १८ मार्चको ये बिल पास हो गये । इस समय महात्मा गान्धीने इन कानूनों तथा अन्य कानूनोंको तोड़नेके लिए एक कमेटी नियुक्त की । महात्माजीने लोगोंसे सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ली और ३० मार्चको हड़ताल करनेकी अपील की । इस हड़तालको बहुत सफलता मिली और इसने यह प्रमाणित कर दिया कि साधारण जनतामें अपूर्व जागृति हो गयी है । इस समय भारतके मुसलमान भी खिलाफतके विषयमें बहुत चिन्तित थे । यूरोपीय महासमरमें तुर्की जर्मनीका मित्र था । युद्धमें जर्मनीके हारनेके कारण भारतके मुसलमान तुर्कीके भविष्यके विषयमें बहुत आकुल हो रहे थे । उनकी यह विशेष रूपसे इच्छा थी कि जजीरतुल अरब खलीफाकी अधीनतामें

ही रहे और वहाँ गैर-मुसलिम शक्तिका अधिकार या प्रभाव न होने पावे । खिलाफतकी रक्षाके लिए खिलाफत नामकी सस्था स्थापित की गयी । सरकारने मुसलमानोको आश्वासन दिलाया कि तुर्कीके साथ कोई अन्याय नहीं किया जायगा और मुसलमानोके धार्मिक विचारोंका आदर किया जायगा ; लेकिन मुसलमानोको इससे मन्तोप नहीं हुआ ; इसलिए मुसलमानोने भी ३० तारीखको हड़ताल मनायी और हिन्दुओका पूरा साथ दिया ।

यों तो महात्माजी युद्धके आरम्भ होनेके बाद ही दक्षिण अफ्रीकामे लौट आये थे, लेकिन अबतक वह भारतकी राजनीतिमे कोई विशेष भाग नहीं लेते थे । श्री गोपालकृष्ण गोखलेकी सलाहसे, जिनसे उनका बड़ा स्नेह था, वे एक सालतक देजकी स्थितिका अध्ययन करते रहे । उसके बाद भी वे प्रायः सामाजिक सुधारके कामोंमें ही लगे रहे । कांग्रेसके अधिवेशनोमे वह सम्मिलित अवश्य होते थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी प्रस्तावको छोड़कर वे प्रायः अन्य प्रस्तावोंपर भाषण नहीं करते थे । उस समय सरकार उनका बहुत आदर करती थी । सन् १९१५मे उनको 'कैसर-ए-हिन्द' स्वर्ण-पदक प्रदान किया गया । युद्धके समय महात्माजीने सरकारकी सहायता भी की थी । सन् १९१८मे महात्माजीने अपने वक्तव्यमे कहा था कि युद्धमे सरकारकी सहायता करना स्वराज्य पानेका सबसे सीधा और सरल उपाय है और गुजरातके लोगोसे फौजके लिए सैनिक देनेकी भी अपील की थी । सुधारोके सम्बन्धमें भी उनकी ऐसी कोई बुरी राय न थी । सत्याग्रहका प्रयोग वह पहले भी कर चुके थे । दक्षिण अफ्रीकामें भारतवासियोपर जो अत्याचार होते थे, उनका विरोध करनेके लिए महात्माजीने सत्याग्रह शुरू किया था और इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी । बहुत पहले ही वह टाल्सटाय, थोरो और रस्किनकी विचार-धारासे प्रभावित हो चुके थे । पाश्चात्य सभ्यताके वह विरोधी थे । सत्य और अहिंसाको ही वह भारतीय सभ्यताका सार समझते थे और इसीलिए उनका यह विचार था कि भारत ही यूरोपके व्यथित हृदयको शान्ति पहुँचा सकता है ।

सत्याग्रही अस्त्र या पाणविक बलका प्रयोग नहीं करता, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह निश्चेष्ट और निष्क्रिय है । वह पाणविक शक्तिका मुकाबला करनेके लिए आध्यात्मिक शक्तिका प्रयोग करता है । भयरहित हो वह सब प्रकारके कष्टोको सहन करता है । वह दृढ़-संकल्पका होता है और अन्तमें अपने प्रतिपक्षीपर विजय प्राप्त करता है । प्राचीन कालमें धर्मके उपदेशकोने भी सत्य और अहिंसाकी शिक्षा दी थी । भगवान् बुद्धका कहना था कि वैर वैरसे शान्त नहीं होता । क्राइस्टकी शिक्षा थी कि यदि कोई तुम्हारे एक गालपर चपत लगाये तो दूसरा गाल भी सामने कर दो । पर व्यक्तिगत जीवनमें ही इन सिद्धान्तोको कार्य-रूपमें विरले ही परिणत करते थे । सामाजिक जीवनमे यह सिद्धान्त व्यवहारमें नहीं आते थे । महात्माजीने सत्याग्रहके सिद्धान्त और उसकी रण-पद्धतिका पूर्ण विकासकर प्रयोगोंद्वारा यह सिद्ध कर दिया कि राजनीतिक क्षेत्रमे भी इसका उपयोग सफलताके साथ हो सकता है । उनका यह दावा है कि इसी सिद्धान्तके स्वीकार करनेसे जातियोका पारस्परिक वैमनस्य दूर हो सकता है और संसारमे सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती है ।

‘सत्यमेव जयते नानृतम्’, ‘यतो धर्मस्ततो जय.’ अर्थात् सत्य ही अन्तमे विजयी होता है और जहाँ धर्म है वही जय है—ऐसी अनेक उक्तियाँ अपने पुराने ग्रन्थोंमें पायी जाती हैं। इस प्रकार शास्त्र भी सत्य और धर्मको सफलताकी कसौटीपर ही कसता है। यदि सत्य और अहिंसाके पालनसे केवल आध्यात्मिक उन्नति ही होती हो और जीवनके दैनिक व्यवहार-में उनका कुछ उपयोग न हो तो धर्म और सत्यपर लोगोकी आस्था कायम नहीं रह सकती। महात्माजीने सत्याग्रहकी पद्धतिका विकास कर और जीवनमें उसका सफलताके साथ प्रयोगकर यह स्पष्ट दिखला दिया है कि सत्याग्रह एक सुन्दर कल्पना मात्र नहीं है जिसकी साधना केवल साधु-महात्मा कर सकते हैं, किन्तु यह सर्वसाधारणके लिए सुलभ और हर प्रकारसे व्यवहार्य है।

रौलट ऐक्टका विरोध करनेके लिए महात्माजीने इस नवीन रणनीतिका उपयोग किया था और इससे उनको सफलता भी प्राप्त हुई, क्योंकि यद्यपि ये कानून व्यवस्थापक सभासे पास हो चुके थे, तथापि सरकार इनको कार्य-रूपमें परिणत करनेकी हिम्मत न कर सकी। भारतवासियोने इस नये अस्त्रका प्रयोग पहली ही बार किया था। उनके लिए यह एक नया अनुभव था। इसलिए कई जगह सत्याग्रह आन्दोलन अहिंसात्मक न रह सका। अहमदाबाद और अमृतसरमें बलबे हो गये। फौजी सहायतासे सरकारने विद्रोहको शान्त किया। गांधीजीने सत्याग्रह आन्दोलनको स्थगित कर दिया और शान्तिकी स्थापनामें सरकारकी हर तरहसे सहायता की। पंजाब एक फौजी सूबा समझा जाता है। इसलिए वहाँकी सरकार राजनीतिक आन्दोलनोसे सदा भयभीत और त्रस्त रहा करती है और इन आन्दोलनोके कुचलनेके लिए तरह-तरहके उपायोसे काम लिया करती है। बलबेके शान्त हो जानेके बाद भी पंजाबमें फौजी कानून जारी किया गया। १३ अप्रैल १९१९को जलियाँवाला बागका हत्याकाण्ड हुआ। इस घटनाके दो दिन पश्चात् सम्पूर्ण पंजाबमें फौजी कानून जारी कर दिया गया। अमृतसर, गुजराँवाला, कसूर और पंजाबके कई स्थानोमें प्रजापर नाना-भाँतिके अत्याचार किये गये। लोगोकी जायदादे जब्त की गयी, नेताओको हर तरहसे अपमानित और जलील किया गया, लोगोको डराने और धमकानेकी गरजसे मध्ययुगकी अनेक अजीब-अजीब सजाओसे काम लिया गया। डायरने अमृतसरकी गलियोमें लोगोको पेटके बल चलाया। जब ये खबरे अन्य प्रान्तोमें पहुँची तो देशभरमें तहलका मच गया। लोकमतको क्षुब्ध देखकर लगभग छः महीने बाद सरकारने इन घटनाओकी जाँच करानेके लिए हण्टर कमीशनकी नियुक्ति की। इधर कांग्रेस कमेटीने भी अपनी जाँच शुरू की। १९२०में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटीने सर माइकेल ओडायरके ऊपर पार्लेमेंटमें अभियोग चलानेका निश्चय किया और भारतके तत्कालीन वायसरायको इङ्गलैण्ड वापस बुला लेने तथा ऐसे सब अहलकारोको अपने पदसे अलग करने एवम् उनको दण्ड देनेका अनुरोध किया, जिनके विरुद्ध कांग्रेसकी जाँच-कमेटीके पास पर्याप्त प्रमाण उपस्थित थे। सरकारने कांग्रेसकी माँगपर कुछ ध्यान नहीं दिया; बल्कि बहुतसे अंग्रेज डायरके कार्योंकी स्तुति करने लगे और उसकी सहायताके लिए आपसमें चन्दाकर उन्होंने कुछ धन भी एकत्र किया। सरकारकी इस नीतिको देखकर

और अंग्रेजोंकी मनोवृत्तिका परिचय पाकर महात्माजीके विचार यहाँके विदेशी शासनके बारेमें एकदम बदल गये । वे एक कट्टर सहयोगीसे कट्टर विरोधी हो गये । बोअर युद्ध तथा जुलू-विद्रोहके समय महात्माजीने अंग्रेजोंकी सहायता की थी । यूरोपीय महायुद्धके समय फौजमें भर्ती होकर ब्रिटिश साम्राज्यकी रक्षा करनेके लिए लोगोंको प्रोत्साहित किया था । १९१६ की अमृतसर-कांग्रेसमें मुद्दार-योजनाको कांग्रेस-द्वारा स्वीकार करानेके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया था, पर जब सरकारने अपने कृत्योंके लिए पञ्चात्ताप नहीं किया और अपने मुलाजिमोंको उनके किये हुए अत्याचारोंके लिए उचित दण्ड नहीं दिया बल्कि हर प्रकारसे प्रजाके विरुद्ध उन्हींका पक्ष लिया तब गांधीजीकी यह धारणा हो गयी कि यह एक शैतानी हुकूमत है और इससे सहयोग करना महापाप है । इङ्ग्लैण्डने भारतीय मुसलमानोंके साथ भी विश्वासघात किया । युद्धके समय भारतीय मुसलमानोंको अपने साथ रखनेके लिए इङ्ग्लैण्डके प्रधान सचिवने यह वचन दिया था कि मुसलमानोंके धार्मिक विचारोंका खयाल रखा जायगा और तुर्कोंके साथ न्याय होगा । यूरोपीय युद्ध ११ नवम्बर १९१८ को स्थगित हुआ था । २८ जून १९१६ को जर्मनीके साथ वसायकी सन्धि हुई और यद्यपि तुर्कोंने सेव्रे (Sevre) के सन्धि-पत्रपर १० अगस्त १९२०को हस्ताक्षर किया था; तथापि इस सन्धिकी शर्तें हिन्दुस्तानमें इससे बहुत पहले मालूम हो गयी थी । सब तुर्कोंने भी इस सन्धिको स्वीकार नहीं किया था । मुस्तफा कमाल-पाशाके नेतृत्वमें तुर्कोंका एक दल इस सन्धिकी विरोध करनेकी तैयारीमें लगा था । इस सन्धिके अनुसार तुर्कोंको मिस्र, अरब, मेसेपोटामिया, पेलेस्टाइन और सीरियापरसे अपना अधिकार उठा लेना पड़ा था । सन्धिकी शर्तोंको मुनकर हिन्दुस्तानके मुसलमान बहुत विद्रोह हो गये थे; क्योंकि उनको इस सन्धिसे इस बातकी आशंका हो गयी कि खिलाफतका गौरव और प्रभाव नष्ट हो जायगा और जजीरतुल अरबपर ईसाइयोंका नियन्त्रण हो जायगा । अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीकी जो बैठक ३०, ३१ मई १९२०को बनारसमें हुई थी उसने इस बातका निश्चय किया कि असहयोगकी नीतिपर विचार करनेके लिए कलकत्तेमें कांग्रेसका विधेय अधिवेशन किया जाय । पूर्व इसके कि कांग्रेसने असहयोगकी नीतिको स्वीकार किया, केन्द्रीय खिलाफत समितिने इस नीतिका निश्चय कर लिया था । सितम्बर सन् १९२०में कांग्रेसका जो विधेय अधिवेशन हुआ उसने अहिंसात्मक असहयोगकी नीतिको स्वीकार किया और इस सिद्धान्तके अनुसार अपना एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया । खिताबोंका छोड़ना, सरकारी स्कूल और कालेज तथा सरकारसे सहायता पानेवाले या इसके नियन्त्रणको स्वीकार करनेवाले स्कूल और कालेजोंसे अपने लड़कोंको निकाल लेना, राष्ट्रीय विद्यालयोंको स्थापित करना, सरकारी अदालतोंका बहिष्कार और पचायतोंकी स्थापना, नयी कौंसिलों और विदेशी मालका बहिष्कार—इस कार्यक्रमके प्रधान अङ्ग थे । नागपुरकी कांग्रेसमें असहयोगका प्रस्ताव दुहराया गया और कांग्रेसका फिरसे सगठन किया गया । सब उचित और शान्तिमय उपायों द्वारा स्वराज्यकी प्राप्ति, कांग्रेसका ध्येय बनाया गया । लोकमान्यकी स्मृतिमें 'स्वराज्य फण्ड' कायम किया गया और कांग्रेसके कार्यक्रमको अच्छी तरह चलानेके लिए प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंको

आदेश दिया गया कि वे अपने-अपने प्रान्तमें स्वयंसेवकोंका संगठन करें । ३१ मार्च और १ अप्रैल १९२१को अखिलभारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटीकी जो बैठक वेजवाड़में हुई थी उसने आगामी ३० जूनतक 'तिलक स्वराज्य फण्ड'के लिए एक करोड़ रुपया एकत्र करने, एक करोड़ कांग्रेसके सदस्य बनाने और कम-से-कम बीस लाख चर्खोंके चालू करानेका निश्चय किया । इस कार्यक्रमको बहुत अंशमें पूराकर कांग्रेसने अपनी सम्पूर्ण शक्तिको विदेशी वस्त्रके बहिष्कार एवं खादीके प्रचारमें लगा दिया । ५ नवम्बर १९२१को अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटीने प्रान्तोंको अपनी जिम्मेदारीपर अपनी इच्छाके अनुसार किसी रूपमें सत्याग्रह आरम्भ करनेका अधिकार कुछ शर्तोंके साथ दे दिया । असहयोग आन्दोलन लोक-प्रिय हो गया और कांग्रेसकी बढ़ती हुई शक्तिको देखकर सरकार व्याकुल हो उठी ।

इस अपूर्व जागृतिके कई कारण थे । जलियाँवाला बागके हत्याकाण्डके कारण सरकारकी न्याय-प्रियतापरसे लोगोंका विश्वास उठ गया था । हिन्दुस्तानके मुसलमान भी इस समय सरकारसे बहुत अप्रसन्न थे । युद्धके समय उनके साथ जो वादे किये गये थे सरकारने उनमेंसे एकका भी लिहाज नहीं किया । केवल तुर्कीका साम्राज्य ही छिन्न-भिन्न नहीं कर दिया गया था, किन्तु कई मुस्लिम देशोंपर ब्रिटिश सरकार अपने नियन्त्रणको सुदृढ़ करने एवं अपने अधिकारोंका विस्तार करनेकी चेष्टा कर रही थी । अरब उसके नियन्त्रणमें था । इराक और पेलेस्टाइनपर राष्ट्र-संघकी ओरसे उसको शासनका अधिकार (मेण्डेट) मिल चुका था । रूसके फारससे अलग हो जानेके कारण इङ्गलैण्ड सारे फारसपर अपना अधिकार जमाना चाहता था । इसके अतिरिक्त नवम्बर १९१७में रूसमें जो क्रान्ति हुई थी उसका समस्त एशियापर प्रभाव पड़ा । इस क्रान्तिके फल-स्वरूप रूसमें एक नवीन शासन-पद्धतिका उपक्रम हुआ । रूसकी राज्यक्रान्तिका प्रमुख नेता लेनिन था । वह पूँजीवादका कट्टर विरोधी था और शासन-यन्त्रपर श्रम-जोवियोंका आधिपत्य कायम करना चाहता था । उसने अपने देशमें एक नवीन समाजकी प्रतिष्ठा की । यूरोपके पूँजीवादी राष्ट्रोंने बोलशेविक रूसका विरोध किया और दुनियामें उसको बदनाम करनेकी हर तरहसे कोशिश की । उन्होंने रूससे हर तरहका सम्बन्ध हटा लिया और उसके विरोधियोंकी हर तरहसे सहायता की । १९२०में बोलशेविक रूसको अपने प्रतिपक्षियोंपर विजय मिली और अवसर पाकर लेनिनने साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए एशियाके देशोंके साथ सोवियत-सरकारका व्यापारिक एवम् राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया । एशिया और अफ्रीकाके राष्ट्रीय आन्दोलनोंकी सहायता करना रूसने अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि इन्हीं महाद्वीपोंके विविध देशोंके आर्थिक जीवनपर प्रभुत्व पाकर यूरोपके पूँजीवादी राष्ट्रोंने अपनी शक्तिको बढ़ाया था । उसने बुखारा, चीन, फारस, तुर्की और अफगानिस्तानके साथ १९२१में सन्धियाँ कर मित्रता स्थापित की । जो अधिकार जारके शासनकालमें एशियाके विविध देशोंमें रूसको प्राप्त थे उनका उसने अपनी इच्छासे परित्याग कर दिया । इसका एशियावासियोंपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । उसने न केवल एशियाके राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताको ही स्वीकार किया प्रत्युत उनकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेका भी वचन दिया । साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए

उसने एक जबरदस्त सघ स्थापित किया। जापानको भी इस संघमें सम्मिलित करनेकी उसने चेष्टा की और आरम्भमें उसको इस प्रयत्नमें सफलता भी प्राप्त हुई। साम्राज्यवादसे छुटकारा दिलानेके लिए रूसने चीनकी भी अच्छी सहायता की। एशियाके लोगोंने भ्रातृभाव स्थापित करने तथा साम्राज्यवादकी भीषणता खतलानेके लिए उसने समय-समयपर कान्फरेन्सोंका आयोजन किया। इन विविध चेष्टाओंका यह फल हुआ कि १९२०के बादसे ही ग्रेट ब्रिटेनका प्रभाव एशियामें बहुत कम होने लगा। अफगानिस्तानने स्वतन्त्रता प्राप्त की। १९२१में फारसमें राज्य-क्रान्ति हो गयी। तुर्कोंने अपनी तलवारके जोरसे २४ जुलाई १९२३को लोसानकी कान्फरेन्समें सेवरेकी अपमानजनक सन्धिको बदलवा दिया। अगोरामें प्रजातन्त्र शासनकी स्थापना हुई। रूसकी राज्य-क्रान्तिका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि साम्यवादकी विचारधारासे एशियाके देश प्रभावित होने लगे। साम्यवादके सिद्धान्तोंके अनुसार मजदूर-आन्दोलनका नये ढंगसे सङ्गठन शुरू हो गया। मजदूर और किसान राजनीतिमें ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए एशियाके राष्ट्रोंका एक संघ स्थापित करनेकी चेष्टा हुई। 'पेन एशियाटिक लीग' नामकी संस्था कायम की गयी जिसका प्रथम अधिवेशन तोकियो (जापान)में हुआ। देशबन्धु चित्तरजनदास भी ऐसा ही एक सघ स्थापित करना चाहते थे और उनकी यह इच्छा थी कि उसका एक अधिवेशन भारतमें किया जाय, परन्तु वे अपने इस विचारको कार्यमें परिणत न कर सके।

युद्धके कारण यूरोपीय सभ्यताके प्रति जो आदरका भाव था वह भी जाता रहा। जब एशियाके लोगोंने देखा कि यूरोपके राष्ट्र अपने झगड़ोंको शान्ति-पूर्वक नहीं तय कर सकते और अपने स्वार्थ-लाभके लिए लाखों मनुष्योंकी हत्या करनेसे नहीं हिचकते तथा एक दूसरेका संहार करनेके लिए विज्ञानका दुस्प्रयोग करते हैं तब उनको यूरोपकी भौतिक सभ्यताके प्रति घृणा हो गयी। इस युद्धमें यूरोपीय राष्ट्रोंको उपनिवेशोंसे काली सेनाको भी बुलाना पड़ा था। अग्रेजी और फ्रांसीसी सिपाहियोंके साथ हिन्दुस्तानी सिपाही फ्रांसके कई मैदानोंमें जर्मनोंसे लड़े थे।

हम ऊपर कह चुके हैं कि अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटीने अपनी जिम्मेदारीपर सत्याग्रह शुरू करनेकी इजाजत दे दी थी। सरकारकी दमन-नीतिने बहुत जल्द कुछ प्रान्तोंको आत्म-रक्षामें सत्याग्रह आरम्भ करनेके लिए विवश किया। वर्किंग कमेटीने यह निश्चय किया था कि जिस दिन प्रिंस आब वेल्स भारत आयेगे उस दिन सम्पूर्ण भारतवर्षमें हड़ताल रहेगी और प्रान्तीय कमेटियाँ अपने-अपने प्रान्तमें वहिष्कारका प्रबन्ध करेगी। इस निश्चयके अनुसार प्रिंस आब वेल्स जहाँ-जहाँ गये वहाँ-वहाँ उनका वहिष्कार किया गया। वहिष्कारकी सफलता को देखकर सरकार आपसे बाहर हो गयी। प्रिंस आब वेल्सके भारत आनेकी बात पहले भी कई बार उठी थी, पर वहिष्कारकी वजहसे उनका आना स्थगित कर दिया गया था। लार्ड रीडिंगने इस बार बहुत आग्रहके साथ अपनी जिम्मेदारीपर उनको भारत बुलाया था। उनका यह खयाल न था कि वहिष्कारको इतनी सफलता मिलेगी। अपने मनसूबोंको सफल होते न देखकर उनके क्रोधका

पारावार न रहा और उन्होंने कांग्रेसके संगठनको छिन्न-भिन्न करनेका निश्चय किया । इस समय कांग्रेसका एक स्वयंसेवक दल था । इसीके द्वारा कांग्रेसका कार्य होता था । सरकारने कांग्रेसके स्वयंसेवक दलको गैर-कानूनी करार दे दिया । जो अपनेको कांग्रेसका स्वयंसेवक कहता था या जो पुलिसकी नजरोंमें कांग्रेसका स्वयंसेवक समझा जाता था उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी । जिन-जिन शहरोंमें प्रिस और वेल्सका जाना हुआ वहाँ बहुत बड़ी सख्यामें कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओं और स्वयंसेवकोंकी गिरफ्तारियाँ हुईं । सयुक्त-प्रान्त और बंगालके बहुतसे नेता कैद कर लिये गये । सरकारका दमन-चक्र बड़े जोरोंसे चलने लगा । इससे कांग्रेसको आत्मरक्षामें सत्याग्रह करनेका एक अच्छा अवसर मिल गया । अहमदाबादकी कांग्रेस (सन् १९२१)ने लोगोंसे अपील किया कि वे स्वयंसेवक-दलोंमें सम्मिलित होकर सरकारकी चुनौतीको स्वीकार करे और खामोशीके साथ अपनेको गिरफ्तार करा दे । कांग्रेसने इस कार्यको प्रधानता दी और यह भी निश्चय किया कि यदि आवश्यकता हो तो कांग्रेसके अन्य कार्य स्थगित कर दिये जायँ । कांग्रेसने अन्य प्रकारके सत्याग्रहकी तैयारी करनेकी भी सलाह दी । महात्माजीको अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीके समस्त अधिकार दे दिये गये । महात्माजीने सबसे पहले बारडोली ताल्लुकेमें सामूहिक रूपसे सत्याग्रह आरम्भ करनेका विचार किया था । बारडोली ताल्लुकेके लोग तैयारीमें लगे हुए थे, लेकिन चोरीचौराकी घटनाके कारण महात्माजीको सत्याग्रहका विचार कुछ समयके लिए स्थगित कर देना पड़ा । ११-१२ फरवरी १९२२को बारडोलीमें वर्किंग कमेटीकी जो बैठक हुई थी उसने कांग्रेस कमेटीको आदेश दिया कि वे सरकारी आज्ञाका विरोध करनेके लिए स्वयंसेवकोंके जुलूस न निकाले और सभाएँ न करे और जबतक देशमें शान्ति और अहिंसाका वायुमण्डल फिरसे स्थापित नहीं हो जाता तबतक केवल रचनात्मक कार्यमें ही संलग्न रहे । कांग्रेसको यह सूचना मिली थी कि कहीं-कहीं रैयत जमींदारको लगान नहीं दे रही हैं । इसलिए वर्किंग कमेटीने कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओंको यह सलाह दी कि वे किसानोंको इत्तला कर दे कि जमींदारोंको लगान अदा न करना कांग्रेसके प्रस्तावोंके विरुद्ध है । वर्किंग-कमेटीने जमींदारोंको भी इत्मीनान दिलाया कि कांग्रेस उनके जायज हकोंपर किसी प्रकारका आक्रमण करना नहीं चाहती । सयुक्त-प्रान्तके जमींदारोंको आश्वासन दिलानेके लिए यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था । अवधके करीब-करीब हर जिलेमें किसान-सभाओंका अच्छा संगठन हो गया था । वे भी बारडोली की भाँति लगान-वन्दीका आन्दोलन शुरू करना चाहते थे । कांग्रेसके नेताओंने एक वर्षके भीतर स्वराज्य स्थापित करनेका वादा किया था । वह वर्ष भी बीत गया । वाज-वाज किसान यह समझने लगे कि स्वराज्यकी स्थापना होनेपर हमको लगान न देना पड़ेगा, लेकिन महात्माजी जमींदार और किसानकी लड़ाई नहीं चाहते थे । वे देशकी सारी ताकतको सरकारके खिलाफ लगाना चाहते थे । वे केवल ऐसे ही स्थानोंमें लगान-वन्दी शुरू करनेकी इजाजत देनेको तैयार थे जहाँके किसान सरकारको बराह-रास्त लगान अदा करते थे । लेकिन जब उनको खबर लगी कि सयुक्तप्रान्तमें जगह-जगह किसानोंने लगान देना बन्द कर दिया है और चोरीचौराके हत्याकाण्डसे उनको निश्चय हो गया कि

सामूहिक रूपमें या व्यक्तिगत रूपसे सत्याग्रह करनेके लिए उपयुक्त वायुमण्डलका अभाव है, तो उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ करनेका विचार स्थगित कर दिया। बारडोलीके डम निष्चयसे कांग्रेसको बहुत धक्का पहुँचा। लोगोंकी आशाएँ भग्न हो गयीं। चारों ओर निराशा और निरत्माहके चिह्न दिखलायी पड़ने लगे। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने अपने दिवलीके अधिवेशनमें २८-२५ फरवरी १९२२को कुछ आवश्यक सङ्गोष्णोंके साथ बारडोलीके प्रस्तावकों का अस्वीकार किया। वैयक्तिक रूपमें सत्याग्रह आरम्भ करनेका अधिकार प्रान्तोंको दे दिया गया और यह भी निष्चय किया गया कि विदेशी वस्त्रोंकी दुकानोंपर शान्तिमय धरना दिया जा सकता है। बारडोलीके निष्चयमें बहुतसे लोगोंका यह विचार हो गया था कि कांग्रेसने सदाके लिए सामूहिक सत्याग्रहका विचार स्थगित कर दिया है। इसलिए अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने अपना यह विचार प्रकट किया कि कांग्रेसने असहयोगके मूल कार्यक्रमको सदाके लिए स्थगित नहीं कर दिया है और यह आशा प्रकट की कि यदि कांग्रेसके कार्यकर्त्ता अनन्यमनस्क होकर रचनात्मक कार्यक्रमको सफल बनानेकी चेष्टा करें तो सामूहिक सत्याग्रहके लिए भी उपयुक्त वायुमण्डल पैदा किया जा सकता है। इस निष्चयके कुछ दिनों बाद ही महात्माजी गिरफ्तार कर लिये गये और १८ मार्चको उन्हें ६ वर्षके कारावासका दण्ड दे दिया गया। सरकारकी दमन-नीतिके कारण लोग यह चाहते थे कि किसी न किसी रूपमें सत्याग्रह आरम्भ करनेकी आज्ञा दी जाय, इसलिए डम विषयपर विचार करनेके लिए कांग्रेस कमेटीकी एक बैठक जूनमें लखनऊमें हुई थी। कमेटीने समापनियों यह अधिकार दिया कि वे कुछ सज्जनोंको देशमें धूमकर देशकी स्थितिके सम्यन्धमें अपनी रिपोर्ट देनेके लिए नियुक्त करें। सत्याग्रहके प्रश्नको अगली बैठकके लिए स्थगित कर दिया। नवम्बरकी बैठकमें रिपोर्टपर विचारकर कमेटीने निष्चय किया कि देश इस समय सामान्य रूपमें सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करनेकी योग्यता नहीं रखता; किन्तु यह बात ध्यानमें रखते हुए कि ऐसी अवस्था उपस्थित हो सकती है जब परिस्थिति रूपमें सामूहिक सत्याग्रहकी आवश्यकता पड़े और लोग उसके लिए तैयार भी हों, कमेटी प्रान्तीय कमेटियोंको अपनी जिम्मेवारीपर ऐसे सत्याग्रहके आरम्भ करनेका अधिकार देती है यदि वे मय गर्ते पूरी की गयी हो जिनका उल्लेख कमेटीके पूर्व-निष्चयोंमें किया जा चुका है। इस समय कमेटीके विचारार्थ यह प्रश्न भी उपस्थित किया गया था कि कांग्रेसके सदस्योंको कांसिलोके अगले चुनावमें भाग लेना चाहिये या नहीं, पर कमेटीने इसका निष्चय गया-कांग्रेसपर छोड़ दिया। इस समय कांग्रेसमें दो दल हो गये थे। एक दलका यह मत था कि कांसिलोमें जाकर प्रतिबन्ध-नीतिका निरन्तर अनुसरणकर कांसिलोके कार्यका बन्द कर देना चाहिये। यह दल इस कार्य-प्रणालीको असहयोगका एक रूप समझता था। इस दलके प्रमुख नेता देशबन्धु चित्तरंजनदास और पण्डित मोतीलाल नेहरू थे। इस दलमें वे सब लोग शामिल थे जो कांसिलोके वहिष्कारके शुरुआत ही पक्षमें न थे। स्वयं देशबन्धुने नागपुरकी कांग्रेसमें अहिंसात्मक असहयोगके कार्यक्रमका विरोध किया था। विशेषकर वे कांसिलोके वहिष्कारके पक्षमें न थे। यह सच है कि वे कांसिलोमें जाकर सरकारसे सहयोग करना नहीं चाहते थे, पर उनका

यह खयाल था कि कौंसिलोपर कब्जा कर हम सरकारके शासन-यत्नको बहुत-कुछ बेकार कर सकते हैं। लोकमान्यके अनुयायी भी कौंसिलोके बहिष्कारके विरुद्ध थे। लेकिन कांग्रेसके बहुमतके आगे इन सब सज्जनोको उस समय सिर झुकाना पड़ा था। वारडोलीके निश्चयके उपरान्त ऐसे सब सज्जनोकी यह धारणा हो गयी कि असहयोगके कार्यक्रममें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता है। डाक्टर मुजे असहयोगके कार्यक्रमको अव्यावहारिक समझते थे। श्री विठ्ठलभाई पटेल इस बातको नहीं स्वीकार करते थे कि सामूहिक रूपमें सत्याग्रह आरम्भ करनेके लिए कभी भी उपयुक्त वायुमण्डल हो सकता है। दूसरा दल महात्माजीके अनुयायियोंका था। अहिंसात्मक असहयोगके कार्यक्रममें इनका पूरा विश्वास था। इसके प्रमुख नेता श्री राजगोपालाचारी, श्री वल्लभभाई पटेल आदि थे। गया-कांग्रेसमें श्री राजगोपालाचारीके दलका बहुमत था। इसलिए गया-कांग्रेसने कौंसिलोके बहिष्कारका निश्चय किया और कांग्रेसके कार्यकर्त्ताओंसे अनुरोध किया कि वे कम-से-कम ५०, ००० स्वयंसेवक भर्ती करें और कांग्रेसके संगठनको सुदृढ कर सत्याग्रह आरम्भ करनेके लिए जिस तैयारीकी आवश्यकता है उसको पूरा करें। गया-कांग्रेसने सरकारी शिक्षा-संस्थाओं और अदालतोंके बहिष्कारको भी कायम रखा। कांग्रेसके सभापति देशबन्धु दास कांग्रेसके इन निश्चयोंसे सहमत न थे। इसलिए उन्होंने सभापतित्वसे त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसमें एक पक्ष ऐसा भी था जो आपसके इन झगड़ोंको पसन्द नहीं करता था और दोनों दलोंमें किसी प्रकारका समझौता करानेकी कोशिशमें लगा था। इस आपसके झगड़के कारण कांग्रेसका कार्य अस्त-व्यस्त हो गया था। कांग्रेसके नेताओंमें मत-भेद होनेके कारण साधारण जनता सम्भ्रान्त हो गयी थी। लोग अपना कर्तव्य निर्धारित करनेमें अपनेको असमर्थ पाते थे, इसलिए उनकी यह स्वाभाविक इच्छा थी कि नेताओंका यह परस्परका झगड़ा शान्त हो जाय। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटीने मई सन् १९२३की बैठकमें यह निश्चय किया कि कौंसिलोके बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्तावके अनुसार वोटोंमें किसी प्रकारके प्रचारका कार्य न किया जाय। इस निश्चयके होनेपर बर्किङ्ग कमेटीके छ. सदस्योंने त्यागपत्र दे दिया। कमेटीने इन सज्जनोसे अपने त्यागपत्र-पर फिरसे विचार करनेका आग्रह किया, पर जब उन्होंने ऐसा करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की तो कमेटीको त्याग-पत्रोंको स्वीकार करना पड़ा। कौंसिलोके बहिष्कारके प्रश्नपर विचार करनेके लिए कांग्रेसका एक विशेष अधिवेशन दिल्लीमें आमन्त्रित किया गया। इस अधिवेशनमें कौंसिलोके बहिष्कारका प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया और कांग्रेसके सदस्योंको कौंसिलोके निर्वाचनमें खड़े होने तथा मत देनेकी स्वतन्त्रता दे दी गयी। देशबन्धु दासके नेतृत्वमें सन् १९२३में स्वराज्य-पार्टीकी स्थापना हुई और इस पार्टीकी ओरसे चुनावके लिए उम्मेदवार खड़े किये गये।

चुनावके पहले स्वराज्य-दलने एक कार्यक्रम प्रकाशित कर अपनी नीतिकी घोषणा की थी। बिना विलम्बके पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना स्वराज्य-दलका तात्कालिक उद्देश्य था। इस उद्देश्यका स्पष्टीकरण करते हुए कार्यक्रममें यह बतलाया गया था कि देशकी अवस्थाके अनुकूल शासन-विधान बनानेका अधिकार तथा वर्तमान शासन-

यन्त्रपर कार्य-साधक नियन्त्रण प्राप्त करना ही पूर्ण ग्रीपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है। व्यवस्थापक-सभा सम्बन्धी कार्यके विषयमें स्वराज्य दलने अपनी यह नीति निश्चित की कि चुनावके उपरान्त स्वराज्य-दलके सदस्य व्यवस्थापक सभामें सरकारके सामने राष्ट्रकी माँग पेश करेंगे और यदि सरकारने सन्तोषप्रद उत्तर न दिया और जनताके पूर्वोक्त अधिकारको स्वीकार न किया तो स्वराज्य-दल, बहुमत होनेकी अवस्थामें व्यवस्थापक-सभाओंद्वारा शासनके कार्यको असम्भव बनानेके लिए अविश्रान्त और सतत प्रतिबन्धकी नीतिका अनुसरण करेगा। बड़ी व्यवस्थापक-सभाके लिए केवल ४३ स्वराज्य-दलके सदस्य चुने जा सकेंगे। वमसि जो सदस्य चुने गये थे उनको स्वराज्य-दलके साथ सहयोग करनेका आदेश दिया गया था। इस प्रकार स्वराज्य-दलकी संख्या ४६ समझी जा सकती है। बहुमत न होनेके कारण उनको इण्डिपेण्डेंट-दलसे संयोग करना पड़ा और इस संयुक्त दलका नाम नेशनलिस्ट-पार्टी रखा गया। नेशनलिस्ट-पार्टीने यह निश्चय किया कि राष्ट्रीय माँग पेश की जाय और यदि तीन-चौथाई सदस्योंकी रायमें सरकारका उत्तर सन्तोष-प्रद न हो तो उस अवस्थामें नेशनलिस्ट-पार्टी प्रतिबन्धकी नीतिका अनुसरण करनेके लिए बाध्य होगी। इस निश्चयके अनुसार १८ फरवरी १९२४को नेशनलिस्ट-पार्टीकी ओरसे राष्ट्रकी माँग पेश की गयी। यह प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया। इस प्रस्तावद्वारा सपरिषद गवर्नर जनरलसे सिफारिश की गयी कि वह दायित्वपूर्ण शासन स्थापित करनेके लिए गवर्नमेण्ट प्राव इण्डिया ऐक्टमें आवश्यक परिवर्तन करावे और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए जल्दसे जल्द एक गोलमेज-कान्फरेन्स भारतका शासन-विधान तैयार करनेके लिए आमन्त्रित करे और नयी व्यवस्थापक सभाकी स्वीकृति लेकर कानून बनानेके लिए ब्रिटिश पार्लमेण्टके सामने इस शासन-विधानको पेश करे। सरकारने कोई उत्तर न दिया और उसका व्यवहार भी सन्तोष-प्रद न पाया गया। इसलिए प्रतिबन्ध-नीतिका आरम्भ किया गया। बजटकी कई मंदा और फाइनैस विल नामजूर किये गये। लेकिन इण्डिपेण्डेंट पार्टीके सदस्य समान रूपसे निरन्तर प्रतिबन्धकी नीतिका अनुसरण करनेके लिए तैयार न थे। इसलिए स्वराज्य-दल उसका सहयोग न पाकर अपनी नीतिको पूर्णरूपसे कार्यान्वित न कर सका।

यद्यपि १९२३में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी इन दोनों दलोंमें एक प्रकारका समझौता हो गया था, तथापि ये दोनों दल एक दूसरेके साथ मिलकर कार्य करनेको तैयार न थे। कांग्रेसका रचनात्मक कार्य भी इस आपसके झगड़ेके कारण ठीक-ठीक नहीं हो सकता था। इधर जगह-जगह हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़े भी शुरू हो गये थे। असहयोग आन्दोलनके समय मालावारमें जो मोपला-विद्रोह हुआ था उस अवसरपर मुसलमानोंने कुछ हिन्दुओंको जबरदस्ती मुसलमान बना लिया था। इस घटनासे हिन्दू बहुत व्याकुल हो गये। हिन्दुओंने आत्म-रक्षाके लिए सङ्गठनका आन्दोलन शुरू किया। स्वामी श्रद्धानन्दजीने इसी समय हजारों मल्कानोंकी शुद्धि बड़े धूम-धामसे की। इस शुद्धि और सङ्गठनके आन्दोलनके कारण हिन्दू-मुसलमानका झगड़ा और भी बढ़ गया, क्योंकि मुसलमान खुद तबलीगका काम करते हैं, इसलिए वह सिद्धान्त-रूपेण शुद्धि-आन्दोलनका

विरोध नहीं कर सकते थे । उनका आक्षेप केवल यह था कि जिस प्रकारसे और जिस रूपमें शुद्धि-आन्दोलन चलाया जाता है वह अनुचित है । इसमें सन्देह नहीं कि एक बहुत बड़ी सख्यामें मुल्कानोंको हिन्दू बनते देखकर मुसलमानोंका उत्तेजित हो जाना एक स्वाभाविक बात थी, लेकिन इस उत्तेजनाका एक विशेष कारण भी था । इस्लाम-धर्मके अनुसार धर्म-परिवर्तन एक बहुत बड़ा अपराध समझा जाता है और इस अपराधके लिए मृत्यु दण्डका विधान किया गया है । साराश यह है कि विविध कारणोंसे हिन्दू-मुसलमानोंका वैमनस्य बढ़ता ही गया । १९२४में कोहाट और गुलबर्गके भीषण दंगे हुए । दोनों जातियोंके पापका प्रायश्चित्त करनेके लिए महात्माजीने २१ दिनका उपवास किया और दिल्लीमें एकता सम्मेलन किया गया, पर इसका कुछ भी फल न हुआ ।

कांग्रेसका प्रभाव दिन-ब-दिन घटता ही गया । इसलिए जब महात्माजी बीमारीके कारण जेलसे छोड़ दिये गये तब उन्होंने कांग्रेसके दोनों दलोंमें एकता स्थापित करना सबसे आवश्यक काम समझा । इसीलिए उन्होंने २२ मई १९२४को देशबन्धु और पं० मोतीलाल नेहरूके साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसार कांग्रेसकी ओरसे कौंसिल-कार्य करनेका अधिकार स्वराज्य-पार्टीको दिया गया । इस समझौतेके करनेका एक और भी कारण था । उस समय बंगालमें सरकारकी ओरसे जोरोसे दमन हो रहा था । आर्डिनेसद्वारा स्वराज्य-दलके सदस्य नजरबन्द कर लिये गये थे । यद्यपि सरकारका कहना था कि विप्लवको दवानेके लिए ही यह आर्डिनेस पास किया गया है, तथापि जनताकी यह धारणा थी कि बङ्गालकी स्वराज्य-पार्टीके विरुद्ध ही इस अस्त्रका प्रयोग किया जा रहा है । इसमें सन्देह नहीं कि असहयोग आन्दोलनके स्थगित हो जानेके कारण हिंसावादियोंने अपना सगठन फिरसे शुरू कर दिया था, तथापि आर्डिनेसका प्रयोग केवल हिंसावादियोंके विरुद्ध ही नहीं किया गया, बल्कि स्वराज्यदलके कई मान्य सदस्य भी नजरबन्द कर लिये गये । बंगालमें स्वराज्यदलकी अच्छी प्रतिष्ठा थी । कलकत्ता कारपोरेशन उनके अधिकारमें था और बंगाल-कौंसिलमें अन्य दलोंका सहयोग पाकर उन्होंने एक प्रबल विरोधी दल खड़ा कर दिया था । महात्माजी इस दमनका विरोध करनेके लिए भी कांग्रेसके दोनों दलोंको आपसमें मिलाना चाहते थे । वह देशके विविध राजनीतिक दलोंको भी कांग्रेसमें सम्मिलित करनेकी चिन्तामें लगे थे । इसी विचारसे उन्होंने इस समझौतेमें विदेशी वस्त्रके बहिष्कारको छोड़कर असहयोगके अन्य कार्य-क्रमको स्थगित करनेकी कांग्रेससे सिफारिश की । बेलगांव कांग्रेसने इस समझौतेको मजूर किया । इस समझौतेके बाद ही स्वराज्य-दलने अपनी नीति और कार्यक्रममें परिवर्तन किया । निरन्तर अविश्रान्त प्रतिबन्धनकी नीतिके स्थानमें पार्टीने यह निश्चय किया कि वह ऐसे रूपमें प्रतिबन्धकी नीतिसे काम लेगी जिसको वह समय-समयपर निश्चित करती रहेगी । राष्ट्रके उद्योग-व्यवसायकी उन्नतिके लिए, सरकारकी अर्थ शोषणकी नीतिका विरोध करनेके लिए तथा मजदूरोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिए प्रस्ताव या बिल पेश करना तथा अन्य आवश्यक कार्य करना स्वराज्य पार्टीके कार्य-क्रमका एक प्रधान अंग हो गया । इस कार्यक्रमके अनुसार जब व्यवस्थापक सभामें सरकारकी ओरसे फैलादके व्यवसायको संरक्षण देनेके लिए एक

बिल पेश किया गया, तब स्वराज्य-पार्टीके सदस्योंने सिलेक्ट कमेटीकी सदस्यता भी स्वीकार की और बिलके पास होनेमें सरकारकी सहायता की। अगस्त सन् १९४२में देशबन्धु दासने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने स्वराज्य पार्टीकी माँगका इस प्रकार निरूपण किया था—

“सबसे पहले सब प्रान्तोंको स्वाधीनता मिल जानी चाहिये। केन्द्रीय शासनपर भी कुछ नियंत्रण मिलना चाहिये। बड़ी व्यवस्थापक सभापर भी जनताके प्रतिनिधियोंका कुछ न कुछ नियंत्रण होना आवश्यक है। इस नियंत्रणका क्या परिणाम होगा इसका निर्णय गोलमेज परिषद्द्वारा हो सकता है।” अपने वक्तव्यमें आगे चलकर वह कहते हैं कि “बंगालमें विप्लवका आन्दोलन भीषण रूप धारण करता जाता है। उसकी गम्भीरताका सरकारको अन्दाज नहीं है। उसका दवाना भी रोज-व-रोज मुश्किल होता जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन और भारतवर्ष मेरे बताये हुए मार्गपर चलेगे और आपसमें समझौता कर लेंगे, क्योंकि यदि स्वराज्य-दलका आन्दोलन विफल हुआ तो उस अवस्थामें कठोरसे कठोर दमन भी बढ़ती हुई हिंसा और अराजकताका मुकाबिला करनेमें समर्थ न होगा। अधिकारिबर्ग इस बातको नहीं समझता कि स्वराज्य-दलके आन्दोलनके असफल होनेपर लोगोंका विश्वास वैध उपायोपरसे उठ जायगा और वह निराश होकर हिंसा और अराजकताके मार्गके अनुगामी हो जायेंगे।”

मध्य-प्रदेशकी कौंसिलोमें स्वराज्य-दलका बहुमत था और बंगालमें स्वराज्य-दल एक शक्तिशाली दल था जो थोड़ेसे सदस्योंके सहयोगसे बहुमत प्राप्त कर सकता था, इसलिए उन्होंने प्रतिबन्धकी नीतिसे पूरी तौरसे काम लिया और उसका फल यह हुआ कि गवर्नरोंने कौंसिलोको अनिश्चित कालके लिए विसर्जित कर दिया और अपने विशेषाधिकारसे शासनका कार्य करने लगे। अन्य प्रान्तोमें स्वराज्य-दलका बहुमत न था, इसलिए वहाँ प्रतिबन्धकी नीतिसे काम नहीं लिया जा सकता था। १९२५में बड़ी व्यवस्थापक-सभामें इण्डिपेण्डेण्ट पार्टीके लोग धीरे-धीरे नेशनलिस्ट पार्टीसे अलग हो गये और इन्होंने अपना अलग दल बना लिया। इसलिए वहाँ भी प्रतिबन्धकी नीतिका प्रयोग न हो सका। अप्रैल १९२५में भारत-सचिव लार्ड वर्कन हेडने भारतके सम्बन्धमें एक वक्तृता दी थी जिसमें उन्होंने समझौतेकी सम्भावनाकी ओर संकेत किया था। इसी समय बङ्गालके गवर्नर लार्ड लिटन और देशबन्धुमें कुछ समझौतेकी बातचीत हो रही थी और उस समय यह अफवाह उड़ी थी कि बङ्गालकी स्वराज्य-पार्टी कुछ शर्तोंके मंजूर हो जानेपर प्रतिबन्धकी नीतिका परित्याग करेगी और अपना मन्त्रिमण्डल बनाकर सरकारके साथ सहयोग करेगी। हम यह नहीं कह सकते कि इस अफवाहमें कहाँ तक तथ्य था, पर इसमें सन्देह नहीं कि लार्ड लिटन और देशबन्धुके बीच समझौतेकी बातचीत चल रही थी। पर जून १९२५में देशबन्धुकी अकस्मात् मृत्यु हो गयी, इस कारण बातचीतका कोई फल न हुआ। भारत-सचिवने अपनी वक्तृतामें इस बातको स्पष्ट कर दिया था कि सरकारके साथ सहयोग करनेपर ही भारतवासियोंको और अधिकार दिये जा सकते हैं तथा उसने नेताओंको एक शासन विधान तैयार करनेके लिए कहा जिसपर

गम्भीरतासे विचार किया जा सके । २० अगस्त १९१७की घोषणामें भी यह उल्लेख पाया जाता है कि सुधारोको सफल बनानेमें जिस परिमाणमें भारतवासी सहयोग देगे उसी परिमाणमें दायित्व-पूर्ण शासनके संचालनकी योग्यता समझी जायगी । असहयोग आन्दोलनके बाद सहयोगके लिए सरकारका इतना आग्रह करना स्वाभाविक था । बंगालकी प्रान्तीय कान्फरेन्सका जो अधिवेशन मई १९२५ में फरीदपुरमें हुआ था, उसमें सभापतिकी हैसियतसे देशबन्धुने स्वराज्य-पार्टीकी नीतिका स्पष्टीकरण किया था और सम्मानपूर्वक सन्धिके लिए अपनी उत्सुकता प्रकट की थी । ब्रिटिश-साम्राज्यके भीतर रहनेके उन्होंने अनेक लाभ बताये थे । साम्राज्यकी कल्पना उनकी दृष्टिमें एक आध्यात्मिक महत्व रखती थी । उनका कहना था कि यदि साम्राज्यके भीतर रहकर भारतवर्षको आत्मानुभूति और आत्मविकासके लिए पूरा अवसर प्राप्त हो तो इससे भारतका ही नहीं, किन्तु समस्त ससारका कल्याण होगा । पं० मोतीलाल नेहरूने स्कीन कमेटीकी सदस्यता और विट्ठलभाई पटेलने बड़ी व्यवस्थापक सभाके सभापतिका पद स्वीकार किया । पद स्वीकार करते समय श्री पटेलने अपनी वक्तृतामें कहा था कि “स्वराज्य दलके लोगोके सम्बन्धमें प्रायः यह कहा जाता है कि ये केवल छिद्रान्वेषी हैं और दूसरोकी आलोचना करना ही जानते हैं । हमारा कर्त्तव्य है कि हम दिखला दे कि हम रचनात्मक कार्य करनेकी भी योग्यता रखते हैं ।”

सुधारकी जाँच करनेके लिए सरकारने १९२४में जो कमेटी नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्टपर बड़ी व्यवस्थापक सभामें १९२५में वादविवाद हुआ । इस कमेटीके अधिकतर सदस्योंने १९१९के गवर्नमेण्ट आर्ब इण्डिया ऐक्टकी परिधिके भीतर ही कुछ सामान्य सुधार देनेकी सिफारिश की थी । इसका विरोध करनेके लिए स्वराज्य-दलने इस अवसरपर अपनी राष्ट्रीय माँगके प्रस्तावको दुहराना आवश्यक समझा और सितम्बर १९२५में इण्डिपेण्डेण्ट पार्टीके सदस्योकी सहायतासे राष्ट्रीय माँगके प्रस्तावको परिवर्तित रूपमें पास कराया । इस प्रस्तावमें शासन-योजनाकी एक रूप-रेखा मान्न दे दी गयी थी और यह सिफारिश की गयी थी कि किसी कन्वेंशन या गोलमेज कान्फरेन्स अथवा किसी अन्य उपयुक्त संस्थाद्वारा इस योजनापर विचार कराया जाय । १९२४ और १९२५की माँगमें बहुत अन्तर पाया जाता है । १९२४ के प्रस्तावमें शासन-विधान बनानेके लिए गोलमेज परिपद आमंत्रित करनेकी सिफारिश की गयी थी, पर १९२५के प्रस्तावमें यह बात आवश्यक नहीं रखी गयी । यदि सरकार रायल कमीशनद्वारा प्रस्तावित योजनाकी जाँच करावे तो इसमें स्वराज्य दलको कोई आपत्ति न होगी । जहाँ १९२४ के प्रस्तावके अनुसार गोलमेज कान्फरेन्सको अपनी इच्छाके अनुकूल किसी शासन-विधानकी सिफारिश करनेकी स्वतन्त्रता प्राप्त होती, वहाँ १९२५की माँगमें एक सकुचित शासन-योजनाका प्रस्ताव किया गया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विविध कारणोंसे स्वराज्य-पार्टीको अपनी पुरानी नीतिका धीरे-धीरे बहुत कुछ अंशमें परित्याग करना पड़ा । उनको अपनी माँग भी घटानी पड़ी और यह दावा भी छोड़ना पड़ा कि कौंसिलके भीतर रहकर सरकारसे असहयोग करनेके

लिए ही हम कौंसिलमे गये हैं । १९२५ की कांग्रेसने स्वराज्य-पार्टीके कार्य-क्रमको अपना लिया और प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटीयोकी कार्य-कारिणी-समितियोंको अगले चुनावके लिए उम्मेदवार खड़ा करनेका अधिकार दिया । कांग्रेसने १८ फरवरी १९२४ की राष्ट्रीय माँगको भी अङ्गीकार किया । और इस सम्बन्धमे यह निश्चय किया कि बड़ी व्यवस्थापक-सभाकी स्वराज्य-पार्टी जीघ्रसे जीघ्र सरकारको अपना अन्तिम निर्णय देनेके लिए आमन्त्रित करे और यदि अगली फरवरीके अन्ततक सरकार अपना निर्णय न बतावे या सरकारका निर्णय सन्तोष-प्रद न पाया जाय, तो उस अवस्थामे स्वराज्य दलके सदस्य कौंसिलोका परित्याग कर दे । कांग्रेसने अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीको कॉन्सिल-सम्बन्धी कार्य-क्रम बनानेका अधिकार दिया । इस निश्चयके अनुसार अखिल-भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने दिल्लीकी बैठकमे (६, ७ मार्च १९२६) नीचे लिखा कार्यक्रम स्वीकार किया—

१. जबतक कि सरकार राष्ट्रीय माँगका सन्तोषप्रद उत्तर नहीं देती तबतक ऐसे किसी पदको स्वीकार न करना जिसका देना या न देना सरकार के अधीन हो ।

२. जबतक सरकारका उत्तर सन्तोषप्रद नहीं होता तबतक वजटको नामंजूर करना ।

३. ऐसे सब कानूनोंको नामंजूर करना जिनके द्वारा नौकरशाही अपनी शक्तको मजबूत करना चाहती है ।

४. व्यवस्थापक-सभाओंमे ऐसे सब प्रस्ताव और विल पेश करना या उनका समर्थन करना जो राष्ट्रीय जीवनके विकास तथा देशकी आर्थिक, औद्योगिक और व्यावसायिक उन्नतिके लिए आवश्यक हो ।

५. जमींदारोंके स्वत्वोका उचित विचार करते हुए उपयुक्त कानूनद्वारा किसानोंकी अवस्थाको उन्नत करनेका प्रयत्न करना ।

६. सामान्यतः मजदूरोंके अधिकारोंकी रक्षा करना और जमींदार किसान तथा पूँजीपति और मजदूरके पारस्परिक सम्बन्धका समाधान करना ।

स्वराज्य-पार्टीके कुछ सदस्य पद स्वीकार करनेके पक्षमे थे । ऐसे लोग धीरे-धीरे स्वराज्य-दलको छोड़ने लगे । इन लोगोंने अपना एक नया दल बना लिया । उसका नाम रेस्पांसिविस्ट कोआपरेशन पार्टी रखा गया । चुनावके समय कांग्रेसकी प्रतिस्पर्धा करनेके लिए हिन्दू सभाके कुछ नेताओंने इण्डिपेण्डेंट कांग्रेस पार्टी भी कायम की । इन दोनों विरोधी पार्टियोंकी एक ही नीति थी । इस विरोधके कारण चुनावमे कांग्रेसको बहुत अच्छी सफलता न मिली ।

सुधार-जॉच-कमेटीकी नियुक्तिके समयसे ही लोगोकी यह धारणा हो चली थी कि कुछ न कुछ सुधार अवश्य दिये जायेंगे । इसी विचारसे डाक्टर वेसेटने १९२५मे कामन-वेल्थ आक्ट इण्डिया बिल तैयार किया । मुस्लिम लीग फिरसे जिन्दा की गयी और नये

१. यह नोट करनेकी बात है कि कांग्रेसके प्रस्तावमे सितम्बर १९२५ की राष्ट्रीय माँगका उल्लेख नहीं है ।

शासन-विधानमें मुसलमानोंका क्या स्थान होगा, इस विषयपर विचार किया गया। कांग्रेसने सरकारकी बेरुखीको देखकर शक्तिको हर तरहसे बढ़ानेका सकल्प किया। स्वराज्य-पार्टीके समझौतेके लिए उद्यत होनेपर भी तथा सहयोगका वचन देनेपर भी जब सरकारने राष्ट्रीय माँगकी सर्वथा उपेक्षा की और इस प्रकार राष्ट्रका अपमान किया तो कांग्रेसने हिन्दू-मुसलिम तथा सर्वदल एकता द्वारा राष्ट्रकी शक्तिको बढ़ानेका निश्चय किया। गोहाटी कांग्रेसने हिन्दू-मुसलिम वैमनस्य दूर करनेके लिए उचित उपायोंके निर्धारित करनेका वर्किङ्ग कमेटीको आदेश किया। वर्किङ्ग कमेटीने हिन्दू-मुसलिम एकता स्थापित करनेकी दृष्टिसे हिन्दू-मुसलिम नेताओंसे परामर्श कर एक रिपोर्ट तैयार की और अखिल भारतवर्षीय-कांग्रेस कमेटीने मई १९२७में इस रिपोर्टको स्वीकार किया। नवीन शासन-विधानमें मुसलमानोंका क्या स्थान होगा, इसी सम्बन्धमें यह निश्चय हुआ था। गोवध तथा बाजेके प्रश्नपर विचार करनेके लिए कलकत्तेमें अक्टूबर १९२७में एकता सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलनके निर्णयोंको कांग्रेस कमेटीने कुछ संशोधनोंके साथ स्वीकार किया। अखिल-भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलोंके नेताओं तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओंके निर्वाचित सदस्योंसे परामर्श कर भारतके लिए एक शासन-विधान तैयार करनेके लिए आदेश किया था। जब कांग्रेस इन प्रयत्नोंमें लगी थी, सरकारने मुधारोकी जाँच तथा भविष्यके लिए सिफारिश करनेकी गरजसे साइमन कमीशनकी नियुक्ति की। इस कमीशनमें एक भी भारतवासी नहीं रक्खा गया। इस कारण लिबरल दलके लोग असन्तुष्ट हो गये और उन्होंने कमीशनके साथ असहयोग करनेका निश्चय किया। कांग्रेस भी सरकारके इस निर्णयसे अप्रसन्न थी, क्योंकि सरकारने राष्ट्रीय माँगकी अवहेलना की थी। राष्ट्रकी माँग गोलमेज परिषद्द्वारा शासन-विधान तैयार करानेकी थी, पर सरकारने गोलमेज कानफरेन्स आमन्त्रित न कर रायल कमीशन की नियुक्ति की थी। कांग्रेसकी वर्किङ्ग कमेटीने नवम्बर १९३०में इसलिए सब राजनीतिक दलोंसे अपील की कि वह इस कमीशनसे असहयोग करे और उसके सामने न शहादत दे और न किसी ऐसी सिलेक्ट कमेटीकी सदस्यता स्वीकार करे जो इस कमीशनके सम्बन्धमें स्थापित की जावे। दिसम्बर में कमीशनके बहिष्कारके सम्बन्धमें वर्किङ्ग कमेटीने कई सूचनाएँ निकाली। इस प्रकार बहुत-वर्षोंके बाद भारतके विविध राजनीतिक दलोंको एक साथ काम करनेका मौका मिला। साइमन कमीशनका सब दलोंने विरोध किया। जिस दिन साइमन-कमीशनके सदस्योंने भारत-भूमिपर पैर रखा उस दिन सारे भारतमें हड़ताल मनायी गयी। जहाँ-जहाँ साइमन कमीशनका पदार्पण हुआ वहाँ-वहाँ विरोधमें जुलूस निकाले गये और काले झण्डे दिखलाये गये। जिस प्रकार मिस्रियोंने मिलकर कमीशनका बहिष्कार किया था उसी प्रकार भारतवासियोंने साइमन कमीशनका बहिष्कार किया। पुलिसने जगह-जगह जुलूसोंपर लाठीका प्रहार किया। कांग्रेसके प्रतिष्ठित नेता भी पुलिसके इस अमानुषिक अत्याचारसे न बच सके। लाहौरमें लाला लाजपतराय, तथा लखनऊमें पं० जवाहरलाल नेहरू और पं० गोविन्द वल्लभ पंत ऐसे बड़े नेताओंपर भी पुलिसने लाठीका प्रहार किया। सरकारी

कर्मचारियोंके इन घृणित कृत्योंके कारण लोगोंको असाधारण रोष हुआ और नवयुवक प्रतिकारके लिए विक्षुब्ध हो गये । जहाँ भारतकी घरेलू परिस्थिति धीरे-धीरे सुधर रही थी और सब दलोंमें सरकारके विरोध करनेका भाव जागृत हो रहा था, वहाँ एशियामे भी इस समय कुछ ऐसी बातें हुईं जिनका प्रभाव भारतकी राजनीतिक स्थितिपर पड़ा और जिनसे स्वाधीनताके लिए आगे कदम बढ़ानेके लिए भारतको प्रेरणा मिली । इस ऊपर कह चुके हैं कि सोवियट रूसने ब्रिटिश साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए एशियामें एक संघ बनाया था । सोवियट रूसकी इस नीतिके कारण ब्रिटिश सरकारका प्रभाव एशियामे बहुत घट गया । इस कारण १९२१में इङ्ग्लैण्ड रूससे एक व्यापारिक सन्धि करनेके लिए विवश हुआ, पर यह सन्धि स्थायी न हो सकी । मन् १९२६में इङ्ग्लैण्डमें कोयलेकी खानके मजदूरोंने एक हड़ताल की थी । सोवियट रूसकी ट्रेड यूनियनने इन मजदूरोंकी सहायता की, इसलिए ब्रिटिश सरकार सोवियटके प्रौर भी अधिक विरुद्ध हो गयी । १९२६-२७में चीनमें एक क्रान्ति हुई थी । उस समय चीनियोंका भाव विशेष रूपसे इङ्ग्लैण्डके विरुद्ध था, ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलने इस विरोधके लिए सोवियट रूसको उत्तरदायी ठहराया और २४ मई १९२७ को रूससे अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया । इङ्ग्लैण्डने इस बातका प्रयत्न किया कि फ्रान्स और जर्मनी इस विषयमें उनका साथ दें । इङ्ग्लैण्डकी इस कार्य प्रणालीसे सोवियट रूसको और भी नय हुआ । उसने अपनी रक्षाके लिए १९२५में तुर्कीके साथ और १९२६में जर्मनी और अफगानिस्तानके साथ सन्धि की थी । इन सन्धियोंके द्वारा इन राष्ट्रोंने आपसमें यह निश्चय किया कि यदि कोई तीसरी शक्ति इनमेंसे किसीपर आक्रमण करेगी तो वह तटस्थ रहेंगे और कोई किसी ऐसे सम्बन्धमे शरीक न होगा जिसका उद्देश्य उनमेंसे किसीके विरुद्ध आर्थिक अवरोध करनेका हो । यूरोपीय शक्तियोंसे अपनी रक्षा करनेके लिए एशियाके राष्ट्रोंमें आपसका मेल बढ़ता जाता था और एशियाके राष्ट्र सोवियट रूसको अपना सच्चा मित्र और सहायक समझते थे । भारत भी साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए एशियाके अन्य राष्ट्रोंसे सहयोग करना चाहता था । गुलाम होनेके कारण यह सन्धि तो कर नहीं सकता था, पर वह इस बातकी घोषणा तो अवश्य कर सकता था कि वह ऐसे किसी युद्धमें ब्रिटिश सरकारका साथ देनेको तैयार नहीं है जिसका उद्देश्य साम्राज्यवादकी नींवको मजबूत करना हो । १९२७की मद्रासकी कांग्रेसने इस बातकी घोषणा की कि भारतवासी अपने पड़ोसियोंके साथ शान्ति और प्रेमके साथ रहना चाहते हैं । उसका उनसे कोई झगडा नहीं है और ब्रिटिश सरकार अपनी सहायता करनेके लिए भारतवर्षको मजबूर नहीं कर सकती । भारतवासियोंको इस बातका पूरा अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे तो किसी युद्धमें योग दे या न दे । उस समय भारतकी उत्तर-पश्चिम सीमापर युद्धकी तैयारी हो रही थी । और आसामकी ओर एक फौजी प्रान्त बनानेका विचार हो रहा था । कांग्रेसने स्पष्ट कर दिया कि यदि सरकार कोई युद्ध छेड़ेगी तो भारतवासियोंका कर्तव्य होगा कि वे इस युद्धमे योग न दे ।

क्रान्तिमे सफलता पानेपर चीनके लोगोंको कांग्रेसने बधाई दी और उनको इस बातका

इत्मीनान दिलाया कि भारतवासी उनके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं । अपनी सहानुभूति दिखलानेके लिए कांग्रेसने एक मेडिकल कमीशन भेजनेका भी निश्चय किया पर सरकारने इजाजत नहीं दी । चीनियोंके विरुद्ध लड़नेके लिए भारतीय सरकारने कुछ हिन्दुस्तानी फौज चीन भेजी थी । कांग्रेसने इसका विरोध किया और सरकारसे अनुरोध किया कि जो फौज या पुलिस हिन्दुस्तानसे चीन, फारस या मेसोपोटेमिया भेजी गयी हो वह वापस बुला ली जावे । यह सच है कि सरकारपर इन प्रस्तावोंका कोई प्रभाव न पड़ा, पर कांग्रेसने संसारको दिखला दिया कि इन कार्योंके लिए सरकार ही जिम्मेदार है और जनता नहीं चाहती कि दूसरोंकी स्वतन्त्रता अपहरण करनेमें भारतवासियोंका कोई हाथ हो ।

ब्रिटिश साम्राज्यवादका विरोध करनेके विचारसे गोहाटी कांग्रेसने ५० जवाहरलाल नेहरूको ब्रुसेल्सके लिए अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया था । फरवरी १९२७में ब्रुसेल्समें साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए एक "इंटर नेशनल कांग्रेस" हुई थी । इस कांग्रेसमें चीन, मिस्र, फारस, सीरिया, अनाम, कोरिया, मरक्को, मेक्सिको आदि कई देशोंसे प्रतिनिधि आये थे । ५० जवाहरलाल भारतके प्रतिनिधि थे । पण्डितजीकी सिफारिशपर मद्रास-कांग्रेस (१९२७)ने साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए साम्राज्य विरोधी सघ (League against imperialism)से सहयोग करनेका निश्चय किया । मद्रासके अधिवेशनमें ही कांग्रेसने पूर्ण स्वतन्त्रताको अपना ध्येय घोषित किया । इन विविध निश्चयोंके कारण ससारका ध्यान भारतकी ओर आकृष्ट हुआ । कलकत्तेकी कांग्रेस (१९२८)के अवसरपर बाहरसे बहुतसे सन्देश आये । कलकत्तेके अधिवेशनमें कांग्रेसने एक विदेशी विभाग (foreign department) खोलनेका निश्चय किया और अपना यह मत प्रकट किया कि साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए यह उचित मालूम होता है कि भारतवर्ष ऐसे सब देशोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित करे जो साम्राज्यवादका विरोध करना चाहते हैं । दूसरे प्रस्तावद्वारा वर्किङ्ग कमेटीको हिदायत की गयी कि वह सन् १९३०में भारतमें 'पैन एशियाटिक फेडरेशन'का पहला अधिवेशन निमन्त्रित करे । मिस्र, सीरिया, पैलेस्टाइन और इराकको कांग्रेसने सहानुभूति-का सन्देश भेजा और इन देशोंको इस बातका विश्वास दिलाया कि भारत उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता है ।

हम ऊपर कह चुके हैं कि अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटीने अन्य राजनीतिक दलोंके साथ मिलकर एक शासन-विधान तैयार करनेका निश्चय किया था । मद्रास कांग्रेसने इस निश्चयको मजूर किया । वर्किङ्ग कमेटीने इस निश्चयके अनुसार सर्वदल सम्मेलनकी आयोजना की । विविध संस्थाओंके प्रतिनिधि आमन्त्रित किये गये और सम्मेलनका एक अधिवेशन दिल्लीमें (फरवरी, १९२८), एक बम्बईमें (मई, १९२८) और एक लखनऊ (अगस्त, १९२८)में हुआ । शासन-विधानका मसविदा तैयार करनेमें कई तरहकी कठिनाइयाँ प्रतीत हुई । इसलिए शासनविधानके सिद्धान्तोंको स्थिर करनेके लिए एक कमेटी नियुक्त की गयी । इस कमेटीने एक रिपोर्ट तैयार की जो नेहरू रिपोर्टके नामसे प्रसिद्ध है । यह रिपोर्ट औपनिवेशिक स्वराज्यके आधारपर तैयार

हुई थी। इसलिए बहुतसे कांग्रेसके सदस्योंने इसपर यह आक्षेप किया कि यह स्वतन्त्रताके ध्येयके प्रतिकूल है। इस कारण कांग्रेसमें वाद-विवाद उत्पन्न हो गया। जो लोग कांग्रेसके ध्येयको नीचा नहीं करना चाहते थे उन्होंने स्वाधीनता संघ कायम किया। उस संघके केवल वे ही सदस्य हो सकते थे जो कांग्रेसके भी सदस्य थे। पूर्ण स्वतन्त्रताके उद्देश्यके साथ-साथ सामाजिक तथा आर्थिक समताके आधारपर भारतीय समाजका पुनर्निर्माण करना संघका उद्देश्य था। कलकत्ता-कांग्रेस (१९२८) के अवसरपर जब सर्वदल कमेटीकी रिपोर्ट स्वीकृतिके लिए पेश हुई तो बहुत वादविवाद हुआ, पर अन्तमें रिपोर्ट मंजूर की गयी और कांग्रेसने अपना यह निष्पत्ति प्रकट किया कि यदि ब्रिटिश पार्लामेंट इस शासन-विधानको ज्योंकी त्यों ३१ दिसम्बर १९२९ तक मंजूर कर लेगी तो कांग्रेस इसे स्वीकार करेगी अन्यथा कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोग आरम्भ कर देगी और देशको सलाह देगी कि वह टैक्स न जमा करे।

१९२८ की सबसे अधिक महत्वकी घटना बारडोली सत्याग्रह थी। बारडोली ताल्लुकेके किसानोंका कहना था कि मालगुजारीकी तशखीस गलत है और उन्होंने फिरसे जाँच करनेकी सरकारसे प्रार्थना की। जब सरकारने इस साधारण प्रार्थनापर भी ध्यान न दिया तो किसानोंने श्री वल्लभभाई पटेलके नेतृत्वमें सत्याग्रह आरम्भ किया और मालगुजारी देना बन्द कर दिया। लोगोकी जमीने और मवेशी पानीके मोल नीलाम कर दिये गये और उनपर नाना प्रकारके अत्याचार किये गये, पर सत्याग्रही अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहे। उनके अद्भुत सगठन, असीम धैर्य और त्यागको देखकर लोग चकित हो गये। अन्तमें सरकारको झुकना पडा और किसानोंकी माँग स्वीकार करनी पड़ी। सत्याग्रहकी इस रण-पद्धतिमें लोगोका विश्वास बढ़ने लगा और भारतका स्थान ससारकी दृष्टिमें बहुत ऊँचा हो गया।

नवयुवकोमें भी इस वर्ष विशेष रूपसे जागृति हुई। युवक-संघ स्थापित किये गये। नवयुवकोने वहिष्कारके प्रदर्शनमें अच्छा भाग लिया। बम्बई और बङ्गालमें युवकोंका अच्छा संगठन हो गया। इस वर्ष मजदूरोंमें भी बहुत हलचल रही। कई हड़तालें हुई। बम्बईके मजदूरोंकी हड़ताल विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। यह छ' महीनेतक चलती रही। मजदूरोंने अपने सगठन और दृढताका अच्छा सबूत दिया। सन् १९२९में भी मजदूरोंकी हड़तालें जारी रही। बङ्गालमें जूटमिलके लगभग ढाई लाख मजदूरोंने हड़ताल की, पर अच्छा सगठन न होनेके कारण इनको सफलता न मिली। बम्बईके मजदूरोंमें वर्गवादके सिद्धान्तका प्रचार हो रहा था। उनकी मनोवृत्ति बदलने लगी और एक वर्गमें मजदूरोंकी हुकूमत कायम करनेकी प्रवृत्ति पैदा हो गयी। २० मार्च सन् १९२९को बङ्गाल, बम्बई, पञ्जाब और संयुक्तप्रान्तके अनेक कार्य-कर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये और उनपर १२१-अ धाराके अनुसार षडयन्त्रका अभियोग लगाया गया। यह मेरठ-षडयन्त्रका मुकदमा अभीतक समाप्त नहीं हुआ है। सन् १९२९में लाहौर षडयन्त्रका मामला भी चला। राजनीतिक कैदियोंके साथ बुरा व्यवहार होनेके कारण कुछ अभियुक्तोंने भूख-हड़ताल की। श्री जतीन्द्रनाथ दासकी इसीमें मृत्यु हुई। इसका

देशपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इस आत्माहुतिसे जनताका ध्यान राजनीतिक कैंदियोंकी दुरवस्थाकी ओर आकृष्ट हुआ ।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत्मे कांग्रेसका महत्व और प्रभाव बढ़ने लगा । लन्दन, न्यूयार्क, कोवे और गोआमे कांग्रेस कमेटियाँ कायम हुई । कांग्रेसके विदेशी विभागने भारतके बाहरकी संस्थाओंसे सम्बन्ध स्थापित करना शुरू किया, पर डाकके रोके जानेके कारण इस कार्यमे वड़ी अड़चन पड़ी । सबकी निगाहे लाहौर कांग्रेस (१९२६) पर थी । ३१ अक्टूबर, १९२६को लार्ड अरविनने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमे उन्होंने इस बातकी घोषणा की कि सरकारका ध्येय भारतमे औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करना है, और इस बातकी सूचना दी कि लन्दनमे गोलमेज परिषद होगी जिसमे भारतके प्रतिनिधि आमन्त्रित किये जावेगे । इस वक्तव्यके सम्बन्धमे पार्लमेण्टमे जो वाद-विवाद हुआ था उस अवसरपर कुछ सदस्योंने वायसरायकी घोषणाको स्पष्ट कर देनेके लिए भारत-सचिवसे प्रार्थना की थी, पर भारत-सचिवने वक्तव्यका स्पष्टीकरण नहीं किया । इस वाद-विवादमे भाग लेते हुए मजदूर-दलके नेताओंने जो भाषण किये थे उनका सारांश यही है कि यह वक्तव्य किसी नवीन नीतिका प्रख्यापन नहीं करता । २० अगस्त १९१७ की घोषणाके आशयके सम्बन्धमे कुछ लोगोको सन्देह हो गया था । उस सन्देहका निराकरण करनेके लिए ही वायसरायने यह वक्तव्य प्रकाशित किया है । वह केवल पुरानी नीतिका स्पष्टीकरण मात्र है । इस वाद-विवादसे वक्तव्यका मूल्य और भी कम हो गया । वक्तव्यका अर्थ ठीक-ठीक समझनेके लिए महात्माजी, पं० मोतीलाल नेहरू, डा० सप्रू, श्री विट्ठलभाई पटेल और श्री जिन्ना २३ सितम्बर १९२६को दिल्लीमे वायसरायसे मिले । इस मुलाकातमें महात्माजीने वायसरायसे यह आश्वासन चाहा कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल औपनिवेशिक स्वराज्यकी योजनाका समर्थन करेगा । वायसरायने महात्माजीको किसी प्रकार आश्वासन नहीं दिया इसलिए इस मुलाकातका कोई नतीजा न निकला । अब कांग्रेसके सामने कलकत्ता कांग्रेसके प्रस्तावको कार्यान्वित करनेके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया । अतः लाहौरकी कांग्रेसने यह निश्चय किया कि वर्तमान परिस्थितिमे प्रस्तावित गोलमेज परिषदमे कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके जानेसे कोई लाभ नहीं है, इसलिए कांग्रेस गतवर्षके निश्चयके अनुसार यह घोषित करती है कि कांग्रेस विधान-पत्रकी धारा १ में वर्णित 'स्वराज्य' शब्दका अर्थ 'पूर्ण स्वाधीनता' होगा; कांग्रेस यह भी घोषित करती है कि नेहरू कमेटीकी रिपोर्टकी पूरी योजना अब रद्द हो गयी और आशा करती है कि कांग्रेसके सब सदस्य आगेसे पूर्ण-स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए अपनी सारी शक्ति लगायेंगे । कांग्रेसने व्यवस्थापक सभाओंके बहिष्कार करनेका भी निश्चय किया और व्यवस्थापक सभाओंके कांग्रेसी सदस्योंको अपनी जगहसे हटानेका आदेश दिया । कांग्रेसने रचनात्मक कार्यक्रमको उत्साहके साथ चलानेका राष्ट्रसे अनुरोध किया और भारतीय कांग्रेस-कमेटीको यह अधिकार दिया कि जब वह उचित समझे तब सत्याग्रह आन्दोलनका आरम्भ करे । वर्किङ्ग कमेटीने २६ जनवरी सन् १९३०को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनानेका निश्चय किया । इस निश्चयके अनुसार देशभरमे पूर्णस्वराज्य दिवस

बड़े समारोहके साथ मनाया गया । स्थान-स्थानपर सभागों की गयीं और वर्किङ्ग-कमेटी-द्वारा प्रकाशित घोषणा पढ़ी और दुहरायी गयी । भारतके बाहर भी जहाँ कहीं भारतवासी बसे हैं, वहाँ भी पूर्ण स्वराज्य दिवसका उत्सव मनाया गया । कांग्रेसके आदेशके अनुसार व्यवस्थापक सभागोंके १७२ सदस्योंने सदस्यताके त्याग-पत्र दे दिया । फरवरी मन् १९३०में वर्किङ्ग कमेटीकी एक बैठक सावरमतीमें हुई और उसके प्रस्तावानुसार सरकारके साथ सत्याग्रहके युद्धका आरम्भ हुआ । यह युद्ध अभीतक समाप्त नहीं हुआ है । सरकारके साथ कांग्रेसकी विरामसन्धि हो गयी है, लेकिन यदि आपसके समझौतेके समस्या हल न हुई तो फिर युद्ध चलने लगेगा । सत्याग्रहके इस आन्दोलनका इतिहास लिखनेका समय अभी नहीं आया है, लेकिन इसके महत्त्वको देखते हुए और इतिहासके चित्रको अद्यावधि पूरा करनेके उद्देश्यसे आजतककी घटनाओंका संक्षेपमें नीचे उल्लेख किया जाता है । इस युद्धमें देशने अहिंसा और आत्म-बलिदानका अपूर्व परिचय दिया । कमसे कम अस्सी हजार आदमी जेलोंमें गये और एक हजार मारे गये । स्त्रियोंका भाग विशेष उल्लेखनीय रहा, और बच्चोंकी वानरसेना तो मण्डूर ही हो गयी । बम्बईने भी सरकारके अनवरत होनेवाले प्रहारोंके सामने अटल रहकर अपनी वीरताका विशेष परिचय दिया । अस्तु, सावरमतीमें वर्किङ्ग कमेटीकी जिस बैठकका ऊपर जिक्र किया गया है उसमें सत्याग्रहके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था उसका आशय इस प्रकार है :—

वर्किङ्ग कमेटीकी रायमें सत्याग्रह-आन्दोलनका आरम्भ और नियंत्रण उन्हीं लोगोंके द्वारा होना चाहिये जिनकी अहिंसामें पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा है और जो अहिंसाद्वारा ही पूर्ण स्वराज्यको प्राप्त करना चाहते हैं । और चूंकि कांग्रेसके संगठनमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो अहिंसाको नीतिके रूपमें ही स्वीकार करते हैं, इसलिए वर्किङ्ग कमेटी महात्माजी और उनके सहकारियोंको इस बातका अधिकार देती है कि वे जब, जिस रूपमें और जिस प्रकारसे चाहें सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ करें । वर्किङ्ग-कमेटी विश्वास करती है कि जब आन्दोलनका समारम्भ होगा तब कांग्रेसके सदस्य तथा दूसरे लोग सत्याग्रहियोंके साथ पूरा सहयोग करेंगे और उत्तेजना मिलनेपर भी पूर्ण रूपसे अहिंसात्मक बने रहेंगे । वर्किङ्ग कमेटी यह भी आशा करती है कि आन्दोलनके सार्वजनिक होनेकी अवस्थामें वे लोग जो सरकारके साथ सहयोग करते हैं या सरकारसे कुछ लाभ प्राप्त करते हैं वे सब सहयोग करना बन्द कर देंगे और उन लाभोंका परित्याग कर स्वतन्त्रताके इस अन्तिम संग्राममें सम्मिलित हो जायेंगे । वर्किङ्ग कमेटी विश्वास रखती है कि नेताओंके गिरफ्तार हो जानेपर जो लोग बच जायेंगे उनमेंसे जिनमें आत्म-त्याग और देशसेवाका भाव होगा वे आन्दोलनका संचालन करेंगे ।

सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करनेके पूर्व महात्माजीने दूसरी मार्चको वायसरायके नाम एक पत्र भेजा । समझौतेका यह अन्तिम प्रयत्न था । इस पत्रमें महात्माजीने ब्रिटिश शासनकी बुराईयाँ उल्लेख किया और यह निवेदन किया कि यदि वायसराय इन बुराईयोंको दूर करनेका कोई इलाज नहीं निकालेंगे तो मैं अपने आश्रमके साथियोंको लेकर नमक-सम्बन्धी कानून तोड़नेके लिए आश्रमसे बाहर निकलूँगा । वायसरायका

उत्तर मन्तोप-प्रद न था, इसलिए १२ मार्चको महात्माजीने लगभग ८० सत्याग्रही स्वयं-सेवकोंके साथ नमक-सम्बन्धी कानून तोड़नेके लिए डांडी (यह सूरत जिलेमें समुद्र-तटपर एक स्थान है) की ओर प्रस्थान किया। रास्तेमें जहाँ-जहाँ महात्माजी रुकते थे वहाँ-वहाँ बहुत बड़ी-बड़ी सभाएँ होती थी। गाँवके मुखिया और पटेलोंने राष्ट्रीय-आन्दोलनमें सम्मिलित होनेके लिए त्यागपत्र देना आरम्भ किया और इस दौरेसे गुजरातमें अपूर्व जागृति हो गयी। ६ अप्रैलको महात्माजीने डांडीमें समुद्रके किनारे नमक-कानूनको भंग किया। २१ मार्चको अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने यह निश्चय किया था कि जबतक महात्माजी डांडी पहुँचकर नमक कानूनको नहीं तोड़ते तबतक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियाँ अपने-अपने प्रान्तमें सत्याग्रह शुरू न करे। ६ अप्रैलको सत्याग्रह आरम्भ करनेका अधिकार समस्त देशको मिल गया। जगह-जगह नमक बनने लगा और बेचा जाने लगा। लोगोंकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गयी। गुजरातमें कई जगह सामूहिक रूपसे नमक सत्याग्रह किया गया। ऐसे स्थानोंमें जो समुद्रतटके करीब थे नमक सत्याग्रहकी विशेष सुविधा थी। पुलिसका अत्याचार शुरू हो गया। आणन्दमें सत्याग्रहियोंके जिविरपर रात्रिमें हमला किया गया और बेरहमीके साथ सत्याग्रही मारे गये। धुलेरामें नमक छीननेके लिए पुलिसवालोंने सत्याग्रहियोंके ऊपर अमानुषिक अत्याचार किये। इस प्रकारकी घटनाएँ सामान्य हो गयी। धीरे-धीरे यह आन्दोलन सब प्रान्तोंमें फैल गया। नमक-सत्याग्रहके साथ-साथ मादक द्रव्य-निषेध तथा विदेशी वस्त्रके बहिष्कारका कार्य जोरोसे शुरू हुआ। जगह-जगह शराब और विदेशी वस्त्रकी दूकानोंपर धरना दिया जाने लगा। रोजकी गिरफ्तारियोंसे लोगोंका जोश बढ़ने लगा। लोगोंके बढ़ते हुए जोशको देखकर पुलिसका अत्याचार भी बढ़ने लगा। राष्ट्रके इस अपूर्व बलिदानको देखकर सारे ससारका ध्यान भारतकी ओर आकृष्ट हो गया। २३ अप्रैलको पेशावरमें बिना किसी प्रकारकी चेतावनी दिये हुए शान्त और निहत्थी जनतापर सशस्त्र मोटर गाड़ियाँ बेगमें दौड़ा दी गयी और बहुत देरतक भीड़पर गोलियोंकी वर्षा जारी रही। लोग एक बड़ी सख्यामें मरे और घायल हुए। वर्किङ्ग कमेटीने १४ मईको श्री विठ्ठलभाई पटेलके सभापतित्वमें पेशावर जाँच-कमेटी नियुक्त की। अधिकारियोंने कमेटीके सदस्योंको सीमाप्रान्तके भीतर जानेकी इजाजत नहीं दी, इसलिए कमेटीने रावलपिण्डीमें ही जाँचका काम शुरू किया और जब कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो सरकारने उसे ज्वत् कर लिया। २७ अप्रैलको वायसरायने प्रेस क्राइनेस पास किया। ५ मईको महात्माजी कराचीमें गिरफ्तार कर लिये गये, और यरवदा जेलमें अनिश्चित कालके लिए बन्द कर दिये गये। सत्याग्रहियोंने बडाला और धरसानाके नमकके कारखानों-पर धावा बोल दिया। धरसानाके हमलेमें महात्मा गांधीके बहादुर सत्याग्रहियोंने भाग लिया था। इन हमलोंमें पुलिसने सत्याग्रहियोंपर लाठीका प्रहार किया था, लेकिन सत्याग्रहियोंने वीरता और शान्तिके साथ उस अत्याचारका मुकाबला किया। वर्किङ्ग कमेटीने मईकी बैठकमें यह निश्चय किया कि करबन्दीके आन्दोलनके आरम्भ करनेका समय आ गया है और अपना यह मत प्रकट किया कि ऐसे प्रान्तोंमें जहाँ रैयतवारी प्रथा

प्रचलित है, लगान-बन्दीका आन्दोलन शुरू होना चाहिये और बङ्गाल, विहार, उड़ीसामें चौकीदारी टैक्सका देना बन्द कर देना चाहिये । १५ मई सन् १९३०को शोलापुरमें मार्शल ला जारी किया गया । सीमाप्रान्तकी कांग्रेस-कमेटियाँ गैरकानूनी करार दी गयी । ३० मईको वायसरायने दो और आर्डिनेन्स जारी किये । ये आर्डिनेन्स शान्तिमय पिकेटिङ्ग, सरकारी अफसरोंके सामाजिक बहिष्कार तथा करबन्दी आन्दोलनको रोकनेके लिए जारी किये गये थे । दिल्ली और लखनऊमें गोली चली । स्त्रियों और बच्चोंने भी आन्दोलनमें भाग लेना शुरू किया । गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और लाठीप्रहार आम बातें हो गयी । पुलिसके इन अमानुषिक अत्याचारोंके विरोधमें कौंसिलके नरमदलके अनेक सदस्योंने भी इस्तीफा दे दिया । वर्किङ्ग कमेटीने जूनमें ब्रिटिश मानके बहिष्कारका आदेश किया । विदेशी वस्त्रके बहिष्कारमें कांग्रेसको बहुत सफलता मिली । गुजरातमें लगान-बन्दीका आन्दोलन शुरू हो गया और विहारमें चौकीदारी टैक्सके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ । मध्यप्रान्त, वरार, कर्नाटक और महाराष्ट्रमें जगह-जगह जंगलका कानून भी तोड़ा गया ।

२४ जूनको साइमन कमीशनकी सिफारिशें प्रकाशित हुईं । इनसे किसी दलको भी सन्तोष न हुआ । सितम्बरमें साइमन कमीशनकी रिपोर्टके सम्बन्धमें भारतीय सरकारका खरोता प्रकाशित हुआ । भारतीय सरकारकी सिफारिशें साइमन कमीशनकी सिफारिशोंकी अपेक्षा अधिक उदार थी, पर इनको भी कोई दल स्वीकार करनेको तैयार न था । अगस्तमें दिल्लीके चीफ कमिश्नरने कांग्रेसकी वर्किङ्ग कमेटीको नाजायज करार दिया और डाक्टर अनसारी, पं० मदनमोहन मालवीय, श्री विठ्ठलभाई पटेल, तथा वर्किङ्ग कमेटीके अन्य सदस्य, जो दिल्लीकी बैठकमें सम्मिलित होने आये थे, गिरफ्तार कर लिये गये । मद्रास, बम्बई, विहार, और पञ्जाबकी सरकारोंने भी वर्किङ्ग कमेटीको नाजायज करार दे दिया । सितम्बरमें पञ्जाब और दिल्लीकी सब कांग्रेस-कमेटियाँ नाजायज करार दी गयी । ऐसेम्वली और कौंसिल आवु स्टेटके कुछ सदस्योंने १४ जुलाईको श्री जयकरको सरकार और कांग्रेसके बीच समझौता करानेके प्रयत्न करनेका अधिकार दिया । वायसरायकी अनुमतिसे सर सप्रू और श्री जयकर महात्माजी, पं० मोतीलाल जी और पं० जवाहरलालजीसे मिले, पर कोई समझौता न हो सका । १० अक्टूबरको वायसरायने एक आर्डिनेन्स जारी कर प्रान्तीय सरकारोंको गैरकानूनी सस्थाओंकी चल सम्पत्तिको जप्त करने तथा अचल सम्पत्तिपर कब्जा करनेका अधिकार दिया । जगह-जगह कांग्रेस-कमेटियाँ नाजायज करार दी जाने लगी और सरकार कांग्रेस-गिविरोपर कब्जा करने लगी ।

१२ नवम्बरको महाराज जार्ज पञ्चमने गोलमेज परिषदका उद्घाटन किया । उस दिन सारे भारतवर्षमें हड़ताल रही । २३ दिसम्बरको वायसरायने दो और आर्डिनेन्स जारी किये । संयुक्तप्रान्तके कुछ जिलोंमें भी लगानबन्दीका आन्दोलन शुरू किया गया । वारडोली और बोरसद ताल्लुकेके किसानोंने अपना घर-बार छोड़ दिया और पासके बड़ौदा राज्यमें चले गये । १९ जनवरी सन् १९३१को इङ्ग्लैण्डके प्रधान सचिवने अपने

वक्तव्यमें कांग्रेसका सहयोग प्राप्त करनेके लिए अपनी उत्सुकता प्रकट की। उनके आदेशसे वर्किङ्ग कमेटीके सब सदस्य छोड़ दिये गये। ५ मार्चको लार्ड अरविन और महात्मा गांधीके बीच समझौता हो गया। सब आर्डिनेस मंसूख कर दिये गये और सत्याग्रहियोंके छोड़े जानेकी आज्ञा दी गयी। कांग्रेसने सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया, पर विदेशी वस्त्र और मादक द्रव्योंकी दूकानोंपर शान्तिमय धरना देनेका अधिकार सुरक्षित रखा। कराँचीकी कांग्रेसने विराम सन्धिका समर्थन किया और उसने महात्मा गांधीको गोलमेज परिषदके लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और निश्चय किया कि उनके अतिरिक्त जिन अन्य सज्जनोंको वर्किङ्ग कमेटी नियुक्त करेगी वे भी महात्माजीके नेतृत्वमें कांग्रेसका प्रतिनिधित्व करेंगे। कांग्रेसने अपने प्रतिनिधियोंको यह आदेश दिया कि वह गोलमेज परिषद्में सेना, परराष्ट्रनीति, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा आर्थिक नीतिके सम्बन्धमें नियन्त्रण प्राप्त करनेका उद्योग करे। भारतके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारने जो लेन-देन किये हैं उनकी निष्पक्ष जाँच करा कर इसका निश्चय करावे कि इनमेंसे भारत और इङ्ग्लैण्डको कितना-कितना देना है और भारत तथा इङ्ग्लैण्डका यह अधिकार स्वीकृत करावे कि इनमेंसे कोई भी जब चाहे तब एक दूसरेसे अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर सकता है। कांग्रेसने अपने प्रतिनिधियोंको ऐसी तवदीलियोंका अधिकार दिया जो भारत हितके लिए स्पष्ट रूपसे आवश्यक हों।

कराँची कांग्रेस (मार्च सन् १९३१)ने एक प्रस्ताव बड़े महत्वाका स्वीकार किया है। यह नागरिकोंके मौलिक अधिकार तथा आर्थिक व्यवस्थाके सम्बन्धमें है। मौलिक अधिकारोंका उल्लेख तो नेहरू-रिपोर्टमें भी पाया जाता है। अखिल-भारतवर्षीय कांग्रेस-कमेटीने मई सन् १९२९ में अपनी यह राय अवश्य जाहिर की थी कि भारतवासियोंकी गरीबी केवल विदेशियोंकी अर्थशोषण नीतिके कारण ही नहीं है; बल्कि इस गरीबीके लिए समाजका आर्थिक संगठन भी बहुत कुछ अशर्मे उत्तरदायी है और अपना यह मत प्रकट किया था कि इस गरीबीको दूर करनेके लिए तथा जनताकी अवस्थाको सुधारनेके लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक संगठनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जायँ और विविध वर्गोंमें जो घोर असमानता इस समय पायी जाती है वह दूर की जाय। तथापि इस विचारको कार्यान्वित करनेकी कोई चेष्टा नहीं की गयी थी। कराँची-कांग्रेसने अपना यह निश्चय प्रकट किया कि इस बातकी आवश्यकता है कि जनताके सामने यह बात स्पष्ट कर दी जाय कि जिस प्रकारके स्वराज्यकी कांग्रेस कल्पना करती है उसका जनताके लिए क्या अर्थ होगा। कांग्रेसकी राय है कि सच्ची राजनीतिक स्वतन्त्रता वही हो सकती है जिससे लाखों भूखों मरनेवालोंको वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त हो। इसलिए कांग्रेस घोषित करती है कि उसकी ओरसे जो कोई शासन-विधान स्वीकृत होगा उसमें उचित आर्थिक व्यवस्थाका भी प्रवन्ध किया जायगा। कांग्रेसने एक आर्थिक योजना स्वीकार की और उसमें उचित परिवर्तन, संशोधन या परिवर्धन करनेका अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको दिया। वर्किङ्ग कमेटीने कतिपय सज्जनोंकी एक उपसमिति इस कार्यके लिए बनायी। इस उपसमितिके २५ जून सन् १९३१ को अपनी

रिपोर्ट दी। वम्बई की बैठक (६-८ अगस्त) में इस रिपोर्ट पर विचार किया गया और योजनाको अन्तिम स्वरूप दिया गया। हम इस प्रस्तावके मुख्य अंगको यहाँ अधिकल उद्धृत करते हैं।

भौतिक अधिकार और कर्तव्य

१ (क) भारतके प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्र सम्मति प्रकट करने, स्वतन्त्रतापूर्वक परस्पर मिलने और सगठित होने तथा ऐसे कामोंके लिए जो कानून और आचार-नैतिके विरोधी न हों, किसी स्थानपर शान्तिपूर्वक और बिना हथियारके एकत्र होनेका अधिकार होगा।

(ख) भारतके प्रत्येक नागरिकको धार्मिक विश्वासकी स्वतन्त्रता तथा अपने धार्मिक कृत्योंके सम्पादनकी स्वतन्त्रता रहेगी, वशर्ते कि वे सार्वजनिक शान्ति और सदाचारमें बाधक न हों।

(ग) अल्प-संख्यक समुदाय तथा देशके विभिन्न भाषा-मूलक अशोकी संस्कृति, भाषा और लिपिकी रक्षा की जायगी।

(घ) भारतके सब नागरिक, धर्म, वर्ण, विश्वास या लिंगका विचार किये बिना, कानूनकी दृष्टिमें समान समझे जायेंगे।

(च) सरकारी नौकरियों, अधिकारके पदों या सम्मानके सम्बन्धमें तथा किसी व्यवसाय या पेशेके स्वीकार करनेके सम्बन्धमें अपने धर्म, वर्ण, विश्वास या लिंग-भेदके कारण कोई नागरिक अयोग्य न समझा जायगा।

(छ) ऐसे सब कुओ, सड़को, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानोंके विषयमें सब नागरिकोंका समान अधिकार और कर्तव्य होगा, जिनकी रक्षाका भार सरकारी या स्थानीय कोषपर हो या जिनका दानोत्सर्ग सार्वजनिक उपयोगके लिए किया गया हो।

(ज) इस सम्बन्धमें बने हुए नियमोंके अनुसार हथियार रखने और उन्हें लेकर चलनेका प्रत्येक नागरिकको अधिकार होगा।

(झ) किसी भी व्यक्तिकी स्वतन्त्रता न छीनी जायगी और न उसके मकान या जायदादमें प्रवेश किया जायगा और वे न छीने और न जप्त किये जायेंगे, सिवाय उस हालतके जब कि ऐसा करना कानूनके अनुसार हो।

(ट) सब धर्मोंके विषयमें राज्य तटस्थ रहेगा।

(ठ) सब वालिग लोगोंको मत देनेका अधिकार होगा।

(ड) राज्यकी ओरसे निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षाका प्रबन्ध रहेगा।

(ढ) राज्यकी ओरसे खिताब नहीं दिये जायेंगे।

(त) मृत्यु-दण्ड उठा लिया जावेगा।

(थ) भारतका प्रत्येक नागरिक भारतभरमें स्वच्छन्दताके साथ घूम सकता है और उसके किसी भागमें ठहर सकता है, बस सकता है, जायदाद हासिल कर सकता है और रोजगार या व्यापार कर सकता है। रक्षा और कानूनी कार्यवाहीके मामलेमें समस्त भारतमें समानता रहेगी।

श्रमजीवी

२. (क) आर्थिक सगठन न्यायके सिद्धान्तोके अनुकूल होगा जिसमें सबलोग अच्छे दर्जेका जीवन व्यतीत कर सके ।

(ख) उद्योग-धन्धोमें काम करनेवाले मजदूरोके हितोकी रक्षा राज्य करेगा और उन्हे उपयुक्त कानून तथा अन्य उपायोद्वारा पर्याप्त मजदूरी, काम करनेकी स्वास्थ्यकर परिस्थिति, परिश्रमके लिए परिमित घण्टे और मालिक और मजदूरोके झगड़ोको तय करनेके लिए उपयुक्त साधन प्राप्त करानेका बन्दोबस्त करेगा तथा वृद्धावस्था, बीमारी और बेकारीसे सहायता दिलानेका प्रबन्ध भी राज्यकी ओरसे होगा ।

३. गुलामी या गुलामीके समानकी अवस्थासे मजदूरोको स्वतन्त्र करना ।

४. स्त्री श्रमिकोकी रक्षा और प्रसवकालमें अवकाशका काफी प्रबन्ध रहेगा ।

५. पाठशालाओमें पढ़ने योग्य उम्रके बच्चोसे खानो और कारखानोमें काम न लिया जायगा ।

६. किसानों और मजदूरोको अपने हितोकी रक्षाके लिए सघ कायम करनेका अधिकार होगा ।

कर और व्यय

७. भूमि-करकी प्रणालीमें सुधार किया जायगा और वर्तमान लगान और मालगुजारी-में काफी कमी कर और अलाभकर भूमिका लगान कुछ कालके लिए विलकुल माफ करके वर्तमान बोझको यथार्थ-रूपमें हलका कर दिया जायगा । निर्धारित रकमसे जमीनकी अधिक आय होनेपर आय-कर भी लिया जायगा ।

८. एक निश्चित रकमसे अधिककी जायदादपर क्रमागत विरासत कर लिया जायगा ।

९. सेनाका खर्च इस समयकी अपेक्षा कमसे कम आधा कर दिया जायगा ।

१०. गैर फौजी महकमोका खर्च और उनके कर्मचारियोका वेतन बहुत घटा दिया जायगा । विशेषज्ञो या इसी प्रकारके अन्य कर्मचारियोको छोड़कर अन्य कर्मचारियोका वेतन ५००) ६० मासिकसे अधिक न होगा ।

११. भारतमें वननेवाले नमकपर कर न लगेगा ।

आर्थिक तथा सामाजिक योजना

१२. देशके वस्त्र-व्यवसायकी राज्य रक्षा करेगा और इस गरजसे विदेशी वस्त्र और विदेशी सूतका आना रोक देगा तथा अन्य आवश्यक उपायोको काममें लावेगा । विदेशी प्रतियोगितासे राज्य अन्य देशी व्यवसायोका भी संरक्षण करेगा ।

१३. औपधके कामके सिवा अन्य सब प्रकारके उपयोगके लिए मादक द्रव्योका सर्वथा निषेध रहेगा ।

१४. विनियम तथा मुद्रा-नीतिका नियन्त्रण राष्ट्रके लाभके विचारसे होगा ।

१५. आधारभूत उद्योग-व्यवसाय विभाग, खान, रेल, जलमार्ग, जहाज तथा सार्वजनिक गमनागमनके अन्य साधनोपर राज्यका अधिकार होगा ।

१६. कर्जदार किसानोंकी मदद की जायगी और अत्यधिक सूद लेनेकी हर प्रकारकी प्रथापर नियन्त्रण रहेगा ।

१७. नियमित सेनाके अतिरिक्त राष्ट्रकी रक्षाका अन्य साधन संगठित करनेके लिए राज्यकी ओरसे नागरिकोंको सैनिक शिक्षा देनेका प्रवन्ध रहेगा ।

इस योजनाको स्वीकार कर कांग्रेसने अपने संगठनको सुदृढ़ बना लिया है । इससे कांग्रेसकी आधार-शिला मजबूत हो गयी है । साम्राज्यवादका सफलताके साथ विरोध करनेके लिए कांग्रेसको सर्वसाधारणकी सहानुभूति और सहायताकी परम आवश्यकता है और यह सहायता तभी प्राप्त हो सकती है जब जनताको यह विश्वास हो जाय कि नवीन प्रवन्धमे उसके सुखकी वृद्धि होगी । लोकतन्त्र और साम्यवादके इस युगमे कोई संस्था सर्वसाधारणकी आर्थिक उन्नतिकी उपेक्षा नहीं कर सकती । चीनकी राष्ट्रीय संस्था 'कुओमिन्ताग' ने आर्थिक योजनाकी घोषणा करके ही अपनी शक्तको बढ़ाया था और १९२६-२७ मे सफलता प्राप्त की थी ।

कांग्रेसकी यह आर्थिक योजना तात्कालिक आवश्यकताओंके ध्यानसे ही बनायी गयी है और सर्वाङ्ग पूर्ण नहीं है, तथापि हम आशा करते हैं कि भारतवासी अपनी स्थिति और आवश्यकताओंके अनुकूल एक न एक दिन एक सुन्दर शासन-प्रणालीका अवश्य आविष्कार करेगे । कार्यका अवसर मिलनेपर भारतवासी भी रूसियोंकी तरह अपने घरकी अच्छी व्यवस्था करनेमे समर्थ होंगे और अपने देशमे भी एक नये प्रकारके सामाजिक और आर्थिक संगठनकी अभिव्यक्ति होगी जो आज भारतवासियोंमे अन्तर्हित है ।

हम ऊपर विराम सन्धिका जिक्र कर चुके हैं । सरकारने गांधी-अरविन समझौतेकी शर्तोंका ठीक-ठीक पालन नहीं किया । इस प्रकार यह ख्याल हो रहा था कि शायद महात्माजी गोलमेजमे सम्मिलित न होंगे । महात्माजीने न जानेका निश्चय भी कर लिया था, पर वायसरायसे बातचीत करनेके उपरान्त एक और समझौता हुआ जिसके कारण महात्माजीने लन्दन जाना स्वीकार किया । इस समय महात्माजी लन्दनमे हैं । उनका वहाँ बहुत स्वागत और सत्कार हो रहा है, पर इससे यह न समझना चाहिये कि उनको इस यात्रामे कोई सफलता मिलेगी । इंग्लैण्डके सब राजनीतिक दलोंकी नीति भारतके लिए एकही सी है । इंग्लैण्डका मजदूर दल भी साम्राज्यवादकी भावनासे अछूता नहीं बचा है । हम आरम्भमें ही कह चुके हैं कि भारतमे इंग्लैण्डका आर्थिक लाभ दिन-ब-दिन बढ़ता जाता है और इस आर्थिक लाभकी रक्षाके लिए जिन अधिकारोंको अपने हाथमें रखना आवश्यक होगा उन्हें ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कदापि न छोडेगे । ब्रिटिश साम्राज्यमें भारतवर्षका बड़ा ऊँचा स्थान है । भारतको अपने कब्जेमे रखनेके लिए ही अंग्रेजोंने फारस, मिस्र, अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत और 'मोसेपटेमिया'में हस्तक्षेप किया । ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य स्वार्थोंकी रक्षाके लिए भी भारतपर अधिकार बनाये रखना आवश्यक है । अब भारतकी सेनाका प्रधान कार्य उत्तर-पश्चिमकी सीमाकी रक्षा करना नहीं रह गया है । उसका प्रधान कार्य ब्रिटिश साम्राज्यके उन हिस्सोंकी रक्षा करना है जो चीन, फारस आदि देशोंमे पाये जाते हैं, इसलिए ब्रिटिश सरकार भारतकी सेनाको भारतीय

नियन्त्रणमे नही रखना चाहती । साइमन कमीशनकी रिपोर्टमे कहा गया है कि 'भारतकी रक्षाका प्रश्न केवल भारतसे ही सम्बन्ध नही रखता, ब्रिटेन भी इस प्रश्नमें दिलचस्पी रखता है । भारतकी सीमाओंकी रक्षाका प्रश्न समस्त साम्राज्यका प्रश्न है और इसलिए भारतीय सेनाका नियन्त्रण और संचालन ब्रिटिश सरकारद्वारा होना चाहिये ।'

गोलमेज परिषद्का संगठन भी कार्यसाधक नही है । इसके प्रतिनिधि प्रजाकी ओरसे चुने नही गये हैं । भारत और इङ्ग्लैण्डके सब दल और विचारके लोग इसमे आमन्त्रित किये गये हैं और सर्वसम्मतिसे ही जो निश्चय होंगे वही स्वीकार किये जायेंगे । हम तो यह समझते हैं कि भारतका तभी निस्तार होगा जब कांग्रेस अपनेमे इतनी शक्ति पैदा कर लेगी कि ब्रिटिश सरकारको सर्वदल सम्मेलन न बुलाकर केवल कांग्रेसके प्रतिनिधियोंसे ही समझौता करना पड़े ।

जन-जागृतिका पुनर्जन्म

एशियाके पुनर्जागरणका इतिहास विश्व-इतिहासकी कुछ घटनाओंसे जो एशिया-वासियोंके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी अत्यधिक सम्बन्धित है । ऐसी सर्वप्रथम महान् घटना है १९०४-१९०५ का रूस-जापान युद्ध । इस घटनासे एशियावासियोंमे नव-जीवनका संचार होता है । उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तमे अत्यन्त कटु अनुभवोंके पश्चात् एशियावासी इस निष्कर्षपर पहुँचे थे कि उनका पश्चिमी शक्तियोंसे कोई मुकाबला नही । सैनिक कलामे पश्चिमी शक्तियाँ उनसे कहीं श्रेष्ठ हैं । उस समय एशियावासी अपना आत्मविश्वास सर्वथा खो चुके थे और विदेशियोंका सामना करनेकी कल्पनातक उनके मनसे जाती रही थी । स्वयं हमारे देशमे १८५७के महान् विद्रोहके दमनके उपरान्त जनताके हृदयमें यह धारणा बढ्मूल हो चुकी थी कि ब्रिटिश सत्ताका विरोध करना व्यर्थ है । उसके आगे नतमस्तक होना ही उचित है । देशके जिन भागोमे विद्रोह हुआ था वहाँकी जनता अवश्य ही क्रुद्ध थी और उसके हृदयमे तीव्र असन्तोषकी ज्वाला धधक रही थी । उसे ब्रिटिश राजका आधिपत्य स्वीकार करनेमे निश्चय ही विलम्ब लगा परन्तु उसके हृदयमे भी पलभरके लिए भी ऐसी कल्पना नही उठी कि वह अपनी खोयी हुई स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त कर सकेगी । परन्तु भारतके उन भागोमे, जहाँ विद्रोहकी आँच नही पहुँचने पायी थी और जहाँ सबसे पहले पश्चिमी सस्कृतिका प्रसार हुआ, एक ऐसा अंग्रेजीदाँ मध्यमवर्ग उठ खड़ा हुआ जिसके हृदयमे अंग्रेजी सस्कृति और अंग्रेजी संस्थाओंके प्रति विशेष प्रेम था और जिसकी यह प्रबल धारणा थी कि ईश्वरकी कृपासे ही भारतमे अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ है और उससे देशका कल्याण ही होगा ।

भारतमे ब्रिटिश शासनका एक परिणाम यह हुआ कि यहाँका समृद्ध और वर्द्धमान व्यापारी सम्प्रदाय, जिसका कि देशपर भारी राजनीतिक प्रभाव था, सर्वथा नष्ट कर दिया गया । १८३३के चार्टर ऐक्टके जरिये कम्पनीकी व्यापार सम्बन्धी मानोपली

(एकाधिकार) समाप्त कर दी गयी और अंग्रेजोंको हिन्दुस्तानमें आनेकी खुली इजाजत दे दी गयी । इस प्रकार भारतमें विदेशी पूंजी लाने और लगानेकी छूट मिल गयी । इङ्ग्लैण्डकी मशीनोंसे बना माल धड़ाधड़ भारत आने लगा । भारतीय उद्योग यो ही वुरी दशामें थें ; इस खुली प्रतिद्वन्द्विताने उनपर घातक प्रभाव डाला । ब्रिटिश शासनने अपनी निष्चित नीति बना ली कि भारतके उद्योगोंको कोई प्रोत्साहन न दिया जाय और इसे उपनिवेश बनाकर रखा जाय, जहाँसे कच्चा माल लिया जाय और जहाँ इङ्ग्लैण्डका बना माल लाकर खपाया जाय । भारतको ब्रिटिश मालकी मंडी बना लिया जाय ।

ब्रिटिश जमींदार वर्गके ढगपर बङ्गालमें एक नया जमींदार वर्ग भी खड़ा किया गया । देशकी जो पूंजी पहले उद्योग व्यापारमें लगी थी, वह अब जमीनमें लगायी जाने लगी । अब जो कोई व्यक्ति समाजमें अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता था वह इस बातके लिए प्रयत्नशील होता कि वह जमीनका मालिक बने । इनमेंसे जो लोग अंग्रेजी पढ़े थे, वे ऐसे व्यवसायोंकी ओर झुके जिनमें शिक्षित लोगोंकी आवश्यकता थी । वे सरकारी नौकरी पानेके लिए प्रयत्नशील हो उठे । ये दोनों वर्ग नये बुरुजुआ वर्गके आधार बने । यही वह वर्ग था जिसे विदेशी शासनसे विशेष प्रेम था । जिस प्रकार बालक अपने बुजुर्गोंके आशवासनोंपर विश्वास कर लेता है उसी प्रकार यह वर्ग ब्रिटिश सरकारके आशवासनोंपर पूर्णतः विश्वास करता था । प्रेसिडेन्सी नगरोंमें राजनीतिक संस्थाओंको जन्म दिया गया और कुछ वर्षोंके उपरान्त कुछ प्रमुख नेताओंने इस बातकी चेष्टा की कि शिक्षित भारतीयोंका एक अखिल भारतीय संघटन बनाया जाय । अवसर-प्राप्त सरकारी अफसर श्री ए० श्री० ह्यूम भी स्वतन्त्र रूपसे विचार करते-करते इसी निष्कर्षपर पहुँचे । खुफिया पुलिसकी गुप्त रिपोर्टोंद्वारा उन्हें ऐसा पता चला कि जनतामें असन्तोषकी भावना दिन दिन उग्रतर होती जा रही है और अनेक स्थानोंके किसान विद्रोह करनेपर तुल-से गये हैं । ह्यूम साहब नहीं चाहते थे कि गदरकी पुनरावृत्ति हो । अन्तमें वे इसी निष्कर्षपर पहुँचे कि असन्तोष मिटानेका उपाय यही है कि उसे वैधानिक रूप दिया जाय और यह कार्य शिक्षित वर्गका संघटन करनेसे ही हो सकता है । श्री ह्यूमने इङ्ग्लैण्डस्थित रिटायर्ड एंग्लोइण्डियनोंसे और तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डफरिनसे इस विषयमें परामर्श किया । ह्यूम साहबका विचार था कि प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ वर्षमें एकवार मिलकर सामाजिक समस्याओंपर विचार-विनिमय करें और परस्पर मैत्रीकी भावना दृढ़ करे । वे यह भी चाहते थे कि प्रान्तीय गवर्नर इस सभाकी अध्यक्षता करे जिससे सरकारी अधिकारियोंमें और लोकनेताओंमें पारस्परिक सौहार्दकी वृद्धि हो । पर लार्ड डफरिनका मत इससे भिन्न था । उनका सुझाव था कि नया संघटन विरोधी पक्षका कार्य करे । श्री ह्यूम एवं प्रमुख राजनीतिज्ञोंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस प्रकार सन् १८८५ ई०में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका जन्म हुआ । १९१३में श्री गोखलेने कहा था कि किसी भारतीयके लिए यह सम्भव नहीं था कि वह कांग्रेसको जन्म देता । कारण, राजनीतिक आन्दोलनके सम्बन्धमें इतना अधिक विश्वास था कि अधिकारी कभी भी ऐसी संस्थाका संघटन न होने देते ।

इससे यह स्पष्ट है कि श्री ह्यूमने ब्रिटिश राज्यके हितमें ही कांग्रेसको स्थापित करनेका प्रयत्न किया । शासकोको जनताकी भावनाका ज्ञान नहीं था, वे प्राचीन परम्पराके अनुयायियोंपर भी विश्वास नहीं कर सकते थे । अपने शासनको कायम रखनेके लिए वे उन नये शिक्षित युवकोंकी ओर ही आशाभरी दृष्टि लगाये थे जिन्होंने उनके अंग्रेजी स्कूलोमें पश्चिमी ढंगकी शिक्षा प्राप्त की थी ।

हमारे शासकोने पूर्वीय और पश्चिमीय शिक्षा-पद्धतियोंकी राजनीतिक प्रवृत्तियोंका बार-बार विश्लेषण किया और अन्तमें वे इसी निकर्षपर पहुँचे कि देशी शिक्षा-पद्धतिकी अपेक्षा पश्चिमी शिक्षा-पद्धति ही ब्रिटिश हितोके अधिक अनुकूल है ।

सर चार्ल्स ट्रवेलियन अपनी पुस्तक 'आन दि एडुकेशन आव् दि पीपुल आव् इण्डिया' (१८३८) में लिखते हैं—'भारतीयोंको जबतक अपनी पूर्वस्वाधीनतापर विचार करनेका अवसर मिलता रहेगा तबतक अपनी स्थितिमें सुधार करनेका केवल एक ही उपाय उनकी समझमें आवेगा और वह होगा—सभी अंग्रेजोंको तत्काल देशसे निकाल बाहर करना । प्राचीन पद्धतिसे पले-पनपे भारतीय देशभक्तके हृदयमें इसके अतिरिक्त और किसी भावनाका उदय हो ही नहीं सकता । वह मान ही नहीं सकता कि इसके अतिरिक्त और भी कोई उपाय हो सकता है जिससे उसके देशकी गयी हुई प्रतिष्ठा और समृद्धि पुनः लौट सके । अन्य किसी उपायकी ओर उसका ध्यान आकृष्ट ही नहीं किया गया है । यूरोपियन विचार-धाराका प्रवेश करके ही इन राष्ट्रीय भावनाओंको नयी दिशामें मोड़ा जा सकता है ।' (पृष्ठ १६१)

एक अन्य स्थानपर आप लिखते हैं—“वर्तमान स्थितिको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इङ्ग्लैण्ड और भारत जैसे दो दूर देशोंके बीच वर्तमान सम्बन्ध स्थायी नहीं रह सकता । भारतवासी तो अपनी गयी हुई स्वतन्त्रता लौटा ही लेंगे । किसी भी तरहकी नीतिसे इसमें बाधा नहीं डाली जा सकती । पर इस स्थितिको पहुँचनेके दो मार्ग हैं—एक तो है क्रान्तिद्वारा और दूसरा है सुधारद्वारा । क्रान्तिका आन्दोलन आकस्मिक और भीषण है । सुधारका मार्ग मन्द गतिवाला और शान्त है । पहलेमें हमारी पतंग एकबारगी ही कट जायगी, भारतवासियोंसे हमारा पूर्णतः सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा, पर दूसरेमें पारस्परिक लाभ और सद्भावके आधारपर हमारा सहयोग स्थायी हो सकता है । पहले मार्गको बन्द करने और दूसरे मार्गपर अग्रसर होनेका हमारे पास एक ही उपाय है और वह यह कि हम भारतीयोंको यूरोपियन सुधारोंकी पद्धतिपर ले चले । उस ओर उनकी विशेष रुचि भी है । तब वे पुराने ढंगकी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी भावना और विचारका परित्याग कर देंगे । उस स्थितिमें आकस्मिक क्रान्ति असम्भव होगी और तब निश्चित रूपसे भारतके साथ दीर्घकालतक हमारा वर्तमान सम्बन्ध दूसरी प्रकारसे बना रहेगा ।” (पृष्ठ १६२-१६३)

यही वह प्रधान कारण था जिसकी वजहसे ऐसे समय, जबकि भारत एक संघर्षके भीतरसे होकर गुजर रहा था, शासकवर्ग शिक्षित भारतीयोंकी एक सस्था स्थापित करनेमें सहायता कर रहा था और यह संस्था इसलिए थी कि भारतीय अपनी कठिनाइयाँ उसके

सम्मुख उपस्थित करके उन्हें दूर करायें। ऐसा अनुमान था कि शासकवर्ग द्वारा शिक्षित मध्यम श्रेणीकी दी गयी इस मान्यतासे जनताकी दृष्टिमें उसका मान बढ़ जायगा और नेतृत्व प्राप्तिमें सहायता मिलेगी।

कांग्रेसने बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य अथवा निश्चित नीतिके ही अपना कार्य आरम्भ कर दिया। प्रथम अधिवेशनके अध्यक्षने कांग्रेसके उद्देश्य बताते हुए कहा था कि “साम्राज्यके विभिन्न भागोंके सच्चे कार्यकर्ताओंके बीच पारस्परिक प्रेम एवं मैत्रीकी अभिवृद्धि और वर्तमान प्रमुख सामाजिक समस्याओंपर भारतके शिक्षित सम्प्रदायका सुविचारित और अधिकृत मतसंग्रह ही कांग्रेसका उद्देश्य है।” राजनीतिक क्षेत्रमें अध्यक्षकी केवल इतनी ही माँग थी कि सरकारका आधार विस्तृत हो और शासनमें जनताको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

कांग्रेसनेता इस बातको बार बार दोहराते थे कि वे ब्रिटिश साम्राज्यकी परम राजभक्त प्रजा हैं। यदि उनपर कभी ऐसा आरोप लगाया जाता था कि वे राजभक्त नहीं हैं तो वे विशेष रूपसे इस आरोपका खण्डन करते थे। पर कांग्रेसने सामाजिक प्रश्नोंपर कभी विचार नहीं किया। वह मुख्यतः राजनीतिक प्रश्नोंपर ही विचार करती रही। उसकी माँगे उदार होती थी और अनुनय विनय और विरोधकी पद्धतिद्वारा ही वह उनकी पूर्त्तिकी आकांक्षा रखती थी। १८८७के मद्रास अधिवेशनमें कार्य संचालनके नियम स्थिर करनेके लिए एक कमेटी बनायी गयी। इस कमेटीने इस आशयका एक नियम बनानेकी सिफारिश की कि कांग्रेसकी ओरसे प्रचारकार्यके लिए एक स्थायी समिति नियुक्त की जाय परन्तु उसे यह आदेश रहे कि वह सरकारकी कमियो और खामियोकी ओर जनताका ध्यान आकृष्ट करते हुए भी जनताको बताये कि भारतमें अंग्रेजी राज्यने कितना सुख और आनन्द-विखेरा है और अंग्रेजलोग बहुत नेक इरादोंसे भारतपर शासन कर रहे हैं। बादमें जब भारतीय नौकरशाहीपरसे उनका विश्वास जाता रहा तब भी अंग्रेजकी ईमानदारी और न्यायप्रियतामें उनका विश्वास अडिग बना रहा। १८८९में कांग्रेसका यह उद्देश्य घोषित किया गया कि वह वैधानिक उपायोंसे भारतीय जनताके हितोंकी रक्षा करना चाहती है। सूरतमें कांग्रेसके टुकड़े हो जानेके उपरान्त १९०८में प्रयागमें एक सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेसका उद्देश्य यह बताया गया कि वह वैधानिक उपायोंसे औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है।

यह वस्तुतः बड़े आश्चर्यकी बात है कि भारतमें राजनीतिक जागृति अत्यन्त मन्द गतिसे हुई और औपनिवेशिक स्वराज्यका लक्ष्य स्थिर करनेमें कांग्रेसको कोई २३ वर्ष लग गये। फिर भी कांग्रेस ब्रिटेनसे सम्बन्ध विच्छेद करनेके लिए प्रस्तुत न थी। पूर्ण स्वाधीनताका निश्चय करनेके लिए उसे और २१ वर्ष लग गये।

अन्य पराधीन देशोंमें ऐसी बात बहुत कम देखनेमें आती है। चीनकी कूमितांग (प्रजा-पार्टी) का जन्म १८९० ई०के लगभग हुआ था। आरम्भमें वह बहुत छोटी पार्टी थी। न तो उसका कोई निश्चित कार्यक्रम ही था और न लोकतन्त्रात्मक आधार ही। पर मंचू शासनको समाप्त करनेका उसका लक्ष्य स्पष्ट था और उसने लक्ष्य प्राप्त करनेके

जो साधन स्थिर किये थे वे वैधानिक नहीं थे । जर्जर मंचूराज्यको उलटनेके लिए उसने सैनिकोंकी सहायता माँगी । उसने यह भूल अवश्य की कि इस बातको अच्छी तरह महसूस नहीं किया कि उसका भयंकर शत्रु विदेशी साम्राज्यवाद था और जबतक चीनकी जनता इस बातको महसूस नहीं कर पायी तबतक पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए प्रभावकर कार्यक्रमके साथ वह शुद्ध प्रजा-पार्टीकी स्थापना नहीं कर सकी । यह भी ध्यान देनेकी बात है कि सनयातसेन भी मंचू शासन और उसके अत्याचारोंके विरुद्ध चीनके लोहा लेनेमें पश्चिमके लोकतन्त्रवादी देशोंकी सहायता चाहते थे । वे ऐसा समझते थे कि उनका शत्रु घरमें ही है । उनके सरल हृदयमें ऐसी आशा थी कि विदेशी साम्राज्यवादी देश मंचू शासनके उलटनेमें सहायता करेंगे । इस प्रकार भारतीय देशभक्त व्यर्थ ही अंग्रेजोंपर विश्वास रखते थे यद्यपि भारत-स्थित गोरी नौकरशाहीसे न्याय पानेकी आशा उन्होंने सर्वथा छोड़ दी थी ।

उन्नतिशील यूरोपियन संस्कृतिके संघर्षसे सभी जगह एक नये वर्गका जन्म हुआ । यह वर्ग पश्चिमकी उदार नीतिकी ओर आकृष्ट हुआ और अपनी मुक्तिके लिए यूरोपीय जनताकी ओर आशाभरी दृष्टिसे ताकने लगा । यूरोपीय ढंगकी संस्थाएँ इसे रुचने लगी और विदेशियोंकी सहायतासे और उनके सरक्षणमें वह उन संस्थाओंको अपने देशमें भी स्थापित करनेके लिए प्रयत्नशील हो उठा ।

भारतमें शिक्षितवर्ग 'भारतीयकी अपेक्षा अंग्रेज' बन गया जिस तरह इटालियनों या गालकी अपेक्षा रोमन बन गये थे । मुगल साम्राज्यकी समाप्तिपर देशके अनेक भागोंमें जो क्रान्ति और अराजकता फैल गयी थी, उसे ब्रिटिश शासनने मिटा दिया था । अंग्रेजी राजमें लोगोंको जान-मालकी सुरक्षा दिखायी पड़ने लगी । इस स्थितिका मूल कारण यही था ।

क्रान्तिकारी परिणामोंसे युक्त कोई महान घटना ही शिक्षित वर्गकी इस मनोवृत्तिमें परिवर्तन पैदा कर सकती थी । १९०५ ई० में एक ऐसी ही महान घटना घटी । जापानने रूसको पराजित कर दिया । इस घटनाने एशियावासियोंमें महान जागृति उत्पन्न कर दी । इसे देखकर सबसे पहले उनके हृदयमें यह भावना उत्पन्न हुई कि उनके राष्ट्रीय चरित्रमें ऐसा कोई दोष नहीं है जो उनकी राजनीतिक प्रगतिमें रोड़ा अटका सके । विदेशी सत्ताके सम्मुख नतमस्तक होनेकी उनकी भाग्यवादी मनोवृत्ति मिटने लगी और राष्ट्रीय आत्मसम्मान एवं मानवताके अधिकारोंकी नयी भावना उनके हृदयमें जागृत होने लगी । उनकी जो भावना अभीतक मृतप्राय पड़ी थी, उसमें पुनः जीवनके चिह्न दृष्टिगत होने लगे । जनतामेंसे ऐसे ऐसे वीर नेता उत्पन्न होने लगे जो अपनी राजनीतिक आकांक्षाओंपर किसी भी प्रकारका प्रतिबन्ध लगानेके लिए प्रस्तुत न थे । वे इस बातको महसूस करने लगे कि भिक्षाके मार्गद्वारा भारत कभी भी अपने अधिकारोंको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । वे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि स्वावलम्बन द्वारा तथा शासकोंसे पृथक् अपना राष्ट्रीय संघटन करके ही भारत अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है । वे निर्भीकतासे एवं स्पष्ट शब्दोंमें अपना मत प्रकट करने लगे । राजनीतिज्ञोंकी भाषामें घुमाफिराकर अपनी बात कहना

उन्हें पसन्द न था । ऐसी बातोंसे वे घृणा करते थे । जनताकी भावनामें, उमके अधिकारोंमें उनका दृढ़ विश्वास था और इसी विश्वासके बलपर वे अधिकारियोंसे लोहा लेनेको प्रस्तुत होते थे । उन्होंने राजनीतिक 'भिक्षा देहि' की पुरानी नीतिका परित्याग कर दिया । अपनी मुक्तिके लिए उन्होंने अधिकारियोंका मुँह ताकना बन्द कर दिया । इस नयी नीतिको कार्यान्वित करनेके लिए एक नये दलका संघटन किया गया । इस नयी विचार-धारावाले लोगोंकी यह निश्चित धारणा थी कि जनताकी संघटित शक्तिके द्वारा ही स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है और राजनीतिक स्वाधीनताके बिना जनताका सामाजिक, तालीमी, आर्थिक एवं नैतिक अभ्युत्थान भी असम्भव है । इस नवीन विचारधाराके प्रवर्तकोंने जनताको शिक्षा दी कि वह स्वावलम्बनका मार्ग ग्रहण करे, स्वदेशीको अपनाये और विदेशी मालका बहिष्कार करे । बहिष्कारसे उनका तात्पर्य केवल ब्रिटिश मालका बहिष्कार करना ही न था, बल्कि यह भी था कि अंग्रेजोंसे शासन तथा अन्य सार्वजनिक क्रमोंके सभी क्षेत्रोंमें असहयोग किया जाय । इसके लिए इस दलने जनताको सलाह दी कि वह सभी खिताब छोड़ दे और सरकारी शिक्षण-संस्थाओं, अदालतों, कांसिनों और स्थानीय संस्थाओंका पूर्ण बहिष्कार कर दे । जनताकी आर्थिक स्वाधीनताके लिए इस दलने इसे सलाह दी कि वह अपने देशी उद्योगोंको प्रोत्साहन दे और उनकी उन्नति करे । इस प्रकार बहिष्कार एक व्यापक राजनीतिक शस्त्र समझा गया । इस दलने वैधानिक सत्ताको संघटित करनेकी नीति भी निश्चित की और यह सिद्धान्त स्वीकार किया कि यदि नौकरशाही जनताके आत्मावलम्बनके मार्गमें बाधा उपस्थित करे तो निष्क्रिय प्रतिरोधकी नीति चलायी जाय । आवश्यकता होनेपर प्रतिरोधकी यह नीति आक्रामक भी हो सकती थी । इसके अतिरिक्त यह प्रतिरोध किन्हीं विषेय कठिनाइयोंको दूर करानेके लिए नहीं था, बल्कि एक स्वतन्त्र लोकतन्त्रात्मक सरकारकी स्थापना ही उसका लक्ष्य था । इस नये दलकी महत्ता इस बातमें है कि इसने वर्तमान राजनीतिक मूल सत्तोंकी अनुभूति की । इस दलके हाथमें भारतकी राजनीति जब आयी तो उसने अपनी पुरानी पद्धतिका परित्याग कर दिया और इस प्रकार सर्वप्रथम उसकी ठोस बुनियाद पड़ी । पुराने राजनीतिज्ञोंका सारा राजनीतिक दृष्टिकोण ब्रिटिश इतिहासमें विद्यमान था और चूँकि उन्हें जनताकी शक्तिमें विश्वास न था तथा ब्रिटेनकी शक्तिकी भारी धाक उनपर बैठ चुकी थी इसलिए अपनी मुक्तिका पथ खोजनेमें वे सर्वथा असमर्थ थे । नये दलने ऐसी कितनी ही पुरानी धारणाओंको नष्ट कर डाला जिनमें कि हमारे उदार-दलीय नेता अब भी चिपटे पड़े थे ।

१९०८ में कांग्रेस कन्वेंशनने जो विधान निश्चित किया उसके सम्बन्धमें जो वादविवाद आरम्भ हुआ उससे नये और पुराने दलोंको अलग करनेवाला मतभेद स्पष्ट हो गया । नया दल चाहता था कि कांग्रेस लोकतन्त्रात्मक संस्था रहे । उसने लिखित विधानकी माँग उपस्थित की । परन्तु पुराना दल थोड़े ही व्यक्तियोंके हाथमें सत्ता बनाये रखनेके पक्षमें था । दोनों दलोंमें मतभेदका एक प्रश्न और था । वह यह कि आन्दोलन अपने उद्देश्य, लक्ष्य और भावनामें राष्ट्रीय और प्रगतिशील रहे अथवा अनुदार । स्वराज्यका वास्तविक रूप कैसा हो तथा निष्क्रिय प्रतिरोधकी नीति कैसी रहे—इस प्रकारके

प्रश्नोपर भी दोनों दलोमे मतभेद था । नया दल औपनिवेशिक स्वराज्यको भारतके लिए व्यावहारिक और अन्तिम लक्ष्य नहीं मानता था । श्रीअरविन्द घोषके शब्दोमे “कांग्रेस कन्वेन्शनने ऐसा विधान स्वीकार किया जो सकुचित एकांगी, अलोकतन्त्रात्मक था और इस ढंगसे बना था कि उसमे जनताके प्रतिनिधियोका स्वतन्त्र निर्वाचन मर्यादित हो गया था ।

“नेशनलिस्ट’ दल लोकतन्त्र, विधानवाद और प्रगतिका समर्थक था । ‘माडरेट’ दल जिसकी पुराने नेताओमे अगाध श्रद्धा थी उनके कार्योंको भली प्रकार समझे बिना ही उनकी सहायता करता था । जो थोड़ेसे लोगोके शासन अधिनायक पद्धति और प्रायः प्रतिक्रियावादी अपरिवर्तनके पक्षमे थे ।” (देशवासियोके नाम खुली चिट्ठी, १९०८) ।

नये दलके सिद्धान्तों और विचारोकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । यह अपनेको ‘नेशनलिस्ट’ दल कहता था । यो सर्वसाधारण इसे गरम दल (एक्सट्रीमिस्ट) कहते थे । पूर्वी बङ्गालमे बहिष्कारके शस्त्रका कुछ व्यापक रूपमे प्रयोग किया गया और कुछ अशोमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई । राष्ट्रीय स्कूल खोले गये, पञ्चायतोकी स्थापना की गयी और जनतामे स्वदेशीकी भावना प्रसारित की गयी । कानूनका साधारणतः आदर किया जाता था, इसलिए नहीं कि उसका भंग करना अनुचित था वरन् इसलिए कि यह आन्दोलनकी आरम्भिक अवस्था थी । ऐसे समय कानून भंग करना अबुद्धिमत्तापूर्ण एवं असुविधाजनक होता । इस नयी विचारधाराका देशमे सर्वत्र स्वागत किया गया और बंगालमे तो इसने जड़ ही पकड़ ली । आरम्भसे ही इसे सरकारी प्रहार सहन करना पड़ा, पर सूरतके विभाजनके उपरान्त तो सरकार इसपर बुरी तरह टूट पड़ी । उसका दमनचक्र पूरे वेगसे चलने लगा, नेता या तो गिरफ्तार कर लिये गये या वे स्वयं निर्वासित हो गये । कांग्रेसकी नयी विचारधारा दलको अस्वीकार थी अतः उसके सदस्य अनेक वर्षोंतक कांग्रेससे पृथक् रहे । इस कारण कांग्रेसकी शक्तिकी बड़ी हानि हुई और जनतापरसे उसका प्रभाव बहुत कुछ जाता रहा । आन्दोलन छिपकर चलने लगा और देशमे कितने ही आतंकवादी दल बन गये जिन्हें कि कम और कमचोकी पद्धतिमे ही विश्वास था । व्यक्तिगत साहस और अत्यधिक बलिदानके कितने ही उत्तम उदाहरण हमारे सम्मुख उपस्थित हुए परन्तु आतंकवाद हमारे कष्टोकी रामबाण और्पधि साबित न हो सका ।

१९१६मे श्रीमती बेसेन्टके प्रयत्नसे दोनो पक्ष फिर मिल गये । यद्यपि ‘नेशनलिस्ट’ दल कांग्रेसमे पुनः लौट आया था पर एकताके लिए उसे अपने पुराने आदर्शोको बहुत कुछ ढीला कर देना पड़ा । अवश्य ही उसने शीघ्र ही अपना प्रभाव स्थापित कर लिया परन्तु दुर्भाग्यवश उसमे और पुराने उदार पन्थियोमे कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था । असहयोग आन्दोलनके दिनोम नये दलकी अनेक धारणाएँ कार्यरूपमे परिणत हुई । १९०६-१९०८मे जो प्रयोग छोटे पैमानेपर हुए थे वे १९२१-१९२२मे राष्ट्रव्यापी पैमानेपर किये गये । पर यह बात माननी पड़ेगी कि नेशनलिस्टदलकी विचारधाराने नींवका काम किया और उसीपर शुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन पुष्पित-पल्लवित हुआ ।

कुछ लेखकोका ऐसा कहना है कि नया आन्दोलन कुछ अंशोमे प्रतिक्रियावादी

था। यद्यपि यह सही है कि इस नयी विचारधाराके प्रमुख प्रवर्तकोपर हिन्दू संस्कृतिका विशेष प्रभाव था, तथापि अपने लेखों और भाषणोंमें वे सदैव ही पुरातन संस्कृतिके मूल तत्वोंपर जोर देते थे। 'वन्देमातरम्' (१९०८) के एक अग्रलेखके इस अंशसे यह बात स्पष्ट हो जायगी—“हमारी दार्शनिकता और भावुकतामें हमारी पुरातन संस्कृति तथा विचारधाराको बहुत मर्यादित कर रखा है और ये सर्वश्रेष्ठ नहीं तो अनेकांशमें हमारे पतनके लिए उत्तरदायी हैं। इन्हींके कारण हमने अपना प्राचीन एवं गौरवशाली स्थान खो दिया है। यदि हम अब भी इसी मार्गपर चलते रहे तो हम अपनी पराधीनता और पतिततावस्थाको और अधिक स्थायी बना लेंगे।... अपनी इन्द्रियोंको मारकर और बाहरी जगत्के सधर्मोंसे अपनेको वंचाकर हम आन्तरिक शान्ति प्राप्त करनेका दीर्घकालसे प्रयत्न करते आ रहे हैं।... एशियाके और मुख्यतः भारतीय संस्कृतिके पुनर्जागरणमें एशियाके और विशेषतः भारतके प्राचीन आध्यात्मिक आदर्शोंको हमें समझ बूझकर घातक रूढ़ियों और वास्तविकता-विरोधी बातोंसे सर्वथा पृथक् कर देना होगा जिनसे वे आदर्श बुरी तरह गुथ गये हैं।” इन लोगोंके हाथमें पड़कर वेदान्त एक शक्तिशाली दर्शन बन गया। लोकमान्यने गीतारहस्य लिखकर कर्मयोगकी महत्ता बतायी।

बहुतसे नेताओंका दृष्टिकोण आधुनिक था। इस बातका ज्ञान उनकी रचनाओंसे प्राप्त किया जा सकता है। कुछ प्रमुख उदाहरणोंका राजनीतिक उद्देश्योंके लिए उपयोग किया गया, यह देखकर यह कहना ठीक नहीं कि सामाजिक और धार्मिक मामलोंमें वे प्रतिक्रियावादी थे। जनसमूहके भीतर राजनीतिक कार्य करनेके लिए राजनीतिक शिक्षणकी यह पद्धति अत्यन्त उत्तम समझी गयी। जनताकी राष्ट्रीय भावनाओंको जागृत करनेके लिए राष्ट्रीय वीरोंकी जयन्तियाँ मनाना प्रारम्भ किया गया। निश्चय ही कोई व्यक्ति ऐसा कहनेका साहस न करेगा कि लोकमान्यने शिवाजी जयन्तीका जो श्रीगणेश किया उसमें उनके हृदयमें मरहटा साम्राज्य अथवा हिन्दूपद पादशाही स्थापित करनेकी कल्पना थी। सहवासकी आयु-सम्बन्धी विलका उन्होंने विरोध किया था। इस बातको उनके विरुद्ध प्रमाणके रूपमें उपस्थित करके कहा जाता है कि वे सामाजिक मामलोंमें प्रतिक्रियावादी थे। बालिकाओंके विवाहकी आयुमें वृद्धि करनेके प्रश्नपर उन्हें उतनी आपत्ति नहीं थी, जितनी इस बातपर आपत्ति थी कि एक विदेशी जाति और संस्कृति, एक विदेशी सरकार भारतकी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं और प्रथाओंमें हस्तक्षेप करे। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र राजनीति था। वे ऐसे सामाजिक सुधारके आन्दोलन में पड़ना नहीं चाहते थे जिससे सनातनधर्मों वर्गके भीतर राजनीतिक कार्य करनेमें कोई बाधा उपस्थित हो। वे कानूनद्वारा सामाजिक सुधार करानेके पक्षमें नहीं थे। वे चाहते थे कि सामाजिक सुधार शिक्षा और प्रचारद्वारा हो। दलके अन्य नेताओंपर इस प्रकारका आरोप नहीं लगाया जा सकता। वे कट्टर समाजसुधारक थे।

नये दलने विचारोंके क्षेत्रमें सफल क्रान्ति की। हमारे राष्ट्रीय इतिहासमें उसे सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिये। नेशनलिस्ट दलको ही यह श्रेय प्राप्त है कि उसने राष्ट्रीय आन्दोलनको दृढ़ आधारपर स्थापित किया और सर्वप्रथम अपने लक्ष्य और उद्देश्य-

की स्पष्ट रूपसे व्याख्या की तथा यह भी स्पष्ट कर दिया कि अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए वह किन उपायोको ग्रहण करेगा । उसे इस बातका भी श्रेय प्राप्त है कि उसने आरम्भमें जिन नीति और कार्यक्रमका निश्चय किया था, विगत २५ वर्षके भीतर वह ज्योंका त्यों बना रहा । उसमें कुछ भी हेरफेर नहीं किया गया । समाजवादी विचारधाराने अवश्य ही इधर कुछ वर्षोंसे कांग्रेसनीतिको एक नया पूर्वीय जामा पहनाया है, पर वर्तमान युगमें सभी प्रगतिशील आन्दोलनोके लिए ऐसा स्वाभाविक है । नये युगकी मुख्य देन यह है कि उसने उन बातोंको राष्ट्रव्यापी व्यावहारिक रूप प्रदान किया है जो बाते १९०६-१९०८ में नेशनलिस्ट दलने करनेके लिए कही थी । राजनीतिक क्षेत्रमें गांधीजीकी मुख्य देन यह है कि उन्होंने सघर्षके नये नये उपाय खोज निकाले और उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान किया, पर हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि निष्क्रिय प्रतिरोधका विचार १९०६ में ही कर लिया गया था और नयी नीतिका वह अनिवार्य अंग माना गया था । सभी क्रान्तिकारी राष्ट्रीय आन्दोलनोके मूलमें स्वावलम्बन और आत्मनिर्णयकी शक्तिशाली नीति रहती है । तिलक, विपिनचन्द्रपाल और अरविन्द घोषके सबल नेतृत्वमें नेशनलिस्ट दलने ऐसी नीति निश्चित की और उसका पालन किया । इस प्रकार हम देखते हैं कि १९०५का वर्ष हमारे स्वातन्त्र्य आन्दोलनके इतिहासमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इस वर्ष मृतप्राय जनतामें, जिसने अपनी शक्ति और स्वतन्त्रता खो दी थी, नवजीवनका संचार हुआ और इस क्रान्तिका श्रेय नेशनलिस्ट दलको है । उसीने जनताको नया मार्ग दिखाया और उसे ऐसी रामबाण औषधि प्रदान की जिससे वह खोयी हुई स्वधीनता पुनः प्राप्त कर सके ।

दूसरा अध्याय

स्वतन्त्रता संघर्ष

दूसरा अध्याय

अभिभाषण^१

बहनो और भाइयो,

आपने इस सम्मेलनका सभापति चुनकर मुझको जो आदर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । मैं अपनेको इस पदके लिए सर्वथा अयोग्य पाता हूँ । आजकलके जमानेमें राजनीतिक संस्थाओंका सफल संचालन करना हँसी-खेल नहीं है । वह संस्थाएँ भी जिनके सम्मुख उँचे आदर्श हैं और जो तात्कालिक लाभकी उपेक्षा कर समाजके मौलिक हितोंकी सिद्धिमें ही सतत प्रयत्नशील रहती हैं, ईर्ष्या, द्वेष और आपसकी दलबन्दीसे सर्वथा अछूती नहीं रह पाती । भलीसे भली संस्थाएँ भी इस रोगसे मुक्त नहीं हैं । गिरोहबन्दी, पदलोलुपता, अधिकारकी चाह यह ऐसी दुर्वलताएँ हैं जिनसे वचना बड़ोके लिए भी कभी-कभी टुटकर हो जाता है । इन सब कठिनाइयोंका धैर्य और साहसके साथ मुकाबला करना और उनसे विचलित न होना, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और समुदायोंको सन्तुष्ट रखना, विरोधियोंके अनुचित प्रहारोंको सहन करनेकी अपरिमित शक्ति रखना, मनोगत भावोंको गुप्त रखनेमें कुशल होना और प्रत्येक परिस्थितिमें आशावान् बने रहना यह एक ऐसी कला है जिसका जानकार हरएक नहीं हो सकता और जो इस कलाको नहीं जानता वह साधारण रीतिसे राजनीतिक संस्थाओंका सफल सूत्रधार नहीं बन पाता । मुझे खेदके साथ कहना पड़ता है कि इस कलाके सीखनेका मुझे जीवनमें अवसर नहीं मिला । एक अध्यापकका जीवन सरल और नीरस होता है । शिक्षाकी जीविका इसीलिए निर्दोष समझी जाती है और इस पेशेमें अधिकतर वे ही लोग आते हैं जो स्वभावसे शान्त और निस्पृह होते हैं । किन्तु राजनीतिक जीवनमें शान्ति कहाँ ? वह तो राग-द्वेषसे आपूर्ण है । वह जीवन साथ ही साथ इतना सरस और आकर्षक होता है कि लोग अन्य प्रकारसे दुखी होते हुए भी उसमें एक विशेष प्रकारके माधुर्यका रसास्वाद करते हैं ।

अपने प्रान्तके कांग्रेस कार्यमें भी मेरा ऐसा कोई स्थान नहीं रहा है जिसके कारण मैं समझूँ कि आपकी कृपादृष्टि मेरे ऊपर पड़ी । आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बरसोंसे किसी नगर या जिला कांग्रेस कमेटीका मेम्बर भी नहीं रहा हूँ । प्रान्तके संगठनसे मेरा कोई घनिष्ठ सम्बन्ध भी नहीं रहा है । फिर क्या कारण है कि मैं आपकी कृपाका पात्र बना और आपने उचित समझा कि आप मुझको यह गौरव प्रदान करे ? मैं तो यही समझता हूँ कि आपने इस तरह उस शिक्षासंस्थाके कार्यपर अपनी

१. युक्त प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलनके उन्नीसवें अधिवेशन (बरेली) में सभापति पदसे दिया गया भाषण ।

पसन्दोदगोकी मुहर लगाना चाहा है जिसके प्रधानाध्यापकका कार्य मैं इधर कई सालसे कर रहा हूँ—मेरा मतलब काशी विद्यापीठसे है ।

जो विद्यार्थी इस शिक्षा-संस्थासे निकले हैं उनमेंसे अधिकांश राष्ट्रीय कार्यमें लगे हुए हैं और उन्होंने स्वतन्त्रताके युद्धमें उचित भाग लेकर विद्यापीठके गौरवको देशमें बढ़ाया है और उसकी कीर्तिको उज्ज्वल किया है । उनकी शिक्षा-दीक्षामें और उनको विद्या तथा आचरणसे सम्पन्न करनेमें मेरा भी हाथ रहा है और मुझे इसका गर्व है ।

मैं समझता हूँ कि जीवनकी अन्तिम घड़ियोंमें मैं जब अपने कामका हिसाब लगाऊँगा तब मुझे अपने जीवनका वह भाग जो विद्यापीठकी सेवामें व्यतीत हुआ है सबसे अधिक सन्तोषप्रद प्रतीत होगा । यही मेरी पूँजी है और इसी पूँजीके बलपर मेरा राजनीतिक व्यापार चलता है । मैं समझता हूँ कि इसी सबबसे मैं आप महानुभावोंके स्नेहका भाजन बन सका हूँ ।

यद्यपि मैं इस सम्मानके लिए आपका ऋणी हूँ तथापि मैं आपको इस चुनावके लिए मुबारकवाद नहीं दे सकता । यह जानते हुए भी कि मैं इधर दो वर्षसे काफी अस्वस्थ रहता हूँ और किसी कठोर भारको वहन करनेमें असमर्थ हूँ आपने ऐसे असाधारण समयमें मुझको सम्मेलनका सभापति निर्वाचित किया है । देश और ससारके लिए यह एक अनोखा युग है । उन्नति और प्रतिक्रियामें सब जगह संघर्ष चल रहा है । प्रतिक्रियागामी शक्तियाँ जो पतनोन्मुख हैं अपने अस्तित्वके लिए एक आखिरी कोशिश कर रही हैं । प्रगतिशील शक्तियाँ उनसे अपनी रक्षा करनेके लिए तथा अपने विकासके लिए सचेष्ट हैं । एक नवीन अभ्युदयके चिह्न सब ओर परिस्फुट हो रहे हैं । क्रान्तिकी लहर, कहीं द्रुत वेगसे, तो कहीं मन्द गतिसे, उद्वेलित हो रही है । इस समय प्रत्येक व्यक्तिका, जो मानव-समाजका कल्याण और अभ्युदय चाहता है, यह पुनीत-कर्तव्य है कि वह प्रतिक्रियाका विरोध करे और क्रान्तिका स्वागत कर उस नवीन सभ्यता-शालीनताकी मूलभित्तिकी स्थापनामें सहयोग करे जिसके आधारपर एक नये सामाजिक जीवनकी इमारत खड़ी की जानेवाली है । इस समय कोई भी कर्मी जो देशका सच्चा सिपाही है खामोश नहीं बैठ सकता और देशके आह्वानकी उपेक्षा नहीं कर सकता । आप समझ सकते हैं कि इस समय मेरी कितनी प्रबल इच्छा होगी कि मैं अपने कर्तव्यका यथार्थ पालन करूँ किन्तु मनकी इच्छा मनमें ही रह जाती है और रुग्ण तथा क्षीण शरीरसकल्यको पूरा नहीं होने देता ।

ऐसी स्थितिमें मैं आपके निमन्त्रणको अस्वीकार करनेका दुस्साहस नहीं कर सकता था किन्तु आपको तो मुझे इस कठिनाईमें न डालना चाहिये था । यह आपकी गलती है कि मैं इस रुग्णावस्थामें इस आसनपर बिठा दिया गया हूँ । मैं आशा करता हूँ कि आपमें कमसे कम इतनी वजादारी तो जरूर होगी कि आप अपनी गलतीको निभावेगे । मैं आपसे पहले ही अपनी कमजोरियाँ बता चुका हूँ । यह स्पष्ट है कि आपके सहयोगके बिना मैं इस सम्मेलनका कार्य सुचारु रूपसे सम्पन्न न कर सकूँगा । मुझे आपके सहयोगकी जरूरत है और मुझे आशा है कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ न जायगी ।

यह धुशीकी बात है कि पिछले कुछ महीनोंमें हममेंसे हर एकने उस विद्वेषकी अग्निको

दवानेकी कोशिश की है जो हमारे दुर्भाग्यसे गत वर्ष अपने प्रान्तमें प्रज्वलित हो उठी थी । उस समय सारे देशके सामने हमको अपना सिर लज्जासे झुका लेना पड़ता था । बङ्गालको इससे अवश्य प्रसन्नता हुई थी कि देशमें उसका भी साथ देनेवाला पैदा हो गया है और वह अपने अकेलेपनके दुःखको थोड़ी देरके लिए भूल गया था । हमको अब भी काफी सतर्क रहनेकी जरूरत है, क्योंकि कभी-कभी हम देखते हैं कि राखके ढेरको कुरेदनेकी कोशिश की जाती है । इसके अतिरिक्त द्वेपका बीज सर्वथा विदग्ध नहीं हुआ है । हमको द्वेपके कारणोंका अन्वेषण करना चाहिये और यथासम्भव इस बातका प्रयत्न करना चाहिये कि हम अपने तुच्छ झगड़ोंको भुला दे और परस्परके वैमनस्यको दूर कर दे । छोटी-छोटी बातोंको हम महत्व देकर प्रायः बातका बतंगड बना देते हैं । मैं मानता हूँ कि छोटी-छोटी बातें हमेशा सारहीन नहीं होती और कभी-कभी उनकी उपेक्षा करते नहीं बन पड़ता । फिर भी आपसमें झगड़नेका एक समय होता है और उस झगड़नेकी भी एक मर्यादा होती है । हम कांग्रेसवादियोंको इस विषयमें सदा जागरूक और सतर्क रहनेकी जरूरत है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी शक्ति और हमारा एकमात्र आधार हमारा सुव्यवस्थित सगठन ही है । हमारा सगठन जितना दृढ़ होगा, हम जितना अधिक एक अनुशासनके सूत्रमें अपनेको आवद्ध समझेगे उतना ही अधिक अपने विरोधियोंपर विजय पानेमें हम समर्थ होंगे । हम एक महान् व्रतके व्रती हैं । हम केवल एक राजनीतिक दलके सदस्यकी ही हैसियत नहीं रखते, बल्कि हम देशकी परतन्त्रता दूर कर एक नूतन समाजकी नींव डालना चाहते हैं । हमारा काम केवल साम्राज्यवादके शोषणका ही अन्त करना नहीं है, बल्कि साथ-साथ देशके उन सभी वर्गोंके शोषणका अन्त करना है जो आज जनताका शोषण कर रहे हैं । हम एक ऐसी नयी सभ्यताका निर्माण करना चाहते हैं जिसका मूल प्राचीन सभ्यतामें होगा, जिसका रूप-रंग देशी होगा, जिसमें पुरातन सभ्यताके उत्कृष्ट अंश सुरक्षित रहेंगे और साथ-साथ उसमें ऐसे नवीन अंशोंका भी समावेश होगा जो आज जगत्में प्रगतिशील हैं और ससारके सामने एक नवीन आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं ।

हमारा कार्य इतना व्यापक है, हमारा उद्देश्य इतना ऊँचा और उत्कृष्ट है कि हम किसी प्रकार भी छोटी-छोटी बातोंमें पड़कर अपनी शक्तिका अपव्यय नहीं कर सकते । हमको तो उन बहुतसी बातोंकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखना चाहिये जो आज हमको अपने मायाजालमें फँसना चाहती हैं । हमको अपने विशाल लक्ष्यका ध्यानकर इन छोटी बातोंसे मुँह मोड़ना पड़ेगा और अपने लोभका सवरण करना पड़ेगा ।

यदि वास्तवमें हम अपने कार्यका ऐसा ही स्वरूप समझते हैं तो हमको उसके अनुरूप अपने आचरणको बनाना पड़ेगा । हमको अपना कार्य सुसम्पन्न करनेके लिए एक ऐसा सुसंगठित दल तैयार करना होगा जिसके सदस्य अपने उद्देश्यों तथा अपनी कार्यप्रणालीका स्पष्ट ज्ञान रखते हों, जिसमें अनुशासन हो और जिसके नेता दूरदर्शी, कार्यकुशल और नवीन युगकी विशेषताओं और आवश्यकताओंसे अभिन्न हों ।

अपने घरको दुरुस्त करनेके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वह आत्म-

समीक्षाका है। सब उन्नतिका मूल इसीमें निहित है। मनुष्यको अपने कार्यका सतत निरीक्षण करते रहना चाहिये। जहाँ भूल मालूम पड़े उसे सुधार लेना बुद्धिमानकी काम है। यह समझते रहना कि हमने कोई भूल नहीं की है आत्म-वंचना मात्र है। इस मनोवृत्तिसे उन्नतिका क्रम रुक जाता है। इसलिए हमको बारम्बार विचार करना चाहिये कि हमारी अवतककी चेष्टाएँ क्यों विफल हुईं। यदि हमारी कार्य-प्रणालीमें कोई त्रुटि है तो उसे दूर करनेका उद्योग होना चाहिये। यदि सगठनमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है तो उसके लिए तैयार हो जाना चाहिये।

हमको अपने सगठनको दृढ़ बनाना होगा। हमारे सगठनका आधार जितना ही विस्तृत होगा उतना ही अधिक यह शक्ति-सम्पन्न होगा। हमको साम्राज्यविरोधी संग्राममें किसान और मजदूरोंको विपुल संख्यामें सम्मिलित करना होगा। इसी दृष्टिसे कांग्रेसने गत अधिवेशनमें जनतासे सम्पर्क (मास कंटैक्ट) स्थापित करनेका प्रस्ताव स्वीकार किया था। उसको कार्यान्वित करना हमारा काम है।

अवतक कांग्रेसके सदस्य वर्षमें केवल एकवार प्रतिनिधियोंको चुनावके लिए एकत्र होते हैं। उसी समय हम उनके सम्पर्कमें आते हैं। बाकी सालभर हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। हम उनमें चेतना उत्पन्न करनेकी कोई चेष्टा नहीं करते। उनके दैनिक जीवनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता। हमको चाहिये कि हम उनके दैनिक जीवनमें प्रवेश करें। उनके आर्थिक कष्टोंको दूर करनेके लिए उन्हें सगठित करें तथा इस कार्यमें उनको हर प्रकारकी सहायता प्रदान करें। इसी तरह हम जनताके साथ गहरा सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। जनताके दैनिक जीवनके आर्थिक सघर्षको साम्राज्य-विरोधी संग्रामसे सम्बन्धित करनेसे ही जनता राष्ट्रीय आन्दोलनमें सजीव भाग लेनेको तैयार हो सकती है। किसान और मजदूर यह देशके दो ऐसे बहुसंख्यक वर्ग हैं जो इस संग्रामके प्रमुख सैनिक हैं। इनका सगठित होना अत्यन्त आवश्यक है। किसान और मजदूर अपनी-अपनी जमाअतमें ही संगठित हो सकते हैं। इनकी स्वतन्त्र सस्थाएँ होना आवश्यक है। प्रान्तमें जो किसान और मजदूर सघ मौजूद हैं उनके कार्यमें शरीक होना हमारा कर्तव्य है।

इन सस्थाओंके साथ कांग्रेसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना चाहिये। मजदूर और किसान सघके सदस्योंको कांग्रेसमें अपने प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार प्राप्त होना चाहिये; केवल इसलिए नहीं कि कांग्रेसके सम्मुख उनका दृष्टिकोण रखा जा सके, वरन् इसलिए कि वह कांग्रेसके निर्णयोंको अधिकाधिक प्रभावित कर सकें। कांग्रेसके सदस्यकी हैसियतसे नहीं, बल्कि अपनी सस्थाओंके प्रतिनिधिकी हैसियतसे ही वह यह काम कर सकते हैं।

कांग्रेसका कार्य सुचारु रूपसे चलानेके लिए हमको राष्ट्र-कर्मिसघ (नैशनल सर्विस) की आवश्यकता है। हमारे देशको ऐसे कार्यकर्ता चाहिये जो अपना सारा समय राजनीतिक कार्यमें व्यय करें। इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसकी यदि सुव्यवस्था करनी है तो यह तभी सम्भव है जब हम उनकी जीविकाकी फिक्र करें। हमारे प्रान्तमें कई वर्षतक नैशनल सर्विसकी आयोजना थी, किन्तु कुछ समयसे अर्थाभावके कारण हमको

इस सर्विसको तोड़ देना पड़ा । मैं समझता हूँ कि यदि सम्भव हो तो हमको इसका प्रबन्ध छोटे या बड़े पैमानेपर फिरसे करना चाहिये । जो सज्जन इस सर्विसमें सम्मिलित किये जावे उनको निपुण कार्यकर्ता बनानेका आयोजन होना चाहिये । मैं समझता हूँ अबतक हमारा काम जिस तरहसे चलता रहा है वह सन्तोषप्रद नहीं है । पुराने 'फार्मूलो' के सहारे हमारा काम अब नहीं चल सकता । परिस्थितिमें महान् परिवर्तन हो गया है । उसीके अनुसार हमको कार्य-प्रणाली बदलनी होगी । इसमें सन्देह नहीं कि हमारे कार्यकर्ताओंने असाधारण स्वार्थत्याग, अपूर्व लगन और सगठनकी योग्यताका अच्छा परिचय दिया है । किन्तु यह भी प्रत्यक्ष है कि वह समयानुकूल अपने कामके ढंगमें परिवर्तन करनेकी क्षमता नहीं रखते । यह चोटीके कार्यकर्ताओंका काम है कि वह निर्णय करे कि उनको किस किस दिशामें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है और इसे स्थिर करके इसकी शिक्षा दिलानेका प्रबन्ध करे । कार्यकर्ताओंके मानसिक क्षितिजको भी बढ़ानेकी जरूरत है । हमने उनको एक साँचेमें ढाल दिया है पर अब वह साँचा उतना उपयोगी नहीं रह गया है जितना कि पहले था । यह स्पष्ट है कि हमारे पुराने हथियार अब आगे उतने कारगर न रहेंगे । हमारे युद्धका रहस्य और प्रकार (टेकनिक) दूसरोंने जान लिया है और उसके प्रतिकारका प्रकार भी स्थिर कर लिया है । हमारा आन्दोलन एक मजिल ऊपर उठ रहा है । इसके लक्षण स्पष्ट दीख पड़ते हैं । इतिहासकी आवश्यकता चाहती है कि राष्ट्रीय आन्दोलन एक उँचे स्तरमें प्रवेश करे । यह आवश्यकता पूरी होकर रहेगी चाहे यह कार्य हमारे द्वारा सिद्ध हो या अन्य संस्थाओं द्वारा । किसान और मजदूरोंमें वर्ग-चेतना बढ़ती जाती है । वस्तुस्थिति इसके अनुकूल है । इसको रोकनेके तरह तरहके उपाय हो रहे हैं । नये-नये कानून बनाये जाते हैं । उनकी सस्थाएँ गैरकानूनी करार दी जाती हैं, उनके कार्यकर्ता जेलमें बन्द किये जा रहे हैं और उनके अखबारोंसे जमानत तलब की जाती है । कांग्रेस इन नवीन शक्तियोंकी उपेक्षा नहीं कर सकती । इनसे सम्बन्ध जोड़ना और इनकी आकांक्षाओंको अपनाना तथा उनकी पूर्तिके लिए उद्योग करना कांग्रेसके लिए आवश्यक हो गया है । यदि कांग्रेस इस कार्यको नहीं करेगी तो वह पिछड़ जावेगी और इतिहास-निर्दिष्ट कार्य किसी अन्य संस्था द्वारा सम्पन्न होगा ।

यह हम ऊपर कह चुके हैं कि स्वतन्त्रताकी लड़ाईको आगे बढ़ानेके लिए जनताका संगठन अत्यन्त आवश्यक हो गया है । क्या हम नहीं देखते हैं कि देशकी प्रतिक्रियागामी शक्तियाँ समाजके वह वर्ग जो जनताका शोषण करते हैं और अपने अस्तित्वके लिए विदेशी हुकूमतके आश्रित हैं, आज ब्रिटिश साम्राज्यवादकी छत्रछायामें अपनेको सगठित कर रहे हैं ? उन्नतिशील वर्गोंकी बढ़ती हुई शक्तिको रोकनेके लिए ही इस नवीन विधानका जन्म हुआ है । जहाँ १९१६ ई०के विधानका आश्रय भारतीय शासनमें तथा उद्योग-व्यवसायके क्षेत्रमें हिन्दुस्तानियोंको एक छोटा-सा हिस्सेदार बनाकर सन्तुष्ट करना था वहाँ इस नये विधानका गूढ़ अभिप्राय देशकी सकल प्रतिक्रियागामी शक्तियोंको राष्ट्रीयताके विरोधमें खड़ा करना है । इस उद्देश्यको पूरा करनेके लिए शासकोंकी ओरसे अथक प्रयत्न कई सालसे हो रहा है । उनकी यह कोशिश है कि नये विधानमें शासनकी वागडोर

उन वर्गोंके हाथमें रहे जो गवर्नमेंटके सहायक हैं। उसी दृष्टिसे संरक्षणोंके नियम बने हैं; इसी दृष्टिसे चुनावके निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये हैं। उसी दृष्टिसे हरिजनोंको और ईसाइयोंको सुरक्षित स्थान अथवा पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसी विचारसे अपने प्रान्तके देहाती क्षेत्रोंमें रगीन बक्सकी व्यवस्था नहीं की गयी है। उसी दृष्टिसे सार्वदेशीय व्यवस्थापक सभा (फेडरल लेजिसलेचर)के लिए अप्रत्यक्ष चुनावका प्रचार स्वीकृत हुआ है और देशी राज्योंकी प्रजाको अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार नहीं दिया गया है।

सन् १९३२ में ही अर्थात् नये विधानके मंजूर होनेके तीन वर्ष पूर्व ही इस प्रान्तके तत्कालीन गवर्नर सर मालकम हेली (अब लार्ड हेली) ने अपनी वक्तृताओंमें यहाँके जमींदारों तथा व्यापारियोंको सलाह दी थी कि वह अपना एक दल संगठित करें जो उनके हितोंकी रक्षा करनेके लिए इन नये अधिकारोंका उपयोग करें। इस सम्बन्धमें उन्होंने गवर्नमेंटकी नीतिको इन शब्दोंमें स्पष्ट किया था—

“आपकों एक दल संगठित करना होगा, जिसके पास एक कोष हो और जो उन्नित रूपसे अनुशासनके सूत्रमें परस्पर आवद्ध हो। जबतक यह संगठन प्रस्तुत नहीं हो जाता तबतक हम अधिकारी लोग छत्तको आपके लिए सुरक्षित रखनेका प्रयत्न कर सकते हैं। हम प्रचारद्वारा ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे ऐसे दलकी सृष्टिमें सहायता मिले किन्तु हम दलकी सृष्टि नहीं कर सकते। यह काम दूसरोंके करनेका है। मेरी अपील बड़े और छोटे जमींदार, व्यापारी तथा विविध पेशेके लोगोंसे है। हमारे सामने एक बड़ा खतरा है। केवल जायदादवाले लोगोंको ही नहीं वरंच सब शान्तिप्रिय लोगोंको इस खतरेसे बचनेके लिए संगठित हो जाना चाहिये।” एक दूसरी वक्तृतामें आप जमींदारोंको चेतावनी देते हैं कि यदि नये अधिकार गलत हाथोंमें चले गये तो नये विधानसे न आप और न प्रान्त कुछ लाभ उठा सकेगा। यदि इसके बाद शासकोंकी ओरसे यह कहा जाय कि हम निर्वाचनके मामलेमें तटस्थ हैं तो इस उक्तिपर कैसे विश्वास किया जा सकता है।

ज्यो-ज्यो वर्ग-चेतना बढ़ती जावेगी त्यो-त्यो मध्यम श्रेणीके लोग (अर्थात् बड़े जमींदार, पंजीपति आदि) विदेशी सत्ताके और नजदीक आते जावेंगे। इसका कारण यह है कि इस श्रेणीके लोग विदेशी हुकूमतको तो किसी प्रकार सहन भी कर सकते हैं किन्तु जनसाधारणकी क्रान्तिको सफल होते नहीं देख सकते। यह अवस्था अपने देशमें उत्पन्न होती जाती है। ऐसे समय निम्न मध्यम वर्गके लोग किकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं। सामान्यतः वह मध्यम श्रेणीके प्रभाव और अधिकारसे विशेषरूपसे प्रभावित हुआ करते हैं। जनतापर सामान्य रूपसे उनका विश्वास नहीं रहता। वह उसके अपरिमित शक्ति-भंडारसे अपरिचित हैं। जनताकी शक्तिका प्रदर्शन होनेपर भी वह सहसा इस बातपर विश्वास नहीं करते कि यह शक्ति टिकाऊ हो सकेगी। सच बात तो यह है कि जनता आज प्रगतिशील नेतृत्वको स्वीकार करनेके लिए तैयार है किन्तु हम आप ही आत्म-विश्वासकी कमीसे इन नवीन शक्तियोंका स्वागत करनेमें अपनेको अशक्त पाते हैं।

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि हमारा कार्य व्यापक है। इसलिए हम जीवनके किसी विभागकी भी उपेक्षा नहीं कर सकते। हमको प्रत्येक क्षेत्रमें कार्य करनेकी आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थानसे हमारे उद्देश्यकी पूर्तिमें थोड़ा बहुत सहायक अवश्य हो सकता है। अपने साहित्य की गतिविधिपर भी हमको सदा ध्यान रखना चाहिये। प्रगतिशील साहित्यके प्रस्तुत करनेमें हमको भी सहयोग करना चाहिये। नये समाजके गठनके कार्यमें साहित्यसे बड़ी सहायता मिल सकती है।

साहित्यिकोंकी ओरसे यह आवाज उठायी जाती है कि राजनीतिज्ञ साहित्यपर भी अपना नियन्त्रण कायम करना चाहते हैं। ससारके साहित्यिकोंका सदासे यह कायदा रहा है कि वह राजनीतिज्ञोंके हस्तक्षेपका विरोध करते आये हैं। वह राजनीतिको सदासे ही तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते आये हैं और राजनीतिज्ञोंसे वह सदा सशंक रहते हैं। यह बात अकारण नहीं है। किन्तु जो लोग सामाजिक जीवनको ही बदलना चाहते हैं वह कैसे साहित्यकी उपेक्षा कर सकते हैं? साहित्यकी प्रत्येक कृति चाहे उसका स्वरूप और विषय कुछ भी क्यों न हो कुछ न कुछ राजनीतिक परिणाम अवश्य उत्पन्न करती है। यदि लेखक राजनीतिक परिस्थितिसे परिचित हो और बुद्धिपूर्वक लेखन-क्रियाको सम्पन्न करे तो उस क्रियाका परिणाम इच्छानुकूल हो सकता है। इससे हम अवश्य चाहेंगे कि हमारे साहित्यिक वर्तमान राजनीतिका ज्ञान प्राप्त करे। यदि वह जीवनसे सम्पर्क रखना चाहते हैं और एक सफल कलाकार बनना चाहते हैं तो इस युगमें जब वर्ग-सघर्ष प्रबल वेगसे चल रहा है वह कैसे अपनेको इससे अलग कर सकते हैं। जीवनकी कथा ही यह है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किन्तु हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि हम साहित्यको किसी खास साँचेमें ढाले या उसका किसी प्रकार नियन्त्रण करे। हम यह भी नहीं चाहते कि उनकी कृतियोंका विषय शुद्ध राजनीतिक हो। स्टालिनके शब्दोंमें हम एक अच्छे कलाकारको उसके क्षेत्रसे हटाकर एक रद्दी किस्मका हडताल करानेवाला मजदूर नेता नहीं बनाना चाहते। वह कलाके द्वारा जितनी अच्छी सेवा कर सकता है उतनी राजनीतिके क्षेत्रमें प्रवेश करके नहीं कर सकता।

प्रान्तके साहित्यिकोंसे मेरा नम्र निवेदन है कि वह जनताके लिए साहित्य प्रस्तुत करें। इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिए सरल भाषाका प्रयोग करना आवश्यक होगा। चूँकि हमारे प्रान्तकी भाषाको राष्ट्रकी भाषा बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे साहित्यका सारे देशपर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है।

मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि जनताको आर्थिक कार्यक्रमके आधारपर संगठित करना हमारा मुख्य कार्य होना चाहिये। पहले हम प्रान्तके किसानोंकी अवस्थापर विचार करेंगे और इस बातके बतानेका प्रयत्न करेंगे कि अबतक किसानोंने अपने कष्टोंको दूर करनेके लिए क्या किया है।

अपने प्रान्तकी जनसंख्या लगभग ५ करोड़के है। गत ३० वर्षोंमें यद्यपि हमारी जनसंख्यामें अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तथापि भूमिका बोल निरन्तर बढ़ता ही जाता है। पिछले ३० वर्षोंमें खेतीपर आश्रित रहनेवाली जनसंख्यामें ४० लाखकी वृद्धि हुई है।

यदि साथ-साथ इसी अनुपातमें खेतीके रकबेमें भी वृद्धि हुई होती तो बेकारीके बढ़नेका प्रसंग न उपस्थित होता, किन्तु दुःखका विषय यह है कि भूमिके बोझमें वृद्धि होनेके साथ-साथ खेतीके रकबेमें उलटे कमी ही हुई है। इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ है कि प्रान्तके कितने ही अधिवासियोंको अपनी रोजी कमानेके लिए भारतके अन्य प्रान्तों तथा विदेशोंमें प्रति वर्ष जाना पड़ता है। ऐसे लोगोंकी संख्या बराबर बढ़ती जाती है।

दूसरा परिणाम यह हुआ है कि खेतोंके टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं। जोत टूटती जाती है और छोटे खेतोंकी संख्यामें वृद्धि होती जाती है। खेती करना इस तरह लाभदायक नहीं रह जाता। ऐसे किसानोंकी संख्या कुछ कम नहीं है जिनकी जोतका रकबा मुश्किलसे १ बीघेका दशांश होगा। अपने प्रान्तमें काश्तका रकबा ३॥ करोड़ एकड़ भूमि है। जनसंख्यामेंसे लगभग इतने ही लोग प्रधानतया अथवा अंशतः खेतीपर निर्भर करते हैं। इस प्रकार फी आदमी पीछे १ एकड़ भूमिका औसत पड़ता है। अन्य देशोंसे यदि हम तुलना करें तो हमको मालूम होगा कि हमारे प्रान्तमें भूमिका औसत फी आदमी पीछे बहुत कम पड़ता है।

गत ३० वर्षमें लगानमें काफी वृद्धि हुई है। सन् १९३१ की मर्दुमशुमारीकी रिपोर्टके अनुसार जहाँ मालगुजारीमें केवल ७५ लाख रुपयेका इजाफा हुआ है वहाँ काश्तकारका लगान ६ करोड़ ६५ लाख बढ़ गया है। इधर लगानमें इजाफा हुआ है तो उधर पैदावारका खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगानकी रकममें नजरानेकी रकम भी जोड़ना चाहिये। फी एकड़ भूमि पीछे ५।।।) ४० नजराना देना पड़ता है।

इन विविध कारणोंसे किसानकी गरीबी बढ़ती जाती है। गरीबीके साथ-साथ उसका कर्ज भी बढ़ता जाता है। सन् १९२९ में प्रान्तीय लेनदेन जाँच-कमेटी (प्राविशल वैकिङ्ग इक्वाइटी कमिटी)ने देहातोंमें रहनेवाले लोगोंका कर्ज १२४ करोड़ रुपया कूता था। इस रकममेंसे केवल २० करोड़के करीब जमींदारोंका कर्ज है, बाकी किसानोंका। सन् १९२९ के बादसे कर्जकी रकम बढ़ती ही जाती है।

लगभग ४० फी सदी किसान और छोटे जमींदार ऋणके असह्य बोझसे इतना अधिक दबे हुए हैं कि वह एक प्रकारसे महाजनोके गुलाम हैं। उनका ऋण जीवनभर उनके चुकाये न चुकेगा। यह ठीक है कि गवर्नमेन्ट ने इधर कानून बनाकर इस बोझको हलका करनेकी कोशिश की है, पर इस कानूनसे अधिक लाभ बड़े-बड़े जमींदारोंको ही पहुँचता है। जहाँ किसानका महाजन खुद उसका जमींदार है वहाँ इस कानूनसे किसानको कुछ भी मदद नहीं मिलती। जमींदार सौ तरीकेसे अपना कर्ज वमूल कर लेता है। इसके अतिरिक्त इस कानूनके बन जानेसे किसानको अब कर्ज नहीं मिलता। कौन महाजन इस कानूनके होते अब देहातमें लेन-देन करेगा? कर्जके बिना किसानका काम नहीं चलता। वह सदा कर्जमें डूबा रहता है। इसीके आधारपर वह किसी प्रकार अपना काम चलाता रहता है। जबतक स्टेटकी ओरसे कम सूदपर किसानोंको कर्ज देनेकी व्यवस्था न की जायगी तबतक इस प्रकारके कानूनोंसे किसानोंको विशेष लाभ नहीं पहुँच सकता। कोआपरेटिव सोसाइटीका काम अपने प्रान्तमें सर्वथा असफल रहा है।

हमारे प्रान्तके काश्तकारीके कानून भी बहुत खराब है। विशेषकर अवधमें किसानोंकी अवस्था अत्यन्त दयनीय है। उनसे कई जगह गैर-कानूनी टैक्स भी लिये जाते हैं। हरी बेगारी और रसद देनेके अलावा उनको नाजायज अववाव भी देने पड़ते हैं। वेदखलीकी तलवार सदा सिरपर लटकती रहती है। पैदावारकी कीमत गिर जानेसे किसान एक अजब मुसीबतमें है। यद्यपि लगानमें तखफीफ की गयी है तिसपर भी किसानको इससे बहुत आसाइश नहीं हुई है। बहुत जगह तो जमींदारोंने अपने किसानोंकी यह रकम मुजरा भी नहीं दी है और उनसे पूरा लगान वसूल कर लिया है। इस रिआयतके होते हुए भी बहुतसे किसान अपना लगान अदा नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह वेदखल कर दिये जाते हैं या वेदखलीसे बचनेके लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है।

विचारे किसानोंने सन् १९२०-२१में एक वृहत् आन्दोलन कर बड़ी मुश्किलसे अपनी एक माँग पूरी करा पायी थी। पहले अवधमें कोई किसान ७ वर्षसे अधिक खेतपर काबिज रहनेका हकदार न था। ७ वर्ष बाद जमींदार जब चाहता था उनको वेदखल कर देता था। वेदखलीके खिलाफ तीव्र आन्दोलन होनेकी वजहसे गवर्नमेण्टने १९२२ ई०में कानूनमें कुछ परिवर्तन किया था। उनका हीनहयाती हक मान लिया गया था, किन्तु दूसरे प्रकारसे वेदखल करनेकी कई धाराएँ कानूनमें बढ़ा दी गयी थी। उदाहरणके लिए यदि किसान एक विस्वाभर भूमिपर भी जमींदारीका हक हासिल कर ले तो वह वेदखल हो सकता है। इसी तरह शिकमियोंको जमीन उठानेके लिए भी उसकी वेदखली हो सकती है। जमींदार 'फार्म' खोलनेके लिए तथा अपनी सीरके लिए भी खेतसे वेदखल कर सकता है।

इस कारण इस कानूनसे यद्यपि कुछ लाभ किसानोंका अवश्य हुआ, तथापि वेदखली बन्द न हो सकी। उसकी नयी मदे निकल आयी। किसानोंकी पुकार (स्लोगन) आज भी वेदखली बन्द करानेकी है। वे कमसे कम कब्जेदारी चाहते हैं। उनके लगानका बोझ भी कम होना चाहिये। इस मन्दीके जमानेमें उनकी जोत विलकुल ही लाभप्रद नहीं रह गयी है। इस वर्ष तो वाढने किसानोंको विलकुल तबाह कर दिया है। साधारण उपायोसे उनकी अवस्थामें सुधार होना असम्भव है। ग्रामोद्धारकी योजना सदा विफल रही है। जो रकम गवर्नमेण्टने इस कामके लिए मजूर की थी उसका बहुतसा भाग दफ्तरके खर्चमें ही लग गया। ज्यादातर काम दिखाऊ होता है। अधिकारियोंको प्रसन्न करनेके लिए ही अधिकतर लोग इसमें थोड़ा-बहुत दिखावटी काम करते हैं। किसीको इस कामके लिए वह उत्साह नहीं है जो होना चाहिये। अब भविष्यमें इस मदके लिए सरकारसे और ग्रांट भी न मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस तरहकी योजनाएँ आँखमें धूल डालनेके लिए होती हैं। इन प्रयत्नोंसे किसानोंकी एक भी समस्या नहीं हल हो सकती। साँड़की नस्ल सुधारने और गायका दूध पीनेकी पुकार (स्लोगन) शाब्दिक मायाजाल (सोशलडेमागागी) के सिवाय कुछ नहीं है। किसानोंकी मौलिक माँगोंकी कथा तो दूर रही उनकी तात्कालिक माँगोंसे एक भी माँग इस योजना द्वारा पूरी नहीं हो सकती। ग्रामोद्धारका जो महकमा खोला गया है उससे गवर्नमेण्टका एक नया सगठन

अवश्य तैयार हो गया है जो गवर्नमेण्टकी ओरसे गाँवोमे प्रचारका काम करता है। इसके द्वारा जमींदारोको आगामी निर्वाचनमे सहायता भी पहुँचायी जा सकती है।

अब प्रश्न यह है कि हमारे किसान और छोटे जमींदार अपनी मुसीबतसे छुटकारा किस प्रकार पा सकते हैं। छोटे जमींदारोंकी हालत भी इधर बहुत खराब हो गयी है। साढ़े छियासी फीसदीसे ज्यादा जमींदार १००)६०से भी कम मालगुजारी सालमे देते हैं; ५६ फीसदी जमींदार २४)६०से कम सालाना मालगुजारी देते हैं। २०३ जमींदार ऐसे होंगे जो २००००)६० या इससे अधिक मालगुजारी देते हैं; लगभग ६००के ऐसे जमींदार हैं जिनकी सालाना मालगुजारी ५०००)६० या उससे अधिक है। अपने प्रान्तमे कुल लगभग २२ लाख जमींदार हैं। इनमेसे ८६½ फीसदी जमींदार किसानोके आन्दोलनमे सम्मिलित हो सकते हैं। किसान और छोटे जमींदारोको अपना एक दृढ़ संगठन बनाना चाहिये। जब बड़े जमींदार संगठित हो रहे हों तो कोई कारण नहीं है कि किसान अपना संगठन क्यों न बनावें। छोटे जमींदारोका हित बड़े जमींदारोके साथ रहनेमे नहीं है। वह तो कहने भरके लिए ही जमींदार हैं। बहुतसे छोटे जमींदारोंके पास इतनी जमीन भी नहीं है कि वह अपने कुटुम्बका पालन-पोषण कर सकें। उनकी जमींदारी इतनी छोटी है कि उससे उनको कोई लाभ नहीं होता। कर्जके बोझसे वह भी परेशान हैं।

सामन्तशाहीके युगमे जब समाजमे बड़े जमींदारोका आधिपत्य था किसान अपनेको खुली तीरपर संगठित नहीं कर सकते थे। उनको चुपचाप सब जुल्म बर्दाश्त कर लेना पड़ता था। जब अत्याचारकी मात्रा बहुत बढ़ जाती थी और आर्थिक कष्ट असह्य हो जाता था तो वह विद्रोह कर बैठते थे, किन्तु पशुबलके द्वारा वह जल्द दबा दिये जाते थे। इस प्रकार पुराने युगमे ससारमे सर्वत्र समय-समयपर किसानोके विद्रोह हुए हैं। जब वह बहुत बड़ी सख्यामे खेतसे बेदखल कर दिये जाते थे तो वह कभी-कभी गुप्त सभाएँ बनाकर अपनी रक्षाका आयोजन करते थे और जमीनपर कब्जा पानेके लिए जोर-जबर्दस्ती करते थे। कभी-कभी उनका विद्रोह सफल हो जाता था। किसानोका सबसे बड़ा विद्रोह चीनका 'टैपिंग' विद्रोह है। कई वर्षतक विद्रोही चीनके एक बहुत बड़े भागपर हुकूमत करते रहे और यदि विदेशी राज्य हस्तक्षेप न करते तो उनका राज्य स्थिर हो जाता।

जब पूँजीवादका युग आता है तब सामन्तोंकी सत्ता नष्ट होने लगती है, कमसे कम उनका अधिकार और प्रभाव स्टेटमे बहुत घट जाता है। किसानोको अपने संगठन कायम करनेका अधिकार मिल जाता है, यद्यपि वह इस अधिकारसे तबतक लाभ नहीं उठा सकते जबतक उनको शिक्षित वर्गका नेतृत्व प्राप्त नहीं होता। किसान सदा दूसरेके नेतृत्वमे ही आगे बढ़ सकते हैं। अपना नेतृत्व स्वयं करनेकी उनमें क्षमता नहीं रहती। वह अपने भरोसे या तो विद्रोह कर सकते हैं या जमींदार और राज्यसे अनुनय-विनय कर सकते हैं। संगठन तथा प्रचारके तरीकेसे वह अनभिज्ञ हैं। जब शिक्षित समुदाय किसानोका संगठन करने लगता है तब वैध उपायोसे काम लेकर किसान अपनी उन्नति

करना आरम्भ करते हैं । साधारणतः किसान राजनीतिसे अलग रहते हैं । वह अपने आर्थिक प्रश्नोंके लिए ही आन्दोलन करते हैं ।

सन् १९१८ में प्रयागमें एक किसान-सभा कायम की गयी थी । यूरोपीय युद्धके बाद सारे एशियामें बेचैनी थी । युद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिए मित्र-राष्ट्रोंने आत्म-निर्णयके सिद्धान्तको स्वीकार किया था । प्रेसिडेंट विलसनकी नीतिकी घोषणासे पददलित राष्ट्रोंमें एक अपूर्व उत्साह था । उनकी आशाएँ ऊँची हो गयी थी । लडाईके जमानेमें गाँवके हजारों आदमी फौज और 'लेवरकोर' में भरती हुए थे । युद्धमें भाग लेनेसे उनका मानसिक क्षितिज विस्तृत हो गया था । राजनीतिक सभाओंका भी उनपर प्रभाव पड़ा था । लडाईके बाद गल्लेका निर्य्य बहुत बढ़ गया था । इससे किसानकी अच्छी आमदनी हो गयी थी । ताल्लुकेदार इस आमदनीमें हिस्सा बँटाना चाहते थे । कानूनके अनुसार वह सात सालमें एक बार ही फी रुपया एक आना लगानमें इजाफा कर सकते थे । इसलिए उन्होंने वेदखलीके कानूनसे फायदा उठाकर किसानोंको वेदखल करना शुरू किया और नजरानेमें गहरी रकम लेकर दूसरे काश्तकारोंके साथ उस जमीनका बन्दोवस्त करना शुरू किया । अक्सर जमीनके बन्दोवस्तके लिए बोली बोली जाती थी और जिस काश्तकारकी बोली सबसे ज्यादा होती थी उसको पट्टेपर जमीन दी जाती थी । बहुतसे किसान इस तरह वेदखल कर दिये गये । बहुतोंको पट्टेके लिए महाजनसे ज्यादा सूदपर रुपया उधार लेना पड़ता था ।

नजरानेकी माँगसे किसान तंग आ गये थे । प्रयागकी किसानसभाने किसानोंको सङ्गठित करना शुरू किया । श्रीधर बलवन्त जोधपुरकर जो बाबा रामचन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं उस समय जौनपुर जिलेमें रहते थे और वहाँ से परतापगढ जिलेके किसानोंमें प्रचार किया करते थे । सन् १९२० में किसान सभाका कार्य तेजीसे बढ़ने लगा । किसानोंकी माँग यह थी—(१) वेदखलीपर रोक; (२) दस्तूरसे ज्यादा अववाव न हो, (३) बेगारपर रोक, (४) जुर्मानाका बन्द होना, (५) गैर-कानूनी टैक्सका बन्द होना । किसानोंको प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि हम सदा शान्त रहेंगे; गैरकानूनी टैक्स नहीं देंगे; बेगार बिना मजदूरी लिये न करेंगे, पतई, भूसा, रसद बाजार-भावपर बेचेंगे; नजराना न देंगे चाहे वेदखल हो जायँ । वेदखल खेतको दूसरा कोई किसान न लेगा; लगान ठीक वक्तपर अदा करेंगे । जबतक वेदखलीका कानून मसूख न होगा हम दम न लेंगे । प्रत्येक किसानको १४ प्रतिज्ञाएँ लेनी पड़ती थी ।

परतापगढसे किसान आन्दोलन रायवरेली जिलेकी दक्षिणकी तहसीलोंमें फैला । सन् १९२१ के आरम्भमें आन्दोलन पुष्ट हो गया था । किसानोंकी सभाओंमें हजारोंकी भीड़ होती थी । हिन्दू-मुसलमान, पुरुष-स्त्री सब सम्मिलित थे । किसान आन्दोलन साम्प्रदायिक भेदभावसे सर्वथा मुक्त था । गवर्नमेण्ट और ताल्लुकेदार किसानोंकी जागृतिसे भयभीत हो गये थे । ७ जनवरी १९२१ को मुशीगञ्जमें गोली चली । इसमें कई किसान आहत हुए । गोलीकाण्डके बादसे रायवरेली आन्दोलन कुछ शिथिल पड़

गया। यह आन्दोलन उस समय अवधके कई जिलोंमें फैला हुआ था। किसानोंके दृढ़ संगठनको देखकर अवधके अधिकारियोंने लगान कानूनके बदलनेकी आवश्यकताको स्वीकार किया। नोटिस वेदखली रोक दी गयी और नया कानून बनाकर किसानोंको हीनहयातीका हक दिया गया। उस समय देणमें असहयोग आन्दोलन चल रहा था। गवर्नमेंट यह नहीं चाहती थी कि किसान उस आन्दोलनमें शरीक हों। उस मंशासे भी किसानोंकी कुछ मांगें स्वीकार करना आवश्यक था। उनकी मुख्य मांग वेदखलीपर रोककी थी। जैसे ही यह मांग स्वीकृत हुई किसानोंकी असहयोगमें दिलचस्पी कम हो गयी। कांग्रेस किसानोंकी आर्थिक मांगोंके लिए लड़ना नहीं चाहती थी, किन्तु अपने आन्दोलनमें उसका सहयोग प्राप्त करना अवश्य चाहती थी। धीरे-धीरे असहयोग आन्दोलन भी शिथिल पड़ गया। सन् १९१६ के अन्तमें हरदोई, ग्वाली, सीतापुर और लखनऊ जिलोंमें 'एका आन्दोलन' के नामसे किसान आन्दोलन फिर आरम्भ हुआ। यह आन्दोलन ताल्लुकेदार और गवर्नमेंटके अधिकारियोंके विरुद्ध था। इन जिलोंके ताल्लुकेदार कागजमें दर्ज लगानसे कहीं अधिक वसूल करते थे। इसी कारण किसानोंमें वैचैनी थी। किसानोंका एक प्रसिद्ध नेता मदारी पासो था जिसके पकड़नेमें अधिकारियोंको काफी तरह-तुद उठानी पड़ी थी। जब कभी किसानोंका कोई स्वयंसेवक पकड़ा जाता था तो वह बड़ी संख्यामें इकट्ठा हो जाते थे और उसको छुड़ा लेते थे। इसके कई उदाहरण हमको मिलते हैं। किसानोंने दर्ज लगानसे अधिक देनेसे इनकार कर दिया। कई जगह ताल्लुकेदारके आदमियोंसे मारपीट भी हो गयी।

एका सभा दो प्रकारकी होती थी। एक तो शुद्ध आर्थिक और दूसरेमें साथ-साथ राजनीतिक कार्यक्रम भी रहता था। सभामें स्वराज, स्वदेशी और अदालतोंके बहिष्कार सम्बन्धी प्रस्ताव पास होते थे। ५० जनार्दन जोशी, जो उस समय रायबरेलीमें डिप्टी कलेक्टर थे, अपनी एक रिपोर्टमें लिखते हैं कि एक रियासतमें कागजमें दर्ज लगान ७७०००) रु० था, लेकिन ताल्लुकेदार अपनी रिआयासे ६५००) की फाजिल रकम वसूल करता था। दूसरी रियासतमें ३२०००) रु० के स्थानमें रिआयामें ४५०००) रु० वसूल किया जाता था। जोशीजी आगे चलकर लिखते हैं कि इसमें आश्चर्यकी क्या बात है यदि किसान इस सड़ी पद्धतिके विरुद्ध विद्रोह करता है। श्रीयुत कालसर आर्ड. सी. एस. लिखते हैं कि एक रियासतमें लगानकी रकम १७००) रु० थी लेकिन रिआयासे ५७००) रु० वसूल किया जाता था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इन जिलोंमें साधारणतः रिआयासे दर्ज लगानका डेवढा वसूल किया जाता था। किसानोंके असन्तोषका एक और कारण भी था। जो भूमा अववावकी शकलमें रिआयासे लिया जाता था उसका परिमाण निश्चित नहीं था। एक खाँची या एक गठरी देनेका रिवाज था। किन्तु खाँची और गठरीकी तौल नियत नहीं थी। एक मनसे लेकर ४ मनतक खाँचीकी तौल और २० से ४० सेरतक गठरीकी तौल समझी जाती थी। चूँकि उस समय भूसेकी कीमत बहुत बढ़ गयी थी, इसलिए किसानोंको इतना भूसा देना और भी अखरता था। अववावके सम्बन्धमें कानून भी स्पष्ट न था। जगह-जगह किसानोंकी पचायते कायम हो गयी थी

और यह कभी-कभी फौजदारीके मामले भी देखती थी । मुलजिमोपर कभी-कभी जुर्माना भी होता था ।

धीरे-धीरे अधिकारियोने इस आन्दोलनको दवाना शुरू किया । कुछ दिनो बाद किसान आन्दोलन बहुत दुर्बल पड़ गया । सन् १९३२ मे भी कांग्रेस कमेटीने लगानवन्दीका आन्दोलन शुरू किया । यह आन्दोलन इलाहाबाद और रायवरेलीमे अच्छी तरह चलता रहा, किन्तु अन्य जिलोमे यह जोर न पकड़ सका । सन् १९३३ मे प्रयागमे केन्द्रीय किसान संघकी स्थापना की गयी । इसकी शाखाएँ भी कुछ जिलोमे खोली गयी, किन्तु व्यवस्थित रूपसे कुछ काम न हो सका । इधर अन्य प्रान्तोमे भी किसान आन्दोलनका सूत्रपात हुआ । विहारमे किसानोका एक बड़ा मजबूत सगठन है । अखिल भारतवर्षीय किसान संघकी स्थापना हुई । उसका प्रथम अधिवेशन लखनऊमे गत अप्रैलमे हुआ था । कांग्रेसके कार्यकर्ताओको चाहिये कि जिले-जिले किसान संघकी स्थापना करे और किसानोको उनकी आर्थिक माँगोके आधारपर सगठित करे ।

मजदूरोका सगठन भी अपने प्रान्तमे यूरोपीय युद्धके बादसे ही आरम्भ होता है । युद्धके बाद देशभरमे मजदूरोमे काफी असन्तोष था । उस समय व्यवसायका बाजार गर्म था । मिल-मालिकोको खूब मुनाफा हो रहा था, किन्तु मजदूरोकी मजदूरी बहुत थोड़ी थी । मजदूरी बढ़ानेके लिए देशभरमे हड़ताले हुई । इसी अवसरपर अपने प्रान्तमे तीन यूनियन कायम हुई—कानपूर मजदूर सभा, बी० एन० डब्लू० रेलवेमैन यूनियन और ओ० आर० रेलवे मैन यूनियन (इसका अब ई० आई० रेलवेमैन यूनियन नाम है) । सन् १९२७ से सगठनका काम वाकायदा शुरू हुआ । कानपुर-मजदूर सभाको श्री हरिहरनाथ शास्त्रीने स्वर्गीय पं० गणेशशंकरजी विद्यार्थीकी सहायतासे सुसगठित किया । सभाने मजदूरोसे रुपया इकट्ठा कर अपना एक भवन निर्माण किया । सभाकी ओरसे पुस्तकालय, वाचनालय और डिसपेसरी खोली गयी और मजदूर सभा सेवासमितिकी स्थापना की गयी । यह सस्थाएँ आज भी वर्तमान हैं । सभाने 'मजदूर' नामका एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला जिसका सम्पादन इस समय श्री राजाराम शास्त्री कर रहे हैं । सभाके उद्योगसे सन् १९२७ मे कानपुरमे 'आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' का वार्षिक अधिवेशन हुआ । इसकी वजहसे अपने प्रान्तमे मजदूर आन्दोलनको बल मिला और १९२९ मे प्रथम प्रान्तीय सम्मेलन कानपुरमे पं० जवाहरलाल नेहरूके सभापतित्वमे हुआ । अबतक ५ प्रान्तीय सम्मेलन हो चुके हैं । प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजदूरोको सगठित करती है और उनके संग्राममे हिस्सा लेती है । गत ८-९ वर्षमे १० नयी यूनियन कायम हुई हैं । अपने प्रान्तमे मजदूर आन्दोलनका आरम्भ कांग्रेसके सदस्योद्वारा हुआ है ।

सन् १९३५मे अपने प्रान्तके कारखानोकी संख्या ५९७ और मजदूरोकी संख्या १३९२६० थी । फैक्टरी इन्स्पेक्टरोकी इतनी कमी है कि सन् १९३४मे केवल ६२ कारखानोका एक बार मुआयना हो सका था । मजदूरोको अपने हितोकी रक्षाके लिए जगह-जगहपर मजदूर संघ स्थापित करने चाहिये । मिर्जापुर, आगरा, हाथरस, गोरखपुर

तथा मुरादाबाद आदि स्थानोंमें लाख, लोहा, चूड़ी, जूता, कपड़ा, शक्कर और वर्तन बनानेके व्यवसायमें हजारों मजदूर काम करते हैं। इनको संगठित करनेकी जरूरत है। योग्य कार्यकर्ताओंकी कमीसे मजदूर संगठनका काम बहुत आगे नहीं बढ़ रहा है। जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता लगनसे मजदूरोंका संगठन करते भी हैं वह गवर्नमेंटके दमन-चक्रके चंगुलमें फँस जाते हैं। हड़तालके समय दफा १४४का प्रयोग किया जाता है और मजदूरोंकी सभाएँ रोक दी जाती हैं। मजदूर कार्यकर्ताओंपर दफा १५३ और १२४ अ के मुकदमें चलाये जाते हैं। उनसे एकसर जमानते भी माँगी जाती हैं। मजदूरोंकी वर्ग-चेतना बढ़ती जाती है। उनके आन्दोलनसे हुकूमत घबराती है और उसको दबानेके लिए मिल-मालिकोंके सहयोगसे नाना प्रकारके उपायोंसे काम लेती है।

कांग्रेसके कार्यकर्ताओंको मजदूर-संगठनकी ओर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिये और ट्रेड यूनियन कांग्रेसके कार्यकर्ताओंके साथ सहयोग करना चाहिये। इससे साम्राज्य-विरोधी मोरचा और भी दृढ़ होगा। सौभाग्यसे हमारे प्रान्तमें मजदूर कार्यकर्ताओंसे कांग्रेसवालोंका अच्छा सम्बन्ध है। चुनावके कार्यमें भी हमारा उनका सहयोग है। यदि हम इस आवश्यक कार्यकी ओर ध्यान दे तो बहुत जल्द एक अच्छा मजदूर संगठन खड़ा किया जा सकता है। क्षेत्र विस्तृत है। केवल योग्य कार्यकर्ताओंकी कमी है।

तीन वर्ष हुए बस्ती-गोरखपुरमें ईख संघकी स्थापना हुई थी। इसमें प्रधान रूपसे कांग्रेस कार्यकर्ता काम करते थे। वास्तवमें यह किसानोंका संगठन था। इधर इसका काम बहुत कुछ ढीला पड़ गया है। हमें ईख संघको फिरसे जगाना चाहिये। जहाँ-जहाँ शक्करकी मिलें हैं वहाँ-वहाँ ईख संघ कायम करना चाहिये। साथ-साथ शक्करके कारखानों के मजदूरोंको भी संगठित करना चाहिये।

हमारे सामने यही मुख्य काम है। जनताको संगठित करके ही हम राष्ट्रीय आन्दोलनको पुष्ट कर सकते हैं। हमारी दृष्टिमें चुनावका काम गौण है। फिर यह काम चन्द महीनोंका ही है। फरवरीमें चुनाव समाप्त हो जायगा। हम अपनी लड़ाईको अधिक प्रभावशाली बनानेके लिए ही व्यवस्थापक सभाओंमें जा रहे हैं। हम इन सभाओंका उपयोग अपने प्रचार-कार्यके लिए करना चाहते हैं। हमारे आन्दोलनका यह एक और प्लैटफार्म होगा। चुनाव-संग्रामके समय जनताको राजनीतिक शिक्षा देनेका एक अच्छा मौका मिलता है। जनताको हमें नये अधिकारोंका खोखलापन बतला देना है। हमें उनको बतलाना है कि नये विधानके द्वारा जनताकी कोई समस्या नहीं हल हो सकती। मौलिक समस्याएँ तो स्वतन्त्र होनेपर हल हो सकती हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादका भारत-पर पंजा मजबूत करनेके लिए नये विधानमें संरक्षण सम्बन्धी कई नियम हैं। साम्राज्यके स्वार्थ सुरक्षित रखनेके लिए और ब्रिटिश साम्राज्यवादके सामाजिक आधारको सुदृढ़ बनानेके लिए इस विधानका निर्माण हुआ है, किन्तु जनताके हितोंकी सर्वथा उपेक्षा की गयी है। अधिकार-सम्पन्न वर्गोंके स्वार्थ भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह साम्राज्यवादके सहायक हैं। विधानमें इसकी विशेष रूपसे व्यवस्था कर दी गयी है कि ऐसे वर्गों के

अधिकारोमे किसी प्रकारका सणोधन या परिवर्तन न हो सकेगा । किन्तु निरीह, अकिंचन किसानकी दरिद्रता दूर करनेका किसी प्रकारका आश्वासन नहीं दिया गया है ।

हमको यह न भूलना चाहिये कि साम्राज्यवाद जनताका अर्थशोषण करके ही पनप सकता है । यूरोपके प्रत्येक राष्ट्रको आर्थिक संकटका मुकाबला करना पड़ रहा है और इस संकटसे त्राण पानेके लिए वह अपने उपनिवेशोको और अधिक चूसता है । ऐसी अवस्थामे जनसाधारणकी चिन्ता कौन करता है ?

कांग्रेसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह विधानको रद करनेके लिए ही अपने प्रतिनिधि व्यवस्थापक सभामे भेज रही है । उसका उद्देश्य विधानको कार्यान्वित करना नहीं है, किन्तु उसका विरोध करना और अन्त करना है । कांग्रेसने अपनी चुनाव-घोषणामे साफ कह दिया है कि उसके मतमे व्यवस्थापक सभाओ द्वारा स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त हो सकती और आदेश दिया है कि कांग्रेसके सदस्य इन सभाओका ऐसा उपयोग करे जिससे जनताकी शक्ति बढे और व्यवस्थापक सभाओके बाहर जो कार्य हो रहा है उसमे सहायता मिले तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए जिस शक्तिकी आवश्यकता है उसका विकास हो । कांग्रेसने अपना एक कार्यक्रम भी जनताको यह बतलानेके लिए प्रकाशित किया है कि उसका लक्ष्य क्या है । इस प्रकार कांग्रेसने इसका संकेत कर दिया है कि जब कभी वह अधिकारसम्पन्न होगी तब वह क्या करेगी । कृपिसम्बन्धी प्रश्नोपर प्रान्तीय कमेटियाँ विचार कर रही हैं और शीघ्र ही कांग्रेसकी ओरसे एक कार्यक्रम प्रकाशित होगा जिसमें कृपिसम्बन्धी सब प्रश्नोका विचार होगा और उनके सम्बन्धमे कांग्रेसकी नीति निर्धारित की जावेगी । प्रान्तीय कमेटियोको यह भी अधिकार दिया गया है कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओको देखते हुए यदि जरूरी समझे तो परिपूरकके रूपमे एक और घोषणा प्रकाशित कर दे । अपने प्रान्तकी कमेटी इस कार्यमे सलग्न है और आशा है कि वह प्रान्तके विशेष प्रश्नोके सम्बन्धमे भी अपनी नीति निर्वाचकोपर प्रकाशित कर देगी ।

इस प्रकार हम देखेंगे कि व्यवस्थापक सभाओकी ओर हमारा एक विशेष दृष्टिकोण है । इस सम्बन्धमे मन्त्रिपद ग्रहण करनेके प्रश्नपर विचार करना अनुचित न होगा । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने इस प्रश्नपर अभीतक विचार नहीं किया है । उसने निश्चय किया है कि यह प्रश्न चुनावके बाद ही तय किया जाय, किन्तु यह प्रश्न फैजपुर कांग्रेसके सामने आनेवाला है, इसलिए इसके सम्बन्धमे मैं कुछ शब्द कह देना आवश्यक समझता हूँ । मेरा निवेदन है कि विधानको रद करनेकी नीतिको स्वीकार करके हम मन्त्रिपद ग्रहण करनेकी बात सोच भी नहीं सकते । इसका अर्थ होगा ब्रिटिश साम्राज्यवाद-से समझौता करना और विधानको काममे लाना ।

कांग्रेससे देशको बहुत बड़ी आशा है और यदि हम बिना पूर्ण अधिकार प्राप्त किये मन्त्रिपद ग्रहण करेंगे तो हम अपनी प्रतिज्ञाओको पूरा न कर सकेंगे और हम देशके विश्वासपात्र न रह जायँगे । जनता भी इस धोखेमे पड़ जायगी कि इस नवीन विधानमे कुछ न कुछ तत्त्वकी बात अवश्य होगी, तभी तो कांग्रेसके लोग पदग्रहण कर रहे हैं ।

पदग्रहण करके विधानको रद्द कराना तो दूर रहा हम साम्राज्यवादके अङ्गमाल वन जायेंगे और देशकी मनोवृत्ति धीरे-धीरे वैध ग्रान्दोलनके पक्षमें ढलने लगेगी ।

आशा है हमारे प्रान्तके प्रतिनिधि फैजपुर कांग्रेसके अधिवेशनमें देशको इस भावी खतरसे बचानेका प्रयत्न करेंगे ।

चुनावके क्षेत्रमें कांग्रेसका मुकाबला करनेके लिए गवर्नमेण्टने नेशनल एंग्लिकल्चरल पार्टीको खड़ा किया है । मैं ऊपर बता चुका हूँ कि किस तरह लार्ड हेलीकी कोशिशसे इस पार्टीका उस समय जन्म हुआ जब कि कांग्रेस देशकी स्वाधीनताके लिए लड़ रही थी और कांग्रेस कार्यकर्ता जेलोंमें बन्द थे । मैदान खाली पाकर गवर्नमेण्टने बड़े-बड़े जमींदारोंको संगठित करनेका काम अपने हाथमें लिया । पार्टीके जो नियम आरम्भमें बने थे उनके अनुसार केवल बड़े-बड़े जमींदार ही दलके सदस्य हो सकते थे । नामने लोगोंको यह धोखा हो सकता है कि यह किसानोंकी कोई पार्टी होगी, किन्तु ऐसा नहीं है । यह तो राजा और नवाबोंकी पार्टी है । छोटे जमींदारोंको भी इसमें कोई स्थान नहीं है तो किसानोंका क्या कहना । अब जब चुनाव करीब आया तो गत जुलाईके महीनेमें पार्टीने अपने कुछ नियम बदल दिये । अब प्रत्येक व्यक्ति जो पार्टीके उद्देश्य स्वीकार करता है पार्टीका सदस्य हो सकता है । चुनावके कारण पार्टीने अपने प्रोग्राममें भी परिवर्तन किया है । चुनावके कारण अब पार्टीको इतना कहनेके लिए मजबूर होना पड़ा है कि वह नये विधानको अपर्याप्त और असन्तोषप्रद समझती है । जो कान्फरेस गर्मियोंमें फर्ग्युवादमें हुई थी उसकी कार्यवाही देखनेसे भालूम होता है कि कान्फरेसने उतने महत्त्वके प्रश्नपर विचार ही नहीं किया था । अब यह पार्टीके मन्त्रीने अपनी एक पुस्तिकामें नये विधानका समर्थन करते हुए यह लिखा है कि कोई भी विधान पूर्ण नहीं हो सकता, विधान तो विकासकी चीज है, यह विधान भी बदलेगा और यह बात हमारे स्वरूप पर बहुत कुछ निर्भर करेगी । देशमें एंग्लिकल्चरिस्ट पार्टी ही ऐसा एक दल है जिसको नये विधानका विरोध करनेका अब भी साहस नहीं होता । बलिहारी है चुनावकी जो इस-प्रतिक्रियागामी दलको भी एक हलका कदम आगे बढ़ानेको विवश करता है । अब कमसे कम यह इतना तो कहने लगा है कि हम इस नये विधानसे सन्तुष्ट नहीं हैं ।

पार्टीके मैनिफेस्टोमें कहा गया है कि पार्टी मजदूरोंकी अवस्थाको सुधारनेका यत्न करेगी ।

यदि समझना हो कि पार्टीका इससे क्या आशय है तो पार्टीके मन्त्रीका वह परचा देखिये जो उन्होंने 'वोटरोको नेक सलाह' इस शीर्षकसे प्रकाशित किया है । मन्त्रीजी बताते हैं कि हमारी 'नौजवान पार्टी'की ओर मजदूर और किसान खिंचे आ रहे हैं । आगे आप कहते हैं कि हमारी पार्टी "मजदूरोंको मेहनतसे काम करनेका आदी बनावेगी ।" मन्त्रीजीकी रायमें मजदूर प्रायः आलसी और कमजोर होते हैं, जब मन्त्रीजीकी ऐसी मनोवृत्ति है तो इस दलसे मजदूरोंको क्या आशा हो सकती है ? ज्यादा अच्छा होता यदि पार्टी अपने मैनिफेस्टोमें इसकी घोषणा करती कि वह ऐसा कानून बनानेका प्रयत्न करेगी जिससे हरी, बेगारी और रसदकी प्रथा बन्द हो जायेगी और बड़े-बड़े जमींदार नाजायज

रकमे न वसूल कर सकेंगे । किसानोंके सम्बन्धमें इस घोषणामें केवल इतना ही कहा गया है कि पार्टी उचित लगान नियत कराने और जोतको स्थायी बनानेका उद्योग करेगी । इसके शब्द जान-बूझकर अस्पष्ट रखे गये हैं । मन्त्रीजीने एक जगह अपनी यह राय जाहिर की है कि पट्टेकी मीयाद कुछ बढ़ाई जा सकती है । क्या पार्टी साफ-साफ नहीं कह सकती थी कि वह किसानोंको कब्जेदारीका हक दिलानेकी कोशिश करेगी ? घोषणाका यह अर्थ केवल उस आक्षेपका उत्तर देनेके लिए रखा गया है जो पार्टीके विरुद्ध प्रायः किया जाता है कि यह बड़े-बड़े जमींदारोंकी पार्टी है । पार्टी शब्दाडम्बरसे काम लेना चाहती है, किन्तु हम उसको यह बतलाना चाहते हैं कि शब्दोंसे कोई धोखेमें नहीं आ सकता । पार्टीमें कोई अनुशासन भी नहीं है और हो भी कैसे सकता है जब कि उसके सदस्य किसी सिद्धान्तके अधीन नहीं हैं । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह पार्टी गवर्नमेण्टहाउस पार्टी है, यही उसका वास्तविक रूप है । असली रूपको छिपानेकी चाहे जितनी कोशिश क्यों न की जाय वह छिप नहीं सकता । अकबरका यह मिसरा पार्टीपर खूब चस्पा होता है—“उन्हींके मतलबकी कह रहा हूँ, जवान मेरी है बात उनकी । उन्हींकी महफिल सँवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी ।”

पार्टीका दावा है कि वह हिन्दू-मुस्लिम झगड़ोंसे पाकसाफ है । जबतक साम्प्रदायिकतासे काम चलता रहा तबतक इसके प्रमुख हिन्दू सभा और मुसलिम कान्फरेसके सर्वेसर्वा थे । अब जब आर्थिक प्रश्न जनताके सम्मुख आने लगे हैं और वर्ग-चेतना बढ़ती जाती है, जमींदार वर्गको अपने वर्गके स्वार्थोंके आधारपर अपना संगठन करना पड़ता है । अब भी पार्टीके कई सदस्य चुनावकी दृष्टिसे साम्प्रदायिक सस्थाओंसे अपना सम्बन्ध बनाये रखना लाभदायक समझते हैं ।

संयुक्तप्रान्तकी हिन्दू सभा तो हिन्दू मन्त्रियोंके हाथकी कठपुतली हो रही है । हिन्दू-हितोकी दुहाई देकर अपने लिए प्रधान मन्त्रित्वके पानेकी यह चेट्टा मात्र है । जिस हिन्दू-सभामें मन्त्रियोंके एजेंट और गवर्नमेण्ट ‘ड्विप’ की तूती बोलती हो उसका आदर हिन्दू समाजमें कैसे हो सकता है ? जो सज्जन मालवीयजीके विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव लानेकी धृष्टता दिखा सकते हैं वे किस मुँहसे हिन्दू हितोके कर्णधार बननेका दावा पेश करते हैं ? वह बताये कि उन्होंने अबतक हिन्दू-हितोकी रक्षाके लिए क्या किया है ? और आज क्या कर रहे हैं ? क्या एक हिन्दूके प्रधान मन्त्री बन जानेसे ही हिन्दू-हित साधित हो जाते हैं ?

जनताको किसीके शाब्दिक मायाजालमें न फँसना चाहिये । आजकल हर जगह जनताको गुमराह करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । जनताको इससे सावधान होनेकी जरूरत है ।

वास्तविकता यह है कि प्रान्तीय हिन्दू-सभा और नेशनल ऐग्रिकलचरिस्ट पार्टी प्रतिक्रियाके गढ़ हैं । इन सस्थाओंके पीछे न त्याग है और न सेवाका भाव ; केवल चुनावमें सफलता प्राप्त करनेके लिए ही यह सारा खेल रचा जा रहा है ।

केवल भारतमें ही नहीं बरञ्च सारे ससारमें उन्नति और प्रतिक्रियाके बीच आज

संघर्ष चल रहा है। प्रतिक्रियागामी शक्तियाँ सारे संसारमें संगठित हो रही हैं। प्रगतिशील शक्तियाँ एक सूत्रमें आवद्ध होकर उनसे मोर्चा ले रही हैं। यह दृश्य हर जगह देखनेमें आता है। इसका कारण यह है कि पूँजी-प्रथा विकासकी उस चरमसीमाको पहुँच गयी है जहाँ वह उत्पादनकी वृद्धिमें रुकावट डालती है। पूँजीप्रथाके आन्तरिक विरोधको मिटाना पूँजी प्रथाकी सीमाके भीतर सम्भव नहीं है। पूँजीवादका वर्तमान रूप साम्राज्यवाद है। यह पूँजीवादकी आखिरी मजिल है। समाजकी भावी उन्नतिके लिए इस प्रथाका लोप होना आवश्यक है। मानव-समाजको दारुण परिणामसे बचानेका यही एकमात्र उपाय है। पूँजीवाद आज अपनी समस्याओंको हल करनेमें अपनेको अयोग्य पाता है। पूँजीवादकी रक्षाके लिए अनेक प्रयोग किये जा रहे हैं, पर एकाको भी सफलता नहीं मिल रही है। अर्थशास्त्रियोंने यही समझ रखा है कि कृत्रिम उपायोसे वस्तुओंकी कीमत बढ़ानेसे और उत्पादनका नियन्त्रण करनेसे पूँजी-प्रथाकी रक्षा हो सकती है। उनका ख्याल है कि पूँजी-प्रथाकी रक्षाके लिए यह भी आवश्यक है कि एक निश्चित योजनाके अनुसार राष्ट्रके आर्थिक-जीवनका संगठन किया जावे, किन्तु अभीतक सब प्रयोग निष्फल प्रमाणित हुए हैं।

पूँजी-प्रथा आज अपनेको इस संकटकी अवस्थामें पाती है। उसे अपनी रक्षाका कोई मार्ग नहीं सूझ पड़ता। ससारका बाजार साम्राज्यवादी राष्ट्रोंके लिए संकुचित होता जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अव्यवस्थित और अस्त-व्यस्त होते जाते हैं। राष्ट्रोंकी प्रतिस्पर्धा फलस्वरूप भीषण होती जाती है और प्रत्येक राष्ट्र अपनी रक्षाके लिए अपनेको सुसज्जित कर रहा है। आपसमें होड़-सी लग गयी है। इससे ससारकी आर्थिक पद्धति विनष्ट-सी हो रही है।

जब पूँजी-प्रथाका इस प्रकार ह्रास और संगठन होने लगता है तब वह एक प्रतिक्रियाकी पद्धति होकर ही रह सकती है। यही प्रतिक्रिया 'फैसिज्म' कहलाती है। पूँजी-प्रथाको जीवित रखनेकी यह अन्तिम चेष्टा है।

मजदूरोंकी वर्ग-चेतना बढ़नेसे साम्राज्यवादका संकट और भी बढ़ जाता है। पूँजी-प्रथाके ह्रासके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय जगत्में वर्गोंका परस्पर संघर्ष भी बढ़ता जाता है। पूँजीपति पार्लमेण्टके द्वारा शासन करनेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं, इसलिए वह अधिनायकत्वकी शरण लेते हैं, मजदूरोंके संगठनको छिन्न-भिन्न कर देते हैं और शासनके वर्वर तरीकोसे काम लेते हैं। विचारोंको नियंत्रित करनेके लिए तरह-तरहके कानून बनाते हैं। विद्यार्थियोंसे ससारकी समस्याओंका पक्षपातरहित अध्ययन करनेकी स्वतन्त्रता भी छीन ली जाती है। प्रचारके सब साधनोंपर शासनका अधिकार रहता है और प्रत्येक प्रश्नपर शासनका जो मत है वही जनताके सामने पेश हो सकता है। अपने देशमें भी विचारोंपर कठोर नियन्त्रण हो रहा है। अपने प्रान्तके इण्टरमीडियेट कालेजके विद्यार्थी किसी प्रकारकी सभा या संस्थामें विना प्रिंसिपलकी आज्ञाके सम्मिलित नहीं हो सकते। इस सर्व्यूलरका अभिभावकोंको विरोध करना चाहिये।

फैसिस्टकी वैदेशिक नीति भी शान्तिमय नहीं होती। वह युद्धकी नीतिका अवलम्बन

करते हैं। वह समझते हैं कि युद्धसे उनकी कठिनाइयाँ दूर हो जायँगी, किन्तु ऐसा होनेका नहीं। पिछले युद्धने ससारको दो टुकड़ोमें बाँट दिया है—सोवियट रूस तथा पूँजीवादी संसार। एक समाजवादका प्रतिनिधि है तो दूसरा पूँजीवादका। इस वँटवारेने ही समाजवाद बनाम पूँजीवादके प्रश्नको ससारका मुख्य प्रश्न बना दिया है। अगला युद्ध पूँजीवादको और भी दुर्बल कर देगा और समाजवादी दुनियाका क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो जायगा। कई देशोमें पूँजीवादका अस्तित्व ही खतरेमें पड़ जायगा। यह सत्य पूँजीवादी राष्ट्रोंकी समझमें नहीं आता और वह एक विश्वव्यापी युद्धको सन्निकट लानेकी कोशिशमें लगे हुए हैं। युद्धके बादल चारों ओर मँडरा रहे हैं। जो राष्ट्र सम्पन्न और तृप्त हैं वह युद्धको टालनेके प्रयत्नमें हैं और जो अतृप्त हैं वह युद्धको छेड़नेके मनमूवे बाँध रहे हैं। स्थिति काफी अनिश्चित और भयावह है। ससारकी प्रगतिशील शक्तियाँ यदि सम्मिलित चेष्टा करे तो वह इस युद्धको कुछ कालके लिए अवश्य टाल सकती हैं। सन् १९१४ की अपेक्षा ऐसी शक्तियाँ इस समय कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। पहले तो सोवियट रूसका अस्तित्व ही प्रगतिशील शक्तियोंको काफी प्रोत्साहन देनेवाला है। फिर आर्थिक संकटके कारण निम्न-मध्यम-श्रेणी तथा विविध पेशेके लोग और किसान भी आज दुखी हैं और वह अपने दुखोंसे छुटकारा पानेके लिए अधिकाधिक मजदूरोंके साथ सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार कई देशोमें सामान्य जनताके विविध समुदायोंका एक संयुक्त मोर्चा बन गया है जो फैसिज्म और युद्धका विरोध कर रहा है। उपनिवेशोंके अधिवासी भी साम्राज्यवादसे छुटकारा पानेके लिए स्वतन्त्रताके संग्रामको आगे बढ़ा रहे हैं। वह भी फैसिज्मके विरुद्ध हैं, क्योंकि फैसिज्मसे उनको भी भय है। इटली अवीसीनियाके युद्धने इस बातको स्पष्ट कर दिया है। सब उपनिवेशोंकी सहानुभूति इस युद्धमें उसी प्रकार अवीसीनियाके साथ थी जिस प्रकार सोवियट रूस और ससारकी मजदूर जमातकी। यह सब शक्तियाँ यदि सगठित हो जायँ और अपनी पूरी शक्ति लगा दें तो फैसिस्ट आक्रमण अब भी रोका जा सकता है। पहला काम इस आक्रमणका मुकाबला करना है। यदि इस प्रयत्नमें प्रगतिशील शक्तियाँ सफल हुईं तो उनको अपने उद्देश्य से पूरा करनेकी शक्ति प्राप्त हो सकेगी।

आज फैसिस्ट आक्रमण स्पेनकी गवर्नमेंटके विरुद्ध चल रहा है। फैसिस्ट राष्ट्र-विद्रोहियोंकी सहायता कर रहे हैं किन्तु हस्तक्षेप न करनेकी नीतिके कारण गवर्नमेंटको लड़ाईका सामान नहीं मिलता है। स्पेनकी जनता बड़ी वहादुरीके साथ शत्रुओंका मुकाबला कर रही है, पर अब तक गवर्नमेंटको हारपर हार खानी पड़ी है। मैड्रिड शत्रुओंके हाथ आनेवाला है। आश्चर्य है कि अबतक किस प्रकार वहाँकी गवर्नमेंट पराजित नहीं हुई है। स्पेनके भाग्यके निपटारेपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस गृह-कलहका जो भी परिणाम हो इसमें सन्देह नहीं कि स्पेनकी जनताको कुचलना कोई सरल काम नहीं है।

साथ-साथ उपनिवेशोंमें क्रान्तिकी लहर उठ रही है। जो देश इटली अवीसीनियाके युद्धक्षेत्रके समीपके थे उन्होंने अपनी स्वतन्त्रताके लिए एक प्रयत्न किया। मिस्रसे

अंग्रेजोंने मुसोलिनीके भयके कारण समझौता कर लिया । फिनलैंडमें अस्वीडिश विद्रोह हुआ जो सेना द्वारा दबा दिया गया । फ्रेंच सरकारमें गौटिया और मेनानादि गणतन्त्रवादी कुछ शर्तोंके साथ स्वीकार करनेपर नाथ्य होना पड़ा । अन्य देशोंमें भी गणतन्त्र फैल रहा है और अनुकूल परिस्थिति होनेपर वहाँ भी स्थिति बदलेगी ।

हमको यह न समझना चाहिये कि हम अकेले हैं, जो गलियाँ आज पैगम्बराना बिरोध कर रही हैं वह सब हमारे साथ हैं । जो पद्धति राष्ट्र मान्यमानके लिए उद्योग कर रहे हैं वह भी हमारे साथ हैं । हमनेगाँवोंमें एक नये नये मोर्चा है । अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर जमान तथा वह समुदाय जो आज मानवता अथवा स्वतन्त्रताके लिए लड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हैं ।

हम सब उग गतिके प्रतिनिधि हैं जिसका मान उत्थान हो रहा है और जिसका भविष्य उज्ज्वल है । यह हो सकता है कि हम अपनी दुर्बलता और भयके कारण सफलता न प्राप्त कर सकें और हमको सभी कुछ समझाए और प्रोत्साहित करना पड़े ।

किन्तु यदि हम सतत उद्योग करने जायेंगे तो अन्तमें हमारा विजय निश्चित है ।

आरतीनके ये सॉप !

कांग्रेसके पदग्रहणका एक भयानक किन्तु अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक समस्याने अब पहलेसे कहीं अधिक गम्भीर रूप धारण कर लिया है । साधारण कांग्रेसजनोंकी आशाके प्रतिकूल, आज मृतप्राय साम्प्रदायिक संस्थाओंमें जान प्रा गयी-नीं दिगायी दे रही है । उनका संगठन और प्रचारका कार्य भी पड़ोसी अपेक्षा नैतज्ञों से तेज हो गया है । पहले जिन संस्थाओंमें चुनावके समय थोड़ी-सी चहल-पहन दिगायी दे जाती थी उनका साहम आज उस हदतक बट गया है कि वे कांग्रेसका प्रतिद्वन्द्वी होनेका दम भरने और देशवासियोंका सच्चा प्रतिनिधि होनेका दावा पेश करने लगी हैं । इनका ही नहीं, इनके स्वरूपमें भी परिवर्तन हुआ है । अब ये साम्प्रदायिक संस्थाओंका नाम बदलकर राजनीतिक संस्थाएँ बन रही हैं । कलकत्ता हिन्दू महासभा और मुस्लिमलीगका मुख्य कार्य हिन्दुओं और मुसलमानोंके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारोंकी रक्षा करना समझा जाता था, अगर कांग्रेस इनके साथ समझौता कर लेती तो ये कांग्रेसके साथ राजनीतिक क्षेत्रमें कन्धेसे कन्धा भिड़ा कर चलनेको, या कमसे कम उनकी राहमें रोड़े न अटकानेको तैयार थी, किन्तु आज हम देखते हैं कि कांग्रेससे उन संस्थाओंका विरोध केवल साम्प्रदायिक प्रश्नोंपर ही नहीं रह गया है । अब कांग्रेसके साथ उनका विरोध मौलिक है; विरोध उसकी विचारधारा और उसकी कार्य-प्रणालीसे है । आज उन संस्थाओंके कर्णधारोंके बीच पारस्परिक कटुता बहुत कम दिखायी पड़ती है, वे आपसमें न लड़कर अपने मुख्य और समान शत्रु कांग्रेससे लड़ रही हैं । कांग्रेसके खिलाफ साम्प्रदायिक संस्थाओंका संयुक्त मोर्चा जोर पकड़ रहा है । हिन्दू महासभा और मुस्लिमलीगकी ओरसे कांग्रेसको

यह कह कर कोसा जा रहा है कि वह शासन करनेके अयोग्य है वह धर्म और संस्कृतिकी रक्षा करनेमें असमर्थ है, उसके हाथसे शक्ति छीनकर संस्थाओंके प्रतिनिधियोंके हाथोंमें, शक्ति देनेसे ही देशका भला हो सकता है ।

जैसा कि हमने ऊपर कहा, साम्प्रदायिक समस्याका जटिल होना कांग्रेसके पद-ग्रहणके बाद अनिवार्य था । नये शासन-विधानके लागू होनेके बाद देशकी स्थितिमें एक महत्वपूर्ण अन्तर हो गया है । आज सूबोंमें हुकूमतकी वागडोर, राजनीतिक शक्ति, एक बड़े हदतक जनताके हाथमें आ गयी है । जनताके प्रतिनिधियोंके रूपमें ८ सूबोंमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल कायम है । परन्तु अपने साम्प्रदायिक स्वरूप, प्रतिगामी कार्यक्रम और साम्राज्यशाहीके समर्थनके कारण साम्प्रदायिक संस्थाओंके नेताओंको इस राज्यशक्तिमें उनके इच्छानुसार भाग नहीं मिल पाया और उनकी चाह उनके मनमें ही दबी रहकर खटक रही है । कहनेको हिन्दूसभा और मुस्लिमलीग आदि साम्प्रदायिक संस्थाओंका उद्देश्य अपने सम्प्रदायके सर्वसाधारण लोगोंकी भलाईके लिए प्रयत्न करना रहा है, पर यदि इन संस्थाओंद्वारा किये जानेवाले कार्यपर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि व्यवहार-रूपमें ये संस्थाएँ मुट्ठीभर सामन्तों, राजाओं, तालुकेदारों, जमींदारों और शहरके कुछ अनुदार मध्यम श्रेणीके लोगोंकी संस्थाएँ रही हैं, जो कि धर्मके नामपर अपने वर्गका स्वार्थ-साधन करने, सरकारी नौकरियों और ऐसेम्बलीमें सीटें आदि प्राप्त करनेके काममें लायी जाती रही हैं । कांग्रेसके हाथमें शासन-शक्ति आ जानेसे ये वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारोंको छीना हुआ देखकर क्षुब्ध हो रहे हैं । राजनीतिक अधिकारोंसे ये वंचित थे ही साधारण जनता, किसानों, मजदूरोंकी आर्थिक अवस्थामें सुधारके जो कानून पास हो रहे हैं उससे इनकी सुविधाओंपर भी आघात पहुँच रहा है । फलस्वरूप इनका क्षोभ विद्रोहका रूप धारण कर रहा है । किसानोंके आर्थिक भारको कम करनेवाले लगान और कर्जकी कमी वगैरहके कानून ज्यों-ज्यों पास होते जाते हैं और कांग्रेसजन जिस अनुपातमें किसानों और मजदूरोंकी आर्थिक माँगोंके आधारपर उनका संगठन करते जाते हैं उसी अनुपातमें इन लोगोंका कांग्रेस-विरोध बढ़ता जाता है और ज्यों-ज्यों इनकी आर्थिक सुविधाओंपर आघात और जनतामें श्रेणी-चेतना बढ़ती जायगी, त्यों-त्यों कांग्रेसके प्रति इनका विरोध भी बढ़ता जायगा ।

साम्प्रदायिक नेताओंमें जो क्षोभ पैदा हो गया उसकी वजहसे उन्होंने खासकर मुस्लिमलीगके नेताओंमें, ऐसा जहर उगलना शुरू कर दिया था जिसका लाजिमी नतीजा था कि जगह-जगह दंगे हो जाते । अगर इन लोगोंने जानबूझकर दंगे नहीं कराये तो कमसे कम अपने उत्तेजनाजनक भाषणों और लेखों आदिके द्वारा ऐसा दायुमण्डल तो तैयार कर ही दिया था जिसमें दंगे हो जाना लाजिमी हो गया था । दुर्भाग्यवश कांग्रेसके नेताओंने दूरदर्शितासे काम लेकर पहलेसे ही दंगोंको रोकनेकी तैयारी न की, मन्त्रिमण्डलोंने दंगोंको रोकनेकी तैयारी न की और पुलिसने इन दंगोंको शान्त करनेमें आगे बढ़कर उचित तत्परता नहीं दिखायी । इसका नतीजा यह हुआ कि सम्प्रदायवादियोंको यह कहकर कांग्रेसको बदनाम करनेका मौका मिल गया कि कांग्रेसी हुकूमत अमन-अमान बनाये रखनेमें

असमर्थ है। इन दंगोंकी वजहसे हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंमें कांग्रेसकी प्रतिष्ठाकी धक्का लगा है। मुसलमान सम्प्रदायवादियोंकी करतूतो, साम्प्रदायिक देश-द्रोहियोंकी चालो और कांग्रेस मन्त्रिमण्डलकी ढीली-ढाली नीति इन सबने मिलकर कांग्रेसको हिन्दू जनतामें बदनाम किया।

हिन्दू-महासभामें एक अश ऐसे लोगोका था जो ब्रिटिश साम्राज्यशाहीसे लडकर देशमें हिन्दू राज्यकी स्थापनाका स्वप्न देखता है। आरम्भमें कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलकी स्थापनासे यह वर्ग सन्तुष्ट था। कांग्रेसमें हिन्दुओंकी मुख्यता होनेके कारण इसका यह विश्वास हो चला था कि आगे चलकर देशमें हिन्दूराज्य कायम हो सकेगा। दंगोंके अवसरपर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलद्वारा जो नीति बरती गयी उसकी वजहसे यह वर्ग भी निराश हो गया। हैदराबादके आन्दोलनमें कांग्रेसने जिस प्रकार अपनेको अलग रखा और आन्दोलनको साम्प्रदायिक रूप धारण करने दिया उससे भी हिन्दू जनतामें कांग्रेसके सम्बन्धमें गलतफहमी फैली और हिन्दू महासभाके प्रति सहानुभूति बढी।

मुस्लिमलीगकी प्रतिष्ठा बढने और मुसलमानोका उसपर सिकका जमनेका एक कारण यह हुआ कि जिन प्रान्तोमें मुसलिम लीगसे अलग रहकर मुसलमानोंने चुनाव लडा था और मिनिस्ट्री कायम की थी, उन प्रान्तोमें उन्हे अपने नीचेकी जमीन खिसकती दिखायी दी। चूकि ये प्रान्त चारो ओरसे कांग्रेसी प्रान्तोसे घिरे हुए हैं, इसलिए उन प्रान्तोकी जनताकी अवस्थामें सुधार होते देख स्वभावतः इन प्रान्तोकी जनतामें प्रतिगामी मिनिस्ट्रियो-के प्रति असन्तोष बढ चला। ऐसी हालतमें फजलुल हक और सिकन्दर हयात इस बातके लिए मजबूर हुए कि मुसलिम लीगमें सम्मिलित होकर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलको बदनाम करे और मुसलमानोके मजहबी जजवातको उभाडकर अपने अस्तित्वको सुरक्षित रखे।

इस प्रकार ये साम्प्रदायिक संस्थाएँ अपना पुराना चोला बदलकर समाजके प्रतिगामी वर्गोंकी ताकतको सुरक्षित रखनेवाली समस्याएँ बन गयी हैं। अलग-अलग संगठन होनेपर भी आज इन संस्थाओंका मौलिक स्वरूप एक ही हो गया है और भविष्यमें भी घट ऐसा समय आ सकता है जब कि अपने चेहरेपरसे साम्प्रदायिकताका नकाब उतारकर या उसे नाममात्रको ही कायम रखकर वे संस्थाएँ एक-दूसरेकी खुलेआम मदद करती नजर आयें।

सम्प्रदायवादी संस्थाओंके इस नये दृष्टिकोणपर यूरोपकी फैसिस्ट विचारधाराकी छाप है। फैसिस्ट राष्ट्रोंकी ओरसे गुप्त और अर्ध-प्रकट रूपसे जो प्रचार जारी है उसपर भी इनका काफी असर पड़ा है। पूर्विय जगतमें फैसिस्ट विचारधाराका प्रचार करने और लडाईं छिडनेकी हालतमें इन राष्ट्रोंका समर्थन फैसिस्ट-राष्ट्रोंके पक्षमें प्राप्त करनेके लिए फैसिस्ट राष्ट्रोंकी ओरसे कई वर्षोंसे लगातार प्रयत्न हो रहे हैं और इस कार्यके लिए इन राष्ट्रोंकी ओरसे काफी धन भी खर्च किया जाता है। इन लोगोंने उन सभी देशोंमें अपना जाल बिछा रखा है जिनपर या तो इनकी आँखें गडी हुई हैं और जिन्हें वह आगे चलकर हडप जानेके स्वप्न देख रहे हैं या जिन देशोंमें नाजी-प्रचारद्वारा युद्धकी अवस्थामें ब्रिटेन, फ्रान्स और रूसको तंग किया जा सकता है। फिलिस्तीन और सीरियाके अरब-

आतंकवादियोंको इटली और जर्मनीकी ओरसे शस्त्रास्त्रोंकी मदद भी पर्याप्त मात्रामें दी गयी है। हिन्दुस्तानको फैसिस्ट राष्ट्रोंने अपना विशेष कार्यक्षेत्र बनाया है। इनमेसे जापान और इटलीका प्रचार तो साधारण है, किन्तु जर्मनीका नाजी-प्रचार काफी बड़े पैमानेपर हो रहा है। हिटलरके आर्य-जातिकी श्रेष्ठताके सिद्धान्तके नामपर हिन्दू युवकोंको नाजी विचारधाराकी ओर आकर्षित किया जाता है। ऐसे हिन्दू महासभावादी युवकोंपर इस प्रचारका काफी असर पड़ रहा है जो यह समझनेमें असमर्थ हैं कि फैसिज्म साम्राज्यवादका ही आगे बढ़ा हुआ रूप है। जर्मनीका आर्य-जातिकी श्रेष्ठताका सिद्धान्त, स्वस्तिक चिह्न और ब्रिटेनका विरोध ऐसे युवकोंके भ्रमको और भी पुष्ट करते हैं। मुसलमानोंकी वीरताकी प्रशंसा की जाती है और ब्रिटेनकी फिलिस्तीन और सीमान्त नीति लेकर उन्हें ब्रिटेनके खिलाफ उभाड़ा जाता है। मुसलमानोंपर इस प्रचारका काफी असर पड़ा है। खाकसार आन्दोलन तो स्पष्टतः नाजी तरीकोपर चलाया जा रहा है। ब्रिटिश सरकारकी ओरसे इस प्रचारको रोकनेकी कोशिश इसलिए नहीं की जाती कि वह समझती है कि समाजवादका जो प्रचार यहाँ हो रहा है उसके असरको दूर करनेके लिए फैसिस्ट प्रचार आवश्यक है।

हमारे देशमें फैसिस्ट प्रचार इस प्रकार कुछ लोगोंपर अपना असर कर रहा है इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। सच तो यह है कि पूँजीवादकी ह्रासावस्थाके इस जमानेमें सारी दुनिया ही दो खेमोंमें बँट गयी है। एक ओर वे प्रगतिशील लोग हैं जो मौजूदा पूँजीवादी सगाज-व्यवस्थाको हटाकर समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, दूसरी ओर वे फैसिस्ट लोग हैं जो मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्थाको ही सैनिक शासनके बलपर रखना चाहते हैं। हमारा देश अभी भी पराधीन है, इसलिए हमारे यहाँ ये दो भाग स्पष्ट रूपसे दिखायी नहीं देते। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि साम्प्रदायिक संस्थाओंके नये स्वरूपमें हमें फैसिस्ट आन्दोलनके आरम्भका दर्शन होता है।

हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनके लिए इस प्रकारकी प्रगति किस हदतक खतरनाक है और इस नये खतरेका किस तरह मुकाबला किया जाय इसपर हम फिर विचार करेंगे।^१

पहले हम कह आये हैं कि साम्प्रदायिक संस्थाओंके स्वरूपमें कांग्रेस पदग्रहणके बाद, बुनियादी तबदीली हुई है। अब वे अपने सम्प्रदायकी जनताके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारोंकी रक्षाके लिए ही आन्दोलन नहीं करती; धार्मिक-संस्थाओंके स्थानपर वे राजनीतिक संस्थाएँ बन रही हैं। कांग्रेससे उनका विरोध केवल साम्प्रदायिक समस्यापर न होकर उसकी मौलिक विचारधारा और कार्य-प्रणालीसे है। हिन्दू-महासभा और मुसलिम लीगका पुराना आपसी झगडा खत्म हो चला है और उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेसका विरोध हो गया है। इन संस्थाओंके द्वारा समाजके उन प्रतिगामी वर्गोंके नेतृत्वमें एक संयुक्त मोर्चेका संगठन हो रहा है, जो कांग्रेसके पदग्रहणके फलस्वरूप अपने राजनीतिक

अधिकारोंसे वंचित हो गये हैं और जनताके आर्थिक भारको कम करनेके लिए बनाये जानेवाले कानूनों और किसान-मजदूरोंमें बढ़ती हुई श्रेणी-चेतनाकी वदौलत जिनकी आर्थिक सुविधाओंपर आघात हो रहा है ।

इन समस्याओंके प्रतिगामी नेतृत्व और दृष्टिकोणकी वदौलत हमें उनसे यह खतरा नहीं कि वे विस्तृत जनाधार (mass basis) वाली कांग्रेसकी प्रतिद्वन्द्वी संस्थाएँ बन सकेंगी, किन्तु उनके द्वारा होनेवाले विरोधी प्रचारको रोकनेका प्रयत्न किया गया तो इसमें सन्देह नहीं कि वे हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनको छिन्न-भिन्न करनेमें बहुत-कुछ अंगोंमें सफल हो सकेंगी । प्रजातान्त्रिक तरीकेसे इन संस्थाओंको कांग्रेसके मुकाबलेमें बढ़नेकी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उनकी ओरसे राष्ट्रीय आन्दोलनके बढ़ते हुए प्रभावको रोकनेके लिए उतना जायज तरीकेका इस्तेमाल किया जायगा जो कि पश्चिमके फ़ैमिस्टोद्वारा काममें लाया गया है । इन संस्थाओंद्वारा प्रजातन्त्रके विरुद्ध प्रचार आरम्भ कर दिया गया है । हालमें मि० जिन्नाने वम्बईके एक भाषणमें यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रजातन्त्रमें उनका विश्वास नहीं है । हिन्दू-महासभाके पत्र भी लोकतन्त्र प्रणालीके विरुद्ध अधिकाधिक लिखने लगे हैं । कांग्रेसके और देशमें फैली हुई प्रगतिशील विचारधारा-के खिलाफ मिथ्या और भ्रमपूर्ण प्रचार करके, संगठित गुण्डाशाहीके तरीकेका इस्तेमाल करके और साम्प्रदायिक वैमनस्यको फैलाकर इनके द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलनकी प्रगतिमें बाधाएँ डाली जायँगी । सबसे बड़ा खतरा इन साम्प्रदायिक दंगोंका ही है । अगर साम्प्रदायिक दंगाने भीषण रूप धारण किया और विभिन्न सम्प्रदायोंमें आपसी मनमुटाव जोर पकड़ता गया तो ऐसी हालतमें, जैसा कि महात्मा गांधीने बार-बार जोर दिया है, राष्ट्रीय आन्दोलनको सफलतापूर्वक चलाना बहुत कठिन हो जायगा ।

साम्प्रदायिक समस्याको हल करनेका पुराने समझौतेका तरीका बहुत अधूरा रहा है । उसके द्वारा केवल शिक्षित मध्यम श्रेणीकी समस्या हल होती थी; समझौतेकी बातचीतके जरिये उन्हें अपने तबकेके लिए एसेम्बलीमें सीटें और सरकारी नौकरियोंमें हिस्सा हासिल करनेमें मदद मिलती रही है । चूँकि इस समस्याके बने रहनेमें इन तबकेका स्वार्थ-साधन होता था, इसलिए वह इसे मिटानेका सच्चे दिलसे प्रयत्न न करता था । लेकिन आजकी अवस्थामें तो पुराना तरीका सिर्फ अधूरा नहीं, बल्कि एकदम बेकार पड़ गया है । अब साम्प्रदायिक संस्थाओंकी माँग सिर्फ सरकारी नौकरियों और हुकूमतोंमें हिस्सा पाना ही नहीं है; आर्ज उनकी माँग है कि जनताकी आर्थिक अवस्थामें सुधार करनेकी दृष्टिसे स्थिरस्वार्थ वर्गवालोंकी जो आर्थिक सुविधाएँ छीनी जा रही हैं, वे बन्द कर दी जायँ, परन्तु इन मसलेपर कोई समझौता नहीं हो सकता । ऐसा करना जनताके साथ विश्वासघात करना होगा । आर्थिक प्रश्नोंपर जमींदारों और पूँजीपतियोंके साथ समझौता करके कांग्रेस अपने क्रान्तिकारी स्वरूपको ही खो देगी ।

अगर कांग्रेस जनताके आर्थिक प्रश्नोंको हल करने और चुनावके वादोंको पूरा करनेकी ओर ध्यान देगी तो देहातोंमें सम्प्रदायवादियोंकी दान नहीं गल सकती ।

सम्प्रदायवादियोंका जोर शहरोमें और कस्बोंमें रहनेवाली शिक्षित मध्यम श्रेणी तथा अशिक्षित आबारा श्रेणीको अगर कांग्रेसने अपनानेका प्रयत्न नहीं किया तो ये लोग इन प्रतिक्रियागामियोंकी चालवाजीके शिकार होंगे। ये ही वर्ग पश्चिममें भी फैसिस्ट आन्दोलनकी खास ताकत रहे हैं। इन वर्गोंमें फैली हुई भीषण बेकारी इन वर्गोंके नवयुवकोंको सम्प्रदायवादियोंके चंगुलमें फँसनेको मजबूर करेगी। अपनी अशिक्षाके कारण अपनी आर्थिक दुर्दशाके कारणोंको न समझ सकने और जिन अवस्थाओंमें वे काम करते हैं उनकी बदौलत उनमें आगामी चेतनाका विकास न होनेके कारण वे औरोंके मुकाबले आसानीसे गलतफहमीके शिकार बनाये जा सकते हैं। किसानोंकी माँगोंको लेकर तो कांग्रेस आन्दोलन करती आयी है, पर शहरके इन तबकोंकी ओर अभी तक उसका ध्यान नहीं गया है। शहरोमें कांग्रेसका काम अब तक सिर्फ सभाएँ करके प्रस्ताव पास कर देना और मौके-बे-मौके जलूस निकाल देना भर ही है, लेकिन यह कार्यक्रम बिल्कुल ही अधूरा है। हमें शहरके उपर्युक्त वर्गोंकी रोजमर्राकी आर्थिक माँगोंको लेकर उनके लिए आन्दोलन करना होगा। तभी हम इनकी सक्रिय सहानुभूतिको अपने साथ ला सकेंगे, इनमें वास्तविक चेतनाका विकास कर सकेंगे और व्यवहार रूपमें यह सिद्ध करके दिखा सकेंगे कि आज जो साम्प्रदायिक नेता उनके हिमायती बन रहे हैं वे सच्चे सवालियोंके सामने आनेपर भाग खड़े होते हैं और उनका वास्तविक उद्देश्य अपने वर्गका स्वार्थ-साधन है। साम्प्रदायिक उपद्रवोंके समय शान्ति बनाये रखने तथा राष्ट्रीय आन्दोलनके कार्यको आगे बढ़ानेके लिए हमें स्वयंसेवकोंका दल हर शहर और देहातमें कायम करना होगा। कितने ही नौजवान साम्प्रदायिक संस्थाओंमें इसलिए भर्ती हो जाते हैं कि वहाँ वे स्वयंसेवकसेनामें भर्ती होकर एक प्रकारका मानसिक सन्तोष प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगोंका भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है।

अन्तमें, इस प्रसंगमें यह कहना भी बहुत आवश्यक है कि आजकी हालतमें जबकि स्थिरस्वार्थी वर्ग कांग्रेस विरोधी मोर्चेको सुदृढ़ कर रहे हैं, कांग्रेसकी भीतरी एकताको बनाये रखना हमारे लिए पहलेसे भी ज्यादा जरूरी हो गया है। विचारधारा तथा दृष्टिकोणकी विभिन्नता होनेपर भी कांग्रेसके भीतर सभी समूहोंको कन्धेसे कन्धा भिडाकर चलना चाहिये। हमारी आपसी फूटसे हमारी राष्ट्रीय संस्था और राष्ट्रीय आन्दोलनकी ताकत कमजोर होगी, विरोधियोंको जनताको भ्रममें डाल रखने और उसे गलत रास्तेपर ले जानेमें सहायता मिलेगी। साथ ही हमारे भीतर स्वयं अवसरवादको प्रोत्साहन मिलेगा। आजकल कांग्रेस जिस प्रकार वामपक्ष और दक्षिणपक्षका अखाड़ा-सा बना चाहती है उससे हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन छिन्न-भिन्न हो जायगा और साम्राज्यशाहीसे सफल मोर्चेकी तैयारी एक-अर्सेके लिए टल जायगी। श्री सुभाषचन्द्र बोसपर कार्य-समितिने अनुशासन-भंग करनेके लिए जो कड़ी कार्रवाई की है उससे यही जान पड़ता है कि इस बढ़ते हुए साम्प्रदायिक खतरेके नये स्वरूपकी ओर हमारे नेताओंका ध्यान नहीं है। हम कांग्रेसके दक्षिण और वाम दोनों पक्षोंके नेताओंसे और खासकर गांधीजीसे यह अनुरोध करते हैं

कि वे ऐसी सूरत ढूँढ निकालें जिससे विचारधारा सम्बन्धी मतभेद रखते हुए भी कांग्रेसके भीतर सभी साम्राज्य विरोधी दल मिलकर काम कर सकें ।^१

कांग्रेसके सामने सवाल

विकास जीवनका लक्षण और स्वभाव है । प्रकृतिमें जहाँ कहीं भी जीवन है हम इस नियमको लागू पाते हैं । विकासका मार्ग जीवनके लिए संघर्षकी राहमें होता है । जीवनके लिए संघर्ष मनुष्य समाजमें अनेक प्रकारकी कसमकस और जटिलताएँ और संघर्ष मनुष्य-समाजके विकास और विस्तारके साथ विस्तृत रूप ग्रहण करते जाते हैं । कबीलोंकी शक्लसे वे जातीय और जातीय शक्लसे वे राष्ट्रीय संघर्ष हमारे सामने आते हैं । आज यूरोपमें जारी अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष भी एक बहुत बड़े परिमाणमें जीवनके लिए संघर्ष है; क्योंकि आधुनिक परिस्थितियोंमें जीवनके विकासके लिए मार्ग बन्द हो रहा है ।

जीवनके लिए संघर्ष और विकास बहुत हदतक एक चीज है । जीवन-संघर्ष और विकासके लिए जरूरी है कि जीवनके मार्गमें जो बाधाएँ या प्रतिकूल अवस्थाएँ आयें उन्हें दूर किया जाय । गुलामी चाहे वह वैयक्तिक हो या राष्ट्रीय, जीवनके क्षेत्रको बहुत संकुचित कर देती है और गुलामीकी अवस्थामें जीवनका विकास न हो सकनेके कारण व्यक्ति और राष्ट्र मृत्युकी ओर चलने लगते हैं । मनुष्य और राष्ट्र मौतसे बचनेके लिए गुलामीके खिलाफ लड़ते हैं । गुलामीके खिलाफ लड़ना हमारा स्वभाव है ।

सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दीके अन्तर्राष्ट्रीय जीवन संघर्षका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश विदेशी गुलामीमें फँस गया और हमारा राष्ट्रीय जीवन स्वाभाविक विकासके मार्गपर न चलकर विदेशी साम्राज्यको पुष्ट करनेका माधन बनने लगा । जीवनके स्वभाव और लक्षणके अनुसार यह जरूरी था कि हमारा देश इस गुलामीसे निजात पानेकी कोशिश करता । यह कोशिशें शुरू हुई । कई जगहोंमें यह कोशिशें हुई । जिनका गवाह इतिहास है । इन सब कोशिशोंमें सबसे बड़ी कोशिश जो आज ५४ वर्षसे जारी है हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है ।

कांग्रेसका जन्म

जिस समय कांग्रेसका जन्म हुआ, उस समय हमारा देश गुलामीकी सबसे दर्दनाक हालतमें था । उस समय स्पष्ट तौरपर आजादीकी बात सोचना, उसका सपना देखना भी हमारे लिए आसान नहीं था, परन्तु आजादी या जीवनकी इच्छा और प्रयत्न सूक्ष्म रूपसे या अप्रकट रूपसे कौमके दिलमें मौजूद था । यह प्रयत्न उस गहरी गुलामीमें एक संघटनके रूपमें प्रकट हुआ जिसका नाम पड़ा कांग्रेस । उस समय कांग्रेसका काम अधिकार

माँगना नहीं, रियायते माँगना था; उस समय कांग्रेस आजादी नहीं, बल्कि नौकरियाँ माँग करती थी। उस समय नाममात्रके अधिकारके रूपमें भी कोई ऐसी चीज हमलोगोंके हाथमें नहीं थी जिसके लिए हमलोग आपसमें लड़ सकते।

कांग्रेसका उस समयका उद्देश्य था विदेशी साम्राज्यकी मातहतमें कुछ अधिकार या रियायते माँगना। यह रियायते थी विदेशी साम्राज्यकी मशीनरीमें कल पुर्जे बननेकी इच्छा या नौकरी पानेकी इच्छा। यदि हम सूक्ष्म रूपसे देखें तो इस नौकरी माँगनेकी इच्छामें भी आजादीकी एक कायर और सोयी हुई इच्छा थी।

आजादी नहीं नौकरियाँ

उस समय कांग्रेसकी अपील थी—हम तुम्हारे गुलाम तो हैं, परन्तु हमें अपनी इच्छासे ही गुलामी करने दो। अपनी इच्छासे गुलामी करनेका या विदेशी साम्राज्यकी नौकरी करनेका अधिकार माँगनेकी योग्यता हमारे देशकी सर्वसाधारण जनतामें नहीं थी। इसके लिए वे ही लोग उपयुक्त थे और इसका स्वप्न वे ही लोग देख सकते थे जो विदेशी साम्राज्यकी शिक्षा-दीक्षा काफी हदतक प्राप्त कर चुके थे और विदेशी नौकरशाहीके सम्पर्कमें आते रहते थे। यह लोग थे हमारे उच्च शिक्षा-प्राप्त बड़े लोग या वकील, डाक्टर, एडिटर, इत्यादि या कुछ बहुत बड़े-बड़े व्यापारी। इन लोगोंने बहुत आजिजी और नम्रतासे एक आवाज उठायी—जिसे इनसे नीचे परन्तु सर्वसाधारणसे बहुत ऊँचे लोगो और श्रेणियोंने सुना और इस आवाजमें कुछ अपनापन और कुछ अपने स्वार्थकी प्राप्तिकी गन्ध उन्होंने पायी और वे लोग भी पतंगोंकी तरह कांग्रेसके आशाके प्रकाशके लैंपके चारों ओर भँडराने लगे।

उस समय प्रतिवर्ष कांग्रेस होती थी, परन्तु जनसाधारणको उसके अस्तित्वका भी ज्ञान नहीं था। उस समय कांग्रेसकी राजनीति जनताकी राजनीति न थी। न जनता उसे समझती थी और न जनताको वह राजनीति समझानेकी जरूरत ही समझी जाती थी।

स्वराज्यका नारा

कांग्रेसकी यह आवाज और भावना आहिस्ता-आहिस्ता मध्यम श्रेणीतक पहुँची, जो कि विदेशी साम्राज्यकी उन रियायतोंसे सन्तुष्ट नहीं हो सकती थी, जिन्हें ऊँची श्रेणीके लोग माँग रहे थे और जो केवल गिनेचुने आदमियोंके लिए ही हो सकती थी। यह मध्यम श्रेणीके नागरिकलोग रियायतोंकी अपेक्षा ऐसे अधिकार चाहते थे जिनके लिए शासनके अधिकारोंकी जरूरत थी। इस श्रेणीके नेता बालगंगाधर तिलक थे। उन्होंने आकर अंग्रेजोंके हाथसे शासन माँगनेका प्रश्न उठाया और पहले-पहल 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' की आवाज उठायी।

इस आवाजने राष्ट्रके शरीरमें एक स्फूर्ति पैदा कर दी परन्तु यह आवाज भी जनसाधारणकी नहीं थी। यह आवाज थी जनताके उस अंगकी, जो कार्यमें छोटे-मोटे भाग लेता आया था और विदेशी साम्राज्यके विधानमें बेवस हो गया था। जनताके

इस अगको हम मध्यम श्रेणी कह सकते हैं। इस आवाजकी जड़में राजनीतिक भावना और जोश था और उसने शहरोंमें रहनेवाली मध्यम श्रेणीकी जनताको खूब स्पर्श किया, परन्तु ग्रामोंके रहनेवाले किसानों और मजदूरोंतक वह आवाज नहीं पहुँची।

इसके बाद कांग्रेसमें गांधीयुग आया। उसका आरम्भ हुआ मन् १९१८ के रौलट ऐक्टके विरोधसे। रौलट ऐक्टके विरोधमें जो आन्दोलन उठा उमका ढंग ऐसा था कि वह जनताकी चीज बनने लगा। गाँव-गाँव कांग्रेसका प्रचार होने लगा और स्वराज्यकी माँग जनताके सम्मुख रखी गयी। किसानोंसे बात करते समय, उनके सम्पर्कमें आनेसे, उनके दृष्टिकोणसे भी बहुत-सी बातें कही गयी; परन्तु यह आन्दोलन भी वास्तविक अर्थोंमें देशकी जनताका आन्दोलन न बन सका और इसकी वजह स्पष्ट थी कि जनताके रोजमर्राके जीवनसे इसका कोई सम्बन्ध न था।

आर्थिक प्रश्नोंकी चर्चा

कांग्रेसके मंचसे सबसे प्रथम हमें सन् १९३० में जनतासे सम्बन्ध रखनेवाले आर्थिक प्रश्नोंकी चर्चा सुनायी देती है और यह चर्चा उठी महात्माजीद्वारा लार्ड इरविनके सम्मुख रखी गयी माँगोंके रूपमें। यह माँग थी लगानको कमसे कम ५० फीसदी कम कर देनेकी। इस माँगका कारण यही था कि किसानोंकी आवाज अब कांग्रेसतक आने लगी थी। आर्थिक प्रश्नोंकी ओर कांग्रेसका ध्यान इस समयसे बढ़ने लगता है। कराँची कांग्रेसमें और उसके बाद लखनऊ कांग्रेसमें ५० नेहरूने जनतासे सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नोंको कांग्रेसद्वारा हाथमें लेनेकी आवश्यकतापर जोर दिया। इसका कारण यह था कि इसके पहले बारडोली (गुजरात) और यू० पी० में किसानोंकी समस्या राजनीतिक क्षेत्रमें आकर हमारी राष्ट्रीय लड़ाईका मुख्य हथियार बन गयी थी। हमें यह समझना पड़ेगा कि आर्थिक प्रश्नोंकी उपेक्षा करनेसे कांग्रेसकी शक्ति जो उस समय बढ़ गयी थी, वैसी न बन पाती।

इसके बाद कांग्रेसी सरकारोंका जमाना आता है। चुनावमें कांग्रेसकी सफलताका श्रेय बहुत हदतक हमारे चुनावके मैनीफेस्टो या प्रतिज्ञापत्र को है। इस प्रतिज्ञा-पत्रद्वारा कांग्रेसने जनताके आर्थिक जीवनमें सुधारोंकी प्राप्ति दिलाकर उनके जीवनके विकासके मार्गमें आनेवाली रुकावटोंको हटानेका आश्वासन दिया। परिणाममें हम कांग्रेसको किसानोंके सम्बन्धमें कानून बनाते हुए देखते हैं, परन्तु इन फुटकर कानूनोंसे कहाँतक सफलता हो सकती है ?

यदि कांग्रेसका उद्देश्य हमारे राष्ट्रको उसके जीवनके मार्गमें आनेवाली बाधाओंसे मुक्त कर उसे वास्तवमें विकास और जीवनके पथकी ओर ले जाना है जिसमें कि देशकी जनता जीवनका अधिकार पा सके, तो यह काम कुछ राजनीतिक नारों 'स्लोगन्स' की माला जपनेसे पूर्ण नहीं हो सकता। 'पूर्ण स्वराज्य', 'साम्राज्यवादसे आजादी' इन सब नारोंका तभी कुछ अर्थ हो सकता है जब हमारे सामने अपने समाजका ऐसा कोई रूप हो जिसमें जनता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रमें आत्मनिर्णयके अधिकारका

उपयोग कर सके, कांग्रेस किसी ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमको देशके सामने प्रोग्रामके तौरपर रख सके और हमारे नेताओंके विचार इस विषयमें स्पष्ट हो । इसके बिना न तो कांग्रेस को और न तो कांग्रेस-सरकारको ही सफ़ता मिल सकेगी, उल्टे वे अपना प्रभाव खो देंगे ।

हमारे सामने आनेवाले आर्थिक प्रश्न दिन-प्रति-दिन गम्भीर होते जाते हैं और पुरानी सामाजिक व्यवस्था समाजकी अधिकांश जनताके जीवनको असम्भव बनाये दे रही है । इस समय यदि कांग्रेस देशकी समस्याओंको हल करनेका दावा करती है तो उसके लिए आवश्यक है कि एक नयी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाका आदर्श छटपटाती हुई जनताके सामने रखे । पुरानी सामाजिक व्यवस्था जो कि अनुपयुक्त हो चुकी है यदि कांग्रेस उसीकी लीपापोतीमें लगी रहेगी, तो वह भी उस पुरानी व्यवस्थाकी ही तरह अनुपयुक्त हो जायगी । उसका नेतृत्व समाप्त हो जायगा ।

अब केवल जेलखाने भर देनेकी नीतिसे ही काम नहीं चलेगा । जहाँ हमारा आन्दोलन पहुँच चुका है उससे आगे वह तभी बढ़ सकेगा जब हम जनताके जीवनको असम्भव बना देनेवाले प्रश्नोंको हाथमें लेंगे । हमें समाजमें मौजूदा श्रेणियोंकी स्थिति और मौजूदा व्यवस्थामें उनके हितोंके विरोधको समझकर उनका उपाय करना होगा और इस दृष्टिसे ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रमें जनताका राज्य कायम करनेका कार्यक्रम लेकर चलना होगा ।

यदि हम जनताकी शक्तिके बलपर साम्राज्यवादसे रियायतें ऐंठकर उससे समझौता करना चाहते हैं तो एक बात है । उसके लिए हमारा मौजूदा कार्यक्रम ठीक हो सकता है, परन्तु यदि वास्तविक पूर्ण स्वतन्त्रता हमारा लक्ष्य है तो हमें जनताके हाथमें शक्ति देने और उसे अपनी आर्थिक समस्याएँ हल करनेका अधिकार देना होगा ।

समयकी माँग

हमने शिक्षाके क्षेत्रमें एक कार्यक्रमकी बुनियाद रखी है । इसी प्रकार हमें आर्थिक क्षेत्रमें भी एक मौलिक और साहसपूर्ण परिवर्तनकी बुनियाद रखनी होगी । हमारे उद्योग व्यवसाय किस प्रकार चलेगें, उनकी व्यवस्था और संगठन किस प्रकार होना चाहिये कि मेहनत करनेवाली जनता अपने परिश्रमका पूरा फल पा सके और उत्पत्ति (पैदावार) के साधनोंपर उसका अधिकार रहे, किस प्रकार जनतामें प्रत्येक व्यक्तिको एक बराबर आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक अधिकार होंगें, किस प्रकार जनताकी सभी श्रेणियोंके व्यक्तियोंको सभी क्षेत्रोंमें जीविका प्राप्त करने, उन्नति और विकास करनेका समान अधिकार होगा । संक्षेपमें कहा जा सकता है कि हम समाजका संगठन किस प्रकार एक ऐसे आदर्शपर कर सकेंगे जिसमें बेकारी, भूख, शोषण अत्याचार आदि नहीं होंगे । ये हैं वास्तविक प्रश्न जिनका सम्बन्ध देशकी जनताके जीवनसे है और जिन्हें हल करनेकी ओर कांग्रेसको कदम बढ़ाना चाहिये । यदि कांग्रेस इन प्रश्नोंको हाथमें लेनेसे कतरायेगी तो उसका अन्त हो जायगा ।

आज हम कांग्रेसको अपने आन्दोलनके मार्गमें उस मजिलपर खड़ा पाते हैं जहाँ

उसमें आगे बढ़नेकी इच्छा तो है परन्तु वह अपने-आपको उसके योग्य नहीं पाती । स्पष्ट शब्दोंमें कहा जायगा कि वह आन्दोलनको आगे चलानेके लिए कोई हथियार नहीं खोज पाती । इस हथियार न खोज पानेका अर्थ वास्तवमें है उद्देश्य निश्चय न कर पाना ।

कांग्रेसकी शक्ति है जनता; और जनता आज सोयी हुई नहीं वह मनुष्ट भी नहीं । जनता आज जितनी असन्तुष्ट और सचेत है, वैसे कभी नहीं थी । जनता अपनी समस्याओंको लेकर व्याकुल है । यदि जनताकी इन समस्याओंको कांग्रेस अपना लेती है तो वह जनताकी प्रतिनिधि रह सकेगी और जनताकी ये समस्याएँ उसका हथियार बन जायेंगी और इनका हल उसका उद्देश्य बन जायगा, परन्तु यदि कांग्रेस इन सब महत्वपूर्ण समस्याओंसे पल्ला खीचकर ही अपना अस्तित्व कायम रखना चाहेगी, तो बिना ईधनकी आगकी तरह वह जल्द ही बुझ जायगी ।

कांग्रेसके भविष्य और अस्तित्वके बारेमें ये प्रश्न हैं जिनकी ओर हमारे नेताओंका ध्यान जाना चाहिये और इस समय आवश्यकता है कि कांग्रेस एक ऐसी योजना तैयार करे, जिसमें इन प्रश्नोंका स्पष्टीकरण हो और जनता उसे समझ सके ।^१

समझौता विरोधी सम्मेलन

पाठकोंको मालूम होगा कि श्री सुभाषचन्द्र बोस रामगढ़में समझौता विरोधी सम्मेलन करने जा रहे हैं । वर्किंग कमेटीने अपने हालके प्रस्तावमें यह बात साफ कर दिया है कि यह युद्ध साम्राज्यशाही युद्ध है और भारतवर्ष पूर्ण स्वाधीनतासे कमकी कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकता । वर्किंग कमेटीके इस प्रस्तावमें स्पष्ट शब्दोंमें यह भी कह दिया गया है कि डोमिनियन स्टेट्स साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य भारतवर्षको लागू नहीं होता, क्योंकि यह पद एक प्राचीन सभ्य जातिके उपयुक्त नहीं है और इससे भारतवर्ष कई तरहसे ब्रिटिश राजनीति और आर्थिक सगठनसे बँध जावेगा । उपर्युक्त प्रस्तावमें यह भी कहा गया है कि भारतवासियोंको ही अपने भाग्यके निर्णय करनेका अधिकार है और वही स्वराज्य पंचायत (Constituent Assembly)के द्वारा अपना विधान तैयार कर सकते हैं और ससारके दूसरे देशोंके साथ जैसा चाहे वैसा सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । साधारण रीत्या यह आशा की जाती थी । इस प्रस्तावके पास होनेके बाद सुभाषबाबू समझौता विरोधी सम्मेलनकी निरर्थकता और अनावश्यकताको मान लेगे, किन्तु बात ऐसी नहीं हुई । वह अब भी यह कहनेसे वाज नहीं आते कि वर्किंग कमेटी ब्रिटिश गवर्नमेंटसे समझौता कर लेगी । समझमें नहीं आता कि वर्किंग कमेटी क्या करे जिससे सुभाष बाबूके सन्देहका निराकरण हो । किन्तु क्या वास्तवमें उनको अब भी शक है कि हमारे नेता अपने ही निर्णयके विरुद्ध आचरण करेंगे अथवा केवल 'हाई कमाण्ड'के

विरुद्ध अपना प्रचार करनेकी गरजसे ही यह बात कही जाती है। उनकी 'इस प्रकारकी भविष्यवाणी दो बार गलत साबित हो चुकी है। गत वर्ष त्रिपुरीके पहले उन्होंने वर्किंग कमेटीपर फिडरेशन (संघ-शासन) के प्रश्नपर ब्रिटिश गवर्नमेण्टसे साजिश करनेका दोषारोपण किया था। जब आरोपको प्रमाणित करनेके लिए उनको चुनौती दी गयी तब उन्होंने यह कहा कि उनका मतलब यह नहीं था कि वह स्वयं इस बातपर विश्वास करते हैं। इसी तरह वह युद्ध छिड़नेके वाद कहते रहे कि कांग्रेसके लोग वजारते नहीं छोड़ेंगे और जोककी तरह अपनी कुर्सियोमे चिपके रहेंगे। यह भविष्यवाणी भी सच न निकली। खेदकी बात है कि सुभाषबाबू ऐसे उच्चकोटिके नेता अकारण ऐसी बातें बार-बार करते हैं। इसके लिए कोई आधार उनके पास नहीं है। वर्किंग कमेटीके हालके प्रस्तावके बाद तो इस मामलेमे तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता। प्रस्तावके शब्द विलकुल साफ हैं। किसी किस्मकी गुंजाइश बाकी नहीं रखी गयी है। फारवर्ड ब्लाकके एक बड़े हिमायती प्रोफेसर रंगाका कहना है कि वर्किंग कमेटीका हालका प्रस्ताव सुभाषबाबूकी एक बहुत बड़ी जीत है। इसका अर्थ यह है कि सुभाषबाबूके निरन्तर प्रचारके कारण ही वर्किंग कमेटीको इस तरहकी स्पष्टवादिताके लिए बाध्य होना पडा है। यदि यह ठीक है तो क्यों उस प्रस्तावपर अविश्वास प्रकट कर इस बड़ी जीतको हारमे परिवर्तित करनेकी चेष्टा की जा रही है।

समझौतेकी गुंजाइश नहीं

मेरा यह बराबर विचार रहा है कि समझौतेके लिए आज कोई गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि हमारे नेता डोमिनियन स्टेट्ससे सन्तुष्ट हो जाते, पर आजकी स्थितिमे मैं यह माननेको तैयार नहीं हूँ कि वह इससे कमपर भी समझौता कर लेते। आज कांग्रेसकी शक्ति बहुत बढ़ गयी है। मन्त्रिपद छोड़नेसे एक वैधानिक संकट उपस्थित हो गया है। शासन-विधानको स्थगित कर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट संसारको यह धोखा नहीं दे सकती कि भारतमे शान्ति विराजती है और यहाँके लोग उसके शासनसे सन्तुष्ट हैं। फिर युद्धकी अवस्था है। ऐसे समय तटस्थ राष्ट्रोंकी सहानुभूति और नैतिक सहायताका भी बड़ा महत्त्व हुआ करता है। तटस्थ राष्ट्र, जिनका स्वार्थ अटका नहीं है, किसी ऊँचे आदर्शके लिए ही किसी लड़नेवाले राष्ट्रको अपनी नैतिक सहायता देनेपर तैयार हो सकते हैं। कांग्रेसने अपने वक्तव्यद्वारा संसारके सम्मुख अपना दावा रखा है और संसारको बतानेकी चेष्टा की है कि यह युद्ध तभी नैतिक दृष्टिसे न्याययुक्त है जब ब्रिटिश गवर्नमेण्ट भारतवर्षकी स्वाधीनताको स्वीकार करे।^१

1. The Congress must press the National Demand on the authorities and insist on his immediate fulfilment.... Let not our leaders who are now deliberating at Wardha ask for a whit less than what is our inherent birthright. If they are called on to negotiate let them do so honourably (Forward Bloc 9 Sept. 1939)

इन विविध कारणोंसे कांग्रेसके नेता आज किसी बातसे सन्तुष्ट नहीं हो सकते, किन्तु अंग्रेजोंपर भी ऐसा दबाव नहीं पड़ा है कि वह कोई बड़ी बात करनेके लिए तैयार हो जावे। दुनियाको वह दिखलाना अवश्य चाहते हैं कि अपनी ओरसे वह हिन्दुस्तानको सन्तुष्ट करनेके लिए हर तरहसे तैयार हैं। किन्तु कांग्रेस भारतके ग्रन्थ समुदायोंके साथ न्याय करनेको तैयार नहीं है और इसी कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता। यही वजह है कि समझौतेकी चेष्टा दो बार विफल हो चुकी है और अब तो एक प्रकारसे इसके लिए दरवाजा ही बन्द हो गया है। समझौतेकी बातचीतके लिए भी गांधीजीको दोष दिया गया है। कहा जाता है कि वह दिल्ली-तीर्थ-यात्राके लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, पर यह बात कम लोग जानते होंगे कि युद्धके आरम्भ होनेपर सुभाष बाबूके पत्र 'फारवर्ड ब्लाक' ने ६ सितम्बरके अंकमें अपने अग्रलेखमें वर्किंग कमेटीसे अनुरोध किया कि वह राष्ट्रीय मार्गको अधिकारियोंके सामने पेश करे और उसकी तात्कालिक पूर्ति पर जोर दे। इस लेखमें यह भी कहा गया था कि यदि हमारे नेता बातचीत करनेके लिए आमन्त्रित किये जावे तो वह निमन्त्रण स्वीकार करे, किन्तु सम्मानपूर्वक बातचीत करे।' एक वर्ष पहले मालदामे जो जिला राजनीतिक कांग्रेस हुई थी उसमें भी इस प्रकारकी बात कही गयी थी। यह स्पष्ट है कि सुभाष बाबू वर्धाकी आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीकी बैठकतक अधिकारियोंसे बातचीत करनेके विरुद्ध नहीं थे। उनकी शिकायत इतनी ही थी कि वर्किंग कमेटीने अपना वक्तव्य देनेमें देर कर दिया; बल्कि यदि यह कहा जाय कि यही उनका प्लान था तो अनुचित न होगा। 'अल्टिमेटम' देनेकी योजनाके भी अन्तर्गत यही बात थी। फिर गांधीजीने वासरायके निमन्त्रणको स्वीकार कर कौन-सा अपराध किया? वह तो सुभाष बाबूकी नीतिका ही अनुसरण कर रहे थे।

इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो सघर्षको वचाना चाहते हैं और समझौतेके लिए उत्सुक हैं, उनकी चले तो वह छोटा-मोटा सौदा करके भी इस सकटका अन्त कर दे, किन्तु आजकी अवस्थामें ऐसे व्यक्तियोंका समूह कांग्रेसको बहुत प्रभावित नहीं कर सकता। वे कांग्रेसमें समझौतेके प्रस्तावको लानेका भी साहस नहीं कर सकते। नेताओंपर वह बराबर दबाव डालते रहते हैं, पर वस्तुस्थिति उनकी बहुत सहायता नहीं करती, इसलिए उनकी चेष्टाएँ विफल होती हैं और उनकी इच्छाओंकी पूर्ति नहीं हो पाती। पर आजकी अवस्थामें ब्रिटिश गवर्नमेण्टपर न कोई ऐसा दबाव ही है कि वह कोई सार पदार्थ देना स्वीकार करे और न कांग्रेस ही किसी छोटी चीजको लेना कबूल कर सकती है।

अनुचित मार्ग

मैं यह मानता हूँ कि ऐसे समूहकी काररवाइयोंसे हमको सतर्क रहनेकी आवश्यकता है और उनका विरोध करना भी आवश्यक है, पर इसका यह तरीका नहीं है कि हम वर्किंग कमेटीको किसी साजिशका दोषी ठहरावे और उसके खिलाफ जिहाद बोल दे। वर्किंग

कमेटीने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है । हम इस हालके प्रस्तावके हवालेसे ही समझौता करनेवालोका मुँह बन्द कर सकते हैं । समझौते और सौदा करनेकी प्रवृत्तिको हम उचित उपायोका अवलम्बन करके ही दवा सकते हैं । गाली-गलौजसे यह काम सिद्ध होनेवाला नहीं है । उससे तो उल्टे काम विगड़ता है । एक ओर जहाँ हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस प्रवृत्तिको रोके दूसरी ओर हमको यह भी चाहिये कि संग्रामकी तैयारी करे । जन-आन्दोलनको पुष्ट करके ही हम साम्राज्यविरोधी शक्तियोको बढ़ा सकते हैं । इसी प्रकार वह वातावरण प्रस्तुत हो सकता है जिसके होते हुए राष्ट्र और कांग्रेस अपने ग्रादशसे भ्रष्ट नहीं हो सकती । इसके लिए अविश्वास और सन्देहका वातावरण घातक है । बराबर यह कहनेसे कि कांग्रेस लड़ेगी नहीं और हमारे नेता सुलहके लिए उत्सुक हैं हम कांग्रेसके प्रति जनतामे अविश्वासको बढ़ाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि जनता निस्साह हो जाती है और युद्धकी तैयारीसे हट जाती है । ऐसी शिक्षा और प्रचारका एक ही परिणाम होता है कि कार्यकर्ता असली कामसे हट जाते हैं । वह केवल अपने नेताओको अषणब्द कहकर अपनी उग्रताका परिचय देना पर्याप्त समझते हैं । नेताओकी पोल खोलनेके प्रयत्नमे वह अपनी ही पोल खोलते हैं । जो लोग इसपर विश्वास करनेको तैयार हो जाते हैं कि कांग्रेस नहीं लड़ेगी वह इसपर विश्वास सहसा नहीं करते कि सुभाष बाबू और उनका दल लड़ेगा और यदि ऐसा विश्वास भी करते हैं तो भी यह बात उनके मनमें नहीं बैठती कि केवल उनके लड़नेसे कोई देशव्यापी प्रभावशाली आन्दोलन हो सकता है । सुभाष बाबूने ब्रिटिश गवर्नमेण्टको चेतावनी दी है कि देश वर्किंग कमेटीके साथ नहीं है इसलिए उन्हें उससे किसी प्रकारका समझौता नहीं करना चाहिये । किन्तु देश जानता है और गवर्नमेण्ट जानती है कि किसके ग्राह्वानपर राष्ट्र क्रान्तिपथपर अग्रसर हो सकता है । नतीजा यह होता है कि इस शास्त्रार्थसे केवल विरोधियोकी ही शक्ति बढ़ती है, कुछ राष्ट्रीय कार्यकर्ता गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, प्रस्तुत कार्यसे पराङ्मुख हो मौखिक शास्त्रार्थको ही राष्ट्रकी सबसे बड़ी सेवा समझते हैं ।

इस समय विचारकी बड़ी अस्त-व्यस्तता है । लोगोके दिमाग साफ नहीं है, विविध प्रश्नोमे वह उलझे हुए हैं । हरएक अपनी ओर घसीटता है और सबसे बड़ा उग्रवादी होनेका दावा पेश करता है । शब्दोका मायाजाल भी विचित्र है । 'स्लोगन' और नारे बड़े प्रभावशाली होते हैं । यदि नारे ठीक हुए तो यह बड़ा अनर्थ भी करते हैं । इसलिए स्लोगन देनेका काम बड़ी जिम्मेदारीका है । आजकल तरह-तरहके नारे चल पड़े हैं । यह वर्तमान अस्त-व्यस्तताको और भी बढ़ाते हैं । एक ही बातको बार-बार दुहरानेसे लोग उसकी सच्चाईके कायल हो जाते हैं । आजकल इस तरहका गलत प्रोपेगेंडा (प्रचार) बहुत हो रहा है । जो इस कलामे जितना ही सिद्धहस्त हो उसे उतनी ही तात्कालिक सफलता मिलती है । इसे कौन पूछता है कि सत्यता किधर है । सत्य भी मौजूद रहकर आज विजयी नहीं रह सकता, उसको भी अपने प्रचारके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है । ऐसी हालतमे हमारी राष्ट्रीय कमेटियोको ठंडे दिलसे सब बातोपर विचार करना चाहिये और छानबीन करके ही किसी निर्णयपर पहुँचना चाहिये केवल जोशसे कुछ नहीं होता है ।

बुद्धिकी कसीटीपर कसकर ही तथ्यका निर्णय हो सकता है। अकारण सवपर अविश्वास और सन्देह करनेसे कोई लाभ नहीं होता और राजनीतिक जीवन भी कटु और दुखद हो जाता है। हमको वस्तुस्थितिको ठीक-ठीक समझकर ही अपना कर्तव्य निर्धारित करना चाहिये। वस्तुस्थिति यदि प्रतिकूल है तो उसको यथासाध्य बदलनेकी चेष्टा करनी चाहिये किन्तु जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक करनेसे क्या लाभ।

आजकी स्थिति यह है कि जवतक मनमय कांग्रेस आगे नहीं बढ़ती और गांधीजी आगे नहीं बढ़ते तबतक कोई प्रभावशाली राष्ट्रव्यापी आन्दोलन नहीं हो सकता। कांग्रेसकी नीतिकी घोषणा हो चुकी है। उसपर अकारण सन्देह करना अनुचित है और अपनी शक्तिको क्षीण करना है। कांग्रेसको अग्रसर करनेका प्रत्येक उपाय करना चाहिये। वह आनेवाले संग्रामकी तैयारीमें लगनेसे ही होगा, एक दूसरेको दोषी ठहराने से नहीं।

सम्मेलनका उद्देश्य

समझौता विरोधी सम्मेलनके सम्बन्धमें सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इसका गूढ़ उद्देश्य हमको कांग्रेसकी विरोधीसंस्था बनाना है। मुनाफ वावू १० फरवरीके 'फारवर्ड ब्लॉक' के अंकमें लिखते हैं कि कांग्रेसमें सड़ान आ गयी है, इसे हमें रोकना है। उनका कहना है कि कांग्रेस समझौते कर लेगी और इस तरह कांग्रेस नामका उपयोग करनेके हकको खो बैठेगी, क्योंकि वह ऐसा करके अपने आदर्शसे भ्रष्ट हो जावेगी। इस समय वामपक्ष ही कांग्रेसका वास्तविक कर्णधार होगा और उसको दक्षिण पक्षके लोगोंको कांग्रेससे पृथक् करनेका अधिकार होगा। उनको डर है कि दक्षिण पक्ष कांग्रेसमें अपने फर्जी बहुमतके बलपर कांग्रेससे न निकलेगा और उस समय कांग्रेसके दो टुकड़े हो जावेंगे और जनताको फँसला करना होगा कि वह किमको अपनावे। वह एक मुकाबलेकी दूसरी कांग्रेस खड़ी करना चाहते हैं। आजकी कांग्रेसमें उनको बैठनेका हक नहीं है, इसलिए वह अपनी दूसरी कांग्रेस बनानेकी फिक्रमें २४ फरवरीके अंकमें वह लिखते हैं कि "रामगढ़ कांग्रेसके बारेमें यदि वामपक्षी परेजान न हो तो उससे आसमान फूट न पड़ेगा। अच्छा हो यदि वह रामगढ़ कांग्रेसको शुद्ध दक्षिण-पक्षकी कांग्रेस बनानेमें सहायता दें। इस साल कांग्रेस पण्डालके बाहरकी घटनाएँ अधिक जरूरी होंगी। रामगढ़में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन होने जा रहा है। यदि इसको सफलता मिली तो राजनीतिक दृष्टिसे कांग्रेसके महत्त्वको यह ढक देगा यह शब्द विचारणीय है। इससे स्पष्ट है कि मुनाफ वावू कांग्रेसके महत्त्वको घटाना चाहते हैं और उसको क्षीण और नष्ट कर एक प्रतिद्वन्द्वी संस्था खड़ी करना चाहते हैं। मुनाफ वावू कांग्रेसके प्रति सदा अपनी अटल श्रद्धा प्रगट किया करते थे। उनका झगड़ा 'हाई कमाण्ड' से था, न कि कांग्रेससे। आरम्भमें वह गांधीजीको भी इस झगड़ेमें अलग रखने थे, उनके लिए आदरका भाव था। उनके और वकिंग-कमेटीके सदस्योंमें वह फर्क किया करते थे। धीरे-धीरे यह फर्क भी मिट गया है और कांग्रेसके प्रति वह अपनी पुरानी श्रद्धा भी खो बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा क्यों न हो कांग्रेस संस्थासे छोटा है। हम व्यक्तिके पुजारी नहीं हैं।

हम संस्थाकी महत्ताको मानते हैं साथ ही साथ हमें न भूलना चाहिये कि संस्थाका नष्ट करना सहल हो सकता है संस्थाका बनाना उतना सुगम नहीं । हमारा तो विश्वास है कि कांग्रेसमें एक सच्चे साम्राज्यविरोधी बननेकी पूरी ताकत है । कांग्रेसके क्रमिक विकासका इतिहास इसका साक्षी है । हमारे इस कथनका यह आशय नहीं है कि कांग्रेसके दूसरे रास्तेपर जानेकी सम्भावना ही नहीं है, किन्तु इसकी आशा कम है । इसके अतिरिक्त जबतक यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती तबतक अपने तर्काश्रित विश्वासको छोड़ना भी अनुचित होगा । इस सम्भावनाको दूर करनेका अच्छा उपाय यह नहीं है कि हम कांग्रेसका विरोध करने लगे और पुरानी इमारतको ढहानेकी कोशिश करें, किन्तु हमें उचित साधनोंसे काम लेकर खतरेको दूर करने का उपाय करना चाहिये ।

एक बुनियादी सवाल

फारवर्ड ब्लाकके एक दूसरे नेता श्री निहारेन्दु दत्त मजूमदार तो प्रसन्न होंगे यदि इस सम्मेलनसे एक वामपक्षी (left) कांग्रेसका जन्म हो । उन्होंने मौजूदा कांग्रेसके सामने कुछ शर्तें रखी हैं । एक शर्त यह है कि वर्किंग-कमेटीमें वामपक्षियोंका बहुमत हो । जब कांग्रेसमें दक्षिणपक्षका बहुमत है तो उनके सामने यह शर्त रखना कि तुम समस्त नैष्ठिक अधिकार वामपक्षको सौंप दो, कहाँतक उचित है और इसे कौन माननेको तैयार होगा ? ऐसी असम्भव शर्त रखनेके माने यही होते हैं कि आप किसी-न-किसी बहानेसे एक नयी कांग्रेस बनाना चाहते हैं । हम जानना चाहते हैं कि क्या इसी तरह कांग्रेसको दो टुकड़ोंमें बाँटकर वामपक्ष प्रबल हो सकता है । यह तो साम्राज्यविरोधियोंको कमजोर करनेकी योजना है, इससे तो राष्ट्रीय संग्राम निश्चय ही दुर्बल पड़ जायगा । यह एक बुनियादी सवाल है । इसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते । इस समय सत्याग्रह होता है या नहीं इस प्रश्नका उतना महत्व नहीं है जितना इस नये खड़े किये सवालका है । जिन लोगोंका कांग्रेस संस्थाके प्रति सद्भाव है, जैसा कि कांग्रेस समाजवादियोंका और रायवादियोंका है—वह ऐसी दशामें समझौता विरोधी सम्मेलनको एक साधारण बात समझकर हँसीमें नहीं डाल सकते । यदि सम्मेलनके पीछे यह गूढ़ उद्देश्य न होता तो हम किसी-न-किसी तरह इसे वर्दाश्वित कर लेते और उतने चिन्तित न होते । किन्तु इस स्पष्टीकरणके बाद कौन कह सकता है यह सम्मेलन कांग्रेसके अस्तित्वके लिए खतरनाक नहीं है । सम्मेलनके प्रमुख कांग्रेस-वर्किंग-कमेटीको ब्रिटिश साम्राज्यवादका दोस्त और साथी कहकर बदनाम करते हैं जो कांग्रेसके प्रति विरोधके भावको जगाता है ।

श्री अन्नपूर्णयाका कहना है कि मन्त्रिपद ग्रहणके विरोधमें इस प्रकारका एक सम्मेलन हुआ था, तब आज समझौता विरोधी सम्मेलनका क्यों विरोध किया जाता है । यह मिसाल ठीक नहीं है क्योंकि कांग्रेसमें मन्त्रिपद लिया जाय या नहीं इसपर विवाद होनेवाला था । देशके सामने प्रश्न था कि मन्त्रिपद लिया जाय या शासन विधानमें संकट उत्पन्न किया जाय । यह प्रश्न अनिवार्य हो गया था और इसका उत्तर देना जरूरी था । ऐसी अवस्थामें जो लोग मन्त्रि पद ग्रहणके विरुद्ध थे उनका इसके विरुद्ध आवाज उठाना

स्वाभाविक और आवश्यक था। किन्तु समझौतेके सम्बन्धमें यह बात नहीं कही जा सकती। कोई भी व्यक्ति समझौता करानेके लिए कांग्रेसमें प्रस्ताव नहीं ला रहा है। उल्टे वर्किंग कमेटी अपनी नीतिकी घोषणा कर यह बात स्पष्ट कर देती है कि पूर्ण स्वाधीनतासे कम कोई वस्तु स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए और खासकर इस कारणसे कि सम्मेलन बुलानेका उद्देश्य केवल समझौतेकी मनोवृत्तिकी द्वाणा ही नहीं है, किन्तु कांग्रेसको तोड़ना है और उसके बदलेमें दूसरी संस्था खड़ी करनी है हम इस सम्मेलनका विरोध करनेके लिए विवश हो गये हैं।

कम्युनिस्टोंकी चुप्पी

श्री मानवेन्द्रनाथराय और श्री जयप्रकाशनारायणने अपने-अपने दलकी स्थिति स्पष्ट कर दी है। कम्युनिस्ट अभीतक चुप हैं। इसका रहस्य मालूम नहीं होता। उनको एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिये। ऐसे महत्वके प्रश्नपर चुप रहना किसी राजनीतिक दलको शोभा नहीं देता। यह उसके राजनीतिक दिवालियेपनकी निशानी है या अवसरवादिता है। कहा जाता है कि इस विषयमें भी कम्युनिस्ट तटस्थ रहना चाहते हैं। दो पक्षमें जब कोई पक्ष मान्य न हो तब तटस्थ रहा जाता है। इस प्रश्नपर तटस्थ रहनेके अर्थ होंगे कांग्रेसका विरोध करना। तो क्या हम समझें कि कम्युनिस्टोंने अपने सयुक्त मोर्चेकी नीतिको छोड़ दिया है और अपनी पुरानी नीति फिरसे अख्तियार कर ली है? आशा है वह अपनी राय जाहिर कर लोगोको तरह-तरहके अटकल लगानेका मौका न देगे।

आजकी स्थिति बड़ी भयावह है। जहाँ राष्ट्रकी शक्ति बढी है वहाँ नये-नये खतरे भी पैदा हो रहे हैं। हमको सावधानीसे काम लेना है। पूर्वापरका अच्छी तरह विचार करके ही हमको अपना मार्ग स्थिर करना है। आशा है, कांग्रेस कार्यकर्त्ता इस प्रश्नकी विवेचना करेंगे और किसी ऐसे निर्णय पर पहुँचेंगे जिससे राष्ट्रकी क्षति न हो।^१

पाकिस्तान की योजना देशके लिए आत्मघातक है

देशके बँटवारेका फैसला केवल धार्मिक अल्पसंख्यकोपर नहीं छोड़ा जा सकता। मुसलिम-लीगने अपने लाहौरके इजलासमें हिन्दुस्तानके बँटवारेकी एक योजना मंजूर की है। इसे आमतौरसे 'पाकिस्तान' कहते हैं। मुसलिमलीगका कहना है कि हिन्दू और मुसलमान दो कौमों हैं, इनका राष्ट्र नहीं हो सकता, इसलिए हिन्दुस्तानमें धार्मिक समुदायके आधारपर तीन स्वतन्त्र राष्ट्र होने चाहिये। लीग हिन्दुस्तानकी एकता और और अखण्डताको नहीं स्वीकार करती। कांग्रेस इस माँगका विरोध करती है, किन्तु महात्माजीने कहा है कि यदि स्वराज्य पचायतके मुसलिम प्रतिनिधि इस माँगपर इसरार

करेंगे तो विवश होकर उसे स्वीकार करना पड़ेगा । महात्माजीका ख्याल है कि मुसलमान स्वयं इस योजनाका विरोध करेंगे । स्वराज्य पंचायतके क्या अधिकार होंगे, कौनसे प्रश्नोका निर्णय केवल मुसलिम प्रतिनिधियोंके हाथ में होगा आदि वाते अभी तक साफ नहीं की गयी हैं । मेरी रायमें प्रत्येक प्रश्न मुसलिम प्रश्न नहीं बनाया जा सकता । हिन्दुस्तानकी एकता और अखण्डताका प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं है कि इसका निर्णय किसी अल्प समुदायके हाथमें छोड़ दिया जाय । इस प्रश्नका सम्बन्ध मुसलमानोंके अतिरिक्त अल्प-समुदायोंसे भी है । बहुसंख्यक समुदाय भी इस प्रश्नकी उपेक्षा नहीं कर सकता । ऐसी अवस्थामें इसका निर्णय स्वराज्य-पंचायतके बहुमतके आधारपर ही होना चाहिये ।

मुसलमान पृथक् राष्ट्र नहीं

इतना ही कहना पर्याप्त न होगा, इसलिए हम इस प्रश्नकी मीमांसा करेंगे । धर्मके आधारपर राष्ट्र नहीं होते । राष्ट्रकी सबसे बड़ी पहचान भाषा है । हिन्दुस्तानके मुसलमान एक भाषा नहीं बोलते । वह प्रान्तोंमें बँटे हैं और अपने-अपने प्रान्तकी भाषा बोलते हैं । बंगालके मुसलमान और तामिल मुसलमानोंमें धर्मको छोड़कर कोई समानता नहीं है । बंगालका मुसलमान बंगाली हिन्दूके कहीं ज्यादा नजदीक है ।

हिन्दू और मुसलमानकी नस्ल एक है । संस्कृतिमें भी काफी सम्मिश्रण है । मुसलमानोंकी एक भाषा है और हिन्दुओंकी दूसरी ऐसी नहीं है । दोनों एक ही भाषा बोलते हैं । भाषाके आधारपर यदि राष्ट्र बनते हो तो कहना होगा कि भारतवर्षमें बंगाली, पंजाबी, सिन्धी, तेलगू गुजराती आदि राष्ट्र हैं । यदि राष्ट्रको आत्मनिर्णयका अधिकार दिया जाय तो इन विविध जातियोंको यह अधिकार देना होगा न कि हिन्दुओं या मुसलमानोंको । इस रीतिके अनुसार यदि पंजाबके लोग अलग होना चाहें तो हो सकते हैं, किन्तु इसका फैसला बहुमतसे नहीं हो सकता; क्योंकि प्रश्न असाधारण है । जबतक एक बहुत बड़ी तादाद इस माँगका समर्थन न करे पृथक् होनेका अधिकार देना अनुचित होगा ।

रूसका उदाहरण

इस सम्बन्धमें रूसका उदाहरण पेश किया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रूसके साम्राज्यमें कजक, उजबेक, वशकिर, तातार आदि भिन्न-भिन्न नस्लें थी जिनके देश अलग-अलग थे और जो जीतकर रूसी साम्राज्यमें दाखिल कर लिये गये थे और जिनपर जारका हर तरहका अत्याचार होता था । उनकी संस्कृतिको कुचल दिया गया था और उनकी कोई स्वतन्त्र सत्ता न थी । वह बराबर जारके विरुद्ध बगावत करते थे और उनमें साम्राज्यसे अलग होनेके लिए आन्दोलन चलते थे । ऐसी स्थितिमें लेनिनने इनको स्वभाग्य-निर्णयका अधिकार देना उचित समझा, लेकिन लेनिन साथ-साथ यह भी कहा करता था कि कर्तव्य तो एक साथ रहना बतता है । लेनिनके शब्द यह थे कि हम पृथक् होनेके विरुद्ध हैं, किन्तु पृथक् होनेका अधिकार देनेके पक्षमें हैं ।

यह जातियाँ रूसियोंको अविश्वासकी दृष्टिसे देखती थी; क्योंकि रूस (Great Russia) में प्रतिव्रियावादियोंका बोलवाला था । इनके विश्वासको प्राप्त करनेके लिए लेनिनके लिए यह आवश्यक था कि वह पृथक् होनेके अधिकारको भी स्वीकार कर लेता । यहाँपर यह कहना आवश्यक है कि इस प्रश्नपर सोवियत डेमाण्डोंमें एकमत न था । रोजालकूजेमवर्ग इस नीतिका कट्टर विरोध करती थी । वह स्वभाग्यनिर्णयके सिद्धान्तको खतरनाक समझती थी । उनका कहना था कि इसमें पूँजीपतियोंका ही आधिपत्य बढ़ता है । लोकमतको प्रभावित करनेके लिए पूँजीपतियोंके पास हजार तरीके हैं । जिस तरह वोट लेकर समाजवादकी स्थापना नहीं हो सकती उसी तरह उनका कहना था कि इस प्रकार हम जनताको केवल अपनी-अपनी जातिके प्रतिगामी पूँजीवादियोंके हाथ साँप देंगे । इस अधिकारके वर्तनेसे रूस छिन्न-भिन्न होने लगेगा । समाजवादका इनमें कोई उपकार न होगा, उल्टे क्रान्ति-विरोधी शक्तियाँ उत्तेजित होंगी । अन्तमें ऐसा हुआ भी । फिनलैण्ड और युक्रेनके पूँजीवादियोंने क्रान्तिका विरोध करनेके लिए जर्मनीसे सहायता माँगी और विवश होकर सोवियत रूसको फौज भेजकर हस्तक्षेप करना पड़ा । सिद्धान्तमें तो पृथक् होनेका हक मान लिया गया, पर जब कभी किसी जातिने इस हकको हासिल करनेकी चेष्टा की तो उसे दवा दिया गया । इस तरह हम देखते हैं कि सोवियत रूसमें इस नीतिपर कभी अमल नहीं किया गया । यह तो अवसरवादिताकी नीति थी और उससे कुछ काम भी निकला, किन्तु वास्तविक नीति तो सदा यही थी कि कोई सोवियत संघसे बाहर न जाने पावे । रूसकी कम्युनिस्ट पार्टीकी सातवीं कांग्रेसमें स्टालिनने कहा था—“नेशनल सोवियट रिपब्लिकके अपनी सत्ताकी रक्षा तभी कर सकती हैं और पूँजीवादपर गालिब आ सकती हैं जबतक कि वह एक संघमें सम्मिलित हैं ।”

वात सच थी, पर स्वभाग्यनिर्णयका सिद्धान्त प्रत्येकको आत्महत्या करनेका भी हक देता है । हमारे देशमें तो अवसरवादिताकी दृष्टिसे भी इसे स्वीकार करनेकी जरूरत नहीं है । पजाबी, सिन्धी आदिमें से किसीने भी ऐसी माँग पेश नहीं की है और वह पेश क्यों करे ? वह सब समान रूपसे ब्रिटिश साम्राज्यवादके अधीन है । उन सबके दुःख-सुख एकसे हैं । उनमेंसे एक दूसरेपर अत्याचार नहीं कर सकता । उनकी संस्कृति और भाषापर यदि कोई आघात करता है तो वह विदेशी सत्ता है । ऐसी अवस्थामें इनमेंसे कोई स्वतन्त्र राष्ट्रकी माँग क्यों पेश करे ? इसके अतिरिक्त भारतीय एकताकी भावना प्रबल होती जाती है और सब इसका अनुभव करने लगे हैं कि समवेत चेष्टासे ही भारत स्वतन्त्र किया जा सकता है और अर्जित स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेमें समर्थ हो सकता है । आजकी हालतमें तो यह बात और साफ हो गयी है । अब जमाना छोटे राष्ट्रोंका नहीं है ।

पाकिस्तानकी माँगका रहस्य

यह माँग कुछ मुसलमानोंकी ओरसे पेश की गयी है । मुसलिमलीगका यह दावा कि वह सब मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करती हैं झुठलाया गया है । आजाद मुसलिम कानफरेन्सकी सफलता इसका प्रमाण है । बंगालके मुसलमान तो पाकिस्तानकी योजनाको

पसन्द नहीं करते । मौलवी फजलुलहक साहब भी इस योजनापर मुग्ध नहीं हैं । वह अब भी भारतीय एकताकी बात करते हैं । सिकन्दर हयातखाँ भी इसके हामी नहीं हैं । दूसरे 'लीगर' जो इसका राग अलापते थे उनकी असली मशा थी कि यह काम ब्रिटिश सत्ताकी मददसे हो, पर अब जब लडाईकी शक्ल बदली और इसमें भी शक होने लगा कि वह सत्ता इस देशमें रह भी जावेगी तो धीरे-धीरे उन्होंने हिन्दुस्तानकी हिफाजतके लिए एक नेशनल गवर्नमेण्ट कायम करनेका नारा बुलन्द करना शुरू किया । ज्यादातर तो धमकीके लिए पाकिस्तानकी योजना बनायी गयी है । इसमें असलियत कम है, लेकिन अगर मुसलिम लीगका इसपर अनुरोध हो तो हमको इसका विरोध करना ही पड़ेगा । प्रत्येक समुदायकी सस्कृतिकी रक्षाके लिए कांग्रेस वचनबद्ध है और कांग्रेसने यह भी स्वीकार किया है कि अल्प समुदाय अपने अधिकारोकी रक्षाके लिए जो व्यवस्था चाहेंगे वह कर दी जावेगी । इससे अधिक और क्या किया जा सकता है ? मुसलमान प्रान्तोमें वेंटे हुए हैं । कजक, उजबेग, ताजिक आदिकी मिसाल यहाँ लागू नहीं होती ।

सरहदी सूबे और वलूचिस्तानको छोड़कर कोई ऐसा प्रान्त नहीं है जहाँ खालिस मुसलमान ही बसते हो । शायद यह सूबे अलग होना न चाहेंगे । और सूबोमें बसनेवाले मुसलमानोंकी तुलना रूसी साम्राज्यके यहूदी, पोल, लेट (Letts), स्थोनियन आदि लोगोसे की जा सकती है । कुछ सूबोमें तो इनकी आबादी हिन्दुओसे ज्यादा है । वहाँ तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इन सूबोका शुमार न होना चाहिये । शेष सूबोमें जहाँ यह अल्पसंख्यामें हैं वहाँ इनके अधिकारोकी रक्षाकी व्यवस्था की जायगी । रूसमें यहूदी, लेट, स्थोनियनके अधिकारोकी जिस प्रकार रक्षा की गयी है उस प्रकार इनकी भी होनी चाहिये । इन जातियोके अपने देश न थे, यह साम्राज्यमें फैले हुए थे, इसलिए इनको स्वभाग्यनिर्णयका अधिकार नहीं दिया गया ।

भारतीय कम्युनिस्टोंकी भूल

हमने ऊपर दिखलानेकी कोशिश की है कि रूसका उदाहरण यहाँ लागू नहीं होता । तिसपर भी हिन्दुस्तानकी कम्युनिस्ट-पार्टीने सन् १९३१ से ही समस्त राष्ट्रीय अल्प-समुदायोको आत्मनिर्णयका अधिकार दे रखा है । रूसमें अलग होनेका हक भी शामिल है । यह उनके उद्देश्यकी घोषणा (draft platform) में है । आँख मूंदकर नकल करनेका यही नतीजा है । यह बात होती इसलिए है कि सोवियट यूनियनकी नीतिको कोमिण्टर्न (Third International) बिना विचारे अपनाती है और भिन्न-भिन्न देशोकी कम्युनिस्ट पार्टियाँ उसके फैसलेपर चलनेको बाध्य हैं । प्रत्येक पार्टीको देश-कालका विचार कर अपनी नीतिको स्थिर करनेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिये । दूसरे देशके लिए जो नीति उपयुक्त है उसे यन्त्रवत् अपने यहाँ लागू करना पड़ता है । लेनिनकी शिक्षा थी कि कोमिण्टर्न समान नियमो तथा संघर्षकी एक-सी नीतियोके आधारपर नहीं निर्मित हो सकता । जबतक राष्ट्रीय विभिन्नता मौजूद है और यह भेद बहुत समयतक कायम रहेंगे—संसारमें मजदूर जमातके अधिनायकत्व होनेके बाद भी—तबतक

'टेक्टिस'का भेद रहेगा । हम राष्ट्रीय विभिन्नताओंको नहीं मिटा सकते । ऐसा सोचना मूर्खता होगी । हमको मौलिक सिद्धान्तोमे अवस्थानुसार हेर-फेर करना पड़ेगा । प्रत्येक देशका अपना अलग एक ढंग रहता है और अपने ढंगसे ही वह उस मौलिक कार्यक्रमको सम्पन्न करता है । यह विवेकता अपनी विशेष अर्थनीति, राजनीति, संस्कृति, धार्मिक विकास आदिके कारण हुआ करती है । इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । देशकान्तके भेदसे नीति बदलती रहती है, इसलिए बिना अपनी अवस्थापर पूरा विचार किये दूसरे देशकी नीतिको अपनाना भयावह होता है ।

सन् १९३१ मे पृथक् होनेका प्रश्न भी हमारे सामने न था । यह माँग अभी हालसे पेश होने लगी है । उस समय इस अनावश्यक घोषणाको करके एक नया प्रश्न व्यर्थके लिए खड़ा किया गया । इससे केवल गलत विचारोंको सहारा मिलता है और जब वही विचार स्थूल रूप धारण कर लेते हैं तब उनको दवानेकी कोशिश की जाती है । यह बहुत गलत तरीका है ।

अभी हालमें जब जिन्ना साहबने कांग्रेसके सामने यह माँग की थी कि कांग्रेस मुस्लिम लीगको तमाम मुसलमानोंका प्रतिनिधि मान ले उस वक्त कुछ कम्युनिस्ट मुसलमानोंने इस माँगको मान लेनेपर जोर दिया था और यह भी कहा था कि उस हालतमे कांग्रेसके मुसलमान मुस्लिम लीगमे ढाखिल हो जावेगे । यह भाई अपने भोलेपनमे समझते थे कि इससे हिन्दू-मुसलिम एकताके लिए रास्ता साफ हो जावेगा । शायद वहाँ जाकर हमारे ये भाई नीचेसे संयुक्त मोर्चेकी नीति (United front from below) चलाते । यह इस बातको भूल गये थे कि उस हालतमें कांग्रेस धीरे-धीरे हिन्दू संस्था बन जाती ।

पहली गलती तो इनकी यह है कि केवल धर्मके आधारपर यह राष्ट्र-निर्माण मानते हैं । स्टालिनने राष्ट्रकी सबसे बड़ी पहचान भाषाको बताया है । दूसरी गलती यह है कि रूसके इतिहासका ठीक-ठीक अध्ययन किये बिना और अपने देशकी स्थितिपर पूर्ण विचार किये बिना ही अपना कार्यक्रम बना डालते हैं । दूसरेका अनुकरण करनेमे सुविधा अवश्य है, परन्तु हमको यह न भूलना चाहिये कि समाजवादीका मार्ग मुगम नहीं है, उसकी साधना मुलभ लाभको साधना नहीं है, समाजवाद एक वैज्ञानिक वस्तु है इसलिए समाजवादीकी नीति और कार्यप्रणाली भी वैज्ञानिक होनी चाहिये ।

थोड़ी देरके लिए यदि यह मान भी ले कि मुसलमानोंको स्वभाग्यनिर्णयका अधिकार मिलना चाहिये तो किस तर्कके आधारपर सिक्खोंकी ऐसी ही माँगको हम अस्वीकृत कर सकेंगे ? सिक्खोंका भी एक अल्प समुदाय है । ऐसी अवस्थामे सिक्खोंको मध्य-पंजाबमें एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनानेका अधिकार देना होगा । पंजाबके पूर्वी हिस्सेमे जाट कौम बसती है, वह भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता चाहेगी, इसे हम कैसे रोक सकेंगे ? इस तरह हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिमका मुस्लिम राष्ट्र मुसलिमलीगकी इच्छाके अनुसार न बन सकेगा । राष्ट्रका विस्तार बहुत घटाना पड़ेगा, पर इससे लीगियोंको कैसे सन्तोष

होगा ? यह नहीं हो सकता कि किसी अल्प समुदायकी सब उचित-अनुचित माँगें मान ली जावे, विशेषकर जब कि अन्य अल्प समुदायोको उनकी पूर्तिसे हानि हो ।

प्रगतिका मार्ग

भारतमें जितने अल्प समुदाय हैं उनके अधिकारोंकी पूरी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है । उनके साथ न्यायका ही नहीं वरंच उदारताका व्यवहार होना चाहिये । उनको सांस्कृतिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । जितनी पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनकी उन्नतिके लिए विशेष ध्यान देना चाहिये । धार्मिक वैमनस्यका एक यह भी कारण है कि शिक्षाकी दृष्टिसे मुसलमान हिन्दुओंसे पिछड़े हुए हैं । बहुत कालतक वह अंग्रेजी शिक्षाका विरोध करते रहे और इसीलिए राजनीतिक चेतना उनमें अपेक्षाकृत कम है । कांग्रेस राजनीतिक दौड़में काफी आगे बढ़ गयी है । उसमें लोकमत प्रबल है, इसीलिए नेतृत्व भी बदला, किन्तु मुसलिम लीगका नेतृत्व अभी पुराने ढंगका ही चला आता है । वह जनताके आर्थिक प्रश्नोंको लेकर आन्दोलन नहीं करता । वह धार्मिक प्रश्नोंमें प्रायः मुसलमानोंको उलझाये रहता है । कांग्रेसका विरोध करना ही उसका मुख्य लक्ष्य है । न उसके कोई ऊँचे आदर्श हैं, न गरीब मुसलिम जनताकी ही उसे फिक्र है । मुस्लिम स्थिर स्वार्थोंकी रक्षा करना उसका उद्देश्य है । कांग्रेस और लीगका यह अन्तर है । इसी असमानताके कारण कोई तसफिया नहीं हो पाता । यह असमानता मुसलमानोंमें शिक्षाके प्रसारसे ही दूर हो सकती है, धीरे-धीरे दूर भी हो रही है । इसमें हम सबको सहायक होना चाहिये, किन्तु किसी मौलिक प्रश्नका निर्णय अल्प समुदायोके हाथ छोड़ा नहीं जा सकता ।^१

रामगढ़ कांग्रेसकी नीतिमें परिवर्तन आत्मघातक है^२

मैं कम्युनिस्टोंके इस कथनसे सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेसके कुछ उच्च नेता ब्रिटिश साम्राज्यशाहीके हाथ देशको बेच देना चाहते हैं । मैं समझता हूँ कि वे भी उतने ही ईमानदार हैं जितने कि दूसरे लोग और नीतिका वे प्रतिपादन इसलिए करते हैं कि उसे वे ईमानदारीके साथ स्वाधीनता-आन्दोलनके लिए सही समझते हैं, न कि इसलिए कि पूँजीपतियोंके प्रतिनिधि होनेके नाते वे पूँजीपतियोंका हित उस नीतिमें देखते हैं, जैसा कि कम्युनिस्टोंका ख्याल है । -

रामगढ़की नीतिमें परिवर्तन

यूरोपीय युद्धके आरम्भसे लेकर अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकके समयतककी कांग्रेसकी काररवाईका विस्तारपूर्वक उल्लेख करते हुए आचार्यजीने सिद्ध किया कि रामगढ़-

१. 'संघर्ष' १७ जून १९४० ई०

२. अ० भा० कांग्रेस कमेटीमें भाषण

में कांग्रेसने जो नीति अपनायी थी कार्यसमितिके प्रस्तावसे उसका अन्त किया जा रहा है। यूरोपीय युद्धके आरम्भ होनेपर १४ सितम्बरको वर्धामे कांग्रेस कार्यसमितिकी जो बैठक हुई उसमे ब्रिटिश सरकारसे पूछा गया था कि वह स्पष्ट करे कि उसके युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्य क्या है। आगे चलकर जब अक्टूबर मासमे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक बुलायी गयी तो उसने निश्चय किया था उसमे ब्रिटिश सरकारसे उसके युद्ध सम्बन्धी उद्देश्योंके अतिरिक्त सुलह-सम्बन्धी उद्देश्य भी पूछे गये थे और कांग्रेसजनोंको प्रत्येक प्रकारकी परिस्थितिका सामना करनेके लिए तैयार रहनेको कहा गया था, जिसका स्पष्ट अर्थ यही था कि अगर ब्रिटिश सरकार अपने वक्तव्यों और कार्योंसे स्पष्ट रूपसे यह नहीं सिद्ध कर देती कि यह युद्ध साम्राज्यवादी उद्देश्योंके लिए नहीं लड़ा जा रहा है तो कांग्रेस आजादीकी लड़ाई छेड़नेके लिए मजबूर होगी। इसके बाद 'स्वाधीनता दिवस' जिस ढंगसे मनाया गया, उससे कांग्रेसजनोंको यह बतलाया गया कि स्वतन्त्रता संग्रामके छेड़नेकी तैयारी की जा रही है। कांग्रेसके रामगढ़-अधिवेशनमे साफ तौरपर इस बातका एलान कर दिया गया है कि वर्तमान यूरोपीय युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है, उसमें भाग लेना अपनी गुलामीकी जंजीरोको ही कसना होगा और फिर कांग्रेस-कमेटियोंको लड़ाईकी तैयारी करनेके लिए सत्याग्रह कमेटियोंमे परिवर्तित हो जानेका आदेश दिया गया। रामगढ़ कांग्रेसमे महात्मा गांधीके सेनापतित्व स्वीकार कर लेनेसे भी कांग्रेस-जनोका यही विश्वास दृढ़ हुआ कि कांग्रेस युद्धमे भाग नहीं लेने जा रही है, क्योंकि महात्मा गांधी किसी हालतमे अधिकसे अधिक ब्रिटिश सरकारको देशकी नैतिक सहायता ही देनेको तैयार थे, इससे अधिक नहीं, अतः प्रस्तावके कुछ समर्थकोंका यह कहना कि कार्य-समितिका निश्चय रामगढ़के निश्चयके प्रतिकूल नहीं है, वास्तविकताके अनुकूलन ही है।

स्थितिमें परिवर्तन नहीं

यह समझना भ्रम है कि आज परिस्थितिमे कोई ऐसा परिवर्तन हो गया है कि जिसकी कल्पना रामगढ़में नहीं की जा सकती थी। अथवा जिसके कारण रामगढ़मे निर्धारित की हुई नीतको हमे बदलना पड़े। युद्धमे चाहे जो भी शक्ति जीते उपनिवेशोंकी भलाई इसीमे है कि वे अपनी स्वाधीनताकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करे। अगर आजकी हालतमे इंग्लैण्ड जीत भी जाय तो यह समझना भूल होगी कि यह लोकतन्त्रकी विजय होगी। पूँजीवाद और प्रजातन्त्रका प्रचलित रूप लड़ाईके बाद भी बना नहीं रह सकता। अगर इंग्लैण्डके पूँजीवादी शासक युद्धमें जीत जायँ तो वे भी अपने देशमे एक नियन्त्रित पूँजी-वादी व्यवस्था चलानेका प्रयत्न करेंगे, भले ही वह उसे फैसिज्मका नाम न दे। जो हालत आज फ्रासकी है उससे बहुत कुछ मिलती-जुलती हालत उस अवस्थामे इंग्लैण्डमे भी हो जानेका डर है। अतः मनुष्यताकी रक्षाके लिए इस युद्धमे हमारे सम्मिलित होनेका प्रश्न आजकी हालतमे नहीं उठता। हमारे सामने ब्रिटिश सरकारने भी कोई नया प्रस्ताव नहीं किया जिसके जवाबमें हमें अपनी ओरसे कुछ कहना हो।

रामगढ़के प्रस्तावमे हिन्दुस्तानकी आजादीका प्रश्न एक विस्तृत दायरेके अन्दर

देखा गया है। रामगढके प्रस्तावमे हिन्दुस्तानकी आजादीके अलावा एशिया और अफ्रीकाके दूसरे अनेक उपनिवेशोकी आजादीकी भी माँग की गयी है, किन्तु दिल्लीके निश्चयमे इस पहलूकी कोई चर्चा नहीं की गयी है। हमे अपने राष्ट्रीय आन्दोलनके अन्तर्राष्ट्रीय पहलूको भूल नहीं जाना चाहिये।

कांग्रेसके तथाकथित राष्ट्रीय सरकार बनानेके खतरेकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेसके युद्ध-विरोधी परम्पराके साथ ही उसकी राष्ट्रीयताकी परम्पराके नष्ट हो जानेका डर है और यह कार्य वैसी ही नासमझीका कहा जायगा जैसा यह कि पुनर्जन्म प्राप्त करनेकी आशामे आत्म-हत्या कर ली जाय।^१

सत्याग्रहपर पावन्दियाँ

११ अक्टूबरको वर्धा वकिंग-कमेटीकी बैठक शुरू होगी। मालूम नहीं महात्माजी सत्याग्रहकी कौन योजना उसके विचारार्थ रखते हैं, किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि महात्माजी किसी न किसी रूपमे व्यक्तिगत सत्याग्रहसे ही आन्दोलनका आरम्भ करेंगे। महात्माजी एक अरसेसे कहते आते हैं कि वह सामूहिक सत्याग्रहके लिए देशमे उपयुक्त वातावरण नहीं पाते। रामगढकी वक्तृतामे अवश्य सामूहिक सत्याग्रहकी बात उन्होंने की थी, किन्तु मईके महीनेसे वह बराबर सामूहिक सत्याग्रहके न छेड़नेकी बात ही कहते आये हैं। पहले सत्याग्रहका आधार देशकी आजादीका सवाल था, किन्तु अब वह आधार भी बहुत सकुचित कर दिया गया है। बम्बईके प्रस्तावमे और महात्माजीके भाषणमे यह बात साफ कर दी गयी है। कांग्रेस अपनी नीतिका अहिंसात्मक तरीकेसे अनुसरण करनेकी स्वतन्त्रता चाहती है। कांग्रेस साम्राज्यवादी युद्धका विरोध करनेकी नीतिको अरसेसे अपनाये हुए है। महात्माजी अहिंसाके सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक युद्धके विरोधी हैं। कांग्रेसकी इस नीतिके अनुसार काम करते हुए कितने ही कार्यकर्ता जेलखानोमे बन्द कर दिये गये। कांग्रेस इसी प्रश्नको लेकर सत्याग्रह करने जा रही है। स्वभावतः यह सवाल उठता है कि रामगढ-कांग्रेसके वाद क्या ऐसी बातें हुईं जिनके कारण सामूहिक सत्याग्रह अनुपयुक्त समझा गया और आजादीका सवाल छोड़ दिया गया? मैं समझता हूँ कि हिंसाके भयसे महात्माजी सामूहिक सत्याग्रहकी आज्ञा देनेसे धवड़ाते हैं और मुसलिम लीगके विरोधके कारण आजादीके सवालको इस समय उठाना नहीं चाहते। शायद उनका ख्याल है कि राज-शक्तिके सवालको लेकर सत्याग्रह आरम्भ करनेसे मुसलिम लीगके नेताओंको यह ख्याल हो सकता है कि इस तरह कांग्रेस गवर्नमेण्टको उससे समझौता करनेके लिए मजबूर करना चाहती है। उनके ख्यालसे इसका नतीजा यह होगा कि मुसलिम लीग आन्दोलनमे रुकावट डालेगी। अपना रास्ता साफ करनेके लिए शायद

गांधीजीने सत्याग्रहका यह नया आधार बनाया है। फ्रांसके पतनसे भी किसी प्रकारका आन्दोलन शुरू करनेकी उनकी हिचकिचाहट बढ गयी है और वह इसीलिए सत्याग्रह शुरू करनेको तैयार हो गये हैं क्योंकि उनके ख्यालसे गवर्नमेण्ट कांग्रेसके कुचलनेके लिए तुली हुई है। उनके गव्दोमे यह सत्याग्रह आत्मरक्षाके लिए है।

कांग्रेसका संगठन इस प्रकारका नहीं है कि वह राज्य-शक्ति लेनेमें समर्थ हो सके। फिर सत्याग्रह आन्दोलनका साधारणतः समझातेमे ही अन्त हो सकता है? इसके द्वारा राज-सत्तापर दबाव काफी पड़ता है पर यह वर्तमान संगठनकी सहायतासे विदेशी सत्ताको नष्ट नहीं कर सकता। अहिंसाको सिद्धान्तरूपेण ग्रहण करनेसे उसकी वारीकियोंमे जाना अनिवार्य हो जाता है जिनपर लम्बे-लम्बे शास्त्रार्थ चलते हैं और जैसा कि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायोंके पण्डित आपसमे किया करते हैं। इनसे वास्तविकतासे कम सम्बन्ध रहता है, अक्सर बालकी खाल निकाली जाती है जिसका समझना साधारण लोगोंके लिए असम्भव हो जाता है। इस शास्त्रार्थमे पड़नेके कारण हमारे कई महीने खराब गये और जिस तरहसे हम अपने निर्णय रोज बदलते रहे उससे हमारी प्रतिष्ठामे कुछ कमी ही हुई है।

बम्बईके प्रस्तावमें कहा गया है कि नागरिक-स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए जिस मात्रा और रूपमे सत्याग्रहकी आवश्यकता होगी उतनीही मात्रा और परिमाणमे उसका व्यवहार किया जायगा। यह तो हमने वर्तमान नेतृत्वसे कभी आशा नहीं की थी कि वह राज्य-शक्ति लेनेके लिए सब उपयुक्त उपायोंका अवलम्बन लेगे, पर हम यह अवश्य मानते थे कि पूर्ण स्वतन्त्रताके सवालको लेकर आन्दोलनका आरम्भ किया जायगा और इसी विश्वासमे हम समाजवादी आरम्भसे ही वर्किंग कमेटीका साथ देते आये हैं। हमारा यह ख्याल ठीक निकला कि सत्याग्रह अनिवार्य है और दल कहते रहे कि नेता लड़ेंगे नहीं, किन्तु हम कहते रहे कि परिस्थिति ऐसी है कि यदि वह लड़ना न भी चाहें तो उनको लड़नेपर मजबूर होना पड़ेगा। हमारा यह कथन ठीक निकला, किन्तु हमको यह पता नहीं था कि आन्दोलन का आधार इतना संकुचित कर दिया जायगा। मुसलिम लीगसे इतना डरनेकी क्या जरूरत है। उससे कई बार चुलहकी कोशिशें की गयी, पर सब मेहनत बेकार गयी। अब तो हमको यह समझकर काम करना है कि सम्प्रदायवादियोंके विरोधका भी हमें मुकाबला करना है। अगर हम इसके लिए तैयार न हो तो उसके माने होंगे कि हमने सदा के लिए अपने लक्ष्यके लिए लड़ना छोड़ दिया। बाहरी और भीतरी रूकावटोंका समान रूपसे मुकाबला करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं समझता कि सवाल क्यों बदल दिया गया। इससे हमने अपनी लड़ाईको बहुत कमजोर कर दिया। उसमे शुरूसे ही बाँध-बाँध दिये और पाबन्दियाँ लगा दी, जिससे वह जन-क्रान्तिमे विकसित न हो सके। इस प्रश्नसे साधारण लोगोंको कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है और उनमे यह योग्यता भी नहीं है कि वह भाषण देकर या लेख लिखकर इस अधिकारको उपयोगमें लानेकी चेष्टा करे। तो क्या हम समझे कि देशकी अनपढ़ जनता इस आन्दोलनसे अलग रखी जायगी? यदि ऐसा हुआ तो हमारा आन्दोलन प्रभावशाली कैसे हो सकेगा?

यदि स्वराज्यके लिए सत्याग्रह शुरू होता तो आशा की जा सकती थी कि धीरे-धीरे वह देशव्यापी होगा और किसान, मजदूर, छोटे पेशेके लोग भी बड़ी तादादमें उसमें शरीक होंगे। उस अवस्थामें देशमें शक्ति रहते असहयोग और सत्याग्रहका पूरा कार्य-क्रम, जिसकी घोषणा सन् १९२१ में हुई थी, काममें लाया जा सकता था। उसमें विकासकी काफी गुंजाइश होती। जन-आन्दोलनकी हृदयरारी भी हमारे नेता न कर सकते, केवल अपने नियन्त्रणमें रखकर गलत रास्ते पर जानेसे उसे बचाते, लेकिन आधार को इतना सुकुचित कर देनेसे विकास के सब मार्गोंके वन्द हो जानेकी आशंका है। मेरी पहली आपत्ति यह है। दूसरी शका यह उठती है कि युद्ध समाप्त होनेपर क्या होगा? जो सवाल सत्याग्रहका आधार बनाया जा रहा है उससे तो यही मालूम होता है कि सत्याग्रह भी वन्द हो जायगा, क्योंकि जब युद्ध ही न होगा तो उसके विरोधका प्रश्न कहाँ उठता है।

मैंने इन शंकाओंको इसलिए उठाया है कि लोग इस सत्याग्रहमें भाग ले और स्वराज्यके लक्ष्यको भी सामने रखे जिसमें विकासका अवसर मिले। प० जवाहरलालजीका कहना है कि आजादीका सवाल बालायताक नहीं रखा गया है, किन्तु महात्माजी और सरदार साहब तो ऐसा नहीं कहते। खैर। यदि पं० जवाहरलालको ऐसा कुछ कहनेका अधिकार है तो सर्वसाधारणको भी है। मैं चाहता हूँ कि वम्बईके प्रस्तावका ऐसा ही अर्थ करे और धीरे-धीरे आन्दोलनको एक विराट् जन-आन्दोलनका रूप दे, यदि ऐसा हुआ तो हम क्रान्तिके पथपर बहुत आगे बढ़ेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। युद्धके बाद भी क्रान्तिकी अवस्था जारी रहेगी। दुख तो इस बातका है कि इसमें आत्मविश्वासकी कमी है और हम ऐसा बन्दोबस्त चाहते हैं जिसमें किसी प्रकारकी जोखिम न उठाना पड़े, इसीलिए यह हिचकिचाहट है और आन्दोलन शुरू करनेमें इतनी देर हो रही है, पर क्रान्तिकारियोंको इस तरह न धवराना चाहिये।

यदि जन-आन्दोलनके जीवन-मरणका प्रश्न न होता तो मैं इस प्रकारके सत्याग्रहका समर्थन न करता। कांग्रेसकी खामोशीसे जन-आन्दोलनको कड़ा धक्का पहुँचेगा, पर जननायकोंकी मनोवृत्तिका अध्ययन करने और कांग्रेस-संगठनकी दुर्बलताओंका पता चलनेका यह अच्छा मौका है। इससे आगेके लिए हम सबक सीख सकते हैं। यह बात हमें न भूलनी चाहिये कि बिना जोखिम उठाये कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि आनेवाले जमानेमें हमको किसानों और मजदूरोंके संगठन पर और अधिक जोर देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इसपर काफी जोर दे रही है, पर अब इस ओर और ज्यादा ध्यान देनेकी आवश्यकता है। यदि सत्याग्रहको शक्तिशाली बनाना है तो किसानों और मजदूरोंको साम्राज्य-विरोधी संघर्षमें खींचना पड़ेगा। इसके लिए किसान सभा और मजदूर-सभाका काम बड़े पैमानेपर करना पड़ेगा अन्यथा इन वर्गोंमें निश्चेष्टता आ जावेगी और वह हमारे आन्दोलनसे बहुत कुछ पृथक् रहेंगे। समाजवादियोंके मतमें यह पूँजीवादी प्रजा-सत्तात्मक क्रान्ति (bourgeois democratic revolution) की मंजिल है।

इसका एक स्तम्भ विदेशी सत्ताका विरोधी है और दूसरा किसानोंकी क्रान्ति है । जब पहला स्तम्भ कुछ दुर्बल पड़े तब दूसरेको मजबूत करनेकी कोशिश होनी चाहिये ।

मेरी समाजवादियोंसे अपील है कि कांग्रेस-आन्दोलनमें पूरा-पूरा भाग लेते हुए वह किसान और मजदूरोंके संगठनके कामको भी काफी दिलचस्पीके साथ करें ।^१

व्यक्तिगत सत्याग्रह और आजादीकी लड़ाई

महात्मा गांधीके वक्तव्यपर एक दृष्टि

महात्माजीके हालके वक्तव्यसे बड़ी निराशा हुई । इसलिए नहीं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह फिलहाल एक ही व्यक्तित्व तक सीमित रहेगा, किन्तु इसलिए कि उसमें कुछ ऐसे सिद्धान्तोंका निरूपण किया गया है जो मेरी अल्पबुद्धिमें हमारे आन्दोलनके लिए घातक है । वक्तव्यसे मालूम होता है कि सत्याग्रहका उद्देश्य केवल भाषणकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करना है । बम्बईके प्रस्तावमें तथा बम्बईमें दिये हुए महात्माजीके भाषणोंमें जो बातें शायद साफ नहीं की गयी थी, वह इस वक्तव्यसे साफ हो जाती हैं । यह तो शायद स्पष्ट ही था कि आजादीका सवाल इस समय छोड़ दिया गया है, पर यह स्पष्ट नहीं था कि सत्याग्रहका उद्देश्य लड़ाईके लिए हिन्दुस्तानके जन-धनके उपयोगको रोकना नहीं है, बल्कि महज अपने अधिकारको जताना है । महात्माजीका वक्तव्य इस बातको स्पष्ट कर देता है । कुछ व्यक्तियोंके सत्याग्रहसे कुछ अंशमें यह काम सिद्ध होता है तो बात दूसरी है, पर सत्याग्रहका उद्देश्य यह नहीं रखा गया है । हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है कि जबतक कार्यकर्ताओंकी एक बहुत बड़ी फौज इस कामको एक साथ न करे तबतक काममें सफलताकी आशा नहीं करनी चाहिये । इसलिए पहले तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ही, वह भी जब बहुत थोड़ेसे चुने हुए लोगोंमें ही सीमित रखा जाय, इस काममें बड़ी भारी रुकावट है, फिर जब यह कहा जाता है कि प्रतिपक्षीको जहाँतक हो सके कम परेशान करो, उसके काममें कम-से-कम बाधा डालो तो यह उद्योग बेकार-सा हो जाता है । उद्देश्य केवल अपने अधिकारकी रक्षा करनेका है, कुछ हासिल करनेका नहीं । कांग्रेसके युद्ध-विरोधी प्रस्तावको भी हम इस तरह कार्यान्वित नहीं करते, राष्ट्रीय माँगको हासिल करनेकी बात तो दूर रही ।

हम इसके लिए तैयार नहीं थे । यू० पी० की प्रान्तीय कांग्रेस कौंसिलने अपनी पिछली बैठकमें जो प्रस्ताव पास किया था उसका क्षेत्र तो अति विस्तृत था । उसमें आजादीका सवाल भी रखा गया था और युद्धके लिए हिन्दुस्तानके जन-धनके इस्तेमाल को रोकनेकी बात भी कही गयी थी । याद रखिये कि यह प्रस्ताव हमने बम्बईके इजलासके बाद पास किया था, पर महात्माजीके वक्तव्यने इस प्रस्तावको निरर्थक-सा बना दिया है अजीब हालत है कि कांग्रेसके निश्चयोंके असली अर्थका पता बहुत देरमें चलता है !

परेशानी कैसी

महात्माजीने अपने वक्तव्यमें कहा है कि मैं स्वयं सत्याग्रह नहीं करना चाहता । इस निश्चयका कारण बताते हुए महात्माजी कहते हैं कि इसका कारण यह भी है कि कांग्रेस गवर्नमेंण्टको परेशान नहीं करना चाहती । यह थ्योरी सत्य और अहिंसा-सम्मत बतायी जाती है । हमारी अल्पबुद्धिमें यह नहीं आया कि इसका सत्य और अहिंसासे क्या सम्बन्ध है, जब हम सत्याग्रह किसीको परेशान करनेकी गरजसे नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने उद्देश्यको हासिल करनेके लिए ही करना चाहते हैं । महज छेड़छाड़के लिए कोई आन्दोलन करना नामुनासिव होगा यह हम मानते हैं, उससे हमारा ही नुकसान है । यह तो वही मसल हुई कि दूसरेकी नाक काटनेके लिए हम अपनी नाक कटवानेके लिए तैयार हैं । जब युद्ध आरम्भ होनेपर वर्किंग-कमेटीने अपना लम्बा वक्तव्य निकाला था और बादमें रामगढ़-कांग्रेसने अपना प्रस्ताव पास किया था, जिसमें बताया गया था कि यह युद्ध साम्राज्यवादी है और अगला कदम सत्याग्रहका होगा, उस समय हमको प्रतिपक्षीको परेशान करनेका ख्याल न था । जब कभी हम स्वराज्यकी लड़ाई छेड़ेंगे, साम्राज्यशाहीको परेशानी होगी ही, लेकिन क्या हम जन्मसिद्ध अधिकारको छोड़ देंगे ? क्या हम यह समझे कि जबतक युद्धमें प्रतिपक्षीके हारनेके लक्षण नहीं दिखायी पड़े तबतक तो सत्याग्रह करना सत्य और अहिंसाके प्रतिकूल नहीं है, लेकिन जब हमारा प्रतिपक्षी शत्रुसे वित्ताडित होने लगे और उसके पराजयकी आशका हो जावे तब गुलामोंको लड़ाई रोक देनी चाहिये । जब हमारा प्रतिपक्षी लड़ाईमें सँभल जाय, यह तर्क हमारी बुद्धिमें नहीं आता । हिन्दुस्तानकी आजादी ही अंग्रेजोंके लिए काफी परेशानीकी बात है, वह ऐसा ही समझते हैं, लेकिन हम तो हिन्दुस्तानको आजाद करके अंग्रेज कौमपर एहसान करेंगे । मैं यह बात मजाकमें नहीं कहता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो कौम दूसरोको गुलाम बनाती है वह अन्तमें खुद गुलाम हो जाती है, इसलिए स्वराज्यकी लड़ाई ऐसे मौकेपर छेड़ना परेशान करना नहीं है । हमारी लड़ाई तो शान्तिमय है । हम उनके देशपर तो आक्रमण कर नहीं रहे हैं, केवल अपने देशको आजाद करना चाहते हैं, इसमें किसीको परेशान करनेका सवाल कहाँ उठता है । खेल और कुश्तीके कायदे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आजादीके जगमें इन कायदोंकी गुजाइश नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्षी किसी कायदेको माननेको तैयार नहीं है । हमारी लड़ाई अहिंसाकी है, लेकिन हमारा प्रतिपक्षी हिंसाका आश्रय लेता है ! जिस समय वह सकटसे घिरा हुआ है उस समय भी वह हमारे साथ इन्साफ करनेको तैयार नहीं है अल्प समुदायोंका बहाना कर टालमटोलकी बातें करता है । हिन्दुस्तानकी इकाई तोड़ने और प्रजातन्त्रकी भावनाको दवानेकी चाल चलता है । हमारा सकल्प पहले ही हो चुका है । उसके होनेसे केवल भारतका ही नहीं बल्कि अंग्रेज जातिका भी कल्याण है । यह सकल्प दूसरोको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, केवल अपनी चीज वापस चाहता है इसमें अर्थ कहाँ है ? मैं तो इसे धर्म-युद्ध ही समझता हूँ ।

मैं जीवनमें नैतिक आचरणको बड़ा महत्त्व देता हूँ । मैं संकीर्ण राष्ट्रीयताका कट्टर

विरोधी और अन्तरराष्ट्रीयताका पुजारी हूँ । किसी जातिके प्रति मेरा विद्वेष नहीं है । इङ्ग्लैण्डके शासकवर्गका मैं अलवत्ता विरोधी हूँ, किन्तु अंग्रेजोंके प्रति मुझे राग नहीं है । सब राष्ट्रोंकी जनताका मैं आदर करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रत्येक राष्ट्रकी प्रजा शान्तिप्रिय हुआ करती है, वह विदेशकी अग्नि प्रज्वलित नहीं करना चाहती । युद्धोंकी जिम्मेदारी उसपर नहीं है, किन्तु पूँजीपतियों और फौजी अफसरोंपर है ।

हमारा कर्तव्य

इन सब विचारोंके रखते हुए यदि इस समय हम आजादीके लिए सत्याग्रह करें तो हम किसी पहलूसे भी अनीति नहीं करेंगे । एक वर्षकी नोटिस सचेत करनेके लिए क्या काफी नहीं है और यदि इसपर भी कोई नहीं सँभलता तो हम क्या करें ? मुझे भय है कि यदि हम इस प्रकारका अटल सिद्धान्त बना लेंगे कि सड़कमें फँसे रहनेपर शत्रुको परेशान न किया जाय तो कभी भी आजाद न होंगे । साम्राज्यवादका मुकाबला करना आसान काम नहीं है, तिसपर यदि हम ऐसे सिद्धान्तपर अमल करने चलेगें तो लक्ष्यतक पहुँचना असम्भव हो जायगा । उस हालतमें हमको स्वराज्यकी आशा न रखनी चाहिये । मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि महज प्रतिपक्षीको परेशान करनेकी गरजसे आन्दोलन करना बचपना होगा, लेकिन अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए आये सुनहरे अवसरोंको खोना भी गलती होगी । किसी ठोस कारणसे आन्दोलनको शुरू न करना ठीक हो सकता है किन्तु केवल इस आधारपर अपने निश्चयको स्थगित कर देना ठीक नहीं ।

श्रद्धा जरूरी चीज है, लेकिन उसे तर्कके आश्रित होना चाहिये । सिपाहीको भी पूछनेका हक है । भाड़ेके सिपाहियोंकी बात दूसरी है, हालाँकि इस नये जमानेमें वह भी कभी-कभी पूछ बैठते हैं । लेकिन अपनी इच्छासे सिपाहीका वाना लेनेवाले लोगोंकी शंका तो दूर करनी ही होगी । इस नये युगमें 'सैनिकको कारण पूछनेका अधिकार नहीं' (There's not to reason why) वाली बात गलत होती जाती है । इसमें शक नहीं जबतक कोई किसी संस्थामें है उसको अनुशासनकी रक्षा करनी होगी और सेनापतिके आदेशोंका पालन करना होगा, लेकिन अपने दिलकी बात कहनेका हक तो उसे मिलना चाहिये ।

कार्यकर्ताओंसे अपील

इस लेखके लिखनेका एक कारण और है । मुझे कांग्रेसके सदस्योंमें निश्चेष्टता आ जानेका भय है । कहीं ऐसा न हो कि जबतक अपना नम्बर न आये तबतक लोग हाथपर हाथ धरे बैठे रहे । मैं देखता हूँ कि ऐसा हो रहा है । जबसे मन्त्रि-पदका त्याग हुआ है तबसे किसानोंकी शिकायतें दूर करनेकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । युद्धके कारण कारखानोंके मजदूरोंकी आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गयी हैं, इस ओर भी ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है । मैं चाहता हूँ कि कांग्रेसजन चिरपरिचित रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करते हुए इन जरूरी कामोंको भी करते रहे । मेरी अपील समाजवादियोंसे विशेष रूपसे

है, क्योंकि वह इस कामके महत्त्वको अच्छी तरह समझते हैं और थोड़ा बहुत उसे करते भी रहते हैं। इस ओर उन्हें लगनसे लग जाना चाहिये। जनताको आर्थिक कार्यक्रमके आधारपर संगठित करना और उसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना परम आवश्यक है। इस समय किसीका भी निश्चेष्ट रहना आत्महत्याके समान है। निश्चेष्टता मृत्यु है। जो अपनेको क्रान्तिकारी कहता है वह इस आसरे चुप बैठा नहीं रह सकता कि मेरा तो अभी नम्बर ही नहीं आया और यह सोच नहीं सकता कि सत्याग्रहके सिवाय कोई दूसरा कार्य ही इस समय क्या है। ऐसी दूषित मनोवृत्ति बहुधा देखनेमें आती है। हम सबको इससे बचना चाहिये।^१

भारतकी स्वाधीनताका प्रश्न

इस लेखमालाकी प्रस्तावनामें हमने यह दिखलानेकी कोशिश की थी कि सच्चे जनतन्त्रकी स्थापनाके लिए क्रान्ति आवश्यक है, क्योंकि इसी प्रकार जनसमूहकी दीक्षा होती है और क्रान्ति तभी सम्भव है जब साम्राज्यशाहीके लिए सकटकी अवस्था उत्पन्न हो और जनता उस अवसरमें लाभ उठानेके लिए तैयार हो। हमने संक्षेपमें यह दिखलानेकी चेष्टा की थी कि पूंजीवादी पद्धतिका ह्रास होता जाता है और उसपर संकट बार-बार आयेगे और इस तरह क्रान्तिके लिए अवसर भी मिलते रहेंगे। सच तो यह है कि पूंजीवादी पद्धतिका असंगतिके कारण ही युद्ध अनिवार्य हो गये हैं। पूंजीवादियोंके लिए सर्वप्रधान चीज मुनाफा है। जो लोग अस्त्र-शस्त्रका व्यापार करते हैं वह युद्धजीवी होते हैं। इनका गुट अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिको कायम नहीं रहने देता। दो राष्ट्रोंमें युद्ध भी चलता रहता है और वह एक दूसरेके हाथ अस्त्र-शस्त्र भी बेचते रहते हैं। पिछले यूरोपीय युद्धमें यही हुआ। १९१४ से १७ तक जर्मनीको हालैंड, स्विटजरलैंड, नार्वे और स्वीडनके जरिये युद्ध-सामग्री बराबर मिलती रही और इसी प्रकार जर्मनी भी, फ्रांसको फौलाद भेजता रहा। इतिहास-लेखकोंका कहना है कि यदि जर्मनीका अवरोध आरम्भमें ही कड़ाईसे किया गया होता तो युद्ध चार वर्ष न चलता और एक वर्षमें ही कैसरको सुलहके लिए मजबूर होना पड़ता। लेकिन अस्त्र-शस्त्रके व्यापारी युद्धको इतनी जल्दी समाप्त होने देना नहीं चाहते थे। इस तरह तो उनका व्यापार ही मारा जाता। नैनविल जिला, जहाँ जर्मनीके लोहेके कारखाने थे, अरक्षित था और फ्रांसीसी सेना इतनी नजदीक थी कि यदि वह चाहती तो उसपर कब्जा कर लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करनेसे जर्मनीकी फौलादकी पैदावार बहुत कम हो जाती और इसका नतीजा यह होता कि लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलती। अनातोले फ्रांसको जब यह मालूम हुआ तब उसने कहा कि हम तो विश्वास करते थे कि यह पितृभूमिके लिए प्राणविसर्जन करेंगे,

किन्तु यह व्यवसाय और व्यापारके लिए प्राण देते हैं। पिछले युद्धके समयकी इस प्रकारकी घटनाओंका उल्लेख किया जा सकता है, जिससे स्पष्ट हो जायगा कि पूंजीवादियोंके बड़े-बड़े गुट अपने मुनाफेके लिए शान्ति कायम नहीं होने देते। अनातोले फ्रासका यह कहना बहुत ठीक है कि इनका आराध्य देव, पितृभूमि नहीं, किन्तु इनका मुनाफा है।

पूँजीवादी पद्धति सार्वभौमिक है। इस कारण भौगोलिक हद्दे टूट रही हैं और अन्तर्राष्ट्रीयता बढ़ रही है। पूँजीवादी वर्ग अपने भौगोलिक राज्यकी इतनी परवाह नहीं करता जितना अपने वर्गके स्वार्थोंकी। जिस प्रकार समाजवादियोंका कहना है कि मजदूरोंकी कोई पितृभूमि नहीं है 'दुनियाके मजदूर एक हो जायें' उसी प्रकार पूँजीवादी गुटका भी यही नारा है कि हमारी पितृभूमि कोई नहीं है, दुनियाके पूँजीवादियो ! आओ हम सब मिलकर जनताकी क्रान्तिको दवाने और अपने वर्गको सुरक्षित करनेके लिए एक हो जायें। जहाँ समाजवादी सत्ताकी पीड़ित और शोषित जनताका संयुक्त मोर्चा बनाते हैं वहाँ मुट्ठीभर सत्ताके पूँजीपति भी अपने स्वार्थोंकी रक्षाके लिए जनताके विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। अपने स्वार्थोंकी रक्षाके लिए यदि युद्धकी आवश्यकता हो तो उनके लिए भी तैयार हैं और अपने देशकी भोली-भाली जनताको तलवारके घाट उतारनेमें जरा भी दरेग नहीं करते।

वर्गके भीतर भी संघर्ष चलता रहता है, किन्तु जब जनतासे किसी भी साम्राज्यवादी राष्ट्रको खतरा पैदा होता है तो जनताको कुचलनेके लिए साम्राज्यशाहियाँ एक हो जाती हैं और जन-क्रान्तिसे अपनी रक्षा करनेके लिए आपसकी लड़ाई भी बन्द कर देती हैं। पिछले यूरोपीय युद्धमे यही हुआ। शुरूमे लड़ाई जारी रखनेकी कोशिश की गयी, किन्तु जब लम्बाई-चौड़ाईके कारण जनताकी आँखें खुली, वह युद्धकी भीषणता और वास्तविकताको समझनेमें लगी और फौजमे भी अशान्ति फैलने लगी, तब पूँजीवादियोंके गुटने शान्तिकी प्रयत्न करना शुरू कर दिया। जर्मन और फ्रांसीसी सिपाही लड़ाईसे ऊब कर आपसमें भाईचारा बढ़ाने लगे। जगह-जगह फौजमे विद्रोह होने लगे। सिपाही लड़ाईका मैदान छोड़कर भागने लगे। रूसकी जो फौज फ्रांस लायी गयी थी उसने ब्रेस्ट लिटाव्स्कके सुलहनामोंके बाद लड़नेसे इनकार कर दिया। इसपर उनके हथियार छीन लिये गये और १०, ००० सिपाहियोंका कत्लेआम हुआ। यह इसलिए किया गया ताकि उनका छूत फ्रांसीसी सिपाहियोंको न लगे। सन् १९१८ मे यहाँतक हालत हो गयी थी कि फ्रांसकी गवर्नमेण्ट आमतौरसे अपनी फौजोपर अविश्वास करती थी। डधर शहरोमें हडतालें शुरू हो गयी और ऐसी हालतमे यदि लड़ाई कुछ दिन और जारी रहती तो सामाजिक क्रान्तिका होना अनिवार्य था।

रूसकी क्रान्ति १९१७ मे सफल हो चुकी थी। उससे एक नवीन प्रेरणा क्रान्तिकारियोंको मिलती थी। पूँजीवादियोंके लिए यह एक नया खतरा था। साम्राज्यशाहीकी लड़ाईमे दस्तूर है कि एक राष्ट्र जीतता है और दूसरा हारता है। यह एक ऐसी चिन्ताजनक बात न थी, किन्तु जब साम्राज्यशाहियोंको समान रूपसे जनक्रान्तिसे खतरा पैदा हो जाता

है तब युद्धको बन्द करनेमें ही उनकी रक्षा होती है, इसलिए जब यह खतरा पैदा हुआ और दूसरे तरीके इस खतरेको दूर न कर सके तभी आर्थिक अवरोध लड़ाईके साथ लागू किया गया और सुलहकी बातचीत शुरू की गयी । लड़ाई बन्द होनेमें देर न हुई, क्योंकि यूरोपके शासक-वर्गने सामान्य खतरेको जल्द पहचान लिया । इधर लड़ाई बन्द की गयी और उधर जनक्रान्तिको दवानेके मनसूबे मिल-जुलकर होने लगे । विजयी और पराजित सेनाओंके एक दूसरेसे अलग रखा गया । विलमेशोने प्रस्ताव किया कि क्रान्तिको रोकनेके लिए अमेरिकाकी फौजसे सहायता ली जाय । फ्रासके अखबारोंने रूसकी नयी आजादीका गला घोटनेके लिए लूडेनबार्गको समस्त अधिकार देनेकी चर्चा चलायी । मित्रराष्ट्रोंकी मंजूरीसे एक जर्मन दस्ता रूस-क्रान्तिके विद्रोहियोंकी मददके लिए फिनलैण्ड भेजा गया जो फिनलैण्डकी राजधानी हेलसिंकीके ४० हजार समाजवादियोंके कत्लमें मददगार हुआ । लड़ाई बन्द कर मास्कोपर धावा बोलनेका प्रस्ताव अमेरिकाके राष्ट्रपति बुडरो विलसनको दिया गया, किन्तु विलसनने इस प्रस्तावको मंजूर नहीं किया । बर्लिनके स्पार्टेकिस्ट (Spartacist) नामक समाजवादियोंको दवानेके लिए ५००० मशीनगने जर्मनोके हाथमें छोड़ दी गयी । इस तरह साम्राज्यवादी युद्ध एक दूसरे तरीकेके युद्धमें परिवर्तित हो गया । अब साम्राज्यशाहियाँ भी मिलकर जनतासे लड़ने लग गयी । सामाजिक प्रणालीको सुरक्षित रखनेके लिए धनीवर्गने हर तरहकी चाल खेली । उसके लिए एक नयी समस्या उठ खड़ी हुई । यह वर्ग-समस्या थी । यह समस्या उसके लिए सर्वोपरि थी । इसने राष्ट्रनीतिमें काफी उलट-फेर किया । मध्यम श्रेणीमें वर्ग-चेतना बहुत बढ़ गयी । सन् १९१४-१८ के इतिहासने उसके दिलोंको दहला दिया । यही कारण है कि जब हिटलरने यह दावा पेश किया कि वह बोल्शेविज्मको नेस्तनाबूद करना चाहता है तो साम्राज्यशाहियोने उसे सामाजिक क्रान्तिको रोकनेका एक बाँध समझकर मजबूत करना शुरू किया । फ़ैसिस्टोको सन्तुष्ट करनेकी नीति (Appeasement Policy) का यही रहस्य है । स्पेनके प्रजातन्त्रको कुचलनेकी साजिशका भी यही रहस्य है । इस साजिशमें ब्रिटेन और फ्रास भी सम्मिलित थे । हालाँकि फ्रैंकोकी जीतने हिटलरको मजबूत कर दिया और फ्रासको ब्रिटेनका आश्रित बना दिया, हिटलरने बोल्शेविज्मका हौवा दिखाकर अपना मतलब साधा और यूरोपकी ताकतोंको बेवकूफ बनाकर अपने राज्यका विस्तार बिना लड़ाईके किया और लड़ाईका अवसर आनेपर उसी बोल्शेविक रूससे समझौता भी कर लिया । यह सब इसीलिए सम्भव हुआ क्योंकि शासकवर्ग जनक्रान्तिको बचाना चाहते थे और वर्गके स्वार्थ उनके लिए सर्वोपरि हो गये थे ।

लुप्त तो यह है कि यह लोग बराबर शान्तिकी रट लगाये रहते हैं । एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो यह कहे कि हम शान्ति नहीं चाहते, शान्तिकी स्थापनाके लिए नाना प्रकारके आयोजन भी करते हैं, किन्तु तिसपर भी युद्ध नहीं टलते । नि शस्त्रीकरणके बिना शान्ति कायम नहीं हो सकती लेकिन शासकवर्ग ऐसे अडगें लगाता है जिससे नि शस्त्रीकरण नहीं हो पाता । इसका कारण यही है कि पूँजीवादी अपने मुनाफेको सबसे पहले देखते हैं । अस्त्र-शस्त्र तैयार कर वह कृत्रिम तरीकेसे बेकारीको भी घटाते हैं । इससे यह दिखानेकी

भी कोशिश की जाती है कि आर्थिक मन्दी कम हो रही है और सम्पत्की अवस्था लौट रही है । यदि आज निःशस्त्रीकरण हो और उत्पादनकी पद्धति साथ-साथ बदली न जाय तो बेकारी बहुत बढ़ जायगी जिससे क्रान्तिका खतरा भी बढ़ जायगा । इस वजहसे भी निःशस्त्रीकरणका विरोध किया जायगा । यह साफ है कि जबतक पूँजीवादी पद्धति प्रचलित है तबतक युद्ध अनिवार्य है । यदि आप युद्धका अन्त करना चाहते हैं तो पूँजीवादी पद्धतिके अन्तके लिए तैयार हो जाइये । पर साधारणतः लोग इन दोनोंके घनिष्ठ सम्बन्धको नहीं समझते ।

पिछले युद्धकी चर्चा हमने इसलिए की जिसमें पाठकोको मालूम हो जाय कि साम्राज्यशाहीपर सकट आनेके कारण जनक्रान्तिकी सम्भावना कितनी अधिक हो जाती है । यदि लड़ाई चन्द महीने भी और चलती तो निस्सन्देह फ्रांस और जर्मनीमें समाजवादी पद्धति कायम हो जाती । इसके फलस्वरूप सारे यूरोपका कायापलट हो जाता । पिछली बार जनक्रान्तिकी सहायता करनेमें कई कारण थे । पहले तो लड़ाई बहुत लम्बी चली और उस समयतक सेनाका यन्त्रीकरण (Mechanization) इतना नहीं हुआ था जितना कि अब हो गया है जिसकी वजहसे उस समय नरसंहार अत्यधिक हुआ । दूसरा कारण यह कि संसारकी नैतिक सहायता प्राप्त करनेके लिए मित्रराष्ट्रोंने बड़े-बड़े आदर्शोंकी घोषणा की थी । मित्रराष्ट्रोंकी ओरसे कहा गया था कि लड़ाई जनतन्त्रकी रक्षा और विस्तारके लिए है और भविष्यमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नये आधारपर कायम होंगे जिससे युद्धोंका सदाके लिए अन्त हो जायगा । युद्धके दौरानमें इस घोषणासे भी प्रेरणा मिली थी, पर युद्धके बाद भी जनक्रान्तिको इससे बराबर प्रेरणा मिलती रही, क्योंकि मित्रराष्ट्रोंने अपने वादोंको पूरा नहीं किया और इस प्रकार जनतामें उत्तेजना और अशान्ति उत्पन्न की ।

हमने ऊपर देखा कि युद्धकालमें यद्यपि शासकवर्गके समयसे होशियार हो जानेसे जनक्रान्ति हर जगह न हो सकी तथापि लम्बी चौड़ी वाते करनेसे और बादको उनको पूरा न करनेसे क्रान्तिका सिलसिला फिर शुरू हुआ । एशियामें तो खासकर युद्धके समाप्तिके बाद ही क्रान्तिका सिलसिला शुरू हुआ था । सन् १९१९ में मिस्र, भारत और चीनमें नया सिलसिला शुरू हुआ था । सन् १९२१ में ईरानके शाह गद्दीसे उतारे गये और सन् १९२३-२४ में तुर्कीमें प्रजातन्त्र कायम हुआ । लड़ाईके जमानेमें या तो क्रान्ति सर्वसाधारण हो जाती है या केवल उन्हीं देशोंमें होती है जो लड़ाईमें परास्त होते हैं अथवा जहाँकी फौज लड़ाईमें शरीक होनेसे इनकार करती है ।

इस बारका युद्ध कुछ दूसरे ढंगका है । इसमें आदमियोंकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी पिछली बार पड़ी थी । इस बार शासकवर्ग पिछली भूलको दुहराना भी नहीं चाहता । आज वह युद्ध और शान्तिके उद्देश्योंका स्पष्टीकरण करनेको तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि जनतामें आशा पैदा करना और फिर उसे पूरा न करना काफी खतरनाक होता है । इसका कटु अनुभव उसको पिछली बार हो चुका है । आज उसकी वर्गचेतना भी बहुत बढ़ी-चढ़ी है । इसीलिए यह भरसक ऐसा प्रयत्न करना चाहता है जिससे जनक्रान्ति न होने पावे । इसीलिए यदि आगे चलकर जनक्रान्तिकी सम्भावना

प्रवल होगी तो यह भी बहुत मुमकिन है कि सुलहकी चर्चा उठाकर लड़ाई बन्द कर दी जावे । पूंजीवादी प्रजातन्त्र पूंजीवादी प्रथाको कभी खतरेमे न डालेगा और आज चाहे भले ही वह कह ले कि फैसिस्ट वर्बर और पशु हैं पर जरूरत पड़नेपर वह इन्हीसे मामिला पटा लेगा लेकिन जनताको उभरने न देगा ।

हमने पिछले युद्ध और आजके युद्धका यह अन्तर इसलिए बताया जिसमे पाठक यह समझ जायें कि जनक्रान्तिका कार्य पहलेकी अपेक्षा कुछ कठिन हो गया है । फ्रासकी हार एक प्रकार बिना लड़े ही हो गयी । फ्रासके शासकवर्गका नैतिक पतन इतनी तेजीसे हुआ और उसमे देशसे विश्वासघात करनेवाले लोगोका एक ऐसा स्थान था कि किसी दूसरे नतीजेकी उम्मीद ही न हो सकती थी । जिनसे क्रान्तिके नेतृत्वकी आशा की जा सकती थी, वह या तो गृहयुद्ध (Civil war) का नारा बुलन्द करनेके कारण राष्ट्रके शत्रुकी कोटिमे आ गये और इसलिए उनका दमन हुआ या उन्होने तूफानके सामने अपनी कमजोरीके कारण सिर झुका दिया । पिछली बार रूसकी सफल क्रान्ति और क्रान्तियोका प्रेरक बनी थी । इस बार उसको आत्मरक्षाके लिए ही पूरी ताकत लगानी पड़ रही है । आज हम दुनियामे आँख पसारकर देखे तो क्रान्तिके केन्द्र नजर न आयेगे । यूरोपमें हिटलरका आतक ऐसा बैठ गया है कि अभी वहाँके लोगोको होश सँभालनेमे कुछ अरसा लगेगा । या तो जब हिटलरकी युद्धमे हार हो या जब आर्थिक संगठन लड़ाईके बोझको बर्दाश्त न कर सके और छिन्न-भिन्न होने लगे तभी क्रान्ति हो सकती है । एशियामे चीन अवश्य फैसिज्मकी बाढको रोके हुए है और अपनी आजादीकी रक्षाके लिए अपूर्व त्याग और शौर्य प्रदर्शित कर हम सबको प्रेरणा दे रहा है । चीन इसलिए पूर्वी एशियामे आजादी और लोकतन्त्रका हिमायती है । सारा यूरोप हिटलरके सामने झुक गया पर चीन जापानकी फैसिस्ट और फौजी गवर्नमेण्टके आगे न झुका । चीनके बाद हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जो कमसे कम साम्राज्यशाही युद्धका प्रतिवाद कर रहा है । अमेरिका जिसने पिछली बार अपने प्रेसिडेण्टके मुखसे एक नयी दुनिया कायम करनेकी बात की थी, आज फैसिज्मका विरोध करके ही सन्तुष्ट है । कुछ प्रगतिशील लोग यह भी कहते हैं कि सबका प्रधान कार्य आज फैसिज्मका विरोध करना है और यही जनक्रान्तिकी तैयारी है । इसमे शक नहीं कि पूंजीवादी प्रजातन्त्र और फैसिज्ममे गुणकी दृष्टिसे अन्तर है, तथापि यह मानना पड़ेगा कि साम्राज्यवाद फैसिज्मके मुकाबले सफल होकर स्वयं फैसिस्ट रूप धारण कर सकता यदि वह साम्राज्यकी भावनाका परित्याग नहीं करता । प्रो० लास्कीने अपनी एक हालकी पुस्तकमे यह दिखलानेकी चेष्टा की है कि जबतक ब्रिटेन यूरोपकी क्रान्तिका अग्रदूत नहीं बनता तबतक वह युद्धमे विजयी नहीं हो सकता । मेरी रायमे सच्ची नीति यह है कि बाहर हम फैसिज्मका विरोध करे और घरमे प्रतिगामी शक्तियोका । यूरोपके स्वतन्त्र राष्ट्रोंसे यह कहना ठीक होगा कि वे फैसिज्मका मुकाबला करे किन्तु पराधीन देशोंसे केवल इस गुणकी विभिन्नताके कारण यह कहना कि वे फैसिज्मके विरोधमे साम्राज्य-शाहीका साथ दे गलत होगा । ब्रिटेनकी मौजूदा गवर्नमेण्ट प्रगतिशील नहीं है और न यह आशा ही है कि वह जल्द प्रगतिशाली बन सकेगी ।

इस तरह आज क्रान्तिके मार्गमें काफी रुकावटें हैं तथापि इसमें सन्देह नहीं कि जब आर्थिक संगठन टूटने लगेगा और बेकारी बढ़ेगी तब जनता क्षुब्ध होगी । इसलिए यदि युद्धकालमें क्रान्तिका सुअवसर नहीं मिलता तो युद्धके बाद तो अवश्य मिलेगा । लेकिन उसकी तैयारी तो एक अरसेसे शुरू हो जानी चाहिये थी । हिन्दुस्तानमें तो हमने वक्तकी काफी बर्बादी की । सत्याग्रह यदि नहीं शुरू हुआ था तो कमसे कम माकूल तैयारी तो करते । इस समय तो शहरी ग्राजादीके सवालको लेकर सत्याग्रह हो रहा है । इससे कमसे कम युद्धका नैतिक विरोध प्रदर्शित होता है । स्वतन्त्र होनेके लिए हमको जनतामें जागृति उत्पन्न करना होगा और उसको संगठित करना होगा । वर्तमान सत्याग्रहको आधार बनाकर यदि हम सभी तैयारीमें लग जावे तो बड़ा काम हो । अगले लेखमें हम गत वर्षका सिंहावलोकन करेंगे और अपनी निश्चेष्टताकी कहानी सुनावेंगे । तदनन्तर हम कुछ ऐसे प्रश्नोंपर विचार करेंगे जो हमारे रास्तेमें रुकावट डालते हैं । फिर सच्ची तैयारी किसे कहते हैं और उसका उपकरण और साधन कैसा हो इन विषयोंपर हम विचार करेंगे ।^१

भारतकी स्वाधीनताका सवाल

सन् १९३९-४० का सिंहावलोकन

युद्धके खतरेकी ओर कांग्रेसका ध्यान सबसे पहले सन् १९२७ में गया था । जब इटलीने अवीसिनियापर आक्रमण किया तब यह खतरा और भी बढ़ गया और इसलिए सन् १९३६ में कांग्रेसने अपना यह निश्चय प्रकट किया कि वह साम्राज्यवादी युद्धमें भाग लेनेका विरोध करती है । त्रिपुरीका अधिवेशन एक दृष्टिसे बड़े महत्त्वका था क्योंकि उसमें युद्धका विरोध करनेका निश्चय महज दुहराया ही नहीं गया था किन्तु साथ-साथ राष्ट्रीय माँगका प्रस्ताव भी पास किया गया था और यह कहा गया था कि अब समय आ गया है जब हमको स्वभाग्यनिर्णयके सिद्धान्तको लागू करना चाहिये । त्रिपुरीमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जबतक साम्राज्यवाद और फैसिज्मका समान रूपसे अन्त नहीं कर दिया जाता तबतक ससारमें शान्ति स्थापित नहीं हो सकती, कांग्रेस स्वतन्त्रता और शान्तिके मार्गका अनुसरण करना चाहती है, उसकी वैदेशिक नीति इसी आधारपर बननी चाहिये और इसलिए उसका यह निश्चय है कि वह साम्राज्यवाद और फैसिज्मसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहती ।

दुःखके साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय माँगका प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया गया और आनेवाले खतरेका मुकाबला करनेके लिए तथा अपने निश्चयोंको पूरा करनेके लिए देशको तैयार नहीं किया गया । मन्त्रिप्रद ग्रहण कर लेनेके बादसे कांग्रेसके एक भागमें

वैधानिक मनोवृत्ति प्रबल होने लगी । जनताकी हलचलसे उसको घबराहट होती थी । युद्धके आरम्भ होनेके बाद भी कोई खास तैयारी नहीं की गयी । दुनिया को यह दिखानेके लिए कि कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेण्टकी नैतिक सहायता देनेके लिए तैयार है यदि विश्वास हो कि यह लड़ाई लोकतन्त्रके लिए लड़ी जा रही है । कांग्रेस इसी कोशिशमें लगी रही कि ब्रिटिश गवर्नमेण्टसे उसके इरादे साफ कराये जाये । युद्धका उद्देश्य क्या है और सुलहकी शकल क्या होगी यह सवाल बार-बार हुकूमतसे पूछे गये, पर उसने इन सवालको जवाब देनेसे गुरेज किया । वह जवाब क्यों देने लगी; दूधका जला छाँछ फूँक-फूँक कर पीता है । सन् १९१४ में जो यूरोपीय युद्ध हुआ था उसमें मित्रराष्ट्रोंने बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की थी और लोकतन्त्रकी दुहाई देकर संसारकी नैतिक सहायता प्राप्त की थी पर विजयी होनेपर वह अपने वादोको भूल गये । युद्धके दौरानमें लोगोको आशा बँध गयी थी कि युद्धके बाद नये आदर्शोंके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित होंगे और स्वेच्छा-चारिताका अन्त और लोकतन्त्रकी स्थापना होगी, पर जब इन आशाओंपर पानी फिर गया तब जनतामें उत्तेजना और अशान्ति उत्पन्न हुई और क्रान्तियोंका सिलसिला शुरू हुआ । इस अनुभवसे लाभ उठाकर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इस बार उस भूलको दोहराना नहीं चाहती, इसलिए वह युद्धके उद्देश्योका स्पष्टीकरण करनेको तैयार नहीं है । कुछ अरसेतक इन्तजार करनेके बाद जब वायसरायके वक्तव्यसे स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट गोल बातें करनेके सिवाय कुछ करना नहीं चाहती तब कांग्रेसने विवश होकर मन्त्रियोको वापस बुला लिया, पर साथ-साथ यह भी साफ कर दिया कि वह सम्मानपूर्वक समझौतेकी कोशिशोको जारी रखेगी । महात्माजीका शुरूमें यह ख्याल था कि ब्रिटिश हुकूमतकी जन-धनसे सहायता न कर उसकी नैतिक सहायता करनी चाहिये । लेकिन वकिंग-कमेटीका एक भी सदस्य इस ख्यालका न था, इसलिए महात्माजीने अपनी रायमें कुछ तबदीली की । जब गवर्नमेण्टने अपने उद्देश्योका स्पष्टीकरण नहीं किया और कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया तब महात्माजीने मन्त्रिपद छोड़नेका परामर्श दिया और रामगढ़में नेतृत्व भी ग्रहण किया । रामगढ़ कांग्रेसमें पूर्ण स्वाधीनताकी माँग दुहरायी गयी और यह साफ कर दिया गया कि 'डोमिनियन स्टेट्स' (अपनिवेशिक स्वराज्य) उसको स्वीकार नहीं होगा । यह भी घोषणा की गयी कि यह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है और कांग्रेसका दूसरा कदम सत्याग्रह होगा । महात्माजीने अपने भाषणमें सामूहिक सत्याग्रह करनेका विचार प्रकट किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि जबतक देश तैयार नहीं हो जाता तबतक वह कुछ नहीं करेगा । उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम तथा अनुशासनपर जोर दिया । उनके आदेशसे कांग्रेस-कमेटियाँ सत्याग्रह कमेटियोमें तबदील हो गयी और रचनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाने लगा । जिनको इस कार्यक्रमके प्रभावशाली होनेमें विश्वास नहीं था वह भी इसमें इस विचारसे शरीक हुए कि बिना इन शक्तोंके पूरा किये सत्याग्रहके शुरू होनेकी कोई सम्भावना नहीं है । कोई प्रान्तीय कमेटी अपने कार्यक्रमको रचनात्मक कार्यतक सीमित रखनेके लिए बाध्य न थी । उसको इसका पूरा अधिकार था कि वह रचनात्मक कामके साथ अन्य कामोको भी जोड़े, यदि वह काम कांग्रेसके सिद्धान्त

के प्रतिकूल न हों किन्तु संयुक्तप्रान्तको छोड़कर किसी भी दूसरे प्रान्तमें एक पूर्ण आयोजना तैयार करनेकी कोशिश नहीं की गयी । वजारतके जमानेमें किसानोंकी शिकायतोंकी सुनने और उनको रफा करनेका काम निरन्तर जारी था । इस तरह कांग्रेसका सम्पर्क किसानोंके साथ बराबर बना था और कांग्रेस उसके दैनिक संघर्षमें हिस्सा लेती थी । मंत्रिपदका परित्याग करनेके बादसे यह सम्पर्क बहुत कम हो गया । किसानोंकी सहायता करनेका एक ही तरीका नहीं है । यदि हमारी गवर्नमेण्ट नहीं है तब भी हम किसानोंको संगठित कर उनकी मांगोंके लिए शान्तिमय लड़ाई लड़कर उनकी सहायता कर सकते हैं । स्वयंसेवकोंके सघटनका काम भी बहुत जरूरी था, पर दो एक प्रान्तोंको छोड़कर इस दिशामे कुछ नहीं किया गया । कहातक कहा जाय, कांग्रेसकी नीतिको जनताको समझानेका भी काम प्रायः नहीं ही किया गया । यह काम प्रायः वामपक्ष करता रहा और इसीलिए वे काफी तादादमें गिरपतार भी किये गये । सत्याग्रहके आरम्भके पूर्व ही लगभग पाँच हजार राजनीतिक बन्दी हो चुके थे । इस संस्थामे दक्षिणपक्षके लोगोंकी संख्या बहुत थोड़ी है । दक्षिणपक्ष समझौतेकी आशा लगाये बैठा हुआ था । इसके अतिरिक्त साधारणतः कांग्रेसजन सत्याग्रहके लिए किसी विशेष तैयारीकी जरूरत नहीं समझते और जब एक बार सत्याग्रह शुरू हो जाय तब तो उनके ख्यालसे किसी दूसरे कामकी जरूरत ही नहीं रह जाती । एक जमाना था जब जेलका डर दूर करना जरूरी था, लेकिन आज तो कांग्रेसने सबके लिए यह काम आसान-सा कर दिया है । जिसको देखिये वही आज सत्याग्रहकी धमकी देता है, इसीलिए महज जेल जानेका आज वह महत्त्व नहीं रह गया है । हम कई मजिले पार कर चुके हैं । अब हमको आगे बढ़ना चाहिये । राजशक्ति कैसे मिलती है इसकी तस्वीर कांग्रेसवालोंके सामने नहीं रखी गयी है । इस कमीको हमे पूरा करना चाहिये । रामगढमे तो निश्चय हो चुका था कि कांग्रेसका अगला कदम सत्याग्रह होगा, लेकिन वह बराबर टलता ही गया । हिन्दू-मुस्लिम सवाल महात्माजीको परेशान कर डालता था । उनको इसमे भी शक था कि देश कहाँतक शान्तिके पथपर अन्ततक कायम रहेगा । इन दो कारणोंसे उनको सत्याग्रह शुरू करनेमे हिचकिचाहट होती थी । इसी दुविधामे जब वे थे तब मईके महीनेमे फ्रांसकी हार हुई । इस घटनाका गांधीपर गहरा असर हुआ । एक तो उन्होंने लडाईके दौरानमे ब्रिटिश हुकूमतको परेशान न करनेका निश्चय किया, दूसरे अहिंसाकी व्याख्याका और विस्तार कर यह भी तय किया कि अब समय आ गया है जब उन्हें यह घोषणा कर देनी चाहिये कि जहाँतक उनका सम्बन्ध है वह आजाद हिन्दुस्तानमे फौज नहीं रखेंगे और यदि बाहरी आक्रमण होगा तो उसका मुकाबला सत्याग्रहसे करेंगे । यदि कांग्रेस उनके विचारको स्वीकार करती है तो वह उसका नेतृत्व करेंगे अन्यथा नहीं । बर्किंग-कमेटीमे उन्होंने उसकी चर्चा चलायी और जब उसके बहुत से सदस्य इस विचारसे सहमत नहीं हुए तब वह पृथक् हो गये । फ्रांसकी हारके बाद कांग्रेसके नेतृत्वका एक बड़ा भाग विचलित हो गया । वह भीतरी अराजकता और बाह्य आक्रमणके भयसे पंगु हो गया, इसीलिए वह सत्याग्रह शुरू करनेको तैयार न था । महात्माजीके अलग होनेसे मुलह-समझौतेका रास्ता साफ हो गया था क्योंकि उसका ख्याल था कि

गवर्नमेण्ट यदि समझौता करेगी तो इसी शर्तपर करेगी कि कांग्रेस लड़ाईमें उसकी मदद करे जिसके लिए गांधीजी तैयार न थे । इस तरह पूनामे समझौतेका प्रस्ताव पास हुआ । लेकिन वायसरायने कांग्रेसका प्रस्ताव मजूर नहीं किया । अब सत्याग्रह शुरू करनेके सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था । बकिंग कमेटी गांधीजीको फिर कांग्रेसमे लायी और उनके सन्तोषके लिए अहिंसाकी नयी व्याख्याको स्वीकार किया । गांधीजीपर गवर्नमेण्टकी वेरुखीका बुरा प्रभाव पडा और उन्होने किसी-न-किसी शकलमे सत्याग्रह करनेका निश्चय किया । गांधीजी गवर्नमेण्टको परेशान भी नहीं करना चाहते थे और कांग्रेसको जिन्दा रखना तथा गवर्नमेण्टका जवाब देना भी उनके लिए जरूरी था, इसलिए उन्होने व्यक्तिगत सत्याग्रहका रास्ता निकाला और नागरिक स्वतन्त्रताका सवाल उठाया ।

महात्माजी अपने सिद्धान्तके अनुसार लड़ाईके दौरानमे समझौता नहीं करते, लेकिन दूसरे दक्षिणपक्षके नेता समझौते के लिए ही सत्याग्रह कर रहे हैं उनके बयानोसे यह साफ है । जनता भी यही समझती है । लोगोका ख्याल है कि अगर गवर्नमेण्ट समझौतेके लिए तैयार हो जायगी तो कांग्रेसके नेता महात्माजीपर दबाव डालेंगे कि समझौतेके रास्तेमे वह सहूलियत पैदा करे और यदि उनका सिद्धान्त इसे गवारा नहीं करता तो वह कृपया एक बार फिर पृथक हो जायँ और उनको सौदा करने दे । समझौतेका प्रयास सफल न होनेपर ही सत्याग्रहका उपक्रम हुआ है । इससे यह धारणा और पुष्ट होती है । नेतृत्वका अधिकांश भाग समझौता ही चाहता है । वह क्रान्तिकी छायासे घबराता है । उससे यह आशा अब नहीं रह गयी है कि वह रामगढके प्रस्तावको कार्यान्वित करेगा । यदि महात्माजीके कारण युद्धके दौरानमे समझौता न हो सका तो युद्धके बाद जब विधानके प्रश्नपर फिरसे विचार होगा तो हमारे नेता फिर समझौतेकी बातचीत चलावेंगे । कांग्रेसके लिए सबसे बड़ा खतरा यही है । मन्त्रिपद ग्रहण कर हमने अपने लिए एक मुसीबत बुला ली । वैधानिक मनोवृत्तिको तो उत्तेजना मिली ही जिसकी वजहसे अवसरवादियोको कांग्रेसमे घुसनेका मौका मिला साथ साथ मुसलिम लीगका भी विरोध बढ़ गया और हिन्दू-मुसलिम प्रश्नने भयंकर रूप धारण कर लिया ।

राज्यशक्ति हासिल करनेके लिए किस किस्मकी तैयारी होनी चाहिये यह भी हम नहीं जानते । पुराने ढंगसे ही अब हम भी काम करते हैं और कांग्रेसको एक नये साँचेमे ढालनेकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है । इस प्रश्नपर हम किसी दूसरे लेखमे विचार करेंगे । इस लेखमे तो हम केवल एक वर्षका हिसाब दे रहे हैं । कांग्रेसके अधिकारियोने कोई खास तैयारी नहीं की इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं ।

अब जरा वामपक्षकी भी कथा सुनिये । पहले तो वामपक्षमे कोई एकता नहीं है वह कई टुकडोमे बँटा हुआ है । यह हालत केवल हमारे ही देशमे नहीं है, किन्तु सारे ससारमे वामपक्षके टुकडे-टुकडे हो गये हैं । दलोके भीतर भी कहीं-कहीं उपदल बन गये हैं । इस परिस्थितिके बुनियादी कारणोमे जानेका यह मौका नहीं है किन्तु इसकी वास्तविकतासे इनकार नहीं किया जा सकता । भारतवर्षमे वामपक्षके अन्तर्गत कई दल हैं । इस समय इनमेसे कुछकी राहें भी अलग हो गयी हैं । काम करनेका तरीका तो भिन्न था ही ।

रायपन्थी आज जिस नुकतेपर पहुँच गये हैं उसको देखते हुए उनके साथ मिल-जुलकर काम करनेका सवाल ही नहीं उठता। कम्युनिस्ट संयुक्त मोर्चेके तभीतक कायल रहते हैं जबतक उनमें शामिल होनेसे उनकी ताकत बढ़ती रहे। जब कभी उनके दिमागमें यह ध्याल आता है कि क्रान्ति नजदीक आ गयी है तब वह संयुक्त मोर्चेमें हटकर अपना राग अलग अलग करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि वह क्रान्तिका नेतृत्व अकेले करना चाहते हैं जो संयुक्त मोर्चेमें शामिल रहकर नहीं हो सकता। समाजवादी एकता भी वह इसलिए नहीं चाहते कि विभिन्न दल मिल-जुलकर कुछ हासिल करे, बल्कि इसलिए कि इस तरह वह अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं और समाजवादी दलोंपर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं। जबतक आप उनको बेरोक-टोक काररवाई करने दें तबतक वह आपको क्रान्तिकारी मानेंगे, लेकिन अगर आपने इसमें रुकावट डाली और अपनेको अलग रखनेकी व्यवस्था की तो आप तत्काल सुधारवादी और समाजवादियोंमें फूट डालनेवाले हो जायेंगे। असलियत यह है कि यह क्रान्तिके नेतृत्वमें अपनी ही प्रधानता चाहते हैं। यदि यह सम्भव नहीं है तो यह क्रान्तिको ही असम्भव बनानेकी चेष्टा करेंगे। दलके हित इनके लिए जनान्दोलनके हितोंसे भी बढ़कर हैं। यह तो अपनेको क्रान्तिका तनहा ठेकेदार समझते हैं। इनको छोड़कर सब सुधारवादी हैं, इसलिए अगर क्रान्ति हो तो इन्हींके नेतृत्वमें हो। इसीलिए क्रान्तिके जमानेमें वही संयुक्त मोर्चा इनको मजूर होगा जिसमें इनका प्राधान्य है। दूसरे तरहके मोर्चे क्रान्तिके लिए अहितकर हैं। उनको कमजोर करना और उनके नेतृत्वको बदनाम करना इन क्रान्तिके ठेकेदारोंके लिए अत्यन्त जरूरी हो जाता है। जितनी साम्राज्य-विरोधी संस्थाएँ हैं उनपर कब्जा पाना और यदि इसमें सफलता न मिली तो उनको ध्वंस करना भी जरूरी हो जाता है। यह ध्वंसात्मक कार्य बक्त आनेपर 'क्रान्तिकारियों' के लिए मैदान साफ रखनेके लिए अत्यन्त जरूरी है। जबसे युद्धका आरम्भ हुआ है तबसे कम्युनिस्टोंका सम्पर्क जनतासे बहुत कम हो गया है। अब वह एक ही फ्रण्ट (मोर्चे) पर काम करते हैं, यह है विद्यार्थी फ्रण्ट। वह पार्टी जो अपनेको श्रमजीवी वर्गकी पार्टी कहती थी और दूसरोंका इसी आधारपर मजाक उड़ाती थी कि उसके सदस्य निम्न-मध्य-श्रेणीके हैं आज स्वयं निम्न-मध्य-श्रेणी (Petty bourgeoisie) की पार्टी हो गयी है। विद्यार्थियोंमें काम करनेको हम काफी महत्व देते हैं, लेकिन जनताका स्थान कोई दूसरा समुदाय नहीं ले सकता। मजदूर सस्थाओंमें कम्युनिस्टोंका क्या स्थान है यह अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेसके हालके अधिवेशनसे साफ हो गया है। एक बहुत दिनोका भ्रम दूर हो गया। हकीकत यह है कि वहाँ भी अन्य दल इनसे कई गुना ज्यादा हैं। किसानोंमें इनकी खास जगह कोई कभी नहीं रही। बंगालके कुछ जिलोंको छोड़कर किसानोंमें इनका काम नहीं के बराबर है। कांग्रेसमें तो इनका कभी कोई विशेष स्थान रहा ही नहीं है। अब तो वह कांग्रेसके ही खिलाफ हो गये हैं। जब ऐसी हालत है तो विद्यार्थी-फ्रण्टपर आधिपत्य जमाना बहुत जरूरी हो जाता है। विद्यार्थियोंमें यदि बहुमत नहीं है तो मतलबववाराके और तरीकोंसे काम लेना चाहिये। डा० अण्णरफ साहवने तो यहाँतक कहा कि इतिहासका तकाजा है कि विद्यार्थीसंघके दो टुकड़े

हो जायें, क्योंकि आज यह बहुत जरूरी बात साफ हो जाय कि कौन क्रान्तिकारी है और कौन सुधारवादी । वाकई डाक्टर साहबने हसका काम किया । जिस तरह हस दूधका दूध, पानीका पानी अलग कर देता है उसी तरह डाक्टर साहबने अपने भेडियोको वक़रियोसे अलग कर लिया । डाक्टर साहब जब अपनी वक्तूता दे रहे थे उस समय उनके पक्षके विद्यार्थीने यही समझा होगा कि वह विद्यार्थी-संघमें भेद उत्पन्न कर कोई इतिहास-निर्दिष्ट क्रान्तिकारी काम कर रहे हैं । अब विद्यार्थी-संघपर कब्ज़ा जमाकर यह आलथी-पालथी मारकर बैठेंगे और क्रान्तिका इन्तजार करेंगे । इनका दुर्भाग्य है कि और संस्थाएँ इनके कब्ज़ेमें नहीं हैं और न वह खतम ही हो पाती हैं । इससे इनके जरिये क्रान्तिके सफल होनेमें जरा शक होता है ।

लेकिन यह तो अपनी शुद्ध क्रान्ति चाहते हैं, कोई अधकचरी चीज नहीं । इसलिए कमजोर होते हुए भी यह दूसरोसे सम्मानपूर्वक समझौता नहीं करेंगे । इस घातक मनोवृत्ति-ने हिटलरका उत्थान किया था । जब नाजी सैनिकोकी ताकत बढ़ने लगी तब मजदूरोने उनको अपना दुश्मन समझकर उनका पीछा करना शुरू किया और लड़ाईकी तैयारी करना चाहा । हिटलरने एक लाख भूरी कमीजवालोको जब वर्लिन बुलाया तब वामपक्षके विभिन्न जिलोके नेताओने आपसमें परामर्श किया कि ऐसी परिस्थितिमें क्या करना चाहिये । सभी विचारके समाजवादी इकट्ठा थे । बहुतोने सलाह दी कि फौरन आम हड़तालकी घोषणा होनी चाहिये और मजदूरोको लड़ाईके लिए सयुक्त मोर्चा बनाना चाहिये । लेकिन कम्युनिस्टोने कहा कि हिटलरको आने दो हम उससे समझ लेंगे । इस निश्चेष्टताके कारण मजदूरोका लड़नेका जोश ठंडा हो गया । जर्मन पार्लमेण्ट (Reichstag) को जलवाकर नाजियोने इस वहाने लोगोका दमन करना शुरू किया और इस तरह विद्रोहकी आशापर पानी फिर गया । यह सबसे अकेले ही समझना चाहते हैं, इसलिए किसीसे नहीं समझ पाते । इन्होने एक साल कोरी वक़ासमें ही निकाल दिया । जनान्दोलनकी सिद्धिके कामकी सर्वथा उपेक्षा की ।

फारवर्ड ब्लाकको बने अभी दो-ढाई सालसे ज्यादा नहीं हुए हैं । इसकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है । कांग्रेसके वर्तमान नेतृत्वका विरोध ही इसका मुख्य आधार रहा है । इस कारण तरह-तरहके लोग इसमें सम्मिलित हो गये । इसने स्वतन्त्र रीतिसे सत्याग्रह-संग्राम चलानेकी कोशिश की, पर विफल रहा । अब इन्होने अपनी गलती पहचानी है और ये अपने कामका ढंग बदल रहे हैं, लेकिन वर्ग-संघटनोमें इनका विशेष काम नहीं है, और हो भी कैसे सकता है । इसके लिए दो वर्षका समय बहुत थोड़ा होता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि फारवर्ड ब्लाक अपनी नीतिको फिरसे स्पष्ट करेगा और किसान मजदूरोमें काम करनेपर जोर देगा ।

समाजवादी सयुक्त मोर्चेपर तबतक जोर देते रहे जबतक कांग्रेसके नेताओने समझौतेका प्रस्ताव नहीं पास किया था । पूनामें समाजवादियोने समझौतेका घोर विरोध किया, क्योंकि वह कांग्रेसके प्रस्तावोके विरुद्ध था और उससे जनान्दोलनको ठेस पहुँचती थी । समाजवादी कांग्रेस-नीतिका प्रचार करनेके साथ-साथ किसानो और मजदूरोमें भी थोड़ा

बहुत काम करते थे । आज तो वह इसपर काफी जोर देते हैं । यदि अन्य वामपक्षी भी इस कामको अमलमे महत्व दें तो इस दिशामें काफी काम हो सकता है ।

इतना कहनेपर यह मानना ही पड़ेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रहके आरम्भ होनेतक वामपक्ष-के दलोंने ही प्रधानतया कांग्रेसके युद्ध-विरोधी निश्चयका जनतामें प्रचार किया था ।

एक वर्ष तो किसी तरह व्यतीत हो गया । क्या भविष्यके लिए कुछ आशा की जा सकती है ? वामपक्षसे तबतक कुछ नहीं हो सकता जबतक वामपक्षके वे दल जिनके उद्देश्य एक हैं इस बातको नहीं समझ लेते कि संयुक्त मोर्चा बनानेके सिवाय कोई दूसरी गति नहीं है । लेकिन यह तभी सम्भव है जब ईमानदारीकी रीतिसे काम हो और ठेकेदारीसे हमारे दोस्त दस्तवरदार हो । समाजवादियोंने एकताके लिए काफी कोशिश की । सालोतक इसी कोशिशमे लगे रहे । इसके लिए पार्टीमें सभी विचारके समाजवादियोंको स्थान दिया गया, लेकिन इस रखकी कद्र न की गयी और सदा अपना मतलब गाँठनेमे दूसरे लगे रहे । इस समय हर जगह यह रोग फैल गया है कि दलविशेषके स्वार्थ आन्दोलनकी जरूरतसे भी ऊपर है । जबतक इस रोगसे हमारा छुटकारा नहीं होगा तबतक हम कुछ नहीं कर सकते । इसके लिए अहंमन्यताको कम करना होगा और यह मानना होगा कि हमारे सिवा दूसरे भी क्रान्तिकारी हो सकते हैं ।^१

आगे बढ़नेमे इस एकताका अभाव रुकावट डालता है । दूसरी बड़ी रुकावट हिन्दू-मुसलिम समस्या है । अगले लेखमें हम इसपर विस्तारसे विचार करेंगे ।

अगस्त-क्रान्तिका स्वरूप और उसका सन्देश

प्रश्न—६ अगस्तको छोड़े गये भारत छोड़ो आन्दोलनकी, आपकी रायमे क्या मुख्य विशेषता है ?

उत्तर—यह आन्दोलन भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलनका सबसे बड़ा जन-संग्राम था । किसी पूर्वनिश्चित योजनाके अभावमे भी देशकी जनता सर्वत्र सरकारके विरुद्ध उठ खड़ी हुई और जैसा कि स्वतन्त्र-प्रसूत जनक्रान्तियोमे देखा जाता है, उसने शासन-सत्ताके केन्द्रोपर अधिकार करना और विदेशी शासनके प्रतीकोको नष्ट करना आरम्भ किया । प्रचलित शासन-व्यवस्थाके विरुद्ध शान्तिमय प्रदर्शन तथा स्वतन्त्र-प्रसूत व्यापक जन-विद्रोहमें जो अन्तर होता है वही 'भारत छोड़ो' आन्दोलन तथा उसके पूर्ववर्ती कांग्रेसके आन्दोलनोमे देख पड़ता है ।

प्रश्न—क्या 'अगस्त-आन्दोलन' को कांग्रेसका आन्दोलन कहना उचित होगा ? कांग्रेस 'हार्डिमाण्ड'का अपनी गिरफ्तारीके बाद आन्दोलन चलानेके सम्बन्धमें किसी योजनाका न छोड़ जाना किस बातका द्योतक है ?

उत्तर—यह आन्दोलन कांग्रेसका आन्दोलन था इसमे मुझे कोई सन्देह नहीं है ।

अपने लेखों और भाषणोंद्वारा महात्माजी तथा कांग्रेसके दूसरे नेताओंने आन्दोलनके लिए वातावरण पहलेसे ही तैयार कर रखा था । कांग्रेस-कार्यसमितिके सदस्योंकी गिरफ्तारीकी बातको ध्यानमें रखते हुए यह आदेश जारी कर दिया गया था कि नेताओंकी गिरफ्तारीके पश्चात् हर व्यक्ति अपनेको ही अपना नेता समझे और अहिंसाके दायरेके भीतर रहते हुए जो उचित समझे करे । इस आदेशके बावजूद यह तर्क करना कि महात्माजी गिरफ्तार हो गये और आन्दोलन छेड़ नहीं सके, अतः जो आन्दोलन आरम्भ हुआ वह कांग्रेसका आन्दोलन नहीं वरन् नेताओंकी गिरफ्तारीपर केवल विरोध-प्रदर्शन था, मेरी रायमें शाब्दिक तर्क मात्र है, कोरी वकालती बहस है ।

मेरा अनुमान है कि महात्माजी राष्ट्रीय मार्गको लेकर वायसरायसे बातें करनेवाले थे, इसी कारण सम्भवतः वे सत्याग्रहका स्पष्ट कार्यक्रम रखना उचित नहीं समझते थे । किन्तु देशकी अनिश्चित अवस्थाको देखते हुए वे चुप भी नहीं बैठ सकते थे । इस कारण उन्होंने बीचका मार्ग अपनाया अर्थात् 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीसे स्वीकृत कराया । कार्यक्रमका दिया जाना यद्यपि उचित ही होता, किन्तु जनताकी तत्कालीन मनोदशाको देखते हुए यह निःसंकोच रूपसे कहा जा सकता है कि कार्यक्रमके रखे जानेसे भी आन्दोलनके स्वरूपमें अन्तर न आता ।

प्रश्न—अगस्त-आन्दोलनसे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओंको क्या प्रमुख शिक्षाएँ मिलती हैं ?

उत्तर—इस आन्दोलनने दिखलाया कि जनता बहुत आगे बढ़ गयी है, कार्यकर्तागण पीछे रह गये हैं । प्रचारका कार्य बहुत हो चुका, जनतामें क्रान्तिकारी चेतनाका विकास सन्तोषजनक सीमातक हो चुका है, आवश्यकता है इस चेतनाको सघटनात्मक रूप देनेकी । कार्यकर्ताओंको क्रान्तिके स्वरूपका अध्ययन करना चाहिये और उसका संचालन करनेके लिए क्रान्तिकारी रचनात्मक सघटन-कार्यमें जुट जाना चाहिये । क्रान्तिका संचालन करनेकी कलाके साथ कार्यकर्ताओंको यह भी समझना चाहिये कि सत्ता हाथमें आनेपर उसे कैसे बनाये रखा जा सकता है ।

प्रश्न—क्या आपकी रायमें अगस्त-आन्दोलनमें अपनायी गयी तोड़-फोड़की प्रणाली कांग्रेसकी अहिंसा-नीतिके विरुद्ध थी ?

उत्तर—मैं हिंसा-अहिंसाकी शास्त्रीय बहसमें पड़ना नहीं चाहता । हिंसा-अहिंसाका सूक्ष्म विचार बहुत कठिन है । इस विषयमें विद्वान् भी मोहको प्राप्त होते हैं । किन्तु इस सम्बन्धमें मेरा मत यह है कि जितने मानवोचित और प्रभावशाली उपाय हैं उन सबका अवलम्बन किया जा सकता है । उपायोके औचित्यका विचार करनेमें उनकी नैतिकताका भी विचार करना होता है, किन्तु नैतिकताका मापदण्ड ऐसा न होना चाहिये जिसके अनुसार कार्य करना सामान्य जनोके लिए असम्भव हो ।

प्रश्न—अगस्त-आन्दोलनके अनुभवोंके प्रकाशमें आपकी रायमें कांग्रेसको अपने शान्तिकालीन रचनात्मक कार्यक्रममें क्या परिवर्तन करना चाहिये ?

उत्तर—इसमें सन्देह नहीं कि सामाजिक सुधार अथवा शिक्षाके प्रचारके लिए जो कार्य किया जाय उससे राष्ट्रकी पुष्टिमें सहायता मिलती है किन्तु राजनीतिक दृष्टिसे

हम उसी रचनात्मक कार्यक्रमको महत्व देगे जो प्रत्यक्ष रूपसे विदेशी सत्ताको हटाने और अपनी सत्ताको कायम करनेमें सहायक होता हो । इस दृष्टिसे किसानों और मजदूरोंका उनकी आर्थिक माँगोंके आधारपर संघटन, गाँवोंमें आत्मरक्षाका कार्य करनेवाले स्वयं-सेवकोंका संघटन, ग्राम-पंचायतोंकी स्थापना, शासन-पद्धतिसे स्वतन्त्र सहयोग-समितियोंकी स्थापना, विशेष महत्वके हैं जो अन्य शान्तिकालीन रचनात्मक कार्य हैं उनका महत्व तभी है जब कि उन्हें इस कार्यक्रमके साथ आनुपगिक रूपसे रखा जाय ।

प्रश्न—क्या अगस्त-क्रान्तिके परिणामस्वरूप आपको स्वाधीनता-आन्दोलनके लिए किसी प्रकारका खतरा दिखायी पड़ता है ?

उत्तर—इस आन्दोलनमें लोगोंने जिस साहस, शौर्य आदिका परिचय दिया उसके लिए उचित आदर रखते हुए भी हमको उसकी त्रुटियोंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । एक यह भूल हो सकती है कि हम संग्रामके उस स्वरूपको ही अतिरञ्जित महत्व देने लग जायें और उसको महज डुहरानेकी चेष्टा करें । वास्तविक जन-क्रान्तिके स्वरूपके लिए मजदूरोंकी आम हड़ताल और किसानोंकी लगानवन्दीका होना बहुत आवश्यक है । हमें इस बातका ध्यान रखना है कि आन्दोलन कुछ चुने हुए व्यक्तियोंके समूहोंका आतंकवादी विद्रोह नहीं बरन् देशव्यापी पैमानेपर जनताकी क्रान्ति हो ।^१

सफल क्रान्तिकी तैयारी कीजिये

सन् १९४२ में आन्दोलनके मुकाबलेमें पहले आन्दोलन प्रदर्शनमात्र थे, स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए हमारा यह पहला प्रयास था । इसको हम सच्चे अर्थमें जनताकी क्रान्ति कह सकते हैं । इस क्रान्तिमें लाखों भारतवासियोंने भाग लिया और हजारों नवयुवकोंने प्राणोंकी बाजी लगाकर भारी खतरेको उठाया । इसकी रूपरेखा थी जो उन क्रान्तियोंकी होती है जिनका नेतृत्व जनता स्वयं करती है और जिनकी प्रगति स्वरसेन (स्वतःप्रसूत) होती है । ऐसी क्रान्तिकी जो खूबियाँ होती हैं वह इसमें भी पायी जाती हैं और उसकी त्रुटियाँ भी । सामाजिक क्रान्तिकी दृष्टिसे इसका महत्व नहीं है, किन्तु राष्ट्रीय क्रान्तिकी दृष्टिसे इसका बहुत ऊँचा स्थान है । पुनः यह भी ठीक है कि इस क्रान्तिके फलस्वरूप जनतामें अपूर्व जागृति हुई है और सामाजिक क्रान्तिकी यह आधार-शिला है ।

यह क्रान्ति न अगस्तके प्रस्तावसे सम्बद्ध है । यह प्रस्ताव ऐतिहासिक महत्व रखता है और प्रत्येक दृष्टिसे अपने समयके लिहाजसे यह पूर्ण है । हम इस प्रस्तावको युगके अनुकूल पाते हैं । इसकी राष्ट्रीयता सकुचित नहीं है, किन्तु उदार है और अन्तर्राष्ट्रीयताके साथ इसका सामंजस्य है । राष्ट्रीयताकी भावना आज भी प्रबल है और प्रत्येक युद्धके पश्चात् वह और भी प्रबल हो जाती है । जब रूसमें आज हम राष्ट्रीयताका बोलवाला पाते हैं तब उन देशोंका क्या कहना जो अभी अपनी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रहे हैं । राष्ट्रीयता

इन गुलाम देशों का एक जवर्दस्त शस्त्र है। किन्तु हमारी विशेषता यह है कि जहाँ हम अपनी स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील हैं वहाँ हमारी पूरी सहानुभूति उन सब अधीन देशों के साथ है जो हमारी तरह साम्राज्यवाद के चंगुल से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमारी यह भी घोषणा है कि हम स्वतन्त्र होकर किसी देश की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करेंगे। इस प्रकार हमने अपने पड़ोसी राष्ट्रों को अभयदान किया है और उनका सींहास प्राप्त किया है।

साथ ही साथ हम संसार के अन्य देशों से पृथक् भी नहीं रहना चाहते। हम स्वतन्त्र राष्ट्रों के कुटुम्ब में सम्मिलित होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहते हैं और विश्वशान्ति की स्थापना में सहायक होना चाहते हैं। स्वतन्त्र भारत शान्तिका एक जवर्दस्त समर्थक होगा और सस्कृतियों के आदान-प्रदान में उसका उचित मान होगा। हमको न उपनिवेशों की आवश्यकता है और न किसी दूसरे राष्ट्र के आर्थिक-जीवन पर प्रभुत्व पाने की। हम आत्मतुष्ट हैं, क्योंकि हमारा जन-बल और धन-बल पर्याप्त है। हमारा पुरातन इतिहास भी हमको यही शिक्षा देता है।

जहाँ इस प्रस्ताव में उदार राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता का उल्लेख है वहाँ अपने देश की जनता के हितों की उपेक्षा भी नहीं की गयी है और स्वराज्य के स्वरूप का किंचिन्मात्र दिग्दर्शन भी कराया गया है। हम चाहते हैं कि राष्ट्र की शक्ति जनता के हाथ में आवे अर्थात् किसान और मजदूर जो राष्ट्र की सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं, राज्यशक्तिका संचालन और उपयोग करें। हमारा स्वराज्य मध्यम वर्ग का स्वराज्य नहीं होगा, किन्तु वास्तव में किसान-मजदूर-राज होगा।

यह तो हमारा सन् ४२ का निश्चय है। इसी को कार्यान्वित करने के लिए अग्रस्त-क्रान्ति हुई थी। किन्तु इस प्रस्ताव के सब पहलू क्रान्ति में भाग लेनेवाले के सामने न थे। क्रान्तिकी कोई तैयारी भी न थी। क्रान्तिके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना ही क्रान्तिके लिए पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए उपयुक्त सगठन की आवश्यकता होती है। क्रान्तिका आरम्भ और स्वरसेन होना बहुत अच्छा है। जनता की लाभ की दृष्टि से यही श्रेयस्कर है, किन्तु क्रान्तिके पीछे व्यापक दृष्टि रखनेवाले और क्रान्तिके विज्ञान के समझने वाले कर्णधार चाहिये और चाहिये सगठन जो उनके आदेशों के अनुसार जनता की उन्मुक्त शक्तियों का समुचित उपयोग कर सके। ऐसी क्रान्तिके अवसर पर जनता का नैतिक बल बहुत बढ़ गया है और लाखों आदमी मानवता के सद्गुणों का अपने में अनुभव करते हैं। क्रान्तिके कार्य को यही बात सुगम बनाती है और सफल क्रान्तिकी रक्षा करने में भी यही समर्थ होती है।

क्रान्तिकी सफलता के लिए सेना का विद्रोह करना, कम से कम उसका तटस्थ रहना, आवश्यक होता है। सन् ४२ में सेना का सहयोग हम भारत में पा सके, यद्यपि देश के बाहर आजाद-हिन्द-फौज के सगठन ने भारतीय सेना के एक अंश में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। यदि कहीं यह सुयोग देश के भीतर प्राप्त होता और राष्ट्र के दो अंग—नागरिक और सैनिक—अलग-अलग काम न कर एक सूत्र में आवद्ध होते तो क्रान्तिकी

सफलता निश्चित थी। अन्य त्रुटियोंके साथ-साथ यह एक भारी कमी थी जिसकी ओर भी ध्यान देनेकी आवश्यकता है।

६ अगस्त सन् ४२ हमारे इतिहासमें सदा स्मरणीय रहेगा, किन्तु यदि हम उसकी वैज्ञानिक विवेचना कर उससे उचित उपदेष्टा न लेंगे और अपनी त्रुटियाँ और दुर्बलताओंका अध्ययन कर उनके दूर करनेकी चेष्टा न करेंगे तो हम अगस्त-क्रान्तिका पूरापूरा लाभ न उठा सकेंगे। हमको यह न भूलना चाहिये कि हमने अपने लक्ष्यको अभी नहीं पाया है। ६ अगस्तके दिन हमको इस निश्चयको दुहराना चाहिये और उसको कार्यान्वित करनेके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिये।^१

मध्यकालीन सरकार

इतिहासमें जिस स्थायी क्रान्तिकारी गवर्नमेण्टका उल्लेख मिलता है वह एक भिन्न वस्तु है। उसका निर्माण सफल क्रान्तिके पश्चात् होता है। उसका कार्य राष्ट्रीय विधान-परिषद्को आमंत्रित करना होता है। वही विधान-परिषद्का चुनाव करती है और इसका प्रबन्ध करती है कि प्रत्येक वॉलिग पुरुष और स्त्रीको स्वच्छन्द मत देनेका अधिकार हो तथा चुनावमें किसी प्रकारकी अनियमितता न हो। पुनः यही स्थायी गवर्नमेण्ट परिषद्को राष्ट्रका भावी विधान बनानेका पूर्ण अधिकार देती है। इस गवर्नमेण्टका यह भी कर्तव्य होता है कि जब तक नयी गवर्नमेण्ट अस्तित्वमें नहीं आती तबतक वह देशका शासन करे तथा परिस्थितिके अनुसार जनताके हितोंकी रक्षाके लिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करे। हममें लेनिनके अनुसार स्थायी गवर्नमेण्टको कमसे कम निम्नलिखित कार्यक्रमको कार्यान्वित करना चाहिये था—निरंकुश शासनका अन्त, लोकतन्त्रकी स्थापना, हर वॉलिग पुरुष और स्त्रीको वोट देनेका अधिकार, वॉलेट द्वारा वोट, व्यक्तिकी स्वतन्त्रता, भाषाकी स्वतन्त्रता, प्रेसकी स्वतन्त्रता तथा सभा करनेकी स्वतन्त्रता, राष्ट्रोंको स्वभाग्य-निर्णयका अधिकार, मजदूरोंके लिए आठ घण्टेका दिन तथा उनके स्वत्वोंकी रक्षाके लिए कानून आदि। यह कार्यक्रम देगकी तात्कालिक परिस्थितिके अनुसार होता है। हमारे यहाँ परिस्थिति ऐसी हुई कि विधान-परिषद् पहले बन गयी और मध्य-कालीन सरकार पीछे बनी। किन्तु केवल इससेकोई अन्तर नहीं आता क्योंकि यहाँ चुनावमें कोई अनियमितता नहीं हुई। अन्तर चुनावके प्रकारमें है। यहाँ व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा चुनाव हुआ है और इन सभाओंके सदस्योंका चुनाव वॉलिग मताधिकारके आधारपर नहीं हुआ है। यदि मध्यकालीन सरकारका निर्माण पहले हो गया होता तब भी यही स्थिति होती, क्योंकि कांग्रेसने चुनावके इस प्रकारको स्वीकार कर लिया था। यह भी स्पष्ट है कि यहाँकी विधान-परिषद् एक ऐसी संस्था नहीं है जिसको पूर्ण अधिकार प्राप्त हों कुछ सिद्धान्त उसके लिए निरूपित कर दिये गये हैं। इनको माननेके लिए वे बाध्य हैं

अन्यथा उसको विधान बनानेकी स्वतन्त्रता है। पुनः क्रान्तिके सफल होनेके पश्चात् उसका निर्माण नहीं हुआ है। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेण्टने भारतके स्वतन्त्रताके हकको तथा भावी विधान बनानेके हकको स्वीकार कर लिया है। किन्तु उसकी एक शर्त यह भी है कि अल्पसंख्यक समुदायोंके हितोंकी रक्षाका विधान दिया जाय तथा उसके साथ कुछ प्रश्नोंके निपटारेके लिए सन्धि की जाय। ये प्रश्न क्या हैं और उनका निपटारा ब्रिटिश गवर्नमेण्ट किस प्रकार चाहती है यह हमको नहीं बताया गया है। मुझको यही बात सबसे अधिक खटकती है।

रास्तेके खतरे

इसमें सन्देह नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेण्टने समझ लिया है कि वह अब भारतपर पुराने ढंगसे शासन नहीं कर सकती। दिन प्रति दिनके शासनका काम वह भारतको सौंपना चाहती है, किन्तु अपने आर्थिक हितोंको वह सुरक्षित रखना चाहती है, क्योंकि यदि उसका व्यापार बढ़ता नहीं तो वह इंग्लैण्डकी जनताको सन्तुष्ट नहीं रख सकती। वह यह भी चाहती है कि फौजी दृष्टिसे भारत उसका मित्र रहे तथा युद्धकी अवस्थामे भारतसे उसको पूरी सहायता मिले। इस सम्बन्धमे ब्रिटिश सेनाके एक भागको वह हमारे देशमे कुछ वर्षोंके लिए रखनेकी माँग कर सकती है। ब्रिटिश अफसरोद्वारा भारतीय सेनाकी शिक्षा हो, ब्रिटेनसे ही लड़ाईका सामान खरीदा जाय तथा युद्धकी अवस्थामे उसको मार्गकी सुविधा रहे और हर तरहकी मदद दी जाय, ये सब माँगें भी हो सकती हैं। मित्र, ईराकमे ऐसा ही हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेण्टका यह रवैया रहा है कि सन्धि-पत्रकी पहली धारामे वह पूर्ण स्वतन्त्रताको स्वीकार करती है और अगली धाराओंमे उसपर अनेक प्रकारके प्रतिबन्ध लगा देती है। मुझे सबसे अधिक भय सन्धि-पत्रकी शर्तोंसे है और आज जब उसकी उपेक्षा की जाती है तो मुझे आश्चर्य होता है। मेरी रायमे जहाँ और बातोंका स्पष्टीकरण कराया गया, वहाँ इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिये था। पुनः वालिग मताधिकारके अनुसार विधान-परिषद्का न चुना जाना एक बड़ी कमी है। वालिग मताधिकार स्वयं एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त है। यदि विधान-परिषद्का चुनाव इस सिद्धान्तके अनुसार होता तो देशका वातावरण ही दूसरा होता। उस अवस्थामे जनता सजग होती, विधान-परिषद्से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित होता और वह परिषद्के कामोंमे दिलचस्पी लेती। क्रान्तिके सफल होनेके पश्चात् तो जनताकी सक्रियता बहुत बढ़ जाती है। इस लाभसे हम वञ्चित हैं।

हमारे देशमे जो प्रयोग इस समय हो रहा है वह एकदम नया है। इसकी सफलताके सम्बन्धमे मतभेदकी सम्भावना बनी रहती है। जो इस प्रयोगके पक्षमे हैं वे भी निश्चित रूपसे नहीं कह सकते कि इसके द्वारा हमारा लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए वे क्रान्तिकारी मनोवृत्तिको बनाये रखने और अपने सगठनोंको सुदृढ़ बनानेका उपदेश देते हैं। वे इसकी आशा अवश्य रखते हैं कि समझौतेके मार्गसे सफलता मिलेगी अन्यथा वे समझौता स्वीकार ही क्यों करते ?

एक कमजोरी और है जिसकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है । जब समझौतेसे काम होता है तब विधान-परिपद्मे प्रधान पक्षोंका सम्मिलित होना आवश्यक हो जाता है । मुसलिम लीगके बाहर रहनेसे परिपद् कमजोर है ।

मध्यकालीन सरकारकी स्थिति चाहे जो हो, जब वह बन गयी तो प्रश्न यह है कि इसके प्रति हमारी नीति क्या हो । कांग्रेसने एक कदम उठाया है, एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है । लीगका केवल असहयोग नहीं है, उसका प्रबल विरोध भी है । समय भी असाधारण है, प्रश्न बड़े जटिल हैं, मजदूरोमे घोर अशान्ति है, आये दिन हड़ताले होती हैं । ऐसे नाजुक समयमे कांग्रेसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है । यह उसकी परीक्षाका समय है । जनताको कांग्रेससे बड़ी आशा है और उसको स्थितिका पूरा पता नहीं है । इससे दिक्कत और बढ़ गयी है । यदि कांग्रेस किसी कारण असफल रही तो उसकी प्रतिष्ठाको भारी धक्का लगेगा । देशकी बहुत बड़ी क्षति होगी, इसलिए किसीका कोई मत क्यों न हो, सबको सफलताकी कामना करनी चाहिये और इसका पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि कांग्रेसकी शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा बढ़े ।

मध्यकालीन सरकार क्या करे

मध्यकालीन सरकारसे हमे पूरा लाभ भी उठाना चाहिये । यह सरकार स्थायी क्रान्तिकारी गवर्नमेण्टके समकक्ष हो या न हो, इसका कर्तव्य हो जाता है कि लोकतन्त्रकी स्थापनाके लिए यह जितना आगे जा सकती है जाये । लोकतान्त्रिक शासनकी स्थापना समाजवादके मार्गकी पहली मंजिल है, और अस्थायी क्रान्तिकारी गवर्नमेण्टका काम लोकतन्त्रके मार्गको प्रशस्त करना है । यह काम निरकुश शासन तथा सामन्तशाहीका अन्त करने, जनताके लाभके लिए उचित कानून बनाने तथा लोकतन्त्रकी भूमिका कायम करनेसे सिद्ध होता है । इस दृष्टिसे मध्यकालीन सरकारको नागरिकताके अधिकारोंकी रक्षा तथा उनकी सीमाकी वृद्धि करनी चाहिये । मजदूरोंके कामके घण्टे कम करना चाहिये, उनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिये, उनके लिए अन्य सुविधाओंका आयोजन करना चाहिये, तथा ट्रेड-यूनियन आन्दोलनको पुष्ट करना चाहिये । यातायातके मार्ग, बिजली और कौयलेकी खानोंको राष्ट्रकी सम्पत्ति करार देना चाहिये । उद्योग व्यवसायोंका जनताके लाभके लिए नियन्त्रण होना चाहिये । प्रान्तीय क्षेत्रमे जमींदारी प्रथाका अन्त, सहयोग समितियों और ग्राम-पंचायतोंकी स्थापना, स्थानीय स्वायत्त-शासन-सुधार तथा सम्मिलित निर्वाचन प्रणालीकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये । केन्द्रीय सरकारको वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अन्वेषणकी व्यवस्था करनी चाहिये । कृषिकी उन्नतिके उपायोंको निर्धारित कर योजनाएँ बनानी चाहिये और उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये तथा शिक्षाके प्रसारके लिए प्रान्तोंको धनसे सहायता करनी चाहिये । देशी राज्योपर प्रभाव डालकर वहाँ उत्तरदायी शासनकी स्थापना करनी चाहिये । कांग्रेसको मुसलिम जनतासे अधिक सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और उसे अपने प्रभावमे लाना चाहिये । जनताको शासनके सस्पर्शमे लाना चाहिये । जनतामे लोकतन्त्रकी भावना बढ़े, उसका आत्म-विश्वास बढ़े इसका प्रयत्न

करना चाहिये । आजकी कपड़े और अनाजकी समस्याको केन्द्रीय सरकार ही हल कर सकती है । कपड़ेकी देहातमे वडी कमी है, इस कमीको पूरा करना है । फिलहाल राशनिंग रहना जरूरी है । इस बातकी चेष्टा करते रहना चाहिये कि जितनी जल्दी यह हट जाय उतना ही अच्छा है । जनताको आजकी स्थिति बतलानेकी वडी जरूरत है । इङ्गलैण्डमे युद्धके बाद भी राशनिंग जारी है । युद्धकालकी अपेक्षा आज इसमे ज्यादा कडाई है । संसारके खाद्यपदार्थोंकी समस्या वडी कठिन है । अमेरिकाने कंट्रोल उठा लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ वस्तुओंकी कीमत बहुत बढ़ गयी । इस कारण अमेरिकाने बाहर भेजनेके लिए गेहूँकी खरीद बन्द कर दी है । संसारके अन्य देशोसे हमको अन्न मिलेगा या नही यह अनिश्चित है । हम काफी अन्न पैदा भी नही करते । जनताको यह सब दिक्कतें बतानी चाहिये । यह झूठी शान न होनी चाहिये कि हम सब कुछ कर सकते हैं । एक कठिन समस्या साम्प्रदायिक शान्ति बनाये रखनेकी है । इन सब कामोके करनेके लिए कांग्रेस तथा जनताको गवर्नमेण्टपर बराबर दबाव डालते रहना चाहिये तथा उसकी सहायता हर प्रकारसे करनी चाहिये । इन सब कामोसे जनताकी शक्ति बढ़ेगी और यही प्रधान वस्तु है ।^१

स्वाधीनता दिवस और हमारा कर्तव्य

स्वाधीनता दिवसके अवसरपर सदाकी भाँति इस वर्ष भी देशके करोड़ों नर-नारी विदेशी शासनका अन्त करने और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञाको दुहरायेगे । हमारी आजादीकी लड़ाई आज जिस मंजिलमे पहुँच चुकी है उसे देखते हुए, इस बातको ध्यानमे रखकर कि विधान परिषद्ने नेहरूजी द्वारा उपस्थित किये गये लक्ष्य-सम्बन्धी उस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया है जिसमे कहा गया है कि परिषद् स्वतन्त्र भारतीय लोकतन्त्र-का विधान प्रस्तुत करेगी आवश्यकता इस बातकी थी कि इस अवसरपर हम विदेशी आधिपत्यका अन्त करनेकी प्रतिज्ञा नही बरन् उसके स्थानपर देशकी स्वाधीनताकी घोषणा करते और उसपर आक्रमण करनेवाली शक्तियोंका मुकाबला करनेकी प्रतिज्ञा करते । किन्तु स्थिति यह है कि स्वाधीनता दिवसके प्रतिज्ञा-पत्रमे 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव सम्बन्धी जो पैराग्राफ था वह भी निकाल दिया गया है । हमारे नेताओंकी रायमें जब कि कांग्रेस शासकोके साथ समझौतेके द्वारा स्वाधीन भारतका विधान बनाने जा रही है ऐसे अवसरपर भारत छोड़ोके नारेका दुहराना शिष्टाचारके विरुद्ध होगा । कितने ही नेताओंने सार्वजनिक रूपसे यह मत व्यक्त भी किया है कि ब्रिटिश शासक स्वयं भारत छोड़कर जा रहे हैं, इस माँगको पूरा करानेके लिए अब हमे लड़नेकी, जनक्रान्तिका मार्ग अपनानेकी आवश्यकता न होगी ।

ब्रिटेनको परेशानियाँ

मेरी रायमें परिस्थितियोंका सूक्ष्म विश्लेषण करनेपर इस प्रकारकी धारणा बना लेनेके यथेष्ट प्रमाण नहीं मिलते कि ब्रिटिश शासक अपने साम्राज्यवादी स्वार्थोंको तिलांजलि देकर स्वयमेव यहाँसे विदा हो जाना चाहते हैं और अब भविष्यमें उनके विरुद्ध जनसंघर्षकी तैयारी अनावश्यक हो गयी है। यह सही है कि युद्धोत्तर विश्वमें ब्रिटेनकी स्थिति बहुत निर्बल हो गयी है। ब्रिटिश नौसेनाकी शक्ति क्षीण हो चली है और नौसेनाका पुराना महत्त्व भी घट चला है। ब्रिटिश साम्राज्यके कनाडा और आस्ट्रेलिया सरीखे देश अपनी रक्षा तथा अन्य आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए ब्रिटेनका नहीं, वरन् अमेरिकाका मुँह ताकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत औपनिवेशिक स्वाधीन देश अब समूचे ब्रिटिश साम्राज्यकी रक्षाका भार अपने ऊपर न लेकर केवल उस क्षेत्रकी रक्षामे ही विशेष रुचि रखते हैं जिसमें वे स्वयं अवस्थित हैं। परमाणु वम तथा अन्य भयानक सामरिक आविष्कारोंको ध्यानमें रखकर, ब्रिटेनको अपनी सामरिक योजनाओंमें परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। संसारके विभिन्न देशोंमें लगी हुई ब्रिटेनकी पूँजीका बड़ा भाग समाप्त हो चुका है और आज भारत तथा मिस्र सरीखे देशोंका बड़ा ऋण ब्रिटेनपर चढ़ा हुआ है। अमेरिकाके विराट् औद्योगिक विस्तार तथा पूर्वय यूरोपके रूसी प्रभाव-क्षेत्रमें चले जानेके कारण, ब्रिटेनके मालको खरीदनेवाला बाजार भी बहुत सकुचित हो गया है। ब्रिटेनके कल-कारखाने ध्वस्त हो गये हैं और उसकी घरेलू आर्थिक समस्याएँ गम्भीर रूप धारण कर रही हैं। यदि अमेरिकाका ऋण ब्रिटेनको न मिल गया होता तो उसकी अवस्था बहुत ही शोचनीय होती। यह भी सही है कि महायुद्धके परिणामस्वरूप उपनिवेशोंकी जनतामें जागरणकी जो लहर आयी है, जिस प्रकार विद्रोहकी भावना सेनातकमें जा पहुँची है और आर्थिक समस्याओंने जो भयंकर रूप धारण कर लिया है उसे देखते हुए उपनिवेशोंमें सगिनोके बलपर अपने शासनको बनाये रखना अथवा गोरी नौकरशाहीके प्रबन्धके बलपर आर्थिक समस्याओंको हल कर सकना ब्रिटिश शासकोंकी शक्तिके बाहरकी बात है।

शासकोंकी नयी योजना

किन्तु अपनी सामयिक स्थितिकी निर्बलता और आर्थिक स्थितिकी गम्भीरता तथा उपनिवेशोंकी बदली हुई परिस्थिति और पुराने ढंगसे शासन करनेकी असमर्थताको देखते हुए भी ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ हिम्मत नहीं हार बैठे हैं। परिवर्तित परिस्थितियोंमें किस प्रकार अपने साम्राज्यवादी स्वार्थोंको अधिकसे अधिक सुरक्षित रखा जा सकता है वे बड़ी कुशलताके साथ इसके लिए अपनी योजनाएँ बना रहे हैं। दिन-प्रतिदिनके शासनका भार वे उपनिवेशोंके राजनीतिक दलोंको सौंप देनेके लिए तैयार हैं किन्तु आज उपनिवेशोंमें ब्रिटिश पूँजी तथा तैयार मालके लिए दूसरे देशोंकी अपेक्षा जो विशेष सुविधाएँ उन्हें प्राप्त हैं उनका परित्याग करनेके लिए तैयार नहीं हैं। जबतक किसी देशको अपनी इच्छाके अनुसार अपना आर्थिक विकास करने तथा अपनी वैदेशिक नीति और रक्षा-नीतिको

अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार संचालित करनेकी पूर्ण स्वाधीनता न हो तबतक वह कैसे स्वाधीन कहला सकता है ।

ब्रिटिश शासक आज सगीनोके बलपर ये सुविधाएँ नहीं बनाये रख सकते, इसलिए मुसलिमलीग देशी नरेश तथा दूसरी प्रतिगामी शक्तियोंकी पीठ थपथपाकर उन्हें उत्तेजित करके और उनकी बहुत-सी काररवाइयोको तरह देकर वे अपना काम बनाना चाहते हैं । देश विभिन्न प्रतिस्पर्धी भागोमें बँटा रहे, विभिन्न भागोके निवासी आपसमें मिलकर समूचे देशकी समृद्धिकी योजना बनानेके स्थानपर एक दूसरेको भय और ईर्ष्याकी दृष्टिसे देखते रहे और अपने क्षेत्रकी समृद्धिकी ओर ही उनका ध्यान रहे इसीमें वे आजकी परिस्थितियोंमें अपने इन दोनों आधारभूत स्वार्थोंकी सुरक्षाका उपाय पाते हैं । जिस प्रकार भारतको वे 'हिन्दुस्तान', 'पाकिस्तान' और 'राजस्थान'में बाँटना चाहते हैं उसी प्रकार फिलिस्तीन-को भी अरविस्तान, यहूदिस्तान और अग्नेजिस्तानके तीन टुकड़ोमें बाँटना चाहते हैं इसी प्रकार नील नदीकी घाटीमें सूडानका पाकिस्तानी अस्तित्व अलग बनाये रखना चाहते हैं । आजकी परिवर्तित परिस्थितियोंको देखते हुए दूसरे पुराने साम्राज्यवादी देश भी ब्रिटेनकी कूटनीतिका अनुसरण कर रहे हैं । फ्रेंच शासक हिन्दचीनमें कोचीन-चीनके रूपमें पाकिस्तानकी सृष्टि कर रहे हैं ।

प्रतिगामी शक्तियोंको उत्तेजना

जहाँ ब्रिटिश शासक उपनिवेशोके भीतर अपने स्वार्थोंकी रक्षाके लिए प्रतिक्रियागामी शक्तियोंको उभाड़ रहे हैं, वहाँ साम्राज्यपर बाह्य आक्रमणके प्रति भी वे पूर्णरूपेण सजग एवं सतर्क हैं । ब्रिटेनको अपने साम्राज्यके लिए रूससे बड़ा खतरा मालूम पड़ता है । रूसका मुकाबला करनेके लिए ब्रिटिश शासक अमेरिकाके साथ गठबन्धन कर रहे हैं । अमेरिका आज पूँजीवादका सबसे बड़ा गढ़ है । उसका मौन साम्राज्यवाद ससारके वृहत् भागपर फैला है और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । किन्तु इसकी परवाह न करते हुए ब्रिटिश शासक अमेरिकाके साथ मिलकर अपनी सैनिक-रक्षाकी योजनाएँ बना रहे हैं । मध्यपूर्व और भूमध्यसागरके प्रदेशोके आन्तरिक मामलोमें ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर हस्तक्षेप कर रहे हैं । अफ्रिकामें ब्रिटेन और अमेरिकाके जो हथियारके कारखाने खुल रहे हैं और लीबीया, नाइजेरिया और सूडानको सैनिक अड्डोके रूपमें विकसित करनेकी योजना बन रही है उसका उद्देश्य साम्राज्य-रक्षाकी तैयारी ही है ।

ब्रिटिश शासकोंकी पुरानी चाल

जबतक ब्रिटिश फौजे हमारे देशसे नहीं चली जाती, अपने देशके सैनिक साधनोका उपयोग करनेकी पूर्ण स्वाधीनता हमें नहीं प्राप्त होती, युद्धकालमें ब्रिटेनको अपने सैनिक अड्डोका उपयोग करनेकी शर्त हमें माननी पड़ती है और अपने देशका आर्थिक विकास करनेके लिए हम पूर्ण स्वतन्त्र नहीं होते, ब्रिटिश मालके लिए विशेष सुविधा देनी पड़ती है, तबतक केवल देशके शासन-प्रबन्ध देशवासियोंके हाथमें आ जाने मात्रसे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि देश स्वतन्त्र हो गया । ब्रिटिश राजनीतिज्ञोका यह पुराना तरीका

है कि वे अपनेको संकटग्रस्त देख उपनिवेशोंकी स्वतन्त्रता भी स्वीकार कर लते हैं, किन्तु जहाँ कि वे एक और सिद्धान्तरूपमें स्वाधीनता स्वीकार करते हैं वहाँ मित्रताकी मन्धिके वहाने दूसरी ओर ऐसी शर्तें लगा देते हैं कि स्वाधीनता केवल आन्तरिक गौरवकी वस्तु रह जाती है। मित्रकी स्वाधीनता कबकी स्वीकार की जा चुकी है किन्तु आज भी ब्रिटिश फौजे वहाँसे बिदा नहीं हुई, ईराककी सन्धिके अनुसार युद्धकी आशंका होनेपर ही ब्रिटिश फौजे वहाँ भेजी जा सकती है, किन्तु आज युद्धकी आशंका न होते हुए भी भारतीय फौजें बसराके बन्दरगाहमें डटी हुई हैं। ट्रांसजार्डनको इसी प्रकारकी स्वाधीनता कुछ मास पूर्व ब्रिटेनने प्रदान की है।

पूँजीपतियोंका गठबन्धन

नामकी स्वाधीनता हुए भी किस प्रकार औद्योगिक दृष्टिसे अनुन्नत और सैनिक दृष्टिसे निर्बल देश वहाँके पूँजीवादी शासकों तथा विदेशी कूटनीतिज्ञोंकी सहायतामें साम्राज्यवादी शोषणके शिकार बनाये जा सकते हैं इसका ज्वलन्त उदाहरण एशियाकी सबसे बड़ी जनसंख्यावाला देश हमारा पड़ोसी चीन है। चीन अमेरिकाका उपनिवेश नहीं है, किन्तु चीनी कम्युनिस्टोंके विरुद्ध च्यांगकाई शेककी सरकारकी और पूँजीवादी नेतृत्वसे प्रभावित कोमितांग दलकी अमेरिका शस्त्रास्त्रोंसे सहायता कर रहा है और ऋणकी लम्बी रकम देकर केन्द्रीय सरकारकी तवाह आर्थिक अवस्थाको संभाल रहा है। बदलेमें च्यांगकाई शेककी अनुगृहीत सरकार अमेरिकन पूँजीको चीनमें सब प्रकारकी सुविधाएँ देनेकी तैयार है। आजके स्वदेशीकी भावनाको जमानेमें पूरी तरह अमेरिकन पूँजीसे चलाये जानेवाले कारखाने भले ही न खड़े किये जायें, पर अमेरिकन और चीनी दोनों ही प्रकारकी सम्मिलित पूँजीसे अनेक कारखाने चीनमें खुलेंगे और देशी और विदेशी पूँजीपति सम्मिलित रूपसे चीनी जनताका शोषण करेंगे। जब अमेरिका चीनी कम्युनिस्टोंके खिलाफ कोमितांगकी सहायता कर रहा है तो अमेरिका और रूसका युद्ध छिड़नेपर कोमितांग-दल निश्चय ही रूसके विरुद्ध अमेरिकाकी मदद करेगा। यह सहयोगात्मक साम्राज्यवाद ही आजके युगका सबसे बड़ा संकट है जिससे जनताको सावधान होनेकी आवश्यकता है।

अतः आइये, स्वाधीनता दिवसके इस पुण्य पर्वपर हम प्रतिज्ञा करें कि विदेशी आधिपत्यके प्रत्येक रूपका जबतक हम अन्त न कर लेंगे तबतक हम अपने साम्राज्य-विरोधी क्रान्तिकी तैयारी बन्द न करेंगे और चैनकी सास न लेंगे। यदि हमारे पुराने और अनुभवी नेता यह समझते हैं कि समझौतेके रास्तेसे स्वराज्य मिल सकता है तो वह समझौतेकी कोशिशमें लगे रहे, किन्तु युद्धकी तैयारीको भी जारी रखें। बर्माके फासिज्म-विरोधी जन-संघके युवक नेता श्री आगसानके शब्दोंमें हम अच्छेसे अच्छे परिणामकी आशा करें, किन्तु बुरेसे बुरे परिणामके लिए तैयार रहें।^१

कांग्रेस किधर

यह कहा जाता है कि कांग्रेस दुर्बल और क्षीण होती जाती है, कांग्रेसमें आपसकी दलबन्दी और फूट बढ़ती जाती है, अनुशासनकी कमी होती जाती है तथा कांग्रेस कार्यकर्ता माधारणतः अपने आदर्शोंसे च्युत होते जाते हैं। कांग्रेसको इस नये खतरेसे बचानेके लिए कई सुझाव पेश किये गये हैं। कोई कहता है कि कांग्रेसके भीतर अनेक विचारधाराओंको स्थान देनेसे यह गड़बड़ी उत्पन्न हो गयी है, इसलिए यदि कांग्रेसके भीतर पार्टियोंको स्थान न दिया जाय तो यह बुराई दूर हो सकती है। इस सिलसिलेमें यह कहा जाता है कि अब समय आ गया है कि कांग्रेसको पार्टीका स्वरूप देना चाहिये। अब वह स्वतन्त्रता अर्जित करनेके लिए विविध वर्गोंका संयुक्त मोर्चा मात्र नहीं रह गया है। उनका कहना है कि जबतक विविध दलोंके लिए उसमें स्थान रहेगा तबतक अनुशासनका ठीक-ठीक पालन नहीं हो सकेगा। इन मित्रोंका कहना है कि वर्तमान अवस्थामें सब कांग्रेसजनोंकी समान रूपसे कांग्रेसके प्रति वफादारी नहीं है तथा प्रत्येक दलका सदस्य सर्वोपरि अपने दलमें प्रतिपन्न होता है। कांग्रेसमें चुनावके अवसरपर जो अत्याचार होता है उसके रोकनेका यह उपाय निर्धारित किया जाता है कि कांग्रेसके साधारण सदस्योंको मत देनेका अधिकार न होना चाहिये। निर्वाचन क्षेत्र केवल कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंका होना चाहिये जिनके लिए कुछ शर्तोंका पालन करना अनिवार्य होना चाहिये। कांग्रेसकी ओरसे कांग्रेस-विधानमें सशोधन करनेके लिए जो उपसमिति नियुक्त की गयी थी उसकी यही सिफारिश है।

हमारा निवेदन है कि जबतक रोगका निदान ठीक-ठीक नहीं होगा तबतक रोगका इलाज भी न होगा। ऊपर जिन उपायोंका निर्देश किया गया है वह इतने प्रभावशाली नहीं हैं कि उनके प्रयोगसे रोगके आरामकी आशा की जा सके। चुनावके समयकी बुराईयोंको रोकनेके लिए चुनावकी प्रथाको ही अप्रजातांत्रिक बना देना एक दोषका निरसन करना और एक दूसरे घातक दोषको निमज्जण देना है। जीवनके अन्य विभागोंमें ग्राम-पंचायतसे लेकर व्यवस्थापिका सभातक साधारण चुनावको कायम रखना और केवल कांग्रेसके चुनावके लिए जनतंत्रके सिद्धान्तको ढीला करना उचित नहीं प्रतीत होता। हाँ! यह ठीक है कि कांग्रेसके सगठनकी तुलना इन संस्थाओंसे पूर्ण रूपसे नहीं की जा सकती। कांग्रेसके पदाधिकारियोंके लिए विशेष योग्यताका नियम रखना आवश्यक है, किन्तु चुनावका तरीका इस प्रकार बदल देना कि जनतंत्रके सिद्धान्तका परित्याग करना पड़े उचित नहीं है। पुनः कांग्रेस वालिग मताधिकार देनेके पक्षमें है। इस आधारपर जो चुनाव होंगे उनमें अनाचारकी आशंका सदा बनी रहेगी। इस अनाचारको रोकनेके लिए उचित उपायोंका विधान करना आवश्यक है, किन्तु इसके लिए वालिग मताधिकारका ही परित्याग करना उचित नहीं होगा। लोकतन्त्र-पद्धतिके अनाचार किसी-न-किसी अंश या रूपमें सर्वत्र पाये जाते हैं, किन्तु इसके लिए कोई इस पद्धतिके परित्यागकी सिफारिश नहीं करता। विशेषकर जब हम लोकतन्त्र शासनकी स्थापना करना चाहते

है तो यह उचित प्रतीत होता है कि जो संस्था इस सिद्धान्तको समाजमें प्रतिष्ठित करना चाहती है उसे स्वयं अपना संचालन इसी पद्धतिके अनुसार करना चाहिये ।

पुनः यह कहा जाता है कि विविध विचारधाराओंपर आश्रित अनेक दलोंके समावेशसे कांग्रेसकी अवस्था बिगड़ रही है और उसका अनुशासन शिथिल पड़ रहा है तथा अब जब स्वतन्त्रता प्राप्त-सी हो गयी है तब कांग्रेसको संयुक्त मोर्चा बनाये रखनेका कोई अर्थ नहीं है । इन सज्जनोंका कहना है कि कांग्रेसके उद्देश्यकी पूर्ति हो जानेसे कांग्रेसके सम्मुख स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेका ही प्रश्न रह जाता है किन्तु यह भ्रम भूल जाते हैं कि कांग्रेसकी बीमारीका यह कारण नहीं है । ये कांग्रेसजन जो अपनेको कांग्रेसके अनन्य भक्त कहते हैं और एक नेता एक पताकाका नारा लगाते हैं, आपसमें ही लड़ा करते हैं । वह अपनी महत्वाकांक्षाको पूरा करनेके लिए व्यक्तिगत दलोंकी सृष्टि करते हैं और इतनी दुरी तरह लड़ते हैं कि लज्जासे सिर झुका लेना पड़ता है । उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बात किसीसे छिपी नहीं है । अतः यदि विविध दल कांग्रेसमें बाहर कर दिये जायँ तब भी रोगसे छुटकारा नहीं मिलेगा । नवीन व्यक्तिगत दलोंकी सृष्टि होगी और आज भी इनकी कमी नहीं है । इस सम्बन्धमें एकमात्र कांग्रेसनिष्ठकी जो बात कही गयी है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है । मनुष्यकी मूलनिष्ठा जीवनके आधारकी और सामाजिक मूल्योंमें होती है । इसीसे प्रेरित होकर वह विविध संस्थाओंमें सम्मिलित होता है और उनका परित्याग करता रहता है । एक समय एक व्यक्ति एक संस्थाका सदस्य हो सकता है और उसकी निष्ठा समान रूपसे दोनोंमें हो सकती है । ऐसे अवसर आ सकते हैं जब इन दो निष्ठाओंमें परस्पर विरोध उत्पन्न हो, किन्तु यदि उस व्यक्तिके लिए दोनोंकी आवश्यकता है तब वह इस विरोधका परिहार कर लेगा । अन्ततोगत्वा इसका निर्णय उस व्यक्तिके मूल्य और आदर्श ही करेंगे कि उसको किस संस्थामें रहना है । कोई संस्था अपने सदस्योंसे इतना ही चाह सकती है कि वे उसके निर्णयोंका पालन करें । इससे अधिक चाहना तथा उनके आत्मविश्वास और सिद्धान्तोंको सीमित करनेकी चेष्टा करना सर्वथा अनुचित होगा ।

इस सम्बन्धमें हम यह भी कहना चाहते हैं कि यदि संयुक्त मोर्चेका काम समाप्त हो गया है और कांग्रेस अपने लक्ष्यको प्राप्त कर चुकी है, अथवा जून १९४८ में प्राप्त कर लेगी तो उस समय कांग्रेसके अस्तित्वकी ही क्या आवश्यकता है । विभिन्न विचार रखनेवाले तथा स्वतन्त्र भारतके लिए विभिन्न कार्यक्रमको प्रस्तुत करनेवाले सभीने कांग्रेसकी सेवा की है और सबके उद्योग और प्रयत्नका ही यह फल है कि देश स्वतन्त्र होने जा रहा है । ऐसी अवस्थामें स्वतन्त्र हो जानेपर कांग्रेस संस्थाको जीवित रखना, युद्धसे सब दलोंको पृथक् कर देना तथा एक विचारके लोगोंको उसपर एकाधिकार कायम करने देना कहाँ तक उचित है ? कांग्रेस किसीकी भी दास नहीं है । यह समस्त राष्ट्रकी सम्पत्ति है । इसके निर्माणमें सबका हाथ रहा है । अतः यह कहना अमुक-अमुक निकल जावे और 'हम' अकेले इसका संचालन करें सर्वथा अन्याय है । फिर यह 'हम' हैं कौन ? इसका निर्णय कौन करेगा ? हमको यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि महात्माजीका यह विचार है

कि देशके स्वतन्त्र होनेपर कांग्रेसकी आवश्यकता न रह जायगी । आचार्य कृपलानीने भी इसी तरहका विचार व्यक्त किया है । कुछ और नेता भी इसी विचारके मालूम होते हैं, किन्तु अधिकांश नेता, कांग्रेस-संस्थाको जीवित रखना चाहते हैं । हम समझते हैं कि यह दूसरे वास्तविकताको ज्यादा पहचानते हैं । अधिकारारूढ होनेपर अपनी सत्ता बनाये रखनेके लिए कांग्रेसकी प्रतिष्ठा और मर्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, इस लाभको वह नहीं छोड़ना चाहेंगे । कुओमिनतांग भी आजतक एक दलके रूपमें जीवित रहा है और आज जब अन्य दलोसे समझौता करनेको बाध्य हो रहा है तब भी वह जनतान्त्रिक ढंगको स्वीकार करनेके लिए अपनी प्रस्तुतता दिखाता है । किन्तु यदि महज इस कार्यके लिए कांग्रेसको जिन्दा रखना है तो फिर यह समझ लेना चाहिये, कि उसका वह पुराना स्वरूप नहीं रहेगा । तब कांग्रेसकी राजनीति बदल जावेगी और वह विशेष रूपसे चुनावकी एक मशीन बन जावेगी । ऐसी अवस्थामें ऐसी संस्थाओंमें जो दोष आ जाते हैं वह कांग्रेसमें भी आ जावेंगे । कुओमिनतांगका उदाहरण हमारे सम्मुख है । फिर त्याग और तपस्याका वातावरण कांग्रेसमें नहीं रहेगा और शक्तिके लिए छीना-झपटी शुरू हो जावेगी । भविष्यमें उसको एक दूसरे प्रकारके नेतृत्वकी आवश्यकता होगी । वैधानिक पण्डितोंका महत्त्व बढ़ेगा । किन्तु आज हमारी नीति सर्वथा अस्पष्ट है । एक ओर कहा जाता है हमारा कार्य समाप्त हो गया है और दूसरी ओर हमसे त्यागी और तपस्वी होनेको कहा जाता है । यदि वास्तवमें लक्ष्यकी प्राप्ति हो गयी है और लक्ष्य स्वतन्त्रतातक ही सीमित है और उसके रूप-रंगकी फिक्र नहीं है तो उन लोगोंको जो कानूनके बनानेमें रस लेते हैं और जो वैधानिक योग्यता रखते हैं आगे लाना चाहिये । किन्तु हम ऐसा भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करनेसे नेतृत्व दूसरोंके हाथमें चला जावेगा और स्थिर स्वार्थोंको धक्का लगेगा । हमारी गति विचित्र है । हमको समझ लेना चाहिये कि कांग्रेसको यदि चुनावकी मशीन बनाना है तो फिर त्याग और तपस्याकी बात करना व्यर्थ है और आजका रोना भी व्यर्थ है । उस हालतमें power politics को प्राधान्य मिलेगा और अन्य स्वतन्त्र देशोंके समान हमारे राजनीतिज्ञ भी दुनियादार बन जावेंगे और अपने अगके स्वार्थोंकी रक्षामें लग जावेंगे । कांग्रेसमें एक प्रकारका और विचार भी पाया जाता है, इसका विवेचन करना भी आवश्यक है । वह यह है कि स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए अब कांग्रेसजनोंको रचनात्मक कार्यमें लग जाना चाहिये । किन्तु अब जब सभी सरकारी कर्मचारी देशभक्त हो गये हैं तो यह काम उन्हींके सुपुर्द क्यों नहीं किया जाता ? रचनात्मक कार्यकी व्याख्या करते समय यह सज्जन महात्माजीके कार्यक्रमकी ओर पुनः हमारा ध्यान दिलाते हैं, किन्तु वह भूल जाते हैं कि महात्माजी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम देशको स्वतन्त्र करनेके लिए प्रभावशाली बनाया गया था । यह हो सकता है कि जो कार्यक्रम स्वतन्त्रता दिलानेमें समर्थ हो वही उसकी रक्षा भी कर सके । अतः हमको इस कार्यक्रमकी परीक्षा इस दृष्टिसे करनी चाहिये । इस कार्यक्रममें कई बातोंका समावेश है । कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनकी प्रत्येक समाजकी आवश्यकता पड़ती है । उनका स्वतन्त्रताकी रक्षाके प्रश्नसे कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । पुनः कुछ बातें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध

समाजके आर्थिक संगठनसे है, यथा खद्दरका उत्पादन और ग्रामोद्योग । प्रश्न यह है कि क्या स्वतन्त्र भारतको इस कार्यक्रमकी औद्योगिक नीति स्वीकृत होगी ? कांग्रेस गवर्नमेण्ट ही इस नीतिको अपनाती नहीं मालूम होती है । चाहिये तो यह कि हम पहले अपनी अर्थ-नीतिको निर्धारित करें और उसके अनुसार गवर्नमेण्ट अपना कार्यक्रम बनावे, किन्तु हम करते हैं इसके सर्वथा विपरीत । हम एक कार्यक्रमको स्वीकार कराना चाहते हैं और यह नहीं देखते कि यह कार्यक्रम किसी अर्थ-नीतिको स्वीकार करके ही बना है । इस सम्बन्धमे यह भी विचारणीय है कि व्यक्ति तथा व्यक्तियोंके समूह इसके लिए क्या कर सकते हैं । आर्थिक योजना बनाना गवर्नमेण्टका काम है और उसको कार्यान्वित करना भी उसीका काम है । हाँ, यदि आर्थिक योजना इस प्रकारकी है जिससे सामाजिक संगठन लोकतन्त्रात्मक बनता है और जिसके द्वारा उत्पादनके साधन समाजकी मिलकियत हो जाते हैं, तब इनका महत्व सामाजिक और सांस्कृतिक हो जाता है । उस अवस्थामे जीवनकी नयी दिशाकी ओर सर्वसाधारणको मोड़नेके लिए प्रचारकी आवश्यकता होती है और यह काम नि.स्वार्थसेवी ही कर सकते हैं । उस अवस्थामे किसी गैर-सरकारी संस्थाकी भी आवश्यकता पड़ती है, पर तब केवल कार्यक्रमका उल्लेख न कर सिद्धान्तोंका स्पष्टीकरण होना चाहिये और समाजकी नयी रूपरेखाके अनुसार ही एक पूर्ण योजना प्रस्तुत करनी चाहिये । उक्त कार्यक्रमकी आर्थिक योजना भी अधूरी है और आजके युगके अनुरूप नहीं है । आजके युगकी आत्म-तृप्तता (autarchy) का नियम नहीं चल सकता ।

पुनः इस रचनात्मक कार्यक्रमके अन्य अंग किसान, मजदूर और विद्यार्थियोंके संगठनसे सम्बन्ध रखते हैं, पर प्रश्न यह है कि यह संगठन किस उद्देश्यसे हैं और जबतक उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया जाता हमारा कार्य निरुद्देश्य होनेसे कुछ अधिक लाभदायक नहीं होगा ।

मजदूरोंके संगठनके प्रश्नको ही ले लीजिये । इनका संगठन कई दृष्टिसे हो सकता है । एक दृष्टि यह भी है कि आज जब अनेक दल मजदूरोंमे काम कर रहे हैं और उनके कामसे गवर्नमेण्टको कुछ परेशानी हो रही है तो मजदूरवर्गपर कांग्रेसद्वारा कांग्रेस-गवर्नमेण्टका नियंत्रण कायम करना उपयोगी होगा । हम समझते हैं कि शायद यही दृष्टि इन महानुभावोंके सामने है । आज कांग्रेसके अनुसार गवर्नमेण्टको चलानेकी बात नहीं कही जा रही है । आज तो माँग इस बातकी है कि कांग्रेस-मशीन गवर्नमेण्टकी सहायता करे और उसके निश्चयोंको कार्यान्वित करानेमे मददगार हो । हर जगह कांग्रेस गवर्नमेण्टे हड़तालके विरुद्ध है और कांग्रेस-नेता हड़तालको बन्द करानेका हर प्रकारसे प्रयत्न करते हैं । इतना ही नहीं, यह कहा जाता है कि अब कांग्रेस गवर्नमेण्टके होते हड़तालकी आवश्यकता ही क्या है । यह लोग कराँचीके मौलिक अधिकारोंके प्रस्तावको भूल गये हैं । कहीं-कहीं केवल यूनियन (संघ) बनानेकी चेष्टा करनेपर ही प्रत्येक सेप्टी कानूनके अनुसार कार्यकर्ता नजरबन्द कर लिये जाते हैं ।

इंग्लण्ड और अमेरिकामे आये दिन हड़ताले होती हैं, युद्धकालमे बड़ी-बड़ी हड़ताले हुईं, यहाँ भी हो रही हैं । इस प्रवाहको कौन रोक सकता है ? मजदूरोंकी उचित माँगे

पूरी कीजिये, हड़ताल आप ही बन्द हो जायँगी, पर शासकोको प्रत्येक दशामे कोचना होता है तभी सामाजिक न्याय मिलता है, इसीलिए हड़तालके अन्तिम अस्त्रको हम मजदूरोसे नहीं छीन सकते; यह अधिकार उनको प्राप्त होना ही चाहिये। यह तर्क कि कारखानोके बन्द होनेसे कपडे आदिकी और कमी हो जावेगी—मजदूरोके गले नहीं उतरता। यह उपदेश मिलमालिकोको देना चाहिये और आज महँगीके जमानेमे जब मजदूरोकी क्रयशक्ति बहुत कम हो गयी है उनकी मजदूरीका पर्याप्त मात्रामे बढ़ाया जाना परम आवश्यक है।

यह कहा जायगा कि उक्त कार्यक्रमकी आवश्यकता किसान-मजदूर राज कायम करनेके लिए है। उत्तरमे हमारा यह निवेदन है कि हमने तो एक प्रकारसे इस नारेको भुला-सा दिया है। लोग यही समझते हैं कि अगस्त सन् १९४२ का प्रस्ताव 'अग्रेज, भारत छोड़ो' मात्र था। उसके और आवश्यक अंग भुला दिये गये हैं। इसीलिए लोग समझते हैं कि हमारा कार्य समाप्त-सा हो गया है। हमने इस महान् उद्देश्यके लिए लोगोकी मनोवृत्तिको काफी तैयार नहीं किया था शायद इसीलिए ये अत्यन्त महत्वपूर्ण अश भुला-से दिये गये हैं, अन्यथा इसकी इस प्रकार उपेक्षा नहीं होती। कांग्रेसको अपना लक्ष्य स्थिर करना होगा। फिर वह जो कुछ हो, उसीके अनुसार कार्यक्रम बनेगा। यदि कांग्रेसको चुनावकी मशीनमात्र बनाये रखना है तो बड़े-बड़े आदर्शोंकी बात छोड़ देनी चाहिये। किन्तु यदि वास्तवमे किसान-मजदूर-राज्यकी स्थापना करना कांग्रेसका अब भी लक्ष्य है तो कांग्रेस-द्वारा इसको स्पष्ट रूपसे स्वीकार कराना चाहिये और हमारे प्रत्येक कार्यमे इसको प्रथम स्थान मिलना चाहिये।

आज कांग्रेस द्वारा उन्हीका आप्यायन होता है जो किसी-न-किसी पदपर आरूढ हैं, इनमेसे कुछकी महत्त्वाकांक्षाकी पूर्ति होती है, इसलिए वह सन्तुष्ट हैं। कुछ ऐसे पदो-पर नियुक्त हैं जहाँ रहकर वह कुछ सार्वजनिक सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार उनका भी आत्मसंतर्पण होता रहता है। किन्तु सामान्य कांग्रेस-जनकी उच्च भावना तथा उसकी आदर्शप्रियताकी सन्तुष्टि नहीं होती। हमको यह न भूलना चाहिये कि किसी सस्थाकी परख उसके चोटीके नेताओसे नहीं होती। महान् पुरुषोको तो भारत सदा जन्म देता रहा है, किन्तु उनके होते हुए भी हम अवन्तिके गर्तमे समय-समयपर गिरते रहे हैं। सस्थाकी परख उसके द्वितीय-तृतीय श्रेणीके कार्यकर्ताओसे होती है। अतः यह धारणा मिथ्या होगी कि जबतक हमारे पास महात्माजी, जवाहरलालजी और मौलाना आजाद ऐसे नेता हैं तबतक सब कुशल है, हमारा अनिष्ट नहीं हो सकता।

यदि हम वास्तवमे किसान-मजदूर-राज्यके पक्षमे हैं तो हमको यह स्थूल सत्य समझ लेना चाहिये कि ऐसे राज्यकी स्थापना किसान-मजदूर स्वयं ही करेंगे। हम उनके लिए उसकी स्थापना नहीं कर सकते, हमारा केवल इतना काम है कि हम उनको इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए संगठित करें, किन्तु यह संगठन हड़तालके हथियारको छीनकर नहीं हो सकता और न मजदूरोको यह बतानेसे ही हो सकता है कि वह अपने सेवा योजकोपर पूर्ण विश्वास रखे और केवल अनुनय-विनयसे ही काम ले। जब शुद्ध मजदूर आन्दोलन इस

अस्त्रके कभी-कभी प्रयोगके बिना नहीं चल सकते तब किसान-मजदूर-राज्यकी स्थापनाकी बात तो दूर रही इसके लिए एक दूसरी क्रान्तिकी ही आवश्यकता होगी ।

सब बातोंपर विचारकर यही उपयुक्त प्रतीत होता है कि कांग्रेस एक छोटा-ना ध्येय अपने सामने रखकर उसके अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तुत करे, किन्तु अब उसे अपने कार्यके स्वरूपको स्पष्ट ढंगसे स्थिर करना होगा । नीतिको अस्पष्ट रखनेसे अब काम नहीं चलेगा । किन्तु कांग्रेसको महज चुनावकी मशीन बनाकर त्याग और तपस्याकी आशा करना व्यर्थ है । उस अवस्थामे कांग्रेस संस्थाका वही रूप होगा जो अन्य देशोमे ऐसी संस्थाओंका हुआ करता है ।^१

लोकतन्त्रकी स्थापनाका मार्ग

पाकिस्तानकी माँग मुसलिम लीगके नेताओं द्वारा मुसलिम जनताकी हीन-भावना और आकांक्षाओंकी पूर्ति न होनेके कारण उनमे जो असन्तोष व्याप्त हो रहा था उसको दूर करनेके लिए रखी गयी थी । स्वतन्त्र पाकिस्तानकी माँग रखकर लीगी नेताओंने मुसलिम जनताका ध्यान भोजन और स्वाधीनताकी वास्तविक समस्याओंकी ओरसे हटानेकी चेष्टा की । मुसलिम सम्प्रदायमे घृणा, भय और सन्देहके सिद्धान्तोंका प्रचार किया गया और मनुष्यकी उन विध्वसात्मक प्रवृत्तियोंको उत्तेजना देनेकी चेष्टा की गयी जो अन्ततोगत्वा मजहबी झगडोमे फूट पड़ी और जिसने मनुष्यको पशुके स्तरपर पहुँचा दिया ।

समस्याका हल नहीं

किन्तु अब जब कि पाकिस्तानके लक्ष्यकी सिद्धि—खण्डित रूपमे ही सही—हो गयी है, समूची परिस्थिति मुसलमानोंको एक नयी रौशनीमे दिखायी पड़ेगी । पाकिस्तानी राज्यके सामने बहुत-सी कठिनाइयाँ होंगी और उसे अनेक जटिल प्रश्नोंको हल करना पड़ेगा । कुछ लोगों द्वारा यह माँग पेज की जायेगी कि इस्लामके सिद्धान्तोंके आधारपर पाकिस्तानको धार्मिक राज्यका रूप दिया जाय । एक ओर जिन प्रान्तोंको पंजाबके अपने ऊपर हावी होनेका डर है वे केन्द्रको शिथिल बनानेपर जोर देंगे, दूसरी ओर पंजाबकी पूर्वी वंगालका डर बना रहेगा जो कि अपनी जन-संख्याके बलपर पाकिस्तानकी केन्द्रीय सरकारपर हावी होगा । इसके अतिरिक्त और इन सबसे बढ़कर जनताकी गरीबी और बेकारीको दूर करनेका बुनियादी सवाल होगा । इन समस्याओंका हल होना कठिन देखकर पाकिस्तानके नेता जनताको भुलानेके लिए पाकिस्तानकी सीमाके सशोधनकी कोशिश कर सकते हैं । वे अपने अनुयायियोंके सामने यह तर्क रख सकते हैं कि उनकी मुसीबतोंकी जड़ खण्डित पाकिस्तान है और जबतक उनका मूल स्वप्न पूरा नहीं होता तबतक जनताकी मुक्ति न होगी । इस प्रकार जनताकी आकांक्षाओंकी पूर्ति न होनेके

कारण असन्तोष और क्षोभकी समस्याका समाधान करनेके लिए भय और घृणाका वातावरण बनाये रखा जा सकता है और मनुष्यकी विध्वसात्मक प्रवृत्तियोंको पुनः खुलकर नाचनेका अवसर दिया जा सकता है ।

यदि दुर्भाग्यवश घटनाओंका यह रूप हुआ तो भारतीय संघमें भी उसकी अवाछनीय प्रतिक्रियाएँ हुए बिना न रहेगी । किन्तु यदि पाकिस्तानके नेताओंको भारतीय संघमें रहनेवाले अपने भाइयोंका कुछ ख्याल हुआ तो वे इस बातका ध्यान रखेंगे कि वे जिस राज्यका निर्माण करने जा रहे हैं वह एक लोकतन्त्रात्मक राज्य होगा, जिसमें सभी व्यक्ति समान नागरिकताका उपभोग कर सकेंगे और जहाँ अल्पसंख्यकोंके हितोंकी पूरी तरह रक्षा की जायगी । किन्तु पाकिस्तानी नेता क्या करते हैं और क्या नहीं करते, हमें इसपर निर्भर नहीं रहना है । वे चाहे जो भी करें, हमारा कर्तव्य स्पष्ट है । हमें इस बातका ध्यान रखना है कि लोकतन्त्रात्मक राज्यका जो चित्र हमारे सामने है वह किसी कारण विकृत न होने पाये ।

सुदृढ़ राज्यकी आवश्यकता

यह स्पष्ट है कि हमें एक सुदृढ़ राष्ट्रीय राज्यका संघटन करना है । अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीकी पिछली बैठकमें सरदार पटेलने इस बातकी ओर संकेत किया था । शायद वे यह सोचते हैं कि एक शक्तिशाली सेना और नौकरशाहीके संघटनसे ही इस उद्देश्यकी पूर्ति हो सकती है ।

सम्भवतः वे और दूसरे नेता सोचते हैं कि हमारे सामने निकट महत्त्वका कार्य यही है, दूसरी चीजोंपर वादमें ध्यान दिया जा सकता है । किन्तु जिस प्रकार आज शान्तिकी स्थापनामें इसलिए बाधा पड़ रही है कि उसकी बुनियाद लडाईके दौरानमें ही नहीं डाली गयी उसी प्रकार अभीसे यदि लोकतन्त्रकी बुनियाद नहीं डाली गयी और लोकतन्त्रात्मक प्रक्रियाएँ नहीं अपनायी गयी तो भारतीय संघको सर्वग्रासी अधिनायकतन्त्रवादी राजका रूप ग्रहण करते हुए देखेंगे । शक्तिशाली सेना और नौकरशाहीवाला राज्य, जिसमें नौकरशाहीकी मनोवृत्तिपर नियन्त्रण रखने और शासन-प्रबन्धमें प्रमुख भाग लेनेवाली लोकतन्त्रात्मक संस्थाएँ न हों तो लोकतन्त्रके लिए भारी खतरा साबित होता है । यदि पूँजीवादी हितोंको आज राज्यपर हावी होनेका मौका दिया जाता है तो आगे चलकर इस स्थितिको बदलना सम्भव न होगा ।

एक ऐसे देशमें जो अनेक जातियों और सम्प्रदायोंमें बँटा हुआ है और जिसमें ऊँच-नीचके भेदभावोंसे भरी हुई सामाजिक सम्बन्धकी शृंखला पायी जाती है, यह और भी आवश्यक हो जाता है कि जनताको पग-पगपर लोकतन्त्रके सिद्धान्तोंकी याद दिलायी जाय । लोकतन्त्र अभ्यास और परम्पराकी वस्तु होती है । जबतक हम वर्तमान सामाजिक ढाँचोंको सहारा देनेवाले मिथ्या विश्वासों और आस्थाओंका अन्त न करेंगे तबतक हमें अपने देशमें लोकतन्त्रकी स्थापनाकी आशा न करनी चाहिये ।

समताका आधार

यदि हमें सुदृढ़ राजकी स्थापना करनी है तो हमें समाजको समताके आधारपर संघटित करना होगा । यदि प्रभुशक्ति सर्वसाधारणमें निहित होती है तो हमें सर्वसाधारणको शक्तिमान बनाना होगा, श्रृंखलाकी जो भी कड़ी निर्वल दिखायी दे उसमें शक्ति भरनी होगी । एक जवर्दस्त सामाजिक उलट-फेरके द्वारा ही सामाजिक सौहार्दकी स्थापना हो सकती है । बिना सामाजिक सौहार्दके सुदृढ़ राज्यका निर्माण नहीं हो सकता । दुर्भाग्यवश हमारे नेता धारा-सभाओंसे बाहर लोकतन्त्रके व्यवहारपर जोर देनेकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते । जिनके हाथमें देशका संचालन-सूत्र है वे पुलिस, फौज और नीकरशाहीके सदस्योपर ही भरोसा कर रहे हैं । यदि राष्ट्र-निर्माणके कार्यको आगे बढ़ानेके लिए गैर-सरकारी संस्थाओंसे काम लेनेकी बात उनके सामने रखी जाती है तो ऐसे मुझावोंके प्रति वे कोई उत्साह नहीं दिखाते । यह बात समझ लेनेकी है कि भारतीय संघका मार्ग फूलोंसे भरा हुआ नहीं होगा । समय आ गया है कि हम इस उचितके सत्यको हृदयंगम कर लें कि सतत जागरूकता ही स्वतन्त्रताका मूल्य होती है ।

आनेवाले समयमें बाह्य और आन्तरिक समस्या दोनोंपर ही पूरा ध्यान देना होगा । सघके भीतर विच्छिन्नकारी शक्तियोंका नियन्त्रण हिंसाके प्रयोगद्वारा नहीं, बल्कि इन शक्तियोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली जनताकी उचित मांगों और आकांक्षाओंकी पूर्ति द्वारा करना होगा । जो विभाजक शक्तियाँ अबतक स्वाधीनता प्राप्त करनेके समूचे ध्यानको एक ही ओर लगा देनेवाले कार्यकी ओर लगी हुई थी अब खुलकर खेलनेके लिए अवसर पायेगी । इस प्रकारकी प्रवृत्तियाँ अभी ही उभरती हुई नजर आ रही हैं । उदाहरणके लिए बम्बईके भविष्यके सम्बन्धमें कांग्रेसजनोंमें अभीसे मतभेद उत्पन्न हो गया है । एक दल उसे गुजरातका अंग बनाना चाहता है तो दूसरा महाराष्ट्रका । प्रान्तके अन्तर्गत प्रादेशिक स्वायत्त शासनको स्वीकार करके आदिवासियोंके पार्थक्यवादी आन्दोलनकी माँगका हमें सहानुभूतिपूर्ण हल ढूँढना होगा । विभिन्न प्रान्तोंकी ईर्ष्याके उभड़नेका खतरा भी है और उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रान्तीय झगड़ोंका निपटारा करनेके लिए हमें अपनी पूरी बुद्धि और समझका उपयोग करना पड़ेगा । सबके ऊपर भूख और गरीबीकी समस्याको हल करना तो है ही ।

बादा नहीं प्रत्यक्ष चाहिये

अब हमें यह देखना है कि एक सुदृढ़ राज्यकी स्थापना किस प्रकार हो सकती है । आधुनिक उद्योग-धन्धोंके बिना ऐसे राज्यकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । ब्रिटिश शासनसे विरासतमें शिक्षा, दरिद्रता, पिछड़े उद्योग-धन्धे तथा अत्यन्त पुराने ढंगकी कृषि-व्यवस्था ही हमें प्राप्त हुई हैं । हमें सभी काम नये सिरेसे आरम्भ करना है, किन्तु जनताके हार्दिक सहयोगके अभावमें हमारी प्रगति सम्भव नहीं । इस महान् निर्माण-कार्यमें हमें जनताकी शक्तिका प्रयोग करना है और उसमें दिलचस्पी एवं उत्साह पैदा करना है । यह सब तबतक सम्भव नहीं जबतक राज्य जनतामें नया विश्वास नहीं

उत्पन्न कर देता । उसे न केवल आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याणका वादा करना है, बल्कि सामाजिक उन्नतिका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देना है । ऐसी अवस्थामे ही लोग सभी आपत्तियोंका सामना करेंगे । सोवियत रूसका उदाहरण हमारे सामने है । लेनिनकी प्रेरणासे राज्यद्वारा जारी किये गये कानूनोंने देशमे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा कर दी थी जिससे श्रमिकोंमे नया जीवन आ गया और वे अनुभव करने लगे कि उन्हें अपने राज्य-निर्माण का कार्य पूरा करना है । सोवियत जनताने उज्ज्वल भविष्यकी आशामे हर तरहके कष्टोंको प्रसन्नतापूर्वक सहन किया ।

अगर हम जनताको संघटित करना चाहते हैं और एक नये जीवनका आधार तैयार करनेमे उसका सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें रूसी उदाहरणका अनुकरण करना होगा ।

इस राष्ट्रीय कार्यमे सामाजिक दृष्टिसे दलित वर्गोंका हार्दिक सहयोग प्राप्त होगा और उनकी सामूहिक शक्तिका तभी सदुपयोग हो सकता है जब कि हम उन्हें यह अनुभव करा देंगे कि आजका सामाजिक भेदभाव शीघ्र ही समाप्त हो जायगा । हमारे देशमे जनताकी शक्तिका एक ऐसा विशाल स्रोत है जिसका अधिक उपयोग नहीं किया गया है और इसमे तभी सफलता मिल सकती है जबकि हम बुद्धिमत्तापूर्वक और सहानुभूतिके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे ।

हमे जनतामे यह विश्वास उत्पन्न कर देना है कि राज्य उनकी मान्य महत्ताको स्वीकार करता है और शासन-व्यवस्थाके वे स्वयं एक मुख्य अवयव हैं ।

हमे यह भी स्मरण रखना है कि वर्तमान युगमे व्यक्तिको आर्थिक उन्नति करनेके लिए समान अवसर दिये जानेपर विशेष जोर दिया जाय ।

जहाँ विभिन्न वर्गोंमे पायी जानेवाली विषमता, आर्थिक विषमता, बहुत अधिक है, सुखमय जीवन सम्भव नहीं ।

इसलिए सामाजिक विषमताकी समाप्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाके विकासके लिए अत्यन्त आवश्यक है । यह विलकुल स्पष्ट है कि यदि हिन्दू-राज्यका नारा कार्यान्वित किया गया तो लोकतन्त्र मुरझा जायगा और हमारी सामाजिक व्यवस्थाके वर्तमान दोष स्थायी बन जायेंगे । अनुदार और प्रतिक्रियावादी शक्तियोंका जोर पुनः बढ़ जायगा और हिन्दू धर्मके नामपर इस बातकी पूरी कोशिश की जायगी कि लोकतन्त्रीय आदर्शोंका आर्थिक क्षेत्रमे विकास न हो सके । पुरानी पद्धतियोंको पुनर्जीवित करनेकी चेष्टा घातक ही सिद्ध हो सकती है, पर नया सामाजिक दृष्टिकोण, जिसके विकासकी हमलोग चेष्टा करते रहे हैं और जिसके द्वारा ही जन-शक्तिकी एक नयी दिशा प्रदान की जा सकती है, उस प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोणद्वारा दबा दिया जायगा जो भविष्यके विरुद्ध भूतकालीन व्यवस्थाका पोषक है ।

हमे उन नये सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शोंकी रक्षा करनी है जिनका निर्माण जनताके इतने कष्ट सहनके बाद हो सका । गत दो पीढ़ियोंकी शिक्षाको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये । इस बीच हिटलरके सर्कीर्ण राष्ट्रवादके विरुद्ध हमें मेजिनीके व्यापक

राष्ट्रवादको अपनानेकी शिक्षा मिली है। हमने बराबर यह ध्यान रखा है कि हमारी राष्ट्रीयता आक्रमणशील संकुचित राष्ट्रीयताकी अधोगतिको न प्राप्त होने पाये। आधुनिक युगमें राष्ट्रीयता अधिक अनुदार होती जा रही है, इसलिए यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम पूर्ण सतर्क रहे।

१५ अगस्तसे ही

यदि उपर्युक्त बातें सही हैं, तो हमें अपने देशकी राजनीतिके नये अध्यायको आरम्भ करनेमें देर न करनी चाहिये। १५ अगस्तसे ही इसका श्रीगणेश किया जा सकता है। उस दिन नव-निर्मित सरकारको घोषित एव दलित वर्गों और पिछड़ी जातियोंके लिए आशाका एक नया सन्देश घोषित करना चाहिये जिसमें जनताकी सार्वभौम सत्ताको स्वीकार किया गया हो। उसी दिन हमारे सामाजिक जीवनके नये आधारकी भी घोषणा होनी चाहिये और उसमें सकेत होना चाहिये कि नयी शासन व्यवस्थामें जनताको भाग लेने-देनेके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। किन्तु महज वादोंसे ही काम नहीं चल सकता। नयी सरकारको अपनी लगनका प्रमाण भी देना होगा। घोषणा-मात्रसे लोगोंमें उत्साह नहीं उत्पन्न हो जायगा जबतक उसके साथ ही हम उस घोषणापर अमल करना भी नहीं आरम्भ कर दें। क्या ही अच्छा होता अगर उसी दिन राज्यद्वारा जमींदारी प्रथाकी वास्तविक समाप्तिकी घोषणा हो जाती।

गैर-सरकारी संस्थाएँ

लोकतन्त्रकी नींव हमें अभीसे डालनी होगी। कोरे वस्तुवादी इस कार्यको उतना महत्वपूर्ण नहीं समझ सकते हैं जितना कि रक्षा-व्यवस्था और एक योग्य सिविल सर्विसका संघटन। किन्तु ये सभी कार्य समान महत्वके हैं और किसीको भी भविष्यके लिए नहीं टाला जा सकता। यथार्थवादी व्यक्ति तात्कालिक आवश्यकताओंकी ओर विशेष ध्यान देता है और वर्तमान आवश्यकताओंके सामने भविष्यकी उपेक्षा कर देता है। ऐसी यथार्थवादिता व्यक्तिको अवसरवादितानेके गड्ढेमें गिरा सकती है। दूसरी तरफ एक विशुद्ध आदर्शवादी एक ऐसे भविष्यके चक्करमें जो कभी आनेवाला नहीं है, वर्तमानका बलिदान कर सकता है। किन्तु ऐसा आदर्शवादी जिसके आदर्शकी जड़े यथार्थवादमें हैं, बीचके एक चुनहले मध्यम मार्गको ग्रहण करेगा और भविष्यके साथ वर्तमानके सम्बन्धको कायम रखेगा। यथार्थवादी व्यक्ति आदर्शोंको हवाई बात कहकर उसका उपहास कर सकता है, किन्तु वह भूल जाता है कि इतिहासकी प्रेरक शक्ति राजनीति और कूटनीति नहीं बरन् आदर्शोंके प्रति विश्वास और उत्कट लगन ही रही है।

सार्वभौमिक शिक्षाके बिना लोकतन्त्रका निर्माण सम्भव नहीं है। शिक्षा देनेके अतिरिक्त यदि हमें समाजमें लोकतन्त्रीय पद्धतिका प्रसार करना है तो इस कार्यमें हमें सहकारी आन्दोलनसे बढ़कर दूसरी वस्तुसे सहायता नहीं मिल सकती है। इस तरहका सामाजिक संगठन स्थानीय लोगोंमें कर्तृत्व शक्तिको बढ़ाता है, सामाजिक कल्याणके लिए समानताके आधारपर लोगोंको संघटित करता है और लोकतन्त्रको विकसित करता

है। ऐसे क्रान्तिकारी जन-संघटनके नैतिक प्रभावसे लोकतन्त्रीय ढंगसे शासित स्वतन्त्र व्यक्तिवाले समाजके निर्माणमें सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस बातका भी प्रयत्न होना चाहिये कि देशके पिछड़े हुए भागोंकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो सके। इन्हीं तरीकोंसे हम भयंकर सामाजिक विपमताको समाप्त कर सकते हैं जिससे आज हमारा सामाजिक संघटन दूषित हो गया है। साथ ही राज्यका यह विशेष कर्तव्य होना चाहिये कि वह प्रत्येक समूहको उन्नतिका समान अवसर प्रदान करे।

सरकारी व्यवस्था चाहे वह कितनी ही कुशल क्यों न हो, अकेले इन उद्देश्योंकी प्राप्ति नहीं कर सकती है। गैर-सरकारी संस्थाओंकी स्थापना करनी होगी और उनके द्वारा सरकारी कार्योंको पूरा करनेके लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन आरम्भ करना होगा। कांग्रेस-संघटन, जो चुने हुए कुशल लोगोंका समूह रहा है, का इस कार्यमें उपयोग किया जा सकता है। कांग्रेसमें आदर्शवाद और आत्मत्यागकी भावनाकी कमी नहीं है। यदि आज यह पतनोन्मुख है, तो इसका एकमात्र कारण परिवर्तित परिस्थितियोंके अनुकूल लक्ष्य और कार्यक्रमका अभाव है। राष्ट्रद्वारा अपनायी जानेवाली आधारभूत नीतियोंके मूल स्रोतके रूपमें कांग्रेसका जो महत्व अवतक रहा है उसे वह तेजीसे खो रही है। इसका काम अब केवल चुनाव लड़ना और सरकारके निर्णयोंकी स्वीकृति देना मात्र रह गया है। प्रत्येक व्यक्ति इसको सुसंघटित करनेकी बात करता है, किन्तु इस समस्यापर विचार करनेके लिए किसीको समय नहीं है। इस आत्मसन्तोषका, जिससे सारा राष्ट्र पीड़ित है, अवश्य अन्त होना चाहिये। यह सोचना गलत है कि जबतक गांधीजी और जवाहरलाल-जी मौजूद हैं तबतक राष्ट्रका भाग्य इनकी मुट्ठियोंमें सुरक्षित है। हमें स्मरण रखना चाहिये कि किसी संघटनका महत्व उसके उच्च नेताओंद्वारा नहीं बल्कि उसके साधारण कार्यकर्ताओंद्वारा आँका जाता है। भारत अपनी ह्रासवस्थामें भी कितने ही महान् पुरुषोंको जन्म दे चुका है, किन्तु सर्वसाधारण व्यक्तिको उठाया नहीं जा सका। जो राजनीतिक पद्धति उच्च नेताओंपर इस प्रकार आश्रित रहती है, उसमें कोई मौलिक दोष अवश्य है। मेरी रायसे यह मनोवृत्ति हमारी उस सामाजिक व्यवस्थाकी देन है जो पीड़ित करके थोड़ेसे ऐसे विशेष व्यक्तियोंको जन्म देती है जो इन लाखों व्यक्तियोंके उद्धारके रूपमें सामने आते हैं। लोकतान्त्रिक सरकारका कार्य चलानेके लिए औसत दर्जेकी योग्यतावाले व्यक्तियोंकी बड़े पैमानेपर आवश्यकता है। साधारण जनता कैसे ऊँची उठायी जाय और उसे लोकतान्त्रिक जीवन-प्रणालीकी शिक्षा कैसे दी जाय यही हमारी समस्या है। क्या हम इस कार्यको पूरा कर सकेंगे ?

हिन्दुस्तान और राष्ट्रमण्डल (१)

यह बड़े दुःखकी बात है कि हिन्दुस्तान धीरे-धीरे उन सभी घोषित आदर्शोंको छोड़ता जा रहा है, जिनके लिए उसने गत २० वर्षोंसे संघर्ष किया था। धीरे-धीरे हम परस्पर

विरोधी दो गेमोंमें एक गेमकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। चालते हुए भी हम बड़ी तेजीके साथ इन्तर्लैण्डकी प्रतिक्रियावादी परराष्ट्र नीतिके साथ अपनेको एकतावादी कर रहे हैं। अभी तक किसीने यह नहीं बताया कि इन तरहके गठबन्धनमें हिन्दुस्तान का क्या लाभ होगा ? एक बात तो हमें साफ दिखायी दे रही है कि हमारे देशवासियोंके साथ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके देशोंमें बराबरीका वर्ताव नहीं हो रहा है।

भारत सरकारकी नीति न समाजवादी है और न राष्ट्रवादी। देशके नेताओंने हमें धोखा दिया है। हमें उम्मीद करनी चाहिये कि देशकी जनता जागेंगी और हम भयंकर झूलको मुघारेगी।

इस समझौतेमें ब्रिटेन सबसे बड़ा हिस्सेदार है और ब्रिटिश साम्राज्य उम्मीद पूर्णताका प्रतीक है। यद्यपि मजदूर सरकार अपने देशमें समाजवादी नीति अन्विष्ट कर चुके हैं, लेकिन उनकी विदेश-नीति साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी है। उनकी अन्तिम ब्रिटेन पैग्वो-अमेरिकी गुटका एक प्रमुख सदस्य है और आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड अपनी सुरक्षाके लिए उसमें सहयोग कर रहे हैं। उनकी वर्तमान विदेशी नीति रक्तकी नीतिका ही अण है। वह प्रगतिशील शक्तियोंके विरुद्ध हर जगह राजाओं, सामन्तों और पुराने रईसोंका समर्थन कर रहा है। मलायामें वह अपने साम्राज्यवादी हितोंकी रक्षा कर रहा है और अन्य देशोंमें यूरोपीय शक्तियोंके साम्राज्यवादी दावोंकी हिमायत कर रहा है।

इसके अलावा एक बात यह भी है कि कामनवेल्थके उन सदस्योंके साथ भारतका किसी अर्थमें साम्य नहीं है, उनकी ठीक जगह तो कामनवेल्थके बाहर ही होती। कामनवेल्थके पुराने सदस्य तो ब्रिटिश बादशाहके प्रति राजभक्ति रखनेके लिए जातीयता, परम्परा, संस्कृति और स्वतन्त्र-सम्बन्धोंके कारण बाध्य थे।

केवल 'ब्रिटिश' नाम हटा देनेसे ही कामनवेल्थके अगली स्वरूपमें अन्तर नहीं आ जाता। या तो हम यह मान लें कि कामनवेल्थ कुछ राज्योंका दीनाटाना संगठन है, जिसके पीछे उद्देश्योंकी कोई एकता नहीं ऐसी हालतमें उसकी सदस्यतासे हमारा क्या लाभ होगा ? या अगर हम मानें कि इस संगठनके पीछे एक सामाजिक और आर्थिक नीति है, तो उस हालतमें हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे लक्ष्यका मेल बैठना है या नहीं।

यह साफ है कि जिन लोगोंने दोनों गुटोंमें किसी एकके साथ गठबन्धन कर लिया, उनसे विश्वमें शान्ति-रक्षा करनेकी आशा नहीं की जा सकती। जो लोग तटस्थताकी नीति अपनाये हुए हैं, जैसा कि हमनोग, उनको इन गुटोंमें कतई अलग रहना चाहिये।

कामनवेल्थके साथ हमारे सम्बन्धोंकी प्रतिक्रिया हमपर अवश्य पड़ेगी। सोवियत प्रेस तो पहलेसे ही हमारा विरोधी था, अब इस घटनासे तो उसे एक बहाना मिल जायगा।

यद्यपि मैं सोवियत रूसकी परराष्ट्र नीतिकी कई बातोंसे सहमत नहीं हूँ, तो भी मैं यह कहनको तैयार नहीं हूँ कि सोवियत रूस खामखाह लड़ाई करना चाहता है और उसका

रख आक्रमणात्मक है। अगर हम वास्तवमें तटस्थ रहना और दुनियामें शान्ति तथा प्रगति लाना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोसी देशोंके साथ अनाक्रमण सन्धि करनी चाहिये और दुनियाकी प्रगतिशील शक्तियोंके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहिये।”

हिन्दुस्तान और राष्ट्रमण्डल (२)

पण्डित नेहरूके प्रति अत्यधिक सम्मान और स्नेह होनेके कारण मैं उनके साथ किसी विवादमें नहीं पड़ना चाहता, किन्तु कुछ दिन पूर्व उन्होंने राष्ट्रमण्डलके प्रश्नपर अपने ब्राडकास्ट-भाषणमें मेरा भी नाम लिया है, अतएव इस अवसरपर उनको तथा जनताको अपना विचार स्पष्ट रूपसे बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। नेहरूजीकी कुछ सफाईका तो मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि राष्ट्रमण्डल कोई महाराज्य नहीं है और उससे हम जब चाहें सम्बन्ध-विच्छेद कर सकते हैं। साथ ही अगर हिन्दुस्तानका राष्ट्रमण्डलमें रहना हितकर मान लिया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि प्रधान मन्त्रीजीको इस कार्यमें काफी सफलता मिली है। हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि राष्ट्र मण्डलकी सदस्यतासे सिद्धान्ततः हमारी स्वतन्त्रतामें बाधा पहुँचती है या नहीं, बल्कि हमें यह देखना है कि क्या उससे हिन्दुस्तानका स्थायी हित होता है और क्या उससे विश्व-शान्ति और प्रगतिमें सहायता मिलेगी? इस कसौटीसे हमें इस प्रश्नपर विचार करना है, किन्तु मुझे अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि सिवाय व्यर्थकी बातें बनानेके पण्डित नेहरूने कभी यह बतानेकी कोशिश नहीं की कि उससे इन महान् उद्देश्योंकी पूर्तिमें किस प्रकार सहायता मिलेगी। मैं न तो अलगावकी नीतिका समर्थक हूँ और न मेरे अन्दर किसी जाति-विशेषके प्रति कोई विरोध-भाव ही है। मैं अंग्रेजोंका बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी कुछ विशेषताओंका प्रशंसक भी हूँ। मैं संकीर्ण राष्ट्रीयताको इस युगका सबसे बड़ा अभिशाप मानता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि जहाँतक हो ब्रिटेनके साथ समझौता और सहयोग भी होना चाहिये। तात्पर्य यह कि अगर मुझे यह विश्वास हो जाय कि वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितिमें राष्ट्रमण्डलके अन्दर ही हिन्दुस्तानका हित-साधन और उद्देश्य-पूर्ति हो सकती है तो मैं निस्सन्देह इसका समर्थन करूँगा, किन्तु अफसोस है कि मुझे प्रधान मन्त्रीजीके हालके भाषणोंमें एक भी ऐसी बात नहीं मिली जिससे मेरे विचारमें परिवर्तन हो सके।

प्रधान मन्त्रीजीने राष्ट्रमण्डलके प्रश्नपर हालके विवादको विलकुल व्यर्थ कहा है और फिर भी इसपर विधान-परिपद् तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीसे विचार करनेका अनुरोध किया है। मुझे अफसोस है कि नेहरूजी इतने महत्वपूर्ण प्रश्नको जरासी बातमें ही खतम कर देना चाहते हैं। क्या वह नहीं जानते कि इसी प्रश्नको लेकर हिन्दुस्तानमें २२ वर्षोंसे विवाद चल रहा है? १९०७ की सूरत-कांग्रेसमें जिन प्रश्नोंपर फूट पड़ी

उनमें एक यह भी था और वह मतभेद १९१६ तक बना रहा । इसी प्रश्नको लेकर १९२८ में पण्डित नेहरूने अन्य लोगोंके सहयोगसे इण्डिपेण्डेन्स आफ इण्डिया लीगकी स्थापना की । इसी प्रश्नपर १९२८ की कलकत्ता-कांग्रेसमें उन्होंने गांधीजी तथा मोतीलालजीका विरोध किया और अपने इसी विचारके कारण ही १९२९ में वह भारतीय युवकोंके हृदय सम्राट बने । इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि जब उन्होंने ब्रिटेनसे पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेदका जोरदार समर्थन किया तो उनके अन्दर कोई ब्रिटिश-विरोधी भावना काम नहीं कर रही थी, बल्कि इसके लिए कुछ विशेष कारण थे । हमलोग भी उन दिनों अलगावकी नीतिके समर्थक नहीं थे । अतएव अगर हमें उस ध्येयका जिसे मैं अपने विद्यार्थी-जीवनसे ही ही मानता रहा हूँ परित्याग करना है तो मैं उन विशेष कारणोंको जानना चाहूँगा जिनसे आज हमें अपनी नीतिमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता पड़ी ।

मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि पण्डित नेहरूके पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलनवाले भाषणसे तो उनके ब्राडकास्ट भाषणका प्रभाव भी नष्ट हो गया । विगत कुछ वर्षोंमें जब कभी हमलोगोंका उनसे मतभेद हुआ तो वह बिना कोई दलील दिये ही हमलोगोंपर संकुचित दृष्टि और नारोंमें चिपके रहनेका आरोप लगाते रहे हैं, किन्तु यह कोई दलील नहीं और इससे तो वामपक्षियोंपर उनका आक्रोश ही प्रकट होता है । वह हमारी मखौल उड़ा सकते हैं और दोषारोपण भी कर सकते हैं, किन्तु किसी विरोधीको प्रभावित करनेका यह तरीका नहीं है । मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ और उनसे व्यर्थ विवाद नहीं करना चाहता, किन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमसे कुछ लोग विगत २५ वर्षोंके राष्ट्रीय आन्दोलनके विचारों और विश्वासोंसे दुरी तरह चिपके हुए हैं और जो आज भी पूर्ण नहीं हुए हैं तो दूसरी ओर प्रधान मन्त्रीजी भी ब्रिटिश शासनकी नौकरशाही व्यवस्था तथा अन्य कुरीतियोंमें दुरी तरह उलझ गये हैं । वह वर्तमान परिवर्तनशील जगत्में प्रगतिशील विचार और कार्यकी आवश्यकताका उपदेश देते हैं, किन्तु उनकी सरकारकी नीति स्वयं द्विविधा और भीरुतापूर्ण है और अगर वह यथास्थितिको कायम नहीं रखना चाहती तो समझौतावादी तो अवश्य है । इतने दिनोंके सरकारी अनुभवसे अब उनके पुराने आदर्शों एवं सिद्धान्तोंकी व्यावहारिकतामें वह आस्था नहीं रही । उनकी वाते तथा कार्य सभी गोलमटोल होते हैं । यही कारण है कि उन्होंने निश्चित और ठोस सम्बन्धकी अपेक्षा एक अनिश्चित और गोलमटोल सम्बन्धको अधिक पसन्द किया । इससे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वह अलगावकी नीतिके समर्थक नहीं हैं और उन लोगोंके साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम रखना चाहते हैं जिनको वह जानते हैं तथा जिनके विचारोंसे वह काफी सहमत हैं ।

मैंने अपने एक पूर्व वक्तव्यमें राष्ट्रमण्डलमें सम्मिलित होनेके विरुद्ध अपने विचारोंको संक्षेपसे कह दिया था । इधर राष्ट्रमण्डलके सदस्य-राष्ट्रोंके राजनीतिज्ञोंने पण्डित नेहरूकी प्रशंसाका जो राग अलापा है उससे मेरे विचारोंकी पुष्टि ही हुई है । अब तो हम जालमें फँस चुके हैं और विधान चाहे जो कुछ भी हो, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अब हमको यूरोपीय राजनीतिमें अधिकाधिक फँसानेका खेल शुरू करेंगे । कहा जाता है कि राष्ट्र-

मण्डलसे हमें सैनिक सहायता प्राप्त होगी, किन्तु हमारे शत्रु कौन हैं जिनसे राष्ट्रमण्डल हमारी रक्षा करेगा । उसके सभी प्रमुख सदस्य-राष्ट्र आंग्ल-अमेरिकन गुटमें शामिल हैं और पाश्चात्य यूरोपीय संघ तथा अटलांटिक पैक्टके समर्थक हैं । ऐसी स्थितिमें राष्ट्र-मण्डल हिन्दुस्तानकी तटस्थता-नीतिमें कदापि सहायक न होगा ।

पण्डित नेहरूने एक नये एशियाके निर्माणका उल्लेख किया है और इसके नामपर हमसे राष्ट्रमण्डलका समर्थन करनेके लिए कहा है । किन्तु उन्होंने यह बतानेका कष्ट नहीं किया कि इन दोनोंका एक दूसरेसे क्या सम्बन्ध है ? मेरे विचारसे तो राष्ट्रमण्डलमें शामिल होनेसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रोंके साथ हमारे सम्बन्धपर बुरा प्रभाव पड़ेगा । ब्रिटेन मलायामें साम्राज्यवादी नीतिका अनुसरण कर रहा है और उसका डच और फ्रांसीसी साम्राज्यवादके साथ गठबन्धन भी है । दक्षिण-पूर्वी एशियामें जिन शक्तियोंका उदय हो रहा है और जो शीघ्र ही सत्तारूढ़ होगी, वे राष्ट्रमण्डलके साथ किसी प्रकारके सम्बन्धकी विरोधी हैं । हमलोगोंने अपनेको पहले ही एक गुटमें शामिल कर लिया है और अगर दूसरे उसके विरुद्ध जाते हैं तो हम उनपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं ।

प्रधान मन्त्रीजीका विश्वास है कि हिन्दुस्तान राष्ट्रमण्डलमें रहकर विश्व-शान्तिमें अधिक प्रभावकर रूपसे योगदान दे सकता है । किन्तु इस बातकी बिल्कुल आशा नहीं है कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डलके दूसरे राष्ट्रोंकी नीतिको प्रभावित कर सकेगा । उन राष्ट्रोंने सयुक्त राष्ट्रसंघमें अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नोंपर हिन्दुस्तानके विरुद्ध मत दिया है । अपनी देशभक्ति और सदाशयताके कारण ही हम ऐसा सोचते हैं । किन्तु इस गुरुतर कार्यको करनेके लिए न तो हमारे पास सैनिक शक्ति है न नैतिक बल । गांधीजीके बताये हुए मार्गोंको तिलांजलि देकर हम कबतक उनका नाम बेचते रहेंगे । हमने जो कुछ नैतिक शक्ति संचित की थी वह नष्ट हो रही है । हिन्दुस्तान केवल मनुष्यकी विवेक-बुद्धिसे नैतिक अपील कर सकता है, किन्तु उसके लिए हम दिनोदिन असमर्थ हो रहे हैं ।

यह अत्यन्त दुखकी बात है कि हिन्दुस्तान पण्डित नेहरूकी महती विचार और कार्य-शक्तिका कुछ मनोवैज्ञानिक कारणोंसे पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है । क्या ही अच्छा होता अगर हमारे प्रधान मन्त्रीजी राष्ट्रमण्डलके फन्देसे बाहर निकलकर विश्वको एक नये दृष्टिकोणसे देखते ।^१

लखनऊमें ९ अगस्तको भाषण—कामनवेल्थविरोधी^२

८ अगस्त सन् ४२ को कांग्रेसने यह फैसला किया था कि हमारे नये विधानमें देशकी राजनीतिक ताकत किसान-मजदूरके हाथमें दी जाये, परन्तु लोगोंके दिल-दिमाग इस फैसलेको माननेके लिए तैयार नहीं किये गये थे । सन् ४२ की क्रान्ति शुद्ध राजनीतिक

१. 'जनवाणी'—जून १९४६ ई०

२. सन् १९४६ ई०

क्रान्ति थी, सामाजिक क्रान्ति नहीं। उसके साथ जनताके सामाजिक संघर्ष नहीं चल पड़े, अन्यथा आज देशकी शक्ति ही दूसरी होती।

सन् ४२ की क्रान्तिके बाद अंग्रेज समझ गये कि बिना फौजकी सहायताके जागृत हिन्दुस्तानपर शासन करना कठिन है; परन्तु सन् ४६ के नौ-सैनिक विद्रोहने बताया कि फौज-पुलिस भी उनके खिलाफ होती जा रही है। द्वितीय महायुद्धसे ब्रिटेन कमजोर होकर निकला, इसलिए उसके सामने हिन्दुस्तानको आजादी देनेके सिवाय दूसरा चारा न रहा।

अंग्रेजोंकी चाल सफल

लेकिन अंग्रेज बड़ी चालाक कौम है, उसने बाहर निकलते-निकलते भी देशका बँटवारा करके उसे कमजोर कर दिया। पाकिस्तान बनानेमें उसकी मशा यही थी कि दोनों देश हमारी सहायताके मुँहताज रहेगें और खुशी-खुशी कामनवेल्थमें आ जायेंगे।

ब्रिटिश सरकारकी चाल सफल हुई। हिन्दुस्तानकी सत्तारूढ पार्टी कांग्रेसने कामनवेल्थमें रहनेका फैसला कर दिया है। लेकिन यह निर्णय उसके अवतकके किये वादोंके खिलाफ है। सन् १९०६ में इसी प्रश्नको लेकर कांग्रेसमें दो पार्टियाँ हुईं। कलकत्ता-कांग्रेसमें दादाभाई नौरोजीने स्वराज्यकी माँग रखी। सन् १९०७ में यह मतभेद अधिक उग्र हो उठा और सूरत-कांग्रेसमें नरम और गरम दल अलग-अलग हो गये। ६ वर्षतक वे अलग रहे। फिर इसी लखनऊमें सन् १९१६ में कांग्रेसमें एकता स्थापित हुई। सन् १९२७ में मद्रासमें जवाहरलालजीने मुकम्मिल आजादीका सवाल उठाया और 'इण्डिपेण्डेन्स आफ इण्डिया लीग' बनायी जिसमें सुभाषबाबू भी शामिल हुए। सन् २८ तक यह लीग चलती रही। उस वर्षकी कांग्रेसमें बड़ी गरम तकरीरें हुईं। तब हुआ कि ब्रिटिश सरकारको एक सालकी अन्तिम चेतावनी (अल्टीमेटम) दी जाय। अगर इस अवधिमें वह औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन स्टेट्स) दे देती है, तब तो हिन्दुस्तान कामनवेल्थमें रहेगा अन्यथा नहीं। सन् १९२९ में लाहौर अधिवेशनमें कांग्रेसने अपना ध्येय बदला। पूर्ण स्वतन्त्रताका लक्ष्य उसने स्वीकार किया; मतलब कि उसने माना कि ब्रिटिश साम्राज्य या कामनवेल्थसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा।"

आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देश पड़ोसीके नाते अमेरिकाकी ओर ही ज्यादा झुके रहते हैं, लेकिन एक धर्म, एक नस्ल, एक जवान होनेके कारण वे कामनवेल्थमें भी शिरकत किये हुए हैं। पर हिन्दुस्तान किस दृष्टि से, किस लाभके लिए कामनवेल्थमें रहे?

पण्डित जवाहरलाल नेहरूने बताया कि कुछ क्षणिक लाभ है हमें, पर इसके लिए हम विदेशियोंके खानदानके मेम्बर क्यों बनें? अंग्रेजोंके साथ आप शौकसे दोस्ती रखिये, क्योंकि आजकल ब्रिटेनमें मजदूर सरकार है। उसकी गृहनीति अच्छी है, परन्तु उसकी विदेश-नीति गलत है। ब्रिटिश सरकार सरमायेदारीकी पुरानी परम्पराओंसे घिरी हुई है। वह उन ताकतोंकी उभारती है जो प्रगतिशील नहीं हैं और अब तो उसने

अमेरिकाके साथ मिलकर एक गुट बना लिया है । अमेरिका आज दुनियाकी सबसे खतरनाक ताकत है । सियासी मंशाको पूरा करनेके लिए वह मुल्कोको कर्ज देता है ।

इंगलैण्ड खुद मुंहताज है

कुछ लोग कहते हैं कि हम कामनवेल्थमे रहेंगे तो हमें औद्योगिक निर्माणके लिए मशीने मिलेगी, लेकिन इंगलैण्ड आज इस स्थितिमे है ही नहीं कि वह हमे मशीनें दे सके । अमेरिकासे मशीने मँगानेमे डालरका झगड़ा है । हमारी कांग्रेस सरकारे बजट सेशनके शुरूमें बड़ी लुभावनी योजनाएँ रखती है, लेकिन सालके अन्तमे कहती है कि डालर न मिल पानेके कारण मशीने नहीं आ सकी । पौण्डपावना भी नहीं मिल पा रहा है । हम अलग रहते तो ब्रिटेनपर कुछ दबाव भी डाल सकते थे ।

रूस शत्रु बन गया

जब यह क्षणिक लाभ भी हमे नहीं मिलता, तब आखिर कौनसा फायदा है जिसके लिए हम कामनवेल्थमे रहें ? नुकसान जरूर है । जबसे हमने कामनवेल्थकी साझेदारी मंजूर की है तबसे रूस खामखाह हमारा विरोधी हो गया है । हमारे पड़ोसी एशियाई देशोंमें भी समाजवादकी ताकतें उभड़ रही हैं, उनकी भी इच्छा है कि हिन्दुस्तान कामनवेल्थमें न रहे । कामनवेल्थमे जितने मुल्क हैं, खुलेतौरसे या छिपे-छिपे ऐंग्लो-अमेरिकी गुटमें आ गये हैं । ऐसी हालतमे हम कितना ही तटस्थताका ढोल पीटें, कोई हमपर विश्वास करनेवाला नहीं । सब यही कहेंगे कि अगर आप आज इस गुटके साथ नहीं हैं तो जब मौका पड़ेगा तब उसके साथ हो जायेंगे । अब हमारा मुल्क आजाद है, इसलिए दुनियाके सभी मुल्क हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक गुटके होकर रह गये तब हमसे दूसरे गुटके देश दोस्ती कैसे करेगे ?

[कामनवेल्थकी अर्थनीति]

कामनवेल्थ आखिर है क्या ? उसके पीछे वर्षोंका इतिहास है, वैदेशिक नीति है, एक आर्थिक व्यवस्था है जो पूंजीवादी है । फिर उससे हमारा मेल कैसे हो सकता है ? सरमायेदारोका कोई मुल्क नहीं, वे अपने स्वार्थके लिए अपने मुल्कको कुर्बान कर सकते हैं । न्यायकाईशेकने उन कारणोंको दूर न किया जिनके कारण कम्युनिस्ट आगे बढ़े, उल्टे वह पूंजीवादी अमेरिकाकी गुलामी करता रहा । जबतक सरमायेदारीका सिलसिला रहेगा तबतक दुनिया पनप नहीं सकती, उसमे अमन नहीं रह सकता । सरमायेदारोकी निगाह दुनियाकी दौलत हड़पनेपर रहती है, इसीलिए जंग होती है, राष्ट्र-प्रेम उभारा जाता है और सरमायेदार युद्ध करा देते हैं ।

हम हरेक कामसे दोस्ती करनेको तैयार हैं । हमारा ब्रिटेनसे व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समझौता हो सकता है, परन्तु हम किसी कुनवेमे नहीं दाखिल होंगे । अगर होंगे तो एशियाके आजादी-पसन्द देशोंके कुनवेमे—तरक्की-पसन्द कुनवेमे शामिल होंगे ।

सच्चा स्वराज्य नहीं हुआ

सच्चा स्वराज्य अभी नहीं हुआ है और ६ अगस्त सन् ४२ को शुरू हुई क्रान्तिका दौरा अभी समाप्त नहीं हुआ है । जबतक लोगोकी जहनियत—मनोवृत्ति नहीं बदलती तबतक मुल्ककी समस्याएँ हल न होगी । लाखो लोगोको जबतक एक नयी उम्मीदसे नहीं भर दिया जाता तबतक वे कष्ट-सहनके लिए तैयार नहीं हो सकते ।

जनताकी मायूसी दूर करो

कांग्रेसी सरकारोसे हमारा कहना है—लोगोमे मायूसी छायी हुई है, उसे दूर करना चाहिये । जब जनताको विश्वास हो जायगा कि आप उसके बुनियादी सवालको हल करनेके लिए तैयार हैं तभी वह आपपर विश्वास कर सकेंगी । हमारी शिकायत यह नहीं है कि आपकी रफ्तार धीमी है, पर हमारी शिकायत है कि आपके कदम गलत पड़ रहे हैं । आप लम्बे-चौड़े वादे न कीजिये, छोटे बुनियादी काम ही हाथमे लीजिये अपनी ताकतके मुताबिक; तब जनताका सहयोग आपको प्राप्त होगा । एक बार आपपर विश्वास जमनेपर जनता भी थोड़े दिन और मुसीबत सहनेके लिए तैयार हो जायगी । जनतासे मेरी अपील है कि वह अपनी समस्याओंको खुद समझनेकी कोशिश करे और जो सही रास्ता हो उसे अख्तियार करे ।

तीसरा अध्याय

समाजवादकी ओर

तीसरा अध्याय

कांग्रेस समाजवादी कान्फरेन्स'

हमारे सूबेमे प्रगतिशील शक्तियाँ काफी मजबूत रही हैं। यह सूबा साम्राज्योका लीलास्थल रहा है, अतः हमारे यहाँ बड़े-बड़े शहर बन गये और शहरके रहनेवालोका हमारे राष्ट्रीय जीवनमे अत्यधिक प्रभाव रहा है। शहरके रहनेवाले गाँववालोसे ज्यादा प्रगतिशील होते हैं। इसी कारण हमारे सूबेकी कांग्रेस भी और सूबोसे ज्यादा प्रगतिशील रही है। तब अगर कांग्रेस-समाजवादी पार्टीका हमारे सूबेमें जोर है तो आश्चर्य ही क्या ? अगर हम ठिकानेसे काम करे तो हमारा ख्याल है कि इस सूबेकी कांग्रेसमे हम बहुमत अपनी तरफ कर सकते हैं। बराबर तो हम अब भी हैं। हमारी शक्ति बिखरी हुई है। हम अच्छी तरह संगठित नहीं हैं, नहीं तो यह सूबा प्रगतिशील शक्तियोका नेतृत्व कर सकता और राष्ट्रीय आन्दोलनको आगे बढ़ानेमे सब सूबोसे ज्यादा हिस्सा लेता। इसका सबूत तो यही है कि इन दो-तीन महीनोमे ही पार्टीके करीब-करीब एक हजार सदस्य बन गये। यह कान्फरेन्स इसीलिए की गयी कि हम सबको यह बता दे कि कांग्रेस समाजवादी पार्टीके संगठनका कार्य अब जोरोसे मुस्तैदीसे हो रहा है और फिर हम बहुत दिनोंसे मिले भी नहीं थे तथा मिलकर अपने प्रान्त और देशकी समस्याओपर विचार भी नहीं किया था।

समाजवादी नेतृत्वकी आवश्यकता

हम समाजवादियोको लेनिनकी यह बात बराबर याद रखनी चाहिये कि सामाजिक स्वतन्त्रताके लिए राजनीतिक स्वतन्त्रताकी लड़ाई बहुत जरूरी है। सामाजिक स्वतन्त्रताकी लड़ाई (Social struggle) चलानेके लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक स्वतन्त्रताकी लड़ाई (Democratic struggle) मे पूरा-पूरा हिस्सा लिया जाय और उसे सफल करनेकी कोशिश की जाय। समाजवादी अगर राजनीतिक लड़ाईमे पूरा-पूरा भाग नहीं लेते तो सामाजिक स्वतन्त्रताके लिए लड़नेकी नौबत ही नहीं आयेगी। कांग्रेस समाजवादी पार्टीका जन्म, जैसा कि उसका नाम ही बताता है, इसलिए हुआ था कि इन दोनों तरहकी लड़ाइयोको मिला देनेकी जरूरत थी। समाजवादियोको राष्ट्रीय आन्दोलनमे कांग्रेसमे हिस्सा लेनेके लिए राजी करना था और राष्ट्रीय आन्दोलनमें समाजवादी शक्तियोका प्रभुत्व कायम करना था; एक क्रान्तिकारी नेतृत्व कायम करना था।

१. २ और ३ अप्रैल सन् १९३८ को लखनऊमे प्रान्तीय कांग्रेस समाजवादी कान्फरेन्समे सभापतिकी हैसियतसे दिया गया भाषण।

कांग्रेसमें आन्दोलनका अर्थ अभीतक सिर्फ प्रचार करना रहा है। प्रचार तो 'स्वतन्त्रता' 'स्वराज्य' ऐसी गोल-मटोल बातोंको लेकर किया जा सकता है, मगर जब प्रचारसे काम नहीं चलता और वास्तवमें आन्दोलन (agitation) करनेकी जरूरत पड़ती है तो ऐसी स्पष्ट बातोंसे काम नहीं चलता; खासकर जब उसमें जनताको भी शामिल करनेकी बात हो। ऐसे आन्दोलनके लिए जिसमें जनताको पूरा-पूरा शामिल करना है, कुछ साफ-साफ ठोस बातोंकी जरूरत होती है, जिनका जनताकी रोजाना जिन्दगीसे गहरा सम्बन्ध हो यानी जनताकी आर्थिक माँगोंको वृद्ध करनेकी जरूरत पड़ती है। यही एक तरीका राजनीतिक स्वतन्त्रताकी लड़ाईको आगे बढ़ाने, उसमें और भी ताकत लानेका है। जनसाधारणको संगठित कर उनमें लड़नेकी ताकत पैदा करनेका और कोई उपाय नहीं है। फिर तो यह साफ है कि यह काम बिना सामाजवादी नेतृत्वके पूरा नहीं हो सकता था। इन्हीं कारणोंसे समाजवादी पार्टी पैदा हुई और इन्हीं उद्देश्योंको हासिल करनेकी वह कोशिश करती रही है।

आर्थिक माँगोंकी बुनियादपर आन्दोलन करनेसे, आर्थिक लड़ाई लड़नेसे, देशकी ताकत बढ़ती है। इसीसे कांग्रेसकी भी ताकत बढ़ी है। इसका मिसाल तो पिछले असेम्बलियोंका चुनाव ही था। अधिकांश कांग्रेसजनोंको यह विश्वास नहीं था कि इस पिछले चुनावमें कांग्रेसकी इतनी जबरदस्त जीत होगी, क्योंकि वह आर्थिक माँगोंके बिना चलाये गये आन्दोलनकी ताकत नहीं जानते थे। इस चुनावने उनकी आँखें खोली।

सज्जत संगठन बनाइये

अब इतना तो जरूर हो गया है कि लोग अपनेको समाजवादी कहनेसे घबराते नहीं। अब तो सभी लोग आज यह साबित करनेकी कोशिश करते हैं कि एक नये प्रकारका समाजवाद वह भी चाहते हैं। महात्मागांधी भी अपनेको समाजवादी कहते हैं। ऐसी हालतमें एक समाजवादीकी पहचान बातोंसे नहीं हो सकती। उसकी काररवाईको देखना होगा। हम भी प्रचारसे आगे बढ़कर संगठनके कार्यमें जुट जायेंगे तो खरे और खोटे समाजवादीकी परख करना आसान हो जायगा। इसलिए हमें संगठनके कार्यपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके लिए अपना एक पत्र होना चाहिये और अपने विचारोंका प्रतिपादन करनेके लिए पुस्तक-पुस्तकाएँ तैयार करनी चाहिये।

हमारे संगठनकी कमजोरी उसके शिथिल होनेके कारण हमें बड़ी मुश्किल हो रही है। यह जो कांग्रेसके अन्दर नरमदल-और गरमदलवालोका झगड़ा उठ खड़ा हुआ है इसका दारोमदार मेरे ख्यालमें हमारी संगठनकी शिथिलतापर है। किसान-सभाओं और कांग्रेसके सम्बन्धको ही लीजिये। यह ठीक है कि कांग्रेसके कुछ नेता कांग्रेसके कार्यकर्ताओं-को किसान-सभाओंमें काम करनेसे रोकते हैं, किसान-सभाओंका पनपना उन्हें बुरा लगता है, मगर मेरा विश्वास है कि इच्छा होते हुए लोग ऐसा नहीं कर पाते अगर किसान-सभाओंके ऊपर अनुभवी अग्रगामी कांग्रेसजनोंकी अच्छी देख-रेख होती। किसान-सभाओंका दायरा इतना बढ़ गया है और देखरेख करनेवाले इतने कम या असंगठित हैं कि

किसान सभाओंकी काररवाईकी अच्छी देख-रेख नहीं हो पाती । तरह-तरहके लोग किसान-सभाओंमें घुस पड़े हैं और मनमानी काररवाई करते हैं । मेरा विश्वास है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी यदि अच्छी तरह संगठित होती और किसान-सभाओंकी काररवाईपर पूरा नियंत्रण रखती तो कांग्रेसके नरमदलको शिकायत करनेका मौका मुश्किलसे मिलता और किसान-सभाओंके खिलाफ लोगोको भड़कानेमें इतनी आसानी न होती । इससे यह साफ है कि हमारे राष्ट्रीय सयुक्त मोर्चेका हमारे अच्छी तरह संगठित होनेसे कितना सम्बन्ध है ।

इसी संगठनकी कमजोरीके कारण शासन-सकटके जमानेमें हरिपुरा-कांग्रेसमें हमारी पार्टी कमजोर पड़ गयी । जैसा नेतृत्व उसे देना चाहिये था वह न दे सकी । अगर हमारा संगठन अच्छा होता, हमे अपनी संगठित शक्तिपर भरोसा होता तो हरिपुरामें आपको दूसरा ही दृश्य देखनेको मिलता ।

संगठनके सम्बन्धमें हमे एक दो बातें याद रखनी हैं । हमारी पार्टीको खतरा ऐसे लोगोसे है जो समाजवादके सिद्धान्त या तरीकोमें विश्वास न रखते हुए हमारी पार्टीमें इसलिये आ जाते हैं कि वह कांग्रेसके नेतृत्वसे जाती बातोंकी वजहसे चिढ़े हुए हैं या जो हमारी पार्टीको कांग्रेसके ओहदे हासिल करनेका साधन बनाना चाहते हैं । हमे ऐसे लोगोसे बचना है और ऐसे लोगोको ही पार्टीमें दाखिल करना है जिनकी परख असली तरीकेसे हो चुकी है । दूसरी बात जो हमे ख्यालमें रखनी चाहिये वह यह है कि दूरदराजकी बातोंपर उतना ध्यान न देकर हमे आजकी बातोंपर ध्यान देना चाहिये । मूल सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें कड़ाई इतनी जरूरी नहीं है जितनी कि आजके आन्दोलनके तौर-तरीकोके सम्बन्धमें । दूसरे शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि मूल सिद्धान्तोंसे ज्यादा महत्त्वकी बात हमारे लिए इस समय विधि और उपाय (tactics) हैं । प्रजातान्त्रिक क्रान्तिके लिए हमारी जो लड़ाई चल रही है उसमें सफल नेतृत्व करनेके लिए सुलझे हुए उपायोका निर्धारण करना ही सबसे बड़ा काम है । इस कारण सदस्योंकी छान-बीन करते समय हमे इस बातका ख्याल करना है कि पार्टीके अन्दर ऐसे ही लोग दाखिल किये जायँ जो राष्ट्रीय आन्दोलनका सफल नेतृत्व करनेकी योग्यता रखते हो यानी हमारी आजादीकी लड़ाईको आगे बढ़ानेके सुलझे हुए तरीको की सच्ची वाकफियत रखते हो ।

जबतक हम अपना संगठन मजबूत नहीं करते हम न तो प्रगतिशील शक्तियोका ही नेतृत्व कर सकते हैं और न राष्ट्रीय आन्दोलनका ही । कांग्रेस समाजवादी पार्टीके सामने दो बड़े-बड़े काम हैं । एक तो सभी अग्रगामी शक्तियोको एक साथ करना और दूसरा ब्रिटिश साम्राज्यशाहीके खिलाफ अग्रगामी शक्तियोके नेतृत्वमें जवर्दस्त सयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा तैयार करना । यह बात साफ है कि दूसरे काममें हमे सफलता तभी मिलेगी जब हम पहले कामको अन्जाम दे सकें । हमे खुशी है कि हमारी पार्टी इसके लिए अपने जन्म-कालसे ही प्रयत्नशील रही है । हमे यह प्रयत्न जारी रखना है ।

साथ-ही-साथ हमे इसकी कोशिश करनी है कि कांग्रेसके अन्दर सुधारवादी मनोवृत्ति जोर न पकड़ने पावे । हमारी आजकी जो अवस्था है उसमें शासन संकटोका होना

अनिवार्य है। एक तो अभी खत्म हुआ, मगर अभी और आनेवाले हैं। इनका मुकाबला करनेके लिए राष्ट्रीय आन्दोलनके क्रान्तिकारी नेतृत्वकी आवश्यकता है। हमें लोगोंको यह समझाना है कि साम्राज्यशाहीको मजबूर करनेकी ताकत हममे तभी आयेगी जब हम जनताकी आर्थिक लड़ाईको राजनीतिक लड़ाईके साथ घुलमिल जाने दें। उदाहरणके लिए किसानों और मजदूरोंके प्रदर्शनकी विधि हमे काममें लानी है। उन्हें अपनी माँगोंके लिए संगठित रूपसे आन्दोलन करना सिखाना है। कांग्रेसके चार आना मेम्बरोसे हमारा सच्चा सम्पर्क इसी तरह हो सकता है।

आजकी हालत तो यह है कि ऐसे प्रदर्शनोंपर नाराजगीका इजहार किया जाता है। कहा जाता है कि इनकी जरूरत क्या है। इस विचारधारा, इस मनोवृत्तिको हमें दूर करना है। ऐसे प्रदर्शनोंमे यहाँतक कि किसान-सभाओंके कायम करनेमें कांग्रेसके बड़े-बड़े नरमदलके नेता भी पुराने जमानेमे शामिल हो चुके हैं। खुद मरदार बल्लभभाई पटेल हमारी प्रान्तीय किसान संघकी बैठककी सदस्यता कर चुके हैं। मगर आज चूँकि किसान-सभाएँ क्रान्तिकारी रूप अख्तियार कर रही हैं, इन्हे खतरनाक बताया जाता है।

इससे यह पता चलता है कि इसमे कोई सिद्धान्तकी बात नहीं है। मगर हमे अपना काम इस तरह करना चाहिये जिसमे हमें इन्हें कांग्रेसके साधारण सदस्योंकी निगाहमें बदनाम करनेका कोई बहाना न मिले। लाल झण्डा ले चलना ठीक है, मगर उसे राष्ट्रीय प्रदर्शनोंमे राष्ट्रीय झण्डेसे ऊँची जगह देना एक गलत बात है। ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनको ध्यानमे रखकर अगर हम काम करें तो कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलनको क्रान्तिके पथपर बढ़ाते हुए हम राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और समाजवादकी बीचकी मंजिलें तेजीसे तय करते जायेंगे। यह ठीक है कि समाजवादी होनेकी हैसियतसे हमें इसकी तैयारी करनी है कि स्वराज्यकी लड़ाई जैसे ही खतम हो या उसके खतम होते-होते सामाजिक स्वतन्त्रताकी लड़ाई शुरू हो जाय, मगर यह भी ठीक है कि अगर स्वराज्यकी लड़ाईमे हम जल्दसे जल्द कामयाबी हासिल नहीं करते तो सामाजिक स्वतन्त्रताकी लड़ाईकी नीवत ही नहीं आयेगी।

संयुक्त मोर्चा और भारतीय कम्युनिस्ट

विविध विचार रखनेवाले व्यक्तियों या समुदायोंमे किसी सामान्य शत्रुके विरुद्ध या किसी विशेष उद्देश्यकी पूर्तिके लिए जो संयुक्त कार्य किया जाता है वही प्रधान रूपसे संयुक्त मोर्चा है। यूरोपमे फैसिज्म और युद्धका विरोध करनेवाली कई संस्थाएँ रही हैं, पर इन संस्थाओंके उद्देश्य और उनकी कार्यप्रणाली समान न थी। आपसमें कई प्रश्नोंको लेकर इनमे काफी मतभेद और विरोध था। बाजी संस्थाएँ तो एक दूसरेकी ही परम शत्रु थी। किन्तु इनमेसे जिन संस्थाओंने यह अनुभव किया कि तत्काल अपने मौलिक मतभेदोंको भुलाकर मिलजुलकर सामान्य शत्रुका सामना करना चाहिये, उन्होंने इस

विशेष उद्देश्यसे आपसमें संयुक्त मोर्चा कायम किया । समाजवादके विरोधी प्रजातन्त्रवादियोंको भी यह लगा कि यदि फैसिज्मका उत्कर्ष होता है तो उससे प्रजातन्त्रकी क्षति होती है और प्रजातन्त्रके लोपकी सम्भावना उत्पन्न हो जाती है । 'समान शीलव्यसनेषु सख्यम्' की नीतिके अनुसार एक ही मुसीबतमें गिरपतार समुदाय और संस्थाओंने समान शत्रुका मुकाबला करनेके लिए आपसमें एक संयुक्त मोर्चा कायम किया । इसी प्रकार चीनमें जब जापानका आक्रमण प्रबल वेगसे बढ़ने लगा तब राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टोंने आपसकी लड़ाईको वन्द कर जापानके आक्रमणका सफलताके साथ मुकाबला करनेके लिए एक संयुक्त मोर्चा कायम किया ।

संयुक्त मोर्चेकी कठिनाइयाँ

एक विशेष अवसरपर किसी विशेष प्रश्नको लेकर भी क्षणिक संयुक्त मोर्चा कायम किया जाता है । यह संयुक्त मोर्चा व्यक्तियों और समुदायों दोनोंके बीच हो सकता है । संयुक्त मोर्चा कायम करनेमें कई तरहकी कठिनाइयाँ पड़ा करती हैं । जो सस्थाएँ कलतक एक-दूसरेकी टीका-टिप्पणी किया करती थी और एक-दूसरेके नेताओंकी निन्दा किया करती थी, उनका किसी एक प्रश्नपर भी संयुक्त मोर्चा कायम करना दुष्कर होता है । पुरानी वाते जल्दी भुलायी नहीं जा सकती और व्यक्तिगत द्वेषके कारण नेता संयुक्त मोर्चेको अकसर कायम भी नहीं होने देते । यदि नेता दूरदर्शी नहीं हैं, समयकी आवश्यकताको नहीं पहचानते और आपसके झगड़ोंसे ऊपर नहीं उठ सकते तो संयुक्त मोर्चा साधारणतया नहीं कायम हो पाता । प्रायः जब दोनों ओरसे इसकी आवश्यकता अनुभव की जाती है या जनसमुदाय अपने नेताओंको इसके लिए विवश करता है, तभी संयुक्त मोर्चा कायम होता है । राष्ट्रपर विदेशी आक्रमण होनेसे या कोई सामान्य भारी खतरा उत्पन्न होनेसे संयुक्त मोर्चा सुगमतासे कायम हो जाता है । किन्तु साधारण अवस्थामें इसमें बड़ी अड़चनें पड़ती हैं । जब दो सस्थाओंमें संयुक्त मोर्चा कायम होता है तो उसकी शर्तें और मोर्चेका कार्यक्रम भी तय कर लिया जाता है । यद्यपि सस्थाएँ संयुक्त मोर्चा बनानेके वाद भी एक-दूसरेकी समालोचना करती रहती हैं, तथापि आलोचनाकी शैली बहुत कुछ बदल जाती है । यह भी देखनेमें आता है कि सब शर्तें तय हो गयी और काम चल निकला, किन्तु कुछ समय बाद मोर्चा टूट गया, क्योंकि एक दल संयुक्त मोर्चेमें प्रधान स्थान पानेकी अनुचित चेष्टा करता है, जिससे दूसरोको उसकी जिम्मेदारी और सद्भावनापर सन्देह होने लगता है ।

संयुक्त मोर्चेके तरीके

कम्युनिस्टोंकी भाषामें यह मोर्चा 'ऊपरसे' (from above) और 'नीचेसे' (from below) दो तरहसे कायम होता है । इन शब्दोंका अर्थ हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । जब म्वाहिदा दो सस्थाओंके नेताओंके दरमियान होता है तब कहा जाता है कि संयुक्त मोर्चा 'ऊपरसे' कायम हुआ । जब ऐसा कोई म्वाहिदा नहीं हो पाता तब साधारण सदस्योंके साथ मिलकर काम करनेकी चेष्टा की जाती है ।

उनको बतलाया जाता है कि नेता स्वार्थी हैं या दूरदर्शी नहीं हैं, वह संयुक्त मोर्चेकी नितान्त आवश्यकताको नहीं महसूस करते। इसके बिना जनताके आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष सफलताके साथ नहीं चलाये जा सकते, अतः तुमको नेताओंकी परवाह नहीं करनी चाहिये और हमारे साथ मिलजुलकर कार्य करना चाहिये। इसे नीचेसे संयुक्त मोर्चा (united front from below) कहते हैं।

जिस देशकी व्यवस्था ही ऐसी हो कि वहाँका शासनविधान राज्यमें एकसे अधिक दलकी स्थापनाकी इजाजत नहीं देता, वहाँ ऊपरसे संयुक्त मोर्चेका प्रश्न ही नहीं उठता; वहाँ एक ही प्रकारकी विचारशैली राज्यसे स्वीकृत होती है। वहाँ तो विभिन्न विचार रखनेवाली संस्थाएँ होती ही नहीं। वहाँ विभिन्न विचारके व्यक्ति या छोटे समुदाय ही होते हैं; इसलिए इन विभिन्न विचारके लोगोंको संयुक्त मोर्चेके लिए राजी करना पड़ता है। इसे 'नीचेसे संयुक्त मोर्चा' कह सकते हैं, पर इस प्रकारके संयुक्त मोर्चेकी कोशिश उन देशोमें भी की जाती है जहाँ एकसे अधिक विभिन्न विचारवाली संस्थाएँ मौजूद होती हैं। यह तभी होता है जब उनके नेताओंसे कोई समझौता हो नहीं पाता या उनसे समझौता करना इष्ट नहीं होता। तब साधारण सदस्योंमें नेताओंके विरुद्ध प्रचार किया जाता है और उन्हें साथ काम करनेके लिए तैयार किया जाता है। जो नदस्य इस प्रकारसे प्रभावित हो अपनी पुरानी संस्था छोड़ देते हैं और दूसरी संस्थामें शरीक हो जाते हैं उनके बारेमें यह नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ संयुक्त मोर्चा स्थापित किया गया है। यह उन्हींके बारेमें कहा जा सकता है जो अपनी पुरानी संस्थामें रहते हुए संयुक्त मोर्चेके साथ पूरा सहयोग करते हैं। किन्तु यह साफ है कि नेताओंके पीठ पीछे 'नीचेसे' संयुक्त मोर्चा कायम करना सम्भव नहीं है। इस प्रयत्नमें बहुत कम सफलताकी सम्भावना है। प्रत्येक संस्थाका अपना नेतृत्व और अपना अनुशासन रहता है। संस्थाका प्रत्येक सदस्य इनसे बंधा रहता है। नेतृत्वके प्रति उसकी श्रद्धा होती है। उसकी उपेक्षा कर साधारण सदस्योंके साथ संयुक्त मोर्चा स्थापित करना माधारणतः सम्भव नहीं होता। एक ऐसी विराट संस्थामें जिसकी शाखाएँ दूरतक फैली हों और जिसका अनुशासन कुछ ढीला हो यह सम्भव है कि इस कार्यमें कुछ स्थानीय कमेटियोंके साथ संयुक्त कार्य करनेका अवसर मिले। किन्तु यह बात बड़े पैमानेपर नहीं हो सकती। यह एक ऐसी बात है जिसके समझनेमें देर न लगनी चाहिये, पर हमारे कम्युनिस्ट भाई कभी-कभी 'नीचेसे संयुक्त मोर्चा' के नारेको बुलन्द करते देखे जाते हैं। नेताओंके साथ समझौता करके ही किसी संस्थाका हार्दिक सहयोग प्राप्त हो सकता है और वही प्रभावशाली भी होता है। यह कहना कि हम साधारण सदस्योंके साथ तो संयुक्त मोर्चा बनानेको तैयार हैं, किन्तु उनके नेताओंके साथ नहीं, कोरा पाण्डित्य होगा। यह तो वैसी ही बात होगी जैसी कि यदि कोई कहे कि हम पूँजीपतियोंके विरुद्ध की गयी हड़तालको समाप्त करनेके लिए समझौतेकी बातचीत तो करनेको तैयार हैं, किन्तु उनके साथ नहीं। हड़तालको खतम करनेके लिए किसी न किसी समय पूँजीपतियोंके साथ आपको बातचीत करनी ही होगी। उसी प्रकार सगठित जनताको संयुक्त कार्यके लिए आमंत्रित करना तबतक सम्भव नहीं

है जबतक आप उन नेताओंसे बातचीत नहीं करते जिनको जनता श्रद्धा और विश्वासकी दृष्टिसे देखती है। किसी और प्रकारसे कार्य करनेका अर्थ होगा महज राजनीतिक निश्चेष्टताका प्रदर्शन।

किन्तु हमारे कम्युनिस्ट भाई कभी 'ऊपरसे' सयुक्त मोर्चेकी नीति वर्तते हैं और कभी 'नीचेसे'। अवस्थाके अनुसार वह सदा अपनी नीतिको बदलते रहते हैं, किन्तु उनको इसमें विशेष सफलता नहीं मिली है।

कांग्रेस और कम्युनिस्ट

हिन्दुस्तानके सामने सबसे बड़ा और पहला सवाल पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना है है विविध वर्गके लोग ब्रिटिश साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए कांग्रेसमें सम्मिलित हैं। इस विरोधके लिए कांग्रेस ही प्रधान संस्था है। कांग्रेसके अतिरिक्त अन्य साम्राज्य-विरोधी संस्थाएँ भी हैं, जैसे मजदूर-सभा, किसान-सभा, युवक-सघ, विद्यार्थी-सघ आदि।

भारतके कम्युनिस्टोका कांग्रेसके प्रति रुख सदा एकसा नहीं रहा है। यह बार-बार बदलता रहा है। कभी वह कांग्रेसमें रहनेके पक्षपाती रहे हैं, कभी नहीं। किन्तु एक बातमें उनकी राय कभी नहीं बदली है; वह कांग्रेसको निश्चित रूपसे भारतके पूँजीपतियोंकी वर्ग-संस्था मानते हैं। उनका विचार है कि कांग्रेसका नेतृत्व सदैव सगठन और विचार-शैलीकी दृष्टिसे पूँजीवादी रहा है और उसका कार्यक्रम और उसकी नीति पूँजीवादी वर्गके स्वार्थों और हितोंका पोषक रही है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस और उसके नेताओंका महत्त्व कम करनेकी सदा चेष्टा की है। वह जनताको कांग्रेसके प्रभाव-क्षेत्रसे अलग करना चाहते हैं।

१९२८ का घातक निश्चय

सन् १९२८ तक कम्युनिस्ट कांग्रेसमें भी काम करते थे और कहीं-कहीं उसकी कार्यकारिणी समितिके सदस्य भी थे। उस समय उनकी संख्या बहुत स्वल्प थी। चीनमें भी कम्युनिस्ट वहाँकी राष्ट्रीय संस्था, 'कुओमिन्ताग'में शरीक थे। अपनी स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ता कायम रखते हुए उन्होंने 'कुओमिन्ताग'में प्रवेश किया था। सनयातसेनकी अनुमतिसे ही यह कार्य हुआ था। इससे कम्युनिस्टोको राष्ट्रीय आन्दोलनको प्रभावित करनेका अच्छा अवसर मिला था। इस नीतिका अवलम्बन करनेसे चीनकी जनतामें कम्युनिस्टोका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। साथ-साथ 'कुओमिन्ताग' की नीतिको भी बनाये रखनेमें वह सफल हुए थे। किन्तु सन् १९२७-२८ में कम्युनिस्टो और दूसरोंसे झगड़ा हो गया, वह 'कुओमिन्ताग' से निकाल दिये गये और च्यांगकाई शेकने उनको नेस्तनाबूद करना चाहा। चीनके अनुभवके बाद उपनिवेश-सम्बन्धी नीति एकदम बदल गयी और सन् १९२८ में कम्युनिस्ट इण्टर-नेशनलने यह निश्चय किया कि उपनिवेशोंमें राष्ट्रीय सुधारवादी संस्थाओंसे किसी तरहकी शिरकत नहीं हो सकती। इस निश्चयके अनुसार भारतके कम्युनिस्ट भी कांग्रेससे अलग हो गये और सन् १९३०-३२ के सत्याग्रह-आन्दोलनमें

भाग लेनेके वजाय उनका विरोध करते रहे । सन् १९२८ के बाद कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही कमजोर हो गयी और अपनी संकुचित नीतिके कारण जनान्दोलनसे बहुत कुछ अलग हो गयी । ट्रेड यूनियन कांग्रेसमें भी दो दल हो गये और कम्युनिस्टोंने अपनी 'लाल' यूनियन अलग बनायी । सन् १९३४ में पार्टीकी नीतिका स्पष्टीकरण करनेके लिए एक मसविदा तैयार किया गया और इसीके आधारपर पार्टीका संगठन शुरू हुआ । पार्टीने मजदूर, किसान और शोपित मध्यम श्रेणीका एक साम्राज्यविरोधी संयुक्त मोर्चा बनानेका निश्चय किया । उसके लिए उन्होंने एक स्वतन्त्र संस्थाका निर्माण आवश्यक समझा जिसका अपना प्रोग्राम हो । इस सम्बन्धमें अपनी 'थीसिस' (फरवरी, ३४) में उन्होंने लिखा कि "आज कम्युनिस्ट पार्टीके सामने सबसे जरूरी काम एक ऐसी संस्थाका निर्माण करना है जो साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए समस्त शोपित वर्गके संयुक्त मोर्चेकी अभिव्यक्ति हो । कम्युनिस्ट पार्टीके प्रभावमें तैयार किये हुए क्रान्तिकारी कार्यकर्ता इस मोर्चेके मूलाधार होंगे और क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन किसान-सभाएँ और युवक-सघके क्रान्तिकारी अंशोंके सामूहिक सम्बन्धके आधारपर यह संस्था बनायी जायगी । इसे हम (Anti-Imperialist League) अर्थात् "साम्राज्यविरोधी लीग" कह सकते हैं । सब शोपित वर्गोंकी माँगे इसके प्रोग्राममें शामिल की जायँगी और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, मजदूर और किसान राज्य-आदि इसके नारे होंगे । यह एक सर्वसाधारणकी संस्था होगी जिसमें सभी शोपित वर्गके लोग सम्मिलित होंगे । इस लीगकी स्वतन्त्र सत्ता होगी । यह कांग्रेससे केवल स्वतन्त्र ही नहीं होगी, किन्तु उसकी विरोधी होगी । लीगको निरन्तर सुधारवादी नेताओं और संस्थाओंकी आलोचना करनी चाहिये और श्रमिकोंके सामने उसके वास्तविक चरित्र (role) का उद्घाटन करना चाहिये । साथ ही साथ इसे अपने झण्डे और नारोंके साथ कांग्रेसके प्रदर्शनमें भी भाग लेना चाहिये । निम्न मध्यम श्रेणीके सगठनोंमें उदाहरणके लिए युवक-सघोंमें, सुधारवादी किसान-सघोंमें इसे अपनी टुकड़ियाँ इस गरजसे भेजनी चाहिये ताकि ये सगठन लीगमें दाखिल हो जायँ । श्रमिक जनतासे सुधारवादिसंगठन और नेतृत्वको अलग करनेके लिए यह निहायत जरूरी है कि कम्युनिस्ट संयुक्त मोर्चेमें अपने नेतृत्वको कार्यरूपमें सिद्ध कर दिखावें ।" इस उद्धरणसे यह स्पष्ट हो जायगा कि सन् ३४ में कम्युनिस्ट कांग्रेसको संयुक्त मोर्चेसे बाहर ही नहीं रखते थे, किन्तु संयुक्त मोर्चेकी एक संस्था उसके विरोधमें खड़ा करना चाहते थे । इसका कारण यही था कि वह कांग्रेसको एक सुधार-वादी संस्था समझते थे ।

कांग्रेस समाजवादियोंकी निन्दा

सन् १९३४ में जब कांग्रेस समाजवादी पार्टीका जन्म हुआ तब उन्होंने इसे left reformism अर्थात् वामपक्षीय सुधारवादका लकव दिया । उनके मतसे कांग्रेसमें पूँजीवादी विचारधाराका ही प्रधान्य था और गांधीवाद और 'कांग्रेस समाजवाद' एक ही विचारधाराके दो पक्ष थे । उनके अनुसार कांग्रेस समाजवादी पार्टी जनताके विद्रोहका

विकास न करके उसकी तरक्कीको रोकनेवाली थी । उनका ख्याल था कि यह महज कम्युनिस्टोंके प्रभावको रोकनेकी एक तरकीब है ।

सन् १९३५ मे कम्युनिस्टोंकी सातवी कांग्रेस हुई और उसमे कुछ महत्वपूर्ण निश्चय हुए । उन्होने अपनी पुरानी भूलोको स्वीकार किया और ट्रेड यूनियन एकताकी नीति फिरसे स्थिर की, सकीर्णताके परित्याग करनेका आदेश दिया और संयुक्त मोर्चेकी नीतिको नये ढंगसे वर्तनेपर जोर दिया । किन्तु इस नीतिका अनुसरण एक साथ सब देशोमे नही किया गया । इस नयी नीतिको लेकर हिन्दुस्तानके कम्युनिस्टोमे बहुत वाद-विवाद हुआ और धीरे-धीरे यह नयी नीति काममे लायी जाने लगी । कांग्रेस समाजवादी दल अपने जन्मकालसे ही ट्रेड यूनियन एकताके लिए प्रयत्नशील था और जब कम्युनिस्टोने 'इण्टर नेशनल' से नया आदेश पाया तो अपनी 'लाल' यूनियन तोड़ दी और एकताके लिए कांग्रेस समाजवादी दलके साथ सहयोग किया । धीरे-धीरे पुरानी संयुक्त मोर्चेकी नीति भी बदलने लगी । अब कम्युनिस्टोने कांग्रेसकी स्थानीय कमेटियोंकी ओर ध्यान देना उचित समझा । उस समय कम्युनिस्ट पार्टी गैर कानूनी करार दी जा चुकी थी । इसलिए उसे सब कानूनी अवसरोंसे लाभ उठाना था । इसी गरजसे वह कांग्रेससे भी लाभ उठाना चाहती थी । कांग्रेसमे जनताके सम्पर्कमे आनेका अच्छा मौका मिलता था और इस काममे हुकूमत रुकावट भी नही डाल सकती थी । कम्युनिस्ट उन श्रेणियोंपर इस प्रकार अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे जो उनके विचारसे साम्राज्यवादका विरोध तो करना चाहती थीं किन्तु अभी कांग्रेस संस्थासे पृथक् नही हुई थी । कम्युनिस्ट पार्टीकी कांग्रेससे शिरकतका तो सवाल ही नही उठता था । पार्टीको सुधारवादका उसी प्रकार विरोध करना था जिस प्रकार साम्राज्यशाहीका । कम्युनिस्ट कांग्रेस सगठनका अपने मतलबके लिए उपयोग करना चाहते थे, जनताको सगठित संघर्षके लिए तैयार करना चाहते थे, और उसको सुधारवादियोंके प्रभावसे मुक्त करना चाहते थे । इसके विपरीत उनके कथनानुसार रायपथी और समाजवादी कांग्रेसको बलिष्ठ करनेके हकमे थे ताकि वह सफलताके साथ मजदूर, किसान और शहरके गरीबोंको धोखेमे रख सके ।

कम्युनिस्टोंकी आत्म-प्रवंचना

कम्युनिस्टोंकी रायमे जनताका कांग्रेसकी समझौतेकी नीतिपरसे विश्वास उठ गया था, किन्तु कम्युनिस्ट पार्टी इस परिस्थितिसे पूरा लाभ नही उठा सकी थी और उसके कामको बिगाड़नेके लिए समाजवादी दल उत्पन्न हो गया था । उसकी रायमे कम्युनिस्टोंके बढ़ते हुए प्रभावको दवानेके लिए ही यह एक नया तरीका सुधारवादियोंने निकाला था ताकि समाजवादके नामपर जनताकी आखमे धूल डाली जाय ।

कांग्रेस तो उनके मतसे सुधारवादी संस्था थी, किन्तु देशमे कतिपय मजदूर-यूनियन तथा कुछ अन्य साम्राज्यविरोधी संस्थाएँ मौजूद थी जो सुधारवादकी कट्टर विरोधी थी और जो क्रान्तिकारी जनताको अपनी ओर आकृष्ट करनेका सामर्थ्य रखती थी । किन्तु अब वह यह सोचने लगे थे कि इन संस्थाओंका प्रभाव कही अधिक हो सकता है

“यदि संस्थाओं के रूप में वह कांग्रेस की स्थानीय संस्थाओं से सहयोग करे। इस सहयोग का आधार सामूहिक सदस्यता होना चाहिये। कांग्रेस के साथ सम्बन्ध होना जरूरी है, क्योंकि साम्राज्यविरोधी संघर्ष इससे तेजी के साथ बढ़ाया जा सकता है, पर इस सम्बन्ध का यह अर्थ न होगा कि वे अपनी स्वतन्त्रता और अपना स्वरूप ही खो बैठे। कांग्रेस से सम्बन्ध स्थापित करने के बाद यह संस्थाएँ सब क्रान्तिकारी अंशों को एकत्र कर गांधीजी की शैली के अनुसार नहीं, किन्तु सही ढंग से संघर्ष करेगी। जनता को एक स्वतन्त्र राजनीतिक शक्त के बनाने में सहायक होना आवश्यक है।”

इस उद्धरण से यह बात साफ हो जाती है कि कम्युनिस्ट सन् १९३६ में यह चाहते थे कि क्रान्तिकारी संस्थाएँ कांग्रेस कमेटी से सम्बन्ध स्थापित कर उनके सदस्यों को कम्युनिस्ट ढंग से संघर्ष करने के लिए तैयार करे। इसमें प्रधानता कांग्रेस की न थी, किन्तु अन्य संस्थाओं की थी। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह कांग्रेस के दायरे के लोग इस प्रकार के संयुक्त मोर्चे में शामिल नहीं किये जा सकते थे। वास्तव में वह कांग्रेस का सम्बन्ध इसलिए चाहते थे कि कांग्रेस कानूनी काम के लिए मौका देती थी और कांग्रेस एक राजनीतिक क्षेत्र भी था जहाँ शोषित वर्गों के विविध समूह बनते थे। वह चाहते थे कि असली क्रान्तिकारी संस्थाएँ इस क्षेत्र का अपने लिए उपयोग करे। उनकी राय में आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों के लिए जनता को तैयार करने और उसको कांग्रेस के प्रभाव से अलग करने का सबसे प्रभावशाली तरीका संयुक्त मोर्चे की नीति ही थी। कांग्रेस के बारे में सामान्य रूप से उनकी राय इतनी खराब थी कि वह अपने भोलेपन में यह समझते थे कि ‘जो लोग वरसों गांधीजी की दुम में बँधे रहे वह कैसे मजदूर और किसान से प्रेम कर सकते हैं और हिन्दुस्तान में समाजवादी राज्य स्थापित करने की बात सोच सकते हैं।’ इसका तो यह अर्थ हुआ कि एक बार जो गांधीवादी हो गया, वह कभी छुटकारा नहीं पा सकता। उनका शायद यह ख्याल है कि जिस-पर कभी कांग्रेस का साया नहीं पड़ा है वह ज्यादा आसानी से क्रान्तिकारी बनाया जा सकता है। यह है क्रान्तिकारी मनोवृत्ति और राजनीतिज्ञता !

किसान सभा और कम्युनिस्ट

सन् १९३६ में अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन हुआ था। उसका कार्यक्रम क्या हो और उसकी सत्ता किस प्रकार की हो इस पर एक ‘थोसिस’ में कम्युनिस्टों ने विचार किया था। उसका कहना था कि “ये किसान सभाएँ प्रायः कांग्रेस जनो और कांग्रेस समाजवादियों द्वारा संगठित होगी और इसलिए इन पर कांग्रेस का कुछ प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। पर हमको दृढ़ता के साथ अनुरोध करना चाहिये कि आरम्भ से ही किसान सभा की स्वतन्त्र सत्ता हो और वह कांग्रेस का पुछला न बने। किसानों पर जो कांग्रेस का प्रभाव है उसको घटाने के लिए हमें किस नीतिका सहारा लेना चाहिये? हमारे कुछ साथी गाँव में कांग्रेस के प्रभाव को सही तौर से नहीं आँकते। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसानों में कांग्रेस के प्रति बहुत असन्तोष है, विशेषकर गाँव के

स्वयंसेवकोंमें । हमको निस्सन्देह किसान सभाको कांग्रेसका पुछल्ला वननेसे रोकना चाहिये, पर यह काम होशियारीसे होना चाहिये ! हमे कांग्रेसकी नीति और उसके श्रेणी आधारको खोलकर बता देना चाहिये ”।

यह उद्धरण भी कांग्रेसको कमजोर करने और अन्य स्थानोंको मजबूत बनानेकी नीतिकी ओर इशारा करता है ।

दत्त और ब्रैडलेका लेख

कुछ दिनों बाद कामरेड दत्त और ब्रैडलेका लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था ‘हिन्दोस्तानमें साम्राज्यविरोधी जनमोर्चा ।’

यह लेख बड़े मार्केका था । इसमें प्रथम बार कम्युनिस्टोंद्वारा स्वीकृत किया गया था कि कांग्रेस अपने संगठन और कार्यक्रममें कुछ और परिवर्तन कर साम्राज्यविरोधी जनमोर्चा बन सकती है । हमे वस्तुसे काम है, न कि नामसे । किन्तु हमे यह मानना होगा कि आजकी हालतमें कांग्रेस अभी संयुक्त मोर्चा नहीं बन पायी है । उसके विधानमें अब भी जनताके कई अंश छूट जाते हैं । उसका प्रोग्राम अभी पूरी तरह साफ-साफ राष्ट्रीय संघर्षका प्रोग्राम नहीं है । उसका नेतृत्व भी अभी ऐसा नहीं है । जनताकी निहित शक्तियोंका उद्बोधन करनेके बजाय वह उनपर ‘ब्रेक’ का काम करता है । जरूरत इस बातकी है कि कांग्रेसके द्वारा जो एकता सिद्ध हो चुकी है उसमें किसी प्रकारकी कमी किये बिना उसका अधिक विस्तार किया जाय और उसके संगठन और नेतृत्वको एक नये स्तरमें ले जानेकी चेष्टा की जाय ।इसलिए हमे पहले कांग्रेसका सम्बन्ध अन्य जनसंस्थाओंके साथ जोड़ना चाहिये, कांग्रेसके विधानको बदलवानेकी कोशिश होनी चाहिये और सामूहिक सम्बन्धकी माँग पेश करनी चाहिये । जब तक यह कार्य सिद्ध नहीं होता तबतक कांग्रेस कमेटी, ट्रेड यूनियन, किसान-सभा, युवकसंघ, समाजवादी समुदाय तथा अन्य साम्राज्यविरोधी संगठनोंकी सम्मिलित संस्थाएँ जगह-जगह कायम करनी चाहिये ।”

इस लेखमें आगे चलकर इस बातपर जोर दिया गया है कि पहले वामपक्षकी शक्तियोंमें एकता स्थापित होनी चाहिये और वही इस संयुक्त मोर्चेकी जान होगी । मोर्चे का प्रधान नारा “स्वराज्य पचायत” (Constituent Assembly) होगा । कुछ दिन पहले तक यह नारा पूँजीवादका नारा कहकर बदनाम किया जाता था । अब यही नारा संयुक्त मोर्चेका मुख्य नारा बन गया !

जनमोर्चेका स्वरूप

इस लेखसे कम्युनिस्टोंमें बड़ी खलबली मची, क्योंकि अबतक जो कुछ उनकी ओरसे कहा या लिखा गया था उस सबको यह लेख काटता था । काफी समयतक इस सम्बन्धमें वाद-विवाद चलता रहा । अन्तमें इस लेखके प्रकाशनके एक वर्ष बाद मार्च सन् १९३७ में ‘पोलिट ब्यूरो’ ने इसके समर्थनमें एक वक्तव्य निकाला । इसमें इस मोर्चेका नया नामकरण हुआ । अब इसे संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा कहने लगे । इस मोर्चेके श्रेणी आधारका जिक्र

करते हुए इस वक्तव्यमें कहा गया है कि 'इसमें मुट्ठीभर प्रतिगामियो और राज्यभक्तोंको छोड़कर समस्त भारतीय जनताका समावेश होता है।' कांग्रेसका श्रेणी आधार तो पूंजीवादी और सुधारक जमींदार वर्ग बताया जाता है, किन्तु साम्राज्यविरोधी जनमोर्चेका श्रेणी आधार समस्त राष्ट्र है ! यह एक अजीब बात है ।

इसके बाद ही किसान सभाका कांग्रेसके साथ क्या सम्बन्ध हो, इसपर कम्युनिस्टोका नया निश्चय प्रकाशित हुआ । किसान सभा अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती हुई कांग्रेसके ही आधारपर एक शक्तिशाली मोर्चा कायम करनेकी कोशिश करेगी । इसीलिए वह कांग्रेससे सामूहिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है ।

कम्युनिस्ट इंटरनेशनलकी सातवीं कांग्रेसमें हिन्दुस्तानपर रिपोर्ट देते हुए वंग मिंग (Wang Ming) ने कहा था कि "हिन्दुस्तानके कम्युनिस्टोंने संकीर्णता दिखाकर बड़ी भूल की है । वह कांग्रेससे अलग हो गये और उसके द्वारा संगठित प्रदर्शनोमें भाग नहीं लेते थे । साथ ही, उनका निजका संगठन भी ऐसा न था जिसके आधारपर स्वतन्त्र रीतिसे वह एक जवर्दस्त जनान्दोलन खड़ा कर सकते । उनका जनतासे सम्पर्क बहुत कम हो गया । ... इस तरह कम्युनिस्ट समुदायने वास्तवमें जनतापर गांधीवाद और सुधारवादका प्रभाव बने रहनेमें मदद की । कम्युनिस्टोको इस संकीर्णताको छोड़ना चाहिये और कांग्रेसके भीतर तथा उससे सम्बद्ध सुधारक और क्रान्तिकारी संस्थाओंमें काम करना चाहिये ।

लेनिनकी यही शिक्षा थी । उसका कहना था कि "सुधारक संस्थाओंके साथ संयुक्त मोर्चा बनाते हुए शर्तें इस गरजसे न रखनी चाहिये जिसमें उनके नेता उन्हें नामंजूर कर दें, वल्कि साधारण माँगोंको भी यदि वह श्रेणियोंकी माँगें हैं या साम्राज्यविरोधी माँगें हैं, मान लेना चाहिये, क्योंकि इतिहास इसका साक्षी है कि साधारण अधिकारोंके लिए किये गये छोटेसे छोटे आन्दोलनोंने क्रान्तियोंको जन्म दिया है ।" पर हमारे भाई इस शिक्षाको बहुत दिनोतक भूले रहे और अपने ही नेताओंके याद दिलानेपर भी अमल करनेमें बहुत समय लगा दिया । सन् १९३५ में अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट संघकी ७ वीं कांग्रेस हुई थी, पर लगभग २ वर्षके बाद ही इस नीतिपर ठीक ढंगसे अमल होना शुरू हुआ ।

कांग्रेसका जो श्रेणी आधार कम्युनिस्टोंने मान रखा है उसके कारण तथा इस कारण कि उनको विचार-स्वातन्त्र्य तथा अपनी नीति स्वयं निर्धारित करनेका हक नहीं है, यह शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो गयी थी और फिर उत्पन्न हो सकती है ।

मौलिक मतभेद

समाजवादी और रायपन्थी कांग्रेसको राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके लिए किये जानेवाले संघर्षका उपकरण समझते हैं । हमारे मतमें कांग्रेसका नेतृत्व चाहे जैसा क्यों न हो, आन्दोलनकी दृष्टिसे कांग्रेस एक क्रान्तिकारी शक्ति है । कांग्रेस प्रजातन्त्रवादी तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन है । यह हमारा विचार है । इसी स्थलपर हमारा कम्युनिस्टोसे मौलिक मतभेद है । दत्त-ब्रैडलेने अपने लेखमें इसी बातको दबी जवानसे स्पष्टरीत्या

माना है। किन्तु इसकी क्या गारण्टी है कि वह इसपर कायम रहेंगे ? आज भी वह अपनी स्थिति बदलते नजर आते हैं।

रूस-जर्मन सन्धिके बाद यूरोपमें कम्युनिस्टोंने संयुक्त मोर्चेकी नीतिका परित्याग कर दिया है। सोशल डेमोक्रेसी (Social democracy) के नेताओंके साथ मिलकर अब वे न तो सभी मजदूरोंका संयुक्त मोर्चा (Worker's front) बनानेके लिए तैयार हैं और और न कोई राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (People's front)। उनकी रायमें "अब मजदूर-वर्गकी एकता और जनताका सम्मिलित मोर्चा केवल 'नीचेसे' ही स्थापित किया जा सकता है।" यूरोपमें कम्युनिस्ट इंटरनेशनलकी नीतिमें परिवर्तन होनेके साथ ही अब भारतीय कम्युनिस्टोंकी नीतिमें भी तबदीली आ गयी है। जबतक यूरोपमें संयुक्त मोर्चाका जोर रहा तबतक भारतीय कम्युनिस्ट भी संयुक्त मोर्चा और संयुक्त नेतृत्वका नारा लगाते रहे। संयुक्त नेतृत्वको कायम रखनेके वे इस अंशतक पक्षपाती थे कि जब स्वतन्त्रता-दिवसके प्रतिज्ञापत्रमें जोड़े गये नये अशोक काग्रेस समाजवादी पार्टीकी ओरसे विरोध किया गया तो उन्होंने हमारी आलोचनाकी खिल्ली उड़ा दी और समूचे प्रतिज्ञापत्रको ग्रहण किया किन्तु आज तो कम्युनिस्टोंका प्रमुख कार्य संयुक्त नेतृत्वके स्थानपर केवल मजदूर जमातके नेतृत्वके लिए प्रयत्न करना हो गया है। लड़ाईकी तैयारीके जमानेमें तो वे गांधीजीके नेतृत्वको आवश्यक समझते रहे, पर आज कम्युनिस्टोंका प्रमुख कार्य गांधीवाद नेतृत्वका भण्डाफोड़ करना, जनतापरसे उसका प्रभाव नष्ट करना, जनताको यह समझाना कि रचनात्मक कार्यक्रम केवल अधूरा ही नहीं है, बल्कि वह मुख्य प्रश्नको बरगलानेके लिए है और जनताका विश्वास गांधीवादी नेतृत्वपरसे हटानेकी कोशिश करना है। इस प्रकार आज कम्युनिस्टोंका कार्य गांधीवादके विरोधमें भी उसी तीव्रतासे युद्ध करना हो गया है जितना कि साम्राज्यवादके साथ।

अब यह कहा जाने लगा है कि क्रान्ति सन्निकट है। इस अवस्थामें संयुक्त मोर्चेकी नीतिमें परिवर्तन करना लाजिमी है। जनता क्रान्तिकी ओर द्रुत वेगसे अग्रसर हो रही है, नेतृत्व पिछड़ रहा है, युद्धसे भागता है और समझौता करना चाहता है। अतः इस अवस्थामें 'नीचेसे' ही संयुक्त मोर्चा होना चाहिये, अर्थात् नेताओंकी उपेक्षा कर साधारण सदस्योंके साथ संयुक्त कार्य होना चाहिये। हम इस नीतिके थोथेपनको ऊपर दिखा चुके हैं। भारत एक कृषिप्रधान देश है। एंगेल्सने ठीक कहा है कि ऐसे देशमें जबतक किसानोंमें काफी काम नहीं किया जायगा और उनका विश्वास नहीं प्राप्त किया जायगा, कम्युनिस्ट क्रान्ति नहीं कर सकते। कौन कह सकता है कि हमारे कम्युनिस्ट भाइयोंका किसानोंपर अच्छा प्रभाव है ? कितने प्रान्तोंमें किसान-सभाका ठोस काम है और इनमें भी कितने कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं ? वह तो उँगलीपर गिने जा सकते हैं। मजदूरोंमें भी काफी काम नहीं हुआ है। रेलवेके मजदूर अब भी सुधारवादियोंके प्रभावमें हैं। इन आवश्यक क्षेत्रोंकी उपेक्षा की गयी है। कार्यकर्ता बहुत कम हैं, क्षेत्र हैं विस्तृत। यह समझना कि रूसके क्रान्तिकारियोंको परिस्थितिकी जो सुविधाएँ मिली थी वह हमको भी मिलेगी और इसी भरोसे किसी जबर्दस्त कार्यक्रमको बनाना वचन होगा।

यथार्थवादी दृष्टिकोणकी आवश्यकता

समयका व्यवहार अत्यन्त निष्ठुर भी हो सकता है। हमारी साधना सुलभ नहीं होगी। कमसे कम इस आधारपर कोई बड़ा काम उठा लेना जोखिम उठाना होगा। हमको नाप तोलकर वस्तुनिष्ठ क्रान्तिकारीकी तरह आचरण करना चाहिये। अपनी शक्तिका मुवालागेके साथ अन्दाज लगाना और विरोधी शक्तिका काम, वस्तुनिष्ठा नहीं कहलायी जा सकती। इसकी कमी हम कम्युनिस्ट भाइयोंमें पाते हैं। कांग्रेस एक महती शक्ति है। उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 'नीचेसे' संयुक्त मोर्चेकी नीतिपर चलकर हम इस शक्ति-भण्डारका समुचित लाभ नहीं उठा सकते। हम आकाशके तारे न गिनें और ज्योतिषसे काम न लें, किन्तु वस्तुस्थितिको पहचाने और उसके अनुसार अपना कार्यक्रम बनावें।

समाजवादीके तरीके भले ही दूरे हों, किन्तु राष्ट्रवादियोंके अपर्याप्त तरीकोंका भी उसे समर्थन करना चाहिये, जब साम्राज्यविरोधी युद्ध सामने हो। ऐसे मौकेपर कांग्रेसके नेताओंकी पोल खोलनेका व्यापार खतरनाक है। इससे युद्धकी तैयारी नहीं होती बल्कि उसको काफी धक्का पहुँचता है। यह तो हमारे अनुभवकी बात है। दूर जानेकी जरूरत नहीं है। यह कहकर हमारे नेता लड़ेंगे नहीं, लड़ें भी तो समझीता कर लेंगे, हमने जनतामें निरुत्साह पैदा कर दिया है। इस निरुत्साहको दूर करनेमें कठिनाई हो रही है। क्या यह पोल खोलनेकी नीति इस समय घातक नहीं सिद्ध हो रही है? क्या यदि यह कहा जाय कि यह नीति सघर्षकी नीति नहीं है तो क्या कोई बड़ा अन्याय किया जाता है?

किन्तु हमारा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि गांधीवादी नेतृत्वकी कोई आलोचना की ही न जाय, अपना कार्यक्रम रखा ही न जाय और स्वतन्त्र रूपसे जारी रखे गये अपने कार्योंको छोड़ दिया जाय। मौकेको देखते हुए ये सभी आवश्यक हैं, किन्तु इनका प्रमुख उद्देश्य गांधीवादी नेताओंकी पोल खोलकर उनका अमर जनतापरसे हटाने और जनताको निरुत्साहित करनेके स्थानपर जनतामें अपने विचारों और कार्यशैलीका प्रचार बढ़ाना और और युद्धकी ओर उन्हें ले जाना होना चाहिये। हमारी आलोचना मौकेको देखते हुए और समयके साथ होनी चाहिये। हमें यह न भूलना चाहिये कि आजकी हालतमें, जब कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चेके भीतर समाजवादी अल्प संख्यामें हैं, अगर हम तुरन्त देशव्यापी संग्राम छेड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रीय आन्दोलनके लिए संयुक्त नेतृत्व अनिवार्य है, अपरिहार्य है। हाँ, यदि गांधीवादी नेतृत्व लड़नेसे ही इन्कार कर दे और साम्राज्यशाहीके साथ समझीता करनेको तैयार हो जाय तब अवश्य स्थिति दूसरी होगी। उस समय हम अपनी शक्ति और सामर्थ्यके अनुसार, अपने पृथक् कार्यक्रमके अनुसार जनताको लेकर आगे बढ़नेके लिए स्वतन्त्र होंगे। आज जरूरत इस बातकी है कि रामगढ़ कांग्रेसने लड़ाईके लिए जो कार्यक्रम हमारे सामने रखा है और कांग्रेस समाजवादी पार्टीने रामगढ़ कांग्रेसके लिए जो कार्यक्रम तैयार किया था इन दोनोंके आधारपर हम जनताको बड़ेसे बड़े पैमानेपर

संगठित करे। ऐसा करके ही हम जनताके विश्वासभाजन बनकर वह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसके बलपर गांधीजीके नेतृत्वमे युद्ध आरम्भ होनेपर हम उसपर अपना प्रभाव डाल सकेंगे और यदि गांधीजी युद्ध न छोड़ें तो हम स्वतन्त्र रूपसे कोई कार्रवाई कर सकेंगे।

युद्ध और जनता^१

यह युद्ध आरम्भमे कम्युनिस्टोके लिए साम्राज्यवादी था। जब जर्मनी-रूसका समझौता हो गया तो और जोर-शोरसे साम्राज्यवादी हो गया। इङ्ग्लैण्ड और फ्रांसका साम्राज्यवाद जर्मनीके नाजीवादसे भी ज्यादा बदतर करार दिया गया। हिटलरको शान्तिप्रिय और इङ्ग्लैण्डको सारी खुराफातकी जड़ बतलाया गया। जब जर्मनीने रूसपर आक्रमण किया तब इनका यही विचार था कि चर्चिलने हिटलरको बरगलाकर रूसके विरुद्ध कर दिया है। अर्थात् अनाक्रमण सन्धिके कारण यह हिटलरको देवतास्वरूप समझने लगे थे और इनका ख्याल था कि जर्मनीको रूससे लड़ानेमे इङ्ग्लैण्डकी शरारत होगी। इस सिध्दाई और भोली समझकी क्या दाद दी जाय। लुत्फ तो यह है कि इसी समझके बलपर हमारे दोस्त अकेले दुनियामे क्रान्ति करना चाहते हैं।

इस युद्धके बाद भी ५ महीनेतक बराबर यह युद्धको साम्राज्यवादी बताते रहे। रूसके युद्धमे सम्मिलित होनेसे भी इनकी रायमे पहली दिसम्बर सन् १९४१ के पहले युद्धका स्वरूप जरा भी नहीं बदला था। स्टालिनके तीसरी जुलाईके भाषणने, जिसमे उन्होंने कहा था कि हमारे देशकी स्वतन्त्रताकी लड़ाई यूरोप और अमेरिकाकी जनताकी लड़ाईमें मिलकर एक हो जायगी और यह स्वतन्त्रताके लिए जनताका एक संयुक्त मोर्चा होगा, भारतीय कम्युनिस्टोको भी प्रभावित किया था। लेकिन चूँकि उसमे भविष्यकालका प्रयोग हुआ था इस कारण हमारे दोस्त यह न समझ पाये कि एग्लो सोवियत और सोवियत अमेरिकन समझौतेने भविष्यको वर्तमानकालका रूप दे दिया है और यह जनताका संयुक्त मोर्चा इस समझौताके बाद वास्तवमे तैयार हो गया है। इसके बाद स्टालिनका ऐसा कोई भाषण न हुआ जिसमे उन्होंने स्पष्ट शब्दोमे इस संयुक्त मोर्चेके तैयार हो जानेका निर्देश किया हो। हाँ, इस घटनासे जेलमे नजरबन्द कुछ कम्युनिस्ट अवश्य प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपने मित्रोको बाहर कहला भेजा कि सोवियत-यूनियनके लड़ाईमे आ जानेसे युद्धके स्वरूपमे बुनियादी तबदीली हो गयी है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टीको अपनी नीति बदलनी चाहिये। इसपर कम्युनिस्ट पार्टीने इनके तर्कोंका खण्डन करते हुए फिर इसी सिद्धान्तको प्रतिपादित किया कि युद्ध अब भी साम्राज्यवादी है।

१. अखिल भारतीय किसान सम्मेलन (विदौल, मुजफ्फरपुर) मे अध्यक्षपदसे दिया हुआ भाषण।

कम्युनिस्ट नीतिमें परिवर्तन

यहाँकी कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेनकी पार्टीसे सम्बद्ध है और समय-समयपर वहाँसे आदेश मिलते रहते हैं जिनको माननेके लिए वह बाध्य है। ब्रिटेनकी पार्टीके मन्त्री हैरी-पालिटने जुलाई सन् १९४१ में अपनी पार्टीके नाम एक अपील प्रकाशित की जिसमें उन्होंने युद्धके स्वरूपके बदल जानेके कारण पार्टीकी नीतिके बदलनेकी आवश्यकता बतलायी। यह अपील भारतमें नवम्बरमें पहुँची। इस पत्रको पढ़कर यहाँकी कम्युनिस्ट पार्टीको भी अपनी नीति बदलनी पड़ी। अब उनको यह कहना पड़ा कि हम गलतीपर थे और हैरी पालिट सही थे। ये अपनेको यह कहकर कोसने लगे कि हम उन सिद्धान्तों और अनुमानोंसे गुमराह हो गये थे जो राष्ट्रवादकी उपज हैं और हमने मार्क्स लेनिनकी मजदूर जमातकी अन्तर्राष्ट्रीयताको भुला दिया। यदि हैरी पालिटका यह पत्र इनके हाथ न लगा होता तो यह युद्ध अब भी साम्राज्यवादी युद्ध रहता। पालिटके पत्रमें कोई ऐसे नये तर्क नहीं दिये गये हैं जो उसके बिना नहीं सोचे जा सकते। पत्रकी मुख्य बात यही है कि युद्धमें सोवियत-यूनियनके आ जानेसे एक मौलिक परिवर्तन हो गया है और लोकतन्त्रवादी और प्रगतिशील जनताके सामने हिटलरकी हारके लिए युद्ध करना एक महत्त्वका सवाल हो गया है। पत्रमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि चर्चिलकी गवर्नमेण्ट भी इस बुनियादी तबदीलीको मानती है। पार्टीने इसीके अनुकूल अपनी नयी नीति निर्धारित की है। पार्टीको अपने ऊपर और जनतापर विश्वास करना चाहिये कि जनता गवर्नमेण्टको हिटलरसे मेल करनेसे रोकेगी और इस सम्बन्धमें उसको किसी प्रकारका अनुमान न लगाना चाहिये। हमारे दोस्तोंने यह न सोचा कि यदि उपनिवेशमें रहनेके कारण वह राष्ट्रवादसे प्रभावित हो सकते थे तो इंग्लैण्डमें रहनेके कारण हैरी पालिट तथाकथित राष्ट्र-रक्षा (national defence) से प्रभावित हो सकते थे। हैरी पालिट शुरूसे ही हिटलरके विरोध करनेके पक्षमें थे। उन्होंने जर्मनी-रूसका समझौता नापसन्द किया था और उसके बादकी कम्युनिस्ट पार्टीकी नीतिसे वह सहमत नहीं थे। इसी कारण वह मन्त्री-पदसे कुछ समयके लिए अलग हो गये थे। जब जर्मनीने रूसपर आक्रमण किया तब उनको जन-संयुक्त मोर्चाकी पुरानी नीतिको बर्तनेका अवसर मिला। रूसका भी यही आदेश था। इस नीतिपर अमल करनेमें ब्रिटेनकी भी रक्षा थी। इस जानकारीके बाद क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस प्रकार सन् १९१४ के युद्धमें कितने ही साम्यवादियोंने अपने देशकी रक्षाके नामपर युद्धको साम्राज्यवादी कहना स्वीकार नहीं किया उसी प्रकार हैरी पालिट भी इंग्लैण्डकी रक्षाके प्रश्नसे प्रभावित होकर सोवियत रूसके नाम पर इस युद्धको जनताका युद्ध कहते हैं।

महायुद्धका स्वरूप

आज हैरी पालिटके फतवेको पाकर कम्युनिस्ट इसे जनताका युद्ध कहने लगे हैं। इसमें स्वामी सहजानन्दजी भी कम्युनिस्टोंके साथ हैं। स्वामीजी किसान सभाके फूटमें ही नहीं, लड़ाईके मामलेमें भी पूरी तरह इनके साथ हैं। हम यह मानते हैं कि

साम्राज्यवादी युद्ध घटनाचक्रसे राष्ट्रीय युद्ध हो सकता है और राष्ट्रीय युद्ध साम्राज्यवादी हो सकता है। किन्तु इस युद्धका स्वरूप अभी नहीं बदला है। युद्धमे कुछ राष्ट्रीय तत्त्व आ गये हैं, किन्तु वह गौण है। प्रधान तत्त्व आज भी साम्राज्यवादी है। दूसरी ओर युद्धक्षेत्रका विस्तार होनेसे, अर्थात् जापान और अमेरिका, इन दो साम्राज्यवादी राष्ट्रोंके आ जानेसे युद्धमे नये साम्राज्यवादी तत्त्व आ गये हैं। अब यह युद्ध विश्वव्यापी हो गया है। इसका सूत्र चीन और रूसके हाथमे नहीं है। चीन इंग्लैण्ड और अमेरिकाकी सहायतापर आश्रित है और रूसपर लड़ाई लादी गयी है। वह इस युद्धके उद्देश्योको बदलनेके लिए अपनी खुशीसे नहीं शरीक हुआ है। चर्चिल और रूजवेल्ट भी 'दुश्मनका दुश्मन दोस्त होता है' इस आधारपर रूसके साथ हैं। मुसीबतमे अजीब-अजीब लोगोका साथ हो जाता है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह सब शरीफजादे हैं? युद्धके सूत्र इंग्लैण्ड और अमेरिकाके हाथमे हैं, जो साम्राज्यवादी हैं। भविष्यकी सबसे जवर्दस्त साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिकाकी होगी। उसकी इस युद्धमें प्रधानता है। राष्ट्रीय तत्त्व गौण है और युद्धके निर्णयोमे उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि युद्ध प्रधानतया अब भी साम्राज्यवादी है। चीन और रूसके साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति है। इस कारण नीतिमे थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। पर यदि युद्धका स्वरूप प्रधान अंशमे नहीं बदला है तो नीतिमे कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

यदि इंग्लैण्ड और अमेरिका अपनी युद्ध और शान्तिकी नीतिको बदलें और अपनी साम्राज्यवादी मनोवृत्तिका परित्याग कर आज अपने साम्राज्यवादी हितोंका परित्याग करे तो यह युद्ध अवश्य जनताका फैसिलस्ट विरोधी युद्ध हो जायगा, पर ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिये। हम साम्राज्यवादके युगमे रह रहे हैं। राष्ट्रोंको जब अपनी नीतिमे शान्तिमय उपायो तथा कूटनीतिसे सफलता नहीं मिलती तब वह सैन्यबलका प्रयोगकर अपने उद्देश्योको प्राप्त करना चाहते हैं। तृप्त राष्ट्र अपने साम्राज्यकी रक्षा करना चाहते हैं और अतृप्त राष्ट्र ससारका फिरसे बटवारा करनेके लिए तृप्त राष्ट्रोंको विवश करना चाहते हैं। वर्तमान युद्धका यही हेतु है। दूसरोंकी स्वतन्त्रता छीनकर और उनका आर्थिक शोषण कर तृप्त राष्ट्रोंके साम्राज्यकी स्थापना हुई है। यों तो पूंजीवादी सत्ता सर्वप्राप्ती होती है और किसी प्रकार उसकी भूख शान्त नहीं होती, ; किन्तु जब एक पुराना पूंजीवादी राष्ट्र एक विशाल साम्राज्यकी स्थापना कर लेता है, कतिपय देशोंके आर्थिक जीवनपर प्रभुत्व कायम कर लेता है और जगह-जगह अपना प्रभाव-क्षेत्र बना लेता है तब किसी जवर्दस्त प्रतिद्वन्द्वीका मुकाबला होनेपर वह 'शान्तिका पाठ पढ़ने लगता है। यह तो वही मसल है कि हजार चूहे खाकर विल्ली हजको चली। लीग ऑव नेशन्सकी स्थापना इसीलिए हुई थी कि इंग्लैण्ड और फ्रांस अपने हस्तगत मालको हजम कर सकें और पदाक्रान्त राष्ट्र उनके विरुद्ध सिर न उठा सकें। पूर्विय यूरोपमे फ्रांसने अपनेको मजबूत करनेके लिए क्षुद्र राष्ट्रोंका समूह बनाया। इस समूहमे ऐसे राष्ट्र भी शामिल थे जिनका शासन स्वेच्छाचारी फौजी अधिनायकोंके हाथमे था।

तिसपर भी इन राष्ट्रोंका समर्थन फ्रांस करता था। संसारका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जेमें करके इन्होंने यह कहना शुरू किया कि युद्धद्वारा अपने झगड़ोंको निपटानेका तरीका गलत है और जो शान्ति भंग करता है उसे लीगसे दण्ड मिलना चाहिये। किन्तु जब जापानने चीनपर आक्रमण किया और मंचूरिया ले लिया तब चीन लीगका सदस्य था। लीगसे सहायताकी अपील की किन्तु लीगने कोई सहायता न दी। लीग आव् नेशनस तो इंग्लैण्ड और फ्रांसकी साम्राज्यवादी नीतिका समर्थन करनेके लिए बनायी गयी थी। यही दो राष्ट्र इसके प्रधान थे। यह आपसमें जो समझौता कर लेते थे उसीको लीग-द्वारा स्वीकृत करालेते थे। दुर्बल राष्ट्रोंके सबल राष्ट्रोंद्वारा उसे जानेपर अपनी सुविधाके अनुसार ही कोई काररवाई करते थे। लोकतन्त्र तथा क्षुद्र राष्ट्रोंकी रक्षाके लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। जर्मनीको सन्तुष्ट करनेकी कोशिश इसलिए करते थे जिसमें इनपर आक्रमण न करे, बलिदानका बकरा चाहे दूसरा कोई भले ही बने। मित्र राष्ट्रोंकी ओरसे आज कहा जाता है कि यह यद्ध स्वतन्त्रता और लोकमतकी रक्षाके लिए है। किन्तु हमने देखा कि जब जर्मनीने चेकोस्लोवाकियाके लोकतन्त्रपर आक्रमण किया तब इंग्लैण्ड और फ्रांसने कुछ न किया, किन्तु उल्टे हिटलरसे म्यूनिकका समझौता कर लिया। पर जब पोलैण्डके अर्ध फैसिस्ट राष्ट्रपर आक्रमण हुआ तब इंग्लैण्डने जर्मनीके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी।

क्या यह युद्ध फासिज्मविरोधी है ?

कहा जाता है कि यह युद्ध फैसिज्मका विरोध करनेके लिए लड़ा जा रहा है, क्योंकि एक ओर रूस और लोकतन्त्रवादी राष्ट्र हैं तथा दूसरी ओर फैसिस्ट राष्ट्र। किन्तु यह भ्रम मात्र है। हम ऊपर देख चुके हैं कि पोलैण्ड अर्ध फैसिस्ट, राष्ट्र लोकतन्त्रवादियोंके साथ है। ग्रीस भी उनके खेमेमें है। पूर्विय यूरोपके कुछ दूसरे अर्ध फैसिस्ट राष्ट्र भी युद्धके पहले इनके साथ थे। किन्तु हिटलरकी जीतने उनको इससे अलग कर दिया। यह भी ख्याल गलत है कि प्रधान फैसिस्ट राष्ट्र एक साथ मिलकर फैसिज्मकी विचार-पद्धतिको फैलानेके लिए लड़ रहे हैं। फैसिस्ट भी साम्राज्यवादी हैं। उनमें भी परस्पर स्वार्थोंका संघर्ष चलता रहता है। जर्मनी और इटलीके हितोंका प्रत्यक्ष विरोध मध्य यूरोपमें देखा जा सकता है। किसको नहीं मालूम-कि आस्ट्रियाके प्रश्नको लेकर हिटलर और मुसोलिनीमें काफी तनातनी हो गयी थी। किन्तु स्वार्थवश ये इस समय साथ हैं। समय आनेपर एक दूसरेके विरोधमें भी खड़े हो सकते हैं। हिटलरने वोलशेविज्मका अन्त करनेके लिए यह लड़ाई नहीं छोड़ी है। वह तो वर्साइकी सन्धिको खतम कर यूरोपका प्रभुत्व चाहता है। वोलशेविज्मका हीआ दिखाकर वह बराबर इंग्लैण्ड और फ्रांसको बेवकूफ बनाता रहा और कई प्रदेश उसने बिना लड़े ही ले लिये। किन्तु जब चेम्बरलेनने देखा कि अब बहुत जल्दी हमारी वारी आनेवाली है तो युद्धकी घोषणा कर दी। यह वस्तुस्थिति है। सबको अपनी-अपनी फिक्र है। कोई राष्ट्र किसी आदर्शके लिए नहीं लड़ रहा है। सब अपने स्वार्थके लिए लड़ रहे हैं और हर एकसे मंत्री

करनेको तैयार है, चाहे वह प्रजातन्त्रवादी हो या फैसिस्ट । इस बातको फिरसे दुहरानेकी जरूरत है कि कोई भी राष्ट्र इस समय किसी वादके लिए नहीं लड़ रहा है । जिस तरह बोलशेविज्मका हौआ दिखाकर हिटलर इतने साल बिना लड़ाईके अपना काम निकालता रहा उसी तरह मित्र राष्ट्र अब स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रकी दुहाई देकर भोली-भाली जनताको बेवकूफ बनाना चाहते हैं । हिटलरको बोलशेविक रूससे अनाक्रमण सन्धि (Non-aggression Pact) करनेमे कोई मुश्किल नहीं हुई । स्टालिन भी फैसिस्ट जर्मनीसे पैक्ट करनेको खुशी-खुशी राजी हो गया । यह पैक्ट क्यों टूटा यह दूसरी कथा है, किन्तु यह भी असन्दिग्ध है कि वह इसलिए नहीं टूटा कि रूस एक कम्युनिस्ट राज्य है । आज भी रूस और जापानका पैक्ट कायम है । यह तो राजनीतिकी चाले है । कुछ दिन हुए सर स्टैफर्ड क्रिप्सने कहा था कि रूस दूसरी गवर्नमेण्टोके मामलेमे हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । लड़ाई खतम होनेपर यह अपनेको मजबूत करनेमे लगेगा और इसलिए वह अपने राज्यकी सीमाओको सुधारना चाहता है । स्वयं स्टालिनने कहा था कि हम राष्ट्रीय युद्ध लड़ रहे हैं ।

यदि यह युद्ध फैसिज्मका अन्त करनेके लिए चल रहा है तो इंग्लैण्ड रूसकी पूरी मदद क्यों नहीं करता ? सर स्टैफर्ड क्रिप्सतकने इसकी शिकायत की है । इस समय वास्तवमे अकेला रूस ही जर्मनीका सफल मुकाबला कर रहा है । और मोर्चोंपर तो मित्रराष्ट्रोंकी हार हो रही है । यदि उद्देश्य एक है तो जो राष्ट्र वास्तवमे जर्मनीका सफल मुकाबला कर रहा है उसकी पूरी मदद होनी चाहिये । यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमे लोकतन्त्र और फैसिज्मकी प्रतिद्वन्द्विता चल रही है तो एकदेशीय दृष्टि नहीं होनी चाहिये । दुनियाके पैमानेपर ही लोकतन्त्र और फैसिज्मका फैसला होगा । फिर अपना-अपना क्या ? एक कुटुम्ब समझकर सब साधनोका उपयोग अच्छेसे अच्छे ढंगसे होना चाहिये । किन्तु पेंचपर पेच लगे हुए हैं । कही तो इसका डर है कि इंग्लैण्डमे कम्युनिस्ट विचार न फैल जाये । इसकी भी फिक्र है कि किसी भी हालतमे इंग्लैण्डकी रक्षाकी वर्तमान अवस्थामे तनिक भी फर्क न आये ।

युद्ध और भारत

हमसे कहा जाता है कि रूसकी आजादीमे तुम्हारी आजादी शामिल है और इसलिए युद्धमें सहयोग करनेको कहा जाता है । इसका अर्थ यह है कि यदि दूसरे पदाक्रान्त राष्ट्र स्वतन्त्र होते हैं तो हम भी अन्तमे स्वतन्त्र हो जावेगे । किन्तु हमको तो धुरी राष्ट्रोंने गुलाम नहीं बना रखा है । हम तो एक लोकतन्त्रवादी राष्ट्रके गुलाम हैं । वह चाहे तो आज भी भारतको स्वतन्त्र घोषित कर सकता है । इसमे धुरी राष्ट्र क्या अड़चन डाल रहे हैं ? यह भी सच नहीं है कि जितने देशोंपर आज हिटलरका कब्जा है उन सबको वह सदाके लिए गुलाम बनाना चाहता है । युद्धकी आवश्यकतासे प्रेरित होकर ही उसको ऐसा करना पड़ा है । इंग्लैण्डको भी विवश होकर नारवेकी तटस्थताको भग करना पड़ा था । इस प्रकार इंग्लैण्ड और रूसने ईरानमे हस्तक्षेप किया था । और यदि यह सच है

कि सबकी आजादीमे हमारी आजादी भी शामिल है तो यह भी मानना पड़ेगा कि हमारी गुलामीमे सबकी गुलामी छिपी हुई है। यदि हम अपनी दासताके बन्धन यहां काटने हैं तो दूसरी प्रगतिशील शक्तियोंको भी बन्धन बनाते हैं। तथ्य यही है कि भारत अपनी स्वतन्त्रता अर्जित करके ही, सिर्फ इसी तरीकेमे हम और चीनकी मदद कर सकता है।

विचारिये कि यदि भारत स्वतन्त्र होता तो क्या करना ? यदि हम चीन देगेके लिए मान भी लें कि यह युद्ध प्रजातन्त्रकी स्थापनाके लिए लड़ा जा रहा है तो भी क्या स्वतन्त्र भारत बिना सोचे विचारे आगमे कूद पड़ता ? किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्रने प्रयत्नक ऐसा नहीं किया। जिनकी यह लड़ाई नहीं है वह उनमे आग ही खला चाहते हैं। हम भी यही चाहता था। तुर्कीकी भी यही नीति है। हम भी इसी नीतिले अनुसरण करने। हाँ, यदि हमारे देशपर कोई राष्ट्र आक्रमण करता तो हम उसका स्वागत करने और उस अवस्थामे उन राष्ट्रोंसे मैत्री करने जो हमारे पक्षके विपक्षी होंगे। किन्तु आज जब हम गुलाम हैं तो भी हमको दूसरोंकी आजादीके लिए लड़नेको कहा जाता है।

यह एक अजीब-सी बात है। शायद कहनेवाले यह समझते हैं कि गुलामीकी जानकी कीमत ही कितनी। अपने देशमे भारतवासी शाये दिन किसी न किसी गुलामीके शिकार होते रहते हैं। इसमे तो कही अच्छा है कि वह दूसरोंकी आजादीके लिए लड़कर मरें। हम भारतवासियोंको आजादीकी मुग़ीबतों और कठिनाइयोंका अनुभव तो है नहीं। हमने तो केवल उसका सुनहला पहलू देखा है। उर्गामें हम मरत हैं। हमारा जोश इन कदर बढ़ा हुआ है कि हम दुनियाके गुलामी और आर्थिक शोषणको मिटा देना चाहते हैं। इसीलिए हमारी चीन और रूसके साथ तात्कालिक सहानुभूति है। किन्तु गहनमेष्टोमें यह उत्साह और आदर्शवादिता नहीं पायी जाती। क्या हमारे इन आदर्शवादिताका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है या हम गुलामोंको इस तरह चिढ़ाया जा रहा है ? यह भी कहा जा सकता है कि अब तो युद्ध दरवाजेपर आ गया, अब गुलामी आजादीका क्या सवाल है ? अब तो अपनी मातृभूमिकी रक्षात नवाच है। किन्तु हमको इन कालिल ही नहीं रकड़ा गया है कि हम अपनी रक्षा कर सकें। हमको तो पीरनावागिन बनाकर रखा गया है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं या कोस सकते हैं। लड़ाईमें शरीक होकर हम अपनी मदद तो न कर सकेंगे किन्तु अपनी गुलामीकी जज़ीरोंको अवश्य मजबूत कर देंगे। दुनियाको यही बतलाया जायगा कि हिन्दुस्तान अपनी गुलामीसे सन्तुष्ट है।

वर्तमान महायुद्धके उद्देश्य

साम्राज्यवादने दुनियाका बन्दरबाँट किया है और दुनियाको तीन समुदायोंमें बाँट दिया है। अमेरिका, इंग्लैण्ड और जर्मनी इन समुदायोंका नेतृत्व करते हैं। अन्य छोटे राष्ट्र इनमेंसे किसी एकका साथ देनेके लिए विवश हैं। इस युद्धमें इंग्लैण्ड अमेरिकाके आश्रित हो गया है। यदि यह कहा जाय कि शायद इस युद्धमे इंग्लैण्ड और अमेरिकाका एक गुट हो गया है तो शायद अत्युक्ति न होगी। दोनोंकी प्रतिद्वन्द्विता कुछ अरसेसे चली

आती है। किन्तु इसे युद्धकी आवश्यकताओं और अमेरिकाकी महती शक्तिने इङ्गलैण्डको अमेरिकाके आश्रित होनेके लिए विवश किया है।

एटलांटिक घोषणा (Atlantic Charter) एक गुटकी नीतिको निर्धारित करता है और हिटलरकी नयी व्यवस्था (New Order) और जापानका सम्मिलित समृद्धि कार्यक्रम (Co-prosperity Programme) दूसरे गुटकी नीति जाहिर करता है। इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। एटलांटिक घोषणामें केवल उन्हींके लिए स्वभाग्य निर्णयका सिद्धान्त माना गया है जिनको हिटलरने आक्रान्त किया है। इङ्गलैण्डके साम्राज्य और उसके उपनिवेशोंको यह सिद्धान्त लागू नहीं होता। अमेरिका भी इस घोषणाद्वारा अपने साम्राज्यवादी हितोंका परित्याग नहीं करता। ऐसी अवस्थामें कौन विश्वास कर सकता है कि यह लड़ाई लोकतन्त्र और आजादीके लिए लड़ी जा रही है? पराये धनपर तो सभी लक्ष्मीनारायण होते हैं। यूरोपके आक्रान्त और विजित राष्ट्रोंके लिए स्वभाग्य निर्णयके सिद्धान्तको मानना इङ्गलैण्डके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इङ्गलैण्डके अधीन यह राष्ट्र कभी नहीं रहे हैं। इङ्गलैण्ड यूरोपपर अपना प्रभुत्व शक्ति-सन्तुलनकी नीतिको वर्तकर ही कायम रख सकता है। छोटे राष्ट्रोंको स्वभाग्य निर्णयका अधिकार देकर सन्तुलन कायम होता है। पिछले महायुद्धके बाद भी कई प्रदेशोंको स्वभाग्य निर्णयका अधिकार देकर और उनको जर्मनीसे स्वतन्त्र कर जर्मनीकी शक्तिको क्षीण किया गया था। इसी उद्देश्यसे आज भी यूरोपके आक्रान्त राष्ट्रोंकी स्वाधीनता स्वीकार की गयी है। यदि एक महान् आदर्शकी पूर्तिका स्वांग भी रचा जा सके और साथ-साथ अपना उद्देश्य भी सिद्ध होता हो तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? किन्तु यदि इस आदर्शके अनुसार भारत, वर्मा, सिहल तथा अफ्रिकाके उपनिवेशोंमें काम किया जाय तभी ब्रिटेनकी सचाई साबित हो सकती है। अन्यथा यह मक्कारी ही समझी जायगी।

हिटलरकी नयी व्यवस्था

हिटलरकी नयी व्यवस्था भी धोखेकी चीज है। नाजीवाद तथा फासिस्टवाद एक बर्बरवस्तु है। वह मानव स्वतन्त्रताको पददलित करता है। मनुष्यके व्यक्तित्वकी उनकी नजरमें कोई कीमत नहीं है। उसके लिए कोई सामाजिक या आध्यात्मिक आदर्श (spiritual values) नहीं है, किन्तु हिटलरने अपने देशकी बेकारीको दूर कर दिया है। उसका खयाल है कि यदि वह यूरोपसे बेकारी और आर्थिक अनिश्चितता (Economic insecurity)को दूर कर सके तो यूरोपमें उसका प्रभुत्व कायम हो सकता है। उद्योग-व्यवसायके क्षेत्रमें जो आर्थिक संकट बार-बार उपस्थित होते रहते हैं और जिससे अस्तव्यस्तता होती रहती है उसके कारण जनतामें आर्थिक अनिश्चितताका भाव उत्पन्न हो गया है। इसी अनिश्चितताके कारण जर्मनीका निम्न-मध्यम-वर्ग नाजीवादका आधार बना। इस अनिश्चितताको नाजीवादने फिलहाल तो दूर कर दिया है यद्यपि ऐसा करनेके लिए नाजीवादने रहन-सहनका दर्जा काफी गिरा दिया है।

पार्लमेण्टरी प्रजातन्त्रके पास इस समस्याका कोई तत्कालीन हल भी नहीं है, इसीलिए उसका ह्रास तथा फासिस्टवाद या समाजवादकी उन्नति हो रही है ।

फासिस्टवाद यद्यपि साम्राज्यवादकी एक विशेष अवस्था मात्र है तथापि उसने पूंजीपतियोंके मुनाफेका काफी नियन्त्रण कर तथा अन्य उपायोंका अवलम्बन कर जर्मनीसे बेकारीको दूर कर दिया है और लोगोंको यह आश्वासन दिया है कि यद्यपि उनके रहन-सहनका दर्जा पहलेकी अपेक्षा गिर गया है तथापि उद्योगक्षेत्रकी अस्तव्यस्तताके कारण उनको समय-समयपर अकिंचनता, दरिद्रता और बेकारीका सामना न करना पड़ेगा । यह सच है कि मनुष्य केवल रोटीसे ही सन्तुष्ट नहीं होता, किन्तु जबतक रोटीका सवाल हल नहीं होता तबतक उसके लिए यही एक सवाल अहमियत रखता है । भूखे पेट भजन नहीं होता । किन्तु एक बार जब यह सवाल हल हो जाता है तब मनुष्यका ध्यान और सवालोंकी ओर जाता है । यही कारण है कि आज जर्मन लोग हिटलरके पीछे हैं । लडाईका संकट जबतक रहेगा तबतक उसके पीछे रहेंगे । हार ही जर्मनजातिको हिटलरके विरुद्ध कर सकती है या कोई ऐसा वाद हो जो आर्थिक निश्चितताके साथ-साथ मानवोचित आदर्शोंकी भी पूर्ति करता हो ।

इसमें सन्देह नहीं कि नाजीवादको तात्कालिक सफलता ही मिल सकती है । उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं है, क्योंकि यह इस भूलमे पड़ गया है कि मनुष्यके केवल पेट होता है, मस्तिष्क और भाव नहीं होते । हिटलरकी नयी व्यवस्था यूरोपको 'आर्थिक चिन्तासे मुक्त करना चाहती है । वह यूरोपमे एक ऐसी आर्थिक पद्धति कायम करना चाहती है जिससे यूरोपवासी आये दिन पूंजीवादके सकटोंसे बचे रहे । यही इसकी विशेषता है । दूसरी दृष्टियोंसे जब आप इस व्यवस्थाकी परीक्षा करेंगे तो इसमे दोष ही दोष दिखायी देंगे । हिटलरके मित्रराष्ट्र इटलीको औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) मिल सकता है और अन्य छोटे-छोटे राष्ट्रोंको देशी राज (Home Rule) दिया जायगा । प्रत्येक राष्ट्र यथासम्भव अन्नादिकी दृष्टिसे आत्मनिर्भर बनाया जायगा । कई उद्योग-प्रधान प्रदेश अपनी प्रधानता खो देंगे । हिटलरकी सेना सब राष्ट्रोंकी रक्षा करेगी । यह सब तो होगा । किन्तु नाजीवादकी वर्चस्वता सारे यूरोपपर छा जायगी । पर जबतक मित्रराष्ट्र यूरोपके सामने ऐसी व्यवस्था न रखेंगे जिसके आधारपर आर्थिक निश्चितताकी आशा की जा सके तथा आये दिनके युद्धोंसे छोटे राष्ट्रोंकी रक्षा हो सके तबतक स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रकी कोरी वकवाससे यूरोपके राष्ट्रोंको सन्तोष नहीं होगा । इंग्लैण्ड जब अपने देशकी बेकारीको युद्धकी अवस्थामे भी पूरी तरहसे दूर नहीं कर सका है तब उसके नुस्त्रोंको दूसरे कैसे विश्वास करें ? छोटे राष्ट्र स्वभाग्य-निर्णयके सिद्धान्तको लेकर क्या करें ? नच बात तो यह है कि इसी सिद्धान्तके लागू करनेसे छोटे राष्ट्र मुसीबतमे पड़ गये हैं । यूरोपीय संघके बने बिना यूरोपका कल्याण नहीं है । छोटे राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता पड़ोसी शक्तिशाली राष्ट्रोंको अपने युद्धके लोभको संवरण नहीं करने देती । यदि एक समुदायमे सब सम्मिलित हो और सबके समान अधिकार हो और सब एक दूसरेके साथ

सहयोग करें तभी स्वभाग्य-निर्णयका सिद्धान्त सार्थक हो सकता है। पर यह पूंजीवादके युगमें सम्भव नहीं।

हिटलरकी नयी व्यवस्था (New order) यूरोपके लिए है और जापानकी सम्मिलित समृद्धिकी योजना (Co-prosperity Programme) पूर्वी एशियाके लिए है। एशियामें जो अद्भुत जागृति हुई है और राष्ट्रीय भावका उत्थान हुआ है उसीको देखकर यह योजना बनायी गयी है। इस युगमें जापान एशियावासियोंको अरसेके लिए गुलाम नहीं बना सकता। इंग्लैण्डने जिस तरह अपना साम्राज्य स्थापित किया उस तरह जापान आज नहीं कर सकता। जनताकी स्वतन्त्रताकी प्रबल भावनाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए जापानको मीठी घूंट पिलानेके लिए विवश होना पड़ता है। वह ऐसा जाहिर करता है मानो पूर्वी एशियासे यूरोपकी सत्ता मिटाना उसका एकमात्र उद्देश्य है। बहुतसे इस मिथ्या प्रचारमें फँस जाते हैं। यूरोपीय साम्राज्यवादसे एशियाके लोग तग आ गये हैं। इसीलिए यह प्रचार काम कर जाता है। चूँकि पूर्वी एशियाके देश कमजोर हैं इसलिए जापान उनकी रक्षाका वचन देता है और सबको अपने कुटुम्बोंमें शामिल होनेके लिए निमन्त्रित करता है। वह इस कुटुम्बका 'कर्त्ता' (हिन्दू कुटुम्बका प्रमुख कर्त्ता कहलाता है) बनना चाहता है। वह कहता है कि जब हम सब एक कुटुम्बके सदस्य हो गये तो हर एक राष्ट्रको हर बातके लिए स्वतन्त्र व्यवस्था करनेकी क्या जरूरत बाकी रह जाती है? जापानके पास बड़ी सेना है और लोहे आदिके आधारभूत कल-कारखाने हैं। प्रत्येक राष्ट्र इनका उपयोग अपने लाभके लिए कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने अन्न-वस्त्र और आन्तरिक रक्षाका प्रबन्ध स्वयं कर ले और शेष की व्यवस्था जापानमें पहलेसे ही मौजूद है। जापान इस प्रकार पूर्वी एशियाके राष्ट्रोंको देशी राज 'Home Rule' मात्र देना चाहता है जैसा इंग्लैण्डने मिस्र, फिलिस्तीन, ईराक आदिको दे रखा है। हमको यह भी न भूलना चाहिये कि वह एक सबल राष्ट्र बननेके लिए कुछ प्रदेशोंपर अपना प्रत्यक्ष अधिकार भी चाहता है। यदि आप खुशी-खुशी उसकी योजनाको नहीं स्वीकार करते तो वह आपके ही देशके कुछ लोगोंको फोड़कर एक नकली स्वदेशी हुकूमत कायम करेगा। मचूरिया और चीनमें उसने ऐसा ही किया है।

मित्रराष्ट्र तथा धुरीराष्ट्रोंकी नयी व्यवस्थाकी यह हकीकत है। इन सबसे जनताका कल्याण नहीं होनेका है और न कोई समस्या ही हल हो सकती है।

समाजवाद एकमात्र उपाय है

जवतक पूंजीवाद और उसकी विशेष अवस्थाएँ, साम्राज्यवाद और फासिस्टवादका लोप नहीं होता तवतक ससारमें शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। जहाँ हिटलरकी नयी व्यवस्था और जापानकी सम्मिलित समृद्धिकी योजना किसी प्रकार आर्थिक अनिश्चितताको तत्काल दूर करनेमें समर्थ हो सकती है वहाँ वे मनुष्यकी स्वतन्त्रताकी भूखको नहीं मिटाती। जहाँ मित्रराष्ट्रोंकी योजना यूरोपके आक्रान्त देशोंकी स्वतन्त्रताको स्वीकार करती है वहाँ उनकी आर्थिक अनिश्चितताको दूर नहीं कर पाती तथा अपने अधीन

उपनिवेशोकी गुलामीको कायम रखती है। मनुष्य रोटी, शान्ति और स्वतन्त्रता तीनों चाहता है। यह सब बातें सच्चे समाजवादकी स्थापनाद्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं। मानवता ही समाजवादका आधार है। समाजवाद मनुष्यके व्यक्तित्वका सम्मान करता है और उसके विकासके लिए पूर्ण अवसर देता है। उत्पादनके साधन व्यक्तिकी मिलकियत न होकर सारे समाजकी मिलकियत बन जाते हैं और अर्थनीतिका संचालन व्यक्तियोंके मुनाफेके लिए न होकर सारे समाजके लाभके लिए होता है। समाजवादकी स्थापनापर निश्चितताका लोप हो जाता है। साथ-साथ रहन-सहनका दर्जा भी ऊँचा होता जाता है। ज्ञान और संस्कृति उच्च वर्ग तक सीमित न रहकर सारे समाजके लिए सुलभ हो जाती है। रोजा लुक्सेम्बर्गके शब्दोंमें 'समाजवाद रोटी-मक्खनका सवाल नहीं है किन्तु एक सांस्कृतिक आन्दोलन है, एक विशाल तथा उन्नत ससारव्यापी विचार-पद्धति है (Socialism is not a bread and butter problem, but a cultural movement, a great and proud worldideology.) इसीलिए मार्क्सका कहना है कि मजदूरवर्ग-को रोटीकी अपेक्षा शौर्य, आत्मविश्वास, स्वतन्त्रता और आत्मसम्मानकी अधिक आवश्यकता है। समाजवाद ही सच्चे मानेमें लोकतन्त्रकी स्थापना कर सकता है। आजका सीधा सवाल पूँजीवाद बनाम समाजवादका है। जबतक पूँजीवादका बोलवाला है तबतक युद्धोका होना अनिवार्य है। इसीलिए क्रान्तिकारी जमाते विश्वव्यापी पैमाने-पर पूँजीवादका विरोध करती हैं। इससे बचनेका तरीका यही है। युद्धमें सहयोग देकर हम साम्राज्यवादी हितोकी ही रक्षा करते हैं।

कम्युनिस्ट दोस्त अन्तर्राष्ट्रीयताकी दुहाई देते हैं। इससे बढ़कर अन्तर्राष्ट्रीयता क्या हो सकती है ? लेनिनके शब्दोंमें "केवल एक ही प्रकारकी व्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रीयता है अर्थात् अपने ही देशमें क्रान्तिकारी आन्दोलनके विकासके लिए हार्दिक उद्योग करना और प्रत्येक देशके इसी प्रकारके आन्दोलनका समर्थन (प्रचार, सहानुभूति और सामानद्वारा) करना।" इसको छोड़कर सब आत्मप्रवञ्चना है।

‘देश-रक्षा’का पाखण्ड

कम्युनिस्ट भाइयोंने कुछ समयसे "जनताका युद्ध" का नारा छोड़कर देशभक्तिकी अपील करनी शुरू की है। यह युद्ध जनताका युद्ध है इस भ्रममें जनता नहीं पड़ी है, वह तो अपने नित्यके अनुभवसे युद्धके साम्राज्यवादी स्वरूपको देख रही है। केवल मुट्ठीभर कम्युनिस्ट इस धोखेमें पड़े हैं या यो कहिये कि धोखेमें पड़नेके लिए मजबूर हैं। किन्तु उनका प्रचार व्यर्थ साबित हो रहा है। वातावरण इस विचारके सर्वथा प्रतिकूल है। इसलिए कम्युनिस्टोंने जनताके युद्धका जिक्र करना ही एक तरहसे बन्द कर दिया है। अब वह मातृभूमिकी रक्षाके नामपर ब्रिटिश गवर्नमेण्टके साथ सहयोग करनेकी अपील करते हैं। उनका तर्क है कि शत्रु दरवाजेपर आ गया है; हम स्वतन्त्र रीतिसे उसका मुकाबला नहीं कर सकते; इसलिए राष्ट्रकी रक्षाके लिए हमको गवर्नमेण्टसे सहयोग करना चाहिये। इसी नीतिकी निन्दा लेनिनने "मिथ्या देश-रक्षा" (National

Defencism) कहकर की है। गवर्नमेण्टके साथ सहयोग कर हम उसके साम्राज्यवादी हितोंकी रक्षा करते हैं, देशकी नहीं। गुलामोका भी कोई देश होता है।

इस तर्कका अर्थ तो यह हुआ कि चाहे युद्ध साम्राज्यवादी क्यों न हो जब युद्ध दरवाजेपर आ जावे तब सब विचार छोड़कर और मतभेदको भुलाकर अपनी हुकूमतकी सहायता करो। यह न वैज्ञानिक ढंगसे सोचते हैं, न साम्राज्यवादी, न राष्ट्रीय और न अन्तर्राष्ट्रीय। यह केवल अवसरवादिता है। ऐसे ही लोगोंको लक्ष्य कर मार्क्सने एक अवसरपर कहा था “I have sown dragons and have harvested fleas” “मैंने अग्निसर्पकी खेती की मगर हाथ लगे इस।” यदि एक तीर नहीं काम करता तो दूसरा छोड़ो। किसी तरह काम निकालना चाहिये। जनतामें जिस तरहका प्रचार काम कर सके उस तरहका प्रचार होना चाहिये। मार्क्सवादी जनताको न देवताकी तरह पूजता है और न उसकी अवमानना करता है। वह जनतासे सीखता है और जनताको सिखाता है। लेकिन कम्युनिस्ट तो जनताको मिट्टीका लोढ़ा समझते मालूम होते हैं। यह तो हिटलरका तरीका है। कमसे कम मुझे ऐसी आशा इनसे न थी। मैं समझता था कि और चाहे जो कुछ हो कम्युनिस्ट कमसे कम जनताको जान बूझकर बेवकूफ बनाना नहीं चाहेंगे। जो जनता इतिहासको बनाती और बिगाड़ती है उसके साथ मजाक करना ठीक नहीं है। उसका निरादर करना इतिहासके साथ विश्वासघात करना है।

मैंने युद्धके सम्बन्धमें विविध पहलुओंकी विस्तारसे चर्चा इस कारण की है कि आज कम्युनिस्टोंकी विचारपद्धतिकी मीमांसा करना सबसे महत्वका क्रान्तिकारी कार्य हो गया है। यह ठीक है कि उनका प्रचार उत्तरमें बीज छीटनेके समान है। किन्तु पढ़े-लिखे लोग कभी-कभी अपनी प्रकाण्ड विद्वत्ता या अल्पज्ञानके कारण सीधी-सादी बात समझनेमें भी असमर्थ रह जाते हैं। पढ़े-लिखे लोगोंकी दिमागी ऐय्याणी कभी-कभी नये-नये विवाद खड़ा करती है और अपनी वाक्चातुरीसे दूसरोंको परास्त करना चाहती है। इसमें उनको खास मजा आता है। और जब ऐसी विचारधाराको रूस और तृतीय इण्टरनेशनलका सहारा मिल जाय तब तो कहना ही क्या है? क्रान्तिके मार्गको परिष्कृत करनेके लिए इस विचार-पद्धतिके खोखलेपनको दिखाना निहायत जरूरी है।

कम्युनिस्टोंकी कार्यपद्धति

कम्युनिस्टोंकी कार्य-पद्धति भी उतनी ही दूषित है। कम्युनिस्ट लोग अन्तर्राष्ट्रीय एकता तथा संयुक्त मोर्चेकी दुहाई देते हैं मगर हर जगह फूट पैदा करते नजर आते हैं। विद्यार्थी-आन्दोलन तथा किसान-आन्दोलनका अनुभव तो यही बतलाता है। यह कोई आकस्मिक घटनाएँ नहीं हैं। हमारा कर्तव्य है कि इसका अनुसन्धान करे और समझे कि क्या कारण है कि जहाँ कहीं कम्युनिस्ट जाते हैं वहाँ संस्थाओंको छिन्न-भिन्न कर देते हैं। उनके साथ संयुक्त मोर्चाबन्दी बहुत दिन नहीं चलती। कम्युनिस्टोंकी नीति है कि जब कभी वह कमजोर होते हैं या जब कभी उनको किसी खतरेका सामना करना पड़ता है तब वह संयुक्त मोर्चेका नारा बुलन्द करते हैं। इस प्रकार वह अपनी शक्ति और प्रभावको

बढाते हैं । यदि वह किसी समय काफी सबल हो जाते हैं तो उस संस्थापर अपना आधिपत्य जमानेकी कोशिश करते हैं । जब कभी उनकी समझमें क्रान्तिकारी परिस्थिति उपस्थित होती है तभी वह संयुक्त मोर्चेकी नीतिका परित्याग करते हैं और उन संस्थाओंपर पूरा कब्जा करना चाहते हैं जिनमें उनका या तो बहुमत है या परिस्थिति कब्जा पानेके लिए अनुकूल है । इसका कारण यह है कि उनकी ऐसी मान्यता है कि वही सच्चे क्रान्तिकारी हैं और दूसरे लोग सुधारवादी हैं । वह अपनेको क्रान्तिका ठेकेदार समझते हैं और उनके कार्यमें दूसरे बाधा न डाल सके इसलिए किसी दूसरी संस्थाके अनुशासनमें नहीं रहना चाहते और वर्ग-संगठनपर अपना अक्षुण्ण प्रभाव जमाना चाहते हैं । यही कारण है कि वह कम्युनिस्ट, जो सन् १९३७ से संयुक्त मोर्चेका नारा बुलन्द करने लगे थे और कांग्रेसकी एकताके लिए लम्बी बातें किया करते थे, युद्धके उपस्थित होते ही कांग्रेसके विरुद्ध आवाज उठाने लगे, उन सब दलोको सुधारवादी कहने लगे जिनके साथ वह अबतक सहयोग करते आये थे और जिनको कलतक क्रान्तिकारी स्वीकार करते थे । मजदूर और किसान सभाओंमें उनको सामान्य स्थान प्राप्त था । इसलिए इन संस्थाओंमें उनकी दाल नहीं गल पाती थी । किन्तु विद्यार्थी-संगठनपर अच्छा प्रभाव होनेके कारण उस संगठनमें झगड़ा खड़ा करना उनके लिए आसान था । नागपुर अधिवेशनके अवसरपर उन्होंने दूसरे दलोको निकालनेका प्रयत्न किया और स्वागत समितिकी सहायतासे इस कामको पूरा कर सके । कुछ दिनों बाद जब सत्याग्रह आन्दोलनमें कई प्रमुख किसान नेता गिरफ्तार हो गये तब उन्हें किसान-सभामें बेजाब्ता कार्यवाही करनेका मौका मिला । यहाँ इस बातकी जरूरत नहीं है कि मैं कम्युनिस्टोंकी उन अनियमित कार्यवाहियोंका उल्लेख करूँ जिनके द्वारा उन्होंने किसान-सभाके जिम्मेदार लोगोको उनसे अलग होनेके लिए विवश किया । इसमें स्वामी सहजानन्द सरस्वतीका भी पूरा हाथ था ।

कम्युनिस्टोंकी साम्प्रदायिकता

कम्युनिस्टोंके इतिहासमें यह पहला मौका नहीं है जब कि उन्होंने वर्ग-संगठनोको अपनी कार्यवाहियोंसे कमजोर कर दिया है । भारत क्या हर जगह उसके पर्याप्त उदाहरण हमको मिलते हैं और क्यों न मिले जब कि उनकी मनोवृत्ति इतनी सक्रुचित, अनुदार और मिथ्या धारणाओंपर स्थापित है । यह अपनी भूलोको स्वीकार भी करते हैं, उनको सुधारते भी हैं । किन्तु फिर भी उन्हीं भूलोको दुहराते हैं । हर जगह इन्होंने क्रान्तिको बरवाद किया है ! इसी दूषित मनोवृत्तिकी वदौलत आन्दोलन और क्रान्तिसे भी अपने दलको ये अधिक महत्त्व देते हैं । इनके कठमुल्लापनका क्या कहना है । यह शब्दप्रमाणके माननेवाले हैं । जीवनका अनुभव इनके लिए इतना महत्त्व नहीं रखता जितना कि शास्त्रका एक वाक्य । इनका आचरण पग-पगपर मार्क्सकी शिक्षाके प्रतिकूल होता है । इन्होंने कम्युनिज्मको एक धार्मिक सम्प्रदायका स्वरूप दे दिया है । इनके भी महन्त है । मास्को इनका मक्का है । तृतीय इण्टरनेशनलके आदेश इनके लिए वेदवाक्य हैं, चाहे उनकी उपयुक्तता समझमें आवे या न आवे ?

हमारी नीति

खैर कम्युनिस्ट जो भी सोचे या करे, हमारा रास्ता साफ है। हम आजादी चाहते हैं। हम साम्राज्यवाद और फासिज्म दोनोंके विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि जनतामें आक्रमणकारीके विरोधका भाव जगे। हमको किसी राष्ट्रका आक्रमण वर्दाशित नहीं हो सकता। हम सब नयी व्यवस्थाओंकी हकीकतको समझते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र दूसरेको मुक्त करनेके लिए आत्मबलिदान नहीं करता है। हम जापानको सचेत कर देना चाहते हैं कि वह यह न समझे कि हम भारतवासी उसका स्वागत करेंगे। हम गुलाम हैं जरूर-पर एक गुलामीके बदले दूसरी गुलामीको ओढ़नेको तैयार नहीं हैं। हम हर आक्रमणकारीका मुकाबला करेंगे। हमारे पास जो अस्त्र है उन्हीका प्रयोग हम कर सकते हैं। असहयोग ही हमारा अस्त्र है। इसका प्रयोग हम बीस सालसे कर रहे हैं। भारतकी मिट्टी और आबोहवासे वेवसीकी हालतमें यह अस्त्र पैदा हुआ है।

यह जनताका युद्ध कैसे बनेगा ?

यदि इस युद्धमें कम्युनिस्ट जनताका हार्दिक सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको नीचे लिखी शर्तोंको गवर्नमेण्टसे पूरा कराना चाहिये। इन शर्तोंके पूरा हुए बिना जनताका सहयोग नहीं मिल सकता :—

(१) जनताको यह अनुभव होना चाहिये कि देश स्वतन्त्र हो गया है और उसको अपने देशकी रक्षा करनी है। यह कार्य भविष्यके वादोंसे नहीं हो सकता और न वायसरायकी काउन्सिलके भारतीय करनेसे। यहाँका प्रत्येक अधिवासी और सामान्यजन जब अपनेको स्वतन्त्र समझे तभी समझना चाहिये कि देश स्वतन्त्र हुआ।

(२) सामाजिक कानूनका बनना जिससे यहाँके किसानों, मजदूरों तथा निम्नश्रेणीके लोगोंकी बेकारी और गरीबी दूर हो।

वर्तमान युगमें इन शर्तोंका पूरा होना युद्धमें सहयोग प्राप्त करनेके लिए जरूरी है। जनता १९ वीं शताब्दीकी जनताकी तरह निश्चेष्ट और उदासीन नहीं है। वह जानना चाहती है कि युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है और उससे उसका क्या सम्बन्ध है। वह जानना चाहती है कि युद्ध पूँजीपतियोंके लाभके लिए लड़ा जा रहा है या वह जनताके हितमें है। वह यह भी जानना चाहती है कि युद्धके लिए पूँजीपति भी त्यागके लिए तैयार हैं या केवल उसीसे त्याग करनेको कहा जाता है।

पिछले युद्धका अनुभव उसके सामने है। उस वार भी कहा गया था कि यह युद्ध लोकतन्त्रकी रक्षा और स्वतन्त्रताके लिए है। किन्तु हुआ कुछ नहीं। इसलिए जनता सतर्क है और जानना चाहती है कि इस वार भी पिछली वारकी तरह कहीं धोखा तो नहीं दिया जाता है। वह यह भी आश्वासन चाहती है कि नयी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिसमें युद्ध सम्भव न हो। फ्रांसमें जब पोलैण्डकी रक्षाके लिए युद्ध घोषित किया गया और जगह जगह पोस्टर चिपकाये गये जिसमें लिखा था—‘स्वतन्त्रता खतरेमें है, पूरी ताकत लगाकर उसकी रक्षा करो’ तब लोग पूछते देखे गये कि पोलैण्डपर आक्रमण और

हमारी स्वाधीनता खतरे में ? लोग यह नहीं समझ पाते थे कि हम पोलैण्डके लिए क्यों लड़े। पिछले युद्धके रक्तस्त्रावकी याद उनके हृदय-पटलपर अंकित हो गयी थी। माताएँ सोचती थी कि लड़कोको क्या हमने इसीलिए पाला-पोसा और सुशिक्षित किया था कि जब वह जीवनक्षेत्रमें प्रवेश करनेके योग्य हो जायँ तब हम उन्हें वधस्थानमें मौतके घाट उतरनेको भेज दें।

स्वतन्त्र देशोंकी जनता साम्राज्यशाहीकी लड़ाइयाँ लड़नेको नहीं तैयार है। जर्मन जातिके साथ वर्साईमें ग्रन्याय न किया गया होता और वादको आर्थिक संकटके कारण जर्मन तबाह न हो गये होते और हिटलरने कमसे कम राष्ट्रीय अपमानको घोने और आर्थिक अनिश्चितताका अन्त करनेका प्रयत्न न किया होता तो जर्मन लोग आज हिटलरके साथ न होते।

फ्रांसके पतनके कारणोंका विश्लेषण करनेसे मालूम होता है कि बड़े-बड़े सेनापति और राजनीतिज्ञोंकी धोखेवाजी ही पतनका कारण न थी किन्तु जनताका निरुत्साह और उदासीनता भी। यह उदासीनता इस कारण थी कि जन सयुक्त मोर्चे (People's front) की सरकारने जो कानून मजदूरोंके हितके लिए बनाये थे वह वादको रद्द कर दिये गये थे।

इंग्लैण्डमें चर्चिलकी गवर्नमेण्टके आनेके बादसे कंजर्वेंटिव गवर्नमेण्टने कई ऐसे कानून मजदूरोंके लाभके लिए युद्धकी आवश्यकताओंसे विवश होकर बनाये हैं जो मजदूर पार्टीकी पुरानी माँगों की अपेक्षा कहीं अधिक बड़े हुए हैं। पर इतना भी पर्याप्त नहीं समझा जाता है। इस युद्धने यह दिखा दिया है कि पूँजीवाद इस युद्धके जीतनेमें काफी रुकावट है। हथियारोंके तैयार करने और जनशक्तिके उपयोगमें इंग्लैण्डकी वह सामाजिक व्यवस्था हारिज हो रही है जिसका आधार व्यक्तिगत सम्पत्तिकी रक्षा और मुनाफा कमाना है। आज इंग्लैण्डमें खाद्यसामग्रीकी पैदावार बढ़ानेका प्रयत्न हो रहा है। इसके लिए खेतके मजदूरोंकी मजदूरी काफी बढ़ा दी गयी है। लेकिन बैकर, जमींदार और व्यापारी अपने स्वार्थके कारण अब भी रुकावट डाल रहे हैं।

यह सर्वग्रासी युद्ध (total war) है। इसके जीतनेके लिए चौमुखी कोशिश होनी चाहिये। आवादीके प्रत्येक हिस्सेकी मदद और हार्दिक सहयोगके बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। युद्ध जीतनेके लिए सबको आत्मत्याग करनेके लिए तैयार होना पड़ेगा। केवल सिपाहीका आत्मत्याग काफी नहीं है। नागरिकोंको भी पूरा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। सब स्वार्थोंकी उपेक्षा करनी होगी। आवश्यकता पड़नेपर व्यक्तिगत सम्पत्ति भी वलिदान करना होगा। हिटलरको किसी किस्मकी अड़चन नहीं है। पर इंग्लैण्डका पूँजीपति वर्ग अपने स्वार्थोंको छोड़नेको तैयार नहीं है। जब गवर्नमेण्टने खेत-मजदूरकी मजदूरी बढ़ायी तो खेतोंके मालिक गल्लेका भाव बढ़ानेकी माँग करने लगे। यह वर्ग लड़ाईका बहुत बड़ा बोझ गरीबोंपर छोड़ना चाहता है। पूँजीपतियोंका एक भाग देशके स्वार्थोंको भी अपने वर्गके स्वार्थोंके लिए वलिदान कर देगा। इसी वर्गके प्रतिनिधि वाल्डविन और चेम्बरलेन थे। चर्चिल साम्राज्यके हितोंको सर्वोपरि मानता है। जिस

तब पूँजीपतियोंका वर्ग बड़ी कठिनाईसे अपने विशेषाधिकारोंको छोड़नेको तैयार है उसी तरह जनता अब यह जानना चाहती है कि उसके क्या अधिकार हैं और यदि उससे सहायता माँगी जाती है तो उसकी मुसीबतोंको दूर करनेके लिए हुकूमत क्या करनेको तैयार है। यह हालत स्वतन्त्र और प्रजातन्त्र कहलानेवाले देशोंकी है। फिर जगें हुए परतन्त्र देशोंका क्या कहना ! पहले तो वहाँकी जनता परदेशी राजसत्ताके विरुद्ध होती है; दूसरे क्रान्तिके डरसे हुकूमत जनताको हथियार नहीं देती। जनता और अधिकारियोंके बीच अविश्वासकी एक दीवार खड़ी रहती है। जनता अपनी स्वतन्त्रताके लिए बार-बार उद्योग करती है : हुकूमत उसका दमन करती है। इसलिए इनका सम्बन्ध और भी कटु और विद्वेषपूर्ण हो जाता है।

जो संगठन तेजस्वी, आत्मत्यागी और जनताका प्रिय होता है वही हुकूमतका विरोध करता है और वास्तवमें युद्धके समय वही हुकूमतके भी कामका होता है। किन्तु उसी संगठनसे हुकूमत सबसे ज्यादा घबराती है और उसीका सबसे कम विश्वास करती है। हुकूमतके वादोंका जनता विश्वास नहीं करती है। हुकूमतमें इतना माहौल और दूरदर्शिता नहीं होती कि वह युद्धकी आवश्यकताओंको समझकर सब पुरानी परम्पराओंको तोड़ दे। जनतामें आत्मविश्वासकी कमीसे आक्रमणकारियोंके विरोधकी उतनी तीव्र भावना नहीं होती। इन सब कारणोंसे जनताका सहयोग नहीं प्राप्त होता, वह तटस्थ रहती है। इसलिए साम्राज्य ब्रिटेनकी कमजोरीका हेतु है। यह बात मलाया और बर्मा में प्रमाणित हो चुकी है। किन्तु तिसपर भी साम्राज्यका मोह छोड़ा नहीं जाता।

जनता किस आशापर साथ दे ? उसकी गरीबी, बेकारी, बेवसी और गुलामी यह सब साम्राज्यवादके कारण हैं। आज भी उसके आर्थिक बोझ बढ़ते जाते हैं। संयुक्त-प्रान्तमें बेदखलीका ताँता लगा हुआ है। अकेले गोरखपुर जिलेमें २०००० बेदखलियाँ हुई हैं। जमींदारोंका जुल्म बढ़ता जाता है सरकारी अहलकार तरह देते हैं। इस्तेमालकी सब चीजें महँगी होती जाती हैं। गल्ला उसी हिसाबसे महँगा नहीं है क्योंकि गल्लेकी कीमतपर नियन्त्रण है और महँगाईसे जो थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, वह बनियोंका, न कि किसानोंका। आज कहा जाता है कि ज्यादा खाद्यसामग्री पैदा करो, किन्तु जैसा हम आगे दिखावेगे वर्तमान काश्तकारी कानूनके रहते यह सम्भव नहीं है। कोई भी गवर्नमेण्ट, जिसका निकट सम्पर्क जनतासे होता और जो वास्तवमें युद्धमें सफल होना चाहती, बेदखलीको बन्द कर देती और किसानोंके रास्तेसे उन तमाम अड़चनोंको दूर करनेका प्रयत्न करती जो उसको पैदावार बढ़ाने नहीं देती।

ब्रिटेन साम्राज्यके बोझसे पिसा जाता है। यह गलत है कि जापानके टैंक और डाइव बाम्बर साम्राज्यको छिन्न-भिन्न कर रहे हैं। साम्राज्यके बोझको फेंककर नैतिकताका अभेद्य कवच पहिन ब्रिटेन आज भी विजयी हो सकता है। उसके इस कार्यसे जापान-जर्मनीके अस्त्र-शस्त्र निस्तेज और निष्प्रभ हो जायेंगे। यह एक ऐसा प्रचार-कार्य होगा कि इससे युद्धकी कायापलट हो जावेगी। जर्मनीद्वारा आक्रान्त देशोंको एक नूतन सन्देश मिलेगा और उनके बुझे हुए दिलोंमें एक नवीन आशाका संचार होगा। एशियाके

देशोंमें एक कोनेसे दूसरे कोनेतक विजली दौड़ जायगी । जापानका सारा प्रचार व्यर्थ हो जावेगा । एशिया-अफ्रिकाकी असंख्य जनता फैसिज्मको नेस्तानाबूद करनेपर तुल जावेगी । फिर मोर्चोंकी कमी नहीं रहेगी । पर जो लोग अस्त्र-शस्त्रपर ज्यादा विश्वास करते हैं वह नैतिकताके रहस्यको नहीं समझ सकते । केवल युद्धसामग्रीकी समृद्धिके आधारपर जो लड़ाई लड़ी जावेगी उसका नतीजा निश्चित रूपसे नहीं बताया जा सकता ।

हमारे सामने चीनियोंकी मिसाल पेश की जाती है । किन्तु लोग भूल जाते हैं कि चीन स्वतन्त्र है और चीनियोंमें जापानियोंके विरुद्ध प्रबल विद्वेषका भाव मौजूद है । इसका कारण यह है कि सन् १८९५ ई० से जापान चीनपर आक्रमण करता आ रहा है और उसने चीनके कई प्रदेश हस्तगत कर लिये हैं । जापानका भारतके साथ राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहा है । इसलिए उसके विरुद्ध विद्वेष भाव होना सम्भव नहीं है । फिर चीनमें जनताकी आर्थिक अवस्थाको सुधारनेकी थोड़ी बहुत चेष्टा भी हो रही है । सहयोग समितिका आन्दोलन चल रहा है । एडगर स्नो (Edgar Snow) ने अपनी 'जली भूमि' (Scorched Earth) नामक पुस्तकमें बतलाया है कि जो प्रान्त कम्युनिस्टोंके अधिकारमें हैं और जहाँ किसानोंकी अवस्था ज्यादा अच्छी है वहाँके निवासी युद्धमें ज्यादा उत्साहके साथ सहयोग दे रहे हैं । एडगर स्नोकी गिकायत है कि अभीतक चीनका एक तिहाई भाग ही युद्धके लिए संगठित किया जा सका है और उनके अनुसार इसका कारण यही है कि किसानोंकी अवस्थाके सुधारनेपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है । इसके लिए वह को-आ-मिटिंगको उत्तरदायी ठहराते हैं ।

युद्धके अनुभव बता रहे हैं कि जबतक जनताको एक नवीन आशा और नवीन उद्देश्यसे प्रभावित नहीं किया जावेगा जिनके लिए वह मरनेके लिये तैयार हो और जिनकी रक्षाके लिए वह आत्मवलिदान करे, तबतक युद्धमें किसी पक्षको सफलता नहीं मिल सकती । रूस और चीनके साथ जो सबकी हार्दिक सहानुभूति है उससे कहाँतक लाभ उठाया जा सकता है ? इनका मित्र राष्ट्रोंके खेमेमें होना मित्र राष्ट्रोंको बल पहुँचाता है । पर यह पूंजी उनकी निजकी नहीं है और दूसरेकी पूंजीके आधारपर कबतक काम चल सकता है ? वही युद्धनीति सर्वोत्तम है जो जनताकी सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिकी आवश्यकताको पूरी करती है । इतिहास गतिशील है । वह ऐसी सस्थाओंको बहुत अरसेतक कायम नहीं रहने देगा जो जड़ हो गयी हैं और उसकी प्रगतिमें बाधा पहुँचाती हैं । पुराने साम्राज्य ध्वस्त हो रहे हैं । यह प्रक्रिया हमारी आँखोंके सामने चल रही है । उनका स्थान लेनेके लिए किसी नयी संस्थाका जन्म होगा । यदि संसारकी प्रगतिशील शक्तियाँ वर्तमान युद्धको सामाजिक क्रान्तिके युद्धमें परिणत करके समाजवादकी स्थापनाके लिए सचेष्ट न हुईं तो कुछ समयके लिए फैसिज्मके छा जानेका अन्देश है ।

सब समझदार लोग इंग्लैण्ड और अमेरिकासे यह सवाल कर रहे हैं कि वे साम्राज्यवादके बोझसे अपनेको हल्का करे तथा सब राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर समस्त संसारमें एक ऐसी नयी व्यवस्थाका आरम्भ करे जिससे जनताको सच्ची शान्ति, आर्थिक निश्चिन्तता और स्वतन्त्रता प्राप्त हो । संसारकी उन्नतिका तथा विजय

प्राप्त करनेका यह सर्वोत्तम उपाय है। आधी लड़ाई तो विचारोकी लड़ाई है। जिसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है वह अस्त्र-शस्त्र-सुसज्जित होनेपर भी कुछ नहीं कर सकता। विचारोकी शक्ति टैंकोसे भी कहीं ज्यादा गहरी और जवर्दस्त है। विचार पहाड़ों और समुद्रोंका भी उल्लङ्घन करते हैं और उनके सामने राष्ट्रीय हृदे बेकार हो जाती है। इंग्लैण्डके प्रसिद्ध फौजी अफसर लिडलहार्ट (Liddellhart) के शब्दोंमें 'इस लड़ाईका फैसला मनोवैज्ञानिक (psychological) क्षेत्रमें होगा।' इसके लिए जनताकी जीविकाका प्रश्न हल करना और उसके अधिकारोंको विस्तृत करना आवश्यक है। किन्तु, साम्राज्यवादी राष्ट्र क्यों इन बातोंपर ध्यान देने लगे ? वह अपनी पाशविक शक्ति और असीम धनके गर्वके नशेमें चूर हैं। यदि कुछ करना भी चाहते हैं तो कदम फूँक-फूँककर रखते हैं। पर आज इसका जमाना नहीं रहा। आज तो करोड़ों दिलोंको हिला देनेवाली नीतिकी जरूरत है।

युद्ध-सम्बन्धी समस्याएँ

हम चाहें या न चाहें हमारे ऊपर यह युद्ध लाद ही दिया गया है। युद्धके कारण हमारे देशमें तरह-तरहकी समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं। अपने देशके कल्याण, अपने देशवासियोंके सुख और शान्तिकी दृष्टिसे हमें इन समस्याओंका सामना करना है, इनको हल करना है। ज्यों-ज्यों देश इन समस्याओंको हल करनेकी ओर बढ़ेगा वह स्पष्ट अनुभव करेगा कि स्वतन्त्रता और सामाजिक क्रान्तिकी कितनी तात्कालिक आवश्यकता है। इसके बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती और हमारे सारे प्रयत्न बेकार मालूम पड़ते हैं, हमारी सारी योजनाएँ कागजोंमें ही धरी रह जायँगी। अगर इन कठिनाइयोंका दृढ़तासे सामना नहीं किया गया तो सारा देश बड़ी परेशानी और तकलीफ उठायेगा।

युद्धके कारण चीजे महँगी हो ही जाती हैं। हमारे देशमें भी ऐसा ही हो रहा है। सभी चीजोंका दाम दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। शहरोंमें रहनेवाले लोगोंको बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ रहा है। जीवन-निर्वाहकी समस्या बड़ी कठिन हो गयी है। देहात में समस्या थोड़ी भिन्न है, मगर देहातके लोग भी हर तरहसे परेशान हैं। किसानोंकी मामूली जरूरतकी चीजें महँगी हो गयी हैं और हर तरहका जुल्म बढ़ गया है। मौका पाकर जमींदार अपनी खोयी हुई सुविधाएँ तथा अधिकार फिरसे हस्तगत करने, किसानोंको बेदखल करने तथा उनसे तरह-तरहकी वसूलियाँ वियाँ करनेमें लगे हैं। इस देशकी हुकूमत तो लड़ाई चलानेकी धुनमें है। उसे लड़ाईके लिए रुपये और सामान इकट्ठा करनेकी परेशानी है और यह सब धूम फिरकर किसानोंके ऊपर पड़ता है। हुकूमत जमींदारोंको पकड़ती है और जमींदार किसानोंको पकड़ते हैं।

जैसे-जैसे युद्ध फैलता और बढ़ता जायगा ये समस्याएँ और भी विकट रूप धारण करती जायँगी। हम सभी लोगोंके सामने महँगी और भरपेट भोजनकी सामग्री इकट्ठा करनेका प्रश्न आयेगा। साधारण समयमें भी हिन्दुस्तानमें चावल और गेहूँ काफी नहीं पैदा होता। हमें हर साल वर्गसि ३५ लाख टन चावल मँगवाना पड़ता था। करीब-

करीब यही हालत गेहूँकी थी। हमारी गेहूँकी पैदावार काफी नहीं होती। इधर लड़ाईके लिए हिन्दुस्तानसे गल्ला बाहर भेजा गया और उधर वर्मापर जापानियोंका कब्जा हो जानेकी वजहसे जापानसे चावलका आना बन्द हो गया। लेकिन वर्मासे लोग भाग-भागकर लाखोंकी संख्यामें हिन्दुस्तान चले आये हैं। इसके अलावा आवागमनकी कठिनाइयोंके कारण खाद्य सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थानको भेजना कठिन होता जा रहा है। तो ऐसी हालतमें गल्लेकी कमीका खतरा हमारे सामने पेश होता है और ऐसा मालूम होता है कि बाहरसे हम यह सामान नहीं मँगवा सकेंगे; शायद देशके अन्दर भी एक जगहसे दूसरी जगह हम ये चीजें मुश्किलसे पहुँचा पावें।

जब खाद्य सामग्री माँगसे कम पड़ जायगी तो दामका बढ़ जाना तो स्वाभाविक है। बाजार-भावको रोकनेकी कोशिश की जा रही है। उससे कुछ थोड़ा काम चलेगा मगर असली सवाल तो और गल्ला पैदा करनेका है। इसके दो उपाय हैं। एक तो यह कि गल्लेकी खेती बढ़ायी जाय और दूसरा यह कि खेतोंकी उपज बढ़ायी जाय। ऐसे तो हिन्दुस्तानकी जमीनका एक चौथाई हिस्सा अभी बेकार पड़ा है मगर वास्तवमें इस जमीनपर जल्द-से जल्द जानवरोंका चारा ही पैदा किया जा सकता है। गल्ला पैदा करनेके लिए तो इस जमीनको बहुतसारी चीजोंकी जरूरत है। इस कारण खेती बढ़ानेका सवाल तो टेढ़ा है।

और गल्ला कैसे पैदा हो ?

तब रही बात खेतीकी उपज बढ़ानेकी। यह हो सकता है। इसकी कोशिश सभी ओरसे की जा रही है। सरकार इसे अपने ढंगसे कर रही है। 'वही रफ्तार बढ़ेगी जो पहले थी सो अब भी है'। कांग्रेसने भी इस ओर अपनी शक्ति लगानी शुरू की है। ऐसा ख्याल है कि हर हिस्सेके लोग अपनी-अपनी जरूरतके लिए काफी गल्ला पैदा कर ले तो काम बन जाय। इसलिए किसानोंसे अपील की जा रही है कि वह अधिक-से-अधिक अन्न पैदा करनेमें लग जायें।

बात बहुत दुरुस्त है। इस कठिन समस्याका आजकी हालतमें और कोई हल हो नहीं सकता। मगर जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है वह निहायत ही नाकाफी है। उससे हमारा उद्देश्य नहीं हासिल होगा। लोगोंको इसका ख्याल करना चाहिये कि जिससे वह अपील कर रहे हैं उसके दिल और दिमागपर इसका क्या असर पड़ेगा। आखिर यह भी कोई सोचता है कि एक किसान इस तरह जी-तोड़ परिश्रम करनेकी बात क्यों सोचे ? क्या इसलिए कि यह लड़ाई उसकी लड़ाई है और ब्रिटिश सरकारके जीत जानेपर उसका भाग्योदय होगा ? यह तो उसकी अपलमें नहीं अँटता। सरकारकी ओरसे जो व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है उसका अनुभव करते हुए ऐसी विचारधाराको उत्तेजना नहीं मिलती। तो क्या इसलिए कि शहरोंके बसनेवालोंको बड़ी तकलीफ होगी ? उन्होंने उसके लिए क्या किया है या कर रहे हैं ? या इसलिए कि जो कुछ वह पैदा करे वह मालिकके लगान, महाजनके सूद और तरह-तरहकी माँगोंको पूरा करनेमें खत्म हो जाय

और वह बेचारा हाथ टटोलता रह जाय ? ऐसी हालतमें उसके हृदयमें उत्साह कैसे पैदा हो सकता है ?

यह बात सही है कि गल्लेकी महँगीका फायदा उठानेके लिए किसान कुछ-न-कुछ ज्यादा गल्ला पैदा करनेकी ओर जरूर झुकेगे, मगर इस तरह जो पैदावार बढ़ेगी उससे देशका काम थोड़े ही चलेगा । पैदावार काफी बढ़ानी होगी और उसके लिए किसानोंको अपनी जान लगा देनी होगी । यह उद्देश्य कैसे हासिल होगा ? सरकार और उसके गुमाश्तोंके तरीके तो ऐसे हैं कि उससे परेशान होकर किसान अपनी जगहसे टससे मस न हो तो कोई आश्चर्यकी बात न होगी । अन्देश तो है कि इस दुर्व्यवहारसे यह गल्लेकी समस्या और भी जटिल न हो जाय, किसान बिल्कुल ही विगड़ न खड़ा हो । चीजोंका दाम यो ही बढ़ गया है, जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारोंका पुराना रवैया फिर शुरू हो गया है और ऊपरसे सरकारकी ओरसे लड़ाईमें मदद करनेकी माँग आकर दवाती है । यह तो परेशानी और तबाहीका रास्ता है ।

अगर हमलोग चाहते हैं कि यह मसला सही तरीकेसे तय हो और किसान उत्साहके साथ इस काममें शामिल हो तो हमें उनके हाँसले बढ़ानेका उपाय करना होगा । हमें वह सारी बातें करनी होंगी जिससे किसानकी खेतीसे और ज्यादा दिलचस्पी हो, जिससे उसके दिलमें अपने खेतकी उपज बढ़ानेकी परेशानी पैदा हो । पुराने रीतिरिवाजों रिश्ते-नाते, नियमों तथा कानूनोंका बोझ जबतक उसके ऊपर लदा रहेगा तबतक उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती । यही तो समाजवादी कितने वर्षोंसे कहते आ रहे हैं । इसके लिए यह जरूरी है कि कमसे कम फैजपुर कांग्रेसमें जो किसान-सम्बन्धी कार्यक्रम कबूल किया गया था उसपर अमल किया जाय । किसानोंको जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारोंकी ज्यादातीसे नजात दिलायी जाय, कर्ज तथा सूदखोरीसे उन्हें बचाया जाय, लगानमें कमी की जाय, बेदखलीका तरीका खत्म किया जाय, किसी न किसी शक्लमें जमीनमें किसानोंकी मिल्कियत मान ली जाय और खेतीकी तरक्कीके लिए जरूरी इन्तजाम जल्दसे जल्द किये जायँ । तब कही यह मामला काबूमें आ सकता है । वरना हमलोग यो ही हाथ-पैर पीटते रह जायेंगे ।

रूस तथा चीनका उदाहरण

आखिर हमें तो अपने देशकी बेकारी और गरीबी दूर करनी ही है, देशको स्वतन्त्र करना है, अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनी है और तत्काल लड़ाईकी परेशानियोंका सामना करना है । यह सब कैसे होगा ? यह सब कौन करेगा ? अगर हम चाहते हैं कि हमारे देशकी जनता जोश और हिम्मतके साथ इस काममें पड़े तो हमें सामाजिक क्रान्तिके कार्यक्रमको तत्काल अपनाना पड़ेगा, उसी तरह जैसे चीनको अपनाना पड़ा है । आखिर हमसे रोज कहा जाता है कि हम रूस और चीनके आदर्शका अनुकरण करें; जिस बहादुरीसे रूसी और चीनी अपनी आजादीके लिए लड़ रहे हैं उसी तरह लड़नेको हम भी तैयार हो जायँ । मगर अपने लोगोंमें यह जोश और हिम्मत पैदा करनेके लिए रूस और चीनमें

जो तरीके अख्तियार किये गये उसकी चर्चा नहीं की जाती । रूसको तो जाने दीजिये । वहाँ तो मजदूर-किसान राज चल रहा है मगर चीनमें १९३७ में जो प्रयत्न किसानोंको सन्तुष्ट करनेके लिए किये गये उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये । यह उसका नतीजा है कि आज चीनी जनता प्राणपणसे अपने देशके लिए लड़ रही है और बिना अच्छी तैयारीके आज पाँच वर्ष हुए जापान ऐसे सुसज्जित शत्रुका सामना कर रही है ।

जापानके हमलेके पहले चीनके किसानोंकी बड़ी बुरी अवस्था थी । हिन्दुस्तानके किसानोंकी ही तरह वे जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारोंकी गैरवाजिव वमूलियावियों तथा ज्यादातियोंसे परेशान थे । सन् १९२६ से लेकर सन् १९३७ तक बराबर किसानोंकी ओरसे माँगें पेश की गयीं और कुओमिंटान्ग (चीनकी राष्ट्रीय पार्टी) ने उनके लिए नये कार्यक्रम बनाये जिनमें २५ सैकड़े लगान घटानेका फैसला किया गया था । सन् १९३७ में उसने किसानोंको जमीनमें मिलिकयत दिलाने और अधिकसे अधिक लगानकी दर तय करनेका प्रस्ताव स्वीकार किया । मगर जमींदारोंकी ताकतके मुकाबले यह पूरा कार्यक्रम काममें नहीं आ सका । फिर भी जो सुधार कर दिये गये उनसे किसानोंको थोड़ा सन्तोष हुआ और वे अपनी सरकारके लिए हिम्मतसे लड़ रहे हैं । यह तो भीतरी चीनकी बात है । मगर जो सूबे जापानके कब्जेमें चले गये हिस्सोंके पास हैं वहाँ तो लगानमें २५ सैकड़े कमी करके, सूद ज्यादासे ज्यादा १० सैकड़े तय करके जमींदारों और महाजनोंसे किसानोंकी रक्षा की गयी । जो जमीने दो सालसे बेकार पड़ी थी उन्हें सहयोग कृषिके तरीकेसे काममें लानेके लिए किसानोंको दे दिया गया । ऐसी जमीनमें, खेती करनेके बाद, किसानोंको मिलिकयत हासिल हो जाती है । इन सूबोंकी हुकूमतोंने खेतीके सामान सिचाई वगैरहका इन्तजाम भी किसानोंके लिए कर दिया है । जमींदारशाहीकी मनमानी खतम करनेकी पूरी कोशिश हुकूमतकी ओरसे की गयी है, जिसका नतीजा यह हुआ कि सन् १९३८ में खेतीसे पैदावार ७० सैकड़े बढ़ गयी । दूसरी फसल और भी ज्यादा हुई । जो बात वर्षोंसे नहीं हो पाती थी वह लड़ाईके कारण तेजीसे ही गयी ।

इसीका नतीजा यह है कि आज चीनकी जनता इस हिम्मत और दिलेरीके साथ अपनी आजादीके दुश्मनोंका मुकाबला कर रही हैं । यही तरीका आजादी हासिल करने तथा उसे कायम रखनेका है । कमसे कम लड़ाईके जमानेमें तो देशकी जनताके खिलाफ की जानेवाली काररवाइयाँ बन्द होनी चाहिये । इसे बन्द करवाना तो लड़ाई चलानेवालोंके लिए भी जरूरी है । इससे बढ़कर युद्धविरोधी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती । युद्धसम्बन्धी जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं और होगी उन्हें हल करनेके लिए भी जनताको परेशान करनेवाली चीजे बन्द होनी चाहिये । विशेषकर खाद्य-सामग्री उत्पन्न करनेका काम तो इसके बिना जोर नहीं पकड़ सकता ।

स्वतन्त्रता तथा समाजवादसे ही उद्धार होगा

हमारी आजकी जितनी भी दूसरी समस्याएँ हैं, जैसे कि आन्तरिक शान्तिका प्रश्न आदि, इनका हल भी इसीपर निर्भर है कि हमारे देशकी जनताका हौसला बढे, वे इस

देशको अपना देश समझे और देशकी रक्षा के लिए पूरी शक्ति और दृढताके साथ प्रयत्न करे। यह हम स्वतन्त्रता तथा समाजवादकी बुनियादपर ही कर सकते हैं। स्वतन्त्रता तथा समाजवाद हमारे लिए दूरकी वस्तु न होकर तात्कालिक कार्यक्रमके रूपमें आ रहे हैं। इन्हीं आदर्शोंको सदा अपने समक्ष रखकर हम आजकी अवस्थामें अपना कर्तव्य निर्धारित कर सकते हैं।

आजकी अवस्थामें कांग्रेसने आत्मनिर्भरता तथा आत्मरक्षाका कार्यक्रम देशके सामने रखा है और अपनी स्वयंसेवक सेना भी वह फिरसे तैयार कर रही है। कांग्रेसने यह भी तय किया है कि वह देशपर होनेवाले सभी प्रकारके आक्रमणोंका सामना अहिंसात्मक असहयोगके सहारे करेगी। इस अस्त्रका प्रयोग वह ब्रिटिश हुकूमतके खिलाफ अभी नहीं करना चाहती। कारण यह है कि इससे तत्काल जापानियोंका हौसला बढ़ेगा और हिन्दुस्तानपर आक्रमण करनेका ख्याल उनके दिलोंमें जोर पकड़ सकता है। सत्सार्की स्वतन्त्रता और शान्तिके ख्यालसे कांग्रेस अभीतक ब्रिटिश हुकूमतसे झगड़ा बचाती रही है। कांग्रेसने इस मामलेमें बहुत धैर्यसे काम लिया है। मगर इस धैर्यका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। लोग अब भी यह नहीं समझ पाये हैं कि आजका हिन्दुस्तान साम्राज्यवादी व्यवस्था वर्दाशित करनेको अब विलकुल तैयार नहीं है। इसके रहते-रहते तो हमारे किसी मसलेका हल नहीं निकल सकता, बहुत कुछ अड़चन ही पैदा हो जाती है। युद्ध-सम्बन्धी समस्याएँ भी और जटिल रूप धारण कर लेती हैं; उन्हें सुलझाना मुश्किल हो जाता है।

अपनी तात्कालिक समस्याओंको सुलझानेके लिए हमें अपने पैरोंपर खड़ा होना चाहिये। इसका तरीका कांग्रेसने बताया है। हमें उत्साह तथा दृढताके साथ कांग्रेससे मिलकर काम करना चाहिये। देशमें ऐसा सगठन तथा शक्ति उत्पन्न करनी चाहिये जिससे कि भविष्यकी विपत्तियोंका हम सफलतासे सामना कर सकें। इसमें कांग्रेस सभीके सहयोगकी आशा रखती है और उसे यह सहयोग मिलना चाहिये। आज हमें पूरी एकतासे काम करना है। कम्युनिस्ट ही नहीं, श्री राजगोपालाचारीकी तरह वयोवृद्ध नेता भी, बुद्धिभेद तथा फूट पैदा करनेमें लगे हुए हैं। इसका प्रतिकार करना है और राष्ट्रीय शक्तिकी सृष्टि तथा रक्षा करनी है।

समाजवादी क्रान्तिकी रूपरेखा

हमको यह समझ लेना चाहिये कि अब समय आ गया है कि हम प्रचारके स्तरसे ऊपर उठें। इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेसमें मजदूर और विद्यार्थियोंमें काम करनेका महत्त्व हमारे कारण हुआ है। यह भी निर्विवाद है कि किसानोंमें आर्थिक आधारपर काम करनेकी प्रवृत्ति कांग्रेसमें हमारे कारण हुई है। यदि हम कहें कि हमारी पार्टीकी नीति और कार्यक्रमका यह फल है कि अगस्त सन् ४२ में कांग्रेसने किसान-मजदूर राज्यकी

स्थापनाको अपना लक्ष्य बनाया तो अत्युक्ति न होगी। किन्तु इन सब क्षेत्रोंमें हमारा काम प्रचारात्मक रहा है, पर अब इस प्रकारके कार्यका उतना महत्त्व नहीं रह गया है। अग्रस्त-क्रान्तिके फलस्वरूप राष्ट्रीय और क्रान्तिकारी भावना देशके विविध वर्गोंमें व्याप्त हो गयी है। भारतकी स्वतन्त्रताका लक्ष्य सबने स्वीकार कर लिया है। आन्दोलनका विस्तार तो हो गया है, किन्तु अब उसमें गम्भीरता लानेकी आवश्यकता है। यह कार्य व्याख्यानो द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए क्रान्तिकारी ढंगका रचनात्मक कार्य करनेकी आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि विना संघर्षके भारतको पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती, उसी प्रकार यह समझना भी जरूरी है कि पुराने ढंगकी तैयारी हमको स्वतन्त्रता नहीं दिला सकती। गत अग्रस्त-क्रान्तिका इतिहास मनन करनेसे हमको अपनी दुर्बलता और त्रुटियाँ मालूम हो जायँगी। हमको मालूम हो जायगा कि सफलताके लिए तैयारी और संगठनकी आवश्यकता है तथा क्रान्ति स्वतः सफल नहीं हुआ करती। यह ठीक है कि बहुजन समाजका क्रान्तिमें सम्मिलित होना क्रान्तिको बल देता है तथा इसी प्रकार क्रान्ति लोकतन्त्रके मार्गसे विचलित नहीं होती। किन्तु यह भी निर्विवाद है कि क्रान्तिका संगठन सुदृढ़ होनेसे ही तथा क्रान्तिके संचालकोकी दृष्टि स्पष्ट तथा रचनात्मक होनेसे ही क्रान्ति सफल होती है तथा उसकी आधारशिला मजबूत होती है। आजकी अवस्थामें इस तैयारीमें प्रचारका बहुत निम्न स्थान है। आवश्यकता है क्रान्तिकारी मनोवृत्तिसे रचनात्मक और संगठनात्मक काम करनेकी। अतः प्रत्येक क्षेत्रमें कामके ढंगको बदलना आवश्यक है। बड़ी-बड़ी सभाएँ करना तथा राष्ट्रीय पर्व मनाना ही अबतक हमारा काम रहा है। संस्थाओंके पदोंके लिए होड़ भी होता रहा है। किन्तु अब आवश्यकता इस बातकी है कि हम जगह-जगह गाँवोंके समूहोंको क्रान्तिका केन्द्र बनावे जहाँके लोग इस प्रकार संगठित हो कि विदेशी शक्तिको हटाकर अपनी शक्तिको जमा सके और ग्रामकी संस्थाओं द्वारा राज-काज चला सके। मिदनापुर और सताराके उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ क्षेत्रोंको चुनकर उनमें इस प्रकार काम करें, जिसमें वहाँके रहनेवाले नवीन शिक्षा ग्रहण कर लोकतन्त्रात्मक ढंगसे अपने संगठनको चलावे तथा जीवनके कई विभागोंमें यथा-सम्भव आत्मनिर्भर हो। इन क्षेत्रोंमें प्रौढ़-शिक्षा और सहयोग (Cooperation) को उत्तेजन दिया जाय; ग्राम पंचायतद्वारा सब झगड़े तय किये जाय, किसान युवकोंके स्वयंसेवकोंके स्वयंसेवक दलका संगठन कर आत्मरक्षाका विधान किया जाय; जमींदार, महाजन तथा पुलिसके अत्याचारोंका विरोध करनेकी क्षमता पैदा की जाय, जनताकी राजनीतिक चेतनाकी सतहको ऊँचा किया जाय तथा अन्य सब आनुपगिक कार्य किये जायँ जिनसे हमारे उद्देश्यकी पूर्ति हो। यदि केन्द्रमें क्रान्तिकी भावना न हो, तो यह सब कार्य निर्जीव हो जायँगे। इसी प्रकार मजदूरोंमें शुद्ध मजदूर आन्दोलनकी सतहसे ऊपर उठकर हमें मजदूरोंको समय आने पर आम हड़तालके लिए तैयार करना चाहिये। यह ठीक है कि इसका भी आधार एक सुदृढ़ मजदूर-आन्दोलन ही होगा, किन्तु हमारा कार्य केवल इस आधारको विस्तृत तथा गम्भीर करनेतक सीमित न होगा। यह तो सुधार-

वादियोंका काम है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस कार्यको हेय समझते हैं। हम इसके महत्त्वको स्वीकार करते हैं। यह भी ठीक है कि क्रान्ति नित्य नहीं हुआ करती है तथा सुधारवादी समझा जानेवाला काम ही क्रान्तिका आधार बनता है। किन्तु अब हम एक ऐसे युगमें रह रहे हैं, जब पुरानी रूढ़ियाँ टूट रही हैं, जब वर्तमान समाजके आधारमें ही आमूल परिवर्तन करनेकी आवश्यकता है, जब राजनीतिक तथा सामाजिक क्रान्तिके बिना मानव-समाजका कल्याण नहीं हो सकता है, तब सुधारवादको अपना एकमात्र उद्देश्य बनाना हमारी भूल होगी। आज सुधारके कार्य क्रान्तिके सहायक होकर ही समाजके उपकारक हो सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियोंको कार्यकुशल बनाना, उनमें विविध क्षेत्रोंमें लोकनायक होनेकी क्षमता उत्पन्न करना तथा वर्तमान समस्याओंको समझने और समाधान करनेकी योग्यता उत्पन्न करना हमारा प्रधान कार्य होना चाहिये। इसी प्रकार यदि कांग्रेसको क्रान्तिका उपकरण बनना है तो उसको भी अपनी परिपाटी बदलनी होगी। वास्तविकता यह है कि उसके कामका ढंग पुराना पड़ गया है और उससे नये युगकी आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होती। सच तो यह है कि इन सब वर्ग-संस्थाओंपर कांग्रेसका साया पड़ा है और जबतक कांग्रेस नहीं बदलती, इनके बदलनेमें भी कठिनाई है। किन्तु वे लोग जो संग्रामकी अनिवार्यताके कायल हैं उनका उत्तरदायित्व इस दिशामें औरोसे कहीं अधिक है। उनको नया मार्ग दिखाना चाहिये और जो लोग आज उनके कार्यक्रमको सन्देह और अविश्वासकी दृष्टिसे देखते हैं, उनके सामने कार्यसे, न कि केवल वातासे अपने कार्यक्रमकी उत्कृष्टता प्रमाणित करनी चाहिये। अतः समाजवादियोंका कर्तव्य है कि वह नये कदमको उठावे। जबतक हम अपने दिल और दिमागको न बदलेगे, तबतक कार्य-सिद्धि नहीं होगी। सफलताकी यही कुञ्जी है। इसके बिना जो भी कार्य किया जायगा, वह क्रान्तिको निकट लानमें सहायक न होगा।

एक कारण है जिससे इस नये ढंगका अस्तित्व करना जरूरी है। आज हम देखते हैं कि देशमें नयी-नयी अनेक पार्टियाँ बन रही हैं। आजके युगमें जब समाजके मौलिक आधारके विषयमें ही तीव्र मतभेद है और सर्व साधारणका यह विश्वास हो रहा है कि आजादी बहुत निकट आ गयी है, पार्टियोंकी सङ्ख्यामें वृद्धि होना स्वाभाविक है। यह युग समुदायका है, न कि व्यक्तिका। जब आर्थिक क्षेत्रमें समूहकी प्रधानता हो रही है तथा सामुदायिक अर्थ-नीतिका महत्त्व रोज बढ़ता जाता है; तब यह तत्त्व समाजके सब अंगोंमें व्याप्त होता जाता है। व्यक्ति आज समूहसे अतिरिक्त अपना पृथक् महत्त्व नहीं रखता। समूहके उद्देश्यको चरितार्थ करके ही वह कृतकृत्य होता है। वह मशीनके एक पुर्जेके समान हो रहा है। पुनः राज्यशक्ति सन्निकट है, इस विश्वासके कारण विविध समुदायोंका उदय होता है जो अपने-अपने लिए उस शक्तिको प्राप्त करना चाहते हैं। इनमेंसे बहुतेरे युग-धर्मका प्रतिनिधि बननेका दावा करते हैं और उनकी वाणी भी युगके अनुकूल होती है। यह युग समाजवादका युग है, अतः इनमेंसे बहुतोंको अपनेको समाज-वादका समर्थक बनाना पड़ता है। अब इनमें यदि विवेक करना है तो वाणी मात्रसे विवेक न होगा। इनकी समस्त चेष्टा, इनका कार्यकलाप देखकर ही इनमें विवेक किया जा

सकता है। वाणीका अनुसरण करनेवाला कार्य ही विशेष हो सकता है। अन्यथा जनतामें संस्थाओंकी बहुलताके कारण वृद्धि-विभ्रम होनेका डर है।

अग्रस्त-क्रान्तिके वादसे कही-कही यह भी आवाज सुन पड़ती है कि विचार-धाराकी सर्वथा उपेक्षा कर हमको उन सब शक्तियोंको एकत्र करना चाहिये जो साम्राज्यवादका ध्वंस करना चाहती हैं। आज जब समाजवाद सर्वत्र सफल या अग्रसर हो रहा है तब उसकी सर्वथा उपेक्षा कर केवल राजनीतिक क्रान्तिकी बात सोचना युगके साथ विश्वासघात करना है। आज यह कहना कि यह मंजिल मध्यम वर्गीय क्रान्तिकी है, बड़ी भारी भूल होगी। आज एक ही क्रान्तिद्वारा हम छलांग मारकर किसान मजदूरोंका राज्य कायम कर सकते हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे सामने राजनीतिक क्रान्तिके साथ-साथ सामाजिक क्रान्तिका भी ध्येय हो। अधिकसे अधिक क्या सम्भव है और किन साधनोंद्वारा सम्भव है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। अन्यथा विदेशी सत्ताके हटनेपर वह विविध शक्तियाँ परस्पर ही लड़ जायँगी, जिन्होंने मिलकर यह कार्य सिद्ध किया है। भविष्यके सम्बन्धमें इनमें कुछ समझौता होना आवश्यक है। यह भी हो सकता है कि दृष्टिके स्पष्ट न होनेके कारण हम सम्भाव्यसे कमपर ही सन्तोष कर लें।

किन्तु इस कथनसे यह नहीं समझना चाहिये कि हम सिद्धान्तोंकी वहसमें पड़कर शक्तिको खर्च करना चाहते हैं और एक जीवित आन्दोलनको साम्प्रदायिक सकीर्णतासे पंगु बना देना चाहते हैं। हम उन लोगोमें भी नहीं हैं जो अपनेको एकमात्र क्रान्तिका ठेकेदार समझते हैं। हमारे मतमें सच्चा मार्क्सवाद कोई अटल सिद्धान्त (Dogma) नहीं है। जीवनकी गतिके साथ-साथ यह भी बदलता है। इसकी विशेषता इसका क्रान्तिकारी होना है। मार्क्सकी शिक्षामें समयके अनुसार हेरफेर करना तबतक Revisionism नहीं है जब तक आप इस परिवर्तनसे उसके क्रान्तिकारी तत्त्वोंको सुरक्षित रखते हैं। बर्नस्टीन (Bernstein) और काट्स्की (Kautsky) Revisionist इसलिए थे कि उन्होंने मार्क्सवादके हीरको ही, उसके तत्त्वविशेषको ही निकालकर फेंक दिया था। क्या लेनिनने मार्क्सवादकी मूल शिक्षामें परिवर्तन नहीं किया? क्या आज जो कुछ कम्युनिस्ट पार्टियाँ कर रही हैं, वह मार्क्सवादको बहुतकुछ अंशमें बदलना नहीं है? आज उनका सर्वत्र जोर केवल लोकतन्त्रपर है। आज क्या वह अन्य दलोंके साथ, चाहे वह समाजवादीसे अन्य भी क्यों न हों, सम्मिलित गवर्नमेंट नहीं बना रही है? यदि है, तो कम्युनिस्टोंकी इनमें से कुछ बातोंको हम समयकी आवश्यकता समझते हैं। किन्तु कम्युनिस्टोंका हमारे प्राचीन भाष्यकारोंकी तरह प्रायः यह है कि वह सूत्रों को ठीक मानते हुए उनका अर्थ ही बदल देते हैं। विवादके समय वह मार्क्सके सब सिद्धान्तोंको यथार्थ सिद्ध करनेका प्रयत्न करेंगे, किन्तु उनका आचरण इनमेंसे कुछके कभी-कभी विरुद्ध भी होगा और तब भी वह यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वह किसी पुराने सिद्धान्तको तोड़ रहे हैं। धार्मिकोंकी प्रवृत्ति ठीक इसी तरहकी होती है। मूलको गलत कहने से उनके धर्मके शाश्वतत्वको हानि पहुँचती है। किन्तु काल मूलमें परिवर्तन चाहता है और इसलिए इनको मूलको बिना बदले उसका नया

अर्थ करना पड़ता है। जीवनमें गति और क्रिया होती है। अतः मार्क्सवाद भी गतिशील और क्रियाशील है और इसलिए उसमें लोच है। किन्तु जब वह स्थिर वस्तु हो जाता है, तब उसका क्रान्तिकारी तत्त्व नष्ट हो जाता है और वह एक प्रकारका राजनीतिक व्याकरण हो जाता है जिसके कठोर नियमोंमें किसी प्रकारका हेरफेर नहीं हो सकता। मार्क्सवादको एक जिन्दा शास्त्र माननेमें ही उसका गौरव है। एक तो यो ही पुराने विचार निरर्थक हो जानेके पीछे भी बहुत दिनोंतक जीवित रहते हैं और जीवनको प्रभावित करते रहते हैं और इसी कारण आर्थिक पद्धतिके बहुत कुछ बदल जानेपर भी पुरानी विचारशैलीके बदलनेमें बहुत समय लगता है और जब हम कुछ सिद्धान्तोंको अटल मान लेंगे तब तो हमारा कार्य और भी कठिन हो जायगा।

मार्क्सवाद और उसके तरीकोंके सम्बन्धमें यह कहना एक गलतफहमी है कि यह लोकतन्त्रात्मक नहीं है। यह एक मिथ्या धारणा है। सोवियत रूसकी शासन-प्रणालीके लोकतन्त्रात्मक न होनेके कारण यह धारणा पुष्ट हो गयी है। पुनः राजनीतिक लोकतन्त्रके अपूर्ण होनेके कारण तथा पूँजीवादके युग में उसकी प्रतिष्ठा होनेके कारण हम उसको 'Capitalist democracy' कहकर उसका बार-बार उपहास करते रहे हैं। इन्हीं कारणोंसे लोकतन्त्र एक मखौलकी वस्तु बन गया था। १९ वीं सदीका लोकतन्त्र अपूर्ण अवश्य था और अपूर्ण होते हुए भी वह पूर्णताका दावा करता था। इस कारण उसकी कमजोरियोंको दिखाना और भी आवश्यक था। २० वीं सदीमें लोकतन्त्रकी व्याख्या और विस्तृत होती गयी है और नागरिक स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक लोकतन्त्रके साथ-साथ आर्थिक जनतन्त्र भी इसका आवश्यक अङ्ग माना गया है, किन्तु 'Capitalist democracy' का मखौल उड़ानेसे तथा सोवियत रूसमें राजनीतिक लोकतन्त्रके अभाव से लोकतन्त्रके इस अंगको क्षति पहुँची है। इसका बुरा परिणाम यह हुआ है कि बहुतसे ऐसे लोग जो पहले कम्युनिस्ट थे, इस कमीके कारण आर्थिक लोकतन्त्रकी भी उपेक्षा करनेको तैयार हैं। उनके मतमें प्रधान वस्तु व्यक्तिकी स्वतन्त्रता है। इस प्रकार लोकतन्त्रका क्षेत्र दोनों ओरसे सकुचित हो गया है। हमको एक पूर्ण वस्तु चाहिये। दोनों प्रकारके लोकतन्त्रसे ही व्यक्तित्वकी कृतकृत्यता हो सकती है, किन्तु पार्थक्यके कारण समाजमें दलगत प्रभुत्व (Totalitarianism) की वृद्धि हुई है और मार्क्सवादको क्षति पहुँची है। फैंसिज्मके जन्ममें भी Capitalist democracy का विरोध और उसका उपहास सहायक रहा है। उसको अपूर्ण बताना आवश्यक था; किन्तु पूँजीवादके साथ-साथ उस अधरी चीजका मजाक उड़ाना ठीक न था। इस बातमें कम्युनिज्म और फासिज्मकी समानता होनेके कारण कुछ लोगोंने दोनोंको एक ही कोटिमें रखा है। इंग्लैण्डके एक अर्थशास्त्री तो इस कारण समाजवादको ही गुलामीकी ओर ले जानेवाला समझते हैं। उनके मतमें आर्थिक क्षेत्रमें स्वतन्त्रता रहने से ही अन्य प्रकारकी स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकती है। वह लोकतन्त्रकी दुहाई देकर पूँजीवादको ही जिन्दा रखना चाहते हैं। पुनः कई फासिस्ट राज्योंके कायम हो जानेसे नागरिक स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक लोकतन्त्रका प्रश्न एक महत्वका प्रश्न हो गया। इस प्रश्नने

अन्य प्रश्नोको थोड़े समयके लिए अभिभूत कर लिया तब कम्युनिस्टोकी भी ग्राँखें खुली और उन्होंने फासिज्मका सफल विरोध करनेके लिए राजनीतिक लोकतन्त्रकी रक्षाके नाम पर जगह-जगह संयुक्त मोर्चा बनाया । यही कारण है कि युद्धकालमें यूरोपके कम्युनिस्टोके प्रोग्राम राजनीतिक लोकतन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रतापर ही जोर देते थे और उनमें समाजवादको स्थान न था तथा आज भी उनका सबसे अधिक जोर लोकतन्त्रपर ही है । किन्तु खेदकी बात है कि सोवियत रूसमें इस ओर कार्य नहीं हुआ है । यदि वहाँ राजनीतिक लोकतन्त्रकी स्थापना हो जाती तो स्थितिमें महान् परिवर्तन हो जाता । फासिस्ट शक्तियोंका विनाश इसी नारेके आधारपर हुआ है । यदि बहुजन इसी आधारपर फासिज्मका विरोध करनेके लिए संगठित हो सकता तो इस आधार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है ।

पुनः मार्क्सने लोकतन्त्रका तथा प्रत्येकके व्यक्तित्वके पूर्ण विकासका कई जगह उल्लेख किया है और यह भी बताया है कि समाजवादकी स्थापनासे ही यह उद्देश्य पूरा हो सकता है । आज मार्क्सकी इस शिक्षापर विशेष जोर देनेकी जरूरत है । अतः सहज रूपसे यह प्रश्न हमारी विचार-कोटिमें आ जाता है कि यह कार्य कैसे पूरा हो सकता है । इस सम्बन्धमें विचारधाराके नामका प्रश्न आ जाता है । नामका भी अपना महत्त्व है । मार्क्स और एंगल्सने जब 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' लिखा था तब पुस्तकके नामका प्रश्न उनके सामने था । मैनिफेस्टोकी भूमिकामें इस प्रश्नका विवेचन किया गया है और क्योंकि उस समय काल्पनिक समाजवाद (Utopian socialism) का बड़ा प्रभाव था, इसलिए 'सोशलिस्ट' नाम रखना उचित न समझा गया । इसी कारण संस्थाका नाम भी कम्युनिस्ट लोग रखा गया । किन्तु सन् १८६५ के लगभग हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट नामका परित्याग किया जाता है । सन् १८६३ में लसाल (Lasalle) ने जर्मनीमें एक सोशलिस्ट लेबर पार्टी स्थापित की थी और सन् १८६६ में बाबेल (Babel) और लिबकनेख्त (Liebknecht) ने एक दूसरी पार्टीकी स्थापना की थी, जिसका नाम 'सोशल डेमोक्रेटिकपार्टी' रखा गया । सन् १८७५ में दोनों एकमें मिला दी गयी । इन पार्टियोंके प्रतिष्ठापक मार्क्सवादी थे और इस समयसे मार्क्सिस्ट पार्टियोंका नाम सर्वत्र यही रखा जाने लगा । नाममें यह परिवर्तन क्यों हुआ, यह विचारणीय है । काल्पनिक समाजवादका महत्त्व नष्ट हो चुका था, इसलिए सोशलिस्ट नामका प्रयोग करनेमें अब कोई खतरा नहीं था । उस समय समाजमें डेमोक्रेट राजनीतिक क्षेत्रमें सबसे उग्र समझे जाते थे और वह लोकप्रिय भी थे । अतः समाजवादियोंको बताना था कि उनकी भी राजनीति उग्र है । इसलिए उन्होंने इस नामको अपनाया, किन्तु अपनी विशेषताको भी नामसे व्यक्त करना था, इस कारण सोशल डेमोक्रेट नाम रखा गया । अर्थात् वह डेमोक्रेट जो सामाजिक प्रश्नोंमें दिलचस्पी लेते हैं, जिनके उद्देश्यमें राजनीति और समाजनीति दोनोंका समावेश है । रूसकी पार्टीका भी यही नाम था, किन्तु जब प्रथम महायुद्धमें रूसको छोड़कर अन्य देशोंकी पार्टियोंने वास्ले कान्फरेंस (सन् १९१२) के निश्चयके विरुद्ध अपने-अपने देशके पूँजीपतियोंका युद्धमें साथ दिया, तब लेनिनने कम्युनिस्ट नामको

फिरसे जिन्दा किया। लेनिनके उद्योगसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनलकी स्थापना हुई और रूसकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कहलाने लगी।

इस इतिहाससे हमको यह मालूम होता है कि कम्युनिज्म शब्दका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। नाम रखते समय हमको यह विचार करना है कि जो नाम हम स्वीकार करे, वह समयकी माँगको ध्यानमें रखे और वह ऐसा न हो जिससे किसी प्रकारका भ्रम उत्पन्न हो। यदि कोई नाम बदनाम हो चुका है तो उसका परित्याग करना ही उचित है। जिस समय हमारी पार्टीका जन्म हुआ था, उस समय भारतके कम्युनिस्ट कांग्रेसके विरोधी थे और इसलिए सन् १९३० के सत्याग्रह आन्दोलनमें उन्होंने मजदूरोंको उसमें शरीक होनेसे रोका था। अतः हमें अपनेको उनसे पृथक् करना आवश्यक था। हम इसके भी विरुद्ध थे कि हमारी पार्टी किसी बाहरी सस्थाके अधीन हो। हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्थामें शरीक होनेके विरुद्ध कभी भी न थे और आज भी नहीं हैं, किन्तु हम इसके लिए तैयार नहीं कि कोई बाहरी सस्था हमारा नियन्त्रण करे, विशेषकर जब उस सस्थामें एक ही देशका प्राधान्य हो।

इसलिए हमारी पार्टीका नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। सोशल डेमोक्रेट बदनाम हो चुके थे, इसलिए इस नामको हम अपना नहीं सकते थे। पुनः 'डेमोक्रेट' शब्दके प्रयोगकी अब कोई आवश्यकता भी नहीं थी; क्योंकि डेमोक्रेट शब्द अब उग्र राजनीतिका सूचक नहीं रह गया था। हमारे देशमें इसका कोई महत्त्व भी न था। हमारे विरोधियोंने हमको सोशल फासिस्ट (Social fascist) आदि नामोंसे पुकारा, किन्तु वही सन् ४२ की परीक्षामें खरे नहीं उतरे। उनकी नीति Revisionism कहलायेगी, क्योंकि उन्होंने, जहाँतक हमारे देशका सम्बन्ध है, लेनिनके साम्राज्यवाद विरोधी युद्धके नारेको जन-युद्धके नारेमें परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार मार्क्सवादके क्रान्तिकारी तत्त्वका परित्याग किया। सन् ४२ के आचरणके कारण कम्युनिस्ट नाम हमारे यहाँ और भी बदनाम हो गया है।

आज हमारे लिए नामका सवाल फिर उठ गया है। कहा जाता है कि 'कांग्रेस' शब्द निकाल देना चाहिये, क्योंकि इसके जोड़नेसे हमलोगोंमें एक प्रकारसे यह भ्रम फैलता है कि कांग्रेसने हमको स्वीकार कर लिया है। मैं नहीं समझता कि ऐसा भ्रम किसीको हुआ है; किन्तु यदि ऐसी आपत्ति की जाती है तो मुझको ऐसा करनेमें कोई एतराज नहीं है।

इससे भी अधिक महत्त्वका प्रश्न यह है कि आज अपने उद्देश्यको स्पष्ट करनेके लिए समाजवादमें कोई विशेषण लगाना चाहिये या नहीं। मैं समझता हूँ कि ऊपर हम जिस प्रश्नका विवेचन कर चुके हैं, उससे 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद' इस शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता स्पष्ट हो चुकी होगी। 'Social democracy' न कह कर 'Democratic socialism' कहना चाहिये। इससे मार्क्सका अभिप्राय ठीक-ठीक व्यक्त होता है तथा Democracy को छोड़कर सच्चे समाजवादकी स्थापना नहीं हो सकती है, यह बात भी जाहिर हो जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकता पड़नेपर मजदूर जमातका अधिनायकत्व थोड़े समयके लिए न स्थापित किया जाय। इसकी सदा

आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस समय मार्क्सने इसकी चर्चा की थी, उस समय स्थिति सर्वथा भिन्न थी। आज भी सर्वत्र एक ही स्थिति नहीं है। यदि प्रजातान्त्रिक क्रान्ति किमान-मजदूरके नेतृत्वमें हुई तो बहुत सम्भव है कि अधिनायकत्वकी स्थापनाका प्रश्न न उठे।

हममें मजदूर वर्गका अधिनायकत्व न होकर कम्युनिस्ट पार्टीका अधिनायकत्व है तथा वह धीरे-धीरे स्थायी होता जाता है। यदि हममें वर्गविहीन समाजकी स्थापना हो चुकी है जैसा कि कहा जाता है तब अधिनायकत्वकी क्या आवश्यकता रह गयी है? अनुभव बताता है कि प्रभुताके मदसे उत्तम व्यक्ति और सस्याएँ अपने अधिकारको स्थिर बनानेका प्रयत्न करती हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता आ पड़े तो इस अधिकारको जितने कम समयके लिए चला जाय, उतना ही अच्छा है और अधिकारको प्रयोग करने-वालोंकी संख्या जितनी बड़ी हो सके, उतना अच्छा है।

श्रेणीसजग किसान और मजदूरोंके नेतृत्वमें की गयी जनतान्त्रिक क्रान्तिको इसकी कदाचित् आवश्यकता न होगी। मैं नहीं समझ पाता कि इस मवालको लेकर इतना वाद-विवाद क्यों है? मार्क्सने स्वयं यह नहीं कहा है कि इस मंजिलसे गुजरना सर्वत्र अनिवार्य है। आज तो इसकी अनिवार्यता और भी कम होती जाती है। यूरोपके कई देशोंमें एक दलकी गवर्नमेण्ट नहीं बन पायी है। वहाँ समाजवाद और कम्युनिज्मका झगड़ा सर्वत्र चल रहा है। दोनोंका एक संगठनमें मिल जाना कठिन है। यदि दो दल एक कार्यक्रमपर एक मत हो जायें तो कई देशोंमें जनतान्त्रिक ढंगसे धीरे-धीरे समाजवादकी स्थापना हो सकती है। दुख इसीका है कि वामपक्षमें कही भी एका नहीं हो पाता। कहना ही पड़ता है कि कम्युनिस्टोंकी नीति इसके लिए जिम्मेदार है।

अतः हम जनतान्त्रिक समाजवादके पक्षपाती हैं। उत्पत्तिके साधनोंको समाजके अधीन करनेसे अधिकारिवर्ग (Bureucracy) का प्रभुत्व बढ़ जाता है। इसकी रोक-थाम करनी होगी। इसके लिए ऐसे नियम काममें लाने होंगे जिनसे जनताका उनपर नियन्त्रण रहे। उद्योग व्यवसायके प्रबन्धमें राज्यके अतिरिक्त मजदूरोंका काफी हाथ होना चाहिये। स्वायत्त-शासनकी संस्थाओंद्वारा भी कुछ व्यवसायोंका संचालन हो सकता है। समाजमें रंग, जाति और वर्णका भेद मिटा देना चाहिये। प्रत्येक व्यक्तिको उन्नतिका पूरा अवसर मिलना चाहिये। समाजवादी राष्ट्रको साम्राज्यवादका विरोधी होना चाहिये; आर्थिक तथा राजनीतिक समानताकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये।

किन्तु जबतक हम जनतान्त्रिक समाजवादकी स्थापना नहीं कर पाते तबतक हमारी क्या नीति हो? पार्टीने विधानपरिपद्धमें जानेका विरोध किया है, इसीलिए कि वह सर्वाधिकार प्राप्त संस्था नहीं है। इस परिपद्धका भविष्य अनिश्चित-सा है। यदि हमने कोई विधान प्रस्तुत किया और वह प्रयोगमें आया तब अपनी नीतिको और स्पष्ट रूपसे निश्चित करनेका समय हमारे लिए आयेगा। किन्तु यह निर्विवाद है कि उस समयसे ही समाजवादी क्रान्तिका युग शुरू होगा जिसे पूंजीवादी जनतान्त्रिक क्रान्तिका वचा हुआ काम भी पूरा करना होगा। उस समय दलोंका नये आधारपर निर्माण होगा। आजकी

अवस्थामें क्रान्तिकारी मनोवृत्तिको जिन्दा रखना, मजदूरोका सुदृढ संगठन बनाना, किसान-मजदूरोका जहाँ सम्भव हो, संयुक्त मोर्चा बनाना तथा किसान-मजदूरोके जमींदार पूंजीपतियोसे जो संघर्ष हो, उनका नेतृत्व करना हमारा काम है। इन सब कार्योंको सुसम्पन्न करनेके लिए पार्टीको एक उपयुक्त साधन बनाना अति आवश्यक है। पार्टीके सदस्योंकी शिक्षा-दीक्षाकी उचित व्यवस्था करना, उनको विभिन्न कार्योंमें नियुक्त करना तथा संगठनको सुदृढ करना हमारा कर्तव्य है।^१

समाजवादी दल^२

कामरेड सभापति महोदय और मित्रो,

आज पार्टीके इस पाँचवे वार्षिक अधिवेशनके अवसरपर आप सबका हार्दिक स्वागत करनेका गौरवास्पद कर्तव्य मुझे मिला है। हम नौ वर्षके बाद एकत्र हो रहे हैं। इस बीच ससारके सभी भागोमें व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इस महायुद्धसे ब्रिटिश साम्राज्य-वादको महान् धक्का लगा है और उपनिवेशोके लोगोमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके आन्दोलन अत्यधिक सवल हो गये हैं। राष्ट्रीय तथा क्रान्तिमूलक चेतना एव भावनाएँ जनतामें बहुत द्रुत गतिसे परिपक्व हो रही हैं। हमारे अपने देशमें ही जनतामें अभूतपूर्व चेतना और क्रियाशीलता दृष्टिगोचर होती है यद्यपि दुर्भाग्यवश प्रतिक्रियावादी नेतृत्वमें ये प्रायः हानिकर एवं अवाञ्छनीय दिशाओमें मुड़ी हुई हैं और इस कारण प्रगतिशील कार्यक्रमके लिए हानिप्रद हुई हैं, किन्तु इन सब बातोंसे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि जनतामें एक चेतना जागृत हुई है जो इसके पहले कभी नहीं हुई थी और यदि प्रतिक्रियावादी नेतृत्वको उसके वर्तमान शक्ति और प्रभावके पदसे च्युत कर दिया जाय तो जनता क्रान्तिमूलक संघर्षकी ओर ले जायी जा सकती है।

ससारके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोका सतुलन तो नष्ट हो ही गया है साथ ही सभी देशोमें विभिन्न वर्गोंके बीचका साम्य भी आलोडित हो गया है। निम्नतर मध्यम-वर्गके बड़े-बड़े भागोका आर्थिक दृष्टिसे विनाश-सा हो गया है और अब अपनी माँगोंके लिए उन्होंने हड़तालके अस्त्रका प्रयोग किया। महायुद्धके कारण यूरोपकी सबसे अधिक क्षति हुई है। इसकी आर्थिक स्थिति छिन्न-भिन्न हो गयी है। विभिन्न दलोका सामाजिक आधार बदल रहा है और प्राचीन दुर्जुआ उदार दल अपने पहलेके प्रभावका बहुत अंश खो चुके हैं। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दलोकी शक्ति बढ़ गयी है और एक नवीन उदारचेतादल (Catholic Party) जो समाजके पिछड़े हुए अंशका प्रतिनिधित्व करता है आविर्भूत हो गया है।

१. 'जनवाणी'—फरवरी १९४७ ई०

२. मार्च १९४७ को कानपुरमें सोशलिस्ट पार्टी कान्फरेन्सके स्वागताध्यक्ष-पदसे दिया गया भाषण।

इन तीनों वर्षों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर और हमारे भारतवर्ष में और उसके बाहर महायुद्ध के फलस्वरूप जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं उन्हें दृष्टि में रखते हुए हमें अपनी नीति फिर से निर्धारित करनी है। पूँजीवाद अपने आन्तरिक विरोधों का निराकरण नहीं कर सकता है और फलतः उसे स्थायी बनाने के सभी प्रयत्नों की विफलता अवश्यम्भावी है। बृहत् चतुष्टय (The Big Four) को शान्तिकी समस्या का समाधान नहीं प्राप्त हो सका है। एक दूसरे विश्वव्यापी संघर्षों की तैयारियाँ प्रारम्भ हो चुकी हैं और राष्ट्रों की नये प्रकार की दलबन्दी हो चुकी है। यद्यपि अभी प्रत्येक देश थका हुआ है, उसे कुछ समय के लिए विश्राम और पुनरुज्जीवन की बड़ी आवश्यकता है और हर जगह लोग रोटियों के लिए और शान्तिके लिए चिल्ला रहे हैं, तथापि राज्यों के सूत्रधार और नेता फिर अपने पुराने जघन्य व्यापार में लग गये हैं।

पूँजीवाद के आन्तरिक विरोध ऐसे हैं कि विभिन्न शक्तियों के पारस्परिक संघर्ष और वैमनस्य स्पष्ट होकर ही रहेंगे चाहे इसमें अपेक्षाकृत जल्दी हो या देर। समाज के आधार बुरी तरह हिल चुके हैं और शासक वर्ग नहीं जानते कि इन परिवर्तित दशाओं में शासन कार्य कैसे चलावे। उससे नवीन दशा के साथ अपना सामञ्जस्य बैठाने की नहीं बनता और उसमें यह क्षमता कि वा दूरदर्शिता है ही नहीं कि वह नयी विपत्तियों पर समाज का निर्माण कर सके। आये दिन स्पष्ट होता जा रहा है कि जब तक सम्पत्ति-सम्बन्धी वर्तमान सम्बन्ध आमूल परिवर्तित नहीं किये जाते तब तक संसार में स्थायी शान्ति नहीं स्थापित हो सकती। नवीन युग का सूत्रपात हो रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवाद के चरितार्थ होने की घड़ी आही गयी है तथापि कुछ दुर्निवार प्रत्यय हमारे मार्ग में अब भी विद्यमान हैं जिनका अतिक्रमण आवश्यक है इसके पहले कि संसार लक्ष्य तक पहुँच सके। जहाँ तक सिद्धान्तों और आदर्शों का सम्बन्ध है हम लोगों को इस विचार से लोहा लेना है कि समाजवाद और गणतन्त्र एक साथ नहीं रह सकते। बहुत से लोग तो यहाँ तक कह गये हैं कि सोशलिज्म दासतामूलक समाज का मार्ग प्रणस्त करता है। एक अंग्रेज अर्थशास्त्री का मत है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐसे ही समाज में अक्षुण्ण रह सकती है जहाँ आर्थिक स्थिति राज्य अधिकार के जाल से मुक्त रहती है। ये महाशय व्यक्तिके स्वतन्त्र प्रयास के समर्थक हैं और चूँकि सोशलिज्म का सिद्धान्त है कि उत्पादन और वितरण व्यवस्थामूलक हो उनका कहना है कि ऐसे कार्यक्रम में आवश्यक स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो सकती। सोवियत रूस में समाजवाद की जो मिट्टी पली दी गयी है और फलतः वहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता का जो अभाव हो गया है इस कारण भी यह विश्वास अभिसिञ्चित हो गया है कि व्यवस्थामूलक सुनिश्चित आर्थिक कार्यक्रम अवश्यमेव दलगत प्रभुत्व (Totalitarianism) और नौकरशाही की स्थिति पैदा कर देगा।

यह दुर्भाग्य की बात है कि रूस की स्थितिको ही सोशलिज्म का नमूना मानकर यह अनुमान किया जाता है कि सोशलिज्म कैसा होगा और इसी अनुमान को आधार मानकर आलोचना की जाती है। जिन लोगों की कम्युनिज्म में आस्था रूस की राजनीतिक और सामाजिक स्थितिके कारण छिन्न-भिन्न हो गयी है और जो अब व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य और

मानवके अधिकारोंको प्रधानता देने लग गये हैं वे प्रायः स्टालिनके दलके षड्यन्त्रोंको इस स्थितिका कारण बताते हैं। साथ-ही-साथ ऐसे भी लोग हैं जो इन विषयोंमें अधिक गम्भीर विचार रखते हैं और जिनका मत है कि व्यवस्थामूलक कार्यक्रम व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यको ह्रास पहुँचावेगा। इन दोनों ही दृष्टिकोणोंमें सत्यांश है, किन्तु यदि गणतन्त्रीय कार्यक्रमका सूत्रपात कर दिया जाय तो इस खतरेसे बचा जा सकता है। व्यवस्थाके मूलमें कोई ऐसी आन्तरिक बात नहीं है जिसके कारण मानवके अधिकारोंके लिए कोई खतरा (भयावह स्थिति) उपस्थित हो जाय। किसी भी राज्यकी आर्थिक स्थितिकी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि इस प्रकारके कार्यक्रममें सन्निहित खतरे न्यूनतम हो जायें। गणतन्त्रीय भावनाओंको राज्यव्यवस्था-प्रवन्धकी सीमाके बाहर भी ले आना, अर्थसम्बन्धी व्यवस्थाका विकेन्द्रीकरण, ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओंकी स्थापना जो खास-खास उद्योग-धन्धे चलवाये और स्वतन्त्र मजदूरवर्गके सघटनोंद्वारा समाजकी आर्थिक व्यवस्थाका नियमन इत्यादि ऐसे उपाय हैं जिनसे खतरा दूर किया जा सकता है।

एक बात और है जिसके कारण कम्युनिज्मकी निन्दा की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टीके आचरण, उसके षड्यन्त्र और द्विविधामूलक व्यापार, उसकी सुस्पष्ट अवसरवादिता और दूसरोंके साथ व्यवहारमें नैतिक मान्यताओंकी नितान्त अवहेलनाओंके कारण सोशलिज्म वदनाम हो गया है। जब कभी कम्युनिस्ट पार्टीने दूसरी राजनीतिक पार्टियोंके साथ कन्धासे कन्धा मिलाया है तो उसने अपने लाभ और सुभीतेके लिए ही ऐसा किया है और जब कभी इसने दूसरी संस्थाओंके साथ सम्बन्ध जोड़नेका प्रयत्न किया है तो उसका उद्देश्य या तो उसे हथिया लेनेका रहा है या उसे छिन्न-भिन्न कर देनेका। उनके सिद्धान्त और चालोंमें जो कौतूहलपूर्ण सतत परिवर्तन हुआ करते हैं उनके साथ चल सकना दुर्लभ बात है। यह सत्य स्वीकार ही करना पड़ेगा कि सोशलिज्मके उद्देश्योंको कम्युनिस्ट दलोंके सिद्धान्तगुण्य व्यापार और उनकी सन्दिग्ध नैतिकताके कारण अत्यन्त हानि पहुँची है। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि इनके व्यवहारका मापदण्ड दूसरे प्रकारका हुआ होता तो वामपक्षीय एकता सम्भव हो गयी होती।

विचारणीय बात है कि यद्यपि वे आज गणतन्त्रका समर्थन करते हैं तथापि यही प्रतीत होता है कि कुछ सामयिक सुविधाएँ प्राप्त करनेकी उनकी यह एक चालमात्र है। वह जो कहते हैं वही उनकी सच्ची भावना नहीं रहती यह तो इसी बातसे सिद्ध हो जाता है कि सोवियत रूसमें जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता देनेके लिए कुछ भी नहीं होता। बल्गेरियाका सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट डिमीट्राफ तो अपनी पार्टीसे छिपाता ही नहीं कि यह सब कुछ इतर उद्देश्योंकी सिद्धिका छद्म उपाय है। उसके शब्द हैं "अभी तो कम्युनिस्ट पार्टीको एक साधारण गणतन्त्रीय दलका ही रूप धारण करना है। ऐसे कम्युनिस्ट जिन्हें इस प्रकारके द्व्यर्थक दृष्टिकोणके कारण कष्ट पहुँचता है या तो मार्क्सवादी ही नहीं है या वे केवल उत्तेजनावादी (Provocateurs) हैं।" भला ऐसे वक्तव्यके समक्ष गैरकम्युनिस्टोंसे कैसे आशा की जा सकती है कि वे उनके साथ मिलकर कोई कार्यक्रम बनावे।

ससारके कम्युनिस्टोको फासिज्म और युद्धके खतरेके विरुद्ध जनतामे स्वतन्त्रता और गणतन्त्रके नामपर मोर्चे बनाने थे । युद्धकालमे कम्युनिस्ट यूरोपमे प्रतिरोधात्मक आन्दोलन चलाते थे उनके सम्बन्धमे अपने कार्यक्रममे कम्युनिज्मका नामतक नही लेते थे । तब वे केवल डिमोक्रेसीका दम भरते थे । असंख्य जनसमूहको स्वतन्त्रता और गणतन्त्रके नामपर फासिज्मके विरुद्ध कार्यरत किया गया और अब जब युद्ध समाप्त हो गया है और फासिस्ट शक्तियोका दम टूट गया है तो युक्तिसंगत यही बात है कि इन उदात्त विचारोकी महान् सम्भावनाओको चरितार्थ किया जाय और यह बात असंशयात्मक रूपसे सुस्पष्ट कर दी जाय कि हम लोग गणतन्त्रात्मक समाजवादके पक्षमे बद्धपरिहर हैं ।

जहाँतक कि कांग्रेसके समाजवादियोंका सम्बन्ध है हमलोग सदैव जनतन्त्र और स्वतन्त्रताके ही लिए आरूढ़ रहे हैं । हमने सदैव एक स्वयंसिद्ध बातके तीरपर यह माना है कि समाजवाद ही पूर्ण जनतन्त्र है और यह कहा है कि समाजवाद एक सिद्धान्त है जो मानव व्यक्तित्वके स्वतन्त्र विकासपर उतना ही जोर देता है जितना आर्थिक स्वतन्त्रता पर । सोवियत रूसने मानव-क्रिया-कलापके विभिन्न क्षेत्रोमे जो सिद्धियाँ प्राप्त की हैं उनके हमलोग सदैव प्रशंसक ही रहे हैं, पर हम उसके मित्त भावसे आलोचक रहे हैं और खेदके साथ यह कहते आये हैं कि उसने राजनीतिक स्वतन्त्रताके प्रश्नकी उपेक्षा की है ।

जो लोग यह समझते हैं कि मार्क्सके विचार (Teachings) जनतन्त्रके विरुद्ध हैं, वह गलती करते हैं । मार्क्स अपने युगका एक महान् मानवतावादी था । विचार प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता (freedom of expression) का अधिकार वह मनुष्यकी सम्पत्तिमे सबसे पवित्र सम्पत्ति मानता था । कितने जोरके साथ उसने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका समर्थन किया था, वह सुविदित है । उसका कम्युनिज्म पूर्ण जनतन्त्रको स्वीकार करके चला था । यही कारण था कि वह यह विश्वास करता था कि जन-तन्त्रवादी इंग्लैण्ड और अमेरिकामे समाजवाद हिंस्र उपायोका उपयोग किये बिना ही स्थापित हो जायगा । उसका विचार था कि मनुष्योपर प्रतियोगिता एव सम्पत्तिके कारण जो नियमन और रोक-थाम चलाते हैं, वही सब अनर्थोका मूल है । एजिल्सने कम्युनिज्मकी यही व्याख्या की कि यह निम्नस्तरकी जनताकी मुक्तिके लिए आवश्यक साधनोका सिद्धान्त है । निश्चय है कि मार्क्स किंवा एजिल्स ऐसे समाजवादका समर्थन कभी न करते जो जनताके लिए कामकी व्यवस्था करनेके साथ ही उसे दासत्वकी शृङ्खलामे बाँधे और उसकी सच्ची स्वतन्त्रताका अपहरण करे ।

मार्क्सके मतानुसार मानवके विकासक्रममे सामन्तशाही और पूंजीवादकी स्थितिमे व्यक्ति मानव रह ही नहीं गया था और निम्न स्तरकी जनतामे क्रान्ति कराकर ही व्यक्तिके लुप्त अस्तित्वका पुनरुद्धार किया जा सकता है । उसका यह विचार था कि निम्नवर्गका व्यक्ति ही मानवताका प्रतिनिधि है और उसकी विजयसे ही मानवताकी भावनाकी विजय होगी । अपनी व्यवस्थामे उसने सामाजिक मानवको केन्द्रस्थानमे रखा था । मार्क्सद्वारा स्थापित कम्युनिस्ट लीगके मुख-पत्र, कम्युनिस्ट जर्नलकी कोलोके कम्युनिस्ट ट्रायलवाली प्रति (सितम्बर १८४७) मे छपी हुई इस बातसे बहुत बातोका पता चल जाता है—

“हमलोग उन कम्युनिस्टोंमें नहीं हैं जो व्यक्तिकी स्वतन्त्रताका नाश करनेके लिए वद्ध परिकर हैं, जो विश्वको एक विशाल वैरक अथवा कारखानेमें परिणत कर देना चाहते हैं। कुछ ऐसे कम्युनिस्ट भी हैं जो नि सकोच व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा करनेमें उनके विवेकको कोई ठंम नहीं लगती। ये लोग चाहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ससारसे बहिष्कृत कर देना चाहिये, क्योंकि इसे वे पूर्ण सामजस्यके लिए व्यवधानस्वरूप समझते हैं। किन्तु हमलोग स्वतन्त्रताके बदले बराबरी नहीं चाहते। हमलोगोंको विश्वास है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्थामें वैसी पूर्व स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी जैसी ऐसे समाजमें जो सामाजिक स्वामित्व (Communal ownership) पर आधारित हो।”

कहा जा सकता है कि जब मार्क्स स्वतन्त्रता और जनतन्त्रका समर्थक था तो उसने निम्नवर्गकी तानाशाही (dictatorship) की चर्चा क्यों की। हमलोगोंको स्मरण रखना चाहिये कि वह इस तानाशाहीकी कल्पना केवल ऐसे देशोंके लिए करता था, जहाँ जनतन्त्रीय व्यवस्थाएँ और परम्पराएँ दृढतासे स्थापित नहीं थी और जहाँ पूँजीपतियोंका दल तुरन्त ही राज्यकी सारी सैनिक शक्तिका प्रयोग अपने प्रतिद्वन्दियोंके विरुद्ध कर सकता है। फिर इस तानाशाहीकी कल्पना केवल अल्पकालके लिए की गयी थी, साथ ही यह मजदूर जनताकी गणतन्त्रीय तानाशाही होती न कि किसी दलविशेषकी।

मार्क्स-दर्शनका आविर्भाव इस अभिप्रायसे नहीं हुआ था कि पूँजीवादके अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता किस प्रकार सुनिश्चित बन गयी है उसका निराकरण कर दिया जाय, बल्कि इस उद्देश्यसे कि जनतन्त्रकी भावना और स्वतन्त्रताको पूर्ण बना दिया जाय और उसे साधारण मानवके लिए प्राप्य बना दिया जाय। मार्क्सने १९ वीं शताब्दीके आर्थिक मानवकी भर्त्सना यह कहकर की कि वह अमानुषिक एव पाशविक हो गया है, क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्थामें पडकर साधारण मानव दासताको प्राप्त हो गया है और ऐसा हो गया है कि उसे जड़ पदार्थोंकी भाँति प्रयोग किया जा सकता है।

जनतन्त्रकी वह भावना, जिसका सम्बन्ध पूँजीवादके उत्थानके साथ जोड़ा जाता है, अपूर्ण थी, क्योंकि वह केवल राजनीतिक क्षेत्रतक ही सीमित थी। किन्तु २० वीं शताब्दीके प्रारम्भसे धीरे-धीरे उसका विस्तार होता रहा है और उसके अन्तर्गत आर्थिक जनतन्त्रवाद भी आ गया है। कम्युनिस्टोंके लिए यह आवश्यक था कि वे जनतन्त्रकी पूँजीवादी भावनाकी कमी और अनुपयुक्तताका दिग्दर्शन कराते; किन्तु उदार परम्पराके लिए अनादरकी भावना रखना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। अपने प्रचारसे उन्होंने जनतन्त्रीय सस्थाओंके मूलको कमजोर बना दिया। इस प्रकार कम्युनिस्टोंने उदार परम्पराके नाशमें सहायता पहुँचायी, इसपर आगे चलकर फासिस्टोंने भी उसी प्रकार प्रहार किया और इस प्रकार फासिज्मके सूत्रपातका मार्ग प्रशस्त कर दिया : इस बड़ी भूलका बहुत बड़ा मूल्य सोशलिज्मको चुकाना पडा। जर्मनीमें फासिज्मकी चमत्कारिक उन्नति और फासिस्ट विचारोंका विश्वव्यापी प्रसार मानवताकी सभी प्रकारकी उन्नतिके लिए एक खतरा हो गया—सोशलिज्मकी तो बात ही क्या !

प्रजातन्त्र और सोशलिज्मके एक प्रश्नपर ही अपने विचार प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता मैंने ली है, क्योंकि इस समयका यह एक मौलिक प्रश्न हो गया है। हमें जनतन्त्र और स्वतन्त्रतामें अपना विश्वास फिरसे घोषित करना है। आज इस घोषणाकी आवश्यकता सबसे अधिक है, क्योंकि यदि विगत महायुद्धने कोई बात प्रमाणित की है तो वह यह है कि साधारण मानव अपने लिए काम और उसे करनेके लिए अनुकूल और अच्छी परिस्थिति सुनिश्चित कर लेनेके बाद निश्चय ही अपने लिए स्वतन्त्रता और जनतन्त्रकी माँग करेगा ताकि वह पूर्ण रूपसे अपना विकास कर सके।

सम्मेलन तो अपनी नीतिके विषयमें एक सुस्पष्ट घोषणा करेगा ही और पार्टियोंका संगठन-सम्बन्धी कार्यक्रम भी निर्धारित करेगा ही।

एक बात और है जिसकी चर्चा अपना वक्तव्य समाप्त करनेके पूर्व मैं कर देना चाहूँगा— इस समय कुछ दलों द्वारा यह पुकार हुई है कि वामपक्षियोंको एक हो जाना चाहिये। उनकी माँग है कि वामपक्षी दलोंको चाहिये कि एकत्र होकर एक संयुक्त मोर्चेका निर्माण करें। इसमें सन्देह नहीं कि यदि सभी क्रान्तिमूलक समाजवादी शक्तियाँ एकीभूत हो जायँ तो वह प्रतिक्रियावादी मोर्चेके विरुद्ध एक अभेद्य शक्ति हो जायगी। किन्तु खेदकी बात है कि सुविदित कारणोंसे, जिनकी ओर ऊपर संक्षेपमें संकेत किया जा चुका है, निकट भविष्यमें ऐसा एकीकरण सम्भव नहीं प्रतीत होता। हम कांग्रेसके सोशलिस्ट अपने तई बहुत हानि उठाकर भी इस देशमें सोशलिस्ट ऐक्य स्थापित करनेका अधिकसे अधिक प्रयत्न कर चुके हैं और अन्तमें हमें पता चला है कि हमलोग केवल मृगतृष्णाके फेरमें पड़े रहे हैं और जो लोग हमारे साथ मिलनेकी उत्सुकता प्रकट कर रहे थे, वे केवल अपनी पार्टीके सुभीतेके लिए वैसा कर रहे थे। आन्दोलनको सवक बनाना उनका उद्देश्य नहीं था। आश्चर्य तो यह है कि भारतवर्षमें ही यह बात नहीं हुई। वामपक्षियोंमें एकताका अभाव एक सर्वव्यापी रोग है। कम्युनिस्टोंकी व्यवहार-व्यवस्थामें कोई महत्त्वपूर्ण कमी है जिसके कारण सोशलिस्टोंमें इतना पारस्परिक अनैक्य है। जबतक इनमें आमूल परिवर्तन नहीं हो पाता, ऐक्यकी कोई आशा नहीं। सभी वामपक्षियोंके लिए और विशेषतः कम्युनिस्टोंके लिए मैं कम्युनिस्ट-लीगके मुख-पत्र (सितम्बर १८४७) में से निम्नांकित अग्र देना चाहता हूँ—

‘यहाँ हमें थोड़े शब्द निम्नवर्गके केवल उनलोगोंसे कहना है जो अन्य राजनीतिक अथवा सामाजिक दलोंमें हैं। हम सबको आजके समाजसे लोहा लेना है, क्योंकि यह हमें दवाता है और दीनता और घृणित दशामें सड़ने देता है। खेद है कि यह समझने और आपसमें ऐक्य स्थापित करनेके बजाय हम आपसमें लड़ने झगड़नेके लिए ही उद्यत रहते हैं, जिससे हमें दबानेवालोंको आनन्द मिलता है। ऐसी जनतन्त्रीय राज्यव्यवस्थाके प्रतिष्ठापनके निमित्त जिसके अन्तर्गत प्रत्येक दल वक्तव्यों एवं लेखोंद्वारा अपने आदर्शोंके लिए बहुमत अपने पक्षमें करनेमें समर्थ हो सके, एक ही व्यक्तिकी भाँति हम सब एक हो जानेके बजाय आपसमें ही इस बातके लिए झगड़ते रहते हैं कि जब हमलोग विजयी हो जायँगे तब क्या होगा और क्या नहीं होगा।

‘यदि हमें ठोस शक्ति प्राप्त करनी है तो विभिन्न दलोंके मुखियोंका भिन्न विचारवालो-पर कटु आक्रमण करना बन्द करना होगा और विरोधी सिद्धान्तोंके माननेवालोंपर गालियोंकी बौछारके व्यापारका अन्त करना होगा ।’

एक बार फिर हम आपलोगोंका इस महत्त्वपूर्ण सभामे योग देनेके निमित्त स्वागत करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी कमियो और वुटियोंपर ध्यान न दे ।

किसानोंका उद्धार कैसे हो ?

जमींदारी प्रथाका अन्त करके जमीनपर उसके जोतनेवालेका अधिकार स्थापित किया जाय, यह हमारे किसान-आन्दोलनकी सबसे प्रमुख माँग रही है । इस माँगको कांग्रेसने सिद्धान्तरूपमे स्वीकार कर लिया है और हमारे प्रान्तमे इस माँगको व्यावहारिक रूप देनेके सम्बन्धमे रूपरेखा तैयार करनेके लिए एक सरकारी कमेटी भी बैठायी गयी है । खेती ही हमारे देशका मुख्य उद्योग-धन्धा है । इसमे देशके लगभग ७३ फी सदी लोग लगे हुए हैं । बिना जमींदारी प्रथाका अन्त हुए इस उद्योग-धन्धेकी तरक्की नहीं हो सकती, किसान जमीनको अपनी समझकर उसकी पैदावार बढ़ानेके लिए हर तरहका त्याग करनेके लिए तैयार नहीं हो सकता, भूमिपर नये साधनोंका प्रयोग करनेकी प्रेरणा उसे नहीं मिल सकती । खेतीकी उन्नतिके लिए जमींदारी प्रथाका अन्त होना और खेती परसे दूसरे उन सभी बीचके लोगोंको हटाना, जो खेती न करते हुए भी उसकी पैदावारके अंशको हड़प जाते हैं, बहुत आवश्यक है ।

जमींदार प्रथाका अन्त करनेकी किसान-आन्दोलनकी माँगको स्वीकार करके भी प्रान्तीय सरकार इस कार्यको पूरा करनेमे बड़ी सुस्तीसे काम ले रही है । महायुद्धकी समाप्ति होनेपर पश्चिमी यूरोपके अनेक देशोंमे जमींदारी प्रथाका अन्त किया गया । किन्तु इन देशोंमे इस कामको एक वर्षमे ही पूरा कर डाला गया । हमारे यहाँ अभी इस बातका निश्चय नहीं हो पाया कि जमींदारोंको मुआवजा कितना दिया जाय ।

मुआवजेका सवाल

जहाँतक समाजवादियोंका सम्बन्ध है, वे सिद्धान्ततः मुआवजा दिये जानेके विरोधी हैं । हमारे देशमे मुआवजा देनेका प्रश्न सिद्धान्तकी दृष्टिसे इसलिए भी नहीं उठता कि जमींदारी प्रथा हमारे देशकी अपनी प्रथा न होकर विदेशी शासनद्वारा अपनी सुविधा और सहायताके लिए खड़ी की गयी प्रथा है । अपने देशमे प्राचीन कालमे ऐसे लोग तो होते थे जो एक खास इलाकेकी मालगुजारी वसूल करके सरकारको दे देते थे और बदलेमे सरकारकी ओरसे उन्हें उसका एक अंश कमीशनके रूपमे मिल जाया करता था, किन्तु वे भूमिके

१. द्वितीय बनारस जिला किसान-सम्मेलनके अध्यक्ष-पदसे १० अप्रैल १९४७ को जो भाषण किया था उसके प्रमुख भागका सारांश है ।

अधिकारी कभी नहीं स्वीकार किये जाते थे । उसका अधिकारी तो किसान अथवा ग्राम पंचायतें ही होती थी । सम्राट् अणोकने जब स्वयं अपनी सीर और खुदकाशतके अतिरिक्त अन्य भूमि भी भिक्षुओंको दानमें दे देनेकी इच्छा प्रकट की तो उन्हें मन्त्रियोंने बताया कि उन्हें ऐसा करनेका अधिकार नहीं है ।

हमारे प्रान्तके अवधके तालुकेदारोंने तो जमींदारी पानेके लिए एक कौड़ी भी खर्च नहीं की । सन् १८५७ के स्वाधीनता-संग्राममें विद्रोही जमींदारोंकी जमीने छीनकर अंग्रेजोंकी मदद करनेवालोंको दे दी गयी । अवधके तालुकेदारोंकी जमीन इसी प्रकार मिली हुई है । अतः न्यायकी दृष्टिसे उन्हें मुआवजा पानेका कोई हक नहीं है । जब कि जमींदारी प्रथाका अन्त करनेके लिए सरकारको कानूनन् मुआवजा देना ही पड़ेगा ऐसी हालतमें यह रकम थोड़ीसे-थोड़ी होनी चाहिये ।

जमींदारोंकी धाँधली

सरकारकी ओरसे जमींदारी प्रथाका अन्त करनेमें जो सुस्ती दिखायी जा रही है उसके कारण किसानोंपर इस समय एक जवर्दस्त आफत आयी हुई है । जमींदार यह सोचते हैं कि जमींदारी तो जानेवाली है इसलिए इस समय उसके जरिये ज्यादासे ज्यादा जो भी वसूल किया जा सके वसूल कर लिया जाय । साथ ही वे नजराना लेकर तालाबों, चारागाहों और सार्वजनिक रास्तोंकी जमीनको भी जोतपर उठा रहे हैं जिससे आगे चलकर अपनी जमींदारीकी खेतीके बड़े हुए रकबेके मुताबिक वे मुआवजेकी भी अपेक्षाकृत बड़ी रकम वसूल कर सकें । शिकमी काण्टकार बड़ी तादादमें बेदखल किये जा रहे हैं । प्रान्तीय सरकारका कर्तव्य है कि वह जल्द-से-जल्द जमींदारी प्रथाको समाप्त करे । साथ-ही इस बीच जमींदारोंद्वारा जो जुल्म हो रहे हैं उनसे किसानोंकी रक्षा होना भी अत्यन्त आवश्यक है । यह प्रसन्नताकी बात है कि प्रान्तीय सरकारने इस आशयका एक कानून पास किया है कि जिन जमींदारोंके अत्याचारोंसे किसान बहुत तंग आ गये हैं उनकी जमींदारी सरकार 'कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स' की देख-रेखमें ले ले । आशा है, यह कानून केवल कागजी ही नहीं रह जायगा, सरकारकी ओरसे कड़ाईके साथ इसको पालन करनेका प्रबन्ध किया जायगा । जंगलों, चारागाहों, सार्वजनिक मार्गों आदिकी रक्षाके लिए भी शीघ्र एक कानून बनाये जानेकी आवश्यकता है ।

जमींदारोंके अन्तके पश्चात्

जमींदारी प्रथाका अन्त हो जानेसे ही किसानोंकी वर्तमान दुरवस्थाका अन्त नहीं हो जायगा । जमीनपर बड़े हुए वेहद भारको हटाने तथा उसकी पैदावार बढ़ानेके लिए सरकार तथा स्वयं किसानोंको साहसपूर्ण कदम उठाने होंगे । उद्योग-धन्धोंका उचित विकास न होनेके कारण भूमिपर भार वेहद बढ़ गया है और वह छोटे-छोटे असंख्य अलाभकर टुकड़ोंमें बँट गयी है । भूमिपर इस भारको दूर करनेके लिए सरकारको उद्योग-धन्धोंका तेजीसे विस्तार करनेकी नीति अपनानी चाहिये । छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें बँटी हुई जमीनको लाभकर बनाने और उससे पूरा फायदा उठानेके लिए हमें चकवन्दीकी नीति अपनानी

पड़ेगी । चकबन्दी हो जानेपर भी एक परिवारके हिस्सेमें जमीनका जितना बड़ा टुकड़ा आता है उसपर आधुनिक यन्त्रोंका लाभकर प्रयोग नहीं किया जा सकता । खेतोंमें आधुनिक यन्त्रोंके प्रयोगके लिए बड़े-बड़े खेतोंका होना जरूरी है । अतः आवश्यकता इस बातकी है कि समूचे गाँवके लोग मिलकर सहकारी कृषिकी प्रथाको अपनावे, सबकी जमीन एक साथ जोती और बोयी जाय, फसलके काटनेके वक्त क्षेत्रफलके हिसाबसे पैदावार बाँट ली जाय । सिंचाईके लिए सरकारको बिजलीका प्रबन्ध करना चाहिये । बहुतसे किसान आज कर्जके भारसे बुरी तरह पिस रहे हैं । सरकारका कर्तव्य है कि वह उन्हें सस्ते दरपर सूद देनेवाली सरकारी बैंक खोलकर साहूकारी-पाशसे मुक्त करे । किसान सस्ती दरपर अच्छी खाद और बीज वगैरह प्राप्त कर सकें और अपनी पैदावारका उन्हें पूरा मुआवजा मिल सके इसके लिए जरूरी है कि बीचके दलालोंको दूर किया जाय तथा खरीद और बिक्रीका सारा कार्य सहकारी समितियोंके जरिये किया जाय । इस प्रसंगमें किसानोंको प्रान्तीय सरकारके गाँव हुकूमत विलके द्वारा जो अधिकार मिलनेवाले हैं उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिये ।

किसान-सभाओंका कार्य

अवतक किसान-सभाओंका कार्य मुख्यतः प्रचारात्मक रहा है, वे किसानोंकी शिकायतोंको सरकारके सामने रखकर उन्हें दूर करनेके लिए आन्दोलन करती रही हैं । किन्तु अब जब कि जमींदारी प्रथाका अन्त निकट है और राज्यसत्ता भारतीयोंको हस्तान्तरित होनेवाली है तब उन्हें किसान-मजदूर राज्यकी स्थापनाके ध्येयको लेकर रचनात्मक कार्यमें लगना है । जमींदारोंके लठैतों तथा साम्प्रदायिक उपद्रवकारियोंसे किसानोंकी रक्षाके लिए ग्राममें किसान-सेना अर्थात् स्वयं सेवक दलके संघटनकी आवश्यकता है ।

सबसे बड़ी बात किसान कार्यकर्ताओंको जो करनी है वह है किसानोंको आपसमें मिल-जुलकर काम करना सिखाना । गाँवके मुकदमोंका निपटारा, गाँवकी शिक्षाका प्रबन्ध, किसानोंकी आवश्यकताकी वस्तुओंकी खरीद और बिक्री इन सबको किसानोंको अपनी पचायत और सहयोगसमितियोंके द्वारा करना चाहिये । किसान कार्यकर्ताओंका कर्तव्य है कि वे रूस, अमेरिका आदि भारतके बाहरी देशोंमें होनेवाले कृषि-सम्बन्धी प्रयोगोंका अध्ययन करे और मालूम करे कि उनसे भारतीय किसान क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ।

किसान-सभाओंको एक ओर सरकारपर जोर डालकर उससे किसानोंके हितके कानून बनवाना है, दूसरी ओर स्वयं किसानोंकी मनोवृत्ति बदलनी है । अमेरिकाके किसानके पास अच्छा घर, बगीचा, और मोटर है, किन्तु हमारे देशका अन्नदाता किसान अपना ही पेट भरनेमें असमर्थ रहता है । इसके लिए वह अपने भाग्यको दोष देकर प्रायः सन्तोष कर लेता है । पर किस्मतकी यह मार हमारे ही देशके किसानोंपर ही क्यों है, अमेरिकाके किसानोंपर क्यों नहीं ? हमें किसानोंके मस्तिष्कसे भाग्यवादको निकाल फेंकना है, उन्हें अपने पैरोंपर खड़ा होना, सिखाना है, एक दूसरेके साथ सहयोग करना सिखाना है ।

ग्राम और नगरोंका फर्क मिटे

आज हमारे ग्रामोंका जीवन इतना नीरस और कठोर है कि ग्रामोंके जो नवयुवक थोड़ी-बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वे शहरमें ही रहना चाहते हैं, गाँवको लौटना उन्हें खलता है। हमें ग्रामोंमें भी नगरोंमें प्राप्त होनेवाले विज्ञानकी विभूतियोंका प्रचार करना है और अन्ततोगत्वा ग्राम और नगरके भेदको ही मिटा देना है। यह कार्य तभी पूरा होगा जब कि शोषणपर आधारित सामन्तवाद तथा पूँजीवादका अन्त कर दिया जाय, बहुतेकी मिहनतकी कमाईपर गुलछरें उड़ानेवाले कुछ न रहें, सभी लोग एक दूसरेके साथ सहयोग करते हुए परिश्रम करें और व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई और समूहकी भलाई व्यक्तिकी भलाई समझी जाय। इस शोषणमुक्त समाजकी स्थापनाके लिए किसान-सभाओंको मजदूर-सभाओंके साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करके आन्दोलन करना होगा।

कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी

मैं अबतक इस बातका समर्थन करता रहा कि हमें कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहिये। आज मैं आपसे यह कहता हूँ कि हमें कांग्रेस छोड़ देना चाहिये।

कांग्रेस छोड़ना कोई खुशीकी बात नहीं है। मैं तीस सालसे कांग्रेसका कार्यकर्त्ता हूँ। मैं इन सब वर्षोंका सम्बन्ध छोड़ रहा हूँ। मैं अच्छे मित्रोंको छोड़ रहा हूँ। राजनीति भी अजीब चीज है। राजनीतिमें मित्र दुश्मन बन जाते हैं।

मैं तो सन् १९३४ से कहता रहा हूँ कि कांग्रेस समाजवादका अस्त्र नहीं बन सकती।

हमें कांग्रेस छोड़नेकी जल्दी नहीं थी। कांग्रेस हमें उसे छोड़ देनेके लिए बाध्य कर रही है। एक बार कांग्रेसके अध्यक्षने हमसे कहा था कि हम अपनी पार्टीके नामसे 'कांग्रेस' शब्द निकाल दें। दूसरे कांग्रेसने हमसे यह भी कहा कि हम अपनी पार्टीका द्वार गैर-कांग्रेसियोंके लिए भी खोल दें। हमने कानपुरमें यह सब कुछ किया। अब उन्होंने एक ऐसा विधान बनाया है कि अब हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं।

गांधीजीने कांग्रेसके लिए अधिक सुन्दर भविष्य सोचा (Visualise) था। वह कांग्रेसको जन-सेवकोंका समूह (beehives) बनाना चाहते थे। वह उसे लोक-सेवक-सघ बनाना चाहते थे। गांधीजी अब नहीं हैं और उन्होंने कांग्रेसको एक राजनीतिक दल बना डाला है।

कांग्रेसके अन्दर जन-तान्त्रिक कार्यवाही (functioning) नामुमकिन हो गयी है। उस सस्थामें रहना असम्भव हो गया है।

माउन्टबेटन प्लैन मजूर कर, कांग्रेसने अपने बुनियादी वसूलोंको छोड़ दिया है। देश वेशक आजाद हो गया है, लेकिन 'आजादी मृत्यु और तबाहीका पैगाम लेकर आयी। पुरानी बुराईयाँ उभर आयी। इतिहासने वह चीज कभी नहीं देखी जो बात हमने आजादीके फौरन बाद देखी। साम्प्रदायिक बैरने सामूहिक हत्याओंका भयंकर रूप धारण कर

लिया। सामन्तशाही और स्थिर स्वार्थोंसे समर्थित साम्प्रदायिकता तूफानकी तरह देशमें फैल गयी। साम्प्रदायिक घृणा और रोपकी शक्तियाँ नये राज्यकी जड़ोंतकको उखाड़ फेंक देना चाहती हैं।

हिन्दुस्तानमें असाम्प्रदायिक जनतन्त्रकी रक्षाके लिए इन प्रतिगामी शक्तियोंका मुकाबला करना चाहिये। साम्प्रदायिकताकी इन प्रतिगामी शक्तियोंके अलावा, कम्युनिस्ट लोगोको भी हमारे नये राज्यकी रक्षाका कुछ ध्यान नहीं है। उनकी वफादारी भी देशके बाहर (Interterritorial) है। हमें कम्युनिस्टोंसे भी लड़ना है।

अगस्त सन् १९४७ से पहले कांग्रेस एक विस्तृत सयुक्त मोर्चा थी। उसका प्रगतिशील, सदा विकासमान और व्यापक विचार था। लेकिन आज वह एक पार्टी है। वह राजनीतिक स्वतन्त्रताको ही अपना ध्येय समझती है और अब शक्तिका उपयोग करनेमें ही संलग्न है। ऐसा मालूम होता है कि उसने हुकूमत करना ही अपना काम समझ रखा है। कांग्रेसने तो सरकारसे अपना समीकरण (identification) कर लिया है। वह तो अब सरकारके अधीन हो गयी है।

कांग्रेसमें हर किस्मके आदमी शरीक हो गये हैं। कलके देश-भक्त गद्दार बताये जाते हैं। कांग्रेस-राजके अन्दर देशभक्तकी व्याख्या ही बदल गयी है।

कांग्रेसके आदर्शों और कांग्रेस सरकारोंके कार्योंमें बड़ा अन्तर है। कांग्रेसका दावा है कि सम्प्रदायवादियोंका उसमें कोई स्थान नहीं। लेकिन कट्टर सम्प्रदायवादी सरकारके मेम्बर हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल पूंजीवादियोंको आश्वासन देते हैं कि पण्मुखम् चेटी उनके प्रतिनिधि हैं और इसलिए उन्हें भयकी जरूरत नहीं। वह चाहते हैं कि मुस्लिमलीगी लीगको खत्म कर कांग्रेसमें शामिल हो जायें। वह कांग्रेसमें हिन्दू सभाइयोंका स्वागत करते हैं। इस तरह एक द्वारसे कांग्रेस सोशलिस्टोंको निकालती है और दूसरे द्वारसे पूंजीवादियों और सम्प्रदायवादियोंको शामिल करती है। ईश्वर ही कांग्रेसकी रक्षा कर सकता है !

कांग्रेस सरकार कहती है “पैदा करो या मरो”। वह मजदूरोंसे अधिक त्यागकी माँग करती है। यह कैसे हो सकता है ? “पैदा करो या मरो” का नारा केवल मजदूरोंसे ही सम्बोधित नहीं किया जा सकता है। यह नारा पूंजीपतियों और धनियोंसे भी सम्बोधित होना चाहिये। अगर स्थिर स्वार्थ चार कदम आगे बढ़नेको तैयार हो तो मैं सरकारको विश्वास दिलाता हूँ कि मजदूर पीछे नहीं रहेगा।

हम भग्नहृदय कांग्रेसके बाहर नहीं आ रहे हैं। हमारे आदर्श भिन्न हैं। आज आदर्शोंका विरोध है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि जो कांग्रेसमें रह गये हैं वे सब प्रतिगामी हैं।

साम्प्रदायिक घृणा और भावना तथा साम्प्रदायिकताके जहरको खत्म करनेके लिए हमें कांग्रेससे सहयोग करना चाहिये। अगर हमारे राज्यको सबल बनना है, तो असाम्प्रदायिक जनतन्त्रका वातावरण सारे देशमें फैलना चाहिये।

हम अपने देशमें नये जीवनकी बुनियाद डालते जा रहे हैं। नौकरणाही बिल्कुल प्रतिगामी, भ्रष्ट और दकियानूसी है। शासनयन्त्र, अंग्रेजोंकी कृति, नितान्त कालातीत है। हमे कर्मचारियोंकी नयी शिक्षा देनी होगी। उन्हें यह बात समझानी है कि वे जनता और राज्यके नौकर हैं। वृद्धिजीवियोंके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हमे उन्हें अपनेमें शामिल करना चाहिये।

ऐसा दिखायी देता है कि सरकारका एकतन्त्रीकरण हो रहा है। कांग्रेसमें अधिनायकत्व बढ़ रहा है। सरकारी पीटोंके खिलाफ जनतान्त्रिक, स्वतन्त्र, निर्भीक और स्वस्थ विरोधकी माँग है। इस माँगको सोशलिस्ट पार्टी ही पूरा कर सकती है। इतिहासके इस चैलेञ्जको हमें स्वीकार करना होगा।

हमे यह नहीं भूलना चाहिये कि जनतन्त्रकी जड़ें जनतामें हैं। अगर जनता शक्तिसम्पन्न है, तो राज्य भी शक्तिशाली होगा।

मैं यह माननेको तैयार हूँ कि कांग्रेस छोड़नेके बाद कुछ दिनोंतक हमे वियावानमे रहना पड़ेगा। लेकिन इसकी क्या परवाह है?

कांग्रेस जीवनहीन होती जा रही है। राष्ट्र आशाकी नयी किरण तथा स्रोतकी खोजमें है। इस आशाका स्रोत किसानों और मजदूरोंमें है। आशाकी इस नयी किरणकी खोजका उत्तरदायित्व सोशलिस्ट पार्टीपर है। हमे इस उत्तरदायित्वको मजूर करना है। मुझे यकीन है कि हम शीघ्र ही समाजवादी समाजका विकास कर सकेंगे। शीघ्र ही जनतान्त्रिक समाजवादको स्थापित करनेमें सफल होंगे। हमारा स्वप्न सत्य सिद्ध होगा।

जनतन्त्रकी रक्षाके लिए विरोधी दलकी आवश्यकता

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने और मेरे ग्यारह साथियोंने आज असेम्बलीसे त्यागपत्र देनेका निर्णय कर लिया है और कांग्रेस-असेम्बली पार्टीके नेताको अपना त्यागपत्र दे दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेससे पृथक् होनेका यह निर्णय हमारे जीवनका सबसे कठिन निर्णय है। बिना पूर्वविचारके हमने यह निर्णय सहसा नहीं किया है। कठोर कर्तव्य-भावनासे प्रेरित होकर ही तथा अपने आदर्शों और उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए हम इस निर्णयपर पहुँचनेके लिए विवश हुए हैं। इस निर्णयपर पहुँचनेमें हमने काफी समय लिया है। हम देशकी वर्तमान स्थितिसे भलीभाँति परिचित हैं। हम मानते हैं कि देश सकटकी अवस्थासे गुजर रहा है। किन्तु हम इन सकटोंकी सूचीमें अपनी संस्कृति तथा जनतन्त्रको भी शामिल करते हैं। आज जनतन्त्र तथा हमारी संस्कृति भी खतरेमें है। यह निर्विवाद है कि जनतन्त्रकी सफलताके लिए एक विरोधी दलका होना आवश्यक है—एक ऐसा विरोधी दल, जो जनतन्त्रके सिद्धान्तमें विश्वास रखता हो, जो राज्यको

१. सोशलिस्ट पार्टीके नासिक अधिवेशनके निश्चयानुसार युक्तप्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाकी सदस्यतासे दूसरे १२ साथियोंके साथ इस्तीफा देते हुए पढ़ा गया वक्तव्य।

किसी धर्मविशेषसे सम्बद्ध न करना चाहता हो, जो गवर्नमेण्टकी आलोचना केवल आलोचनाकी दृष्टिसे न करे तथा जिसकी आलोचना रचना और निर्माणके हितमे हो न कि ध्वंसके लिए ।

जनतन्त्रका अभ्यास नहीं

हम इस अत्यन्त आवश्यक कार्यको पूरा करना चाहते हैं । हम इस बातको कहनेके लिए क्षमा चाहते हैं कि इस कार्यकी पूर्ति हमारे ही द्वारा हो सकती है । दुर्भाग्यवश जनतन्त्रकी कोई परम्परा हमारे देशमे नहीं है तथा साम्प्रदायिकताका इस समय प्राधान्य है । हम जनतन्त्रके अभ्यस्त नहीं हैं । इस कारण रचनात्मक विरोधके अभावमे अधिनायकत्वकी मनोवृत्तिका पनपना सुगम है । केवल साम्प्रदायिकताका विरोध करनेसे जनतन्त्रकी स्थापना नहीं होती । इस सम्बन्धमे मैं कहूँगा कि क्या ही अच्छा होता यदि माननीय पुलिस-सचिव हमारे गृहसचिव होते । कल तथा अपने वजट भाषणमे उन्होंने जिन सिद्धान्तोका निरूपण किया है और जिस प्रकार जनतन्त्रकी प्रगतिके लिए जनतन्त्रकी आवश्यकता प्रतिपादित की है, उससे हम पूर्णतः सहमत हैं । हम आशा करते हैं कि यह नीति केवल उनकी व्यक्तिगत राय ही न होगी, बल्कि गवर्नमेण्टकी स्थिर नीति होगी । यदि ऐसा है तो हम आशा कर सकते हैं कि रचनात्मक विरोधी दल गवर्नमेण्टका पूरक होगा और अपने महत्त्वपूर्ण कार्यमे सफलता प्राप्त करेगा ।

सम्पत्तिके उत्तराधिकारी

वियोग सदा दुःखदायी होता है । इस विछोहका हमको कोई कम दुःख नहीं है । हमको इससे मार्मिक पीड़ा पहुँची है, किन्तु सस्थाओं तथा व्यक्तियोंके जीवनमे ऐसे अवसर आते हैं, जब उनको अपने आदर्शों और उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए अपनी प्रियसे प्रिय वस्तुका भी त्याग करना पड़ता है । हम सन्तप्त हृदयसे अपना पुराना घर छोड़ रहे हैं । किन्तु जो अपनी पैतृक सम्पत्ति है, उससे हम दस्तवरदार नहीं हो रहे हैं । यह सम्पत्ति भौतिक नहीं है । यह आदर्शों तथा पवित्र उद्देश्योंकी सम्पत्ति है । इस सम्पत्तिका उत्तराधिकारी न केवल ज्येष्ठ पुत्र होता है और न इस सम्पत्तिका समविभाग ही होता है । धार्मिक समुदायोका पर्सनल ला अर्थात् व्यक्तिगत विधान उसपर लागू नहीं होता । इस सम्पत्तिका दायदा वही हो सकता है, जो अपने आचरण और विश्वाससे अपनेको उसका अधिकारी सिद्ध करे । इसमे मिथ्या गर्व नहीं है । हम अपनी सीमाओं को जानते हैं । हम अपनी कमजोरियोंसे भी परिचित हैं । किन्तु हम यह कहना चाहते हैं कि हम इसका अधिकारी बननेका प्रयत्न करेंगे ।

विद्वेषकी भावना नहीं

ब्रिटिश पार्लमेण्ट तथा अन्य व्यवस्थापिकाओंका इतिहास बताता है कि ऐसे अवसरपर लोग त्यागपत्र भी नहीं देते । हम चाहते तो इधरसे उठकर किसी दूसरी ओर बैठ जाते । किन्तु हमने ऐसा करना उचित नहीं समझा । ऐसा हो सकता है कि आपके आशीर्वादसे निकट भविष्यमे हम इस विशाल भवनके किसी कोनेमे अपनी कुटीका निर्माण कर सकें

(हर्षध्वनि) । किन्तु चाहे यह संकल्प पूरा हो या नहीं, हम अपने सिद्धान्तोंसे विचलित न होंगे । हम जानते हैं कि हमारे देशका यह युग निर्माणका है, न कि ध्वंसका । अतः हमारी आलोचना सदा इसी उद्देश्यसे होगी । हम व्यक्तिगत आक्षेपोंसे सदा बचनेका प्रयत्न करेंगे और हम किसी ऐसे विवादमें न पड़ेंगे । राजनीतिक जीवनको स्वस्थ और नीतिपूर्ण बनानेमें हम अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं । इन बातोंमें महात्माजीका उपदेश हमारा पथ-प्रदर्शन करेगा । हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने किसी विद्वेष और विरोधके भावसे प्रेरित होकर यह कार्य नहीं किया है । हममें किसी प्रकारकी कटुता नहीं है । हमारे बहुतसे साथी और सहकर्मी कांग्रेसमें हैं और उनके साथ हमारा सम्बन्ध मधुर रहेगा । हम जानते हैं कि उनको भी हमारे अलग होनेसे दुःख पहुँचा है । हमारे समान राजनीतिक आदर्श तथा हमारी समान निष्ठा अब भी हमको एक प्रकारसे उनसे एक सूत्रमें बाँधे रहेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक कुटुम्बके सम्मानित सदस्य होते हुए भी इस भवनके अन्य कुटुम्बोंके अधिकारोंकी भी रक्षा करते हैं । अतः हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमको आशीर्वाद देगे कि हम अपने उद्देश्योंकी पूर्तिमें सफलता प्राप्त करें । हम आपके प्रति तथा कांग्रेस असेम्बली पार्टीके नेता माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पन्तके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं ।

हमने कांग्रेस क्यों छोड़ी ?

कांग्रेसकी स्थापना देशको स्वतन्त्र करनेके लिए हुई थी । इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए एक ऐसी राष्ट्रीय संस्थाकी जरूरत थी जो आजादी पानेके लिए विविध वर्गों और विचारधाराओंका एक संयुक्त मोर्चा बन सके । बिना देशके स्वतन्त्र हुए कोई भी अर्थनीति सफल नहीं हो सकती थी । राजनीतिक स्वतन्त्रता पाना सबका समान ध्येय था । कांग्रेस इस प्रकारका संयुक्त मोर्चा थी । इसी कारण यद्यपि समाजवादी पार्टीका जन्म सन् १९३४ ई० में हुआ, पार्टीने कांग्रेसमें रहकर संयुक्त मोर्चेको मजबूत किया । समाजवादी पार्टीके भीतर रहनेकी वजहसे कांग्रेस आर्थिक कार्यक्रमको महत्व देने लगी । पण्डित जवाहरलाल नेहरूने भी कांग्रेसके प्लेटफार्मसे समाजवादका प्रचार किया । फैजपुर-कांग्रेसमें किसानोंकी समस्याओंकी ओर अधिक ध्यान दिया गया और फलस्वरूप असेम्बलीके सन् १९३७ के चुनावमें किसानोंने कांग्रेसका साथ देकर कांग्रेस-पार्टीको सफल बनाया और उसकी गवर्नमेण्ट कई प्रान्तोंमें कायम की । किसानोंके प्रभावमें कांग्रेसको धीरे-धीरे जमींदारी प्रथाका अन्त करनेके लिए बाध्य होना पड़ा । कांग्रेसने आजादीके लिए जो सत्याग्रहकी लड़ाइयाँ लड़ी उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस धीरे-धीरे जनताकी संस्था होने लगी और जनताके प्रभावमें उसे अधिकाधिक जनताकी माँगोंको स्वीकार करना पड़ा । यहाँतक कि सन् १९४२ में अपने ८ अगस्तके प्रस्तावमें कांग्रेसको यह स्वीकार करना पड़ा कि वह

किसान-मजदूर राज्य स्थापित करेगी। इस घोषणाके साथ सन् ४२ के जन-आन्दोलनका श्रीगणेश हुआ था। यद्यपि कांग्रेसने धीरे-धीरे किसानोंके अधिकारोंको स्वीकार किया और वह उनको अपने प्रभावक्षेत्रमें लायी तथापि मजदूरोंके लिए कांग्रेस उतना नहीं लड़ी। यही कारण है कि कांग्रेसके सामाजिक आधारमें मजदूरोंका वह स्थान नहीं है। पिछले चुनावमें मजदूरोंने भी कांग्रेसका साथ दिया, किन्तु इसका कारण यह है कि मजदूर भी आजादी चाहता था। वर्गकी हैसियतसे वह तब भी कांग्रेससे अलग-सा था। शोषित वर्गोंके साथ महात्माजी तथा अन्य कांग्रेसजनोंकी जो सहानुभूति थी उसके कारण मजदूर भी एक अस्पष्ट रूपसे कांग्रेसकी ओर आकर्षित होता था, किन्तु उसने कांग्रेसको उस तरह नहीं अपनाया जिस तरह किसानवर्गने अपनाया था।

अब हिन्दुस्तान आजाद हो गया है। सर्वत्र कांग्रेसकी गवर्नमेण्ट शासनारूढ है। कांग्रेसका कार्य अब पूरा हो गया है। जब कोई आन्दोलन सफल हो जाता है उसके नेताओंके हाथोंमें अधिकार आता है तब उसमें एक प्रकारकी जडता आ जाती है। जो आन्दोलन पहले सजीव था और निरन्तर विकसित होता रहता था वह अब धीरे-धीरे निश्चित रूप धारण करने लगता है और उसमें विकासकी गुंजाइश गायब होने लगती है। गवर्नमेण्टका संस्थापन अधिकार बढ़ने लगता है और संस्था धीरे-धीरे अपने स्वतन्त्र अस्तित्व और महत्त्वको खोने लगती है। क्योंकि कांग्रेसका ध्येय अब पूरा हो गया है इसलिए वह अब गवर्नमेण्टकी इच्छाकी पूर्तिमात्र करने लगी है।

प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस आज अपनी आर्थिक नीतिको इस प्रकार बदल सकती है कि हम कह सकें कि यह नीति समाजवादके आधारपर आश्रित है। यह कार्य अब दुष्कर क्या असम्भव हो गया है।

कांग्रेसका निरन्तर विकास होता आया है, किन्तु लक्ष्यके शुद्ध राजनीतिक होनेके कारण इसका प्लेटफार्म काफी चौड़ा रहा है। इस विकासका कारण यह था कि कांग्रेस एक आन्दोलन था। इस आन्दोलनसे प्रभावित होकर कांग्रेसमें नये-नये समूह और वर्ग सदा आते रहे हैं। आन्दोलनकी मर्यादा गवर्नमेण्टकी आवश्यकताओंसे सीमित न थी। गवर्नमेण्ट सदा स्थिरता चाहती है। वह परिवर्तनोंसे घबराता है। उसकी चाल सदा मन्द होती है, जन-आन्दोलनका स्वागत करनेके बजाय वह उसका रोक-थाम करती है और उसका उत्तर सदा यही होता है कि जब हम जनताके हितोंकी रक्षा करनेको तैयार हैं तो आन्दोलनकी क्या आवश्यकता है। जनताका हित किसमें है इसका अन्तिम निर्णायक वही बनना चाहते हैं। कांग्रेस गवर्नमेण्टकी मनोवृत्ति भी ऐसी ही बन गयी है। इसमें कोई आश्चर्य करनेका कारण नहीं है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेसकी कोई ऐसी स्पष्ट और विशद अर्थनीति न थी जो नीचेसे आयी होती, इसलिए कांग्रेसमें भी वही जड़ता आती जाती है। यह ठीक है कि कांग्रेसमें काफी असन्तोष है और यह असन्तोष इसी कारणसे है कि कांग्रेस अबतक एक आन्दोलन थी न कि एक पार्टी। विविध विचारधाराएँ जो अबतक कांग्रेसमें रहकर काम करती थी अब एक साथ काम करनेमें दिक्कत महसूस करती हैं। स्वतन्त्रता पानेके बाद आर्थिक प्रश्न सफाईसे सामने आने लगे हैं और वह उत्तर चाहते

है। कांग्रेसका वह दल जिसका कांग्रेस मशीनपर कब्जा है अब अन्य विचारधाराओंको कांग्रेसमें स्थान नहीं देना चाहता। वह कांग्रेसको एक पार्टीका रूप देना चाहता है। गवर्नमेण्टका फायदा भी इसीमें है। इसी प्रकार वह कांग्रेसको अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह दल एक प्रकारसे मध्यम श्रेणीका प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेसकी परम्पराके अनुसार इनकी भी सहानुभूति जनताके साथ है और आज कोई गवर्नमेण्ट जनताकी अपेक्षा भी नहीं कर सकती। किन्तु इस सहानुभूतिकी मर्यादा बहुत सीमित है। यदि कोई शुद्ध पूँजीवादी गवर्नमेण्ट होती तो उसको भी विवश होकर जनताकी स्थितिको उन्नत करना होता। उसमें और वर्तमान गवर्नमेण्टमें अन्तर इतना ही है कि यह गवर्नमेण्ट जनताका साथ देनेके लिए स्वतः स्वतन्त्र है। किन्तु वह एक प्रकारकी परवशतामें पड़ी हुई है। गवर्नमेण्टमें भी विचारोंकी समानता नहीं। उनमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जो समाजवादको स्वीकार करते हैं, किन्तु गवर्नमेण्टकी नीति एक व्यक्तिविशेषके विचारोंके अनुसार नहीं निर्धारित होती, चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो। इसलिए यह कहना कि क्योंकि केन्द्रीय गवर्नमेण्टके प्रधान सचिव पण्डित जवाहरलाल नेहरू हैं इसलिए गवर्नमेण्ट सोशलिस्ट है, गलत होगा। हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि एक सोशलिस्ट प्रधान सचिवके होते हुए उसकी कैबिनेटमें पूँजीपतियोंके समर्थक कई सचिव क्यों हैं तथा उसमें हिन्दू महासभाके एक प्रधान व्यक्ति क्यों हैं। हम यह नहीं मानते कि पण्डितजीने इन सज्जनोंको अपनी खुशीसे मन्त्रिमण्डलमें लिया है। वह इनको लेनेके लिए परिस्थितियोंसे मजबूर कर दिये गये हैं। ये परिस्थितियाँ क्या हैं। एक तो कांग्रेस मशीनपर जिनका कब्जा है वह पण्डितजीके विचारोंके नहीं है, वह पूँजीपतियोंके समर्थक है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेसकी कोई अर्थनीति नीचेके प्रभावसे ठीक-ठीक नहीं बन पायी है। यदि बन पाती तो कांग्रेसकी मशीनपर पण्डितजीका ही कब्जा होता। आज पण्डितजीका सबसे अधिक प्रभाव है देश और विदेश दोनोंमें। वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है। किन्तु वह मध्यम वर्गका जिसका मशीनपर कब्जा है प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस वर्गको पण्डितजीकी बहुत जरूरत है। असलियतको छिपानेके लिए और गवर्नमेण्टकी शोभाको बढ़ानेके लिए तथा उसे लोकप्रिय बनानेके लिए, पण्डित नेहरूके बिना यह गवर्नमेण्ट अपनी लोकप्रियता खो देगी। इस उद्देश्यको पूरा करनेके लिए वह नेहरूजीको थोड़ा-बहुत सन्तुष्ट भी करेंगे, किन्तु यह दिखानेके लिए कि उसके बिना वह कुछ नहीं कर सकते वह कभी-कभी अपना हाथ खींच लेंगे। और आज जब पैदावार बढ़ानेकी इतनी जरूरत है अपनी पूँजी व्यवसायसे खींचकर नेहरूजीको यह दिखलाना चाहेंगे कि उनकी सहायताके बिना यह कार्य नहीं हो सकता। किसी गवर्नमेण्टकी नीतिके अन्तिम निर्णायक व्यक्तिविशेष नहीं होते, किन्तु पार्टी मशीन होती है, यह मशीन पण्डित नेहरू और जनताको एक दूसरेसे अलग करती है।

महात्माजीसे बढ़कर प्रभावशाली कौन हो सकता है, किन्तु क्या हम नहीं जानते कि इधर दो वर्षोंसे गवर्नमेण्टपर उनका प्रभाव क्षीण हो गया था। वह स्वयं कहा करते थे कि पैदलोपर मेरा प्रभाव है, किन्तु शतरंजके बड़े मुहुरोपर जैसे वज्र और आदिपर अब मेरा

प्रभाव नहीं है। क्या हम नहीं जानते कि देशका बँटवारा बिना उनके पूछे हो गया था ? इसलिए हमारा समाधान यह कहकर करना कि गवर्नमेण्टके नेता पण्डित जवाहरलालजी हैं ठीक नहीं है।

नये विधानके अनुसार कांग्रेस वस्तुतः एक पार्टी हो गयी है। अब कांग्रेसकी मशीनका पूरा-पूरा उपयोग गवर्नमेण्टके लाभके लिए किया जायगा। जन-आन्दोलन कांग्रेसके अनु-शासनके नामपर रोके जायँगे। कांग्रेस एक प्रकारसे गवर्नमेण्टकी केवल प्रचारक रह जायगी। जन-आन्दोलनपर रोक थाम होनेसे जनता नये नये अनुभवोंसे वंचित हो जायगी। इसकी भी आशा कम है कि कांग्रेसद्वारा कोई रचनात्मक कार्य भी हो सकेगा। ऐसी स्थितिमें कांग्रेसका सामाजिक आधार नित्य सकुचित हो जायगा। जमींदारी प्रथाका अन्त करनेके बाद कांग्रेस बड़े-बड़े किसानों और मध्य वर्गकी सस्था रह जायगी। केवल जमींदारी प्रथाका अन्त करनेसे जमीनकी समस्याएँ हल न होगी, गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरोंके प्रश्न हल न होंगे। यह एक नया समाधान चाहेगे। मजदूरवर्ग भी आगे बढ़ न सकेगा।

सामाजिक संघर्षसे चेतना पैदा होती है और जब एक प्रकारसे इसका नेतृत्व कांग्रेस न करेगी तो कांग्रेसके विकासका क्रम बन्द हो जायगा। सत्याग्रह-संग्रामोंसे ही कांग्रेसका सामाजिक आधार विस्तृत हुआ था। प्रत्येक संग्रामके बाद कांग्रेसकी शक्ति बढ़ी है और जनताके आनेसे उसका कार्यक्रम दे देनेसे उसकी सफलताका निश्चय नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने हालमें जो कार्यक्रम स्वीकार किया है वह ऊपरसे आया है नीचेसे नहीं। कांग्रेसका सामाजिक आधार इसका उपयुक्त साधन नहीं है। उपयुक्त साधनके अभावमें साध्यकी सफलता नहीं हो सकती। यही कारण है कि सन् ४२ के प्रस्तावपर विधानपरिषद्ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जनताको पता नहीं है कि क्या विधान बन रहा है। यदि जनतामें उसका प्रचार किया जाता और उसकी राय ली जाती तो विधानमें कुछ परिवर्तन हो सकता था।

समाजवादी पार्टीके सामने ऐसी स्थितिमें यह प्रश्न उठा कि उसको क्या करना चाहिये। देशकी सकटकी अवस्था उसे कोई निश्चय फैसला करनेसे रोक रही थी। कांग्रेससे निकलना तो उसको था ही किन्तु प्रश्न था कि इसके लिए उपयुक्त समय क्या है ! हमारी अनिश्चितता इसी कारण थी, किन्तु जब कांग्रेस-विधानमें यह सशोधन कर दिया गया कि कांग्रेसमें कोई पार्टी नहीं रह सकती तब हमारे लिए निकलनेके सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा।

इसके अतिरिक्त जनतन्त्रके आधारको सुदृढ़ करनेके लिए भी निकलना आवश्यक हो गया। जनतन्त्रकी सफलताके लिए स्वस्थ रचनात्मक विरोधका होना जरूरी है। आज इसका नितान्त अभाव है और साम्प्रदायिक दल इस कार्यको नहीं कर सकते। उनकी आलोचनाका विशेष महत्त्व और आदर नहीं है। भारतीय परिस्थितिमें कांग्रेसका कोई दल इस कमीको पूरा कर सकता है। यह दल समाजवादी दल ही हो सकता है।

जब कांग्रेसमें विकासकी गुंजाइश नहीं रह जाती तब उन वर्गोंके आधारपर जो समाज-वादका आधार बन सकते हैं, एक नये संगठनका निर्माण करना आवश्यक हो जाता है।

यह वर्ग मुख्यतः गरीब किसान और मजदूरवर्ग ही हो सकता है। शिक्षित वर्गका तो प्रत्येक दलके लिए महत्त्व है। विशेषज्ञोंकी सहायताके बिना कोई शासन नहीं चल सकता। समाजवादी पार्टीको तो यह सहायता और भी अपेक्षित है, क्योंकि वह निश्चित आर्थिक योजनाके महत्त्वको स्वीकार करना चाहते हैं। इसीलिए हम व्यवस्थापकोंकी और विशेषज्ञोंकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इनमेंसे जो हमारी नीतिको स्वीकार करते हैं उन्हें अपने दलमें सम्मानपूर्वक प्रविष्ट करना है। उनकी सहायतासे हमको अपनी नीति और कार्यक्रमको भी सुस्पष्ट बनाना है।

हमारे कार्यक्रमका विविध रूप होगा। हम मुख्यतः किसान और मजदूरोंकी सेवामें रत रहेंगे। सामाजिक शक्तिका उद्गमस्थान इन्हीं वर्गोंमें है। इन्हीं वर्गोंसे शक्ति लेकर हम समाजवादकी स्थापना कर सकते हैं। यही वर्ग समाजवादके मुख्य आधार हैं। साथ ही पार्लमेण्टरी प्रोग्रामकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ग्राजकी स्थितिमें उसका अपना विशेष महत्त्व है। इस प्रकार हम देशकी समस्याओंका भी अध्ययन कर सकेंगे और उनके सम्बन्धमें अपना मत देशवासियोंके सम्मुख रख सकेंगे। इस कार्यसे रचनात्मक मनोवृत्तिके बनेनेमें भी सहायता मिलेगी। किन्तु हम यह नहीं भूल सकते कि हमको पार्लमेण्टरी प्रोग्राममें तभी सफलता मिलेगी जब हमारी जड़े जनतामें फैल जायें।

इस सम्बन्धमें यह कहना आवश्यक है कि हम रचनात्मक कार्यक्रमको ऊँचा स्थान देंगे। लोकतन्त्रकी स्थापनाके लिए सर्वत्र सहकारिताकी भावनाको उत्तेजित करना है। यही काम अकेले गवर्नमेण्ट नहीं कर सकती। इस ओर हम विशेष ध्यान देना चाहते हैं।

कार्य महान् है और हमारे साधन कम हैं। यदि हमारे उद्देश्य और कार्यक्रम देशकी आवश्यकताको पूरा करनेवाले हैं और यदि विद्याचरण सम्पन्न लोकसेवक इस आन्दोलनका नेतृत्व करें तो इसका सामाजिक आधार विस्तृत होगा और कार्यमें सफलता मिलेगी।

कुछ गम्भीर प्रश्न . .

भारतीय विधानका प्रारम्भ ही इस घोषणाके साथ होता है कि 'भारत एक प्रजातान्त्रिक और असाम्प्रदायिक राज्य है।' हम सभी जानते हैं कि प्रजातन्त्र और असाम्प्रदायिकताकी भावनाएँ वैज्ञानिक, बौद्धिक तथा नयी चेतनावाले युगकी उपज हैं। इसलिए यह बुद्धिसंगत है कि इन विचारोंको भारतीय भूमिमें पनपने देनेके लिए विचारों और भावनाओंका अनुकूल वातावरण तथा इनकी पुष्टि और जीवनके लिए पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रामें हो।

जादूकी छड़ी घुमाते ही प्रजातन्त्रका वातावरण उपस्थित नहीं हो जाता, उसके पीछे एक परम्परा होती है और व्यक्तिको अपने स्वभावमें उसे लाना पड़ता है। सत्य तो यह है कि भारतीय जनता प्रजातान्त्रिक विचारोंकी नहीं है। इसलिए आज इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि हम अपनी पुरानी आदतको बदलकर अपने चरित्रका नये रूपमें

निर्माण करे। मानना पड़ेगा कि यह कोई सरल कार्य नहीं और इस दिशामें प्रगति बड़ी धीमी रहेगी। सतत सचेष्ट रहकर, अनवरत चेष्टा करते रहनेपर ही हम प्रजातान्त्रिक जीवन-पद्धतिपर चलनेकी आशा कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, चूँकि हमारे देशमें आवश्यकतासे अधिक धार्मिक भावना है, इसलिए उसको असाम्प्रदायिकताकी ओर मोड़नेका प्रयत्न करना भी बहुत आवश्यक है।

राष्ट्रीयताको तिलाञ्जलि

आज देशकी जो दशा है, उसमें इस दोहरे कामका पूरा होना कठिन हो गया है। धार्मिक आधारपर देशका बँटवारा हो जानेसे, दोनों ओर साम्प्रदायिक घृणाका बोलवाला है और फलस्वरूप देशका बौद्धिक और भावनाशील वातावरण पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। साम्प्रदायिक उपद्रवोंने हत्या, लूट, आगजनी, बलात्कार और अपहरणका स्थान ले लिया है। साम्प्रदायिकता आज सबके सिरोपर चढ़कर बोल रही है, राष्ट्रकी विचारधारा-पर आज साम्प्रदायिकताकी अपनी विचारसरणियाँ हावी हो रही हैं। अन्य विचार-धाराओंके लिए अभी कोई स्थान नहीं। हमारा सारा सामाजिक जीवन आज भ्रष्ट हो गया है और हमारा राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन निम्न स्तरपर उतर आया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा राजनीतिक चिन्तन अस्त-व्यस्त और हमारी उदार भावनाएँ सकुचित हो गयी हैं। हमारे नैतिक मूल्य बहुत नीचे गिर गये हैं और अब हम हर समस्याको एक सम्प्रदायके सकुचित दृष्टिकोणसे देखने लगे हैं। साम्प्रदायिकताका मतलब है फिरकापरस्तीकी ओर लौट जाना और उस मानेमें हमने अपनी राष्ट्रीयताको तिलाञ्जलि दे दी है।

एक बार हमने यह सोचा था कि जब देशमें फिरसे शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो जायगी, तब राष्ट्र अपने खोये हुए नैतिक संतुलनको पुनः शीघ्रतासे प्राप्त कर लेगा और स्वतन्त्रता संग्रामोंके दिनोंमें हम जिन उच्च आदर्शोंके लिए लड़े थे, उनको पूरा करनेमें द्विगुणित उत्साहसे जुट पड़ेगे। लेकिन जब ऊपरी ढगसे सारी वाते व्यवस्थित हो गयी, तब भी एक न एक प्रश्न, जैसे पहले काश्मीरका, अब हैदराबादका—साम्प्रदायिक भावनाको उभारते रहते हैं और जन-जीवन अब भी अशान्त बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जबतक ये प्रश्न हल नहीं किये जाते, राष्ट्रका नैतिक स्वास्थ्य गिरता ही जायगा। इसलिए आज यह बहुत आवश्यक हो गया है कि इन प्रश्नोंका निपटारा शीघ्रताके साथ किया जाय।

प्रतिक्रियावादियोंको प्रोत्साहन

लेकिन यह कहते दुःख होता है कि सार्वजनिक जीवनमें जिन लोगोंको प्रमुख स्थान प्राप्त है वे परिस्थितिकी इस गम्भीरताको अनुभव नहीं करते। कहाँ तो वे वर्तमान परिस्थितिको बदलनेमें अपनी पूरी शक्ति लगाते और कहाँ वे ऐसे सार्वजनिक भाषण तथा प्रचार करते हैं, जिनसे प्रतिगामी और प्रगति-विरोधी शक्तियोंको अप्रत्यक्ष रूपमें उत्साह मिलता है। वे यह नहीं समझते कि ये प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ प्रभावशाली होकर

हमें उस नयी जीवन-पद्धतिको अपनानेसे रोकेंगी, जिसका अपनाया जाना राष्ट्रकी रक्षा और विश्वकी प्रगतिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। ऐसी शक्तियाँ अपने राजनीतिक उद्देश्योंकी प्राप्तिके लिए मनुष्यकी बुद्धिसे अपील करनेके बजाय परम्परागत विश्वासों और रीतिरिवाजोंकी दुहाई देती हैं। जनताका ज्ञानवर्द्धन न करके वे उसमें मति भ्रम फैलानेकी चेष्टा करती हैं। राजनीतिक विवादमें वे हर तरहकी ऊलूल-जल्लू बातें घसीट लाती हैं। ऐसा लगता है कि चुनावोंका मूल उद्देश्य ही वे आँखोंसे ओझल कर बैठती हैं। येनकेन प्रकारेण चुनाव जीत लेना ही उनका मुख्य उद्देश्य मालूम होता है। चुनावोंके सिलसिलेमें मतदाताओंकी ज्ञान वृद्धि भी होनी चाहिये, इसकी ओर शायद उनका ध्यान नहीं जाता।

धर्मके नामपर

चुनावका समय ऐसा समय है जब राजनीतिक विवादको उच्च धरातलपर रखकर स्वस्थ राजनीतिक वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। इस सिलसिलेमें लोगोंकी धार्मिक भावनाओंको भी असाम्प्रदायिक बनानेकी चेष्टा की जाती है और राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओंकी ओर उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेकिन जब हमारे सार्वजनिक नेता धार्मिक मंचपर खड़े होकर जनतासे वोट देनेके लिए अपील करते हैं, तब जादू और अन्धविश्वासका वातावरण उत्पन्न न हो तो क्या हो? जब कोई नेता मतदाताओंसे कहता है कि अमुक व्यक्तियोंको ही वोट दो, अन्यथा ईश्वर तुमपर कुपित हो जायगा, तब ऐसा लगता है मानो वह ईश्वरको आँखोंसे अधिक जाननेका दावा रखता है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकारके दावेमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन इससे तो इतना होता ही है कि जो लोग ईश्वरमें विश्वास करते हैं, उनके दिलमें झूठमूठ एक भय घर कर जाता है।

संस्कृतिके नामपर

भारतीय संस्कृतिकी कई बातें प्रशंसा और रक्षाके योग्य हैं, लेकिन हमारी परम्परागत संस्कृतिके नामपर जितनी चीजें चलती हैं, उन सबकी प्रशंसा और रक्षा नहीं होनी चाहिये। धिसे-धिसाये विचारों, जीर्णशीर्ण सामाजिक सिद्धान्तों और मतवादोंसे हमें हानि ही पहुँच सकती है। परम्परासे चले आनेवाले कुछ विचार तो आजकी परिस्थितिमें विलकुल असंगत हो गये हैं और उनका तिरस्कार आवश्यक है। सावधानीसे हमें अपनी प्राचीन संस्कृतिके उन अंगोंको चुनना है जो हमारी वर्तमान समस्याओंको सुलझानेमें समर्थ हों। लेकिन यदि कोई प्रमुख सार्वजनिक नेता प्राचीन भारतीय संस्कृतिके नामपर अपना चित्र रखे बिना, वोटोंसे अपील करता है तो वोटरोपर निस्सन्देह यही प्रभाव पड़ेगा कि नेता प्राचीन भारतीय संस्कृतिके उन सभी परम्परागत विश्वासों तथा रीति-रिवाजोंकी प्रशंसा कर रहा है, जो साधारण जनको बहुत प्रिय हैं और जिनको वे बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। ये सारी बातें केवल इसलिए कही जाती हैं कि अपने राजनीतिक विरोधी-को नीचा दिखाया जा सके और जनताके सामने उसे भौतिकवादी तथा अपनी संस्कृतिको धृष्ट करनेवालेके रूपमें चित्रित किया जा सके। इस तरहकी अपील एक प्रतिगामी नारा

वनकर रह जाती है और असाम्प्रदायिक राज्य और प्रजातन्त्रको दृढ़ करनेमें इससे कोई मदद नहीं मिलती ।

एक प्रमुख नेताने तो यहाँ तक कहा है कि ईश्वरमें आस्था होना भारतीय संस्कृतिका अविभाज्य अंग है । कई लोग इस बातकी सत्यतापर सन्देह करेंगे कि ईश्वरपर विश्वास किये बिना भी मनुष्य धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है । दूसरोको इसमें विरोधाभास भले ही लगे, किन्तु भारतके विषयमें यह शब्दशः सत्य है । ईश्वरमें आस्था होना भारतीय संस्कृतिका आवश्यक अंग नहीं है । इस देशमें कई ऐसे धार्मिक मतवाद प्रचलित हुए जिन्होंने अपने अनुयायियोंके लिए ईश्वरके प्रति विश्वासको शर्त नहीं बनाया । भारतीय संस्कृतिकी मूल आत्मा और उसका सार इससे विलकुल भिन्न है । वह विश्वके नैतिक शासनमें विश्वास करता है । इस स्थलपर इसकी विस्तृत विवेचना असंगत होगी, फिर भी ठीक परिस्थितिका स्पष्टीकरण आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना यह भ्रम हो सकता है कि भारतीय संस्कृति अत्यधिक धार्मिक है । कोई भी राज्य अपनी जनताकी संस्कृतिसे अलग नहीं रह सकता । राज्यका यह प्रधान कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह अपनी जनताकी संस्कृतिको दूसरोमें फैलावे और विश्वविद्यालयोंके द्वारा भावी सन्ततिके लिए इसकी विरासत देनेका प्रबन्ध करे ।

हमारी सच्ची संस्कृति

भारतीय संस्कृतिके एक 'विद्वान् समर्थक' के कथनका एक ही मतलब हो सकता था कि चुनावमें खड़े हुए उसके विरोधी उम्मेदवार नास्तिक और भारतीय संस्कृतिके द्रोही थे । लेकिन जो अपनी संस्कृतिका शत्रु है, वह स्वयंका शत्रु है । हमको केवल यह याद रखना है कि संस्कृति जड़ नहीं होती; इतिहासके किसी युगमें यदि वह ह्रासोन्मुख होती है तो किसी युगमें विकासोन्मुख । हमारी संस्कृतिके दो पहलू रहे हैं । एक व्यक्तिवादी और दूसरा समष्टिवादी अर्थात् विश्वजनीन । आधुनिक युगमें हमें अपनी संस्कृतिके विश्वजनीन पहलूपर ही जोर देना है । हमें यह भी याद रखना चाहिये कि जब कभी हमने अपनी संस्कृतिके इस पहलूपर ध्यान केन्द्रित किया, भारतका गौरव बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्रोंमें अत्यधिक बढ़ा । यदि हम विश्वप्रेमकी इस भावनाको, जो मानवमात्रके प्रति प्रेम उपजाती है, फिर अपना ले तो हम अपने देशको उसी उच्च पदपर पहुँचा सकते हैं ।

राजनीति और धर्म

यही एक तरीका है जिससे हम अपनी संकुचित परिधिसे निकलकर असाम्प्रदायिक ढंगपर सोच सकेंगे । हम एक ऐसे ससारमें रह रहे हैं जिसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हो चुके हैं । हमसे उसका नया तकाजा है । इस नयी परिस्थितिका सामना हम तभी कर सकेंगे जब हममें वही उदारता, सहिष्णुता और मैत्रीभाव हो जो हमारी संस्कृतिकी विशेषता रहे हैं । भारतीय संस्कृतिका हित हम उसकी कुछ गली-सड़ी परम्पराओंसे चिपके रहकर नहीं कर सकते । इसके लिए तो हमें उसके सारको ही ग्रहण करना पड़ेगा । सक्षेपमें,

यदि हम सचमुच चाहते हैं कि अपने राष्ट्रका सगठन असाम्प्रदायिक आधारपर करें तो हमें राजनीतिमें धर्मका हस्तक्षेप रोकना ही होगा ।

विरोधी दलका भारतीयकरण

पहले मैंने कहा है कि हमारे देशके विरले लोगोमें ही प्रजातान्त्रिक चरित्र या व्यवहार पाया जाता है । उसको स्थापित करनेके लिए हमें अपनी सारी सद्भावना और शक्ति लगानी पड़ेगी । वच्चोमें प्रजातान्त्रिक स्वभाव शिक्षाके द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है । लेकिन राजनीतिक स्तरपर शासनारूढ दलको यह स्वीकार करना चाहिये कि प्रजातन्त्रकी स्थापनाके लिए विरोधी दलका होना आवश्यक है । लेकिन जब कभी वैधानिक स्वतन्त्रतापर जोर दिया जाता है और विरोधी दलके संघटनकी आवश्यकता बतलाई जाती है तब सरकारी गद्दियोंपर बैठे लोग इसकी ज़रूरतसे इन्कार कर देते हैं । और यह सब कुछ किया जाता है भारतीय परम्पराके नामपर । विरोधी दलकी माँगको शान्त करनेके लिए हालमें ही यह नुस्खा अपनाया गया है । यह कहा जाता है कि पञ्चिमी पद्धतिका अनुकरण किये बिना ही भारत अपने यहाँ प्रजातन्त्रका विकास कर सकता है और ऐसा करते हुए वह उन अच्छी बातोंको छोड़ सकता है जिनको पश्चिममें प्रजातन्त्रके निर्माणके लिए आवश्यक अंग समझा जाता है । उनकी यह भारतीय परम्परा तब नहीं टूटती जब विधान-परिपद्धमें यूरोपीय देशोंके विधान जैसे के तैसे स्वीकार कर लिये जाते हैं । लेकिन उस प्रजातान्त्रिक विधानकी सुरक्षाके लिए जब एक आवश्यक बात सुझायी जाती है जो सदियोंके अनुभवका निचोड़ है, तब भारतीय परम्परा जैसी एक रहस्यात्मक वस्तुके नामपर उसका विरोध किया जाता है । भारतीय परम्पराके इन समर्थकोंको हमारी नेक सलाह है कि पूर्वजोंके इस सन्निध्यका वे पालन करें कि एक निश्चित आयुके बाद वे सामाजिक जीवनसे सन्यास ले लिया करें । यदि हमारे मन्त्रिगण और राजनीतिज्ञ ६० वर्ष की आयुमें सार्वजनिक क्षेत्रसे अलग हो जाया करें तो शासन और जनता दोनोंका बड़ा भला होगा । मैं सुझाव दूँगा कि भारतके नये प्रस्तावित विधानमें इस प्रकारका एक नियम जोड़ दिया जाय । आजकी नयी समस्याओंको सुलझाने और शासन चलानेके लिए तो हमें ऐसे नवयुवकोंकी आवश्यकता है, जिनके पास उत्साह और नया दृष्टिकोण हो । जीवनसे थके हुए और पुरानी परिपाटीपर सोचनेवाले मनुष्य तो गड़बड़घोटाला ही करेंगे । यदि कर्मचारियोंके लिए एक निश्चित उम्रके बाद नौकरीसे अलग हो जानेकी शर्त है, तो कोई कारण नहीं कि मन्त्रियोंको उस नियमसे वरी किया जाय । हम एक ऐसे गतिशील युगमें रह रहे हैं, जिसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है । वुजुर्ग लोगोंसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि बदलती हुई हालतोंमें भी वे उतनी ही तत्परता और शीघ्रतासे काम कर सकेंगे ।

तानाशाहीकी ओर

अगर आप विरोधी दलकी आवश्यकतासे इनकार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप निरकुश शासनका समर्थन कर रहे हैं । भारतीय सरकारें धीरे-धीरे,

अधिनायकवादकी ओर झुक रही है। उनका यह दावा है कि वर्तमान शासन-व्यवस्था विल्कुल ठीक है और उसका समर्थन करना चाहिये। राष्ट्रीय सरकारके नामपर जनतासे यह अपील की जाती है कि वह इसको समझदारी और न्यायका ठेकेदार मानकर इसपर विश्वास करे। हमारे शासक आज अपनी आलोचना वर्दाश्वत नहीं कर सकते। उन्हें अपने निर्णयपर अत्यधिक भरोसा है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान संकट कालमें किसीकी सहायताके बिना ही सामना करनेका उनको अत्यधिक गर्व है।

जनतामें आतंक है

लेकिन मुझे सबसे अधिक दुःख यह देखकर हुआ है कि आज अधिकांश जनतापर कांग्रेसके अधिकारियोंका आतंक बैठ गया है। जो कांग्रेसजन-कांग्रेस और सरकार, दोनोंमें उच्च पदपर, हैं, उनसे जनता बहुत डरती है। सम्भवतः वह कांग्रेसजनोंसे अधिक भय खाती है, क्योंकि वे अपने असीम अधिकारोंसे उसे हानि पहुँचाना चाहते हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्तिके पूर्व का प्यार आज भय और घृणामें बदल गया है। इस भयका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और जनताकी गतिविधि पगु हो गयी है। महात्माजीकी शिक्षाओंका सार था निर्भयता। लेकिन आज तो उनके तथाकथित अनुयायी ही जनतामें भय उत्पन्न करनेके उत्तरदायी हो रहे हैं। और जहाँ निर्भयता नहीं वहाँ प्रजातन्त्र कभी सफल नहीं हो सकता। सीधी-सादी बात तो यह है कि आज जनता स्वतन्त्रताकी आभाका अनुभव नहीं करती। फलतः राजनीतिक असफलता सामने है, जो क्रमशः राजनीतिक असन्तोष और उदासीनतामें परिणत होती जा रही है।

इन सारी बातोंका एक ही कारण है कि आज कांग्रेसकी राजनीति गन्दी हो गयी है। अब राजनीति अधिकार और धन-प्राप्तिका एक साधन मात्र बन गयी है। कांग्रेसकी राजनीति आज पहलेकी तरह जनताको नये सत्योंका दर्शन करानेके लिए संघर्ष नहीं करती, ससारको पहलेसे अच्छा बनानेके लिए अब वह प्रयत्न नहीं कर रही है। कांग्रेसजनोंकी सामाजिक चेतना मन्द पड़ गयी है और ऐसा लगता है कि कांग्रेसकी आत्माको लकवा मार गया है और यह इसलिए हुआ है कि कांग्रेस आज आन्दोलन नहीं रह गयी।

जनताको अब पहलेकी तरह इससे प्रेरणा नहीं मिलती। इससे केवल उन्ही लोगोंको प्रेरणा मिलती है जो इसकी सेवाओंके बलपर मन्त्रियों और सभा सचिवोंके पदपर पहुँच गये हैं और यह भी इसलिए क्योंकि उनको भ्रम है कि वे जनताकी सेवा कर रहे हैं।

इसलिए या तो कांग्रेसको खत्म हो जाना चाहिये या उसे अपना कायाकल्प करना चाहिये। देशका सबसे बड़ा राजनीतिक सगठन होनेके कारण इसका उत्तरदायित्व भी महान् है। उसका कर्तव्य है कि यह जनतामें गौरव और निर्भयताकी नयी भावना भरे और एक नयी दिशाका निर्देश करे। आजकी यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि जनताको यह नया प्रकाश मिला तो उसकी शक्तका रुद्ध स्रोत मुक्त होकर वह उठेगा और एक नये समाजके निर्माणके लिए शक्तिशाली सघटित प्रयत्नकी सम्भावना उपस्थित हो जायगी। लेकिन आजकी स्थितिसे तो निराशा ही होती है। यह वातावरण हमारे उन सभी सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्योंको नष्ट कर देगा, जिनको अपना लक्ष्य बनाकर

हम बहुत दिनोंसे जंगलकी काँटोभरी राहपर चलते रहे हैं। यह विल्कुल स्पष्ट है कि आजकी स्थितिमें राजनीति जीवित नहीं रह सकती।

इस अप्रिय स्थितिको सुधारनेके लिए क्या वे लोग कुछ करेंगे जो ऐसा कर तो सकते हैं, परन्तु करना नहीं चाहते ? या उनकी अँगोपर पट्टी बँधी है जो वे बदलती हुई हालतोको नहीं देख पाते ? अथवा वे चाहते हैं कि नियति ही अपना निश्चित पथ ग्रहण करे ?

सन् ४२ की क्रान्तिका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ'

आज १५ अगस्त है। आप सोचते होंगे कि यह दिवस हम और कांग्रेसी साथ-साथ क्यों नहीं मना रहे हैं। उत्तर स्पष्ट है। आज हमारा और कांग्रेसका रास्ता अलग-अलग है। ब्रिटिश साम्राज्यवादमें लड़नेमें हम मंवे साथ थे। किन्तु कांग्रेसमें ६ अगस्त सन् १९४२ की प्रतिज्ञाको भुला दिया। इस प्रतिज्ञाका महत्त्व बहुत ज्यादा है। इस प्रतिज्ञामें तीन महत्त्वपूर्ण चीजें हैं—(१) आजादी, (२) किसान-मजदूर राज और (३) विश्व-वन्धुत्व। किन्तु देशके नये वन रहे विधानमें किसान-मजदूरों अथवा मेहनतकोंके हाथमें सत्ता जानेकी कोई गुञ्जाइश नहीं है। राजनीतिक आजादी मिल जानेपर कांग्रेसके नेताओंने अपने कामको समाप्त समझ लिया। किन्तु वास्तवमें अभी ४२ का आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक आजादी अवश्य मिल गयी है किन्तु नये समाजका निर्माण और आर्थिक विपमताको समाप्त कर समता स्थापित करना अभी जेप है।

उपर्युक्त उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए सन् ४२ में भारतकी जनताने महान् बलिदान किये। कुछ समय बाद यह विद्रोह दब गया मालूम पड़ा। वास्तवमें विद्रोह दबा नहीं था, उसपर राख अवश्य पड़ गयी थी। जनता अवसरकी ताकमें थी। नेताओंके जेलसे छूटनेपर यह स्पष्ट हो गया था।

गत १५ अगस्तको हमें जो आजादी मिली वह हमारी शक्तकी वजहसे ही प्राप्त नहीं हुई। उसका एक कारण ब्रिटेनकी शक्तिका क्षीण होना भी था। शक्ति क्षीण होनेके कारण इतने बड़े साम्राज्यपर काबू बनाये रखना उनके लिए कठिन था। अतः उन्होंने अपने स्वार्थोंको दृष्टिमें रखकर ही समझौता किया। इस समझौतेमें भी उन्होंने हमें दुर्बल बनाया। देशका विभाजनकर राष्ट्रीयताका नाश किया और उसे साम्प्रदायिकताकी भट्टीमें झोंक दिया। देश सभी नैतिक मूल्योंको भूल गया। वर्तमान युग विज्ञान और विश्ववन्धुत्वका है। इस परिवर्तनशील युगमें हमें नये सामाजिक मूल्य अपनाने होंगे। जो देश उन्हें नहीं अपनायेगा उसका पतन निश्चित है।

आज स्थिर स्वार्थवाले और पूँजीपति कांग्रेसपर प्रभुत्व बढ़ानेका उपक्रम कर रहे हैं। इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। एण्गिआई देशोंके सम्मेलनके अवसरपर यह

१. लखनऊ सोशलिस्टपार्टीके तत्वावधानमें हुई सार्वजनिक सभामें दिये हुए भाषण-का सारांश।

आशा वैधी थी कि भारत एशियाका नेतृत्व करेगा । प्राचीन कालमें भी भारतने एशियाका नेतृत्व किया था । यह नेतृत्व हमारी सस्कृति और नैतिकताके कारण ही सम्भव हो सका था । प्राचीन भारतने दुनियामें प्रभुत्व स्थापित करनेकी कामना नहीं की । उसने सदैव एक नया सन्देश दिया । एशियाके गुलाम देशोंसे सहानुभूति रखनेके कारण भारत आज भी एशियाका गुरु बन सकता था । एशियाके देश यह चाहते भी थे । किन्तु आज स्थिति बदल गयी है । एशियाई देश देखते हैं कि आप अपने घरकी समस्याएँ ही हल नहीं कर सकते । फिर एशियाके नेतृत्वका सवाल कहाँ ?

हमारे लिए यह अत्यधिक लज्जाकी बात थी कि अपने उच्च आदर्शोंको भूलकर हम चर्वरता और साम्प्रदायिकताका गन नृत्य करे । आज जनतन्त्रका मूल्य नहीं समझा जा रहा है । विरोधी दलका मुँह बन्द कर साम्प्रदायिकताका राज लादा जा रहा है । यह मार्ग पतनका है ।

हमें सन् ४२ का मार्ग नहीं भूलना है । आज कांग्रेसके नेताओंने उस मार्गको भुला दिया है । इन नेताओंका विचार है कि हमारी लड़ाई समाप्त हो गयी, यह समय भोगका है, सरकारी पदोंपर रहकर ही जनताकी सेवा सम्भव है । वर्तमान अवस्थामें जनताकी शक्ति कैद है, उसको बाहर निकलनेका मौका नहीं मिलता । हमारी सरकारें जनताके सहयोगकी उपेक्षा कर फौज, पुलिस और सिविल सर्विसके बूतेपर शासन कर रही हैं । देशभरकी जनतामें आतंक फैला हुआ है । गांधीजीने जनताको निर्भय बनना सिखाया था किन्तु कांग्रेसी राजमें ही जनता दस्त है । गत चुनावोंके अवसरपर एक वोटरने मुझसे कहा था कि आज न वोट देनेकी आजादी है, न मरनेकी । ऐसी हालतमें जनतन्त्र चल नहीं सकता । जो जनता पहले कांग्रेसके प्रति श्रद्धा रखती थी वही आज उससे डरी हुई है ।

कांग्रेसी सरकारें विरोधी दलकी आवश्यकता नहीं समझती । विरोधी दलको विदेशी चीज और भारतीय सस्कृतिके विरुद्ध बताया जाता है । ये ही सरकारें आँख मूंदकर विदेशी विधानोंकी नकल कर रही हैं । क्या यहाँ भारतीय सस्कृतिसे विरोध नहीं होता ? जनतन्त्रकी सफलताके लिए अंग्रेज विरोधी दलको आवश्यक समझते हैं ।

आज समाजवादको भी विदेशी बताया जा रहा है । ऐसे लोगोंसे मैं पूछता हूँ कि पूँजीवाद भी तो बाहरसे आया है । वह भी तो विदेशी है । फिर उसका विरोध क्यों नहीं ? अगर आपको विदेशी चीजोंसे ही डर है तो पूँजीवादका नाश क्यों नहीं करते ? पूँजीवादके अभावमें समाजवादकी आवश्यकता ही नहीं रहती । यदि पूँजीवादको समाप्त नहीं किया जाता तो समाजवादी आन्दोलनको भी नहीं रोका जा सकता ।

संस्कृतिका प्रश्न

भारतीय सस्कृतिको समझना अत्यधिक कठिन है । बिना समझे उसकी असामयिक दुहाई देना व्यर्थ है । जीवन और सस्कृति परिवर्तनशील हैं । किसी भी देशके लिए ताजे पानीकी भाँति नवीन संस्कृतिकी आवश्यकता होती है । अन्यथा जीवन-प्रवाह

हम बहुत दिनोंसे जंगलकी काँटोभरी राहपर चलते रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आजकी स्थितिमें राजनीति जीवित नहीं रह सकती।

इस अप्रिय स्थितिको सुधारनेके लिए क्या वे लोग कुछ करेंगे जो ऐसा कर तो सकते हैं, परन्तु करना नहीं चाहते ? या उनकी आँखोंपर पट्टी बँधी है जो वे बदलती हुई हालतोंको नहीं देख पाते ? अथवा वे चाहते हैं कि नियति ही अपना निश्चित पथ ग्रहण करे ?

सन् ४२ की क्रान्तिका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ^१

आज १५ अगस्त है। आप सोचते होंगे कि यह दिवस हम और कांग्रेसी साथ-साथ क्यों नहीं मना रहे हैं। उत्तर स्पष्ट है। आज हमारा और कांग्रेसका रास्ता अलग-अलग है। ब्रिटिश साम्राज्यवादसे लड़नेमें हम संव साथ थे। किन्तु कांग्रेसने ६ अगस्त सन् १९४२ की प्रतिज्ञाको भुला दिया। इस प्रतिज्ञाका महत्त्व बहुत ज्यादा है। इस प्रतिज्ञामें तीन महत्त्वपूर्ण चीजें हैं—(१) आजादी, (२) किसान-मजदूर राज और (३) विश्व-वन्धुत्व। किन्तु देशके नये वन रहे विधानमें किसान-मजदूरों अथवा मेहनतकशोंके हाथमें सत्ता जानेकी कोई गुञ्जाइश नहीं है। राजनीतिक आजादी मिल जानेपर कांग्रेसके नेताओंने अपने कामको समाप्त समझ लिया। किन्तु वास्तवमें अभी ४२ का आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ है। राजनीतिक आजादी अवश्य मिल गयी है किन्तु नये समाजका निर्माण और आर्थिक विषमताको समाप्त कर समता स्थापित करना अभी शेष है।

उपर्युक्त उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए सन् ४२ में भारतकी जनताने महान् बलिदान किये। कुछ समय बाद यह विद्रोह दब गया मालूम पड़ा। वास्तवमें विद्रोह दबा नहीं था, उसपर राख अवश्य पड़ गयी थी। जनता अवसरकी ताकमें थी। नेताओंके जेलसे छूटनेपर यह स्पष्ट हो गया था।

गत १५ अगस्तको हमें जो आजादी मिली वह हमारी शक्तकी बजहसे ही प्राप्त नहीं हुई। उसका एक कारण ब्रिटेनकी शक्तका क्षीण होना भी था। शक्ति क्षीण होनेके कारण इतने बड़े साम्राज्यपर काबू बनाये रखना उनके लिए कठिन था। अतः उन्होंने अपने स्वार्थोंको दृष्टिमें रखकर ही समझौता किया। इस समझौतेमें भी उन्होंने हमें दुर्बल बनाया। देशका विभाजनकर राष्ट्रीयताका नाश किया और उसे साम्प्रदायिकताकी भट्टीमें झोक दिया। देश सभी नैतिक मूल्योंको भूल गया। वर्तमान युग विज्ञान और विश्ववन्धुत्वका है। इस परिवर्तनशील युगमें हमें नये सामाजिक मूल्य अपनाने होंगे। जो देश इन्हें नहीं अपनायेगा उसका पतन निश्चित है।

आज स्थिर स्वार्थवाले और पूँजीपति कांग्रेसपर प्रभुत्व बढ़ानेका उपक्रम कर रहे हैं। इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। एशियाई देशोंके सम्मेलनके अवसरपर यह

१. लखनऊ सोशलिस्टपार्टीके तत्वावधानमें हुई सार्वजनिक सभामें दिये हुए भाषण-का सारांश।

आशा वैधी थी कि भारत एशियाका नेतृत्व करेगा । प्राचीन कालमें भी भारतने एशियाका नेतृत्व किया था । यह नेतृत्व हमारी सस्कृति और नैतिकताके कारण ही सम्भव हो सका था । प्राचीन भारतने दुनियामें प्रभुत्व स्थापित करनेकी कामना नहीं की । उसने सदैव एक नया सन्देश दिया । एशियाके गुलाम देशोंसे सहानुभूति रखनेके कारण भारत आज भी एशियाका गुरु बन सकता था । एशियाके देश यह चाहते भी थे । किन्तु आज स्थिति बदल गयी है । एशियाई देश देखते हैं कि आप अपने घरकी समस्याएँ ही हल नहीं कर सकते । फिर एशियाके नेतृत्वका सवाल कहाँ ?-

हमारे लिए यह अत्यधिक लज्जाकी बात थी कि अपने उच्च आदर्शोंको भूलकर हम बर्बरता और साम्प्रदायिकताका गगन नृत्य करें । आज जनतन्त्रका मूल्य नहीं समझा जा रहा है । विरोधी दलका मुँह बन्द कर साम्प्रदायिकताका राज लादा जा रहा है । यह मार्ग पतनका है ।

हमें सन् ४२ का मार्ग नहीं भूलना है । आज कांग्रेसके नेताओंने उस मार्गको भुला दिया है । इन नेताओंका विचार है कि हमारी लड़ाई समाप्त हो गयी, यह समय भोगका है, सरकारी पदोंपर रहकर ही जनताकी सेवा सम्भव है । वर्तमान अवस्थामें जनताकी शक्ति कैद है, उसको बाहर निकलनेका मौका नहीं मिलता । हमारी सरकारें जनताके सहयोगकी उपेक्षा कर फौज, पुलिस और सिविल सर्विसके बूतेपर शासन कर रही हैं । देशभरकी जनतामें आतंक फैला हुआ है । गांधीजीने जनताको निर्भय बनना सिखाया था किन्तु कांग्रेसी राजमें ही जनता त्रस्त है । गत चुनावोंके अवसरपर एक वोटरने मुझसे कहा था कि आज न वोट देनेकी आजादी है, न मरनेकी । ऐसी हालतमें जनतन्त्र चल नहीं सकता । जो जनता पहले कांग्रेसके प्रति श्रद्धा रखती थी वही आज उससे डरी हुई है ।

कांग्रेसी सरकारें विरोधी दलकी आवश्यकता नहीं समझती । विरोधी दलको विदेशी चीज और भारतीय सस्कृतिके विरुद्ध बताया जाता है । ये ही सरकारें आँख मूँदकर विदेशी विधानोंकी नकल कर रही हैं । क्या यहाँ भारतीय सस्कृतिसे विरोध नहीं होता ? जनतन्त्रकी सफलताके लिए अंग्रेज विरोधी दलको आवश्यक समझते हैं ।

आज समाजवादको भी विदेशी बतायाकर उसका विरोध किया जाता है । ऐसे लोगोंसे मैं पूछता हूँ कि पूँजीवाद भी तो बाहरसे आया है । वह भी तो विदेशी है । फिर उसका विरोध क्यों नहीं ? अगर आपको विदेशी चीजोंसे ही बैर है तो पूँजीवादका नाश क्यों नहीं करते ? पूँजीवादके अभावमें समाजवादकी आवश्यकता ही नहीं रहती । यदि पूँजीवादको समाप्त नहीं किया जाता तो समाजवादी आन्दोलनको भी नहीं रोका जा सकता ।

संस्कृतिका प्रश्न

भारतीय सस्कृतिको समझना अत्यधिक कठिन है । बिना समझे उसकी असामयिक दुहाई देना व्यर्थ है । जीवन और संस्कृति परिवर्तनशील हैं । किसी भी देशके लिए ताजे पानीकी भाँति नवीन सस्कृतिकी आवश्यकता होती है । अन्यथा जीवन-प्रवाह

असम्भव हो जाता है। मैं जीवन-प्रवाहको बढ़ानेवाली संस्कृतिका ही उपासक हूँ, मध्य-युगीन संस्कृति गुलामीका उपासक नहीं। भारतकी प्राचीन संस्कृतिका आधार विश्व-वन्धुत्व, श्रेष्ठ गुणोंको ग्रहण करना और दुर्गुणोंका परित्याग करना है। इसी संस्कृतिकी हमें रक्षा करनी है। स्थिति बदलनेपर जीवनके नये मूल्य अपनाने होते हैं।

वर्तमान युग जनतन्त्र और समाजवादका युग है। रूस और पूर्वी यूरोपके देशोंमें समाजवादी आन्दोलनको लगभग पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आज इंग्लैंडकी स्थिति भी यही है। वहाँ मजदूर दलकी सरकार है। आजसे ५० वर्ष पूर्व समाजवादके आन्दोलनको मूर्खता कहा जाता था। आज दुनियाके लगभग सभी देशोंमें नवीन रास्ते अपनाये जा रहे हैं। अधिकांश देशोंमें समाजवादी दलोंके सहयोगके बिना शासन चलाना असम्भव हो गया है। समाजवादका एकमात्र शक्तिशाली विरोधी अमेरिका आज विश्वके लिए अभिशाप बन रहा है।

हमारे देशमें कांग्रेससे समाजवादकी आशा की जाती थी, किन्तु अब यह आशा धूलमें मिल गयी है। कांग्रेसकी प्रतिज्ञाएँ अत्यधिक मुन्दर हैं, लेकिन कोरी प्रतिज्ञासे काम नहीं चलता। हमें प्रत्येक सगठनके सामाजिक आधारको देखना होगा। आज यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसका सामाजिक आधार पूँजीवाद है। अतः उससे समाजवादकी स्थापना नहीं हो सकती। आज जमींदारी समाप्त हो जानेके बाद यदि जमींदार एक पार्टी बनावे और पूँजीवादको समाप्त करनेका नारा लगावे तो क्या हम उनके नारेपर विश्वास कर सकते हैं? ऐसे लोगोंसे पूँजीवादके नाशकी आशा नहीं की जा सकती।

कांग्रेस आज निर्जीव हो गयी है। आन्दोलन और नवीन आदर्शोंके विरुद्ध वह जनताके मार्गमें रोड़े अटका रही है। वर्तमान स्थितिमें कांग्रेस सरकारका नियन्त्रण करनेके बजाय कांग्रेस स्वयं सरकारसे नियन्त्रित होती है। पिछले चुनावोंमें जमींदारों और पूँजीपतियोंने खुले दिलसे कांग्रेसकी मदद की है। वे धीरे-धीरे कांग्रेसमें घुम रहे हैं। वे जानते हैं कि उन्हें अन्यत्र शरण नहीं मिल सकती। कांग्रेस उनके प्रभावमें आती जा रही है। अब ऐसे लोगोंसे किसान-मजदूर राज्यकी स्थापना कैसे हो सकती है?

स्वस्थ विरोधी दलके अभावमें शासन निरंकुश और भ्रष्ट हो जाता है। जनतन्त्रको सफल बनानेके लिए हमें नयी परम्परा कायम करनी होगी। सोशलिस्ट पार्टीने कांग्रेससे अलग होकर और विरोधी दलकी तरह कार्य करनेका निश्चय कर देशका अत्यधिक उपकार किया है। विभिन्न साम्प्रदायिक दल अपने रूप बदलकर कांग्रेसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेसके छोटे-छोटे उग्र दल समाजवादी पार्टीमें सम्मिलित हो रहे हैं। कांग्रेस अब राष्ट्रीय संस्था नहीं रह गयी है। यह एक सबसे बड़ा और पुराना राजनीतिक दल अवश्य है। कांग्रेसमें भी कुछ समाजवादी हैं, किन्तु अल्पसंख्यक होनेके कारण उनकी बात वहाँ नहीं सुनी जाती।

राष्ट्र-निर्माणके लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज जनताका सहयोग है। गरीब जनता—किसान-मजदूर—भी त्याग कर सकती है। किन्तु यह तभी सम्भव है जब उसे नवीन सामाजिक ढाँचेमें उचित स्थान प्राप्त हो। रूसकी राज्यक्रान्तिके बाद वहाँकी

सरकारने विदेशी सहायताके बिना केवल जनतासे आश्चर्यजनक उन्नति कर डाली । रूसकी जनता समझती थी कि उसके परिश्रमसे चन्द व्यक्ति ही मौज न करेगे । राष्ट्रकी सम्पत्तिको उत्पन्न करनेवाला किसान-मजदूर सब कुछ कर सकता है । इसके लिए उसका राज्य कायम होना जरूरी है । जनतामे विश्वास खोना आत्मविश्वास खोना है । आकस्मिक परिवर्तन सम्भव भले ही न हो, किन्तु पुराने ढाँचेके रहते थोड़ा परिवर्तन भी नहीं हो सकता । कांग्रेसका सामाजिक आधार उसे आगे नहीं बढ़ने देता ।

इतना ही नहीं, वह तो आपको पीछेकी ओर खींच रहा है । सरकारने पूँजीपतियोंको १० वर्षतक निर्विघ्न शोषणका पट्टा दे दिया है । उसके बाद राष्ट्रीयकरण करनेकी बातें व्यर्थ हैं । समाजवादके बिना बेकारीकी समस्याका हल भी सम्भव नहीं है । भारतमे समाजवादी पार्टी ही समाजवादकी स्थापना कर सकती है ।

एक बात और है । हमे राज्य और सरकारके अन्तरको भली भाँति समझ लेना चाहिये । उपर्युक्त दोनों चीजे पृथक् हैं । राज्य स्थायी होता है, किन्तु सरकार बदलती रहती है । उसका बदलना जरूरी होता है । उसे हम बदलेगे भी ।

जो लोग सन् ४२ की प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं उनको मैं सोशलिस्ट पार्टीमे सम्मिलित होनेके लिए निमन्त्रण देता हूँ । हम केवल पुरानी पूँजीके आधारपर अपना कार्य नहीं चलाना चाहते । उच्च आदर्शमे विश्वास करनेवाले सभी शिक्षित व्यक्तियोंका हम स्वागत करते हैं । पार्टीका संचालन पूर्णतः जनतन्त्रात्मक ढंगसे होगा ।^१

पटना अधिवेशन^२

साथियो,

यह बहुत ही खेदका विषय है कि हमारे मनोनीत सभापति श्री यूसुफ मेहरअली साहब अपनी बीमारीके कारण इस ऐतिहासिक महत्त्वके अधिवेशनकी सदस्यता करने नहीं आ सके । इस मौकेपर हमारे विचार विमर्शका पथ-प्रदर्शन तथा हमारे कार्योंका संचालन करनेके लिए हमे उनकी सख्त जरूरत थी । उनके परिपक्व तथा सतुलित विचार, समाजवादी आदर्शोंके प्रति उनकी अटल निष्ठा, उनकी जबरदस्त संगठन शक्ति और उनका मोहक व्यक्तित्व—इन सभी गुणोंने मिलकर भारतवर्षकी राजनीतिमे उनका एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान बना दिया है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि निरन्तर अस्वस्थताके कारण वे अपनी बहुमूल्य सेवाएँ पार्टीको समर्पित करनेमे असमर्थ हैं । फिर भी बड़ी ही उत्सुकतासे हम आशा करते हैं, और यही हमारी शुभकामना है कि वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जायेंगे और इस देशमे समाजवादी लक्ष्यकी स्थापनामे बहुमूल्य देन दे सकेंगे ।

उनकी अनुपस्थितिमे मुझे उनका स्थान ग्रहण करनेके लिए कहा गया है । दूसरी

१. 'संघर्ष' २३-अगस्त, १९४८ ई०

२. सभापतिके पदसे दिया गया भाषण (१९४९) ।

वार पार्टी-सम्मेलनकी सदरत करनेको बुलाया जाना तथा साथी मेहरअली साहबका प्रतिनिधि बनना, मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन उनके स्थानकी पूर्ति पूर्ण रूपसे कोई भी नहीं कर सकता और इस प्रकार मुझे जो सम्मान प्रदान किया गया है उससे मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है। मैं इस महान् गौरवके पदको स्वीकार करनेमें अपनेको कमजोर पा रहा हूँ, विशेषकर ऐसे समयमें जब अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित हैं जिन्हें हमें हल करना है। फिर भी मेरी कर्तव्यभावना मुझे इस सम्मानपूर्ण पदको स्वीकार करनेको बाध्य करती है, और मैं इस आशामें इसे स्वीकार करता हूँ कि आप सम्मेलनके कार्य-संचालनमें मुझे अपना हार्दिक तथा उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

यह वर्ष हमारी पार्टीके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण वर्ष है। एक स्वतन्त्र पार्टीके रूपमें अपने अस्तित्वका हमने पहला साल ही अभी पूरा किया है। पिछले साल नासिकमें हमने अपनी उस पितृ-संस्थासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेका महत्त्वपूर्ण निश्चय किया था, जिसकी पूरे चौदह वर्षोंतक हमने वफादारीके साथ सेवा की थी। उसके बाद कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जो हमें उस निश्चयपर पुनर्विचार करनेके लिए प्रेरित करे। इसके विपरीत, ज्यों-ज्यों दिन व्यतीत होते जाते हैं, हमें ऐसे ताजे प्रमाण मिलते जाते हैं जो इस बातको सिद्ध करते हैं कि हमारा वह निश्चय विलकुल सही तथा आवश्यक था। अपनी एक स्वतन्त्र मत्ता स्थापित कर लेनेके बादसे हमारी जिम्मेदारियों तथा हमारे कर्तव्योंमें कई गुना वृद्धि हो गयी है। आपनोगोमें बहुतसे लोगोंको, जो नासिकमें उपस्थित थे, याद होगा कि मैंने वहाँ अपने भाषणमें इस बातकी तरफ लोगोंका ध्यान आकर्षित किया था कि सम्भव है आनेवाले कुछ दिनोंतक हम विलकुल अन्धकारमें पड़ जायें। हमारी बढ़ी हुई प्रतिष्ठा और प्रभावका एक कारण यह था कि हम बहुत दिनोंसे कांग्रेससे बँधे चले आते थे। हमें कांग्रेसके अन्दर एक आलोचक दल समझा जाता था जिसका प्रमुख कार्य कांग्रेसको क्रान्तिकारी मार्गसे विचलित होकर एक विशुद्ध पार्लियामेण्टरी पार्टी बननेसे रोकना था। हमने इस कार्यको बड़ी सफलतापूर्वक सम्पादित किया, यहाँतक कि हमारे नेताओंसे कुछ, जिन्होंने १९४२ के संघर्षमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाग लिया था, देशके नायक बन गये और उनसे पार्टीकी प्रतिष्ठा और जनप्रियता बहुत ही बढ़ गयी। लेकिन जब हम एक विरोधी पार्टीके रूपमें कांग्रेससे बाहर निकल आये, यह सारी चीजें बदल गयीं। बहुतसे लोगोंने तो हमारे निश्चयके महत्त्वको समझा ही नहीं। वे सन्दिग्ध और कर्तव्य-विमूढ़ हो गये और इस विचित्र दृश्यको देखकर स्तब्ध रह गये कि समाजवादी-पार्टी कांग्रेस-पार्टीकी विरोधी पार्टी बनकर उससे बाहर निकल आयी और उसने कांग्रेसके नेतृत्वको चुनौती दे दी। कांग्रेसके लोगोंने भी जानबूझकर हमें गलत रूपमें प्रदर्शित करनेकी कोशिश की। उन्होंने हमपर एक ऐसे गाढ़े समयमें कांग्रेसकी पीठमें छुरा भोकेनेका दोषारोपण किया जब कि सम्पूर्ण देश सकटकालीन स्थितिसे गुजर रहा था। कुछ लोगोंने हमपर पितृघातका दोष लगाया। हमारे विरुद्ध तरह-तरहकी गालियोंका प्रयोग किया गया और हमको अत्यन्त विकृत रूपमें दिखानेकी चेष्टा की गयी। अतएव हमको जनताको

यह समझानेमें कि हमने यह कदम क्यों उठाया, बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा । जनतामें फैला हुआ बहुत-सा भ्रम इस प्रयत्नसे दूर हुआ । किन्तु फिर भी बहुतसे लोग हमारे विरोधियोंके भुलावेमें आ गये और बहुत दिनोंतक आश्वस्त नहीं हो सके । आरम्भमें हमारी प्रतिष्ठाको एक धक्का लगा । हमारी नीयतपर तरह-तरहके आक्षेप किये गये । कहा गया कि हमलोग असन्तुष्ट पद-लोभी हैं जो अतृप्तिके कारण विरोध-पक्षके नये रूपमें सामने आये हैं । युक्तप्रान्तीय धारासभाके उपनिर्वाचनोंमें राजनीतिक प्रश्नोंपर पर्दा डाला गया । अप्रासंगिक प्रश्नोंको उस्थित करके और जनताकी धार्मिक भावनाओंको उद्बुद्ध करके निर्वाचकोंको भ्रममें डालनेकी कांग्रेसजनोंने पूरी चेष्टा की । जनताकी तर्कशक्ति और बुद्धिके स्थानपर परम्परा-जनित विश्वासो, भावनाओं और रूढियोंका उद्बोधन किया गया । व्याख्यान-मंचके हथकण्डोंका प्रयोग किया गया और 'धर्म तथा सस्कृतिपर विपत्ति' के नारे लगाये गये । कांग्रेसी उम्मेदवारोंके पक्षमें गांधीजीकी आत्माका बार-बार आह्वान किया गया । निर्वाचकोंको प्रभावित करनेके लिए शासन-यन्त्रका प्रयोग किया गया और अनेक भ्रष्टाचारोंका आश्रय लिया गया । इसके बाद यदि चुनावमें हमारी गहरी हार हुई तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं । यह सच है कि इन उपचुनावोंके परिणामस्वरूप हमारे साथियोंको एक गहरा धक्का लगा, किन्तु यह भी सच है कि वे बहुत जल्द इसके प्रभावोंसे मुक्त हो गये । जनताकी प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकारकी हुई । कुछ लोगोंने वैधानिक तरीकोंमें विश्वास ही खो दिया, कुछकी यह राय थी कि मतदानका तरीका बदलना चाहिये और साथ ही कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टीकी शक्तिमें विश्वास खो दिया । पहले उन्होंने पार्टीकी शक्ति और उसके प्रभावके सम्बन्धमें अतिरजित धारणा बना ली थी । ऐसी ही धारणा सोशलिस्ट पार्टीके, विशेषकर युक्तप्रान्तके, कार्यकर्त्ताओंकी थी । किन्तु उन्हें यह देखकर बड़ा धक्का लगा कि परिणाम उनकी आशा और अनुमानके विपरीत हुआ । उनका अनुमान गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने स्थितिके एक ही अंगको अत्यधिक महत्त्व दिया था, अर्थात् कांग्रेससे जनताके बढ़ते हुए असन्तोष और अलगावको । सोशलिस्ट पार्टीको सगठित होनेका समय भी नहीं मिला था कि चुनावकी घोषणा हो गयी । मैं चुनाव-सम्बन्धी असफलताका मुख्य कारण कार्यकर्त्ताओंकी कमी और चुनावके सगठनात्मक कार्यकी अनुभवहीनताको समझता हूँ । यद्यपि खोयी हुई शक्ति धीरे-धीरे पुनः प्राप्त की जा रही है और स्थितिमें बहुत कुछ सुधार हुआ है, जैसा कि टाउन एरियाके चुनावों और बम्बईमें कारपोरेशन तथा असेम्बलीके उपचुनावोंके परिणामसे प्रकट होता है—फिर भी इन दोनों दृष्टियोंकी पूर्ति नहीं हुई और वे अब भी हमें परेशान कर रही हैं । मैं समझता हूँ कि जबतक ये दोनों कारण वने रहेंगे, हमारी गति तेज नहीं हो सकती । मुझे इस बातमें किञ्चिन्मात्र सन्देह नहीं है कि देशकी स्थिति पार्टीके अत्यन्त अनुकूल है और यदि हम अवसरसे लाभ उठाना जानते हो तो हम सरलतापूर्वक बड़ी सफलताएँ प्राप्त कर सकते हैं । यो भी चुनाव-सम्बन्धी सारी बातोंका हिसाब लगानेपर मेरा विश्लेषण इतना निराशाजनक नहीं है जितना कि वह ऊपरसे दिखायी देता है । सब प्रकारकी प्रारम्भिक कठिनाइयाँ होते हुए

भी हमने कुछ क्षेत्रोंमें ३८, ४२ और ४३ प्रतिशत वोट पाये । दूसरे क्षेत्रोंमें हमारे उम्मेदवारोंको २४ से ३० प्रतिशततक वोट मिले । बहुत थोड़े क्षेत्रोंमें ही हमारी हार अधिक हुई और हमारी जमानतें जप्त हुई । अवश्य ही यह कोर्ट बुरा परिणाम नहीं रहा और यदि मतदानकी वही प्रणाली यहाँ भी होती जो बम्बई नगरमें है, तो अवश्य ही हमने उतनी ही प्रतिशत सीटें जीती होती जितनी कि बम्बईमें हमें मिली । कोई भी वस्तु सफलताकी भाँति सफल, नहीं होती—हमारा विश्लेषण कितना ही गम्भीर क्यों न हो—इसमें सन्देह नहीं कि चुनावमें हमारी पराजयका उस समय जनताके मनपर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा । इस सक्षिप्त सिंहावलोकनमें इस वर्षकी मुख्य घटनाका उल्लेख आवश्यक है । इसकी बहुत चर्चा हुई है और इसकी प्रतिक्रिया सम्पूर्ण देशपर हुई । फिर भी हमारी हार पार्टी-कार्यकर्त्ताओंको हतोत्साह न कर पायी । उलटे और भी सक्रिय कार्यकी प्रेरणा इसने प्रदान की और हमें अपने बलावलका सही अन्दाजा हुआ । अपनी त्रुटियोंके विषयमें हम सचेत हो गये और हमने समझा कि हमारा प्रभाव और सम्मान कांग्रेसके साथ रहनेमात्रसे अत्यधिक बढ़ा हुआ था । इस सबकी भी हमें अत्यन्त आवश्यकता थी और जहाँ हमारी हानि केवल क्षणिक रही, वहाँ एक दृष्टिसे हमारे पृथक् होनेके उपरान्त कांग्रेसकी स्थायी क्षति हुई । उसने सदाके लिए अपना राष्ट्रीय स्वरूप खो दिया । आज उसकी हैसियत एक राजनीतिक पार्टीकी ही रह गयी है और अब वह भारतीय जनताका एकमात्र प्रतिनिधि होनेका दावा नहीं कर सकती । सिद्धान्तोंका संघर्ष बहुत आगे बढ़ गया है । मजदूर-आन्दोलन अपनी एकता खो चुका है । कांग्रेस, जिसके लिए पहले मजदूर और किसान-संगठनोंका कोई उपयोग न था, आज सरकारके हितमें इन संगठनोंके नियन्त्रणकी आवश्यकता समझती है । इस प्रकार मजदूर-वर्ग तीन सगठनोंमें विभक्त हो चुका है और अब मजदूर-संगठनोंको सरकार और राजनीतिक पार्टियोंसे स्वतन्त्र नहीं रखा जा सकता । यही दृश्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें भी प्रकट हो रहा है । एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो सरकार और राजनीतिक पार्टियों तथा सिद्धान्तोंसे मुक्त हो, राजनीतिक वास्तविकताओंसे मेल नहीं खाता है और इसीलिए यह विचार कार्यरूपमें नहीं लाया जा सकता ।

कांग्रेसके सत्ताह्वित होनेके साथ कुछ नवीन मनगढन्त सिद्धान्तोंको प्रचारित किया जा रहा है । बहुधा श्रमिकोंके हड़तालके अधिकारको अस्वीकार किया जाता है और कुछ हड़तालकोंको गैर-कानूनी करार देनेके लिए कानून बनाये जा रहे हैं । सरकार और जनताको एक बता दिया जाता है और कहा जाता है कि सरकारद्वारा नियन्त्रित तथा निर्देशित उद्योगों में हड़ताल न होनी चाहिये । भारतीय प्रकृतिके नामपर विरोधपक्ष तथा वैधानिक स्वतन्त्रताकी आवश्यकतातकको अस्वीकार किया जाता है । कांग्रेस सरकारकी पिछलगू हो गयी है और इसलिए सामाजिक संघर्षोंमें अग्रसर होनेकी अपनी स्वतन्त्रता खो चुकी है । आज इसका प्रधान कार्य सरकारके स्वार्थके लिए जन-आन्दोलन रोकना हो गया है । भारतीय आन्दोलन ऊँचे स्तरपर उठना चाहता है, वह सामाजिक और आर्थिक जीवनके नये ढाँचेको पानेके लिए लड़ रहा है । कांग्रेस उग्र नारोंका प्रयोग करती है और कहती है कि

उसका संकल्प एक वर्गविहीन समाजकी स्थापना करना है। कांग्रेसके अध्यक्षने यह भविष्यवाणी भी की है कि अगले पाँच वर्षोंमें रक्तहीन क्रान्तिके द्वारा देश समाजवादी राज्यकी प्राप्ति कर लेगा। किन्तु व्यवहारमें कांग्रेसके ये सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं और जनताको एक नवीन दिशाकी प्रेरणा प्रदान करनेमें वह असफल रही है। जान पड़ता है कि जनतामें अब उसे विश्वास नहीं रहा। जन-आन्दोलनको नया वाना पहनाने और पुनः दीक्षित करनेके लिए स्वयं जन-आन्दोलनकी अपेक्षा उसका विश्वास कानूनमें अधिक दिखायी देता है। इसने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किये हैं और न कोई महत्वका सामाजिक परिवर्तन उपस्थित किया है। यह सच है कि विभाजन-जनित कुछ समस्याओंको, जिनका उसे अकस्मात् सामना करना पड़ा, उसने कुशलतापूर्वक हल करनेकी चेष्टा की है। उसने कुछ दूषित और प्रतिक्रियावादी शक्तियोंको रोका है जिससे उसे पराभूत हो जानेका भय था। किन्तु ये शक्तियाँ बारबार सिर उठानेका प्रयत्न कर रही हैं और यद्यपि इस समय वे दब गयी हैं, तथापि हम अपनेको धोखा देगे, यदि हम यह विश्वास कर बैठे कि उनका सदाके लिए विनाश हो चुका है। उनकी नीचे अब भी सुरक्षित हैं और वे प्रवृत्तियाँ और विचार जिनसे इन शक्तियोंको बल मिलता है अब भी अपरिपक्व युवकोंके चित्तको आकर्षित कर रहे हैं। यह निश्चित है कि वे बार-बार नये वानोंमें प्रकट होती रहेगी, जबतक हम इस विपको सामाजिक जीवनसे निकाल फेंकनेके लिए कुछ ठोस कार्य नहीं करते। इस विपका निवारण करनेके लिए एक शक्तिशाली सांस्कृतिक आन्दोलनकी आवश्यकता है जो मध्ययुगीन अन्धविश्वासके स्थानपर ज्ञान और बुद्धिवादकी प्रतिष्ठा करे। इन प्रतिक्रियावादी शक्तियोंको कांग्रेसमें सम्मिलित होनेका निमन्त्रण देकर खतम नहीं किया जा सकता। यह सोचना कि यदि ये अपना अलग संगठन समाप्त कर कांग्रेसमें मिल जायँ तो इससे कांग्रेसकी शक्तिमें वृद्धि होगी और वह दृढ़ होगी, समस्याको आवश्यकतासे अधिक आसान समझ लेना है। मेरा यह निश्चित विचार है कि यह प्रक्रिया आरम्भ होनेपर कांग्रेस और अधिक विकारग्रस्त हो जायगी। मुख्य प्रश्न तो यह है कि क्या कांग्रेस अपने नये उद्देश्योंकी पूर्तिके विषयमें सच्ची है? सरदार पटेलका कहना है कि वर्तमान सरकार उद्योगधन्धोंके राष्ट्रीयकरणकी योजना कार्यान्वित करनेमें असमर्थ है। यही वास्तविक सत्य है, इसके अलावे अन्य वाते पाखण्ड और कपटाचार हैं; और ऐसी दशामें यह साफ है कि सरकार किसी भी आर्थिक व्यवस्थाकी स्थापनाके लिए कोई समुचित प्रयत्न नहीं करेगी। उसने वस्तुस्थितिको यथावत् बनाये रखनेका निश्चय किया है, और धनी तथा सुविधाप्राप्त वर्गोंको इससे डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं। अतः पूँजीपतियोंकी अपने भविष्यकी चिन्ता या तो वनावटी है या प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताओंके परस्पर-विरोधी और भ्रामक वक्तव्योंसे उत्पन्न हुई है। प्रकट सत्य तो यह है कि कांग्रेस एक सरक्षणशील शक्ति हो गयी है और केवल शुभ घोषणाओंसे उसके स्वरूपको नहीं बदला जा सकता। वर्गविहीन समाजकी स्थापना हवाई वातोंसे नहीं हो सकती। समाजवादी उद्देश्योंकी घोषणाएँ केवल कांग्रेसके वास्तविक रूपको ऊपरसे ढँकनेमें ही सहायक हो सकती हैं। उसकी कथनी और करनीका अन्तर बुद्धिमानोंको धोखा नहीं दे सकता। यह सोचना

गलत है कि कांग्रेसकी उग्र राष्ट्रीयताके गर्भसे समाजवादका जन्म केवल धोपणाओं और व्याख्यानोके सहारे सम्भव होगा । सर्वहारा वर्गको अपने नये ऐतिहासिक कर्तव्यके प्रति, जाग्रत करनेके लिए जोरदार सामाजिक कार्यक्रम और उस वर्गका सगठन आवश्यक है और उसे वर्गविहीन समाजकी स्थापनाके कर्तव्यकी पूर्तिके योग्य बनानेके लिए पर्याप्त शिक्षाकाल आवश्यक होगा । बिना जन-सहयोगके कोई भी क्रान्ति सफल नहीं हो सकती । कांग्रेस जिस मार्गपर चल रही है वह उसे एक अन्धो गलीमें ले जायगा और आजकी महत्वपूर्ण समस्याओको वह हल न कर सकेगी । कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टीके उद्देश्यो और नीतिमें कोई अन्तर नहीं है, इस कथनमें कोई सत्यता नहीं । कुछ शर्तोंको पूरा करनेपर ही कोई सगठन सामाजिक परिवर्तन लानेका समुचित साधन हो सकता है और कांग्रेस इन शर्तोंको पूरा नहीं करती । कांग्रेस उग्र राष्ट्रीयताका प्रतिनिधित्व करती है और अधिनायकवादकी ओर अग्रसर हो रही है । इसी कारण प्रत्येकसे कांग्रेसमें सम्मिलित होनेको कहा जा रहा है । अपनेमें सम्मिलित करनेके पहले किसी समुदायकी विचारधारा और पिछले इतिहासको वह नहीं देखना चाहती । उसकी एकमात्र चिन्ता उन सारे विरोधो और उन स्वतन्त्र सगठनोको समाप्त कर डालनेकी है जो उसके अधिकारका विरोध करनेकी इच्छा कर सके । यदि प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक शक्तियाँ अपना अलग अस्तित्व समाप्त कर उसके अनुशासनमें आ जायँ तो वह सहर्ष उनके साथ शक्तिका वँटवारा कर लेगी । फिर भी यदि यह कार्य सम्पन्न हो गया तो कांग्रेसकी क्या दशा होगी, यह सोचकर हम काँप जाते हैं । तथापि कांग्रेसके अध्यक्ष महोदय यह कहनेका साहस करते हैं कि पाँच वर्षमें वर्गविहीन समाज स्थापित हो जायगा !

मेरे आदरणीय साथी राममनोहर लोहियाने अपने युक्तप्रान्तके चुनावके दौरेमें 'संकटवाद' शब्दका प्रयोग किया है । यह छोटासा शब्द कांग्रेसजनोद्वारा प्रतिदिन होनेवाले भाषणोकी मूल प्रवृत्तिको स्पष्ट करता है । उनका कथन है कि वह नवजात राज्य तरह-तरहके खतरोंसे घिरा हुआ है । अतः प्रत्येक नागरिकको सरकार-भक्त बनना चाहिये और उसे अपना अधिक सहयोग देना चाहिये । इनमेंसे कुछ संकट अब दूर हो चुके हैं । पर उनके भाग्यसे नये संकट उत्पन्न होते रहते हैं । इनमें सबसे नया साम्यवादका संकट है । हमसे कहा जाता है कि चीनका पतन हो रहा है, साम्यवादका संकट हमारी सीमाओतक पहुँच गया है और यदि इस समय कोई परिवर्तन अपने देशमें होता है तो कम्युनिस्ट इससे लाभ उठावेंगे । मेरी रायमें यह प्रचार समाजके संरक्षणशील तत्वोको और उन राजनीतिक दलोको जो प्रजातन्त्रका समर्थन करते हैं और अधिनायकवादके विरुद्ध हैं डराये रखनेका एक साधन है । साधारणतया यह भी विश्वास किया जाता है कि मध्य मार्गके राजनीतिक दलोका भी कोई भविष्य नहीं है और इस मध्य मार्गके दलोंमें सोशलिस्ट पार्टी भी एक है । यह एक गलती है जिसके सुधारकी आवश्यकता है । मैं कम्युनिस्ट पार्टीको उग्र वामपक्षी पार्टी नहीं मानता । मेरे विचारसे वही पार्टी उग्र वामपक्षी पार्टी हो सकती है जिसमें सामाजिक न्याय और समानताकी प्राप्तिके लिए क्रान्तिकारी परिवर्तन लानेकी बुद्धिमत्ता और साहस हो । कोई अधिनायकवादी पार्टी

सोशलिस्ट पार्टी नहीं हो सकती चाहे इसके सामाजिक उद्देश्य सोशलिस्ट पार्टी जैसे ही क्यों न हो। किसी राजनीतिक दलकी कार्य-प्रणालीकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उस दलका स्थान निर्णय करते समय इसकी विवेचना करनी ही होगी, क्योंकि साध्य और साधन अन्योन्याश्रित हैं और एक दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते। साम्यवाद प्रजातन्त्रका हिमायती नहीं है और मानव-व्यक्तित्वके विकासके लिए आवश्यक मूल्योका आदर नहीं करता। यह उस वैधानिक प्रजातन्त्रकी छिल्ली उड़ाता है जिसकी रक्षाके लिए इसने विगत महायुद्धमे इतना जोर लगाया। इसके लिए नैतिक नियमोकी कोई उपयोगिता नहीं है और क्षणिक लाभके लिए सन्देहात्मक नैतिकताके उपायोका आश्रय लेनेमे भी इसे हिचक नहीं होती। इसके साथ ही साथ यह रूसकी वैदेशिक नीतिका पुछल्ला है और उसके लिए यह अपने ही राज्यकी प्रादेशिक एकताको छिन्न-भिन्न कर सकता है या अपने ही राज्यको पलट सकता है। इन कारणोंसे कम्युनिस्ट पार्टी उग्र वामपक्षी पार्टी नहीं हो सकती। ऐसी पार्टी तो सोशलिस्ट पार्टी ही है क्योंकि इसे प्रजातन्त्रमे पूर्ण विश्वास है और इसने समाजमे क्रान्तिकारी आर्थिक परिवर्तन लाना अपना उद्देश्य बनाया है। इसके साथ ही साथ यह केवल विशुद्ध विधानवादी दल ही नहीं है। इसकी क्रान्तिकारी परम्परा और जनतामे इसके कार्य इस बातकी गारण्टी है कि यह अपनी क्रान्तिकारिताको नहीं छोड़ेगी।

मेरी रायमे यहाँ इस धारणापर भी विचार करना आवश्यक है जिसके कारण लोग समझते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टीके लिए इस देशमे आगे आनेका अधिक उपयुक्त अवसर है। जो लोग इस समस्यापर अधिक दूरतक नहीं सोचते, यह अधिकांश ऐसे ही लोगोका विश्वास है। चीनमे कम्युनिस्ट विजय ही इस भ्रान्त धारणाका कारण है। लोग यह भूल जाते हैं कि दोनो देशोकी परिस्थितियोमे महान् अन्तर है। सोलह वर्षके लम्बे युद्धके कारण चीनकी स्थितिमे लगातार अव्यवस्था रही है और इसकी आर्थिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो चुकी है। वास्तवमे पिछले चालीस वर्षोंसे वहाँ शान्ति नहीं रही है। इसके विपरीत भारतवर्षमे सदा शान्ति और सुरक्षा रही है और शासनतन्त्र कभी भङ्ग नहीं हुआ। युद्ध कभी भारतवर्षके प्रवेशद्वारोतक नहीं पहुँच सका और हमे मानव-जीव और सम्पत्तिका वह विनाश नहीं देखना पड़ा जो चीनमे आये दिन हुआ है। इसके साथ ही साथ चीनमे एक कम्युनिस्ट राज्य रहा है जो सदा अपनी सीमाओका विस्तार करता रहा और कोमिन-तांगसे नेतृत्वके लिए प्रतिस्पर्धा करता रहा है। भारतवर्षमे कम्युनिस्ट पार्टी जनप्रभाव-शून्य पार्टी है। चीनकी तरह भारतवर्षकी आर्थिक दशा भी नहीं खराब हुई है और न उस तरहकी मुद्रास्फीति ही हुई है। हमारे देशका शासनप्रबन्ध भी उतना भ्रष्ट नहीं है और सेना तथा पुलिस भी नये राज्यके प्रति वफादार बनी हुई है। चीनके कम्युनिस्टोके पक्षमे एक और मुख्य बात यह थी कि वहाँके लोगोको दोमेसे एकको चुनना था—या तो कम्युनिस्ट पार्टीको चुने या कोमिनतांगको। इसके अलावे उनके सामने दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल जन समर्थन विहीन छोटे-छोटे दल हैं। चीनकी कम्युनिस्ट सरकार च्यांग-काई-शेकके शासनसे नि सन्देह अच्छी है। उन्होने सामन्तवादी प्रथाको

तोड़ दिया है और जमीन खेत जोतनेवालोको बाँट दी है। उन्होंने अपने सिद्धान्तोंमें भी चीनकी स्थितिके अनुकूल सुधार कर चीनी साम्यवादको नया स्वरूप दिया है जो कभी-कभी इसी कारण 'खेतिहर साम्यवाद' कहलाता है। माओत्सेतुगका रुसका पुछल्ला होना भी निश्चित नहीं। भारतवर्षमें लोगोको अपनी इच्छानुसार चुनावकी अधिक स्वतन्त्रता है। सोशलिस्ट पार्टीको किसान और मजदूरोंके रूपमें जनताका समर्थन प्राप्त है। उसने जनताको आक्रुष्ट किया है और कुछ ऐसे राष्ट्रीय व्यक्तियोंको उपस्थित किया है जिनका जनता आदर करती है। यह पार्टी बढ़ रही है और यदि इसकी कमियाँ दूर कर दी जायँ तो यह कांग्रेससे राजनीतिक सत्ताके लिए प्रतिद्वन्द्विता कर सकती है। कुछ लोगोका यह भी कहना है कि चीनमें कम्युनिस्ट राज्यकी स्थापनाके बाद चीन भारत-वर्षमें अपनी सेना भारतीय कम्युनिस्टोंकी सहायताके लिए भेजेगा। यह कोरी कल्पना है। नये कम्युनिस्ट राज्यको कितनी ही आन्तरिक समस्याओंका सामना करना पड़ेगा। वह अपनी ही समस्याओंमें उलझा रहेगा और शान्ति-सुरक्षाकी स्थापना ही उसके लिए कठिन होगी। अपने पड़ोसियोंसे मित्रता रखना ही उसके लिए हितकर होगा और यदि भारत चीनकी नयी सरकारको अपनी स्वीकृति देगा तो उसे भी सद्भावनाके रूपमें इसका उत्तर देना होगा और इस दशामें वह भारतके कम्युनिस्टोंको अपनी हरकते सुधारनेकी सलाह भी दे सकता है। किसी भी दशामें उसके लिए भारतीय कम्युनिस्टोंकी आकाक्षाओंका समर्थन करना कुछ वर्षोंतक सम्भव न होगा। यदि भारतकी परिस्थितिको वास्तवमें अच्छी तरह समझना है तो एक बातपर और विचार करना होगा। भारतके प्रधानमन्त्री अपनी नीतियोंके निर्माणमें उतने कठोर और सकीर्ण नहीं हैं जैसे कि चीनमें च्यांगकाईशेक रहे हैं। मुझे तो यहाँतक विश्वास है कि यदि वे सकटके समय यह समझे कि क्रान्तिकारी परिवर्तनके बिना स्थिति नहीं सँभाली जा सकती तो वैसा कदम अवश्य उठावेगे। दोनों नेताओंके दृष्टिकोण और सिद्धान्तमें महान् अन्तर है। इसलिए सब बातोंपर विचार करनेके बाद मैं इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि भारतवर्षमें कम्युनिस्ट-नेतृत्वकी दिल्ली दूर है। इस देशमें राजनीतिक असन्तोष, राजनीतिक घृणा और उदासीनताके रूपमें तेजीसे परिवर्तित हो रहा है और यही कारण है कि यहाँ आलोचनात्मक चिन्तनका अत्यन्त अभाव है। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है, किन्तु इसका उपाय हो सकता है यदि सरकार जन-जीवनमें एक नयी भावना उत्पन्न करे। उदासीनताकी इस भावनाको मिटाना है और जनताको राजनीतिक मामलोंमें सक्रिय दिलचस्पी लेनेके लिए उत्साहित करना है। जनताके उदासीन मनोभाव मैत्रीभावमें परिवर्तित होने चाहिये और यह तभी सम्भव है, जब भोजन और वस्त्रके बुनियादी सवाल सन्तोषप्रद रूपसे हल हो जायँ और दमन-भयसे, मुक्त होकर सरकारकी आलोचना करनेकी वैधानिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

यहाँपर देशकी प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताकी चर्चा करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा। दुर्भाग्यसे, प्रजातन्त्रवादका मूल यहाँकी मिट्टीमें नहीं है। प्रजातन्त्र एक जीवन-विधि है और एक ऐसे देशमें जहाँ प्रजातन्त्रके अभ्यास और उसकी परम्पराका प्रायः अभाव है। इसका वातावरण सतत प्रयत्नोद्धार ही तैयार किया जा सकता है। सम्प्रदायवाद

इसका सबसे बड़ा शत्रु है और यदि प्रजातन्त्रात्मक जीवन-प्रणालीको सफल बनाना है, तो उसका उन्मूलन अनिवार्यतः होना चाहिये। साम्प्रदायिकताके परिणामस्वरूप हमारी राजनीतिक विचारधारा भी विकृत हो गयी है और अधिकांशमें हमारी परम्परागत चिन्तन प्रणालीने, जिसका हमारी वर्तमान समस्याओंके साथ कोई मेल नहीं है, अतिशय महत्त्व प्राप्त कर लिया है। यह स्पष्ट तौरपर समझ लेना है कि प्राचीन संस्कृतिके पुनर्जीवनका आन्दोलन आज दिन उपस्थित समस्याओंके समझने एवं उनका हल निकालनेमें हमें कुछ भी मदद नहीं पहुँचा सकता। हमलोग शीघ्रगामी सामाजिक परिवर्तनोंके युगमें रह रहे हैं, जहाँ परिस्थितियाँ सदैव हमारे लिए नित्य नयी माँग उपस्थित करती रहती हैं। हमलोग अपनेको प्रत्येक क्षण नवीन परिस्थितियोंके अनुकूल बनानेके लिए विवश हैं। विज्ञान और शिल्पके इस युगमें, राजनीतिक और आर्थिक सगठन इतने जटिल होते जा रहे हैं कि लदे हुए जमानेके जीर्ण विचारोंके बलपर उनका नियन्त्रण और संचालन हम नहीं कर सकते। यदि आज हमें जीवित रहना है तो हमें अनिवार्यतः उन सामाजिक और राजनीतिक मूल्योंको अपनाना ही होगा, जो वर्तमान समाजके लिए अपरिहार्य हैं। इनमेंसे एक प्रजातन्त्रवाद भी है। प्रजातन्त्रवादका अर्थ सामान्य जनके प्रति आदर और उसकी राष्ट्रविधायक शक्तिमें विश्वास है। जनसाधारण कोई जडराशि नहीं है जिसकी उपेक्षा की जाय। उसमें आरम्भशक्ति भी होती है और वह सकटके समय क्रियाशीलताका जोरदार तकाजा पेश करता है। इसलिए जो प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तोंके पोषक हैं, वे किसी हालतमें भी सामान्यजनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे लोग जन-शिक्षाके द्वारा साधारणजनको इस योग्य बनायेगे कि वह अपनी इच्छाको व्यक्त कर सके और शासन-व्यवस्थाकी आलोचना करनेके अपने अधिकारोंका भी उपयोग कर सके। दुर्भाग्यसे जो शासनारूढ हैं उनका मनोभाव अनुदार है। जनताद्वारा की गयी सरकारी नीतिकी आलोचनाके प्रति सरकार सहिष्णु नहीं है। अवश्य ही विरोधी विचारोंको स्वतन्त्र रूपसे व्यक्त करने और सगठित करनेके अधिकारपर सरकारी आक्रमण राजनीतिक प्रगतिको रोकता है, उसमें बोलने, लिखने और सघबद्ध होनेकी स्वतन्त्रता सुरक्षित होनी चाहिये और एक न एक वहाने स्वतन्त्र समाजके अधिकारोंपर कुठाराघात करनेकी क्रिया बन्द होनी चाहिये। किन्तु वैधानिक स्वतन्त्रताके बावजूद हम देखते हैं कि जनतान्त्रिक भावोंका गला घोटा जा रहा है और नागरिक स्वतन्त्रता कुचली जा रही है। इन घातक हमलोका तगड़ा विरोध करनेके लिए एक सुसगठित लोकमतका अभाव है। जनताकी उदासीनता अधिकारियोंको और भी गैरजिम्मेदार बना देती है और यदि वह कोई आवाज अन्यायके विरुद्ध उठाती भी है तो वह अनसुनी कर दी जाती है। खतरेके समय यदि सरकार जनताकी सम्मति प्राप्त कर विशेषाधिकारोंसे काम ले तो इसमें किसीको भी आपत्ति नहीं हो सकती, किन्तु साम्प्रदायिक शान्तिके नामपर, जबकि वस्तुतः कोई आतंक या भयकी बात न हो, जनताके मौलिक अधिकारोंपर एक लम्बे समयतक रोक लगाना अवश्य ही अवाञ्छनीय है। यदि सरकार अपने वचनोंके प्रति सच्ची है तो उसे अवश्य इसका सबूत देना चाहिये कि वह प्रजातान्त्रिक तरीकोपर चलती है और विधानका आदर

करती है। जनतन्त्रकी सीमाओंको सीमित करनेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर विस्तृत करना चाहिये।

इस सम्बन्धमें शिक्षाके महत्त्वपर भी जोर देना होगा, क्योंकि शिक्षाके माध्यमसे ही राष्ट्रके तरुणोंमें प्रजातान्त्रिक तरीकोंकी आदतें डाली जा सकती हैं। देशके उन तरुणोंको जो ध्वसात्मक सिद्धान्तोंके विपरीत प्रभावमें आ गये हैं, पुनः शिक्षाद्वारा इसके दृष्टिपरिणामोंसे वचाना है और इसके लिए हमारे शिक्षाकेन्द्रोंमें जन-तान्त्रिक विचारों एवं भावोंका वातावरण तैयार करना है। इस नये कार्यमें देशके विश्वविद्यालय एक प्रमुख भाग ले सकते हैं। इन विश्वविद्यालयोंको सृजनात्मक विचारोंका केन्द्रस्थल बन जाना है, यहाँ अध्येताओंको अपने अध्यापकोंके निकट सम्पर्कमें आने और निरन्तर विचारोंका आदान-प्रदान करनेका अवसर मिले। इसी कारण शिक्षण-सरथाओंको देशके जीवनमें अलग नहीं रहना चाहिये और इसे मान लेनेमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिये कि गौरवपूर्ण पार्थक्यकी नीति निश्चित रूपमें हानिकारक है। वर्तमान समस्याओंपर तर्क-वितर्क करनेको प्रोत्साहन मिलना चाहिये और अध्यापकोंको देशके सामाजिक और राजनीतिक जीवनमें भाग लेनेका अधिकार मिलना चाहिये। विश्वविद्यालयोंको बढ़ते हुए अधिनायकवाद और उसी तरहके सिद्धान्तोंके कुप्रभावोंसे मोर्चा लेनेमें प्रमुख भाग लेना चाहिये। इन विश्वविद्यालयोंको चाहिये कि वे प्रजातन्त्रको मजबूत बनावे और नवयुवकोंको अपने पेशेके लिए ही तैयार न करे बल्कि इसलिए भी कि वे नागरिक कर्तव्योंकी पूर्ति कर सकें। विश्वविद्यालयोंकी शिक्षण-प्रणाली ऐसी हो कि सत्य परीक्षण करनेमें अध्येताओंकी दृष्टि साफ हो और सत्यको ग्रहण करनेमें वे साहसी हो, चाहे वह सत्य प्रिय या अप्रिय हो। शिक्षा तो एक सतत प्रवाह है; ज्ञानकी सीमाओंका विस्तार हो रहा है। नवीन सत्यों और सिद्धान्तोंका उद्घाटन हो रहा है और नये विज्ञानोंका विकास हो रहा है। इसलिए, लाजिमी तौरपर यह आवश्यक है कि मस्तिष्कका समय-समयपर परिष्कार होता रहे, जिसमें चित्तमें सामाजिक चेतनाका लोप न हो जाय, जिसकी मानव-विकासके लिए अत्यन्त आवश्यकता है। अध्ययनके पाठ्यक्रमोंमें विधानके साथ-साथ मानवशास्त्रोंका भी समावेश होना चाहिये। अध्येताओंमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिये और ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि युवकोंके हृदयमें सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्योंका महत्त्व घर कर जाय। यहाँपर हमें यह भी भूल जाना है कि विज्ञानके विकास और सामाजिक समस्याओंपर उसके प्रयोगसे ही संस्कृतिका समाजीकरण तथा दरिद्रताका निवारण सम्भव हुआ है। प्राचीन समाजमें, जब कि समाजके आर्थिक ढाँचेको मूलतः परिवर्तित करना सम्भव नहीं था, दयालु लोग, जो दरिद्रों और दलितोंकी दशापर द्रवित होते थे, सिर्फ धनीमानी व्यक्तियोंसे उनके प्रति उदारता बरतनेकी याचना करके ही रह जाते थे। वह विज्ञान ही है जिसने हमारे लिए उन नवीन मानव-मूल्योंको प्रस्तुत किया है, जिनके सहारे हम सामाजिक न्याय एवं समता प्राप्त कर सकते हैं। समाजवाद निश्चय ही एक स्वप्नमात्र रह जाता और एक विश्वव्यापी आन्दोलनका वर्तमान स्वरूप कभी न प्राप्त करता, यदि विज्ञान और शिल्पने बहुलताका युग न ला दिया होता। किन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोणको मानव मूल्योंमें

आस्था रखकर ही आगे बढ़ना है, जिससे अश्रेयस्कर प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिए विज्ञानका दुरुपयोग न हो। वैज्ञानिक ज्ञानकोषको सभ्यताके विकास तथा सदुद्देश्योंकी पूर्तिके निमित्त समाजकी सेवामे अर्पित होना चाहिये।

प्रचलित भ्रान्त धारणाओंमेसे एक धारणा यह भी है कि समाजवाद प्रजातन्त्रके विरुद्ध है, इस धारणाका उन्मूलन होना चाहिये। मार्क्स एक महान् मानवतावादी था। व्यक्ति-स्वातन्त्र्यके लिए उसका आग्रह उल्लेखनीय है। उसका विश्वास था कि इतिहासकी एक दिशा है और उसके अनुसार इस युगमे क्रान्तिकारी सर्वहारा ही मानव-समाजका प्रतिनिधि है। उसने पूंजीवादको एक अनुचित सामाजिक व्यवस्था बतलाया था, क्योंकि मुनाफेकी लिप्सामे वह व्यक्तिवाद और अहम्मन्यताको जन्म देता है। पूंजीवादी व्यवस्थाके अन्दर श्रमिकवर्ग अपनी श्रमशक्तिको दूसरी अन्य वस्तुओंकी तरह बेचनेको बाध्य होता है और अपने मानव-तत्त्वसे च्युत हो जाता है। इस वर्गको पुनः उसने मानव-स्वरूपमे प्रतिष्ठित करना चाहा था। इस कार्यके लिए मुनाफेकी प्रवृत्ति और प्रतिद्वन्द्वितापर आश्रित पूंजीवादी व्यवस्थाके स्थानपर एक मार्क्सवादी व्यवस्थाकी स्थापना करनी होगी, जिसमे मुनाफेकी लिप्साके स्थानपर एकता और सहयोगकी भावनाका विकास हो। मार्क्सके शब्दोंमे 'सर्वहाराकी मुक्तिमे ही मानव-समाजकी मुक्ति सन्निहित है, क्योंकि समाजके समस्त उत्पीड़न सर्वहारा वर्गमे ही केन्द्रित हैं।' रोजा लुक्समबर्गके शब्दोंमे 'समाजवाद केवल रोटीकी समस्या ही नहीं है प्रत्युत एक विश्वव्यापी सांस्कृतिक आन्दोलन है।' अधिनायकतन्त्र आतंक पैदा करता है और मनुष्यको राज्यकी मशीनका एक पुर्जामाल बना देता है। यह मनुष्यके गौरवको नष्ट करता है और व्यक्तित्वके विकासका अवसर नहीं देता। यह एक नये ढंगके आतंक और दासताको जन्म देता है, जिसमे नागरिककी अपनी कोई इच्छा नहीं होती और वह राज्यका एक पुर्जामाल होता है। अवश्य ही, समाजवाद जो कि सामान्य-जनकी स्वतन्त्रताका हामी है, सरकारके इस स्वरूपकी स्वीकृति नहीं दे सकता। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट लोगोके, जिन्होंने जनवादी मोर्चेके दिनोंमे और फिर विगत महायुद्धके समय वैधानिक प्रजातन्त्रकी रक्षा तथा युद्ध और फासिज्मके खिलाफ लड़नेके लिए समस्त प्रजातान्त्रिक शक्तियोंके साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया था, अपने देशमे ही एक निरंकुश अधिनायकतान्त्रिक राज्य है, जो वहाँकी जनताके जीवनपर अपना पूर्ण नियन्त्रण रखता है। जनताके प्रजातान्त्रिक अधिकारोंकी रक्षाके प्रश्नपर जनयुद्ध लड़ा गया और जीता भी गया। युद्धका मूल प्रश्न राजनीतिक प्रजातन्त्र और फासिज्मके बीच निपटारा करना था। प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको साधारण-जनकी किसी महत्वपूर्ण समस्याको व्यक्त करना चाहिये, तभी वह लाखों मनुष्योंको साहसपूर्ण कार्योंके लिए प्रेरित कर सकती है। यह नहीं कहा जा सकता कि विगत युद्ध आत्मरक्षाके लिए था। प्रश्न यह है कि 'आत्मरक्षा किस लिए?' जनता अपने जनतान्त्रिक अधिकारोंका आदर करती थी और अपने देशको फासिस्ट विचारधाराके आक्रमणसे बचाना चाहती थी। मानव-जीवन और सम्पत्तिकी इतनी बर्बादी और विनाशके बाद अधिनायक-तन्त्रको स्वीकार करना नितान्त पागलपन ही होगा। यह आशा की जाती

थी कि रूसी लोग जिन्होंने फासिस्ट शक्तियोंको पराजित करनेमें महत्त्वपूर्ण भाग लिया था, अपने घरको सँभालेंगे और राज एव अपनी सामाजिक संस्थाओंको जनतान्त्रिक रूप देंगे । परन्तु ऐसी कोई भी बात नहीं हुई और इसलिए यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि रूसी नेताओंको राजनीतिक लोकतन्त्रमें कोई प्रेम नहीं था और वे फासिज्मके विरुद्ध संघर्षमें ससारके जनतान्त्रिक राष्ट्रोंको अपनी ओर घसीट लानेके लिए ही उनकी जनतान्त्रिक भावनाओंका उपयोग कर रहे थे । किन्तु जिन मानवीय मूल्योंके रक्षार्थ संसारने अपना इतना खून बहाया उनको दृढ़ताके साथ बचाना ही चाहिये और यदि अपनेको साम्यवादी या समाजवादी कहनेवाले इसमें असफल सिद्ध होते हैं तो वे जनहितके साथ गद्दारीके दोषभागी होंगे ।

प्रान्तीयता एक दूसरा अभिशाप है जिसे हमारी जनताको भुगतना पड़ता है । भारतीय एकताको दृढ़ करनेके लिए अन्तर्प्रान्तीय बन्धुत्व और मेलका होना आवश्यक है । यह तभी सम्भव है जब हम एक दूसरेको समझने और एक दूसरेकी भाषा और उनके साहित्यको जाननेका प्रयत्न करें । एकतान्त्रिक शासन-प्रणाली इसका उपचार नहीं है । भाषाके आधारपर प्रान्तोंके पुनर्निर्माणकी माँगको हम अब नहीं रोक सकते और समय रहते ही इस माँगको स्वीकार कर लेनेमें ही कुशलता है । हमारा पुराना इतिहास और हमारी परम्परा दोनों ही इस माँगके अनुकूल रहे हैं और संघ-शासन विधान भारतीय स्थितिके लिए अति उपयुक्त है । निस्सन्देह हमारे इन अभीष्ट उद्देश्योंकी पूर्तिके अन्य प्रकार भी ह । उनमेंसे एक प्रकार यह है कि समस्त प्रान्तीय भाषाओंके लिए एक ही लिपि अपनायी जाय । इससे इन भाषाओंके सीखनेके कार्यमें सुविधा होगी, क्योंकि इनमेंसे अधिकांशका पैतृक स्रोत एक ही है । जातीय और साम्प्रदायिक भेदोंसे रहित एक सामान्य ढीवानी-कानून और एक सामान्य आर्थिक संगठन, दूसरा अति अत्यावश्यक सुधार है जिससे अन्तर्-प्रान्तीय बन्धनोंको दृढ़ बनानेकी याशा की जा सकती है । पारस्परिक अविश्वास और विरोधके सभी कारणोंको दूर करना चाहिये और एक प्रान्तके अन्तर्गत समस्त समुदायों—विशेषतः अल्पसंख्यकों—को विश्वास दिलाना चाहिये कि उनके उचित स्वार्थोंके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा और समस्त वर्गोंके हाथ सामाजिक न्याय होगा । जाति-व्यवस्था भारतका अभिशाप रही है । इसने हिन्दू-समाजको अभेद्य विभागोंमें विभक्त कर दिया है । हालके चुनावोंमें जाति प्रथाकी बुराईयाँ प्रत्यक्ष दिखायी पड़ी हैं । जातिगत आधारपर राजनीतिक गुट बनाये जा रहे हैं और कुछ विशेष स्थानोंपर तो तथाकथित निम्न-जातियोंने उच्च जातियोंके विरुद्ध अपनेको संगठित कर लिया है । यह भारतीय स्थितिमें और जन्म और सम्पत्ति सम्बन्धी विशेषाधिकारोंके विरुद्ध अकिञ्चन और दलितोंके संघर्षका द्योतक है । यह स्थिति हमारे लिए चाहे जितनी अप्रिय हो, पर मुझे भय है कि हमें इस अपरिहार्य अवस्थासे गुजरना ही पड़ेगा । अतीतमें साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणालीकी स्वीकृति और कुछ विशेष सम्प्रदायोंके लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना वर्तमान अवस्थाके लिए मुख्य रूपसे उत्तरदायी है । फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारी राजनीतिमें यह केवल एक अस्थायी मंजिल है । किन्तु यह देखकर परेशानी होती है

कि कुछ स्थानोपर कांग्रेसके लोग अपने प्रभुत्वको कायम रखनेके लिए जातीय संगठनोके साथ गठबन्धन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि हम निम्न जातियोको उचित रीतिसे शिक्षित करें और अपने आचरणसे उन्हें दिखा दे कि हम उनके सामाजिक और आर्थिक स्तरको ऊँचा करनेकी सचमुच इच्छा रखते हैं और हम उनके उचित राजनीतिक अधिकारोको स्वीकार करने तथा अपने एकाधिकारकी प्रवृत्तियोको त्यागनेको तैयार हैं तो जात-पाँतके सकीर्ण आधारपर छोटे-छोटे गुट बनानेकी निरर्थकता हम उन्हें समझा सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टीके लिए शोपितोके अधिकारोकी रक्षक होनेके कारण उनका विश्वास प्राप्त करनेका सबसे अधिक अवसर है। उन्हें पार्टीके सिद्धान्तो और नीतियोमे दीक्षित किया जा सकता है और राजनीतिमे जातिवाद तथा सम्प्रदायवादसे दूर हटाया जा सकता है। केवल एक समाजवादी समाजमे जो समता और सामाजिक न्यायके उपर प्रतिष्ठित होता है, उनकी सामाजिक और आर्थिक दशामे सुधार किया जा सकता है।

दूसरा आवश्यक प्रश्न जिसपर मैं विचार करना चाहूँगा कृपक-समस्या है। जमींदारी-निर्मूलन बहुत दिन पहले ही हो जाना चाहिये था, किन्तु अभीतक उसका अन्त दिखायी नहीं दे रहा है। किन्तु तर्कके लिए मैं मान लेता हूँ कि यह निकट भविष्यमे खतम होने जा रही है। मेरे अपने प्रान्तमे जमींदारी-निर्मूलन-समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और सूचित किया गया है कि एक विलका मसौदा तैयार हो रहा है। इसके सुझाव प्रगतिशील नहीं हैं और वे धारा-सभाके, जिसने इस कमेटीको नियुक्त किया था, प्रस्तावका पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। व्यवस्थापिका सभाका आदेश सरकार और खेतिहरके बीचके मध्यस्थ वर्गको समाप्त करनेका था। किन्तु इसे समितिके सुझावोका आधार नहीं बनाया गया है। समितिका सुझाव शिकमीदारोके एक बहुत बड़े वर्गको अधिकार-विहीन कर देता है और उसकी सिफारिशोमे भूमिके पुनर्वितरणकी कोई भी गुञ्जाइश नहीं है। दूसरी बात जिसपर मैं जोर देना चाहता हूँ मुआविजेकी अदायगीके सम्बन्धकी है। सत्त्वत सोशलिस्ट पार्टी इस सिद्धान्तको नहीं मानती। हम इस मतके हैं कि सामान्यतः स्वामित्वके आधारपर कोई भी मुआविजा नहीं देना चाहिये, किन्तु पुनर्वासनके आधार पर गरीब भूस्वामियोको हरजाना दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि धनिकोको किसी प्रकारका, हरजाना पानेका अधिकार नहीं है, पर गरीबोके लिए ऐसी सुविधाएँ प्रस्तुत की जायेगी, जिनसे वे नया-जीवन प्रारम्भ कर सकें। किन्तु चूँकि सरकारने मुआविजा चुकानेके सिद्धान्तको मान लिया है, अतः हमने भी अपने प्रस्तावमे थोड़ा परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया है। हमने मुआविजेकी एक क्रमिक योजना बनायी है और सबसे बड़ी रकम एक लाख तय की है। हमने यह भी सुझाव रखा है कि अधिकतम क्षेत्र जिसे रखनेकी अनुमति किसी खेतिहरको दी जा सकती है तीस एकड़से अधिक न होना चाहिये और यह नियम कानूनकी स्वीकृतिके साथ ही लागू होना चाहिये। यदि यह नियम मान लिया जाता है तो बड़े खेतोको तोड़ देना पड़ेगा और किसानो और जमींदारोके गरीब वर्गोके बीच वितरणके लिए भूमि प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त रिपोर्टमे उन लोगोके भाग्यका भी कोई विचार नहीं किया गया है जिनके खेत आवश्यकतासे भी

छोटे हैं—यद्यपि इनकी संख्या बहुत अधिक है। हम समझ सकते हैं कि ऐसे प्रान्तमें खेती अलाभकर ही रहेगी और अनाजकी अतिरिक्त उपज बहुत अधिक न होगी। उनकी समस्या टेढ़ी है और यद्यपि यह सच है कि उन्नत बीजो, अच्छी खाद और उन्नत नस्लके चौपायोंके सहारे भूमिकी उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है, तथापि यह तभी सम्भव है जब वे अपने साधनोंका एक साथ उपयोग करे और सहकारी उद्योगकी ओर अग्रसर हो। किन्तु इसमें स्वभावतः समय लगेगा। इस बीच जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह यही कि वर्तमान स्थितिमें हम जितने अधिक खेतोंको लाभप्रद बना सके बनाये, और जो लाभप्रद न बन सके उन्हें दूसरे प्रकारकी सहायता दे। मेरी रायमें यदि सरकार उनकी पूरी लगान माफ करनेको तैयार न हो तो भी उसे बहुत कम कर देना चाहिये।

दूसरी आलोचना जो मैं करना चाहता हूँ लगानकी उस रकमके बारेमें है जिसे जमींदारी निर्मूलनके उपरान्त किसानसे वसूल किया जायगा। प्रस्ताव यह है कि उनसे वही लगान वसूल की जावे जितना वह आज दे रहे हैं। यदि यही किया गया तो किसानको कोई मानसिक तुष्टि न होगी और वह अपनी स्थितिमें कोई परिवर्तन महसूस नहीं करेगा। हमारा सुझाव है कि जो मालगुजारी आज जमींदार दे रहे हैं किसानोंसे उससे अधिक रकम लगानमें न ली जाय। इस आधारपर कि हरजानेका भार काश्तकारको लेना चाहिये, उक्त प्रस्तावका औचित्य नहीं माना जा सकता। हम इसके विरुद्ध हैं, क्योंकि यह एक दूसरे प्रकारका शोषण ही होगा। हमारे मतसे राज्यको यह भार वहन करना चाहिये था उसे दूसरे शोषक वर्गोंके कंधोंपर डाला जाना चाहिये। हम इस विचारका भी समर्थन नहीं करते कि भूमिकी कीमत लेकर किसानोंके हाथ बेचा जाय, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे यह समझे कि भूमिपर उन्होंने स्वामित्वके अधिकार अर्जित किये हैं। यदि लगानका भार हल्का हो जाता है और किसी प्रकारकी गैरकानूनी रकमें वसूल नहीं की जाती है तथा वे वेदखलोंके शिकार नहीं बनाये जाते तो वे पूर्ण रूपसे मन्तुष्ट हो जायेंगे।

रिपोर्टकी दूसरी कमी यह है कि इसने भूमिहीन श्रमिकोंकी ओर बहुत ध्यान नहीं दिया है। न्यूनतम मजदूरीका कानून बनना चाहिये और उनकी आमदनीकी पूर्तिके लिए ग्रामीण उद्योग-धन्धोंकी स्थापना होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त जितनी भूमि परती है उसके बीस प्रतिशतसे अधिक जोतमें लायी जानी चाहिये और खेतिहर मजदूरोंको इस जमीनपर बसाना चाहिये। किन्तु सर्वोपरि, यह आवश्यक है कि गांवोंमें समस्त मानवीय सम्बन्धोंको बदला जाय और उन्हें लोकतान्त्रिक आधारपर स्थापित किया जाय। इस ध्येयकी सिद्धिके लिए कृषिमें और उसकी उपजके विक्रयमें सहकारिताकी व्यवस्था आवश्यक है। ग्राम-पंचायतोंको गांवका राजनीतिक अदालती और आर्थिक संगठन मान लेना चाहिये। गांववाले सरलतासे सहकारिताको नहीं अपना लेंगे और हमें समझा-बुझाकर, प्रचार और प्रोत्साहनके द्वारा इन्हें इसकी उपयोगिताका विश्वास दिलाना होगा। कृषक अनुभवसे सीखते हैं और यदि किसानको सहकारी प्रणालीकी श्रेष्ठताका विश्वास हो जाय, क्योंकि इससे उसे अच्छी उपज और अपनी पैदावारका अच्छा

दाम प्राप्त होता है, तो वह तत्परतापूर्वक इसे अपना लेगा । इसके लिए सरकारी यंत्र पर्याप्त नहीं है । गैरसरकारी सस्थाओंके द्वारा उसके प्रयत्नको पूरा करना होगा, क्योंकि केवल ऐसी ही सस्थाएँ इस कार्य में उत्साह और साहसकी भावना ला सकती हैं । ग्राम-पंचायतोंका अब भी जनताके मनपर प्रभाव जमा हुआ है और यदि उन्हें एक नये रूप और नये आधारपर पुनरुज्जीवित किया जाय तो वे अन्ततोगत्वा सफल सिद्ध हो सकती हैं । पंचायतोंके ही द्वारा लगान वसूली भी की जानी चाहिये ।

गाँवोंके सम्बन्धमें इतनी अधिक उदासीनता दिखायी गयी है कि जबतक हम एक नवीन वातावरण उत्पन्न करनेके लिए कोई त्रान्तिकारी कदम नहीं उठाते, तबतक गाँवोंकी स्थितिमें कोई भी उन्नति नहीं होगी । गाँवोंमें सामाजिक सुविधाओं और सांस्कृतिक केन्द्रोंका सर्वथा अभाव है और इसका दुःखद परिणाम यह है कि शिक्षित नवयुवकोंको वहाँ ठहरनेके लिए कोई आकर्षण नहीं रहता और वे नगरोंकी ओर चले जाते हैं और इस प्रकार अपनी सेवाओं और नेतृत्वसे गाँवको वंचित कर देते हैं । इस परिस्थितिका उपचार होना चाहिये और देहातोंकी दशामें सुधार करनेके लिए यह आवश्यक है कि इन सभी सुधारोंको तुरन्त और एक साथ आरम्भ किया जाय ।

उपर्युक्त बातें अन्य प्रान्तोंपर भी समानरूपसे लागू होती हैं ।

दूसरा प्रश्न जो मेरे समक्ष विचारणीय है वह है श्रमका । औद्योगिक झगड़ोंके निवटारेके लिए सरकारने जो व्यवस्था की है, उससे मजदूरोंके सामूहिक रूपसे सौदा करनेके अधिकारमें अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं । औद्योगिक झगड़ोंको तय करनेके लिए सरकारने समझौता बोर्डों और औद्योगिक पंचायतों अदालतोंकी स्थापना की है, किन्तु उनकी व्यवस्था इतनी जटिल है तथा उनकी कार्यप्रणाली इतनी धीमी और दीर्घसूत्री है कि उससे मालिकोंका ही लाभ होता है और मजदूरोंकी पर्याप्त रक्षा नहीं हो पाती है । इतना ही नहीं, कारखाना-समितियोंका विधान तो औद्योगिक लोकतन्त्रकी जड़ ही काट देता है । सरकार गैर-काग्रेसी संघटनोंकी उपेक्षा करती है और उसकी नीति भी पक्षपातकी है । भारतीय राष्ट्रीय मजदूर-संघको वह मजदूरोंका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने-वाली सस्था स्वीकार करती है । युक्तप्रान्तमें तो इसे ही कारखाना-समितियोंके सदस्योंको मनोनीत करनेका भी अधिकार दे दिया गया है । अपनी कारखाना-समितियोंके लिए कार्यकर्त्ताओंको निर्वाचित करनेके मजदूरोंके लोकतन्त्रात्मक अधिकारपर यह एक प्रहार है । फलतः अनेक खानोंकी कारखाना-समितियाँ अपने मजदूरोंका प्रतिनिधित्व नहीं करती और मजदूरोंका विश्वास उन्हें प्राप्त नहीं है । ये समितियाँ मजदूर-संघटनोंसे असम्बद्ध रहकर उनके प्रभावकी उपेक्षा करती हैं । फलतः उन्हें संघोंका समर्थन तथा सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता । इस कानूनका बुरा प्रभाव यह पड़ता है कि ये कारखाना-समितियाँ मजदूर-संघटनोंके विरोधमें खड़ी कर दी जाती हैं । सरकारी नीतिसे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर-संघको अनुचित सहारा मिल रहा है, आमतौरसे मजदूर इसके विरोधी हैं । इस प्रकार मजदूर-संघटनोंकी मजदूरोंके लिए उचित वेतनकी माँग करनेकी शक्ति बहुत कम कर दी जा रही है और उनके हड़ताल करनेका अधिकार वस्तुतः

छीन लिया जा रहा है। सरकार उत्पादनमें वृद्धि करनेके लिए मजदूरोंसे अपील करती है, किन्तु प्रतिनिधि तथा प्रभावशाली संघटनोंकी उपेक्षा करके और मजदूरोंके सिरपर अनुचित ढंगसे एक ऐसे संघटन को लाद करके जो वस्तुतः अल्पसंख्यक मजदूरोंका ही प्रतिनिधित्व करता है, वह उत्पादन-वृद्धि कार्यमें सहयोग देनेसे मजदूरोंको हतोत्साहित करती है। ऐसा ज्ञात होता है कि सरकारका एकमात्र उद्देश्य मजदूर आन्दोलनको छिन्न-भिन्न कर देना और कांग्रेस नियन्त्रित भारतीय राष्ट्रीय मजदूर-संघको अप्रत्यक्ष महायत्ना और स्वीकृति प्रदान कर मजदूरोंको उसके कब्जेमें आ जानेके लिए विवग करना तथा हड़ताल करनेके अधिकारसे मजदूरोंको वञ्चित करना है। यह ध्यान देनेकी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर-संघ समझौता-वार्ता तथा पचायतपर ही विश्वास करता है और किसी भी स्थितिमें हड़ताल करना उसे स्वीकार नहीं है। यह स्पष्ट है कि सरकार जो अन्य दलोंपर राजनीतिक उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए मजदूरोंको वरगलानेका दोषारोपण करती है, वस्तुतः इसके लिए वह स्वयं ढोपी है। गैर-कांग्रेसी मजदूर-संघटनोंको वैधानिक काररवाइयोंके लिए साधारणतः अनुमति नहीं दी जाती है और उनके कार्यकर्त्ता गिरफ्तार और निष्कासित कर दिये जाते हैं। इस बातके अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर-संघमें सम्मिलित न होनेके कारण गैर-कांग्रेसी युनियनोंके सदस्योंको उनके उचित अधिकारों से वञ्चित किया गया है। डालमियाँनगरकी शान्तिपूर्ण हड़तालको भङ्ग करनेके लिए फौजका उपयोग किया गया और निकटस्थ ग्रामोंके निवासियोंको हड़तालियोंसे सहानुभूति रखनेके कारण आतंकित किया गया। हड़तालियोंके नेता साथी बसावनसिंहको गिरफ्तार कर लिया गया। जमशेदपुरमें सोजलिस्ट पार्टीकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नेशनल डिविज-क्यूटिव) के सदस्य मुजी अहमददीनको गिरफ्तार कर लिया गया और पार्टीके अनेक कार्यकर्त्ताओंको निष्कासित भी कर दिया गया है। उपर्युक्त वस्तुओंके मूल्योंमें वृद्धिके कारण वास्तविक मजदूरीमें कमी तथा मजदूरोंके प्रति सरकारके तानाशरे व्यवहारके फलस्वरूप मजदूर उद्विग्न हो रहे हैं और इससे उनमें संघर्षकी भावना बढ़ रही है। हड़ताल करनेके अधिकारकी प्रमान्यता तथा संघटित रूपसे उचित मजदूरी माँगनेके अधिकारपर विभिन्न प्रतिबन्धोंके परिणामस्वरूप शान्तिपूर्ण तरीकोपरसे स्वभावतः मजदूरोंका विश्वास हट जायगा। अनेक मजदूर-संघोंने अभी हालमें ही कम्युनिस्टोंको तिरस्कृत किया है और कम्युनिस्ट-नियन्त्रित अखिल भारतीय ट्रेड युनियनने कांग्रेससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। यदि इस प्रगतिको जारी रखना है तथा भारतीय मजदूर आन्दोलनको सुदृढ़ माँगोंपर बढ़नेका अवसर देना है तो सरकारको पक्षतपातपूर्ण नीतिका परित्याग करना पड़ेगा और यह जानना होगा कि कौन शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक तरीकोपर विश्वास करता है तथा कौन हिंसात्मक तरीकोपर विश्वास करता है तथा अपना मुख्य उद्देश्य समझता है। असन्तोष उत्पन्न करना विद्रोहकी अग्नि भड़काना है, किन्तु खेदका विषय है कि सरकार मजदूरोंके असन्तोषके आधारभूत कारणोंका अन्त न करके पूँजीपति-वर्ग को प्रमत्त करनेकी नीति अपनाये हुए है। सरकारको पूँजीपतियोंसे यह आशा है कि प्रोत्साहन देनेसे वे उद्योग-व्यवसायोंकी उन्नतिमें अधिकसे अधिक पूँजी लगायेंगे और इसी

आशापर उन्हें पुनः और अधिक सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं । सरकारकी नीतियोमे निम्न मध्यवर्गकी मानसिक स्थितिकी छाया झलकती है जिसमे न तो जन-क्रान्तिके पथपर चलने-का साहस है और न अपने स्वार्थोको पूर्णरूपसे पूँजीवादी वर्गके स्वार्थोसे मिला देनेकी इच्छा ही है । यह वर्ग सदा ही इन दोनो परस्पर विरोधी स्वार्थोमे क्षणिक सामंजस्य स्थापित करनेकी चेष्टा करता रहता है और मुख्यतः पूर्णरूपसे पूँजीवादी वर्गके प्रभावमे रहता है, परन्तु समय ऐसा है कि मौलिक परिवर्तनकी साहसपूर्ण और सुदृढ नीतिसे ही परिस्थिति सँभल सकती है ।

राज्योकी समस्या एक अन्य प्रश्न है जिसके सम्बन्धमे भी थोड़ा प्रकाश डालना यहाँपर अप्रासंगिक न होगा । हिन्द-सरकारके रियासती विभागका यह दावा है कि उसने जादूका काम करके दिखाया है । भारतवर्षसे अंग्रेजोका शासन समाप्त होनेके साथ साथ राजाओके प्रभुत्वका अन्त होना भी अवश्यम्भावी था । छोटे राजाओके मामलोको तय करनेमे रियासती विभागको जो कूटनीतिक सफलता प्राप्त हुई उसकी हम सराहना कर सकते हैं, किन्तु इस कथनकी वस्तुथितिसे पुष्टि नही होती कि राज्योमे रक्तहीन क्रान्ति सम्पन्न हुई है । कतिपय रियासतोमे जनताने स्वयं आगे कदम बढ़ाया और राजाओको अधिकार त्याग करनेके लिए बाध्य किया । यह भी आवश्यक है कि जिन रियासतोका प्रान्तोमे विलय हुआ है वे पूर्णरूपसे उनमे समन्वित कर दी जायँ । काश्मीर और हैदरावादके राजवशोका अन्त होना चाहिये । इस देशमे जो विदेशी वस्तियाँ हैं उन्हें भारतीय संघका अंग बना देना चाहिये । हम गोआके अपने उन वीर सार्थियोको नही भूल सकते जो पुर्तगालके एक किलेमे सड़ रहे हैं और जिन्हें लम्बी अवधिकी सजाएँ दी गयी हैं । सभी जगह जनता विद्रोहके लिए तैयार है और इन विदेशी वस्तियोकी जनताका अपना राजनीतिक भविष्य निश्चित करनेका अधिकार अवश्य ही स्वीकार करना होगा ।

लोगोके मस्तिष्कको आन्दोलित करनेवाले प्रश्नोमे एक प्रश्न यह है कि हिन्दको ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके अन्तर्गत ही रहना चाहिये या उससे बाहर निकल आना चाहिये । आज ससार दो शक्तिशाली गुटोमे विभाजित है और अगर हम तृतीय विश्वव्यापी युद्ध से अलग रहना चाहते हैं तो इन दलोमेसे किसी एकमे भी हमारे लिए स्थान नही है । भारतीय राज तटस्थताकी नीतिके लिए वचनबद्ध है और यदि युद्ध आरम्भ होता है तो इसमे किसी ओरसे हिस्सा लेनेकी उसकी कोई इच्छा नही है । भारतवर्षका हित इस बातमे है कि वह युद्धसे अलग रहे और इस बातका प्रत्येक सम्भव उपाय किया जाय कि किसी प्रकार भी विश्वकी शान्ति भग्न न होने पावे । भारतवर्ष अपना यह 'पार्ट' तभी प्रभावकर ढंगसे अदा कर सकता है जब कि वह किसी भी दलमे अपनेको शामिल न करे । यदि वह किसी दलमे शामिल हो जाय तो इससे दोमेसे एक बड़ी शक्तिके विरोधका सामना करना पड़ेगा । ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलका सदस्य होनेसे उसकी शान्ति एव युद्ध-सम्बन्धी नीतिमे हिस्सा लेनेका कर्तव्य भी अपने ऊपर आ जाता है, यदि ऐसी बात न भी हो तो इतना तो निश्चित ही है कि इससे तटस्थ रहनेकी हमारी ईमानदारीपर दूसरोका सन्देह बढ़ जायगा । इसके साथ ही ऐसे राष्ट्रमण्डलमे भारतवर्षके लिए कोई स्थान नही है जिसका एक सदस्य

हमारे देशवासियोंके साथ समानताका वर्तव नहीं करता और उनको निम्न और हीन अवस्थामे रखता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जनतन्त्रोंमें ब्रिटेनका प्रमुख स्थान है तथा यह आशा की जाती है कि वह दुनियाकी जनतन्त्रवादी शक्तियोंका नेतृत्व करेगा। किन्तु फ्रान्स और हालैंड जो कि उसके साथी हैं, दक्षिण पूर्वी एशियामे अपनी साम्राज्यवादी नीतियोंका परित्याग करनेके लिए तैयार नहीं हैं। कम्युनिज्मके विरुद्ध एक गठके रूपमे पश्चिमी यूरोपका संघ बनाया गया है और इसे अमेरिकाकी प्रबल सहायता प्राप्त है। अग्रेजोंने ही वर्मामे उपद्रव खड़ा कर दिया है और वहाँ वे आन्तरिक फूटको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आस्ट्रेलियाके परराष्ट्र-मन्त्रीने असावधानीसे वर्माको पुनः राष्ट्रमण्डलमे सम्मिलित हो जानेकी सलाह भी दे दी है। हिन्दुस्तानका अगोच्छेद करके ही ब्रिटिश सरकारने यहाँ सत्ता हस्तान्तरित की। इन सब बातोंसे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे एशियाई राष्ट्रोंको कभी अखण्ड और शक्तिशाली नहीं देखना चाहते। इन विभिन्न कारणोंसे हमारे लिए राष्ट्रमण्डलमे रहना हितकर नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सांस्कृतिक और व्यावसायिक कार्योंके लिए भी ब्रिटेनके साथ मैत्री-सम्बन्ध न स्थापित करें। किन्तु हम यह कदापि स्वीकार नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान ब्रिटेनकी परराष्ट्रनीतिसे बँधा रहे और उसे विनाशका भी युद्धका एक अखाड़ा बनना पड़े। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि ब्रिटेन तथा उसके पश्चिमी मित्र दक्षिण पूर्वी एशियामे जिस नीतिका अनुसरण कर रहे हैं उससे इन राष्ट्रोंमे साम्यवादकी ही शक्ति बढ़ेगी और अगर इस प्रदेशमे साम्यवाद विजयी हुआ तो इन राष्ट्रोंकी सहायतासे तृतीय गुट निर्माण करनेकी रही-सही आशापर भी पानी फिर जायगा।

मैंने यह कहा है कि पार्टीके अन्दर भी कुछ त्रुटियाँ हैं जिनका सुधार आवश्यक है। सर्वप्रथम, हमारा वर्तमान विधान नवीन परिस्थितियोंके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। इसमे परिवर्तनकी आवश्यकता है और पार्टीको एक नये आधारपर पुनर्संघटित करना होगा। अभीतक यह कुछ चुने हुए लोगोंकी ही पार्टी है, किन्तु अगर हमें अपना उद्देश्य प्राप्त करना है और सचमुच कांग्रेसका प्रतिद्वन्द्वी बनना है तो अपना संघटन व्यापक बनाना पड़ेगा। हमें जनतामे घुसकर उसका विश्वास प्राप्त करना होगा। पार्टीको लोकतान्त्रिक समाजवादका उपकरण बनाना है और इसके लिए बुद्धिजीवी वर्गका सहयोग अपेक्षित है। हमलोगोंको महान् निर्माण-कार्य करना है और इसमे पूरी शक्ति और बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। हम केवल प्रचारसे सफल होनेकी आशा नहीं कर सकते। शोषण और विभेद सुविधाओंका अन्त करनेके लिए उत्पादनके साधनोंका समाजीकरण करना पड़ेगा और सार्वजनिक सेवाओंको जनसाधारणके हितकी दृष्टिसे संघटित करना है। अनायोजित आर्थिक पद्धतिके स्थानपर नियोजित अर्थनीतिको अपनाया होगा और सबके ऊपर मानवीय सम्बन्धोंको इस प्रकार बदल देना पड़ेगा जिसमे कि जीवन ही लोकतन्त्रात्मक ढंगका बन जाय। इन सब कार्योंको सफलतापूर्वक सम्पन्न करनेके लिए आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओंपर गम्भीर तथा ठोस अध्ययन अपेक्षित है। पार्टी को न केवल एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम ही प्रस्तुत करना है, प्रत्युत उसे असंख्य जनताको यह विश्वास

दिलाना है कि 'पार्टी' को अपने कर्तव्यका ज्ञान है और आवश्यकता पड़नेपर उसे कार्यान्वित करनेकी शक्ति भी उसमें विद्यमान है। जहाँ हम एक ओर किसानों और मजदूरोंके वर्ग-सघटनका निर्माण करते हैं और अपनी सेवा तथा कठिन परिश्रमसे उनका विश्वास प्राप्त करते हैं, वहाँ हमें बुद्धिवादियोंमें प्रविष्ट होकर उन्हें 'पार्टी' के झण्डेके नीचे सघटित करना है। अर्थशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञानके अध्येताओंको 'पार्टी' में लाना है और अपनी नीति निर्धारित करने तथा समस्याओंके अध्ययन करनेके लिए उनके परामर्श और पथप्रदर्शनको सदा प्राप्त करते रहना है। हममें कार्यकर्ताओंका अभाव है और मैं समझता हूँ कि यही हमारी मुख्य दुर्बलता है। हमें उच्च कोटिके कुशल कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता है, जिन्हें समस्याओंका उचित ज्ञान हो तथा 'पार्टी' के कार्यकर्ताओंकी उत्पन्न करनेका जिनमें पर्याप्त उत्साह हो। समाजवादी नवयुवक सघ एक ऐसा सघटन है जिसे यदि उचित रूपसे सघटित किया जाय तो वह पार्टीके लिए सदस्य तैयार कर सकता है। कार्यकर्ताओंकी ट्रेनिंगके लिए श्रमिक विद्यालयोंकी स्थापना होनी चाहिये जहाँ उन्हें केवल सैद्धान्तिक ज्ञान ही न प्राप्त कराया जाय, प्रत्युत उनकी कार्य-क्षमताका भी उचित विकास हो।

यदि हमने उन सभीके लिए द्वार न खोले जो 'पार्टी' के विधान तथा उसके कार्यक्रममें विश्वास रखते हैं तो हम अपने कर्तव्यकी पूर्ति न कर सकेंगे। हमें उन सभी मजदूर-सघों, किसान-पचायतों, समाजवादी नवयुवक संघों, सहयोग समितियों तथा इस प्रकारके अन्य सघटनोंको 'पार्टी' से सम्बद्ध कर लेना चाहिये जो एक प्रस्तावद्वारा 'पार्टी' की योजनाओं और उसकी नीतिको स्वीकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सोशलिस्ट सिद्धान्तोंको स्वीकार करता है तथा 'पार्टी' के अनुशासनको पालन करनेकी प्रतिज्ञा करता है उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिये। वर्तमान अवस्थामें जब कि आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है और सम्पन्न लोग भी मजदूरोंमें सम्मिलित हो रहे हैं, हमें इन वर्गोंके व्यक्तियोंको 'पार्टी' में लानेसे कोई विशेष खतरा नहीं है।

मध्यमवर्गीय लोगोंको पार्टीमें लेनेसे कुछ खतरा तो अवश्य है, परन्तु थोड़ेसे विवेक और सावधानीसे हम उस खतरेको टाल सकते हैं। यह स्पष्ट है कि हम उन लोगोंको जो सम्प्रदायवादी हैं या स्थिरस्वार्थोंका प्रतिनिधित्व करते हैं नहीं ले सकते, जबतक हमें इस बातका पूर्ण विश्वास न हो जाय कि उनमें वास्तविक हृदय-परिवर्तन हुआ है और वे जीवनके समाजवादी-दर्शनको तहेदिलसे स्वीकार कर चुके हैं। पार्टीके प्रधान मन्त्रीने एक विद्वत्तापूर्ण मसविदा तैयार किया है जिसमें उन्होंने पार्टीके विधानपर भली भाँति विचार किया है और एक प्रस्तावित विधान भी नये सिद्धान्तोंके आधारपर तैयार किया गया है। मैं इस तथ्यसे भी अनभिज्ञ नहीं हूँ कि इस प्रश्नपर तीव्र मतभेद है, किन्तु मैं यह जानता हूँ कि साधारणतया कुछ परिवर्तनकी आवश्यकताका अनुभव किया जा रहा है। कुछ लोग ईमानदारीके साथ यह समझते हैं कि समान रूपसे व्यक्तिगत सदस्योंकी भर्ती खतरेसे खाली नहीं है और वे विधानमें किसी ऐसे परिवर्तनका तीव्र विरोध करते हैं जो अन्तमें पार्टीके क्रान्तिकारी स्वरूपको विनष्ट कर सकता है। यहाँ मैं इस समस्याके पक्ष-विपक्षका विस्तृत विवेचन नहीं करूँगा। परन्तु मैं यह कहनेसे अपनेको रोक नहीं

सकता कि पार्टीमें एक ऐसी प्रवृत्ति लक्षित होती है जो पार्टीको अपने लिए सुरक्षित रखनेकी उत्कट इच्छासे नवागन्तुकोके लिए उसका दरवाजा मजबूतीसे बन्द रखना चाहती है । यह एक अवाछनीय प्रवृत्ति है जिसका उन्मूलन पार्टीकी उन्नतिके लिए आवश्यक है । नवीन रक्तकी प्राप्ति सदा वाछनीय है । पार्टीको थोड़ेसे लोगोकी निधि बननेके लिए नहीं छोड़ा जा सकता और प्रत्येक सच्चे समाजवादीको पार्टीमें सम्मिलित होनेका अधिकार है । इस प्रकारका संकुचित दृष्टिकोण समाजवादी उद्देश्यके प्रति विश्वासघात होगा । यह नितान्त अहम्मन्यता और अहंकारकी प्रवृत्ति है जिसमें वस्तुस्थितिके ज्ञानका खेदजनक अभाव दिखायी देता है । यह प्रकट सत्य है कि जबतक पार्टी सार्वजनिक स्वरूप नहीं धारण करती, वह अपने उद्देश्योकी पूर्ति नहीं कर सकती ।

पार्टीके पुनर्र्गठनकी आवश्यकता है । उसकी विभिन्न शाखाओके कार्योंमें कोई सन्तोषजनक समन्वय नहीं है । विभिन्न शाखाओके कार्योंकी देखरेख करने तथा उन्हें अधिक सक्रिय बनानेके लिए उचित निरीक्षणकी व्यवस्था होनी चाहिये । पार्टी सम्बन्धी कार्योंके नये केन्द्र खोलने पड़ेगे और किसान पंचायतोको सुसंगठित दृढ़ करना होगा । इस सम्बन्धमें हमलोगोको रचनात्मक कार्यपर विशेष जोर देना है । विस्तृत क्षेत्रमें केवल प्रचार-कार्यकी अपेक्षा कुछ चुने हुए क्षेत्रोंमें ठोस कार्य अधिक वाछनीय है । हमलोग प्रचार-कार्यमें अभ्यस्त हो गये हैं, किन्तु अब इससे काम नहीं चलेगा । देहातोंमें भी राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गयी है, किन्तु अबतक वहाँ कोई ऐसा संगठन नहीं है जो संघर्ष-कालमें उनको पथ-प्रदर्शन और कार्य-निर्देशका केन्द्र बना सके । ऐसे सजीव केन्द्रोंका निर्माण करना है, जहाँ नवीन सामाजिक जीवनका दर्शन हो सके । देहातोंमें नवजीवनका संचार करनेके लिए सहकारिताका विशेष महत्त्व है और अगर हमारे साथी इस ओर अधिक आकृष्ट हैं तो यह हमारे लिए परम सन्तोषका विषय होगा । यदि हम जनताके समक्ष निःस्वार्थ और रचनात्मक कार्योंद्वारा समाजवादी नीतिको कार्यान्वित करनेके लिए अपनी सच्चाई और योग्यताका प्रमाण पेश कर सके तो हम उसमें नया जीवन डाल सकते हैं और एक नया विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं । यद्यपि हमारा सन्देश सुननेके लिए काफी सख्यामें लोग एकत्र होते हैं, हमें उन लोगोको यह विश्वास दिलाना है कि हम अधिकारारूढ होनेपर उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे । हम ठोस कार्यद्वारा ही जनताको आश्वस्त कर सकते हैं, न कि प्रचारद्वारा । अगर हम पार्टी-संघटनको अधिक व्यापक बना सके और जनताका सद्भाव प्राप्त कर सके तो उससे हमारी काफी शक्ति-वृद्धि होगी और हम निश्चित रूपसे चुनावमें विजय प्राप्त करेंगे । जनतामें कार्य करना हमारी मुख्य चिन्ता होनी चाहिये । पार्टीको सामाजिक संघर्षोंका प्रतीक होना चाहिये तथा उसमें साधारण जनताकी आवश्यकताएँ, इच्छाएँ और आकांक्षाएँ अभिव्यक्त होनी चाहिये । हमारी बातोकी सही कसौटी हमारा कार्य है । आत्म-तुष्टि खतरनाक होती है । अपनी सभाओमें विशाल जनसमूहको देखकर हमें भ्रममें नहीं पड़ना चाहिये । जनताका कांग्रेसमें विश्वास नहीं रहा है और वह यही देखनेके लिए हमारे पास आती है कि क्या हम उसे कोई अच्छी चीज दे सकते हैं । वे हमारे पास इसलिए आते हैं कि

हम शासनाखंड नहीं है, किन्तु वे इस बातका पक्का आश्वासन चाहते हैं कि जब राजनीतिक शक्ति हमारे हाथोंमें आ जायगी तो हम भ्रष्ट नहीं होंगे और अपनी प्रतिज्ञाओंके प्रति ईमानदार रहेंगे । केवल मौखिक आश्वासनोंसे उन्हें सन्तोष नहीं होगा । अकिंचन और शोषित वर्गोंके नि स्वार्थ सेवासे ही उनके सन्देह दूर हो सकते हैं ।

मजदूरोमें काम करनेका हमारी पार्टीमें अपना महत्त्व है, और यह देखकर सन्तोष होता है कि इस दिशामें काम आगे बढ़ा है । मजदूरोमें हमारा एक व्यापक मंच तैयार हो गया है और अधिकांश व्यक्ति जो जनतन्त्र और समाजवादके समर्थक हैं, इसमें सम्मिलित हो गये हैं । सभी गैर-कांग्रेसी और गैर-कम्युनिस्ट युनियन शीघ्र ही एक शक्तिशाली संघटनके रूपमें एकत्र हो जायेंगी जिसका नाम 'हिंद मजदूर सभा' रखा गया है । यह संघटन साढ़े छ लाखकी सदस्यतासे आरम्भ किया गया था और प्रभावशाली संघटनों द्वारा इसमें सम्मिलित होनेकी घोषणा की गयी है । बिहार और युक्तप्रान्तमें बहुत-सी ऐसी युनियने हैं जो सोशलिस्ट पार्टीके प्रभावमें हैं और इस संघटनमें सम्मिलित होंगी । आशा की जाती है कि 'हिंद मजदूर सभा' की कुल सदस्यता शीघ्र ही १५ लाख हो जायगी जो कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन कांग्रेसकी घोषित कुल सदस्यतासे कहीं अधिक है । उन सभी युनियनोंसे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन कांग्रेस अलग हो चुकी है और अबतक हमारे नये संघटनमें सम्मिलित नहीं हुई है । मैं अपील करता हूँ कि वे हमारे साथ शामिल हो और हमें बल प्रदान करे ताकि इस देशमें सुदृढ़ ट्रेड युनियन आन्दोलनका निर्माण किया जा सके । मजदूरोमें काम करनेके हमारे ढंगमें भी पर्याप्त सुधार करनेकी गुंजाइश है । हमें श्रमिक हितकारी कार्योंमें भी लगना चाहिये और मजदूर-वर्गको उत्तरदायित्वकी भावना बढ़ानेकी शिक्षा देनी चाहिये तथा उसे उसके उज्ज्वल भविष्यका भी ज्ञान कराना चाहिये ।

मैं आशा करता हूँ कि मैंने सभी मुख्य-मुख्य बातोंपर प्रकाश डाल दिया है । मुझे इस बातका पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टीका भविष्य महान् है । इसमें पर्याप्त शक्ति विद्यमान है और यदि हम यह जानते हैं कि अपने सामने आये हुए अवसरका उपयोग कैसे किया जाय तो हम जनताके हृदयमें अपने लिए स्थान बना लेंगे और दिनपर दिन शक्तिशाली हो जायेंगे । आज एक ऐसे दलकी आवश्यकता है जो जनतन्त्रवादी राज्यको सुदृढ़ बनानेके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो, हिंसात्मक तरीकोंके प्रयोगका विरोधी हो और जनतन्त्रवादी ढंगसे उत्पादनके साधनोंका समाजीकरण करना चाहता हो । हम क्रान्तिकारी युगमें रह रहे हैं, जब कि विशाल जन-समुदाय अधिकाधिक समाजवादी सिद्धान्तोंके प्रभावमें आ रहा है । सब जगह जनता शान्ति चाहती है, किन्तु यदि रोटीकी समस्या और किसी प्रकारसे हल न हुई तो लोग संघर्षका स्वागत करेंगे । पूंजीवादी शक्तियोंकी अदूरदर्शितापूर्ण नीतिने उन्हें अन्धा बना दिया है और वे परिस्थितिको नहीं समझ सकती । उनकी सर्वग्राही एकाधिकारकी प्रवृत्ति उन्हें इस सत्यका अनुभव नहीं होने देती कि उनकी नीतियों तथा कार्योंसे कम्युनिस्टोंका प्रभाव समाप्त होनेके स्थानपर बढ़ता ही जा रहा है । केवल तभी शान्ति कायम रह सकती है और युद्ध टाला जा सकता

है जब कि हितकारी योजनाओंको व्यापक रूपमें कार्यान्वित किया जाय, आयोजित आर्थिक प्रणालीके द्वारा मजदूरोके रहन-सहनका दर्जा ऊँचा उठाया जाय और उत्पादनके साधनोपर क्रमशः समाजका स्वामित्व स्थापित हो । आज कीमतें ऊँची चढ़ती जा रही हैं और मुद्रा-स्फीति घटानेके प्रयत्नोका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है । आर्थिक दुरवस्था जनताको उत्तेजित कर रही है और अव्यवस्थाकी स्थितिमें पनपनेवाले लोग इसका पूरा-पूरा लाभ उठानेके लिए सन्नद्ध हैं । किन्तु फिर भी सरकार उस खतरेसे भलीभाँति अवगत नहीं है जो कि उसके सामने विकट रूप में खड़ा है । जब उसके विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वह पूँजीपतियोंको प्रसन्न रखनेकी नीति अपना रही है और स्थिर स्वार्थियोंद्वारा प्रभावित है तो उसके सूतधारोको बुरा लगता है । परन्तु भेरी समझमें नहीं आता कि उनकी इस नीतिकी और कौनसी दूसरी व्याख्या की जाय जो दिनपर दिन पूँजीपतियोंके सूक्ष्म प्रभावमें जा रही है । हमें इस बातको समझना चाहिये कि हम इतिहासके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते । हमें अपनेको यह धोखा नहीं देना चाहिये कि भारतवर्ष दक्षिण-पूर्वी एशियाके देशोंसे भिन्न है । सकटकालमें एकाएक उथल-पुथल होती है और उसी प्रकार जनमतमें आत्यन्तिक परिवर्तन हो जाते हैं । ऐसी दुःखद स्थितिमें हमारा कार्य और भी कठिन हो गया, किन्तु इस कठिनकालमें हमारे कार्यकर्ताओंमें हतोत्साह और निराशा नहीं आनी चाहिये, प्रत्युत इससे हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिये । यदि हम अपनी 'पार्टी' को विरोधी दलके रूपमें सघटित कर सके तो हम इस मन स्थितिका उपचार कर सकेंगे । किसी उत्कट कार्यक्रमकी आवश्यकता नहीं है । केवल ऐसे सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिये जो वृद्धिजीवी-वर्गकी उदासीनताको दूर कर सके और उसमें नये उत्साह और नयी आशाका संचार कर सके । हमारी जनता अज्ञान और निर्धनतामें डूबी हुई है, वह निष्क्रिय और निरुत्साह हो गयी है और उसकी सारी आशाएँ और अभिलाषाएँ समाप्त हो चुकी हैं । किन्तु यदि हम उनके उत्साह तथा खोये हुए आत्म-विश्वासको पुनर्जाग्रत कर सके तो हम उन्हें पुनः सक्रिय रूपमें ला सकते हैं और यह तभी सम्भव है जब कि 'पार्टी' चरित्रवान कार्यकर्ताओंको उत्पन्न कर सके जिनका 'पार्टी' के सिद्धान्तों और उसकी नीतिमें दृढ़ विश्वास हो । केवल इसी प्रकारका विश्वास ही नवजीवन प्रदान कर सकता है और भयंकर सकटकी घड़ियोंमें, जब कि उनके विश्वासका परीक्षणकाल है, उन्हें दृढ़ और अविचल रख सकता है । 'पार्टी' के समक्ष यही प्रमुख कार्य है और हमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति इसकी पूर्तिमें लगा देनी चाहिये ।

इतिहास हमारे पक्षमें है । आज मानव-समाजोंको एक नवीन सामंजस्य और समन्वयकी आवश्यकता है । चारों ओर प्राचीन और अर्वाचीनमें तीव्र सघर्ष हो रहा है । यह नवयुगका उषाकाल है और हमलोग मुक्तिके द्वारपर खड़े हैं । किन्तु सामाजिक स्वतन्त्रताके सूर्योदयसे पूर्व हमें अपनेको उस नव-संस्कृतिके योग्य सिद्ध करना है । वर्तमान युगमें लोकतन्त्रको प्रतिष्ठित करनेके लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी अर्थनीतिको जनहितकी दृष्टिसे सुनियोजित करें । यदि हम दृढ़ता और विश्वासके साथ अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होते रहें तो सभ्यताकी अगली मजिलको अवश्य प्राप्त करेंगे ।

मुझे विश्वास है कि सोशलिस्ट पार्टी अपनेको पूर्ण समर्थ बनायेगी और कार्यरूपमे यह सिद्ध कर देगी कि लोकतन्त्र और समाजवादकी एक साथ प्रगति सम्भव है ।

सत्याग्रह और प्रजातन्त्र

इस समय इंग्लैण्डमे मकानोकी बड़ी किल्लत है । गरीब बे-घरवार हो रहे हैं और अमीरोंके पलैट कहीं-कहीं खाली पड़े हैं तथा फौजके लोगोंके रहनेके लिए बनाये गये कैम्प भी खाली हैं । अधिकारियोंसे कहा गया कि खाली मकानोको इन गरीबोंके लिए ले लिया जाय, किन्तु उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया । जब गरीबोंने देखा कि उनके रहनेका कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है तब उन्होंने इन रिक्त स्थानोंमे जाकर अपना सामान रखना आरम्भ किया । यह ठीक है कि उनका यह काम नियम-विरुद्ध है । किन्तु जब अधिकारी कुछ सुनते नहीं और टाल-मटोल करते हैं तब इनके लिए कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता । ऐसी अवस्थामे सत्याग्रहद्वारा ही अधिकारी अपना कर्तव्य पालन करनेके लिए विवश किये जा सकते हैं ।

‘न्यु स्टेट्स्मैन एण्ड नेशन’ (२४ अगस्त, १९४६) की सम्पादकीय टिप्पणीमे प्रश्न किया गया है कि इस घटनासे हम क्या सबक ले सकते हैं । सम्पादकका उत्तर यह है “सत्याग्रहद्वारा अधिकारियोंको अपने कर्तव्यसे नियोजित करना पड़ता है । मजदूरोंको विद्रोही समझकर उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है । यह नहीं समझना चाहिये कि उन्होंने अपने कार्यसे अपने इस हकको खो दिया है कि इनके साथ न्याय किया जाय । इसके विपरीत मन्त्रिमण्डलको सदा सतर्क रहना चाहिये और यह देखना चाहिये कि विविध विभागोंका काम इतना धीमा-तो नहीं है कि उसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो जाय जिसके विरुद्ध लोगोंको विद्रोह करना पड़े ।”

पुनः २८ सितम्बरकी एक टिप्पणीमे ‘न्यु स्टेट्स्मैन एण्ड नेशन’ कहता है कि यह आन्दोलन निस्सन्देह बहुत आवश्यक था । जो स्थानीय अधिकारी अपने काममे ढीले थे अथवा जो प्रतिक्रियावादी थे वे इस आन्दोलनसे बहुत डर गये । सम्भवतः इस आन्दोलनसे मिस्टर बेवन (Bevan) अधिक-से-अधिक मकान बनानेके लिए विवश हुए हैं । “यद्यपि सरकारके लिए इस आन्दोलनको रोकना अनिवार्य था, तथापि कभी-कभी थोड़ी गैर-कानूनी कार्यवाही और सत्याग्रह वैधानिक शासनकी व्यवस्थामे उपयोगी सिद्ध होते हैं । वे लोग भी जो व्यक्तिगत जायदादके स्वत्वोंकी दुहाई देते हैं इस आन्दोलनसे प्रभावित हुए हैं और उनकी समझमे आ गया है कि बे-घरवार लोगोंको कितना कष्ट होता है । इस आन्दोलनसे सरकारको यह भी मालूम हो गया है कि मकान बनानेके बारेमे जनता क्या चाहती है और इस प्रोग्रामके कार्यान्वित करनेसे जितनी तरक्की होगी उसी हिसाबसे जनता सरकारके कार्यके सम्बन्धमे अपनी राय कायम करेगी । विदेशी समाचार चाहे बड़े-बड़े शीर्षकोंके साथ पत्रोंमें दिये जायँ और ऐसे शीर्षक घरेलू राजनीतिको

नसीब न हो, किन्तु एक साधारण नागरिक सन्धियोंकी अपेक्षा मकानोकी कही ज्यादा फिकर करता है, यदि उसको यह विश्वास हुआ कि मजदूर-सरकार मकानोकी व्यवस्थाके लिए सब कुछ कर रही है, तभी उसका विश्वास सरकारको प्राप्त हो सकेगा !”

इसी प्रकार इंग्लैण्डमे कभी-कभी ऐसी हड़तालें होती हैं, जिनसे जनताको बड़ी असुविधा होती है । ये हड़तालें युनियनके अधिकारियोंकी रायसे भी नहीं होती: इसलिए ये नियम-विरुद्ध हैं । हड़ताल करानेवालोका यह कहना है कि जो मशीनरी मजदूरीके प्रश्नका निपटारा करानेके लिए बनी है उसकी गति इतनी मन्द है कि वह वर्दाश्तके बाहर है । उनकी यह भी शिकायत है कि युनियनके अधिकारी प्रबन्ध और व्यवस्थाके काममें डूबे रहते हैं और अपने उन दिनोंके पुराने अनुभवोको भूल गये हैं जब वे स्वयं मजदूरी करते थे । इसका फल यह है कि अब वे मजदूरोकी सच्ची हालतको नहीं जानते और इस प्रकार सामान्य मजदूरोकी जो शिकायतें हैं, उनके साथ उन्होंने सहानुभूति खो दी है । इसलिए उनका कहना है कि सारी मशीनरीको एक धक्का लगाना है । उनका कहना ठीक है कि अधिकारियोंको सत्याग्रहद्वारा ही सक्रिय बनाया जा सकता है । आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग-व्यवसायके सघटन तथा मजदूरोसे समझौता करनेकी मशीनरीमे आमूल परिवर्तन किया जाय न कि हड़ताल करनेवालोको विद्रोही कहकर दण्ड दिया जाय ।

हमारे देशमे इस समय हड़तालोकी बाढ-सी आ गयी है, किन्तु यह समझना हमारी भूल होगी कि इन सबके पीछे कम्युनिस्टोका हाथ है । मजदूरोकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है । उनको अनेक प्रकारके कष्ट हैं । उनकी युनियनको प्रायः मान्यता नहीं दी जाती । उनकी शिकायतोको सुनना और ऐसे कानून बनाना जिससे उनके कष्टोका निवारण हो शासकोका कर्त्तव्य है । प्रत्येक हड़तालसे किसी-न-किसीको कष्ट अवश्य होता है । यह भी ठीक है कि सामानके तैयार होनेमें रुकावट होती है, जिसके कारण जनताका कष्ट और बढ़ जाता है । किन्तु फिर इसका इलाज क्या है ? हड़ताल ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके प्रयोगसे मजदूरवर्ग अपने कष्टोका निवारण करता है । ट्रेड युनियन आन्दोलनका आधार ही हड़ताल है । इस अस्त्रको मजदूरोके हाथसे छीन लेना उनके साथ अन्याय करना है और उनको बेवश तथा लाचार कर देना है । अपनी सम्मिलित शक्तिसे मजदूरी तय करनेका सिद्धान्त (collective bargaining) माना जा चुका है । जब मजदूरोकी उचित माँगोंकी बराबर उपेक्षा की जाती है, तब उनकी प्रार्थनापर ध्यान नहीं दिया जाता, तब उन बेचारोके लिए हड़तालके सिवा दूसरा उपाय ही क्या है ? जब उनकी सर्वथा उपेक्षा की जाती है तब अधिकारियोका ध्यान आकृष्ट करनेके लिए वे कभी-कभी शान्तिमय प्रदर्शन करते हैं । इसपर वे गिरफ्तार कर लिये जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि तबतक वे कामपर वापस न जायेंगे जबतक उनकी माँगोपर विचार नहीं किया जायगा । हम नहीं समझते कि सरकार इन प्रदर्शनोंसे क्यों भयभीत है ? शान्तिमय प्रदर्शन और हड़ताल करनेका सबको हक है । हम नहीं मान सकते कि अपनी सरकार होनेपर यह अधिकार जाता रहता है । ‘लॉ एण्ड आर्डर’ का होवा दिखाकर नागरिक स्वतन्त्रताका अपहरण नहीं किया जा सकता । शान्ति और

कानूनकी स्थापना होनी चाहिये, किन्तु इसके लिए नागरिक स्वतन्त्रताका बलिदान सामान्य अवस्थामे नहीं किया जा सकता। साम्प्रदायिक बलवोकी बात न्यारी है। उनकी तुलना शान्तिमय प्रदर्शनों और हड़तालोसे करना उचित नहीं है। यदि सरकार स्वयं मजदूरोके हितोका ध्यान रखे तो हड़ताल और प्रदर्शनोंकी प्रायः आवश्यकता ही न हो। किन्तु देखनेमे यही आता है कि अच्छीसे अच्छी सरकारपर भी कर्तव्यपालन करनेके लिए दबाव डालना पड़ता है। मिल-मालिकोसे तो न्यायकी आशा करना ही व्यर्थ है। अनुभव यही बताता है कि जो युनियन हाल की है और कमजोर है, उनको जिन्दा रहनेके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मालिकोसे अपनी छोटीसे-छोटी माँगको मनवानेके लिए भी हड़तालकी धमकी देनी पड़ती है या सचमुच हड़ताल करनी पड़ती है। मालिक यूनियनको सदा बुरी दृष्टिसे देखते हैं और वे यही समझते हैं कि इनसे हमारे अधिकारोको खतरा है। हमारी रायमे प्रजातन्त्रके लिए कभी-कभी सत्याग्रहका सहारा लेना पड़ता है। विद्रोह कहकर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि हिंसाका प्रयोग रोकना है तो शान्तिमय सत्याग्रहके अधिकारको कभी भी नहीं छीनना चाहिये। अधिकारियोको अपने कर्तव्यका ज्ञान करानेके लिए और उनकी सुस्ती दूर करनेके लिए यह एक उत्तम उपाय है। हम विनयपूर्वक कहना चाहते हैं कि स्वराज्यके स्थापित होनेपर भी इसका अधिकार रहना चाहिये। किन्तु आज तो हम पूर्ण स्वराज्यका उपभोग भी नहीं कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम न करे जिससे हमारे विरोधियोको यह कहनेका अवसर मिले कि जिन कामोके लिए हम विदेशी शासनकी निन्दा करते थे, उन्हीं कामोको हम स्वयं कर रहे हैं।

मालिक और मजदूरके आपसी झगड़ोको तय करनेके लिए अनिवार्य पचायतका प्रस्ताव रखा गया है। आजके युगमे लोग राज्यपर अधिकाधिक निर्भर रहना चाहते हैं। मालूम होता है कि प्रजातन्त्रके तरीकोपरसे लोगोका विश्वास उठता जाता है। हर बातके लिए कानूनकी माँग की जाती है। किन्तु कानूनसे उद्योगके क्षेत्रमे शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। उल्टे इससे झगड़ोके बढ़नेका अन्देशा है। इस अनिवार्य गुलामीसे बचनेके लिए मजदूर हिंसा करनेके लिए मजबूर हो जायगा। यदि अदालतका निर्णय मजदूरको पसन्द न आया तब वे उस निर्णयका विरोध करेंगे और सरकारके विरुद्ध हड़ताल करनेके लिए बाध्य होंगे। हमको तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिसमे मजदूर सहयोग करें, न कि विद्रोह।

अमेरिकाके प्रेसीडेंट ट्रूमैनने तो हृदय कर दिया। वह इतना आगे बढ़ गये कि उन्होंने गत मईके महीनेमे कांग्रेससे एक ऐसा असाधारण कानून बनवाना चाहा जिसका अर्थ मजदूरको संगीनोके भयसे अपने कामपर बने रहनेके लिए मजबूर करना है। उन्होंने अपने लिए ऐसे अधिकार चाहे, जो किसी प्रेसीडेंटको कभी नहीं दिये गये। उनकी माँग यह है कि जब कभी कोई हड़ताल हो तो उनको किसी भी व्यवसायपर कब्जा करने तथा असाधारण अवस्थाकी घोषणा करनेका पूरा अधिकार हो। ऐसी घोषणाके बाद वह मुनाफा जम्मा कर सकें, आज्ञाका पालन न करनेपर मजदूर-नेताओको जेल भेज सकें, मजदूरोंके

के हकोंको वापस ले सके, और नियत की गयी मजदूरी और शर्तोंपर उनको कामपर वापस जानेका हुक्म दे सकें। यदि मजदूर इन्कार करे तो वे सेनामें उनकी अनिवार्य भरती कर सकें और सिपाहीकी हँसियतसे उनपर फौजी कानून लागू कर सकें। जो तनखाह सिपाहियोंको दी जाती है, उसी तनखाहपर उनसे कारखानोंमें काम लें और यदि वे इस पर भी हड़ताल करे तो उनके कोर्टमार्शलकी आज्ञा दे सकें।

यह तो प्रजातन्त्रका गला घोटना है। इससे मजदूरोंकी हालत गुलामोंसे भी बदतर हो जायगी। मालिक मजदूरके झगड़े ऐसे हैं जो आपसके समझौतेसे ही तय हो सकते हैं। इनमें राज्यका दखल देना अनुचित होगा। जब किसीको भी उसकी इच्छाके विरुद्ध काम करनेके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, तब यह विचित्र बात मालूम पड़ती है कि सामूहिक रूपसे उसी कामको करनेके लिए मजदूर बाध्य किया जा सकता है। जिसे कोई अकेले कर सकता है उसे औरोंके साथ मिलकर क्यों नहीं कर सकता? अनिवार्य पंचायतद्वारा मिल-मालिकोंके झगड़े तय कराना प्रजातन्त्रकी पद्धतिके प्रतिकूल है।

कृषिसुधार-समितिके सामने वयान

मेरा पहला प्रस्ताव यह है कि सरकार और कृषकों यानी जमीन जोतनेवालोंके बीच और कोई मध्यवर्गी लोग न हों। युक्त प्रदेशकी धारासभाने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया था उसका आशय यह था कि सरकार और खेतिहरोंके बीचके सबलोग उठा दिये जायें, पर जमींदारी उठा देनेके प्रश्नका विचार करनेके लिए जो कमेटी सरकारने नियुक्त की थी उसने अपनी सिफारिशोंका आधार इसे नहीं माना है। कमेटीने इसे बहुत बदल डाला है। मुझे स्मरण है कि सार्वजनिक निर्वाचन होनेके पूर्व कांग्रेस-कार्यसमितिने निर्वाचन सम्बन्धी जो मन्तव्य अपनाया था उसमें यह कहा गया था कि सरकार और किसानके बीचके लोग उठा दिये जायें। उसमें 'किसान' शब्दका प्रयोग किया गया था। कार्य-समितिकी उस बैठकमें मैं उपस्थित था जिसमें यह मन्तव्य स्वीकृत हुआ। (असेम्बलीवाले अपने प्रस्तावमें हमलोगोंने 'काश्तकार' शब्द रखा था।) मूल मसविदेमें 'जमीन जोतनेवाला' ये शब्द थे और इनका प्रयोग पण्डित जवाहरलाल नेहरूने किया था। कुछ वाद-विवादके पश्चात् यह राय हुई कि सब प्रकारके किसानोंको अलग कर देना ठीक न होगा, चाहे कोई किसान खुद जमीन जोतते हों या पारिश्रमिक देकर दूसरोंसे जुतवाते हों। अतः मेरा पहला प्रस्ताव यही है कि सब प्रकारके बीचके लोग उठा दिये जायें। जमींदारी उठा देनेका विचार करनेवाली कमेटीकी जो सिफारिश है उसके अनुसार तो काश्तकारोंके बहुतसे शिकमी काश्तकार जमीनसे वंचित हो जायेंगे। कमेटीकी रिपोर्टमें उनके अधिकार नहीं माने गये हैं और नयी सिफारिशें कानूनको गवर्नर-जनरलकी मंजूरी मिलते ही अमलमें आ जायेंगी। इस बीच फार्मोंकी संख्या बढ़ेगी और किसानोंकी जमीनें छिन जायेंगी। किसानोंके शिकमी काश्तकारोंका कोई वैधानिक अधिकार नहीं माना गया है, इससे पूंजी-

पतियोंके फार्म धीरे-धीरे बनते जा रहे हैं। अतः अभीसे यदि इसकी रोक-थाम न हुई तो भविष्यमें देख पड़ेगा कि बड़े-बड़े फार्म बन गये हैं जिन्हें पूँजीपति अथवा व्यक्तिविशेष चला रहे हैं। कमेटीकी इन सिफारिशोंमें जमीनके पुनर्वितरणकी कोई विधि नहीं है। मेरे विचारमें बहुसंख्यक गरीब किसानोंकी दृष्टिसे सबसे पहला सुधार जो अत्यन्त आवश्यक है, यह है कि जमीनके पुनर्वितरणका अधिकार सरकारके हाथमें होना चाहिये और यह काम आजमें ही हाथमें लिया जाना चाहिये।

दूसरी बात क्षतिपूर्तिके सम्बन्धमें है। हमलोगोंका जहाँतक सम्बन्ध है, हमलोग सिद्धान्ततः क्षतिपूर्ति करना ठीक नहीं समझते, यद्यपि इस विषयमें मतभेद है। यूरोपके जो समाजवादी अपनेको मार्क्सवादी नहीं कहते, क्षतिपूर्तिकी रकम देना ठीक समझते हैं, पर उनका कहना यह है कि क्षतिपूर्तिका भार अन्य शोषक श्रेणियोंपर रखा जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, सरकार कोई उद्यम अपने हाथमें ले और उस उद्यमके जो लोग पहले मालिक थे उन्हें क्षतिपूर्ति देनी हो तो यह क्षतिपूर्ति अन्य उद्योग-धन्धेवालोंको करनी होगी। यही उनका नियम है। उपस्थित प्रसंगमें हमलोगोंकी यह राय तो नहीं थी कि जमीनके मालिक जानकर किसीको क्षतिपूर्तिकी रकम दी जाय, पर पुनर्निवासके आधारपर क्षतिपूर्ति कराना हमलोगोंने स्वीकार किया था अर्थात् जिन लोगोंकी जमीन ले ली जायगी उन्हें यह अधिकार है कि सरकार उन्हें फिरसे बसाये। इसी आधारपर हमने क्षतिपूरण माना है। और यही जब मानना है तब क्षतिपूर्ति पानेका अमीरोंको तो कोई अधिकार नहीं रहता, पर गरीबोंको अधिकसे अधिक रकम मिलनी चाहिये और उनके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिये कि वे कोई नया उद्योग-धन्धा शुरू कर सकें। यह दूसरा सिद्धान्त है। पर हमलोग देखते हैं कि हमारी सिफारिश सरकारको स्वीकार होनेवाली नहीं है, इसलिए हम क्षतिपूर्तिकी एक मर्यादा निश्चित करना चाहते हैं। सरकार तो यह निश्चित कर ही चुकी है कि क्षतिपूर्ति की जाय और यह भी तय कर चुकी है कि जिन मालिकोंको १०,००० रु० से अधिक मुनाफा मिलता रहा हो उन्हें उनके मुनाफेकी तिगुनी रकम दी जाय। हमलोगोंने सबसे बड़ी मर्यादा यह रखी है कि एक लाख रुपयेसे अधिक क्षतिपूर्तिकी रकम किसीको भी न दी जाय। फिर, बहुत से गरीब जमींदार होंगे जिनकी जमीने निकल जायेंगी। सरकार उन्हें क्षतिपूर्तिके तौरपर जो कुछ देना चाहती है वह बहुत-ही कम है। यह रकम भी उन्हें एक मुश्त नहीं मिलेगी बल्कि किश्त-दर-किश्त कई बरसोंमें पूरी की जायगी। इससे उन्हें कोई नया उद्योग आरम्भ करनेकी सुविधा नहीं मिलेगी। अतः इसके हम विरोधी हैं। हमलोग यह चाहते हैं कि किसीके भी हाथमें ३० एकड़से अधिक जमीन न होनी चाहिये और यह बात अभीसे हो, आगेके लिए छोड़ न दी जाय। इस तरीकेसे सरकार बड़े-बड़े फार्मोंको तोड़ सकेगी और जो जमीन इस तरह मिलेगी वह उन छोटे जमींदारोंको बाँट दी जा सकेगी जो खेती करना चाहते हैं, दूसरोंके परिश्रमका शोषण न कर स्वयं हल चलाना चाहते हैं। इन लोगोंके फार्म बड़े किये जा सकते हैं और नयी शर्तोंपर उनकी सख्या बढ़ायी जा सकती है। यह दूसरा सुधार है जो हमलोग सूचित करते हैं। हमारे प्रान्तमें सैकड़ें ६० से भी अधिक खाते आर्थिक दृष्टिसे लाभजनक नहीं हैं।

मैं जानता हूँ, जमीनकी उपज बढ़ानेके लिए कई उपाय करने पड़ेंगे जैसे अच्छे बीज, खाद और अच्छी नस्लके बैल । पर इतनेसे ही काम न चलेगा । जमीनकी उपज बढ़ानेमें बहुत समय लगेगा । किसानोंकी आमदनी बढ़ानेका कोई दूसरा उपाय भी करना होगा । किसानोंके इन छोटे-छोटे खातोंको लाभजनक बनानेके काममें बड़ी कठिनाई है । पर मुझे स्मरण है कि एक बार युक्तप्रदेशकी प्रान्तिक कांग्रेस कमेटीने एक प्रस्तावके द्वारा उस समयकी सरकारसे यह सिफारिश की थी कि जो खाते लाभजनक नहीं हैं वे जब तक लाभजनक नहीं हो जाते तबतक उनपर कोई लगान न लगायी जाय । मेरी सूचना यही है कि हर उपायसे इन खातोंको लाभजनक बनाया जाय । किसी हद तक यह काम बन सकता है, क्योंकि हमारे प्रान्तमें बहुत-सी जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो अभीतक जोती नहीं गयी है । खेती करने लायक जमीनमेंसे १९० में बीस हिस्सा जमीन जोती जा सकती है । सरकारका यह कर्त्तव्य है कि यह जमीन जोतनेके काममें लाये और यहाँ किसानों करनेवाले मजदूरोंको बसाये । इस तरह उन्हें मौका दे कि वे अच्छे किसान बने । पर मेरा यह विशेष आग्रह है कि जबतक खाते लाभजनक नहीं बन जाते तबतक उनकी कुछ मदद की जाय । एक मदद यह है कि यदि इन्हे पूरी लगानकी छूट न दी जा सकती हो तो कमसे कम वह लगान बहुत कुछ घटा दी जाय ।

जमींदारी-उन्मूलन कमेटीका यह ध्यान है कि जमींदारवर्गका उन्मूलन होनेपर काश्तकार वही लगान देता रहेगा जो वह आज दे रहा है । अतः उसकी स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और न उसे कोई सन्तोष हो सकेगा । यदि जमींदारवर्ग उठा देना है तो किसान यह समझता है कि उसका स्थान हमलोग ग्रहण करेंगे और जो रकम जमींदार मालगुजारीके तौरपर देते थे वही हमलोग दिया करेंगे । लगानका जो बोझ किसानोंपर आज है वह यदि घटनेवाला न हो तो इससे देहातोंमें असन्तोष फैलेगा । जमींदारी उठ जानेपर भी किसानोंको वही लगान देना पड़ेगा, यह बात उचित नहीं मालूम होती । हमारी सिफारिश यह है कि जमींदार आज जो मालगुजारी दे रहे हैं उससे अधिक किसानोंको कुछ न देना पड़े । इस सम्बन्धमें यह प्रश्न उठता है कि तब मुआविजेका बोझ कौन उठाये । सरकारने अब इसे लगान न कहकर मालगुजारी कहनेका तरीका इच्छित्यार किया है । इससे किसानोंकी स्थितिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । सरकार यह कह सकती है कि जमींदारोंको जो मुआवजा देना है उसका भार काश्तकार उठा ले । हमलोग इसके विरोधी हैं, क्योंकि इसे हम एक दूसरे प्रकारका शोषण ही समझते हैं । यदि यह भार उसके सिरोपर आगामी ४० वर्षतक बना रहा तो जमींदारके बदले सरकारके द्वारा उनका यह शोषण ही हुआ । हमारी सूचना यह है कि या तो यह बोझ स्वयं सरकार उठा ले या अन्य शोषक वर्गोंके कन्धोंपर रखा जाय अर्थात् उद्योग-धन्धोंके मालिकोंपर करोका बोझ खूब बढ़ाकर यह रकम वसूल की जाय । मैं तो यह भी पसन्द करूँगा कि ये काश्त या ये खाते किसानोंको बेच दिये जायँ, क्योंकि हमलोग यह नहीं चाहते कि किसानोंमें जमींदार हो जाने की भावना भर जाय जबतक कि वे जमींदार माने जानेकी पुकार स्वयं न मचाये । उनपर लगानका बोझ यदि हलका हो जायगा तो उन्हें पर्याप्त सन्तोष होगा, साथ ही यदि

यह अधिकार किसीको न हो कि उनसे बेगारी ले सके और न उनकी बेदखलियाँ हो सकें यह कहना तो कोई दलील नहीं है कि मुआवजेका बोझ जब काश्तकारको ढोना है तब सरकार उससे लगान ही लेती रहेगी, न कि मालगुजारी ।

हम लोकतन्त्रसे वैगै हुए हैं, अतः यह सर्वथा आवश्यक है कि मानवताका ध्यान रखा जाय और देहातोमे लोगोके जो परस्पर सम्बन्ध है उन्हें बदलकर एक नवीन लोकतन्त्रात्मक आधारपर स्थापित किया जाय । देहातोमे लोकतन्त्रात्मक चाल-ढाल, रहन-सहन चलाने तथा लोकतन्त्रकी परम्परा स्थापित करनेके लिए सहयोग का होना नितान्त आवश्यक है । सहयोग ही ग्राम-जीवनका आधार होना चाहिये ताकि ग्रामीण जनता परस्पर सहयोग करना सीखे, सहयोगसे उत्पादन करे और सहयोगसे ही अपने उत्पादनका त्रय-विक्रय करे । ग्राम-पंचायत ग्रामकी राजनीतिक, अदालती और आर्थिक सघटन-संस्था मानी जाय । इस तरह सहयोग आरम्भ कराना मैं बहुत ही आवश्यक समझता हूँ । सामूहिक खेतीके मैं विरुद्ध हूँ, कारण देहातोमे इसकी सम्भावना नहीं देख पड़ती । इसका बड़ा विरोध होगा जैसा कि रूसके अनुभवसे प्रकट है । हम यह भी जानते हैं कि सभी कम्युनिस्टो और फोर्न इण्टरनेशनलके सदस्योने इसका परित्याग कर दिया है और यह निश्चय किया है कि जोर-जबर्दस्ती और हिंसासे काम लेनेके बजाय अधिक अच्छा तरीका यह है कि लोगोको समझा-बुझाकर, लाभ और सुविधा दिखाकर तथा प्रचार-कार्यके द्वारा लोगोको इस बातके लिए तैयार किया जाय कि वे एक रूप होकर सहयोगका अवलम्बन करे । कृषक अनुभवसे सीखते हैं । यदि पास-पड़ोसमे अच्छे प्रयोग-फार्म हो और कृषक यह देखें कि खेतीका यह ढंग अधिक अच्छा है और इससे अधिक उपज होती है तो वे भी उसका अनुकरण करने लगेंगे । इसमे अवश्य ही कुछ समय लगेगा और आरम्भ अभीसे कर देना चाहिये । मेरे विचारमे, यह काम सरकारी तौरपर बहुत अच्छा नहीं होता । पहली बात यह है कि हमलोगोंमें वह उत्साह और वह सत्साहस नहीं है जो देहातोमे नव-जीवनका संचार करनेके लिए अत्यन्त आवश्यक है । हम व्यक्तिप्रधान लोग हैं, फिर भी ग्राम-पंचायत-का कुछ प्रभाव तो अब भी जनताके चित्तपर है । यदि इस पंचायत-पद्धतिका पुनरुद्धार किया जाय, उसके उस पुराने ढंगपर नहीं बल्कि आजकी आवश्यकताओको सामने रखकर एक नये ढंगसे एक नवीन आधारपर यह काम हो तो मैं समझता हूँ कि लोग धीरे-धीरे उसे अपनायेंगे ।

लगानकी वसूलीका काम ग्राम-पंचायतके द्वारा ही होना चाहिये । दो-तीन गाँव मिलकर एक सहयोगी संस्था बना सकते हैं, कारण बहुतसे गाँव बहुत ही छोटे-छोटे हैं । सहयोगी खेत बनानेके सम्बन्धमे गाँवके जन-समाजका जनमत लिया जाय, यदि समाजके दो-तिहाईसे अधिक वालिग लोग सहयोगी खेतीके पक्षमे हो तो सहयोगी खेतीका आरम्भ करा दिया जाय । ऐसे खेतोको विशेष अवसर और विशेष सुविधाएँ दी जानी चाहिये, ताकि दूसरे लोग भी धीरे-धीरे इसका अनुकरण करने लगे । यदि इस तरह सहयोग

चला तो इससे परस्पर सम्बन्धका एक नया ढंग निकल आया और इससे गाँववालोंमें लोकतन्त्रकी वह भावना भर जायगी जिसकी इतनी आवश्यकता है ।

इस सम्बन्धका और एक पहलू है जिसका कृषिसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी बड़े महत्वका है । गाँवोंकी अबतक इतनी उपेक्षा हुई है कि उन्हें सुधारने और एक वातावरण उत्पन्न करनेकी कोई चेष्टा नहीं की जायगी जिसमें गाँववाले अपनेको सुखी समझ सकें तो गाँवोंकी कोई उन्नति नहीं होगी । आजकी स्थिति यह है कि जो लोग शिक्षित हो लेते हैं वे गाँवोंमें नहीं रहना चाहते । इससे गाँवोंके कोई नेता नहीं होते और होते हैं तो वे ही पुराने ढंगके आदमी । मैं समझता हूँ, यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारे नवयुवक शिक्षा ग्रहण कर इस योग्य बने कि अपनी जनताकी सेवाके लिए गाँवोंमें रह सकें । हम देखते हैं, हमारे प्रान्तमें जनताको साक्षर बनानेके लिए एक बहुत बड़ा आन्दोलन चला है । पर अनुभव यह बतलाता है कि जो लोग आज साक्षर होते हैं वे कुछ समय बाद निरक्षर हो जाते हैं, कारण जहाँ वे रहते हैं वहाँ कोई सांस्कृतिक वातावरण नहीं है । अतः यह जरूरी है कि ये स्कूल और पाठशालाएँ समाज-जीवनके केन्द्र बनें । उनके साथ पुस्तकालय और वाचनालय हो, साथ ही थियेटर और आमोद-प्रमोदके उपयुक्त साधन गाँवोंमें हो । मैं केवल अर्थकी दृष्टिसे इसका विचार नहीं करता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे भी इसे देखता हूँ । ग्रामका सारा दृश्य एक मनोहर चित्र बने । इसके लिए यह आवश्यक है कि ये सब सुधार तुरत और एक साथ किये जायँ ।

अब कृषि-सम्बन्धी मजदूरकी बातपर मैं आता हूँ । इन मजदूरोंकी हालत बहुत ही खराब है । कानूनसे उनकी कोई कमसे कम मजदूरी नहीं निश्चित हुई है । बहुतसे स्थानोंमें जानता हूँ जहाँ हमारा यह आन्दोलन नहीं पहुँचा है और नवीन जागरण नहीं उत्पन्न हुआ है वहाँ जमींदार इन मजदूरोंको ४ या ५ आने प्रतिदिन देते हैं । कहीं-कहीं १० या १२ आने अथवा एक रुपये तककी मजदूरी बढी है, पर सर्वत्र नहीं । इसलिए मेरी यह सूचना है कि कृषि-सम्बन्धी मजदूरकी कमसे कम मजदूरी निश्चित करनेवाला कोई 'कम-से-कम मजदूरीका कानून' शीघ्र ही बन जाय । फिर जब नये सरकारी फार्म बन जायँ तब इन भूमिरहित मजदूरोंको उन जमीनोपर बसनेको राजी किया जाय ।

तब भी उनकी आमदनीकी कमी पूरी करनेके लिए गृह-शिल्पके धन्धोंकी आवश्यकता रहेगी ही । कृषि-सम्बन्धी मजदूरोंका भाग्य तबतक सुधर नहीं सकता जबतक सरकार गृहशिल्पके धन्धे चलानेमें विशेष यत्नवान् नहीं होती । यदि यह काम सहयोगके आधार-पर हुआ तो मानवताके नाते यह भी एक विशेष लाभ होगा । पर कम-से-कम गृहशिल्पका उद्धार तो करना ही चाहिये । —

अनिवार्य गल्ला-वसूली योजना

अन्न और सिविल सप्लाईके मिनिस्टरने २३ अप्रैलको प्रेस कान्फरेन्समें सरकारी खाद्य-नीतिका समर्थन किया और डा० लोहियाकी आलोचनाओंका जवाब देनेकी कोशिश

की। डा० लोहिया एक योग्य अर्थशास्त्री हैं और विलक्षण वाद-विवादी हैं। वह अपनी खबर-खुद ही ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि जब वे अपने दौरेसे वापस आवेंगे तो अपने आलोचकोको तर्कपूर्ण ढंगसे जवाब देंगे।

जनताका तिरस्कार

मेरा यह वक्तव्य देना केवल इसलिए जरूरी हो गया कि वाद-विवादमे मेरा नाम खींच लाया गया और जनताके दिमागपर ऐसा प्रभाव डालनेकी कोशिश की गयी मानो इस मामलेमे सोशलिस्ट पार्टीकी जो नीति है उससे मेरा मतभेद है। यह सही है कि मैं कण्ट्रोल नीतिका बराबर समर्थक रहा हूँ और कण्ट्रोल-तोड़ नीतिका कट्टर विरोधी रहा हूँ जिसे प्रान्तीय सरकारोंने चलाया और जिससे देशको बहुत नुकसान पहुँचा। यह भी सही है कि पिछले साल मैं अनिवार्य गल्ला-वसूलीके पक्षमे था, लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि मैं उस योजनाका पूरे तौरपर समर्थन करता था। मैं योजनाकी कुछ खास बुरी बातोंके खिलाफ था और बराबर मैंने इसकी ताईद की कि योजनामे जो खराबियाँ हैं उन्हें दूर किया जाय। उनदिनो गाँव-पंचायतोंके अभावमे अनिवार्य वसूली ही एकमात्र व्यावहारिक उपाय थी। लेकिन अब पंचायते कायम हो गयी हैं। मैं इसका कोई कारण नहीं देखता कि जनताके इस संगठनको वसूलीका काम अपने ऊपर लेनेके लिए क्यों नहीं प्रेरित किया जाय।

अगर हमलोग जनतामे प्रजातान्त्रिक भावना भरना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि वे अपने मामलेका प्रबन्ध और अपने आर्थिक जीवनको खुद व्यवस्थित करे तो हमपर ही यह निर्भर करता है कि हम-उन्हे सरकारकी आर्थिक नीतियोंको अमलमे लाने लायक बनावें। जन-साधारणमे हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है और हमारा उनपर कुछ भी भरोसा नहीं है। यही कारण है कि हम उनपर जिम्मेदारी डालनेकी बात नहीं सोचते। किसानोंमे सगठनात्मक प्रतिभाकी कमी नहीं है, हमें उन्हें केवल जगाना है और किसानोंको उनकी प्रतिभासे परिचित करा देना है। अनेक सदियोंसे इस प्रतिभाको दबाया गया है और अब उसे रचनात्मक काममे लगानेके लिए स्वतन्त्र वातावरणकी जरूरत है। मेरा पक्का विश्वास है कि बिना जनताके सक्रिय और जागरूक समर्थनके कोई भी बड़ा मसला नहीं हल हो सकता।

मुझे यह कहते हुए दुःख है कि सवालके इस पहलूको सही पार्श्वभूमिमे नहीं देखा गया। यह काम कठिन हो सकता है, लेकिन बिना जरूरी कोशिश किये किसीको हार कबूल नहीं करनी चाहिये। असलियत तो यह है कि सदियोंसे पीड़ित और शोषित किसानोंमे जो गतिहीनता और उदासीनता खास तौरपर पैदा हो गयी है उसे दूर करनेका सरकारने सुनहला मौका खो दिया।

सरकार 'माँ-बाप' बनी

लगता है कि सरकारके लिए जनताके संगठनका कोई उपयोग नहीं है। वह जनताके "माँ-बाप" के रूपमे काम करना चाहती है और यह महसूस करती प्रतीत नहीं होती कि

अगर जनता अपने मसले तय करनेमें खुद सक्रिय हिस्सा लेती है तो उसका कितना महत्व होता है। यही एक तरीका है जिसके जरिये सामाजिक अनुशासनकी सृष्टि की जाती है। हालात तो इतनी बिगड़ गयी है कि कभी-कभी गांधी-स्मारक फण्डके लिए चन्दा उठानेका काम अफसरोंपर छोड़ दिया जाता है। अभी-अभी फैजाबादसे लौटा हूँ और मैं यह जानकर दंग रह गया कि वहाँ इस फण्डके लिए चन्दे उठानेमें स्थानीय अफसरोंने प्रमुख हिस्सा लिया। आज भी वही दवाव और जबरदस्तीका तरीका लागू किया जाता है और लोगोंको यह जान कर आश्चर्य होगा कि जो लोग बन्दूक बगैरहके लाइसेन्सको नया करने या गोली खरीदनेके लिए परिमितके लिए दरखास्त देते हैं उनसे अनिवार्य रूपसे चन्दा ले लिया जाता है। शान्ति और अहिंसाके प्रतीकके नामके साथ इस घृणित कार्यको जोड़ देना अपवित्रतासे कम नहीं है। बहुत महीने पहले मुझसे कहा गया कि जिला अफसरोंके पास चन्दा न उठानेका आदेश भेज दिया गया है, लेकिन मैं पाता हूँ कि कमसे-कम फैजाबादमें तो इस आदेशका पालन नहीं किया जा रहा है। हर दृष्टिसे जबरदस्ती चन्दा लेनेका यह घृणित कायदा फौरन् बन्द होना चाहिये।

बसूली योजनाके दोष

यह निश्चित बात है कि हमलोग गाँव-पंचायतोंद्वारा बसूली नीतिको, जिसके लिए कारण उपर बताये जा चुके हैं, अमलमें लानेका तरीका पसन्द करेंगे, लेकिन किसी बजहसे सरकार अगर यह कदम उठानेको तैयार नहीं है तो सोशलिस्ट पार्टी अनिवार्य बसूलीका विरोध नहीं करेगी बशर्ते कि बसूली-योजनाकी खराब बातें दूर कर दी जाती हैं। इस मामलेमें मुझे यह कहनेके लिए डा० लोहियाका अधिकार प्राप्त है कि वह इस विचारका समर्थन करते हैं। बाराबंकीके गरीब किसानोंने—उनके बीच कोई धनी किसान नहीं थे—जो मेमोरेण्डम प्रधान मन्त्रीके पास पेश किया उसमें यह साफ लिखा हुआ था कि वे गल्ला-बसूली नीतिको अमलमें लानेमें सरकारसे सहयोग करनेको पूर्ण तैयार हैं। वे जो चाहते थे वह यह था कि वे प्रधान मन्त्रीका ध्यान अपनी उन तकलीफोंकी ओर खींचना चाहते थे जो उन्हें होंगी अगर योजना मूल रूपमें ही कार्यान्वित हुई।

मन्त्रीजी जरा सोचें

किसी जिम्मेदार मन्त्री या प्रधान मन्त्रीके लिए किसानोंको भड़कानेका दोष सोशलिस्ट कार्यकर्ताओंपर लगाना अशोभनीय है। साथ ही इस बिनापर कि किसानोंने अपने जिलेमें कायम किये गये सरकारकी गैर-सरकारी एजेन्सियोंको पूरा नजरअन्दाज किया उनकी माँगोंको सुननेसे इन्कार करना भी अशोभनीय है। जो पार्टी हुकूमतमें है उसकी गलतियों और धाँधलियोंसे हमारा राजनीतिक फायदा उठाना बिल्कुल जायज है, लेकिन हमलोग उन लोगोंसे नहीं हैं जो अपने संकुचित राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए जनताकी मुसीबतोंसे फायदा उठाते हैं। हम जो करते हैं वह शोषितोंके हितके लिए करना पड़ता है जिनका हित-साधन हमारा उद्देश्य है और हम बड़े धनी किसानोंके हितके लिए ऐसा नहीं करते जैसा कि बताया गया है। सोशलिस्ट पार्टी बड़े और धनी किसानोंका कोटा बढ़ानेके

पक्षमें है लेकिन वह गरीब किसानोंको जिनके पास फाजिल गल्ला नहीं है राष्ट्रीय संकटके नामपर शोषित होने नहीं दे सकती । शहरकी भलाईके लिए गाँवका युगोसे शोषण किया जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि गाँव और शहरके भेदको मिटा दिया जाय । सोशलिस्टो और कम्युनिस्टोके विश्वासका यही आधार है और हमलोग अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे अगर हमलोगोंने वसूली-योजनाके उन हिस्सोका विरोध नहीं किया जिसके मुताबिक नौकरशाहोंकी सुविधाके लिए गरीब किसानोंको अपने थोड़ेसे अन्नसे हिस्सा बँटानेको मजबूर किया जाता है ।

प्रदर्शनका अर्थ समझो

मैं पूरी जिम्मेदारीके साथ यह वयान देता हूँ कि जो किसान १५) या उसके आसपास तककी सालाना लगान देते हैं उनके पास सरकारको देनेके लिए अतिरिक्त गल्ला नहीं है । मैंने सरकारी आँकड़ोका अध्ययन नहीं किया है जिसे मैं जानता हूँ कि किसी भी सिद्धान्तके अनुकूल बनाया जा सकता है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभवसे उपर्युक्त बातें कह रहा हूँ । मैं अबधके किसानोंको काफी करीबसे जाननेका दावा करता हूँ और साथ ही मैंने गाँवके कुछ अहम सवालोकामें अध्ययन भी किया है । मेरे वयानकी सत्यताको जाननेके लिए केवल आसपासके गाँवोंमें जानेकी जरूरत है ।

फिर, मैं यह समझ नहीं सकता कि जों किसान बिल्कुल ही कोई फसल नहीं उपजाते हैं उन्हें खुले बाजारसे अन्न खरीदकर सरकारको देनेके लिए क्यों मजबूर किया जाय । इसके साथ-साथ यह तो होना ही चाहिये कि जिस इलाकेमें वर्षाकी कमी या ज्यादा या पत्थर पड़नेके कारण फसल खराब हुई है वहाँसे वसूली नहीं करनेकी व्यवस्था की जाय ।

मैं चाहूँगा कि लखनऊमें जो प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ, जैसा लखनऊके हालके इतिहासमें नहीं हुआ है, उससे खाद्य मन्त्री सही नतीजा निकालें और यह कहकर कि बुरे मतलबसे प्रदर्शनका आयोजन किया गया था नजर-अन्दाज नहीं करें । ये सुझाव बड़े अच्छे ख्यालसे दिये गये हैं ताकि गरीब किसानोंके प्रति अन्याय नहीं हो जिसके हितकी रक्षा हर हालतमें होनी ही चाहिये ।

गाँवोंमें शोषितोंका संयुक्त मोर्चा कायम हो'

यद्यपि प्रान्तमें गाँव-पंचायतोंका संगठन जिस रूपमें किया गया है उसमें बहुतसी त्रुटियाँ हैं, किन्तु पंचायतोंको जो भी अधिकार मिले हैं उनके जरिये बहुत कुछ काम हो सकेगा ।

१. पंच-सम्मेलनके प्रतिनिधियोंके कर्तव्यके सम्बन्धमें २६ मईको सम्मेलनमें दिया गया भाषण ।

क्रान्तिकारी अधिकार

गाँववालोको वालिग मतके आधारपर प्रतिनिधियोंको चुननेका अधिकार देकर निस्सन्देह युवतप्रांतीय सरकारने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वालिग मताधिकार एक क्रान्तिकारी अधिकार है, यह प्रजातन्त्रकी आधारशिला है, जम्हूरियतका बुनियादी पत्थर है। बिना जाति, सम्प्रदाय या सामाजिक हैसियतका भेद किये, सभी वालिग स्त्री-पुरुषोंको एक दर्जा दिये बिना जम्हूरियत, प्रजातन्त्र कायम नहीं हो सकता।

विराट् जनजागरण

इस क्रान्तिकारी अधिकारको पाकर सदियोंसे सतायी और कुचली हुई जनतामें एक नयी ताकत आयी। जो लोग इन्सान नहीं समझे जाते थे, जमींदारोंके सामने चारपाईपर नहीं बैठ सकते थे और खुलकर अपनी रायका इजहार नहीं कर सकते थे वे नीच जातिके पुकारे जानेवाले लोग गाँव-सभाओंके पंच और सरपंच चुने गये।

ग्रामीण वर्गसंघर्ष

गाँव-पंचायतोंके चुनावोंमें 'ऊँच' और 'नीच' जातियोंका संघर्ष वस्तुतः शोषको और शोषितोंके बीच चलनेवाले वर्गसंघर्षका रूप है। यह शकल ऐसी नहीं जिसे मैं पसन्द करूँ, इसमें जो खतरे हैं उनसे शोषित जनताको आगाह करना होगा। पर गाँवोंमें वर्गसंघर्ष आरम्भमें 'ऊँची' जातियोंके विरुद्ध 'नीची' जातियोंके विद्रोहका रूप लेगा ही। देशके पिछले इतिहासको भुलाया नहीं जा सकता।

नयी चेतना जगाइये

समाजवादियोंको इस संघर्षको सही शकल देनी है। कुचला हुआ मजदूर आर्थिक एकाधिकारका दोष जातिकी ऊँचाईको देता है। वह यह नहीं देख पाता कि शोषक और शोषित 'ऊँची' और 'नीची' दोनों जातियोंमें बँटे हुए हैं, किसीमें वे थोड़े हैं किसीमें ज्यादा। पुराने जमानेमें कौमियतका उसूल, राष्ट्रीयताका सिद्धान्त नहीं था। देहातका गरीब विरादरीकी ही परिभाषामें सोचता है। हमें देहातकी शोषित जनताको समझाना है कि जाति, वंश और सम्प्रदायके भेदोंको भूलकर शोषक वर्गोंके आर्थिक प्रभुत्वके विरुद्ध वे संयुक्त मोर्चा कायम करें। चूसे जानेवाले मेहनतकशोंका बेलिहाज जात-पात और मजहब-मिल्लत एक खेमा बने।

अपढ़, पर नासमझ नहीं

यह धारणा कि चूँकि किसान अपढ़ है इसलिए वह गाँवका प्रबन्ध नहीं कर सकता ठीक नहीं है। किसानने दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिकी पोथियाँ न पढ़ी हों पर वह जिन्दगीकी किताबसे बहुत कुछ सीखता है। अपने हितकी बातें वह बहुत अच्छी तरह समझता है। यही कारण है कि कांग्रेसपरसे उसकी आस्था हट चली है। यही कारण है कि यद्यपि वह हमारी बात ध्यानसे सुनता है, पर हमारे ऊपर पूरा विश्वास करनेसे पहले हमें अच्छी तरह परख लेना चाहता है।

उदासी कैसे हटे ?

आज किसानोमे, और जनताके दूसरे वर्गोमे भी, बहुत बड़ी उदासी छायाई हुई है। वे किर्कर्तव्यविमूढ़ नजर आते हैं। मुल्ककी आजादीसे किसानोने बड़ी उम्मीदे बाँध रखी थी। वे रामराज्यका सपना देख रहे थे, किन्तु आज जनताकी मामूली जरूरते भी पूरी नहीं हो पाती। इस कारण लोगोके दिल टूट गये हैं। हमे इस निराशा और उदासीनताके वातावरणको बदलना है। इस वातावरणको बदलनेके लिए हमे जनतामे समानताकी भूख जगानी है। हमे एक ऐसी नयी दुनिया बसानी है जिसमे सबके लिए अवसरकी समानता होगी। इसी विश्वाससे ही बुझे हुए दिलोमे एक नयी शक्ति, एक नया उत्साह पैदा होगा।

किसान अपनी जिम्मेदारीको ठीकसे निवाह सके* इसके लिए उनकी शिक्षा जरूरी है। किसानोको शिक्षित करना सरकारका फर्ज है। हुकूमतकी बागडोर सँभालनेवाले अनेक नेता चुनावके नतीजोसे घबरा गये हैं। किन्तु सरकार अपना फर्ज अदा करे या न करे पचोको तो किसानोको राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नोकी शिक्षा देनी ही है।

समाजवादियोंका कर्तव्य

यद्यपि वर्तमान गाँव-पंचायतके अधिकार और साधन एक हदतक सीमित हैं फिर भी ये पंचायते ऐसी व्यवस्थापिका सभाएँ नहीं हैं जहाँ आपका कार्य केवल विरोधी दल बनाना हो। पंचायतोसे रचनात्मक कार्य भी साथ-साथ चल सकता है। आपको रचनात्मक कार्यमे लगना चाहिये। यदि आप बिना जात-पाँत, सम्प्रदाय आदिका भेद किये ईमानदारीसे रचनात्मक कार्य करके अपनेको शोषित जनताका सच्चा सेवक और हमदर्द सिद्ध कर देगे तो वह आपको अपना साथी और रहबर समझेगी। अपने ऊँचे सिद्धान्तोको रखते हुए, लक्ष्यकी सिद्धिके प्रति दृढप्रतिज्ञ रहकर, सच्चे दिलसे जनताकी सेवा करते हुए, ग्रामीण जनतामे समताकी भूख जगाकर आप गाँव-पंचायतोको प्रजातन्त्रकी वास्तविक आधारशिला और समाजवादकी स्थापनाका साधन बना सकेंगे।

जनताका आशा-दीप बुझ रहा है

मैं इधर कुछ अरसेसे तीन-चार बातोपर जोर दे रहा हूँ। सबसे मौलिक बात यह है कि देशमे निराशा और निरुत्साहका वातावरण छाया हुआ है और लोगोमें सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नोके प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है। हमारे नवयुवक भी इस उदासीनताके शिकार होते जाते हैं। इस परिस्थितिके अनेक कारण हैं। नवार्जित स्वाधीनताका उल्लास किसीके हृदयमे नहीं है और इसी कारण नवीन रचनाके लिए उत्साहका भी अत्यन्त अभाव है। बिना अदम्य उत्साहके कोई भी महान् कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता और यही कारण है कि कोई भी योजना जो बनायी जाती है केवल कागजपर

रह जाती है कार्यान्वित नहीं होती है । राष्ट्र-निर्माणका कार्य बड़े महत्त्वका है और जबतक जनता उत्साहपूर्वक इस कार्यमें सलग्न नहीं होती तबतक इस दिशामें प्रगति नहीं हो सकती । आज इसी उत्साहकी कमी है । गवर्नमेण्ट राष्ट्र-निर्माणके लिए प्रायः अपने कर्मचारियोंपर ही निर्भर रहना चाहती है । कदाचित् उसकी दृष्टिमें जनता एक उपास्यदेवके तुल्य है जिसका नाम जप और जयघोष मात्र करना चाहिये, किन्तु जो निष्क्रिय और कूटस्थ है । किन्तु वस्तुतः जनता जड़ और अचेतन नहीं है; आजके युगमें तो वह नित्य-प्रति अधिकाधिक सक्रिय होती जाती है । जनता ही स्रष्टा और विधाता है । उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती । सब निर्माण और भगलके कार्योंमें उसके सहयोगकी आवश्यकता है । इस सहयोगको प्राप्त करनेकी कोई विशेष चेष्टा नहीं हो रही है और न यह सहयोग प्राप्त ही हो सकता है जबतक कि उसके लिए भूमिका न तैयार कर ली जाय । जबतक निराशाका वातावरण रहेगा तबतक जनतामें उत्साह उत्पन्न नहीं होगा । अतः सबसे पहले इस वातावरणको बदलना होगा । वातावरणके बदलनेके लिए गवर्नमेण्टको सबसे पहले जनताको वस्तुस्थिति बतानी होगी और उससे त्याग करनेकी अपील करनी होगी । किन्तु गवर्नमेण्टके लोग सब्ज बाग ही दिखाया करते हैं और जनताको इस बातका निरन्तर आश्वासन देते रहते हैं कि बहुत जल्द ही दूध और शहदकी नदियाँ बहनेवाली हैं । कोई कहता है कि अपने प्रान्तका सहकारिताका आन्दोलन संसारमें सर्वश्रेष्ठ है; कोई कहता है कि अन्य देशोंकी हालत हमारी अपेक्षा कहीं अधिक खराब है ।

चुनावके समय लम्बे-बौड़े वादे किये गये थे और गवर्नमेण्ट बननेके बाद भी इनमें वृद्धि होती रही, किन्तु यह वचन अभीतक पूरे नहीं किये गये हैं और न उनमेंसे बहुतोके पूरे होनेकी आशा ही है । वह वस्तुस्थिति बतानेसे घबराते हैं । इसका बुरा परिणाम यह होता है कि जब लोगोंकी आशा भग्न हो जाती है और वह देखते हैं कि स्थिति सुधरनेके बदले बिगड़ती जाती है तो वह निराश हो जाते हैं और यह निराशा धीरे-धीरे उदासीनतामें परिवर्तित होती जाती है । गवर्नमेण्टको यह चाहिये कि जितना उसके लिए शक्य हो उतना ही बोझ उठावे और अपनी कठिनाइयोंको जनताके सम्मुख रखे । सारांश यह है कि वर्तमान स्थितिके बदलनेके लिए मिथ्या प्रचारकी भावनाको छोड़कर ठोस सत्यको चाहे वह अप्रिय ही क्यों न हो, अपनाना होगा । यह पहली शर्त है । दूसरी शर्त यह है कि जनतासे त्याग और तपस्याके लिए कहनेके पूर्व नेताओं और कर्मचारियोंको सबसे पहले इसका उदाहरण पेश करना होगा । जनताकी मनोवृत्ति तबतक नहीं बदल सकती जबतक नेता और कर्मचारी अपने ऐशोआराममें काफी कमी करनेको तैयार न हो । यह एक ऐसी मोटी बात है कि जिसके समझनेमें कठिनाई नहीं होनी चाहिये । लेकिन यह तो आज शान दिखानेकी फिक्कमें है । मैं मानता हूँ कि पूँजीवादी युगमें जहाँ रुपया सबका मानदण्ड हो रहा है शायद विदेशोंमें अपनी कद्र करानेके लिए कुछ बाहरी तडक-भड़ककी जरूरत हो, किन्तु स्वदेशमें अपनी हैसियतसे ज्यादा दिखावा सर्वथा अवांछनीय है । हमारा देश गरीब है, हमको अपनी पूँजी संचित करनी है । अतः हमको किफायतसारीसे काम लेना चाहिये और अपना जीवन बहुत सादा रखना चाहिये । इस एक सुधारसे हमारे राष्ट्रीय

जीवनमें बड़ा अन्तर पड़ जायगा । तदनन्तर सबसे पहले हमको २-३ मौलिक कामोंको लेना चाहिये और उनको पूरा करनेमें सारी शक्ति लगा देनी चाहिये । अन्न-वस्त्रकी समस्या सबसे प्रथम समस्या है । ज्यों ही यह समस्या सुलझने लगेगी त्यों ही वातावरण बदलने लगेगा । इस समय होता यह है कि गवर्नमेण्ट यह दिखानेका प्रयत्न करती है कि वह सब कुछ कर सकती है और कर रही है । इससे अपनी स्वल्प शक्तियोंको हम विखेर देते हैं । अन्न-वस्त्रकी समस्याके बाद लोक-शिक्षा तथा उच्च-शिक्षाका नम्बर आता है । लोक-शिक्षासे मेरा आशय केवल अक्षर-ज्ञानसे नहीं है । निरक्षरोंको भी नित्यके प्रश्नोंके सम्बन्धमें शिक्षा होनी चाहिये । युवकोंकी ओर विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये ।

संक्षेपमें मेरा यह कहना है कि जबतक जनताकी मनोवृत्ति तथा उसका भाव नहीं बदलता, हम कुछ नहीं कर सकते । हम सब जानते हैं कि आज निराशा छायी हुई है किन्तु उसको दूर करनेके लिए हमने कौन-सा कदम उठाया है ? सार्वजनिक प्रश्नोंमें बढ़ती हुई अरुचिको रोके बिना कुछ नहीं होगा । हो सकता है कि गवर्नमेण्ट यह समझती हो कि उसका इसमें कोई नुकसान नहीं है, किन्तु यही अरुचि समय आनेपर कुरुचिमें परिवर्तित हो सकती है । अतः सर्वप्रधान समस्या मनोवैज्ञानिक है ।

दूसरी बात जिसपर मैं जोर देता हूँ यह है कि लोकतन्त्रकी रक्षा और उन्नतिके लिए एक स्वस्थ विरोधी दलका होना आवश्यक है । कांग्रेसके बाहर सबलोग इस आवश्यकताको स्वीकार करते हैं । किन्तु कांग्रेसके भीतर अब भी बहुतसे व्यक्ति इसको विविध युक्ति देकर अनावश्यक ठहराते हैं । कुछका कहना है कि भारतीय प्रकृतिके यह विरुद्ध होगा । राजेन्द्र बाबूका कहना है कि यद्यपि विरोधकी आवश्यकता है तथापि यह विरोध कांग्रेसके भीतर ही मौजूद है, अतः कांग्रेसके बाहर विरोधी दलकी आवश्यकता नहीं है । यह तर्क हमारी अल्प बुद्धिमें ठीक नहीं है । कांग्रेसके भीतर जो लोग हैं वह उसके बहुमतसे बँधे हुए हैं । वह व्यवस्थापिका सभामें बहुमतके निर्णयके विरुद्ध कुछ कह नहीं सकते । आज तो अवस्था यह है कि हमारे विधानको एक अल्प समुदाय ही बना रहा है । पहले कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है, उसमें बहुमतसे निर्णय हो जाता है और यही निर्णय विधान-परिषद्से स्वीकृत होता है । ऐसे भी अवसर आते हैं जब कि यदि जाँच की जाय तब मालूम होता है कि कांग्रेसका अल्पमत और स्वतन्त्रमत मिलकर कांग्रेसके बहुमतके निर्णयके विपक्षमें है । किन्तु उसको अपनी इच्छाके अनुरूप मत देनेकी स्वतन्त्रता नहीं है । विधानके बनानेमें पार्टीका ह्विप जारी होना सर्वथा अनुचित है । जब मैं कहता हूँ कि विरोधी दलकी आवश्यकता स्वीकार की जाय तब मेरा मतलब यह नहीं है कि विरोधी दलोंके लिए कुछ सीटें छोड़ दी जायँ । मैं इतना ही चाहता हूँ कि इस सिद्धान्तको कांग्रेस भी मुक्तकण्ठसे स्वीकार करे । मैं कांग्रेससे कोई भिक्षा नहीं माँगता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस प्रकार सच्चे विरोधी दलकी सृष्टि नहीं हो सकती । कांग्रेसने उदारतापूर्वक केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभामें कुछ गैर कांग्रेसियोंको भी ले लिया है, किन्तु इससे कहीं विरोधी पक्ष थोड़े पनप पाये हैं । यह व्यक्तिविशेष हैं जिनके पीछे न कोई विशेष प्रोग्राम है और न कोई संगठन ।

न होगी । इस अधिकारको स्वीकार करनेका अर्थ केवल यह है कि राज्य भाषण आदिकी स्वतन्त्रता देता है और यह मानता है कि शान्तिमय सत्याग्रहका अधिकार व्यक्तियोंको है । इस स्वीकृतिके बाद वह यह नहीं कह सकता कि यह सिद्धान्ततः गलत है । वह इतना ही कह सकता है कि सत्याग्रहका उद्देश्य पवित्र नहीं है अथवा उसके लिए कोई उचित कारण नहीं है ।

या तो ऐसे मामले अदालतमें न जायेंगे और यदि गये तो अदालत नाममात्रको दण्ड देगी, यदि ऐसे सत्याग्रहसे शान्तिभंग नहीं होती । यह अधिकार तब भी होना चाहिये जब राष्ट्रीय सरकार हो और लोक-तन्त्रात्मक सरकार हो । किन्तु आज कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं कि जब अपनी गवर्नमेण्ट हो गयी तो हड़ताल, सत्याग्रह आदिका अधिकार होना चाहिये । इसका परिणाम यह हो जाता है कि गवर्नमेण्ट और भी वेधड़क होकर गलत आज्ञाएँ प्रचारित करती जाती है । यह ठीक है कि लोकतन्त्रात्मक शासनमें ऐसे अवसर कम आने चाहिये और प्रत्येकको विशेष आवश्यकता पड़नेपर ही इस अस्त्रका सोच-समझकर प्रयोग करना चाहिये । किन्तु आज तो प्रान्तके प्रान्त दफा १४४ या पब्लिक सेफ्टी ऐक्टके शिकार हो रहे हैं । गवर्नमेण्टने इस प्रकार अपनेको हास्यास्पद बना दिया है । यह कैसे विश्वास किया जाय कि समूचे प्रान्तमें इस विशेषाधिकारकी आवश्यकता है । किसी व्यापक अराजकताके चिह्न हमको दिखायी नहीं पड़ते । कलकत्तेमें अथवा हैदराबादके कुछ हिस्सोंमें इसकी आवश्यकता हो सकती है । किन्तु कम्युनिस्टोंका ऐसा कोई प्रभाव नहीं जिससे शान्तिभंगकी सर्वत्र आशङ्का हो । जनता उनके साथ नहीं है यह कई बार सिद्ध हो चुका है, फिर यदि सर्वत्र इस प्रकारके विशेषाधिकार बरते जावे तो यही सन्देह होता है कि गवर्नमेण्ट अन्य पार्टियोंके काममें बाधा उपस्थित करना चाहती है । धीरे-धीरे भारत एक बड़ा कैदखाना होता जाता है । ऐसी अवस्थामें सत्याग्रहका अधिकार स्वीकार करना और भी आवश्यक है ।

भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलोंका कांग्रेसके साथ सहयोग होना तब तक सम्भव नहीं है जबतक इन बातोंका निर्णय नहीं हो जाता । यदि कांग्रेस किसी दलका सहयोग नहीं चाहती तो कोई हर्ज नहीं है, किन्तु जनताकी उपेक्षा करके वह भी जिन्दा नहीं रह सकती और जनताका सहयोग तभी उसे प्राप्त होगा जब वह किसी ऊँचे आदर्शको उसके सामने रखकर और स्वयं उसपर चलकर उसकी उदासीनताको दूर करेगी और उसके बुनियादी सवालको हल करेगी ।

चौथा अध्याय

समाजवाद

चौथा अध्याय

समाजवादका लक्ष्य

समाजवादका ध्येय वर्गविहीन समाजकी स्थापना है। समाजवाद प्रचलित समाजका इस प्रकारका संगठन करना चाहता है कि वर्तमान परस्पर-विरोधी स्वार्थोवाले शोषक और शोषित, पीडक और पीडित वर्गोंका अन्त हो जाय; वह सहयोगके आधारपर सगठित व्यक्तियोंका ऐसा समूह बन जाय जिसमें एक सदस्यकी उन्नतिका अर्थ स्वभावतः दूसरे सदस्यकी उन्नति हो और वह मिलकर सामूहिक रूपसे परस्पर उन्नति करते हुए जीवन व्यतीत कर सके।

संसारकी आजादी

मानव-इतिहासके आरम्भसे अवतक समाजमें शोषक और शोषित वर्गोंका संघर्ष चलता रहा है। मनुष्य सामाजिक प्रगतिके नियमोंका दास बनकर कार्य करता रहा है; वह समाजके विकासकी दिशा बोधपूर्वक निर्धारित करनेमें असमर्थ रहा है। समाजवाद ऐसे शोषणमुक्त और स्वतन्त्र समाजकी रचना करना चाहता है जिसमें मनुष्य अपनी इस असमर्थताके दायरेसे ऊपर उठ सके और सामाजिक विकासका नियन्त्रण कर सके। कार्ल मार्क्सके शब्दोंमें 'समाजवाद मनुष्यको विवशताके क्षेत्रसे हटाकर उसे स्वाधीनताके राज्यमें (from the realm of necessity to the realm of freedom) ले जाना चाहता है।'

समाजवाद संसारको आजाद करना चाहता है, व्यक्तित्वके विकासमें रुकावट डालने-वाले सामाजिक बन्धनोंसे उसे छुटकारा दिलाना चाहता है। शोषणमुक्त समाजकी रचना करके, मौजूदा समाजकी प्रचलित दासता, विषमता और असहिष्णुताको सदाके लिए दूर करके, समाजवाद स्वतन्त्रता, समता और भ्रातृभावकी वास्तविक स्थापना करना चाहता है। स्वतन्त्रता, समता और भ्रातृभावके आदर्श तो पुराने ही हैं। प्राचीन कालमें सामाजिक स्वतन्त्रताके जो आन्दोलन समय-समयपर होते रहे हैं उनकी पताकापर ये ही आदर्श वाक्य अंकित रहे हैं। यूरोपकी कायापलट करनेवाली महान् राज्यक्रान्ति—फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति—का भी मूलमन्त्र यही था लेकिन हम आज देखते हैं कि फ्रान्सीसी राज्यक्रान्तिके आदर्शोंकी सिद्धि होनेके बाद भी विषमता दूर नहीं हुई है। सच तो यह है कि ये व्याधियाँ समाजमें पहलेकी अपेक्षा आज और भी बढ़ गयी हैं।

फ्रांसकी राज्यक्रान्ति

यहाँपर कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब दासता, विषमता और असहिष्णुताके भाव समाजमें आज विद्यमान हैं तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि फ्रान्सकी राज्यक्रान्ति

सफल हुई ? इस प्रश्नका उत्तर ठीक-ठीक समझनेके लिए इस बातको अच्छी तरह समझ लेना होगा कि समता और स्वतन्त्रता आदि भावनाओंका अर्थ क्या है ? समता आदि भावनाओंको निरपेक्ष (absolute) आदर्श, कभी न बदलनेवाला, नहीं कहा जा सकता । समाज, काल और देश-भेदसे इनके अर्थोंमें भी अन्तर हो जाता है । फ्रान्सीसी राज्यक्रान्तिके विचारोंका इन नारोंसे क्या अर्थ था, यह समझनेके लिए आवश्यक है कि हम यूरोपके उस समयके सामाजिक संगठनका अध्ययन करे और देखे कि उस समय यूरोपके समाजमें प्रचलित विषमता और दासताका स्वरूप क्या था ? हम देखते हैं कि फ्रान्सीसी राज्यक्रान्तिके समयके यूरोपमें सामन्तशाहीकी तूती बोलती थी । उस समय समाज छोटे-छोटे भू-भागोंमें बँटा हुआ था । समाजके राजनीतिक और आर्थिक जीवन-पर राजाओं, जागीरदारों और महन्तोंका प्रभुत्व था । गाँवोंकी जनता कृषकदासों (serfs) का जीवन व्यतीत करती थी । उत्पादनकी शक्तियोंको इस सामन्तवादी आर्थिक व्यवस्थामें अधिक फैलनेकी गुंजाइश नहीं थी । व्यापारियोंका वर्ग प्रभावशाली हो रहा था, लेकिन राजनीतिक शक्ति सामन्तोंके हाथमें होने और आर्थिक दृष्टिसे जनसंख्याके प्रादेशिक खण्डोंमें बँटे रहनेके कारण व्यापारके मार्गमें बाधा पड़ती थी । कृषकदासता प्रथा (serfdom) के प्रचलनके कारण कृषक जनताके पास इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि वह व्यापारियोंद्वारा अब अधिक मात्रामें पैदा की जानेवाली वस्तुएँ खरीद सके । साथ ही कृषकदास अपनी जमीनको छोड़कर कारखानोंमें काम करने भी नहीं जा सकते थे । ऐसी अवस्थामें व्यापारी पूँजीपति वर्गके लिए यह स्वाभाविक था कि वह एक ऐसी क्रान्तिकारी नेतृत्व करता जिसके फलस्वरूप सामन्तोंकी ताकत खत्म होकर ऐसा प्रजातन्त्र स्थापित होता जिसमें राज्यकी सत्ता पूँजीपतियोंके हाथमें आती और व्यापारके फैलावके लिए आजादी हासिल होती । फ्रान्सीसी राज्यक्रान्तिमें सामन्तवादी समाजकी विषमता और दासता दूर की गयी और इसी अर्थमें हम फ्रान्सीसी राज्यक्रान्तिकी सफलताकी बात भी करते हैं ।

आधुनिक विषमताएँ

आज जब हम कहते हैं कि स्वतन्त्रता, समता आदिके आदर्शोंको हमें सिद्ध करना है तो हमारा अर्थ उस अर्थसे भिन्न होता है जो कि फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिके नेताओंका था । जैसा कि हमने ऊपर देखा, फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिकी अर्थ उन सामन्तवादी विषमताओंको हटाना था जो पूँजीवादके विकासके मार्गमें बाधक थी । आज हमारा ध्येय उन विषमताओं और बन्धनोंको दूर करना है जो पूँजीवादके प्रसारसे उत्पन्न हुई हैं और जो आज उत्पादनकी शक्तियोंको आगे बढ़नेसे रोक रही हैं ।

पूँजीवादी प्रणालीके संसारव्यापी होनेके कारण आज संसारभरमें पूँजीपतियोंका बोलवाला हो रहा है । प्राचीन कालके सामन्तोंका स्थान पूँजीपतियोंने ले लिया है । राष्ट्र और संसारकी दीलत मुट्ठीभर पूँजीपतियोंके हाथमें आ गयी है । लन्दन शहरके व्यापारी ब्रिटिश साम्राज्यभरकी आर्थिक बागडोर अपने हाथमें रखते हैं । फ्रांसकी

लाखोंकी आवादीपर राज्य करनेवाले दो सौ धनकुबेरोके परिवार हैं। यही हालत हर जगह पायी जाती है। हर राष्ट्र स्पष्टतः दो मुख्य शोषक और शोषित भागोंमें बँट गया है। एक ओर तो लक्ष्मीके लाड़ले मुट्ठीभर पूँजीपति हैं जो शानदार महलोमें रहते हैं, जिन्हें सभ्यताकी सभी विभूतियोंका सुख प्राप्त है, जो समाजके भाग्यविधाता समझे जाते हैं—जिनके अधिकारमें उत्पादन, विनिमय और वितरणके सभी साधन हैं। दूसरी ओर शोषित वर्गके वे बहुसंख्यक अभागे लोग हैं, जिनकी एकमात्र पूँजी उनकी श्रमशक्ति है, जो लोग अपने परिश्रमसे समाजकी सभी वस्तुएँ पैदा करते हैं पर जिनको न पेट भरनेको अन्न और न तन ढकनेको कपड़े हैं—जिनका कार्य अमीर पूँजीपतियोंकी कृपापर निर्भर रहकर रात-दिन शोषणकी चक्कीमें पिसते रहना ही है।

यो तो कहनेको कानूनकी निगाहमें शोषक और शोषित दोनों ही वर्गके लोग बराबर हैं, कानून सभीके साथ समान रूपसे न्याय करता है, लेकिन हमसे हर कोई इस बातको जानता है कि गरीबोंके साथ होनेवाला न्याय कितना पक्षपातसे भरा होता है और न्यायालयोंमें रोज ही न्यायके गलेपर छुरी फिरा करती है। समाजमें पूँजीपतियोंकी जो वर्गस्थिति है उसकी बदौलत अधिकारके सभी स्थानोंपर पूँजीपतियोंका ही एकाधिपत्य होता है। ये पूँजीवादी अधिकारी कितना भी निष्पक्ष होनेकी कोशिश क्यों न करें लेकिन स्वभावतः उनका दृष्टिकोण अपने वर्ग-स्वार्थसे रेंगा हुआ होता है।

भूखों मरनेकी आजादी

कहा जाता है कि पूँजीवादी प्रजातन्त्रकी स्थापनासे आजकी दुनियामें आजादी कायम हो गयी है, किन्तु श्रमजीवियोंके लिए यह आजादी पूँजीपतियोंकी शर्तपर अपना आत्म समर्पण करने या बदलेमें भूखों मरनेकी ही आजादी है। सच तो यह है कि आजकलके पूँजीवादी समाजमें साधारण मनुष्योंके लिए जीवनकी कठिनाइयाँ सामन्तवादी युगकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ गयी हैं। गरीबी और अमीरी उस समाजमें भी बहुत दर्जेतक थी, किन्तु आजका-सा यह हाल न था कि एक तरफ सारी सम्पत्ति चन्द इने-गिने हाथमें इकट्ठा हो गयी है और दूसरी तरफ लाखों मेहनत करनेवाले परिवार भूखों मरते हैं। सामन्तवादी जमानेमें उत्पादनकी शक्तियोंका आजका-सा विकास न था, जीवनकी बहुत-सी सुविधाएँ, जो आज मिल सकती हैं, प्राप्त न थी। पर आज तो हर देशमें बेकारोंकी एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो रही है। जो लोग काममें लगे हुए हैं उनको अपने श्रमका पूरा मुआवजा मिलना तो दूर रहा उल्टे हमेशा उन्हें यह डर रहता है कि किसी भी क्षण के बेकारीके गिरोहमें फँके दिये जा सकते हैं।

यह विषमता क्यों ?

आजकलके समाजकी यह भीषण विषमता क्यों ? इस विषमताका कारण यह है कि उत्पादन, विनिमय और वितरणके साधनोंपर चन्द पूँजीपतियोंका अधिकार है। उत्पादनके इन साधनोंमें—मिलों, कारखानों और बैंकों आदिमें—काम करनेवालोंका इन साधनोंपर कोई अधिकार नहीं है। प्राचीन कालमें जब कि गृहशिल्प (cottage

industry) प्रणालीकी प्रधानता थी, आजकलकी भाँति बड़े पैमानेपर पैदावार नहीं होती थी, उत्पादनके साधनोपर व्यक्तिगत अधिकार हुआ करता था और बहुत हदतक पैदावार करनेवाले व्यक्तिको अपनी पैदावारका लाभ मिलता था । आज बड़े पैमानेपर पैदावार होती है, पर उत्पादनके साधनोपर समाजका या उनमें काम करनेवाले आदमियोका कोई अधिकार न होकर व्यक्तिगत पूँजीपतियोका अधिकार होता है । फलस्वरूप सारा नफा इन व्यक्तिगत पूँजीपतियोकी ही जेबोंमें जाता है और मजदूरोको मुश्किलसे उनके पेट भरनेके लिए दिया जाता है ।

पूँजीवादी प्रणालीका नतीजा न सिर्फ समाजके दूसरे लोगोके लिए ही बल्कि पूँजीपतियोके लिए भी घातक होता है । चूँकि समाजका बहुसंख्यक भाग परिश्रम करनेवालोंका है, जिनकी क्रयशक्ति (purchasing power) दिन-ब-दिन घटती ही चली जाती है, इसलिए पूँजीपतियोको अपने कारखानेका माल बेचना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जाता है । यो तो किसी योजना (plan) के अनुसार पैदावार न होनेके कारण पूँजीवादी आर्थिक प्रणालीमे संकट आया ही करते थे, लेकिन श्रमिक जनताकी क्रयशक्तिके ह्रासके फलस्वरूप अब इस संकटने स्थायी रूप धारण कर लिया है । इस प्रकार उत्पादनकी शक्तियो और उत्पादनके साधनो तथा उत्पादनकी शक्तियो और विनिमयके बीच घोर असंगतियाँ उपस्थित हो गयी हैं । समाजवादका उद्देश्य इन्ही असमानताओ और असंगतियोंको दूर करना है ।

अगर कुछ लोग यह समझते हो कि समाजवाद हर प्रकारकी आजादी या समानता कायम करने जा रहा है तो यह उनकी भूल होगी । समाजवाद पूर्ण समानता लानेका दावा नहीं करता । समाजवादी समाजमे भी समाजके सदस्योमे शारीरिक और मानसिक अन्तर रहेगे ही । समाजवाद यह अवश्य करेगा कि वह शोपक वर्गका अन्त करके, असमानता का आर्थिक आधार (economic basis) नष्ट कर देगा और सबको अवसरकी समानता प्रदान करेगा ।

सामाजिक वर्गोका अर्थ

पहले बताया गया है कि समाजवादका ध्येय वर्गरहित समाजकी स्थापना है । यहाँपर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वर्ग शब्दसे हमारा अभिप्राय क्या है । वर्गके सम्बन्धमे बहुतसी मिथ्या धारणाएँ प्रचलित हैं । कुछ लोग यह समझते हैं कि समाजमें अमीर और गरीब ये दो वर्ग हमेशासे रहते आये हैं और समाजवादका उद्देश्य इन दोनो समूहोके अन्तरको मिटाकर समाजके सभी सदस्योमे आर्थिक एकरूपता स्थापित करना है । यह ठीक है कि हजारो वर्षोंसे यह अमीरो और गरीबोका भेद चला आया है, मगर यह कहना गलत है कि हमेशा ऐसा रहा है और रहेगा । गरीबी कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई यही तो समाजवाद बताता है । इसीमे तो श्रेणी-सघर्षका रहस्य है ।

भ्रमपूर्ण धारणाएँ

इसमें सन्देह नहीं कि समाजवाद जिस नयी सामाजिक व्यवस्थाकी कल्पना करता है उसमें आजकलकी भाँति भीषण आर्थिक विषमताएँ न पायी जायँगी, लेकिन इसका यह अर्थ निकालना भ्रमपूर्ण होगा कि समाजवादी आर्थिक एकरूपता कायम करना चाहते हैं। समाजवादका आदर्श हर व्यक्तिसे उसके योग्यतानुसार काम लेकर उसके आवश्यकतानुसार उपयोगकी वस्तुओंका प्रवन्ध करना है। यह तो निश्चित ही है कि समाजके विभिन्न व्यक्तियोंकी आवश्यकता भी विभिन्न होगी। ऐसी हालतमें सबकी आमदनी बराबर कैसे की जा सकती है? कुछ लोग वर्गोंका अर्थ समाजमें प्रचलित विविध धन्धे या पेशे (vocations) समझते हैं। इन लोगोंकी रायमें समाजवाद सभी पेशोंको मिटाकर सबको एक पेशेका बना देना चाहता है। यह स्पष्टतः असम्भव कल्पना है। यह मुमकिन है कि समाजवादी व्यवस्थामें आजकल प्रचलित कुछ धन्धोंकी जरूरत न पड़े। उदाहरणार्थ, समाजवादी समाजमें हमें फौजकी जरूरत न होगी। लेकिन जबतक समाजका अस्तित्व मौजूद है समाजके भीतर विभिन्न कार्योंको सुचारु रूपसे चलानेके लिए श्रमविभाजन मौजूद रहेगा और फलस्वरूप अनेक पेशे भी मौजूद रहेंगे। सब पेशोंको हटाकर एक पेशा कायम करनेकी दलील वास्तवमें समाजवादके उन विरोधियोंद्वारा दी जाती है जो इसके जरिये बड़ी आसानीसे यह साबित करना चाहते हैं कि वर्गरहित समाजकी रचना एक असम्भव कल्पना है।

वर्गोंकी परिभाषा

समाजवादी जब वर्गोंका उल्लेख करता है तो वह समाजमें प्रचलित उन उत्पादन सम्बन्धों (production relations) को ध्यानमें रखता है जिनपर समाजकी आर्थिक-प्रणाली आश्रित होती है। वर्ग या सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियोंका समूह है जो सामाजिक उत्पादनमें एक प्रकारका कार्य करते हैं और उत्पादनके क्रममें लगे हुए दूसरे व्यक्तियोंके साथ उनका सम्बन्ध भी एकही सा होता है। यह एक-सा सम्बन्ध श्रमके साधनोंके सम्बन्धमें भी लागू होता है। इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि वितरणके क्षेत्रमें एक वर्गके सदस्योंकी आमदनी भी प्रायः एक सरीखी होगी। उदाहरणार्थ, हम आजके समाजमें मजदूरों और पूँजीपतियोंको देखते हैं। सभी मजदूरोंके समूह, चाहे वे कपड़ोंकी मिलोंमें काम करते हों, खानोंमें काम करते हों या और कहीं, एक ही श्रेणीमें गिने जायँगे। सामाजिक उत्पादनमें, आर्थिक वस्तुओंकी पैदावारमें, इनका भाग एक-सा

1. A Social class is the aggregate of persons playing the same part in production, standing in the same relation towards other persons in the production process, these relations being also expressed in things (instrument of labour)—Bukharin in Historical Materialism.

है। ये सभी उत्पादनके साधनोसे रहित हैं अर्थात् मिलो या कारखानोके मालिक वे खुद नहीं हैं। सभी अपनी श्रमशक्ति बेचकर मजदूरी कमाते हैं। उत्पादनके क्रममे लगे हुए दूसरे लोगो अर्थात् मिलमालिको आदिके प्रति सामूहिक रूपसे इनका सम्बन्ध एक सरीखा है। इसलिए सभी समूहोके मजदूर एक ही मजदूर श्रेणीमे गिने जायेंगे। इसी प्रकार पूँजीपतियोका भी एक वर्ग है। चाहे कपडेके मिलके मालिक हो, चाहे खानोके मालिक हो अथवा हथियारोके कारखानोके मालिक हो, सभी उत्पादनके क्रममे एक-सा भाग रखते हैं। ये सभी उत्पादनके साधनोके मालिक हैं, सभी मजदूरोकी श्रमशक्ति खरीदकर उससे नफा कमाते हैं। उत्पादनके क्रममे लगे हुए दूसरे समूहोके साथ उनका सम्बन्ध एकसा है।

आधारभूत वर्ग

यद्यपि अवतकका हर समाज उत्पादक सम्बन्धोके आधारपर कई वर्गोमे बाँटा जा सकता है, किन्तु आधारभूत रूपसे हर समाजमे दो ही वर्ग पाये जाते हैं—एक तो वे लोग जिनका स्थान समाजमे मालिकोका होता है और उत्पादनके साधनोपर जिनका एकाधिपत्य होता है, दूसरा वह वर्ग जिसका काम हुकम बजा लानेका होता है, जो पहले वर्गके लिए दास बनकर काम करता है और उसके द्वारा शोषित किया जाता है। ये दोनो वर्ग परस्पर एक-दूसरेके विरोधी होते हैं। दोनो आधारभूत वर्गोमे सदा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमे वर्गसंघर्ष जारी रहता है। प्राचीनकालमे दास और स्वतन्त्र मालिक, मध्ययुगमे सामन्तगण और कृषकदास (serf) और आजकलके पूँजीवादी समाजमे पूँजीपति और मजदूर इसी प्रकारके आधारभूत वर्ग हैं। इन आधारभूत वर्गोके अतिरिक्त भी समाजमे कई प्रकारके वर्ग पाये जाते हैं। परन्तु उन वर्गोका स्वार्थ अन्ततोगत्वा इन्ही आधारभूत वर्गोमेसे किसी एकके साथ होता है। इसमे शक नहीं कि कुछ वर्ग ऐसे भी पाये जाते हैं जिनका स्वार्थ थोडाबहुत दोनो वर्गोके साथ होता है, परन्तु इन दो आधारभूत वर्गोसे स्वतन्त्र इनका कोई अपना पृथक् स्वार्थ नहीं होता। प्रसिद्ध समाजवादी विद्वान् बुखारिनके मतानुसार समाजमे आधारभूतवर्गोके अतिरिक्त निम्नलिखित वर्ग पाये जाते हैं.—

मध्यम वर्ग (middle classes)—इस वर्गमे वे सामाजिक आर्थिक समूह आते हैं जो कि समाजकी संगठन-व्यवस्थाके लिए आवश्यक हैं। इन लोगोका स्थान आधारभूत शोषक और शोषित वर्गोके बीचका हुआ करता है। दिमागी काम करनेवाले श्रमिक इसी श्रेणीमे आते हैं।

परिवर्तनशील वर्ग (transition classes)—इन वर्गोमे वे समूह आते हैं जो प्राचीन समाज-व्यवस्थासे निकलते हैं, पर अब जिनकी शकल बदलती जा रही है और जो दिन-व-दिन विरोधी वर्गोमे बँटते चले जा रहे हैं। किसानो और कारीगरोके वर्ग इसी प्रकारके हैं। दिन-व-दिन इस वर्गके सदस्य निकलकर सम्पत्तिजीवी या मजदूर वर्गमें मिलते जा रहे हैं। धनी किसान व्यापारी बनता है और धीरे-धीरे पूरा पूँजीपति बन

बैठता है । इसके विपरीत गरीब किसान अपनी जमीन और खेतीके औजारोंसे वञ्चित होकर दिन-ब-दिन मजदूर बनता जा रहा है ।

मिश्रित वर्ग (mixed classes)—इसमें ऐसे समूहोंकी गणना होती है जिनका स्वार्थ किसी बातमें एक वर्गके साथ है और किसी बातमें दूसरे वर्गके साथ । उदाहरणार्थ,—रेलवेमें काम करनेवाला एक मजदूर जिसके घरपर अपना कुछ खेत भी है, इसी वर्गमें आता है । खेतपर मजदूरसे काम लेनेके कारण वह मालिक भी है और खुद मजदूरीका पेशा करनेके कारण मजदूर भी है ।

इन वर्गोंके अलावा कुछ लोग ऐसे भी पाये जाते हैं जो उत्पादनके काममें कोई भाग नहीं लेते । ऐसे वर्गोंकी गणना त्यक्त वर्ग (declassed) समूहोंमें की जाती है । भिखारी और आबारोंकी गणना इन्हींमें करनी चाहिये ।

मानव-समाजका विकास

समाजकी आदिम व्यवस्थामें मानव-समुदाय आर्थिक वर्गोंमें बँटा हुआ न था । मानव-समुदायके ऐतिहासिक विकासका सिंहावलोकन करते हुए हम देखते हैं कि आदिम (primitive) समाज आर्थिक दृष्टिसे पारस्परिक सहयोगके आधारपर संगठित था । यह वह जमाना था जब कि लोग प्रायः खानाबदोशों (nomads) की जिन्दगी बिताते थे । जंगलके फल और जड़ी-बूटियाँ बटोरकर, चिड़ियों और जानवरोंका शिकार करके और मछलियाँ पकड़कर अपनी जीविका चलाया करते थे । उस समय लोग जो कुछ इकट्ठा करके लाते थे वह किसी व्यक्ति-विशेषकी सम्पत्ति न होकर समुदायकी सम्पत्ति होती थी जिसे वे लोग आवश्यकतानुसार आपसमें बाँट लेते थे । बादमें पशुओंको पालकर उनका दुग्ध और मांस भी भोजनके काममें लाते थे । जबतक आदमी खाना-बदोशीकी हालतमें घूमता रहा और खेती करना सीखकर व्यवस्थित जीवन नहीं व्यतीत करने लगा तबतक वर्ग-विभेदका भौतिक आधार (material basis) पूर्ण रूपसे नहीं तैयार हो पाया था ।

वर्गोंकी उत्पत्ति

किन्तु धीरे-धीरे उत्पादनकी शक्तियोंका आगे विकास हुआ, जीवनकी कठिनाइयोंको सरल बनानेके प्रयत्नमें मनुष्यने खेती करना सीखा । खेतिहर बन जानेके बाद वह व्यवस्थित जिन्दगी बिताने लगा । अब खानाबदोशीकी अवस्थामें रहनेवाला वह ऐसा असहाय प्राणी नहीं रह गया जो पग-पगपर प्राकृतिक शक्तियोंका शिकार बना रहता था । अब धीरे-धीरे वह प्रकृतिके रहस्योंको जानने और उसके नियमोंका पता लगाकर उसकी अथाह शक्तियोंपर क्रमशः नियन्त्रण प्राप्त करने लगा । विज्ञान और कलाका आरम्भ हुआ । आरम्भिक यन्त्रोंका आविष्कार हुआ । यद्यपि सहयोगपर आधारभूत पुराने

समाजके बहुतसे रस्मों-रिवाज अब भी कायम थे, पर बहुत-सी बातोंमें तब्दीलियाँ भी हो गयीं । कृषि और ऐसे औजारोंके साथ जिनपर व्यक्ति अकेले ही काम कर सकता था, समाजके अन्दर श्रमका विभाजन भी बढ़ता गया । वस्तुओंका विनिमय (exchange) भी आरम्भ हुआ और विनिमयके नये-नये साधनोंकी खोज हुई । पुरोहितों और योद्धाओं आदिकी श्रेणियाँ बन गयीं ।

अब आर्थिक सहयोगपर आधारभूत आदिम व्यवस्थाकी सामाजिक समानताका लोप होने लगता है । पहलेकी तरह जीवन-निर्वाहके साधनोंको लोग अब सम्मिलित रूपमें इकट्ठा नहीं करते थे, फलस्वरूप आर्थिक उपजपर सबका समान स्वामित्व जाता रहा था । अब समाजमें गरीबों और अमीरोंका भेद पैदा हो गया । जिन लोगोंको समाजमें मुखियोंका पद मिल गया था, जो लोग पुरोहित बन गये थे या जो लोग बलवान् थे और लड़ाईमें गिरोहोंके नेता बन सकते थे ऐसे लोग छल, बल, कौशलसे समाजके मालिक बन बैठे ।

स्वामी और दास

उन दिनों विभिन्न जातियोंमें जमीन आदिके लिए लड़ाइयाँ बहुत होती थी । इन लड़ाइयोंमें जो लोग पकड़े जाते थे वे विजेताओंके यहाँ दास बनकर काम करते थे । इस तरह समाजमें धीरे-धीरे दास और उनके मालिक-जैसे वर्ग पैदा हो गये । दासोंकी संख्यामें वृद्धि होनेके और भी कई प्रकार थे, लेकिन मुख्य स्रोत जातियोंका पारस्परिक युद्ध ही था ।

ससारके विभिन्न भागोंमें जिन आरम्भिक सभ्यताओंका उदय हुआ उन सभीमें दासों और स्वामियोंका वह वर्ग-भेद पाया जाता है । प्राचीन कालमें दासताकी प्रथाके प्रचलनसे ही स्वामी-वर्गके सुविधाप्राप्त सदस्योंको यह अवसर मिल सका था कि वे अपनेको जीविका-निर्वाहके लिए आवश्यक दिन-रातके कठिन परिश्रमसे मुक्त करके ज्ञान-विज्ञान और कला-कौशलकी उन्नतिकी ओर लगा सकें । अगर दासताकी प्रथा उस समय प्रचलित न होती जो ग्रीस, रोम तथा मिस्र और प्राचीन कालकी दूसरी सभ्यताएँ जिनपर आज हम गर्व करते हैं समृद्धिकी उस सतहपर न पहुँच सकती थी जिसपर उन्हें हम पाते हैं । प्राचीन भारतमें भी दासताकी प्रथा विद्यमान रहनेके प्रमाण मिलते हैं । सभ्यताके आरम्भिक विकासके लिए दासताकी प्रथा एक ऐतिहासिक आवश्यकता (historic necessity) थी । उस युगमें जब यन्त्रोंका आजकी भाँति विकास नहीं हो पाया था, जब जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक कम-से-कम साधनोंको जुटानेके लिए लोगोंको दिन-रात जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, उस समय कला-कौशल आदिकी वृद्धि उसी हालतमें हो सकती थी जब कि मनुष्योंके लिए समूहको सांस्कृतिक विकासके लिए अवसर प्रदान किया जाता । यही कारण है कि हम देखते हैं कि अरस्तू जैसा विद्वान् भी बिना दासोंके समाजकी कल्पना नहीं कर सकता था ।

सामन्त और कृषकदास

धीरे-धीरे उत्पादक शक्तियोंका विकास होता गया, दास-प्रथाके जमानेमें श्रमका जो विभाजन अस्तित्वमें आया था वह और भी फैलता और जड़ पकड़ता गया । खेती और व्यापारकी वृद्धि होती गयी । इन सबका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि दासताकी प्रथाका भी स्वरूप बदला । अब वह सामन्तवादी युग आ जाता है जब कि बड़े-बड़े सामन्त योद्धाओं और पुरोहितोंका समाजमें बोलवाला था । खेतीकी सारी जमीनपर इन्हीं मठाधीणों या सामन्त सरदारोंका कब्जा हुआ करता था और किसानोंका बहुसंख्यक समुदाय उनको अपना मालिक मानकर और बदलेमें उन्हें भूमि-कर प्रदान करके जमीनको जोतता था । पुरानी दासता-प्रथा जिसमें स्वामी अपने दासके शरीर और आत्माका मालिक हुआ करता था अब मिट गयी और उसका स्थान कृषकदास (serfdom) ने लिया । कृषकदासताके अनुसार किसानकी जमीन और किसानपर भी सिद्धान्ततः स्थानीय सामन्तका अधिकार समझा जाता था । इन किसानोंको सामन्तकी जमीनपर बेगार भी करनी पड़ती थी । इस समय समाजमें सामन्त (feudal lords) और कृषक (serf) ये दो आधारभूत वर्ग थे और जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे इन दोनों दुनियादी तबकोंमें जोरोंकी कशमकश जारी थी ।

औद्योगिक क्रान्ति

इसी जमानेमें व्यापारियोंका वर्ग भी बढ़ रहा था । इस समयतक वस्तुओंका विनिमय काफी मात्रामे होने लगा था । इस विनिमयके वर्तमान माध्यम, सिक्कोंका भी प्रचार हो चला था । प्राचीनकालमें जब कि सिक्कोंका प्रचलन न था और गाय, घोड़े आदि जानवर या कुछ कीमती वस्तुएँ विनिमयके माध्यमका काम करती थी तो उस हालतमें व्यापारके फैलावके लिए गुंजाइश बहुत कम थी । सिक्कोंका चलन हो जानेके बादसे व्यापार तेजीसे बढ़ चला । आरम्भमें राजधानीमें और बादको अन्य प्रमुख केन्द्रोंमें इन व्यापारियों और व्यवसायिकोंके सघ (guild) बन गये । इन व्यापार-सघोंका काम वस्तुओंकी कीमत निर्धारित करना, व्यापारियोंके बीच अवाञ्छनीय प्रतिस्पर्धाको रोकना, व्यापारकी दशाओंका निरीक्षण तथा नियन्त्रण करना और व्यापारियोंके आर्थिक झगड़ोंका निपटारा करना आदि होता था ।

सामन्तशाही जमानेमें उत्पत्ति व्यक्तिगत रूपसे गृह उद्योगधन्धोंके जरिये ही होती थी । छोटे-छोटे औद्योगिक केन्द्रोंमें फैले हुए अपनी अपनी दूकानके अनेक मालिक होते थे । वे अपने परिवारवालों और उन लोगोंकी सहायतासे जो काम सीखना चाहते थे अपना कारोबार चलाते थे । मालिकको खुद भी पूरा परिश्रम करना पड़ता था । पर ज्यों-ज्यों व्यापार बढ़ता गया त्यों-त्यों औद्योगिक क्रान्तिके लिए पूर्वावस्था तैयार होती गयी । आरम्भमें बढ़ती हुई माँगको पूरा करनेके लिए कुछ मालिकोंने थोड़े मजदूरोंसे अपने घरपर मजदूरीपर काम लेना शुरू किया—उस ढंगपर जिस ढंगपर आज बनारसके रेशमके व्यवसायमें बहुतसे जुलाहे एक मालिकके कारखानेमें इकट्ठे होकर काम करते हैं ।

छोटे पैमानेके व्यक्तिगत उत्पादनके स्थानपर बड़े पैमानेके सामूहिक उत्पादनका बीज वृद्धि करनेके उपाय सोच निकाले जाते हैं और एक समय आता है जब भाष और बिजलीसे काम होने लगता है और बड़े पैमानेपर माल तैयार करनेवाले आधुनिक ढंगके कारखाने तैयार हो जाते हैं । कुटीरशिल्प प्रणालीके स्थानपर बड़े पैमानेपर कारखानोंद्वारा विकसित यन्त्रोका सहारा लेकर उत्पादन करनेकी जो नयी प्रणाली प्रचलित हुई उसने औद्योगिक अवस्थाओमें एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी, जिसे इतिहासकारोंने औद्योगिक क्रान्ति कहकर पुकारा है । यह औद्योगिक क्रान्ति १८ वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें पहले-पहल यूरोपमें और यूरोपमें भी सबसे पहले इंग्लैण्डमें हुई ।

इंग्लैण्डमें औद्योगिक क्रान्तिके सर्वप्रथम घटित होनेके कई कारण हैं । भाषसे चलने-वाले यन्त्रोंके लिए लोहे और कोयलेकी आवश्यकता थी, इंग्लैण्डमें ये दोनों ही खनिज-पदार्थ पास-पास और बहुतायतसे मिलते हैं । इसी प्रकार समुद्री मार्गपर इंग्लैण्डकी सुविधापूर्ण भौगोलिक स्थिति, वहाँकी जलवायु, कुशल कारीगरोंकी मौजूदगी, पूर्वके साथ इंग्लैण्डका व्यापार आदि कारणोंने इंग्लैण्डमें औद्योगिक क्रान्तिको पहले जन्म दिया । पूर्वके साथ और विशेषकर हिन्दुस्तान और हिन्द महासागरके साथ इंग्लैण्डका जो व्यापार होता था उसकी बदौलत इंग्लैण्डके पूँजीपतियोंके पास काफी पूँजी इकट्ठी हो गयी थी जिसके कारण इंग्लैण्डमें वे अपने व्यवसायको उत्तरोत्तर बढ़ानेमें समर्थ हुए ।

पूँजीपति और मजदूर

सामन्तवादी युगके बाद पूँजीवादका जमाना आता है । उत्पादनकी शक्तियोंके आगे विकासके मार्गमें सामन्तशाही आर्थिक प्रणालीमें रुकावट हो चली थी । समाजमें व्यापार बढ़ रहा था, पर सामन्तशाही ढाँचेमें उसके फैलावके लिए गुंजाइश बहुत कम थी । समूचे राष्ट्र छोटे-छोटे भूखण्डोंमें बँटे हुए थे, जिनका मालिक कोई सामन्त हुआ करता था । व्यापारके लिए आवश्यक कच्चे मालपर इन सामन्तोंका अधिकार था । कारखानोंमें जाकर काम करनेके लिए किसान स्वतन्त्र न थे, क्योंकि वे कृषकदास होनेके नाते अपने मालिकोंके खेतपर वेगार करनेके लिए बाध्य थे । जगह-जगह थोड़ी-थोड़ी दूरपर व्यापारियोंसे उनके मालपर चुगी वसूल की जाती थी । ऐसी हालतमें व्यापार किस तरह चल सकता था ? इधर कृषक-दासतामें फँसे होनेके कारण किसानोंका भी बुरा हाल था । फलस्वरूप, जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक बड़ी प्रजातान्त्रिक क्रान्ति हुई जिसने समाजका ढाँचा ही बदल दिया । इस क्रान्तिके परिणामस्वरूप सामन्तवादके स्थानपर पूँजीवादकी स्थापना हुई । पूँजीवादी आर्थिक प्रणालीकी विशेषता यह है कि उत्पादन, विनिमय और वितरणके साधनों, यानी जमीन, मिला, कारखानों, वैको आदिपर चन्द पूँजीपतियोंका कब्जा हो जाता है और समाजका बहुतसंख्यक वर्ग मजदूर बन जाता है । मजदूरवर्ग उत्पादनके साधनोंसे वञ्चित रहनेके कारण उत्पादनके साधनोंके मालिकों अर्थात् पूँजीपतियोंके हाथ अपनी श्रमशक्ति बेचकर और बदलेमें मजदूरी प्राप्त कर जीवन निर्वाह करता है । गुलामी-प्रथाके युगमें जो स्थान मालिकोंका था और सामन्तशाही

प्रणालीमे जो सामन्तोका था वही स्थान वर्तमान आर्थिक प्रणालीमे पूँजीपतियोका हो जाता है । इसी प्रकार, गुलामो और कृपकदासोका स्थान मजदूर वर्ग लेता है । पूँजीपति और मजदूर ये आजकलके दो आधारभूत वर्ग हैं जिनमे आपसमे आज हमारी आँखोके सामने भीषण वर्ग-सघर्ष चल रहा है ।

आर्थिक युग

ऊपर हमने संक्षेपमे यह दिखानेकी कोशिश की है कि आर्थिक उत्पादनकी शक्तियोके विकासके साथ-साथ किस प्रकार समाजकी आर्थिक प्रणालियाँ बदलती रही हैं और यह कि हर आर्थिक प्रणालीमे अपरिवर्तित रूपसे दो आधारभूत वर्ग यानी दुनियादी आर्थिक श्रेणियाँ मौजूद रही हैं । इन दोनो श्रेणियोके हित परस्पर एक दूसरेके विरुद्ध रहे हैं और प्रभुत्वशील (dominant) वर्ग दूसरे वर्गको दास बनाकर, उसकी श्रमशक्ति शोषण करके, अपने लिए जीवनकी सुविधाएँ प्राप्त करता रहा है । हमने देखा कि मनुष्य-समाजकी आदिम व्यवस्था सहयोगपर आधारित थी । उस समय सभी मिलकर जीविका-निर्वाहकी सामग्री एकत्र करते थे और सम्पत्तिपर सबका समान रूपसे अधिकार था । आगे चलकर व्यक्तिगत सम्पत्तिका उदय होनेपर, पहले दासता-प्रथा, फिर सामन्तशाही और अन्तमे पूँजीवादका जमाना आता है । इन तीनों युगोमे क्रमशः स्वामी और दास, सामन्त और कृपकदास और पूँजीपति और मजदूर यह परस्पर-विरोधी आधारभूत वर्ग पाये जाते हैं ।

यहाँपर यह बात ध्यान देनेकी है कि जिस ढंगसे एक युगके बाद दूसरे युगके आनेकी बात कही गयी है, ठीक उसी प्रकार सभी देशोके इतिहासमे स्पष्ट रूपसे एक युगके बाद पूर्ण रूपसे दूसरा युग काम करता हुआ नजर नहीं आता । प्रायः ऐसा होता है कि नयी आर्थिक व्यवस्थाके आ जानेपर भी प्राचीन आर्थिक व्यवस्थाके बहुत कुछ अंश दूसरी व्यवस्थाके भीतर भी पाये जाते हैं । उदाहरणके लिए अगर हम अपने ही देशको ले तो यहाँपर हमें किन्ही-किन्ही स्थानोमे गुलामीके जमानेकी यादगार भी मिलेगी, सामन्तशाही जमानेका आर्थिक ढाँचा दिखायी पड़ेगा (विशेषकर देशी रियासतोमे) और पूँजीवादी आर्थिक प्रणालीके युगमे तो हम रह ही रहे हैं । अतः, जब हम किसी युगकी बात करते हैं तब हमारा मतलब उस समयकी उस समाजमे प्रचलित प्रधान आर्थिक प्रणालीसे होता है ।

वर्गविहीन समाज

जब कोई समाजवादी वर्गरहित समाजकी स्थापना करनेकी बात करता है तो उसका मतलब इन्ही आर्थिक वर्गोंसे होता है । समाजवाद एक ऐसे समाजकी स्थापना करना चाहता है जिसमे परस्पर-विरोधी शोषक और शोषित आर्थिक वर्ग मिट जायँ और समाज सहयोगके आधारपर सगठित व्यक्तियोका सच्चा प्रजातन्त्र बने । जबतक समाजका ढाँचा इस प्रकारका बना रहेगा कि एक वर्ग दूसरेको दबाता रहेगा तबतक सामूहिक रूपसे समाजके सदस्योकी उन्नति नहीं हो सकती । समाजवादी समाजमे जब कि राजसत्ता फिर शोषित वर्गोंके हाथमे आ जाती है और उत्पादनके साधनोपर सारे समाजका अधिकार हो

जाता है, मनुष्योंके शोषणका आर्थिक आधार ही खत्म हो जाता है । अबतक समाजके विकासमें एक आर्थिक प्रणालीके बाद जो दूसरी आर्थिक प्रणालियाँ कायम हुईं उनमें राज सत्ता एक वर्गसे निकलकर दूसरे नये वर्गके हाथमें आती रही है, उत्पादनके साधनोंपर वर्ग-विशेषका अधिकार होता आया है । किन्तु समाजवादी प्रणालीमें इसके विपरीत उत्पादनके साधनोंपर समाजका ही अधिकार होता है और शोषक और शोषित दोनों ही वर्ग नष्ट हो जाते हैं । समाजवादी समाजमें राज्यका—जो कि अबतक शासकवर्गद्वारा शासित-वर्गके दमनका हिंसा-प्रधान अस्त्र रहा है—भी अस्तित्व न रहेगा । उस समय मनुष्य पहली बार पशुतुल्य जीवन त्यागकर मनुष्योचित जीवन शुरू करेगा । अबतक जिस प्रकार वह सामाजिक विकासकी शक्तियोंका दास बनकर रहता आया है अपनी उस विवशताके दायरेसे ऊपर उठकर अब वह बोधपूर्वक अपनी प्रगतिकी दिशाको निर्धारित और नियन्त्रित कर सकेगा ।

वर्ग-संघर्षकी आवश्यकता

हमारा वर्ग-विहीन समाज स्थापित करनेका लक्ष्य वर्ग-संघर्षके साधनको अपनाते ही सिद्ध हो सकता है । आज समाजमें शोषक और शोषित वर्गोंके बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें हमारा फर्ज शोषित जनतामें ऐसी चेतना पैदा करना है कि शोषित-वर्गोंकी लड़ाई आर्थिक न रहकर राजनीतिक बन जाय । हमें शोषित-वर्गोंके सदस्योंके मनमें यह बात बैठा देनी है कि जबतक समाजकी प्रचलित व्यवस्था कायम है और उत्पादनके साधनोंपर पूंजीपतियोंका कब्जा है तबतक उनकी हालत नहीं सुधर सकती ।

वर्ग-चेतना क्या है ?

शोषक वर्गों, यानी जमींदार और पूंजीपति, तथा शोषित वर्गों, यानी किसान, मजदूर और दूसरे सताये हुए तबकोंके बीच संघर्ष तो आज भी जारी है । परन्तु आज उनकी यह लड़ाई आर्थिक लड़ाई मात्र है । कारखानोंके मजदूर बड़ी तादादमें संगठित रूपमें मालिकोंसे मोर्चा लेते हैं और अपनी इस लड़ाईमें कुर्बानी भी बहुत करते हैं । लेकिन उनकी यह लड़ाई मजदूरीको बढ़ाने, कामके घण्टे घटाने, अपने साथियोंपर किये अत्याचारोंको दूर करने या इसी प्रकारकी दूसरी शिकायतोंको रफा करानेके लिए होती है । यहाँपर ध्यान देनेकी बात यह है कि मजदूरोंकी यह सारी लड़ाई वर्तमान व्यवस्थाके भीतर केवल अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त करनेके लिए ही होती है । मालिकोंका कारखानोंपर जो अधिकार है उसको वे चुनौती नहीं देते । हमें मजदूरोंको समझाना है कि समाजके मौजूदा आर्थिक ढाँचेको कायम रखते हुए केवल छोटे-मोटे अधिकारोंके लिए लड़नेसे ही काम न चलेगा, बल्कि सारी मजदूर जमातको संगठित होकर एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसमें मौजूदा आर्थिक व्यवस्थाका ही अन्त हो जाय और एक ऐसी नयी आर्थिक प्रणालीकी स्थापना की

जाय जिसमें आजकी तरह उत्पादनके साधनोपर किसी एक वर्ग-विशेषका अधिकार न हो, बल्कि समूचे समाजका अधिकार हो। ऐसे ही नये समाजमें हम युगोसे चले आते हुए शोषण और वर्ग-विभेदका अन्त कर सकेंगे और समाजके हर परिश्रमी सदस्य को उसके व्यक्तित्वके विकासका उचित अवसर प्रदान कर सकेंगे।

भारी भ्रम

समाजवादियोंके विरुद्ध अनेक स्वार्थी और अनभिज्ञ लोगोके द्वारा, विशेषकर शोषक-वर्गके सदस्योद्वारा, यह अभियोग लगाया जाता है कि वे समाजके भीतर वर्ग-विद्वेषकी सृष्टि कर रहे हैं। इन लोगोके कथनानुसार समाजमें शान्ति कायम है किन्तु समाजवादी लोग विभिन्न वर्गोंको आपसमें लड़ाकर अशान्ति पैदा करना चाहते हैं, वे शान्तिके शत्रु और घृणाके प्रचारक हैं, पर यदि हम वस्तुतः स्थितिकी जाँच करें तो इससे अधिक यथार्थतासे दूर और कोई बात न होगी। सच तो यह है कि जो लोग समाजवादियोंके विरुद्ध इस प्रकारका अभियोग लगाते हैं वे न तो समाजकी वास्तविकतापर ध्यान देते हैं, न उन्हें सामाजिक विकासके नियमोंका पता है और न वे वर्गयुद्धका ठीक-ठीक अर्थ ही समझते हैं। शोषकवर्गके अनेक सदस्य तो जान-बूझकर लोगोके मनमें भ्रम पैदा करनेके लिए ही ऐसी मन-गढन्त बातोंका प्रचार करते हैं। वर्ग-युद्ध समाजवादियोंका पैदा किया हुआ नहीं है। वह तो समाजमें हमेशा चलता रहता है और उसी समयसे चलता आया है जबसे वर्गोंकी उत्पत्ति हुई। और यदि हम गम्भीरतापूर्वक, मार्क्सवादी व्याख्याकी रोशनीमें, अवतकके इतिहासका अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि अवतक समाजमें जो प्रगति हुई है प्रगति की एक मजिलसे उठकर जब जब मानव-समाज एक दूसरी ऊँची-मजिलपर पहुँचा है, तब-तब यह कार्य वर्ग-संघर्षके द्वारा ही सम्पादित हुआ है। वर्ग-संघर्ष ही सामाजिक प्रगतिका आधार रहा है। समाजवादी लोग वर्गसंघर्षको पैदा नहीं करते और न वे उसको पसन्द ही करते हैं। उनका उद्देश्य तो जैसा कि हम कह चुके हैं, समाजका ऐसा संगठन करना है जिसमें परस्पर-विरोधी वर्गों और उनमें निरन्तर चलनेवाले वर्ग-संघर्षका अन्त हो जाय। लेकिन चूँकि हम किसी सामाजिक उद्देश्य की सिद्धि तभी कर सकते हैं जब कि हम सामाजिक प्रगतिके नियमोंका अध्ययन करें, और उन नियमोंके अनुसार अपने कार्यकी दिशा निर्धारित करें, इसलिए समाजवादियोंको बाध्य होकर वर्ग-संघर्षको अपना पड़ता है। वर्ग-संघर्षके द्वारा ही समाजकी उन्नति होती आयी है, समाजवादी इस कठोर सत्यकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसी अवस्थामें जब कि समाजमें वर्ग-संघर्ष चल रहा है तब तो हमारे लिए केवल यही रास्ता बच रहता है कि हम यह चुन लें कि हमें शोषक और शोषित इन दोनों वर्गोंमेंसे किसका साथ देना है।

घृणाका प्रचार

समाजवादियोंपर घृणा फैलानेका इल्जाम भी बेबुनियाद है। जो समाजवादी अन्ततोगत्वा वर्ग-विहीन समाजकी रचना करना चाहते हैं उनके सम्बन्धमें ऐसा किस

प्रकार कहा जा सकता है ? इसके अतिरिक्त इस समय भी समाजवादी व्यक्तिगत घृणाको दूर करनेका ही प्रयत्न करता है । उदाहरणके लिए आज हम यह देखते हैं कि जब एक मजदूर अपने मालिकसे मजदूरीके लिए लड़ता है तब वह उसे घृणाकी दृष्टिसे देखता है, लेकिन समाजवादी मजदूरको यह बतलाता है कि अगर मजदूरको उचित मजदूरी नहीं मिलती तो इसमें दोष व्यक्तिगत रूपसे खास मालिकका नहीं है, बल्कि उस पूंजीवादी प्रणालीका है जिसने उत्पादनके साधनोंको मुट्ठीभर पूंजीपतियोंके हाथमें दे दिया है । अगर मजदूरवर्ग शोषण-सम्बन्धसे मुक्ति चाहता है तो उसे वह व्यक्तिगत रूपसे पूंजीपतियोंको हानि पहुँचानेकी भावनासे काम करके या मशीनोंको तोड़-फोड़कर नहीं, बल्कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणालीको मिटाकर और मशीनोंपर शोषित वर्गोंका कब्जा करके ही मिल सकती है । इसी प्रकार समाजवादी मजदूरोंमें चलनेवाली प्रतिस्पर्धा और घृणाको दूर करनेका प्रयत्न करते हैं । बेकारी और गरीबीके इस युगमें हर मजदूर दूसरे मजदूरको बीजरूपमें (potentially) प्रतिद्वन्द्वी समझकर उससे घृणा करता है, किन्तु समाजवाद मजदूरोंको यह बतलाता है कि वे आपसमें सहयोग करके और सगठित होकर ही शोषण-रहित समाजकी रचना कर सकते हैं । व्यक्तिगत घृणाको दूर करनेके लिए समाजवादियोंको श्रेय मिलना चाहिये । समाजमें प्रचलित शोषण सम्बन्धके प्रति समाजवादी जरूर घृणा पैदा करता है और उसे वह उचित समझता है, क्योंकि वर्तमान दुर्दशाके प्रति घृणा उत्पन्न करके ही हम व्यक्तिके मनमें उस दुर्दशाके प्रति विद्रोह पैदा कर सकते हैं ।

क्रान्ति क्या है ?

ऊपर कहा गया है कि वर्ग-संघर्षके द्वारा ही अबतक समाज तरक्कीकी एक मंजिलसे दूसरी मंजिलपर जाता रहा है । आर्थिक उत्पादनकी प्रणाली अपने विकासके क्रममें एक ऐसी अवस्थाको पहुँच जाती है कि उस ढाँचेके मातहत रहकर उत्पादनकी शक्तियाँ (forces of production) आगे उन्नति नहीं कर सकती ; उनका विकास रुकने लगता है—उत्पादन-सम्बन्धों और उत्पादक शक्तियोंका विरोध चरम सीमापर पहुँच जाता है । उस समय उत्पादक शक्तियोंके विकासके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पुराना आर्थिक ढाँचा नष्ट किया जाय और एक नयी आर्थिक प्रणाली कायम की जाय जिसमें उत्पादक शक्तियोंके ऊपरसे वे बन्धन उठ जायँ जो कि उसके विकासको रोकते रहे हैं । पुरानी आर्थिक प्रणालीका नाश करके उसके स्थानपर एक नयी आर्थिक प्रणाली कायम करना एक ऐसी घटना है जो कि मामूली सुधारवाद (reformism) के रास्ते नहीं हो सकती । सुधारवादके जरिये किसी ढाँचेको तभीतक बदला जा सकता है जबतक ढाँचेकी बुनियादको कायम रखते हुए उसमें ऊपरी तब्दीलियाँ की जाती हैं । जब ढाँचेमें बुनियादी तब्दीलीका सवाल उठता है तब वे स्थिर स्वार्थवाले वर्ग जो यह देखते हैं कि उनकी सुविधाएँ बुनियादी तब्दीलीकी बदौलत खत्म होनेवाली हैं, अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर, अपनी सारी ताकतके साथ, इस प्रकारकी तब्दीलीकी मुखालिफत करते

है। फलस्वरूप समाजके ढाँचेमें आधारभूत परिवर्तनकी ऐतिहासिक आवश्यकता क्रान्तिके द्वारा ही पूर्ण होती है।

इतिहासकी भौतिक व्याख्या

यहाँपर यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि मनुष्यके विविध कार्यक्षेत्रोंमें भी विकासके लिए इन्ही क्रान्तियोंके जरिये रास्ता साफ होता रहा है। एक सीमातक उन्नति करनेके बाद उत्पादनके क्षेत्रकी भाँति ही दूसरे क्षेत्रोंमें भी तभी उन्नति हो सकती है जब कि आर्थिक उत्पादनके ढाँचेमें आधारभूत परिवर्तन हो। दूसरे शब्दोंमें समाजका आर्थिक ढाँचा ही वह आधार या बुनियाद है जिसपर मनुष्यके अन्य कार्यक्षेत्रोंकी प्रणालियाँ—राजनीति, आचारनीति, साहित्य, कानून आदि—खड़ी होती है। अगर मनुष्यके सामाजिक संगठनको घरकी उपमा दे तो हमें कहना पड़ेगा कि आर्थिक उत्पादनका ढाँचा अर्थात् जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक वस्तुओंके पैदावारका तरीका, इस घरकी नींव है और मनुष्यके दूसरे कार्य—साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धार्मिक, आध्यात्मिक आदि—इसी घरका ऊपरी ढाँचा है।

उत्पादन-सम्बन्ध

समाजके इस बुनियादी आर्थिक ढाँचेका वर्णन करते हुए कार्लमार्क्सने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “अर्थशास्त्रकी विवेचना”में एक स्थलपर लिखा है—“समाजमें व्याप्त उत्पादन-व्यवस्थामें लगे हुए मनुष्य निश्चित सम्बन्ध स्थापित करते हैं जो कि निर्धारित (determined) रहते हैं—अर्थात् वे मनुष्योंकी इच्छापर निर्भर नहीं होते—ऐसे उत्पादक सम्बन्ध जो कि उत्पादनकी भौतिक शक्तियोंके विकासकी निश्चित अवस्थाके अनुरूप होते हैं। इन्ही उत्पादन-सम्बन्धोंके योगसे समाजकी आर्थिक प्रणाली बनती है जो कि वह वास्तविक आधार होती है जिसपर वैधानिक और राजनीतिक भित्तिका निर्माण होता है।”

मार्क्सके इस उद्धरणमें तीन बातें ध्यान देनेकी हैं। एक बात यह कि समाजके

1. In the social production which human beings carry on, they enter into definite relations, which are determined, that is to say, independent of their will—production relations which correspond to a definite evolutionary phase of the material forces of production. The totality of these production relations forms the economic structure of society, the real basis upon which a legal and political superstructure develops”—Karl Marx in “A Critique of Political Economy.”

तैयार करते हैं, उन्हींके अनुरूप उत्पादन सम्बन्ध बनते हैं। सक्षेपमें उत्पादक शक्तियोंके विकासके अनुरूप उत्पादक सम्बन्ध कायम होते हैं, उत्पादक सम्बन्धोंको जोड़कर समाजका आर्थिक ढाँचा बनता है और आर्थिक ढाँचेके आधारपर राजनीतिक और सांस्कृतिक ढाँचेकी दीवार खड़ी होती है।

विचारधारामें परिवर्तन

समाजके आर्थिक ढाँचेमें परिवर्तन होनेके साथ उसकी मानसिक विचारधारामें किस प्रकार एकदम परिवर्तन हो जाता है इसका एक उदाहरण जिससे इतिहासके विद्यार्थी ज्यादा अच्छी तरह परिचित हैं, सोलहवींसे उन्नीसवीं शताब्दीका यूरोप है। इस समय यूरोपके आर्थिक ढाँचेमें परिवर्तन हुआ अर्थात् सामन्तशाहीका स्थान पूंजीवादने लिया। आर्थिक ढाँचेके इस परिवर्तनके साथ ही हमें यूरोपके समूचे विचारक्षेत्रमें भी क्रान्तिकारी वेगसे परिवर्तन दिखायी पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्रमें सामन्तोंका प्रभुत्व जाता रहता है, राजाका दैवी अधिकार (divine right of king) अब दन्तकथाकी कल्पनामात्र रह जाता है और राष्ट्रीयता तथा प्रजातन्त्रकी भावनाओंका प्रादुर्भाव एवं प्रसार होता है। यदि हम ध्यानपूर्वक इस महान् राजनीतिक परिवर्तनके मूलकी खोज करें तो हमें पता चलेगा कि प्रजातन्त्र और राष्ट्रीयताकी भावनाओंका प्रसार इसीलिए हुआ कि उत्पादनकी शक्तियोंके विकासके लिए इनकी आवश्यकता थी।

सामन्तशाही कालके राजनीतिक ढाँचेमें वृहद् भूखण्ड या राष्ट्र जो भौगोलिक दृष्टिसे एक इकाई (unit) कहे जा सकते थे, अनेक छोटे-छोटे प्रादेशिक खण्डोंमें बँटे हुए थे, जिनपर छोटे-छोटे जागीरदारों या सामन्तोंका निरंकुश शासन हुआ करता था। व्यापारियोंको अपने मालपर एक ही राष्ट्रके भीतर एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जानेके लिए कई बार चुगी अदा करनी पड़ती थी, जिससे पदार्थोंका मूल्य बहुत बढ़ जाता था। साथ ही इन छोटे प्रदेशोंके भीतर जो कच्चा माल, आवागमनके साधन—सड़के, पुल, आदि होते थे उनका अपनी इच्छानुसार लाभ व्यापारी-वर्ग न उठा सकता था। अतः व्यापारियोंके नये वर्गको यह आवश्यकता पड़ी कि वह ऐसी राज्य-पद्धति कायम करे जिसमें प्रभुताका विभाजन वंशकी मर्यादाके आधारपर न होकर सम्पत्तिके स्वामित्वके आधारपर हो। यद्यपि कहनेको समाजके सभी शोषित वर्गोंकी सहानुभूति प्राप्त करनेके लिए पूंजीपतियोंने प्रजातन्त्रको जनताकी भलाईके लिए जनताके प्रतिनिधियोंका शासन बतलाया, लेकिन हम यह स्पष्ट देख सकते हैं कि तथाकथित शासन वास्तवमें पूंजीवादी वर्गके प्रतिनिधियोंका शासन है जो कि जनताके हितोंको ठुकराकर पूंजीपतियोंके वर्गस्वार्थकी रक्षा करता है। मार्क्सके शब्दोंमें “वर्तमान शासन-तन्त्रकी कार्यकारिणी समूचे पूंजीपति वर्गके हितोंको देखनेवाली प्रबन्धक समिति ही है।”^१ अर्थशास्त्रके क्षेत्रमें इसी समय ऐडम

1. The executive of the modern State is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie—“Communist Manifesto”.

स्मिथ, रिकार्डो आदि उस विचारधाराके ग्रंथशास्त्रियोंकी प्रधानता हुई जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि व्यापारकी वृद्धि और मजदूरोका शोषण करके अर्थोद्योगिकरणकी वृद्धि करनेमें ही देशकी समृद्धि है। कानूनमें अब वंगमर्यादा और स्तवेका महत्त्व जाता रहा और आपसके एकरारकी आजादी (freedom of contract) पर जोर दिया जाने लगा। धर्म और आचार-नीतिके क्षेत्रमें अब 'शास्त्रवाक्य प्रमाणम्' माननेकी प्रथा लुप्त होने लगी और लोग हर बातको तर्क और विवेककी कसीटीपर कमाने लगे। दार्शनिक विचारोंमें भी परिवर्तन हुआ। अध्यात्मवादके स्थानपर भौतिकवादका प्रसार हुआ। वर्कले, स्पिनोजा, फायरबाख आदि नये-नये दार्शनिकोंने बताया कि यह दृश्य जगत् अलौकिक पराभावनाकी माया न होकर प्रकृतिका ही विकास है। साहित्यके क्षेत्रमें अब यथार्थवादकी प्रधानता हुई।

इन परिवर्तनोंका महत्त्व हम तबतक ठीक नहीं समझ सकते जबतक हम अपने नामने इस सत्यको रखकर न चलें कि इस समय यूरोपके आर्थिक ढाँचेमें परिवर्तन होता है—सामन्तशाहीके स्थानपर पूँजीवादकी उत्पत्ति होती है। जो लोग इतिहासकी भौतिकवादी व्याख्याको स्वीकार करके नहीं चलते वे इस प्रग्तका उत्तर नहीं दे पाते कि आखिर ये परिवर्तन जो यूरोपीय समाजकी विचारधारामें देख पड़ते हैं अलग-अलग और पहले या बादमें क्यों हुए? ऐडम स्मिथका जन्म सौ साल पहले क्यों नहीं हुआ? या न्यूयॉर्क साहब एक सदीके बाद क्यों नहीं पैदा हुए? इतिहासकी भौतिकवादी व्याख्या ही इन महान् परिवर्तनोंके रहस्यकी व्याख्या करनेवाली एकमात्र कुजी है। यूरोपमें सामन्तशाही पद्धतिके स्थानपर पूँजीवादी पद्धतिके प्रसार होनेपर मानव विचारधाराकी विभिन्न प्रणालियोंमें हम परिवर्तन होते देखते हैं। दूसरे युगों और दूसरे देशोंका अध्ययन भी इसी दृष्टिकोणसे करके ही सामाजिक परिवर्तनोंका रूप समझा जा सकता है।

मार्क्सवादका उदय

इसी जमानेमें जब कि पूँजीवादी उत्पादन-प्रणालीका व्यापक प्रसार हो जाता है, हम समाजको प्रगतिके नियमोंका वैज्ञानिक विवेचन करनेवाली एक नयी विचारधाराका अर्थात् मार्क्सवादका प्रादुर्भाव देखते हैं। सामाजिक विकासकी मीमांसा करते हुए पूँजीवादी उत्पादन-प्रणालीके विकासके नियमोंका अध्ययन करके कार्ल मार्क्सने यह बतलाया कि संसारका विकास समाजवादकी ओर हो रहा है और यह नयी स्थिति वर्ग-संघर्षके जरिये ही आयेगी। मार्क्सने सामाजिक विकासके जो जो नियम हमारे सामने रखे वे सब प्राचीन कालसे ही समाजमें काम करते चले आ रहे थे। समाजकी आर्थिक-रचनाके अनुसार उसकी दूसरी विचारप्रणालियाँ बनती थी, प्रकृतिकी शक्तियोंका नवीन ज्ञान होनेपर और परिणामस्वरूप उत्पादक शक्तियोंका स्वरूप बदलनेपर, समाजका आर्थिक ढाँचा बदलता रहा है और उसके साथ ही समाजकी रचनामें सर्वांगीण परिवर्तन होता रहा है। यह परिवर्तन द्वन्द्वमान ढंगसे (dialectically) वर्ग-संघर्षके जरिये होता रहा है। मार्क्सकी विशेषता यह थी कि उसने, अपने साथी एंगेल्सकी सहायतासे वैज्ञानिक ढंगसे इन नियमोंकी विवेचना करते हुए, उन्हें एक विचार-पद्धतिमें

संग्रहित किया जिसे हृदयङ्गम करके हम समाजके भूत और वर्तमानके इतिहासको समझ सकते हैं और भविष्यके लिए अपना कर्तव्य निर्धारित कर सकते हैं ।

जब मार्क्सने पहले-पहल यह बतलाया था कि दुनिया समाजवादकी ओर जा रही है तो पूँजीवादके समर्थक विद्वानोंने मार्क्सके विचारोंका मजाक उड़ाया था, समाजवादको स्वप्नमात्र बतलाया था । आज हम अपनी आँखोंके आगे देख रहे हैं कि किस प्रकार यह स्वप्न प्रत्यक्ष हो रहा है और मार्क्सका भविष्यकथन सत्य सिद्ध हो रहा है । आज संसारके छठे भागपर, रूसमें, समाजवादकी विचारधाराके अनुसार व्यावहारिक रूपमें समाजका संगठन हो रहा है । कई देशोंमें मजदूरोकी पार्टियाँ ताकतमें आ चुकी हैं । वर्ग-सघर्षने अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है । प्रजातन्त्रवादी देशोंमें धारा-सभाओंकी लड़ाई अब सीधे टोरी और लेबर (मजदूर) पार्टियोंके बीच रह गयी है । बीचके लिबरल लोगोंका प्रभाव घटता ही चला जा रहा है । शोषित-वर्गके सदस्य शोषकोंके स्वार्थोंकी रक्षाके लिए बनायी गयी विचारधाराके प्रभावसे मुक्त हो रहे हैं ।

समाजवादकी ओर

समाजवादका आदर्श सर्वसाधारणमें इतना जनप्रिय हो गया है कि उसके बड़ेसे बड़े विरोधीकी भी यह हिम्मत नहीं पड़ती कि वह खुलेआम समाजवादका विरोध कर सके । इसके विपरीत, बड़ेसे बड़े प्रतिक्रियावादी सिद्धान्तोंका प्रतिपादन भी समाजवादके नामपर किया जाने लगा है । हिटलर भी जर्मन जनतापर अपना प्रभाव जमाये रखनेके लिए अपने प्रतिगामी सिद्धान्तोंका प्रचार 'राष्ट्रीय समाजवाद' (National Socialism) के नामपर ही करता था । जब कोई भी विचार सर्व-साधारणके मनपर काबू कर लेता है—और वह तभी काबू कर लेता है जब कि सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे वह वांछनीय होता है—तो उसके विरोधियोंको उससे खुलेआम लड़नेकी हिम्मत नहीं होती और खुली लड़ाईके बदलेमें छिपी लड़ाईका रास्ता अख्तियार करते हैं । आज हिन्दुस्तानमें भी हम यही हालत देख सकते हैं । यहाँ भी भारतीय समाजवाद, वर्णश्रम समाजवाद, मुस्लिम समाजवाद और वैदिक समाजवाद आदि तरह-तरहके समाजवादोंका हवाला देकर यह कहा जाने लगा है कि मार्क्स और लेनिनद्वारा प्रतिपालित वैज्ञानिक समाजवाद विदेशी है और अपने देशमें उसकी आवश्यकता नहीं !

पूँजीवादकी ह्रासवस्था

ऊपरके उदाहरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार आर्थिक रचनामें परिवर्तन होनेके साथ समाजकी समूची विचारधारामें परिवर्तन हो जाता है । इतिहासके किसी कालको भी लेकर उसका विश्लेषण करनेपर हमें यही नियम काम करता हुआ दिखायी देगा । आजकलकी अवस्थाका विश्लेषण करके देखें तो हमें पता चलेगा कि उत्पादनकी शक्तियों और उत्पादनकी अवस्थाओंके बीचकी असंगतियों (contradictions) के आत्यन्तिक रूपसे बढ़ जानेके कारण पूँजीवादी आर्थिक-रचना जर्जर हो रही है और परिणामस्वरूप वर्तमान पूँजीवादी सामाजिक भवनका ऊपरी ढाँचा भी

जर्जर हो रहा है। साहित्य, दर्शन, ग्रंथशास्त्र, राजनीति किसी क्षेत्रको क्यों न लें, हम देखेंगे कि विकासकी गति रुक गयी है और सभी क्षेत्रोंमें किकर्तव्यविमूढताका साम्राज्य हो रहा है। जब समाजकी आधारभूत आर्थिक प्रणाली उन्नति करती रहती है तभी उसके साथ दूसरे विचार-क्षेत्रोंमें भी उन्नति होती है और यह स्वाभाविक ही है कि जब आधार ही क्षीण और जर्जर हो जाय तो ऊपरी ढाँचा भी हिल जाय। राजनीतिके क्षेत्रका विचार करनेपर हम देखते हैं कि आज प्रजातन्त्रका ह्याम हो रहा है और उसके स्थानपर तानाशाही (dictatorship) की वृद्धि हो रही है तथा सकुचित राष्ट्रीयताकी भावना जोर पकड़ रही है।

आर्थिक क्षेत्रमें मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका स्थान राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता (autarchy) का सिद्धान्त ले रहा है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता और भ्रातृभावके विचारोंका प्रसार रुक गया है और सभी बड़े राष्ट्र एक महायुद्धकी तैयारीमें लगे हुए हैं जो कि किसी क्षण भी घटित हो सकता है। दर्शनके क्षेत्रमें रहस्यवादकी वृद्धिके रूपमें प्रतिगामिताका प्रचार हो रहा है। साहित्यमें आर्थिक रचनाका प्रतिविम्ब निराशावाद, संशयवाद और स्वप्नलोकवादके रूपमें मिलता है। कवि और लेखक जीवनकी कटु यथार्थतासे घबराकर सुखद स्वप्नों और कल्पनाओंका मानसिक विण्व-निर्माण कर मनको सान्त्वना दे रहे हैं। इतिहासमें खोजकी प्रवृत्ति रुक गयी है। संक्षेपमें, जिस उत्साह और लगनके साथ पूंजीवादके विकासके कालमें उस प्रणालीके सार्थक विद्वान् काम कर रहे थे उस उत्साह और लगनका आज कहीं भी पता नहीं चलता।

इसके विपरीत, सोवियत रूसमें, जहाँ एक नयी समाजवादी आर्थिक रचनाका निर्माण हो रहा है, लोगोंके दिल एक नये उत्साहसे भरे हुए हैं। जहाँ पूंजीवादी देशोंमें लोग अपने भविष्यके बारेमें सणक हैं, उसे अन्धकारमय समझते हैं, वहाँ रूसमें लोगोंके मन एक नयी आशा, एक नयी उमंगसे भरे हुए हैं और वे अपने भविष्यको सुखद एवं उज्ज्वल समझते हैं। चारों ओरसे पूंजीवादी राष्ट्रोंसे घिरे होने और पड़ोसी फासिस्ट राष्ट्रोंके आक्रमणका भय प्रतिक्षण बने रहनेके कारण रूसके निवासियोंको अपनी रक्षाकी तैयारीके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सम्पत्तिका बहुत बड़ा अंश आज वे सैनिक तैयारीकी भेंट चढ़ानेको बाध्य हैं। किन्तु पूंजीवादी देशोंकी भाँति यह त्याग करते हुए उन्हें खेद और सन्ताप नहीं हो रहा है। उनका विश्वास है कि वर्तमानके सुखोंके इस त्यागके द्वारा वे अधिक समृद्ध और सुखद भविष्यका निर्माण कर रहे हैं।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

जब हम कहते हैं कि समाजके आर्थिक ढाँचेकी बुनियादपर ही मनुष्यकी अन्य सभी क्षेत्रोंकी प्रणालीका ढाँचा खड़ा होता है—किसी समयका साहित्य, धर्म, राजनीति, कानून और दर्शन आदि उस समयके समाजमें प्रचलित आर्थिक ढाँचेके द्वारा निर्धारित होता

है—तो हमारा यह मतलब कदापि नहीं होता कि समाजका समूचा विकास पूर्ण रूपसे उत्पादन-सम्बन्धोपर ही निर्भर होता है और उसपर विचारोका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । किसी समय समाजमें जो दर्शन, धर्म, कानून आदि प्रचलित हैं समाजके आगेके विकासमें इन सबका भी काफी प्रभाव पड़ता है, किन्तु साधारणतया इनका प्रभाव आर्थिक परिस्थिति-के प्रभावके मुकाबले बहुत कम पड़ता है ।

विचारोंका प्रभाव

किसी समाजकी विचार-प्रणालियोंमें अर्थात् प्रचलित दर्शन, धर्म, राजनीति आदिमें उस समय आधारभूत परिवर्तन होता है जब कि समाजकी आर्थिक रचनामें आधारभूत परिवर्तन होता है । इस प्रकार जब एक विशेष प्रकारकी विचार-परम्परा जड़ पकड़ लेती है तो आगे समाजका जैसा विकास होता है उसपर उसकी छाप पड़ती ही है, किन्तु यह विशेष प्रकारकी विचार-परम्परा प्रधानतः स्वयं एक विशेष प्रकारकी आर्थिक रचनापर आश्रित होती है । संक्षेपमें जब-जब समाज तरक्कीकी एक मजिलसे दूसरी मजिलपर जाता रहा है तब-तब विचार-प्रणालियोंकी दिशा प्रधानतः उस समयकी आर्थिक रचनाके द्वारा निर्धारित होती रही है ।

आजकल तो आर्थिक तत्त्वका यह प्रभाव बहुतसे पूँजीवादी विद्वान् भी बहुत अशोक्त मानने लगे हैं । पर मार्क्सके समयमें लोग सामाजिक जीवनके विकासपर उसके आर्थिक जीवनका यह प्रभाव नहीं स्वीकार करते थे । उस समयके विद्वानोका यह ध्याल था, और आजकलके भी अनेक विद्वानोका है, कि समाजका विकास केवल मनोवैज्ञानिक तत्त्वोंके आधारपर ही होता है । एक महापुरुष पैदा होता है, वह समाजके हितको दृष्टिमें रखते हुए कुछ सामाजिक सिद्धान्तोको प्रतिपादित करता है, जिसके पीछे लोग चलते हैं । समयकी एक निश्चित अवधि बीत चुकनेके उपरान्त कुछ दूसरे महापुरुष पैदा होते हैं और उनके द्वारा फिर नये सिद्धान्त सामने रखे जाते हैं और इस प्रकारके सिद्धान्तोका प्रचलन होनेसे ही सामाजिक विकास होता है । जब नये महापुरुष पैदा होकर नये प्रकारके सिद्धान्त सामने रखते हैं तो इन नये सिद्धान्तोके आधारपर समाजका सारा ढाँचा—जिसमें आर्थिक ढाँचा भी शामिल है—फिर नये सिरेसे सगठित होता है । इस प्रकारसे समाजके विकासका क्रम चालू रहता है । मार्क्सने बतलाया कि किसी विशेष परिस्थितिमें विशेष प्रकारके नये सिद्धान्तोका प्रतिपादन करनेवाले महापुरुष स्वयं बदली हुई परिस्थितियोंके परिणाम होते हैं और उनका सिद्धान्त भी समाजमें इसीलिए स्वीकार किया जाता है कि वह नयी परिस्थितियोंके अनुकूल होता है ।

एक गलतफहमी

जिस जमानेमें समाजके विकासकी विवेचना करते हुए विद्वान् लोग नये परिवर्तनोका सारा श्रेय विचारोको ही देते थे और सबसे महत्त्वपूर्ण और आधारभूत तत्त्व अर्थात् आर्थिक परिस्थितिकी उपेक्षा करते थे उस समय मार्क्स और उनके अनुयायियोंके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे आर्थिक तत्त्वके प्रभावपर अधिक जोर देते । किन्तु अज्ञानवश और बहुत

अंशोंमें समाजवादके विरोधियोंद्वारा जानबूझकर गलतफहमी पैदा करनेवाले प्रयत्नोंके कारण, कुछ लोगोमें यह भ्रम फैल गया है कि मार्क्सवादियोंके मतानुसार केवल आर्थिक तत्त्व ही सामाजिक जीवनके विविध रूपोंको यन्त्रवत् निश्चित करता है और निरंकुश सर्वशक्तिमान् सत्ताकी भाँति जिधर चाहता है उनकी नकेल पकड़कर मोड़ता है। एंगेल्सने खुद सन् १८६० में “सोशललिस्ट एकेडेमी” के सम्पादकोंको दो पत्र लिखे थे जिनमें उन्होंने इस मिथ्या धारणाका खण्डन किया है और बताया है कि समाजके विकासमें विचारोंके महत्त्वको मार्क्सने इन्कार नहीं किया है; उन्होंने सिर्फ यह बतलाया है कि प्रधान भाग आर्थिक तत्त्वका ही होता है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

इसके पूर्व कि हम उदाहरण देकर यह समझाये कि किस प्रकार उत्पादनके नये साधनोंके व्यापक रूपमें प्रचलित होने और वर्गसंघर्षके चरमसीमापर पहुँचनेसे सामाजिक क्रान्तियाँ घटित होती रही हैं यह प्रासङ्गिक जान पड़ता है कि संक्षेपमें द्वन्द्वात्मक भौतिकवादकी व्याख्या कर दी जाय। मार्क्सवादके इस दार्शनिक पहलूकी जानकारीके बिना हम सामाजिक विकासके नियमोंको उनके यथार्थरूपमें नहीं समझ सकते। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद वह दार्शनिक प्रणाली (methodology) है जो हमें उन आन्तरिक नियमोंका ज्ञान कराती है जिनके अनुसार इस भौतिक जगत्का विकास होता है, इस भौतिक जगत्के रहनेवाले प्राणियोंका विकास होता है और उनके विचारोंमें रूपान्तर होता है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दृश्य जगत्की गति (motion) के नियमोंकी व्याख्या करता है।

भौतिक अद्वैतवाद

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादके अनुसार जगत्का जो कुछ व्यापार हमें इन्द्रियगोचर होता होता है वह किसी ऐसे स्वतन्त्र निरंकुश और अलौकिक चेतन-सत्ताकी लीला या माया नहीं है जिसके सहारे या जिसकी आज्ञासे प्रकृति अपनी सृष्टि रचती है। मार्क्सवादके अनुसार, इसके विपरीत, भौतिक पदार्थ (matter) ही वह आदिम बीज सत्ता है जिसका रूपान्तर यह दृष्ट जगत् है। चेतनाका जो स्वरूप हम देखते हैं वह भौतिक पदार्थके रूपान्तरके क्रममें ही एक अवस्था-विशेषमें पैदा होता है। मार्क्सवादी दर्शन जड़ और चेतनकी पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र सत्ता—द्वैतवाद—नहीं मानता; वह बतलाता है कि आदिम अवस्थासे अवतक पदार्थका जो रूपान्तर हुआ है उसके क्रमसे ही अवस्था विशेषमें चेतनाका प्रादुर्भाव होता है, अर्थात् चेतना विकासमान पदार्थका एक गुण है। दूसरे शब्दोंमें हम मार्क्सवादी दर्शनको पदार्थवादी अद्वैतवाद कह सकते हैं।

निरन्तर परिवर्तन

आदिम पदार्थोंके (जिसके विकासका ही स्वरूप जगत् है) रूपान्तरके क्रमका विचार करनेपर पहली बात जो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद बतलाता है वह यह कि जगत्का सारा व्यापार शाश्वत परिवर्तनके क्रममें है। ससारकी हर एक वस्तुमें हर क्षण परिवर्तन

या रूपान्तर हो रहा है। अतएव यदि हम किसी वस्तुके यथार्थ रूपको समझना चाहें तो हम उसके किसी अवस्था-विशेषमे पाये जानेवाले रूपका अध्ययन करके ही यह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु-विशेषके यथार्थ रूपको समझनेके लिए हमें उसके विकासात्मक स्वभावको ध्यानमे रखकर ही उसका अध्ययन करना होगा। उदाहरणार्थ, आजके पूंजीवादी समाजको ही लें। अनेक पूंजीवादी विद्वान् वर्तमान समाजके नियमोका विश्लेषण करके यह बतलाते हैं कि पूंजीवाद क्या है। मार्क्सवादके अनुसार उनकी यह व्याख्या अधूरी ही समझी जायगी। पूंजीवादका वास्तविक स्वरूप समझनेके लिए हमें पूर्व प्रचलित सामन्तवादी व्यवस्थापर दृष्टिपात करना होगा, यह पता लगाना होगा कि पूंजीवादी सम्बन्धोका आरम्भ किन अवस्थाओमे और किस प्रकार होता है, यह देखना होगा कि पूंजीवादकी उत्पत्तिके बादसे उसके विकासमे अबतक कौनसे नियम काम करते रहे हैं और फिर यह देखना होगा कि पूंजीवादकी इस आखिरी मजिलमे पुराने नियम कहाँतक काम करते हैं और उसकी नयी विशेषताएँ क्या हैं। इसी दृष्टिसे अध्ययन करनेपर ही हम पूंजीवादी समाजके नियमोकी वैज्ञानिक व्याख्या कर सकते हैं। सक्षेपमे, मार्क्सवादी दर्शन हमें यह बतलाता है कि विश्वका व्यापार कोई बना-बनाया (ready made) खेल नहीं है, यह किसी ढाँचेके भीतर काम नहीं कर रहा है, इसका कोई स्थिर स्वरूप नहीं है,—सारा जगत् एक प्रक्रिया (Process) है और प्रतिक्षण उसमे रूपान्तर होता रहता है।

आन्तरिक विरोध या असंगति

भौतिक पदार्थका यह विकास या रूपान्तर एक सीधी रेखामे अर्थात् यन्त्रवत् (mechanically) नहीं होता। विकासकी प्रगतिमे हर क्षण आन्तरिक असंगतियाँ (inner contradictions) उत्पन्न होती रहती हैं और इन्हीं असंगतियोंके द्वारा ही नया रूपान्तर होता है। उदाहरणार्थ, अगर हम पूंजीवादसे पूर्व प्रचलित सामन्तवादको ले तो हम देखेंगे कि सामन्तवादी समाजके भीतर जो आरम्भिक नियम काम कर रहे थे उन्हींके अनुसार विकास करते-करते सामन्तवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणालीके रूपमे परिणत नहीं हो गयी। इसके विपरीत हम देखते हैं कि सामन्तवादी प्रणालीके विकासकी अवस्था-विशेषमे ऐसी असंगतियाँ उत्पन्न होती हैं जो कि प्रारम्भिक विकासके कालमे नहीं थी और ये ही असंगतियाँ बढ़ते-बढ़ते ऐसा रूप धारण कर लेती हैं जब कि सामन्तवादी प्रणालीके भीतर घोर संघर्ष पैदा होता है और पूंजीवादी समाजकी स्थापना होती है। इसी प्रकार ससारके हर एक व्यापारका प्रतिक्षण नवीन रूपान्तर होता रहता है। एक समयमे जो साम्यावस्था (equilibrium) कायम रहती है उसीके भीतरसे नयी असंगतियाँ उत्पन्न होती हैं जिनके गर्भमे प्रस्तुत साम्यावस्थाके विनाशके बीज मौजूद रहते हैं। इन असङ्गतियोंके अंकुरके बढ़ते-बढ़ते एक अवस्था ऐसी आती है जब प्रचलित साम्यावस्था नष्ट हो जाती है और एक नयी साम्यावस्था पैदा होती है। इस नयी साम्यावस्थाके भीतरसे फिर नयी असङ्गतियाँ उत्पन्न होती हैं और

वे बढ़कर इस नयी साम्यावस्थाका नाश करती है और उसके स्थानपर दूसरी नयी साम्यावस्थाकी स्थापना करती है । इस प्रकार एक साम्यावस्थाके स्थानपर, उसकी असंगतिका सृजन करनेवाली प्रकृतिके कारण हमेशा दूसरी नयी साम्यावस्था कायम होती रहती है और प्रगति अपने पथपर इसी प्रकार अग्रसर होती रहती है ।

गुणात्मक परिवर्तन

ऊपर हमने बताया कि अवस्था-विशेषके भीतर जो असंगतियाँ उत्पन्न होती हैं वे बढ़ते-बढ़ते ऐसा रूप धारण कर लेती हैं कि पुराने समाजका मूलतः नाश हो जाता है और नये समाजकी उत्पत्ति होती है । इस सम्बन्धमें हमें यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये कि किसी वस्तुकी मात्रामें लगातार वृद्धि होनेपर ऐसी अवस्था आती है जब उसमें गुणका भेद (qualitative change) उत्पन्न हो जाता है । उदाहरणार्थ, सामन्तवादी समाजकी ही पुरानी अवस्थाको ले तो हम देखेंगे कि उसमें जो असंगतियाँ उत्पन्न हो रही थी उनके गुणात्मक रूपसे बढ़ जानेपर ही एक समय ऐसा आया जब कि उसके स्थानपर पूँजीवादी प्रणाली स्थापित हो सकी । सामन्तवादी समाजमें कुछ व्यक्तियोंके पास रुपये इकट्ठे हो रहे थे, किन्तु उन रुपयेको पूँजी बनाने का सौभाग्य तभी प्राप्त हो सका जब कि वह वातावरण तैयार हो गया जिसमें इन रुपयेकी बढ़ती बढ़ती पैमानेपर मजदूरोकी श्रमशक्ति खरीदकर और उससे बनी हुई चीजें बेचकर बढ़नेमें अतिरिक्त मूल्य (surplus value) उत्पन्न करना सम्भव हुआ ।

परिवर्तनके सख्यात्मकके स्थानपर गुणात्मक रूप धारण करनेका एक बहुत सरल उदाहरण हमें पानीका मिलता है । जब पानीको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि पानीके भीतर गर्मीकी मात्रा बढ़ती रहती है फिर भी अवस्था-विशेषतक उसमें उबाल नहीं आता । किन्तु गर्मीकी काफी मात्रा इकट्ठी हो जानेपर पानीके भीतर गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है; पानीका उबलना और भापका बनना शुरू हो जाता है । सामाजिक विकासके क्षेत्रमें देखनेपर पता चलता है कि उसमें भी एक व्यवस्थाके भीतर जो असंगतियाँ उत्पन्न होती रही हैं वे बढ़ते-बढ़ते एक ऐसी अवस्थामें पहुँच जाती हैं जब कि गुणात्मक परिवर्तन होता है । गुणात्मक परिवर्तनकी इस मञ्जिलमें पुराने समाजका रूपान्तर क्रमिक सुधार (reformism) के जरिये न होकर आकस्मिक वेगसे अर्थात् क्रान्ति (revolution) के द्वारा होता है । जिस प्रकार बच्चा माँके गर्भमें बढ़ता है, किन्तु लगभग नौ मासके उपरान्त एक दिन वह अचानक माताको कड़ी प्रसववेदना देते हुए बाहर निकल पड़ता है उसी प्रकार पुराने समाजके भीतर नये समाजकी अवस्थाएँ जब परिपक्व हो जाती हैं तो अचानक क्रान्तिके द्वारा नये समाजका जन्म होता है । क्रान्ति नये समाजकी प्रसववेदना है । एक समाजसे नये उन्नत समाजकी ओर जानेके लिए क्रान्ति एक अनिवार्य सीढ़ी है । मार्क्सवादका क्रान्तिकारी दर्शन हमें यही सिखलाता है ।

समाजवादका मूलाधार—मानवता

भौतिकवादके सिद्धान्तको माननेके कारण समाजवादके विरुद्ध प्रायः यह आक्षेप किया जाता है कि समाजवाद केवल सकुचित आर्थिक दृष्टिकोणसे ही सब प्रश्नोपर विचार करता है और इसलिए वह कोई ऐसे आदर्श समाजके सम्मुख उपस्थित नहीं करता जिनकी पूर्तिके लिए मनुष्यको आत्मत्याग करना पड़े। अज्ञानवश लोग समाजवादपर यह लाञ्छन लगाते हैं, किन्तु इस इल्जाममें सत्यका लवलेश भी नहीं है। प्रमुख समाजवादियोंकी जीवनी ही इस इल्जामको झुठलाती है। वैज्ञानिक समाजवादके जन्मदाता मार्क्सका जीवनचरित्र जिन्होंने पढ़ा है वे इसे अच्छी तरह जानते हैं कि किस कष्टसे उसने अपनी जिन्दगी वसर की थी और आर्थिक कष्ट होते हुए भी उसने एक क्षणके लिए मानवसमाजकी सेवाके लक्ष्यको नहीं छोड़ा। उसकी जिन्दगीमें ऐसे मौके अक्सर आये जब घरमें खानेतक-को न था, घरसे बाहर निकलनेके लिए कपड़ेतक न थे और कर्जके बोझसे वह पिसा जा रहा था। लेकिन वह सदा निश्चल भावसे अपनी साधनामें लगा रहा और सख्तसे सख्त मुसीबतमें भी सिद्धान्तोपर अटल रहा। लोग कह सकते हैं कि अपनी खपतको पूरा करनेके लिए कार्ल मार्क्सने ये सब कष्ट सहें होंगे पर जिन सिद्धान्तोंका उसने निरूपण किया है उनमें उच्च आदर्शोंके लिए जगह नहीं है। आमतौरसे यह समझा जाता है कि समाजवाद महज रोटीके सवालको हल करनेकी कोशिश करता है और चूँकि वह इतिहासको वर्गसंघर्षकी प्रक्रियामात्र मानता है इसलिए उससे किसी ऊँचे आदर्शकी आशा करना व्यर्थ है।

भ्रमपूर्ण धारणा

हम प्रमुख समाजवादियोंकी उक्तियोंसे ही नहीं, वरन् समाजवादके मौलिक सिद्धान्तोंके आधारपर यह दिखलानेका प्रयत्न करेंगे कि लोगोंकी यह धारणा बिल्कुल गलत है। एक बार मार्क्सने स्वयं कहा था कि उसकी खाल इतनी मोटी नहीं है कि वह मानव समाजके कष्टोंकी ओर अपनी पीठ फेर दे। हट्टेनने मार्क्सके बारेमें बिल्कुल ठीक कहा है कि उसका हृदय इतना विशाल और कोमल था कि औरोंकी अपेक्षा मानवसमाजके साधारणसे साधारण दुःख भी उसको ज्यादा प्रभावित करते थे। जिस प्रकार भूकम्पमापक यन्त्र पृथ्वीके सूक्ष्मसे सूक्ष्म कम्पनका भी हिसाब रखता है उसी तरह मार्क्स मनुष्यके साधारणसे साधारण कष्टका हिसाब रखता था। समाजके इस अन्यायको वह वर्दास्त नहीं कर सकता था कि एक वर्गके लोग सम्पन्न और सुसंस्कृत हो और दूसरे गुलामोंकी तरह रातदिन मेहनत करनेपर भी जिन्दगीकी साधारण आवश्यकताओंसे वंचित रखे जायें। जो श्रम करते हैं और समाजकी दौलतको पैदा करते हैं, जो पृथ्वीके गर्भसे सोना, चाँदी आदि धातु, कोयला और तेल निकालते हैं, जो कारखानेमें तरह-तरहका तिजारती माल तैयार करते हैं, जो रेल और जहाजद्वारा दुनियाके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक माल पहुँचाते हैं, जो बड़े-बड़े महल खड़े करते हैं और इस पृथ्वीको सजाते हैं, वे स्वयं जानवरोकी जिन्दगी गुजारते हैं, गन्दे और तंग मकानोंमें रहते हैं, जहाँ हवाकी गुजर नहीं, मैले-कुचैले कपड़े

पहनते हैं और शिक्षासे वंचित रखे जाते हैं। समाजका वह अनाचार जो करोड़ों मानव-संतानको मानवतासे वंचित कर उन्हें जानवरकी-सी जिन्दगी बसर करनेके लिए मजदूर करता है, मार्क्सको चोट पहुँचाता था। मार्क्सने एक स्थलपर कहा है कि सर्वहारा मजदूरको रोजमर्राके भोजनकी अपेक्षा शौर्य, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और स्वातन्त्र्यकी कहीं ज्यादा जरूरत है। रोजा लज्जेस्वर्गने फ्रेञ्ज मेहरिङ्गको एक पत्रमें लिखा था कि समाजवाद रोटीका सवाल नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक आन्दोलन है जो संसारमें एक महती विचारधाराको प्रवाहित करता है। इस सांस्कृतिक आन्दोलनका केन्द्र मानव है। मानव सर्वोपरि है। जो सिद्धान्त, वाद या विचार—चाहे वह कोई धर्म हो या दर्शन या अर्थशास्त्र—मानवके उत्कर्षको घटाता है वह मार्क्सको मान्य नहीं है।

धर्मकी अपूर्णता

मार्क्स मानवकी आत्मचेतनाको सबसे बड़ा देवता मानता है। फायरबाख्रके समान मार्क्सका कहना था कि मनुष्य धर्मको बनाता है, न कि धर्म मनुष्यको और मानवैतर परम-पुरुषकी कल्पना मनुष्यके ख्याल और वहमका नतीजा है। उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है, यह केवल मनुष्यका विकृत और ख्याली प्रतिरूप मात्र है। जितना ही अधिक मनुष्य ईश्वरको गुणोसे विभूषित करता है उतना ही अधिक वह अपनेको खण्डित और विकलित बनाता है। मानवकी परिपूर्णतामें धर्म बाधक है। परलोककी सुन्दर कल्पनाका धर्म अपनी आजकी जिम्मेदारियोंसे बरी हो जाता है। धर्म आज रुदियों और स्थिर स्वार्थोंका समर्थक है। उसके अनुसार वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ईश्वरकृत है और इसलिए वह सदाके लिए अपरिवर्तनशील है। धर्म वर्तमानको रक्षित रखना चाहता है और जिस समाजमें वर्ग-संघर्ष नित्य बढ़ता चला जाता है उस समाजको वह अपने प्रचलित रूपमें अधुण्ण रखना चाहता है। आजकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थामें मनुष्य अपनी पूर्ण ऊँचाईको नहीं पहुँच सकता, अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, लेकिन धर्म इसी व्यवस्थाका पोषक और समर्थक है। धर्म परमेश्वरकी कल्पना कर मनुष्यको दुर्बल बना देता है, उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होने देता और उसकी स्वतन्त्रताका अपहरण करता है, जीवनकी ठोस हकीकतसे उसको अलग कर ख्याल और वहमकी काल्पनिक दुनियामें उसको नचाता है और उसकी आत्मचेतनाको पूर्णरूपसे विकसित नहीं होने देता। धर्मके बोझके तले मानव दबा पड़ा है, समाजवाद धर्मकी सच्ची मीमांसा कर धर्मकी कैदसे मनुष्यको नजात दिलाता है और इस तरह मानवताके गौरवको बढ़ाता है।

पूँजीवादी प्रथाका दोष

जिस तरह धर्म मानवताको विकृत और खण्डित करता है उसी तरह उत्पादनकी पूँजीवादी प्रक्रिया मानव-श्रमके गौरवको नष्ट कर देती है। इस प्रक्रियामें मजदूर उत्पादनके साधनोसे पृथक् कर दिया जाता है। मजदूरका श्रम भी और तितारती मालकी तरह बाजार-भावपर बाजारमें विकता है। मजदूर मेहनत मशक्कत कर जो वस्तु तैयार करता है उसपर उसका प्रभुत्व नहीं होता। मजदूर उत्पन्न वस्तुको अपनेसे अलग समझता है।

यह श्रम उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, इसलिए उसको उसमें रस नहीं आता। वह श्रम कर प्रसन्न नहीं होता और न उससे उसकी शारीरिक और बौद्धिक शक्तिका स्वच्छन्द विकास ही होता है। इससे उसका स्वास्थ्य अवश्य विगड़ता है और उसकी आत्माका हनन होता है। इसलिए श्रमिक अपने व्यक्तित्वको अपने श्रमसे बाहर ही अनुभव करता है। ऐसा श्रम मनुष्यको प्रकृति और अपने व्यक्तित्वसे अलग कर देता है। जितना ही अधिक वह श्रम करता है उतनी ही शक्तिशाली वह दुनिया बनती जाती है जिसका कि वह निर्माण करता है और उतना ही दरिद्र और अकिञ्चन वह स्वयं और उसका आन्तरिक संसार होता जाता है। ऐसे ही श्रमसे व्यक्तिगत सम्पत्तिकी उत्पत्ति होती है और उत्पादन-पर उन लोगोका ही प्रभुत्व होता है जो स्वयं कुछ पैदा नहीं करते। पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाकी यह एक मौलिक घटना है। इसीलिए एंगेल्सने कहा है कि इन्सानकी हैसियतसे चेतनापूर्वक उत्पादनकी प्रक्रियामें लगे, न कि वतौर क्षुद्र व्यक्तियोंके जिनमें सामाजिक चेतना नहीं है और इसी तरह तुम तमाम कृत्रिम असंगतियों और विरोधोका अन्त कर सकोगे। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि मानव-समाजका उद्धार सामाजिक शक्तियोंके ऐसे नवीन सगठनद्वारा ही हो सकता है जो मनुष्यको उन साधनोका मालिक बनावे जो उनको जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए समाजवाद व्यक्तिगत सम्पत्तिका निश्चित लोप चाहता है, क्योंकि यह मनुष्यको अपने श्रमसे अलग करती है। व्यक्तिगत सम्पत्तिके लोपसे ही मानव-समाज मानवताके गुणोसे संयुक्त किया जा सकता है। इसी तरह पूर्ण चेतनाके साथ मानव सच्चे मनुष्यत्वको पुनः प्राप्त कर सकता है। मानवके स्वास्थ्यलाभके लिए समाजवादकी आवश्यकता है।

अर्थशास्त्रियोंका विकृत दृष्टिकोण

हमारे अधिकांश अर्थशास्त्री पूँजीवादका समर्थन करते हैं। उनमें इतिहासके ज्ञानकी कमी है। वे कोरे अर्थशास्त्री हैं। वे यह नहीं देखते कि मनुष्य उत्पादनकी शक्तियोंकी वृद्धि करता हुआ आपसमें एक निश्चित सम्बन्ध स्थापित करता है और इस सम्बन्धका रूप और प्रकार निश्चित रूपसे बदलता है, जब उत्पादनकी शक्तियाँ बदलती हैं और उनकी वृद्धि होती है। आजकी उत्पादन-प्रणालीसे जो सामाजिक सम्बन्ध हैं वे तभी तक कायम हैं जबतक वर्तमान प्रणाली कायम है। अर्थशास्त्रके जो नियम उन्होंने निश्चित किये हैं वे अटल और शाश्वत नहीं हैं। वे केवल वर्तमान प्रणालीको ही लागू होते हैं, एक विशेष ऐतिहासिक विकासकी अवस्थामें ही उन नियमोंकी सत्यता है। अर्थशास्त्रके ये नियम ऐसे ऐतिहासिक सामाजिक सम्बन्धोंके द्योतक हैं जो अस्थायी हैं। इन सम्बन्धोंके बदलते ही नियम भी बदल जावेंगे। इसलिए इन नियमोंको अटल बनाना मूर्खता है। यदि ये नियम अटल होते तो सामाजिक और आर्थिक विकासकी सम्भावना ही न रह जाती।

आज समाजमें बेतरतीबी और अस्तव्यस्तता है। मनुष्य, मनुष्यके खिलाफ सघर्ष करता है और सब व्यक्ति, जो एक दूसरेसे अपने व्यक्तित्वके कारण ही अलग किये गये हैं सबके विरुद्ध सघर्ष करते हैं। सामन्तशाही जमानेके नियन्त्रणों और बन्धनोंसे मुक्त होकर

प्राथमिक शक्तियाँ श्रवाध गतिमें परिचालित होती हैं और यद्यपि जातिर द्वेषमें व्यक्ति स्वतन्त्र मालूम होता है, तथापि वास्तवमें वह गुनाम है। जो अवयव उसमें पृथक् कर दिये गये हैं, जैसे सम्पत्ति, श्रम और धर्म उनकी श्रवाध गतिको वह भूलभंग अपनी स्वतन्त्रता समझता है, किन्तु असन्वित यह है कि कि यही श्रवाध गति उनकी गुनामी और मानवतामें उसके अलग किये जानेको जाहिर करती है।

पूँजीवादी राज्य

पूँजीवादी राज्यमें मनुष्यको जो राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है उसका अर्थ केवल इतना ही है कि वह पूँजीवादी समाजका सदस्य और राज्यका नागरिक बन जाता है। वर्तमान राज्य (State) मनुष्यके साधारण अधिकारोंको स्वीकार करता है। राज्य राजनीतिक दृष्टिसे व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वीकार नहीं करता और उन्निष्ठ बंटका अधिकार प्रदान करनेमें वह जायदादका लिहाज नहीं करता। राज्यने जन्म, निष्ठा और व्यवसायके फर्कोंको भी राजनीतिक दृष्टिमें मिटा दिया जब उसने अपने विधानमें सबको समान रूपसे राजनीतिक अधिकार प्रदान किया। धर्मका अस्तित्व भी किसी प्रकार राज्यके पूर्ण विकासमें बाधक नहीं माना गया। किन्तु पूर्ण रूपमें विकसित राज्य प्रधानतः सामाजिक जीवनका ही प्रतिनिधित्व करता है, न कि मानवके भौतिक जीवनका। राज्य जब मनुष्यके साधारण अधिकारोंको स्वीकृत करता है तब उसका अर्थ केवल इतना ही होता है कि वह पूँजीवादी समाजके व्यक्तिके अस्तित्वको और साथ ही साथ मानव-जीवनके बौद्धिक और भौतिक अवयवोंकी श्रवाध गतिको स्वीकार करता है। इन प्रकार राज्य मनुष्यको धर्मके बन्धनोंसे नहीं मुक्त करता, वह केवल उसको धार्मिक स्वतन्त्रता अर्थात् किसी धर्मविरोधको अपने लिए चुन लेनेका अधिकार ही प्रदान करता है। इसी तरह राज्य केवल वोटका हक देनेमें सम्पत्ति, जन्म और व्यवसायके कृत्रिम भेदोंका लिहाज नहीं करता। किन्तु इस विधानसे व्यक्तिगत सम्पत्ति का लोप नहीं हो जाता। राजनीतिक स्वतन्त्रता मानवको स्वतन्त्र नहीं करती। मानव तो तभी स्वतन्त्र होगा जब उसका जीवन खण्डित न हो, जब उसके जीवनके बौद्धिक और भौतिक अवयव उससे पृथक् न कर लिये जायें; जब कि वह एक सामाजिक जीव होकर अपनी जिन्दगी बसर करे और अपना काम-काज देखे और जब मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्तियोंको सामाजिक शक्तियोंकी तरह संगठित कर सामाजिक शक्तिको राजनीतिक शक्तिके रूपमें अपनेसे अलहदा न करे। विविध खण्डशास्त्र जो मनुष्यके अवयवोंको उससे पृथक् कर उनका अध्ययन करते हैं, मानवताके आलोकमें क्षीण और सारहीन नजर आते हैं।

यथार्थवादी मार्ग

मानवताका सबसे बड़ा पुजारी होते हुए भी मार्क्स ब्याली घोंटे नहीं दीड़ता, वह काल्पनिक जगत्में स्वच्छन्द विचरण करना पसन्द नहीं करता। वह इस दुनियाकी ठोस हकीकतको ही अपने अनुसन्धानका आधार बनाता है। उसने किसी सुन्दर सत्ताकी कल्पना नहीं की है। वह पुरानी दुनियाको अँधेरेमें लाकर उसकी परीक्षा और आलोचना

करना चाहता है और इस तरह ऐतिहासिक विकासके सिद्धान्तोका निरूपण कर वह दुनियाकी तलाश करता है। अबतकके जो दर्शन हैं वह जीवनकी पहलीका हल पका-पकाया तैयार रखते हैं, किन्तु मार्क्स सदाके लिए सब अवस्थाओका पहलेसे ही नहीं उत्तर दे देता। वर्तमान जगत्की आलोचना करना वह अपना काम समझता है और निहायत वेददीके साथ वह इस कार्यको सम्पन्न करता है। वह नतीजोसे घबराता नहीं और अधिकारियोके साथ टक्कर लेनेसे भी नहीं डरता। उसकी शिक्षा है कि ऐतिहासिक विकासके क्रमको समझनेकी कुजी समाजमें है। मनुष्य सामाजिक है। संसारसे बाहर उसका अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थाका आधार उत्पादनकी क्रिया और वस्तु-विनिमय होता है। क्या उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है और उत्पन्न वस्तुओका विनिमय किस प्रकार होता है ये बातें निश्चित करती हैं कि उत्पन्न वस्तुओका वितरण कैसे होगा और समाजमें वर्ग-विभाजन किस प्रकार होगा। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक क्रान्तियोंके अन्तिम कारणोकी तलाश मनुष्योके मस्तिष्कमें न होनी चाहिये, अपितु उत्पादनके प्रकार और विनिमयके परिवर्तनोमें। इन कारणोका पता युगके दर्शनमें नहीं किन्तु समयके आर्थिक सगठनमें मिलेगा। यह ज्ञान बढ़ता जाता है कि वर्तमान सामाजिक संस्थाएँ बुद्धिसगत और न्याययुक्त नहीं हैं और यह इस बातका चिह्न है कि उत्पादनके तरीकोमें और विनिमयके प्रश्नोमें खामोशीके साथ ऐसे परिवर्तन होते रहे हैं जो सामाजिक व्यवस्थाके अब अनुकूल नहीं पड़ते। इससे यह भी स्पष्ट है कि जो उपाय उन बुराइयोको दूर कर सकते हैं जिनका पता चला है उनको भी किसी-न-किसी रूपमें उत्पादनकी बदली हुई अवस्थामें मौजूद रहना चाहिये। इन उपायोका बुद्धिबलसे ईजाद नहीं करना है किन्तु मौजूदा उत्पादनकी अवस्थामेंसे तलाश करके निकालना है।

वर्तमान सामाजिक प्रणाली पूंजीवादी है। ज्यो-ज्यो इसका विकास होता जाता है त्यों-त्यों उत्पादनकी शक्तियो और उत्पादनके प्रकारका संघर्ष बढ़ता जाता है। यह संघर्ष किसीकी इच्छाके अधीन नहीं है। यह उन लोगोकी भी इच्छाके परे है जो इस संघर्षको पैदा करते हुए मालूम होते हैं। वर्तमान प्रणालीकी बुराइयोको दूर करनेका साधन सर्वहारा मजदूर है। पूंजीवादी उत्पादन जहाँ मुट्ठीभर पूंजीपतियोमें सम्पत्तिको केन्द्रित करता है वहाँ वह अकिञ्चन मजदूरको भी पैदा करता है। मजदूरवर्गके पूंजीवादी समाजका एक वर्ग है जो सार्वभौमिक चरित्रवाला है क्योंकि इसकी तकलीफें सार्वभौमिक हैं। यह किसी विशेष अधिकारकी माँग नहीं करता, क्योंकि कोई खास अन्याय उसके साथ नहीं किया गया है क्योंकि वह स्वयं सरापा अन्याय है। यह वर्ग किसी इतिहास-सिद्ध अधिकारके नामपर अपील नहीं कर सकता, किन्तु मानवताके नामपर ही इसकी अपील होती है, यह वर्ग बिना अन्य वर्गोंके नजात दिलाये नजात नहीं पा सकता। यह वह वर्ग है जिसमें मानवताका सर्वथा लोप हो गया है और यह मानवताको पूरी तरह प्राप्त करके ही अपनेको पा सकता है। सर्वहारा मजदूरमें आत्मचेतनाकी कमी है। जब उसको उस प्रणालीका ज्ञान होगा जो उसको सदा सच्चे मानवकी पदवी प्रदान कर सकती है तब उसका निस्तार होगा। समाजवादका सिद्धान्त तभी एक शक्तिके रूपमें परिणत

हो सकता है जब जनता उससे प्रभावित हो और उसे अपनावे । जो सिद्धान्त जनताकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करता है वही कार्यमें परिणत होता है । सर्वहारा मजदूरका लोप किये बिना मार्क्सवादी-दर्शनका सिद्धान्त कार्यरूपमें परिणत नहीं होता और मजदूर सिद्धान्तको कार्यरूपमें परिणत किये बिना अपना निस्तार नहीं कर सकता ।

मजदूरवर्गका महत्त्व

पूँजीवादी समाजमें मजदूर इस ऐतिहासिक कार्यको सम्पन्न करता है । समाजवादी क्रान्तिका वही अग्रणी है । किसी मजदूर या मजदूरवर्गका तात्कालिक उद्देश्य क्या है इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । सामयिक पूँजीवादी समाजके सगठनमें उसका जो स्थान है वह उसको इस इतिहास-निर्दिष्ट कार्यके करनेके लिए कभी-न-कभी विवश करेगा । जब मजदूरवर्ग अपने कष्टको केवल कष्टके रूपमें नहीं देखता है, बल्कि उसका क्रान्तिकारी पहलू भी पहचानने लगता है उसी क्षणसे इतिहासको प्रगति मिलती है और मजदूरवर्ग चेतना-पूर्वक क्रान्तिके कार्यमें लग जाता है । क्रान्ति इतिहासके विकासके क्रमको बदल नहीं देती, किन्तु उसकी गतिको तीव्र कर देती है । मार्क्सके शब्दोंमें क्रान्ति इतिहासकी रेलगाड़ी (locomotive of history) है । वह केवल इतिहासकी रफ्तारको तेज कर देती है ।

जो लोग किसी सामाजिक व्यवस्थाकी खूबियोंको सुरक्षित रखकर महज उनकी बुराइयोंको दूर करना चाहते हैं वह भूल करते हैं । यह बुरा पहलू ही सघर्षको जन्म देकर इतिहासका निर्माण करता है । जो पूँजीवादी पद्धति दौलत पैदा करती है वही गरीबी और बेकारीको भी जन्म देती है । जिस मात्रामे पूँजीपतिकी वृद्धि होती है उसी मात्रामे परिणामस्वरूप मजदूरवर्गकी भी वृद्धि होती है ।

इसलिए अच्छे पहलूको कायम रखकर बुरे पहलूको दूर करनेकी चेष्टा निरर्थक है । इस प्रकार हम एक ऊँचे दर्जेकी सामाजिक व्यवस्थाको जन्म नहीं दे सकते । इस तरह तो सामन्तशाहीका नाश और पूँजीवादी पद्धतिका जन्म कदापि न हुआ होता । यह तो इतिहासको निस्तार बनानेका ढग है ।

मार्क्सने जनताको खोयी हुई मानवताको फिरसे पानेका उपाय ही नहीं बताया, किन्तु उसको इस कार्यके लिए तैयार भी किया । पुराने दार्शनिकोंने जहाँ वस्तुस्थितिके बनानेकी चेष्टा की थी वहाँ मार्क्सका दर्शन समाजकी रूपरेखाको बदलनेका शास्त्र है । मानवताके लिए मार्क्स सदा लड़ता रहा और इसके लिए उसने अनेक कष्ट भी सहे । जो जनताको मानवतासे वंचित रखते हैं उनके प्रति मार्क्सका क्रोध सात्विक क्रोध है । मेहर्गिने मार्क्सको दूसरा प्रोमेथियस बताया है । प्रोमेथियस पश्चिमी दर्शनकी जन्त्रीका सर्वोत्कृष्ट और सन्त शहीद हो गया है । प्रोमेथियस न इन्द्रके वज्रसे डरता था, न उसे धमकियोंकी परवाह थी । वह ताम्रमय देवताओंको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखता था । मुसीबत वर्दाश्त कर लेना उसे मंजूर था, लेकिन किसी हालतमें वह देवताओंकी गुलामी नहीं कर सकता था । कार्ल मार्क्सने मानवताको पुनः प्रतिष्ठित करनेके प्रयत्नोंको नहीं छोड़ा । उसने

कभी पूंजीपतियोंकी नाराजगी या धमकियोंकी परवाह नहीं की। लाख मुसीबतोंके झेलनेपर भी वह कभी अपने पथसे विचलित नहीं हुआ। उसका दर्शन एक जीता-जागता दर्शन है जिससे मनुष्यको एक नवीन स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है। जो आज समाजमें पददलित, तिरस्कृत, अशिक्षित और दरिद्र है उनमें नये जीवनका संचार करना, उनके तमाविष्ट हृदयोंमें एक नवीन ज्योतिको जगाना मार्क्सके दर्शनका ही काम है। यही दर्शन करोड़ों लोगोंको मुक्ति-पथका निर्देश करता है। इसी मार्गके पथिक होकर लोग एक नूतन समाजकी सृष्टि करेंगे जहाँ मानव मानव होकर रहेगा और ससारकी कोई भी शक्ति फिर उसकी मानवताका अपहरण न कर सकेगी।

वर्ग-संघर्षकी अनिवार्यता

पहले यह बताया जा चुका है कि समाजमें विकास उसकी आन्तरिक असङ्गतियोंके जरिये होता है। यह असङ्गतियाँ जब अपनी चरम सीमापर पहुँच जाती हैं तो सामाजिक क्रान्ति घटित होती है। समाजको तरक्कीकी एक मंजिलसे दूसरी मंजिलपर ले जानेवाली कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि यही सामाजिक क्रान्ति होती है। यह भी कहा जा चुका है कि हमारे अवतकके सामाजिक ढाँचेमें, जो कि शोषक और शोषित वर्गोंके आधारपर संघटित रहा है, यह क्रान्ति वर्गसंघर्षकी चरम सीमापर पहुँचनेपर ही घटित होती रही है। आगे हम इतिहासके कुछ उदाहरणोंद्वारा अपने इस कथनकी पुष्टि करनेका यत्न करेंगे।

दासोंका विद्रोह

वर्ग-संघर्षका इस प्रकारका पहला उदाहरण हमें पुराने जमानेके गुलामों और उनके मालिकोंके बीचमें मिलता है। आजकलके मजदूरी पानेवाले गुलाम यानी मजदूर श्रेणीके लोग जिस तरह अपनेको भलीभाँति सुसंगठित करके लड़ते हैं, पुराने जमानेके गुलामोंकी लड़ाई ठीक इसी तरहकी नहीं पायी जाती क्योंकि आजकलके मजदूरकी तरह वे लोग बड़े-बड़े कारखानोंमें बड़ी तादादमें काम न करके अलग-अलग व्यक्तिगत रूपसे अपने-अपने मालिकोंके यहाँ काम करते थे। ऐसी हालतमें उनपर जो अत्याचार होता था वह उन्हें तत्कालीन आर्थिक रचनाका अवश्यम्भावी परिणाम मालूम नहीं होता था। कितने ही मालिक अपने गुलामोंके साथ दयालुताका व्यवहार भी करते थे; अतः स्वभावतः गुलाम लोग इस भ्रमके शिकार हो जाते थे कि उनपर होनेवाला अत्याचार स्वामीविशेषके निर्दय स्वभावका ही परिणाम है किन्तु गुलामोंमें चेतनाका संचार होनेके मार्गमें इस कठिनाईके होते हुए भी वर्ग-संघर्ष बढ़ता ही गया और समाजमें भयंकर विद्रोह हुए। दास-क्रान्तिका प्रमुख उदाहरण प्राचीनकालके रोममें देखनेको मिलता है। दासताकी प्रथा प्राचीनकालके भारतवर्षमें भी पायी जाती थी और यह प्रथा पूरी तरहसे अंग्रेजी राज्यके आनेके बाद समाप्त हुई है।

कृषकोंका विद्रोह

दास-प्रथाकी समाप्तिके बाद हम सामन्तवादी युगमें आते हैं। इस जमानेमें भूमिके स्वामी सामन्तो और उनके लिए दासका काम करनेवाले कृषक दासोंके बीच वर्ग-संघर्ष चलता है। आरम्भमें किसानोंका क्रोध छिटफुट उत्पातोंके रूपमें ही प्रदर्शित होता है। वे व्यापक पैमानेपर किसी विप्लवका संगठन नहीं कर पाते। पुराने जमानेके गुलामोंकी तरह इन किसानोंके मालिक भी अलग-अलग होते हैं और किसानोंको अलग-अलग खेतोंपर काम करना पड़ता है। दूसरे, जिस जमानेकी हम बात कर रहे हैं उस जमानेमें आवागमनके साधनोंका विकास भी आजकी तरह नहीं हो पाया था। अतएव आरम्भमें किसानोंके विद्रोहोंका अलग-अलग स्थानोंमें छोटे पैमानेपर छिटफुट रूपसे होना स्वाभाविक है। किन्तु आगे चलकर बार-बार अकाल पड़नेसे और किसानोंकी आवादी बढ़नेसे जब किसानोंका कष्ट परकाष्ठापर पहुँच जाता था और जमीनका पाना उनके लिए जीने मरनेका सवाल बन जाता था तब यह वर्ग-संघर्ष व्यापक और उग्ररूप धारण करता था। किसान-वर्ग यह अनुभव करने लग जाता था कि सामन्तवादीवर्गसे छीनकर और सामन्तशाहीके स्थानपर किसानोंका राज्य कायम करके ही उनकी समस्या हल हो सकती है। किसानोंके व्यापक विद्रोहोंके कुछ मुख्य उदाहरण जर्मनीका 'कृषक युद्ध' (Peasant War of Germany) रूसका 'पूकोगाफ विद्रोह' और चीनका 'ताइपिंग विद्रोह' (Taiping rebellion) है।

किसानोंकी विचारधारा

किन्तु, जैसा कि ऊपर कहे विद्रोहोंके इतिहाससे पता चलता है, किसान लोग प्रचलित व्यवस्थाका विध्वंस अवश्य कर सकते हैं, वे नयी व्यवस्थाका निर्माण नहीं कर सकते। किसान आन्दोलनके प्रेरक आदर्श किसानोंको आगे देखनेकी अपेक्षा पिछले जमानेकी ओर देखनेको बाध्य करते हैं। किसानवर्ग सामन्तवर्गके हाथसे जमीन तो जरूर छीननेको तैयार हो जाता है, किन्तु जब विप्लवके बाद समाजके पुनर्र्गठनका सवाल आता है तो वह पुराने जमानेकी व्यवस्थाको ही फिरसे चालू करनेकी कोशिश करता है। पुराने जमानेमें गाँवोंका प्रबन्ध पंचायतोंके जरिये होता था। खेतीका प्रबन्ध भी पंचायतें करती थी। गाँवोंकी जमीनपर व्यक्तियोंका अलग-अलग स्वामित्व न होकर पंचायतका ही स्वामित्व समझा जाता था। इन पंचायतोंको सुविधानुसार जमीनका किसानोंमें फिरसे बँटवारा करनेका अधिकार था। फ्रांसमें इस प्रकारकी पंचायतोंको कम्यून और रूसमें उन्हें मोर कहते थे। हिन्दुस्तानमें भी खेतीकी यह पंचायती प्रथा पायी जाती थी। जिन स्थानोंमें इस पंचायती प्रथाकी परम्परा किसानोंके दिमागमें ताजी रही है वहाँके किसान विद्रोहके बाद फिरसे इसी पंचायती प्रथाको लाना चाहते रहे हैं।

किसानोंका उद्देश्य राजतन्त्रका विनाश भी नहीं था। इसके विपरीत धार्मिक विचारोंमें रेंगे होनेके कारण वे राजाको ईश्वरका अवतार समझते थे और उनका विद्रोह भी प्रायः ऐसे ही व्यक्तियोंके नेतृत्वमें चलता था जो कि किसानोंमें यह धोपणा करते थे कि ईश्वरने उनके मनमें नये वननेकी प्रेरणा की है। पूकोगाफ और ताइपिंग विद्रोहके

नेता इसी प्रकारके थे । आरम्भमें किसानोको इसका विश्वास ही न होता था कि राजा सामन्तवर्गके शोषणका समर्थक है । किसानोका विश्वास यह था कि उनपर जो अत्याचार होता है, उनकी माँगे जो स्वीकार नहीं की जाती वह भ्रष्ट राज्य-कर्मचारियों या बुरे स्वभाववाले स्थानीय सामन्तोके कारण ही । राजाको तो वे पृथ्वीपर सर्वन्यायकारी परमपिता परमात्माका साक्षात् अवतार मानते थे । किन्तु राजासे बार-बार फरियाद करनेपर भी जब उल्टे उनका दमन ही होता था, उनके प्रतिनिधि जेलोमे डाल दिये जाते या मौतके घाट उतार दिये जाते थे तब कही जाकर उनकी आखे खुलती थी । किन्तु फिर भी वे यह नहीं अनुभव करते थे कि उनको राजप्रथाका ही विनाश करना है, बल्कि अपने नेताको ही वे राजा स्वीकार कर लेते थे ।

किसानोके विद्रोह दूसरे देशोकी तरह हिन्दुस्तानमे भी होते रहे हैं, किन्तु उनके शृङ्खलाबद्ध इतिहासके ठीक-ठीक न मिल सकनेका कारण यह है कि हमारे यहाँ ऐतिहासिक घटनाओका नियमित रूपसे वृत्तान्त रखनेकी प्रथा नहीं रही है । इसके अतिरिक्त बहुतसी बातें सरकारी कागजातके भीतर ही छिपी हैं जिनकी ठीक-ठीक छानबीन अंग्रेजी हुकूमतके हटनेके बाद ही की जा सकती है । विभिन्न प्रान्तोके जिलेके गजेटियरो (District gazetteers) की छानबीन करनेपर किसानोके अनेक विद्रोहोका पता चलता है, विशेषकर गुजरात और विहार के भील, सन्थाल आदि आदिमनिवासी जातिके किसानो-द्वारा । इन विद्रोहोके नेता भी अक्सर ऐसे ही लोग होते थे जो यह कहते थे कि उन्हें किसी खास देवीसे विद्रोह करनेकी प्रेरणा मिली है । मुस्लिम शासन तथा ब्रिटिश शासनके आरम्भिक कालमे इस प्रकारके अनेक विद्रोहोका वर्णन मिलता है ।

सम्पत्तिजीवी वर्गका महत्त्व

किसानोके विद्रोहने पुरानी व्यवस्थाको नष्ट करके नयी व्यवस्थाकी स्थापना करनेवाले आधारभूत युद्धका रूप तभी धारण किया जब कि सम्पत्तिजीवी वर्ग (bourgeoisie) ने भी इस युद्धमे हाथ बँटाया । यह हम पहले बता चुके हैं कि इस सम्पत्तिजीवी या पूँजीवादी श्रेणीके विकासके मार्गमे सामन्तवादी प्रथा किस प्रकार बाधक थी और यह कि इस श्रेणीके हितोकी रक्षा और वृद्धि तभी हो सकती थी जब कि सामन्तशाही वर्गके हाथसे निकलकर राजनीतिक प्रभुत्व इस वर्गके हाथमे आ जाय । सम्पत्तिजीवी वर्ग ऐसा नया उठता हुआ वर्ग था जिसके सदस्योकी सख्या बहुत थोड़ी थी । ऐसी हालतमे यह वर्ग पुराने सामन्तवर्गकी ताकत खत्म करके अपनी ताकत उसी हालतमे कायम कर सकता था जब कि सामन्त-शाहीवर्गके साथ लड़नेमे समाजके दूसरे वर्गों अर्थात् किसानो और कारीगरों आदिको भी वह अपनी ओर मिला सकता । यही कारण है कि सम्पत्तिजीवी वर्गने समता, स्वतन्त्रता और भ्रातृभावके नारे सामने रखकर किसानोकी सहानुभूति प्राप्त की और उनकी मददसे नये पूँजीवादी प्रजा-सत्तात्मक राज्यकी स्थापना की ।

किसानोका वर्ग ऐसा नहीं है जिसके सभी सदस्योके हित एक समान हो । भूमिरहित या कम भूमिवाले छोटे किसानका स्वार्थ स्पष्टतः बड़े किसानके हितसे टक्कर खाता है ।

किन्तु जब जमींदारोंके खिलाफ एक आधारभूत युद्ध छेड़ा जाता है तब समूचा किसान-तबका अपने वर्गके आन्तरिक विरोधोंको भूलकर एक होकर इस लड़ाईमें भाग लेता है ।

ऊपर यह बतलाया गया है कि सामन्तवादी वर्गके खिलाफ किसान जो लड़ाई लड़ते हैं वह सामन्तशाही व्यवस्थाके खिलाफ बुनियादी लड़ाईकी सूरत तभी अस्तित्व पर करती रही है जब पूँजीवादी वर्गके हाथोंमें लड़ाईका नेतृत्व रहा है । प्रजा-सत्तात्मक क्रान्तिका कार्यक्रम जहाँ पूर्णतया किसानोंके नेतृत्वमें ही चला है वहाँ व्यापारियोंको सामन्तशाही जमानेके मुकाबले तिजारतकी तरक्कीके लिए कुछ रियायतें भले ही मिल गयी हों, लेकिन पुरानी व्यवस्थाको हटाकर नयी व्यवस्थाकी स्थापनाका कार्यक्रम नहीं पूरा किया जा सका । चीनका ताइपिंग विद्रोह इसी प्रकारके युद्धका नमूना था । किसानोंके नेतृत्वकी इस असफलताका कारण पूँजीवादी वर्गकी तरह उनके पास एक नयी विचारधाराका न होना था ।

पूँजीवादी वर्गकी प्रतिगामिता

लेकिन ऐसे देशोंमें जहाँ विविध ऐतिहासिक कारणोंसे पूँजीवादका स्वाभाविक विकास रुक जाता है तो सम्पत्तिजीवी समुदाय क्रान्तिकारी नहीं रह जाता । उदाहरणार्थ हम अपने मुल्कको ही ले लें । विदेशी ब्रिटिश साम्राज्यवादने देशी पूँजीवादको पनपनेसे रोक रखा है और पूर्व प्रचलित सामन्तवादी ढाँचोंको भी कायम रख छोड़ा है । स्वाभाविक अवस्थामें हमारे पूँजीपतियोंको सामन्तशाही विरोधी युद्धका नेतृत्व करना था । यह सम्पत्तिजीवी वर्गके हितमें है कि सामन्तशाही वर्गका—जमींदारों, जागीरदारों, महन्तों और राजाओंका जो भी प्रभुत्व देशके आर्थिक या राजनीतिक जीवनपर है वह हटे । हमारा देश किसानोंका देश है । उद्योगधन्धोंद्वारा तैयार होनेवाली चीजोंकी खपत यहाँ तभी हो सकती है जब कि इन किसानोंकी आमदनी बढ़ायी जाय । किसानोंकी आमदनी बढ़ानेके लिए यह जरूरी है कि कृषक जनताका जो धन जमींदारों, नवाबों, महन्तों और राजाओंकी जेबमें चला जाता है उसे किसानोंके पास ही रहने दिया जाय । हमारे किसानोंकी क्रयशक्ति (purchasing power) प्रायः शून्यको पहुँच गयी है । बिना सामन्तशाही वर्गके शोषणको खतम किये हुए किसानोंकी आमदनी नहीं बढ़ायी जा सकती और फलस्वरूप उद्योगधन्धोंके विकासके लिए रास्ता साफ नहीं होता । इंग्लैण्ड और फ्रांसकी तरह हमारे पास ऐसे उपनिवेश भी नहीं हैं जहाँ हम अपने मालकी खपत कर सकें । हिन्दुस्तानमें उद्योगधन्धोंके विकासके लिए एक मात्र मार्ग उसकी आन्तरिक क्रयशक्तिका विस्तार करना, देशके अत्यधिक बहुमतकी अर्थात् किसानोंकी आमदनी बढ़ाना है । लेकिन फिर भी हमारे देशके पूँजीपति सामन्तवर्गको समाप्त करनेके लिए होनेवाली लड़ाईके कार्यक्रमके साथ नहीं हैं । इसके विपरीत कितने ही पूँजीपति जमींदारी प्रथाके समर्थक हैं । अपने प्रान्तमें ही देखते हैं कि पूँजीपतियोंके सेनापति सर ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव काश्तकारी विलके विरोधमें तालुकेदारोंका साथ देनेके लिए तैयार हैं ।

उपनिवेशोंके पूँजीपति

मौजूदा जमानेमें जिन स्थानोंमें सम्पत्तिजीवी प्रजासत्तात्मक क्रान्ति नहीं हो पायी है उन औपनिवेशिक राष्ट्रोंके पूँजीपतियोंकी प्रतिक्रियावादिताके दो मुख्य कारण हैं ।

एक कारण तो यह है कि सामन्तवादी वर्गके ही अनेक सदस्योंने पूँजीवादी उद्योगधन्धोंमें अपनी पूँजी लगा रखी है। हमारे प्रान्तके ही कई ऐसे जमींदार मिलेंगे जिनकी आमदनी जमींदारीके अलावा उद्योगधन्धोंसे, भी होती है। ऐसे पूँजीपतियोंका जमींदारी प्रथाका समर्थन करना स्वाभाविक ही है। दूसरी बात ध्यान देनेकी यह है कि मौजूदा जमानेमें स्वयं पूँजीवादी प्रथाके खिलाफ मजदूरोंका आन्दोलन भी शुरू हो जाता है। पूँजीवादी प्रथाके ह्रास और सामाजिक क्रान्तिके इस युगमें पूँजीपति वर्ग यह देखता है कि सामन्त-शाही आर्थिक प्रभुत्व मिटानेका अर्थ होता है उत्पादनके साधनोंमें व्यक्तिगत सम्पत्तिका अन्त करनेके आत्मघातक सिद्धान्तको स्वीकार कर लेना, अगर पूँजीपतियोंने जमींदारोंकी सम्पत्ति छीनी जानेमें मदद दी तो उनकी सम्पत्ति भी खतरेमें पड़ जा सकती है। ऐसी हालतमें उत्पादनके साधनोंपर व्यक्तिगत सम्पत्ति और उससे उत्पन्न होनेवाले सामाजिक शोषणको बनाये रखनेवाले पूँजीपति-वर्ग और सामन्तवादी-वर्ग दोनों एक हो जाते हैं। पूँजीपति-वर्ग प्रजासत्तात्मक क्रान्तिका नेतृत्व करनेके स्थानमें उसका विरोध करनेको तैयार हो जाता है।

श्रमजीवी वर्गका महत्त्व

ऐसी स्थितिमें पूँजीवादी वर्गके खिलाफ लड़कर भी शोषित वर्ग प्रजासत्तात्मक क्रान्तिको सफल बनाते हैं। क्रान्तिको सफल बनानेका काम अब श्रमजीवीवर्ग दूसरे शोषितोंके साथ मिलकर करता है। पहले कह आये हैं कि कृषकवर्गके पास ऐसी विचारधारा नहीं होती कि वह पुरानी व्यवस्थाका अन्त करके नयी व्यवस्था कायम करनेमें नेतृत्व ग्रहण कर सके। यद्यपि वह सामन्तशाही और पूँजीशाहीके दुहरे शोषणके बोझसे दबकर पहलेकी अपेक्षा भी अधिक क्रान्तिकारी बन जाता है, लेकिन फिर भी उसकी खास माँग जमीनकी ही होती है। उसको इस बातसे कोई प्रयोजन नहीं होता कि राजशक्ति किस वर्गके हाथमें जाती है। जो वर्ग किसानोंकी इस आधारभूत माँगकी पूर्ति करनेके लिए तैयार हो उसीके पीछे किसान हो लेते हैं। फ्रांसमें जो प्रजासत्तात्मक क्रान्ति हुई उसमें उसने पूँजीपतियोंका नेतृत्व स्वीकार किया। रूसकी राज्यक्रान्ति इसके विपरीत श्रमजीवी वर्गके नेतृत्वमें हुई। श्रमजीवी वर्गका उद्देश्य पूँजीवादी व्यवस्थाका ही अन्त करना होता है। पूँजीवादी प्रणालीका अन्त करनेके सिलसिलेमें स्वभावतः मजदूरवर्गको सामन्तवादी शोषणका अन्त करनेका कार्यक्रम भी रखना होगा।

क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी वर्गका महत्त्व

उपनिवेशोंमें प्रजासत्तात्मक क्रान्तिके कार्यक्रमको सफल बनानेमें बुद्धिजीवीवर्गके क्रान्तिकारी तत्वके (revolutionary intelligentia) का विशेष महत्त्व होता है। ऊपर हम कह आये हैं कि औपनिवेशिक देशोंमें प्रजासत्तात्मक क्रान्ति श्रमजीवी-वर्गकी प्रधानतामें सफल होती है, किन्तु उपनिवेशोंका मजदूर पूँजीवादी देशोंके मजदूरोंकी तरह शिक्षित नहीं होता। उसे वने हुए पूँजीवादी देशोंके मजदूरोंकी तरह कई पीढ़ियाँ नहीं गुजर चुकी होती, उसका उतना व्यापक सगठन नहीं होता, विदेशी

मजदूरोकी तरह इन मजदूरोको पूंजीपतियोके खिलाफ लड़ाईका अनुभव नही होता । संक्षेपमें उपनिवेशोके मजदूरोके भीतर आरम्भमे वह राजनीतिक चेतना और वह शक्ति नही पायी जाती जिससे वे प्रजासत्तात्मक युद्धमे सीधे नेतृत्व अपने हाथमे ले सके । मजदूरवर्गको अपनी शक्ति और महत्त्वका ज्ञान करानेका कार्य उपनिवेशोमें क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीवर्गके सदस्योद्वारा सम्पन्न होता है । उपनिवेशोमे ही क्यो स्वतन्त्र पूंजीवादी राष्ट्रोमे भी मजदूरोकी राजनीतिक शिक्षाका कार्य गैरमजदूर श्रेणीके समाजवादी बुद्धिजीवियोद्वारा होता है । मजदूरवर्गका नेतृत्व अगर उनपर ही छोड़ दिया जाय तो उनके अन्दर राजनीतिक चेतना आ ही नही सकती । वैसी हालतमे उनके भीतर केवल पूंजीपतियोंसे सुधारवादी तरीकेसे लडकर सुविधाएँ प्राप्त करनेकी आर्थिक चेतना (trade union consciousness) ही आ सकती है । पूंजीवादी ढाँचेको कायम रखते हुए चन्द रियायतोके लिए ही मजदूरोको नही लडना है, बल्कि उन्हे पूंजीवादी व्यवस्थाके ही मूलसे लडना है, यह चेतना मजदूरोमे क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीवर्गके द्वारा ही लायी जाती है ।

माक्सवाद और पूंजीवादी विज्ञान

आज प्रत्येक पूंजीवादी देश असाधारण संकटकी अवस्थामे है । यह अवस्था क्षणिक और अस्थायी नही है । यह अवस्था पूंजीवादके अन्तका आरम्भ घोषित करती है । इस वार संकट आर्थिक दायरेतक ही सीमित नही है । आर्थिक आधारके ह्रासके साथ-साथ पूंजीवादकी समग्र सामाजिक और आर्थिक पद्धति छिन्न-भिन्न होने लगती है । ह्रासके स्पष्ट चिह्न और लक्षण पूंजीवादी विचार-पद्धतिके क्षेत्रमे भी देख पडते हैं । निराशा, प्रतिगामी भाव, आदर्शवादका प्रचलन, रहस्यवादकी पुनरुत्पत्ति, विज्ञान और वैज्ञानिक तरीकोका परित्याग और मध्ययुगके पण्डित और टीकाकारोके तरीकोका फिरसे प्रचार यह सब वाते इस बातका सवूत है कि पूंजीवादी विचार-पद्धतिके ध्वसका क्रम असाधारण रीतिसे गहरा है । यदि पूंजीवादी राष्ट्रोके आर्थिक संकटने उत्पादनको कई पीढियोंके पीछे फेंक दिया है तो पूंजीवादी विज्ञानपर आये हुए संकटने विज्ञानको सैकडो वर्ष पीछे फेंक दिया है । समाजवादी रूसमे माक्सका वैज्ञानिक सिद्धान्त आज वृहत् जनसमुदायकी चीज हो रहा है और अन्वेषणका जो काम हो रहा है, उसके फलस्वरूप उन विशिष्ट नियमोका पता चल रहा है, जिनका आविर्भाव विभिन्न ऐतिहासिक समाजोके जीवनमें हुआ है । उधर पूंजीवादी राष्ट्रोमे पूंजीवादी पद्धतिके ह्रास और ध्वसके साथ-साथ पूंजीवादी इतिहास-विज्ञानका बुरा हाल हो रहा है । व्यवस्थाका सर्वथा अभाव और निराशाके भावका प्राबल्य पाया जाता है । इतिहासके क्षेत्रमे वैज्ञानिक रीतिसे खोजका काम करनेवालोकी सख्या घटती जाती है और प्रायः ऐसे लोग मौलिक अनुसन्धानके कार्यको छोड़ते जाते हैं, इसलिए नही कि उनको अवकाश नही है, किन्तु इसलिए कि उनके लेख

और ग्रन्थोंके प्रकाशनकी आशा नहीं है। धनकी विशेष कमी है। जनताकी अभिरुचि विकृत हो गयी है। व्यापारकी मनोवृत्ति यहाँ भी काम करती है। फ्रासमें अनेक लेखक इतिहासको उपन्यासके रूपमें लिखते हैं। इन ग्रन्थोंमें प्रायः सत्यका ख्याल नहीं रखा जाता। समाजविज्ञानकी आज जो दुर्दशा हो रही है उसका ठीक अन्दाज तभी लग सकता है जब हम पिछली एक शताब्दीके इतिहासका सिंहावलोकन करें। यह दुरवस्था आज नहीं शुरू हुई है। फ्रासकी राज्यक्रान्तिका युग पूंजीवादी समाज-शास्त्रके सबसे अधिक विकासका काल था। उस समय उसका अनुसन्धान सामाजिक विकासके नियम और क्रमके बहुत नजदीक पहुँच गया था। मार्क्सने अपने पुरोगामी पूंजीवादी वैज्ञानिकोंसे बहुत कुछ सीखा था। अपनी पूर्ण पद्धतिका निर्माण करनेमें मार्क्सने पूंजीवादी विद्वानोंकी प्रणालियोंके स्वास्थ्यकर, जीवनप्रद और क्रान्तिकारी तत्त्वोंको सर्वहारा मजदूरकी विचार-पद्धतिमें परिवर्तित कर पूंजीवादी पद्धतिका विरोध करनेके लिए एक तीक्ष्ण शस्त्रका निर्माण किया था। मार्क्सवादके कतिपय मौलिक सत्योंकी घोषणा मार्क्सने पहले पहल नहीं की थी, किन्तु पूंजीवादी वैज्ञानिकोंने सर्वप्रथम उनकी सत्यता स्वीकार की थी। सार्वभौमिक दृष्टिका भौतिक आधार वर्ग और वर्गसंघर्ष द्वन्द्ववाद आदि सिद्धान्तोंका निरूपण पहले ही हो चुका था।

क्रान्तिके जमानेमें ही इन विचारकोंने समाज तथा सामाजिक विकासके सम्बन्धमें अपने विचारोंको स्पष्ट और विशद कर पाया था। इसके विपरीत १७वीं शताब्दीकी विचारधारा प्राकृतिक विज्ञानके रंगमें रंगी हुई थी। नये युगके आर्थिक विकासका तकाजा था कि प्राकृतिक विज्ञानका विकास हो, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन प्राकृतिक शक्तियोंका उपयोग किये बिना सम्भव न था। प्राचीन युगकी विचारधाराकी विशेषता उसका दार्शनिक दृष्टिकोण था। मध्ययुग पण्डितों और टीकाकारोंका युग था जो प्राचीन ग्रन्थोंका भाष्य करनेमें अपनेको कृतकृत्य मानते थे। इन सबसे भिन्न नवीन युगके पूंजीवादियोंका दृष्टिकोण व्यावहारिक था। बेकन (Bacon) प्राचीन और मध्ययुग दोनोंकी विचार-पद्धतिसे समानरूपसे प्रहार करता है। बेकन (Bacon) का कहना है कि हमारे समाजका उद्देश्य प्रकृतिकी आन्तरिक शक्तियों और प्रेरक कारणोंको समझना तथा प्रकृतिपर मनुष्यकी शक्तिका अत्यन्त विस्तार करना है। उस समय प्राकृतिक विज्ञानकी ओर सामान्यतः आकर्षण था। उस समय समाजशास्त्रका स्वतन्त्र अस्तित्व न था। उस समय समाज और मनुष्य-सम्बन्धी विचार पूर्णतया इस एकांगी वैज्ञानिक विचारके प्रभावमें थे। कानून-विज्ञानकी बुनियाद एक ऐसा प्राकृतिक नियम समझा जाता था जो मानव-स्वभावसे उद्गत हुआ था और जो देश तथा कालके अवस्थाओंसे सर्वथा स्वतन्त्र तथा सब मनुष्यों और राष्ट्रोंके लिए सामान्य था।

अठारहवीं शताब्दीका भौतिकवाद ससारको एक प्रक्रियाके रूपमें नहीं देखता था। उसको यह मान्य नहीं था कि संसार एक ऐसा पदार्थ है जिसमें निरन्तर विकास होता रहता है। उस युगमें प्रकृतिका उपयोग करनेके लिए यह काफी था कि प्रकृतिकी वर्तमान अवस्थाका अनुसन्धान किया जाय। इस कामके लिए उसको अतीत जाननेकी कोई जरूरत न

थी। मानव-समाजके इतिहासके विषयमें यही धारणा थी। जब कि ऐतिहासिक विकासका कोई ख्याल न था तो अतीतके इतिहासमें कहाँसे दिलचस्पी पैदा होती? डेजरटीज (Descartes) का विचार था कि पुरानी किताबोंमें दिये हुए कहानी-किस्सोंको पढ़ना वक्त खराब करना है। उस समयका वह सामान्य विचार था कि मानव-समाज सब काल और सब देशोंमें एकहीसा होता है और इस प्रकार इतिहाससे कोई नयी बात नहीं मालूम होती। मॉन्टेस्क्यू (Montesque) जलवायुके प्रभावको स्वीकार करते थे पर इससे आगे वह भी नहीं गये थे। ऐतिहासिक विकासके सिद्धान्तोंको कोई नहीं मानता था। यह समझा जाता था कि मनुष्यको प्रभावित करने तथा उसके आचार और रिवाजको बदलनेके लिए सामाजिक जीवन और मानव-इतिहासके अध्ययन-की जरूरत नहीं है बल्कि इसके लिए मानव-प्रकृतिका अध्ययन जरूरी है जो उस समयके ख्यालके बमूजिव अपरिवर्तनशील था। हालबैख (Holbach) का कहना था कि मानव-यन्त्रके कार्य सदा उन्हीं नियमोंसे नियन्त्रित होते हैं जो प्रकृतिके समस्त जीवोंमें निहित हैं। प्राकृतिक नियमका ख्याल समाजको भी लागू किया गया। उस समय लोग इसका स्वप्न देख रहे थे कि हम आचार-विज्ञानका निर्माण कर उसके आधारपर एक आदर्श कानून-पद्धतिका निर्माण करेंगे। इस दृष्टिके अनुसार यह सोचना वाजिव न था कि सामाजिक जीवनकी घटनाओंपर नजर डालना मनुष्यके वास्तविक स्वभावका ज्ञान प्राप्त करनेमें बाधा उपस्थित करता है। 'हालबैख' और 'हेल्वेटियस' के विचारसे हमारा अज्ञान और उससे भी ज्यादा निश्चित सामाजिक समूहोंके स्वार्थ मानवप्रकृतिकी सच्ची आवश्यकताओंके स्पष्ट ज्ञानको नहीं होने देते। इसलिए मनुष्यकी आवश्यकताओंकी जहाँतक हो सर्वमान्य बनानेका प्रयत्न होना चाहिये अर्थात् उनको असाधारण सामाजिक घटनाओंसे पृथक् रहना चाहिये। हालबैख प्राकृतिक आचार और राजनीतिके सिद्धान्त कायम करना चाहते थे।

प्राकृतिक विज्ञानकी दूसरी दिशा बुद्धिपरत्व है। प्रकृतिकी शक्तियोंका संचालन करनेके लिए उसके नियम जानना जरूरी है और उसके नियम केवल शुद्ध तर्ककी सहायतासे जाने जा सकते हैं। इसी दृष्टिको समाजमें भी लागू किया गया। सामाजिक जीवनकी मानव-प्रकृतिकी जानकारी ही प्रभावित किया जा सकता है। समाजका अपना इतिहास है और उसका विकास होता है। इन बातोंसे इनकार करके वास्तविक ज्ञानका दरवाजा ही बन्द कर दिया गया। यही माना गया कि केवल तर्क सामाजिक जीवनकी बुराइयोंको खोज सकता है और उनको हटा कर प्राकृतिक नियमोंके अनुसार सामाजिक जीवनका निर्माण कर सकता है। सामाजिक जीवनका केवल एक क्षेत्र इन विचारोंके अधीन नहीं लाया जा सका। यह अर्थशास्त्रका क्षेत्र था। इस शास्त्रको विकसित करनेकी पूँजीवादी समाजकी उतनी ही आवश्यकता थी जितनी कि प्राकृतिक विज्ञानकी। उसके व्यावहारिक महत्वके कारण यही एक ऐसा समाजशास्त्र था, जो बहुत जल्द इन विचारोंके प्रभावसे बरी हो सका। १७वीं शताब्दीके मध्यमें ही इंग्लैण्ड के अर्थशास्त्री विलवेन पेटी (Wilbain Petty) ने आर्थिक घटनाओंको समझानेमें शुद्ध तर्कका आश्रय न लेकर

संख्या, नाप और तौलसे काम लिया। वह पहला व्यक्ति था जिसने यह उद्घोषित किया कि द्रव्य नहीं किन्तु श्रम सामाजिक सम्पत्तिका मूल है।^१

इंग्लैण्डमे जहाँ औद्योगिक क्रान्ति हो रही थी आर्थिक घटनाओके विश्लेषणको प्रमुख स्थान दिया जा रहा था। फ्रासमे, जो राज्यक्रान्तिकी ओर अग्रसर हो रहा था, आर्थिक घटनाओके सामाजिक पहलूपर विचार हो रहा था। फ्रासके फिजियोक्रैट्स (Physiocrats) की आर्थिक पद्धतिका आरम्भ वितरण-परिक्रियासे होता है और यद्यपि फ्रासकी आर्थिक पद्धतिमे कृषिका प्रधान स्थान होनेसे फिजियोक्रैट्सकी पद्धति एडम स्मिथ (Adam Smith) से बहुत पिछड़ी हुई है तथापि इनके पास—चाहे वह आरम्भिक अवस्थामे ही क्यों न हो—समाजके वर्गीकरणका स्थान मौजूद था। क्वेसने (Quesney) ने समाजको वर्गोंमे बाँटा था। टर्गो (Turgot) ने पूंजीपति तथा श्रमजीवी वर्गोंको परस्परविरुद्ध बतलाया था। नेकर (Necker) के निबन्धोमे यह विचार निश्चित रूपसे पाया जाता है कि उत्पादनके साधनोके मालिक और अपने श्रमसे अपने जीवन निर्वाह करनेवाले श्रमजीवी वर्गके परस्पर सघर्षमे कानूनके संरक्षणमें पूंजीपति अपने अधिकारोके बलपर श्रमजीवीको दबाते हैं।

टर्गो और नेकरमे वर्गीकरण और वर्गसघर्षके विचार पाये जाते हैं और यह भी कि जब क्रान्ति होती है तो वर्गोंके आन्तरिक विरोध और भी प्रकट हो जाते हैं, जिनके कारण सामाजिक विकासके क्रमका विशद रूप हमको मिलता है। बारनार (Barnare) की दृष्टिमे मानव-इतिहास वर्गसघर्षका इतिहास है। यह दृष्टि ऐतिहासिक भौतिकवादके अत्यन्त सन्निकट है। वह इन्साइक्लोपीडिस्ट (Encyclopidists) के दर्शनका विरोधी था, क्योंकि यह दर्शन ऐतिहासिक सत्यकी उपेक्षा कर महज कयासपर आश्रित था। यह दार्शनिक घटनाओकी परीक्षा न कर केवल कयाससे ही काम लेते थे। बारनार (Barnare) के अनुसार सामाजिक जीवनका सदा विकास होता रहता है। वह ऐसे नियमोंकी सम्भावनासे इनकार करता है जो सदाकालीन हो और जो जीवनकी प्रत्येक अवस्थामे लागू हो सके। उसका कहना था कि कानून लोगोकी इच्छापर निर्भर नहीं करते, किन्तु किसी विशेष समाजके विकासकी अवस्थापर निर्भर करते हैं। एक नियम जो अच्छा है वह दूसरे समय भिन्न अवस्थामे हानि पहुँचानेवाला भी हो सकता है। बारनार सामाजिक घटनाओका वर्ग आधार ढूँढता है, किन्तु वह समाजके वर्गीकरणके उत्पादनके सम्बन्धको नहीं बल्कि सम्पत्तिके सम्बन्धोंको मूल कारण समझता है। उसके लिए समाजका सारा जीवन सम्पत्तिमे केन्द्रित है। वर्ग-सघर्ष उसके लिए सम्पत्तिके विविध प्रकारोका सघर्ष है। इस दृष्टिसे वह मानव-इतिहासकी आलोचना करता है। उसके विचारमे प्रारम्भिक कालकी समानता सम्पत्तिके अभावके कारण थी। सम्पत्तिके विकासके साथ-साथ असमानताका जन्म होता है। किसान बड़े जमींदारोंके चंगुलमे फँसता है। चल सम्पत्ति, जिसकी वृद्धि व्यापार व्यवसायके द्वारा होती है, पूंजीपतियोका आधार है।

बड़े पैमानेकी जमींदारी सामन्तोका आधार है। सम्पत्ति-विहीन श्रमजीवी समाजसे वहिष्कृत है। वारनारका कहना है कि जबसे सम्पत्तिके नये प्रकार उत्पन्न होने लगे हैं, तभीसे राजनीतिक नियमोंमें क्रान्तिकी तैयारी शुरू हो जाती है। सम्पत्तिका नया वितरण शक्तिको नये ढंगसे तक्सीम करता है। सेन्ट साइमन (St. Simon) भी लगभग इन विचारोंका माननेवाला था। वर्गविकासके साथ-साथ वह विज्ञानको भी ऐतिहासिक विकासका कारण मानता था। यह भी सच है कि वह धर्मके प्रभावसे मुक्त न हो सका तथापि वह वारनारके दृष्टिकोणको गहरा रंग देता है। वारनारकी तरह वर्ग-विभाजनके मूलमें वह अनिश्चित सम्पत्ति नहीं पाता, किन्तु उत्पादनके साधनोंके रूपमें ही सम्पत्तिको इसका मूल कारण समझता है। क्रान्तिके कारण पूँजीवादियोंका सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण बदलने लगा था। वारनार और सेन्ट साइमन उनके प्रतिनिधि मात्र थे। क्रान्तिका प्रभाव फ्रांसतक ही सीमित न रहा, जर्मनीमें भी वर्गसंघर्षकी दृष्टिसे सामाजिक विकासकी परीक्षा होने लगी। इंग्लैण्डमें यह बात किसीसे छिपी न थी कि दो वर्गोंके बीच राज्यशक्तिके लिए संघर्ष चल रहा है। सामाजिक दृष्टिकोणमें जो परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव विज्ञानपर भी पड़ा। प्रकृतिपर भी विकासका सिद्धान्त लागू किया गया। औद्योगिक क्रान्तिके कारण इंग्लैण्ड और फ्रांसमें विज्ञानकी वृद्धि हुई और राजनीतिक प्रश्नोंका तात्कालिक उत्तर देना पड़ा। जर्मनी आर्थिक क्षेत्रमें पिछड़ा हुआ था। राजनीतिक दृष्टिसे वह बढ़ा हुआ था कि एकता अमीतक कायम नहीं हुई थी, अभी वहाँ क्रान्ति होनेकी थी और पूँजीवादी-वर्ग आगे चलकर राजनीतिक दृष्टिसे कमजोर पाया गया। वहाँ अलवत्ता व्यावहारिक झुकाव न था बल्कि अब भी आदर्शवाद-का जोर था। वहाँ विकास और क्रान्तिके नवीन विचार इस सूक्ष्म दार्शनिक रूपमें देखे और परखे गये। विकासके क्रमका अन्वेषण आगे चलकर जर्मनीमें भी हुआ, किन्तु वही आदर्शवादी दर्शनके रूपमें, वारनारने द्वन्द्ववाद (dialectic) का जिक्र सरसरी तौरपर ही किया था, किन्तु जर्मनीके दार्शनिकोंने उसको विकसित रूप दिया।^१

फ्रांसकी क्रान्तिके दिनोमें तथा उसके १० वर्षके बादके जमानेमें पूँजीवादी सामाजिक और ऐतिहासिक विचार-पद्धति अपनी चोटीतक पहुँच गयी थी। यही वह जमाना था जब ऐतिहासिक भौतिकवादकी मुख्य दलीलोंकी चर्चा हवामे थी। इसी सिद्धान्तको विकसित कर मार्क्सने पीछेसे अपनी पद्धति गठित की थी।

इसलिए यह जरूरी था कि हम देखनाते कि पूँजीवादी विचारशैली सदासे ऐसी वाँझ और वेदम न थी जैसा कि वह आज हो गयी है। एक समय था जब वह अपने अन्वेषणमें सामाजिक विकासके मौलिक नियमके करीब पहुँच गयी थी। मार्क्सने इस बातको स्वयं स्वीकार किया था। सन् १८५२ में उसने वेडमंयरको लिखा था—

“आधुनिक समाजमें वर्गोंके अस्तित्व तथा वर्ग-संघर्षकी खोजका श्रेय मुझको नहीं है। मुझसे बहुत पहले पूँजीवादी इतिहास-लेखकोंने इस वर्ग-संघर्षके ऐतिहासिक विकासका

वर्णन किया था, और पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने वर्गों के आर्थिक ढाँचे का । मैंने जो कुछ नवीन किया वह यह था कि मैंने प्रमाणित कर दिया कि वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास-क्रम की विशेष ऐतिहासिक अवस्था से सम्बद्ध है, और वर्गसंघर्ष निश्चित रूप से श्रमजीवी वर्ग के अधिनायकत्व में परिणत होता है, और यह अधिनायकत्व अस्थायी है और तभी तक रहता है जब तक वर्गविहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती ।”

इन नवीन सिद्धान्तों के कारण जो पूंजीवादी विचारकों को स्वीकृत न थे उन्हें अपनी जगह से हटना पड़ा और वे फिर मानव-सिद्धान्त की ओर झुके । कुछ हद तक पूंजीवादियों का खुदपसन्दी का स्वभाव और मनोवृत्ति उनको सामाजिक नियमों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने नहीं देती । किन्तु उनके दृष्टिकोण में जो गहरा परिवर्तन उपस्थित हो गया है उसको समझने के लिए महज इतना काफी नहीं है । इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह था कि सामन्तशाही पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त पूंजीपतियों को क्रान्ति या क्रान्तिके सिद्धान्तों की जरूरत बाकी न रही । एक नये दुश्मन अर्थात् श्रमजीवी वर्ग के मुकाबिले में आ जाने से वर्गसंघर्ष की तरफ उसका रुख बदल गया । क्रान्ति और वर्गसंघर्ष विलकुल ठीक है जब तक वे पूंजीपतियों के स्वार्थों की हिमायत करते हैं । किन्तु जब वे पूंजीपतियों का विरोध करने लगते हैं तब वे हानिकारक हो जाते हैं और उनका दबाना वाजिव हो जाता है । बारनार भी जो साधारणतया गहरी सूझ का आदमी था अपने सिद्धान्त को छोड़ने को तैयार हो गया, जब एक बार क्रान्ति उसकी राजनीतिक योजना की सीमा का उल्लंघन कर गयी । बारनार सम्पत्तिका जवर्दस्त समर्थक था, यही हाल गुइजो (Guizot), मिग्ने (Mignet) और थीर्री (Thierry) नामक ऐतिहासिकों का है । जब मध्यम श्रेणी का विरोध करने के लिए श्रमजीवी वर्ग आगे आया तब इतिहास-लेखकों के लिए वर्गसंघर्ष एक शर्म की बात हो गयी और सामाजिक शान्ति इनको अभीष्ट होने लगी । इतिहास के क्षेत्र में बारनार अद्वैत दृष्टिका मानने वाला था, किन्तु गुइजो की द्वैत दृष्टि थी । वह सामाजिक उन्नति में और व्यक्तिगत उन्नति में अन्तर करता था और इन दोनों को एक दूसरे से स्वतन्त्र मानता था । वह इतिहास में दैवी योजना का हाथ देखने लगा था । विकासवाद जिसका १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बड़ा जोर था, जाहिरा एक उन्नतिशील सिद्धान्त था, खासकर अपरिवर्तनशील मानव-स्वभाव के विचारों के मुकाबिले में । किन्तु वास्तव में विकासवाद का उपयोग आरम्भ से ही प्रतिक्रिया के समर्थन में होने लगा था, जहाँ तक क्रान्तिकारी वर्ग सिद्धान्त के विरोध का सवाल था । जब क्रान्तिका मार्ग पूंजीपतियों के स्वार्थ का सहायक न रह गया किन्तु उनके लिए खतरनाक हो गया तब यह कहा जाने लगा कि समस्त संसार की उन्नति विकास द्वारा होनी चाहिये न कि क्रान्ति द्वारा ।

पूंजीवादी विज्ञान का मार्ग अब प्रतिक्रिया का मार्ग हो गया । उसने क्रान्तिकारी वर्ग सिद्धान्त को छोड़ दिया । सेन्ट साइमन की सामाजिक शिक्षा और हेगेल की दार्शनिक शिक्षा उस नये सम्मान और विचार के फल थे जो क्रान्तिके युग में पैदा हुए थे, किन्तु इनकी भी द्वैत दृष्टि थी और यद्यपि यह नये दृष्टिकोण से प्रभावित हुए थे तथापि यह पुराने तास्सुब और विचारशैली से अपने को मुक्त नहीं कर सकते थे । सेन्ट साइमन का वर्गसिद्धान्त पिछली

शताब्दीके शुद्ध आदर्शवादसे मिश्रित था । हेगेलकी शिक्षामें ग्रंथीतका प्रभाव स्पष्ट पाया जाता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक विकासके आदर्शवादी रहस्यमय प्रकारको विकासके द्वन्द्ववादसे मिलाती हैं । इस द्वैतभावके कारण इन दोनों शिक्षाओंका परिणाम एकसा ही हुआ । दोनों शिक्षाओंके लाजिमी नतीजेसे जो घबराये नहीं वह समाजवादके सिद्धान्तोंके माननेवाले हो गये । दूसरी ओर जिन पूंजीवादी शास्त्रियोंने वर्ग और द्वन्द्ववादसम्बन्धी शिक्षाका परित्याग किया उन्होंने इन शिक्षाओंका केवल अंग ग्रहण किया जो आदर्शवादी था । मार्क्स साइमनवादियोंका उत्तराधिकारी था, जिन्होंने वर्तमान पूंजीवादी समाजकी शोषण परिक्रियाको समझ लिया था और जो उनके स्थानमें ऐसे सघ कायम करना चाहते थे जिनमें शोषणके लिए कोई स्थान न हो । किन्तु किस प्रकार ऐसे सघ कायम हो सकते हैं, इस सम्बन्धमें उनके विचार काल्पनिक थे । अपना उद्देश्य प्राप्त करनेके लिए उन्होंने श्रमजीवी वर्गकी ओर ध्यान न दिया किन्तु वे मनुष्यकी सद्विच्छापर निर्भर करते रहे इस कारण उनकी शिक्षा काल्पनिक और निस्सार हो गयी ।

जहाँ सेन्ट साइमनके अनुयायियोंमें वामपक्षी समाजवादी थे वहाँ आगस्टाइन थीरी (Augustin Thierry) और आगस्टे कौन्टो (Auguste Comte) दक्षिण पूंजीवादी थे । थीरीके प्रतिगामी विचार हम ऊपर देख चुके हैं । कान्टे विधेयवाद (positivism) का सस्थापक था । उसकी विचारप्रणालीमें वर्गसिद्धान्त, संघर्ष या क्रान्तिका उल्लेख भी नहीं है । उसके अनुसार समाजका आकार तदनुरूप विचारके विकासकी अवस्थापर निर्भर करता है । उसका कहना है कि बहुदेववादके अनुरूप सैनिकवाद, आध्यात्मिक अवस्थाके अनुरूप साम्राज्यवाशाहीके विविध स्थायी रूप और विधेयवाद (positivism) के अनुरूप व्यवसायवाद है ।

अब सामाजिक घटनाओंकी परीक्षाके स्थानमें मनोवैज्ञानिक (psychological) हेतुओंकी छानबीन होने लगी । पूंजीवादी ऐतिहासिकोंमें यह परिवर्तन अहेतुक नहीं है । उनमेंसे एक भी यह बात न समझ सका कि सामाजिक मनोविज्ञान स्वयं सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक जीवनकी घटनाओंसे उत्पन्न होता है । वास्तविक जीवनकी घटनाओंका अनुसन्धान न करना और समाजशास्त्र तथा इतिहासको मनोविज्ञानके दर्जेपर ले आना उस प्रयत्नका फल है जो वर्गसंघर्षके उल्लेखको इतिहाससे मिटा देना चाहता है । सामाजिक विकासके वास्तविक नियमोंके अन्वेषणसे पूंजीपतियोंका तो अर्थ भला होनवाला था नहीं, इसलिए उन्हें अबसे सामान्य तर्कोंसे ही काम लेना था जो कुछ भी न बतलावे न समझावे । इसीलिए सामाजिक श्रेणियोंका विचार बहिष्कृत कर दिया गया, इतिहासमें आध्यात्मिक तत्वको जरूरतसे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, और ऐसे भी शास्त्री पैदा हुए जिन्होंने इतिहासकी सारी प्रक्रियाको कुछ महापुरुषोंका खेल बताना शुरू किया जो अपनी इच्छाके अनुसार अद्भुत रचना-शक्तिके जरिये मानव-समाजके भाग्यका फैसला करते हैं ।^१

माक्स और नियतिवाद

अपने मूलरूपमें नियतिवादका प्रश्न जीवस्वातन्त्र्यवादसे उत्पन्न हुआ प्रश्न था । क्या मनुष्य स्वतन्त्र कर्ता है अथवा वह अवश होकर कार्य करता है ?

कर्मस्वातन्त्र्यवादके विरोधमें यह तर्क उपस्थित किया गया था कि यदि सर्वशक्तिमान् ईश्वरने मनुष्यकी सृष्टि उसके स्वभावकी सारी आवश्यकताओंको पूरा करके की है, तो मनुष्यको दण्ड देनेका उसको नैतिक अधिकार नहीं है । इसके उत्तरमें प्रतिपक्षी मानव-प्रतीति, मनुष्यके अनुभवका प्रमाण देते थे । वास्तविक जीवनमें मनुष्य जानते हैं कि वह विकल्पोमेंसे चुनाव करते हैं । वह यह भी जानते हैं कि मनुष्यकी सद्गति या दुर्गति होती है और प्रयोजन-विशेषके लिए बुद्धिपूर्वक यत्नशील होनेसे मौलिक सुधार भी होता है । कर्मस्वातन्त्र्यका केवल इतना अर्थ है कि मनुष्य दो विकल्पोमेंसे अपनी इच्छाके अनुसार किसी एकको चुननेकी योग्यता रखता है ।

प्रतिपक्षका कहना है कि यदि कर्मस्वातन्त्र्य है, तो इसका अपनी परिधिमें इतना सामर्थ्य तो होना चाहिये कि वह सर्वशक्तिमान्के आशयको व्यर्थ कर दे । किन्तु उस अवस्थामें ईश्वरका सर्वशक्तिमत्त्व जाता रहेगा । चूँकि यह अचिन्त्य है और ऐसी कल्पना करना मनुष्यके लिए पाप है, अतः मनुष्य स्वतन्त्र कर्ता नहीं है ।

कालविन (Calvin) के कट्टर अनुयायियोंका भी यही मत था कि मनुष्यका वास्तविक स्वातन्त्र्य किसी अंशमें भी स्वीकार करना ईश्वरके सर्वशक्तिमत्त्वपर आक्रमण करना होगा । इससे विश्वकी धर्मताको भी व्याघात पहुँचेगा । जीव नहीं समझ सकता कि ईश्वरने क्यों किसीकी नारकीय गति आरम्भसे ही निश्चित की है और दूसरोंके लिए भगवत्प्रसादवश मोक्ष नियत किया है । इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि यह व्यवस्था दैवकृत है ।

बहुत पीछे जब अपराध करनेवालेके साथ दयाका व्यवहार करनेकी माँग पेश की गयी तब यह विवाद पुनः उठ खड़ा हुआ । सुधारकोकी ओरसे इसपर जोर दिया गया कि चूँकि अपराधीका स्वभाव और चरित्र उसकी परिस्थिति तथा शिक्षा-दीक्षापर निर्भर करता है और वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, अतः बदला लेनेके भावसे उसको दण्ड देना निष्ठुर और बुद्धिके प्रतिकूल है । उनका कहना है कि मनुष्य सर्वथा वशगत गुण और परिस्थितिका फल है । वह अवश और असहाय है । परिस्थिति तथा वशके अनुसार ही उसका निर्माण होता है । जिस प्रकार घड़ीकी सुइयाँ अवश हैं उसी प्रकार मनुष्य अवश है ।

कालविनके जिन अनुयायियोंका इसके सदृश मत है उनमें और इन सुधारकोंमें केवल इतना ही वैशिष्ट्य है कि जहाँ कालविनके अनुयायी मनुष्यका संचालन करनेवाली शक्तिको ईश्वर कहते हैं वहाँ यह सुधारक उसे प्रकृति, शिक्षा-दीक्षा या वशगत गुण या परिस्थिति कहते हैं । दोनों अवस्थाओंमें मनुष्यकी कर्तृत्वशक्ति शून्यके समान हो जाती है और बाह्यशक्ति जो संचालन करती है अनन्त हो जाती है ।

क्या माक्सको ऐसे विचारोंके साथ कोई सहानुभूति थी ? उन्होंने इन विचारोंके

ऐतिहासिक महत्त्वको जाना, किन्तु साथ-साथ उन्होंने इनकी मर्यादा और भ्रान्तताको भी पहचाना, उन्होंने यह भी देखा कि इन मतोंके प्रतिपक्ष भी समान रूपसे एकांगी और भ्रान्त है।

चाहे हम प्रतीतिके प्रमाणको अभ्रान्त माने और मनुष्यकी इच्छाको निर्विशेष और परिपूर्ण माने अथवा प्रतीतिके प्रमाणको भ्रान्त मानें, फल एक ही होता है। पहले पक्षमें मानवी इच्छा, दूसरे पक्षमें ईश्वर, परिस्थिति आदि अनन्तका स्थान लेती है तथा इनका प्रतिपक्ष शून्यका स्थान लेता है। दोनों अवस्थाओंमें हम प्रधान प्रश्नकी अवहेलना करते हैं, क्योंकि हम अकारण ही प्रतिवादकी एक कोटिको दवा देते हैं और यही मुख्य प्रश्न है, जिसका हमको विचार करना है। यह मानवी इच्छा और दैवका प्रतिवाद है।

दार्शनिक, नीतिज्ञ तथा समाजशास्त्रविद् चाहे विविध रूपसे इस समस्याको हल करनेकी चेष्टा करे तथापि सबका इसमें ऐकमत्य होगा कि एक शृङ्खलाको ध्वस्त करके असामंजस्यसे भागना अनुचित होगा। चाहे आप मानवेच्छाके अस्तित्वका अथवा सत्ताका प्रतिपेध करे—चाहे उसे ईश्वर कहे या परिस्थिति या अन्य कुछ, प्रश्नका विवेचन नहीं होता।

मार्क्सने स्पष्ट देखा कि प्रश्नका ठीक रूप नहीं है। वास्तविक जीवनकी भूमिमें मनुष्य और उसकी परिस्थितिके बीच क्रिया प्रतिक्रिया का सम्बन्ध होता है। परिस्थितिका सर्वशक्तिमत्त्व स्वीकार करनेका अर्थ मनुष्यका प्रतिपेध करना है। मानवी इच्छाकी निर्विशेष निरपेक्षता स्वीकार करना मनुष्यका सर्वशक्तिमत्त्व स्वीकार करने और परिस्थितिका प्रायः अभाव माननेके बराबर है। युक्तियुक्त फल प्राप्त करनेके लिए दोनोंके सक्रिय अन्योन्य सम्बन्धको समझना होगा।

हॉब्स (Hobbes) तथा अन्य भौतिकवादियोंने पहले ही देख लिया था कि मानवी इच्छा-शक्तिमें निर्मर्यादित “स्वतन्त्रता” आरोपित करना सदोष है। शक्ति और स्वतन्त्रता अभिन्न हैं। प्रत्येक वस्तु उसी हदतक स्वतन्त्र है जिस हदतक उसको कार्य करनेकी शक्ति है, किन्तु प्रत्येक वस्तुकी उतनी ही शक्ति होती है और हो सकती है, जितनी शक्ति उसकी प्रकृति रख सकती है।

वृक्ष अपनी वृद्धि करनेमें स्वतन्त्र है, किन्तु इसी शर्तके साथ कि उसकी परिस्थितियाँ वृद्धिके अनुकूल हैं। पुनः यह उसी तरह और उसी परिमाण में बढ़ सकता है, जितना उसकी प्रकृतिके लिए सम्भव है। यह स्पष्ट है कि वृक्षमें पखने नहीं उग सकते, इसकी स्वतन्त्रता उसको नहीं है।

‘मनुष्य अपनी परिस्थितिके अधीन है’ इस वादका क्रान्तिकारी उपयोग तब था जब इसका उपयोग ऐसे राजाओंके विरुद्ध किया जाता था, जो प्रजाके साथ अन्याय और अत्याचारका व्यवहार करते थे और जो यह कहकर अपनी वर्चस्वताका समर्थन करते थे कि साधारण जन इस योग्य नहीं हैं कि उनको स्वतन्त्रता दी जाय। प्रजाका शोषण करनेवालोंके विरुद्ध भी यह वाद उपयोगी सिद्ध होता था, जो यह तर्क करते थे कि यह मूर्ख अपने पैसों और अवकाशका सदुपयोग करना नहीं जानते और इसलिए इनकी नितान्त आवश्यकताओंकी

पूर्तिके अतिरिक्त इनको पैसा नहीं देना चाहिये और इनको अवकाश भी नहीं मिलना चाहिये ।

किन्तु यह वाद भयावह हो जाता है जब यह मर्यादाका उल्लंघन करता है । पहले तो इस वादसे अत्याचार करनेवालो और प्रजाका शोषण करनेवालोको अच्छा बहाना मिल जाता है, फिर इससे दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है । इसका इन्जाज क्या है ?

फाएरबाख (Feuerbach) पर माक्सका जो तीसरा वाद (thesis) है उसका इसी प्रश्नसे सम्बन्ध है ।

“परिस्थितियोंके बदलने और शिक्षाके बारेमें जो भौतिकवाद है वह भूल जाता है कि मनुष्य परिस्थितियोंको बदलता है और यह कि शिक्षककी स्वयं शिक्षा होनी चाहिये ।”—
—माक्स

यहाँ रावर्ट ओवन (Robert Owen) से सकेत है । उनका यह दावा था कि “समुचित उपायोंका अवलम्ब लेकर अच्छे-से-अच्छा और बुरे-से-बुरा मानव-चरित्र समाज या ससारको पेश किया जा सकता है ।” उनका यह भी कहना था कि यह उपाय विद्यमान हैं और यदि वह लोग जिनका समाज में प्रभाव है चाहें तो इनका उपयोग कर सकते हैं । किन्तु इससे यह परिणाम निकलता था कि यह प्रभावशाली लोग इन उपायोंसे काम नहीं लेते और न लेगे । इनका स्वभाव और चारित्र्य ही ऐसा बन गया है जो इनको दूसरी ओर ले जाता है ।

इससे यह पहली निकली कि रावर्ट ओवनका ‘चारित्र्य’ कहाँसे आया, यदि वह उन्हीं परिस्थितियों और शिक्षा के फल है । यदि उनका स्थान उस वर्गमें है जो प्रभाव रखता है, तो उनका स्वभाव और उनकी प्रवृत्ति दूसरोंसे भिन्न क्यों है और यदि वह उस वर्गके हैं, जिसके स्वभावको बदलनेकी जरूरत है, तो उन्होंने ऐसे स्वभावको कहाँसे पाया, जिसको पुष्ट करनेकी आवश्यकता है, न कि बदलने की ?

माक्सने इसका यह हल निकाला कि मनुष्य और परिस्थितियाँ दोनों परिवर्तनशील और अस्थिर हैं तथा दोनोंका सदा अन्योन्य सक्रिय विरोध होता रहता है और इससे वृद्धि-विकास होता है—

“इतिहासकी प्रत्येक मजिलपर हम एक भौतिक परिणाम पाते हैं । यह उत्पादक शक्तियोंका जोड़ है; यह व्यक्तियोंका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध तथा व्यक्तियोंका अन्योन्य सम्बन्ध है, जिसका इतिहासने निर्माण किया है । यह सम्बन्ध क्रमागत है । यह भौतिक परिणाम उत्पादक शक्तियोंका समूह, पूँजीके विविध रूप तथा विविध अवस्थाएँ हैं । एक ओर प्रत्येक नयी पीढ़ी इस समूहमें परिवर्तन करती है और दूसरी ओर यह समूह उस पीढ़ीके जीवनकी अवस्था निर्धारित करता है तथा उसको निश्चित और विज्ञेय स्वभाव प्रदान करता है । जिस प्रकार मनुष्य परिस्थितियोंको बनाता है उसी प्रकार परिस्थितियाँ मनुष्यको बनाती हैं ।”—(German Ideology)

माक्सके कैपिटल (Capital, Vol. I, Chap. viipp 156-7) में भी इन परस्पर-विरोधी सम्बन्धका इसी प्रकार उल्लेख है :—

“श्रम एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों हिस्सा लेते हैं। इस प्रक्रियामें मनुष्य स्वतः उन भौतिक प्रतिक्रियाओंका जो उसके और प्रकृतिके बीच होती है आरम्भक होता है और वह उनका नियन्त्रण और नियमन करता है। वह स्वयं प्रकृतिकी एक शक्ति है पर वह अपनेको प्रकृतिके विरुद्ध खड़ा करता है। वह अपने हाथ-पैर हिलाता है तथा दिमाग को सक्रिय बनाता है, जिसमें वह अपनी आवश्यकताओंके अनुरूप प्रकृतिके उत्पादकोंको आत्मसात् कर सके। बाह्य ससारपर इस प्रकार क्रिया कर और उनको बदलकर वह अपने स्वभावको भी बदलता है। वह अपनी प्रसुप्त शक्तियोंकी वृद्धि करता है और उनको अपने अधीन कर स्वेच्छाके अनुसार काम करनेके लिए विवश करता है।”

इन दो अवतरणों से यह स्पष्ट है कि मार्क्सवाद नियतिवाद (Determinism) नहीं है। यह कहना कि मनुष्य प्रकृतिको बदलता है, अपने स्वभावको बदलता है और अपनी प्रसुप्त शक्तियोंका विकास करता है, इस कथनका उल्टा है कि मनुष्य घड़ीकी मुड़्योंकी तरह अवश है। साथ-ही-साथ यह कहना कि मनुष्य यह सब तभी कर सकता है जब वह प्रकृतिपर सक्रिय प्रतिक्रिया करता है, यह कहना कि वह परिस्थितियोंको उसी हदतक बना सकता है, जिस हदतक परिस्थितियाँ मनुष्यको बनाती हैं, यह माननेके बराबर है कि, नियतिवादमें भी सत्यका अंश है।

मार्क्सवाद नियतिवादके महत्त्वपूर्ण और यथार्थ अंशका ग्रहण करता है। संक्षेपमें इतिहासका जो वाद मार्क्स एंगल्सका है वह एक आकारमें नियतिवादी है, किन्तु केवल इस अर्थपर कि वह साथ-ही-साथ अनियतिवादी भी है, अर्थात् वह आध्यात्मिक और यान्त्रिक प्रश्नका सर्वथा अतिक्रमण करता है और विरोध विकासद्वारा वस्तुतः भौतिक हो जाता है।

यही बात आर्थिक आकारोंके लिए भी सच है। मार्क्स एंगल्सने यथार्थ देखा कि समस्त सामाजिक क्रियाके लिए आर्थिक क्रियाका पूर्व होना नितान्त आवश्यक है, किन्तु उन्होंने एक क्षणके लिए भी इसका प्रतिपेध करनेकी कल्पना नहीं की थी कि अन्य क्रियाओंका सद्भाव है और अन्तिम परिणामके उत्पादनमें यह भी हेतु है। इसके विपक्षमें उन्होंने देखा कि आर्थिक क्रियाका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसी योग्यता प्रतिपादित की जाय जिससे आर्थिक क्रियाकी आवश्यकता चाहे अल्पकालके लिए ही क्यों न हो, न रहे। उन्होंने यह भी देखा कि आर्थिक क्रियाओंका महत्त्व इसमें है कि वह आर्थिक क्रियाओंसे इतर क्रियाओंकी विविधता और इयत्ताको उत्तरोत्तर बढ़ाती जाती हैं तथा सामाजिक और राजनीतिक चेष्टाएँ और प्रयत्न बहुधा आर्थिक परिवर्तनको उत्तेजन देकर आर्थिक क्रियाओंके विकासको उत्तेजित करते हैं और उनके स्वरूपको निश्चित करते हैं।

संक्षेपमें मार्क्स एंगल्सका वाद न शुद्ध आर्थिक है और न आर्थिकसे भिन्न है। यह दोनों हैं और इसलिए द्वन्द्वात्मक (Dialectical) है।

एंगल्सने स्पष्ट रूपसे नियतिवादका प्रत्याख्यान किया है। मार्क्स और एंगल्सने स्पष्ट रूपसे इसका प्रतिपेध किया है कि उन्होंने कभी भी यह कहा है कि ऐतिहासिक महत्त्वके सम्बन्ध और शक्तियाँ केवल आर्थिक होती हैं। जिस वादकी यह प्रतिज्ञा है

कि केवल आर्थिक तथ्य और शक्तियोग ही मानव समाजकी ऐतिहासिक उत्तरोत्तर उन्नतिपर वास्तविक प्रभाव पड़ता है, उसी वादके लिए हम सचमुच 'आर्थिक नियतिवाद' इस आख्याका व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए यह मिथ्य होता है कि यह माक्स और एंगल्सका सिद्धान्त नहीं था।^१

१. टी० ए० जैक्सनके एक लेखके आधारपर।

पाँचवाँ अध्याय

शिक्षा

पाँचवाँ अध्याय

युवकोंका समाजमें स्थान और भारत

सामान्यतः उन समाजोमे, जहाँ स्थिरता आ गयी है और जहाँ विकासकी गति अत्यन्त मन्द है, वृद्धोकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा होती है। ऐसे समाजमे वृद्धोका ही नेतृत्व होता है और उनका अनुभव ही समाजका मुख्य आधार होता है। चीन और भारतके समाज इसके उदाहरण हैं। हमारे पूर्वजोका कहना है कि वह सभा ही नहीं है जहाँ वृद्ध नहीं है। ऐसे समाज की शिक्षा-प्रणालीमे लोक-परम्पराका बड़ा महत्त्व होता है। वहाँ शिक्षाके नये प्रकारोकी परखका प्रश्न ही नहीं उठता। जिनकी सस्कृति और जिनका इतिहास प्राचीन है, उनकी यही कथा है। जबतक समाजके आधारभूत मौलिक सिद्धान्तोके परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता और जबतक समाज के आर्थिक ढाँचेमे क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होता, तबतक यही अवस्था बनी रहती है।

किन्तु जब समाजकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसको जीवित रहनेके लिए अपनी पुरानी पद्धतिको बदलनेके लिए विवश होना पड़ता है, तब उसके सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य भी बदलने लगते हैं। नूतन समाजके आरम्भक प्रायः युवक ही होते हैं, कम-से-कम उनके सहयोगके बिना नूतन समाजकी प्रतिष्ठा नहीं होती। इसका कारण यह है कि युवकमे साहस, शौर्य, तेज और त्यागकी भावना प्रबल होती है। वह अभी ससारके कीचडमे नहीं फँसा है, इसलिए वह वस्तुस्थितिकी भी उपेक्षा कर आदर्शके लिए आत्म-बलिदान करनेके लिए उद्यत हो जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि उसकी अभी कोई ऐसी दृष्टि नहीं बनी है जो उसको समाजकी नवीन आवश्यकताओके समझनेसे रोके। इसके विपरीत इन आवश्यकताओका उसे विशेष अनुभव होता है। अतीतसे नाता तोड़नेमे उसे वह कठिनाई नहीं होती जो वृद्धोको होती है।

जिस समाजमे ऐसी अवस्था उत्पन्न होने लगती है, वहाँ नये समाजका उपक्रम करनेके लिए युवकोका आन्दोलन आरम्भ हो जाता है और युवक अपनी सस्थाएँ बनाने लगते हैं। जबतक ऐसी अवस्था उत्पन्न नहीं हो जाती, तबतक किसी समाजमे युवक-आन्दोलनकी सृष्टि नहीं होती। युवक-आन्दोलनका होना, न होना इसपर भी आश्रित है कि उस जाति-विशेषका क्या स्वभाव है और उस समाजकी परम्परा क्या रही है। यदि लोग समयसे सुधार करनेके अभ्यस्त हैं और सकटकी अवस्थाको टालना जानते हैं तो युवक-आन्दोलन कदाचित् न भी हो। किन्तु जो जाति क्रान्तिप्रिय है और जहाँके समाज-नेता काफी दूरदर्शी नहीं हैं तथा अपने कट्टरपनके कारण समझौतेके लिए तैयार नहीं हो पाते, वहाँ युवक-आन्दोलन और सगठनका होना अनिवार्य हो जाता है।

साधारणतः समाजको नवयुवकोकी प्रसुप्त शक्तियोका उपयोग करनेकी आवश्यकता

नहीं पड़ती। वृद्ध होनेपर वह पुरानी पीढ़ीका स्थान लेते हैं। किन्तु जब किसी समाजके जीवन-मरणका प्रश्न उपस्थित हो जाता है, जैसा कि युद्धके समय होता है, तब युवकोकी प्रसुप्त शक्तियोंका उपयोग किये बिना संकट टल नहीं सकता। जब कभी कोई आकस्मिक संकट आ जाता है अथवा समाजको नवीन दृष्टिको आवश्यकता होती है, तब युवकोके शक्ति-भण्डारका उपयोग करना ही पड़ता है।

आज पुराने युगका अन्त हो रहा है और हम एक नवीन युगमें प्रवेश कर रहे हैं, सारे संसारका यही हाल है। यह संक्रमण-काल है। युद्धके पश्चात् जीवनके मूल्य सर्वत्र बदल रहे हैं। पुरानी सस्थाएँ जीर्ण-शीर्ण हो रही हैं और उनके आधारभूत विचारोंपरसे लोगोकी आस्था उठती जा रही है। समाजको एक नये दर्शनकी आवश्यकता है, जो उसका पथ-प्रदर्शक हो।

उद्देश्यकी आवश्यकता

यो तो प्रत्येक समाज नवीन परिस्थितिके अनुकूल अपना आचरण और व्यवहार बदलनेका प्रयत्न करता है, किन्तु जबतक किसी महान् उद्देश्यकी गम्भीर अनुभूति नहीं होती, तबतक समाजमें सामञ्जस्य और स्थिरता नहीं आती और उसकी समग्रता नष्ट होने लगती है। इस नवीन दर्शनमें नवयुवकोकी ही आस्था होती है। उन्होंने ही इन नवीन मूल्योंकी सृष्टि की है और उन्हींको उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना है।

यही कारण है कि हम सर्वत्र देखते हैं कि नवयुवक समाजका नेतृत्व करने आगे आ रहे हैं। नव समाजमें, जिसका इतिहास पुराना नहीं है, नवयुवकोका स्वागत होता है और वह शीघ्र ही अधिकारारूढ हो जाते हैं, किन्तु पुरातन समाजमें वृद्धोका वही पुराना स्थान अब भी चला आता है। उसमें युवकके अधिकार स्वीकार नहीं किये जाते।

इसलिए नवयुगके लानेमें देर होती है। युवकोको अपनी कल्पनाके बलसे नयी नीति बनानेका अवसर नहीं मिलता। अतः उनका असन्तोष बढ़ता है और वह अपनी शक्तियोंका सदुपयोग रचनात्मक कार्यमें न कर, टीकाटिप्पणी और आलोचनामें ही उन्हें नष्ट कर देते हैं। इससे समाजका ग्रहित ही होता है।

यह ठीक है कि पुरानी परम्पराकी रक्षाके लिए वृद्धोका रहना भी आवश्यक है, किन्तु उनको यह स्वीकार करना चाहिये कि अब समय आ गया है जब उन्हें युवकोको जिम्मेदारीके पदोंपर बैठाना चाहिये।

अपने देशमें यह बात अभीतक पूरी तरह नहीं मानी गयी है, किन्तु जबतक हम युवकोंका अधिकार स्वीकार न करेंगे, तबतक नये समाजकी रचनाका काम सफल न होगा। चूंकि मन्त्रिमण्डलमें प्रायः युवक ही हैं और आगसानकी अवस्था केवल बत्तीस वर्षकी थी। किन्तु हमारे यहाँके केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे युवक कहा जा सकता है। कांग्रेसकी वर्किंग कमेटीका भी यही हाल है। पण्डित जवाहरलालने अपने सभापतित्वमें तीन-चार युवकोको स्थान दिया था, किन्तु उनके हट जानेके बाद वे लोग भी हटा दिये गये। हमारे पुराने नेताओंको युवकोके साथ मिलकर काम करनेमें

असुविधा होती है, इसमें केवल एक अपवाद है—पण्डित जवाहरलाल । जवाहरलालजीने नयी नीतिका सूत्रपात किया था और वह सदा इस बातको अनुभव करते हैं कि युवकोके अधिकारको स्वीकार करना चाहिये, किन्तु कोई परम्परा नहीं बन पाती ।

यदि युवकोका अधिकार स्वीकार कर लिया जाय तो इसके कई लाभ हैं । पहली बात तो यह समझनेकी है कि जो आज अधिकारारूढ है उनका कर्तव्य है कि वे अपने उत्तराधिकारियोंको आजसे तैयार करें । अन्यथा इन वृद्धोके हट जानेपर उनकी जगह लेनेवाले योग्य अनुभवी व्यक्ति न मिलेंगे । दूसरी बात यह है कि भारतके स्वतन्त्र होनेपर जो बड़ी जिम्मेदारी देशपर आ गयी है, उसको सहन करनेकी शक्ति कुछ वृद्धोको छोड़कर अन्य वृद्धोमें नहीं है । पुन नूतन समाजकी रचनाका और प्रचलित सामाजिक पद्धतिको तोड़नेका युवकमें सामर्थ्य है । जो समाज नया उपक्रम करना चाहता है और जिसको क्रान्तिकारी परिवर्तनकी आवश्यकता है, उसको युवकका सहयोग अवश्य चाहिये और यह सहयोग युवकके अधिकारको स्वीकार करके ही प्राप्त हो सकता है ।

स्वतन्त्र राष्ट्रके विद्यार्थियोंको हड़ताल करते हम नहीं सुनते । उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती । परतन्त्र राष्ट्रके विद्यार्थी राजनीतिक आन्दोलनोमें खूब भाग लेते हैं । उनको समय-समयपर प्रदर्शन और हड़ताल करनी पड़ती है, राजाके अधिकारियोंके साथ सघर्ष होनेसे उनको गोली भी खानी पड़ती है । ऐसे वातावरणमें रहनेसे उनकी एक विशेष प्रकारकी मनोवृत्ति बन जाती है ।

किन्तु जब राष्ट्र स्वतन्त्र हो जाता है, तब यही मनोवृत्ति हानिकारक सिद्ध होती है । राष्ट्रके संचालकोका कर्तव्य है कि बदली हुई परिस्थितिमें वे ऐसे विधानो और उपायोका अवलम्ब लें जिनसे युवकोकी मनोवृत्ति बदले और वह अपनी शक्तियोंका विनियोग रचनात्मक कामोमें करे । पहले तो पुराने अभ्यासको छोड़ना कठिन होता है और दूसरे जब समाजके नेता पुरानी वृत्तिको बदलनेका प्रयास नहीं करते, तब कठिनाई और बढ़ जाती है । पुरानी मनोवृत्तिको बदलनेका उपाय युवकके अधिकारको स्वीकार करना है । यदि आजकी पीढ़ी आनेवाली पीढ़ीकी शिक्षा-दीक्षाका भार अपने ऊपर न लेगी और उसको विकासका अवसर न देगी, तो वह इतिहासके सम्मुख दोषी ठहरायी जायेगी ।

राष्ट्र-निर्माणका कार्य अभी आरम्भ भी नहीं हुआ है । प्रत्येक दिशामें हमको प्रगति करनी है । शताब्दियोंका रास्ता थोड़े वर्षोंमें तय करना है । लोकतन्त्रकी स्थापनाके लिए सार्वजनिक शिक्षाकी आवश्यकता है । इसके लिए अस्पृश्यताका निवारण और जातपातके कठोर बन्धनोको तोड़ना भी जरूरी है । लोकतन्त्र अभ्यासका विषय है, केवल लोकतन्त्रका पाठ पढ़नेसे और उसका नारा लगानेसे उसकी स्थापना नहीं होती ।

इसलिए सहयोगका प्रचार कर सामाजिक सम्बन्धोको बदलना तथा नयी आर्थिक पद्धतिको प्रतिष्ठित करना नितान्त आवश्यक है । सुन्दर भविष्यके निर्माणके लिए आज सर्वसाधारणसे त्यागकी अपील करनी है, किन्तु जबतक कोई ऐसा उद्देश्य समाजके सम्मुख नहीं रखा जाता जिसके लिए लोग श्रम करे, तबतक त्यागकी आशा करना व्यर्थ है ।

इन सब कामोंके लिए युवककी आदर्शप्रियता, उसकी निर्भीकता, उसका साहस और उसकी लगन चाहिये । यह तभी हो सकता है जब हम युवकके अधिकारको स्वीकार करें ।

यदि हम इस विषयमें अपने कर्तव्यका पालन न करेंगे तो भय है कि हमारा युवक कहीं गैरजिम्मेदार न हो जाय ।

विद्यार्थी समाजकी उच्छृंखलता विदेशी शासनसे लड़नेका एक अनिवार्य फल है । एक अर्थमें कांग्रेस-कार्यकर्त्ता भी उच्छृंखल थे । किन्तु स्वतन्त्रताकी जो कीमत हमको अदा करनी थी, उसमें यह भी शामिल था ।

युवकको अधिकार दो

लेकिन अब समय आ गया है जब विद्यार्थियोंको आत्म-शासनके महत्त्वको समझना चाहिये । आजकी उच्छृंखलताके बदलेमें कोई सार वस्तु नहीं मिलती । इतना ही नहीं, उससे समाजका अनिष्ट ही होगा । यह उच्छृंखलता युवकके अधिकारको स्वीकार करनेसे ही दूर होगी ।

इस सम्बन्धमें एक बात और विचारनेके योग्य है । युवक शक्तिका भण्डार होता है । जिस परिस्थितिमें रहता है उससे वह अत्यन्त प्रभावित होता है । वह भावप्रवण होता है तथा शूरता दिखानेके किसी अवसरको वह छोड़ना नहीं चाहता । यदि उसका समाज स्वतन्त्र होनेकी चेष्टा कर रहा है, तो वह उसीमें लग जाता है और यदि उसका समाज साम्प्रदायिक युद्धमें लगा है, तो वह उसका अगुआ बनना चाहता है । यदि इस दृष्टिसे देखा जाय, तो युवक न प्रगतिशील है और न प्रतित्रियावादी । वह किसी भी नये काममें लगाया जा सकता है । शर्त यह है कि उसकी भावना पूरी होनी चाहिये और उसे कामका मौका मिलना चाहिये ।

इसलिए यदि हम युवककी शक्तिका सदुपयोग नहीं करेंगे तो दूसरे उसका दुरुपयोग करेंगे । फासिस्ट राष्ट्रोने युवककी शक्तिके महत्त्वको समझा और अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए उसका दुरुपयोग किया ।

क्या हम राष्ट्र-निर्माणके कार्यके लिए युवकोंके अधिकारको स्वीकार नहीं करेंगे ? मैं यह जानता हूँ कि प्रत्येक अधिकारके साथ कर्तव्य होता है । किन्तु आजकी परिस्थितिमें अधिकारको स्वीकार करके ही कर्तव्यकी बात कही जा सकती है । स्थूल सत्य यह है कि आजकी किसी भी समस्याका समाधान युवकोंके सहयोग बिना समुचित रूपसे नहीं हो सकता ।^१

विद्यार्थियोंका राजनीतिमें स्थान

हमारे देशमें विद्यार्थियोंकी अनेक समस्याएँ हैं । इनमेंसे दोको छोड़कर शेष सब साम्प्रदायिक हैं । दो समस्याएँ जिनमें सब सम्प्रदायके विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं

‘स्टूडेंट्स कांग्रेस’ और ‘स्टूडेंट्स फेडरेशन’ है। पहली राष्ट्रीय कांग्रेसकी समर्थक है और इसका विद्यार्थी-समाजपर सबसे अधिक प्रभाव है। दूसरी कम्युनिस्टोके प्रभावमे है, किन्तु कम्युनिस्टोकी राष्ट्र-विरोधी नीति और अवसरवादिताके कारण उसका प्रभाव विलुप्त हो गया है। सम्प्रदायवाद हमारे देशका एक विशेष रोग है। इसलिए साम्प्रदायिक राजनीतिक संस्थाओके साथ-साथ विद्यार्थियोंकी भी साम्प्रदायिक संस्थाएँ सगठित हो गयी हैं, किन्तु इनका सगठन क्षीण और दुर्बल है। इन संस्थाओमे लीगी विद्यार्थियोंकी संस्थाकी प्रधानता है, पर यह भी अभीतक समुचित रूपसे सगठित नहीं हो पायी है। राष्ट्रीय मुसलिम विद्यार्थियोंकी भी अपनी संस्था है। यह लीगी विद्यार्थियोंकी संस्थाका जवाब है। अन्य साम्प्रदायिक संस्थाएँ कांग्रेसके विरुद्ध नहीं हैं, किन्तु साम्प्रदायिक प्रश्नोके सम्बन्धमे उनकी दृष्टि सकुचित है, राष्ट्रीय नहीं है। इस प्रकार केवल लीगी और कम्युनिस्ट विद्यार्थियोंकी संस्थाएँ कांग्रेस-विरोधी हैं। इस समय लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और डा० अम्बेडकरकी शिड्यूल्ड कास्ट पार्टीका गठ बन्धन-सा हो गया है। इस सयुक्त मोर्चेका एकमात्र आधार कांग्रेसका विरोध करना है, अन्यथा इन विविध दलोके उद्देश्य और उनकी कार्यप्रणाली असमान हैं। सयुक्त मोर्चेका यह एक नवीन, विकृत और निकृष्ट रूप है।

यूरोपके देशोमे राजनीतिक दलोसे सम्बद्ध विद्यार्थियोंकी संस्थाएँ होती हैं। किन्तु प्रत्येक दलसे सम्बद्ध विद्यार्थी-संस्थाका होना आवश्यक नहीं है। प्रायः कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ही अपने विद्यार्थी सदस्योंके लाभके लिए ऐसी संस्था बनाते हैं। अन्य दलोमे इस ओर उपेक्षाका भाव देखा जाता है। जहाँ कहीं कम्युनिस्ट बहुत कमजोर होते हैं, वहाँ अन्य किसी विद्यार्थी-संस्थामे घुस जाते हैं और धीरे-धीरे विविध ढंगसे उसको अपने अधिकारमे ले आते हैं। ऐसा इंग्लैण्डमे भी हुआ। वहाँके मजदूर दलकी ओरसे सन् १९३० के लगभग विश्वविद्यालयोके उन विद्यार्थियोंके लिए, जो मजदूर दलकी राजनीति स्वीकार करते थे, युनिवर्सिटी लेबर फेडरेशन नामकी एक संस्था स्थापित की गयी थी। किन्तु मजदूर दलने इस संस्थामे काफी दिलचस्पी नहीं ली और इस कारण कम्युनिस्टोको उसपर अधिकार जमानेका सुयोग मिला। गत महायुद्धके प्रारम्भ होनेपर कम्युनिस्टोके प्रभावसे इस संस्थाने सन् १९४० मे जर्मनीके विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ करनेकी नीतिकी निन्दा की और जर्मनीसे सुलह करनेकी माँग पेश की। उस समय आर्थर ग्रीनउड फेडरेशनके सभापति थे। ज्यों ही उनका ध्यान उक्त प्रस्तावकी ओर आकृष्ट किया गया, त्यों ही उन्होंने अपने पदसे इस्तीफा दे दिया। इसपर सम्मेलनने यह घोषित किया कि मिस्टर ग्रीनउड तथा मजदूर नेता युद्धका समर्थन कर समाजवाद तथा मजदूर वर्गके हितोके साथ दगा कर रहे हैं। इस सम्मेलनके बाद ही मजदूर दलसे फेडरेशनका सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया। गत सम्मेलनमे उसका नाम ‘स्टूडेंट लेबर फेडरेशन’ रखा गया। नाम बदलनेका कारण यह बताया गया कि विश्वविद्यालयोके अतिरिक्त ट्रेनिङ्ग कालेजोके विद्यार्थियोंको भी सम्मिलित करना है किन्तु वास्तविक कारण यह था कि अपनी युद्धकालीन नीतिके

कारण संस्था वदनाम हो गयी थी । इस वर्ष इस संस्थाने मजदूर दलसे पुनः सम्बद्ध होनेकी प्रार्थना की, पर यह प्रार्थना अस्वीकृत हुई ।

इसी प्रकार हमारे देशमें भी गत युद्धके आरम्भ होनेपर स्टूडेण्ट्स फेडरेशनमें फूट पड़ गयी थी । यहाँ राजनीतिक दलोसे सम्बद्ध विद्यार्थी-संस्थाएँ नहीं थी । विद्यार्थी-समाजकी एक ही प्रधान संस्था थी । परतन्त्र देशमें साम्राज्यवादका सफल विरोध करनेके लिए विविध वर्गोंका संयुक्त मोर्चा आवश्यक होता है । कांग्रेस ही यह संयुक्त मोर्चा है । इसके भीतर रहकर ही भिन्न-भिन्न विचारधाराके दल संयुक्त मोर्चेको पुष्ट और सबल बनाते हैं । ऐसी अवस्थामें कांग्रेसके भीतर रहनेवाले राजनीतिक दल अलग-अलग विद्यार्थी-संस्थाओंका निर्माण नहीं करते । कांग्रेसके समान वह सब एक ही विद्यार्थी-संस्थामें रहकर काम करते हैं । किन्तु मुसलिम लीगकी घातक नीतिके कारण यहाँ साम्प्रदायिक विद्यार्थी-संस्थाएँ बनने लगी । लीगने यह कार्य आरम्भ किया और उसकी देखादेखी अन्य सम्प्रदायोंने भी अपनी-अपनी अलग संस्था बना डाली । युद्धके पहले कम्युनिस्ट भी औरोंके साथ एक ही संस्थामें काम करते थे । किन्तु, क्योंकि वह अपनेको क्रान्तिका एक मात्र ठेकेदार समझते हैं, इसलिए जब कभी उनको क्रान्तिकी सम्भावना प्रतीत होती है, तब वह उन सब संस्थाओंपर एकाधिकार प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं, जिनका उपयोग वह समझते हैं कि क्रान्तिके लिए किया जा सकता है और यदि वह इसमें सफलताकी आशा नहीं रखते तो संस्थामें फूट डाल देते हैं और उसको दो टुकड़ोंमें विभक्त कर देते हैं । इसी नीतिके अनुसार कम्युनिस्टोंने नागपुरके अधिवेशनमें भेदकी ऐतिहासिक आवश्यकताको बताते हुए फेडरेशनको दो भागोंमें विभक्त कर दिया । कम्युनिस्ट और उनके हमराही एक ओर थे और दूसरी ओर थे राष्ट्रवादी विद्यार्थी जिनमें कांग्रेस समाजवादी भी शामिल थे ।

अगस्त सन् ४२ के आन्दोलनके कारण राष्ट्रवादी विद्यार्थी जेलोंमें बन्द कर दिये गये और क्योंकि कम्युनिस्टोंका उस समय 'जनयुद्ध' का नारा था और वह विदेशी साम्राज्यवादसे सहयोग कर रहे थे इसलिए वह जेलोंके बाहर थे । इस परिस्थितिका उन्होंने पूरा-पूरा लाभ उठाया, किन्तु यह लाभ चिरस्थायी न हो सका । अपनी देश-विद्रोही नीतिके कारण वह बहुत वदनाम हो गये और विद्यार्थी-समाजमें उनका प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगा । उनके दुर्भाग्यसे राष्ट्रवादी विद्यार्थियोंने सन् ४४ में अपने संगठनको सुदृढ़ किया और स्टूडेण्ट्स कांग्रेसको जन्म दिया ।

इसी प्रकार इंग्लैण्डमें भी फेडरेशनका प्रभाव घटने लगा । विश्वविद्यालयोंके जिन विद्यार्थियोंने युद्धमें भाग लिया उनकी दृष्टि नूतन अनुभवोंके कारण अन्य विद्यार्थियोंकी अपेक्षा अधिक परिपक्व हो गयी और उनके नेतृत्वमें केम्ब्रिज, आक्सफोर्ड और लन्दनके विद्यार्थियोंकी समाजवादी सोसाइटियाँ बनने लगी और इनका सम्बन्ध फेडरेशनसे न होकर स्थानीय मजदूर दलसे होने लगा ।

इसमें सन्देह नहीं कि इन स्थानोंमें अन्य संस्थाएँ भी हैं, जो कम्युनिस्टोंके प्रभावमें हैं और जो एस० एल० एफ० (S. L. F.) से सम्बद्ध हैं । यदि इंग्लैण्डका मजदूर दल

इस विषयमें अपनी कोई व्यापक नीति स्थिर करे और समस्त देशके लिए अपनी सरक्षतामें विद्यार्थियोंकी कोई संस्था स्थापित करे तो कम्युनिस्टोंका प्रभाव तेजीसे कम हो सकता है । किन्तु मजदूर दलकी उदासीनताके कारण काम नहीं हो रहा है । यह उदासीनता विद्यार्थी-संस्थाओंतक ही सीमित नहीं है । किन्तु युवक-संघके विषयमें भी ऐसी ही उदासीनता पायी जाती है । पहले एक लेबर लीग आन्व यूथ (Labour League of Youth) था, किन्तु कुछ समयसे यह संस्था मृत-सी है और मजदूर दल उसको फिरसे संगठित करनेमें कोई निश्चित मत नहीं रखता ।

अभी हालमें जो मजदूर सम्मेलन बौर्नमथ (Bournemouth) में हुआ था वहाँ लीगको फिरसे संगठित करनेके प्रश्नपर विचार किया गया, किन्तु प्रस्ताव गिर गया । तिसपर भी जगह-जगह मजदूर युवकोंके समूह बन रहे हैं और शीघ्र ही मजदूर दलको इस विषयमें कोई-न-कोई निश्चय करना पड़ेगा ।

एक राष्ट्रीय संस्थाका न होना वहाँके मजदूर विद्यार्थियोंको खटकता है और वह इस बातका प्रयत्न कर रहे हैं कि मजदूर दल इस कमीको शीघ्र पूरा करे । अभी करीब पाँच महीने हुए कि केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेबर क्लबने मजदूर दलके सहयोगसे समाजवादी युवकोंका एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किंग्स कालेजमें आमन्त्रित किया था, जिसमें हालैण्ड, बेलजियम, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इटलीसे प्रतिनिधि आये थे । कई अन्य देशोंके भी प्रतिनिधि बुलाये गये थे, किन्तु कुछ कठिनाइयोंके कारण वह सम्मिलित न हो सके । सम्मेलनमें आये हुए प्रतिनिधियोंने जो विवरण दिया, उससे पता चलता है कि यूरोपके विविध देशोंमें विद्यार्थी तथा युवक संस्थाओंकी अच्छी उन्नति हो रही है और इस विषयमें ब्रिटिश मजदूर दल बहुत पिछड़ा हुआ है । अन्य देशोंमें इंग्लैण्डकी अपेक्षा कहीं बड़े पैमानेपर युवक-संगठन बन चुके हैं और यह केवल विश्वविद्यालयोंतक ही नहीं सीमित है । इटलीमें सोशलिस्ट युवक-संस्थाके सदस्योंकी संख्या एक लाखसे ऊपर है, बेलजियममें २० हजारसे ऊपर और नार्वेमें ५० हजारसे ऊपर है । अनेक देशोंके युवकोंने गत युद्धमें भूमिगत (गुप्त) आन्दोलनमें अच्छा भाग लिया था और अपनी वीरता, साहस और संगठन-शक्तिका परिचय दिया था । यह बात इटलीपर विशेष रूपसे लागू है और यही कारण है कि वहाँके युवक-संघका सोशलिस्ट पार्टीमें अच्छा प्रभाव है ।

इस कान्फरेन्समें एक बड़े महत्त्वके प्रश्नपर विचार हुआ । प्रश्न यह था कि इन विद्यार्थियों और युवक-संस्थाओंका अपनी पार्टियोंमें क्या सम्बन्ध रहे । यह प्रश्न हमारे लिए भी महत्त्वका है । हमको केवल स्टूडेंट्स कांग्रेसके सम्बन्धमें ही विचार करना है । हमारे यहाँ प्रश्नका रूप यह है कि इस विद्यार्थी-संस्थाका राष्ट्रीय कांग्रेससे क्या सम्बन्ध हो ? क्या स्टूडेंट्स कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेससे स्वतन्त्र हो ? क्या उसको अपनी नीति निर्धारित करनेकी और उस नीतिको स्वीकृत करानेके लिए राष्ट्रीय कांग्रेसपर दबाव डालनेकी स्वतन्त्रता दी जाय ?

उक्त कान्फरेन्समें आये हुए प्रतिनिधियोंमें इस विषयपर तीव्र मतभेद था । इटली,

बेलजियम और फ्रांसके प्रतिनिधि इन संस्थाओंको अपनी नीति स्थिर करनेकी स्वतन्त्रता देनेके पक्षमें थे, किन्तु नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैण्ड और हालैण्डके प्रतिनिधि इस मतके विरुद्ध थे। उनका कहना था कि ऐसी स्वतन्त्रता देनेसे पार्टी और युवक-संस्थामें भेद होनेका बड़ा भय है। डेनमार्क, नार्वे और स्वीडनमें युवकोंका संगठन मजदूरदलद्वारा हुआ है, किन्तु इनका मुख्य काम शिक्षासम्बन्धी रहा है। पार्टीसे भिन्न इनकी कोई नीति नहीं है और नीति निर्धारित करना इनका काम नहीं है। ये संस्थाएँ केवल नये सदस्योंकी भर्ती करती हैं। जब इनको पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है और राजनीतिक कार्यका कुछ अनुभव हो जाता है, तब उनको दलभुक्त होनेके लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

गत अप्रैलमें परफिगुअन, फ्रांस (Perfiguan, France) में जो सोशलिस्ट यूथ इण्टर नेशनल (Socialist Youth International) स्थापित हुआ था, वहाँ भी ऐसा ही भेद प्रकट हुआ था। सार्वदेशिक मजदूर युवक संस्थाके अभावमें इस सम्मेलनमें इंग्लैण्डका कोई प्रतिनिधि न था। किन्तु Presidium में एक स्थान इंग्लैण्डके लिए सुरक्षित रखा गया है। इण्टर नेगनलकी अगली बैठक गत सितम्बरमें पेरिसमें होनेवाली थी। हमारे यहाँ भी इस प्रश्नपर मतभेद है। स्टूडेंट्स कांग्रेस कभी-कभी राजनीतिक प्रश्नोंपर अपना स्वतन्त्र मत प्रकट करती है, यद्यपि ऐसे अवसर कम ही आते हैं। प्रश्न यह है कि स्टूडेंट्स कांग्रेसको ऐसी स्वतन्त्रता देनी चाहिये अथवा नहीं। जावितेसे स्टूडेंट्स कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेससे सम्बद्ध नहीं है, किन्तु उसके सदस्य यही मानते हैं कि यह संस्था कांग्रेसकी नीतिको स्वीकार करती है तथा किसी अवस्थामें उसका विरोध नहीं करेगी। सच यह है कि इसी कारण आज इसका इतना प्रभाव है। इस प्रभावको अक्षुण्ण रखनेके लिए आवश्यक है कि वह कांग्रेसका विरोध न करे, फिर भी यह प्रश्न शेष रह जाता है कि स्टूडेंट्स कांग्रेसको राजनीतिक प्रश्नोंपर अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने तथा नये सुझाव करनेका अधिकार होना चाहिये या नहीं? हमारे देशके कुछ नेता ऐसी स्वतन्त्रता नहीं देना चाहते, किन्तु अभी तक अधिकृत रूपसे कांग्रेसकी ओरसे कुछ कहा नहीं गया है। हम देखेंगे कि यूरोपके जिन देशोंकी युवक संस्थाएँ ऐसी स्वतन्त्रताकी माँग पेश करती हैं, वे वे देश हैं जहाँके नवयुवकोंने युद्धके जमानेमें संगठित रूपसे शत्रुओंका तीव्र प्रतिकार किया था और अपने माहस, त्याग और शौर्यके कारण ख्याति पायी थी। इस कारण उनमें आत्मविश्वास बड़ा और उन्होंने अपना महत्त्व समझा। अब वह अपना स्वतन्त्र मत रखना चाहते हैं और अपनी पार्टीके निश्चयोंको प्रभावकारी करना चाहते हैं। उनकी दृष्टिमें शिक्षाका कार्य उनके लिए काफी नहीं है। वे अपना मुख्य कार्य राजनीतिक समझते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका अपनी पार्टीमें विश्वास नहीं है, किन्तु इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वे पार्टीकी नीति निर्धारित करनेमें हाथ बँटाना चाहते हैं। युद्धकालीन नये अनुभवोंके कारण उनकी दृष्टि पुराने नेताओंकी अपेक्षा नवीन है और वे समझते हैं कि यदि नीति स्थिर करनेमें वे सहायक हों, तो पार्टीके लिए कदाचित् अधिक हितकर हो। पार्टीके प्रति वे वफादार हैं, किन्तु वे यह चाहते हैं कि पार्टीकी नीतिको प्रभावित करनेका उनको अधिकार हो। युद्धके कारण जो असाधारण अवस्था उत्पन्न

हुई, उसके कारण इन देशोंके युवकोंको वे कार्य करने पड़े, जो शायद शान्तिकी अवस्थामें न करने पड़ते और इसी कारण उनको नेतृत्वका भी अवसर मिला ।

दूसरी ओर वे देश जो इस मतका विरोध करते हैं वे ऐसे हैं, जहाँ परम्पराके प्रति बड़ा आदर है और जहाँके युवकोंको राजनीतिक चेतनाके विकासका ऐसा अवसर नहीं मिला । इसके अलावा इन देशोंमें या तो सुप्त आन्दोलन नहीं हुए या ये आन्दोलन उतने उग्र और प्रबल नहीं थे ।

हमने संक्षेपमें इस अन्तरका कारण बताया । किन्तु प्रश्न यह है कि इन संस्थाओंके लिए इष्ट क्या है ? इसमें सन्देह नहीं कि जब हम इस प्रश्नका निर्णय करें, हमको देश-विशेषकी परिस्थिति तथा वहाँके युवकोंकी मनोवृत्तिको ध्यानमें रखना होगा । हम इनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते । अब फर्मानोका युग नहीं है । इसके अलावा 'पुरानी पीढ़ी और नयी पीढ़ीमें इतना अन्तर है कि पुरानी पीढ़ीके वे लोग जो नयी पीढ़ीके सम्पर्कमें नहीं आये हैं और जिनको उनका विश्वास नहीं प्राप्त है वे उनकी मनोवृत्तिको ठीक-ठीक समझ भी नहीं सकते । ऐसी अवस्थामें उनको इस प्रश्नका निर्णय करनेमें धैर्यसे काम लेना चाहिये । १९४२ के आन्दोलनमें प्रमुख भाग लेनेके कारण तथा विद्यार्थी-आन्दोलनका मुख्य ध्येय राजनीतिक होनेके कारण हमारे देशके विद्यार्थियोंने राजनीतिक क्षेत्रमें अपना स्थान बना लिया है । यही अवस्था चीनकी रही है । इसलिए यदि वे कुछ स्वतन्त्रताकी माँग करें तो इसपर हमको आश्चर्य न होना चाहिये । हम चाहते हैं कि कुछ स्वतन्त्रता उनको दी जाय । इसमें कई लाभ हैं । पहले तो ऐसा करनेसे उनका आप्यायन होगा । पुनः कांग्रेसके नेताओंको युवकोंके विचारोंसे अवगत होनेका अवसर मिलता रहेगा । पर इस स्वतन्त्रताकी मर्यादा भी निश्चित कर देनी होगी । जबतक कोई प्रश्न विचार-कोटिमें हो तबतक उसपर अपना विचार व्यक्त करनेके लिए स्टूडेंट्स कांग्रेसको स्वतन्त्रता रहनी चाहिये, किन्तु जब राष्ट्रीय कांग्रेस उस प्रश्नपर अपना निश्चय दे दे, तब वाद-विवाद बन्द हो जाना चाहिये । इसके अलावा कार्यमें एकता होनी चाहिये । इसमें भिन्नता ठीक नहीं है । ऐसा होनेसे परस्परका सम्बन्ध कटु हो जायगा, जो देशके लिए हानिकर होगा । इस समय स्टूडेंट्स कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेससे सम्बद्ध नहीं है । हम समझते हैं कि जाव्तेका सम्बन्ध मुनासिब भी न होगा । इसलिए मर्यादित स्वतन्त्रता देना और भी ठीक होगा ।'

योग्य शिक्षकोंकी कमी

अभी कुछ दिन हुए ट्रेनिंग कालेज प्रयागके विद्यार्थियोंका चुनाव करनेके लिए गवर्नमेण्टद्वारा नियुक्त कमेटीकी बैठकमें सम्मिलित होने में प्रयाग गया था । आवेदन-पत्रोंके देखनेसे पता चला कि प्रथम श्रेणीके विद्यार्थियोंकी सख्या बहुत थोड़ी है, एक प्रकारसे

नहींके बराबर है। इधर मैंने सुन रखा था कि योग्य शिक्षक नहीं मिलते, उनका नितान्त अभाव है। एक ओर शिक्षाका विस्तार हो रहा है, दूसरी ओर नये स्कूलोंके लिए अच्छे शिक्षकोंके मिलनेमें बड़ी कठिनाई होती है। मालूम होता है अध्यापकोंके पेशेके लिए आकर्षण बहुत कम हो गया है। गत महायुद्धके जमानेमें कई नये विभाग खुले जिनमें प्रवेश पानेके लिए विशेष योग्यताकी आवश्यकता न थी, किन्तु पुरस्कार अध्यापकोंके पुरस्कारकी अपेक्षा कहीं अधिक था। सुशिक्षित युवकोंकी कमीके कारण हर तरहके लोग इन विभागोंमें भर्ती किये गये। युद्धके समाप्त होनेके पश्चात् भी नित्य नये विभाग खुलते जाते हैं। इन नयी नौकरियोंका पुरस्कार भी अच्छा है। इनके लिए अवश्य ग्रैजुएट होनेकी शर्त रखी गयी है। जाँचसे मालूम हुआ कि इन नये स्थानोंके लिए अधिक योग्य व्यक्ति उम्मीदवार होते हैं, दूसरा कारण यही है कि इनको अच्छा पुरस्कार मिलता है। उधर वेतन (Pay) कमीशनने सब वर्गके कर्मचारियोंके पुरस्कारमें वृद्धि की है। यह ठीक है कि अध्यापकोंके पुरस्कारमें भी वृद्धि हुई है, किन्तु इनका पुरस्कार दूसरे वर्गोंकी अपेक्षा कम है। यही कारण है कि अध्यापनके कार्यके लिए योग्य शिक्षकोंकी कमी होती जाती है। उच्च श्रेणीमें उत्तीर्ण होनेवाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रान्तीय सिविल सर्विस, इण्डियन सिविल सर्विस या पुलिस सर्विसमें चले जाते हैं, क्योंकि इनकी परीक्षा होती है और सफारिशका वह महत्त्व नहीं रह गया है जो पहले था। जो इन स्थानोंको नहीं पा सकते थे उनमेंसे ही छूट-छूटकर कुछ अध्यापक हो जाते थे। किन्तु निम्न श्रेणीके अध्यापकोंके मिलनेमें इतनी कठिनाई नहीं होती थी, पर इधर कुछ वर्षोंसे नौकरीके कुछ नये सींगे खुल जानेसे इनके मिलनेमें भी कठिनाई हो गयी है।

यदि समाजमें लोकतन्त्रकी स्थापना करनी है तो जनताको शिक्षित करना आवश्यक हो जाता है। सार्वजनिक शिक्षा ही जनतन्त्रका आधार है। किन्तु यदि शिक्षाके सब विभागोंके लिए योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे तो शिक्षाके विस्तारकी उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती। लोकतन्त्रके लिए प्राथमिक शिक्षा अब पर्याप्त नहीं समझी जाती। प्रत्येक व्यक्तिको कमसे कम मौलिक शिक्षा (basic education) मिलना चाहिये, जिसमें वह समाजके प्रति अपने कर्तव्यको समझ सके और शासनमें हाथ बँटा सके।

प्राचीन कालमें शिक्षा देनेका भार ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु, पादरी या मौलवियोंपर था। समाजमें उनके लिए बड़ा सम्मान था। केवल भोजन और वस्त्र लेकर ही वह समाजकी शिक्षाकी व्यवस्था करते थे। दानशील व्यक्ति और राज्यकी ओरसे इनकी संस्थाओंको सहायता मिलती थी। गाँवमें भिक्षु या ब्राह्मण अपनी टोली खोल देते थे और बालकोंको प्रारम्भिक शिक्षा देते थे। जगह-जगह उच्च शिक्षाकी भी व्यवस्था थी। मठ या सधारामोंमें बड़े पैमानेपर शिक्षाका आयोजन होता था। इस प्रकार पुराने समाजमें कम व्ययसे ही शिक्षाके प्रसारका कार्य होता था। जो शिक्षक थे उनको समाज आदरकी दृष्टिसे देखता था। किन्तु आज मनुष्यका मापदण्ड रूपया हो गया है। जिसके पास अधिक धन है उसीका आदर है। स्कूलके अध्यापकोंको न अच्छा वेतन मिलता है, न समाजमें उसका आदर ही है और न उसको कोई अधिकार ही-प्राप्त है। ऐसी अवस्थामें प्रतिभाशाली

व्यक्तिके लिए अध्यापकका कार्य आकर्षक नहीं है। राष्ट्रीय आन्दोलनमें जो उच्च शिक्षाप्राप्त लोगोकी कमी है, उसका एक कारण यह भी है कि प्रथम महायुद्धके बाद सरकारी कर्मचारियोंके वेतनमें अति मात्रामे वृद्धि हुई और सिविल सर्विसकी परीक्षा यहाँ भी होने लगी। शिक्षाके क्षेत्रमें योग्य शिक्षकोकी कमीका कारण भी यही है।

यह चिन्ताका विषय है और इसपर गम्भीरताके साथ विचार करनेकी आवश्यकता है। हमारा भविष्य उज्ज्वल हो इसके लिए अध्यापनके कामको आकर्षक बनाना पड़ेगा। आज जब समाजका आर्थिक कष्ट बढ़ गया है और रूपयोंमें मनुष्यकी कीमत आँकी जाती है, तब पुरस्कारकी वृद्धिका प्रश्न अध्यापकके लिए भी महत्त्वका हो जाता है। पुनः नये अधारपर समाजकी व्यवस्था एकाएक नहीं हो सकती। जीवनके प्रेरक हेतु एकाएक बदले नहीं जा सकते। कमसे कम पूँजीवादी समाजमें धनका महत्त्व रहेगा ही। ऐसी अवस्थामें केवल अध्यापकसे त्यागकी आशा रखना ही व्यर्थ है। अतः अध्यापनके कार्यको आकर्षक बनानेका एक ही तरीका है और वह है उसके वेतनमें समुचित वृद्धि। हमारी कठिनाई और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि पुलिस आदि विभागमें पुरस्कारकी कही ज्यादा वृद्धि हुई है। यदि समान योग्यताके लोगोका समान वेतन हो तो असन्तोष नहीं होता। असमानताके कारण असन्तोष बढ़ता है। यह मनुष्यका स्वभाव है। वेतन-वृद्धि करते समय इस बातपर कही भी ध्यान नहीं दिया गया है। समाजमें शान्ति-स्थापनके कार्यको शिक्षाकी अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है। यह सब जगहका हाल है। ससारमें सर्वत्र अध्यापकको सबसे कम पुरस्कार मिलता है। निम्न श्रेणीके अध्यापकोका हाल और भी बुरा है। हमारे देशकी अवस्था इस दृष्टिसे और भी गिरी हुई है। यहाँ विश्वविद्यालयके प्रोफेसरका पुरस्कार प्रारम्भिक स्कूलके शिक्षकके वेतनका २० गुना है, जब कि इंग्लैण्डमें केवल ६ गुना है। इंग्लैण्डमें प्रारम्भिक स्कूलके शिक्षकको उतना ही वेतन मिलता है, जितना उद्योग व्यवसायमें कार्य करनेवाले मजदूरको। अभी गवर्नमेण्ट आफ इण्डियाके 'पे कमीशन' ने यह सिफारिश की है कि अशिक्षित मजदूरकी गुजारे लायक मजदूरी आज ५५) ६० मासिक होनी चाहिये और इसे गवर्नमेण्टने स्वीकार कर लिया है। किन्तु हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूलके अध्यापकको कुल जमा ३३) ६० मिलता है। यह ठीक है कि केन्द्रीय गवर्नमेण्टकी आमदनी कही ज्यादा है और वह इतना मासिक पुरस्कार नियत कर सकती है, किन्तु ऐसा करनेसे प्रान्तीय गवर्नमेण्टकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आमदनीके कुछ सींगे जो प्रान्तोंके होने चाहिये आज केन्द्रीय गवर्नमेण्टके हाथमें हैं। प्रान्तीय गवर्नमेण्टको इन्हे केन्द्रसे वापिस लेना चाहिये और आयके नये द्वार भी खोज निकालने चाहिये। इसके बिना अध्यापकोके पुरस्कारमें और वृद्धि नहीं हो सकेगी और बिना इसके उनको आप सन्तुष्ट न कर सकेगे।

हमने इस प्रश्नके महत्त्वकी ओर ऊपर सकेत किया है और यह कहा है कि यह प्रश्न और देशोंको भी परेशान कर रहा है। अमेरिकामें यह प्रश्न विकट रूप धारण कर रहा है। गत एक वर्षमें ६००० स्कूल बन्द हो चुके हैं। इस वर्ष ७५,००० बच्चोंकी पढ़ाईका प्रबन्ध नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त ५० लाख बच्चोंकी पढ़ाईका जो थोड़ा-बहुत

प्रबन्ध हो सका है, वह नहींके बराबर है। अधिकतर इन बच्चोंकी पढ़ाई अधूरी होगी और वह अपना समय बहुत कुछ बरबाद ही करेंगे। समझा जाता है कि अवस्था और भी बिगड़ती चली जायेगी। 'न्यूयार्क टाइम्स' अखबारके शिक्षा-सम्पादक बेजामिन फाइन (Benjamin Fine) ने ६ महीने खर्च करके इसकी जाँच की है और एक लेखमाला प्रकाशित की है जिससे इस प्रश्नपर काफी रोगनी पड़ती है। उनका निष्कर्ष यह है कि यद्यपि हमारे पब्लिक स्कूलोंपर एक भी हवाई आक्रमण नहीं हुआ है तथापि "वह उसी प्रकार नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हैं जैसे भारी बाम्बरोसे वह हो सकते थे।"

बेजामिन फाइन लिखते हैं कि सामान और इमारतोंकी स्कूलोंमें नितान्त कमी है। पुनः सन् १९४० से ७०,००० प्रतिवर्षके हिसाबसे अध्यापक अपना पेशा छोड़ रहे हैं। मिसूरी राज्यमें केवल २ प्रतिशत अध्यापक बच गये हैं और यदि सारे देशका हिसाब लगाया जाय तो सन् १९४१ का आधा स्टाफ रह गया है।

इनका स्थान जिन लोगोंने लिया है वह बिल्कुल निकम्मे हैं। हर जगह यही शिकायत सुननेमें आयी कि अध्यापकोंकी नितान्त कमी है। कई जगहोंमें कई मुख्य विषयोंकी पढ़ाई बन्द करनी पड़ी है। कहीं-कहीं तो अध्यापक केवल हाजिरी लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ करनेकी उनकी योग्यता ही नहीं है। एक ओर तो अध्यापकोंकी माँग बढ़ रही है और दूसरी ओर अध्यापकोंकी संख्या घटती जाती है। कालेजके विद्यार्थियोंमेंसे केवल ७ प्रतिशत अध्यापक होना चाहते हैं, जहाँ एक समय २२ प्रतिशत कालेजके विद्यार्थी अध्यापकोंकी शिक्षा लिया करते थे।

बेजामिन फाइनका कहना है कि इस संकटका कारण अध्यापकोंका कम वेतन है। अमेरिकामें अध्यापकोंका औसत साप्ताहिक वेतन ३७.०२ डालर है, वाशिंगटन नगरमें कूड़ा जमा करनेवाला जो मजदूरी पाता है उससे यह ३.३७ डालर अधिक है। टैक्सी ड्राइवरोंका पुरस्कार अध्यापकोंके पुरस्कारसे अधिक है। डिट्रोइट (Detroit) में कुत्ते पकड़नेवालोंका वेतन २४८४ डालर वार्षिक है जब कि उसके अध्यापक २०६४ डालर ही वर्षमें पाते हैं।

मिस्टर फाइनका कहना है कि अनपढ़ जनताकी सहायतासे लोकतन्त्रका काम नहीं चल सकता। जनता इस समस्याकी गम्भीरताका धीरे-धीरे अनुभव करने लगी है और कई स्टेट अध्यापकोंके पुरस्कारमें वृद्धि करनेका प्रस्ताव कर रहे हैं।

ऐसी अवस्थामें अध्यापकोंका अपनी युनियन बनाना स्वाभाविक है। कहीं-कहीं अध्यापक हड़तालकी धमकी दे रहे हैं। मिस्टर फाइन कहते हैं कि जबतक उनके पुरस्कारमें वृद्धि नहीं होती तबतक वह लड़कोंका पढ़ाना छोड़ते ही जायेंगे और कोई दूसरा काम तलाश कर लेंगे। अमेरिकामें तो दूसरे काम भी मिल जाते हैं। वहाँ भी अभीतक इस समस्याको ठीक-ठीक हल करनेका प्रयत्न नहीं किया गया है। जब धनी अमेरिकाका यह हाल है तो निर्धन भारतका क्या कहना। हमारे यहाँ भी अध्यापकोंके वेतनमें कुछ वृद्धि हुई है, किन्तु वह पर्याप्त नहीं है। गवर्नमेंटकी कठिनाइयोंसे हम परिचित हैं। प्रश्न ऐसा सुगम नहीं है, किन्तु हमको उसे भुला नहीं देना चाहिये। सहानुभूतिके साथ हमको इस प्रश्नपर

विचार करना चाहिये और अध्यापकोकी अवस्थाको जहाँतक हम उन्नत कर सकें उसे उन्नत करना चाहिये । प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि अध्यापकोके साथ भी न्याय होना चाहिये, किन्तु इससे कहीं अधिक गम्भीर है । हमको तो अभी लोकतन्त्रकी स्थापना करनी है और जनसाधारणको शिक्षित बनाना है । अनिवार्य शिक्षा ही जनतन्त्रकी आधारशिला है और इसकी सफलता योग्य शिक्षकोपर निर्भर है । अतः नये समाजकी नींव योग्य अध्यापक-वर्ग है । इस वर्गके महत्त्वको समझकर उसकी आवश्यकताओंको पूरा करना और अध्यापकके कामको आकर्षक बनाना राज्यका कर्तव्य है । कहीं भी इस दृष्टिसे अवतक विचार नहीं किया गया था, क्योंकि अध्यापकोके मिलनेमें कठिनाई नहीं होती थी । गत युद्धके कारण ही यह समस्या उत्पन्न हो गयी है । युद्धकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए हर जगह नये विभाग खोलने पड़े और अच्छा वेतन नियत करना पड़ा । आर्थिक कष्टके बढ़ जानेसे पुरस्कार-वृद्धिका प्रश्न भी उपस्थित हो गया । जिन विभागोंको आर्थिक महत्त्व दिया गया, उनका वेतन भी ज्यादा रखा गया । युद्धके समय जब व्यय घटानेका प्रश्न आता है तब शिक्षापर जो रकम खर्च की जाती है उसमें ही सबसे पहले कमी की जाती है । संस्कृतिपर ही पहला वार होता है, कमसे कम उसके विस्तारकी बात युद्धके जमानेमें नहीं सोची जाती । समाजकी रक्षाका प्रश्न प्रधानता ले लेता है और इस नयी मनोवृत्तिके कारण शिक्षाकी उपेक्षा की जाती है । इसमें बड़ा खतरा है । हमको यह सोचना होगा कि एक नूतन समाजका गठन करनेके लिए क्या परमावश्यक है । रक्षाका विधान करना पहला कर्तव्य है, किन्तु इसके पश्चात् अन्न-वस्त्रका प्रबन्ध तथा शिक्षाकी व्यवस्था होनी चाहिये । हमारे देशमें जहाँ केवल १५ प्रतिशत लोग साक्षर हैं, वहाँ तो यह प्रश्न बहुत ही महत्त्व रखता है ।^१

क्या धार्मिक शिक्षा हमारी शिक्षा-संस्थाओं-

द्वारा दी जानी चाहिये ?

पुरानी दुनियामे धार्मिक शिक्षा बच्चोंकी शिक्षाका एक अविच्छिन्न अंग मानी जाती थी । देवमन्दिर या गिरजाघर समाजके जीवनका केन्द्र हुआ करता था और जिस धर्मके माननेवाले जो लोग होते उसी धर्मके द्वारा उनके मन, बुद्धि और हृदयका नियमन होता था । सत्तत्त्वका स्वरूप तथा पदार्थोंके मूल्योंका मान इत्यादि सभी बातें धार्मिक विश्वाससे ही निर्धारित होती थी । पारलौकिक जीवनकी आशा और मोक्ष पानेका आश्वासन होनेसे मनुष्य ऐहिक जीवनका भार प्रसन्न और धीर होकर वहन करते थे । पर धीरे-धीरे विज्ञानने आकर यह सारा ढंग बदल डाला और धर्मके स्थानमें बुद्धिका युग प्रवर्तित हुआ । विज्ञान और उसकी कार्यप्रणालीके प्रगमनके साथ मनुष्यका ऐहिक जीवन सुखी

और समृद्ध बना सकनेकी एक विशेष आशा संचारित हुई। यही कारण है कि विज्ञान और प्रगति एक चीज समझे जाने लगे। विज्ञानके भरोसे स्वर्गतकको दखल कर लेनेकी बात लोग सोचने लगे। इससे एक नया आश्वासन मिला, एक नया विश्वास जाग उठा। फलतः धीरे-धीरे धार्मिक विश्वास क्षीण होने लगे और मठ-मन्दिरों या गिरजाघरोंका पहलेका-सा प्रभाव मनुष्योंके हृदयोंपर नहीं रह गया। विज्ञानके प्रभावके अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण बातें ऐसी जुट गयीं जिनसे ऐसी स्थिति बन गयी। नये सामाजिक वाद निकल पड़े और नये आर्थिक और राजनीतिक सिद्धान्तोंने मनुष्योंके मनोको अपने वशमें कर लिया। साधारण मनुष्यने अपनी दीर्घकालीन निद्रा और उदासीनता त्याग दी और नया जीवन पाकर वह सर्वत्र चलने-फिरने लगा। धीरे-धीरे कर्मक्षेत्रके केन्द्रपर उसने अपना प्रभाव डाला। इन सबसे एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें उसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता था। वह अब पारलौकिक जीवनकी अपेक्षा इसी अपने ऐहिक जीवनकी बात अधिक सोचने लगा। स्वाभिमान और मानव-गौरवकी एक नवीन बुद्धि उसमें जागी और वह अपने अन्दर एक ऐसी शक्ति अनुभव करने लगा जिससे इस दुनियामें वह अपना जीवन अधिक सुखी बना सकता है। पर अनुभवसे उसने यह सीखा कि धार्मिक सस्थाएँ शोषितों और दलितोंका पक्ष करनेके बजाय यथावत् स्थितिका ही समर्थन किया करती हैं और जनताकी आर्थिक तथा सामाजिक दुःस्थितिके आमूल परिवर्तनका सदा विरोध ही करती हैं। उसने यह भी देखा है कि धर्माचार्योंके ये पीठ सरकारके महज पुछल्ले बन गये हैं और राष्ट्रोंके पारस्परिक युद्धोंमें ये अपनी-अपनी सरकारका ही पक्ष लेकर अपने अनुयायियोंको दूसरे राष्ट्रवालोंकी हत्या करनेका उपदेश किया करते हैं। इसके अतिरिक्त, लिखे-पढ़े लोग भी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ आदि धर्मके बाह्य अंगोंको अनावश्यक समझने लग गये। ये लोग अज्ञेयवादी बने और इलहाम अथवा ईसाकी ऐतिहासिकता जैसे प्रश्नोंकी चर्चा भी श्रद्धा विरहित तर्कोंकी कसौटीपर करनेमें इन्हें कोई सकोच नहीं होता था। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितिमें धार्मिक विश्वासोंका नष्ट होना ही अनिवार्य था। जिस किसी भी देशमें पाश्चात्य संस्कृति और विचारपद्धति घुसी, वहाँ एक नया सण्यवाद उठ खड़ा हुआ और पुराने विश्वास उखड़ने लगे।

हिन्दुस्तानमें जब ब्रिटिशोंका राज्य हुआ तब यहाँ सार्वजनिक शिक्षाकी एक ऐसी पद्धति चलायी गयी जिससे धार्मिक शिक्षा पहले-पहल अलग कर दी गयी। शिक्षा अंग्रेजीकी दी जाय या प्राचीन संस्कृतिकी इसके बाद-विवादमें अंग्रेजोंकी जीत हुई और ईस्ट इण्डिया कम्पनीने अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विज्ञानसे हिन्दुस्तानके लोगोंको लाभान्वित करनेका सकल्प किया। सार्वजनिक शिक्षालयोंमें धार्मिक शिक्षा देनेकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, क्योंकि विभिन्न धर्मसम्प्रदायोंके लड़के इन विद्यालयोंमें पढ़ने आते थे। अतः इन दुस्तर कठिनाइयोंके कारण विदेशी सरकारने सार्वजनिक विद्यालयोंमें केवल धर्म-निरपेक्ष शिक्षाकी ही व्यवस्था की। इस नीतिके कारण मुसलमान समाज बहुत कालतक इस नवीन शिक्षा-पद्धतिसे कोई लाभ नहीं उठा सका, कारण वह अपने धार्मिक विश्वासों और सिद्धान्तोंका विशेष कायल था और इस सिद्धान्तको माननेवाला था कि धार्मिक

शिक्षा शिक्षाका अविच्छिन्न अंग है। नवीन शिक्षाने पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियोंके बीच संघर्ष उत्पन्न कर दिया और इसके फलस्वरूप नये सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन चल पड़े। हिन्दुस्तानकी बुद्धि बहुत अस्थिर हो गयी और हमारे सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासोंका नया मूल्याङ्कन होने लगा। पुरातन धार्मिक पद्धतियोंपरसे शिक्षित लोगोंका विश्वास उठ चला और पश्चिमके नये राजनीतिक और सामाजिक तत्त्वज्ञान हमारे आदर और मानके पात्र हुए।

मुसलिम समाजने धीरे-धीरे अपने आपको इस नवीन शिक्षापद्धतिके अनुकूल बहुत कुछ बना लिया, पर वह बार-बार सरकारसे यह आग्रह करता रहा कि मुसलिम विद्यार्थियोंके लिए धार्मिक शिक्षाका कुछ प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये। सरकारने इस हदतक यह बात मान ली कि उसने ऐसे साम्प्रदायिक विद्यालय पृथक् रूपसे स्थापित करनेको प्रोत्साहन देना स्वीकार किया जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सके। पर सार्वजनिक विद्यालयोंका धर्म-निरपेक्ष स्वरूप क्योंकि त्यों बना रहा। लोकमतके आदरार्थ थोड़ी रियायत अवश्य ही की गयी और अब जो नियम प्रचलित है वह यह है कि सरकारी स्कूलों और कालेजोंमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षाके देवे हुए समयको छोड़कर अन्य समयमें निम्नलिखित शर्तोंपर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है—

१—स्कूल या कालेजका कोई अध्यापक धार्मिक शिक्षाका काम नहीं कर सकता, पर धार्मिक शिक्षक जो कोई होगा, संस्थाके मुख्य चालकके अधीन रहेगा।

२—जिम सम्प्रदायकी बात हो उसी सम्प्रदायकी इसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी और उन शिक्षाके लिए होनेवाला खर्च चलाना होगा।

३—अपने बच्चोंको धार्मिक शिक्षा दिलाना या न दिलाना बच्चोंके माता-पिताकी मर्जीपर होगा।

सहायताप्राप्त शिक्षा-संस्थाएँ चाहें तो अपने यहाँ उस शर्तपर धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं कि विवेक-बुद्धिके सर्वमान्य अधिकारोंका आदर बना रहे।

स्कूलोंमें धार्मिक शिक्षाके प्रश्नपर समय-समयपर सरकारद्वारा नियुक्त कमेटियोंने बार-बार विचार किया है, पर उस विषयमें कोई साग्रह और सार्वधिक माँग नहीं देख पड़ती।

१९३३ में युक्त प्रदेशकी सरकारने प्रारम्भिक और उच्च शिक्षाके पुनःसंघटनका विचार करनेके लिए जो कमेटी नियुक्त की थी उसने इस प्रश्नका विचार किया था। उसकी मुख्यतः यही राय रही की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर मर्तक्यके लिए उसने इसका निर्णय सरकारपर छोड़ दिया, क्योंकि राज्यकी नीतिके साथ यह प्रश्न सम्बद्ध है।

जबसे राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई है तबसे इस प्रश्नका फिरसे विचार होने लगा है और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे महान् व्यक्ति जो न केवल हमारे शिक्षा-मन्त्री हैं प्रत्युत उदार भाव और प्रगतिशील विचारके पूर्ण और गतिमान् विद्वान् हैं उनका भी समर्थन हालमें ही इसे प्राप्त हुआ है।

नये जमानेकी बुराइयोंको दूर करनेके लिए आमतौरपर धार्मिक शिक्षाका ही उपाय

वतलाया जाता है। पाश्चात्य देशोंमें लोगोका विश्वास विज्ञानपरसे और इसलिए इस उन्नतिपरसे भी उठ चला है, क्योंकि विज्ञानका दुरुपयोग हो रहा है और कुपथमें उसकी प्रवृत्ति है। उन देशोंमें आजकल धर्म और गुप्त विद्याकी ओर लोगोकी रुचि फिरसे हो रही है। लोग कोई ऐसी चीज चाहते हैं जिसपर वे अपना विश्वास टिका सकें, पर पुराने धर्म-सम्प्रदायोसे उन्हें सन्तोष नहीं होता। वे कोई नया धर्म, नया इलहाम ढूँढ़ रहे हैं, पर यह धर्म या इलहाम उन्हें मिले, इससे पहले वे निराशावादी तत्त्वज्ञानोंसे घिर रहे हैं। कुछ जीवनकी कठिन वस्तुस्थितियोंसे भागकर गुप्त विद्या और पुराने धार्मिक विश्वासोंका आश्रय ढूँढ़ते हैं, कुछ जीवनको दुःखमय देख निराश होकर बैठ जाते हैं। किसीमें वह जीवन-विश्वास नहीं रह गया जिसकी जीवनके लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। मनुष्य केवल तर्कसे नहीं जी सकता; उसे धारण करने और प्रेरणा पानेके लिए विश्वासकी आवश्यकता होती है। पर यह विश्वास धर्म-निरपेक्ष होना चाहिये और उससे भविष्यके लिए आध्यात्मिक आश्वासन मिलना चाहिये।

परन्तु हमारे देशकी हालत अभी इस दर्जेतक नहीं पहुँची है। हम अभी-अभी स्वाधीन हुए हैं और अभी हमने अपनी यात्राका आरम्भ किया है। हमें कई नवीन प्रश्न हल करने हैं और निर्माणका काम हमारे सामने है। हमें स्वाधीनता और प्रगतिपर विश्वास है। निराशा या संशयसे हम ग्रस्त नहीं हैं। पर एक भिन्न प्रकारके सांस्कृतिक संकटने हमें घेरा है। हमारी समाज-नीतिक पुराने रोग पहलेसे बहुत ही अधिक उग्ररूपमें उभड़ पड़े हैं और हमें नष्ट किया चाहते हैं। ये रोग हैं दलवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद और प्रान्तवाद। गैरसरकारी सेनाओंको गैरकानूनी करार देने और सम्प्रदायमूलक राजनीतिक सघटनोपर रोक लगाने मात्रसे यह बुराई समूल नष्ट होनेवाली नहीं है। बीमारी अस्थि-मज्जाके अन्दर घुसी बैठी है। हमें अपने बच्चोंको नवीन शिक्षा देनी होगी और समस्त जनताका मन ही बदलना होगा। तभी कोई महान् कार्य बन सकता है। अपने नवयुवकोंको हमें ऐसा बनाना होगा कि धार्मिक द्वेष और शत्रुताका सम्प्रदाय उनपर अपना कोई असर न डाल सके। उन्हें लोकतन्त्र और अखण्ड मानवताके आदर्शोंकी दीक्षा देनी होगी, तभी हम साम्प्रदायिक सामञ्जस्य और सद्भाव चिरन्तन आधारपर स्थापित कर सकेंगे।

साम्प्रदायिक मेल उत्पन्न करनेकी सदिच्छासे ही कदाचित् स्कूलोंके पाठ्यक्रममें धार्मिक शिक्षाके समावेशकी बात कही जाती है। पर लोग क्षमा करे, मुझे यह कहना ही पड़ता है कि यह दवा बीमारीसे भी अधिक घातक साबित होगी। धार्मिक शिक्षाके समर्थनमें यह कहा जा सकता है कि सभी धर्म मूलतः एक हैं और सही दृष्टिसे देखा जाय तो ऐसा धर्म एकत्व-साधनकी ही एक शक्ति है। मैं मानता हूँ कि कुछ सर्वव्यापक तत्त्व ऐसे हैं जो सब धर्मोंमें समान हैं। पर ऐसे भी कुछ तत्त्व हैं जो एक-एक सम्प्रदायके अपने-अपने विशेष हैं। जनता जिस धर्मको समझती और पालन करती है वह तो विशिष्ट विधियुक्त कर्म और पूजा-पाठ ही है और ये सब सम्प्रदायोंके अलग-अलग हैं। सीधी और सच्ची बात यही है कि धर्म समाजकी एक घातक शक्ति है।

राष्ट्रीय सरकारका काम यह है कि वह इन विभिन्नताओंको पीछे कर दे और सबके

लिए समान चीजोंको आगे करे जो सबको मिलाती और विभिन्न प्रकारके लोगोंको एकत्वमें बाँधती है। स्कूलोंके पाठ्यक्रममें धार्मिक शिक्षाका समावेश करनेसे ये साम्प्रदायिक भेद विशेषरूपसे उन बच्चोंके सामने आयेगे जिन्हें इन भेदोंका अभी कोई ज्ञान नहीं है। यह कहा जा सकता है कि धार्मिक शिक्षाका एक स्वास्थ्यकर प्रभाव होता है और धर्माध्यापक यदि योग्य हुए तो धार्मिक शिक्षाका कोई वैसा अनर्थकारी परिणाम नहीं हो सकता। पर यह कहते हुए लोग इस बातको भूल जाते हैं कि ऐसे धर्माध्यापक जो धर्मके बाह्यांगकी अपेक्षा मूलतत्त्वके अधिक विश्वासी हैं, बहुत ही कम हैं। कुछ लोगोंका यह वीद्विक विश्वास हो सकता है कि सब धर्म मूलतः एक हैं, पर इनके हृदयोंमें भी अपने ही वैयक्तिक धर्मकी श्रेष्ठताका विश्वास जमा हुआ होता है। आजके शिक्षित लोग तो, धर्म शब्दके वास्तविक अर्थमें, धार्मिक रह ही नहीं गये हैं, यद्यपि अपने राजनीतिक स्वार्थोंके साधनमें इन धार्मिक विश्वासों और भावोंसे काम लेते उन्हें कोई संकोच नहीं होता।

फिर यह बात भी हमें ध्यानमें रखनी चाहिये कि कोई बच्चा धर्म और चरित्रकी बातें मौखिक शिक्षासे नहीं सीखा करता। उसके चारों ओर जो परिस्थिति होती है उसीसे उसको प्रेरणा मिलती है। दर्जमें बैठकर जो मौखिक शिक्षा वह कानसे सुनता है उससे उसका चरित्र उतना प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसके अध्यापको, माता-पिताओं और पड़ोसियोंके चरित्र उसपर अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। अतः, उदाहरणार्थ, यदि हम अपने बच्चोंको सेवा-भाव सिखाना चाहें तो सेवा-भावके गुणोंकी प्रशंसा करनेसे बच्चोंके वैसे भाव नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें सेवा करनेके अवसर देनेसे दूसरोंकी सेवा करनेमें जो सुख और अनन्द है वह उन्हें प्राप्त होगा।

साम्प्रदायिकताको दूर करनेका एक मात्र उपाय सबका जीवनध्येय एकसा बनाना और सबके लिए सहयोगयुक्त प्रयासोंके अवसर निर्माण करना है। पथ-भ्रष्ट युवकोंको उसकी भूल दिखाने और रास्तेपर ले आनेका तरीका यही है कि कर्ममय जीवनकी उसकी सहज इच्छाको नष्ट करे और राष्ट्रके हितार्थ और शिष्टताके साथ अपने जीवन-निर्वाहार्थ उसे कोई उपयोगी कार्य सौंपे। हिन्दुस्तानका इतिहास एक नवीन कार्यको लेकर पुनः लिखना होगा और हमारी समान सांस्कृतिक परम्परा एक एक बच्चेतक पहुँचानी होगी। सामाजिक लोकतन्त्र हमें वह विश्वास प्रदान करता है जिससे हम जी सकते हैं और इस विश्वासके बलपर मानव अखण्डता साध सकते हैं और अन्तमें उन कृत्रिम दीवारोंको ढाह सकते हैं जो हमलोगोंको एक दूसरेसे अलग करनेके लिए धर्म और जात-पातने खड़ी की हैं। हमें अपनी समान राष्ट्रीयताको सिद्ध करनेके लिए किसी इलहामसे कोई सान्त्वना पानेकी आवश्यकता नहीं है। इलहामोंके दिन लड़ गये। उनकी परख हो चुकी, वे खरे नहीं उतरे। हमारा यह नवीन युग हमसे वह नया कार्य कराना चाहता है जो वर्तमान धर्मसम्प्रदायोंके द्वारा पूरा नहीं हो सकता। किसी समन्वययुक्त धर्मसे भी काम नहीं चलेगा चाहे वह कितना ही प्रबुद्ध और वैज्ञानिक क्यों न हो। धर्म और विज्ञानका कोई युक्तिसंगत मेल बैठाना भी सम्भव नहीं प्रतीत होता।

लोकतन्त्र और मानव तथा सामाजिक मानसे मूलांकन, इन दो बातोंपर विश्वास ही

हमारे लिए बस है। यदि यह विश्वास है तो विज्ञानके बलसे हम मानव अस्तित्वके उद्देश्योको सिद्ध कर सकते हैं।

शिक्षा देनेवालेका यह काम है कि शिक्षापद्धतिमें नया सुधार करे और पाठ्यक्रमके अतिरिक्त ऐसे काम निकाले जिससे बच्चेको स्कूलके अन्दरकी परिस्थितिसे ही उन सामाजिक आदर्शों और चारित्रिक दृष्टान्तोंकी शिक्षा मिले जो राष्ट्रको उत्तम बनानेमें साधक होते हैं। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे विचारों और भावोंकी एकता परिपुष्ट हो ताकि मन बुद्धि और हृदयकी एकता साधित हो सके।

धार्मिक शिक्षासे लोग और भी अधिक हठधर्मी और साम्प्रदायिक बनेंगे, वह उदार और व्यापक दृष्टि उनकी न होगी जो राष्ट्रीय एकताके लिए इतनी आवश्यक है।

साम्प्रदायिकतासे हमारे राष्ट्रको जो खतरा है उसे जो लोग समझते और उसकी तीव्र वेदना अनुभव करते हैं उन्हें चाहिये कि वे एकत्र होकर इस दैत्यसे जूझनेके साधन और उपाय करे। दूरदर्शी और विश्वासी नेता ही इस सांस्कृतिक संकटसे तारनेमें हमारी मदद कर सकेंगे।'

युवकोंको संदेश

दक्षिण एशियाके विभिन्न देशोंकी युवक संस्थाओंके उन प्रतिनिधियोंका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ जो कलकत्तेमें इस उद्देश्यसे एक सम्मेलनमें एकत्र हो रहे हैं कि स्वाधीनता और सम्यक् जीवनके निमित्त युवक समानरूपसे जो सघर्ष चला रहे हैं उसके बलकी वृद्धि हो। विदेशी साम्राज्योंके विरुद्ध किये जानेवाले संघर्षमें इन देशोंके युवक सदा ही आगे रहे हैं। इनमेंसे कुछ देश स्वाधीन हो भी चुके हैं और दूसरे बड़ी कठिन परिस्थितियोंका सामना करते हुए अपनी लड़ाई अनवरत जारी रखे हुए हैं। पर इतिहास क्या फैसला देगा यह स्पष्ट है और साम्राज्योंके दिन गिनतीके रह गये हैं।

जिन देशोंको स्वाधीनता प्राप्त हो चुकी है उन देशोंमें युवकोंके सघर्षका एक नवीन अध्याय आरम्भ हुआ है। वहाँ अब यह सघर्ष राजनीतिक स्वाधीनताके लिए नहीं रहा। अब जो सघर्ष है वह रोटी और शान्तिके लिए है। वहाँ युवकोंको जो लड़ाई लड़नी है वह दरिद्रता, अज्ञान और शोषणसे है। युवकोंको जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें नेतृत्व करने योग्य अपने-आपको बनाना है। राष्ट्रके नेताओंका यह कर्तव्य है कि वे युवकोंके अधिकार माने। मानव-इतिहासका जब एक नवीन अध्याय बन रहा है और जब हमें एक नवीन समाज-रचना निर्माण करनी है तब यह युवकोंका ही काम है कि यशस्विताके साथ इस भारको उठा ले। इस नये कार्यमें जीवनसुलभ बल, साहस, त्याग और बुद्धिमत्ताकी आवश्यकता है। बुद्धिमत्ता विविध मानव-अनुभवोंसे ही प्राप्त होती है। इसे छोड़ अन्य

सभी गुण युवकोंमें यथेष्टरूपसे मिलते हैं । बुद्धिमत्ता भी प्राप्त करनेका युवक यत्न करेगा जब वे विश्वास और उत्तरदायित्वके पदोंपर बैठायें जायेंगे ।

अतः इस सम्मेलनमें उपस्थित प्रतिनिधियोंसे मैं यह अनुरोध करूँगा कि वे राजनीतिक संघर्षकी ओर आवश्यकतासे अधिक ध्यान न दें । उन्हें यह स्मरण रहे कि राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर लेनेसे ही क्रान्ति पूर्ण नहीं होती । युवक-आन्दोलनके उद्देश्य इतने विशाल हो कि उनमें ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक आन्दोलनका भी समावेश हो जाय कि जिससे सामाजिक न्याय और बौद्धिक उन्नतिका राज्य प्रतिष्ठित हो । इस नये ढंग और ढाँचेमें युवक अपना काम तभी खूबी कर सकते हैं और राष्ट्रके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनमें अपना स्तंभ बढा सकते हैं जब कि वे अपनी नीति नये ढंगपर सुधार लें और अपनी रचनात्मक क्षमताका प्रमाण दें । दक्षिण पूर्व एशियामें स्वाधीनताके उद्योगके फलस्वरूप जो नवीन राज्य निर्मित हो रहे हैं उनपर अपने जन्मकालसे ही बहुत बड़ी कठिनाइयोंका सामना करनेका दुःसह भार आ पड़ा है । इन कठिनाइयोंको पार करनेके लिए राज्यके अधिकारोंकी महत्ता व्यक्तिके अधिकारोंको दबाकर बढ़ायी जा रही है । संकटका सामना करनेके लिए राज्यको बलवान् तो बनाना ही होगा, पर जनताको और भी अधिक बलवान् बनाना होगा, यदि हम चाहते हैं कि लोकतन्त्र सुदृढ़ आधारपर प्रतिष्ठित हो । इन नवीन संकटोंका सामना सफलताके साथ तभी किया जा सकता है जब हम जनताके अधिकारोंको मानें और उसमें स्वाभिमान और आत्मगौरवकी नयी चेतना जगाकर उसे प्रतिक्रियाकी शक्तियोंके विरुद्ध संघटित करें ।

हिन्दुस्तानमें इस समयकी सबसे बड़ी आवश्यकता साम्प्रदायिकता और दलवादिताको जड़मूलसे उखाड़ फेंकना है । हिन्दुस्तानके युवकोंको धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र राज्यके हकमें अपना संघर्ष जारी रखना है । जो युवक अपने इस नवप्राप्त स्वाधीनतापर उपस्थित संकटको देख रहे हैं उनका यह कर्तव्य है कि सुसज्जित होकर प्रतिक्रियाकी अन्धशक्तियोंको परास्त करनेका पूरा प्रयास करें । युवकोंमें ही एक दल पथभ्रष्ट हो चुका है और युवक-संस्थाओंका यह सर्वप्रधान कर्तव्य है कि अपने उन पथभ्रष्ट भाइयोंको फिरसे अपने अन्दर ले आये । यदि यह सीमित कार्य पूरा हो गया तो मुझे विश्वास है कि लोकतन्त्रका भविष्य उज्ज्वल है । युवकोंको एक बहुत बड़े उत्तरदायित्वका निर्वाह करना है । मुझे आशा और भरोसा है कि वे अवसरको समझकर ऊपर उठेंगे और अपने कर्तव्य-पालनमें उत्तीर्ण होंगे ।

मैं सम्मेलनकी हर तरहसे सफलता चाहता हूँ ।

जन-शिक्षा

लोकतन्त्र केवल एक शासन-पद्धति ही नहीं है, बल्कि वह एक जीवन-प्रणाली है । अतएव लोकतान्त्रिक आदर्शोंको केवल राजनीतिक क्षेत्रतक ही सीमित नहीं रखा जा सकता,

मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें उनको प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। अगर कोई नवजात राष्ट्र दूसरे देशोंकी लोकतान्त्रिक शासन-पद्धतिका ही अनुकरण करता है और केवल उसीको प्रगतिका सूचक मान लेता है, तो वह कदापि सच्चा लोकतान्त्रिक शासन स्थापित करनेमें सफल नहीं हो सकता। इसके लिए देशमें लोकतान्त्रिक भावनाका होना आवश्यक है। लोकतन्त्र मनुष्यके अभ्यास और परम्पराका विषय है जो काफी लम्बे और कठिन प्रयासके फलस्वरूप प्राप्त होती है। लोकतान्त्रिक परम्पराका निर्माण किया जाता है और और जनतामें तदनुकूल भावनाएँ विकसित की जाती हैं। जो समाज विविध धर्म और जातिगत भेदभावसे जर्जर हो गया है और जिसमें कुल, सम्पत्ति, जाति और धर्मपर आधारित विशेष स्वार्थोंकी सृष्टि हो गयी है, उसके अन्दर लोकतान्त्रिक जीवनचर्याका निर्माण करनेके लिए और भी सजग प्रयासकी आवश्यकता होती है। जनतामें लोकतान्त्रिक आदर्शोंके प्रति सुदृढ़ आस्था होनी चाहिये और उनसे ही उसका सारा जीवन-क्रम और व्यवहार अनुप्राणित होना चाहिये।

यह सत्य है कि जबतक जनतामें सामाजिक और राजनीतिक चेतना उत्पन्न नहीं होती तबतक लोकतान्त्रिक पद्धतिकी सफलता सम्भव नहीं है। इसका तो उद्देश्य ही यही है कि राष्ट्रके राजनीतिक जीवनमें सबलोग विवेकपूर्वक और सक्रिय रूपसे भाग लें। राजनीतिक और आर्थिक समस्याओंके प्रति जनताकी उदासीनताको दूर करना होगा और सार्वजनिक कार्योंमें उसकी दिलचस्पी पैदा करनी होगी। इसलिए लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्थाकी स्थापनाके लिए व्यापक शिक्षा सबसे आवश्यक है। जनताकी सांस्कृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी कमियोंको सर्वप्रथम दूर करना पड़ेगा और सभी श्रेणियोंमें साक्षरताका व्यापक प्रसार करना होगा। सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछड़ी श्रेणियों और क्षेत्रोंपर विशेष ध्यान देना होगा और उनको शीघ्रातिशीघ्र सुसंस्कृत समाजके समकक्ष लानेके लिए कोई भी कसर उठा नहीं रखनी चाहिये। जबतक जन-संस्कृतिका निर्माण नहीं होता तबतक ऐसे स्वतन्त्र समाजकी स्थापना भी नहीं हो सकती है जिसमें प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक कल्याणके लिए परस्पर सहयोग कर सके।

किन्तु साक्षरता इस दिशामें पहला कदम है। इससे केवल बुद्धिका कपाट खुल जाता है। साक्षर हो जानेपर कोई व्यक्ति केवल साधारण किस्से-कहानियाँ पढ़ सकता है, किन्तु वह शिक्षित नहीं हो सकता और न अपने व्यवहारोंको सामाजिक और विवेकयुक्त ही कर सकता है। वह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओंका भी अध्ययन नहीं कर सकता जिनसे आज चारों ओर उथल-पुथल मची हुई है। ऐसी साक्षरतासे व्यावसायिक वर्ग अनुचित लाभ उठाते हैं और केवल मुनाफा कमानेके लिए ढेरके ढेर ऐसे सस्ते और भद्दे साहित्यको प्रकाशित करते हैं जिनसे केवल मनुष्यकी दुष्प्रवृत्तियोंको उत्तेजना मिलती है। इस प्रकारके पुस्तक-व्यवहारसे जिसकी आजकल काफी धूम है, जनता शिक्षित नहीं होती, बल्कि पथभ्रष्ट होती है। केवल साक्षर समाजसे भी काफी खतरा है और आसानीसे वह अधिनायको और अधिकाराकाक्षियोंके जालमें फँस सकता है। श्रीवालासने ठीक कहा है कि “राजनीति उपचेतन समाजका दुरुपयोग है।” समाजके ये

प्रवचक अपने संकुचित राजनीतिक स्वार्थोंकी सिद्धिके लिए प्रचारके ऐसे हथकण्डोका उपयोग करते हैं जिससे विभिन्न राष्ट्रोंके बीच घृणा और द्वेष उत्पन्न हो । किसी भी राष्ट्रकी जन-शिक्षामे पत्रोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है । पत्रोंके द्वारा ही साधारण जनताको सार्वजनिक घटनाओंकी जानकारी प्राप्त होती है और जनमत तैयार होता है । स्वतन्त्र राष्ट्रोंमे विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ अपने सिद्धान्तों और कार्यक्रमका प्रचार करनेके लिए अपना पत्र प्रकाशित करती हैं । इनका उद्देश्य मतदाताओंको शिक्षित करना होता है, न कि मुनाफा कमाना । अक्सर उनसे काफी घाटा होता है जिसे चन्दा या पार्टीके कोषसे पूरा किया जाता है । किन्तु जब जनता साक्षर हो जाती है तो समाजमे कुछ ऐसे समाचारपत्रोंका भी आविर्भाव होता है जिनका उद्देश्य जनताको शिक्षित करना नहीं, बल्कि अपनी अर्थ-सिद्धि होता है । वे प्रेम, हत्या तथा अन्य अपराधोंके उत्तेजनापूर्ण और सनसनीदार समाचार प्रकाशित करते हैं और इस प्रकार मनुष्यकी दुष्प्रवृत्तियोंको जगाकर अपना घृणित स्वार्थ-साधन करते हैं । ऐसे पत्रोंसे भयकर प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है । इससे मानव-प्रकृतिका पतन होता है, न कि उत्थान और उद्घात्तीकरण । जन-शिक्षामे उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती है और न उनका यह उद्देश्य ही होता है । ये मानव-प्रकृतिकी कमजोरियोंसे अपने राजनीतिक उद्देश्योंकी पूर्ति करना चाहते हैं । यद्यपि अभीतक हमारे देशमे ऐसे पत्रोंका उदय-नहीं हुआ है, किन्तु इसमे अधिक समय नहीं लगेगा । एक दूसरे प्रकारके पत्रोंका भी हमारे देशमे आविर्भाव हो रहा है जो औद्योगिक वर्गके स्वार्थोंका प्रतिनिधित्व करते हैं । हमारे राष्ट्रके उद्योगपति अपना कोई राजनीतिक सगठन नहीं बनाते हैं । समाचारपत्रोंको अपने हाथमे रखना ही उनके लिए अधिक लाभ-दायक होता है इस प्रकार वे प्रत्यक्ष या परोक्ष, अनेक रूपोंमे सरकार और जनताको प्रभावित करते हैं । यहाँके उद्योगपतियोंकी ओरसे इधर बहुतसे समाचारपत्र प्रकाशित हुए हैं और राजनीतिक पार्टियोंके लिए अब अपने पत्रोंका संचालन दिन-प्रति-दिन कठिन होता जा रहा है । विज्ञापनदाताओंमे भी वर्ग-चेतना बढ़ती जा रही है और अब वे वामपक्षी पत्रोंको विज्ञापन देना पसन्द नहीं करते ।

जनताको राजनीतिक विषयोंकी शिक्षा तभी समुचित रूपसे प्राप्त हो सकती है, जब कि उसे विभिन्न प्रकारकी विचार-धाराओंको भलीभाँति समझने और उनमे निर्णय करनेका अवसर मिले । राज्यका कर्तव्य है कि वह जनताको ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसके अन्दर विवेचनात्मक शक्तिका विकास हो और उसमे आत्मनिर्माणकी क्षमता आ सके । इसमे नागरिक शिक्षाका सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है जिसमे न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्योंका पालन करनेकी भी शिक्षा दी जानी चाहिये । स्मरण रहे कि हमलोग अब विश्व-सघर्षी और अग्रसर हो रहे हैं और हमारी सभी शिक्षा-योजनामे वह दृष्टिकोण निहित रहना चाहिये । हमलोग विश्वके अन्य भागोंमे होनेवाली घटनाओंके प्रति आँखें मूँदकर अकेले नहीं रह सकते । हमारी शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि हम आजके विश्वमे सुरक्षा और सुखके साथ जीवन व्यतीत कर सकें । हमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सद्भाव और भ्रातृत्वकी स्थापना करने तथा अपने दायित्वका निर्वाह

करनेके लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिये । यद्यपि यह कार्य महान् है, किन्तु पूर्ण और सम्पन्न जीवन व्यतीत करनेके लिए इसकी पूर्ति आवश्यक है । अगर हम साहसके साथ और सचेत होकर अपने कर्तव्यका पालन करेंगे तो निस्सन्देह हमारा भविष्य उज्ज्वल है ।

इस दृष्टिसे हमारी शिक्षा-प्रणालीमें क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिये । मानव-कल्याणके हेतु अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग प्राप्त करनेके लिए एक नये जीवन-दर्शन और नये प्रयासकी आवश्यकता है । तात्पर्य यह कि हमारी जन-शिक्षा-योजना इस प्रकारकी होनी चाहिये जिससे जीवनके प्रति स्वस्थ और असांभ्रदायिक दृष्टिकोण बन सके, उसमें लोकतान्त्रिक और मानवीय मूल्योंकी प्रतिष्ठा हो और सामाजिक व्यवहारके नवीन संस्थानोंका निर्माण हो । साथ ही शिक्षामें जीवन-पर्यन्त-प्रगति होनी चाहिये । हमलोग एक परिवर्तनशील जगत्में रहते हैं । इसलिए समय-समयपर हमारे मनोभावों और विचारोंकी पुनर्व्यवस्था आवश्यक है । साहित्यिक शिक्षाके अतिरिक्त राज्यका यह कर्तव्य है कि वह समय-समयपर जनताको महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक समस्याओंकी भी शिक्षा दे । उदाहरणस्वरूप सरकारको चाहिये था कि वह विधान-परिषद्द्वारा प्रस्तुत संविधानपर प्रत्येक नगर और गाँवमें सार्वजनिक रूपसे विचारविमर्श करनेकी व्यवस्था करती । वास्तवमें यह जनताके लिए काफी उपयोगी शिक्षा होती । यद्यपि विधान-परिषद्का संगठन वालिग मताधिकारपर नहीं हुआ है और जनतासे उसे सत्ता प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु अगर सरकार देशभरमें विधानपर सार्वजनिक रूपसे विचार-विमर्शका अवसर और सुविधा प्रदान करती तथा जनतामें इसकी ओर दिलचस्पी उत्पन्न करती तो उससे विधानकी कुछ आधारभूत त्रुटियोंका अवश्य परिमार्जन हो जाता । सन् १९३६ के सोवियत् विधानपर इसी प्रकार पहले ग्राम-पञ्चायतों और मजदूर-पञ्चायतोंद्वारा विचार-विमर्श हुआ था । इससे उनके अन्दर काफी चेतना आ गयी थी । इस प्रकार वहाँ राज्यकी ओरसे जनताको सचमुच एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शिक्षा दी गयी थी । इसके विपरीत हमारे देशमें नया विधान चन्द दिनोंमें तैयार हो जायगा, किन्तु उसमें जनताको जरा भी दिलचस्पी नहीं है । इसके लिए राजनीतिक प्रश्नोंपर जनताकी उदासीनताका वहाना विलकुल व्यर्थ है । जनता विलकुल अनभिज्ञ है और विधान-निर्माणमें दिलचस्पी न लेनेका उसपर आरोप नहीं लगाया जा सकता । ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर जिज्ञासा उत्पन्न करना सरकारका प्रमुख कर्तव्य है । डिसरैलीके शब्दोंमें जनता-जनार्दनकी शिक्षा हमारा प्रधान कर्तव्य है, और उनके प्रति अपने इस कर्तव्यको पूरा करनेमें हम अभीतक असफल रहे हैं । हमें जनताको यह बताना है कि किस प्रकार आज उसका भाग्य-निर्माण हो रहा है, उसके अधिकारों और कर्तव्योंका घोषणा-पत्र तैयार हो रहा है । इसी तरहसे हम उनके अन्दर उन नवीन अधिकारों और उद्देश्योंके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकेंगे जो भविष्यमें स्वतन्त्र हिन्दुस्तानकी आधारजिला होगी ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि राज्यको ऐसे सभी अवसरोंका जब कि महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर जनताको शिक्षित किया जा सकता है, उपयोग करना चाहिये । साक्षरता-आन्दोलनकी अपेक्षा यह जन-शिक्षाका अधिक प्रभावशाली तरीका होगा । साथ ही इस कार्यमें राज्यको

शिक्षाके सभी साधनोका उपयोग करना चाहिये । हिन्दुस्तानमे जन-शिक्षाकी केवल योजना तैयार करनेके अतिरिक्त और बहुतसे कार्य करने हैं । लोकतान्त्रिक विचारधारामें समानताका भाव सन्निहित है । यह केवल राजनीतिक विषयोंतक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी परिणति जीवनके अन्य क्षेत्रोंकी ओर भी है । इसके लिए शिक्षा और जीवन-निर्वाहका समान अवसर होना चाहिये और कुल, सम्पत्ति तथा अर्थनीतिपर आधारित भेदभावोका उन्मूलन और सामाजिक न्यायका होना भी आवश्यक है । लोकतन्त्रका क्षेत्र तबतक विस्तृत होता रहेगा जबतक कि सम्पूर्ण मानवजीवनमे यह व्याप्त न हो जाय ।

हमारे देशमे अभी लोकतान्त्रिक प्रगतिका केवल श्रीगणेश हुआ है । यहाँ तो सामाजिक असमानता और वर्णभेद ही हिन्दू-समाजका आधार रहा है । इसके बहुसंख्यक समुदायको अभीतक सभ्यताके सूर्योदयका दर्शन भी नहीं हुआ है और हमलोग उनके साथ अब भी मानवेतर प्राणियोंके समान बर्ताव करते हैं । आदिवासियोंकी जो सांस्कृतिक दृष्टिसे बहुत पिछड़े हुए हैं, नैतिक और भौतिक अवस्था सुधारनेके लिए अभीतक कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया है । ये सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताएँ जन-जीवनमे लोकतान्त्रिक भावनाओंके विकासमे बहुत बड़ी बाधा हैं । और जबतक इन संस्थाओं और परम्पराओंके जिनपर यह भेदभाव और अमानुषिक व्यवहार कायम है, विरुद्ध पूरी शक्तिसे अनवरत संघर्ष नहीं किया जायगा, तबतक नये लक्ष्यकी प्राप्ति की ओर प्रगति असम्भव है ।

जन-शिक्षाके प्रसार और ऐसे कानूनोंके निर्माणके साथ ही, जिससे तमाम सामाजिक असमानताओंका उन्मूलन हो जाता है, हमें ग्रामीण जनतामे लोकतान्त्रिक विचारों और व्यवहारोंको विकसित करनेके लिए देहातोमे जोरदार सहकारी आन्दोलन चलानेकी आवश्यकता पड़ेगी । सहकारितासे केवल यह आर्थिक लाभ ही नहीं है कि वह मध्यम श्रेणीके मुनाफेका अन्त कर कृषिको अधिक लाभदायक बना देती है, बल्कि इसके द्वारा नवीन सामाजिक सम्बन्धोंका एक संस्थान भी तैयार होता है जो प्रतिस्पर्धाके बजाय सहयोगपर आश्रित है और जनतामे भ्रातृभाव उत्पन्न करता है ।

इन उद्देश्योंकी प्राप्ति के लिए गैरसरकारी संस्थाएँ जो भी काम कर रही हो, किन्तु राज्यका प्रधान कर्तव्य है कि वह अपनी राजनीतिक विचारधारामें मौलिक सिद्धान्तों और तदनुकूल आचार-शास्त्रकी जनताको व्यापक शिक्षा दे । इस तरीकेसे ही जनताके सामाजिक कार्य विवेकपूर्वक होंगे और इसी प्रकारकी शिक्षा उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों-द्वारा उत्पन्न सकटसे भी राज्यकी रक्षा कर सकेगी जो समय-समयपर अपना सिर उठाकर उन मानवीय मूल्योंको ही विनष्ट कर देना चाहती हैं जिनकी सुरक्षा तथा विकासका दायित्व राज्यपर है ।^१

आगरा विश्वविद्यालय

उपकुलपतिजी, स्नातकवृन्द, देवियो और सज्जनो,

मैं आगरा विश्वविद्यालयके अधिकारियोंका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे आजके समारम्भके अवसरपर स्नातकोको सम्बोधितकर भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया है। प्रत्येक विद्यार्थीके जीवनमें समावर्तन-संस्कारका दिन चिरस्मरणीय होता है और इसलिए यह उचित है कि इस अवसरपर एक अनुष्ठानका विधान हो। प्राचीन कालमें हमारे गुरुकुलोमें यह महत्त्वपूर्ण संस्कार मनाया जाता था। इस संस्कारके जो मन्त्र तैत्तिरीय शिक्षामें पाये जाते हैं उनसे उत्कृष्ट शिक्षा नहीं हो सकती। वे उदात्त विचार आज भी नवीन हैं और हमारा पदप्रदर्शन कर सकते हैं। उनसे गुरु-शिष्यके परस्पर मधुर सम्बन्धका पता चलता है और सबसे विशिष्ट बात यह है कि शिक्षाको हमारे पूर्वज गुरु और अन्तेवासियोंका सम्मिलित कर्तव्य समझते थे। शिक्षाके क्षेत्रमें विद्यालयके अध्यापक, विद्यार्थी और व्यवस्थापक एक दूसरेके सहयोगी हैं। इस पुराने भावको हमें फिरसे जगाना है। जितनी ही अधिक मात्रामें इस भावको अपनायेगे उतनी ही अधिक मात्रामें हमको शिक्षाके क्षेत्रमें सफलता प्राप्त होगी। तैत्तिरीय शिक्षामें दिये हुए उपदेशसे श्रेष्ठतर उपदेश क्या हो सकता है। थोड़ेसे चुने हुए शब्दोंमें कुलपति अन्तेवासियोंको एक सारगर्भित उपदेश देता है। समावर्तनके अवसरपर उपदेश देनेका अधिकार कुलपतिको ही है, कि बाहरसे किसी प्रिय व्यक्तिको आमन्त्रित करनेका रिवाज-सा पड़ गया है। इस प्रथाके अनुसार आपने यह कर्तव्य इस वर्ष मुझे सौंपा है। यद्यपि मैंने अपने जीवनके विशिष्ट भागको विद्यापीठकी सेवामें व्यय किया है तथापि आपके विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंसे निकट सम्पर्कमें आनेका मुझे अवसर नहीं मिला है। इस दृष्टिसे मैं इन स्नातकोको उपदेश देनेका अपनेको अधिकारी नहीं समझता। किन्तु जब आपने मुझे इस कार्यके लिए निमन्त्रित किया है तो मैं अपने अनुभवके अनुसार कुछ शब्द आपसे निवेदन करूँ।

पूर्व इसके कि मैं शिक्षाके सम्बन्धमें अपने कुछ विचार आपके सम्मुख रखूँ मेरा यह प्रिय कर्तव्य है कि मैं उन नवीन स्नातकोको बधाई दूँ जिन्होंने आज पदवी प्राप्त की है। उनके जीवनमें यह एक विशिष्ट दिन है। उनमेंसे बहुतसे कार्य-क्षेत्रोंमें प्रवेश करेंगे और जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उसका अच्छेसे अच्छा उपयोग करनेका उनको अवसर मिलेगा।

जो स्नातक अपनी शिक्षा समाप्त करके आज यहाँसे बाहर जा रहे हैं उनके ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व है। हमारा देश आज स्वतन्त्र है। हमको एक नवराष्ट्रका निर्माण करना है। इस महान् कार्यके लिए हमको जीवनके विविध क्षेत्रोंमें ऐसे विद्याचरण-सम्पन्न नवयुवकोंकी आवश्यकता है जो सेवाभावसे प्रेरित होकर राष्ट्रके उत्थानके कार्यके लिए अग्रसर हो, हमारे समाजकी अनेक आवश्यकताएँ हैं। आजके युगमें राज्य की कल्पना ही बदल गयी है। आज राज्यका केवल इतना ही कर्तव्य नहीं है कि वह प्रजाके जान-मालकी रक्षा करे और उनसे कर वसूल करे। समाजके विविध विभागोंको पुष्ट और समुन्नत

करना आज उसका कर्तव्य हो गया है । यह बहुजन समाज का युग है, यह लोकतन्त्र और स्वतन्त्रताका युग है । आधुनिक कालमें बहुजनके हितोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । आज यह सम्भव नहीं है कि हम साधारण जनको शिक्षासे वञ्चित रखे । सस्कृति और ज्ञान कतिपय उच्च वर्गोंतक ही सीमित नहीं रखे जा सकते । जबसे उद्योग-व्यवसायके युगका उपक्रम हुआ है तबसे सर्वसाधारणकी शिक्षाका भी आयोजन हुआ है । लोकतन्त्रकी आधार-शिला सार्वजनिक शिक्षा है । यह शिक्षा अभी निम्नतम अवस्थामें है । सर्व-साधारणकी शिक्षाकी कल्पना आरम्भमें प्राथमिक शिक्षातक ही सीमित थी । इससे सर्वसाधारणके लिए ज्ञानके द्वारका उद्घाटन अवश्य हुआ । किन्तु जबतक सबके लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा सुलभ न हो जावे तबतक इससे लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक होती है । सर्वसाधारणकी जानकारीमें थोड़ी वृद्धि अवश्य होती है, किन्तु वह इस प्रकार सुसस्कृत और सुसयत नहीं बन सकते । पुनः व्यवसायी लोग व्यापारके लाभके लिए उनकी रुचिको विकृत कर देते हैं । वह इस प्रकारके समाचार संगृहीत करते हैं जिससे अधम 'स्व' को प्रोत्साहन मिलता है । किन्तु धीरे-धीरे यह कल्पना मान्य होने लगती है कि यदि लोकतन्त्रको उन्नत करना है तो सर्वसाधारणकी शिक्षा भी उन्नत होनी चाहिये । हमारा देश तो इतना निर्धन है कि आज सर्वसाधारणकी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाके व्ययका भार ही सहन करना कठिन है । किन्तु यह निश्चित है कि हमको आज ही नव-समाजका आरम्भ करना है । एक स्वतन्त्र समाजके आधारको दृढ़ बनानेके लिए तथा सुन्दर भविष्यका निर्माण करनेके लिए लोकतन्त्रके इस उपकरणको समर्थ बनाना है । यदि आज माध्यमिक शिक्षा सर्वसाधारणके लिए सुलभ नहीं हो सकती तो प्राथमिक शिक्षणका का सूत्रपात तो करना ही चाहिये । हमें हर्ष है कि हमारे प्रान्तमें इस कार्यका श्रीगणेश हो गया है तथा १० वर्षमें इस उद्देश्यको पूरा करनेका निश्चय किया गया है । यदि हमारा शिक्षित समुदाय अपने कर्तव्यको पहचाने और इस कार्यमें योग दे तो कम समयमें यह प्रारम्भिक कार्य समाप्त हो सकता है और व्ययमें भी कमी हो सकती है । प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपना-अपना काम करते हुए निरक्षरोंको साक्षर बना सकता है । मुहल्लेमें, दफ्तरमें, हाटमें, गाँवके चौपालोंमें, पाठशालामें, मन्दिर-मसजिदमें, सर्वत्र यह कार्य अवैतनिक रूपसे किसी परिमाणमें हो सकता है । आशा है जो नवयुवक आज शिक्षा समाप्त कर जीवनमें प्रवेश कर रहे हैं वह इस कार्यके महत्त्वको समझेंगे और साक्षरताके आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेंगे ।

आज हम एक क्रान्तिकारी युगमें रह रहे हैं । सारा ससार इतिहासके चौराहेपर खड़ा है । हमारी पुरानी संस्थाएँ, हमारे क्रमागत विश्वास, जीवनके प्रति हमारी दृष्टि, हमारे सामाजिक मूल्य, हमारी विचार-पद्धति, हमारी अर्थ-नीति और समाज-नीति सब परिवर्तित हो रहे हैं । एक युगकी परिसमाप्ति तथा नवयुगका उपक्रम हो रहा है । ऐसे संक्रमणकालमें हम रह रहे हैं । ऐसे संकटके समयमें बुद्धि-विभ्रम होना स्वाभाविक है । प्रत्येकके लिए अपने कर्तव्यको निश्चित करना कठिन होता है । मनुष्य भय, संशय, अनिश्चितता तथा सुरक्षाके अभावके कारण चिन्ताग्रस्त होता है और बहुतसे ऐसी अवस्थामें

वास्तविकताका सामना करनेसे घबराते हैं तथा सुदूर अवनतिमें अपना मुँह छिपाते हैं। हमारे दुर्भाग्यसे हमारे देशमें जो साम्प्रदायिक कलह आरम्भ हो गया है वह हमारे कार्यको और भी दुष्कर कर देता है। जनताका ध्यान मौलिक प्रश्नोंसे हट कर गौण प्रश्नोंकी ओर चला जाता है और इस विपाक्त तथा दूषित वातावरणमें जीवनके समाजिक मूल्य और नैतिकता भी नष्ट हो जाते हैं। विद्वेषकी इस अग्निको बुझाना शिक्षितोंका काम है। इससे भी अधिक आवश्यकता है उन उच्च मान्यताओंकी रक्षा करना जिनके आधारपर ही एक सुदृढ़ और जन-तन्त्रात्मक राष्ट्रकी रचना हो सकती है। यदि हमारे नवयुवकोका, जिनके हाथमें नेतृत्व आनेवाला है, जीवनके मूल्योंके प्रति आदरभाव नहीं होगा तो इस देशका भविष्य आशाप्रद नहीं हो सकता। प्रत्येकको अपने दिलको टटोलना है और आत्म-समीक्षा करनी है। हमें सन्देह नहीं कि हमको अपने राष्ट्रको सवल बनाना है, इतना सुदृढ़ बनाना है कि उसका कोई बाल बाँका न कर सके। किन्तु यह इसलिए जिसमें एक स्वस्थ, सुसंस्कृत समाज चिरकालतक मानवताका निरन्तर विकास कर सके। अतः जहाँ हमारे नवयुवकोको सैनिक-शिक्षा लेकर अपनेको देश-रक्षाके कार्यके लिए उपयुक्त बनाना है वहाँ उनको अपने समाजकी अवस्थाका अध्ययन कर अपनी समस्याओंका समाधान करनेकी योग्यता भी अपनेमें प्रतिपादित करनी है। इस युगमें सफलताकी कुञ्जी आत्मसंयम साहस और सद्बुद्धिमें है। हमारी अर्थनीति इतनी पुरानी पड़ गयी है कि आज वह हमारी उन्नतिमें बाधक हो रही है। आर्थिक और सामाजिक विपमताके कारण हमारा समाज छिन्न-भिन्न हो रहा है। कठोर वर्णव्यवस्था, अस्पृश्यता, दरिद्रता और निरक्षरता हमारे समाजके अभिशाप हैं। नवयुवकोको परस्परके भेद-भावको मिटाना है तथा आर्थिक सगठनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देशकी दरिद्रता और बेकारीको दूर करना है। पुनः लोकतन्त्रकी भावनाको पुष्ट करनेके लिए सहकारिताका आन्दोलन अत्यन्त आवश्यक है। लोकतन्त्रके हम अभ्यस्त नहीं हैं और इसीलिए अभी इसकी परम्परा भी प्रतिष्ठित नहीं हुई है। अतः परस्पर सहयोगकी भावनाको पुष्ट कर हम लोकतन्त्रको स्थायी बना सकते हैं तथा गाँवोंमें एक नवीन जीवनका संचार कर सकते हैं। यह सब समाज-सेवाके काम नवयुवकोको करने हैं। यह तभी सम्भव है जब जीवनका कोई गम्भीर उद्देश्य हो और जनताकी हमारी दृष्टिमें प्रधानता हो। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र-निर्माणके कार्यमें अपनी योग्यताके अनुसार भाग ले सकता है। यदि हम अपने उज्ज्वल भविष्यमें निष्ठा रखते हैं और इस बातका ज्ञान रखते हैं कि अपने देशके भाग्यके निर्माणमें हमारा क्या दान हो सकता है तभी हमको कार्य करनेका उत्साह मिल सकता है। नवयुवकोमें काम करनेकी अपूर्व शक्ति, उत्साह और साहस होता है। इसके साथ-साथ यदि सामाजिक आवश्यकताओंका ज्ञान भी हो और लक्ष्य हो तो हमारे नवयुवक आजकी कठिनाइयोंका सामना कर सकते हैं। मुझे आशा है कि हमारे स्नातक एक नवीन दृष्टि और एक नवीन विचार-पद्धतिको लेकर जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं जानता हूँ कि उनका पथ कंटकाकीर्ण है, उनको बनकटी करना है, उनको एक नूतन समाजकी रचना करनी है और उनके साधन और उपकरण स्वल्प और अपर्याप्त हैं। किन्तु यदि उनकी दृढ़ निष्ठा है और वह सत्संकल्पको लेकर अध्यवसायके

साथ आगे बढ़नेको तैयार है तो मुझे अपने देशका भविष्य गौरवमय प्रतीत होता है। इस शुभ संकल्पमें मैं उनके साथ हूँ और मैं उनकी सफलताके लिए प्रार्थी हूँ और मेरी शुभ कामनाएँ उनके साथ हैं।

अब आपकी अनुमतिसे विश्वविद्यालयकी शिक्षाके महत्त्वके सम्बन्धमें तथा उसकी क्या आवश्यकताएँ हैं इस सम्बन्धमें कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि लोकतन्त्रकी स्थापनाके लिए सर्वसाधारणकी शिक्षाकी परम आवश्यकता है। किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि इससे उच्चशिक्षाके महत्त्वमें किसी प्रकारकी कमी आ जाती है। एक सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धतिका हमको विकास करना है। शिक्षाके प्रासादकी आधार-शिला सर्वसाधारणकी प्राथमिक शिक्षा है। किन्तु जिस भवनका निर्माण इस आधारपर होता है उसके कई तल्ले हैं और सबसे ऊँचा तल्ला विश्वविद्यालयकी शिक्षा तथा हर प्रकारकी गवेषणाका है। राज्यका कर्तव्य है कि वह शिक्षाके प्रत्येक अंगको पुष्ट करनेका प्रयत्न करे। शिक्षाका एक निरन्तर क्रम चलता रहता है और सब अंग एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं। अतः एकको दुर्बलकर हम दूसरेकी पुष्टि नहीं कर सकते। विश्वविद्यालयकी शिक्षामें उसका चरमोत्कर्ष पाया जाता है। एक सामान्य नागरिकका विकास करना तथा एक सामान्य सांस्कृतिक दायदकी शिक्षाको सर्वसाधारणके लिए सुलभ कर देना सर्वसाधारणकी शिक्षाका उद्देश्य होना चाहिये। किन्तु बिना उच्चशिक्षाका उचित विधान किये राष्ट्रीय जीवनके विविध क्षेत्रोंके लिए विशेषज्ञ नहीं मिल सकते। आज विज्ञानका युग है। विज्ञानके द्वारा ही हमने प्रकृतिपर विजय पायी है।

आज विज्ञानके बलसे मनुष्यकी दरिद्रता दूर की जा सकती है, वियावानको हम चमन बना सकते हैं। आज मानवी शक्तकी महती वृद्धि हुई है। यह विश्वास होने लगा है कि यह शक्ति असीम है। आज कोई भी परिवर्तन असम्भव नहीं प्रतीत होता है। इसके कारण आधुनिक वैज्ञानिक तथा यान्त्रिक पद्धतिने उन लोगोकी दृष्टि मौलिक रूपसे बदल दी है जो राज्यकी शक्ति संचालित करते हैं। फलस्वरूप राज्यशक्तिके मदसे उन्मत्त लोगोंने समाजके लिए दुर्घटनाएँ उपस्थित कर दी हैं जो भयावह हैं।

आज समाजमें असामञ्जस्य है। यह असामञ्जस्य तबतक दूर नहीं होगा जबतक हम इस बातको स्वीकार नहीं करते कि मनुष्यकी शक्तकी कुछ आवश्यक सीमाएँ हैं, वह अपरिमित नहीं है तथा मनुष्योका एक दूसरेपर जो अधिकार हो उसकी भी सीमा मर्यादित हो जानी चाहिये। एक ओर उद्योग-व्यवसायके मालिक हैं, दूसरी ओर श्रमिकोका समुदाय है। इनके हितोंमें तीव्र विरोध है। यह विरोध जनतन्त्रको छिन्न-भिन्न करता है। यदि समता और जनतन्त्रको सवल बनाना है तो सामाजिक सगठनका वह नमूना जिसे १९ वीं शताब्दीके व्यवसाय-सगठनने कायम किया है, बदलना चाहिये।

मुझे खेद है कि मैं विषयान्तरमें चला गया। मैं निवेदन कर रहा था कि आज हम अपनी समस्याओको विज्ञानकी सहायताके बिना नहीं हल कर सकते। अतः राष्ट्रकी उन्नतिके लिए विज्ञानकी शिक्षाकी उन्नति करना तथा गवेषणाकी समुचित व्यवस्था करना राज्यका कर्तव्य है। राष्ट्र-निर्माणका काम विविध विद्याओंके विशेषज्ञोंके बिना,

नहीं चल सकता। यह ठीक है कि छात्रवृत्ति देकर विदेशमें विद्यार्थी भेजे जा रहे हैं किन्तु कतिपय कठिनाइयोंके कारण इनकी संख्या स्वल्प ही हो सकती है। अतः, आजकी अवस्थाको देखते हुए अपने देशमें विविध प्रकारकी शिक्षाकी विशेष व्यवस्था करनी होगी और कुछ कालके लिए बाहरसे भी विशेषज्ञ बुलाने होंगे। केन्द्रीय गवर्नमेण्टको विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाके व्ययका एक अच्छा भाग देना चाहिये चाहे वह विद्यालय प्रान्तीय विषय ही क्यों न हों। इस सहायताके बिना विश्वविद्यालयोंकी तात्कालिक आवश्यकताओंकी पूर्ति हो सकती है और न उनका विकास ही। केन्द्रीय गवर्नमेण्टको स्वयं इस समय एक बड़ी संख्यामें विशेषज्ञोंकी आवश्यकता है और सदा रहेगी। यह विशेषज्ञ प्रान्तोंके विश्वविद्यालयोंसे ही आते हैं। इनकी संख्या अल्प है। आवादीके २२०६ मेंसे केवल एक व्यक्ति युनिवर्सिटीकी शिक्षा पाता है, जब कि रूसमें अनुपात ३०० मेंसे १ है। अतः राज्यका काम मुकर करनेके लिए तथा विविध सामाजिक सेवाओंका आयोजन करनेके लिए विशेषज्ञोंकी संख्यामें द्रुतगतिसे वृद्धि होनी चाहिये। इस कार्यका महत्त्व सर्वसाधारणकी शिक्षासे भी इस समय अधिक है। इसके लिए पोस्टग्रेजुएटकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक अन्वेषणका समुचित प्रबन्ध तत्काल होना चाहिये। किन्तु इस कार्यके लिए प्रचुर परिमाणमें धन चाहिये। हमारे देशके विश्वविद्यालय आर्थिक सहायताके लिए राज्यपर निर्भर करते हैं। यह सत्य है कि हमारे देशमें दानका बड़ा महत्त्व है और इसकी परम्परा भी है। किन्तु दानका विविध रूप है और जो कुछ ब्रह्मदान मिलता है वह प्रायः स्थानीय विद्यालयोंको जाता है। इस अवस्थामें केन्द्रीय गवर्नमेण्टका विशेष कर्त्तव्य है और हमारी प्रान्तीय गवर्नमेण्टको भी सहायताकी रकमको उचित मात्रामें बढ़ाना चाहिये। यह सन्तोषका विषय है कि माननीय शिक्षामन्त्रीने हालमें युनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमेटीका संगठन किया है और वैज्ञानिक अन्वेषणके कार्यके लिए भी एक समिति नियुक्त की है।

हमारा देश इतना विस्तृत है कि यहाँ परीक्षा लेनेवाले विश्वविद्यालयोंकी भी अत्यन्त आवश्यकता है। यहाँ उच्चशिक्षा थोड़ेसे चुने हुए केन्द्रोंमें नहीं केन्द्रित की जा सकती। लार्ड हैलडेनका तो यहाँतक विचार है कि इंग्लैण्ड ऐसे छोटे देशमें भी ऐसे विश्वविद्यालय अनिवार्य है। इसलिए आगरा विश्वविद्यालयकी नितान्त आवश्यकता है। किन्तु यहाँ भी अन्वेषणको प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

एक दूसरा विषय जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ शिक्षाका माध्यम है। अब समय आ गया है जब हमको राष्ट्रभाषाके द्वारा ऊँची-से-ऊँची शिक्षाका आयोजन कर लेना चाहिये। जब राज काजकी भाषा बदल गयी है तब तो यह काम तेजीसे होना चाहिये। शिक्षाका माध्यम यथासम्भव तत्काल बदल जाना चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमको किसी विदेशी भाषाका अब सहारा नहीं लेना है। विदेशी भाषाकी आवश्यकता बहुत दिनोंतक बनी रहेगी, किन्तु वह शिक्षाका माध्यम न होगी और शिक्षाके कार्यक्रममें उसको गौण स्थान प्राप्त होगा। इस सम्बन्धमें यह भी कहना आवश्यक है कि अपनी भाषामें सब विषयकी ऊँची-से-ऊँची पुस्तकें लिखी जानी चाहिये। किन्तु यह काम किसी एक विश्वविद्यालयके बसका नहीं है। इसके लिए यदि गवर्नमेण्टकी ओरसे कोई

आयोजन हो और उसमें सब विश्वविद्यालयों तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओंका सहयोग लिया जाय तो अति उत्तम हो । एक निश्चित योजनाके अनुसार यह काम होना चाहिये और पाठ्यपुस्तकोंकी रचना जल्द-से-जल्द हो जानी चाहिये । अंग्रेजीके द्वारा हमको यूरोपीय ज्ञान अबतक मिलता रहा है, पर स्वतन्त्र होनेके पश्चात् हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध सब राष्ट्रोंसे हो गया है । ऐसी अवस्थामे अपने देशमें ससारकी विविध भाषाओंकी शिक्षाकी व्यवस्था हमको करनी होगी । यदि सब विश्वविद्यालय मिल-जुलकर इस कामको आपसमें बाँट ले तो यह काम सुचारु रूपसे चल सकता है ।

विद्यार्थियोंकी सख्या निरन्तर बढ़ती जाती है और इसलिए अध्यापक और विद्यार्थी का सम्पर्क भी कम होता जाता है । यह अवस्था अवाञ्छनीय है । परस्परका सम्पर्क बढ़ानेके लिए Tutorial पद्धतिका विस्तार एक अच्छा उपाय है । किन्तु यह पद्धति बड़ी महँगी है और इस कारण इसका विस्तार कठिन है जबतक कि धनका प्रबन्ध न हो । पुनः इस पद्धतिका तभी पूरा लाभ उठाया जा सकता है जब विद्यार्थी इसको अपने कालेजके जीवनका केन्द्र समझे । हालत यह है कि विद्यार्थी इसको पाठ्यक्रमका एक सामान्य अंगमात्र समझते हैं और जबतक परीक्षाका स्वरूप नहीं बदलेगा तबतक अधिकांश विद्यार्थी शिक्षाको वह महत्व नहीं देगे जो उन्हें देना चाहिये । इतना कहनेपर भी यह मानना पड़ेगा कि इस पद्धतिसे कुछ विद्यार्थियोंको लाभ अवश्य होता है । अतः समस्या यह है कि इस पद्धतिको जारी करनेके प्रतिरिक्त और क्या करना चाहिये जिससे विद्यार्थी अध्यापकोंके निकट सम्पर्कमें आये ।

अनुशासनका प्रश्न भी इससे सम्बद्ध है । आज चारों ओरसे इस बातकी शिकायत होती है कि विद्यार्थियोंमें संयमकी कमी हो गयी है । इसके क्या कारण हैं ? इसपर हमको विचार करना है, क्योंकि बिना रोगका निदान जाने रोगका उपशम नहीं हो सकता । इस संयमकी कमीके अनेक कारण हैं । जीवनकी अनिश्चितताके कारण समाजकी सब श्रेणियोंमें असन्तोष पाया जाता है । समाजके मौलिक आधारके सम्बन्धमें ही तीव्र मतभेद है । महायुद्धके पश्चात् आर्थिक कठिनाइयाँ और बढ़ गयी हैं और इसका मनोवृत्तिपर बुरा प्रभाव पड़ता है । आज हमारे देशमें सरकारी विभागोंमें भी कुशलता और अनुशासनकी कमी आ गयी है । सारा देश इस रोगसे ग्रस्त है । आर्थिक कठिनाइयोंको बिना दूर किये पूर्णरूपसे संयमका पुनः प्रतिष्ठित होना सुगम नहीं है । जहाँतक विद्यार्थियोंका सम्बन्ध है उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार कर तथा उनके निकट सम्पर्कमें आकर हम इस शिकायतको बहुत कुछ दूर कर सकते हैं । विद्यार्थियोंको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिसमें वह आत्मसंयमके महत्त्वको समझे । बाहरसे अनुशासनका आरोप प्रायः व्यर्थ हुआ करता है । हमारे विद्यालयोंका वातावरण ही ऐसा होना चाहिये जिसमें असंयमके उदाहरण बहुत कम हो जायें ।

हमारे विद्यार्थियोंको भी समझना चाहिये कि उनको अपने राष्ट्रको सवल बनाना है तथा एक नूतन समाजका निर्माण करना है । समाजके वही नेता और निर्माता होंगे । किन्तु आत्म-संयमके बिना कोई भी व्यक्ति किसी जिम्मेदारीके कामको निभा नहीं सकता ।

शिक्षाकालका उनको अच्छे-से-अच्छा उपयोग करना चाहिये, चरित्रगठन और शरीर-सम्पत्तिके साथ-साथ अपने देशकी वर्तमान समस्याओंका अध्ययन करना चाहिये तथा जनताके निकट सम्पर्कमें आना चाहिये । आजकी समस्याएँ नवीन हैं और जनताकी अभिलाषाओं और आवश्यकताओंको जाने बिना कोई भी कुशल शासक नहीं हो सकता । राष्ट्रके उत्थानके लिए विपुल सख्यामें विद्याचरण-सम्पन्न स्त्री-पुरुष चाहिये जो विविध कार्योंमें निपुण हो और जिन्होंने सेवाका व्रत लिया हो ।

एक प्रश्न हमारे सम्मुख यह है कि किस प्रकार उन निर्धन विद्यार्थियोंके लिए उच्च शिक्षा सुलभ कर सकते हैं जिनमें प्रतिभा है और जो उसके अधिकारी सिद्ध हो चुके हैं । उच्च शिक्षाको गरीब-अमीर सबके लिए सुलभ होना चाहिये । यह ठीक है कि सभी विद्यार्थी युनिवर्सिटी शिक्षाके अधिकारी नहीं हैं । अनुत्तीर्ण विद्यार्थियोंकी बड़ी संख्या इसका प्रमाण है । किन्तु इसका कारण है कि विविध शिल्पकी शिक्षा प्रदान करनेकी समुचित व्यवस्था अबतक नहीं हो पायी है । जब ऐसी व्यवस्था हो जायेगी और जीविकाके विविध द्वार खुल जायेंगे तब स्वतः ही सब विद्यार्थी युनिवर्सिटीमें प्रवेश न लेंगे । किन्तु वे विद्यार्थी जो उसके अधिकारी हैं उससे क्यों वञ्चित रखे जायें केवल इसलिए कि उनके पास साधनोंकी कमी है । ऐसे विद्यार्थियोंकी शिक्षा केवल निःशुल्क ही न होनी चाहिये वरन् उनके भरण-पोषणका भार भी समाजको उठाना चाहिये । विलायतकी युनिवर्सिटियोंमें ४१ प्रतिशत विद्यार्थियोंको किसी न किसी रूपमें सहायता दी जाती है, किन्तु हमारे यहाँ ५ प्रतिशतसे अधिक विद्यार्थियोंको निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाती । इस अनुपातमें वृद्धि होनी चाहिये । यह तभी सम्भव है जब गवर्नमेण्टकी ग्राण्ट बढे और साथ-साथ विश्वविद्यालय अपनी वृद्धि आप करनेके उपाय सोचें । गवर्नमेण्टके सम्मुख अनेक काम हैं और उनमेंसे कई समान रूपसे आवश्यक हैं । उसकी आय भी सीमित है । अतः केन्द्रीय गवर्नमेण्टको युनिवर्सिटी-शिक्षाके लिए पर्याप्त धन देना चाहिये जिसमें गरीब विद्यार्थियोंको भी पूरी सहायता दी जा सके तथा पोस्टग्रेजुएट-शिक्षा और गवेषणाका उचित प्रवन्ध किया जा सके । गरीब विद्यार्थियोंकी सहायताके लिए हमारे प्रान्तके धनवान सज्जनोंको पर्याप्त संख्यामें छात्रवृत्ति देनी चाहिये । विद्यादानसे बढकर कोई दान नहीं है और इसके पानेके सबसे बड़े अधिकारी वह प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जो दरिद्रताके कारण अपनी शक्तियोंके विकासका अवकाश नहीं पाते । प्रान्तके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्डोंको भी इस दिशामें कुछ करना चाहिये । उन्हें अपने जिले और शहरके उन विद्यार्थियोंमेंसे कुछको चुनकर छात्रवृत्ति देनी चाहिये जो उसके पात्र हैं ।

मैंने कुछ ऐसे प्रश्नोंके ऊपर चर्चा की है जो मुझे अत्यन्त आवश्यक मालूम पडे । किन्तु विश्वविद्यालयोंको सफलता तभी मिल सकती है जब अध्यापकोंका पुरस्कार ऐसा हो जिससे उनको सन्तोष हो और उनके चित्तकी एकाग्रता हो सके । आज वस्तुओंका मूल्य इतना बढ गया है कि लेक्चररका काम आजके वेतनमें किसी प्रकार नहीं चल सकता । अतः पुरस्कारमें उचित वृद्धि सब वर्गके अध्यापकोंको हो जानी चाहिये; ऐसा होनेसे ही हमारे अध्यापक दत्तचित्त होकर शिक्षाका काम कर सकते हैं । उचित पुरस्कारके न

मिलनेसे हमारे यहाँ योग्य शिक्षकोकी नितान्त कमी है और यह कमी तभी पूरी हो सकती है जब शिक्षकोकी आर्थिक अवस्थामे सुधार किया जाय । ऐसा करनेसे ही हम उनको समाजमे सम्मानका स्थान दिला सकते हैं ।

मैं एक बार फिर उन सब स्नातकोको वधाई देता हूँ जो आज डिग्री ले रहे हैं । विद्यालयमे रहकर बौद्धिक और नैतिक शिक्षा उन्होने प्राप्त की है । उसका उचित उपयोग करनेका अब समय आया है । मैं आशा करता हूँ कि जिस किसी क्षेत्रमे वह काम करे वह कार्यकुशल सिद्ध होंगे और अपने व्यवहार और चरित्रसे अपने विश्वविद्यालयका गौरव बढ़ावेगे । मैं उनकी उन्नतिकी कामना करता हूँ और प्रार्थी हूँ कि उनको जीवनमे सफलता प्राप्त हो ।^१

अध्यापकोका कर्तव्य

सर मॉरिस गॉयर, स्वागत-समितिके अध्यक्ष एवं सदस्यो, देवियो तथा सज्जनो,

विश्वविद्यालयोके अध्यापकोके इस सम्मेलनका सभापतित्व करनेके लिए जो दया और उदारताके साथ आपने मुझे आमन्त्रित किया है उससे मैं अपनेको गौरवान्वित समझता हूँ ।

आपलोग देशके विभिन्न भागोसे पधारे हैं एक ऐसी समस्याका समाधान करनेके लिए जो आप सबकी सार्वजनिक समस्या है, किन्तु इससे भी बढ़कर आपलोगोके पधारनेका हेतु है अपने अन्दर भावनाओका वह एकीकरण करना जिसके द्वारा आप अपने उद्देश्योको प्राप्त कर सकें और उन आदर्शोको चरितार्थ कर सकें जो आप सबके आदर्श हैं । मैं एक विश्वविद्यालयका अध्यक्ष हूँ, पर मेरा काम मुख्यतः शासनात्मक है । फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाऊँगा कि मैं आपके साथ सम्बन्ध जोड़नेका दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवनका सर्वश्रेष्ठ अंश एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयमे अध्यापन करनेमे बीता है । मैं मुख्यतः अध्यापकोकी विरादरीमे ही हूँ और अध्यापक होनेके ही नाते मैं आपके आह्वानपर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ । आपके सम्पर्कमे आने और आजकी सबसे अधिक जरूरी समस्याओके विषयमे विचार-विमर्श करनेके इस अवसरका मैं स्वागत करता हूँ ।

यह सत्य है कि हमलोगोने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, पर ऐसा प्रतीत होता है मानो अब भी हमलोग पुरानी दुनियामे ही हैं । यह कहते बड़ा खेद होता है कि मुझे देशमे अपने चारो ओर वह युवकोचित उल्लास और साहसका वातावरण नहीं दीखता जिसके द्वारा एक नवजात राष्ट्र अनुप्राणित होता है । ऐसा लगता है कि अभी हमलोगोमे अपने नये जन्म और नयी स्थितिकी चेतना नहीं जागी है । खेदकी बात है कि हम पुरानी विचारधारामे ही पड़े हैं और अपने नये उत्तरदायित्व और कर्तव्योको ठीक-ठीक

नहीं समझ रहे हैं। हमारे विचार-क्रममें गति नहीं है और हममें वह सामाजिक चेतना भी नहीं है जिसके द्वारा ही हम अपनी समस्याओंको ठीक तरहसे समझ सकते हैं। हम ऐसे समयमें हैं जो सतत परिवर्तनका युग है। इसमें अब गतिहीन जड़ीभूत समाजकी मध्ययुगीन भावनाका कुछ काम नहीं रहा, और यदि हममें अपनी नयी परिस्थितियों और नयी आवश्यकताओंके साथ सामंजस्य स्थापित करनेकी बुद्धिमानी और साहस नहीं है तो फल अवश्य ही घातक होगा।

यदि हम सर्वनाशसे बचना चाहते हैं तो हमें इस नयी चुनौतीका सामना करना ही है और यह तभी सम्भव होगा जब हम आत्मपरितोषकी वृत्ति और बौद्धिक जड़त्वको त्यागकर वर्तमान समस्याको नयी रुचि एवं नये दृष्टिकोणसे देखना आरम्भ करें। इस सम्बन्धमें अध्यापकोंका दायित्व सबसे बढकर है। हमलोग नवभारतके नागरिक बननेके पात्र नहीं रहेगे यदि हम इस अवसरके स्तरतक ऊपर उठ न सके और अपने कर्तव्योंका पालन नैतिकताके साथ न करें।

इस लक्ष्यकी सिद्धिके लिए हमें पहले अपना शिक्षा-सिद्धान्त फिरसे निर्धारित करना होगा और नये ढंगसे शिक्षा-पद्धति चलानी होगी। मध्ययुगीन शिक्षामें धनिक-वर्गकी प्रधानता थी, अब इस युगकी शिक्षा मुख्यतः जनतन्त्रात्मक होगी। यदि हम अपना जीवनक्रम सुखमय और सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा-सम्बन्धी नवीन सिद्धान्त और जीवन-सम्बन्धी नवीन मान्यताएँ स्वीकार करनी होंगी। शिक्षाका सच्चा ध्येय ऐसे व्यक्तित्वके निर्माण एवं विकासमें सहायता पहुँचाना है जिसमें ज्ञान, सहज प्रवृत्तियाँ और भाव एकीभूत होकर एक सम्पूर्ण जीवन बने। साथ ही इस पूर्ण विकसित व्यक्तित्वके लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक जीवनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो। समाजका अङ्ग होकर ही व्यक्ति अपनी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमारी गति शनैः-शनैः एक विश्व-समाजकी ओर है, और यदि हम इस विश्व-समाजके नागरिककी भाँति रहना किंवा व्यवहार करना नहीं सीख जाते, तो आनेवाले युगकी चुनौतीका सामना हम नहीं कर सकेगे। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक संस्थाएँ उत्तरोत्तर इतनी पेचीली होती जा रही हैं कि यदि प्रत्येक नागरिक वर्तमान समस्याओंकी ओर अपेक्षित अभिरुचिके साथ ध्यान नहीं देगा, तो हमें दुःखद स्थितिका अनुभव करना होगा। अतएव अध्यापक-वर्गको नये संसारमें बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्यपालन करने है। अब वे जनताके प्रतिदिनके जीवनसे पृथक् नहीं रह सकते। उन्हें समाजकी बौद्धिक एवं व्यावहारिक समस्याओंके सम्बन्धमें सतर्क और सचेष्ट रहना होगा। विश्वविद्यालयका वह पुराना वातावरण जिसमें केवल त्रौद्धिक अध्ययन एवं विकास हुआ करता था, अब एकदम बदलना होगा। अध्यापकवर्गको अपनी उदासीनता, विराग, आलस्य और निष्क्रियताका त्याग करना पड़ेगा और देशकी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओंके समाधानमें सक्रिय भाग लेना होगा। आगे बढ़कर उसे नये समाजकी व्यवस्थामें सक्रिय योग देना होगा। उसे यह निर्णय करना होगा कि पुरानी संस्कृति और शिक्षा-सिद्धान्तका कितना अंश सुरक्षित रखना है और कितना अंश केवल रुढ़िगत महत्त्वका, पर यथार्थमें निःसार होनेसे निकाल

फेकना है। इस क्षेत्रमें सफल होनेके लिए आवश्यक है कि अध्यापक-वर्गमें नवीन उद्देश्यों और आदर्शोंपर दृढ़ विश्वास और आस्था हो और इन्हें प्राप्त करनेके लिए वह उत्साहके साथ दृढ़प्रतिज्ञ होकर पूरा प्रयत्न करे।

अध्यापक-वर्ग अपने कर्तव्य और व्रतका पूर्ण परिपालन कर सके, इसके लिए उसका स्तर उन्नत करना होगा और उसकी जीविकाकी ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि आर्थिक कठिनाइयोंसे मुक्त होकर वह एकचित्त हो अपने जीवन-कर्तव्यके पालनमें लग सके। उसकी बौद्धिक और अध्ययनगत स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रखनी होगी और सभी प्रस्तुत विषयोंपर अपने विचार प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता उसे देनी होगी। सब विषयोंमें उसका रुख तटस्थ तो नहीं हो सकता, पर उसकी विचारधारा पूर्वाग्रहदूषित न हो, हर चीजको वह निष्पक्ष होकर देख सके। छात्रोंके समक्ष किसी विषयपर दूसरोंके विचार और दृष्टिकोण सत्यता और सचाईके साथ रख सके। अध्यापक-वर्गकी विचारधारा किसीके द्वारा दबायी न जाय और न कोई अधिकारी राजनीतिक दल उसे विवश कर उससे अपने विशेष स्वार्थोंकी सेवा ले। विचारोंकी स्वतन्त्रता नितान्त रूपसे आवश्यक है, क्योंकि जबतक अध्यापक और उसके छात्रोंके बीच विचारों और भावनाओंका उन्मुक्त आदान-प्रदान नहीं होता तबतक ऐसे सामाजिक जीवनका विकास नहीं हो सकता जो गतिशील हो। हम अपने विद्यार्थी-वर्गमें विनय एवं शीलके होनेकी अपेक्षा करते हैं। पर यह किसी बाह्य शक्ति किंवा अधिकारका फल न हो प्रत्युत उनकी अपनी आन्तरिक प्रवृत्तियोंसे ही उद्भूत और विकसित हो। इस प्रकार उनमें स्वतन्त्ररूपसे सोचने और कार्य करनेकी शक्ति बढ़ेगी।

किन्तु इस प्रकारके सच्चे शिक्षा-सिद्धान्तोंको चरितार्थ करनेमें उपयोगी होनेके लिए अध्यापकोंको स्वयं अपनेको फिरसे शिक्षित करना और उसे जो कार्य और व्रत पालन करना है उसके लिए उपकरण एकत्र करके सन्नद्ध होना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्तिके लिए शिक्षाका एक निरन्तर क्रम होना चाहिये। ससारके द्रुतगामी परिवर्तनोंको देखते हुए हमें भी समय-समयपर अपनी विचार-बुद्धिको फिरसे उसके साथ मिलानेकी आवश्यकता है। अध्यापक अपने आपको सुसंगठित भी करे ताकि वे शिक्षासमस्याओंपर विचारविमर्श करनेके लिए बारम्बार एकत्र हो सके। यही उपाय है जिसके द्वारा वे अपने वैध स्वत्वोंकी रक्षा कर सकते हैं और समाजके सुधार एवं उन्नयनके क्षेत्रमें अपना प्रभाव डाल सकते हैं। हम इस बातकी ओर भी आपलोगोंका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि देशमें एक ऐसे राष्ट्रीय संघटनके होनेकी आवश्यकता है, क्योंकि अभी ऐसा कोई संघठन नहीं है जिसमें देशके सभी वर्गोंके अध्यापकोंका समावेश हो। यह सत्य है कि विभिन्न कोटिकी पाठशालाओं और अध्यापकोंके संगठन अलग-अलग भी हो सकते हैं, परन्तु यह कोई कारण नहीं है कि सभी कोटियों एवं वर्गोंके अध्यापक मिलकर अपनी एक राष्ट्रीय संस्था न बनायें। यह आवश्यक है कि सब प्रकारके अध्यापक अपनी एक प्रकारकी एकताका अनुभव करें। इस प्रकार वे अध्यापक जो अध्यापकोंके क्रममें सबसे नीचे हैं, अपनेसे बड़े अध्यापकोंके सम्पर्क, राय एवं पथ-प्रदर्शनसे लाभान्वित होंगे और यह अनुभव करेंगे कि सभी अध्यापक मिलकर एक

सम्मिलित विरादरीमें शामिल है। साथ ही इस प्रकारके सम्पर्को अध्यापकोके उन्नयन और सुधार-कार्यको बल और प्रगति प्राप्त होगी।

जब अध्यापकोकी एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो जायगी तभी वे अध्यापन करनेवाले लोगोके विश्वव्यापी संगठनकी बात सोच सकेंगे। सन् १९८६ के अगस्त मासमें न्यूयार्कमें ऐसी एक संस्थाकी स्थापना एक सम्मेलनके अवसरपर हुई थी, जिनमें ३० राष्ट्रोंके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस संस्थाकी स्थापना ठीक समयसे ही हुई थी। जिदामात्र एक सहयोगी प्रयास है और सहकारिताके उपायोके अनुसरणद्वारा ही हम वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शोधके कार्यका विस्तार करनेकी आशा कर सकते हैं। मानव-कल्याणको अग्रसर करनेके निमित्त भी अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और महानुभूतिपूर्ण समझदारीकी आवश्यकता है। यह बात भी स्पष्ट है कि राष्ट्रोंके बीच जो आपसकी गलतफहमी है उसे दूर करके और समानताके सिद्धान्तपर आधारित पारस्परिक कल्याणभावनाके ही द्वारा हम स्थायी शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करनेकी आशा कर सकते हैं। भारतवर्षके लिए यह वाछनीय नहीं होगा कि वह सबसे पृथक् और इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासके बाहर रहे। उक्त संस्थाके ध्येय प्रगणनीय हैं। इसका उद्देश्य है कि संसारकी जितनी अध्यापकोंकी संस्थाएँ हैं सबसे ऐक्य स्थापित हो जाय ताकि नगीको बिना किसी भेदभावके पूर्ण एवं निर्बाध शिक्षा प्राप्त हो सके। अध्यापकोका स्तर ऊँचा उठे और अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिताके लिए उपयुक्त नुयोग प्रगस्त हो। किन्तु मेरा विनम्र मत है कि सबसे पहले हम एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था स्थापित करें जिसमें भारतवर्षके सभी कोटियोंके अध्यापक आ जायँ, ताकि विश्वव्यापी संगठनमें भारतका समुचित प्रतिनिधित्व हो सके और यह संस्था देशके अध्यापकोंकी विरादरीका प्रतिनिधित्व कर सके।

मैं जानता हूँ, बहुतसे अध्यापक इस विचारके हैं कि अध्यापकोका संगठन न केवल अनावश्यक है, अपितु यह उनके लिए अशोभन है, क्योंकि उनकी समझमें इसमें ट्रेड यूनियनवादकी गन्ध आती है। मेरा मत इसके विपरीत है। हड़ताल करना अध्यापकोंके गौरवके लिए अनुचित जैच सकता है, पर मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दीखता कि अपने हितोंकी रक्षाके लिए और साथ ही सांस्कृतिक उद्देश्योंकी उन्नतिके लिए अध्यापक अपनेको नुसंगठित क्यों न बनावे। हर जगह ऐसी संस्थाएँ हैं। अध्यापकोको अपनी स्वयं शिक्षाके लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। मेरी समझमें नहीं आता कि यदि अध्यापक अपने लिए अपनी संस्थाद्वारा जीविकाका समुचित स्तर प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है तो उसके लिए यह अप्रतिष्ठाकी बात क्यों समझी जाती है। हमें भूलना नहीं चाहिये कि अध्यापकोका वेतन सबसे कम है। पर दूसरे पेशोंके लोगोंके साथ जिन्हें इनके बराबर ही योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, यदि इनकी तुलना की जाय तो सामाजिक स्तरकी दृष्टिमें अध्यापकगण दूसरोंकी अपेक्षा नीचे मिलते हैं। मुख्यतः यही कारण है कि प्रत्येक देशमें ट्रेड अध्यापकोंकी बहुत ही कमी है और यहाँ युद्धके बादसे सभी देशोंमें प्राथमिक पाठशालाओंके अध्यापकोका काम बहुत नीचे गिरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे समुन्नत देशोंमें भी प्राथमिक

पाठशालाओंके लिए अध्यापकोकी कमी है और इसका कारण यही बताया जाता है कि इस वृत्तिमें आर्थिक लाभकी कमीके कारण पर्याप्त आकर्षण नहीं रहा ।

इस युगमें जब कि जीवनकी बहुमूल्य वस्तुएँ धनिकोंके ही घर भरती हैं और धन ही सब बातोंका मापदण्ड बन गया है तब बेचारा अध्यापक अपने वेतनमें वृद्धि और अपने जीवनका स्तर सुधारनेके लिए आन्दोलन करता है तो इसमें वह दोषका भागी नहीं । अध्यापक समाजकी धुरी है, क्योंकि शिक्षा राष्ट्रके पुनरुज्जीवनकी सभी योजनाओंका महत्त्वपूर्ण अंग है । अतएव सरकार और स्थानीय अधिकारी दोनोंके लिए उचित है कि ऐसी व्यवस्था करे कि नयी योजनामें अध्यापकवृन्द अपने उचित स्थान एवं स्तरपर आसीन हो । अच्छीसे अच्छी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें अध्यापक अपनी अध्यापनवृत्ति त्यागकर अच्छे वेतन और जीवनके उत्तम उपकरणोंकी प्राप्तिके लिए अन्यत्र न चले जायँ । जब मैं देखता हूँ कि हमारे उत्तम-से-उत्तम अध्यापकोंमेंसे लोग विश्व-विद्यालय छोड़कर सरकारी नौकरी या उद्योग-धन्धोंमें काम करनेके लिए चले जाते हैं जिसके कारण राष्ट्रकी शिक्षाको बड़ा धक्का पहुँचता है तो मुझे बड़ी वेदना होती है ।

इस प्रसंगमें मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि सारे देशमें विश्वविद्यालयोंके अध्यापकोंका केवल एक ही सगठन होना वाछनीय है । मुझे मालूम हुआ है कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालयाध्यापक सघ (All India University Teachers' Federation) नामकी एक संस्थाका जन्म हो चुका है । गत वर्ष इसका सम्मेलन हुआ था । उसने अपना विधान बना लिया है और आगामी वर्षके प्रारम्भमें ही यह अपना प्रथम अधिवेशन करने जा रहा है । यह सत्य है कि कुछ विश्वविद्यालय अभी इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं और अभी इसका कार्य ठीक तरहसे प्रारम्भ नहीं हो पाया है । आशा है कि हमारा यह सम्मेलन इसपर ध्यान देगा और यह स्थिति नहीं आने देगा कि ऐसी दो संस्थाएँ बन जायँ जो परस्पर प्रतिद्वन्द्विता एवं ईर्ष्या करने लगे । दोनों संस्थाओंके सूत्रधारोंको चाहिये कि दोनोंके सगठनोंको एक और सुसंगत करनेके लिए जो कुछ सत्यताके साथ सम्भव हो, अवश्य करे । मैं नहीं जानता कि इनके बीच वे कौनसे महान अन्तर है, जिनके कारण दोनों एक दूसरेसे अभी तक पृथक् रहे, चाहे जो अन्तर हो, वे इतने महत् नहीं हो सकते कि उनके कारण ऐक्य स्थापित न हो सके । मैं नहीं समझता कि उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं । जब उद्देश्यों और ध्येयोंमें ऐक्य है तो कोई कारण नहीं है कि सगठनगत ऐक्य क्यों न स्थापित हो । यदि दोनों ओर सद्भावना हो, तो मुझे आशा है कि इस संस्थाके सगठनके पूर्व ही दोनों संस्थाएँ मिलकर एक हो जायँगी । स्थानिक स्वार्थकी तथा ऐसी ही अन्य बातें कभी-कभी व्यवधान उपस्थित कर सकती हैं, पर ये बातें ऐसी नहीं हैं कि उनका अतिक्रमण सम्भव न हो । मैं इस उत्तम कार्यमें अपनी सेवा अर्पित करता हूँ और आपलोगोंसे तथा उस दूसरी संस्थाके सदस्योंसे अपील करता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धिमें मेरे साथ सहयोग करे । आशा है, आपलोग इस विषयपर एक प्रस्ताव रखेंगे और ऐसे नियम भी निर्धारित करेंगे जिनके द्वारा विश्वविद्यालयोंके अध्यापकोंके बीच ऐक्य स्थापित हो सके । यदि

हम एक साथ होनेके लिए सभी सम्भव उपायोका उपयोग नहीं करते तो हमारा श्रीगणेश शुभ नहीं होगा ।

मुझे यह भी अपेक्षा है कि जिन समस्याओंकी चर्चा मैं इस अभिभाषणमें करूँगा उनके विषयमें अपने मत भी प्रकट करूँ । मुझे निश्चय है कि आप उनपर ध्यान देंगे और उनके विषयमें विचार करेंगे । ऐसी भी समस्याएँ हैं जिन्हें आप बहुत महत्वपूर्ण समझेंगे, किन्तु इस अल्पकालीन अधिवेशनमें उनपर विचार-विमर्शके लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सकेगा । जैसा कि आपके परिपत्रसे सुस्पष्ट है आप लोग विशेष रूपसे इस प्रश्नपर विचार करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालयोंमें शिक्षणका माध्यम क्या हो ।

इस अन्तिम प्रश्नपर ही मैं सर्वप्रथम विचार करूँगा, क्योंकि इसीपर सरकार एवं विश्वविद्यालयोंका विशेष ध्यान है, अतः इसका समाधान तुरत होना चाहिये । यह तो सभी मानते हैं कि कमसे-कम हाई स्कूलकी शिक्षातक मातृभाषाको ही शिक्षाका माध्यम रखना चाहिये । किन्तु विश्वविद्यालयमें पहुँचनेपर शिक्षाका माध्यम क्या हो, इस विषयमें एकमत नहीं है । इण्टर-युनिवर्सिटी बोर्डने तो मातृभाषाको विश्वविद्यालयमें भी शिक्षाका माध्यम रखनेके विरुद्ध मत प्रकट किया है । परन्तु सेण्ट्रल ऐडविजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशनने यह राय दी है कि उच्चतर शिक्षालयोंमें भी मातृभाषाके ही द्वारा शिक्षा दी जाय और इण्टरयुनिवर्सिटी बोर्ड उसके साधन और उपाय सूचित करे । यह सिफारिश इस विषयकी खोज करनेकी ही सिफारिश थी । इस क्षेत्रमें एक कदम और आगे बढ़ा, जब अखिल भारतीय शिक्षा-सम्मेलनने अपने जनवरी सन् १९४८ वाले अधिवेशनमें वाइसचांसलरों और कुछ विशेषज्ञोंकी एक समिति इस विषयपर सुनिश्चित विचार देनेके लिए नियुक्त की । इस समितिकी बैठक सन् १९४८ के मई मासमें हुई और बहुत कुछ विचार-विमर्शके बाद यह निश्चय हुआ कि विश्वविद्यालयोंकी शिक्षा भी मातृभाषाके ही माध्यमद्वारा दी जाय । इस समितिके समक्ष एक विचार यह रखा गया था कि विश्वविद्यालयोंमें राष्ट्रभाषाकी शिक्षाका माध्यम बनाया जाय, किन्तु उन लोगोंने इसे स्वीकार नहीं किया । समितिसे यह कहा गया कि अंग्रेजी भाषाने कम-से-कम एक काम बहुत अच्छा यह किया कि उससे हम सबको विचार करने और उन्हें व्यक्त करनेका एक माध्यम मिला और इस प्रकार देशमें एक एकीकरण सिद्ध हुआ । देशके सभी विश्वविद्यालयोंमें एक ही माध्यम रखनेकी महत्वपूर्ण उपयोगितापर जोर दिया गया था और यह भी कहा गया था कि इस प्रकार जो सुभीता प्राप्त होगा वह राष्ट्रभाषाका केवल साधारण ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उसे अनिवार्य रूपसे पढ़ानेसे नहीं सिद्ध हो सकेगा । मेरी समझमें नहीं आता कि राष्ट्रभाषाको यदि विश्वविद्यालयोंमें शिक्षाका माध्यम नहीं बनाया जाता तो राष्ट्रीय महासभाका कार्य किस प्रकार सम्पादित किया जायगा । राष्ट्रभाषा अपने समुचित स्तरपर तभी स्थापित हो सकेगी और राष्ट्रीय महासभा एवं अन्य राष्ट्रीय सभाओंमें विचार-विमर्शका समुचित माध्यम तभी बन सकेगी, जब उसे सभी विश्वविद्यालयोंमें शिक्षाका माध्यम बना दिया जायगा । इसके साधारण ज्ञानके द्वारा ही व्यवस्थापिका सभाओंमें होनेवाले विचार-संघर्षोंमें सदस्य अपना पूर्ण सहयोग देनेमें समर्थ नहीं होंगे । महासभामें बहुतसे महत्वपूर्ण एवं पेचीदे

राजनीतिक और अर्थशास्त्र-सम्बन्धी प्रश्नोंपर वाद-विवाद होता है और जबतक किसीको उसकी भाषाके माध्यमसे अपने सर्वोत्तम विचार व्यक्त करनेका अभ्यास नहीं होता, तबतक उसे परामर्शोंमें भाग लेनेमें सकोच होगा और यदि किसी प्रकार उसने कुछ साहस किया भी तो उसका भाषण भटकता हुआ और अप्रभावशाली होगा और इस प्रकार वह सदस्य भाषणकलाकी दक्षतासे कोई प्रभाव नहीं पैदा कर सकेगा । ऐसे सदस्यमें एक कमी सदैव बनी रहेगी । सम्भव है कि उसमें विषय-विशेषके सम्बन्धमें चलनेवाले विचार विमर्शमें महत्वपूर्ण योग देनेकी क्षमता हो, पर सभामें उसके मतका कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि वह राष्ट्रभाषामें अपने विचार उन्मुक्तरूपसे विना किसी हिचकिचाहटके व्यक्त करनेकी क्षमता नहीं रखता । जब राष्ट्रका सब कार्य राष्ट्रभाषाके द्वारा होने लगता है तभी राष्ट्रके भाव, और आदर्श सब एक जीवन बनते हैं । सोवियत रूसका उदाहरण हमारे सामने विद्यमान है । वहाँ रूसी भाषा प्रान्तीय भाषाओंके साथ ही एक अनिवार्य विषयकी भाँति आरम्भसे ही पढ़ायी जाती है ।

यदि कोई अपनी भाषाके विषयमें पक्षपात रखता है तो यह बात स्वाभाविक ही है और समझमें आने लायक है । मैं यह भी जानता हूँ कि जिन लोगोकी मातृभाषा पर्याप्त रूपसे समृद्ध है, उनके लिए तो किसी दूसरी भाषाको उच्चतर शिक्षाके माध्यमके रूपमें स्वीकार करना और भी कठिन हो जाता है । किन्तु जो लोग सदैव यह समझते रहे हैं कि अंग्रेजोंसे हमारा सम्पर्क भगवानकी देन और छिपा हुआ वरदान है, और जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षाकी बड़ी प्रशंसा इसीलिए की है कि उसने देशके एकसूत्रीकरणमें बड़ा काम किया है, उन्हें तो हमारे राष्ट्रीय जीवनकी नयी व्यवस्थामें राष्ट्रभाषाको वही स्थान देनेमें कोई संकोच न होना चाहिये । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे प्रस्तावकी परिधि बहुत सीमित है, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि राष्ट्रभाषा माध्यमिक शिक्षाके माध्यमके रूपमें अथवा प्रान्तीय सरकारोंके शासनके कामोंकी भाषाके रूपमें स्वीकार की जाय । मैं समझता हूँ कि आज शायद यह सम्भव भी नहीं है कि दूसरे प्रान्तोंके लोगोको यह प्रस्ताव स्वीकार्य हो सके । किन्तु मुझे निश्चय है कि बहुत दिनोंके पूर्व ही उन्हें स्वानुभवसे यह विश्वास हो जायगा कि हमलोगोंमेंसे कुछने जो प्रस्ताव राष्ट्रके सामने रखा है उसका अनुसरण किये विना अपने देशका काम आगे नहीं चलेगा । फिर भी, मैं कहता हूँ, हमें इस विषयमें अपने दिमाग खुले रखने चाहिये और स्थानीय भावनाओंको ऐसे समय अपने ऊपर अधिकार नहीं जमाने देना चाहिये जब हम राष्ट्रीय महत्वकी किसी समस्याके विषयमें कोई निर्णय करते हो । मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि जबतक कि हममें विश्वविद्यालयोंके लिए शिक्षाके माध्यमके विषयमें एकमत नहीं होता तबतकके लिए राष्ट्रीय महासभामें सदस्योंको उसी भाषामें बोलनेकी स्वतन्त्रता दी जाय जिसमें वे बोलना चाहें । स्पष्ट है कि ऐसे मामलोंमें कोई बात अनिवार्य नहीं की जा सकती और दूसरोंके मनमें विश्वास पैदा करके ही तथा प्रचारद्वारा ही कार्यसिद्धिकी आशा की जा सकती है ।

जिस प्रकार राष्ट्रभाषाको उच्चतर शिक्षाके माध्यमके रूपमें स्वीकार कर लेनेसे सारे देशके लिए विचार करने और उसे व्यक्त करनेके लिए एक माध्यम मिल जायगा उसी

प्रकार एक ही लिपिद्वारा अन्तर्प्रान्तीय एकताकी भावना उत्पन्न करने और उसे अग्रसर करनेमें भी सहायता मिलेगी । हम सब जानते हैं कि भाषा और लिपिमें कोई अविच्छेद सम्बन्ध नहीं है और उन दिनों जब रोमन लिपिके प्रयोगके लिए विश्वव्यापी आन्दोलन चल रहा है, मैं नहीं समझता कि इस देशकी भाषाओंके लिए एक ही लिपिकी माँग करना कोई बहुत बड़ी माँग करना है । यह तो बहुत ही सौम्य प्रस्ताव है, इसे स्वीकार करनेमें कोई हिचकिचाहट न होनी चाहिये । इसकी मुविधाएँ सुस्पष्ट हैं । हमारे लिए एक दूसरेकी भाषाओं और साहित्योंका ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार अन्तर्प्रान्तीय विरोध और दुर्भावना दूर करनेमें और राष्ट्रीयताकी भावना उत्पन्न और विकसित करनेमें सहायता मिलेगी । हमलोग ऐसे युगमें हैं और संसारकी इस युगमें ऐसी अवस्था है कि हमसे प्रत्येकके लिए पड़ोसी राष्ट्रोंकी रहन-सहन, संस्कृति और जीवनक्रमकी यत्किचित् जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है । तब अपने ही देशके विभिन्न प्रान्तोंमें रहनेवाले अपने देशवासियोंके सांस्कृतिक जीवनको समझना कितना अधिक महत्त्वपूर्ण है यह सभी समझ सकते हैं । पारस्परिक सहानुभूति और सद्भावना बहुत सुगम हो जायगी, यदि हम विभिन्न प्रान्तीय भाषाओंके लिए एक ही लिपि स्वीकार कर लें । यह एक व्यापक सुधार है, पर इसका फल भी बहुत व्यापक होगा । सच तो यह है कि यदि हम यह सुधार प्रवर्तित नहीं करते तो राष्ट्रहितकी ही हम उपेक्षा करते हैं अथवा उसकी ओरसे आँखें बन्द किये हुए हैं । मेरी समझमें सब भाषाओंके लिए एक ही लिपिका प्रश्न वही महत्त्व रखता है जो सारे देशके लिए एक राष्ट्रभाषाका प्रश्न । यह भी आवश्यक है कि सभी भारतीय भाषाओंके लिए एक ही वैज्ञानिक शब्दावली बनायी जाय । हमारी एकताके मार्गमें जितने कृत्रिम व्यवधान हैं, उन सबको ही हटानेके लिए हमें सन्नद्ध होना है । पुनरुज्जीवनवाद (Revivalism) से हमारा काम नहीं चलेगा । हमें आगे देखना होगा और ऐसे सब परिवर्तन करने होंगे जो स्वस्थ राष्ट्रीय जीवनके लिए नितान्त आवश्यक हैं । वर्गवाद और प्रान्तवादसे ऊपर उठनेका साहस और सुविचार हममें होना चाहिये और सब चीजोंको विशाल दृष्टिसे देखते हुए दृढताके साथ राष्ट्रहितकी नीतिको जानना चाहिये ।

कोई यह न समझे कि मैं भाषाके आधारपर प्रान्तोंके पुनर्संगठनके विरुद्ध हूँ । मैं उन लोगोंसे हूँ जो यह मानते हैं कि देशके लिए संघीय विधान (Federal Constitution) सबसे अधिक व्यावहारिक होगा, क्योंकि यह हमारे इतिहास एवं परम्पराके सर्वथा अनुकूल है । मानव-बुद्धिमें हमारी इतनी आस्था है कि उसके द्वारा हम अपने संघीय विधानमें ऐसी बातोंका समावेश कर सकेंगे कि देशकी एकता अक्षुण्ण रखी जा सके । साथ ही सबके लिए एक ही सामाजिक और आर्थिक नीति, सभी जातियों और धर्मोंके लोगोंके लिए एक ही कानून, एक ही राष्ट्रभाषा और एक ही राष्ट्रलिपि, ये सब ऐसे साधन हैं जिनके लिए राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सकती है । इससे बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण तो जनताके सभी वर्गोंमें जनतन्त्रीय भावना भर देना है । सब प्रकारकी असमानताओंको दूर कर देना चाहिये और सभी वर्गोंके लिए आत्म-विकासके समान अवसर मिलने चाहिये । यही नहीं, जो लोग सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछड़े हुए हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिये,

ताकि उनकी पिछड़ी स्थितिका यथासम्भव शीघ्र ही निराकरण हो जाय । स्वतन्त्रता और समानताकी भावनाके साथ-साथ एकताकी भावनाका भी प्रादुर्भाव होता है, और कोई कारण नहीं है कि जिन बातोंने आज हमें एक दूसरेसे अलग कर रखा है उन्हें हटा देनेपर हम विभाजक वृत्तियोंको काबूमें न रख सकें ।

अब हम सक्षेपमें उन दो-एक बातोंका विचार करेंगे जिनका सम्बन्ध विश्वविद्यालयकी शिक्षासे है । यह युग ही विज्ञान और विशिष्ट विषयोंके विशिष्ट अध्ययनका है । वैज्ञानिक साधनोंके उपयोगद्वारा आज हमारी समस्याओंमेंसे अनेकोंका समाधान हो सकता है । उदाहरणके लिए आप हमारी गरीबी, रोग, निरक्षरता, कृषि और उद्योग-धन्धोंके वैज्ञानिक आधारपर सगठनकी समस्याओंको ले सकते हैं । विज्ञानके द्वारा प्राकृतिक शक्तियोंका उपयोग समाजके हितके लिए किया जा सकता है और विज्ञान हमें युक्तियुक्त विचार करना भी सिखाता है । मनुष्यकी सहज प्रवृत्तियाँ उसकी बुद्धिको दबा रखती हैं, अतः इस ठीक रास्तेपर चलनेका अभ्यास करा देनेसे हम उन्हें अपने वशमें रख सकते हैं । इस सम्बन्धमें समाज-विज्ञानका महत्त्व स्पष्ट है । यह विज्ञान अभी शैशवावस्थामें है, पर अध्ययन और अनुसन्धानके विषयके नाते इसका महत्त्व बढ़ता जा रहा है । विज्ञान और मनोविज्ञानके नवीन सिद्धान्तोंने मानव-प्रकृति तथा जगत्सम्बन्धी हमारी धारणाओंको बदल डाला है । मनुष्य और प्रकृतिके विषयमें हमारे परम्परागत ज्ञानको अपना स्थान विज्ञानको देना होगा । हमें अपनी बौद्धिक विचार-पद्धति विकसित करनी होगी और जीवनकी जनतन्त्रात्मक रीति ग्रहण करनी होगी । इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए आवश्यक है कि प्रारम्भसे ही हमारे पाठ्यक्रममें विज्ञानका अनिवार्य स्थान रहे और सामाजिक विज्ञानोंके उच्च अध्ययनको उत्साहित कर पूर्ण प्रश्रय दिया जाय । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अधिकाधिक सध्यामें वैज्ञानिक पैदा हो और प्रत्येक विश्वविद्यालयमें सभी क्षेत्रोंमें वैज्ञानिक शोधका समुचित प्रवन्ध हो ।

यह दुर्भाग्यकी बात है कि राजनीतिज्ञों एवं युद्धप्रवर्तकोंद्वारा विज्ञानका बहुत ही जघन्य दुरुपयोग किया जा रहा है । सङ्कुचित राष्ट्रीय भावनाओंके कारण जो ससारव्यापी सघर्षोंके मूलमें हैं, और जो राष्ट्रीय गर्व एवं पक्षपातका पृष्ठपेपण करती हैं, विज्ञानका उपयोग शत्रुराष्ट्रोंके नाश और दूसरे राष्ट्रोंकी आर्थिक स्थितिको अधिकारगत करनेके लिए किया जाता है । विज्ञान उसी दशामें वरदान स्वरूप है जब वह मानवीय मान्यताओंके साथ सम्बद्ध रहे । यदि हमारे वैज्ञानिक समाजके प्रति अपने दायित्व समझते हैं तो वे हीन भावनाओं और प्रवृत्तियोंका परित्याग कर देंगे और युद्धके प्रवर्तकोंके हाथों अपनेको औजारोंकी भाँति जानेसे इनकार कर देंगे, और विज्ञानका इस प्रकारका दुरुपयोग नहीं होने देगे । तब मनुष्यके प्राणोंका मूल्य समझा जायगा और विनाशकारी साधातक इजनोंका निर्माण समाप्त हो जायगा । किन्तु यह तभी सम्भव है जब साधारण जनताको समुचित ढङ्गी शिक्षा दी जाय, और वह राजनीतिज्ञोंकी चाले समझ सकनेके लिए पर्याप्त रूपसे ज्ञानवती एवं बुद्धिसम्पन्न हो जाय और उनके द्वारा चालित होनेसे इनकार कर दे । अब सामाजिक विज्ञानोंकी ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है, इससे यह आशा

करनी चाहिये कि वह समय दूर नहीं है जब हम इन नये विज्ञानोंकी सहायतासे मानव-कल्याणके लिए समाजगत सम्बन्धोंका नियमन कर सकेंगे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सभ्यताकी रक्षा तभी हो सकती है जब राष्ट्रके नेतृत्वमें शिक्षा-भविष्यमें अधिकाधिक भाग लेने लगे ।

इतिहास बताता है कि राष्ट्रीय भावनाके निर्माणमें पाठशालाका बहुत महत्त्वपूर्ण भाग रहा है । पाठशालाके द्वारा राष्ट्रके प्रति-श्रद्धाकी भावना सबल होती रही है और राष्ट्राभिमान और अपने राष्ट्रकी महत्ताके विषयमें अत्यधिक आस्था पैदा होती रही है । फ्रांसिस्ट देशोंमें जहाँ नये नेताओंने जनतन्त्रीय एवं पार्लामेण्टरी भावनाओंके विरुद्ध जनताको, भड़काया और “अधिकारिणी जाति” की मिथ्या कल्पनाका सृजन किया, यह राष्ट्रीय भावना निम्नकोटिकी होकर जघन्य होती गयी । इन लोगोंने स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्वकी भावनाओंपर प्रहार किया, इतिहासमें विपर्यय उपस्थित किया और नवयुवकोंको वरगलाकर उन्हें पापपूर्ण सिद्धान्तोंमें दीक्षित किया । आज ससारमें राष्ट्रगत लोभ और राष्ट्रगत घृणाकी भावना अत्यधिक हो गयी है । बड़े खेदकी बात है कि हम युद्धके सबक भूल गये । निश्चय ही हम विकासक्रममें ‘यूथ’की स्थितिसे बढ़कर राष्ट्रकी स्थितितक पहुँच गये हैं और इस अर्थमें हमने कोई छोटा लाभ नहीं उठाया है । किन्तु अभी हमारी कुछ यूथगत सहज प्रवृत्तियाँ सबल हैं, गायद पहलेसे अधिक शक्तिमान् हैं; केवल बाह्य लक्षण, पताकाएँ किवा नारे बदले हैं । अतएव आवश्यक है कि सभी शिक्षा-प्रवर्तक इस झूठी और भयावह राष्ट्रीयताकी भावनाका विरोध करें । पूर्णरूपसे जनतन्त्र व्यवहारमें लाया जाय तभी राष्ट्रीयताको भ्रामक मार्गोंमें जानेसे रोका जा सकता है । अतएव हमारे लिए यही शोभन है कि विद्यार्थी-समाजके बीच जनतन्त्रीय अभ्यासके विचारों और भावनाओंका प्रचार करें, ताकि राष्ट्रके नवयुवकोंके लिए जनतन्त्र एक वास्तविक धर्मगत बात बन जाय, यहाँ तक कि इसी भावनाओंसे उनका सारा जीवनक्रम एवं व्यवहार अनुप्राणित हो ।

एक और बात है जिसकी चर्चा इस भाषणको समाप्त करनेकेपूर्व करनी उचित होगी । अध्यापकोंका काम केवल बुद्धि-सम्बन्धी शिक्षा देना और चरित्रके विकासमें योग देना ही नहीं है; उन्हें अपने छात्रोंमें समाजके प्रति दायित्वकी भावना भी पैदा करनी है । किन्तु विश्वविद्यालयोंके विस्तारके कारण और पुराने विश्वविद्यालयोंकी जन-संख्या चरमावधितक पहुँच चुकी है इस कारण अध्यापकोंका यह काम अधिक कठिन हो गया है । छात्रों और अध्यापकोंके बीच सम्पर्कके अवसर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं । छात्रावासोंमें स्थानकी कमीके कारण भी विश्वविद्यालयोंको गुरुकुल (residential universities) बनाना दुस्साध्य एवं असम्भव हो रहा है । ट्यूटोरियल क्रम बड़ा खर्चीला है और कहीं-कहीं तो यह विचार किया जाता है कि इसके द्वारा भी अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकेगा । इस बातकी चर्चा करनेमें मेरा अभिप्राय यही है कि और बातोंके साथ आप इस विषयपर भी विचार करें । आप इस समस्याका चाहे जो समाधान निकालें, इसका कोई कारण नहीं दिखायी देता कि प्रस्तुत अवसरोंका उपयोग विद्यार्थी-समाजमें

सामूहिक जीवनकी भावनाको अधिक समृद्ध बनानेमें न किया जाय । गुरुकुलकी परम्परा (residential system) का शिक्षागत महत्त्व तो इसीमें है कि छात्रावासोमें ही हम सहकारिता, सहानुभूति एवं भाईचारेके बहुमूल्य पाठ पढ़ते हैं जो सामूहिक जीवनके लिए बहुत ही सहायक होते हैं ।

विश्वविद्यालयकी शिक्षाके सम्पूर्ण प्रश्नका विचार करनेके लिए भारत-सरकारने एक कमीशन नियुक्त किया है। इसके परामर्शोंकी वडी अभिरुचिके साथ राह देखी जायगी और हम वडी उत्सुकताके साथ इसकी सिफारिशोंकी प्रत्याशा करते रहेंगे ।

मैं जानता हूँ कि आपका भार बहुत बडा है और आपके दायित्व बडे महत्त्वपूर्ण हैं । आपको केवल वैज्ञानिक, विशेषज्ञ अनेक पेशोंके लिए उपयुक्त लोग और अध्यापक पैदा करना ही नहीं है, अपितु आपको विचारो और मानवीय समस्याओंके लिए नेता भी पैदा करना है; और सबसे बढकर तो यह करना है कि विश्वविद्यालय रचनात्मक विचारो और भावनाओंका केन्द्र बन जाय, जिसके हो जानेसे ही जनतन्त्रीय समाजकी स्थापना एवं प्रतिष्ठा कायम रखनेमें सहायता मिल सकती है ।

आज आपलोगोंका एक विशिष्ट स्थान है और आपलोगोंकी कार्यप्रणाली हमारा भविष्य निर्धारित करनेवाली है । मुझे आशा है कि आप निर्भय रूपसे और साहसके साथ अपने दायित्व पूर्ण करनेकी और शिक्षा-क्रमको ऐसा बनानेकी शक्ति रखते हैं कि हम जीवनमें वे सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व प्राप्त कर सके जिनके कारण मानव-जीवन उदात्त होता है ।^१

विश्वविद्यालय दे : नवयुगके नागरिक^२

विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाका उद्देश्य केवल विभिन्न पेशोंमें काम करनेवाले व्यक्तियों (वकीलो, डाक्टरों आदि), कारीगरों, वैज्ञानिकों और शासन-प्रबन्ध करनेवालोंको तैयार करना नहीं बरन् जीवनके प्रति विस्तृत दृष्टिकोण रखनेवाले, समझदार, सुसंस्कृत नागरिक भी तैयार करना है । विश्वविद्यालयोंसे यह भी आशा की जाती है कि वे विचार और मानव-सम्बन्धोंके क्षेत्रमें नेतृत्व करनेवाले व्यक्तियोंको जन्म देगे और सबसे बढकर उनमें रचनात्मक विचारोंके ऐसे केन्द्र बननेकी आशा की जाती है जिनके द्वारा ही आजके कष्ट और संघर्षके युगमें नवीन सामञ्जस्यकी स्थापनामें हमें सहायता मिल सकती है । विश्वविद्यालयोंका यह अन्तिम कर्तव्य सर्वोपरि महत्त्वका है, क्योंकि आजके तीव्र परिवर्तन और विच्छिन्नताके युगमें नयी सामाजिक चेतना और गतिशील चिन्तन ही सामाजिक रोगका विश्लेषण करके उसका उचित निदान ढूँढ सकता है ।

१. All India University Teachers' Convention के दिल्ली अधिवेशन-
में ४ दिसम्बर १९४८ को सभापति पदसे दिया हुआ भाषण ।

२. लखनऊ विश्वविद्यालयके रजत्-जयन्ती-समारोह (१९४९) के अवसरपर ।

प्राचीन संस्थाओंका विघटन

परम्परागत मूल्यो और आदर्शोंपरसे लोगोकी निष्ठा उठती जा रही है और पुरानी संस्थाएँ सर्वत्र ध्वस्त होती दृष्टिगोचर होती हैं। नये युगमे जीवित रहनेके लिए, नये सन्तुलन और सघटनके लिए हमे सतत प्रयत्नशील रहना है। समाजका नवीन सन्तुलन और सघटन तभी सम्भव है जब कि हम नयी समाजिक आवश्यकताओ और आकांक्षाओकी पूर्तिमे सहायक होनेवाले नये मूल्योको स्वीकार करनेमे बुद्धिमत्ता और साहसका परिचय दे। हमारे अध्यापकोको अपनी पुरानी उदासीनता और उपेक्षाकी मनोवृत्तिका परित्याग कर देश और समाजके नवनिर्माणसम्बन्धी प्रश्नोमे क्रियात्मक रुचि लेनी पड़ेगी।

विश्वविद्यालयोको केवल अपने छात्रोको विद्यादान करके सन्तुष्ट नहीं होना है वरन् वयस्क शिक्षा तथा इस प्रकारके दूसरे कार्योंमे रुचि लेकर समाजके प्रति अपने उत्तरदायित्वका निर्वाह करना है। अध्यापकोको विशुद्ध पठन-पाठनके कार्यतक ही अपनेको सीमित न रखकर आगे बढ़ना चाहिये और देशकी सामाजिक और राजनीतिक समस्याओका हल ढूँढनेमे योग देना चाहिये। समाजके प्रति अध्यापकोका यह भी उत्तरदायित्व है कि वे अपने विद्यार्थियोको जनतान्त्रिक ढंगसे आचरण करनेकी शिक्षा दे और उनमे दृढ़ नागरिक भावना भरे। राष्ट्रीय साहित्यके विकासका कार्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसकी पूर्तिमे भी उन्हें हाथ बँटाना है।

अतीतकी उपासनाका खतरा

समाजकी सबसे बड़ी सेवा जो आज विश्वविद्यालय कर सकते हैं वह है प्रतिक्रियावादकी शक्तियोसे संघर्ष करनेमे उसकी सहायता करना। नवयुवकोको गुमराह होनेसे बचाकर उन्हें विवेक और बुद्धिमानीका मार्ग दिखाना सबसे आवश्यक है। आज धर्म और संस्कृतिके नामपर हमारे नौजवानोकी घृणा और द्वेषकी भावनाओको उभाड़ा जा रहा है और मानवतावादी मूल्योकी उपेक्षा करना सिखाया जा रहा है। धार्मिक पक्षपात विहीन, असाम्प्रदायिक लोकतान्त्रिक राज्यकी कल्पनाका मखौल उड़ाया जाता है और नवयुवकोको आगे आनेवाले भविष्यकी ओर देखनेके बजाय सुदूर अतीतकी ओर दृष्टि मोड़नेको कहा जा रहा है। यदि अतीतको पुनरुज्जीवित करनेका आन्दोलन नवयुवकोको अपनी ओर आकर्षित करनेमे सफल हुआ तो मेरी रायमे देशके लिए यह सबसे बड़े खतरेकी बात होगी। इस प्रकारका आन्दोलन यद्यपि घोषित रूपसे सांस्कृतिक आन्दोलनके रूपमे आरम्भ होता है, किन्तु अन्तमे वह राजनीतिक रूप धारण करता है और चूँकि उसकी जड़े जनतामे नहीं होती इसलिए अपने लक्ष्यकी पूर्तिके लिए जनताको साथ लेनेके स्थानपर वह दूसरे 'सुगम' मार्ग अपनाता है। इस प्रकारका आन्दोलन नवयुवकोमे अपूर्व स्फूर्तिका संचार करता है, उनकी सोयी हुई शक्तिको जगाता है, किन्तु इस शक्तिका सदुपयोग देशकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओका समाधान करनेमे न लगाकर साम्प्रदायिक विद्रोह तथा कलह की वृद्धि करनेमें हुआ करता है। यह आन्दोलन जीवनमे नवयुवकोके दृष्टिकोणको

विकृत कर देता है, उनकी विवेक-बुद्धिको कुण्ठित कर देता है और उन्हें आजके समाजकी जटिल समस्याओंको समझनेके अयोग्य बना देता है ।

हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ तथा मिस्त्रके इस्वानुल मुसलमीन सरीखी संस्थाओंके इतिहाससे हमें शिक्षा लेनी चाहिये । इस्वानुल मुसलमीन आरम्भमें प्राचीन संस्कृतिके उद्धारका लक्ष्य रखकर चलनेवाला विशुद्ध सांस्कृतिक आन्दोलन था । उसका उद्देश्य कुरानकी संस्कृतिपर आधारित राज्यकी स्थापना था । किन्तु यह आन्दोलन धीरे-धीरे राजनीतिक रूप धारण करता गया और अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिए उसने अनेक अवसरोंपर आतंकवादका सहारा लिया । राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघके 'सम्बन्ध'में भी यह भविष्य कथन किया जा सकता है कि यह शीघ्र ही राजनीतिक संस्थाका रूप धारण करेगा, अन्यथा समाप्त हो जायगा । यदि हम राष्ट्रको एक भयंकर सकटसे बचाना चाहते हैं तो शिक्षाविदोंका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे हमारे नवयुवकोंमें जनतन्त्रकी भावनाको कूटकर भर दें और उन्हें जीवनके प्रति विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे विचार करनेका अभ्यस्त बनायें ।

अनुशासनकी समस्या

आजकल छात्रोंमें अनुशासनहीनताकी शिकायत प्रायः सुननेको मिलती है । इस अनुशासनहीनताके अनेक कारण हैं । हम एक उलझन और संघर्षसे भरे जमानेमें रह रहे हैं । जीवनकी आधारभूत मान्यताओंके सम्बन्धमें पढ़े-लिखे लोगोंमें एक राय नहीं है । लोगोंकी निष्ठा परस्पर-विरोधी विचारधाराओंके प्रति है । आर्थिक कठिनाइयाँ और बेकारी उत्साहभंगताको जन्म देती हैं । समाजकी विशृंखलता स्वभावतः विद्यार्थियोंमें प्रतिबिम्बित होती है । अनुशासनहीनताको दूर करनेका उपाय यही है कि छात्रोंके जोशको रचनात्मक कार्यमें लगाया जाय और शिक्षकों और शिक्षार्थियोंके बीच घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो ।

शिक्षा एक सहकारी प्रयत्न है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों ही भाग लेते हैं । दोनोंमें आदर्शकी एकता होनेपर ही शिक्षा-संस्थाओंमें सच्चे अनुशासनकी स्थापना सम्भव है । अनुशासनहीनताको समाप्त करनेके लिए हमें अनुशासनकी पुरानी धारणामें भी संशोधन करना होगा और शिक्षकों और शिक्षार्थियोंके बीच सौहार्द स्थापित करना होगा, किन्तु अनुशासनहीनताकी समस्या मूल रूपसे नये सामाजिक संघटनकी समस्याके साथ हल हो सकेगी ।

परीक्षाकी घड़ी

हम ऐसे युगमें रह रहे हैं जब कि संघर्ष और विच्छिन्नता हमारे राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय जीवनकी स्वाभाविक विशेषता बन गयी है । किन्तु समाजके इस असन्तुलनके कारण हमारा यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि हम नये सामञ्जस्यकी स्थापनाके लिए पूरी शक्तिके साथ प्रयत्नशील हो । कुछ लोग भग्नोत्साह होकर निष्क्रिय हो रहे हैं अथवा रहस्यवादकी गोदमें शरण ले रहे हैं और कुछ लोग मनुष्य और समाजके कल्याणके लिए

कार्य करनेका इसे सबसे बड़ा अवसर देखते हैं । इतिहास आज सबकी कड़ी परीक्षा ले रहा है । हमें इतिहासके उस महान् आन्दोलनका साथ देना है जो आजकी सभी परीक्षाओं और सकटोंके बावजूद अन्तमें समाजको एक नया संघटन प्रदान करेगा और सार्वभौमिक शान्ति और समृद्धिके युगका लानेवाला सिद्ध होगा । प्रत्येक शिक्षाकेन्द्रको इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिए प्रयत्नशील होना है ।

छठा अध्याय

संस्कृति

छठा अध्याय

हमारा आदर्श और उद्देश्य

भारतीय समाजमे महान् परिवर्तन होनेवाले हैं । देशमे नवजीवन हिलोर ले रहा है । भारतकी अवरुद्ध जीवनशक्ति अब फिर वेगवती हो चली है । भारतका नया मानव अपने सपने सार्थक करनेको निकल पड़ा है । इस नवजीवन-प्रवाहको रोकनेका प्रयत्न निरर्थक है । इसे रोकनेका प्रयत्न सफल नहीं हो सकता । इस तरह सामाजिक शक्ति नष्ट करनेसे व्यक्तियों तथा समूहोंको रोकना है । सामाजिक शक्तिकी दिशा निर्धारित करनी है, उसका नियन्त्रण करना है । पुराने आदर्शोंसे आज पथनिर्देश नहीं हो पाता । पुरानी परम्परासे आज सहारा नहीं मिलता । आज नये नेतृत्वकी आवश्यकता है । समाजवाद ही यह नया नेतृत्व प्रदान कर सकता है । जनताके विस्तृत तथा व्यापक हितके आधारपर निर्मित यह सम्पूर्ण सामाजिक सिद्धान्त ही हमारा पथप्रदर्शन कर सकता है । जनजागरण तथा जनक्रान्तिकी रीति ही समाजके समुचित विकासका साधन बन सकती है ।

समाजवादका सवाल केवल रोटीका सवाल नहीं है । समाजवाद मानव-स्वतन्त्रताकी कुंजी है । समाजवाद ही एक स्वतन्त्र सुखी समाजमे सम्पूर्ण स्वतन्त्र मनुष्यत्वको प्रतिष्ठित कर सकता है । समाजवाद ही श्रेणी-नैतिकता तथा मात्स्य-न्यायके बदले जनप्रधान नैतिकता तथा सामाजिक न्यायकी स्थापना कर सकता है । समाजवाद ही स्वतन्त्रता, समता और भ्रातृभावके आधारपर एक सुन्दर, सबल मानव-संस्कृतिकी सृष्टि कर सकता है ।

ऐसी सभ्यता तथा संस्कृतिकी स्थापना उत्पादनके साधनोपर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करते ही नहीं हो जायेगी । इसके लिए पुनर्निर्माण कार्य ही समुचित रीतिसे करना होगा । मानव-प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए नागरिक स्वतन्त्रता तथा उत्तरदायित्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाकी आवश्यकता होगी । सुन्दर और सम्पूर्ण मनुष्यत्वकी सृष्टि तभी हो सकती है जब साधन भी सुन्दर हो, मानवोचित हो । उद्देश्य और साधन परस्पर सम्बद्ध तथा परस्पर निर्भर होते हैं । दोनोंका अपना-अपना महत्व है ।

इसके अतिरिक्त इतने कालके सामाजिक विकासके बाद जो मौलिक मानवीय सत्य प्रतिष्ठित हो गये हैं, उनपर जोर देना, उन्हें समाजके पुनर्निर्माणमे उचित स्थान दिलानेका प्रयत्न करना नितान्त आवश्यक है । इनकी अवहेलना करके सभ्य और सुन्दर सामाजिक जीवन नहीं चलाया जा सकता । श्रेणी नैतिकताके नामपर सभी पुराने आदर्शों और सिद्धान्तोंका बहिष्कार उचित नहीं । समाजके दीर्घकालीन अनुभव तथा संचित ज्ञानका निरादर अनुचित होगा । इसके विपरीत पुराने आदर्शों और प्राचीन संस्कृतिका अध्ययन आवश्यक है । हमारी नवीन संस्कृतिके निर्माणमे इनका बहुत बड़ा हाथ होगा ।

‘जनवाणी’ इस सर्वोत्तम सामाजिक कर्तव्यकी पूर्ति करनेकी चेष्टा करेगी । समाजवाद के आलोकसे समस्त सामाजिक जीवनको जगमग कर देना और सभी सामाजिक समस्याओं-का समाधान प्रस्तुत करना ‘जनवाणी’ का उद्देश्य होगा । ‘जनवाणी’ समाजके सम्पूर्ण सर्वाङ्गीण विकासका साधन बननेका प्रयत्न करेगी । इस प्रकार समाजके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कलात्मक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी विषयोपर समुचित प्रकाश डालनेका प्रयत्न ‘जनवाणी’ करेगी ।

हम इस पवित्र कार्यमें सभी जनोत्कर्षके प्रेमियो और जनशक्तिके पुजारियोंके सहयोगकी प्रार्थना करते हैं ।^१

प्रगतिशील साहित्य

वैसे तो प्रगतिशील साहित्यकी परिभाषाके सम्बन्धमें अब भी विवाद चला आता है; किन्तु मोटे तौरपर यह कहा जा सकता है कि जीवनके केन्द्रमें मानवको प्रतिष्ठित करके चलनेवाला साहित्य प्रगतिशील साहित्य है । जीवन और मानव एक दूसरेको प्रभावित करते हैं, परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं । इनकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियासे ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं । समाजके भीतर क्रियाशील रहते हुए भी अपनेको अलगसे देखने, आत्मनिरीक्षण करनेकी आवश्यकता सदैव होती है । किन्तु उससे पृथक् रहकर, जीवन प्रवाहसे हटकर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता । समाजके भीतर रहकर व्यक्तिको सामूहिक हितको दृष्टिमें रखते हुए एक मर्यादा, बन्धन एवं अनुशासन स्वीकार करना पड़ता है । मनुष्य और पशुमें एक मुख्य भेद यह भी है कि मनुष्यका जीवन अपने समाजसे मर्यादित होता है । अतः सच्चे साहित्यकारका कर्तव्य हो जाता है कि वह मनुष्यको समाजसे पृथक् करके, अमूर्त मानवताके स्वतन्त्र प्रतीकके रूपमें सीमित न कर उसे सामाजिक प्राणीके रूप में देखे—ऐसे समाजके सदस्यके रूपमें जिसमें निरन्तर संघर्ष हो रहा है और इन संघर्षोंके कारण जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है ।

कहा जाता है कि कलाकार ‘स्वान्तः सुखाय’ रचना करता है । प्रत्येक रचनात्मक कृतिद्वारा रचयिताको एक प्रकारका आन्तरिक सन्तोष या सुख प्राप्त होता है, इस अर्थमें यह धारणा यथार्थ मानी जा सकती है । किन्तु यदि इसका अर्थ यह लगाया जाय कि कलाकारका और कोई उद्देश्य नहीं होता तो यह धारणा भ्रमपूर्ण होगी । अपने अध्ययन तथा अनुभूतिके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एव कलाकारका एक दर्शन, जीवनकी व्याख्याका एक विशेष दृष्टिकोण होता है और उसकी रचनाके पीछे यह दृष्टिकोण छिपा रहता है । जीवनके इस दृष्टिकोणके अनुसार कलाकार जीवनको एक विशेष दिशामें प्रकटित होते देखना चाहता है । कलाकारके मनमें यह बात स्पष्ट हो अथवा अस्पष्ट, किन्तु उसकी

रचनामें भी उसकी यह अभिलाषा अपेक्षाकृत सुप्त अथवा चैतन्य रूपमें विद्यमान रहती है। हमारा जीवन पृथक्से दिखायी पड़नेवाले अनेक क्षेत्रोंमें बँटा हुआ है। इन पृथक् क्षेत्रोंके भीतर और इनमें परस्पर नाना प्रकारके सघर्ष हो रहे हैं। दर्शन अथवा जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण इस सघर्ष और पृथक्तासे ऊपर उठकर सभीको एक सूत्रमें सम्बद्ध करके और उन्हें यथास्थान रखकर समूचे जीवन-क्षेत्रका एक सम्बद्ध दृश्य (Unified view) प्रस्तुत करता है। यह जीवन-दर्शन जितना ही सुलझा हुआ होगा, साहित्यिक अथवा कलाकारकी रचना सामाजिक प्रगतिमें उतनी ही सहायक हो सकेगी। जीवनके अन्तर्गत अनेक प्रकारके धर्मों—व्यक्ति, कुल, राष्ट्र तथा विश्व—के बीच एक प्रकारका संघर्ष जान पड़ता है। साथ ही उनमें एक प्रकारकी अन्योन्याश्रयता, शृङ्खला और परम्परा भी दिखायी देती है। वस्तुतः यह सघर्ष तभी दिखायी पड़ता है जब हम अन्योन्याश्रयताको दृष्टिसे ओझल कर देते हैं और इन धर्मोंको मर्यादित नहीं कर पाते, उनका उचित सामञ्जस्य नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ राष्ट्र-धर्मका हमें उससे भी उच्चतर विश्व-धर्मके साथ सामञ्जस्य करना पड़ेगा। सामञ्जस्य होनेपर राष्ट्रधर्मका सर्वथा लोप नहीं होता, वह केवल मर्यादित स्थान ग्रहण करता है। राष्ट्रधर्म और विश्वधर्मके बीच गहराईमें न जाकर केवल सतहपरसे देखनेपर जो सघर्ष दृष्टिगोचर होता है उसका लोप होता है। चूँकि व्यक्ति राष्ट्र अथवा विश्वका अंग है, अतः राष्ट्र और विश्वके विकासके साथ ही व्यक्तिको अपने पूर्ण विकासका अवसर प्राप्त होता है। जीवनके केन्द्रमें मानवकी प्रतिष्ठाकी मूल भावनाको लेकर चलनेवाले प्रगतिशील साहित्यिकके लिए विश्वव्यापी जीवन-दृष्टिकोणका होना आवश्यक है।

प्रत्येक युगकी सामाजिक व्यवस्था अपनी आवश्यकताओंके अनुसार एक विशेष जीवन-दृष्टिकोणको जन्म देती है। प्राचीनकालमें भी, चाहे पौराणिक जगत् ही अथवा पाश्चात्य, जबतक एक प्रकारकी आर्थिक संस्थाएँ और परम्पराएँ प्रचलित रही, उनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुए, तबतक समाजमें इस जीवन-दृष्टिकोणके सम्बन्धमें भी सहमति रही। किन्तु इस निरन्तर परिवर्तनशील संसारमें समाजकी बढ़ती हुई आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए उसकी भौतिक आर्थिक मूलभित्तिमें परिवर्तन होता रहता है और इस मूलभित्तिपर निर्मित विचारोंका प्रासाद भी नया रूप ग्रहण करता रहता है। विचार-धाराका तीव्र सघर्ष प्राचीनके विनाश और नवीनके उदयकी सन्धि-वेलामें होता है। प्राचीनके गर्भसे ही नवीनका सृजन करनेवाली शक्तियाँ जन्म लेती हैं। समाजको अतीतकी ओर ले जानेवाली तथा भविष्यकी ओर ले जानेवाली शक्तियोंमें सघर्ष होता है। प्राचीनके गर्भसे निकलकर नवीन भविष्यका निर्माण करनेवाली शक्तियाँ प्रबलतर होती जाती हैं। विरोधी शक्तियोंके क्रमिक विकासके प्रसंगमें हमें समाजमें गुणात्मक परिवर्तन, कई स्तरोंके एक साथ उल्लंघन अथवा उत्क्रान्तिके दर्शन होते हैं। वे विचारशील व्यक्ति जिनके तीव्र संवेदनशील कोमल मानस-पटपर क्षुब्धसे क्षुब्ध घटनाएँ भी अपना प्रभाव अंकित कर जाती हैं, नये परिवर्तनोंके क्रम-विकासके साथ समाजको नये विचार देते हैं।

नयी व्यवस्थाकी स्थापनाके साथ प्राचीनका सर्वथा लोप नहीं हो जाता। अर्वाचीनके

भीतर भी प्राचीन बहुत कुछ बना रहता है। नवीन और प्राचीनमें एक नैरन्तर्य, एक शृङ्खला, एक परम्परा बनी रहती है। पूँजीवादमें भी बहुत दुर्बल और क्षीण रूपमें सामन्तवाद बहुत दिनोतक वर्तमान रहता है और समाजवादकी स्थापनाके साथ भी बहुत दिनोतक पूँजीवादकी कतिपय विशेषताएँ सम्बद्ध रहेगी। विनाश और निर्माणके क्रममें अतीत, वर्तमान और भविष्यके बीच उनको आपसमें जोड़नेवाली एक अटूट कड़ी बनी रहती है। प्रगतिशील साहित्यक इस ऐतिहासिक सत्यको हृदयंगम करते हुए अतीतका सर्वथा परित्याग नहीं करता; साधक तत्त्वोको वह चुन लेता है, बाधक तत्त्वोंका परित्याग करता है। मनुष्य स्वभावतः परम्परापूजक होता है और जो जाति जितनी ही प्राचीन होती है, उसके भीतर अपनी संस्कृतिकी श्रेष्ठताकी भावना उतनी ही अधिक बढ़मूल होती है। अतः भारत-जैसे प्राचीन देशमें हमें नवीन संस्कृतिके निर्माणकी दृष्टिसे अतीतके साधक एवं समर्थक तत्त्वोंका उपयोग करना ही चाहिये।

अतीतकी अनेक विचार-पद्धतियाँ जो आज हमें प्रतिगामी प्रतीत होती हैं, अपने समयके समाजके लिए बड़ी कल्याणप्रद रही हैं। भौतिकवाद तथा यथार्थवादको मानकर चलनेवाली विचारधाराएँ ही जन-कल्याणके मार्गका अनुसरण करती रही हैं और इसके विपरीत आध्यात्मिक अथवा 'विज्ञानवादी' विचार-धाराएँ सदैव अप्रगतिशील रही हैं, ऐसा सोचना उचित न होगा। विज्ञानवाद भी विशेष कालमें प्रगतिशीलताका द्योतक था। उदाहरणके लिए हम बौद्धकालकी अप्रतिष्ठित निर्वाणकी कल्पनाको लें। निर्वाणकी इस कल्पनाके अनुसार साधक निर्वाणमें प्रवेशकी क्षमता रखते हुए भी सामाजिक कल्याणकी भावनासे प्रेरित होकर अपनेको उससे वंचित रखता है, जब कि असंख्य जीव दुःखसे आहत हो और क्लेश-पाशमें फँसे हुए हो, ऐसी अवस्थामें केवल अपने वैयक्तिक मोक्षकी ओर ध्यान देना उसे क्षुद्र प्रतीत होता है। निष्काम कर्मकी भावना भी इसी कालमें जन्म लेती है। कर्म बन्धनका हेतु है। विना कर्मका परित्याग किये हुए मनुष्य आवागमनके चक्रसे छुटकारा पाकर मोक्षकी प्राप्ति नहीं कर सकता। किन्तु विना कर्ममें प्रवृत्त हुए साधक जन-समूहका उद्धार भी नहीं कर सकता। जन-कल्याणकी दृष्टिसे कर्ममें प्रवृत्त होनेकी आवश्यकता तथा कर्मके स्वाभाविक परिणामगत बन्धनोसे निर्लिप्त रहनेके उद्देश्यमें सामञ्जस्य स्थापित करनेकी दृष्टिसे निष्काम कर्मके सिद्धान्तकी उत्पत्ति हुई। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्वसे चतुर्थ एव पञ्चम शताब्दीका काल निश्चय ही भारतीय इतिहासका एक अत्यन्त गौरवपूर्ण अध्याय है। इस कालमें भारतीय जीवनके प्रत्येक विभागमें सक्रियताके दर्शन होते हैं। इस समय निवृत्ति-मार्गमें विश्वास रखनेवाले भी प्रवृत्तिपथपर चलते दिखायी पड़ते हैं। भारतीय साधुओंने मध्य एशियामें भारतीय संस्कृतिके अखण्ड राज्यकी स्थापना इसी कालमें की थी। विदेशोंसे भारतका व्यापारिक सम्बन्ध भी इसी कालमें सुदृढ़ हुआ।

जहाँ हमें अपने देशके गौरवपूर्ण अतीतके उन तत्त्वोंको ग्रहण करना है जो वर्तमान कालमें पुरुषार्थको प्रेरणा देनेवाले हैं, वहाँ आजकी अवस्थामें भारत बननेवाली परम्पराओंका परित्याग कर हमें हल्का होना है और नवीन जीवनके विकासमान मूल्योंको अपनाना है। ये नवीन मूल्य कहाँसे आते हैं, उनका उपक्रम या मूलपात कहाँसे होता है, इस बातकी

खोज करनेकी आवश्यकता नहीं है । आज सारा ससार एक इकाईका रूप धारण कर रहा है । सभी देशोंकी समस्याएँ बहुत कुछ समान-सी हैं । पूँजीवादी शोषणसे त्राण पानेकी समस्या ही संसारके अधिकांश देशोंकी समस्या है । यह स्पष्ट है कि हमारे देशमें आज जो परिस्थिति है, वह दूसरे जिन देशोंमें हमारे देशसे पूर्व आयी और उस परिस्थितिका जो हल दूसरे देशोंने पहले निकाला, उन देशोंसे हमें प्रेरणा ग्रहण करनी ही होगी । नवीन या विदेशी होनेके कारण ही किसी जनकल्याणकारी विचार या मूल्यका परित्याग नहीं किया जा सकता । संस्कृतियाँ जब जीर्ण पड़ जाती हैं, तो नयी संस्कृतियोंके साथ संघर्ष होनेसे ही उनका कार्याकल्प होता है । अपने पुराने रत्न जो कर्ममें रहते हैं, वे भी इस संघर्षसे परिष्कृत होते हैं । जब कि सारा विश्व आज पूँजीवादी विपमताकी चक्कीमें पिसते हुए समान यातना भोग रहा है, यह स्वाभाविक है कि इस यातनासे परित्राण पानेके लिए एक समान विचारधारा अपनायी जाय । जो लोग नवीन मूल्योंको ग्रहण करनेसे भागते हैं और विचारधारा-सम्बन्धी संघर्षसे घबराते हैं, वे अपनेको विकासके पथसे विरत करते हैं । समाजमें विभिन्न स्वार्थोंके संघर्षके कारण निरन्तर परिवर्तन होता रहता है और इस संघर्षके फलस्वरूप ही समाज विकासके पथपर नये कदम बढ़ाता है । यदि क्रमागत विचारों और संस्थाओंको विना आलोचनाके स्वीकार कर लिया जाय तो भावी विकासका मार्ग अवरोद्ध हो जाता है । समाजके अन्तर्गत विभिन्न स्वार्थोंके संघर्ष और उसके फलस्वरूप समाजमें होनेवाले परिवर्तनकी प्रक्रियाका अध्ययन करके हम सामाजिक विकासमें बोधपूर्वक सहायता दे सकते हैं ।

पूँजीवादके ह्रासके इस युगमें और महायुद्धके उपरान्त राष्ट्रीयताका अन्त नहीं हो रहा है—जैसा कि कुछ लोगोका विचार है । प्रत्येक युद्धके पश्चात् राष्ट्रीयताकी ज्वरदस्त लहर आया करती है । किन्तु राष्ट्रीयताकी भावना भी अभिशाप नहीं है, यदि वह संकीर्ण, आक्रमणशील राष्ट्रीयता न हो और विश्व-धर्मसे मर्यादित होकर चल सके । साहित्यिकोका कर्तव्य जनताको चिन्ताशील बनाना और मर्यादित राष्ट्रीयताके सच्चे रूपको समझाना है । उस सकुचित, विकृत राष्ट्रीयतासे जनताको छुटकारा दिलाना है जिसमें जाति अथवा देशको अनावश्यक और अस्वाभाविक प्रधानता दे दी जाती है और जो वर्तमान सामाजिक समस्याओंके हलमें बाधक है । एक लम्बी अवधितक स्वातन्त्र्य-संग्राममें रत रहनेके कारण हमारे देशमें राष्ट्रीयताका जोर होना स्वाभाविक है । किन्तु अनुभवने सिद्ध यही किया है कि इस राष्ट्रीयताकी जड़ गहरी नहीं थी । यह राष्ट्रीयता देशके बँटवारेको रोकनेमें असमर्थ रही और बँटवारेके परिणामस्वरूप उसने जो रूप ग्रहण किया है, उसका समन्वय विश्व-धर्मके साथ करनेमें हमें काफी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा । प्रान्त, समुदाय और जातियोंके बीच कलह भारतका पुराना रोग रहा है, बँटवारेके बाद वह फिर उभड़ना चाहता है । प्रगतिशील साहित्यिकोका कर्तव्य इस विकृत राष्ट्रीयताके खतरोंको पहचाननेकी चेतना जनतामें उत्पन्न करना है । ससारमें एक नये महायुद्धकी तैयारियाँ हो रही हैं । यदि महायुद्ध छिड़ और हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके रहनेवाले एक दूसरेसे बदला लेनेके ही चक्करमें रहे तो दोनोंका विनाश निश्चित है । यदि हम चाहते हैं कि आनेवाले

युद्धमे तटस्थ रहकर उसकी विभीषिकाओंसे अपने देशकी रक्षा करे तो हमे तटस्थ राष्ट्रोंके एक तृतीय शिविरका निर्माण करना होगा । हम कमसे कम दक्षिण-पूर्वीय एशियाके नव स्वतन्त्रता-प्राप्त राष्ट्रों तथा स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए युद्धरत राष्ट्रोंका तीसरा शिविर स्थापित कर सकते हैं । किन्तु दूसरे राष्ट्रोंको हम अपने साथ तभी ला सकते हैं जब कि हम घरेलू झगड़ेमे फँसकर अपनी संमस्त शक्ति उसीमे नष्ट न कर दें, जब हम अपनी दृष्टिको उदार बनावे । यदि भारत प्रतिशोधकी भावनासे ऊपर न उठ सका, यदि उसने आर्थिक क्षेत्रमे ऐसी प्रगतिशील नीति न अपनायी जिसके द्वारा वह अपने उत्पादन सकट आदिके प्रश्नोंको हल करनेके साथ अपनेको सुदृढ़ बनानेमे समर्थ हो और अपने पड़ोसी राष्ट्रोंको भी महायुद्धमे तटस्थ रहनेके लिए तैयार न कर सका, तो हमारा भविष्य बहुत अन्धकारमय सिद्ध हो सकता है । प्रगतिशील साहित्यिकोंको देशको इस विपत्तिकी पूर्व सूचना देनी है । साहित्यिक अपने कर्तव्यका तभी निर्वाह कर सकता है जब कि वह जीवनका गहराईसे अध्ययन करे, वह समाजकी जीवनसरितामे ऊपरी तलपर संचारित होनेवाली प्रवृत्तियोंतक ही अपनी दृष्टिको सीमित न रखे, अन्तःसलिला सरस्वती-की भाँति नीचे रहकर प्रच्छन्न रूपसे कार्य करनेवाली शक्तियोंका भी अध्ययन करे । यह अध्ययन जन-जीवनसे अलग रहकर नहीं किया जा सकता ; प्रगतिशील साहित्यिकोंको जीवनकी समस्याओंका अध्ययन करना होगा, अपनी रचनाओंमे उसे समाजके वर्तमान रूपका चित्रण करना होगा, जनताकी मूक अभिलाषाओंको वाणी देनी होगी, इतिहासका अध्ययन करके उसकी जीवन-प्रदायिनी शक्तियोंका समर्थन करते हुए जनताका मार्ग-प्रदर्शन करना होगा । साहित्यिक अपनेको जनताका पथ-प्रदर्शन करने योग्य तभी बना सकता है, जब कि वह अपनेको जीवन-संघर्षसे सर्वथा पृथक् न रखे, उसमे जनसाधारणके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करनेकी क्षमता हो, वह इतिहासका वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके विकासकी दिशाको पहचाननेमे समर्थ हो, उसकी जीवन-दृष्टि सही हो । इतने गुणोंके अभावमे कितने ही कलाकार, जो प्रथम महायुद्धके उपरान्त प्रगतिशील साहित्यिकोंके शिविरमे प्रविष्ट हुए थे, आज दिशाभ्रमित होकर भटक रहे हैं । युद्धकालमें तथा उसके पश्चात् पुरानी मान्यताओंको भंग होता देखकर वे अवसाद, खिन्नता और विचार कुण्ठाको प्राप्त हो रहे हैं । स्वस्थ जीवन-दृष्टिकोणके अभावमे वे पलायनवादका सहारा ले रहे हैं । कोई रोमन कैथलिक दर्शनकी शरण ले रहा है, कोई भारतीय योगके प्रति आकर्षित हो रहा है । कितने ही किर्तव्यविमूढ़ होकर केवल नैराश्य भावनाको व्यक्त कर रहे हैं । कारण-कार्यकी शृङ्खला और सामाजिक सम्बन्धोंकी ठीक धारणा न होनेके कारण कितने ही कलाकार विज्ञानको ही वर्तमान सांस्कृतिक पतनके लिए उत्तरदायी मान बैठे हैं । जीवन-संघर्षसे भागनेवाले कलाकार आकस्मिक कारणोंसे भले ही प्रगतिशीलोंकी कोटिमे आ जायें, किन्तु उनकी प्रगतिशीलता क्षणिक ही होगी । जीवन-संघर्षसे पृथक् रहकर सच्चे और प्रगतिशील साहित्यकी सृष्टि सम्भव नहीं है । किन्तु इस कथनका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कलाकारके लिए राजनीतिक संघर्षमे लिप्त होना आवश्यक है । संघर्षके इतने निकट रहना कि वह उसका निरीक्षण कर सके, उसके लिए आवश्यक है ।

किन्तु संघर्षके सम्बन्धमे निष्पक्ष सम्मति बना सकने और साहित्य-सृजनके लिए अवकाश प्राप्त करनेके लिए संघर्षमे सक्रिय भाग लेनेसे कलाकारको वचना पड़ता है । स्वास्थ्यप्रद साहित्य-सृजन ही जनान्दोलनमे कलाकारका योग है । नवीन समाजके निर्माणके लिए संघर्ष सभी क्षेत्रोमे हो रहा है । साहित्यिक क्षेत्रमे कलाकारको उस साहित्यका विरोध करना है जिसकी दृष्टि केवल अतीतकी ओर है, जो प्राचीनता और परम्पराका अन्ध-पुजारी है, जिसकी आस्था विश्वके प्रति नहीं, वर्तमान भारतके प्रति नहीं, बल्कि प्राचीन भारतके किसी कल्पित विकृत रूपके प्रति है, जो सकुचित अर्कपणशील राष्ट्रीयताका प्रचार कर रहा है । इस प्रसंगमे प्रगतिशील कलाकारको यह नहीं भूलना है कि उनकी रचनाएँ भोड़ा प्रचार न होकर मर्मस्पर्शी, प्रभावोत्पादक उच्च कलाकृतियाँ हो । कला सोद्देश्य होती है । प्रायः प्रत्येक रचनाके पीछे एक सन्देश होता है, इस व्यापक अर्थमे तो सभी कला-कृतियाँ प्रचारका साधन कही जा सकती हैं । किन्तु कलाकृतिको प्रभावोत्पादक बनानेके लिए यह आवश्यक है कि उसे प्रत्यक्ष प्रचारका साधन न बनाया जाय । दूसरी बात जिसे प्रगतिशील साहित्यिकोको ध्यानमे रखनी है, यह है कि जहाँ कथावस्तु और विवेचना उनकी अपनी वस्तु होगी और नवीन शैलियोंको भी वे अपनायेगे, वहाँ दीर्घकालसे आचार्यों-द्वारा पुष्ट की जानेवाली शैली, टेकनिक, छन्द एव शब्द-विन्यास आदिकी भी वे सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते । प्राचीन साहित्यकी टेकनिक सम्बन्धी विशेषताओको उन्हें अपनाना होगा ।

जैसा कि आरम्भमे कहा जा चुका है, सारा ससार आज शोषणकी चक्कीमे पिसकर समान यातना भोग रहा है और उसकी मुक्तिकी स्थापनामे सहायता देना प्रगतिशील साहित्यका ध्येय है, मानव-मात्रकी एकता और उसकी सिद्धिके लिए शोषणमुक्त सामाजिक व्यवस्थाकी आवश्यकता इन आदर्शोंकी भित्तिपर हमें एक नवीन सस्कृतिका निर्माण करना है । नवीन सस्कृतिके निर्माणमे हमें प्राचीन संस्कृतिके साथ उसकी परम्पराको भी दिखलाना है । हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति नवीन व्यवस्थाकी स्थापनामे सर्वथा बाधक न होकर अनेक अशोमे साधक है । मानव-मात्रकी एकता, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श इस देशमे बहुत पुराना है । वस्तुतः जो कार्य श्रमण-धर्मने आध्यात्मिक क्षेत्रमें मानवकी एकताको स्वीकार करते हुए किया था, वही कार्य भौतिक क्षेत्रमे समाजवादको स्वीकार करके हमें सम्पन्न करना है ।'

संस्कृतवाङ्मयका महत्त्व और उसकी शिक्षा^१

माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा-सचिवजी, श्रीमान् कुलपतिजी, विद्वद्वृन्द, स्नातक बन्धुओं तथा देवियो और सज्जनों,

आपने उपाधि-वितरणोत्सवके शुभ अवसरपर दीक्षान्त भाषणके लिए निमन्त्रित कर मुझे गौरवान्वित किया है। इस कृपाके लिए मैं आपका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

काशी भारतका सबसे प्राचीन नगर और विद्यापीठ है। इसकी शिक्षाकी परम्परा अक्षुण्ण रही है और यह सदासे भारतीय संस्कृति और संस्कृत विद्याका प्रधान केन्द्र रहा है। आज भी इसका सारे देशमें आदर है। काशीके इस संस्कृत महाविद्यालयने विशेष रूपसे प्रसिद्धि प्राप्त की है। इस विद्यालयको अनेक प्राच्य और प्रतीच्य विद्वानोंने सुशोभित किया है और यह उन्हींकी प्रकाण्ड विद्वत्ता और साधनका फल है कि इस विद्यालयकी कीर्ति समस्त भारतवर्षमें फैल गयी है। स्थापनाके आरम्भकालसे ही इस संस्थाका एक उद्देश्य संस्कृत ग्रन्थोंका संग्रह करना भी रहा है और इस उद्देश्यमें इसको विशेष रूपसे सफलता मिली है। डाक्टर वेनिसके उद्योगसे सन् १९१४ में ग्रन्थागारके लिए सरस्वती भवनकी स्थापना हुई थी और यह हर्षका विषय है कि इस पुस्तकालयमें हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकोंकी संख्या ५०००० से अधिक है। यह संग्रह विशेष रूपसे उल्लेखनीय है और सरस्वती-भवनसे जो ग्रन्थमाला प्रकाशित होती है उसमें अवतक इस संग्रहके दो सौ उपादेय ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

मैं अपनेको भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इस विद्यालयके प्रिंसिपल डाक्टर वेनिस, पं० केशव शास्त्री और प्रो० नार्मनसे संस्कृत, प्राकृत, पाली तथा पुरातत्वकी शिक्षा प्राप्त की थी तथा इस महाविद्यालयके गोलोकवासी म. म. श्रीराम शास्त्री तैलग और पं० जीवनाथ मिश्रसे अलंकार-शास्त्र तथा न्यायका अध्ययन भी किया था। भारतीय संस्कृति और प्राचीन इतिहासके प्रति जो मेरी श्रद्धा थी वही मुझको यहाँ खींच लायी थी। उस कालका स्मरण कर मुझे आज भी अपूर्व आनन्द होता है, क्योंकि इन विद्वानोंके चरणोंमें बैठकर मैंने अपनी प्राचीन संस्कृतिका थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त किया था और आधुनिक आलोचना और अन्वेषणके प्रकारका अध्ययन किया था। जो व्यक्ति अपनी ज्ञान-परम्परा तथा अतीतके इतिहासका ज्ञान नहीं रखता वह सभ्य और शिष्ट नहीं कहला सकता, क्योंकि वर्तमानका मूल अतीतमें है और बिना उसको जाने वर्तमान कालके सामाजिक जीवनमें बुद्धिपूर्वक सहयोग करना कठिन है। अतः मैं इस संस्थाका अत्यन्त ऋणी हूँ। एक और दृष्टिसे भी उन दिनोंकी स्मृति बड़ी मधुर है। जो विदेशी विद्वान् यहाँ अध्यापनका कार्य करते थे, वह संस्कृत विद्याके परम अनुरागी थे और उन्होंने इस महाविद्यालयके पण्डितोंसे प्राचीन शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया था। इस कारण यहाँका वातावरण अन्य विद्यालयोंसे सर्वथा भिन्न था।

१. काशी संस्कृत महाविद्यालयके समावर्तन संस्कारके अवसरपर दिया गया दीक्षान्त भाषण।

यह प्रसन्नताका विषय है कि प्रान्तकी गवर्नमेण्टने इस विद्यालयको संस्कृत विश्व-विद्यालयका रूप देनेका निश्चय किया है। अब समय आ गया है कि इस संस्थाका लक्ष्य अधिक व्यापक और समयके अनुरूप बनाया जावे। भारतीय और प्रतीच्य विद्वानोंके सहयोगसे संस्कृतवाङ्मयका उद्धार हो रहा है। इस शुभ कार्यका श्रीगणेश यूरोपीय विद्वानोंने किया था। किन्तु गत ३० वर्षोंमें भारतीय विद्वानोंने अपूर्व उत्साह और लगनसे अन्वेषण और शोधके कार्यमें विशिष्ट भाग लिया है। राजनीतिक चेतनाके साथ-साथ राष्ट्रीय आधारपर सांस्कृतिक जीवनको आश्रित करनेका भी प्रयत्न किया गया है। प्राचीन इतिहास और संस्कृतिके अध्ययनमें विशेष अभिरुचि उत्पन्न हो गयी है और भारतीय विद्वानोंने पाश्चात्य शिक्षाद्वारा अन्वेषणकी वैज्ञानिक पद्धतिको सीखकर साहित्य, भाषा, धर्म तथा सामाजिक संस्थाओंका अध्ययन किया है।

आज भी इस कार्यमें यूरोपीय विद्वान् अपना दान दे रहे हैं। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्र होनेपर हमारा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। हमारा कर्तव्य है कि संस्कृत विद्याके अध्ययनको हम पाठ्यक्रममें विशिष्ट स्थान दे और अन्वेषणके कार्यको प्रोत्साहन दे। आधुनिक युगके दो महापुरुषोंके कारण तथा अपनी प्राचीन संस्कृतिके कारण हमारा संसारमें आदर है। यह खेदका विषय होगा यदि हम इस आवश्यक कर्तव्यकी ओर उचित ध्यान न दे और संस्कृतवाङ्मयकी रक्षा और वृद्धिके उदासीनता दिखावे। संस्कृतवाङ्मय आदर और गौरवकी वस्तु है और उसका विस्तार और गाम्भीर्य हमें चकित कर देता है। हमको उसका उचित गर्व होना चाहिये। संस्कृत संसारकी सबसे प्राचीन आर्य-भाषा है जिसका वाङ्मय आज भी विद्यमान है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। रामायण और महाभारत संसारके अनुपम और बेजोड़ काव्य हैं। यही हमारी संस्कृतिकी मूलभूति है। अनेक नाटक और काव्योंकी सामग्री इन्हीं ग्रन्थोंसे उपलब्ध हुई है। महाभारत वेदके समान पवित्र माना जाता है। (इतिहासपुराण पञ्चम वेदाना वेदम्) महाभारत हमारी प्राचीन संस्कृतिका भाण्डार है। इसमें प्राचीन आचार-विचार, रीति-नीति, आदर्श और संस्थाओंका इतिहास उपनिबद्ध है। यह दर्पणके समान है जिसमें प्राचीन भारतका जीवन प्रतिबिम्बित होता है। कालकी दृष्टिसे रामायण एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। इसलिए वाल्मीकिको आदिकवि कहते हैं। इसमें माधुर्य और प्रसाद-गुण हैं और यह उत्तम काव्यका प्रतिमान समझा जाता है।

इसी कारण रामायण और महाभारतके अनेक संस्करण हैं। रामोपाख्यान यवद्वीप, सुमात्रा, कम्बोडिया, चम्पा, स्याम, चीन और तिब्बतमें प्रचलित था। यवद्वीपकी रामायण-के कुछ अंश भट्टिकाव्यका अनुवाद हैं और कुछ अंश उसके आधारपर लिखे गये हैं। तिब्बतमें जो रामायणका संस्करण प्राप्त हुआ है उसकी कथा रामायणी कथासे भिन्न है। जैनियोंमें भी रामायणके दो संस्करण हैं :—एक वाल्मीकिका अनुसरण करता है, दूसरा बौद्ध-कथासे प्रभावित है। इसी प्रकार महाभारतकी कथा किसी न किसी रूपमें वृहत्तर भारतके कई देशोंमें प्रचलित थी। भारतीय भाषाओंने तुलनात्मक भाषा-विज्ञानको जन्म

दिया है। व्याकरण शास्त्र भी इस देशमें चरमविकासको पहुँचा है। रूसी विद्वान् श्चेरवात्स्कीके शब्दोंमें पाणिनिकी अष्टाध्यायी मानवी बुद्धिको सर्वश्रेष्ठ कृतियोंमेंसे है।

उपनिषदोंकी विचारधारा और साधना ससारके अलभ्य रत्नोंमें से है। भारतमें जिन विशिष्ट विचार-धाराओंने जन्म लिया है उन सबका मूल स्थान उपनिषदोंमें है। उपनिषद्के वाक्योंमें गाम्भीर्य, मौलिकता और उत्कर्ष पाया जाता है और वह प्रशस्त, पुनीत और उदात्त भावसे व्याप्त है। मैक्समूलरका कथन है कि उपनिषद् प्रभातके प्रकाश और पर्वतोंकी शुद्ध वायुके समान है। जिस प्रकार जब हिमानीसे पुण्यसलिला भगवती भागीरथी उद्गत होकर पर्वतमालामें घूमती हुई प्रवाहित होती है तब उनमें स्नान करनेसे बाह्य और आभ्यन्तरकी विशुद्धि होती है और एक क्षणके लिए ऐसी प्रतीति होती है मानो सकल वासनाका क्षय हो गया हो, सकल शरीर प्रीति-रससे आप्लुत और सकल चित्त कुल चेतनाकी भावनासे वासित और व्याप्त हो गया हो, उसी प्रकार उपनिषद्वाक्योंमें अवगाहन कर एक नया चैतन्य और एक नयी प्रेरणा मिलती है। यह वाक्य कभी वासी नहीं होते, कभी पुराने नहीं पड़ते। यह सदा नूतन और सदा नवीन है। उपनिषद् वह स्तम्भ है जिसपर प्रतिष्ठित संस्कृत विद्या और भारतीय संस्कृतिका दीपक सदा प्रकाश देता रहता है। यह हमारी अचल निधि है, यही हमारा जयस्तम्भ है।

संस्कृतवाङ्मयकी व्यापकता भी अद्भुत है। इसके अन्तर्गत अनेक शास्त्र और विद्याएँ हैं। इसकी धारा अविच्छिन्न रही है। संस्कृतवाङ्मयमें मैं पाली और प्राकृतका भी समावेश करता हूँ। एक समय था कि जब संस्कृतका विगल क्षेत्र था। मध्य एशियासे लेकर दक्षिण पूर्ण एशियाके द्वीपोंतक संस्कृतका अखण्ड राज्य था। उस समय विविध सम्प्रदायोंके विद्वान् संस्कृतमें ही ग्रन्थ-रचना करते थे और शास्त्रार्थ भी संस्कृतमें होता था। इस विशाल क्षेत्रपर भारतीय संस्कृतिका अपूर्व प्रभाव पड़ा था। यवद्वीपका प्राचीन साहित्य संस्कृतपर आश्रित था और स्याम, लंका, मलय, जावा, हिन्दचीन आदिकी भाषाओंपर संस्कृतका प्रभाव आज भी स्पष्ट है। इसी कालमें भारतीयोंने इन द्वीपोंमें उपनिवेश बसाये थे। मध्य एशियामें बौद्धधर्मके साथ-साथ भारतीय भाषा, लिपि, दर्शन और कला भी गयी थी। तिब्बतका बौद्ध वाङ्मय भारतीय और भोटके पण्डितोंके सहयोगसे तिब्बती भाषामें अनूदित हुआ था और तिब्बती लिपि भी भारतकी देन है। आज भी तिब्बतके मठोंमें प्राचीन संस्कृतके ग्रन्थ पूजे जाते हैं। दिङनागका न्यायमुख और आलम्बन परीक्षा, धर्म-कीर्तिका प्रमाणवार्तिक आदि कई ग्रन्थ वहाँसे उपलब्ध हुए हैं। महापण्डित श्री राहुल सांकृत्यायन तिब्बतके मठोंसे ५१० हस्तलिखित संस्कृत पोथियोंकी सूची लाये हैं। अनेक भारतीय ग्रन्थ एशियामें पाये गये हैं। सिकिआंगका प्रान्त जो आज रेगिस्तान है, एक समय हराभरा प्रदेश था और उसके नगरोंमें बौद्धोंके अनेक विहार और चैत्य थे जहाँ समृद्ध पुस्तकागार और कलाकी वस्तुएँ थी। इस स्थानपर अनेक भाषाओंका समागम और मिलन होता था। इस प्रदेशसे संस्कृत, प्राकृत, तथा अन्य अपरिचित भाषाओंके ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं। स्टाइनने भारतकी ओरसे खोजका

काम किया था। पुराने विहारोके भग्नावशेषसे बौद्ध मूर्तियाँ तथा रेणु, कागज और कपड़ापर अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। इन खोजोसे एक विलुप्त सभ्यताका पता लगा है। तुर्फान, कूचा, खुतन तथा अन्य स्थानोसे विपुल सामग्री प्राप्त हुई है। यह ग्रन्थ भूर्जपत्र, कागज, चमड़ा या लकड़ीपर लिखे गये हैं। इनकी लिपि गुप्तकालीन अथवा खरोष्ट्री है। बौद्धोके संस्कृत आगमके कई ग्रन्थ यहाँ पाये गये हैं तथा मातृचेटके दो प्रसिद्ध स्तोत्र-ग्रन्थ भी मिले हैं जिनकी प्रशंसा चीनी पर्यटक इत्सिङ्ग करता है। यहीसे अश्वघोषके नाटकोके अंश प्राप्त हुए हैं। खुतनका राजकाज भारतीय भाषाओंमें होता था और यहाँके राजाओंके नाम भारतीय थे। काराशरका प्राचीन नाम अग्निदेश था। कूचासे ही बौद्धधर्म चीन गया था। प्रसिद्ध कुमारजीव कूचाका ही अधिवासी था। कूचाकी संस्कृति भारतीय थी। यहाँ तन्त्र व्याकरणका अध्ययन होता था।

अफगानिस्तानमें सन् १९२२ से प्राचीन खुदाईका काम हो रहा है। हड़ामे अनेक स्तूप, चैत्य और मूर्तियाँ पायी गयी हैं। बामियानमें बुद्धकी विशाल मूर्तियाँ तथा भित्ति-चित्र मिले हैं। यहाँपर भूर्जपत्रपर लिखित संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं। यह महासाधिक विनयग्रन्थ तथा महायानके अभिधर्म ग्रन्थोके अंश हैं। कानुलके उत्तर-पश्चिम खैरखानिह पर्वतपर एक मन्दिरके भग्नावशेष मिले हैं जो गुप्तकालीन मन्दिरकी रचनाका स्मरण दिलाते हैं। यहाँ श्वेत संगमरमरकी सूर्यकी एक प्रतिमा भी मिली है जो चतुर्थ शताब्दीकी है।

कम्बोडिया (कम्बुज देश) जो हिन्दुचीनमें समाविष्ट है ६०० वर्षतक भारतीय संस्कृतिका एक केन्द्र रहा है। यहाँ संस्कृतके लेख पाये गये हैं। यहाँके स्थापत्यमें विष्णु, राम और कृष्णकी कथाएँ सञ्चित हैं। भारतीय कलाका सौन्दर्य यहाँ निखरा है।

कहाँतक कहे, दूर-दूर प्रदेशोंमें भारतीय ग्रन्थ पाये गये हैं। मैक्समूलरके एक जापानी शिष्यने जापानके एक मन्दिरमें सुखावती व्यूहकी पोथी पायी थी। चीन और मंगोलियामें बौद्धधर्मके साथ-साथ भारतीय संस्कृति भी गयी थी। चीनके साहित्यका अध्ययन करनेसे भारतके सम्बन्धमें बहुत-सी बातें विदित होगी। कुछ काल पहले चीनी पर्यटक च्वंग-च्वग-को गयाके सधारामके आचार्यद्वारा लिखित पत्र और उसका उत्तर प्रकाशित हुआ था।

इस सम्बन्धमें यह नहीं भूलना चाहिये कि बौद्धधर्म भारतीय था और उसकी संस्कृति भारतीय थी। अवैदिक होते हुए भी बौद्ध और जैन धर्मका कर्म तथा कर्मफलमें विश्वास था और दोनो नास्तित्ववादका खण्डन करते थे। पुन भारतके सब मोक्षशास्त्र चिकित्सा-शास्त्रके तुल्य चतुर्व्यूह हैं। हेय, हान, हेयहेतु और हानोपाय, यह चार सब मोक्षशास्त्रोके प्रतिपाद्य हैं। यही चार व्यूह योगसूत्रमें हैं। न्यायके यही चार अर्थपद हैं अर्थात् पुरुषार्थ स्थान हैं। बुद्धके यही आर्यसत्य हैं। इन्ही चार अर्थपदोको सम्यक् रीतिसे जानकर निःश्रेयस्की अथवा निर्वाणकी प्राप्ति होती है। सब अध्यात्म विद्याओंमें इन चार अर्थपदोका वर्णन पाया जाता है। सभी शास्त्र समान रूपसे स्वीकार करते हैं कि तत्त्वज्ञान अर्थात् सम्यक् दर्शन योगकी साधनाके विना नहीं होता। न्यायदर्शनमें कहा है कि समाधि-विशेषके अभ्याससे तत्त्वसाक्षात्कार होता है।

यह आत्म-संस्कारकी विधि है। जन्मान्तरमें उपचित धर्मप्रविवेकसे योगाभ्यासका सामर्थ्य उत्पन्न होता है। यह धर्मवृद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त होता है (प्रचय काष्ठागत) और उसकी महायतासे समाधि-प्रयत्न प्रकृष्ट होता है। तब समाधिविशेष उत्पन्न होता है। वैज्ञेयिक सूत्रमें भी कहा है कि आत्मकर्मसे मोक्ष होता है। आत्मकर्मके अन्तर्गत श्रवण, मनन, योगाभ्यास, निदिध्यासन, ग्रामन, प्राणायाम और जम-दम है। योगकी साधना बौद्ध, जैन दोनों धर्मोंमें पायी जाती है। प्राणायामसे काम और चित्तकी प्रशुद्धि होती है और जिस प्रकार न्यायशास्त्र प्राणायाम और अंगुम संज्ञाकी भावनाको विशेष महत्व देता है उसी प्रकार बौद्धागममें भी उनको विशिष्ट स्थान दिया गया है। इनसे काम रागका प्रहाण और नाना प्रकारके अकुशल वितर्कोंका उपशम होता है। मैत्री भावनाका भी माहात्म्य विणिष्ट है। इस प्रकार योगकी साधना वैदिक तथा अवैदिक धर्मोंको एक सूत्रमें बाँधती है और यह साधना सबको समान रूपसे तभी स्वीकार हो सकती थी जब सबके भौतिक विचारोंमें भी किसी-न-किसी प्रकारका सादृश्य हो। मेरी धारणा है कि विविध सम्प्रदायोंके होते हुए भी यदि हमारे देशमें धर्मके नामपर रक्तपात नहींके तुल्य हुए है तो उसका एक कारण यह भी है कि इनकी मोक्षकी साधना समान रही है और जिस युगमें भक्तिमार्गका प्रभाव बड़ा उन युगमें बौद्ध धर्ममें भी उपासनाका प्राबल्य था।

मैंने इसका उल्लेख इस कारण किया कि कहीं आप बौद्ध और जैन आगमकी उपेक्षा न करें। इन ग्रन्थोंमें भारतीय समाजशास्त्रके इतिहासके लिए प्रचुर सामग्री मिलती है और बौद्ध तथा जैन विद्वानोंने न्याय, दर्शन, व्याकरण और काव्यके विकासमें विणिष्ट भाग लिया है।

ऐसे भारतीय वाङ्मयका संरक्षण तथा प्रचार करना हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिये। मैंने भारतीय संस्कृतिके विस्तारका यत्किञ्चित् विवरण इस कारण दिया जिसमें हमारे स्नातकोंको इसकी समृद्धि और मूल्यका ज्ञान हो।

यह कार्य इस महाविद्यालयका प्रधान लक्ष्य होना चाहिये। किन्तु यह कार्य तबतक सम्पन्न नहीं हो सकता जबतक हम आलोचना और गवेषणाकी आधुनिक पद्धतिको न स्वीकार करें। अन्वेषणके कार्यके लिए यहाँ बृहत् आयोजन करना होगा। हम अपनी निधिकी रक्षा और उसका मूल्यांकन ठीक-ठीक नहीं कर सकेंगे जबतक संस्कृत विश्वविद्यालयमें संस्कृतके साथ पाली, प्राकृत, चीनी, भोट, तथा कतिपय पाञ्चात्य भाषाओंकी शिक्षाकी व्यवस्था न की जायगी। पुनः आज नवीन शास्त्रोंका उदय हुआ है और प्राचीन विद्याएँ विकसित होकर प्रौढ़ावस्थाको प्राप्त हुई हैं। अनुसन्धानके कार्यके लिए इनमेंसे जिन शास्त्रों और विद्याओंका जितना ज्ञान आवश्यक हो उतना हमारे विशेषज्ञोंको प्राप्त करना चाहिये। उदाहरणके लिए भाषा-विज्ञानके सिद्धान्तोंको जाने बिना हम प्राचीन ग्रन्थोंका कई स्थलपर ठीक-ठीक अर्थ नहीं लगा सकते। वैदिक साहित्यको समझनेके लिए अनेक जातियोंके सांस्कृतिक इतिहासका तथा उनकी भाषाका ज्ञान भी आवश्यक है। भारतमें अनेक जातियाँ समय-समयपर आती रही हैं जो भारतीय समाजमें घुल-मिल गयी हैं। उनके आचार-विचारका प्रभाव आर्योंकी संस्कृतिपर पड़ा है। उत्तर-पश्चिममें

अनेक धर्म और संस्कृतियोंका मिलन तथा परस्पर आदान-प्रदान हुआ है। वहाँकी कलापर यूनानी और ईरानी कलाका प्रभाव पड़ा था। गान्धारमे अनेक शैलियोंका विकास हुआ था और इनकी पूर्ण निष्पत्ति खुतन, कूचा, तुर्फान आदि कलाके प्रसिद्ध केन्द्रोंमें हुई थी। इस प्रदेशमें बौद्ध धर्मका संपर्क ईरानी, मागी आदि धर्मोंसे हुआ था। अतः इस युगके धर्म और संस्कृतिके इतिहासको जाननेके लिए इन विविध धर्मों और संस्कृतियोंका ज्ञान आवश्यक है। भारतीय समाजशास्त्रकी रचनाके लिए आज केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि हम विविध ग्रन्थोंके आधारपर पर तथ्योंका संग्रह करें, किन्तु साथ-साथ पश्चिमके समाजशास्त्र, नृत्य आदि उपयोगी शास्त्रोंमें प्रतिपादित सिद्धान्त तथा उनमें एकत्र की हुई सामग्रीको जानना भी आवश्यक है।

इस महाविद्यालयमें इस कार्यके लिए अनेक सुविधाएँ हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास एक बृहत् पुस्तकालय है जिसमें हस्तलिखित और मुद्रित ग्रन्थोंका अच्छा संग्रह है। हस्तलिखित पुस्तकोंका सूचीपत्र तैयार किया जा रहा है और प्राचीन पुस्तकोंके प्रकाशनकी भी व्यवस्था की गयी है। काशी संस्कृत-शिक्षाका प्रसिद्ध केन्द्र है और प्राचीन शैलीके अनेक विद्वान् यहाँ प्रवचन करते हैं। नवीन शैलीके संस्कृत-विद्वानोंके सहयोगकी परम आवश्यकता है। पिछले ३० वर्षोंमें जिन भारतीयोंने संस्कृत विद्याके उद्धारका स्तुत्य कार्य किया है उनमें अधिकांश वही हैं जिन्होंने पश्चिमके गवेषणाके प्रकारोंको सीखा है और जिन्होंने नये ढंगसे शिक्षा प्राप्त की है। इनके सहयोगसे यहाँके स्नातक भी इस कार्यके लिए तैयार किये जा सकते हैं। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। मैं जब काशीमें विद्यार्थी था तब संस्कृत कालेजके कुछ शास्त्री फ्रेच, जर्मन, पाली आदि पढ़ा करते थे और उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी। किन्तु इनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। अब इसी कार्यको बड़े पैमानेपर करनेकी आवश्यकता है। इसके लिए इन भाषाओंके अध्यापन तथा छात्रवृत्तियोंकी उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

अपने प्राचीन ग्रन्थोंके प्रामाणिक संस्करण भी अभी नहीं निकल पाये हैं। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रन्थका कोई प्रामाणिक संस्करण न हो यह कितनी लज्जाकी बात है। किन्तु भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस कमीको पूरा कर रहा है। इसका आरम्भ सन् १९१६ में हुआ था और आज भी यह कार्य समाप्त नहीं हुआ है। यह कार्य जितना कठिन और महान् है उतना ही इसका महत्त्व भी है। अशुद्ध पाठोंके आधारपर जो विविध निष्कर्ष निकाले गये थे वह सदोष पाये गये हैं। जब आदिपर्वका वैज्ञानिक संस्करण सन् १९३३ में प्रकाशित हुआ था तब उसपर ससारके विद्वानोंने बड़ा सन्तोष प्रकट किया था और उसे संस्कृत-भाषा-विज्ञानके इतिहासकी सबसे महत्त्वपूर्ण घटना बताकर डा० सुकथकरकी प्रशंसा की गयी थी। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिकी जानकारीके बिना यह महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता था। पुराणोंमें भी शोधका बहुत काम करना है। हस्तलिखित पोथियोंकी खोज भी जारी रहनी चाहिये और उनकी रक्षाका उचित विधान होना चाहिये। विज्ञानकी सहायताके बिना यह साधारण-सा कार्य भी नहीं हो

सकता । जो पोथियाँ जीर्ण-शीर्ण हो रही हैं उनकी रक्षाका एकमात्र उपाय उनका चित्र लेना है । माइक्रोफिल्म और फोटोस्टैट कैमराकी सहायतासे यह कार्य मुकर हो गया है । इस सम्बन्धमें मुझे एक निवेदन करना है कि गवर्नमेंटको इण्डिया आफिस लाइब्रेरीमें संगृहीत भारतीय पुस्तकोंकी वापसीकी चेष्टा करनी चाहिये । समाचारपत्रोंसे ज्ञात होता है कि ऐसी कुछ चेष्टा की जा रही है । यदि यह सत्य है तो यह परम सन्तोषका विषय है । इंग्लैण्डके अतिरिक्त अन्य देशोंमें जो ग्रन्थ गये हैं उनका चित्र प्राप्त करनेका प्रयत्न होना चाहिये । एक ऐसा भी कानून बनाना चाहिये कि भारतसे बाहर कोई प्राचीन ग्रन्थ, चित्र या कलाकी वस्तु न जावेगी ।

मेरी संस्कृत विश्वविद्यालयकी कल्पना यह है कि यहाँ प्राचीन शास्त्रोंके स्वाध्याय-प्रवचनके साथ-साथ गवेषणाकी पूरी व्यवस्था की जाय और इस सम्बन्धमें जिन भाषाओं और नवीन शास्त्रोंकी शिक्षाकी आवश्यकता हो उसका भी प्रवन्ध किया जाय । इस गवेषणाके कार्यमें पुरातन और नवीन शैली, दोनोंके विद्वानोंका सहयोग प्राप्त किया जाय तथा विद्यालयसे निकले हुए आचार्योंको छात्रवृत्ति देकर अन्वेषणके कार्यके लिए तैयार किया जाय । यहाँ ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे अन्य विश्वविद्यालयोंके विद्वान् यहाँ आकर अनुसन्धानके कार्यमें योग दे सकें । किन्तु इस व्यवस्थामें पूरा लाभ तभी होगा जब यहाँके पाठ्यक्रममें उचित परिवर्तन किये जायेंगे । आजके युगमें पुरानी पद्धतिकी संस्कृतकी शिक्षा तभी अपने उद्देश्यको चरितार्थ कर सकती है जब शास्त्रोंकी शिक्षाके साथ-साथ मौलिक शिक्षाकी भी व्यवस्था की जाय । प्रत्येक विद्यार्थीको केवल अपनी जीविकाका ही उपार्जन नहीं करना है, किन्तु उसे एक नागरिकके कर्तव्योंका भी पालन करना है और इससे भी बढ़कर उसे मनुष्य बनना है और मनुष्य भी पुराने युगका नहीं, आजके युगका जब समाजने अपने सामञ्जस्यको खो दिया है, जब विचारोंमें संघर्ष चल रहा है और एक प्रकारकी अनिश्चितता है जिसके कारण जीवनके प्रति कोई स्पष्ट और उत्कृष्ट दृष्टि नहीं बन पाती । वह मनुष्य क्या है जो अपनी मातृभाषाके साहित्यसे परिचित नहीं है, जो एक शास्त्रका विशेषज्ञ होनेके लोभमें अपने साहित्य और कलाकी अमरकृतियों की उपेक्षा करता है ? वह मनुष्य क्या है जो संसारके इतिहाससे अपरिचित है, जिसको वर्तमान समस्याओं और घटनाओंका ज्ञान नहीं है ? वह अपने विषयका विशेषज्ञ हो सकता है । यदि वह विज्ञानका विद्यार्थी है तो वह कुशल शिल्पी हो सकता है, यदि वह संस्कृतका शास्त्री या आचार्य है तो वह पौरोहित्य या अध्यापनका कार्य कर सकता है, किन्तु दोनों दूसरोंका उपकरण ही बन सकते हैं और समाज और राजनीतिके संचालनमें वह अपनेको असमर्थ पाते हैं । इसका कारण यह है कि वह अपने धन्धेको जानते हैं, किन्तु शिक्षा और जीवनके परम उद्देश्यको नहीं जानते । उनकी दृष्टि व्यापक नहीं है और न उनकी शिक्षाका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उनको जीवनके विविध क्षेत्रोंके लिए सामान्य रूपसे तैयार करे । इसलिए प्रत्येक विद्यार्थीके लिए ऐसी पाठ्य-पद्धति होनी चाहिये जिसकेद्वारा यह सामान्य किन्तु परम आवश्यक ज्ञान उसको दिया जा सके । इस दृष्टिसे डाक्टर भगवानदास-समितिके अभिस्तावो तथा निष्कर्षोंका मैं सामान्य रूपसे स्वागत करता

हूँ । नवीन विषयोके समावेशकी बात तो दूर रही, वर्तमान प्रणालीके अनुसार संस्कृत-वाङ्मयका भी एकाङ्गी अध्ययन ही हो पाता है ।

अतः पाठ्यक्रमके क्षेत्रको दो प्रकारसे हमे विस्तृत करना चाहिये । एक—संस्कृत-विद्याकी पाठ्य विधिको व्यापक और सर्वाङ्गीण बनाना । दो—पाठ्यविधिमें आधुनिक विषयोका तथा, हिन्दी, इतिहास, भूगोल, राजशास्त्र, गणितका समावेश करना । साथ-साथ विद्यार्थियोंमें तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययनकी प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिये । इन सिद्धान्तोके आधारपर पाठ्य-पद्धतिका पुनर्निर्माण होना चाहिये, किन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञानके गाम्भीर्यमें कमी न हो तथा गाम्भीर्यकी रक्षा करते हुए आवश्यक मात्रामे उसका विस्तार भी हो । जितना आधुनिक ज्ञान एक साधारण विद्यार्थीके लिए नितान्त आवश्यक है उतना तो संस्कृत पाठशालाओके छात्रोको भी अर्जित करना चाहिये ।

मैं एक दूसरे आवश्यक कार्यकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यह है संस्कृत-वाङ्मयका हिन्दीमें अनुवाद । यदि हिन्दी भाषामे हमारे प्राचीन ग्रन्थ-रत्नोका अनुवाद प्रस्तुत हो तो इससे भारतीय संस्कृतिके प्रचारमें बड़ी सहायता मिलेगी । आधुनिक भाषाओकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते । सारा राज-काज इन्हीं भाषाओमें होने जा रहा है । धीरे-धीरे राष्ट्रभाषा विश्वविद्यालयोंमें शिक्षाका माध्यम हो जायगी । आपको मातृभाषाका तिरस्कार नहीं करना चाहिये । अब वह समय नहीं रहा जब किसी लेखक या कविसे प्रश्न किया जाय कि तुम संस्कृतका परिहार कर हिन्दीमें गद्य या काव्य-रचना करनेमें क्यों प्रवृत्त हुए हो । इसका उत्तर राजशेखर और गोस्वामी तुलसीदासजी दे गये हैं । राजशेखरके अनुसार संस्कृतबन्ध परुष और प्राकृतबन्ध सुकुमार है । वह आगे चलकर कहते हैं कि उक्तिविशेष ही काव्य है भाषा चाहे जो हो । राजशेखरके समयमें संस्कृत काव्य कृत्रिम और क्लिष्ट हो गया था, यह उसके ह्रासकी अवस्था थी । रामायण, महाभारत, महाभाष्य और शंकरभाष्यकी शैली भला दी गयी थी, काव्यका प्रसाद गुण विलुप्त हो गया था । भामहका कहना है कि काव्यको क्लिष्ट और दुरुह नहीं होना चाहिये, उसके समझनेके लिए किसी टीकाकी आवश्यकता न होनी चाहिये । वह इतना सरल हो कि साधारण पढ़े-लिखे लोग, बालक और स्त्रियाँ भी उसे समझ सकें । गद्यका प्राण ओज है (ओजः गद्यस्य जीवितम्) जब संस्कृत किसी वर्गकी भी बोलचालकी भाषा न रह गयी तो उसमें कृत्रिमताका आ जाना स्वाभाविक है । तब पाण्डित्य-प्रदर्शन ही एकमात्र काव्य-रचनाका उद्देश्य रह गया और काव्य हृदयग्राही न रहा । माधुर्य और प्रसाद गुण मातृ भाषाके साहित्यमें ही सुगमताके साथ आ सकता है । अतः मातृभाषामे साहित्य-सर्जन करनेमें हमको गौरवका अनुभव करना चाहिये ।

मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार यह बतानेकी चेष्टा की है कि संस्कृत विश्वविद्यालयका क्या उद्देश्य और क्या कार्यक्रम होना चाहिये । यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालयमें उन सब विषयोके अध्ययनकी व्यवस्था साधारणतः करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है जिनका प्रबन्ध अन्य विश्वविद्यालयोंमें होता है । वहाँका पठन-पाठन

अब राष्ट्रभाषामें होगा । अतः जिनको उन विषयोंकी शिक्षा लेनी है वह वहाँ जा सकते हैं । इसकी सुविधा अवश्य होनी चाहिये किन्तु संस्कृत विश्वविद्यालयका एक विशेष लक्ष्य है जिसकी पूर्ति अन्य विश्वविद्यालयोंमें नहीं हो रही है । एक प्रकारसे यह विद्यालय भी है और प्राच्य विद्याके अन्वेषणका एक प्रतिष्ठान भी है । ज्ञान-राशि अनन्त है, उसकी सीमा नहीं है । इधर अनेक नवीन शास्त्रोंकी प्रतिष्ठा हुई है और ज्ञानका विस्तार इतना बढ़ गया है कि बिना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगके अन्वेषणका कार्य दुष्कर हो गया है । ज्ञानके सदृश दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है । अतः विदेशियोंसे उसके लेनेमें संकोच नहीं होना चाहिये । प्राचीन कलमें भी हमने स्वाध्याय और प्रवचनमें कृपणता नहीं दिखायी थी । आज भी हमको उसी उदार बुद्धि तथा व्यापक दृष्टिसे काम लेना चाहिये । इसीमें हमारा भगल है । इसी प्रकार भारतकी सर्वतोमुखी प्रतिभाका उन्नयन होगा ।

संस्कृतका आदर और सम्मान अधिकधिक बढ़ता जायगा । ससारके प्रत्येक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमें संस्कृतकी शिक्षाका समुचित प्रबन्ध किया गया है । पाश्चात्य जगत्के विद्वान् अन्वेषणके कार्यमें हमसे कहीं आगे बढ़े हुए हैं, उनमें ज्ञानकी पिपासा है; जहाँसे ज्ञान मिल सकता है वहाँसे लेनेमें उनको तनिक भी संकोच नहीं होता । हममें या तो मिथ्या गर्व और चित्तोद्रेक है अथवा आत्मावसाद है । दोनोंका परिहार कर संस्कृतवाङ्मयके संरक्षण और प्रचारमें हमको प्राणपणसे लग जाना चाहिये । जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर उपाधि ले रहे हैं उनका इस विषयमें विशेष उत्तरदायित्व है ।

मैं जानता हूँ कि किस विषयमें परिस्थितिमें आप स्नातक अपना पठन-पाठन करते हैं । प्रवाहके विरुद्ध होते हुए भी आप संस्कृत विद्याकी रक्षामें जो लगे हुए हैं यह स्तुत्य है । आपके जीविकानिर्वाहके लिए कुछ अन्य वृत्तियोंका द्वार अब खुल जाना चाहिये । केवल पौरोहित्य और अध्यापनकी प्रवृत्तियाँ पर्याप्त नहीं हैं । इस दृष्टिसे आपको कतिपय अन्य परीक्षाओंमें सम्मिलित होनेकी सुविधा प्रदान करनी चाहिये । इस दृष्टिसे भी पाठशालाओंकी पाठन-विधिमें परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत होता है । पाठ्य-ग्रन्थावली संशोधन समितिने अपने निश्चयोंमें इस बातका भी ध्यान रखा है । आपकी आर्थिक अवस्थाको सुधारना तथा आपको देशकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए समर्थ बनाना समाजका कर्तव्य है ।

इतने विद्यार्थियोंको विविध उपाधि और पदवियोंसे विभूषित होते देखकर मुझे प्रसन्नता होती है । मैं आपका शुभचिन्तन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप समाजमें अपनी योग्यताके अनुरूप स्थान पाकर शीघ्र कार्यमें नियुक्त हो जायेंगे और जो प्रतिज्ञाएँ आज आपने स्वीकार की हैं उनकी सदा रक्षा करेंगे ।

जिस युगमें हम रह रहे हैं उसकी अपनी विशेषता है । हमारी सभ्यतापर आधुनिक विज्ञानका गहरा प्रभाव पड़ा है । आज सकुचित विचार-धारासे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है । हमारी दृष्टि साम्प्रदायिक और प्रान्तीय न होकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय होनी चाहिये । हममें इन हीन प्रवृत्तियोंसे ऊपर उठनेका सत्साहस और सद्बिवेक होना चाहिये । प्राचीन संस्कृतिके उत्कृष्ट अंशोंकी रक्षा करते हुए हमको आधुनिक युगके

सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्योंको अपनाना होगा । राष्ट्रीय-एकताके लिए किसी विशेष भाषा या लिपि का अनुचित पक्षपात छोड़कर केवल राष्ट्रहितसे प्रेरित होना होगा । जनतन्त्रकी भावनासे प्रेरित होकर हमको सब काम करने होंगे । हमारा चिन्तन वैज्ञानिक होगा और हम ज्ञानकी निरन्तर वृद्धि करते रहेंगे । जिस कुशल चेतनासे प्रेरित होकर प्राचीन ऋषियोंने सकल समाजके कल्याणके लिए सत्पथका उद्घाटन किया था उसी कुशल चेतनाकी भावना कर उन्ही आर्य और उदात्त भावोंसे प्रेरित होकर हम आजकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए व्रती हो और बहुजन समाजके हित-सुखका विधान कर अभ्युदय और निश्चयसकी प्राप्तिके लिए यत्नवान् हो । तभी हम अपना कल्याण और विश्वका कल्याण कर सकेंगे । तभी संसारमे शान्ति, तुष्टि और पुष्टि होगी । आशा है आप ईप्सित फल प्राप्त करेंगे और संस्कृत विश्वविद्यालयका यह शुभसंकल्प विद्वज्जनोंका सहयोग प्राप्त कर सफल होगा ।

प्रवर्त्तता प्रकृतिहिताय पार्थिव.,

सरस्वती श्रुतमहतां महीयसाम् ॥

सार्थो नन्दतु सज्जनानां सकलौ वर्ग. खलाना पुन-

नित्यं खिद्यतु भवतु ब्राह्मणजन सत्याशीः सर्वदा ।

मेघो मुञ्चतु सचित्तमपि सलिल सस्योचित भूतले

लोको लोभपराङ्मुखोऽनुदिवसं धर्मो मतिर्भवतु च ॥^१

सातवाँ अध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति



सातवाँ अध्याय

सोवियत रूसकी एशिया-सम्बन्धी नीति

सोवियत रूसकी एशिया-सम्बन्धी नीतिको भलीभाँति समझनेके लिए सन् १९१७ (वि० स० १९७४) की रूसकी राज्यक्रान्तिके प्रमुख नेता लेनिनके विचारोका थोड़ा-बहुत जानना आवश्यक है। यह प्रसिद्ध ही है कि लेनिन साम्यवादी और पूँजीवादका विरोधी था। वह समाजके ऊँच-नीचके भेदको मिटा देना चाहता था और जिन विविध श्रेणियों या वर्गोंमें मानव-समाज आज विभक्त है उनको मिटाकर केवल श्रमजीवी-वर्गका आधिपत्य प्रतिष्ठित करना चाहता था। सोवियतकी शासन-पद्धति इस राज्यक्रान्तिका फल है, और सोवियत शासन-यन्त्रपर श्रमजीवियोंका आधिपत्य और नियन्त्रण है। इस शासन-पद्धतिने लेनिनके विचारोको कार्यान्वित करनेका यथासाध्य प्रयत्न किया है। यह स्पष्ट ही है कि यूरोपके पूँजीवादी राष्ट्र इस प्रयोगको विफल करनेकी प्राणपणसे चेष्टा करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। लेनिनको केवल आन्तरिक विरोधका ही सामना नहीं करना पड़ा, अपितु यूरोपीय राष्ट्रोंके विरोधका भी मुकाबला करना पड़ा। यूरोपके प्रधान राष्ट्रोंने सोवियत रूससे राजनीतिक सम्बन्ध क्या, व्यापारिक सम्बन्ध भी, स्थापित रखना उचित न समझा और उन्होंने सोवियत रूसको वदनाम करनेमें कोई तरीका उठा न रखा। सोवियत रूसकी कार्य-प्रणालीके सम्बन्धमें तरह-तरहकी मिथ्या, अनर्गल और कपोलकल्पित बातोंके फैलानेका निन्द्य प्रयत्न किया गया। रूसका आर्थिक अवरोध किया गया। यहाँतक की दवाई और वच्चोंके लिए दूधका जाना भी बन्द कर दिया गया। डेनिकिन, ऐडमिरल कोलचक और रैङ्गल आदि विरोधियोंको हर प्रकारकी सहायता दी गयी। सन् १९२० ईसवी (विक्रम स० १९७७) में पोलण्डनिवासियोंको भी यूरोपके राष्ट्रोंने रूसके विरुद्ध सहायता दी। स्वभावतः लेनिनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और उसने इन पूँजीवादी राष्ट्रोंको हर प्रकारसे क्षति पहुँचानेका निश्चय किया। जब यूरोपने सोवियतसे नाता तोड़ा तब लेनिनने विवश होकर एशियाकी ओर दृष्टिपात किया और सोवियत-शासनने अपना यह मन्तव्य प्रकट किया कि वह एशियाके देशोंके साथ व्यापारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करेगा।

बहुत अनुशीलन और मननके बाद लेनिन इस सिद्धान्तपर पहुँचा था कि वर्तमान युगका 'आर्थिक साम्राज्यवाद' पूँजीवादकी आखिरी मञ्जिल है। उसने अपने इस विचारकी साङ्गोपाङ्ग विवेचना 'इम्पीरियलिज्म' नामक पुस्तकमें की है। उसने इस ग्रन्थमें अपना यह मत प्रकाशित किया है कि वर्तमान युगमें पूँजीवाद एक अन्धी गलीमें प्रवेश कर चुका है, जहाँ उसके लिए आगे जानेका मार्ग नहीं है, पूँजीवाद अपने कर्तव्यको

पूरा कर चुका है। अब इसके बाद साम्यवादकी स्थापना निर्विवाद और अवश्यम्भावी है। साम्यवादियोंका मत था कि साम्यवादकी प्रतिष्ठा उन्हीं देशोमे हो सकती है, जहाँ व्यवसायके द्वारा पूंजीवादका प्रसार पर्याप्त परिमाणमे हो चुका हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयताके क्षेत्रमे वे केवल यूरोपके ही अधीन राष्ट्रोंको स्वतन्त्र करानेकी इच्छा रखते थे। अफ्रीका और एशियाके राष्ट्रोंको वे उपेक्षा-भावसे देखते थे। इन महाद्वीपोंके परतन्त्र राष्ट्रोंको स्वतन्त्र करानेकी उनको फिक्र न थी। पर इन सब विषयोमे लेनिनका विचार कुछ दूसरा ही था। लेनिनका कहना था कि आज संसारमें विविध देशोंके आर्थिक जीवनका परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है कि पुरानी प्रथाके साम्यवादियोंका यह कहना कि पूंजीवाद-प्रधान देशोमे ही साम्यवादका प्रयोग सफल हो सकता है, गलत है। उसका मत था कि आज उन्हीं देशोंमें साम्यवादका प्रसार सुलभ है, जहाँ साम्राज्यवादकी शक्ति बहुत प्रबल नहीं है। इसी कारण रूसमे सबसे पहले यह प्रयोग सफल हो सका, क्योंकि रूस साम्राज्यवादी प्रधान राष्ट्रोंमे सबसे निम्न श्रेणीका राष्ट्र था। उसका यह भी कहना था कि यदि दो सबल साम्राज्यवादी राष्ट्रोंमे परस्पर युद्ध हो, तो जो राष्ट्र इस युद्धमे परास्त और विताडित होगा उस क्षीण और दुर्बल राष्ट्रमे भी साम्यवादका प्रयोग चलाया जा सकता है। जब साम्यवादके कट्टर विरोधी साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं जब यह सिद्धान्त स्थिर हुआ कि जहाँ साम्राज्यवाद निर्बल होगा वहाँ साम्यवादका प्रवेश सुलभ हो जायगा, तब साम्राज्यवादको आघात पहुँचाना और उसको ध्वंस करनेका उद्योग करना रूसके साम्यवादीके लिए आवश्यक हो गया। यूरोपके साम्राज्यवादी राष्ट्रोंकी शक्तिका मुख्य स्रोत एशिया और अफ्रीकाके वे देश हैं जो आज उनके अधीन हैं। इन्हीं अधीन देशोंके आर्थिक जीवनपर प्रभुत्व पाकर आज वे परिपुष्ट हो रहे हैं। उनका व्यवसाय इन्हीं अधीन देशोंकी बढौलत चलता है। ये देश उनके व्यवसायके लिए एक मण्डी हैं और उनको कच्चा माल देते हैं, जिस सामग्रीका उपयोग कर ये राष्ट्र अपनी तिजारत चलाते हैं। यदि साम्राज्यवादका अन्त करना है तो एशिया और अफ्रीकाके राष्ट्रीय आन्दोलनोंकी सहायता करना सोवियत रूसका कर्तव्य हो जाता है। आज एशियाके कई राष्ट्रोंमे जागृतिके चिह्न दीख पड़ते हैं। उनमे एक नवीन जीवनका संचार हो रहा है। वे आत्म-गौरवको पहचानने लगे हैं और अपने देशको स्वतन्त्र देखना चाहते हैं। इन राष्ट्रीय आन्दोलनोंकी शक्ति क्रमशः बढती ही जाती है। सोवियत रूसने इन आन्दोलनोंको उत्तेजित करनेकी नीति निर्धारित की। जहाँ पुरानी प्रथाके साम्यवादी एशियाकी उपेक्षा करते थे वहाँ रूसके साम्यवादियोंको एशियाकी ओर अधिक ध्यान देना पड़ा और उन्होंने एशियामे साम्राज्यवादके विरुद्ध प्रचारका कार्य आरम्भ किया और एक ऐसा संघ संगठित किया जो साम्राज्यवादका विरोध करे। आर्थिक साम्राज्यवाद संसारके लिए भयानक है—इस बातको पहले थोड़ेसे विद्वान् ही पहचानते थे। एशियाके लोग तो प्रायः यह भी नहीं जानते थे कि साम्राज्यवाद क्या चीज है, पर लेनिनने एशियाके लोगोंको इसकी भीषणता बतलायी और उनको सतर्क कर दिया। आगे चलकर लेनिनने एशियाके स्वतन्त्र राष्ट्रोंके साथ जो सन्धियाँ की, उन सन्धिपत्रोंमे साम्राज्यवादका उल्लेख

पाया जाता है। लेनिनने एशिया और अफ्रीकाके देशोको तीन भागोमे बाँटा। पहले विभागमे वे देश आते हैं जहाँ वर्तमान युगकी वैज्ञानिक व्यवसाय-पद्धतिका उपक्रम नहीं हुआ है, पर जो साम्राज्यवादी राष्ट्रोद्वारा पददलित हो रहे हैं और ग्रसे जाते हैं। दूसरे विभागमे वे देश परिगणित हैं जहाँ इस नवीन व्यवस्था-पद्धतिका उपक्रम तो हो गया है, पर उसका विशेष रूपसे विकास नहीं हुआ है। तीसरी कोटिमे वे देश आते हैं जहाँ इस पद्धतिका काफी चलन हो गया है। पहले प्रकारके देशोके सम्बन्धमे लेनिनकी यह नीति थी कि वहाँ केवल राष्ट्रीय आन्दोलनको सहायता देकर सबल बनाना चाहिये और साम्यवाद-प्रचारका प्रयत्न न करना चाहिये। दूसरे प्रकारके देशोमे वह साम्यवादका प्रचार करना तो चाहता था, पर वह इस बातका पक्षपाती न था कि उस देशके साम्यवादी राष्ट्रीय आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण करे। तीसरे प्रकारके देशोके सम्बन्धमे उसकी यह स्पष्ट राय थी कि इनमे केवल एक साम्यवादी दलकी सृष्टि करना ही पर्याप्त न होगा, अपितु इस दलको राष्ट्रीय आन्दोलनका नेतृत्व भी ग्रहण करना चाहिये। भारतके सम्बन्धमे उसका विचार था कि यहाँ यूरोपीय महासमरके बादसे नवीन व्यवसाय-पद्धतिकी अच्छी तरक्की हुई है और इसलिए भारतमे साम्यवादका प्रचार सुलभ है। इसीलिए भारतको उन्होंने तीसरी कोटिमे रखा था। इस समय भारतमे राष्ट्रीय आन्दोलनपर मध्यमश्रेणीके लोगोका ही अधिकतर अधिकार है। यहाँके कम्युनिस्ट अभी इतनी शक्तिका संग्रह नहीं कर पाये हैं कि वे भारतकी राष्ट्रीय सस्था कांग्रेसपर अधिकार प्राप्त कर सकें। पर चीनका उदाहरण हमारे सामने है। चीनको साम्राज्यवादसे छुटकारा दिलानेमे रूसकी अच्छी खासी सहायता थी। रूसने जारके समयके अपने सारे अधिकारोका परित्याग कर दिया था। उसने चीनियोकी राष्ट्रीय सस्था कुओमिन्ताङ्गका नवीन ढंगसे सघटन करनेमे सहायता दी थी तथा रण-शिक्षा देनेके लिए रूससे सुयोग्य शिक्षक भी भेजे थे। चीनके नेता सनयातसेनने सोवियतकी सहायताको मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया था और यदि आज चीन स्वतन्त्र राष्ट्र कहलानेके योग्य हो गया है, तो इसका बहुत कुछ श्रेय सोवियत रूसको है। सोवियत रूसने ही चीनको प्रचारकी नवीन पद्धति बतायी और साम्राज्यवादका विरोध करनेमे उसकी हर प्रकारसे सहायता की। पर आज हम क्या देखते हैं? चीनका राष्ट्रपति च्यागकाई शेक जिसने रूसमे रणशिक्षा प्राप्त की थी आज सोवियत रूसका विरोध करनेपर तुला हुआ है और जिन साम्राज्यवादी राष्ट्रोसे छुटकारा पानेके लिए चीन कल रूसका सहारा ले रहा था आज उन्हीसे मित्रता स्थापित कर रहा है। इसका कारण यही है कि कम्युनिस्ट दल कुओमिन्ताङ्गपर प्रधानता पाना चाहता था और उसकी यह इच्छा थी कि चीनमे जो नयी व्यवस्था कायम हो उसमे साम्यवादके सिद्धान्तोके अनुसार कार्य किया जाय। पर यह बात च्यागकाई शेक और उनके अनुयायियोको पसन्द न थी। च्यागकाई शेक पुराने विचारोका समर्थक था और साम्यवादके प्रभावको बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था। उसने कम्युनिस्टोका घोर विरोध किया और उनके ऊपर नाना प्रकारके अत्याचार किये। यहाँतक कि चीन और रूसके बीच युद्ध होनेकी आशका बढ़ती जाती है और लडाईके बादल उमड़े चले आ रहे हैं। च्यागकाई शेक यद्यपि अपने कई साथियोकी अपेक्षा कही अच्छा है,

तथापि उसमें महत्वाकांक्षा और आत्मोत्कर्षकी भावना प्रबल है। वह किस प्रकार कम्युनिस्ट दलके उत्कर्षको सहन कर सकता था ? और जब उसके लिए इस दलका विरोध करना आवश्यक हो गया, तब उसने रूसके विरुद्ध अपनेको सबल बनानेके लिए इंग्लैण्ड ऐसे साम्राज्यवादी राष्ट्रसे मित्रता स्थापित की। यदि चीनका कम्युनिस्ट दल राष्ट्रीय आन्दोलनका सूत्र अपने हाथमें लेनेकी चेष्टा न करता और केवल सहायता देकर ही अपना सन्तोष कर लेता तो यह विरोध कदाचित् आज खड़ा न होता। पर सोवियत रूससे ऐसी आशा रखना व्यर्थ है, क्योंकि वास्तवमें वह राष्ट्रवादका विरोधी है और यदि वह किसी राष्ट्रको स्वाधीन होनेमें सहायता देता है तो केवल इसी विचारसे कि उससे साम्यवादपर आघात पहुँचेगा और यदि परिस्थिति अनुकूल हुई तो साम्यवादका प्रयोग करनेके लिए नवीन क्षेत्र भी हाथ लगेगा। हमको यह भी याद रखना चाहिये कि साम्यवादीका विश्वास है कि किसी स्थानपर साम्यवादकी स्थिरताके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सर्वत्र साम्यवादका प्रचार हो और इसलिए उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उसको साम्यवादकी प्रतिष्ठाकी ओर ले जाती है। साथ-साथ यह भी है कि साम्यवादीके लिए साम्यवादका सिद्धान्त प्रधान है; और सब बातें गौण हैं।

इन सिद्धान्तोंके अनुसार और रूसकी परिस्थितिके अनुकूल सोवियत शासनको एशियाके सम्बन्धमें एक नवीन नीतिका अवलम्बन करना पड़ा और इस नीतिको सफल बनानेके लिए अनेक प्रकारके आयोजन भी करने पड़े। सोवियत शासनने इस बातकी घोषणा की कि उसकी पद्धति और नीति जारकी गवर्नमेण्टकी पद्धति और नीतिसे सर्वथा विभिन्न है और वह उन अत्याचारोंको नहीं होने देगा जो पुराने समयमें जारकी गवर्नमेण्टद्वारा प्रजापर किये जाते थे। उसने रूसके साम्राज्यके भीतर रहनेवाली जातियोंको आत्म-निर्णयका अधिकार दिया। जहाँ पुराने समयमें यूक्रेनियन, जार्जियन और पोलकी अल्प-संख्यक जातियोंको पददलित किया जाता था, उनकी भाषा और संस्कृतिको बलपूर्वक मिटा देनेका उद्योग किया जाता था वहाँ सोवियत शासनने उनको इस बातकी स्वतन्त्रता दी कि वे अपनी भाषा और संस्कृतिका पूर्णरूपसे विकास करें। संस्कृतिकी स्वतन्त्रता और आर्थिक सहयोग^१ इन दो सिद्धान्तोंके आधारपर सोवियत शासनने अल्प-संख्यक जातियोंके जटिल प्रश्नको निपटानेका प्रयत्न किया। इस नीतिका फल यह हुआ कि जातिगत वैमनस्य, जो संस्कृतिके विरोधके कारण हुआ करता था, बहुत कम हो गया। जिन जातियोंकी कोई साहित्यकी भाषा न थी उन्होंने अपनी बोलचालकी भाषाको साहित्यकी भाषा बनानेका प्रयत्न किया और इस प्रयत्नमें सोवियत शासनने उनकी पूरी सहायता की। इसके अतिरिक्त सोवियत शासनने एशियाके राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता स्वीकार की और उनकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेका वचन दिया और एशियाके राष्ट्रोंको यूरोपके साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए सघटित किया। इसी नीतिके अनुसार सोवियत रूसने ब्रिटिश साम्राज्यवादको कमजोर करनेके लिए मिस्र और भारतको अलग करता हुआ तुर्की, फारस

१. लोकल कल्चरल सेल्फ डिटर्मिनेशन एण्ड इकनामिक कोऑपरेशन Local cultural self-determination and economic co-operation.

और अफगानिस्तानका एक सघ खड़ा कर दिया । जारोके समयसे ही इन तीन मुस्लिम राष्ट्रोंपर अपना-अपना अधिकार जमानेके लिए इंग्लैण्ड और रूसके बीच एक गहरी प्रतिद्वन्द्विता चली आती थी और यद्यपि अब जारका शासन उठ गया था तथापि आपसके विरोधके कारण यह स्पर्धा पहलेकी अपेक्षा और भी अधिक बढ़ गयी थी । पर सोवियत रूस इन राष्ट्रोंको दवाना नहीं चाहता था । यही नहीं, वह उनकी रक्षा और सहायता करना चाहता था । एशियाके साम्राज्यवादी राष्ट्र जापानकी भी उसने अपेक्षा नहीं की । वह तरह-तरहके प्रलोभन देकर जापानको भी सन्तुष्ट करना चाहता था । संक्षेपमें वह बाल्टिकसे लेकर पैसिफिकतक एक ऐसे सघको तैयार करना चाहता था जिसमें परस्पर आर्थिक सहयोग हो, और जो समान रूपसे साम्राज्यवादका विरोध करनेके लिए प्रस्तुत हो । यह नीति एक दिनमें सफल नहीं हो सकती थी । बहुत अध्यवसाय और धैर्यके साथ निरन्तर काम करते रहनेके उपरान्त ही इस नीतिका प्रभाव दिखलायी पड़ा । पर पूर्व इसके कि इस नीतिका कोई असर पड़े, इस बातकी आवश्यकता थी कि सोवियत रूस एशियाके राष्ट्रोंका विश्वास-पात्र बने । इसके लिए उसने अनेक उपाय किये । एशियाके लोगोंकी कांग्रेस बुलानेका आयोजन किया गया । पहली कांग्रेस सन् १९२० (वि० सं० १९७७) में बाकुमें हुई थी । कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की ओरसे जिनोवीव ने इस कांग्रेसमें जो भाषण दिया था उसका सार यही था कि एशियाके लोगोंको एक साथ मिलकर यूरोपके साम्राज्यका विरोध करना चाहिये । इसके पश्चात् कई बार एशियाके श्रमजीवियों की कांग्रेसें भी की गयीं । एक कांग्रेस सन् १९२७ (वि० सं० १९८४) में हैकाऊ में हुई थी, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, ओशेनिया और ईस्ट इण्डोचिना के श्रमजीवियोंके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । इन कांग्रेसोंका उद्देश्य साम्राज्यवादके विरुद्ध प्रचार करना और एशियाकी विविध जातियोंमें परस्पर भ्रातृभावकी स्थापना करना था । इन कार्योंका प्रभाव ग्रेट ब्रिटेनपर तत्काल ही पड़ा और सन् १९२० (वि० सं० १९७७) में लायड जार्जकी गवर्नमेण्टने रूससे मेल करनेका प्रस्ताव किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो एशियामें हमारा प्रभाव बहुत घट जायगा । सन्धिकी जो शर्तें लायड जार्जने सोवियतके प्रतिनिधि त्रासिन के सामने रखी थी उनमेंसे एक शर्त यह भी थी कि सोवियत रूस एशियामें—विशेषतः भारत और अफगानिस्तानमें—ब्रिटिश साम्राज्यके विरुद्ध आन्दोलन नहीं करेगा । पर कई घटनाएँ ऐसी हो गयीं जिनके कारण उस समय रूस और इंग्लैण्डके बीच कोई समझौता नहीं हो सका । समझौतेकी बातचीत कभी चलती थी और कभी बन्द हो जाती थी । पूर्व इसके कि कोई समझौता हो सके रूसने तुर्की, फारस और अफगानिस्तानसे इंग्लैण्डके प्रभावको हटा दिया । सन् १९१९ (वि० सं० १९७६) में इंग्लैण्ड का एशियामें बहुत बड़ा दबदबा था । उसके साम्राज्यका बहुत विस्तार हो गया था । यूरोपके अन्य राष्ट्रोंकी अपेक्षा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत

अच्छी थी। अरब उसके नियन्त्रणमें था; ईराक और पैलेस्टाइनपर राष्ट्र-संघकी ओरसे उसको मँहटे^१ मिल चुके थे; तुर्कीका साम्राज्य छिन्न-भिन्न कर दिया गया था; फारसका मैदान साफ पाकर १९१६ (वि० सं० १९७६) के समझौते^२ के द्वारा फारसपर अपना नियन्त्रण मुद्द^३ करने और अपने अधिकारका विस्तार करनेकी चेष्टा की गयी। काकसस, ट्रैन्स काकेशिया, ट्रैन्स कैस्पिया और तुर्कीस्तान उनके कब्जेमें था। इंग्लैंडके कुछ राजनीतिज्ञ यह कहने लग गये थे कि हम काकससकी पर्वतमालाको ब्रिटिश साम्राज्यकी रक्षाकी उत्तरी सीमा बनायेंगे। यह अवस्था सन् १९१६ (वि० सं० १९७६) में थी। पर दो वर्षके भीतर ही काया-पलट हो गया। अफगानिस्तानकी स्वतन्त्रताको ब्रिटिश सरकारको मानना पड़ा और अफगानिस्तानकी परराष्ट्र-नीति ब्रिटिशके अधीन न रहकर अफगानिस्तानके बादशाहके अधीन हो गयी। फारसकी मजलिसने लार्ड कर्जनके समझौतेको ठुकरा दिया और वहाँसन् १९२१ ईसवी (वि० सं० १९७८) में राज्य-क्रान्ति हो गयी। तुर्क कमालपाशाके नेतृत्वमें ग्रीक लोगोंके विरुद्ध बहादुरीके साथ लड़े और उनपर पूरी विजय प्राप्त की। प्रधान मन्त्रि-राष्ट्रोंने अंगोराकी गवर्नमेण्टको सुलहकी बातचीतके लिए आमन्त्रित किया और लोसानकी कान्फरेंस^४ में सेव्रेकी अपमानजनक सन्धियाँ बदल दी गयी। तुर्कीकी लगभग वह सब माँगें स्वीकृत हुईं जो उन्होंने २८ जनवरी, सन् १९२० (१५ माघ सं० १९७७) के 'टर्किश नेशनल पैक्ट' में पेश की थी। सन् १९२१ (वि० सं० १९७८) में सोवियत रूसने फारस, तुर्की अफगानिस्तान और बुखारासे सन्धियाँ की। जारके समय के सुलहनामों जिनके द्वारा रूसने इन देशोंमें तरह-तरहके अधिकार प्राप्त किये थे, रद्द कर दिये गये। जो सुलहनामा फारसके साथ हुआ था उसकी मुख्य-मुख्य शर्तें नीचे दी जाती हैं—

१. सोवियत शासन जारकी अत्याचारकी नीतिका सदाके लिए परित्याग करता है और उसकी यह इच्छा है कि फारसके लोग स्वतन्त्र और प्रसन्न रहे, और उनके देशपर उनका अक्षुण्ण अधिकार रहे और इसलिए वे सन्धियाँ और शर्तनामों रद्द किये जाते हैं, जो फारसके लोगोंके अधिकारोंको कम करनेके अभिप्रायसे किये गये थे।

२. सोवियत शासन जारकी उस नीतिको न्यायके विरुद्ध और बुरा समझता है जिसका उद्देश्य एशियाके राष्ट्रोंका बन्दरवाँट करनेके लिए यूरोपके और राष्ट्रोंके साथ सन्धि करना था। इसलिए सोवियत शासन इस नीतिका सर्वथा परित्याग करता है और घोषित करता है कि वह किसी ऐसे कार्यमें भाग नहीं लेगा जिसका उद्देश्य फारसके अक्षुण्ण अधिकारको कमजोर करना हो और वह उन सब सन्धियोंको रद्द करता है जो जारकी गवर्नमेण्टने फारसको नुकसान पहुँचानेके लिए अन्य शक्तियोंके साथ की थी।

३. सोवियत शासन जारकी गवर्नमेण्टकी उस आर्थिक नीतिको अस्वीकार करता है जिसको वह फारसके सम्बन्धमें वर्तती थी और जिसका उद्देश्य, आर्थिक उन्नतिकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि दासताकी शृङ्खलामें बाँधनेकी दृष्टिसे, फारसको कर्ज देना था। सोवियत

१. Mandate. २. एंग्लोपर्सियन ऐग्रीमेण्ट Anglo Persian agreement.

३. Lausanne conference. ४. Treaty of Sveres.

शासन इसलिए अपने सब हकोंको छोड़ता है और घोषित करता है कि ये कर्जें वसूल नहीं किये जायेंगे ।

४. सोवियत शासन पूँजीवादकी एशिया-सम्बन्धी नीतिकी खुले शब्दोंमें निन्दा करता है और उसकी यह सम्मति है कि इस नीतिके कारण ही एशियाके निवासियोंको अनेक कष्ट सहने पड़े हैं ।

५. सोवियत शासन फारसके आन्तरिक मामलोंमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेगा ।

६. सोवियत रूस और फारसके बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होंगे ।

जो सन्धि तुर्कीके साथ हुई उसकी पहली धारामें इस बातका स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है कि दोनों पक्षोंको साम्राज्यवादका विरोध करना है और दोनोंका स्वार्थ यह चाहता है कि उनमें आपसमें मित्रता स्थापित हो । सन् १९२५ (वि० सं० १९८२) में पेरिसमें सोवियत रूस और तुर्कीके दमियान एक दूसरी सन्धि हुई थी जिसके द्वारा दोनों पक्ष इस बातके लिए वचन-बद्ध हुए कि वे एक दूसरेके विरुद्ध किसीकी सहायता नहीं करेंगे । दो वर्ष बाद एक व्यापारिक सन्धि भी हुई ।

अफगानिस्तानके साथ जो सन्धि सन् १९२१ (वि० सं० १९७८) में हुई उसके द्वारा सोवियत रूसने अफगानिस्तानकी स्वतन्त्रता और आत्म-निर्णयके अधिकारको स्वीकार किया । सन् १९२६ (वि० सं० १९८३) में एक सुलहनामा और हुआ जिसके जरियेसे उन्होंने यह निश्चय किया कि वे एक दूसरेपर आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरेके विरुद्ध किसीके साथ सन्धि नहीं करेंगे और एक दूसरेके विरुद्ध किसी आर्थिक अवरोधमें सम्मिलित न होंगे और वे किसी ऐसी गवर्नमेण्टकी न तो सहायता करेंगे और न उसका साथ देंगे जो उनमेंसे किसीके आन्तरिक मामलोंमें हस्तक्षेप करे । यदि उनमेंसे किसीका किसी तीसरे राष्ट्रके साथ झगडा हो तो दूसरा उदासीन रहेगा । उनमेंसे कोई अपने राज्यके भीतरसे किसी प्रकारका लड़ाईका सामान या फौज न जाने देगा जिसका प्रयोग दूसरेके विरुद्ध किया जाय ।

पूर्वीय एशियामें सोवियत रूसको एक मित्र-राष्ट्रकी आवश्यकता थी । जापान यद्यपि सबल राष्ट्र था तथापि उसकी नीति साम्राज्यवादकी थी । उसको अपने व्यापारके लिए कच्चे वाने और मण्डियोंकी आवश्यकता थी । यूरोपीय युद्धसे लाभ उठाकर उसने शान्तुङ्ग ले लिया और सन् १९१५ (विक्रम सं० १९७२) में चीनके सामने इक्कीस माँगें रखी जिनको चीनी सरकारको विवश होकर स्वीकार करना पडा । सन् १९१८ (विक्रम सं० १९७५) में जापानने व्लाडीवास्तकपर आक्रमण कर दिया । सोवियत रूसके विरुद्ध कोलचककी सहायताके लिए साइबेरियामें उसने अपनी सेना भेजी थी; सखलीनके उत्तरी भागपर, तेलके चश्मोंके लोभसे, उसने अधिकार जमा लिया था । जापानकी शक्तिको बढ़ता हुआ देखकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन भयभीत हो गये थे । वे जापानकी शक्तिको बढ़ानेमें सहायता देना नहीं चाहते थे । इंग्लैण्ड और जापानके बीच जो सन्धि हुई थी उसकी अवधि बीत चुकी थी । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापानके बीच अच्छा सम्बन्ध नहीं था और इंग्लैण्ड इस सन्धिकी अवधिको बढ़ाकर अमेरिकाको नाराज करना

नहीं चाहता था। वाशिंगटन कान्फरेन्सकी कार्यवाहीसे आरम्भमें आपसका मनोमालिन्य और भी बढ़ गया था। सन् १९२४ (विक्रम सं० १९८१) में संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाने एक कानून बनाकर जापानके निवासियोंको अमेरिकामें आकर बसनेसे रोक दिया। इन सब कारणोंसे जापानकी राजनीतिक स्थिति रूसके अनुकूल होती गयी और सोवियत रूसने इस स्थितिसे पूरा लाभ उठाकर जापानके साथ रियायते करके जापानसे मित्रता कर ली। पूर्व इसके कि रूस और जापानकी सन्धि हुई रूसने सन् १९२४ (विक्रम सं० १९८१) में चीनसे सन्धि की। सन् १९२० (विक्रम सं० १९७७) ही में सोवियत शासनने इस बातकी घोषणा की थी कि रूस उन सब अधिकारोंका परित्याग करनेको तैयार है जिनको जारकी गवर्नमेंटने चीनमें प्राप्त किया था और इसके लिए वह कोई मुआवजा भी न लेगा। इसके बादसे ही चीनकी राष्ट्रीय सरकार और सोवियत रूसके बीच मित्रता बढ़ने लगी। चीन विदेशियोंद्वारा पदे-पदे अपमानित हो रहा था। इस अवज्ञा और तिरस्कारको अब वह सह नहीं सकता था। साम्राज्यवादी राष्ट्रोंसे उसको कोई आशा न रही। उसने सोवियत रूसकी ओर हाथ बढ़ाया और सन् १९२४ (विक्रम सं० १९८१) में दोनों राष्ट्रोंके बीच एक सन्धि हुई जिसके द्वारा रूसने उन सब अधिकारोंका परित्याग किया जो उसे प्राप्त थे। कानो और जंगलातमें जो हक रूसको मिले थे वे बिला मुआवजेके वापस कर दिये। इस प्रकार सन् १९२० (विक्रम सं० १९७७) की घोषणाको सोवियत रूसने अक्षरशः सत्य प्रमाणित कर दिया। चाइनीज ईस्टर्न रेलवेके सम्बन्धमें आपसमें यह निश्चय हुआ कि इसका प्रबन्ध रूसी और चीनी दोनोंके हाथमें रहेगा। इस सन्धिको संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाने विरोध किया था। पर चीनने इसका यह उत्तर दिया कि यह हमारी घरेलू बात है, इसमें किसी दूसरेको हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है। रूसने चीनके साथ समानताका व्यवहार किया और कराखोंकी अपनी ओरसे राजदूत नियुक्त किया। यह पहला ही अवसर था कि किसी राष्ट्रकी ओरसे राजदूतकी हैसियतका कोई अधिकारी चीनमें नियुक्त किया गया हो। अपने अधिकारोंकी रक्षा करनेमें चीनकी राष्ट्रीय सरकारको सोवियत रूसने हर तरहकी सहायता पहुँचायी। रूसका प्रभाव चीनमें धीरे-धीरे बढ़ने लगा और जब सन् १९२५ (विक्रम सं० १९८२) में चीनी प्रजातन्त्रके अध्यक्ष डाक्टर सनयात सेनकी मृत्यु हुई तब इस सम्बन्धकी ओर भी मजबूत करनेके लिए रूसने उसकी यादगारमें एक विश्वविद्यालय खोला। साम्राज्यवादी राष्ट्र रूसके इस बढ़ते हुए प्रभावको देखकर घबड़ा गये। उन्होंने कहना शुरू किया कि सोवियत रूस लोगोंको भड़काता है। और उसके बहकानेमें आकर कुली हड़ताल कर देते हैं। इसके उत्तरमें कराखोंने कहा था कि “हमारा यह प्रभाव प्रचार-कार्यका फल नहीं है बल्कि उस न्यायानुमोदित नीतिका फल है जिसको कि सोवियत रूस चीनके साथ बरत रहा है। हमने इस नीतिको केवल शब्दोंद्वारा ही नहीं व्यक्त किया है बल्कि इस नीतिको कार्यान्वित करके यह दिखला दिया है कि हम चीनके साथ न्यायका व्यवहार करना चाहते हैं। यदि हमारा यही अपराध है तो हम इसे स्वीकार करते हैं और हम इसके लिए लज्जित नहीं हैं बल्कि हमको इसका गर्व है।” एक दूसरे मौकेपर कराखोंने अमेरिकाके एक सम्वाददाताके पूछनेपर कहा था कि

“हम प्रचार तो अवश्य करते हैं, पर इस प्रचारके लिए हमको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता । अभी उस दिन कुछ चीनी विद्यार्थी मुझसे मिलने आये थे । मैंने चाय पिलाकर उनकी वैसी ही खातिर की थी जैसी कि मैं आपकी कर रहा हूँ । पर जब वे अमेरिकन लिगेशनमें आपके कौंसलसे मिलने गये तब वे स्वयं उनसे नहीं मिले और एक निम्नश्रेणीके कर्मचारीको उनसे बात करनेके लिए नियुक्त कर दिया और वह कर्मचारी भी उनसे अच्छी तरह नहीं मिला । हमारा यही प्रचारका कार्य है । तुमलोग वेवकूफ हो । इतना भी नहीं जानते कि मनुष्यके हृदयपर किस प्रकार अधिकार पाया जाता है ।” यहाँपर हमें इस बातका विस्तारपूर्वक उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार सोवियत रूसकी सहायतासे चीनकी राष्ट्रीय संस्था कुओमिन्ताङ्गका फिरसे संघटन हुआ और चीनके मजदूर और किसान राष्ट्रीय आन्दोलनमें सम्मिलित हुए; और फलतः चीनने अपने खोये हुए कुछ अधिकारोंको फिरसे प्राप्त किया । चीनकी सन्धिमें छ महीने बाद ही सन् १९२५ (विक्रम सं० १९८२) में रूस और जापानकी सन्धि हुई जिसके जरिये रूसने सखलिन द्वीपके उत्तरी भागमें निकलनेवाले तेलके पचास फी सदी हिस्सेको जापानको देना स्वीकार किया, और अपने राज्यके भीतर खानोंसे धातु निकालने और जंगलोसे लकड़ी इत्यादि लेनेकी रियायत दी । जापानने सखलिनके उत्तरी भागसे अपनी फौज हटा ली । दोनों पक्षोंने एक दूसरेके विरुद्ध प्रचार कार्य न करनेका वचन दिया । इस प्रकार जापान और रूसमें मित्रता स्थापित हुई ।

सोवियत रूसकी एशिया-सम्बन्धी नीतिके प्रयोगका यह संक्षेपमें विवरण है । हमने देखा कि एक समय इस नीतिकी सफलता हर दिशामें हुई और ब्रिटिश गवर्नमेण्टका प्रभाव एशियामें बहुत घट गया । इसी कारण सन् १९२१ (विक्रम सं० १९७८) में इंग्लैण्ड रूससे एक व्यापारिक सन्धि करनेके लिए विवश हुआ था । पर यह सन्धि अधिक दिनोत्तक टिक नहीं सकी । एक दूसरेकी शिकायत करने लगे कि सन्धिकी शर्तें पूरी नहीं की जा रही हैं और जब वोनरलाकी कजर्वेटिव गवर्नमेण्टके हाथमें इंग्लैण्डकी शासनकी वागडोर आयी तब आपसका झगडा और भी बढ़ गया । अग्रेजोंने कई नयी मांगें पेश की जिनमेंसे एक मांग यह भी थी कि काबुल और तेहरानसे सोवियतके प्रतिनिधि वापस बुला लिये जायँ । इंग्लैण्डने सोवियत रूसको लड़ाईकी धमकी भी दी थी । सोवियत लड़ाईके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने प्रतिनिधियोंके वापस बुलानेकी शर्तको छोड़कर प्रायः सब मुख्य-मुख्य शर्तें स्वीकार कर ली थी : इस तरह लड़ाई तो टल गयी, पर कोई बात निश्चित रूपसे तय न हो सकी और आपसके व्यवहामें रूखापन पाया जाने लगा । फ्रांसके रूरके आक्रमणके कारण इंग्लैण्डके लिए रूससे तत्काल लड़ना लाभदायक न था । सन् १९२३ (विक्रम सं० १९८०) में इंग्लैण्डमें मजदूर सरकार आ गयी और उसके प्रधान मन्त्री रैमसे मैकडोनाल्डने सुलहकी बातचीत फिरसे शुरू की और बहुत वाद-विवादके बाद आपसके झगडे बहुत-कुछ तय हो गये और अगस्त सन् १९२४ (विक्रम सं० १९८१) के आरम्भमें दो सन्धियोंपर हस्ताक्षर हुए, पर रैमसे मैकडोनाल्ड पार्लमेण्टकी स्वीकृति चाहते थे । पर पूर्व इसके कि यह विषय पार्लमेण्टमें विचारार्थ उपस्थित किया जाय, एक

और भरोसा जाता रहता है, जब उसको अपना भविष्य संकटमय दीख पड़ता है, जब श्रम और बुद्धि दोनोंका पुरस्कार लोगोको नहीं मिलता और बेकारी बढ़ती है तथा जनतामे निराशा और विरोधके भाव प्रादुर्भूत होते हैं, तब समझिये कि पुरानी सभ्यताका 'रोजे हिसाब' आ गया है। जब जनता सजग होकर विद्रोहके लिए उठ खड़ी होती है, तब सभ्यताको या तो जनतासे समझौता करना पड़ता है या वह उससे लड़नेको तैयार हो जाती है। इस संघर्षका परिणाम अनिश्चित होता है।

पूँजीवादका ह्रास

यह पूँजीवादके ह्रासका युग है। इस युगमे समाजके बहुत थोड़े लोगोको ही अपने व्यक्तित्वके पूर्ण विकासके लिए अवकाश मिलता है, प्रायः लोग अपनी व्यर्थताका ही अनुभव करते हैं। उनका व्यक्तित्व क्षत-विक्षत, विशीर्ण और विकल होता है। पूँजीवाद सम्पत्तिके अधिकारोकी रक्षा करता है; व्यक्तियोंके अधिकारोकी रक्षा करनेमे यह समर्थ नहीं है। हकीकत यह है कि पूँजीवाद आर्थिक क्षेत्रमे जनताको बाजारके नियमोके अधीन कर देता है और उन ऐहिक और आध्यात्मिक मूल्यों (values) के अधीन कर देता है जो पूँजीवादी सत्ताके स्वभावके अनुकूल हैं। और जीवनके ये मूल्य जनताके निजके अनुभवोको अभिव्यक्त नहीं करते। ये मूल्य भूमि और यन्त्रोके उन स्वामियोके अनुभवोको अभिव्यक्त करते हैं जो पूँजीवादी समाजपर प्रभुत्व रखते हैं। अतः जनता व्यक्ति रूपसे अपनी तुच्छताका अनुभव करती है। जिन संस्थाओका वह उपकरणमात्र है उनका विरोध किये बिना वह अपने व्यक्तित्वको सिद्ध नहीं कर सकती। जनताका वह पुराना विश्वास कि उसके साथ सामाजिक न्याय हो रहा है, लुप्त होता जाता है और इसी कारण एक व्यवस्थित समाजका संचालन दुष्कर होता जाता है। जनता सजग हो गयी है। वह अपने अधिकारोको पहचान गयी है और सगठित हो रही है। टाकविल (Tocqueville) ने ठीक कहा है :—

“आरम्भमे जनताने प्रत्येक राजनीतिक संस्थाको बदलकर अपनी अवस्थाको उन्नत करनेकी चेष्टा की, किन्तु प्रत्येक परिवर्तनके बाद उसने पाया कि उसकी स्थितिमे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या परिवर्तनकी गति इतनी मन्द है कि उससे उसको सन्तोष नहीं है। अन्तमे यह सत्य उसपर एक-न-एक दिन प्रकट होगा कि जिसने उसकी अवस्थाको अपरिवर्तन शील, जड़ और स्थिर बना दिया है, वह राज्यका शासन-विधान नहीं है, किन्तु इसकी जिम्मेदारी समाजके अटल नियमोपर है। अतः यह स्वाभाविक है कि जनता एक-न-एक दिन स्वतः यह प्रश्न करेगी कि क्या उसको उन नियमोके बदलनेका अधिकार और सामर्थ्य नहीं है ?”

जनताका जागरण

टाकविलने स्पष्ट देखा कि व्यक्तिगत सम्पत्तिकी पद्धति मानव समतामे बाधा उत्पन्न करती है। हमारी वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक पद्धतिके द्वारा एक गुट या समुदायके हित ही सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वह वैयक्तिक स्वामित्वको एक पवित्र

वस्तु मानती है। किन्तु सर्वसाधारणके लिए यह पद्धति अनिष्टकारी है। इस पद्धतिके अधीन रहते हुए जनताका जीवन नीरस और शुष्क हो जाता है। लोग अपनी तुच्छताका अनुभव करते हैं और उनको इससे बचनेकी राह भी नजर नहीं आती। यह पद्धति जनताका अपने पूर्ण विकासके लिए आह्वान नहीं करती, क्योंकि वह डरती है कि ऐसे आह्वानका क्या परिणाम होगा। उसका निश्चित मत है कि यदि जनताने इस पुकारको सुना और उसपर अमल किया तो उनकी खैरियत नहीं। अतः इसमें आश्चर्य करनेका कोई कारण नहीं है कि जो समाज अपने सदस्योंके व्यक्तित्वके विकासको इस प्रकार रोकता है वह उन भावोंको उभारनेमें समर्थ नहीं होता जिनके उभरने और व्यक्त होनेसे ही कोई पद्धति सुदृढ़ होती है।

समाजपर प्रभुत्व रखनेवाला वर्ग जनतासे भयभीत हो जाता है। वह अपने स्थिर स्वार्थोंकी रक्षाके लिए अपने देशके स्वातन्त्र्यको भी खतरेमें डालनेसे नहीं हिचकता। इस युद्धने यह सिद्ध कर दिया है कि देशकी आजादीकी रक्षा बिना वर्ग स्वार्थका परित्याग किये नहीं हो सकती। फ्रांसके एक समुदायने हिटलरका स्वागत इसलिए किया कि कही जनता विद्रोहकर उस समुदायके स्थिर स्वार्थोंका लोप न कर दे।

दूसरी ओर जनता स्वयं अपना नेतृत्व करनेमें असमर्थ होती है। वह नेताकी तलाशमें होती है। वह कोई साहसिक कर्म करना चाहती है। समाजकी संस्थाओंपर जो उसकी आस्था थी, वह नष्ट हो चुकी होती है और उसका मोह टूट चुका होता है। इस अवसरपर जनताकी मनोवृत्तिसे अनुचित लाभ उठाकर प्रतिक्रिया जनताके सम्मुख एक नवीन आशा और एक साहसिक कर्मके रूपमें उपस्थित होती है। प्रतिक्रिया नाना प्रकारके प्रलोभन देती है और उसके कार्यक्रममें प्रत्येक पीड़ित वर्गके लिए कोई न कोई लुभानेवाली योजना होती है। जनता इस अपीलको सुनती है, क्योंकि यह उसको अपनी व्यर्थतासे बचनेका रास्ता दिखाती है। वह प्रतिक्रियावादियोंके जालमें आ जाती है और उनका अनुसरण करती है। यह सच है कि प्रतिक्रियाके नायक सच्चे मसीहा नहीं हैं। उनके पास कोई दिव्य सन्देश नहीं है जिससे जनताका कल्याण हो सके। किन्तु जनता एक नवीन सन्देशकी भूखी होती है और जिस तरह एक रोगी जो अपने जीवनसे निराश हो चुका है, जड़ी-बूटी बेचनेवाले और तन्त्र-मन्त्र करनेवाले नीमहकीमकी शरणमें जाता है, उसी तरह निराश जनता सन्देशसे आकृष्ट हो उस नायककी ओर दौड़ती है और इसका विचार-विमर्श नहीं करती कि यह सन्देश झूठा है या सच्चा। यही अवस्था जर्मनीके लोगोंकी हुई। हिटलरके उत्थानका रहस्य इसीमें है।

संघर्ष और विरोध

किन्तु यह मोह-माया बहुत दिनोत्तक नहीं चल सकेगी। मित्रराष्ट्रोंने फासिज्मपर विजय प्राप्त की है। इससे यह सम्भव है कि शासक वर्ग कुछ दिनोत्तक चैनसे बैठने पाये, किन्तु वह बहुत दिनोत्तक आराम नहीं लेने पायेगे। विजयसे बड़ी हुई उनकी प्रतिष्ठा अधिक कालतक प्रचलित संस्थाओंमें जनताके पुराने विश्वासको पुनर्जीवित न कर सकेगी। सप्ताहमें सर्वत्र जनताका विश्वास क्रमागत संस्थाओंपरसे उठता जाता है। पुरातन

विश्वास और परम्परागत ऐहिक और पारलौकिक मूल्योंका खोखलापन और उनकी निस्सारता जनतापर प्रकट होती जाती है। आधुनिक युगकी वैचैनीका यही कारण है। क्रान्तिके युगमें ऐसा सदा होता है। मौलिक परिवर्तनके लिए किये गये उद्योगके साथ-साथ संघर्ष, विरोध, समाजका वैकल्य और उसकी विशीर्णता भी होती है। गम्भीर शक्तियाँ काम कर रही हैं और उन्हींके कारण यह संघर्ष और विरोध होता है। किन्तु लोग इन गम्भीर कारणोंकी खोज नहीं करते। वह कुछ व्यक्ति विशेषको ही दोषी ठहराते हैं। ये व्यक्तिविशेष उन शक्तियोंके केवल तात्कालिक प्रतीक हैं। अतः इनको भला-बुरा कहनेसे कुछ लाभ नहीं और न यह विचार ही यथार्थ है कि इन व्यक्तियोंके न होनेपर विरोध शान्त हो जायेगा।

अतः प्रश्न यह है कि हम यह तथ्य समझते हैं या नहीं कि वर्तमान युगमें समाजके जो पुरुषार्थ हैं वह अब सबको समानरूपसे स्वीकृत नहीं हैं। ऐसी दशामें यदि समझनेसे काम न लिया गया और जनताको यह विश्वास न दिलाया गया कि उसके साथ सामाजिक न्याय होगा तो समाजमें विप्लव होगा।

समाजके उत्पादनके सम्वन्ध उत्पादनकी शक्तियोंके विरोधमें हैं। भविष्यमें समाजको, यदि वह आन्तरिक क्रान्तिसे वचना चाहता है तो यह तय करना होगा कि समताकी परिधिमें ही स्वतन्त्रताका अन्वेषण किया जा सकता है। समयसे यदि व्यवस्थित लोकसत्ताकी बुनियादें नहीं डाली गयी तो यह कार्य सम्पन्न न हो सकेगा।

फासिज्मका उत्थान और प्रसार ही दिखाता है कि मानव-इतिहासका एक युग समाप्त हो रहा है। यूरोपीय सभ्यतापर उसके प्रभुत्वका स्थापित होना ही इस बातका प्रमाण है कि यूरोपकी बुनियादोंमें कोई घातक दुर्बलता है।

यूरोपका शासकवर्ग

खेद है कि यूरोपका शासकवर्ग इस रिक्त-स्थानके वाद भी इस सत्यको नहीं पहचान पा रहा है। वह अब भी पूँजीवादी प्रथासे चिपका हुआ है और युगवर्त्मको पहचानकर अपनी गतिविधियोंको बदलनेको तैयार नहीं है। लोकतन्त्रकी दुहाई देनेवाले ये पूँजीपति भी उसी समयतक लोकतन्त्रके भक्त हैं जबतक लोकतन्त्र उनके विशेषाधिकारोंको संशयमें नहीं डालता। ये सोच भी नहीं सकते कि कोई दूसरा भी कानून, कोई दूसरे प्रकारके अधिकार और अन्य सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्य हो सकते हैं। उनकी यह मूर्खता सर्वनाशका कारण है।

हिटलरकी सत्ताका अन्त करके भी यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि फासिज्मके बीजका विनाश हो गया है। जबतक फासिज्मके मूल कारणका उन्मूलन नहीं होता तबतक इसके बार-बार उदय होनेकी आशंका बनी रहती है। फासिज्मका सफल विरोध करनेका एकमात्र उपाय वह विश्वास है जो उस विभीषिकाका अतिक्रमण कर सकता है जिसे फासिज्म विजितोपर लादता है। इस विश्वासकी जड़े पूँजीवादी लोकसत्ताकी जड़ोंसे ज्यादा गहरी होनी चाहिये। पूँजीवादी लोकतन्त्रके विशीर्ण होनेपर ही फासिज्म अधिकारासूढ़ हुआ। अतः एक ऐसी नवीन आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाके कायम

होनेपर ही, जिसके द्वारा सामान्य जनता अपनी परिपूर्णताका अनुभव करे, ससारमे शान्ति और सुख स्थापित हो सकता है। अब पुरानी आर्थिक पद्धतिसे काम नहीं चलनेका। स्वतन्त्र व्यापारका युग चला गया है। युद्धकालमे जो राज्यका नियन्त्रण बढ गया है वह युद्धकी समाप्तिपर विलुप्त नहीं हो जायेगा। व्यवस्थित योजना समाजकी स्वतन्त्रताका अपहरण कर लेगी यदि यह योजना जनताके लाभके लिए प्रगतिशील शक्तियोंद्वारा नहीं प्रस्तुत की जाती। पूँजीपतियों द्वारा तैयार की गयी व्यवस्थित योजना उनके एकाधिकारको सुदृढ करके लोकतन्त्रका अन्त कर देगी। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है यह है कि आजकी अन्योन्याश्रित और परस्पर सम्बन्धित दुनिया उन खतरोंको अब और नहीं उठा सकती जो स्वतन्त्र राज्यमे (Sovereign States) के अस्तित्वके कारण बढते जाते हैं। जबतक प्रत्येक महान् राष्ट्र अपने कुछ अधिकारोंको छोड़नेको तैयार नहीं हो जाता, तबतक अन्तर्राष्ट्रीय समाज गठित नहीं हो सकता। राजनीतिक प्रश्नोंका महत्त्व अधिक समझा जाता है, आर्थिक प्रश्नोंका नहीं। किन्तु मौलिक प्रश्न आर्थिक है। यूरोपके छोटे-छोटे राज्य हो तो कुछ हर्ज नहीं, किन्तु यदि ये छोटे-छोटे राज्य आर्थिक और सैनिक दृष्टिसे एक दूसरेसे स्वतन्त्र रहना चाहें तो यूरोपमे शान्ति स्थापित करना सम्भव न हो सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय समाजकी स्थापनाके लिए राष्ट्रीयताका वर्तमान विकृत रूप बदलना होगा। उसका प्राधान्य सांस्कृतिक क्षेत्रतक ही सीमित रखना होगा। राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमे उसकी प्रधानता हानिकर होगी।

राज्योंका अधिकार अक्षुण्ण रखकर तथा वर्तमान अर्थनीतिका अतिक्रमण किये बिना हम ससारमे शान्तिकी स्थापना न कर सकेंगे। एक बात और। ससारकी कल्याणकारी दृष्टिके साथ साम्राज्यवादका असामञ्जस्य है। अमेरिकाके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ स्वर्गीय वेडल विल्की (Wendell Willkie) के शब्दोंमे “स्वतन्त्र” शब्द अविभाज्य है। यदि हम उसका उपभोग करना चाहते हैं और उसके लिए लड़ना चाहते हैं तो हमें सबको समान रूपसे स्वतन्त्रता प्रदान करनेके लिए तैयार रहना चाहिये—चाहे वह अमीर हों या गरीब, चाहे वह हमसे सहमत हो या नहीं, चाहे वह किसी भी जाति या वर्णके क्यों न हो। ससारके सब भाग एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं और कोई भी राष्ट्र अकेले अपने पूर्ण विकासको नहीं प्राप्त कर सकता।

इन सिद्धान्तोंको ध्यानमे रखकर यदि हम यूरोपकी ओर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलेगा कि ये सिद्धान्त पूर्णरूपेण कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं। प्रत्येक महान् राष्ट्र अपने अधिकारोंको अक्षुण्ण रखना चाहता है। यूरोपको इकाई मानकर यूरोपके आर्थिक जीवनका एक नया संगठन बनानेकी ओर भी ध्यान नहीं है। यह ठीक है कि पूर्वी यूरोपके देशोंकी पुरानी आर्थिक पद्धति नष्ट की जा रही है तथा पश्चिम यूरोपके देशोंमे यत्नतत्पन उद्योग-व्यवसायका समाजीकरण अथवा नियन्त्रण हो रहा है, किन्तु समग्र यूरोपको इकाई मानकर जनताकी दृष्टिसे एक नवीन व्यवस्था स्थापित करनेका विचार दृष्टिगोचर नहीं होता। इसमे हेतु यह है कि युद्ध राष्ट्रीयताके भावको प्रबल कर देता है तथा परस्परका द्वेष और वैमनस्य मुख्य समस्याओंपरसे ध्यान हटा लेता है। लोग अपने क्षुद्र अधिकारोंको

अक्षुण्ण रखना चाहते हैं और अपने जीवनको अपने इच्छानुसार चलानेमें ही स्वतन्त्रताका अनुभव करते हैं। किन्तु आजकी आवश्यकताका तकाजा है कि हम अपनी क्षुद्र गण्डीसे ऊपर उठे तथा सामुदायिक जीवनमें ही अपनी परिपूर्णता देखे। इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्र अपनी विणेषता नष्ट कर दे, किंतु इनका यह अर्थ है कि हम राष्ट्रकी मर्यादाको समझे। अन्यथा आजके युगमें विकृत राष्ट्रीयता आराजकताका स्वरूप धारण कर लेगी। यूरोपमें जो अनर्थ हो रहा है उसका कारण यही है। एक और बात है जिसकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। यूरोपके साम्राज्यवादी राष्ट्र आज भीष्ठासाम्राज्यके स्वप्न देख रहे हैं। वे अपने-अपने साम्राज्य छोड़ना नहीं चाहते। इंग्लैण्डका प्रमुख पत्र 'इकानोमिस्ट' लिखता है—“ब्रिटेन, फ्रांस और हालैण्डकी सम्पत्ति तथा महत्ताके लिए सुदूर पूर्वकी इनकी आवश्यकता है . . .।

“इस बातको स्पष्ट कर देना चाहिये कि ये शक्तियाँ अपने-अपने साम्राज्यका परित्याग करनेका इरादा नहीं रखती। इसके प्रतिकूल वे यह घोषित करना चाहती हैं कि मलाया ईस्ट इण्डिया और फ्रेंच इण्डोचाइनाको फिरसे जीतना और अपने साम्राज्यमें सम्मिलित करना उनका मुख्य ध्येय है।

“इस सम्बन्धमें मित्रराष्ट्र अमेरिकाके मनमें कोई सन्देह रहने देना अनुचित होगा, क्योंकि इससे उसको आगे चलकर विश्वासघातका दोषारोप करनेका अवसर मिलेगा।”
—१६ सितम्बर, १९४४।

इस मनोवृत्तिको देखते हुए ससारका भविष्य सुन्दर और सुखद नहीं मालूम होता। यूरोपका युद्ध समाप्त हो गया है किन्तु क्रान्तिकी अवस्था अभी समाप्त नहीं हुई है। यदि जनताको अपनी शक्तियोंको उन्मुक्त करनेका अवसर मिला तो कुछ आशा की जा सकती है। इंग्लैण्डमें मजदूर दलकी जीत एक शुभ लक्षण है। इससे यूरोपकी प्रगतिशील शक्तियोंको प्रेरणा मिलेगी।

किन्तु किसी ऐसे विराट् आन्दोलनके चिह्न दिखायी नहीं पड़ते जिसका विशाल लक्ष्य हो और जो वर्तमान युगकी आवश्यकताओंको पूरा करता हो।^१

एशियाके स्वतन्त्रता-आन्दोलनकी एक रूप-रेखा

एशियाके प्राचीन देशोंके स्वतन्त्रता-आन्दोलनका इतिहास तीन-चार घटनाओंसे सम्बद्ध है। पहली घटना रूस-जापानका १९०४ का युद्ध है। इस युद्धमें जापानकी विजय हुई। यह विजय एशियाकी यूरोप विजय मानी गयी। इसके पूर्व एशियाकी जातियोंमें यह दृढ़ विश्वास जम गया कि यूरोपकी शक्तियोंके आगे एशियाको सिर झुकाना ही पड़ेगा और एशिया यूरोपका मुकाविला कर नहीं सकता। इस धारणाके कई कारण थे।

१. 'रानी' अगस्त सन् १९४५ ई०।

कई बार एशियाके राष्ट्रोंने अपनी रक्षा करनेके लिए प्रयत्न किये, पर वे कई बार विताड़ित हुए । उनकी फौजी शक्ति यूरोपके राष्ट्रकी फौजी शक्तिके सामने बेकार साबित हुई । उन्होंने यह समझ लिया कि यूरोपका मुकाबिला करनेकी शक्ति उनमें नहीं है । चीन जैसे विशाल साम्राज्यको भी यह कटु अनुभव प्राप्त हुआ । एक समय था जब कि चीनके सम्राट् अपने पड़ोसी राज्योंके अधिपति थे और उनसे खिराज वसूल किया करते थे । वह समझते थे कि उनका प्रतिद्वन्द्वी जगत्में कोई नहीं है । जिस संसारसे वे परिचित थे, उस संसारपर वे प्रभुत्व करते थे और चीनियोंकी यह धारणा थी कि उनके समान सभ्य जाति संसारमें नहीं है । कमसे-कम यूरोपके लोगोको तो वर्वर ही मानते थे । १८ वीं शताब्दीमें जब इंग्लैण्डके वादशाहने व्यापारकी सुविधाएँ प्राप्त करनेके लिए चीनके सम्राट्-के पास एक मिशन भेजा तब सम्राट्ने जो उत्तर दिया वह विचारणीय है । उन्होंने कहा कि इंग्लैण्डमें कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसकी चीनियोंकी आवश्यकता हो, इसलिए हमको किसी विदेशी मालकी आवश्यकता ही नहीं है । हाँ, कोई जाति सभ्य नहीं कहला सकती, यदि वह रेशम, चाय और चीनी-वर्तनका व्यापार नहीं करती । यदि इंग्लैण्डको इन वस्तुओंकी आवश्यकता है तो हम थोड़े परिमाणमें इन वस्तुओंको दे सकते हैं, किन्तु हमको यूरोपके किसी मालकी जरूरत नहीं है ।

एशियाके अधःपतनका युग

यह युग एशियाके अधःपतनका युग था । हर जगह निश्चेष्टता और अकर्मण्यताका राज्य था । लोगोमें किसी प्रकारकी नवीन चेतना एवं प्रेरणा न थी । एशियाके लोग यूरोपकी उदीयमान नयी शक्तियोंकी तनिक भी जानकारी नहीं रखते थे और उनको उपेक्षाकी दृष्टिसे ही देखते थे । इसके प्रतिकूल यूरोपमें एक नवीन जागृति हो रही थी । विज्ञानके युगका आरम्भ हो गया था । जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें नये विचार प्रवेश पा रहे थे । लोगोमें एक नया उत्साह था । हर दिशामें खोज और अन्वेषण हो रहे थे । जीवनकी धारा प्रस्फुटित हो समाजको पुष्ट कर रही थी । भौगोलिक खोजकी उत्कट अभिलाषाने नयी दुनियाको खोज निकाला था । इसके फलस्वरूप नये-नये विज्ञानोंकी प्रतिष्ठा हुई और व्यापारकी समृद्धि हुई । यूरोपके लोग विश्व-विजयके लिए निकल पड़े । धीरे-धीरे आर्थिक क्षेत्रमें क्रान्ति हुई और यन्त्रयुगका सूत्रपात हुआ । पूँजीवादी सत्ताकी स्थापनासे यूरोपके राष्ट्रोंकी फौजी शक्ति बहुत बढ़ गयी और वे दुर्बल राष्ट्रोंको ग्रसने और सत्ताने लगे । चीनका बन्दर बँटवारा हो गया । एशियाके दुर्बल राष्ट्र जो इन नयी शक्तियोंसे अपरिचित थे और जो तमाविष्ट हो अहम्मान्यताके नशेमें चूर थे, अपने घरको न सँभाल सके । एक-एक करके यूरोपके राष्ट्रोंने एशियाके देशोंको अपने अधीन किया, या कम-से-कम उनके आर्थिक जीवनपर प्रभुत्व स्थापित किया । यूरोपीय साम्राज्यवादका एशियामें बोलबाला हो गया । यूरोपकी संस्कृतिका प्रभाव भी बढ़ने लगा । एशियाके लोगोंने धीरे-धीरे अपनी तुच्छताकी स्वीकार किया और उनकी यह धारणा हो गयी कि हम यूरोपका मुकाबिला नहीं कर सकते । जब किसी जातिकी ऐसी मनोवृत्ति हो जाय तो उसका उद्धार किस प्रकार हो !

जापानने सबक सीखा

जापान ही एक ऐसा देश था जो साम्राज्यवादके चंगुलसे बच सका । उसने यूरोपीय संस्थाओंको अपनाया, यूरोपीय ढंगकी सेना सुसज्जित की और उद्योग-व्यवसायकी उन्नति कर अपनेको सुदृढ़ बनाया । स्वभावतः सारे एशियामे वह आदरका पात्र बन गया, लोग समझने लगे कि बिना यूरोपीय संस्थाओंको अपनाये परिवर्तन पाना सम्भव नहीं है । चीनने भी जापानसे सबक सीखा और यूरोपीय ढंगपर अपनी सेना और शासन-प्रणालीको बदलनेका प्रयत्न किया । जापान और अमेरिकामे शिक्षा प्राप्त करनेके लिए विद्यार्थी भेजे गये और चीनी क्रान्तिकारियोंने जापानमे अपना अड्डा बनाया, किन्तु इतना होनेपर भी यह विश्वास नहीं था कि एशियाके लोग यूरोपके मुकाबलेमे खड़े हो सकेंगे ।

किन्तु रूस-जापानके युद्धने यह दिखा दिया कि एशियाके राष्ट्र भी तैयार होनेपर यूरोपके राष्ट्रोंका मुकाबिला कर सकते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि ऐसी कोई नैसर्गिक त्रुटियाँ एशियाके लोगोंमे नहीं हैं, जिसके कारण वह सदा असफल रहे । खोया हुआ आत्म-विश्वास फिर लौट आया, आत्म-ग्लानि दूर हुई और जातीय जागरणका युग आरम्भ हुआ । इसी समयसे एशियाके जीवनका एक नया पृष्ठ आरम्भ होता है । रूस-जापान युद्धने विजलीका-सा असर किया । हर जगह जागृतिके चिह्न दीख पड़ने लगे और राष्ट्रीय उत्थानके लिए प्रयत्न गुरु हो गये । चीनकी मचू-गवर्नमेण्टने शासनमे सुधार करने आरम्भ कर दिये और आगे चलकर विधान बनानेके लिए एक कमीशन भी नियुक्त किया गया था । इसी समय भारतमे स्वदेशी और बहिष्कारका आन्दोलन आरम्भ हुआ तथा कांग्रेसमे एक नये दलका जन्म हुआ, जिसने पूर्ण स्वतन्त्रताको अपना उद्देश्य घोषित किया । पुराने नेताओंका विश्वास था कि अंग्रेज भारतके कल्याणके लिए शासन करते हैं और जब हिन्दुस्तानी इस बातको प्रमाणित कर देंगे कि उनमे शासन करनेकी योग्यता प्रतिपादित हो गयी है तब अंग्रेज स्वेच्छासे शासन उनके सुपुर्द कर विलायत लौट जायेंगे । आज हमको यह सुनकर हँसी आती है और आश्चर्य होता है कि इतने बड़े नेता जिनकी विद्वत्ता और नीतिज्ञतामे कोई कमी न थी, कैसे इस तरहके बालोचित विश्वासको अपना सकते थे । वे तो राजनीतिका कख ग भी न जानते थे । कोई भी दूसरे देशपर उसके लाभके लिए राज्य नहीं करता ।

भारतीय राजनीतिकी सबसे बड़ी तात्कालिक आवश्यकता इस बातको समूल नष्ट करना था । यह काम नये दलने किया । उसने 'भिक्षा देहि' की पुरानी नीतिकी धज्जियाँ उड़ा दी । उसने आत्म-निर्भरताका पाठ पढ़ाया । लोकमान्य तिलकने बताया कि जो अपने पैरोपर अपने-आप नहीं खड़ा होता ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता । अंग्रेज व्यापारके लिए भारत आये हैं, इसलिए स्वदेशी और बहिष्कारके अस्त्रका प्रयोग कर उनके मर्मस्थलपर आघात पहुँचाना चाहिये । असहयोगकी भी चर्चा हुई है और पूर्वी वगलमे इसका प्रयोग भी छोटे पैमानेपर हुआ । औपनिवेशिक स्वराज्यके स्थानमे पूर्ण स्वतन्त्रताके ध्येयका प्रचार किया गया ।

सन् १९०६ ई० मे ईरानमे भी हलचल हुई । ईरान रूसकी सन् १९०५ की क्रान्तिसे भी प्रभावित हुआ । सन् १९०८ मे युवक तुर्क-पार्टीका संघटन हुआ ।

प्रथम यूरोपीय युद्ध

दूसरी घटना जिसका समस्त एशियापर प्रभाव पड़ा सन् १९१४ का यूरोपीय महायुद्ध था । इस युद्धके समाप्त होते ही क्रान्तिकी लहर सर्वत्र दौड़ गयी । इस वार कई नये देश भी क्रान्तिके प्रभावमे प्रथम वार आये ।

युद्ध क्रान्तियोंकी धात्री समझी जाती है । सन् १९१४ के युद्धमे एशियाकी कई कीमोने भाग लिया था । यूरोपके राष्ट्र एशियायी फौजक्रा उपयोग गोरी जातियोंके विरुद्ध नहीं करते थे, किन्तु सन् १९१४ मे स्थितिसे विवश होकर उनको ऐसा भी करना पड़ा । एशियाके लोग यूरोपियनोंके प्रत्यक्ष सम्पर्कमे आये और जो कुछ उन्होंने देखा उससे यह निष्कर्ष निकाला कि पश्चिमकी सभ्यता एशियाकी सभ्यतासे उत्कृष्ट नहीं है । राष्ट्रीय भावनाके प्रवल होनेसे और प्राचीन इतिहासकी अभिज्ञता प्राप्त करनेसे उसमे अपने अतीतके गौरवपर गर्व उत्पन्न हो गया था और उनका अत्यावसाद लुप्त हो गया था ।

रूसकी क्रान्तिका भी बड़ा प्रभाव पड़ा । सन् १९१६ मे महात्माजीने सत्याग्रहका प्रयोग किया और बादमे खिलाफतका आन्दोलन शुरू हुआ । इसी वर्ष मिस्र और चीनमे विराट राष्ट्रीय आन्दोलनोंका जन्म हुआ । मिस्रका आन्दोलन सन् १९२२ मे समाप्त हुआ और मिस्रको स्वतन्त्रता मिली, तथापि यह स्वतन्त्रता असली न थी । मिस्र-इंगलैण्डकी एक सन्धि हो गयी, इसकी शर्तोंके अनुसार अग्रेज स्वेज नहरकी रक्षाके लिए एक फौजी दस्ता रखते हैं, सूडानपर उनका आधिपत्य है और युद्धके अवसरपर मिस्र इंगलैण्डको खाद्य-पदार्थ और अन्य सामग्री तथा मिस्रमे प्रवेश देनेके लिए बाध्य है । अन्तर्राष्ट्रीय मामलोमे मिस्रकी स्वाधीनता नाममात्रकी ही रही है । मिस्रके आन्तरिक मामलोमे भी इंगलैण्ड समय-समय पर हस्तक्षेप करता रहा है । कभी यह हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूपसे होता है ; कभी बादशाह फारूकके द्वारा लोकमत व्यर्थ कर दिया जाता है । इसी युद्धके दौरानमे ब्रिटिश टैकोकी मददसे बादशाह नहसपाशाको प्रधान मन्त्री बनानेके लिए विवश किये गये और जब काम निकल गया और यह देखा गया कि नहसपाशा स्वतन्त्र रीतिसे काम करते हैं तब बादशाहको यह स्वतन्त्रता दी गयी कि वे प्रधान मन्त्री बदल दें । सानफ्रांसिस्को कान्फरेसमे मिस्रके प्रतिनिधियोंका वोट ब्रिटिश सरकारके अधीन था । अभी हालमे मिस्रने अग्रेजी हुकूमतसे एक समझौता किया है, जिसके अनुसार मिस्र 'स्टर्लिङ्ग क्षेत्र' (Sterling Bloc) के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है । इसका फल यह होगा कि कतिपय ब्रिटिशबाजारोमे अमेरिकी डाहलरका बहुतायतसे प्रवेश न हो सकेगा ।

सन् १९१९ मे चीनमे जिस आन्दोलनका आरम्भ हुआ, उसकी परिसमाप्ति सन् १९२६-२७ की क्रान्तिके रूपमे हुई । सन् १९२७ मे दक्षिणसे लेकर उत्तरतकका प्रदेश क्रान्तिकारियोंके हाथमे आ गया और यदि कुओमिन्ताङ्गमे फूट न पड़ी होती तथा कम्युनिस्टों-से झगड़ा न शुरू हुआ होता तो चीन अबतक बहुत-कुछ स्वतन्त्र हो गया होता । बादके कई साल चीनके गृह-कलहमे ही बरबाद हुए और पीछेसे तो जापानका आक्रमण भी शुरू

हो गया। भारतमें खिलाफतका जो आन्दोलन हुआ, उसने मुस्लिम राष्ट्रोंको अत्यन्त प्रभावित किया।

आर्थिक मन्दीका असर

तीसरी घटना विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी (Economic Depression) की है। यह सन् १९२९ में अमेरिकासे शुरू हुई और बहुत जल्द ससार भरमें फैल गयी। उपनिवेशों तथा पराधीन देशोंमें इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि साम्राज्योंने अपने सकटको इनपर टालनेका प्रयत्न किया। इससे जनता क्षुब्ध हुई और क्रान्तिकी लहर कई जगहोंमें फिर उठी। सन् १९३० में भारतमें नमक-त्यागहका जो आन्दोलन हुआ वह भी इसीका फल था। इस समय मिस्र तथा अरबके कुछ देशोंमें भी थोड़ा-बहुत आन्दोलन हुआ। फिलिस्तीनमें तो अरबोंने दण्डीयात्राका अनुकरण किया। आन्दोलनका ध्येय ब्रिटिश मालका बहिष्कार भी था। सन् १९३० में चीनमें भी कुछ प्रयास हुआ था, पर परिस्थिति किसी विराट् आन्दोलनके अनुकूल न थी। सच तो यह है कि इन घटनाओंसे प्रत्येक देश उतना ही लाभ उठा सकता है, जितना कि उसकी निजी तैयारी उसको उठाने देती है।

संसारव्यापी वर्तमान युद्ध

चौथी बड़ी घटना संसारव्यापी युद्ध है जो अभी समाप्त हुआ है।

युद्धकी समाप्तिपर ही प्रायः क्रान्तियाँ होती हैं। छोटे-छोटे देशोंके लिए तो और भी कठिनाई होती है। भारतमें कांग्रेस सन् १९२७ से ही युद्धके खतरेकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती आयी है। त्रिपुरी कांग्रेसमें देशको तैयार करनेका भी प्रस्ताव पास हुआ, यद्यपि इस दिशामें कुछ किया नहीं गया।

सन् ४२ का आन्दोलन

सन् ४२ में जो स्थिति थी उसमें सत्याग्रह-संग्रामके लिए उपयुक्त वातावरण था। सन् १९४२ का आन्दोलन सब पिछले आन्दोलनोंसे बढ चढकर हुआ। यदि यह आन्दोलन न होता तो भारतका राजनीतिक जीवन विलकुल शिथिल पड़ जाता और हम राजनीतिक दौड़में पीछे पड़ जाते। इस आन्दोलनके द्वारा भारतवर्ष एशियाकी स्वतन्त्रताका प्रतीक बन गया और भारतका प्रश्न संसारके मानचित्रपर आ गया। इस आन्दोलनसे हमारी राजनीतिक चेतना प्रबल रूपसे जमी, किन्तु यदि हम सावधानीसे काम न लेंगे, तो जो कुछ हमने कमाया है, उसे भी खो देंगे।

अंग्रेज राजनीतिज्ञोंकी हरकतें

अंग्रेज राजनीतिज्ञोंकी कोशिश हमको हर तरहसे कमजोर करनेकी है। पाकिस्तान और देशी राज्योंको अक्षुण्ण करनेका प्रयत्न इसके प्रमाण है। वह एक ऐसा विधान चाहते हैं, जिसमें स्थिर और न्यस्त स्वार्थोंका बोलबाला हो और जिसमें उन्नतिशील शक्तियोंको बहुत कम अवसर मिले। जो अवस्था मिस्रकी १९२२ में थी, वही अवस्था यह हमारी भी करना चाहते हैं। वह नाममात्रको हमें स्वाधीनता देना चाहते हैं। इस उद्देश्यकी पूर्ति के लिए तरह-तरहकी चालें चली जा रही हैं। हमको यह न भूलना चाहिये कि मिस्रमें

जो पहला चुनाव हुआ था, उसमें कई प्रकारकी स्कावटे डाली गयी थी, जैसे कि हमारे यहाँ आज डाली जा रही है। मिस्रमें वादशाहसे दवाव डलवाकर और अनेक रूपमें अपना दवाव डालकर अग्रेजोंने कई वाद वफद पार्टी (Wafd Party) को पदच्युत् किया और उसके स्थानमें ऐसे राजनीतिज्ञोंको शासनारूढ किया जो वफद पार्टीके लोगोकी अपेक्षा अधिक काबूमें थे। वहाँ जो गवर्नमेण्ट आज शासन करती है वह किसी एक पार्टीकी गवर्नमेण्ट नहीं है, किन्तु कई छोटे-छोटे समूहोंकी सम्मिलित गवर्नमेण्ट है और ये लोग सदा अग्रेजोंकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेको तैयार रहते हैं। भारतमें भी कुछ ऐसी ही कोशिश हो रही है, पर यह चेष्टा सफल नहीं होगी, क्योंकि सन् १९४२ के आन्दोलनने लोगोको सजग कर दिया है और कांग्रेस अत्यन्त लोकप्रिय हो गयी है। इस आन्दोलनके कारण मुसलमानोंमें भी कांग्रेसका प्रभाव कुछ बढ़ा है। आनेवाला चुनाव इसकी सत्यताको सिद्ध करेगा।

वैज्ञानिक क्षेत्रमें भय

जो जमात आजादीके लिए त्याग करती है उसका आनंदर सभी करते हैं, किन्तु हमको भय वैधानिक क्षेत्रमें है। एक गलत कदम उठानेसे वही सिलसिला शुरू हो जायगा जो मिस्रमें सन् १९२२ के बादमें शुरू हुआ था। राष्ट्रीय पचायत (Constituent Assembly) के सम्बन्धमें सतर्कताकी जरूरत है। कांग्रेसको किसी ऐसी विधान-परिपद्में भाग न लेना चाहिये जिसका निर्माण सच्चे आधारपर नहीं किया गया है और जिसको सर्वाधिकार प्राप्त नहीं है। बालिग मताधिकारके आधारपर चुनी हुई परिपद्में ही हमको जाना चाहिये जब उस परिपद्को अपने भविष्यके निर्माणका पूरा अधिकार प्राप्त हो।

एशियामें उथल-पुथल

युद्धके समाप्त होते ही दक्षिण-पूर्वी एशियाके देशोंमें उथल-पुथल आरम्भ हो गयी है। ऐसा होना स्वाभाविक था। हालैण्ड और फ्रांस अपने साम्राज्यको छोड़ना नहीं चाहते, किन्तु जनता अपनी गुलामीको सहन नहीं करती और वह साम्राज्यसे मोरचा ले रही है। यूरोपका वह पुराना रोव खत्म हो चुका है और लोगोका राजनीतिक चैतन्य बढ़ गया है। संसारमें अभी शान्ति स्थापित होनेकी सम्भावना नहीं दिखायी देती। जबतक युद्धके कारण दूर नहीं किये जाते, तबतक शान्तिकी स्थापना असम्भव है। मित्रराष्ट्र शत्रुओंका विनाश करनेके लिए अस्त्र-शस्त्रका निर्माण कर सकनेकी सामर्थ्य रखते थे, किन्तु शान्तिकी प्रतिष्ठा करनेकी योग्यता उनमें नहीं पायी जाती। कूटनीतिज्ञतासे शान्ति कायम नहीं होगी। युद्धका अन्त तभी होगा जब साम्राज्य और पूँजीवादका अन्त कर सच्चे लोकतन्त्रकी स्थापना होगी। किन्तु अभी जनताको और कष्ट सहने हैं। हर जगह अशान्ति है। जनताकी दबी हुई शक्तियोंको जैसे ही उभरनेका अवसर मिला, वैसे ही जगह-जगह विद्रोह होंगे। कुछ विद्रोह सफल होंगे, कुछ कठोरताके साथ दबा दिये जायेंगे और कुछके साथ समझौता होगा।

भारत यदि क्रान्तिके मार्गसे च्युत न हुआ तो उसके लिए कई अवसर निकट भविष्यमें ही आयेंगे । इस समय हममें दृढ़ताकी आवश्यकता है और इस बातकी आवश्यकता है कि ८ अगस्त सन् ४२ के प्रस्तावको सदा हम ध्यानमें रखें ।^१

पेरिसका शान्ति-सम्मेलन

सन् १९१८ के पेरिस-सम्मेलन और सन् १९४६ के पेरिस-सम्मेलनमें एक बहुत बड़ा अन्तर है । शान्तिकी कुंजी जर्मनी है । जर्मनीके प्रश्नके निपटारेपर यूरोपका भाग्य निर्भर करता है । सन् १९१८ के सम्मेलनने सबसे पहले जर्मनीके प्रश्नका निपटारा किया । इस प्रश्नके सम्बन्धमें मित्रराष्ट्रोंमें मौलिक मतभेद न था । सभी जर्मनीकी रण-शक्तिको फिरसे जिन्दा होने देना नहीं चाहते थे । मित्रराष्ट्रोंके साम्राज्यवादको जर्मनीकी रणशक्तिसे खतरा था और वे इस खतरेको मद्देकालिए खत्म करनेमें एकमत थे । इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस प्रश्नका फैसला किया । इस निश्चयसे सम्मेलनका काम मुगम हो गया और मित्रराष्ट्रोंको जर्मनीके सहयोगी राष्ट्रोंपर सन्धि लादनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई । पर इस बार विजयी राष्ट्र जर्मनीके प्रश्नपर एकमत नहीं है और चूँकि वह इस प्रश्नपर आपसमें समझौता नहीं कर पाते, इसलिए बार-बार कान्फरेन्सके कामको रोक देना पड़ता है । किन्तु यदि मित्रराष्ट्र बिना कुछ किये ही उठ जायें तो भी अच्छा न होगा । मित्रराष्ट्र अपने मतभेदको दूर नहीं कर पाते, तथापि वे यह समझते हैं कि सम्मेलनके विफल होनेका बड़ा बुरा परिणाम होगा । यूरोपके निवासी शान्ति चाहते हैं और यदि सम्मेलनका अधिवेशन अनिश्चित तिथिके लिए टाल दिया तो लोग अधीर हो जायेंगे और मित्रराष्ट्रोंका प्रभाव क्षीण हो जायगा । इस अनिष्टसे अपनेको बचानेके लिए, गौण प्रश्न वैदेशिक सचिवोंकी कौंसिलके सिपुर्द कर दिये गये हैं । सन्धियोंके मसविदे तैयार करनेका काम इस कौंसिलके सुपुर्द था । अब उसे अन्य प्रश्नोंको भी अपने हाथमें लेना पड़ा है । इसके अलावा सम्मेलनके कार्यक्रममें तत्काल इटलीके उपनिवेशोंके बँटवारेका प्रश्न सम्मिलित नहीं है । इसे इसलिए छोड़ दिया गया है कि इसपर बहुत झगड़ा है । वैदेशिक सचिवोंकी कौंसिलने इस प्रश्नका निर्णय करनेका प्रयत्न किया था । कौंसिल चाहती थी कि कुछ राष्ट्रोंको इन उपनिवेशोंका ट्रस्टी बना दिया जाय । किन्तु जब रूसने सिर्रेनेका (Cyrenaica) के लिए अपना दावा पेश किया तब मिस्टर वेविन इतने भयभीत हो गये कि उन्होंने कार्यक्रमसे इस प्रश्नको ही हटा दिया । वे अफ्रीकामें सोवियत रूसका प्रवेश सहन नहीं कर सकते ।

इस सबका परिणाम यह है कि मुख्य प्रश्नका विचार आगेके लिए टाल दिया गया है । उसके लिए एक दूसरा सम्मेलन बुलाना पड़ेगा । वर्तमान सम्मेलन गौण प्रश्नों और

सन्धियोंके मसविदोंपर विचार करेगा । जहाँ सन् १९१८ के सम्मेलनने सबसे पहले मुख्य प्रश्नका निर्णय किया था वहाँ वर्तमान सम्मेलन गौण प्रश्नको पहले ले रहा है ।

वैदेशिक सचिवोको मसविदोके तैयार करनेमे ११ महीने लगे थे, इससे स्पष्ट है कि इनका काम कितना कठिन रहा होगा । अब यदि इनके आपसके समझौते सम्मेलनमे नहीं माने जाते तो फिर जिच्च उत्पन्न हो जायगी । यूरोपकी अस्त-व्यस्तताको दूर करनेमे जो विलम्ब हो रहा है, उससे यूरोपके लोग अधीर हो रहे हैं । यह लोकमतका ही प्रभाव था कि वैदेशिक सचिव किसी-न-किसी तरह मसविदेपर राजी हो सके थे । इटली, हंगरी, रूमानिया, बुल्गारिया और फिनलैण्डके साथ जो सन्धियाँ होंगी उनके मसविदोपर सम्मेलन विचार करेगा । अन्य प्रश्नोपर विचार करनेके लिए दूसरे सम्मेलन बुलाये जायेंगे ।

सम्मेलनको वैदेशिक सचिवोकी कौंसिलको फिरसे ये मसविदे सिपुर्द कर देने पडे थे ; और इस समय न्यूयार्कमे कौंसिलकी बैठक हो रही है । कौंसिलके सामने मसविदोके अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी हैं । मुख्य इनमे पाँच हैं—(१) ट्रीस्टके स्वतन्त्र प्रदेशके लिए विधान बनानेका प्रश्न, (२) डैन्यूब नदीमे यातायातकी सबको स्वतन्त्रता देनेका प्रश्न, (३) बालकनमे स्वच्छन्द व्यापारका प्रश्न, (४) हरजानेका प्रश्न और (५) ग्रीसकी सीमाओको निर्धारित करनेका प्रश्न । न्यूयार्कसे जो समाचार आ रहे हैं उनसे पता चलता है कि इनमेसे एक प्रश्नका भी निर्णय नहीं हो रहा है और किसीको नहीं मालूम कि इन प्रश्नोका समझौता कैसे हो सकेगा । आपसका मतभेद बढ़ता ही जाता है । सम्मेलनमे ही दो दल बन गये हैं । एकमे इंग्लैण्ड, अमेरिका और इनके साथी हैं । दूसरेमे रूस और उसके साथी हैं । पेरिस सम्मेलनने यह दिखा दिया है कि इन दलोकी नीतिमे मौलिक अन्तर है । सम्मेलनके बडे राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोको अपना मत स्पष्ट रूपसे प्रकट करनेके लिए बाध्य कर, सुलह और समझौतेके कामको और भी दुष्कर कर दिया गया है, क्योंकि एक बार अपना निश्चित मत प्रकाश्य रूपसे दे चुकनेके पश्चात् उसमे हेर-फेर करना कठिन हो जाता है । ये दोनो दल एक दूसरेसे दूर होते जा रहे हैं । सन्धियोंके मसविदोपर इन दलोका विचार हो रहा है, किन्तु यहाँ भी गाड़ी रुक गयी है । इटलीकी सरकारने मसविदेके सम्बन्धमे एक नोट तैयार किया है, जो १५ नवम्बरको कौंसिलको दिया जायगा ।

कौंसिलने जब ये मसविदे पहली बार तैयार किये थे तब चारो वैदेशिक सचिवोने एक प्रकारसे उनको सम्मेलनमे पास करानेका इकरार किया था और इस विचारसे उन्होंने दो-तिहाई वोटके सिद्धान्तको स्वीकार किया था । यदि ऐसा निश्चय न होता और केवल बहुमतका सिद्धान्त लागू किया जाता और छोटे राज्य हिस्सा लेना चाहते तो ये मसविदे सम्मेलनमे पास नहीं हो सकते थे, क्योंकि सम्मेलनमे सोवियत रूसका अल्पमत है । जब ये मसविदे विचारके लिए सम्मेलनके सामने आये तब मिस्टर वेविन उपस्थित नहीं थे । उनकी अनुपस्थितिमे आस्ट्रेलियाके प्रतिनिधि डा० ईवाट (Evatt) ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि जिन सशोधनोको बहुमत प्राप्त हो उनका वही मूल्य ठहराया जाय जो उन संशोधनोका हो जिनको दो-तिहाई वोट मिले । इस बातको सोवियत प्रतिनिधि कैसे मान सकते थे, क्योंकि उनकी ओरसे कौंसिलमें समझौते हो चुके थे । वह दो-तिहाई

वोटके सिद्धान्तपर अड़ गये । ऐसा मालूम पड़ा मानो दोनों समूहोंमें सघर्ष हो जायगा । ऐसी अवस्थामें ब्रिटिश प्रतिनिधियोंने यह समझीता पेश किया कि जो संगोपन बहुमतसे पास हो, वे भी कार्यक्रममें स्थान पाये और जिनको दो-तिहाई वोट मिलें उनपर भी गम्भीरतासे विचार किया जाय । इस विचारसे आपसका मनमुटाव और सन्देह और भी बढ़ गया । रूसियोंका विचार है कि अंग्रेज और अमेरिकन प्रतिनिधियोंकी रजामन्दीके बिना डा० ईवाट ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते थे ।

यह वाद-विवाद व्यर्थहीका था, क्योंकि अन्तमें चार बड़े राष्ट्रोंपर ही सब निर्भर करता है । छोटे राज्य यदि यह समझे कि उनके वोटसे जो निश्चय होंगे वे सम्मेलनके निश्चय मानें जायँगे तो यह उनकी भूल होगी । उनके अधिकार सीमित हैं और यही तथ्य है कि जो चार बड़े राष्ट्र करेगे वही होगा । इनमें समझौता होना चाहिये और यही नहीं हो रहा है । इस संघर्षमें बहुत समय नष्ट हुआ ।

जब वेबिन साहब वापस आये तब उन्होंने वैदेशिक सचिवोंकी एक मीटिंग की और वे सुलहसे काम करे इसका प्रयत्न किया । किन्तु कौंसिलमें फिर झगड़ा हो गया है और काम आगे नहीं बढ़ रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय दलबन्दी

हमने ऊपर इसका उल्लेख किया है कि सम्मेलनमें दो दल हैं । ये पूर्वी और पश्चिमी ब्लाकके नामसे पुकारे जाते हैं । परस्परके सम्बन्ध और सन्देहके अनेक कारण हैं । यह कहना कि महायुद्ध समाप्त हो गया है, ठीक न होगा । नाजियोंपर जबतक विजय नहीं प्राप्त हुई थी तबतक किसी प्रकार मित्रराष्ट्र मिल-जुलकर काम कर रहे थे । किन्तु नाजियोंकी हारके बादसे ही वे आपसमें झगडने लगे हैं । ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्तराष्ट्रोंके पास सारे संसारमें जहाँ तहाँ हवाई और समुद्री अड्डे हैं । किन्तु रूस अड्डोंके लिए अपना दावा पेश करता है तब ये उसको सन्देहकी दृष्टिसे देखने लगते हैं । अमेरिकाकी नौशक्ति सबसे प्रबल है और इसलिए वह चाहता है कि समुद्रपर सबको स्वतन्त्रता प्राप्त हो । किन्तु उसका कहना है कि डाईनेल्समें रूसको स्वतन्त्रता न दी जानी चाहिये, नहीं तो वह भूमध्य-सागरमें चला आयेगा । रूसकी आर्थिक पद्धति सामुदायिक (Collectivist) है, किन्तु हंगरीमें वह राजनीतिक शक्तिका उपयोग अपनी आर्थिक स्थितिको प्रबल बनानेमें करता है ।

ग्रेट ब्रिटेन अपने लिए तो इटलीके एक-दो उपनिवेश चाहता है, पर सोवियत रूसको इन उपनिवेशोंमें हिस्सा नहीं देना चाहता है । पेरिसके सम्मेलनमें वही हो रहा है जो जर्मनीमें हो रहा है । जर्मनीकी एकता माननेके लिए फ्रांसको छोड़कर तीन बड़े राष्ट्र तैयार हैं और वे यह भी मानते हैं कि जर्मनीके उद्धारके लिए उसकी आर्थिक एकता जरूरी है । किन्तु रूर (Ruhr) के सम्बन्धमें मोलोटोवका कहना है कि व्यवसायके इस क्षेत्रका नियन्त्रण चारों शक्तियाँ मिलकर करें । उनका विचार है कि पश्चिमके राष्ट्र जर्मनीके युद्धके साधनोंका विनाश नहीं चाहते और वे अकेले पश्चिमी ब्लाककी अधीनतामें रूरका निर्माण करना चाहते हैं, जिससे भावी युद्धमें वे उसका उपयोग सोवियतके विरुद्ध कर सकें ।

इसलिए मोलोटोवका अनुरोध है कि रूरके प्रबन्धमे रूसका भी हाथ हो और इसी कारण वे रूरकी व्यावसायिक शक्तिको किसी दूसरे आधारपर बढने देना नहीं चाहते । मोलोटोव जर्मनीकी एकताके पक्षमे हैं और जर्मनीसे रूरको अलग करनेकी जितनी योजनाएँ हैं उन सबका वह विरोध करते हैं । उनका यह ख्याल है कि विभाजनका फल यह होगा कि रूर अकेले पश्चिमके नियन्त्रण मे आ जायगा । इसके विपरीत फ्रांस रूरको जर्मनीसे अलग करना चाहता है । मोलोटोवकी नीतिसे फ्रांसके कम्युनिस्टोको काफी परेशानी होती है । जब रूरने अमेरिकाके प्रस्तावको नहीं माना तो अमेरिका और इंग्लैण्डने अपने क्षेत्रोको एक कर लिया । वे आशा करते हैं कि इसमे आगे चलकर रूसी क्षेत्रभी शामिल हो जायगा ।

हरजानेके प्रश्नपर संघर्ष है । मोलोटोवका कहना है कि क्रीमिया सम्मेलनके निश्चयके अनुसार रूसको हरजानेके लिए केवल जर्मन सामान ही नहीं दिया जायगा, किन्तु वह वर्तमान व्यावसायिक उत्पत्तिसे भी अपना हरजाना पूरा करेगा । मोलोटोवका यह भी कहना है कि अमेरिकाने यह मान लिया था कि सोवियत रूसको १० हजार मिलियन डालर हरजानेके मिलेगे । अवतक यह विचार था कि पौट्सडैमके समझौतेके बाद क्रीमियाके निश्चय रद्द हो गये हैं । पौट्सडैमका निश्चय..... जर्मनीके उत्पादनके साधनोको धीरे-धीरे इतना घटा देता है कि जर्मन लोग केवल साधारण यूरोपीय स्टैंडर्डके अनुसार रह सके । इस निश्चयका यह अर्थ होना चाहिये कि वर्तमान उत्पत्तिसे हरजानेकी रकम नहीं वसूली जायगी । जब कहा जाता है उत्पत्तिको बढाना चाहिये तब मोलोटोव इसकी आवश्यकताको स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इसमे बहुत दिनोतक पर्याप्त वृद्धि नहीं की जा सकती है और यदि वृद्धि आवश्यक है तो यह बात इस शर्तपर स्वीकार की जा सकती है कि नाजियोके प्रभावको कडाईके साथ नष्ट किया जाय और जर्मनीकी युद्ध-शक्ति-को निर्मूल कर दिया जाय ।

जर्मन आज भूखो मर रहे हैं और जब ऐसी अवस्थामे रूसकी ओरसे ब्रिटिश क्षेत्रके और कारखानोकी माँग पेश होती है, तो ग्रेट ब्रिटेन समझता है कि उससे जर्मनोको जिन्दा रखनेका खर्च वर्दाश्त करनेको कहा जाता है ।

मोलोटोवकी शिकायत है कि अग्रेज और अमेरिकन क्षेत्रमे फासिज्म को निर्मूल करनेकी चेष्टा पूरी तरह नहीं हो रही है और न लोकतन्त्रकी आधार-शिला ही ठीक तरह रखी जा रही है । यहाँ हमको स्मरण रखना चाहिये कि लोकतन्त्रसे रूसका अर्थ यह है कि जनताके हितकी दृष्टिसे उचित आर्थिक सुधार किये जायँ । उनके मतमे बिना इसके कोई प्रजातन्त्र शासन सम्भव नहीं है । इसके विपरीत अमेरिकनोका मत है कि पहले राजनीतिक परिवर्तन होने चाहिये और फिर नये शासनको आर्थिक सुधार करनेकी स्वतन्त्रता रहनी चाहिये । किन्तु जब इंग्लैण्डमे मजदूर सरकार है तो आर्थिक परिवर्तन करनेमे एटली साहबको कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

अमेरिकाकी नीति

अब हम अमेरिकाकी नीतिपर विचार करे । इंग्लैण्डका साम्राज्य तो ह्रासकी अवस्थामे है, वह दुर्बल और क्षीण हो रहा है । किन्तु अमेरिकाका 'डालर इम्पीरियलिज्म'

तेजीसे बढ़ रहा है। अमेरिकाका साम्राज्यवाद संसारके लिए एक बड़ा खतरा बनता जाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका कम्युनिज्मका सबसे बड़ा विरोधी रहा है। आज कई पत्र खुलेआम रूसके विरुद्ध ऐटम बमका प्रयोग कर उससे लड़ाई मील लेनेके लिए उत्सुक हैं। वे चाहते हैं कि पूर्व इसके कि रूस ऐटम बमकी खोजमें सफल हो और नये हथियार तैयार कर सके उसके विरुद्ध लड़ाई ठन जानी चाहिये। इंग्लैण्डमें भी कुछ 'टोरी' इस तरहकी बात करते देखे गये हैं। पुनः 'वैटिकन' की ओरसे सोवियत यूनियनके विरुद्ध जेहाद बोल दिया गया है। चीनमें अमेरिका वहाँके कम्युनिस्टोंके विरुद्ध च्यांगकाईशेककी सहायता कर रहा है। अमेरिकाने प्रशान्त महासागरको अपना प्रभावक्षेत्र बना लिया है, जिस प्रकार सोवियत रूसने पूर्वी यूरोपको अपना प्रभावक्षेत्र बना लिया है। रूस निकट पूर्व और सुदूर पूर्वमें अपने प्रभावका विस्तार कर रहा है। इन प्रदेशोंमें अमेरिकाका भी स्वार्थ है। जापानमें अकेले अमेरिकाका अधिकार है और वह पासके द्वीपोंमें अड़े बना रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका और रूसके संघर्षके क्षेत्र बढ़ते जाते हैं। रूसको अमेरिकासे डरनेका पर्याप्त कारण है। अमेरिकाकी कम्युनिस्ट-विरोधी नीतिने उसको और सशंक कर दिया है। अमेरिकाके पास ऐटम बम है। उसकी नौ-शक्ति सबसे बड़ी है और उसके पास उद्योग और व्यवसायके प्रचुर साधन हैं। इसके विपरीत रूसपर बार-बार पश्चिमसे आक्रमण हुए हैं और आज वह देखता है कि हर जगह उसके विरुद्ध फौजी तैयारी हो रही है। आज उसकी आर्थिक अवस्था गिरी हुई है। उसे अभी लड़ाईके जखम भरने हैं। उजड़े हुए स्थानोंको फिरसे आवाद करना है। अमेरिकाकी शक्ति बहुत प्रबल हो गयी है। उसकी दोनों पार्टियाँ पूंजीवादी पार्टियाँ हैं। रूस विस्तारके लिए अवकाश चाहता है और उसके लिए उसको कोई उचित बहाना चाहिये। समझमें नहीं आता कि अमेरिकाको किससे भय है। उसपर आक्रमण करना किसीके लिए भी सम्भव नहीं है। तिसपर भी वहाँके कुछ पत्रकार और राजनीतिज्ञ रूसपर आक्रमण करनेकी बात किया करते हैं। बुलिट साहब (Bullit) तो कहते हैं कि लड़ाई शीघ्र आरम्भ हो जानी चाहिये। वैसेसका पत्र जो हालमें प्रकाशित हुआ है यह सिद्ध करता है कि अमेरिका निश्चित रूपसे रूसके विरोधमें अग्रसर हो रहा है। वैसेस लिखते हैं कि अमेरिका हजारों मीलके फासलेपर हवाई और समुद्री अड़े बना रहा है, जिनका उपयोग केवल रूसके विरुद्ध ही हो सकता है। रूसको पता है कि कुछ फौजी सलाहकार भावी युद्ध रोकनेके लिए युद्धकी सलाह दे रहे हैं। रूसको मिस्टर बिर्न्सके विचार अवगत हैं। वह जानता है कि उनकी नीति रूसियोंसे समझौता करनेकी नहीं है; किन्तु वह इतनी शक्ति संगठित करना चाहते हैं जिससे रूसको दबना पड़े और वह अमेरिकाकी बात माननेके लिए विवश हो जाय। वैसेसने इस नीतिका विरोध किया था। वैसेसका कहना है कि सबको नये आधारपर परस्परके सन्देहोंको दूर करनेका प्रयत्न और समझौता करना चाहिये। किन्तु मिस्टर ट्रूमन (Truman) ने वैसेसको उनके पदसे हटाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह बिर्न्सकी गलत नीतिको जारी रखना चाहते हैं। अमेरिका हर जगह अपने ढंगसे ही अपनी शर्तोंपर सुलह चाहता है और इसमें इंग्लैण्ड उसके साथ है।

बिन्स इसको नहीं छिपाते कि वह ४० लाखकी फौज तैयार रखना चाहते हैं। कोरिया और फिलिस्तीनमें लोकतन्त्रका गला घोटा जा रहा है और चीनमें गृहयुद्ध हो रहा है। मध्यपूर्वसे रूसको निकालनेका उद्योग हो रहा है। डार्डनेल्सके सम्बन्धमें भी रूससे मतभेद है। रूस समझता है कि उसकी रक्षाके प्रश्नसे केवल रूस, रूमानिया, बुल्गारिया और तुर्कीका ही सम्बन्ध रहे। जिस प्रकार डैन्यूबसे रूस बाहरवालोंको निकालना चाहता है, उसी प्रकार वह काले सागरमें बाहरी शक्तियोंका दखल नहीं चाहता। अमेरिका डार्डनेल्सके प्रश्नको तुर्की और इंग्लैण्डका प्रश्न मानता है और इसलिए वह इस मामलेमें इंग्लैण्डका समर्थन करता है।

रूसकी नीति

हमने सक्षेपमें यह दिखानेकी चेष्टा की है कि किन कारणोंसे समझौता नहीं हो रहा है और दल बन रहे हैं, जो भावी युद्धकी सूचना देते हैं। ब्रिटिश और अमेरिकन प्रचार इस आशयका होता है कि अकेले रूसके कारण समझौता नहीं हो रहा है तथा रूसकी नीति अपने राज्यका विस्तार करना है। हम रूसकी वर्तमान नीतिके हर हालतमें समर्थक नहीं हैं, किन्तु हम इंग्लैण्ड और अमेरिकाको कुछ ज्यादा ही दोषी समझते हैं। सोशलिस्ट स्टेट होनेके नाते हम यह अवश्य पसन्द नहीं करते कि रूस इन साम्राज्यवादी राष्ट्रोंकी नीतिका अनुकरण करे तथा आत्मरक्षाके लिए ठीक उसी तरह व्यवहार करे जिस तरह ये राष्ट्र करते हैं। हम यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि रूसको साम्राज्यवादी अमेरिकासे भय है और भयसे प्रेरित होकर ही आज उसकी नीति निर्धारित होती है। जिस प्रकार इंग्लैण्डकी कोई स्थायी वैदेशिक नीति नहीं है, जो सिद्धान्तोंपर आश्रित हो, उसी प्रकार रूसकी नीति किसी सिद्धान्तपर आश्रित नहीं है। आत्मरक्षाके भावसे प्रेरित होकर ही रूस आज अपनी नीति बनाता है। किसी नये युगके उपयुक्त जीवनके नये मूल्योंको ध्यानमें रखकर नहीं। यह बड़े दुःखकी बात है। ससारके एकमात्र सोशलिस्ट राज्यका इस बुरी तरह राज्यशक्तिकी कूटनीतिमें पड़ जाना हमको अखरता है। हम चाहते हैं कि राजनीतिके दौंव-पेचको छोड़कर वह स्थायी शान्तिके लिए प्रयत्नशील हो।

शान्तिका पथ

पर स्थायी शान्ति फौजी, प्रबन्ध प्रभावक्षेत्र और हवाई अड्डोंसे नहीं कायम होती। वह तो इस बदलते हुए युगमें अब पुराने तरीकोंसे नहीं कायम होगी। नये युगकी माँग कुछ और ही है, नये समाजके सामाजिक मूल्य कुछ और ही हैं। इनको पहचानना, इनके उपयुक्त नवीन सस्थाओंकी प्रतिष्ठा करना तथा इनके लिए मार्ग प्रशस्त करना हमारा काम होना चाहिये। आज जो प्रयत्न हो रहे हैं वे सब व्यर्थ हैं। जो मुख्य प्रश्न है उनकी जटिलताके कारण आज उनकी उपेक्षा की जा रही है और गौण प्रश्नोंको प्रधानता मिल रही है। वास्तविकतापर परदा डाला जा रहा है और बुद्धिमत्ता इसीमें समझी जाती है कि कैसे दूसरोंकी आँखोंमें धूल झाँकी जाय। स्पष्टवादिता एक बड़ा दुर्गुण समझा जाता है। ऐटम बमका प्रश्न मुख्य प्रश्न है। इसकी चर्चा बहुत थोड़ी होती है। वैज्ञानिकोंका

यह कहना सत्य है कि नये आविष्कारों और विज्ञानके तथ्योंको गुप्त नहीं रखना चाहिये, उन्हें प्रकाशित कर देना चाहिये। उनका यह भी कथन ठीक है कि ऐसी विद्याका ही प्रचार हो जो शिव है, जो समाजका कल्याण करती है। युद्धके लिए, मनुष्य जातिके संहारके लिए, सभ्यता-शालीनताको विनष्ट या कलुपित करनेके लिए विज्ञानका उपयोग नहीं होना चाहिये। इस प्रश्नको पेरिस-कान्फरेसमें प्रथम स्थान देना चाहिये था, किन्तु हमारी बातपर राजनीतिज्ञ हँसेगे। आज वह भले ही हँस ले, पर वह समय दूर नहीं है जब उनको रोना पड़ेगा। यदि केवल थोड़ेसे व्यक्तियोंकी बात होती तो हमको विशेष चिन्ता नहीं होती, किन्तु मुट्ठीभर राजनीतिज्ञोंकी मूर्खता और दुष्टताके कारण सारे समाजको रोना पड़ेगा। हम प्रभावक्षेत्रोंके बनानेके विरुद्ध हैं और हरजानाके दिलानेके भी पक्षमें हम नहीं हैं, विशेषकर ऐसी अवस्थामें जब कि पराजित राष्ट्र भूखो मर रहे हैं। नाजियोंको दण्ड देना चाहिये, उनके प्रभावको नष्ट कर देना भी आवश्यक है, किन्तु समस्त जातिको दण्ड देना कहाँका न्याय है? लोगोंको अपने देशसे बहिष्कृत करना और उनसे गुलामोंकी तरह काम लेना कहाँतक उचित है? जर्मनीको बरवाद कर, उसकी आर्थिक पद्धतिको छिन्न-भिन्नकर उसके टुकड़े-टुकड़ेकर यूरोप सुखकी नीद नहीं सो सकेगा। आज वह जमाना नहीं रहा जब दूसरोंको दुखी कर कोई देश सुखी हो सके। यूरोपकी समृद्धि जर्मनीकी समृद्धिपर निर्भर है। यह कोई कल्पना नहीं है और न कोई आदर्शवादिता ही है। यह स्थूल सत्य है। सारा ससार एक हो रहा है। एक अंगका फोड़ा सारे शरीरको विकल कर देता है।

इंग्लैण्डकी मजदूर-सरकारकी वैदेशिक नीति टोरियोंकी नीतिसे विशेष भिन्न नहीं है। ग्रीसमें किस प्रकार प्रजातन्त्रका गला घोटा गया और पुराने राजवंशको गद्दीपर बिठाया गया, यह हमसे छिपा नहीं है। राजाके वापस आ जानेसे सन् १९३६ का जमाना जब प्रतिक्रियाका बोलवाला था, फिरसे वापिस आ सकता है। यह भी है कि इंग्लैण्ड अपने साम्राज्यकी रक्षाके लिए अमेरिकाका पुछल्ला बन रहा है। अमेरिका आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड की रक्षाके लिए पैसिफिकमें रूसको बढने नहीं देता। अमेरिकाके हितके लिए इंग्लैण्ड, लेवैण्ट (Levant) और मध्यपूर्वकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। इंग्लैण्डकी औपनिवेशिक नीति भी प्रगतिशील नहीं है। रंगका भेद आज भी किया जा रहा है जब कि सरकार सोशलिस्ट कहलाती है। पुरानी नीति और परम्पराका परित्याग किये बिना आजकी समस्याओंका हल नहीं हो सकता।

दोनों दल एक दूसरेसे भयभीत हैं और इसलिए युद्धकी तैयारीमें लगे हैं। दोनों अपनी रक्षाकी व्यवस्था कर रहे हैं। यदि इंग्लैण्ड और अमेरिका पश्चिमी राष्ट्रोंका गुट बना रहे हैं, तो रूस पूर्वी यूरोपको अपने अधीन कर चुका है। वह चाहता है कि उत्तरमें फिनलैण्डसे लेकर नीचे तुर्की-सीरियाकी सीमातक पश्चिमी ब्लाकके विरुद्ध एक बाँध खड़ाकर दिया जाय ताकि पूँजीवादी प्रभाव प्रवेश न कर सके। प्रत्येक देश इसी उद्योगमें लगा है। प्रत्येक पक्ष अपने लिए सबसे अधिक लेना चाहता है और दूसरेको सबसे कम देना चाहता है। इसलिए रूस डार्डनेल्ससे पश्चिमी ब्लाकको अलग रखना

चाहता है, यद्यपि उसकी नीतिका फल यह होगा कि तुर्की अपनी स्वतन्त्रता खो देगा । इधर इंग्लैण्ड रूसको डार्डनेल्ससे अलग रखना चाहता है । खतरेके जो प्रदेश है, उनमें छीना-झपटी चल रही है । हमारी रायमें प्रश्नका हल यह है कि इन सब स्थानोको किसी एकका प्रभाव-क्षेत्र नहीं बनने देना चाहिये । किन्तु इनपर अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार होना चाहिये । इस नीतिको समान रूपसे बर्तना चाहिये । तेलके चश्मोके लिए जो होड है उसे रोकना चाहिये । तेलके चश्मे उस देशकी मिलकियत हो जहाँ वे पाये जाते हो, किन्तु सब राष्ट्रोको अपनी-अपनी आवश्यकताके अनुसार उचित दाम देनेपर उसमें हिस्सा मिलना चाहिये और इस विषयके सारे अधिकार एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाके हाथमें होने चाहिये । यूरोपके पुनर्निर्माणके लिए भी सबकी रायसे योजनाएँ बननी चाहिये ।

पेरिस-सम्मेलन सफल होता नहीं दीखता । खिचाव बढ़ता जाता है । बार-बार सम्मेलनको मुलतवी करना पड़ता है या झगड़ेके कामोको कौंसिलके सिपुर्द करना पड़ता है । मालूम होता है कई सम्मेलन करने पड़ेंगे । समझौतेका कोई आधार नजर नहीं आता । सहयोग तभी सम्भव है जब कोई ऐसा उद्देश्य हो, जिसके अधीन अन्य सब उद्देश्य हो सके । कोई ऐसे सिद्धान्त सबको मान्य नहीं है, जिनके आधारपर कुछ निश्चय किये जा सके । कमसे कम इतना तो हो कि सवाल अलग-अलग न लिये जायँ । सब सवालोको एक साथ लेना चाहिये, जिसमें एक-सा फैसला हो सके । छोटे राष्ट्रोके अधिकारका प्रश्न भी विचारणीय है । इस समय जो कुछ निर्णय होते हैं उन्हें वैदेशिक सचिव कर लेते हैं । उनकी स्वीकृति सम्मेलनसे ली जाती है । जब यह हाल है तो लोकमतको कौन पूछता है ? छोटे राष्ट्र स्वतन्त्र नहीं हैं । वे किसी-न-किसी महाराष्ट्रके साथ हैं । सारा ढग लोकतन्त्रके विरुद्ध है । इस ढंगको बदलनेकी जरूरत है । यदि पहले सिद्धान्त स्थिर कर लिये जायँ और उनके अनुसार पक्षपातरहित हो काम किया जाय तो सफलताकी आशा हो सकती है ।

जर्मन राजनीतिकी दिशा'

जर्मनीके उस भागमें जो सोवियत रूसके अधिकारमें है, रूसियोके प्रभावसे एक 'सोशलिस्ट युनिटी पार्टी' स्थापित हुई है । इसका आधार 'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी' और कम्युनिस्ट पार्टी' की एकता है । कहा जाता है कि वास्तवमें इन दलोमें एकता नहीं हुई है, किन्तु रूसी अधिकारोके दबावमें आकर सोशल डेमोक्रेट इस नयी पार्टीमें सम्मिलित होनेके लिए बाध्य हुए हैं । डाक्टर के० शुमाखर (Dr. K. Schumacher) जो जर्मनीके पश्चिमी भागोके सोशल डेमोक्रेटिक सस्थाओके नेता हैं, इस एकताका विरोध कर रहे हैं । उन्होने हनोवर और फ्रैंकफुर्टमें अपने दलके अधिकारियोके सम्मेलन किये थे; जहाँ इस एकताके विरोधमें प्रस्ताव पास किये गये हैं । उनका कहना है कि समस्त जर्मनीकी पार्टी कांग्रेसको ही एकताके प्रश्नका निर्णय करनेका अधिकार है । उनका आग्रह है कि

एकताके सम्बन्धमें कोई निश्चय तभी हो सकेगा, जब जर्मनीके विभिन्न विभागोंका, जिनमें मित्रराष्ट्रोंने जर्मनीको बाँट रखा है, लोप हो जायगा और जब उनके अधिकारका इन विभागोंमें अन्त हो जायगा । कम्युनिस्टोंका कहना है कि सोशल डेमोक्रेटोंके पुराने नेता अभी पुराने झगड़ोंको नहीं भूलें हैं और इसीलिए वह एकताके कट्टर विरोधी हैं । कम्युनिस्ट यह आशा करते थे कि यदि यह एकता आरम्भमें केवल रूसी विभागमें ही स्थिर रूपसे कायम हो जाय, तो यह नयी पार्टी समस्त जर्मनीमें सबसे प्रबल पार्टी होगी । किन्तु हालके चुनावोंसे उनकी इस आशापर पानी फिर गया है । बर्लिनके चुनावका फल यह हुआ है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीको ४८.२ प्रतिशत वोट मिले हैं । इस नयी पार्टीका तृतीय स्थान है और उसको केवल १६.३ प्रतिशत वोट मिल सके हैं । इसी प्रकार अन्य विभागोंमें भी जो अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच अधिकारमें हैं सोशलिस्टोंका बहुमत है । सोशलिस्ट युनिटी पार्टीका बहुमत केवल रूसियोंद्वारा अधिकृत विभागमें है । इससे इस आक्षेपको पुष्टि मिलती है कि रूसी क्षेत्रमें जो चुनाव हुए हैं, वे स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं हुए हैं । चुनावमें अधिकारियोंने अपने अधिकारका दुरुपयोग किया है ।

परिणाम यह है कि रूसी विभागको छोड़कर अन्य विभागोंमें जनताने कम्युनिज्मके विरुद्ध अपना मत दिया है और सोशल डेमोक्रेट कम्युनिस्टोंके साथ एकता करनेके पक्षमें वह नहीं है । अतः जब जर्मनीकी एकता स्थापित होगी, तब रूसियोंकी छत्रछायामें काम करनेवाली 'सोशलिस्ट-युनिटी पार्टी' की राजनीतिक शक्ति प्रबल न हो सकेगी । हालके चुनाव इसका स्पष्ट संकेत कर रहे हैं । इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि यह देखकर कि अब सोशलिस्ट युनिटी पार्टी द्वारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, सोवियत रूस इस संस्थाकी भविष्यमें उपेक्षा करे और जर्मनीमें हर जगह कम्युनिस्ट पार्टीका ही एक मात्र सहारा ले ।

हम एकताके पक्षमें हैं, यदि इसका विश्वास हो कि यह एकता स्थायी होगी और कम्युनिस्ट पार्टी आगे चलकर विश्वासघात नहीं करेगी । किन्तु इस पार्टीका अवतकका इतिहास ऐसा नहीं रहा है, जिससे हमको ऐसा भरोसा हो सके । मजदूर-आन्दोलनकी एकतासे मजदूर वर्गका बल बढ़ता है इसमें सन्देह नहीं है । किन्तु ऐसी पार्टीसे क्या आशा की जाय, जो एकताके लिए उसी समय हाथ बढाती है, जब उसको गरज होती है, पर जो अपना मतलब निकल जानेपर किसी समय भी धोखा दे सकती है । इसके उदाहरण इतिहासमें भरे पड़े हैं । सोशल डेमोक्रेटोंको बदनाम करना सुलभ है । किन्तु इसका सारा दोष उन्हींके मर्त्ये नहीं मढ़ा जा सकता । जबतक कम्युनिस्ट इस बातका पुष्ट प्रमाण नहीं देते कि उन्होंने अपने रवैयोंको सदाके लिए बदल दिया है, तबतक कहीं भी इन दो दलोंमें एकता नहीं हो सकती । यह दूसरी बात है कि अनुचित दवाव डालकर, जोर-जबर्दस्तीसे, कहीं-कहीं दिखाऊ एकता कायम हो जाय ।

यह ठीक है कि रूसी विभागसे अन्यत्र सोशल डेमोक्रेटोंको वहाँके अंग्रेज और अमेरिकन अधिकारियोंका सहारा मिला है और यह भी सच है कि इंग्लैण्डमें मजदूरदलकी जो विजय हुई है, उससे भी सोशल डेमोक्रेटोंको अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखनेमें सहायता

मिली है। किन्तु यह भी निर्विवाद है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक-दो स्थानोंको छोड़कर कहीं भी कम्युनिस्टोंके साथ एक दल बनानेको तैयार नहीं है।

सोशलिस्ट युनिटी पार्टीके प्रोग्रामके कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं :—

‘केवल एक ही शक्ति ऐसी है जो प्रतिक्रियाकी शक्तियोंपर अर्थात् मिलिटैरिज्म (सैनिकवाद) और फासिज्मपर अन्ततोगत्वा विजय प्राप्त कर सकती है और यह शक्ति समस्त मजदूर-वर्गकी सम्मिलित शक्ति है, जब उसको किसान तथा कामकाजी बुद्धिजीवी-वर्गका घनिष्ठ और दृढ सहयोग प्राप्त होता है।

“वर्तमान अवस्थामे, जहाँ हिटलरशाहीने अपने युद्धकालीन अपराधोंके कारण तथा अन्य राष्ट्रोंकी जनताके विरुद्ध असह्य दुष्टाचार कर जर्मन राष्ट्रोंकी एकताको खतरेमे डाल दिया है, वहाँ केवल समस्त फासिज्म विरोधी तथा प्रजातान्त्रिक देशव्यापी शक्तियोंकी एकता ही राष्ट्रीय एकताका प्रतिनिधित्व कर सकती है।”

“पार्टीका लक्ष्य प्रजातान्त्रिक मार्गद्वारा ही समाजवादकी स्थापना करना है। किन्तु यदि पूँजीवादी वर्ग लोकतन्त्रकी भूमिका परित्याग करेगा तो यह क्रान्तिकारी उपायोका अवलम्बन ग्रहण करेगी।”

युनाइटेड पार्टी आत्मनिर्भर और स्वतन्त्र होगी। जर्मनीकी मजदूर जनताके हितोंके अनुसार और जर्मनीकी विशेष स्थितिको दृष्टिमे रखकर ही उसकी नीति और कार्य करनेकी शैली निर्धारित और विकसित होगी। अपने निम्नतम तथा उच्चतम कार्यक्रमको सफल बनानेके लिए उसको अपना स्वतन्त्र मार्ग ढूँढ निकालना होगा और इस मार्गका आधार जर्मन जातिके विकासकी विशेषताएँ होगी। राज्यके पुराने ढाँचेका पूर्ण ध्वंस करके तथा जर्मनीका लोकतन्त्रात्मक विकास करके कदाचित् ऐसे नवीन और विशेष आधारोंका सृजन होगा, जिनसे मजदूरवर्गके हाथमे राजसत्ता क्रमशः आयेगी तथा समाजवादकी स्थापना होगी।

“दिन-दिनके संघर्षमे उसका जो दान होगा उसमे तथा अपने सामाजिक गठनमें युनाइटेड पार्टी, मजदूर-वर्गकी पार्टी और समस्त मजदूर जनताकी पार्टी होगी। उसकी आन्तरिक व्यवस्था सम्पूर्ण रूपसे प्रजातान्त्रिक होगी। जर्मन जातिके जो सच्चे राष्ट्रीय हित हैं, उनकी वह रक्षा करेगी और शान्ति-प्रेमी राष्ट्रोंके समुदायमें जर्मनीको पुनः सम्मिलित करानेसे ही यह कार्य सम्पन्न हो सकेगा।

“मजदूरवर्गके आन्दोलनकी जो सुन्दर परिपाटी चली आयी है, उसीके अनुसार युनाइटेड पार्टी मजदूरोंको जो अन्तर्राष्ट्रीयता मान्य है, उसमे प्रतिपन्न होगी और उसका सच्चे हृदयसे समर्थन करेगी और इसी भावसे वह पूँजीवादी देशोंके तथा सोवियत यूनियनके मजदूर आन्दोलनके साथ दृढ सम्बन्ध स्थापित करनेकी चेष्टा करेगी। जिस प्रकार सर्वत्र शान्ति, लोकतन्त्र, प्रगति तथा समाजवादको समुन्नत करना उसका कर्तव्य है, जिस प्रकार जातीय अथवा राष्ट्रीय घृणा और विद्वेष अतिराष्ट्रीयता और सोवियत विरोधी प्रचारका शक्तिभर विरोध करना उसका कर्तव्य है, उसी प्रकार अपने संघर्षके लिए अन्य देशोंके मजदूर-आन्दोलनका समर्थन प्राप्त करना भी उसका कर्तव्य होगा।”

उक्त प्रस्ताव बड़े महत्त्वका है। हमको स्मरण रखना चाहिये कि यह सम्मिलित पार्टीका निश्चय है। अतः स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी भी इस प्रस्तावमें निर्दिष्ट किये गये सिद्धान्तोंको स्वीकार करती है और यह भी मानना होगा कि सोवियत रूसकी इस प्रस्तावपर मुहर है। किन्तु ये सिद्धान्त अबतक कम्युनिस्टोंको मान्य नहीं रहे हैं। इन्हींके न माननेसे यूरोपमें समाजवादियों और कम्युनिस्टोंमें एकता नहीं हो पायी है और मजदूर-आन्दोलनमें फूट पड़ती रही है। इस प्रस्तावमें एक सिद्धान्त यह निरूपित किया गया है कि प्रजातान्त्रिक मार्गद्वारा ही समाजवादकी स्थापना करना हमारा लक्ष्य होना चाहिये और हिंसाका प्रयोग तभी करना चाहिये जब पूर्वोक्त मार्गपर चलना पूंजीपतियोंद्वारा असम्भव कर दिया जाय। किन्तु अबतककी नीतिका आधार तो यही रहा है कि हिंसाका प्रयोग अनिवार्य है और मजदूरवर्गके अधिनायकत्वके बिना समाजवादकी स्थापना असम्भव है। वैधानिक ढंगसे समाजवाद प्रतिष्ठित हो सकेगा, इसकी कल्पना कम्युनिस्टोंने कभी नहीं की थी। दूसरा महत्त्वका सिद्धान्त यह है कि पार्टी आत्मनिर्भर और स्वतन्त्र होगी। अर्थात् दूसरे शब्दोंमें वह मास्कोका मुँह न ताकेगी, उसके इशारेपर नहीं चलेगी और उसकी वैदेशिक नीतिका पुछल्ला नहीं वनेगी। पुनः उसकी नीति अपने देशकी जनताके हितोंको ध्यानमें रखकर ही और उसकी विशेष स्थितिपर विचार करके ही निश्चित होगी, किन्तु आजतक तो इसके प्रतिकूल ही आचरण हुआ है। अपनी नीतिके निश्चित करनेकी स्वतन्त्रता कम्युनिस्ट पार्टियोंको कही भी नहीं रही है और वे सदा सोवियत रूसके इशारेपर और उसीके राष्ट्रीय हितोंको प्रधान मानकर काम करती रही हैं। समाजवादियों और कम्युनिस्टोंके बीच विवाद का यह मुख्य विषय रहा है।

तीसरा सिद्धान्त जिसका हम उल्लेख करना चाहते हैं पार्टीका वह निश्चय है जिसके अनुसार उसकी आन्तरिक व्यवस्था सम्पूर्ण रूपसे प्रजातान्त्रिक होगी। अबतक जनतान्त्रिक केन्द्रीकरण (democratic centralism) का सिद्धान्त मान्य था, जो विगड़ते-विगड़ते एक अधिनायकत्वके सिद्धान्तके रूपमें परिणत हो गया। ट्राट्स्कीके शब्दोंमें 'पार्टीका संगठन पार्टीका ही स्थान ले लेगा, केन्द्रीय समिति संगठनका स्थान ले लेगी और अन्तमें अधिनायक केन्द्रीय समितिका स्थान ले लेगा।' इस सम्बन्धमें ट्राट्स्कीने एक स्थानपर लिखा था कि ऐसा अनुमान करनेका लोभ संवरण करना शायद कठिन है कि स्टालिनिज्मका मल वोलशेविकोंके केन्द्रीय नियन्त्रणके सिद्धान्त (Centralism) में निहित है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टीके सिद्धान्तोंमें इधर कुछ ऐसा हेर-फेर हुआ है अथवा अपनी अवसरवादिताके सिद्धान्तके अनुसार सोशल डेमोक्रेटोंकी शंकाके निवारणार्थ तथा उनको एकताके लिए प्रोत्साहित करनेके लिए ही उक्त पार्टीके कार्यक्रममें इन सिद्धान्तोंको प्रविष्ट किया गया है। जिस प्रकार अमेरिकाके आक्षेपोंको दूर करनेके लिए जिससे वह पूरी तरह युद्धमें सहायता प्रदान करे, तृतीय इंटरनेशनलके तोड़नेका स्वांग रचा गया और सोवियत रूसके अनेक गिर्जे खोल दिये गये, धर्म-स्वातन्त्र्यकी घोषणा की गयी तथा धर्माचार्यका आदर-सत्कार किया गया, क्या उसी प्रकार अपनी शक्तिको

बढ़ानेके लिए तो कही ये सिद्धान्त नहीं घोषित किये गये हैं ? हमको तो इसमें सच्चाईकी बहुत कमी मालूम होती है । यदि वस्तुतः नीतिमें कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, तो इनकी घोषणा सर्वत्र क्यों नहीं की जाती और यह नीति सर्वत्र क्यों नहीं बरती जाती ? यदि ये सिद्धान्त कम्युनिस्टोंको मान्य हो तो एकताके स्थापित होनेमें बहुत देर न लगे । यह नहीं कहा जा सकता कि ये सिद्धान्त मौलिक नहीं हैं और विशेष देश या कालमें ही लागू होते हैं । आजके युगमें इनका व्यापक प्रयोग होनेसे ही सर्वत्र एकता स्थापित हो सकती है । पर कठिनाई तो यह है कि कम्युनिस्ट ऐसी घोषणा करनेसे रहे और इसका भी क्या ठीक कि कब वे अपनी नीति बदल देंगे । कम्युनिस्टोंकी कलावाजियोंसे हम अच्छी तरह परिचित हैं । अपनी नीतिमें आकाश-पातालका अन्तर करनेमें इनको कोई परेशानी नहीं मालूम होती । पाकिस्तानके प्रश्नके सम्बन्धमें ही इन्होंने कितनी बार अपनी नीतिको बदला है । वस्तुस्थिति नहीं बदलती पर ये बदलते रहते हैं और यह पता नहीं चलता कि आखिर ये किस भूमिपर खड़े हैं । हमारे ही देशमें श्री जयप्रकाशनारायणने इनसे एकता करनेके लिए भगीरथ प्रयत्न किया और कोई बात उठा नहीं रखी । किन्तु तृतीय इण्टर-नेशनल और रूस तथा पार्टीके भीतर लोकतन्त्रकी व्यवस्थाके प्रश्नको लेकर ही एकता न हो सकी ।^१

आस्ट्रिया

आस्ट्रियामें सोवियत रूस आर्थिक और राजनीतिक नियन्त्रण प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ है । आस्ट्रियाकी वर्तमान सरकार पश्चिमी यूरोपके मित्रराष्ट्रोंके पक्षमें है और उसके द्वारा ये राष्ट्र रूसकी नीतिको विफल करनेकी चेष्टामें हैं । आपसके इस मन-मुटाव और विरोधका कुफल आस्ट्रियाकी जनताको भोगना पड़ता है और उसकी इस घातक नीतिके कारण ससारकी प्रधान शक्तियोंकी मैत्री भी सन्दिग्ध हो जाती है ।

सन् १९४३ में मास्कोकी जो घोषणा हुई थी उसके द्वारा ससारकी प्रमुख शक्तियोंने आस्ट्रियाकी स्वाधीनताको स्वीकार कर लिया था और यह घोषणा की थी कि आस्ट्रियाके जिस लोकतन्त्रको डालफसने और पीछेसे नाजियोंने विनष्ट किया था, उसका पुनरुद्धार करनेके लिए पूरा अवसर दिया जायगा । इस घोषणाके फलस्वरूप चुनाव हुए और डाक्टर फिलकी सम्मिलित सरकारको सब शक्तियोंने अपनी स्वीकृति दी । आस्ट्रियामें सोशलिस्ट पार्टीका बड़ा तेजीके साथ पुनरुद्धार हुआ और सच तो यह है कि जिन वर्षोंमें वहाँ नाजियोंका शासन था, सोशलिस्टोंका प्रभाव वास्तवमें बढ़ गया । इन विविध सुविधाओंके कारण आस्ट्रियाका पुनरुद्धार बड़ी सुगमताके साथ हो सकता था । किन्तु ऐसा नहीं हुआ है । पुरानी अवस्था बहुत धीरे-धीरे वापस हो रही है । अमेरिकन क्षेत्रके कुछ हिस्सोंके अतिरिक्त सर्वत्र लोग भूखे हैं । क्षेत्रोंमें विभक्त होनेके कारण मालका

एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जाना बहुत कठिन हो रहा है। कोई सम्मिलित आर्थिक नीति नहीं स्थिर हो पाती। मित्रराष्ट्रोंमें परस्पर मतभेद होनेके कारण सरकारको पग-पगपर विरोधका सामना करना पड़ता है। इस स्थितिका उत्तरदायित्व किसी न-किसी अंशमें वहाँकी सरकारपर भी है। यदि वह निष्पक्ष भावसे कार्य करती तो कदाचित् मित्रराष्ट्रोंके परस्पर विरोधको शान्त कर सकती। किन्तु डाक्टर फिगलके मन्त्रिमण्डलका सुझाव एंग्लो-अमेरिकन समुदायकी ओर है। डाक्टर फिगल और उनके साथी इस तथ्यको भूल गये हैं कि उनके देशकी आर्थिक पद्धति डैन्यूवकी पद्धतिसे पृथक् नहीं की जा सकती और आस्ट्रियाके उद्योग-व्यवसायके साधनका अधिकांश सोवियत रूसके क्षेत्रमें है, अतः रूसके लिए आस्ट्रियापर आर्थिक दबाव डालना बहुत सुगम है और यह दबाव डाला जा रहा है। इसका यही फल होनेवाला है कि पूर्वी ब्लाकमें आस्ट्रिया पूरी तरह जड़ हो जायगा। रूस चाहता है कि व्यापारके सम्बन्धमें उनका आस्ट्रियाके साथ समझौता हो जाय। किन्तु आस्ट्रियाकी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जबतक मित्र राष्ट्रोंमें मतभेद कायम है, वह अकेले रूससे समझौता नहीं करेगी। इस कारण रूस आस्ट्रियाकी सरकारको इंग्लैण्ड और अमेरिकाका उपकरण बननेका दोषी ठहराता है।

इस झगड़ेका एक दूसरा कारण भी है। पूर्वी आस्ट्रियामें जर्मनीकी जो पूंजी लगी है, उस सबको रूस अपने अधीन करना चाहता है और उसे हरजानेके रूपमें ले लेना चाहता है। जो उद्योग-व्यवसाय आन्श्लुस (Anschluss) के वादसे आस्ट्रियाकी पूंजीकी सहायतासे कायम किये गये हैं, उनको भी रूस ले लेना चाहता है। रूसका यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सन् १९३८ और सन् १९४५ के बीच आस्ट्रियाके आर्थिक साधनोंका ७५ प्रतिशत अनिवार्य रूपसे जर्मन युद्ध यन्त्रका अपरिहार्य अंग बना लिया गया था। रूसके इस दावेके जवाबमें इंग्लैण्ड और अमेरिकाका कहना है कि उसी जर्मन पूंजी और व्यवसायके पाने का रूस हकदार है जो आन्श्लुसके पहलेसे आस्ट्रियामें लगी थी और कायम थी। वह उन व्यवसायोंको भी इसमें शामिल करते हैं जो पीछेसे जर्मन पूंजीकी सहायतासे कायम हुए। रूसकी इस माँगको व्यर्थ करनेके लिए आस्ट्रियाकी पार्लमेण्टने २६ जुलाई सन् १९४६ को कुछ चुने व्यवसायोंके राष्ट्रीकरणका कानून बना दिया है। रूसी क्षेत्रमें तेलके कुएँ हैं उनका राष्ट्रीकरण हो गया है, इसी प्रकार डैन्यूव स्टीमिंग कम्पनीका और विजलीके व्यवसायके भागोंका जिनकी मिलकियत जर्मनोंकी है राष्ट्रीकरण हुआ है। सोवियत रूस इनको अपनी मिलकियत घोषित कर चुका है। उसकी शिकायत है कि केवल उन्हीं व्यवसायोंका राष्ट्रीकरण हुआ है जो रूसी क्षेत्रमें पाये जाते हैं। उनका कहना है कि जिन व्यवसायोंमें पश्चिमी राष्ट्रोंकी पूंजी लगी है वे राष्ट्रीकरणसे बच गये हैं। इस प्रकार आस्ट्रियाकी हुकूमतको पक्षपात दोषी ठहराता है। यह बात कुछ अंशमें ठीक भी है, किन्तु यह सर्वथा सत्य नहीं है कि कोई भी ऐसा व्यवसाय राष्ट्रीकरणके लिए नहीं चुना गया है, जिसमें पश्चिमके राष्ट्रोंकी पूंजी लगी हो। उदाहरणके लिए जिस्टर्सडॉर्फ (Zistersdorf) के तेलके कुओंमें ब्रिटिश, डच और अमेरिकन फर्मोंके स्वत्व है। इसी तरह 'लेडर वैक' में बहुत-कुछ फ्रेंच पूंजी लगी हुई है। वस्तुतः आस्ट्रियामें पश्चिमकी

बहुत कम पूंजी लगी हुई है। वाद-विवादके पश्चात् अन्तमें चार प्रधान राष्ट्रोंमें यह समझौता हो चुका है कि राष्ट्रीकरणका प्रोग्राम कानूनका रूप ले लेगा यदि एक मासके भीतर चारो राष्ट्र एक स्वरमें आक्षेप नहीं करते।

सच तो यह है कि इन महान् राष्ट्रोंके आपसके झगड़ोंके कारण गरीब आस्ट्रियाको क्षति पहुँच रही है। हर एक उसको अपना साधन बनाना चाहता है, जब कि सबको केवल आस्ट्रियाको दृष्टिमें रखकर काम करना चाहिये। यह स्पष्ट है कि आस्ट्रियाकी आर्थिक पद्धति डैन्यूबसे बँधी हुई है और इस प्रदेशमें सोवियतका प्राधान्य है। इसी कारण रूसके आर्थिक दबावके आगे आस्ट्रियाको सिर झुकाना पड़ेगा अथवा उसकी आर्थिक अवस्था विगड़ जायगी, इस कारण रूस आस्ट्रियाकी सहायता विशेष रूपसे कर सकता है। डैन्यूबके राज्योके साथ व्यापार करनेकी स्थिति पश्चिमी राष्ट्रोंकी पहले नहीं रही है और आज भी नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टिसे रूस आस्ट्रियाको अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि यूरोपके पश्चिम पूर्व भागकी रक्षा करनेमें आस्ट्रियाका बड़ा उपयोग है।

आस्ट्रियाकी प्रधान पार्टियाँ सोशलिस्ट और कैथलिक पीपुल्स दोनो ही सोवियत रूसके पक्षमें नहीं हैं। किन्तु वे अन्त तक पश्चिमी समुदायमें तभी रह सकते हैं जब कार्यरूपमें पश्चिमी राष्ट्र उसके सच्चे सहायक प्रमाणित हो। पर इसकी आशा कम है और यदि रूस चाहे तो उसकी स्थिति ऐसी है कि वह आस्ट्रियाको पूर्ण सहायता दे सकता है। पर यह वह तभी करेगा जब आस्ट्रिया पूर्वी समूहमें शामिल हो जाय। जबतक वह इसके लिए तैयार नहीं होता, तबतक रूसका आर्थिक दबाव जारी रहेगा और शायद अन्तमें आस्ट्रियाको हार माननी पड़ेगी।^१

मिस्रकी राजनीतिक पार्टियाँ

हमको अपने पड़ोसी राष्ट्रोंका बहुत कम ज्ञान है। यूरोपके इतिहासको जाननेकी इच्छा हममें बड़ी प्रबल है। वहाँकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितिको जाननेके लिए हम सदा उत्सुक रहते हैं, किन्तु अपने पड़ोसी राष्ट्रोंमें क्या नवीन आन्दोलन हो रहे हैं और उनके जीवनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसके जाननेके लिए हममें समान रूपसे उत्सुकता नहीं पायी जाती। यह सच है कि यूरोपका इतिहास जाननेके लिए पर्याप्त सामग्री है जब कि एशियाके राष्ट्रोंका इतिहास जाननेके साधन बहुत कम हैं। इसमें भी सन्देह नहीं कि हमारी चेतनाका प्रेरक यूरोप रहा है। पर भविष्यमें हमको अपने पड़ोसियोंसे ज्यादा काम पड़ेगा और इसलिए इस बातकी आवश्यकता है कि हम उनकी भाषा, सस्कृति तथा इतिहासका ज्ञान प्राप्त करें। इस दृष्टिसे हम 'जनवाणी' में अपने पड़ोसी राष्ट्रोंकी वर्तमान स्थितिका विवरण समय-समयपर दिया करेंगे। इस टिप्पणीमें हम मिस्र देशकी राजनीतिक पार्टियोंका संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं।

मिस्र एक कृषि-प्रधान देश है। अधिकांश जनता खेतीपर निर्भर करती है। एक ओर विपुल संख्यामें खेतमें काम करनेवाले लोग हैं जिन्हें 'फलाहीन' कहते हैं, दूसरी ओर मुट्ठीपर वड़े-वड़े जमींदार हैं जिन्हें 'पाशा' कहते हैं। 'फलाहीन' की आर्थिक अवस्था दयनीय है। इनकी आयका अनुमान लगभग १५०) रु० वार्षिक है। शहरमें काम करनेवाले मजदूरोंकी अवस्था इनसे कुछ बहुत अच्छी नहीं है। अन्न, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओंका मूल्य बहुत बढ़ गया है। पाशाओंकी सम्पत्तिका हिसाब बताना बहुत कठिन है; क्योंकि गवर्नमेण्ट इसका कोई हिसाब नहीं बतती। बादशाह फारूककी सम्पत्ति १५ करोड़से १८ करोड़ रुपया याँकी जाती है। कुछ पाशाओंकी सम्पत्ति इससे भी अधिक होगी।

मिस्रके यह दो प्रधान वर्ग हैं। इनके बीच एक छोटा-सा मध्यमवर्ग भी है। वर्गके आधारपर पार्टियाँ हैं। जनताकी पार्टी 'वफद' पार्टी है। यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। दूसरी ओर पाशाओंकी कई पार्टियाँ हैं। इन्हें अमीरोंका क्लव कहना चाहिये। इनको जनताका समर्थन प्राप्त नहीं है, तिसपर भी वह चुनावमें छल-कपटसे अपना बहुमत कर लेती हैं। मिस्रमें चुनावमें बड़ी धाँधली होती है। पुलिस अनपढ़, सहमे हुए गरीब किसानोंको मोटरोंमें भर लेती है, उन्हें चुनावके स्थानपर ले जाती है और उनसे गवर्नमेण्टके आदमियोंको वोट दिलाती है। इस कष्टके लिए वोटरोको कुछ बखशीश दे दी जाती है।

कई पाशा अपनी पूँजी उद्योग-व्यवसायके क्षेत्रमें लगाये हुए हैं। उदाहरणके लिए सिद्दीकी पाशा, जिसने गत सितम्बरमें प्रधान मन्त्रीके पदसे त्यागपत्र दिया था, मिस्रका एक बहुत बड़ा पूँजीपति है। वह 'Egyptian Federation of Industry' का संस्थापक और अध्यक्ष है। वह १८ बड़ी कम्पनियोंका डाइरेक्टर है। इन पूँजीपतियोंकी एक पार्टी है जिसे 'सआदी' कहते हैं। इसका नेता नोक्राणी पाशा है जो इस समय प्रधान मन्त्री है और जिसने सुदानके प्रश्नको यू० एन० ओ० के पास निर्णयके लिए भेजा है। पाशाओंकी एक दूसरी पार्टी है जो उदार दलके माने जाते हैं और जो विधानवादी हैं। जब मिस्र तुर्की साम्राज्यमें शामिल था उस समय अच्छे कुलके तुर्क मिस्रमें बस गये थे और उनके पास बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ थी। यह दल ऐसे ही पाशाओंका दल है। इस दलका बादशाह फारूकसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह दोनों दल चाहते हैं कि व्यापारके क्षेत्रमें वह इंग्लैण्डसे स्वतन्त्र हो और उनको अमेरिकासे व्यापार करनेकी स्वतन्त्रता हो। विदेशी विनिमयपर अंग्रेजोंका जो नियन्त्रण है उससे वह स्वतन्त्र होना चाहते हैं, किन्तु वह अभी अंग्रेजोंकी साझेदारीको तोड़ना नहीं चाहते। अंग्रेजोंके हिस्सेदार बनकर ही उन्होंने उद्योग-व्यवसायके क्षेत्रमें इतनी उन्नति की है किन्तु इस साझेदारीमें उनकी हैसियत छोटी है। वह अपनी हैसियतको तो बढ़ाना चाहते हैं, किन्तु समझते हैं कि यदि अंग्रेजोंकी साझेदारी खत्म हो गयी तो उनको कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा और उनकी पूँजी उतनी सुरक्षित न होगी। एक कारण और है जिससे वह अंग्रेजोंके बिना अपनेको कमजोर पाते हैं। मिस्रमें मजदूर-आन्दोलन बल पकड़ रहा है और मजदूरोंकी बेचैनी बढ़ती जाती है। समाजमें अशान्ति बढ़ती जाती है। बेकारोंकी संख्या ६ लाख हो गयी है। इन पाशाओंका

ख्याल है कि कम्युनिस्ट विचारोंके फैलनेके कारण यह स्थिति दिनपर दिन विगड़ती जायगी । इस बढ़ती हुई वेचैनीका मुकाबला करनेमें वह अपनेको कमजोर पाते हैं और इसलिए वह इंग्लैण्डका सहारा ढूँढते हैं । बादशाह फारुक स्वयं अंग्रेजोंके बड़े विरोधी हैं, किन्तु अपने स्वार्थोंकी रक्षाके लिए उनको अंग्रेजोंका मुँह ताकना पड़ता है । अंग्रेज स्थिर स्वार्थोंके रक्षक समझे जाते हैं । उन्होंने आखिर युनानमें उसके बादशाहको लाकर बैठा ही दिया । जनताकी बढ़ती शक्तिका अवरोध करनेके लिए इन छोटे-छोटे देशोंके राजाओं और अमीरोंको इंग्लैण्डका आश्रय लेना पड़ता है ।

पूँजीपतियों और जमींदारोंकी इन पार्टियोंके विरुद्ध लोकप्रिय 'वफद पार्टी' है । यदि चुनावके समय किसानोंको स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो किसी चुनावमें भी वफदको सुगमतासे कम-से-कम ६० प्रतिशत वोट मिल सकते हैं । सन् १९१९ से यही दल अधिकांश मिस्रियोंके राष्ट्रीय भावोंको व्यक्त करता रहा है । गाँवोंमें किसी और दलका प्रवेश भी नहीं हुआ है, इसके प्रमुख व्यक्तियोंमें भी जमींदार और कुछ पूँजीपति हैं । जमींदार तो अंग्रेजोंका इसलिए विरोधी है, क्योंकि अंग्रेज रुईकी कीमत गिरा देता है, रुईकी खरीदपर उसका एकाधिपत्य है और सुदानमें रुईकी जो खेती होती है वह आधुनिक ढंगसे होती है और उसपर अंग्रेजका एकमात्र अधिकार है । रुईकी फसल ही मिस्रकी खास फसल है और यदि रुईकी कीमत अच्छी न मिले तो जमींदारको असन्तुष्ट होनेका पर्याप्त कारण है । जो थोड़े-बहुत व्यवसायी वफद पार्टीमें हैं उनका विचित्र हाल है । आरम्भमें वह वफदमें सम्मिलित होते हैं क्योंकि वह अंग्रेजोंके विरुद्ध है, किन्तु जब वफदकी नीतिका झुकाव जनता की ओर अधिक होता है तब वह भयभीत होकर पार्टी छोड़ देते हैं और एक नयी पार्टीको जन्म देते हैं या किसी दलमें सम्मिलित नहीं होते ।

'वफद' के इस पक्षको हम 'वफद' का दक्षिण पक्ष कह सकते हैं, किन्तु 'वफद' का एक वाम पक्ष भी है और वही उसकी जान है । इसमें मजदूर, नवयुवक, विद्यार्थी और उदार विचारके शिक्षित लोग शामिल हैं । इस पक्षके प्रभावसे 'वफद' पार्टीके उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं हैं, किन्तु सामाजिक भी होते जाते हैं । दक्षिण पक्षी इस प्रभावको बढ़नेसे रोकते हैं ।

वफदके जो नेता जमींदार हैं वह किसानों और मजदूरोंको केवल साधारण रियायतें देना चाहते हैं, किन्तु किसी मौलिक सुधारके लिए तैयार नहीं हैं । वामपक्षी मिस्रकी स्वाधीनताके साथ-साथ जनताकी आर्थिक स्थितिमें पर्याप्त सुधार करना चाहते हैं और वेकारीको दूर करना चाहते हैं, इस पक्षको कभी-कभी स्वतन्त्र रीतिसे भी कार्य करना पड़ता है । गत वर्ष मजदूर और विद्यार्थियोंकी एक कमेटी बनी थी जिसने देशकी पूर्ण स्वाधीनता और कर्मचारियोंके लिए अधिक वेतनका नारा देकर देशव्यापी हड़ताल करना चाहा था ।

समझौतेकी जो बातचीत इंग्लैण्ड और मिस्रके बीच चल रही थी वह फिलहाल बन्द हो गयी है । सुदानके सवालपर कोई समझौता नहीं हो सका है । वफदका इतना जोर है कि पूँजीपतियोंकी पार्टीको इस प्रश्नपर समझौता करनेका साहस नहीं होता । सिद्दीकी

पासाने गत २८ सितम्बरको त्यागपत्र दे दिया था और नांकराणी पाशाने इस प्रश्नको यू० एन० ओ० के सम्मुख पेश करनेका निश्चय किया है। यदि इनको अब अंग्रेजोंके लिए वफ्दका भय न हो तो शायद यह इस प्रश्नपर समझौता कर लेते। एक ही रास्ता है कि वफ्दके नेता नहास पाशासे बातचीत करें। यह तो स्पष्ट है कि उनको अपनी शर्तें कुछ बदलनी होगी। वफ्दके नेताओंको ऐसा कोई भय नहीं है जैसा कि नांकराणी पाशाको था। इनको तो अपने वामपक्षसे भय है किन्तु अभी कदाचित् 'वफ्द' के दक्षिणपक्षी नेता अपने अनुयायियोंको अपने साथ कुछ दिन और रख सकें यदि अंग्रेज इनको पहलेकी अपेक्षा अच्छी शर्तें दे सकें।

सुदानको मिस्रमें अंग्रेज मिलाना नहीं चाहते। किन्तु यदि मिस्रसे कोई समझौता होना है तो सुदान-सम्बन्धी नीतिमें कुछ-न-कुछ परिवर्तन करना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि कुछ महीने पहले अंग्रेजोंकी ओरसे निम्नलिखित शर्तें नहासको दी गयी थी— (१) अंग्रेजी सेना दो वर्षमें मिस्रको खाली कर देगी, (२) रक्षाके लिए अंग्रेज और मिस्रियोंका एक सम्मिलित बोर्ड होगा, (३) उत्तरी सुदान मिस्रका प्रभावक्षेत्र होगा और दक्षिणी सुदान अंग्रेजोंका। पता नहीं कि यह समाचार कहाँतक सत्य है। किन्तु यदि ऐसी कोई बातचीत हुई है तो यह नहीं मालूम है कि नहासने इसका क्या उत्तर दिया। वह भी अपने वामपक्षसे भयभीत होंगे। जिस आधारपर मिस्रका अंग्रेजोंसे समझौता हो यह स्पष्ट है कि वह तभी स्थायी हो सकता है जब 'वफ्द' उसको स्वीकार करे। यदि 'वफ्द' का अंग्रेजोंसे कोई समझौता हुआ जो 'वफ्द'के वामपक्षको स्वीकार नहीं है तब 'वफ्द' पार्टी में भेद होनेका भय है। हो सकता है कि उस समय वफ्दके दो टुकड़े हो जायें और उसके वामपक्षका स्वतन्त्र संगठन हो। किन्तु आजकी अनिश्चित अवस्थामें कुछ कहा नहीं जा सकता। आनेवाले महीनेमें स्थिति स्पष्ट होगी जब अंग्रेज 'वफ्द' के नेताओंसे बातचीत करेंगे।'

फिलिस्तीन और भारत

फिलिस्तीनमें यहूदियों और अरबोंका झगड़ा एक अरसेसे चल रहा है। दोनों ओरके विप्लवकारियोंने फौजी संगठन तैयार किये हैं। इनमें यहूदियोंके संगठन अधिक मजबूत और कार्यकुशल हैं। यहूदियोंके संगठनोंके नाम Irgun और Noganab हैं। अरबोंने इनके जवाबमें दो संगठन तैयार किये हैं, यह 'निजात' और 'फतवा' नामसे प्रसिद्ध हैं। दोनों संगठनोंमें कुल मिलाकर मुश्किलसे १०,००० नवयुवक होंगे। इनके पास हथियार हैं और यह फौजी वर्दी खुलेआम पहनते हैं, यद्यपि कानूनके अनुसार फिलिस्तीनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकता जिसके सम्बन्धमें विदेशी वर्दी होनेका शक किया जा सके। एक दूसरे कानूनके अनुसार विना लिखित आज्ञाके कोई भी व्यक्ति खुलेतौरपर ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहन सकता और ऐसा कोई विशिष्ट चिह्न धारण नहीं कर सकता जो

यह सूचित करता हो कि वह व्यक्ति किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठनका सदस्य है । किन्तु इन संगठनोंके नवयुवक एक राजनीतिक संस्थाके सदस्य हैं और जो वर्दी यह धारण करते हैं वह अमेरिकनोकी वर्दी है । आश्चर्य है कि इनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती । एक अधिकारीने प्रेस कान्फरेन्समें कहा था कि हार्ड कमिशनर इस कानूनको अभी लागू नहीं करना चाहते । अधिकारियोंके इस आचरणसे अनेक प्रकारके सन्देह होते हैं । समझदार लोगोका ख्याल है कि इन संगठनोको कानूनकी अवहेलना इसलिए करने दिया जाता है, क्योंकि फिलिस्तीनके अधिकारी चाहते हैं कि अरब-यहूदियोंका झगड़ा चलता रहे और अरबोंमें सार्वजनिक आन्दोलन वामपक्षी न होने पावे । इस सन्देहकी पुष्टि एक और बातसे भी होती है । 'फतवा' नामक संगठनका अध्यक्ष पहले सी० आई० डी० का इन्स्पेक्टर था और उसका पिता पुलिसका कर्मचारी है । मुफतीका भतीजा, जमाल हुसैनी, जो हालमें यहूदियोंद्वारा मार डाला गया है, 'फतवा' का संस्थापक था । युद्धकालमें वह रोडीशियामें नजरबन्द था और जबसे वह वापिस आया, निरन्तर यहूदियोंका विरोध करता रहा और ब्रिटिश नीतिका विरोध करना उसने एक प्रकारसे छोड़ दिया था । यह काफी सन्देह उत्पन्न करनेवाली बात थी और राष्ट्रीय नवयुवक उसके सम्बन्धमें यह धारणा बनाने लग गये थे कि वह यहूदियोंके विरुद्ध अंग्रेजोंसे मित्रता करना चाहता था । स्वयं मुफतीके सम्बन्धमें इस प्रकारका सन्देह किया जाने लगा है और अबके जिम्मेदार अरबोंका यह विश्वास है कि चूँकि मुफती सोवियत रूसका विरोधी है, अंग्रेज एक दिन सोवियत विरोधी अरब नेताके रूपमें उसका स्वागत करेंगे । इस सम्बन्धमें यह बताया जाता है कि फिलिस्तीनके पोलिटिकल इण्टेलिजेन्स विभागके अफसर पेरिससे मित्र या लेबनन, मुफतीको भगा लाना चाहते थे और यह भी ध्यान देनेकी बात है कि जब मुफती सिकन्दरियामें थे तब उन्होंने केवल टाइम्स पत्रके मध्यपूर्वस्थित सम्वाददातासे मुलाकात की थी । इन सब बातोंके आधारपर कहा जाता है कि मुफतीका अंग्रेजोंके साथ समझौता हो गया है । पता नहीं इसमें कहाँतक असलियत है । किन्तु एक बात निर्विवाद है कि अंग्रेज इन फौजी संगठनोंके विरुद्ध कार्यवाही न करके अरब-यहूदी झगड़ोंको उत्तेजना देना चाहते हैं । यह नीति ऐसी खुली है कि शकाका कोई स्थल नहीं है । यह भी सत्य है कि साम्प्रदायिक झगड़ोंको उत्तेजना देनेसे सार्वजनिक आन्दोलनका रूप बदलने लगता है तथा क्रान्तिकारी चेतना और भावनाकी वृद्धि नहीं हो पाती । इससे प्रगतिशील शक्तियोंकी गति अवरोध हो जाती है, जो नि सन्देह अधिकारियोंके लिए लाभकारी है । फिलिस्तीनका उदाहरण बताता है कि कुछ ऐसी ही बात हमारे देशमें भी हो रही है । सन् १९३६ में हमारे प्रान्तमें खाकसारोकी वर्दी पहनकर और बेलचा लेकर आम सड़कोपर कवायद करनेसे रोक नहीं जाता था, जब कि कांग्रेसके स्वयंसेवकोंके विरुद्ध ऐसा ही काम करनेपर कानूनी कार्यवाही की जाती थी, हम यह देख चुके हैं । आज जो हिन्दू-मुसलिम दगे बड़े पैमानेपर हो रहे हैं इसमें विदेशियोंका छिपा हाथ हो तो हमको आश्चर्य न होगा । मुसलिम लीगकी नीतिको देखते हुए यही कहना होगा कि उनका नेशनलगार्ड महज सामान्य स्वयंसेवकोंकी जमात नहीं है, उनके कार्यालयमें 'हेल्मट' का पाया जाना इस बात का प्रमाण

है कि इन स्वयंसेवकोंको फौजी शिक्षा दी जाती थी। फिलिस्तीनके ग्ररव संगठन भी बालचर-सस्था होनेका बहाना करते हैं पर वास्तविकता हमसे छिपी नहीं है। आज जब साम्प्रदायिक विद्वेष इतना बढ गया है तब साम्प्रदायिक आधारपर किसी प्रकारका फौजी संगठन होने देना बडा खतरनाक है। हम समझते हैं कि नेशनल गार्ड बनानेकी प्रेरणा लीगको फिलिस्तीनसे मिली है। हिटलरका उदाहरण भी उसके सामने रहा है। फासिस्ट नीतिके अनुसरणका यही परिणाम है, किन्तु यह नीति देशके लिए कितनी घातक है यह हमारे मुसलमान नवयुवक नहीं समझते। उन्हें समझना चाहिये कि अंग्रेजोकी गुलामी एक बहुत बडा अभिशाप है, जिससे छुटकारा पाना हिन्दुओसे लडनेतथा पाकिस्तानकी मांग करनेकी अपेक्षा कही ज्यादा जरूरी है। फिलिस्तीनके नवयुवक इस बातको समझने लगे हैं कि यहूदियोकी अपेक्षा अंग्रेजी राज उनका कही बडा दुश्मन है। काश कि हमारे मुसलिम नवयुवक भी ऐसा समझते।

ईराकके राजनीतिक दल और उनकी स्थिति

गत महायुद्धमे ईराकके शासनने जनताकी राजनीतिक प्रवृत्तिपर नियन्त्रण लगा दिया था। किन्तु लोकतन्त्रकी सर्वत्र चर्चा होनेके कारण तथा मित्रराष्ट्रोकी विविध घोषणाओके फलस्वरूप जनताकी, विशेषकर नवयुवकोकी, राजनीतिक चेतनामे असाधारण वृद्धि हुई थी। युद्धके समाप्त होनेपर इंग्लैण्डमे साधारण चुनाव हुआ और इसमे मजदूर दलकी विजय हुई। इस विजयसे ईराककी जनताको प्रेरणा मिली और उसको अपने भविष्यके सम्बन्धमें आशा बैधी। किन्तु ईराककी हुकमतने जनतान्त्रिक स्वतन्त्रता प्रदान करनेके लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब कि जनता निराश हो रही थी अकस्मात् रिजेण्ट अब्दुल इलाहने गत वर्ष यह घोषित किया कि यदि षड्यन्त्रोको रोकना है तो लोकतन्त्रात्मक शासनकी स्थापना करनी होगी। इस घोषणाको कार्यान्वित करनेके लिए रिजेण्टने सर्वसाधारणको राजनीतिक दलोमे संगठित करनेकी स्वतन्त्रता प्रदान की और इस बातका आश्वासन दिया कि इस कार्यमें राज्यकी ओरसे कोई बाधा नहीं उपस्थित की जायगी। रिजेण्टने अपना यह मन्तव्य भी प्रकाशित किया कि उनकी इच्छा है कि गवर्नमेण्टका जल्द-से-जल्द चुनाव हो जिसमे आर्थिक सुधार किये जा सकें और सामाजिक न्याय हो सके। जिस समय यह घोषणा हुई थी उस समय ऐजरबैजामे विद्रोह हो रहा था। बहुतसे लोगोको ऐसा सन्देह था कि ईराककी जनताकी बढ़ती हुई बेचैनीको रोकनेके लिए ही यह चाल चली गयी थी। शीघ्र ही इस सन्देहकी पुष्टि हुई, क्योंकि गवर्नमेण्टकी ओरसे युद्ध कालीन असाधारण कानून रह नहीं किये गये, राजनीतिक दलोपर लगायी गयी रोक वैसी ही कायम रही और गवर्नमेण्टका नया चुनाव भी नहीं हुआ। यह अवस्था ऐजरबैजामे के विद्रोहके समाप्त होनेके ६ महीने बादतक कायम रही।

३० जून सन् १९४६ को गवर्नमेण्टने त्यागपत्र दे दिया और तौफीक अल सुवैदीने नया मन्त्रिमण्डल स्थापित किया। नये शासनने युद्धकालीन असाधारण कानूनको रद्द कर दिया, राजनीतिक दलोपरसे रोक उठा ली और प्रेसको स्वतन्त्रता दे दी। इसका फल यह हुआ कि ईराकमे ५ दल संगठित हुए। दक्षिण पक्षमे इण्डिपेन्डेन्स पार्टी है, जिसके प्रमुख सदस्य वह लोग हैं जो नाजियोसे सहानुभूति रखनेके कारण युद्धकालमे नजरबन्द कर लिये गये थे।

मध्यमे लिबरल पार्टी है और इसमे गवर्नमेण्टके समर्थक सम्मिलित हैं। वामपक्षकी पार्टियोंमे 'नेशनल डिमाक्रेटिक पार्टी,' 'नेशनल युनियनपार्टी' और 'पीपुल्स पार्टी' के नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं, इन पार्टियोंके कार्यक्रम लोकतन्त्रके सिद्धान्तोपर आश्रित हैं। यह सब दल आर्थिक विकासके लिए योजनाकी आवश्यकताको स्वीकार करते हैं। सब ईराकसे विदेशी सेनाओंके हटानेकी मांग पेश करते हैं और सभी फिलिस्तीनमे एक स्वतन्त्र अरब राज्य देखना चाहते हैं। राजनीतिक दृष्टिसे ही ये दल वामपक्षीय हैं, क्योंकि आर्थिक क्षेत्रमे ये जमीनके राष्ट्रीयकरणका समर्थन नहीं करते, उल्टे व्यक्तिगत सम्पत्तिकी रक्षा करना चाहते हैं। इनमें जो अन्तर है वह लक्ष्यप्राप्तिके उपायोंके सम्बन्धमे है। कम्युनिस्ट पार्टीका सगठन करनेकी राज्यने आज्ञा नहीं दी।

इन प्रगतिशील पार्टियोंके अपने-अपने दैनिक पत्र थे जिनमे यह निरन्तर ईराकके विधानको यथार्थ रूपमे कार्यान्वित करनेपर जोर देते थे और जनताके चुने हुए प्रतिनिधियोंके शासनकी मांग पेश करते थे। इससे प्रतित्रियावादी-वर्ग भयभीत हो गया और उसने सुवैदी गवर्नमेण्टके विरुद्ध षड्यन्त्र रचना आरम्भ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि ३० मई सन् ४६ को कुछ व्यक्तियोंने अरशद अल उमरीके नेतृत्वमे नयी गवर्नमेण्ट कायम की। उमरीने इस बातकी घोषणा की कि उसकी गवर्नमेण्ट किसी दलविशेषकी गवर्नमेण्ट नहीं है और वह केवल नये चुनाव करानेके लिए शासनारूढ हुई है।

किन्तु थोड़े समयमे ही यह बात स्पष्ट हो गयी कि वह किसी-न-किसी वहानेसे प्रगतिशील दलो और उनके पत्रोपर प्रहार करना चाहता था। बगदादके गोलीकाण्डके पश्चात् गवर्नमेण्टका इन दलोके साथ सघर्ष और तीव्र हो गया। इनके अनेक सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये और पार्टियोंके सगठित होनेमे तरह-तरहकी बाधाएँ उपस्थित की जाने लगीं। प्रगतिशील देशोंको दवानेकी चेष्टाएँ होने लगीं। 'नेशनल डिमाक्रेटिक पार्टी' के नेतापर मुकदमा चलाया गया और उनको जेलकी सजा दी गयी। पार्टीका मुखपत्र भी बन्द कर दिया गया। तदनन्तर नेशनल युनियन पार्टीके चार सदस्य गिरफ्तार किये गये और उसके मुखपत्रका प्रकाशित होना बन्द हो गया। ईराकके विधानके अनुसार शासन नहीं हो रहा है। बिना उचित कारणके लोग पकड़ लिये जाते हैं, लोकमत दबाया जाता है और वैधानिक उपायोंका अवलम्बन करनेसे विविध राजनीतिक दल रोके जाते हैं। जिस गवर्नमेण्टने शासनारूढ होनेपर यह घोषणा की थी कि वह पार्लमेण्टको भंग कर नया चुनाव करानेके लिए आयी है वही गवर्नमेण्ट चुनाव कराना तो दूर रहा, आज निरकुश शासन कर रही है और जनतापर अत्याचार करती है। इस स्थितिसे

ऐसे लोगोंको प्रोत्साहन मिलता है जो अवैधानिक तरीकोंसे काम लेना चाहते हैं। ईराकका विधान लोकतन्त्रात्मक है और यदि उसके अनुसार कार्य किया जाय, तो समाजकी उन्नति हो सकती है। किन्तु आज ईराकका मुख्य प्रश्न यह है कि विधानकी रक्षा होगी या नहीं।

प्रश्न यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इस स्थितिके लिए कहाँतक उत्तरदायी है। ईराककी स्वतन्त्रता नाममात्रकी है। ईराकके साथ अंग्रेजोंकी जो सन्धि सन् १९३२ में हुई थी, उसके द्वारा अंग्रेजोंने कई अधिकार अपने हाथमें रख लिये थे। युद्धकालमें उनका प्रभाव और बढ़ गया था। अंग्रेज नहीं चाहते कि ईराककी जनताके लाभके लिए राज्यकी ओरसे सुधार किये जायँ। लोगोंका विश्वास है कि वर्तमान शासकोंको ब्रिटेनका समर्थन प्राप्त है। लोगोंका यह भी कहना है कि उसीके इशारेपर आज ईराकमें लोकमत दबाया जा रहा है और नागरिक स्वतन्त्रताका अपहरण हो रहा है। यह अवस्था प्रायः सभी अरब देशोंमें पायी जाती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि सोवियत रूसके प्रभावको घटानेके लिए तथा अपनी फिलिस्तीन सम्बन्धी नीतिके विरोधको रोकनेके लिए ब्रिटिश हुकूमत इस सामान्य नीतिको बरत रही है।^१

एशियाई सम्मेलन

अभी दिल्लीमें एशियाई सम्मेलनका जो प्रथम अधिवेशन समाप्त हुआ है, वह बड़े महत्त्वका है। इस सम्मेलनको आशातीत सफलता प्राप्त हुई है, यह बात सभीने मुक्त कण्ठसे स्वीकार की है। इसका आयोजन 'इण्डियन काउंसिल आव् वर्ल्ड अफेयर्स' ने किया था। इस सस्थाका उद्देश्य भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओंका अध्ययन करना है। एशियाके देशोंकी ऐसी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओंपर विचार करनेके लिए यह सम्मेलन आमन्त्रित किया गया था, जो सबको सामान्य है। इस प्रकार विवादग्रस्त विषयोंपर इस सम्मेलनमें विचार नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त सम्मेलन बुलानेमें एक उद्देश्य यह था कि उन उपायों और साधनों का अध्ययन किया जाय, जिनके द्वारा एशियाके विविध देशोंके बीच निकटका सम्बन्ध स्थापित हो सके।

सम्मेलनमें एशियाके सभी देशोंसे प्रतिनिधि बुलाये गये थे। इनमें मध्य एशियाके सोवियत रिपब्लिक, जापान, कोरिया और आउटर मंगोलिया भी शामिल थे। प्रायः सभी देशोंके प्रतिनिधियोंने सम्मेलनमें भाग लिया था। खेद है कि जापानको अपने प्रतिनिधि भेजनेकी सुविधा नहीं दी गयी। जापानको इस सम्मेलनसे बाहर रखनेकी चेष्टा गरहित है। हम समझते हैं कि जापानको सम्मेलनमें शरीक होने देनेसे लोकतन्त्रको लाभ ही होता। जिस जापानके शासकोंकी महत्त्वाकांक्षा एशियाका अधिनायक बननेकी थी, उस देशके प्रतिनिधि एशियाई सम्मेलनमें दूसरोंसे कोई ऊँचा स्थान नहीं पा सकते थे।

उनको पहली बार बराबरी के दर्जे पर दूसरे प्रतिनिधियों से बातचीत करना पड़ता और उनको यह अनुभव हो जाता कि नवीन एशियामे साम्राज्यवाद और अधिनायकत्वको स्थान नहीं है।

एशिया के विविध देशों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया से तथा इंग्लैण्ड से 'इन्स्टीट्यूट ऑफ़ इण्टरनेशनल अफेयर्स' ('Institute of International Affairs') की ओर से तथा न्यूयार्क के 'इन्स्टीट्यूट ऑफ़ पैसिफिक रिलेशन्स' ('Institute of Pacific Relations') की ओर से दर्शक आये थे।

पहले दिन सम्मेलन का खुला इजलास बड़े समारोह के साथ हुआ। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने सभानेत्री का आसन ग्रहण किया तथा पं० जवाहरलाल नेहरू ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रत्येक देश के प्रतिनिधिमण्डल के नेताने अपने-अपने देश की ओर से सन्देश पढ़ा, जिसमे सम्मेलन का स्वागत किया गया था। खुले इजलास के समाप्त होने पर निम्नलिखित प्रश्नोपर विचार करने के लिए विविध कमेटियों का संगठन किया गया—

१. एशिया के राष्ट्रीय आन्दोलन।
२. जातिगत (racial) समस्याएँ, विशेष रूप से जातीय संघर्ष का प्रश्न।
३. प्रवास की समस्या और प्रवासियों के साथ व्यवहार और उनकी स्थितिका प्रश्न।
४. औपनिवेशिक अर्थनीति से राष्ट्रीय अर्थनीति में सक्रमण।
५. एशिया के देशों का औद्योगिक विकास और कृषिका पुनर्निर्माण।
६. एशिया के मजदूरों की समस्या और सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था।
७. एशिया की सांस्कृतिक समस्याएँ विशेष रूप से शिक्षा, कला, स्थापत्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान और साहित्य की समस्या।

८. स्त्रियों का समाज में स्थान और एशिया के स्त्री-आन्दोलन।

इन विषयों पर विविध उपसमितियों में विचार किया गया और निबन्ध भी पढ़े गये।

एशिया के विविध देशों के स्वातन्त्र्य-आन्दोलन के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। यह स्पष्ट है कि इस विषय में कुछ अधिक नहीं किया जा सकता था। एक तो सम्मेलन का स्वरूप राजनीतिक नहीं था और उसने राजनीतिक प्रश्नों को छोड़ देने का निश्चय किया था। दूसरे आज की परिस्थिति में सहानुभूति प्रदर्शित करने के अतिरिक्त कुछ विशेष किया नहीं जा सकता। एशियावासियों में आज जो अपूर्ण जागृति देख पड़ रही है उसके कारण तथा मुख्यतः इस कारण कि यूरोप के साम्राज्यवाद ने ही सकल एशिया को अभिमत और त्रस्त किया था एशिया के देशों में परस्पर सहानुभूति पायी जाती है। सम्मेलन ने परस्पर सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का निश्चय कर उस सहयोग और वास्तविक सहानुभूति की नींव डाली है, जिसके आधार पर आगे चलकर राजनीतिक सम्बन्ध भी कायम होंगे।

जातिगत संघर्ष (racial conflict) का प्रश्न भी हमारे लिए कम महत्व का नहीं है। फिलिस्तीन तथा पूर्वी एशिया के देशों में इस प्रश्न का निपटारा शीघ्र हो जाना चाहिये।

फिलिस्तीनके अरब यहूदियोंके प्रवासको कुदृष्टिसे देखते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि फिलिस्तीनमे यहूदी राज्य कायम करनेका यह एक सगठित प्रयत्न है। तुर्कीने इस प्रश्नको सन् १९२४ मे ही हल कर लिया था। पूर्वी एशियाके देशोमें हिन्दुस्तान और चीनके लोग बड़े पैमानेपर बस गये हैं, प्राचीन कालमे इन देशोका सांस्कृतिक सम्बन्ध था, किन्तु पिछले १५० वर्षोंमे जो प्रवास हुआ है, वह प्रधानतः आर्थिक कारणोसे अपढ मजदूरोका हुआ है। यूरोपीय सत्ताने अधीन देशोके आर्थिक साधनोका अपने लाभके लिए उपयोग करनेकी इच्छासे इस प्रस्तावका सदा स्वागत किया है और उसे प्रोत्साहन दिया है। किन्तु आज जब ये देश स्वतन्त्र हो रहे हैं, ये प्रवासी वहाँके निवासियोद्वारा अच्छी दृष्टिसे नही देखे जाते। यह समझा जाता है कि ये वहाँके अधिवासियोकी आर्थिक उन्नतिमे बाधक है।

इस प्रकार जातिगत संघर्ष और विरोध उत्पन्न होता है और इसके मूलमें आर्थिक कारण है। पुनः इन प्रवासियोकी आँखे सदा अपने देशकी ओर लगी रहती हैं और वे उससे अपने अधिकारोकी रक्षा चाहते हैं। उचित तो यह है कि वे जिस देशमे आकर बस गये हैं, उसे ही अपना देश समझे और वहाँकी गवर्नमेण्टसे ही न्यायकी माँग करें। प्रवासियोकी मनोवृत्ति भी अधिकारियोंके विरोधको बढ़ाती है।

आज हम देखते हैं कि यह जातिगत समस्या बर्मा, लका, मलय, श्याम और हिन्द-चीनमे उग्र रूपमे पायी जाती है। इन देशोके अधिवासी हिन्दुस्तानी और चीनियोको बराबरीके अधिकार नही देना चाहते और उनपर कई प्रकारके नियन्त्रण लगाते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिसे जाति-विशुद्धि नामकी कोई वस्तु नही है। सदासे जातियोका सम्मिश्रण होता आया है। यह भी धारणा मिथ्या है कि एक जाति विशिष्ट है और दूसरी निकृष्ट। जो जातिगत विरोध इस समय पाया जाता है, उसका कारण आर्थिक है। किन्तु यह भी सत्य है कि एक जातिके लोग दूसरी जातिके लोगोको अपनेसे निकृष्ट मानते हैं। जातियोके पारस्परिक सम्बन्धका इतिहास जाननेसे तथा निकट सम्पर्कमे आनेसे यह अज्ञान दूर हो जायगा। हमको यह भी स्वीकार करना चाहिये कि किसी देशके निवासियों को प्रवास कर दूसरे देशका आर्थिक शोषण करनेका अधिकार नही है। सम्मेलनका सुझाव है कि सब नागरिकोको कानूनकी दृष्टिमे समान अधिकार मिलने चाहिये, उनको धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये, समाजमे किसी जातीय समूहके साथ भेद-भाव नही होना चाहिये तथा उन सब विदेशियोके साथ समानताका व्यवहार होना चाहिये जो देशमे आकर बस गये हैं। एक प्रस्ताव यह भी किया गया था कि इन सुझावोकी सिफारिश इन देशोकी गवर्नमेण्टको करनी चाहिये और उनसे अनुरोध करना चाहिये कि वे उन्हें कार्यान्वित करें किन्तु सम्मेलनका निर्णय किसी विशेष प्रस्तावके स्वीकार करनेके विरुद्ध था। प्रवासके सम्बन्धमे उपसमितिमे मतभेद था। यद्यपि यह सबको स्वीकार था कि प्रत्येक देशको प्रवासको सीमित करनेका अधिकार है, तथापि सबका समान रूपसे यह मत था कि प्रवास को विलकुल बन्द कर देनेसे आपसका विद्वेष बढ़ेगा। यह भी साधारणतः सबको स्वीकृत था कि एक समयमे कोई व्यक्ति एक ही देशका नागरिक हो सकता है और प्रवासी नागरिक बन जानेपर अपनी मातृभूमिसे रक्षाकी याचना नही कर सकता है।

एक दूसरे महत्त्वका प्रश्न जिसपर उप समितिमे विचार किया गया अर्थनीतिसे सम्बन्ध रखता है। एशियाके विविध देशोमे व्यापारका सम्बन्ध कैसे स्थापित किया जाय ? क्या एशिया आर्थिक दृष्टिसे इकाई माना जा सकता है ? औपनिवेशिक अर्थनीतिसे राष्ट्रीय नीतिमे सक्रमण किस प्रकार हो ? देशके आर्थिक विकासमे विदेशी पूंजीका क्या स्थान होना चाहिये ? इत्यादि प्रश्नोपर उपसमितिने विचार किया। उपसमितिकी रायमे कुछ विशेष शतोंके साथ ही विदेशी पूंजीका उपयोग हो सकता है। मुनाफेको सीमित करना तथा गुजारे लायक उचित मजदूरी दिलाना आवश्यक है। उपसमिति रिपोर्टका यह भी कहना है कि विदेशियोंके राजनीतिक प्रभावसे सर्वथा स्वतन्त्र होनेपर ही संक्रमण उचित रूपसे हो सकता है। राष्ट्रीय अर्थनीतिकी प्रतिष्ठाके लिए कृषिकी ढंगसे उन्नति करना, गृह-उद्योगोको वैज्ञानिक ढंगसे संगठित करना, सहयोग-विकास करना, विदेशोसे व्यापार स्थापित करना तथा माल ले जानेके लिए जहाजोका प्रवन्ध करना, गुजारे लायक उचित मजदूरी निश्चित करना, उद्योग-व्यवसायकी उन्नति करना इत्यादि कार्य आवश्यक है। इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिए यह भी आवश्यक समझा गया है कि एशियाके विविध देश आर्थिक नीतिका विकास मिल-जुलकर करे और एक आवाजसे अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओके सामने उसका समर्थन करे।

यह स्वीकार किया गया है कि एशियामे खेती बहुत पिछडी हुई है। कई देशोमें युद्धकालमे जो बरबादी हुई है, उसके कारण नयी समस्याएँ उठ खडी हुई हैं। उपसमितिकी रायमे खेतके पैदावारको बढ़ाना अति आवश्यक है और इसके लिए नवीन उपायो और साधनोसे काम लेना जरूरी है। अच्छा बीज, अच्छी खाद और अच्छे औजारका उपयोग अत्यन्त आवश्यक है। वह भूमि जो ऊसर-बजर पडी है या किसी कारण खेतीके काममे नहीं आ रही है, उसको खेतीके उपयुक्त बनाना चाहिये। कृषिकी उन्नतिमे राज्यका विशेष कर्त्तव्य है। इसके लिए गरीब किसानोकी पूंजीसे सहायता करनी होगी। भारतका व्यापार इस समय विदेशियोंके हाथमे है। इस अप्राकृतिक अवस्थाको बदलना होगा। किसानोकी अवस्थामें सुधार होना भी आवश्यक है। पैदावारकी बिक्रीका ऐसा प्रवन्ध होना चाहिये, जिसमे पूरा मुनाफा किसानोको ही मिले। खेत-मजदूरको भी जमीन दिलानेकी व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध मे फिलिस्तीनकी सामूहिक खेती जो यहूदियोद्वारा कम्प्यूनके अधीन होती है तथा मध्य एशियाके सोवियत रिपब्लिकोकी सामूहिक खेतीकी प्रणाली रिपोर्टमे की गयी है। भूमि-सम्बन्धी मौलिक सुधारोके बिना खेतीकी उन्नति नहीं हो सकती यह बात रिपोर्टमे स्वीकार की गयी है। औद्योगिक विकासके सम्बन्धमे एशियाकी वर्तमान स्थितिका विचार किया गया। उद्योगका विकास एशियामे बहुत कम हुआ है और अवतक ये देश मुख्यतया कच्चा माल बाहर भेजते रहे हैं और तैयार माल बाहरसे मँगाते रहे हैं। इस कारण इसकी अर्थनीति अवतक औपनिवेशिक रही है। एशियाकी स्वतन्त्रताकी रक्षाकी दृष्टिसे भी इस स्थितिको बदलना है। उसी मात्तामे हम अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेमे समर्थ होंगे जिस मात्तामे हम अपना औद्योगिक विकास कर सकते हैं। पूंजीका प्रश्न तथा सामान विशेष महत्त्वका है। ऐसा प्रतीत होता है कि

विकासके लिए विदेशसे पूँजी लेनी पड़ेगी । किन्तु कुछ शर्तोंके साथ ही विदेशी पूँजी लेनी चाहिये जिसमें अपने आर्थिक जीवनपर विदेशियोका नियन्त्रण न हो सके ।

सम्मेलनके कार्यको स्थायी रूप देनेके लिए एक संगठनका निर्माण किया गया है । इसका नाम एशियाई सम्बन्ध संघ होगा और इसके उद्देश्य इस प्रकार होंगे—

(क) समूचे एशिया और संसारके साथ उनके सम्बन्धके दृष्टिकोणसे एशियाई समस्याओंके अध्ययन तथा ज्ञानकी अभिवृद्धिका प्रयत्न ।

(ख) एशियावासियोंमें आपसमें तथा एशिया और शेष संसारके बीचमें मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा सहयोगकी स्थापनाके लिए कार्य ।

(ग) एशियावासियोंकी उन्नति एवं कल्याणके लिए प्रयत्न ।

इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए एक अस्थायी साधारण समितिकी स्थापना की गयी है । एशियाके प्रत्येक देशमें संघकी शाखाएँ होगी । संघकी शाखाओंका रूप गैरसरकारी होगा और उनके उद्देश्य संघसे मिलते-जुलते होंगे । संघ और उसकी शाखाएँ एशियाई तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंका अध्ययन करेगी, किन्तु उनका दल विशेषसे सम्बन्ध न होगा और न वे राजनीतिक प्रचारमें लगेगी ।

सम्मेलनका अगला अधिवेशन चीनमें सन् १९४९ में होगा । इस संगठनके प्रथम सभापति पं० जवाहरलाल नेहरू होंगे ।

यह कहना अत्युक्ति न होगी कि एशियाके लिए यह घटना बड़े महत्त्वकी है । प्राचीन कालमें जब यातायातकी सुविधाएँ न थी भारतवासी अपने पड़ोसी राष्ट्रोंसे सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध रखते थे; एक समय था जब मध्य एशियासे लेकर दक्षिण-पूर्व एशियाके द्वीपोंतक तथा चीन, जापान, कोरिया और मंगोलियामें भारतीय सस्कृतिका प्रचुर प्रसार तथा प्रभाव था । भारतीय भाषा, लिपि, कला, दर्शन और धर्मका अक्षुण्ण प्रभाव इस विशाल भूखण्डपर था । यहाँ एक समय सस्कृतका आधिपत्य था । यह हमारा उज्ज्वल काल था । ६ वी १० वी शतीमें भी जब भारतकी अवनति द्रुतिगतिसे हो रही थी हम अपना सस्कृति-सम्बन्ध चीन, तिब्बत आदि देशोंसे बनाये हुए थे, किन्तु जब रेल, तारकी सुविधाएँ हमको प्राप्त हुई, हमारा यह पुराना सम्बन्ध छिन्न-भिन्न हो गया है । आज हम अपने पड़ोसियोंके सम्बन्धमें बहुत कम जानकारी रखते हैं । आज यूरोपका हमारे जीवनपर प्रभुत्व पाया जाता है । उसकी पूँजीवादी, अर्थनीति ससारपर छायी हुई है । उसकी विचारधारा और उसका इतिहास हमको विशेषरूपसे प्रभावित करता है । इस अप्राकृतिक स्थितिको बदलनेकी चेष्टा दो बार पहले भी कांग्रेसके नेताओंद्वारा की गयी थी, पर यह सब प्रयत्न विदेशी गवर्नमेण्टने व्यर्थ कर दिये ।

किन्तु अब एशियाके लोगोंको दबाकर नहीं रखा जा सकता । यह शुभ प्रयत्न शुभ घड़ीमें हो रहा है । सम्मेलनका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि यह हमारी एक बड़ी आवश्यकताकी पूर्ति करता है । हम आशा करते हैं कि एशियाके सब देशोंके सम्मिलित उद्योगसे हमारा वह पुराना सम्बन्ध फिरसे जीवन्त स्थापित होगा और एशियावासी ससारको एक नया

मार्ग दिखावेगे जिससे संसारका व्यथित हृदय शान्ति प्राप्त करेगा और राष्ट्र-राष्ट्रके बीच सौहार्द तथा भ्रातृत्वका सम्बन्ध स्थापित होगा ।'

हिन्द चीन और कम्युनिस्ट पार्टी

‘न्यूज वीक’ नामक अमेरिकन पत्रके युद्ध-सम्वाददाता श्री हेरल्ड आइजैक्स (Harold Isaacs) सन् १९४५ में हिन्द-चीन गये थे । उनकी लिखी हुई ‘नो पीस फार एशिया’ नामक पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, इसमें उन्होंने हिन्द-चीनके स्वतन्त्रता-संग्रामका रोचक वर्णन दिया है । लेखकका कहना है कि “वियत नाम’ रिपब्लिक फ्रेंच साम्राज्यवादके मुकाबलेमें कमजोर है, क्योंकि वह विलकुल अकेली पड़ गयी है । उसके पीछे जनताकी शक्ति अवश्य है और वह स्वतन्त्र होनेका दृढ़ निश्चय रखती है तथा उसको इसका दृढ़ विश्वास है कि उसका पक्ष न्यायसंगत है । यह जनताकी बहुमूल्य सम्पत्ति है, किन्तु आजके राजनीतिक बाजारमें इससे कुछ खरीदा नहीं जा सकता ।” ‘वियत नाम’ का काम केवल स्वतन्त्रताकी प्राप्तिसे नहीं चल सकता । उसको दूसरोंकी सहायताकी आवश्यकता है । उसको एक ऐसे संसारका अंग बनना पड़ेगा जो उसको अपनी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए अपने साधनका पुनः संगठन करने दे । यदि ऐसा संसार उसको नहीं मिलता तो कमसे कम कोई ऐसा शक्तिशाली मित्र तो हो जिसपर वह भरोसा कर सके ।

“चीनियोंपर तो अब वह भरोसा कर नहीं सकता । रूसियोंका क्या हाल है ? क्या वह हिन्द-चीनको राजनीतिक सहायता पहुँचावेगे, मुझे तो कोई ऐसा अनम-निवासी (Annamite) नहीं मिला जिसका ऐसा विचार हो । मैं अनेक कम्युनिस्टोंसे भी मिला । यह भी अपने साथी राष्ट्रवादियोंकी तरह ही निराश ही थे । रूसियोंके सम्बन्धमें वह अपने विचार निःसंकोच होकर प्रकट करते थे, उनमेंसे जो बड़े कट्टर किस्मके कम्युनिस्ट थे वह भी, जैसे ड्रान वान गिआओ (Dran Van Giau), यह स्वीकार करते थे कि रूसियोंने अपने सिद्धान्तों और विचारोंके मामलेमें बहुत ज्यादा ढील दे दी है और समझौते किये हैं । ड्रानका कहना था कि रूसियोंसे अनमको किसी प्रकारकी सहायताकी आशा न रखनी चाहिये । एक-दूसरे अनम-निवासी कम्युनिस्टने कुछ कटुताके साथ यह कहा कि ‘रूसी सबसे पहले और सर्वोपरि रूसी राष्ट्रवादी हैं । वह हममें तभी दिलचस्पी लेंगे जब हमसे उनका कुछ काम निकले । हमारा यह दुर्भाग्य है कि तत्काल हमसे उनका कुछ काम नहीं निकलता ।’

“मैंने उससे पूछा कि फ्रांसीसी कम्युनिस्टोंका क्या हाल है । उसने एक नफरतकी साँस ली और कहा कि फ्रेंच कम्युनिस्ट पहले फ्रांसीसी हैं और उपनिवेशोंपर फ्रेंच-शासन बनाये रखनेके पक्षमें हैं और पीछे कम्युनिस्ट हैं । सिद्धान्त रूपमें वह हमारे पक्षका समर्थन

करते हैं, किन्तु व्यवहार में कुछ और ही है । अनमके एक चोटीके कम्युनिस्ट नेताने थोरे (Thorez—फ्रेच कम्युनिस्ट पार्टीका नेता) के सम्बन्धमें हिकारतसे यह कहा कि वह इस पक्षमें है कि अनम-निवासी अन्तमें अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करे (“finally arrive at their independence”), वह कुछ कर हँसा और उसने कहा कि क्या अच्छा खबड़दार लचीला वाक्य है । आप इसे कोई आकार दे सकते हैं और इसका कोई अर्थ कर सकते हैं । हम इन सज्जनोपर निर्भर नहीं कर सकते । इस समय फ्रांसमें इनकी पार्टी सबसे अधिक प्रभावशाली है, किन्तु देखिये फ्रांसीसी इस समय हिन्द-चीनमें क्या कर रहे हैं ।” ...“हिन्द चीनमें मुट्ठीभर फ्रेच कम्युनिस्ट हैं, सैगो (Saigon) में केवल २० थे । मेरे अनमनिवासी कम्युनिस्ट मित्रने मुझे बताया कि इसमेंसे केवल एक उनके साथ सहयोग करता था । शेष तटस्थ रहे, इन फ्रेच कम्युनिस्टोंने हिन्द-चीनकी कम्युनिस्ट पार्टीके लिए एक पत्र तैयार किया था । फ्रेचोका नगरपर कब्जा होनेके दो दिन बादका अर्थात् २५ सितम्बर-का, यह पत्र था, मैं इस पत्रको पढ पाया था, किन्तु इसकी नकल न रख सका । मैंने उससे नोट ले लिये थे । इस पत्रका आशय इस प्रकारका था :—“इस पत्रमें अनम-निवासी कम्युनिस्टोको यह सलाह दी गयी थी कि पूर्व इसके कि वह जल्दीमें कुछ करें उनको चाहिये कि यह निश्चय कर ले कि, उनका संघर्ष ‘सोवियत नीतिकी आवश्यकताओंको पूरा करता है या नहीं ? इस पत्रने साथ-साथ उनको चेतावनी दी कि अन्य देशकी स्वतन्त्रताके लिए ‘समयसे पूर्व जो कार्यवाही’ होगी वह कदाचित् ‘सोवियत की योजनाके अनुकूल न हो ।’ सोवियतकी योजनामें यह हो सकता है कि वह फ्रांसको अपना पक्का दोस्त बनाना चाहता है और उस अवस्थामें अनमका स्वतन्त्रताका आन्दोलन इस योजनाकी सफलतामें बाधक होगा । इसीलिए फ्रेच कम्युनिस्टोंने धैर्य रखनेकी नीतिका अनुसरण करनेको कहा था ।”

पुस्तकके ये उद्धरण इस बातका ताजा प्रमाण पेश करते हैं कि सोवियत रूसकी वैदेशिक नीतिको कार्यान्वित करनेके लिए ही कम्युनिस्ट पार्टियोंका उपयोग किया जाता है । यह प्रसन्नताकी बात है कि हिन्दचीनमें जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी फ्रांसपर भी है । वह इससे नहीं बरी किये जा सकते । उनका गवर्नमेण्टमें होते हुए केवल तटस्थ रहना पर्याप्त नहीं है । फ्रांसके कम्युनिस्टोकी इसमें दोहरी चाल है । एक तो यह कि इस प्रकार वह सोवियत रूसकी वैदेशिक नीतिके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते और रूसको सन्तुष्ट रखते हैं, दूसरे वह अपने देशके अन्य दलोंके मुकाबलेमें अपनेको समान रूपसे राष्ट्रवादी सिद्ध करना चाहते हैं, यह लोग भी साम्राज्यवादी भावनासे सर्वथा मुक्त नहीं हैं ।

फ्रेच कम्युनिस्ट यदि हिन्द-चीनकी कोई सहायता नहीं कर सकते तो न करें, किन्तु हिन्द-चीनवासियोंको भुलावेमें लाना और उनपर यह दवाव डालना कि सोवियत रूसके हितोंकी रक्षाके लिए उनको स्वतन्त्रताके आन्दोलनको स्थगित करना चाहिये सर्वथा अनुचित है ।

ऐसा मालूम पड़ता है कि जबतक एशियाके सब देश स्वतन्त्र नहीं हो जाते तबतक

यूरोपके देशोंकी समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियोंके साथ हमारा सहयोग नहीं हो सकता । इसका कारण यह है कि यूरोपकी यह विधि पार्टियाँ या तो सोवियत रूसके आदेशपर काम करती हैं या स्वयं अपने-अपने साम्राज्यका सर्वथा परित्याग करनेके लिए तैयार नहीं हैं । एशियाके जो देश आज अपनी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रहे हैं, उन देशोंकी समाजवादी पार्टियोंका एक सम्मेलन होना आवश्यक है । इससे एक दूसरेको प्रोत्साहन और बल मिलेगा । इस सम्मेलनमें सबके स्वार्थ और हित परस्पर-विरोधी न होंगे और न कोई एक पार्टी दूसरेको दवा सकेगी, जिनके उद्देश्य और हित समान हैं, जिनकी विचार-धारा एक है और जो एक दूसरेके साथ समानताका व्यवहार करनेको तैयार हैं, उन्हींका एक सम्मेलन होना चाहिये । हिन्द-चीनकी अवस्थाने ऐसे सम्मेलनकी आवश्यकताको और भी महत्व दे दिया है । हम अकेले हैं, हमारा कोई साथी नहीं है, यह भाव हिन्द-चीनके समाजवादी नेताओंके दिलसे दूर कर देना चाहिये, एशियाई कानफरेन्सके अवसरपर इसकी कुछ चर्चा हुई थी । हम आशा करते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी एशियाके समाजवादियोंका सम्मेलन बुलानेकी आयोजना करेगी ।^१

अमेरिकाका नया साम्राज्यवाद

प्रेसिडेंट ट्रुमन (Truman) की नीति एक नये साम्राज्यका निर्माण करना है और वह इस साम्राज्यकी सीमाएँ ऐसी चाहते हैं जिनसे मध्यपूर्वका तेल अमेरिकाके लिए सुरक्षित रहे । वह देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यका अन्त हो रहा है और भविष्यमें ब्रिटेन प्रथम श्रेणीकी शक्ति नहीं रह जायगा । जिन जगहोंको ब्रिटेन खाली कर रहा है उनको अमेरिका भरना चाहता है । अमेरिकाको भय है कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो इन स्थानोंमें सोवियत प्रभाव बढ़ेगा । अतः ब्रिटेन भूमध्यसागरकी एक शक्ति रहा है । अब अमेरिका उसका स्थान ले रहा है । मध्यपूर्वके तेलके चश्मोपर अमेरिकाकी नजर है । ईरानसे लेकर फिलिस्तीनके बन्दरगाहोंतक तेलका विस्तृत क्षेत्र है । इसका अमेरिकाके लिए बड़ा महत्व है । इसके लिए अमेरिकाको ग्रीसकी राजनीतिमें अपना हाथ रखना पड़ता है । वह रूसको अपना प्रतिद्वन्द्वी समझता है । वह समस्त संसारपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है । साम्राज्यशाही मनोवृत्तिका परितोष थोड़ेसे नहीं होता है । अपनी असीम शक्तकी अमेरिकाको चेतना है । उसने अपनी पुरानी उदासीनताको तिलाञ्जलि दे दी है । जहाँतक अमेरिका और रूसकी विचारवाराका प्रश्न है दोनों एक दूसरेके विरोधी हैं । दोनों राज्योंकी अर्थनीति और समाजनीतिमें आपसका संघर्ष है । अमेरिका सदासे ही 'कम्युनिज्म' का विरोधी रहा है । किन्तु इधर यह विरोध बहुत बढ़ गया है । आज तो प्रेसिडेंट ट्रुमनके हुक्मसे अमेरिकामें सरकारी नौकरियोंसे कम्युनिस्टोंकी छँटनी

हो रही है। सरकारी कर्मचारियों की राज्यनिष्ठा की जाँच हो रही है। जिस संस्था के सम्बन्ध में अटर्नी जनरल यह सम्मति दे कि यह फासिस्ट या कम्युनिस्ट है उस संस्था के सदस्य सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकते। ऐसी संस्थाओं की सूची प्रकाशित नहीं की जायगी और इस प्रकार इन संस्थाओं को अपनी सफाई देने का अवसर नहीं मिलेगा। अमेरिका के बाहर जहाँ कहीं उसको कम्युनिस्टों के प्रभाव के बढ़ने की आशंका होती है वहाँ हस्तक्षेप करना चाहता है। ग्रीस और तुर्की को धन और युद्ध-सामग्री से सहायता देने का यही रहस्य है। चीन में कम्युनिस्टों के भय के कारण ही कुओमिन्ताग को सहायता दी जा रही है। चीन और जापान तो एक प्रकार से उसकी सरहद हैं। इन पर वह किसी की वक्र दृष्टि नहीं वर्दाश कर सकता। पैसिफिक के कई द्वीप उसने प्राप्त कर लिये हैं और इनमें वह अपने फौजी अड्डे बना रहा है। यही क्या, भावी युद्ध में चीन और जापान तक उसके अड्डे बन जायेंगे। अफ्रीका का महाद्वीप भी उसकी नजर से नहीं बच पाया है। इसमें सन्देह नहीं कि 'अमेरिका की शती' का आरम्भ हो गया है। किन्तु यह शती संसार के कल्याण के लिए नहीं होगी। वस्तुतः अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव से संसार का अमंगल ही होगा। आज अमेरिका सर्वत्र प्रतिक्रिया का ही समर्थन कर रहा है। ग्रीस के राजवंश और वहाँ की नृशस और दुराचारी गवर्नमेण्ट की धन और युद्ध-सामग्री से सहायता करना प्रतिक्रिया का समर्थन करना नहीं है तो क्या है? अमेरिका की सहायता से ग्रीस की वह शक्तियाँ और संस्थाएँ जो लोकतन्त्र के पक्ष में हैं शासन को अपने हाथ में ले सकती हैं। किन्तु अमेरिका के नायक इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यह आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना होगा। ग्रीस के उत्तरी भाग में जो विद्रोह हो रहा है उसके दवाने में अमेरिकन विशेषज्ञों की सहायता से ग्रीस की आर्थिक अवस्थामें भी सुधार होगा। किन्तु इन उपायों से लोकतन्त्र को जो क्षति पहुँचेगी उसका अनुमान नहीं किया जा सकता। साथ-साथ कम्युनिस्टों का प्रभाव भी बढ़ेगा। जब राजकी पुलिस और फौज जनता पर अत्याचार करेगी तो निरुपाय होकर जनता उन्हीं कम्युनिस्टों की शरण में जायेगी जिनके प्रभाव को कम करने के लिए इन उपायों का अवलम्ब लिया जा रहा है। अमेरिका की ओर से सबलोग सशंक हो गये हैं और कोई यह विश्वास नहीं करता कि यह सहायता नि स्वार्थ भाव से दी जा रही है। इसलिए जो कोई इस गवर्नमेण्ट का साथ देगा वह जनता का विश्वास खो बैठेगा। उसे लोग 'रायलिस्ट' या फासिस्ट समझेगे। यदि ग्रीस की सहायता करने में कोई राजनीतिक कारण न होता तो अमेरिका युगोस्लाविया की भी अन्न से सहायता करता, पर युगोस्लाविया रूस के प्रभाव में है और इसलिए वह सहायता पाने का अधिकारी नहीं है। पहले युद्ध के बाद भी अमेरिकाने इसी आधार पर यूरोप के देशों को सहायता दी थी और आज अब 'अमेरिका की शती' का सूत्रपात हो गया है तब तो इस आधार पर काम करने का और भी कारण है।

इसी प्रकार अमेरिकाने तुर्की को सहायता का वचन दिया है। वह रूस को भूमध्य-सागर की ओर बढ़ने से रोकना चाहता है। तुर्की का शासन भी लोकतन्त्र के आधार पर नहीं है। वहाँ एक प्रकार का सामन्तशाही अधिनायकत्व है, पर अमेरिकाने ब्रिटेन की

पुरानी नीतिको अपना लिया है और जिस प्रकार ब्रिटेन तुर्कीकी रक्षा रूससे सदा करता आया है, उसी प्रकार आज अमेरिका रूसको डार्डेनेल्ससे दूर रखना चाहता है ।

यह ख्याल किया जाता था कि युद्धके बाद इटलीमें 'वैटिकन' (Vatican) का प्रभाव बहुत घट जायगा । सन् १९२६ के समझौतेके बादसे मुसोलिनीको वैटिकनका समर्थन प्राप्त था । सत्तारके सभी कैथलिक ईसाइयोपर वह भरोसा कर सकता था । किन्तु मुसोलिनीके अन्तके बाद यह आशा की जाती थी कि प्रतिक्रियाके इस गढ़का भी पतन होगा । किन्तु वैटिकनके उत्कर्षको जो तात्कालिक धक्का पहुँचा था उससे वह अपनेको सँभाल सका है और इसका कारण अमेरिका है ।

पोपने अपनी नीतिमें इधर परिवर्तन किया है । शताब्दियोंतक वैटिकनकी नीति यूरोपके कैथलिक देशोंसे ही सम्बन्ध रखती थी । किन्तु आज पोपको यह मालूम पड़ता है कि भविष्यमें प्रोटेस्टेण्ट अमेरिका ही उसका घनिष्ठ मित्र होगा और उससे ही उसको धनकी सहायता प्राप्त होती रहेगी । इसीलिए गत फरवरी मासमें 'कार्डिनलो' के चुनावमें पोपने इटलीके उम्मीदवारोंकी अपेक्षा कर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकाके लोगोंको ही चुना है । इसी प्रकार युगोस्लाविया, रूमानिया और जर्मनीके लिए अमेरिकाके कैथलिक ही 'वैटिकन' के राजदूत चुने गये हैं । यह नीति इस बातको प्रदर्शित करनेके लिए वर्ती गयी है कि वैटिकनकी नीति अमेरिकाकी नीतिसे सम्बद्ध है । इस नीतिका पुरस्कार भी वैटिकनको मिला है । अमेरिकाके राजनीतिज्ञ 'वैटिकन' का समर्थन करते हैं और इटली निवासी यह समझने लगे हैं कि यदि वैटिकनका विरोध किया जायगा तो इटलीको अमेरिकासे आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वत्र अमेरिकाका समर्थन प्रतिगामी शक्तियोंको ही प्राप्त है । फासिस्ट और रायलिस्ट इस नीतिका स्वागत कर रहे हैं और उनको यह आशा हो रही है कि उनके अब अच्छे दिन आनेवाले हैं । किन्तु उदार दल और समाजवादी दल बहुत चिन्तित हैं । जो लोकतन्त्रके समर्थक हैं वह कम्युनिस्टोंकी अपेक्षा कहीं अधिक परेशान हैं । उनका ख्याल है कि इस नये साम्राज्यवादका अर्थ युद्धकी पुनरावृत्ति है । उनका कहना है कि फ्रैंकोके प्रति भी अमेरिकाका रुख बदलेगा । वह यह भी समझते हैं कि यूरोपके ध्वस्त प्रदेशोंकी सहायता राजनीतिक शक्तोंके साथ ही की जायगी । सबसे अधिक भय तो इस बातका है कि यू० एन० ओ० की संस्था निरर्थक हो जायगी । अमेरिका और रूस दोनों इस संस्थाकी तभीतक परवाह करते हैं जबतक उनका इससे काम निकलता है । सामुदायिक सुरक्षाकी कोई प्रणाली बन नहीं पाती । जो गति लीग ऑफ नेशन्सकी हुई वही इसकी भी होनेवाली है । अभी पेरिसमें जो सम्मेलन हुआ था वह विफल हो गया । मिस्टर मार्शलके प्रस्तावको मोशियो मोलोटोवने स्वीकार नहीं किया, किन्तु इंग्लैण्ड और फ्रांसमें समझौता हो गया है और इसी प्रस्तावके अनुसार वह मिलकर कार्य करेंगे । रूस को छोड़कर अन्य यूरोपीय राष्ट्रोंको इनकी ओरसे निमन्त्रण दिया जायगा और शीघ्र ही इनका एक सम्मेलन पेरिसमें होगा । यू० एन० ओ० दो भागोंमें विभक्त हो रहा है और

प्रत्येक भाग अपने ढंगसे काम करना चाहता है । ऐसी अवस्थामें जिस उद्देश्यसे यह संगठन बनाया गया था वह विफल हो रहा है ।

यद्यपि ब्रिटेनमें मजदूर पार्टीकी गवर्नमेण्ट है और वह साम्राज्यका परित्याग करता जाता है, तथापि उसका जो सम्बन्ध रूससे है और रूसका जो सम्बन्ध अमेरिकासे है उसके कारण वह भी मध्यपूर्वपर दाँत लगाये बैठा है । जब ब्रिटेन मिस्र और भारतको छोड़ रहा है और जर्मनी और जापान बहुत समयके लिए पंगु हो गये हैं तब भूमध्यसागरपर अपना नियन्त्रण कायम रखनेका प्रयत्न करना कुछ समझमें नहीं आता । इसका एक ही कारण हो सकता है और वह यह कि ब्रिटेन इस क्षेत्रमें रूसको घुसने देना नहीं चाहता । इसीलिए अंग्रेज ग्रीस नहीं छोड़ते और अरब लीग ऐसी प्रतिगामी संस्थाका संरक्षण करते हैं । ईराक, शाम और नज्दमें अंग्रेज अरब जमीनारोंका साथ दे रहे हैं और डल्ल सऊदको वार्षिक रकम देते हैं ।

बताया जाता है कि ट्रूमैनका नया सिद्धान्त अमेरिकाकी जीवनप्रणालीकी रक्षाके लिए है और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि इस प्रणालीको आज रूससे भय है । किन्तु सत्य तो यह है कि यह सिद्धान्त घातक सिद्ध हो रहा है । यदि अमेरिकाकी जीवन-प्रणालीका आधार लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता है तो अमेरिकाको संसारकी प्रगतिशील शक्तियोंका नेतृत्व करना चाहिये । किन्तु इसके विपरीत हम देखते हैं कि वह सर्वत्र प्रतिक्रियाका समर्थन करता है ।

यदि 'कम्युनिज्म' के विस्तारको रोकना ही उद्देश्य है तो इसका यह तरीका नहीं है । यह मानना पड़ेगा कि आज यूरोप और एशियाके आर्थिक जीवनमें क्रान्ति हो रही है । इसके साथ योग देनेसे, न कि इसका विरोध करनेसे, अमेरिकाका उद्देश्य सफल हो सकता है । किन्तु क्रान्तिसे सहयोग करनेका अर्थ होता है यूरोपमें समाजवादका समर्थन करना और पुराने प्रतिगामी और लोकतन्त्र-विरोधी शासनोंका अन्त करना ।

किन्तु वास्तविकता यह है कि लोकतन्त्र और स्वतन्त्रताके नामपर एक नये साम्राज्यवादका जन्म हो रहा है । युद्धके समाप्त होनेपर सबको अमेरिकासे बड़ी अशांति थी । लोग ममझते थे कि अमेरिकाकी सहायतासे सब जगह लोकतन्त्र शासनकी स्थापना होगी और अटलाण्टिक चार्टरके सिद्धान्तोंके अनुसार काम होगा । किन्तु जब यूरोपके राष्ट्रोंने अपने औपनिवेशिक साम्राज्यकी रक्षाके हेतु एशियामें अपनी सेनाएँ भेजी तो अमेरिकाने इसका विरोध नहीं किया । जर्मनीमें वह नार्जीवादका उन्मूलन न कर सका । उसने यू० एन० आर० आर० ए० में भाग लिया । किन्तु पीछे उसने उसका गला घोट दिया और यूरोपके भूखे-नंगोंकी सहायता इस शर्तके साथ की कि वह उन शासकोंका समर्थन करेंगे जिन्हें अमेरिका पसन्द करता है ।

यू० एन० ओ० का अन्त हो रहा है और संसारकी शान्ति खतरेमें है । संघर्ष अनिवार्य होता जाता है । प्रत्येक युद्धके समय यही कहा जाता है कि यह युद्ध लोकतन्त्रके लिए लड़ा जाता है, किन्तु देखनेमें यही आता है कि प्रत्येक युद्धके पश्चात् नये साम्राज्यवादका

जन्म होता है जो संसारमे शान्ति स्थापित होने नहीं देता । पूंजीवाद किसी-न-किसी अवस्थामे जीवित रहता चला आया है । यदि एक पूंजीवादी राष्ट्रका नाश होता है तो दूसरा बलशाली होकर उसका स्थान लेता है । आज अमेरिकाका नया साम्राज्यवाद आगे आ रहा है । अमेरिका मे भी प्रेसिडेण्टकी नीतिके विरुद्ध आवाज नहीं उठ रही है । यह कुछ कम परेशान करनेवाली बात नहीं है ।^१

આઠવાँ અધ્યાય

સ્ફુટ વિચાર

आठवाँ अध्याय

मेरे संस्मरण

मेरा जन्म सम्वत् १९४६ मे कार्तिक शुक्ल अष्टमीको सीतापुरमे हुआ था । हमलोगोका पैतृक घर फैजावादमे है, किन्तु उस समय मेरे पिता श्री बलदेव प्रसादजी सीतापुरमे बकालत करते थे । हमारे खानदानमे सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करनेवाले व्यक्ति मेरे दादाके छोटे भाई थे । अवधमे अंग्रेजी हुकूमत सन् १८५६ मे कायम हुई । इस कारण अवधमे अंग्रेजी शिक्षाका आरम्भ देरसे हुआ । मेरे बाबाका नाम बा० सोहनलाल था । वह पुराने कैनिङ्ग कालेजमे अध्यापकका कार्य करते थे । उन्होंने मेरे पिता और मेरे ताऊको अंग्रेजीकी शिक्षा दी । पिताजीने कैनिङ्ग कालेजमे एफ० ए० कर बकालतकी परीक्षा पास की थी । आँखोकी बीमारीके कारण वह बी० ए० नहीं कर सके । मेरे बाबा उनको कानूनकी पुस्तके सुनाया करते थे और सुन-सुनकर ही उन्होंने परीक्षाकी तैयारी की थी । बकालत पास करनेपर वह सीतापुरमे मेरे बाबाके शिष्य मुन्शी मुरलीधरजीके साथ बकालत करने लगे । दोनो सगे भाईकी तरह रहते थे । दोनोकी आमदनी और खर्च एक ही जगहसे होते थे । मुन्शीजीके कोई सन्तान न थी । वह अपने भतीजे और मेरे बड़े भाईको पुत्रके समान मानते थे । मेरे जन्मके लगभग दो वर्ष बाद मेरे दादाकी मृत्यु हो जानेके कारण पिताजीको सीतापुर छोड़ना पड़ा और वह फैजावादमे बकालत करने लगे ।

जब वह सीतापुरमे थे, तभी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति शुरू हो गयी थी । किसी संन्यासीके प्रभावमे आनेसे ऐसा हुआ था । वह बड़े दानशील और सात्विक वृत्तिके थे । वेदान्तमे उनकी बड़ी अभिरुचि थी और इस शास्त्रका उनको अच्छा ज्ञान था । संन्यासियोका सत्संग सदा किया करते थे । जिस समय उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उस समय फारसीका प्रचलन था । किन्तु अपनी संस्कृति और धर्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उन्होंने संस्कृतका अभ्यास किया था । वह एक नामी वकील थे । किन्तु बकालतके अतिरिक्त भी उनकी अनेक दिलचस्पियाँ थी । बालकोके लिए उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और फारसीमे पाठ्य पुस्तके लिखी थी । इनके अतिरिक्त उन्होंने कई संग्रह-ग्रन्थ भी प्रकाशित किये थे । अंग्रेजीकी प्राइमर तो उन्होंने मेरे बड़े भाईको पढ़ानेके लिए लिखी थी । मेरा विद्यारम्भ इन्हीं पुस्तकोसे हुआ था । उनको मकान बनाने और बाग लगानेका भी शौक था । हमारे घरपर एक छोटा-सा पुस्तकालय भी था । जब मैं बड़ा हुआ तो गर्मीकी छुट्टियोमे इनकी देख-भाल भी किया करता था । मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मेरे पिताजी धार्मिक थे और इस नाते सनातनधर्मके उपदेशक, संन्यासी और पण्डित मेरे घरपर प्रायः आया करते थे । किन्तु पिताजी कांग्रेस और सोशल कान्फरेन्सके कामोमे भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेते

थे । मेरे प्रथम गुरु थे पण्डित कालीदीन अवस्थी । वह हम भाई-बहनोको हिन्दी, गणित और भूगोल पढाया करते थे । पिताजी मुझे विशेष रूपसे स्नेह करते थे । वह भी मुझे नित्य आध घण्टा पढाया करते थे । मैं उनके साथ प्रायः कचहरी जाया करता था । मुझे याद है कि वह मुझे अपने साथ एक बार दिल्ली ले गये थे । वहाँ भारतधर्म-महामण्डलका अधिवेशन हुआ था । उस अवसरपर पण्डित दीनदयालु शर्माका भाषण सुननेको मिला था । उस समय उसके मूल्यको आँकनेकी मुझमें बुद्धि न थी । केवल इतना याद है कि शर्माजीकी उस समय बड़ी प्रसिद्धि थी ।

मैंने घरपर तुलसीकृत रामायण और समग्र हिन्दी महाभारत पढा । इनके अतिरिक्त वैताल पच्चीसी, सिंहासन, वत्तीसी, सूरसागर आदि पुस्तकें भी पढी । उस समय चन्द्रकान्ताकी बड़ी शोहरत थी । मैंने इस उपन्यासको १६ बार पढा होगा । चन्द्रकान्ता सन्ततिको जो २४ भागमें है, एक बार पढा था । न मालूम कितने लोगोंने चन्द्रकान्ता पढनेके लिए हिन्दी सीखी होगी । उस समय कदाचित् इन्ही पुस्तकोका पठन-पाठन हुआ करता था । १० वर्षकी आयुमें मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । पिताजीके साथ नित्य मैं सन्ध्या-वन्दन और भगवद्गीताका पाठ करता था । एक महाराष्ट्र ब्राह्मण मुझको स्वसर वेदपाठ सिखाते थे और मुझको एक समय रुद्री और सम्पूर्ण गीता कण्ठस्थ थी । मैंने अमरकोश और लघुकौमुदी भी पढी थी । जब मैं १० वर्षका था अर्थात् १८९९ में लखनऊमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ था । पिताजी डेलीगेट थे । मैं भी उनके साथ गया था । उस समय डेलीगेटका 'वैज' होता था कपडेका फूल । मैंने भी दरजीसे वैसा ही एक फूल बनवा लिया और उसको लगाकर अपने चचाजाद भाईके साथ 'विजिटर्स गैलरी' में जा बैठा । उस जमानेमें भाषण अंग्रेजीमें होते थे और यदि हिन्दीमें होते तब भी मैं कुछ ज्यादा न समझ सकता । ऐसी अवस्थामें सिवाय शोर-गुल मचानेके मैं कर ही क्या सकता था । दर्शकोने तंग आकर मुझे डाँटा और पण्डालसे भागकर मैं बाहर चला आया । उस समय मैं कांग्रेसके महत्त्वको क्या समझ सकता था । किन्तु इतना मैं जान सका कि लोकमान्य तिलक, श्री रमेशचन्द्र दत्त और जस्टिस रानाडे देशके बड़े नेताओंमें से हैं । इनका दर्शन मैंने प्रथम बार वही किया । रानाडे महाशयकी तो सन् १९०१ में मृत्यु हो गयी । दत्त महाशयका दर्शन दोबारा सन् १९०६ में कलकत्ता कांग्रेसके अवसरपर हुआ ।

मैं सन् १९०२ में स्कूलमें भरती हुआ । सन् १९०४ या १९०५ में मैंने थोड़ी बंगला सीखी और मेरे अध्यापक मुझको कृत्तिवासकी रामायण सुनाया करते थे । पिताजीका मेरे जीवनपर बड़ा गहरा असर पड़ा । उनकी सदा शिक्षा थी कि नौकरोके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, उनको गाली-गलौज न दो । मैंने इस शिक्षाका सदा पालन किया । विद्यार्थियोंमें सिगरेट पीनेकी बुरी प्रथा उस समय भी थी । एक बार मुझे याद है कि अयोध्यामें कोई मेला था । मैंने गौकिया सिगरेटकी एक डिबिया खरीदी । सिगरेट जलाकर जो पहला कश खींचा तो सर घूमने लगा । इलायची, पान खानेपर तवीयत सँभली । मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग क्यों सिगरेट पीते हैं । मैंने उस दिन से आज तक

सिगरेट नहीं छुप्रा । हाँ, श्वासके कण्टको कम करनेके लिए कभी-कभी स्ट्रैमोनियसके सिगरेट पीने पड़े हैं । मेरे पिताजी सदा आदेश दिया करते थे कि कभी झूठ न बोलना चाहिये । मुझे इस सम्बन्धमें एक घटना याद आती है । मैं बहुत छोटा था । कोई सज्जन मेरे मामूँको पूछते हुए आये । मैं घरके अन्दर गया । मामूँसे कहा कि आपको कोई बाहर बुला रहा है । उन्होंने कहा कि जाकर कह दो कि घरमें नहीं है । मैंने उनसे यह सन्देश ज्यों का-त्यों कह दिया । मेरे मामूँ बहुत नाराज हुए । मैं अपनी सिध्दाईमें यह भी न समझ सका कि मैंने कोई अनुचित काम किया है । इससे कोई यह नतीजा न निकाले कि मैं बड़ा सत्यवादी हूँ । किन्तु इतना सच है कि मैं झूठ कम बोलता हूँ । ऐसा जब कभी होता है तो लज्जित होता हूँ और बहुत देरतक सन्ताप बना रहता है । पिताजीकी शिक्षा चेतावनीका काम करती है । मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मेरे यहाँ अक्सर साधु-संन्यासी और उपदेशक आया करते थे । मेरे पिताके एक स्नेही थे । उनका नाम था पं० माधवप्रसाद मिश्र । वह महीनो हमारे घरपर रहा करते थे । वह बँगला भाषा अच्छी तरह जानते थे । उन्होंने 'देशेर कथा' का हिन्दीमें अनुवाद किया था । यह पुस्तक जल्द कर ली गयी थी । वह हिन्दीके बड़े अच्छे लेखक थे । वह राष्ट्रीय विचारके थे । मैं इनके निकट सम्पर्कमें आया । मेरा घरका नाम 'अविनाशी लाल' था । पुराने परिचित आज भी इसी नामसे पुकारते हैं । मिश्रजीपर बँगला भाषाका अच्छा प्रभाव पड़ा था । उन्होंने हम सब भाइयोंके नाम बदल दिये । उन्होंने ही मेरा नाम 'नरेन्द्रदेव' रखा । सनातन धर्मपर प्रायः व्याख्यान मेरे घरपर हुआ करते थे । सन् १९०६ में जब मैं एण्ट्रेसमें पढ़ता था, स्वामी रामतीर्थका फैजाबाद आना हुआ और वह हमारे अतिथि हुए । उस समय वह केवल दूधपर रहते थे । शहरमें उनका व्याख्यान ब्रह्मचर्यपर हुआ था और दूसरा व्याख्यान वेदान्तपर मेरे घरपर हुआ था । उनके चेहरेपर बड़ा तेज था । उनके व्यक्तित्वका मुझपर बड़ा प्रभाव पड़ा और बादको मैंने उनके ग्रन्थोंका अध्ययन किया । वह हिमालयकी यात्रा करने जा रहे थे । मिश्रजीने उनसे कहा कि संन्यासीको किसी सामग्रीकी क्या आवश्यकता । इतना कहना था कि वह अपना सारा सामान छोड़कर चले गये और पहाड़से उनकी चिट्ठी आयी कि "राम खुश है ।"

हमारे स्कूलमें एक बड़े योग्य शिक्षक थे । उनका नाम था—श्रीदत्तात्रेय भीकाजी राणाडे । उनका मुझपर बड़ा प्रभाव पड़ा । उनके पढ़ानेका ढंग निराला था । उस समय मैं ८ वी कक्षामें था । किन्तु अंग्रेजी व्याकरणमें हमारे दर्जेके विद्यार्थी १० वी कक्षाके विद्यार्थियोंके कान काटते थे । मैं अपनी कक्षामें सर्वप्रथम हुआ करता था । मेरे गुत्जन भी मुझसे प्रसन्न रहा करते थे । किन्तु संस्कृतके पण्डित महाशय अकारण मुझसे और मेरे सहपाठियोंसे नाराज हो गये और उन्होंने वार्षिक परीक्षामें हमलोगोंको फेल करनेका इरादा कर लिया । हमलोग बड़े परेशान हुए । उस समय मेरी कक्षाके अध्यापक मास्टर राघेरमण लाल स्कूल लाइब्रेरीके लाइब्रेरियन थे । इनका भी हमलोगोंपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था । अपने जीवनमें एक बार यह विरक्त हो गये थे । इनके घरपर हमलोग प्रायः जाया करते थे । यह अपने विद्यार्थियोंको बहुत मानते थे । लाइब्रेरीकी कुंजी मेरे

मुपुर्द थी और मैं ही पुस्तकें निकालकर दिया करता था। मुझे याद आया कि पण्डितजी दो वर्षके कैलेण्डर अपने नाम ले गये हैं। ख्याल आया कहीं इन्हीं वर्षोंके एण्ट्रेन्सके प्रश्नपत्रोंसे प्रश्न न पूछ बैठें। मैंने अपने सहपाठियोंके साथ बैठकर उन प्रश्नपत्रोंको हल किया। देखा गया कि उन्हीं प्रश्नपत्रोंसे सब प्रश्न पूछे गये हैं। परीक्षा-भवनमें पण्डितजीने मुझसे पूछा कि कहो कैसा कर रहे हो? मैंने उत्तेजित होकर कहा कि जीवनमें ऐसा अच्छा परचा कभी नहीं किया। उन्होंने कोर्सके बाहरके भी प्रश्न पूछे थे। मुझे उन्हें विवश होकर ५० में ४६ ग्रेड देने पड़े और कोई भी विद्यार्थी फेल न हुआ। यदि मैं लाइब्रेरियन महाशयका सहायक न होता तो अवश्य फेल हो गया होता।

सन् १९०५ में पिताजीके साथ मैं बनारस कांग्रेसमें गया। पिताजीके निकट सम्पर्कमें आनेसे मुझे भारतीय सस्कृतिसे प्रेम हो गया था। यह मौखिक प्रेम था। उसका ज्ञान तो कुछ था नहीं, किन्तु इसी कारण आगे चलकर मैंने एम० ए० में संस्कृत ली। १९०४ में पूज्य मालवीयजी फैजाबाद आये थे। भारतधर्म-महामण्डलसे सम्बन्ध होनेके नाते वह मेरे पिताजीसे मिलने घरपर आये। गीताके एक-आध अध्याय सुने। मेरे शुद्ध उच्चारणसे बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि एण्ट्रेन्स पासकर प्रयाग आना और मेरे हिन्दू बोर्डिङ्ग हाउसमें रहना। पूज्य मालवीयजीके दर्शन प्रथम बार हुए थे। उनका सीम्य चेहरा और मधुर भाषण अपना प्रभाव डाले बिना रहता नहीं था। यद्यपि मैंने सेण्ट्रल हिन्दू कालेजमें नाम लिखानेका विचार किया था, किन्तु साथियोंके कारण उस विचारको छोड़ना पड़ा। एण्ट्रेन्स पास कर मैं इलाहाबाद पढ़ने गया और हिन्दू बोर्डिङ्ग हाउसमें रहने लगा। मेरे ३-४ सहपाठी थे। हमको एक बड़े कमरेमें रखा गया। छात्रावासमें रहनेका यह पहला अवसर था।

वङ्ग-भङ्गके कारण कांग्रेसमें एक नये दलका जन्म हुआ था, जिसके नेता लोकमान्य तिलक, श्री विपिनचन्द्र पाल आदि थे। उस समय तक मेरे कोई खास राजनीतिक विचार न थे। किन्तु कांग्रेसके प्रति आदर और श्रद्धाका भाव था। मैं सन् १९०५ में दर्शकके रूपमें कांग्रेसमें शरीक हुआ था। प्रिंस आर्चबिशप भारत आनेवाले थे और उनका स्वागत करनेके लिए एक प्रस्ताव गोखलेने कांग्रेसके सम्मुख रखा था। तिलकने उसका घोर विरोध किया। अन्तमें दवावमें उसे वापिस ले लिया, किन्तु उस समय पण्डालसे बाहर चले आये। विरोधकी यह पहली ध्वनि सुनायी पड़ी। सन् १९०६ में कलकत्तेमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। प्रयाग आनेपर मेरे विचार तेजीसे बदलने लगे। हिन्दू बोर्डिङ्ग हाउस उग्र विचारोंका केन्द्र था। पण्डित सुन्दरलालजी उस समय विद्यार्थियोंके अगुआ थे। अपने राजनीतिक विचारोंके कारण वह विश्वविद्यालयसे निकाले गये। उस समय बोर्डिङ्ग हाउसमें रात-दिन राजनीतिक चर्चा हुआ करती थी। मैं बहुत जल्द गरम दलके विचारका हो गया। हममें से कुछ लोग कलकत्तेके अधिवेशनमें शरीक हुए। रिपन कालेजमें हमलोग ठहराये गये। नरम-नरम दलका संघर्ष चल रहा था और यदि श्री दादाभाई नौरोजी सभापति न होते तो वही दो टुकड़े हो गये होते। उनके कारण यह संकट टला। इस नवीन दलके कार्यक्रमके प्रधान अङ्ग स्वदेशी-विदेशी मालका वहिष्कार

और राष्ट्रीय शिक्षा थे । कांग्रेसका लक्ष्य बदलनेकी भी बातचीत थी । दादाभाई नौरोजीने अपने भाषणमें 'स्वराज' शब्दका प्रयोग किया और इस शब्दको लेकर दोनो दलोमें विवाद खड़ा हो गया । यद्यपि पुराने नेता बहिष्कारके विरुद्ध थे, उनका कहना था कि इससे विद्वेष और घृणाका भाव फैलता है, तथापि बङ्गालके लिए उनको भी इसे स्वीकार करना पड़ा ।

जापानकी विजयसे एशियामे नव-जागृतिका आरम्भ हुआ । एशियावासियोंने अपने खोये हुए आत्मविश्वासको फिरसे पाया और अंग्रेजोंकी ईमानदारीपर जो वालोचित विश्वास था, वह उठने लगा । इस पीढ़ीका अंग्रेजी शिक्षित-वर्ग समझता था कि अंग्रेज हमारे कल्याणके लिए भारत आया है और जब हमको शासनके कार्यमें दक्ष बना देगा, तब वह स्वेच्छासे राज्य सौंपकर चला जायगा । बिना इस विश्वासको दूर किये राजनीतिमें प्रगति आ नहीं सकती थी । लोकमान्यने यही काम किया । इस नये दलकी स्थापनाकी घोषणा कलकत्तेमें की गयी । इसकी ओरसे कलकत्तेमें दो सभाएँ हुई । एक सभा बड़ा-वाजारमें हुई थी । उसमें भी मैं मौजूद था । इस सभाकी विशेषता यह थी कि इसमें सब भाषण हिन्दीमें हुए थे । श्री विपिनचन्द्र पाल और लोकमान्य तिलक भी हिन्दीमें बोले थे । श्री पालको हिन्दी बोलनेमें कोई विशेष कठिनाई नहीं प्रतीत हुई, किन्तु लोकमान्यकी हिन्दी टूटी-फूटी थी । बड़ावाजारमें उत्तर भारतके लोग अधिकतर रहते हैं । उन्हींकी सुविधाके लिए हिन्दीमें ही भाषण कराये गये थे । बङ्गालमें इस नये दलका अच्छा प्रभाव था । कलकत्तेकी कांग्रेसके बाद सयुक्तप्रान्तको सर करनेके लिए दोनो दलोमें होड़ लग गयी । प्रयागमें दोनो दलोके बड़े नेता आये और उनके व्याख्यानको सुननेका मुझको अवसर मिला । सबसे पहले लोकमान्य आये । उनके स्वागतके लिए हमलोग स्टेशनपर गये । उनकी सभाका आयोजन थोड़ेसे विद्यार्थियोंने किया था । शहरके नेताओंमेंसे कोई उनके स्वागतके लिए नहीं गया । उनकी सवारीके लिए एक सज्जन घोड़ागाडी लाये थे । हमलोगोंने घोड़ा खोलकर स्वयं गाडी खींचनेका आग्रह किया, किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया । लोकमान्य के शब्द थे—'Reserve that enthusiasm for a better cause.—इस उत्साहको किसी और अच्छे कामके लिए सुरक्षित रखिये ।' एक वकील साहबके अहातेमें उनका व्याख्यान हुआ था । वकील साहब इलाहाबादसे बाहर गये हुए थे । उनकी पत्नीने इजाजत दे दी थी । हमलोगोंने दरी बिछायी । एक विद्यार्थीने 'वन्दे मातरम्' गान गाया और अंग्रेजीमें भाषण शुरू हुआ । लोकमान्य तर्क और युक्तिसे काम लेते थे । उनके भाषणमें हास्यरसका भी पुट रहता था । किन्तु वह भावुकतासे बहुत दूर थे । उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मसल है कि ईश्वर उसीकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है । तो क्या तुम समझते हो कि अंग्रेज ईश्वर से भी बड़ा है ? इसके कुछ दिनो बाद श्री गोखले आये और उनके कई व्याख्यान कायस्थ पाठशालामें हुए । एक व्याख्यानमें उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़नेपर हम टैक्स देना भी वन्द कर सकते हैं । इसके बाद श्री विपिनचन्द्र पाल आये और उनके ४ ओजस्वी

व्याख्यान हुए। इस तरह समय-समयपर किसी-न-किसी दलके नेता प्रयाग आते रहते थे। लाला लाजपतराय और हैदररजा भी आये। नरम दलके नेताओंमें केवल श्री गोखलेका कुछ प्रभाव हम विद्यार्थियोंपर पड़ा। हमलोगोंने स्वदेशीका व्रत लिया और गरम दलके अखवार मँगाने लगे। कलकत्तेसे दैनिक 'वन्दे मातरम्' आता था, जिसे हम बड़े चावसे पढ़ा करते थे। इसके लेख बड़े प्रभावशाली होते थे। श्री अरविन्द घोष इसमें प्रायः लिखा करते थे। उनके लेखोंने मुझे विशेष रूपसे प्रभावित किया। गायद ही उनका कोई लेख होगा जो मैंने न पढ़ा हो और जिसे दूसरोको न पढ़ाया हो। पाण्डिचेरी जानेके बाद भी उनका प्रभाव कायम रहा और मैं 'आर्य' का वर्षों ग्राहक रहा। बहुत दिनों-तक यह आशा थी कि वह साधना पूर्ण करके बङ्गाल लौटेंगे और राजनीतिमें पुनः प्रवेश करेंगे। सन् १९२१ में उनसे ऐसी प्रार्थना भी की गयी थी। किन्तु उन्होंने अपने भाई वारीन्द्रको लिखा कि सन् १९०८ के अरविन्दको बङ्गाल चाहता है। किन्तु मैं सन् १९०८ का अरविन्द नहीं रहा। यदि मेरे ढङ्गके ९९ भी कर्मी तैयार हो जायें तो मैं आ सकता हूँ। बहुत दिनोंतक मुझे यह आशा बनी रही, किन्तु अन्तमें जब मैं निराश हो गया तो उधरसे मुँह मोड़ लिया। उनके विचारोंमें ओजके साथ-साथ सच्चाई थी। प्राचीन सस्कृतिके भक्त होनेके कारण भी उनके लेख मुझे विशेष रूपसे पसन्द आते थे। उनका जीवन बड़ा सादा था। जिन्होंने अपनी पत्नीको लिखे उनके पत्र पढ़े हैं, वह इसको जानते हैं। उनके सादे जीवनमें मुझको बहुत प्रभावित किया। उस समय लाला हरदयाल अपनी छात्रवृत्ति छोड़कर विलायतसे लौट आये थे। उन्होंने सरकारी विद्यालयोंमें डी जाने-वाली शिक्षा-प्रणालीका विरोध किया था और 'हमारी शिक्षासमस्या' पर १४ लेख पंजाबीमें लिखे थे। उनके प्रभावमें आकर पंजाबके कुछ विद्यार्थियोंने पढ़ना छोड़ दिया था। उनके पढ़ानेका भार उन्होंने स्वयं लिया था। ऐसे विद्यार्थियोंकी सख्या बहुत थोड़ी थी। हरदयालजी बड़े प्रतिभाशाली थे और उनका विचार था कि कोई बड़ा काम बिना कठोर साधनाके नहीं होता। Edwin Arnold की 'Light of Asia' को पढ़कर वह विल्कुल बदल गये थे। विलायतमें श्री श्यामजी कृष्ण वर्माका उनपर प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विद्यार्थियोंके लिए दो पाठ्यक्रम तैयार किये थे। इन सूचियोंकी पुस्तकोंको पढ़ना मैंने आरम्भ किया। उग्र विचारके विद्यार्थी उस समय रूस-जापान युद्ध, गैरीवाल्डी और मैजिनीपर पुस्तकें और रूसके आतंकवादियोंके उपन्यास पढ़ा करते थे। सन् १९०७ में प्रयागमें रामानन्द वावूका "Modern Review" भी निकलने लगा। इसका बड़ा आदर था। उस समय हमलोग प्रत्येक बंगाली नवयुवकको क्रान्तिकारी समझते थे। बँगला साहित्यमें इस कारण और भी रुचि उत्पन्न हो गयी। मैंने रमेशचन्द्र दत्त और वंकिमके उपन्यास पढ़े और बँगला-साहित्य थोड़ा-बहुत समझने लगा। स्वदेशीके व्रतमें हम पूरे उतरे। उस समय हम कोई भी विदेशी वस्तु नहीं खरीदते थे। माघ-मेलाके अवसरपर हम स्वदेशीपर व्याख्यान भी दिया करते थे। उस समय म्योर कालेजके प्रिंसिपल जेनिंग्स साहब थे। वह कट्टर एंग्लो-इण्डियन थे। हमारे छात्रावासमें एक विद्यार्थीके कमरेमें खुदीराम बोसकी तस्वीर थी। किसीने प्रिंसिपलको इसकी सूचना

दे दी । एक दिन शामेको वह आये और सीधे मेरे मित्तके कमरे मे गये । मेरे मित्त कालेजसे निकाल दिये गये । किन्तु श्रीमती एनी वेसेण्टने उनको हिन्दू कालेजमें भरती कर लिया ।

धीरे-धीरे हममेसे कुछका क्रान्तिकारियोसे सम्बन्ध होने लगा । उस समय कुछ क्रान्तिकारियोका विचार था कि I. C. S. मे शामिल होना चाहिये, ताकि क्रान्तिके समय हम जिलेका शासन सँभाल सके । इस विचारसे मेरे ४ साथी इंगलैण्ड गये । मैं भी सन् १९११ मे जाना चाहता था, किन्तु माताजीकी आज्ञा न मिलनेके कारण न जा सका । इधर सन् १९०७ मे सूरतमे फूट पड चुकी थी और कांग्रेससे गरम दलके लोग निकल आये थे । कन्वेंशन बुलाकर कांग्रेसका विधान बदला गया । इसे गरम दलके लोग कन्वेंशन कांग्रेस कहते थे । गवर्नमेण्टने इस फूटसे लाभ उठाकर गरम दलको छिन्न-भिन्न कर दिया । कई नेता जेलमे डाल दिये गये । कुछ समयको प्रतिकूल देख भारतसे बाहर चले गये और लन्दन, पेरिस, जिनेवा और वर्लिनमे क्रान्तिके केन्द्र बनाने लगे । वहाँसे ही साहित्य प्रकाशित होता था । मेरे जो साथी विलायत पढने गये थे, वह इस साहित्यको मेरे पास भेजा करते थे । श्री सावरकर की 'War of Indian Independence' की एक प्रति भी मेरे पास आयी थी और मुझे बराबर हरदयालका 'वन्दे मातरम्', वर्लिनका 'तलवार' और पेरिसका 'Indian Sociologist' मित्ता करता था । मेरे दोस्तोमे से एक सन् १९१४ की लडाईमे जेलमे बन्द कर दिये गये थे तथा अन्य दोस्त केवल वैरिस्टर होकर लौट आये । मैंने सन् १९०८ के बादसे कांग्रेसके अधिवेशनोमे जाना छोड़ दिया, क्योंकि हम-गरम दलके साथ थे । यहाँतक कि जब कांग्रेसका अधिवेशन प्रयागमे हुआ, तब भी हम उसमे नही गये । सन् १९१६ मे जब कांग्रेसमे दोनो दलोमे मेल हुआ तब हम फिर कांग्रेसमे आ गये ।

वी० ए० पास करनेके बाद मेरे सामने यह प्रश्न आया कि मैं क्या करूँ । मैं कानून पढना नही चाहता था । मैं प्राचीन इतिहासमे गवेषणा करना चाहता था । न्यूयोर कालेजमे भी अच्छे-अच्छे अध्यापकोके सम्पर्कमे आया । डाक्टर गंगानाथ झाकी मुझपर बड़ी कृपा थी । वी० ए० मे प्रोफेसर ब्राउनरो इतिहास पढा । भारतके मध्ययुगका इतिहास वह बहुत अच्छा जानते थे । पढाते भी अच्छा थे । उन्हीके कारण मैंने इतिहासका विषय लिया । वी० ए० पास कर मैं पुरातत्व पढने काशी चला गया । वहाँ डाक्टर वेनिस और नारमन ऐसे सुयोग्य अध्यापक मिले । क्वीस कालेजमे जो ग्रैज अध्यापक आते थे, वह संस्कृत सीखनेका प्रयत्न करते थे । डाक्टर वेनिस-ऐसा पढानेवाला कम होगा । नारमन साहबके प्रति भी मेरी बड़ी श्रद्धा थी । जब मैं क्वीस कालेजमे था, तब वहाँ श्री शचीन्द्रनाथ सान्यालरो परिचय हुआ । विदेशसे आनेवाला साहित्य वह मुझसे ले जाया करते थे । उनके द्वारा मुझे क्रान्तिकारियोके समाचार मिलते रहते थे । मेरी इन लोगोके साथ बड़ी सहानुभूति थी । किन्तु मैं डकैती आदिके सदा विरुद्ध था; मैं किसी भी क्रान्तिकारी दलका सदस्य न था । किन्तु उनके कई नेताओसे परिचय था । वे मुझ पर विश्वास करते थे और समय-समयपर मेरी सहायता भी लेते रहते थे । सन् १९१३ मे जब मैंने एम० ए० पास किया, तब मेरे घरवालोंने वकालत पढनेका आग्रह किया । मैं इस पेशेको पसन्द नही

करता था । किन्तु जब पुरातत्त्व विभागमें स्थान न मिला, तब इस विचारसे कि वकालत करते हुए मैं राजनीतिमें भाग ले सकूंगा, मैंने कानून पढा ।

सन् १९१५ में मैं एल० एल० वी० पास कर वकालत करने फैजावाद आया । मेरे विचार प्रयागमें परिपक्व हुए और वही मुझको एक नया जीवन मिला । इस नाते मेरा प्रयागसे एक प्रकारका आध्यात्मिक सम्बन्ध है । मेरे जीवनमें सदा दो प्रवृत्तियाँ रही हैं;—एक पढ़ने-लिखनेकी और, दूसरी राजनीतिकी और । इन दोनोंमें संघर्ष रहता है । यदि दोनोंकी मुविधा एक साथ मिल जाय तो मुझे बड़ा परितोष रहता है और यह मुविधा मुझे विद्यापीठमें मिली । इसी कारण वह मेरे जीवनका सबसे अच्छा हिस्सा है जो विद्यापीठकी सेवामें व्यतीत हुआ और आज भी उसे मैं अपना कुटुम्ब समझता हूँ ।

सन् १९१४ में लोकमान्य मण्डाले जेलसे रिहा होकर आये और अपने सहयोगियोंको फिरसे एकत्र करने लगे । श्रीमती वेसेण्टका उनको सहयोग प्राप्त हुआ और होमरूल लीगकी स्थापना हुई । सन् १९१६ में हमारे प्रान्तमें श्रीमती वेसेण्टकी लीगकी स्थापना हुई । मैंने इस सम्बन्धमें लोकमान्यसे बातें की और उनकी लीगकी एक शाखा फैजावादमें खोलना चाहा । किन्तु उन्होंने यह कहकर मना किया कि दोनोंके उद्देश्य एक हैं, दो होनेका कारण केवल इतना है कि कुछ लोग मेरे द्वारा कायम की गयी किसी संस्थामें शरीक नहीं होना चाहते और कुछ लोग श्रीमती वेसेण्टद्वारा स्थापित किसी संस्थामें नहीं रहना चाहते । मैंने लीगकी शाखा फैजावादमें खोली और उसका मन्त्री चुना गया । इसकी ओरसे प्रचारका कार्य होता था और समय-समयपर सभाओंका आयोजन होता था । मेरा सबसे पहला भाषण अलीवन्धुओंकी नजरबन्दीका विरोध करनेके लिए आमन्त्रित सभामें हुआ था । मैं बोलते हुए बहुत डरता था । किन्तु किसी प्रकार बोल गया और कुछ सज्जनोंने मेरे भाषणकी प्रशंसा की । इससे मेरा उत्साह बढ़ा और फिर धीरे-धीरे संकोच दूर हो गया । मैं जब सोचता हूँ कि यदि मेरा पहला भाषण विगड़ गया होता तो शायद मैं भाषण देने का फिर साहस न करता ।

मैं लीगके साथ-साथ कांग्रेसमें भी था और बहुत जल्दी उसकी सब कमेटियोंमें बिना प्रयत्नके पहुँच गया । महात्माजीके राजनीतिक क्षेत्रमें आनेसे धीरे-धीरे कांग्रेसका रूप बदलने लगा । आरम्भमें वह कोई ऐसा हिस्सा नहीं लेते थे । किन्तु सन् १९१९ से वह प्रमुख भाग लेने लगे । खिलाफतके प्रश्नको लेकर जब महात्माजीने असहयोग आन्दोलन चलाना चाहा तो असहयोगके कार्यक्रमके सम्बन्धमें लोकमान्यसे उनका मतभेद था । जून १९२० में काशीमें ए० आर्डी० सी० सी० की बैठकके समय मैंने इस सम्बन्धमें लोकमान्यसे बातें की । उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवनमें कभी गवर्नमेण्टके साथ सहयोग नहीं किया ; प्रश्न असहयोगके कार्यक्रमका है । जेलसे लौटनेके बाद जनतापर उनका वह पुराना विश्वास नहीं रह गया था और उनका ख्याल था कि प्रोग्राम ऐसा हो जिसपर जनता चल सके । वह कौंसिलोके बहिष्कारके खिलाफ थे । उनका कहना था कि यदि आधी भी जगहें खाली रहे तो यह ठीक है । किन्तु यदि वहाँ जगहें भर जायँगी तो अपनेको प्रतिनिधि कहकर सरकारपरस्त लोग देशका अहित करेंगे ।

उनका एक सिद्धान्त यह भी था कि कांग्रेसमें अपनी बात रखो और अन्तमें जो उसका निर्णय हो उसे स्वीकार करो। मैं तिलकका अनुयायी था, इसलिए मैंने कांग्रेसमें कौंसिल-बहिष्कारके विरुद्ध वोट दिया। किन्तु जब एक बार निर्णय हो गया तो उसे शिरोधार्य किया। वकालतके पेशेमें मेरा मन न था। नागपुरके अधिवेशनमें जब असहयोगका प्रस्ताव पास हो गया तो उसके अनुसार मैंने तुरन्त वकालत छोड़ दी। इस निश्चयमें मुझे एक क्षणकी भी देर न लगी। मैंने किसीसे परामर्श भी नहीं किया, क्योंकि मैं कांग्रेसके निर्णयसे अपनेको बँधा हुआ मानता था। मैंने अपने भविष्यका भी ख्याल नहीं किया। पिताजीसे एक बार पूछना चाहा, किन्तु यह सोचकर कि यदि उन्होंने विरोध किया तो मैं उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन न कर सकूँगा। मैंने उनसे भी अनुमति नहीं माँगी। किन्तु पिताजीको जब पता चला तो उन्होंने कुछ आपत्ति न की। केवल इतना कहा कि तुमको अपनी स्वतन्त्र जीविकाकी कुछ फिक्र करनी चाहिये और जयतक जीवित रहे, मुझे किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं होने दी। असहयोग आन्दोलनके शुरू होनेके बाद एक बार पण्डित जवाहरलाल फैजाबाद आये और उन्होंने मुझसे कहा कि बनारसमें विद्यापीठ खुलने जा रहा है। वहाँ लोग तुम्हें चाहते हैं। मैंने अपने प्रिय मित्र श्री शिवप्रसादजीको पत्र लिखा। उन्होंने मुझे तुरन्त बुला लिया। शिवप्रसादजी मेरे सहपाठी थे और विचार-साम्य होनेके कारण मेरी उनकी मित्रता हो गयी। वह बड़े उदार हृदयके व्यक्ति थे। दानियोमें मैंने उन्हींको एक पाया जो नाम नहीं चाहते थे। क्रान्तिकारियोंकी भी वह धनसे सहायता करते थे। विद्यापीठके काममें मेरा मन लग गया। श्रद्धेय डाक्टर भगवानदासजीने मुझपर विश्वास कर मुझे उपाध्यक्ष बना दिया। उन्हींकी देख-रेखमें मैं दो वर्षतक छात्रावासमें ही विद्यार्थियोंके साथ रहता था। एक कुटुम्ब-सा था। साथ-साथ हमलोग राजनीतिक कार्य भी करते थे। कराचीमें जब अलीबन्धुओंको सजा हुई थी, तब हम सब बनारसके गाँवमें प्रचारके लिए गये थे। अपना-अपना विस्तर बगलमें दबा, नित्य पैदल घूमते थे। सन् १९२६ में डाक्टर साहबने अध्यक्षके पदसे त्याग-पत्र दे दिया और मुझे अध्यक्ष बना दिया। बनारसमें मुझे कई नये मित्र मिले। विद्यापीठके अध्यापकोसे मेरा बड़ा मीठा सम्बन्ध रहा है। श्री श्रीप्रकाशजीसे मेरा विशेष स्नेह हो गया। यह अत्युक्ति न होगी कि वह स्नेहवश मेरे प्रचारक हो गये। उन्होंने मुझे आचार्य कहना शुरू किया, यहाँतक कि वह मेरे नामका एक अंग बन गया है। सबसे वह मेरी प्रशंसा करते रहते थे। यद्यपि मेरा परिचय जवाहरलालजीसे होमरूल आन्दोलनके समयसे था, तथापि श्रीप्रकाशजी द्वारा उनसे तथा गणेशजीसे मेरी घनिष्टता हुई। मैं उनके घरमें महीनो रहा हूँ। वह मेरी सदा फिक्र उस तरह करते हैं, जैसे माता अपने बालककी। मेरे बारेमें उनकी राय है कि मैं अपनी फिक्र नहीं करता हूँ। शरीरके प्रति बड़ा लापरवाह हूँ। मेरे विचार चाहे उनसे मिले या न मिले उनका स्नेह घटता नहीं। सियासतकी दोस्ती पायदार नहीं होती, किन्तु विचारोंमें अन्तर होने हुए भी हमलोगोंके स्नेहमें फर्क नहीं पड़ा है। पुराने मित्रोंसे वियोग दुखदायी है। किन्तु यदि शिष्टता बनी रहे तो सम्बन्धमें बहुत अन्तर नहीं पड़ता। ऐसी मिसालें हैं, किन्तु बहुत कम।

नेताके मुझमें कोई भी गुण नहीं है। महत्त्वाकांक्षा भी नहीं है। यह बड़ी कमी है। मेरी बनावट कुछ ऐसी हुई है कि मैं न नेता हो सकता हूँ और न अग्रध्वज अनुयायी। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अनुशासनमें नहीं रहना चाहता। मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ। नेताओंकी दूरसे आराधना करता रहा हूँ। उनके पास बहुत कम जाता रहा हूँ। यह मेरा स्वाभाविक संकोच है। आत्म-प्रशंसा सुनकर कौन खुश नहीं होता, अच्छा पद पाकर किसको प्रसन्नता नहीं होती, किन्तु मैंने कभी इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सभापति होनेके लिए मैंने अनिच्छा प्रकट की। किन्तु अपने मान्य नेताओंके अनुरोधपर खड़ा होना पड़ा। इसी प्रकार जब पण्डित जवाहरलाल नेहरूने मुझसे वर्किंग कमेटीमें आनेको कहा मैंने इनकार कर दिया। किन्तु उनके आग्रह करनेपर मुझे निमन्त्रण स्वीकार करना पड़ा।

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। इसलिए किसी नये अन्दोलन या पार्टीका आरम्भ नहीं कर सकता। सन् १९३४ में जब जयप्रकाशजीने समाजवादी पार्टी बनानेका प्रस्ताव रखा और मुझे सम्मेलनका सभापति बनाना चाहा तो मैंने इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि समाजवादको नहीं मानता था। किन्तु इसलिए कि मैं किसी बड़ी जिम्मेदारीको उठाना नहीं चाहता था। उनसे मेरा काफी स्नेह था और इसी कारण मुझे अन्तमें उनकी बात माननी पड़ी। सम्मेलन पटनेमें मई सन् १९३४ में हुआ था। बिहारमें भूकम्प हो गया था। उसी सिलसिलेमें विद्यार्थियोंको लेकर काम करने गया था। वहाँ पहली बार डाक्टर लोहियासे परिचय हुआ। मुझे यह कहनेमें प्रसन्नता है कि जब पार्टीका विधान बना तो केवल डाक्टर लोहिया और हम इस पक्षमें थे कि उद्देश्यके अन्तर्गत पूर्ण स्वाधीनता भी होनी चाहिये। अन्तमें हम लोगोंकी विजय हुई। श्री मेहरअलीसे एक बार सन् १९२८ में मुलाकात हुई थी। बम्बईके और मित्रोंको मैं उस समयतक नहीं जानता था। अपरिचित व्यक्तियोंके साथ काम करते मुझको घबराहट होती है, किन्तु प्रसन्नताकी बात है कि सोशलिस्ट पार्टीके सभी प्रमुख कार्यकर्ता भी ही एक कुटुम्बके सदस्योंकी तरह हो गये।

यो तो मैं अपने सूत्रोंमें बराबर भाषण किया करता था, किन्तु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें मैं पहली बार पटनेमें बोला। मौलाना मुहम्मद अलीने एक बार कहा था कि बंगाली और मद्रासी कांग्रेसमें बहुत बोला करते हैं, बिहारके लोग जब औरोंको बोलते देखते हैं तो खिसककर राजेन्द्रबाबूके पास जाते हैं और कहते हैं कि 'रीवाँ बोली न,' और यू० पी० के लोग खुद नहीं बोलते और जब कोई बोलता है तो कहते हैं, "क्या वेवकूफ बोलता है!" हमारे प्रान्तके बड़े-बड़े नेताओंके आगे हमलोगोंको कभी बोलनेकी जरूरत नहीं पड़ती थी। एक समय पण्डित जवाहरलाल भी बहुत कम बोलते थे। किन्तु सन् १९३४ में मुझे पार्टीकी ओरसे बोलना पड़ा। यदि पार्टी बनी न होती तो शायद मैं कांग्रेसमें बोलनेका साहस भी नहीं करता।

पण्डित जवाहरलालजीसे मेरी विचारधारा बहुत मिलती-जुलती थी। इस कारण तथा उनके ऊँचे व्यक्तित्वके कारण मेरा उनके प्रति सदा आकर्षण रहा है। उनके सम्बन्धमें

कई कोमल स्मृतियाँ हैं । यहाँ केवल एक बातका उल्लेख करता हूँ । हमलोग अहमदनगर-के किलेमें एक साथ थे । एकवार टहलते हुए कुछ पुरानी बातोंकी चर्चा चल पड़ी । उन्होंने कहा—‘नरेन्द्र देव । यदि मैं कांग्रेसके आन्दोलनमें न आता और उसके लिए कई बार जेलकी यात्रा न करता तो मैं इन्सान न बनता ।’ उनकी वहन कृष्णाने अपनी पुस्तकमें जवाहरलालजीका एक पत्र उद्धृत किया है जिससे उनके व्यक्तित्वपर प्रकाश पड़ता है । पं० मोतीलालजीकी मृत्युके पश्चात् उन्होंने अपनी वहनोको लिखा कि पिताकी सम्पत्ति मेरी नहीं है, मैं तो सबके लिए उसका ट्रस्टीमालूम हूँ । उस पत्रको पढ़कर मेरी आँखोंमें आँसू आ गये और मैंने जवाहरलालजीकी महानताको समझा । उनको अपने साथियोंका बड़ा ख्याल रहता है और बीमार साथियोंकी बड़ी शुश्रूषा करते हैं ।

महात्माजीके आश्रममें चार महीने रहनेका मौका मुझे सन् १९४२ में मिला । मैंने देखा कि वे कैसे अपने प्रत्येक क्षणका उपयोग करते हैं । वह रोज आश्रमके प्रत्येक रोगीकी पूछताछ करते थे । प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यकर्ताका ख्याल रखते थे । आश्रमवासी अपनी छोटी-छोटी समस्याओंको लेकर उनके पास जाते थे और वह सबका समाधान करते थे । आश्रममें रोग-शय्यापर पड़े-पड़े मैं विचार करता था कि वह पुरुष जो आजके हिन्दूधर्मके किसी नियमको नहीं मानता, वह क्यों असंख्य सनातनी हिन्दुओंका आराध्य देवता बना हुआ है । पण्डित-समाज चाहे उनका भले ही विरोध करे, किन्तु अपढ़ जनता उनकी पूजा करती है । इस रहस्यको हम अभी समझ सकते हैं, जब हम जाने कि भारतीय जनतापर श्रमण-संस्कृतिका कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है । जो व्यक्ति घर-बार छोड़कर निस्वार्थ सेवा करता है, उसके आचारकी ओर हिन्दू-जनता ध्यान नहीं देती । पण्डित-जन भले ही उसकी निन्दा करे, किन्तु सामान्य जनता उसका सदा सम्मान करती है । अक्टूबर सन् १९४१ में जब मैं जेलसे छूटा तब महात्माजीने मेरे स्वास्थ्यके सम्बन्धमें मुझसे पूछा और प्राकृतिक चिकित्साके लिए आश्रममें बुलाया । मैं महात्माजीपर बोल नहीं डालना चाहता था । इसलिए कुछ वहाँना कर दिया । पर जब मैं ए० आई० सी० सी० की बैठकमें शरीर होने वर्धा गया और वहाँ बीमार पड़ गया, तब उन्होंने रहनेके लिए आग्रह किया । मेरी चिकित्सा होने लगी । महात्माजी मेरी बड़ी फिक्र रखते थे । एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गयी । जो चिकित्सक नियुक्त थे वह घबरा गये, यद्यपि इसके लिए कोई कारण न था । रातको १ बजे बिना मुझे बताये महात्माजी जगाये गये और वह मुझे देखने आये । वह उनका मौनका दिन था । उन्होंने मेरे लिए मौन तोड़ा । उसी समय मोटर भेजकर वर्धासे डाक्टर बुलाये गये । सुबहतक तबीयत सँभल गयी थी । दिल्लीमें स्टैफर्ड क्रिप्स वार्तालापके लिए आये थे । महात्माजी दिल्ली जाना नहीं चाहते थे, किन्तु आग्रह होनेपर गये । जानेके पहले मुझसे कहा कि वह हिन्दुस्तानके बंटवारेका सवाल किसी-न-किसी रूपमें लेंगे । इसलिए उनकी दिल्ली जानेकी इच्छा न थी । दिल्लीसे वरावर फोनसे मेरी तबीयतका हाल पूछा करते थे । वा भी उस समय बीमार थी । इस कारण वह जल्दी लौट आये । जिनके विचार उनसे नहीं मिलते थे, यदि वह

ईमानदार होते थे तो वह उनको अपने निकट लानेकी चेष्टा करते थे । उस समय महात्माजी सोच रहे थे कि जेलमे वह इस बार भोजन नहीं करेगे । उनके इस विचारको जानकर महादेव भाई बड़े चिन्तित हुए । उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी इस सम्बन्धमे महात्माजीसे बातें करो । डाक्टर लोहिया भी सेवाग्राम उसी दिन आ गये थे । उनरो भी यही प्रार्थना की गयी । हम दोनोने बहुत देरतक बातें की । महात्माजीने हमारी बात शान्तिपूर्वक सुनी, किन्तु उस दिन अन्तिम निर्णय न कर सके । बम्बईमें जब हमलोग ६ अगस्तको गिरफ्तार हो गये तो स्पेशल ट्रेनमे अहमदनगर ले जाये गये । उसमे महात्माजी, उनकी पार्टी और बम्बईके कई प्रमुख लोग थे । नेताओंने उस समय भी महात्माजीसे अन्तिम बार प्रार्थना की कि वह ऐसा काम न करे । किलेमें भी हमलोगोको सदा इसका भय लगा रहता था ।

सन् ४५ मे हमलोग छूटे । मैं जवाहरलालजीके साथ अलमोड़ा जेलसे १४ जूनको रिहा हुआ । कुछ दिनोंके बाद मैं पूनामे महात्माजीसे मिला । उन्होंने पूछा कि सत्य और अहिंसाके बारेमे अब तुम्हारे क्या विचार हैं ? मैंने उत्तर दिया कि मैं सत्यकी तो सदासे आराधना किया करता हूँ, किन्तु इसमे मुझको सन्देह है कि बिना कुछ हिंसाके राज्यकी शक्ति हम अंग्रेजोसे छीन सकेंगे । महात्माजीके सम्बन्धमे अनेक सम्मरण हैं, किन्तु समयाभावसे हम इससे अधिक कुछ नहीं कहते ।

इधर कई वर्षसे कांग्रेसमे यह चर्चा चल रही थी कि कांग्रेसमें कोई पार्टी नहीं रहनी चाहिये । महात्माजी इसके विरुद्ध थे । देशके स्वतन्त्र होनेके बाद भी मेरी यह राय थी कि अभी कांग्रेससे अलग होनेका समय नहीं है, क्योंकि देश सबकुछ गुजर रहा है । सोशलिस्ट पार्टीमें इस सम्बन्धमे मतभेद था । किन्तु मेरे मित्रोंने मेरी सलाह मानकर निर्णयको टाल दिया । मैंने यह भी साफ कर दिया था कि यदि कांग्रेसने कोई नियम ऐसा बना दिया जिससे हमलोगोका कांग्रेसमे रहना असम्भव हो गया तो मैं सबसे पहले कांग्रेस छोड़ दूंगा । कोई भी व्यक्ति जिसको आत्मसम्मान का ख्याल है, ऐसा नियम बननेपर नहीं रह सकता । यदि ऐसा नियम न बनता और पार्टी कांग्रेस छोड़नेका निर्णय करती तो यह तो ठीक है कि मैं आदेशका पालन करता, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कहींतक उसके पक्षमे होता । कांग्रेसके निर्णयके बाद मेरे सब सन्देह मिट गये और अपना निर्णय करनेमे मुझे एक क्षण भी न लगा । मेरे जीवनके कठिन अवसर जिनका मेरे भविष्यपर गहरा असर पड़ा है, ऐसे ही हुए हैं । इन मौकोंपर, घटनाएँ, ऐसी हुई कि मुझे अपना फैसला करनेमे कुछ देर न लगी । इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ ।

मेरे जीवनके कुछ ही वर्ष रह गये हैं । शरीर-सम्पत्ति अच्छी नहीं है । किन्तु मनमे अब भी उत्साह है । सदा अन्यायसे लड़ते ही बीता । यह कोई छोटा काम नहीं है । स्वतन्त्र भारतमें इसकी और भी आवश्यकता है । अपनी जिन्दगीपर एक निगाह बालनेसे मालूम होता है कि जब मेरी आँखें मुंदगी, मुझे एक परितोष होगा कि जो काम

मैंने विद्यापीठमे किया है, वह स्थायी है । मैं कहा करता हूँ कि यही मेरी पूंजी है और इसीके आधारपर मेरा राजनीतिक कारोबार चलता है । यह सर्वथा सत्य है ।^१

जनसाधारण और सरकारके आदर्श

पंजाबकी एक मासिक घटना

थोड़े दिन हुए कि पंजाबकी व्यवस्थापिका सभामे माननीय रायजादा भगत रामजीने नजरबन्दीके सम्बन्धमें कुछ प्रश्न किये थे । एक नजर बन्दकी माता मृतप्राय थी । नियमानुसार वह राज-कर्मचारियोंकी आज्ञाके बिना नियमित सीमाके बाहर नहीं जा सकता था, परन्तु मातृ-प्रेमसे प्रेरित होकर उसने इस नियमका तिरस्कार किया और अपनी माताकी रक्षाके हेतु औषधि खरीदनेके लिए निर्दिष्ट सीमाका उल्लंघन किया । यह कार्य यद्यपि साधारण दृष्टिसे प्रशसनीय था, तथापि अधिकारी-वर्गके विचारमे यह एक अपराध था और अपराधीका शासन केवल उचित तथा न्याय ही नहीं, बरच प्रजामे शान्ति रखनेके लिए आवश्यक भी था, अतः उसको कारावासका दण्ड दिया गया । यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि जिसको सर्वसाधारण प्रशसनीय तथा अनुकरणीय मानते हैं उसको अधिकारी-वर्ग अन्याय तथा दण्डनीय क्यों मानता है । इन दोनों दृष्टियोंमे विभिन्नता क्यों पायी जाती है ? इस प्रश्नकी विवेचना करना कठिन है, तथापि हम इसका उत्तर देनेकी चेष्टा करेंगे ।

प्रत्येक स्टेट राज्यका एक-न-एक आदर्श होता है और जो कार्य उस आदर्शका समर्थन करता है वह स्टेटकी दृष्टिमे श्रेयस्कर समझा जाता है । परन्तु जो कार्य उस आदर्शका विरोध करता है अथवा उस आदर्शकी प्राप्तिमे कुछ सहायता नहीं देता वह कार्य स्टेटके मन्तव्यके अनुसार प्रशसनीय नहीं है और स्टेट उसकी उपेक्षा करता है । वर्तमान युगमें जिन स्टेटोंका संगठन हुआ है उनका ढग बहुत-कुछ एक ही प्रकारका है । एक ही प्रकारके विचार लेकर उनका जन्म हुआ है और उनके उद्देश्य तथा कार्य-प्रणालीमे न्यूनाधिक समता पायी जाती है । अतः जो बात एक स्टेटके सम्बन्धमे लागू है वह अन्य स्टेटोंके सम्बन्धमे भी कही जा सकती है ।

आधुनिक स्टेटका एक आदर्श यह भी है कि किसी-न-किसी प्रकार अपने राष्ट्रकी वृद्धि करनी चाहिये और इस उद्देश्यकी सिद्धिमे यदि परकीय राष्ट्रोंको पददलित करना पड़े अथवा विजातियोंके जन्मसिद्धतत्व छीनने हो तो कोई हानि नहीं है । अपने राज्यका विस्तार हो, अपना राज्य धर्मसम्पन्न हो और अपने राज्यकी सभ्यताका प्रचार हो, चाहे इस कार्यकी सफलतामे अन्य राज्योंका अनिष्ट ही सम्पादन क्यों न हो, यही वर्तमान युगके प्रायः स्टेटोंका आदर्श हो रहा है ।

सर्वसाधारणका आदर्श इसके विपरीत कुछ और ही है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यही सत्य प्रतीत होगा कि साधारण जन बहुधा शान्तिपूर्वक सुख भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनको राज्य-विस्तारसे क्या प्रयोजन? उनको दूसरोंकी स्वतन्त्रता स्वार्थके लिए छीन लेनेसे क्या लाभ? हाँ, यदि कोई राष्ट्र उनपर आक्रमण करे तो अवश्य आत्म-रक्षाके लिए वह प्रतिकार करेंगे, परन्तु अन्यथा नहीं। जो लोग श्रमजीवी हैं वह केवल यही चाहते हैं कि निर्विघ्न होकर अपने श्रमके फलोका उपभोग करें और एक दूसरेकी सहायता करते हुए समाजकी उन्नति करें। सर्वसाधारणमें से जो स्टेटसे सम्बद्ध होते हैं केवल वही जन-समुदायके आदर्शका विरोध करते हैं और जिन्होंने स्टेटद्वारा शिक्षा प्राप्त की है वही स्टेटके उपदेशकका कार्य करते हैं और स्टेटके विचारोका सर्वसाधारणमें प्रचार करते हैं। इस आन्दोलनका प्रभाव विणेषकर हमारे सुशिक्षित भाइयोपर पड़ता है जो शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते हैं अथवा जो धन तथा सम्मानके लोभसे स्टेटकी सेवा करना स्वीकार करते हैं। परन्तु हमारे किसान तथा मजदूर ऐसे विचारोसे बहुत कम प्रभावित होते हैं। स्टेट अपने आदेशकी सफलताके लिए निरन्तर चेष्टा करता है और एक सुसंगठित सस्था होनेके कारण सर्वसाधारणके लिए इसका विरोध करना दुष्कर हो जाता है। सर्वसाधारण अपनी शक्तियोको बहुधा संगठित नहीं करते। यही कारण है कि स्टेट अपने लक्ष्यकी ओर बढ़े चले जाते हैं, परन्तु सर्वसाधारण उदासीनता तथा निर्वलताके कारण अपने आदर्शकी रक्षा करनेमें असफल रहते हैं। कुछ कालसे सर्वसाधारणका आत्म-ज्ञान बढ़ता जाता है और वह अपनी उदासीनताका परित्याग कर अपनी शक्तियोका संगठन करने लग गये हैं। कितने ही विद्वान आशा करते हैं कि एक दिन अवश्य आवेगा कि जब किसी स्टेटका अस्तित्व न रह जायगा और मनुष्य विना किसी शासनके प्रेमपूर्वक एक दूसरेके साथ व्यवहार करेंगे और परस्पर सहानुभूति दिखाते हुए आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति करेंगे।

आदर्शोंमें भेद होनेके कारण ही स्टेट केवल उसी प्रकारकी वीरताका आदर तथा सम्मान करता है जिससे वह अपने आदर्शकी पुष्टि समझता है। राज्य-विस्तारके लिए स्टेटद्वारा रचे हुए युद्धमें जो सिपाही पराक्रम दिखाता है स्टेट उसका आदर करता है, परन्तु जो व्यक्ति अपने प्राणोकी कुछ भी परवाह न कर किसी डूबते हुएको बचानेके लिए समुद्रमें कूद पड़ता है और उसके प्राणोकी रक्षा करता है स्टेट उसकी वीरताकी उपेक्षा करता है। सिपाही युद्धमें यदि पराक्रम न दिखलावे और प्रणपणसे युद्ध न करे तो स्टेटकी बड़ी क्षति हो और उसका उद्देश्य सफल न हो परन्तु एक साधारण व्यक्तिकी रक्षा करनेवालेसे स्टेटको अपने उद्देश्यमें कुछ भी सहायता नहीं मिलती। हमारे पढ़े-लिखे लोग भी जिनकी शिक्षा स्टेटद्वारा हुई है बहुधा स्टेटकी नाई पहले प्रकारकी वीरताका आदर तथा दूसरे प्रकारकी वीरताकी उपेक्षा करते हैं। हमारे अशिक्षित भाई आये दिन कितने ही वीरोचित कार्य किया करते हैं जो हमारे कानोतक भी नहीं पहुँचते और यदि पहुँचते भी हैं तो उनका उल्लेख समाचार-पत्रों तथा ग्रन्थोमें बहुत कम हुआ करता है। परन्तु यदि कोई सिपाही स्टेटके लिए युद्धमें वीरताके साथ लड़ता है तो उसके पराक्रमका उल्लेख स्वर्णाक्षरोमें होता है और

उसकी चर्चा घर-घर फैलायी जाती है। यही कारण है कि हमारे इतिहास जो बहुधा स्टेटसे सम्बन्ध रखनेवाले अथवा स्टेटसे प्रभावित मनुष्योंद्वारा लिखे गये हैं अधिकतर युद्धोकी ही चर्चा करते हैं।

एक कथाका विवरण हमको महाशय क्रोपाटकिन (Kropotkin) के 'परस्पर साहाय्य' (Mutual Aid) नामक ग्रन्थमें मिलता है जिससे स्टेटोकी कार्य-प्रणालीका परिचय भलीभाँति हो जाता है। यह कथा सन् १८८४ या १८८५ ई० की है। एक मनुष्य फ्रान्स देशके किसी जेलखानेमें कैद था और यद्यपि फ्रान्सके जेलोसे भागना एक दुष्कर कार्य है, तथापि वह किसी-न-किसी प्रकार जेलसे भागा। वह दिनभर छिपा रहा और यद्यपि लोग उसकी ताकमे थे तथापि किसीकी दृष्टि उसपर नहीं पड़ी। दूसरे दिन प्रातः काल वह एक खाईमें जा छिपा। यह खाई एक छोटेसे गाँवके समीप थी। उसका विचार कुछ कपड़े चुरानेका था, जिसमें जेलकी वर्दी जो वह पहने हुए था उतार दे। उसी समय गाँवमें आग लगी। भागे हुए कैदीने एक जलते हुए मकानसे दौड़कर बाहर आती हुई एक स्त्रीको देखा। स्त्री चिल्ला-चिल्लाकर लोगोंसे प्रार्थना कर रही थी कि 'अरे कोई मेरे जलते हुए बच्चेकी रक्षा करो।' बच्चा जलते हुए मकानके कोठेपर था। परन्तु किसीने उसकी विनीत प्रार्थनापर ध्यान न दिया। स्त्रीकी प्रार्थना कैदीके कानों तक पहुँची और वह एकाएक खाईसे निकला और आगको चीरता हुआ उस मकानतक पहुँचा। बच्चेको आगसे सुरक्षित निकाल लाया और उसको उसकी माताको सौंप दिया। इस उद्योगमें उसके कपड़े जलने लगे और उसका चेहरा झुलस गया, पर उसने अपने कष्टकी कुछ भी चिन्ता न की। गाँवके चौकीदारने तुरन्त ही उसको पकड़ लिया और वह जेलखाने लाया गया। फ्रान्सके सब पत्रोंमें यह घटना प्रकाशित हुई, परन्तु उस आभागेको छुड़ानेके लिए किसीने भी प्रयत्न नहीं किया। इसपर क्रोपाटकिन महाशय टीका करते हुए लिखते हैं कि यदि जेलके भीतर कोई कैदी वार्डर (warden) को मारना चाहता और यदि हमारा कैदी वार्डरसे उसकी रक्षा करता तो उसकी अवश्य प्रशंसा होती, क्योंकि वह स्टेटके शासनमें योग देनेवाला होता। परन्तु हमारे कैदीका कार्य केवल मनुष्योचित था और स्टेटके आदर्शके फलीभूत होनेमें सहायक नहीं था और इसीलिए यह इस बातके लिए पर्याप्त था कि वह भुला दिया जाय।

कौन ऐसा सहृदय मनुष्य है जो इस फ्रांसके कैदीके साथ सहानुभूति न दिखावे और इसकी वीरताकी प्रशंसा न करे। इसी प्रकार कौन ऐसा मनुष्य है जो इस भारतीय नजरबन्दके मातृप्रेमकी प्रशंसा न करे और उसको वीरकी पदवी न प्रदान करे। क्रोपाटकिन-के शब्दोंमें इस नजरबन्दका कार्य केवल मनुष्योचित था और इसी कारणसे गवर्नमेंण्टने सहानुभूति प्रदर्शित करनेके स्थानमें उसको दण्डका पात्र समझा। परन्तु हम साधारणजन जिनकी वृद्धि—सौभाग्यसे अथवा दुर्भाग्यसे—उस उन्नत अवस्थाको नहीं प्राप्त हुई, इस नजरबन्दके साथ अवश्य अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करेंगे और उसके वीरोचित गुणोंका गान कर अपनी आत्माको उन्नत तथा पवित्र वनावेंगे।^१

पूँजीवादी समाज और प्रेस

लोकतन्त्रकी रक्षा और उन्नतिके लिए प्रेसकी स्वतन्त्रता आवश्यक है । प्रेसका मुख्य कार्य नागरिकोंको राजनीतिक शिक्षा देना है जिससे वह अपने वोटका उचित उपयोग कर सके । सार्वजनिक प्रश्नोपर अपना मत निश्चित करनेके लिए प्रत्येक व्यक्तिको अधिकतर प्रेसपर ही निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि प्रेसके द्वारा ही उसको उन घटनाओंका ज्ञान होता है, जिनके जाने बिना कोई मत स्थिर नहीं किया जा सकता । किन्तु यह मानना पड़ेगा कि किसी एक समाचार-पत्रके लिए सब घटनाओंका उल्लेख करना सम्भव नहीं है, क्योंकि घटनाएँ अनगिनत हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि पत्र-पत्रिकाएँ बहुत बड़ी संख्यामें प्रकाशित हों, जिसमें एक विचारशील नागरिक कई पत्र पढ़कर घटनाओंका संग्रह करे और इस प्रकार वस्तुस्थितिकी अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करे । आरम्भमें राजनीतिक शिक्षा देनेके लिए ही प्रायः राजनीतिक प्रश्नोंका प्रकाशन हुआ करता था । प्रकाशकोंमें व्यापार-बुद्धि नहीं थी । यदि कोई आर्थिक लाभ होता था तो यह आनुषंगिक था । विविध राजनीतिक दल अपने विचारोंका प्रचार करनेके लिए पत्रोंका प्रकाशन करते थे । इनके सम्पादक सार्वजनिक नेता या विचारक होते थे और सम्पादकीय लेखोंमें एक विशेष राजनीतिक दृष्टिका प्रतिपादन करते थे । किन्तु ऐसे पत्रोंके पढ़नेवाले बहुत कम होते थे । जनतापर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता था । एक तो अधिकांश जनता साक्षर न थी, दूसरे कम पढ़े-लिखे लोगोंमें विचार-शक्ति नहीं होती । इसका परिणाम यह होता था कि स्वतन्त्र देशोंमें शासक-वर्ग और परतन्त्र देशोंमें शिक्षित-वर्ग ही इन पत्रोंको पढ़ा करते थे ।

अपने देशमें श्री मोतीलाल घोष, लोकमान्य तिलक, श्री अरविन्द घोष, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, श्री विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपतराय, श्री गणेशशंकर विद्यार्थी आदि सभी पत्रोंके सम्पादक थे । जो नेता स्वयं सम्पादक न थे, उनके भी अपने पत्र थे । इन पत्रोंको सदा घाटा रहा करता था । सार्वजनिक चन्देसे ही इनका काम चलता था । इनमेंसे यदि किसीकी लिमिटेड कम्पनी बनी भी तो उनमें हिस्सा लेनेवाले मुनाफेकी आशासे हिस्सा नहीं लेते थे । वे यही समझते थे कि हम दान दे रहे हैं । किन्तु धीरे-धीरे देशमें उद्योग-व्यवसायकी वृद्धि होने लगी । इन विविध कारणोंसे प्रेस भी धीरे-धीरे व्यापारकी दृष्टिसे चलाया जाने लगा । यह स्पष्ट है कि इस काममें पूँजीपतियोंकी बड़ी सुविधा है । पूँजीके बढ़नेसे उद्योग-व्यवसायके मालिकोंकी शक्ति बढ़ जाती है और जब प्रजाके हाथमें राजनीतिक शक्तिके आनेका सुयोग प्राप्त होता है, तब स्वभावतः यह वर्ग उस शक्तिको अपने अधीन करने, कमसे कम नये शासकवर्गको प्रभावित करनेकी चेष्टा करने लगता है । लोकमतको प्रभावित करनेका सबसे अच्छा साधन प्रेस है । इसलिए पूँजीपतियोंकी दृष्टि प्रेसपर पड़ती है और अनेक प्रकारसे वह उसपर अपना नियन्त्रण प्राप्त करना चाहते हैं । गत महायुद्धमें भारतीय पूँजीकी वृद्धि अति मात्रामें हुई है और युद्धके कारण ससारके समाचार जाननेकी उत्सुकता भी सर्वसाधारणमें बढ़ गयी है । इस परिस्थितिसे लाभ उठाना

पूँजीपतियोंके लिए स्वाभाविक था। इसीका फल यह हुआ कि आज कई दैनिक पत्र पूँजीपतियोंने खरीद लिये हैं। इनके लिए नये पत्रोंकी स्थापना कठिन होती है, क्योंकि जनतामे इनकी साख नहीं है। जनता तो राष्ट्रीय विचारोका ही स्वागत करती है। इसलिए ये पुराने पत्रोंको, जिनकी प्रतिष्ठा कायम हो चुकी है, खरीद लेते हैं और ऐसे ही सम्पादकोंको नियुक्त करते हैं, जो राष्ट्रीय विचारके माने जाते हैं। इनकी नीति भी राष्ट्रीय होती है, क्योंकि यदि वे ऐसा न करें तो उनका पत्र लोकप्रिय न हो। पुनः राष्ट्रीय नीतिको अपनानेमे इनका हर तरहसे लाभ ही है, क्योंकि उसके सफल होनेसे भारतीय उद्योग-व्यवसाय ब्रिटिश पूँजीसे स्वतन्त्र होता है और उसको प्रसारके लिए अवकाश मिलता है तथा वे जनताका सद्भाव भी प्राप्त करते हैं। किन्तु वे अपने पत्रोंद्वारा अपने वर्गके हितोका अनेक प्रकारसे समर्थन भी करते रहते हैं। उग्र राजनीतिसे वे सदा धवराते रहते हैं और ब्रिटिश साम्राज्यसे समझौतेके अवसरोंको कभी नहीं खोते। नेताओंका आशीर्वाद प्राप्त करनेकी इनकी सदा चेष्टा रहती है और ऊपर समय-समयपर ये अपना प्रभाव भी डालते रहते हैं। आजकल अपने देशमे कुछ प्रमुख पूँजीपतियोंके अनेक पत्र हैं। इनको एक पत्रसे सन्तोष नहीं है। एक-एकके पास तीन-तीन चार-चार पत्रोंकी लडी है। बिडलाजी 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'लीडर' और 'सर्चलाइट' के मालिक हैं, हिन्दीमे 'हिन्दुस्तान' और 'भारत' इनके पत्र हैं। डालमिया साहब धीरे-धीरे पत्रोंके मालिक होते जा रहे हैं। बम्बईका 'टाइम्स आंव इण्डिया' और दिल्लीका 'नेशनल काल' इन्होंने खरीद लिया है। दक्षिणमे गोयनकाजीका 'इण्डियन एक्सप्रेस' और 'दिनमणि' (तामिल) है। कलकत्तासे भी 'इण्डियन एक्सप्रेस' का एक संस्करण निकलता है। दूसरे दर्जेके व्यवसायी भी, जो राजनीतिमे कुछ रस लेते हैं, इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। सिद्दीकी साहबका मुसलिम लीगी पत्र, 'मीनिंग न्यूज' कलकत्तेसे निकलता है। उनके पास यदि पत्रोंकी लडी नहीं है तो वह कमसे-कम एक पत्र तो अपना अवश्य रखना चाहते हैं। आजकल बिना अच्छी पूँजीके दैनिक पत्र नहीं चल सकते। पूँजीपतियोंने दैनिक-पत्रोंका स्टैण्डर्ड काफी ऊँचा कर दिया है। उसमे समाचार और लेख पर्याप्त सख्यामे रहते हैं, मैगजीन-सेक्शन भी रहता है। यदि पुराने पत्र अपने स्टैण्डर्डको ऊँचा न करे और इन विशेषताओंको न अपनावे तो वे चल नहीं सकते। पूँजीकी कमीसे वह ऐसा प्रायः कर नहीं पाते हैं और इसलिए वे पूँजीपतियोंके हाथमे चले जाते हैं।

यह तो आजकी अवस्था है। अभी बहुत कम पत्र पूँजीपतियोंके अधीन हुए हैं। पर ज्यो-ज्यो शिक्षाका प्रसार होता जायगा, त्यो-त्यो अधिकाधिक पत्र पूँजीपतियोंके हाथमे चले जायँगे और जब देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी, तब हमारे देशमे भी 'प्रेस मैगनेट' तैयार हो जायँगे। उस समय पत्रोंका रूप और उद्देश्य एकदम बदल जायगा। स्वतन्त्र होनेकी प्रेरणा तो रहेगी नहीं। नये आधारपर दलोंकी सृष्टि होगी और नये प्रश्न सर्वसाधारणके सामने होंगे। आर्थिक प्रश्नोंका महत्त्व बढ़ जायगा। पूँजीपतियोंके गुट अपने स्वार्थोंकी पूर्तिके लिए लोकमतको तथा देशकी गवर्नमेण्टको प्रभावित करेंगे। शिक्षाके प्रसारके कारण पाठकोंकी सख्या नित्य बढ़ती जायगी और उनकी पिपासाकी

तृप्ति करनेके लिए समाचारपत्रोंकी संख्या भी बढ़ेगी। अनिवार्य शिक्षाके फलस्वरूप जनतामें समाचार जाननेकी उत्सुकता तो बढ़ेगी, किन्तु अपने स्वल्प ज्ञानके कारण वह उन समाचारोंके महत्त्वको आँक न सकेगी। उस समय विचारकों और राजनीतिज्ञोंके पत्रोंके ग्राहक अपेक्षाकृत कम होंगे। व्यापारियोंको अच्छा मौका मिलेगा और व्यापारियोंके पत्र अधिकाधिक प्रकाशित होने लगेंगे, जिनका एकमात्र ध्येय जनताको अपनी ओर आकृष्ट करना होगा। जनताको राजनीतिमें केवल समाचारसे ही रुचि होती है। उनकी विशेष अभिरुचि युद्धके समाचार, पुरुष स्त्रीके सम्बन्धके किस्से, खेलकूद तथा अपराधके समाचारोंमें होती है। इसलिए ऐसे पत्रोंमें समाचार काफी रहते हैं। सस्ती कहानी और कविता भी लोकप्रिय होती है। अतः जनताको सुरुचिपूर्ण साहित्य देना तथा सार्वजनिक प्रश्नोंपर मत निश्चित करनेमें उनकी सहायता करना इन पत्रोंका लक्ष्य नहीं होगा। हमारे देशमें ऐसा समय शीघ्र आनेवाला है।

इंग्लैण्डका उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ सन् १८८० में पहला कानून पास हुआ था, जिसके द्वारा शिक्षा सर्वसाधारणके लिए अनिवार्य की गयी थी। इस कानूनके प्रयोगमें आनेसे कुछ वर्षोंके अनन्तर समाचारपत्र पढ़नेवालोंकी संख्यामें वृद्धि हुई और लार्ड नार्थक्लिफने इस नये वर्गकी मनोवृत्तिका अध्ययन कर उसकी अभिरुचिके अनुकूल पत्र निकाला। उन्हींके अनुसार उनका उद्देश्य शुद्ध व्यापारी था। अपने मालिकोंको (बोटरोको) शिक्षित करनेके लिए सन् १८७० का कानून पास हुआ था, किन्तु शासकवर्ग इतना ही चाहता था कि मतदाता लिखपढ़ सके और कुशल मजदूर बन सके। अपना 'मालिक' बनाना तो उनके विचारोंसे बहुत दूर था। वह कहते थे कि मतदाता हमारे मालिक हैं, जिस प्रकार हम किसानको अन्नदाता कहते हैं।

नार्थक्लिफके विचारके पत्र-मालिक अपने वचावमें कहते हैं कि सर्वसाधारण जो चाहते हैं वही हम उनको देते हैं। हम सर्वसाधारणके लिए राजनीतिक शिक्षाकी व्यवस्था करनेके लिए नहीं हैं। इन पत्र-मालिकोंका गठबन्धन विज्ञापन देनेवाली फर्मोंसे हुआ और आपसके सहयोगसे दोनों फलने-फूलने लगे।

इस परिवर्तनसे पत्र-जगतमें बड़ी हलचल मची। 'टाइम्स' और 'मैन्चेस्टर गार्जियन' अपना स्वरूप बदलनेके लिए विवश हुए, किन्तु उन्होंने अपने मूल ध्येयका परित्याग नहीं किया। अनेक पत्र बन्द हो गये या नये पत्र व्यापारियोंद्वारा खरीद लिये गये। पुराने स्वतन्त्र विचारके सम्पादक धीरे-धीरे लुप्त होने लगे, पत्रोंपर व्यवस्थापकोंका अधिकार हो गया। आज सम्पादककी अपेक्षा व्यवस्थापकका स्थान ऊँचा है, उसीका अधिक मान और उसीका अधिक पुरस्कार है। कुछ पत्रोंको जीवित रहनेके लिए अपने ढगको बदलना पड़ा। उनको आदर्श और व्यापारके बीच समझौता करना पड़ा। आज उन्हीं पत्रोंकी अधिक विक्री है जिनमें अपराध, स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध और खेलके समाचार अधिक रहते हैं। यद्यपि ये पत्र शुद्ध व्यापारकी दृष्टिसे चलाये जाते हैं तथापि इनकी सहानुभूति पूँजीपतियोंके साथ होती है। अपने मालिकोंके विशेष राजनीतिक विचारोंको भी यह परिलक्षित करते हैं। धीरे-धीरे इनमें शक्तिके लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है और यह राजनीतिक

क्षेत्रमें प्रवेश करते हैं। इङ्गितोसे जनताके विचार कैसे मोड़े जा सकते हैं और उनके भावोका उद्रेक कैसे हो सकता है इस शास्त्रमें वे व्युत्पन्न होते हैं और राजनीतिमें वह अपने मानव-ज्ञानका उपयोग करते हैं। अपने विज्ञापनदाताओका भी इनको लिहाज करना पड़ता है, क्योंकि इनकी आयका मुख्य स्रोत विज्ञापन ही है।

समाचार-पत्रोंके क्षेत्रमें भी एकाधिकार होता जाता है। आजका युग पूँजीके एकाधिकारका है, फिर पत्रोंका व्यवसाय इससे कैसे बच सकता था ? इंगलैण्डके 'प्रेस मैगनेट' कुछ थोड़ेसे पत्रोंसे सन्तुष्ट नहीं है। उन्होंने स्थानीय पत्रोंपर भी धावा बोल दिया है। पत्र-व्यवसायियोंके गटोने स्थानीय पत्रोंमेंसे बहुतोंको खरीद लिया है। सबकी नीति लन्दनसे निर्धारित होती है। आज केम्जले (Kemsley) प्रेसका बोलवाला है। जहाँ जाइये वही आपको इसका पत्र मिलेगा। यही अवस्था अमेरिकामे होती जाती है। अभी हालमें वहाँकी सिनेटने एक कमेटी नियुक्त की थी। उसकी रिपोर्ट है कि १९४१-१९४४ में केवल २ प्रतिशत फर्मोंमें मजदूरोकी पूर्ण संख्याका ६२ प्रतिशत काम करता रहा है और बड़े-बड़े व्यवसायियोंका प्रेसपर अधिकार बढ़ता जाता है।

रिपोर्टमें कहा है कि "स्वतन्त्र रूपसे आलोचना तथा अनुसन्धानका होना तथा विविध दृष्टियोंका स्वच्छन्द रूपसे व्यक्त होना लोकतन्त्रके लिए आवश्यक है। अतः हमको इस बातसे चिन्ता है कि (१) हमारे नागरिक प्रायः एक ही दैनिकपत्र खरीद सकते हैं और (२) बहुतोंके लिए यह पत्र ही पत्र-लड़ाईकी दृष्टि पाठकोके सम्मुख उपस्थित करते हैं। यद्यपि समाचार-पत्रोंकी विक्री क्रमशः बढ़ी है तथापि अमेरिकामे पत्रोंकी संख्या विगत ३० वर्षोंमें तेजीसे घटी है। अब हुत कम समुदाय ऐसे हैं जिनके समाचारोंका एकसे अधिक विवरण प्राप्त हो।

"अन्ततः समाचारोंके संग्रह करनेका काम केवल तीन प्रेस-सर्विसोंके हाथ में है और पत्र-प्रकाशकोंने रेडियो-क्षेत्रपर भी आक्रमण कर दिया है। सन् १९०९ में लगभग २६०० दैनिक पत्र थे और २ करोड़ ४२ लाख प्रतियोंकी विक्री थी। सन् १९३२ में दैनिक पत्रोंकी संख्या घटकर १७८६ हो गयी, किन्तु उनकी विक्रीकी संख्या लगभग दुगुनी अर्थात् ४ करोड़ ३४ लाख हो गयी। आजतक इसी प्रकार पत्रोंकी संख्याका ह्रास तथा विक्रीकी संख्यामें वृद्धि होती गयी है।" रिपोर्टमें आगे चलकर यह भी कहा गया है कि पत्र-लड़ियों द्वारा नियन्त्रित पत्रोंकी संख्याका अनुपात तेजीसे बढ़ रहा है। सन् १९४० में इनके नियन्त्रणमें समस्त विक्रीका ४० प्रतिशत था और केवल १८१ ऐसे नगर थे जहाँ एकसे अधिक पत्र पाये जाते थे जिनकी आपसमें होड़ थी; तथा ८८ प्रतिशत अमेरिकनोकी वस्तियोंको केवल एक ही पत्र नसीब होता था और इस प्रकार एक ही दृष्टि उनके सामने उपस्थित की जाती थी।

एकाधिकारके युगमें प्रबल पूँजीवादी राष्ट्रोंका यही हाल है। किन्तु ये राष्ट्र लोकतन्त्रके भी समर्थक हैं, चाहे यह लोकतन्त्र पूँजीवादी ही क्यों न हो। अतः इन देशोंके विचारशील व्यक्ति इस अवस्थाको देखकर लोकतन्त्रके भविष्यके सम्बन्धमें बहुत चिन्तित हो गये हैं। उनका कहना है कि यदि लोकतन्त्रको विकृत होनेसे बचाना है तो प्रेसके सम्बन्धमें

कुछ करना चाहिये । इसलिए इंग्लैण्डमे पार्लेमेण्टके कई सदस्योंने प्रेसकी जाँच करनेके लिए एक कमीशनकी माँग की है । कोई भी समाजवादी यह नहीं चाहेगा कि राज्यका प्रेसपर नियन्त्रण हो । किन्तु आजकी वहाँकी अवस्था भयावह है । जबतक इसमे परिवर्तन नहीं होता तबतक लोकतन्त्र खतरेमे है । हमारी समस्या यह है कि हम किस प्रकार प्रेसकी स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखते हुए समाचारपत्रोंका सदुपयोग जनताकी शिक्षाके लिए कर सकते हैं । हमको प्रेसको जनताकी शिक्षाके लिए उत्तरदायी बनाना है और साथ-साथ प्रेसकी स्वतन्त्रताकी भी रक्षा करनी है । हमको मनुष्यके उत्तम 'स्व' को जगाना है और जो व्यापारी पत्र मनुष्यकी अधम मनोवृत्तिको जागरूक करते हैं और उसकी कुरुचिको व्यापारके लाभके लिए उत्तेजित करते हैं, उनको हमें रोकना है । हमको इसकी भी व्यवस्था करनी है कि जनताके सामने उभयपक्ष उपस्थित किया जा सके जिसमे वह विचार कर उचित निर्णयपर पहुँच सके, ऐसा नहीं कि केवल पूंजीपतिका ही पक्ष उनके सम्मुख हो ।

लार्ड नार्थक्लिफने इंग्लैण्डके पत्र-जगत्मे क्रान्ति उपस्थित कर दी थी, किन्तु इधर सर्वसाधारणके लिए शिक्षाका मापदण्ड ऊँचा कर देनेसे तथा नागरिकों और सैनिकोंमे प्रौढ शिक्षाकी व्यवस्था कर देनेसे एक नवीन युगका आरम्भ हो रहा है, जहाँ जनतामें उच्च शिक्षाके प्रचारमे वृद्धि होनेसे पाठकोका एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया है, जो केवल समाचारोंसे सन्तुष्ट नहीं है और जिसे सनसनीदार खबरे पसन्द नहीं हैं । वह देश-विदेशकी समस्याओं और उलझनोंको समझना चाहता है । उसमे छिछलापन नहीं है । वह युगकी समस्याओंका गम्भीर अध्ययन करना चाहता है । वह ऐसे ही पत्र पसन्द करता है जो इस कार्यमे उसकी सहायता करनेकी क्षमता रखते हो । किन्तु अभी व्यापारी पत्रोंका प्रभाव कम नहीं हुआ है और नये प्रकारके पत्रोंको प्रतिष्ठा प्राप्त करनेमे अभी समय लगेगा ।

हमारे देशमे नार्थक्लिफके युगकी अभी सूचना ही मिली है, किन्तु प्राथमिक शिक्षाके प्रसारके साथ-साथ हमारे यहाँ भी वही अवस्था उत्पन्न हो जायगी जो इंग्लैण्डमे उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तमे हुई थी । वहाँकी अवस्था नित्य विगड़ती जाती है और आज इंग्लैण्ड-निवासी इस विषयमे चिन्ता प्रकट कर रहे हैं । क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम इंग्लैण्डके अनुभवसे शिक्षा ले और अपने समाजको उन दुराइयोंसे बचानेका आजसे ही प्रयत्न करें ?

केवल प्राथमिक शिक्षासे हमारा काम नहीं चलेगा । मौलिक शिक्षा (Basic Education) की पद्धतिको कार्यान्वित करनेसे ही हम मतदाताओंको इस योग्य बना सकते हैं कि वे प्रश्नोंपर सूक्ष्म विचार करना सीखें । सच्ची लोकतन्त्रकी स्थापनाके लिए शिक्षित और सतत् जागरूक जनताका होना आवश्यक है और यह उद्देश्य केवल लिखना-पढ़ना सिखा देनेसे नहीं होगा । जनताके सुसंस्कृत बनानेका महान् उद्योग ही लोकतन्त्रकी स्थापनामे सच्चा सहायक हो सकता है । अभी हमको बहुमतका आदर करना सीखना है और सीखना है शान्तिके साथ वाद-विवाद करना और अपने निर्णयोंमे तर्क और युक्तिको ऊँचा स्थान देना । जो राष्ट्र जात-पाँतके भेदोंसे जर्जरित हो रहा है और जिसका समाज ऊँच-नीचके भेदभावपर आश्रित है, उसके लिए जो कार्यक्रम बनाया जाय उसमे शिक्षाको

उत्तम स्थान देना चाहिये । अब समय आ गया है जब हमारी आँखें अतीतसे हटकर भविष्यकी ओर होनी चाहिये । अतीतके बोझसे तो हम दबे जाते हैं । बुद्धिमान पुरुष मुर्दोंके लिए नहीं लड़ता । अब हम ऐसे कमजोर भी नहीं हैं जो हमको अतीतके गौरवके चलपर दुनियाकी आँखोंमें अपनेको ऊँचा उठानेकी आवश्यकता हो । इस सम्बन्धमें कार्लमार्क्स ने लिखा था—

“क्या वह प्रेस, जिसका व्यापारिक लाभके लिए संचालन होता है और जिसका इस प्रकार नैतिक पतन हो जाता है, वह स्वतन्त्र है ? इसमें सन्देह नहीं कि लेखकोंको जिन्दा रहने और लिखनेके लिए धन कमाना जरूरी है, किन्तु उसको धन कमानेके लिए ही जिन्दा रहना और लिखना नहीं चाहिये । प्रेसकी पहली स्वतन्त्रता इसमें है कि व्यापारसे उसका छुटकारा हो । जो लेखक प्रेसके पतनके लिए जिम्मेदार हो और जो उसको अर्थका दास बना देता है, वह दण्ड पानेके योग्य है और इस आरम्भिक दासताके लिए दण्ड वह बाह्य दासता है जिसे प्रेसका नियन्त्रण (Censorship) कहते हैं अथवा कदाचित् उसका जिन्दा रहना ही उसका दण्ड है ।”

पूँजीवादके आजके युगमें पूँजीवादी राष्ट्रोंमें प्रेसकी ऐसी ही दुर्दशा होगी । एकमात्र समाजवाद ही प्रेसकी वर्तमान दासताको दूर कर सकता है । समाजवादी समाजमें ही व्यक्तित्वके पूर्ण विकासकी सम्भावना है । आजके समाजमें रुपयेका बड़ा जोर है । मनुष्यकी माप रुपयेसे ही होती है । यह सब बदलना है । समाजमें जीवनके सच्चे सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्योंको प्रतिष्ठित करना है । जो लोग इष्टत्व-अनिष्टत्वकी छान-बीन कर सदबुद्धिसे प्रेरित हो कल्याणकारी कार्योंमें अग्रसर हैं वही पूँजीवादके अभिशाप से समाजका परित्राण कर सकते हैं ।^१

विचारकोंके सम्मुख एक नयी समस्या

विश्व-समाजमें आज केवल सामाजिक क्रान्ति ही नहीं हो रही है, किन्तु विश्वके विचारकोंमें भी एक आध्यात्मिक उथल-पुथल मची है । ऐटम बमके आविष्कारने इन विचारकोंको भविष्यके सम्बन्धमें गम्भीरताके साथ विचार करनेके लिए विवश कर दिया है । फासिटीवाद और नाजीवादके मौलिक आधारके अध्ययनने भी भविष्यके सम्बन्धमें सन्देह उत्पन्न कर दिया है । समाजवादसे जिनको बड़ी आशा थी, जिन्होंने रूसके समाजवादमें अपने स्वप्नोंको स्थूल रूप धारण करते देखा था और जो इस कारण स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीके आदरणीय सदस्य हो गये थे, उनमेंसे कई विचारक रूसके समाजवादका विकृत रूप देखकर इतने क्षुब्ध और निराश हुए कि वह रूसके कट्टर विरोधी बन गये और धीरे-धीरे उनमेंसे कुछकी यह धारणा हो गयी कि मार्क्सवादमें ही कोई ऐसा मौलिक दोष है, जिसके कारण यह विकार उत्पन्न हुआ है । महायुद्धके बादसे एक निश्चित योजनाके अनुसार अपने

आर्थिक जीवनका संगठन करना प्रत्येक राज्यके लिए प्रायः अनिवार्य-सा हो रहा है । इस अर्थनीतिका परिणाम क्या होता है, इसको भी इन विचारकोंने रूस तथा जर्मनीमें देखा है । उनका कहना है कि इस प्रकारकी अर्थनीतिका एक परिणाम यह होता है कि नीकरशाही-का बाहुल्य हो जाता है तथा सामाजिक जीवनके प्रत्येक विभागपर राज्यका नियन्त्रण हो जाता है, जो लोकतन्त्र तथा मानव-स्वतन्त्रताके लिए अत्यन्त भयावह है । इन विचारकोंका कहना है कि यह अर्थनीति ही अधिनायकत्वको जन्म देती है ।

आजका युग बहुजनका युग है । इस युगमें समाज प्रसुप्त और निश्चेष्ट नहीं है । पूंजीवादने जनताके महत्त्वको बढ़ा दिया है । पूंजीवादको अपने मुनाफेके लिए असंख्य मजदूरोंको कल-कारखानोंमें लगाना पड़ा । धीरे-धीरे यह मजदूर अपनी संस्थाओंमें संगठित होने लगे तथा अपनी माँगोंको पूरा करनेके लिए हड़ताल करने लगे । धीरे-धीरे क्रान्तिकारी बुद्धिजीवियोंने उनको समाजवादकी विचारधारा दी और मजदूर वर्गको ही इस नयी विचार-पद्धतिकी मूलभूति बनायी । पूंजीवादके गर्भसे एक नये समाजकी सृष्टि होने लगी । मजदूर-समाज मजबूत होने लगा । रूसमें मजदूरोंकी पहली सफल क्रान्ति हुई और इंग्लैण्डमें मजदूरोंका राज्य स्थापित हुआ । इन विशेष कारणोंसे यह स्पष्ट इङ्गित होता है कि एक युगकी परिसमाप्ति और दूसरे युगका उपक्रम हो रहा है । अतः यह शती सामान्य जनकी शती कहलाती है । आज बहुजनके हितोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । आज जो कोई शासक हो उसे जनताके नामपर ही शासन करना होगा । ऐसी परिस्थितिमें जनताके विचारोंसे अवगत रहना तथा उनका नियन्त्रण करना राज्यके लिए आवश्यक है । इसलिए जिस तरह कारखानोंमें बड़े पैमानेपर विविध वस्तुएँ तैयार होती हैं, उसी तरह राज्यकी ओरसे विचार भी तैयार किये जाते हैं । ब्राडकास्टिंगपर राज्यका नियन्त्रण इसीलिए होता है । आज सामाजिक नियन्त्रणके लिए नये उपकरणोंका प्रयोग करनेके लिए राज्य बाध्य है । विज्ञानने इन नये उपकरणों और साधनोंको हमारे लिए उपलब्ध किया है । कई सामाजिक प्रणालियाँ प्रचलित हो गयी हैं । यदि लोक-कल्याणके लिए इनका उपयोग किया जाय, तो समाजका मंगल हो सकता है । किन्तु यह भी स्पष्ट है कि यह राज्यमें असीम शक्तिको केन्द्रित कर देती है और यदि इनका दुरुपयोग हो तो अमंगल ही अमंगल है ।

उदाहरणके लिए रण-पद्धतिमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गये हैं । नूतन अस्त्रोंका आविष्कार हो गया है और नर-संहार अत्यन्त सुलभ हो गया है । इन आविष्कारोंने मुट्ठीभर लोगोंके हाथमें शक्ति केन्द्रित कर दी है । जहाँ यह विदेशी आक्रमणसे देशकी रक्षा करनेमें अधिक समर्थ है, वहाँ इन्हीं साधनोंसे जनताके विप्लवको अधिक सुगमतासे दबा सकते हैं ।

कुछ विचारकोंका कहना है कि यह सामाजिक प्रणालियाँ स्वतः न कल्याण करनेवाली हैं और न अमंगल करनेवाली हैं । जिनके हाथोंमें इन नवीन अस्त्रोंका प्रयोग है, उनकी इच्छा-पर यह निर्भर करता है कि इनका सदुपयोग होगा अथवा दुरुपयोग । किन्तु यह निश्चित नहीं है कि शासकोंकी इच्छा कैसी होगी । इस अनिश्चितताके कारण वह इन सामाजिक

प्रणालियोंके पक्षमें नहीं है। इनका दुरुपयोग होते उन्होंने देखा है। वह देखते हैं कि निश्चित योजनाके अनुसार जो अर्थनीति निर्मित होती है उसकी दिशा अधिनायकत्वकी ओर होती है। वह दोनोंको कार्य-कारणके रूपमें देखते हैं। अतः वह इसको स्वीकार नहीं करते कि ऐसे उपाय भी हो सकते हैं, जिनका आश्रय लेकर हम इस अर्थनीतिसे लाभ उठाते हुए समाजकी रक्षा उसके दोषोंसे कर सकते हैं। फासिटीवादकी वर्तमानता वह अपनी आँखों देख चुके हैं। ससारने लोकतन्त्रकी रक्षाके लिए एक महान् युद्ध रचा और नाजी-शक्तिका अन्त किया। अब वह यह चाहते हैं कि समाजका एक ऐसा रूप हो जिसमें पुनः फासिटीवादका जन्म न हो सके। उनका विचार है कि जबतक यह अर्थनीति रहेगी उसका भय पुन-पुन उपस्थित होता रहेगा।

यह विचारक इसलिए किसी निश्चित योजनाके आधारपर किसी अर्थनीतिका निर्माण नहीं चाहते। यह सबसे अधिक महत्त्व लोकतन्त्र, मानव-स्वतन्त्रता तथा व्यक्तित्वकी परिपूर्णताको देते हैं और क्योंकि इनके मतमें ऐसी अर्थनीति इन सिद्धान्तोंकी पोषक नहीं है, वरन् उसके द्वारा इनको क्षति पहुँचती है, अतः वह ऐसी अर्थनीतिके विरोधी हैं। वह जानते हैं कि पूँजीवादी समाजमें विपमता और अस्त-व्यस्तता रहती है, किन्तु इनके मतमें यह सब वर्दाशित किया जा सकता है यदि मानव-स्वतन्त्रताकी रक्षा हो सके। इसी कारण कुछ विचारक स्वच्छन्द व्यवसायके पक्षपाती हैं। अमेरिकाका उदाहरण देकर वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि साधारण जनकी आर्थिक अवस्था पूँजीवादी समाजमें भी उन्नत हो सकती है। उनका विचार है कि गैरसरकारी व्यवस्था अच्छी और सस्ती होती है और उससे स्वतन्त्रताकी भी रक्षा होती है। इनका कथन है कि लोकतन्त्रका आधार आर्थिक क्षेत्रकी स्वतन्त्रता ही है और यदि राज्यका नियन्त्रण आर्थिक क्षेत्रपर होता है तो उससे लोकतन्त्रका ह्रास होता है।

थोड़ेसे ऐसे विचारकोंकी दलीलोका खण्डन करना कुछ कठिन नहीं है। यह अवश्य सच है कि निश्चित योजनाके आधारपर निर्मित अर्थनीतिसे लोकतन्त्रको भय है, किन्तु ऐसा नहीं है कि इस भयके निराकरणका कोई उपाय नहीं है। पुनः जब यह स्पष्ट है कि आजके युगमें ऐसी अर्थनीतिको अपनाना अनिवार्य हो गया है, तो उसके दोषोंके निरसनका उपाय सोचना ही पड़ेगा। हमारे मतमें ऐसी अर्थनीति और लोकतन्त्र तथा मानव-स्वतन्त्रताके बीच सामञ्जस्य स्थापित हो सकता है। इस सम्बन्धमें कई सुझाव रखे गये हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनका केन्द्रीकरण नितान्त आवश्यक है। किन्तु अन्य व्यवसायोंका विकेन्द्रीकरण होनेसे लोकतन्त्रको व्याघात नहीं पहुँचता। पुनः कार्पोरेशन तथा स्थानीय जन-संस्थाओंके अधीन व्यवसायोंको लेकर लोकतन्त्रकी रक्षा हो सकती है। सहयोग समितियोंद्वारा विविध छोटे व्यवसायोंको संचालित करनेसे भी अधिनायकत्वका दोष बचाया जा सकता है।

पुनः सामान्य जनता लोकतन्त्रके महत्त्वको तभी समझ सकती है जब उसके रोटी-कपड़ेका प्रश्न हल हो। अमेरिकाका उदाहरण सर्वत्र लागू नहीं होता। वह लोकतन्त्र अधूरा है जो समाजकी आर्थिक विपमताको दूर करनेमें असमर्थ है। जो तृप्त है, जिनके

आगे कोई ऐसी कठिन आर्थिक समस्या नहीं है, वह अवश्य मानव-अधिकारों की स्वतन्त्रता का महत्व समझते हैं। किन्तु जो बेकार है अथवा आर्थिक कष्ट में है वह केवल भाषण की स्वतन्त्रता से सन्तुष्ट नहीं हो सकते। सामान्य जन की सांस्कृतिक उन्नतिके लिए उसकी आर्थिक स्थितिकी उन्नति आवश्यक है।

कुछ ऐसे भी विचारक हैं जिनका विश्वास मनुष्यपरसे उठ गया है। नैतिकता का ह्रास देखकर ही उनकी आस्था उठ गयी है। पहले ईश्वर में 'लोगों' का अटल विश्वास था। विज्ञान ने इस विश्वास को खोखला बना दिया और १९ वीं शती में मानव की प्रतिष्ठा हुई तथा जीवन में नये मूल्यों की स्थापना और जीवन के नये मूल्यों की सृष्टि हुई। इनमें ही मानव-स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र है। किन्तु संहार के नये साधनों के प्रयोग से तथा सत्य की अप्रतिष्ठा होने से हमारे आदर्श भी नष्ट हो रहे हैं। आज लोग यथार्थवाद की पूजा करते हैं और आदर्शवादियों को मूर्ख और पागल समझते हैं। परिस्थितिके अनुसार आचरण करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता समझी जाती है; मानो जीवन का कोई गम्भीर उद्देश्य ही नहीं रह गया है! मानव-बुद्धिपरसे इन विचारकों का विश्वास उठ-सा गया है और वह लोकतन्त्र को उचित प्रेरणा देने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इससे भी गम्भीर किसी आदर्श की उनकी तलाश है। वह पुनः धर्म में शरण लेते हैं। यूरोप के विचारक ईसाई धर्म की पुनः स्थापना करना चाहते हैं? उनका विचार है कि ईसाई धर्म से ही लोकतन्त्र तथा समता के सिद्धान्त निकले हैं। अतः स्वभावतः उनकी दृष्टि ईसाई धर्म की ओर जाती है। पोप के शासन में शान्ति भी थी और विविध राज्यों के बीच मैत्री भी। आज वह देखते हैं कि विविध राज्य एक-दूसरे के वैरी हैं और वह यह भी समझते हैं कि किसी एक राज्य का समस्त संसार पर आधिपत्य कायम करके विश्व-शान्ति नहीं हो सकती। अतः वह पोप का शासन फिर से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। कुछ विचारक अध्यात्मवाद में ही शान्ति पाते हैं।

हमारे मत में मानव के ऊपर इतना अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। जीवन के नये सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त हैं। इन मूल्यों पर जिनका अटल विश्वास है वह उन पर उसी प्रकार दृढ़ रह सकते हैं, जिस प्रकार धार्मिक व्यक्ति दुःख-यातना भोगते हुए भी अपने धार्मिक विश्वास पर अटल रहता है। आज के युग में सामाजिक अवस्था का पूर्ण परिचय प्राप्त कर रचनात्मक क्रान्तिकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। सामाजिक संगठन में बिना महान् परिवर्तन किये हमारा जिन्दा रहना भी कठिन है। समाज के प्रश्न धर्म के दामन में से मुँह छिपाने से हल नहीं होंगे। समाज की उन्नति करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। उसको अपनाना होगा। पोप का शासन फिर से प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। हाँ! उसके प्रभाव का दुरुपयोग प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ आज भी कर रही हैं। इस विज्ञान के युग में रहस्यवाद की प्रतिष्ठा करना कठिन है। विज्ञान का सदुपयोग कीजिये; समाज में आदर्शों की प्रतिष्ठा कीजिये; मनुष्य के चरित्र की ओर ध्यान दीजिये; न कि विज्ञान को छोड़ कर कपोल-कल्पित बातों को फिर से जिन्दा कीजिये। मनुष्य के चरित्र पर उसकी परिस्थितिकी प्रभाव अवश्य पड़ता है, किन्तु व्यक्तिगत चरित्र के गठन की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

विद्याचरण-सम्पन्न व्यक्ति ही समाजका सच्चा नेतृत्व कर सकते हैं। सामाजिक प्रणालियाँ स्वतः कुछ नहीं कर सकती, जबतक उनको कार्यान्वित करनेवाले सर्व-भूत हित रत नहीं होते, सामाजिक परिस्थितिके अनुकूल प्राणी होनेसे ऐसे व्यक्तियोंकी समाजमें वृद्धि होगी। जब सामाजिक स्थिति जटिल होती है तभी उसको सुलझानेके लिए महापुरुष जन्म लेते हैं और आर्त-जनता उनका स्वागत करनेके लिए तैयार होती है। आजका विचार-विमर्श तथा स्थितिको सुधारनेके लिए बताये गये अनेक सुझाव इस बातको दिखाते हैं कि समाजके हृदयका मन्थन हो रहा है। समस्या उत्पन्न हो गयी है, उसका हल भी हमको प्राप्त होगा। हम आज अन्धकारमें टटोल रहे हैं किन्तु प्रकाश भी अवश्य दिखायी देगा और समाजका अन्तर्गते निस्तार होगा। किन्तु आजतक जो उन्नति हुई है, उसको ताकपर रखकर नहीं, बरंच उसका उत्तम उपयोग करके ही हमारा अभीष्ट सिद्ध होगा।”

फासिज्मका वास्तविक रूप

पूँजीवादके ह्रासका युग

पूँजीवादके लिए ह्रास और अवनतिका युग है। यो तो पूँजी-प्रथामे संकटका काल समय-समयपर बराबर उपस्थित होता आया है, क्योंकि ऐसा होना पूँजी-प्रथाके लिए अनिवार्य है, पर जो संकट संन् १९२९ मे आरम्भ हुआ, वह जल्द टलता नजर नहीं आता। हो सकता है कि भगीरथ प्रयत्न करनेपर सम्पत्की अवस्था कुछ दिनोंके लिए फिर लौट आये, पर अन्तर्गते इसका फल यही होना है कि निकट भविष्यमें यह संकट और भी भीषण रूप धारण करेगा। उस समय यदि पूँजी-प्रथाके आन्तरिक विरोधको मिटानेका प्रयत्न न किया गया तो वर्तमान सभ्यताका निश्चय ही अन्त हो जायगा और संसारका एक बड़ा हिस्सा अनिश्चित कालके लिए अन्धकार और बर्बरताके खड्डेमें जा गिरेगा।

नयी मशीनोकी सहायतासे पैदावारको अपरिमित रूपसे बढ़ानेका खूब मौका मिला। आपसकी प्रतिस्पर्धाके कारण मुनाफा कमानेके लिए पूँजीपतियोने आवश्यकतासे अधिक माल तैयार कर दिया। इसका फल यह हुआ कि मशीनका माल नहीं विक सका और व्यापारमें संकट उपस्थित हो गया। कारखानोको बन्द कर देना पड़ा, कारखानेदारोका दिवाला निकल गया और मजदूरोकी बेकारी बढ़ने लगी। कुछ दिनोंमें गोदामोका भरा माल विक गया, धीरे-धीरे बन्द कारखाने फिर खुलने लगे, मजदूरी बढी और व्यापार फिर तेजीसे चलने लगा। किन्तु यह अवस्था बहुत दिनोंतक कायम न रही। फिर वही रफ्तार वेढंगी शुरू हुई। प्रत्येक कारखानेमें अपरिमित मात्रामे माल तैयार होने लगा। बाजारमें मन्दी हो गयी। खरीददारोकी कमीसे माल फिर गोदाममें इकट्ठा होने लगा। यह दौर बराबर चलता रहा। सम्पत् और विपत्की अवस्थाएँ ५-७ वर्षका अन्तर देकर बराबर उपस्थित होती रही।

आर्थिक संकटकी दवा समाजवाद

यद्यपि आरम्भमें बड़े पैमानेके व्यवसायने ही अवाधित स्पर्धाको जन्म दिया था, तथापि अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गयी है। व्यवसायकी आवश्यकताओंको बिना विचारे, उत्पादनकी क्रियाको बढ़ाते चले जानेका यही फल है। उत्पादन-शक्ति अब इस दर्जेतक बढ़ गयी है कि पूंजी-प्रथाका उसके साथ सामंजस्य नहीं रह गया है। पूंजीप्रथामे उत्पादन-शक्तिकी अब और उन्नति नहीं हो सकती। जबतक बड़े पैमानेका व्यवसाय वर्तमान पद्धतिके अनुसार संचालित होता रहेगा तबतक मानव-सभ्यताको भय बना रहेगा, मजदूरोंका कष्ट बढ़ता रहेगा तथा साथ-साथ पूंजीपति भी बरवादीसे न बच सकेंगे। दो ही उपाय हैं, या तो व्यवसायकी इस नयी पद्धतिका अन्त कर दिया जाय या समाजकी एक नयी व्यवस्था की जाय जिसमें बड़े पैमानेका व्यवसाय फल-फूल सके और अपने आन्तरिक विरोधोंसे छुटकारा पा सके। जो नयी सामाजिक व्यवस्था होगी, उसमें कारखानेदार न होंगे जो आपसमें प्रतिद्वन्द्विता करें। उस नयी व्यवस्थामे एक निश्चित योजनाके अनुसार तथा समाजके सब सदस्योंकी आवश्यकताके अनुसार औद्योगिक उत्पादन होगा। प्रतिद्वन्द्विताके स्थानमें सहयोग होगा। बिना विचारे व्यक्तिगत लाभके लिए जो काम देवाधीन हो रहा है, उसके स्थानमें बुद्धि-पूर्वक तैयार की हुई एक योजनाके अनुसार कार्य होगा। यह व्यवस्था समाजवादकी व्यवस्था है। मानव-समाजको दारुण परिणामसे बचानेका यही एकमात्र उपाय है। पूंजी प्रथा विकासकी उस चरम सीमाको पहुँच गयी है जहाँ वह उत्पादनकी वृद्धिमें रुकावट डालती है। पूंजीप्रथा अपना काम समाप्त कर चुकी है। समाजकी भावी उन्नतिके लिए इस प्रथाका लोप आवश्यक है। पूंजीप्रथाकी मर्यादित सीमाके भीतर उन्नतिकी अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है।

पूँजी और पूँजीपति

अबतक यही समझा जाता रहा है कि यह व्यापार-संकट तथा औद्योगिक शक्तियोंका यह प्रपञ्च और अपव्यय अनिवार्य है, क्योंकि बाजारोंके हेर-फेरसे तथा अचिन्त्य कारणोंके वश अथवा युद्ध, दुष्काल या आर्थिक आपदासे ऐसा होता है। किन्तु अब यह बात स्पष्ट हो गयी है कि व्यवसाय, कृषि, व्यापार, गमनागमनके साधन तथा यन्त्रोंमें जो असाधारण उन्नति हुई है उसके कारण उत्पादनकी शक्तियोंमें इतनी अधिक वृद्धि हो गयी है कि जितना माल तैयार किया जा सकता है उतना इसलिए नहीं तैयार होता कि वह ऐसी कीमतपर नहीं बेचा जा सकता, जिसमें लागत भी निकल आवे और मुनाफा भी बना रहे। इसलिए आज अनेक कृत्रिम उपायोंसे वस्तुओंकी कीमत बढ़ानेका उद्योग किया जाता है; कारखाने बन्द कर दिये जाते हैं, मजदूरोंको छुट्टी देदी जाती है, अन्न आदि वस्तुएँ नष्ट कर दी जाती हैं और उत्पादनको नियन्त्रित करनेके लिए प्रयत्न किये जाते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री इस गम्भीर अवस्थाके लिए उन राजनीतिक तथा आर्थिक कठिनाइयोंको जिम्मेदार ठहराते हैं, जो युद्धके बाद पैदा हो गयी हैं। कर्जका बोझ, टेरिफ-युद्ध, पुराने सुप्रतिष्ठित बाजारोंका बन्द हो जाना तथा

आत्मनिर्भरताके भावका प्राबल्य यह सब बातें पूँजीप्रथाके संहारके मुख्य कारण नहीं हैं, किन्तु एक अनिवार्य रोगके ऐसे लक्षण हैं, जो रोगका उद्दीपन करते हैं।

पूँजीपतियोमें जो दूरदर्शी हैं वह साफ देखते हैं कि यदि वह अपने मुनाफेको सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उनके लिए सिवाय इसके दूसरा चारा नहीं है कि वह स्वयं योजनाके अनुसार राष्ट्रके आर्थिक जीवनका सघटन करे, कमसे कम, व्यापारके प्रत्येक क्षेत्रमें प्रभावशाली व्यापारियोंने इस बातको मान लिया है कि यदि रोजगारमें मुनाफा कमाना है तो उत्पादनकी शक्तियोंको सीमित और नियन्त्रित करना पड़ेगा। बिना इस सिद्धान्तको सामान्य रूपसे स्वीकार किये हुए ही कई व्यवसायोमें स्पर्धाको रोकनेका प्रवन्ध किया गया। व्यवसायियोंने आपसमें पैदावार तथा कीमत निर्धारित करनेके लिए समझौते किये और एक समझौतेके आधारपर बाजारोका बँटवारा कर लिया। कभी एक देशके भीतर एक व्यवसायके विविध कारखानेदार आपसमें तसफिया कर लेते थे और कभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते भी होते थे। अपने वर्गके स्वार्थोंकी रक्षाके लिए एक सामान्य नीतिका अनुसरण करना पूँजीपतियोंके लिए आवश्यक हो गया है, किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है क्योंकि बड़े-बड़े व्यापारियोंके लिए अपने व्यापारपर अपना अक्षुण्ण अधिकार छोड़ना दुष्कर है और सबके लिए राष्ट्रीय आधारपर व्यवसाय-योजनाकी आवश्यकता समझना भी असम्भव है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्पर्धा

पूँजीपद्धतिके अनुसार सगठित राष्ट्रोंके लिए व्यवसायका क्षेत्र दिनपर-दिन संकुचित होता जाता है। दुनियाका बँटवारा हो गया है। उपनिवेशोमें भी व्यवसायकी उन्नति होती जाती है। इससे संसारका बाजार इन औद्योगिक राष्ट्रोंके लिए संकुचित होता जाता है। इसलिए जबतक इन राष्ट्रोंकी स्पर्धा पूर्णरूपसे जारी रहती है, तबतक व्यवसायमें मुनाफेपर पूँजी लगानेके लिए अवसर कम होते जाते हैं। यह अवस्था तभी सुधर सकती है, जब एक नये आधारपर प्रमुख पूँजीवादी राष्ट्र संसारके व्यवसाय और बाजारका बँटवारा कर ले। किन्तु पूँजीप्रथामे यह सम्भव नहीं है। अवस्था इसके सर्वथा प्रतिकूल है। संसारका व्यापार जितनाही अधिक सिकुड़ता है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध जितने ही अधिक अव्यवस्थित होते हैं, उतना ही अधिक विविध राष्ट्र एक आर्थिक युद्धके लिए अपनेको शस्त्रोंसे सुसज्जित करते जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक जीवनकी रक्षाके लिए तैयारी कर रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपनेको आत्मनिर्भर करना चाहता है। वह नये बाजार और नये प्रदेशकी तलाशमें है। वह अपने देशसे दूसरोंके व्यवसायको निकालना चाहता है। जिन क्षेत्रोंमें वह स्वयं पिछड़ा हुआ है उनमें वह उन्नति करना चाहता है। इससे राष्ट्रीयताकी भावनाको उत्तेजना मिलती है। पूँजीप्रथाकी वर्तमान आवश्यकताओंके कारण इस भावनाको उत्तेजना देनेकी जरूरत है। किन्तु यदि प्रत्येक राष्ट्र इस नीतिका अनुसरण करे तो अन्तर्राष्ट्रीय अव्यवस्था और अस्तव्यस्तता और भी बढ़ जावेगी।

फासिज्म क्या है

वास्तवमे पूंजी-प्रथाका कार्य समाप्त हो चुका है । इसने संसारका बाजार और संसारव्यापी एक आर्थिक पद्धति कायम कर दी है । उसके आन्तरिक विरोध विकसित हो गये हैं, अब वह केवल प्रतिक्रियाकी पद्धति होकर ही रह सकती है । यही प्रतिक्रिया फासिज्म है ।

संसारकी आर्थिक पद्धतिका विघटन हो रहा है । राष्ट्र अब आर्थिक युद्धकी तैयारीमें लगे हैं । राजनीतिक रूपमे उसीका प्रतिफल फासिज्म है । जबसे पूंजीप्रथाका ह्रास होने लगा है, तभीसे प्रत्येक पूंजीवादी राष्ट्रमे फासिस्ट आन्दोलनके विकासके लिए कमोवेश अनुकूल-अवस्था रही है ।

फासिस्ट राज्य आर्थिक राष्ट्रीयताकी ओर झुक रहे हैं । वह व्यवसायकी दृष्टिसे स्वतन्त्र होना चाहते हैं । इस मामलेमे आत्म-निर्भरता प्राप्त करनेकी उनकी चेष्टा रहती है । इस प्रकार वह संसारकी आर्थिक पद्धतिको विघटित कर देते हैं । साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी विघटित हो जाते हैं और संसारका व्यापार ठप हो जाता है ।

इस पद्धतिके द्वारा ही पूंजीवादी देशोका उत्थान हुआ है । इस पद्धतिके विनाशसे, उनके जीवनका परम आवश्यक आधार नष्ट हो जाता है । इसलिए उनकी प्रतिद्वन्द्विता और भी भीषण हो जाती है । फासिज्मके बढ़नेसे राष्ट्रोंके पासके विरोध और भी तीव्र हो जायेंगे । जो राष्ट्र आज फासिस्ट नहीं हैं, उनको भी युद्धकी नीति अपनानी पड़ेगी तथा फासिज्मकी ओर अग्रसर होना पड़ेगा । फासिज्ममे उन्नतिके लक्षण नहीं हैं । यह पूंजी-प्रथाके ह्रास और अवनतिको और भी बढ़ाता है । पूंजीप्रथाको जीवित रखनेकी यह अन्तिम चेष्टा है ।

इटलीमे फासिस्ट पार्टीको अपना अधिनायकत्व जमानेमे कुछ साल लग गये थे, पर जर्मनीके नाजीदलने वही काम चन्द महीनोमे ही कर डाला । जर्मनीके सामने इटलीका नमूना तैयार था । जर्मनीमे जहाँ समाजवादी तथा कम्युनिस्ट दल सुसंगठित थे फासिज्मकी स्थापनाका एक प्रधान कारण यह रहा है कि वहाँके पूंजीपतियोने इस बातकी आवश्यकताको महसूस किया कि यदि पूंजीप्रथाको जीवित रखना है तो पूर्व इसके कि समाजवादी समाजकी स्थापना करे, उन्हें व्यवसाय-योजनाका काम अपने हाथमे लेना चाहिये । उनको इसका वास्तविक भय था कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो रूसकी तरह ही हाल होगा । फासिस्ट आन्दोलनके मूल आधार मध्यम वर्गकी निम्नश्रेणीके वह लोग हैं जो कंगाल हो गये हैं । युद्धके बाद जो मार्क-(जर्मन सिक्का) का भाव गिर गया था, उससे यह लोग तबाह हो गये थे । सन् १९२९ की मन्दीने इनको और बरबाद कर दिया । यही समुदाय फासिस्ट आन्दोलनका मूल आधार बना ।

फासिज्मका वास्तविक रूप

जिन राष्ट्रोंमे अभी फासिज्म स्थापित नहीं हुआ है, वहाँ भी फासिज्म प्रवृत्तिको उत्तेजना मिली है । इंग्लैण्डमे मास्लेका गिरोह है । स्विट्जर लैण्डमे 'डाइफाटेन' दल है ।

फ्रांस, बेलजियम, स्वीडन आदि देशोमे भी इसी प्रकारके संगठन पाये जाते हैं । सयुक्तराष्ट्र अमेरिकामे रूजवेल्टकी योजना धीरे-धीरे फासिज्मके लिए जमीन तैयार कर रही है ।

जर्मनीका नात्सी दल

इन नवीन विचारोकी सफलता देश और कालपर निर्भर करती है । यह छोटे-छोटे समुदाय बहुत दिनोतक इसी अवस्थामे रह सकते हैं, पर यदि आर्थिक और सामाजिक अवस्था फासिज्मके अनुकूल हुई, समाजवादी जनताके विश्वासपात्र न रहे तथा जनता मे एक राष्ट्रवादी अधिनायककी चाह पैदा हुई तो यह छोटे-छोटे समुदाय एक बृहत् दलके प्रारम्भ बन सकेंगे ।

यह प्रतिक्रिया बहुत दिनोतक चल सकती है, यद्यपि यह भी असन्दिग्ध है कि इसका अन्त समाजवाद करेगा । जर्मनीके फासिस्ट बहुत मजबूत हैं । उनके पास केवल राज-शक्तिके ही सब साधन नहीं हैं, किन्तु प्रचारके भी सब साधन हैं—छापाखाना, कला, विज्ञान, सब तरहके क्लब, एसोसियेशन, आर्थिक और सामाजिक संगठन, चर्च इत्यादि । संक्षेपमे, समस्त राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवनके संगठित रूप, फासिस्ट पार्टीको मजबूत बनानेके काममे जान-बूझकर वेददीं से लगाये जाते हैं । अन्य दलोका अन्त कर दिया गया है । जनताके पास संगठनके जो साधन थे वह भी छीन लिये गये हैं । उनका सामूहिक जीवन छिन्न-भिन्न कर दिया गया है । फासिस्ट स्टेटमे मजदूरोको संप्रभु समुत्थानका अधिकार नहीं है । मजदूरोका कोई स्वतन्त्र संगठन नहीं है । जिन मजदूर संगठनोको इजाजत दे रखी है उनमे मजदूरोंको फासिस्टोने परस्पर सलाह करनेकी स्वतन्त्रता नहीं दी है और यह संगठन मजदूरोंके नियन्त्रण या प्रभावमे नहीं हैं । मजदूरोंको केवल चन्दा देना पड़ता है । फासिस्ट पूंजीपतियोसे कामके वारेमे शर्तें तय करते हैं और पीछे यह घोषणा करते हैं कि यह तसफिया मजदूरोंके हितमे किया गया है । ऐसी हालतमे जबतक एक काफी सुदृढ़ और अनुभवी संगठन प्रस्तुत न होगा तबतक फासिस्ट शासनका सफल विरोध जर्मनीमें नहीं हो सकेगा ।

इसके अतिरिक्त आक्रमणका सुअवसर तभी प्राप्त होगा जब फासिस्ट शासन आन्तरिक तथा बाह्य कठिनाइयोके कारण काफी दुर्बल हो जायगा और जनता उसके विरुद्ध हो जायगी । संकटके समय अवश्य आवेगे, बेकारीके घटानेकी जो चेष्टा फासिस्ट कर रहे हैं उससे स्थायी रूपसे बेकारी दूर हो सकती है । यदि विदेशी मामलोमे फासिस्ट स्टेटको दिक्कतें पड़ें तो एक महान् संकट उपस्थित हो सकता है । किन्तु इसका उपयोग तभी हो सकता है जब जर्मनीके समाजवादी और कम्युनिस्ट कार्यकुशलताका परिचय दे और अपनी एक नीति निर्धारित कर समवेत रूपसे कार्य करना आरम्भ कर दें ।

फासिज्मका विकास

फासिस्ट आन्दोलनके अभ्युत्थानके लिए परिस्थिति अनुकूल थी । ससारके सब भागोमे आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त था, राजनीतिक तथा आर्थिक गुटोका सघर्ष तीव्र हो रहा था । राजनीति और व्यापारमे पाप-बुद्धि बहुत बढ़ गयी थी । मजदूरी गिरती जाती थी ।

बेकारी बढ़ती जाती थी। नगरोंमें रहनेवाले मध्यम श्रेणीके लोगोंका जीवन भी संशयास्पन्न था। किसानोंकी भी मुसीबत कुछ कम न थी, क्योंकि खेतीमें सकटकी अवस्था भी उपस्थित हो गयी थी। इस सामाजिक सकटके कारण दलबन्दी बढ़ गयी थी। विविध दल राजनीतिक अधिकार और प्रभावके लिए संघर्ष करते थे, पर इस मुसीबतसे छुटकारा पानेका रास्ता कोई भी नहीं बताता था।

जो शासन-पद्धति लोगोंको मुसीबतसे बचा नहीं सकती, उसके प्रति उनका विद्वेष बढ़ जाता है। भिन्न-भिन्न दलोंकी आपसकी लड़ाईसे वह तंग आ जाते हैं। लोकतन्त्र शासन उनके विद्वेषका पात्र बन जाता है और वह एक मजबूत आदमीकी जरूरत महसूस करने लगते हैं, जो राष्ट्रकी ठीक-ठीक व्यवस्था करे। लोगोंका यह ध्याल होने लगता है कि व्यवसाय, व्यापार, राजस्वकी हीन अवस्था, बढ़ती हुई बेकारी, आर्थिक और राजनीतिक गड़बड़, यह सब लोकतन्त्र शासनकी दुर्बलताओंके परिणाम है। वास्तवमें पूँजी-पद्धतिका जो सकट है, वही लोकतन्त्र शासनके लिए जिम्मेदार है।

जब वह देखते हैं कि पूँजी-प्रथाके सूत्र धीरे-धीरे थोड़ेसे गुटोंमें केन्द्रीभूत होते जाते हैं और पूँजीप्रथामे स्वाधिकार बढ़ता जाता है, जब वह देखते हैं कि बड़े-बड़े ट्रस्ट और व्यवसायके डाइरेक्टरोका व्यक्तिगत प्रभाव वास्तविक है तब व्यवसाय तथा बैंकोंके चादशाहोंके गुटसे उनमें यह भ्रम फैलता है कि अधिनायको (डिक्टेटर्स) के द्वारा शायद सत्ता सम्भव हो, शायद उनके नेतृत्वमें वह संकटकी अवस्थाको पार कर सकें। यही कारण है कि नात्सियोंकी पाशविक वर्चस्वता और अत्याचारको जनताने उपेक्षाकी दृष्टिके साथ देखा।

समाजवादी तथा कम्युनिस्टोंकी भूलसे भी नात्सी दलने लाभ उठाया। जब जर्मनीमें समाजवादकी उन्नति हुई थी, तब समाजवादियोंने अपने शत्रुओंको पूर्णरूपसे पदच्युत नहीं किया था। सेनापर पुराने फौजी लोगोंका आधिपत्य था। व्यापार-व्यवसाय पूँजीपतियोंके हाथमें था। इसके अतिरिक्त समाजवादी तथा कम्युनिस्ट दल बराबर आपसमें लड़ते रहे। इन्होंने एक साथ मिलकर नात्सियोंका मुकाबला नहीं किया।

असली और नकली समाजवाद

जब डाक्टर अन्सारी ऐसे महानुभाव नब्बे फीसदी समाजवादी होनेका दावा करते हैं और साथ-साथ इस विषयपर खुशी भी जाहिर करते हैं कि कांग्रेसको समाजवादसे कोई भी खतरा नहीं है तो मैं इसकी जरूरत महसूस करता हूँ कि खरे और खोटेका फर्क साफ कर दिया जाय, जिसमें असली वस्तुकी पहचानमें कोई दिक्कत न हो। मैं डाक्टर महोदय तथा किसी दूसरे सज्जनकी नेकनीयती और ईमानदारीपर किसी प्रकारका हमला नहीं करता। मैं मानता हूँ कि अपने देशमें बहुतसे ऐसे सज्जन हैं, जो निहायत ईमानदारीके साथ मन्चे दिलसे यह सरल विश्वास रखते हैं कि समाजवादके स्वरूपके सम्बन्धमें जो धारणा

उन्होंने बना ली है, वह ठीक है। इनमें बहुतसे ऐसे सज्जन हैं जो समाजवादके वास्तविक स्वरूपसे अपरिचित हैं, उन्होंने वैज्ञानिक समाजवादका अध्ययनतक नहीं किया है। वैज्ञानिक समाजवाद गम्भीर चिन्तन और अध्ययनका विषय अवश्य है, तिसपर भी उसके स्थूल सिद्धान्तोंके समझनेमें कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती। बहुतसे हमारे ऐसे भाई भी हैं, जो वैज्ञानिक समाजवादके मौलिक सिद्धान्तोंको जानते हुए भी अपनी एक भिन्न कल्पनाको ही सच्चा समाजवाद मानते हैं।

पहले तो हमें ऐसे लोगोंका विचार करना है जो कल्पनाके साम्राज्यमें विचरण करते हैं और तरह-तरहके हवाई महल बनाया करते हैं। जो देश वर्तमानकालमें हीन दशाको प्राप्त हो गया है और जो अतीतके गौरवकी कथासे विशेष रूपसे प्रभावित है, वह अतीतमें ही स्वर्णयुगकी स्थापना करता है और जब कभी वह अपनी उन्नतिकी बात सोचता है, तो वह उसी स्वर्ण-युगको फिरसे वापिस लानेकी चेष्टा करता है। ऐसे देशमें एक ऐसे समुदायका पैदा हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है, जो विश्वास करता है कि अतीतका समाज ही एक आदर्श समाज था जिसमें गरीब और अमीरका फर्क नहीं था और जिसमें सारी प्रजा सुखी और समृद्ध थी, वह एक क्षणके लिए भी नहीं सोचता कि अतीतका वापिस आना कितना असम्भव है। वह इस बातको माननेको भी तैयार नहीं है कि अतीत उतना सुन्दर और मनोरम नहीं था जितना कि वह सोचता है। हम यह मानते हैं कि पूँजीवादी पद्धतिकी बुराईयाँ प्राचीन सामाज्यमें नहीं पायी जाती थी, पर इसमें भी सन्देह नहीं है कि उसकी निजकी बुराईयाँ कुछ कम न थी। प्राचीन समाजमें इस बातकी भी आशा नहीं की जा सकती थी कि श्रमजीवियोंका कोई सगटन बन सकेगा, जो उनको अत्याचारोंसे छुटकारा दिलावे।

इस विचारके लोग समाजवादके प्रभावको बढ़ते देखकर अपनी कल्पना तथा समाजवादके सिद्धान्तोंमें सामञ्जस्य स्थापित करनेकी चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार विज्ञानके इस युगमें प्रत्येक मजहब, जो इस नये वातावरणमें जीवित रहना चाहता है, इस बातको साबित करनेकी कोशिश करता है कि उसके सिद्धान्त विज्ञानसम्मत हैं, उसी प्रकार प्रत्येक समुदाय, जो राजनीतिक क्षेत्रमें अग्रसर होना चाहता है, उसे विवश होकर यह दिखलाना पड़ता है कि उसकी कल्पनाएँ समाजवादके सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं हैं। जो लोग अतीतमें ही स्वर्ण-युगकी कल्पना करते हैं, वह इस बातको दिखलानेकी चेष्टा करते हैं कि अतीतका समाज ही समाजवादके सच्चे सिद्धान्तोंपर आश्रित था। पाश्चात्य देशोंमें तो इसाईयोंने इस प्रकारके प्रयत्न किये हैं। इसीके फलस्वरूप वहाँ क्रिश्चियन सोशलिज्म, (Christian Socialism) पाया जाता है। इसके अनुयायियोंका कहना है कि क्रिश्चियन धर्म और समाजवाद एक-दूसरेके लिए नितान्त आवश्यक हैं और क्रिश्चियन धर्म ही समाजवादका नैतिक आधार है। उनका यह भी विश्वास है कि समाजवादकी विचार-पद्धतिका जन्म ही इसी धर्मसे हुआ है। यदि अपने देशमें भी इस प्रकारके प्रयत्न किये जायें, तो मुझको आश्चर्य न होगा।

हिन्दू चाय और मुसलिम चायकी तरह हिन्दू समाजवाद और मुसलिम समाजवादके पैदा होनेमें देर न लगेगी ।

वैज्ञानिक समाजवादको ऐसे विचारोका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये विचार निराधार और कल्पित हैं और इमनिफ़ इनके सफल होनेकी कोई सम्भावना नहीं है । अतीतके पुनरुज्जीवनका प्रयत्न बालूसे तेल निकालनेके प्रयत्नकी तरह सर्वथा विफल होगा । ऐसे विचारोका प्रचार कर हम देशको गलत रास्तेपर ही ले जायेंगे । केवल कल्पनाके बलपर हम अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं कर सकते । यदि हम मशीन-युगकी बुराइयोंसे बचना चाहते हैं, तो उसका यह तरीका नहीं है कि हम पीछे कदम रखें और सारी औद्योगिक उन्नति-का खातमा करके ससारकी गरीबी और मुसीबतको और भी बढ़ा दें । इन बुराइयोंके अन्त करनेका तरीका एकमात्र वैज्ञानिक समाजवाद है । इस तरीकेके बर्तनेसे हम पूँजीवादी प्रथाके लाभको सुरक्षित रखते हुए उसके दोषोंको दूर कर सकेंगे, अन्यथा नहीं ।

इतिहाससे पता चलता है कि प्राचीनकालमें कई देशोंमें भूमि व्यक्तिकी सम्पत्ति न होकर समाजकी सम्पत्ति मानी जाती थी । रूसमें ऐसी ग्राम-संस्थाएँ १९ वीं शताब्दीतक पायी जाती थी । भारतवर्षके साहित्यसे भी ऐसी संस्थाओंकी सत्ताका पता चलता है । यद्यपि समाजवादकी व्याख्याके अनुसार समाजवादका लक्षण यही है कि उत्पादनके साधन व्यक्ति विशेषकी मिलकियत न होकर समाजकी मिलकियत हो, तथापि हमको इस भूलमें न पड़ना चाहिये कि यह प्राचीन ग्रामसंस्थाएँ वैज्ञानिक समाजवादके सिद्धान्तपर आश्रित थी । उत्पादनके जो तरीके उस समय काममें आते थे, उनसे सम्पत्ति इतनी प्रचुरतामें नहीं उत्पन्न हो सकती थी कि समाजवादके उद्देश्योंकी पूर्ति हो सके । हमको यह ध्यानमें रखना चाहिये कि समाजवादका उद्देश्य समाजके धनको सबमें बराबर-बराबर बाँटना नहीं है । यदि यही उद्देश्य हो, तो अत्यन्त निर्धन देशोंमें इस बँटवारेका फल यही होता कि अमीर लोग तो गरीब हो जाते, पर गरीबोंकी गरीबी दूर नहीं होती । वैज्ञानिक समाजवाद गरीबोंकी गरीबी दूर करना चाहता है, न कि कुछ अमीरोंसे कुछकर उनको तवाह करना । इसलिए वैज्ञानिक समाजवादकी कल्पना भी मशीन-युगके पहले नहीं हो सकती थी । मशीन-युग तथा उसमें पैदा होनेवाला वर्तमान पूँजीवाद ही वैज्ञानिक समाजवादका जन्मदाता है । मशीनके द्वारा जो औद्योगिक उन्नति हुई है, उसने यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रचुरताके इस युगमें जब लोग इसलिए मुसीबत नहीं उठाते कि संसारमें भोजन तथा सुखकी सामग्रीकी स्वल्पता है बल्कि इसलिए कि उत्पादनके साधनोंके मालिक अपने स्वार्थके लिए, न कि समाजके हितके लिए वस्तुओंका उत्पादन करते हैं, समाजवादकी प्रतिष्ठा करना सम्भव हो गया है । मशीनयुगके पहले सम्पत्तिकी वृद्धिका कोई ऐसा बड़ा जरिया नहीं था और इसलिए उस जमानेमें चाहे भूमिपर समाजका ही क्यों न अधिकार रहा हो, समाज-वादके द्वारा समाजकी गरीबी नहीं दूर की जा सकती थी ।

इसका जिक्र करना यो आवश्यक प्रतीत हुआ कि रूसके इतिहासमें हमको एक राजनीतिक दलका (Narodnik) उल्लेख मिलता है जिसकी विचार-पद्धति इसी प्रकारकी थी । यह दल रूसमें ऐसी ग्राम-संस्थाओंको कायम करना चाहता था, जिनमें

भूमिका स्वत्व व्यक्तियोंके हाथमे न होकर सारे समाजके हाथमे हो । इन लोगोका विचार था कि ऐसा करनेसे हम समाजवादकी प्रतिष्ठा भी कर सकेंगे और मशीन-युगके दोषोसे भी मुक्त रह सकेंगे । रूसके वैज्ञानिक समाजवादियोंको इनका घोर विरोध करना पड़ा था और वे इसके मुकाबलेमे तभी सफल हो सके थे, जब बारम्बार विफल होनेके कारण लोगोको इनकी नीतिपरसे विश्वास उठ गया था । रूसके इतिहाससे यह भी पता चलता है कि रूसी-क्रान्तिके समय Narodnik ने समाजवादियोका विरोध किया था और क्रान्तिके दवानेमे श्रम-जीवियोंके विरुद्ध पूंजीपतियोकी सहायता की थी ।

अपने देशमे अभी कोई ऐसा दल पैदा नहीं हुआ है, पर जो लोग अतीतकालमे स्वर्णयुगकी तलाश करते हैं, वह इन्ही ग्राम-संस्थाओका आश्रय लेकर इसी प्रकारके समाजवादकी कल्पना कर सकते हैं ।

यह एक आश्चर्यकी बात है कि अपने देशमे जो लोग मशीन-युगके विरोधी हैं और जिनकी आँख भविष्यपर न होकर अतीतपर है, वह Narodnik की तरह कौसिलोमे न जानेके भी सिद्धान्ततः विरोधी हैं । दोनोंमे विचार साम्य होनेसे कार्यमे भी समानता पायी जाती है और इसी विचारके लोगोमेसे Narodniks के भाई भी निकल सकते हैं ।

अपने देशमे एक और वर्ग है, जो समाजकी वर्तमान अवस्थाको कायम रखना चाहता है, पर देखता है कि उस व्यवस्थासे जो दोष उत्पन्न हुए हैं यदि वह दूर नहीं किये जायेंगे तो वर्तमान समाजका नाश हो जायगा । इसलिए यह वर्ग वर्तमान व्यवस्थामे बिना किसी प्रकारका मौलिक परिवर्तन किये उसके दोषोको दूर करनेकी चेष्टा करता है । अधिकतर लोग इसी वर्गके हैं । यह वास्तवमे समाजसुधारक हैं । इन्हें समाजवादी न कहना चाहिये, पर यह लोग भी अपनेको समाजवादी कहनेकी हिम्मत दिखाते हैं । ये नाना प्रकारके सुधारकी योजनाएँ उपस्थित करते हैं और वर्तमान समाजके सकटको टालनेका प्रयत्न करते हैं । इस वर्गमे ऐसे बहुतसे लोग शामिल हैं, जो सद्भावसे प्रेरित होकर गरीबीको दूर करते हैं । हम उनके त्यागका आदर करते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि जिस नीतिका वह अनुसरण करते हैं उसका हम भी समर्थन करे । सुधारकी इस नीतिसे समाजवादीका अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता । इस नीतिका बराबर विरोध करना चाहिये; क्योंकि खुले विरोधियोकी अपेक्षा इस नीतिके समर्थकोसे वैज्ञानिक समाजवादको अधिक नुकसान पहुँचता है ।

एक और भी वर्ग हो सकता है जो समाजवादियोकी उन माँगोमेसे कुछ माँगोको स्वीकार कर ले, जो परिवर्तनकी अवस्थाको दृष्टिमे रखकर तैयार की गयी हैं और इसी नाते समाजवादी होनेका दावा पेश करे । इन माँगोमे कई ऐसी माँगे हैं, जो व्यक्तिगत सम्पत्तिका अन्त तो नहीं करती, किन्तु उनको मर्यादित अवश्य कर देती हैं । बड़े-बड़े टैक्स तथा वारिसोपर टैक्स ऐसे उपाय हैं जिनसे व्यक्तियोंकी सम्पत्तिका नियन्त्रण हो सकता है ; पर इससे गरीबीका अन्त निश्चय नहीं होता । इस वर्गकी भूल यही है कि यह समझता है कि ये सब उपाय गरीबी तथा समाजकी अन्य प्रचलित बुराइयोको दूर करनेके लिए पर्याप्त हैं । इसके प्रतिकूल एक समाजवादी ऐसी माँगोका समर्थन केवल

इसलिए करता है कि वह जानता है कि व्यक्तिगत सम्पत्तिका लोप एकवारगी नहीं हो सकता ।

मेरी छोटी बुद्धिमे यही आता है कि कांग्रेस धीरे-धीरे इसी विचार-पद्धतिका समर्थन करने लगेगी । कांग्रेससे वैज्ञानिक समाजवादियोंको सचेत रहना चाहिये और उन्हें सुलह और समझौतेके नामपर अपने आदर्शसे नहीं गिरना चाहिये ।

समाजवादके कितने मुख्य-मुख्य विकृत रूप हैं या हो सकते हैं, उनकी चर्चा थोड़ेमे मने ऊपर की है । पाश्चात्य देशोमे भी ये सब रूप और प्रकार पाये जाते हैं ।

वैज्ञानिक समाजवाद न तो सुधारवाद है और न काल्पनिक समाजवाद । यह तर्कोंकी कसौटीपर कसा जा सकता है और यह समाजकी एक ऐसी नवीन आर्थिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करना चाहता है, जिसमे उत्पादनके साधन तथा उत्पन्न वस्तुओंका वितरण और विनिमय समाजके हाथमें हो ।

वर्तमान औद्योगिक पद्धतिके युगके पहले वैज्ञानिक समाजवादकी प्रतिष्ठा करना सर्वथा असम्भव था । यूरोपकी औद्योगिक क्रान्तिके फलस्वरूप ही वैज्ञानिक समाजवादका जन्म हुआ है ।

मशीनके युगमे ही बड़े पैमानेपर उद्योगका होना सम्भव हो सका है और वस्तुओंकी पैदावार असीमित मात्रामे बढ़ायी जा सकती है, पर आपमकी स्पर्धाके कारण पूँजीपतियोंमे मुनाफेके लिए होड़-सी लग गयी और माल खपतसे कही ज्यादा तैयार होने लगा । इसीलिए समय-समयपर व्यापारमे संकटकी अवस्था उपस्थित होती रहती है । आजकल जो विश्व-व्यापी अर्थ-संकट है, उससे छुटकारा पाना कठिन-सा मालूम पड़ता है । लोगोका कष्ट बढ़ता ही जाता है । एक तरफ बेकारी बढ़ती जाती है, दूसरी ओर पूँजीपतियोंको कीमत बढ़ानेके लिए पैदावारको कम करना पड़ता है । जिस प्रकारसे आजका व्यवसाय पूँजी-पतियोंद्वारा संचालित होता है, उससे पैदावारकी वृद्धिमें भारी रुकावट होती है । यह संकटकी अवस्था तभी दूर हो सकती है, जब एक सर्वथा विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाका आयोजन किया जावे । नये समाजमे स्पर्धाको कोई स्थान नहीं रहेगा और एक निश्चित आयोजनाके अनुसार तथा समाजके सब सदस्योंकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए समाजके औद्योगिक जीवनका संचालन किया जायेगा । जब समाजके हितके लिए उद्योग-व्यवसायका संगठन होगा और उत्पादनके सारे साधन व्यक्तियोंकी मिलकियत न होकर समाजकी मिलकियत बन जायेंगे, तो अपने साधनोंके अनुसार समाज जीवनकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए इतने परिमाणमे वस्तुओंका उत्पादन करेगा कि समाजके प्रत्येक सदस्यको पूरी स्वतन्त्रताके साथ अपनी शक्तियोंके विकासका अवसर मिलेगा । समाजके हाथमे जब उत्पन्न वस्तुओंका वितरण और विनिमय रहेगा, तो समाजमे दरिद्रता और अशान्तिके स्थानमे तुष्टि, पुष्टि और शान्ति आ विराजेगी । आज जो पैदावारको कम करनेकी कोशिश की जा रही है उसके कम करनेका कोई कारण नहीं रह

जायगा । पैदावार तेज रफ्तारसे बढ़ेगी । देहातोकी आज जो खराब हालत है, वह दूर हो जायेगी और अर्थ-शोषणकी नीतिका अन्त होगा ।

महात्मा गांधीकी श्रद्धाञ्जलि

कल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीने, जो आजके इस युगके सबसे बड़े महापुरुष थे, अपने जीवनकी अन्तिम लीलाको समाप्त किया । आज दिल्ली शहरमे शामके ४ बजे यमुना नदीके तटपर उनका महाप्रस्थान होनेवाला है । वह हमारे मार्ग-प्रदर्शक थे । उन्होंने हमको जीवनके आध्यात्मिक और समाजिक मूल्योंकी शिक्षा दी । भारतवर्षकी प्राचीन संस्कृतिको परिष्कृत कर उस पुरानी ज्योतिको फिरसे जगाया । भारतीय समाजके करोड़ो निष्चेष्ट और निष्प्राण मानवोंके हृदयोंमें जीवनकी एक नयी ज्योति जगायी, जिसने हमको स्वतन्त्रता प्रदान की । वह मशाल जिसको कि प्राचीन कालके ऋषियोंने इस पुण्य-भूमिमे प्रज्वलित किया था, जिसको भगवान् बुद्धने फिरसे जगाया, जिसको समय-समयपर महापुरुषोंने आकर, जगाकर भारतवर्षकी अखण्ड सम्पत्तिकी रक्षा की, उसी मशालको फिरसे जलाकर और हमारे जीवनमे एक नयी ज्योति, एक नयी स्फूर्ति, एक नया चैतन्य प्रदानकर वही मशाल हमारे कमजोर हाथोंमे सौंपी थी और जब उन्होंने अपने सामने उस मशालको हमारे कमजोर हाथोंसे जमीनपर गिरते देखा तो हमारे हाथोंको बल देनेके लिए अपना सहारा दिया । वह महापुरुष, हमारे राष्ट्रकी सबसे बड़ी सम्पत्ति आज उठ गयी, आज हमसे छिन गयी है । हम आज अपनेको निराश्रित निस्पाय और निरवलम्ब पा रहे हैं । वह हमारा दीपक आज बुझ गया । चारो ओर अन्धकार है । सारा भारतीय समाज शोकमे निमग्न है । ऐसे अवसरपर हममे कातरताका आना स्वाभाविक है ।

इस रंजकी घड़ीमे मुझे अपने देशके इतिहासका वह अवसर स्मरण हो आता है जब हमारे देशका एक महापुरुष, नहीं-नहीं सारे ससारका महापुरुष, अर्थात् भगवान् बुद्धने—जब वह अपना शरीर छोड़ रहे थे—भारतीयोंको एक अनुपम शिक्षा दी थी । उस अवसरपर हमारे प्रान्तके कुशीनगरमे जब भगवान् बुद्ध मृत्युशय्यापर पड़े थे तो अपने पास अपने प्रिय शिष्य आनन्दको न देखकर उन्होंने भिक्षुओंसे पूछा कि आनन्द कहाँ है ? भिक्षुओंने कहा—“भगवान् आनन्द बाहर खड़ा रो रहा है ।” उन्होंने कहा—“उसको बुलाओ ।” वह भगवान्के सम्मुख आया । भगवान्ने कहा—“हे आनन्द, क्यों रोते हो ?” उसने कहा, “ससारका दीपक बुझ रहा है, ससार अन्धकारसे आच्छन्न होनेवाला है । आपकी अनुपस्थितिमे हम निरवलम्ब हो जायेंगे । हमें उपदेश देनेवाला, हमको ससार-चक्रसे उबारनेवाला कौन होगा ?” भगवान्ने कहा—“हे आनन्द, तुम हमारी उस शिक्षा-को क्यों भूल गये ? क्या हमने तुम्हें बार-बार यह नहीं सिखाया कि जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है ? हमने तुम्हें क्या यह नहीं बताया कि तुम अपने पैरोपर

खड़े हो, स्वयं अपने दीपक हो, किसी दूसरे दीपकका सहारा मत लो ? हमारे महानिर्वाणके अनन्तर हमारे निर्वाणकी शिक्षा ही तुम्हारे लिए दीपकका काम करेगी । जाओ, रोओ मत, यह रोनेका समय नहीं है । निर्वाणके लिए सदा प्रयत्नशील होते रहो ।” यदि हमारा राष्ट्रपिता, ससारका महापुरुष अपनी मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ कुछ बात कर सकता तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसका भी उपदेश इन्ही सारगर्भित शब्दोंमें होता । यद्यपि उस समय वह हमको कुछ उपदेश अपनी अन्तिम घड़ियोंमें न दे सके, किन्तु हम जानते हैं कि अपने जीवनमें उन्होंने बार-बार यह कहा कि तुम हमारा सहारा मत ढूँढो ।

इसीलिए सन् ३५ में उन्होंने कांग्रेसकी सदस्यता छोड़ी और इस बातके समझनेके लिए कि बड़े-से-बड़ा महापुरुष क्यों न हो, आखिर उसके जीवनकी अवधि भी निश्चित है । यदि तुम इसी प्रकारसे उसके ऊपर आश्रित होगे तो उसके उठ जानेके अनन्तर तुम अवश्य खिन्न होगे, और अवसादसे भर जाओगे । इसी प्रकार समय-समयपर हमको अपने पैरोपर खड़े होनेका उपदेश देकर महात्माजीने हमको यह बताया कि तुम अपने पैरोपर खड़ा होना सीखो ! भगवान् बुद्धके वह शब्द आज हमारे कानोंमें गूँज रहे हैं । यह दुःखका समय है । ज्यो-ज्यो दिन बीतते जायेंगे हम महात्माजीके अभावको अधिकाधिक अनुभव करते जायेंगे । किन्तु यदि हम उनके सच्चे अनुयायी हैं, यदि हम उनके उपदेशों और आदेशोंपर दृढ़ रहना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि वीर पुरुषोंकी तरह उनकी शिक्षाको शिरोधार्य करें । हम स्वयं अपने पैरोपर खड़े हो । आत्मदीपक बने । भारतवर्षका प्रत्येक व्यक्ति, जो गांधीजीका अनुयायी कहलाता है, उसका आज यह परम पुनीत कर्तव्य है कि अपने हृदयमें उस ज्योतिको जगाकर दूसरोंका मार्ग-प्रदर्शन करे । आज वह हाड़-मासकी कँदसे मुक्त होकर और भी विशाल रूपसे, और भी प्रभावशाली प्रकारसे हमारे हृदयोंपर राज्य करेंगे । उनकी शिक्षाके प्रसारमें कठिनाई होनेके स्थानमें अब सुगमता होगी और आज जब वह राजनीतिके क्षेत्रसे उठे तो भारत ही नहीं सारा संसार उनकी शान्तिप्रेमकी शिक्षाको अपनानेके लिए तैयार होगा । इसके लिए आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय, जो कि अभागे हैं, जिनको कि इस आजादीके साथ जिन्दगीका पैगाम मिलनेकी जगह मौतका पैगाम मिला, यदि हम अब भी सँभलना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि वह मशाल जिसको गांधीजीने हमारे हाथोंको सौंपा, वह पुरानी भारतवर्षकी मशाल जो पुरानी भी है और आजके लिए नयी भी, उस मशालको अपने मजबूत हाथोंसे पकड़े और इस बातकी चेष्टा करें कि हमारे हाथोंसे इस मशालको कोई छीन न ले । जबतक हम उस मशालके नम्बरदार हैं, तबतक भारतवर्षका बाल कोई बाँका नहीं कर सकता । जो आज यह दावा करते हैं कि गांधीजी भारतीय संस्कृति और हिन्दू-धर्मके विनाशक हैं और विरोधी हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्मके मर्म और हृदयको नहीं पहचाना । भारतीय इतिहास पुकारकर कहता है कि ससारमें एकता होनी चाहिये । सर्वत्र एक ही भाव, एक ही आत्माका संचरण होता है । सारा ससार एक सूत्रमें बँधा हुआ है । मानव-जातिसे प्रेम करो । अत्याचार, अनाचारसे घृणा करो ।

जीवनका मार्ग शान्तिमें है, प्रेममें है, धर्ममें है, जीवनके सामाजिक और आध्यात्मिक

मूल्योकी रक्षामें है, अत्याचारमें नहीं, अनाचारमें नहीं, घृणामें नहीं, विद्वेषमें नहीं । मैं पूछना चाहता हूँ इस पतित भारतको उठानेवाला, उसका उद्धार करनेवाला, सारे समाजमें उसको आदर-सम्मान दिलानेवाला, भारतका नाम जो अबतक अपमानित था, तिरस्कृत था, कलंकित था, उसको गौरव प्रदान करनेवाला, भारतीय जिसका नाम लेकर समस्त संसारमें मस्तक ऊँचा करके भ्रमण कर सकते थे यह काम किसका है ? किसने इस भारतीय हिन्दू समाजको, जो कि पतित हो गया था, जो कि घोर वर्ण-व्यवस्थासे पिसा जा रहा था, जिसने स्पृश्यताको इतना उत्तेजन देकर अपने सामाजिक बन्धनको शिथिल कर दिया था, जिसमें सुदृढता नहीं थी उसमें वह सुदृढता लानेवाला, इस भारतीय समाज, हिन्दू समाजके अनाचार अत्याचारको नाश करनेवाला, पतितोका उद्धार, स्त्रियोको समाजमें अपना उचित स्थान दिलानेवाला कौन है ? वह गांधी है । भारतको स्वतन्त्र बनानेवाला कौन है ? वह गांधी है । इसलिए जो चाहते हैं कि भारतका भविष्यमें उत्थान हो, जो चाहते हैं स्वतन्त्रताका उचित उपभोग हो, जो चाहते हैं कि भारतवर्ष केवल अपनी स्वतन्त्रताका भोग न करे, किन्तु समस्त एशियाका मार्ग-प्रदर्शक बने, उसका नेतृत्व करे—नहीं-नहीं सारा संसार, जिसका हृदय आज व्यथित हो रहा है, जो 'वास्तविकता' के भूतसे पिसा जा रहा है, जो जीवनके मूल्योको भूल रहा है, जिसके सामने सामाजिक नीतिका कोई मूल्य नहीं, जिसके सामने सत्यका कोई मूल्य नहीं, उस समाजको यदि कोई शान्ति दिला सकता है उस व्यथित हृदयको शान्त कर सकता है, संसारमें फिरसे शान्ति, सुख और वैभवकी स्थापना कर सकता है तो वह भारतवर्ष कर सकता है । किन्तु तभी कर सकता है जब वह महात्मा गांधीके मार्गके ऊपर चले । हममें वह शक्ति हो कि हम उनके पद-चिह्नोका अनुसरण करें । आज हमें महात्माजीके लिए प्रार्थना नहीं करनी है । वह हुतात्मा जीवनभर सारे समाजकी सेवा करते रहे, मरकर भी उन्होंने अपने समाजका उद्धार किया । हमको आज प्रार्थना करनी है कि 'भगवन्, हमको मद्वुद्धि दो, भगवन् हममें सात्विक बुद्धि दो, भगवन् हम जिस मार्गपर चले वह जीवन प्रदान करनेवाला मार्ग हो, उत्तिष्ठ मार्ग हो । वह हमको पतित बनानेवाला न हो, हमको मृत्युकी घाटीमें उतारनेवाला मार्ग न हो और यदि इस सन्देशको किसीने लिया है तो महात्मा गांधीने । महात्मा गांधी सदा जीवित रहेंगे और वह तभी जीवित रह सकते हैं जब भारतीयोंमें थोड़ेसे भी लोग ऐसे हो जो उनके पद-चिह्नोका अनुसरण करें । गुरु गोविन्दसिंहने जब अपने शिष्योकी परीक्षा की तो उनको पाँच ही शिष्य पूरे मिले, सच्चे मिले, जिनकी उनमें निष्ठा थी, जो उनका पूरी तरहसे अनुसरण करनेको तैयार थे । यही गुरुके पंच प्यारे थे, इन्हींको सबसे पहले उन्होंने अमृत चखाया । अगर मुष्तिमेग्न लोग भारतवर्षमें पैदा हो, और जीवित हो, जो उनमें आस्था रखते हो, जो उनमें श्रद्धा रखते हो, जो उनके बताये हुए मार्ग पर चले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस देशका कोई बाल बॉका नहीं कर सकता । इस देशका भविष्य गौरवमय है और उसके लिए हमें उचित गर्व होगा ।

मुझे इस अवसरपर कुछ और कहना नहीं है । मेरा गला दुःखसे भरा हुआ रुँधा जाता है । यह बहुतसे शब्दोंका अवसर नहीं । यह काम करनेका अवसर है । जो भारतवर्षके

भविष्यके लिए सचेष्ट है, जो चाहते हैं कि उसकी उन्नत अवस्था हो, जो उसको आज पतन-की अवस्थासे बचाना चाहते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे सघबद्ध होकर, इस राजनीतिके पचड़ेको छोड़ना ही तो उसको भी छोड़कर, इस देशमें एक ऐसे जीते-जागते सांस्कृतिक आन्दोलनका प्रचार करें, जिस आन्दोलनके बलपर उनकी शिक्षा इस देशमें टिक सके । प्रार्थी हूँ कि भारतवर्षमें ऐसे विशाल देशमें, जहाँ अनगिनत लोग बसते हैं, यहाँके नर-नारियोमें थोड़ेसे लोग अवश्य होंगे जो आजकी परिस्थितियोंसे उठकर साम्प्रदायिक शान्तिके लिए चेष्टा करेंगे । और यदि ऐसा हुआ तो हमारा भविष्य उज्ज्वल है, इस देशका कल्याण होनेवाला है ।^१

युक्तप्रान्तकी असेम्बलीमें दिया भाषण

संसारके सर्वश्रेष्ठ मानव तथा भारतके राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके प्रति उनके निधनपर अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करनेका अवसर इस व्यवस्थापिका सभाको आज ही प्राप्त हुआ है । अपने देशकी प्रथाके अनुसार तथा लोकाचारके अनुसार हमने १३ दिनतक शोक मनाया । यह शोक महात्माजीके लिए नहीं था, क्योंकि जो सर्व-भूत-हितमें रत है और जो मानव-जातिकी एकताका अनुभव अपने जीवनमें करता रहा हो उसको शोक कहाँ, मोह कहाँ ? यदि हम रोते हैं, विलखते हैं तो अपने स्वार्थके लिए विलखते हैं, क्योंकि आज हम इस बातका अनुभव कर रहे हैं कि हमने अपनी अक्षय निधि खो दी है, अपनी चल सम्पत्तिको गँवा दिया है ।

महात्माजी इस देशके सर्वश्रेष्ठ मानव थे, इसीलिए हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं । हमारे देशमें समय-समयपर महापुरुषोंने जन्म लिया है और इस जातिको पुनरुज्जीवित करनेके लिए नूतन सन्देशका सचार किया है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि अन्य देशोंमें महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मेरी अल्प बुद्धिमें महात्मा गांधी ऐसा अद्वितीय बेजोड़ महापुरुष केवल भारतवर्षमें ही जन्म ले सकता था और वह भी बीसवीं शताब्दीमें, अन्यत्र कहीं नहीं । क्योंकि महात्मागांधीने भारतवर्षकी प्राचीन संस्कृतिको, उसकी पुरातन शिक्षाको परिष्कृत कर युग धर्मके अनुरूप उसको नवीन रूप प्रदान कर, उसमें वर्तमान युगके नवीन सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यका पुट देकर एक अद्भुत एवं अनन्य-तम सामञ्जस्य स्थापित किया । उन्होंने इस नवयुगकी जो अभिलाषाएँ हैं, जो आकांक्षाएँ हैं, जो उसके महान् उद्देश्य हैं, उनका सच्चा प्रतिनिधित्व किया है । इसीलिए वे भारतवर्षके ही महापुरुष नहीं थे अपितु समस्त संसारके महापुरुष थे । यदि कोई यह कहे कि उनकी राष्ट्रीयता सकुचित थी, तो वह गलत कहेगा । यद्यपि महात्मा गांधी स्वदेशीके व्रती थे, भारतीय संस्कृतिके पुजारी थे तथा भारतीय राष्ट्रीयताके प्रबल समर्थक थे, किन्तु उनकी

राष्ट्रीयता उदारतासे पूर्ण थी, ओतप्रोत थी । वह सकुचित नहीं थी । संकुचित राष्ट्रीयता वर्तमान समाजका एक बड़ा अभिशाप है, किन्तु महात्माजीका हृदय विशाल था । जिस प्रकार भूकम्प-मापक यन्त्र पृथ्वीके मृदुसे मृदु कम्पको भी अपनेमे अंकित कर लेता है उसी प्रकार मानव-जातिकी पीड़ाकी क्षीण-से-क्षीण रेखा भी उनके हृदय-पटलपर अंकित हो जाती थी । हमारा देश समय-समयपर महापुरुषोंको जन्म देता रहा है और मैं समझता हूँ कि इस व्यवसायमे भारत सदासे कुशल रहा है, अग्रणी रहा है । पतित अवस्थामे भी, गुलामीकी हालतमे भी भारतवर्ष ही अकेला ऐसा देश रहा है, जो जगद्वन्द्व महापुरुषोंको जन्म दे सका है । मैं समझता हूँ कि इस व्यवसायमे भारत सदासे कुशल रहा है । हमारे देशमे भगवान् बुद्ध हुए तथा अन्य धर्मोंके प्रवर्तक हुए, किन्तु सामान्य जनताके जीवनके स्तरको ऊँचा करनेमे कोई भी समर्थ नहीं हो सका । यह यथार्थ है कि कि पीड़ित मानवताके उद्धारके लिए नूतन धार्मिक सन्देश उन्होंने दिये थे, समाजके कठोर भारको वहन करनेकी समर्थता प्रदान करनेके लिए उन्होंने नये-नये आश्वासन दिये थे, उनके विक्षुब्ध हृदयोंको शान्त करनेके लिए पारलौकिक सुखोंकी आशाएँ दिलायी थी, लेकिन सामान्य जीवनके जो कठोर सामाजिक बन्धन हैं, जो जनताके ऊपर कठोर शासन चल रहा है, जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ हैं, जो दीनो और अकिंचन-जनोको भौतिभाँतिके तिरस्कार और अवहेलनाएँ सहनी पड़ती हैं, इन सब समस्याओंको हल करनेवाला यदि कोई व्यक्ति हुआ तो वह महात्मा गांधी हैं । उन्होंने ही सामान्य जनोके जीवनके स्तरको ऊँचा किया । उन्होंने जनतामे मानवोचित स्वाभिमानको उत्पन्न किया । उन्होंने ही भारतीय जनताको इस बातके लिए सन्मत प्रदान किया कि वह साम्राज्यशाहीके भी विरुद्ध विरोध करे और यह भी पाशविक शक्तियोंका प्रयोग करके नहीं, किन्तु आध्यात्मिक बलका प्रयोग करके हुआ । उनकी अहिंसा बेजोड़ थी । भगवान् बुद्धने कहा था 'अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्' अर्थात् अक्रोधसे क्रोधको जीतना चाहिये । उनकी अहिंसाका सिद्धान्त भी केवल व्यक्तिगत आचरणका उपदेशमात्र न था, किन्तु सामाजिक समस्याओंको हल करनेके लिए अहिंसाको एक उपकरण बनाया और राजनीतिक क्षेत्रमे अपने महान् ध्येयकी प्राप्तिके लिए उसका सफल प्रयोग करना महात्मा गांधीका ही काम था और चूँकि वह ससारमे अहिंसाको प्रतिष्ठित करना चाहते थे, इसलिए उनकी अहिंसाकी व्याख्या भी अद्भुत, बेजोड़ और निराली थी । उनकी अहिंसाकी शिक्षा केवल व्यक्तिगत आचरणकी शिक्षा नहीं है । उनकी अहिंसाकी व्याख्या वह महान् अस्त है जो समाजकी आजकी विषमताओंका, जो वैमनस्य और विद्वेषके कारण है, उन्मूलन करना चाहती है । अहिंसाके ऐसे व्यापक प्रयोगसे ही अहिंसा प्रतिष्ठित हो सकती है ।

सामाजिक और आर्थिक विषमताको दूर कर, मनुष्यको मानवतासे विभूषित कर, आत्मोन्नतिके लिए सबको ऊँचा उठाकर जाति-पाँति और सम्प्रदायोंके बन्धनोंको तोड़कर ही हम अहिंसाकी सच्चे अर्थोंमे प्रतिष्ठा कर सकते हैं । यदि किसीने यह शिक्षा दी तो गांधीजीने शिक्षा दी । इसलिए यदि हम उनके सच्चे अनुयायी होना चाहते हैं तो समाजसे इस विषमताको, इस ऊँच-नीचेके भेदभाव को, इस अस्पृश्यताको, समाजके नीचे-से-नीचेके

स्तरके लोगोंकी दरिद्रताको और आर्थिक विपमताको समाजसे सदाके लिए उन्मूलित करके ही हम सच्चे ग्रहिसक कहला सकते हैं। यह महात्मा गांधीजीकी विशेषता ही थी।

हमारे देशकी यह प्रथा रही है कि महापुरुषके जन्म निधनके बाद हमने उसको देवताकी पदवीसे विभूषित किया। समाधि और मन्दिर बनाये। उसकी मूर्तिको मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित किया या मजार बनाकर उसकी समाधि या मजारपर प्रेम और श्रद्धाके फूल चढ़ाकर हम सन्तुष्ट हो गये। इसी प्रकारसे भारतवासियोंने अनेक महापुरुषोंकी केवल उपासना और आराधना करके उनके मूल उपदेशोंको भुला दिया। मैं चाहता हूँ कि हम आज महात्मा गांधीको देवत्वकी उपाधि न दे, क्योंकि देवत्वसे भी ऊँचा स्थान मानवताका है। मानवकी आराधना और उपासना समाधि-गृह और मजार बनाकर, उनपर फूल चढ़ाकर नहीं होती। दीपक, नैवेद्यसे उसकी पूजा नहीं होती, मानवकी आराधना और उपासनाका प्रकार भिन्न है। अपने हृदयोंको निर्मल बनाकर और उनके बताये हुए मार्गपर चलकर ही उसकी सच्ची उपासना होती है। यदि हम चाहते हैं कि हम महात्मा गांधीके अनुयायी कहलाये तो हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य है कि जनतामें अपने प्रेम और श्रद्धाके भावोंका प्रदर्शन करनेके साथ-साथ हम उनका जो अमर सन्देश है, उसपर अमल करे। उनका सन्देश केवल भारतवर्षके लिए नहीं, वरन् वर्तमान संसारके लिए है, क्योंकि आज संसारका हृदय व्यथित है, दुखी है। एक नये महायुद्धकी रचना होने जा रही है। उसकी पूर्व सूचनाएँ मिल चुकी हैं। ऐसे अवसरपर संसारको एक नूतन आदेश और उपदेशकी आवश्यकता है। महात्माजीका बताया हुआ उपदेश जीवनका उपदेश है, मृत्युका सन्देश नहीं है। और जो पश्चिमके राष्ट्र आज सकुचित राष्ट्रीयताके नामपर मानव-जातिका वलिदान करना चाहते हैं, जो सभ्यता और स्वाधीनताका विनाश करना चाहते हैं, वे मृत्युके पथपर अग्रसर हो रहे हैं, वे मृत्युके अग्रदूत हैं। यदि वास्तवमें हम समझते हैं कि हम महात्माजीके अनुयायी हैं तो हमारी सबकी सच्ची श्रद्धाञ्जलि यही हो सकती है कि हम इस अवसरपर शपथ लें, प्रतिज्ञा करे कि हम आजीवन उनके बनाये हुए मार्गपर चलेगे, जो जनतन्त्रका मार्ग, समाजमें समता लानेका मार्ग, विविध धर्मों और सम्प्रदायोंमें सामञ्जस्य स्थापित करनेका मार्ग है, जो छोटे-छोटे मानवको भी समान अधिकार देता है, जो किसी मानवका पक्ष नहीं करता, जो सबको समान रूपसे उठाना चाहता है। यदि महात्माजीके बताये हुए मार्गको हम अनुसरण करते तो एशियाका नेतृत्व हमारे हाथोंमें होता और हमारा देश भी दो भूखण्डोंमें विभाजित नहीं हुआ होता। हम एशियाका नेतृत्व करेंगे, किन्तु इस गृह-कलहके कारण हमारा आदर विदेशोंमें बहुत घट गया है। इसलिए यदि हम उस नेतृत्वको ग्रहण करना चाहते हैं तो हमको अपने देशमें उस सन्देशको कार्यान्वित करना होगा। भारतवर्षमें बसनेवाली विविध जातियोंमें एकताकी स्थापना करके हमको संसारको दिखा देना चाहिये कि हम सच्चे मार्गपर चल रहे हैं। तभी सारा संसार हमारा अनुसरण करेगा।

महात्माजीके लिए जो सोचते हैं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं थे, उनका काम भारतवर्षतक ही सीमित था, यह उनकी भूल है। भारतवर्ष तो उनकी प्रयोगशालामात्र

था । वह समझते थे कि यदि सत्य और अहिंसासे वह देशमें सफलता प्राप्त कर सकेगे, तो उनका सन्देश ससारमें फैलेगा ।

मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि महात्माजीको अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझमें शक्ति पैदा हो कि मैं उनके बताये हुए मार्गका अनुसरण किसी-न-किसी अंशमें कर सकूँ ।

गांधीजी

गांधी इस युगके एक अद्वितीय पुरुष थे । वे क्या थे, यह किसी लक्षणसे लक्षित नहीं कराया जा सकता, न उन्हें किसी विशिष्ट वर्गमें बैठाया जा सकता है । उनके राजनीतिक तत्त्वज्ञानमें एक प्रकारका अराजकतावाद था, क्योंकि राज्य-संस्थामें उनको विश्वास नहीं था, पर अन्य किसी बातमें पश्चिमके अराजकतावादियोंके साथ उनका कोई साम्य नहीं था । वे समाजवादी थे, पर वैज्ञानिक समाजवादके मानदण्डसे जाँचनेपर उनके विचार समाजवादकी मान्यताओंके साथ न विचारमें मिलते थे न आचारमें ही । सामान्यतः वे धार्मिक प्रवृत्तिके पुरुष माने जाते थे पर न तो उन्हें धार्मिक संस्थाओंपर विश्वास था न हिन्दूधर्मके आचारोंका ही वे पालन करते थे ।

यदि आजसे दो शताब्दी पहले उनका जन्म हुआ होता तो या तो वे कोई बहुत बड़े महात्मा और किसी धर्ममतके संस्थापक हुए होते अथवा कल्पना-साम्राज्यमें विचरनेवाले कोई समाजवादी होते । पर वे ऐसे समयमें हुए जो अति क्षिप्र सामाजिक परिवर्तनोंका समय रहा और उन्होंने यह देखा कि समतायुक्त समाजका स्वप्न इस समय सच्चा हो सकता है ।

मुख्यतः वे मानवहित-साधनके व्रती थे । मनुष्यकी अन्तस्थ सद्बृत्तिपर उनका अटल विश्वास था । मानव-जातिसे प्रेम उनके जीवनका विधान और नियम था । सेवा विशेषतः पीड़ितोंकी, सत्य और अहिंसा; ये ही उनके सामाजिक तत्त्वज्ञानके घटक थे; पर उनकी यह तत्त्वनिष्ठा केवल भावुक और तात्त्विक नहीं, बल्कि अत्यन्त व्यावहारिक थी । वे सत तो थे ही, पर इससे भी अधिक वे द्रष्टा थे और निरन्तर नि स्वार्थ कर्ममें उनकी श्रद्धा थी । सासारिक जीवनसे विरक्त होनेके वजाय वे समाजके जीवनमें वैयक्तिक जीवनकी परिपूर्णता ढूँढते थे । उनका हृदय कोमल था और थे वे बड़े सूक्ष्मदर्शी । उनकी कथनी और करनीमें कोई विरोध नहीं था । अपने जीवनकी प्रयोगशालामें वे सत्यके प्रयोग किया करते थे । समाजकी हिंसावृत्तिके मूल कारणोंका उन्होंने जो अनुसन्धान किया उससे वे इस नतीजेपर पहुँचे कि जबतक मनुष्यके द्वारा मनुष्यका शोषण होता रहेगा तबतक अहिंसाका विधान स्थापित नहीं हो सकता । अहिंसाका व्रत उनके अपने वैयक्तिक जीवनका ही नियम नहीं था, प्रत्युत वे इसे सम्पूर्ण समाजके जीवनका भी नियम बनाना चाहते थे । साध्यकी अपेक्षा साधनके विषयमें उनका विशेष आग्रह था । नित्य-नैमित्तिक जीवनकी विभिन्न परिस्थितियोंमें वे अहिंसाके अपने सिद्धान्तका प्रयोग करते थे । बुराईका

प्रतिकार अहिंसाके द्वारा करनेके हेतु उन्होंने सत्याग्रहका मार्ग निकाला । बुराईसे वे घृणा करते थे, पर बुराई करनेवालेसे नहीं । कई लड़ाइयोंके वे नायक रहे । उनकी सभी लड़ाइयाँ पीड़ितोंके परित्यागके लिए थी । सत्याग्रहके तारक शस्त्रकी ओर आज संसारका विशेष ध्यान है, क्योंकि संसार आज नवीन सहारक शस्त्रोंके भयसे ग्रस्त है ।

गांधीजीका जीवन अहिंसाका एक उपदेश था । वे असलमें सच्ची शान्ति चाहनेवाले परम सात्विक पुरुष थे । उन्होंने आत्यन्तिक और अति कठोर आत्मसंयम साधा था और सबके लिए करुणा और मैत्रीके दिव्य भाव उन्होंने प्राप्त किये थे । मनुष्य-मात्रसे प्रेम करना उनके जीवनका परम विधान था । मानवोचित गुणोंके वे आदर्श थे और अपने आपको राष्ट्रका प्रथम सेवक कहा करते थे । उन्हें किसीका कोई भय नहीं था । सत्यकी सेवामें वे अपने जीवनकी वाजी लगा देते थे । समाजहित-साधन और अध्यात्मनिष्ठाको वे मनुष्यकी सबसे श्रेष्ठ निधि मानते थे और इन्हे अन्य सब चीजोंके ऊपर रखते थे । पर फिर भी वे बड़े व्यवहारज्ञ थे, क्योंकि किसी भी कार्यका आरम्भ करनेके पूर्व वे अपने भौतिक और नैतिक साधनोंका पूर्ण विचार कर लिया करते थे । समझौतेकी कोई बातचीत वे इतनी नहीं तानते थे कि उसका तार टूट जाय और यह कहा करते थे कि सच्चा सत्याग्रही समझौतेके लिए सदा प्रस्तुत रहता है । पर कोई सत्याग्रही कभी सत्यसे विमुख नहीं हो सकता, न कभी बुराईसे मेल कर सकता है । अन्ततक वे अपने पुराने विचारों और आचारोंको बदलते और नये विचार ग्रहण और विकसित करते रहे । पर उनकी विचार-पद्धतिकी आधार शिला कभी नहीं बदली ।

उनके अहिंसा-दर्शनके अनुसार वे किसी स्वतन्त्र राज्यके प्रधान होकर नहीं रह सकते थे, कारण सभी राज्य दमन और हिंसापर अवलम्बित होते हैं । उन्हींके शब्द हैं कि 'मैं अधिकारको स्पर्श कर सकता हूँ, पर ग्रहण नहीं कर सकता ।' यदि वे आज जीते होते तो राज्यकी भूलोंको सुधारने, त्रुटियोंको दूर करनेका काम करते होते और न्याय और सदाचार-के पक्षमें ही अपने प्रचण्ड प्रभावका उपयोग करते । उनके विश्वासकी परीक्षाका जव-जव समय आया, तब-तब वे पर्वतके समान अटल-अचल देख पड़े, विरोधमें खड़े अत्यन्त विषम शत्रुदलवल उन्हें विचलित नहीं कर सके । बड़े-बड़े दावानलोंको बुझाने और तूफानोंको शान्त करनेके प्रचण्ड प्रयास उन्होंने किये और अपना जीवन लगा दिया उन सद्बस्तुओंको पानेके लिए जिनके लिए उनके जीवनका सारा प्रयास था । साम्प्रदायिक पागलपनका बढ़ता हुआ चढ़ाव जब अन्य किसी प्रकारसे रोक नहीं सका, तब उन्होंने अपने जीवनोत्सर्गकी अन्तिम आहुति दे दी जिसकी अद्भुत करामातसे हिंसा और प्रतिक्रियाकी अन्ध शक्तियाँ तत्कालके लिए तो विखर ही गयी । इस आत्म-बलिदानने उस महान् पुरुषका सच्चा व्यक्तित्व अविश्वासियों और राजनीतिक विरोधियोंपर भी प्रकट कर दिया और उनकी शंकाएँ दूर की । जो मुसलिम-समाज उन्हें अपना परम शत्रु मानता था वह अब उन्हें अपना अचूक मार्ग-दर्शक और सुहृद् मानने लगा ।

आत्म-बलिदानके इस अन्तिम कर्मसे उनकी लोकप्रियता इस देशमें तथा बाहर भी शतगुण हो गयी । अपने देशवासियोंके हृदयोंमें वे सदा पूजित रहेंगे और उनका उदाहरण

उन सबको प्रेरणा देगा जो चाहते हैं कि ससार समझदारी और सद्बुद्धिके रास्तेपर लीट आये। उनका ध्यान बहुत-कुछ अपने ही देशके प्रश्नोंमें लगा हुआ था, इससे कुछ लोग उन्हें सकुचित हृदयका एक राष्ट्रवादीमात्र समझ बैठनेकी गलती करते हैं। परन्तु गांधीजी-को ऐसा समझना केवल अज्ञानमूलक है। गांधीजी यह जानते थे कि जगत् मूलतः एक है और इसलिए अहिंसा यदि किसी एक ही देशमें सीमित रही तो वह सफल नहीं हो सकती। पर वे अपनी मर्यादा देखते थे और यह जानते थे कि मेरा कर्मक्षेत्र मूलतः भारतवर्ष ही है। उनका शान्ति और सद्भावनाका सन्देश सबके लिए था, किसी विशिष्ट वर्ग या दलके लिए नहीं। लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय और सार्वराष्ट्रीयताके वे अनन्य साधक थे।

सब द्रष्टाओंके समान उन्होंने भी अपने विचारोंको कोई दार्शनिक रूप नहीं दिया और मार्क्सके समान वे भी अपनी शिक्षाओंका 'गांधीवाद' नाम सुननेपर उसका निषेध किया करते थे। वे हठधर्मी नहीं थे, किसी भी नये विचारको परखनेके लिए वे सदा तैयार रहते थे।

गांधीवाद कोई निगूढ़ दर्शन नहीं, बल्कि आचार-विचारकी एक पद्धति है। उसमें कोई पारभौतिकता नहीं है। उसके सदाचार-सम्बन्धी कुछ नियम हैं जो व्यक्ति और संस्था दोनोंके लिए हैं। उसकी कार्य-पद्धति अहिंसाकी है, पर यह अहिंसा किसी तरह मेल करके चुप और शान्त हो जानेकी वृत्ति नहीं है। बुराईके साथ इसका मेल नहीं होता, उसके साथ इसका असहयोग ही रहता है। इसके द्वारा उसका प्रत्यक्ष प्रतिकार होता है, पर अहिंसात्मक उपायोंसे। सब मानव-समस्याओंको इस प्रकार हल करनेका इसका दावा है और यह विश्वास है कि अन्तमें इसीकी विजय होगी। कारण, मनुष्यकी अन्तस्थ सद्बुद्धि और विश्वमें नैतिक अधिकारका परम प्रभुत्व होनेका इसे भरोसा है। अहिंसा-व्रतके अपने अनुसन्धानसे इसे यह तथ्य मिला है कि वर्गभेदों और सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओंको मिटाये बिना समाजमेंसे हिंसाका उन्मूलन नहीं हो सकता। अतः वर्गहीन समाज इसका ध्येय है और समुत्पन्न समाजकी एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था इसे करनी है जिससे जनतन्त्रताका भाव नष्ट न हो और मनुष्यकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो। विज्ञानसे इसे इसी हृदयक मदद लेना है कि उसके द्वारा मानवताको चोट पहुँचाये बिना उपकारी कार्योंमें जो कुछ सहायता मिल सकती है वह प्राप्त की जाय। पर गांधीवाद वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, जीवनके प्रति इसकी नैतिक मनोवृत्ति है।

साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय द्वेष और लोभके इस जमानेमें गांधीके सन्देशका विशिष्ट महत्व है। वर्गों-वर्गों और राष्ट्रों-राष्ट्रोंके पारस्परिक संघर्षोंसे ससार छिन्न-भिन्न हो रहा है। सर्वत्र लोग शान्तिके लिए तरस रहे हैं, पर वे मूक हैं या उनके मुँह बन्द किये गये हैं। गांधीने शान्तिका मार्ग दिखा दिया है। सार्वराष्ट्रीय सहानुभूति और सहयोगके लिए सचेष्ट सद्भावसम्पन्न लोगोंका यह काम है कि गांधीके आदर्शोंको ग्रहण करे और जगत्की दुष्प्रवृत्तियोंके विरुद्ध संघर्ष करनेकी उनकी पद्धतिका अनुसरण करे।^१